मूल्य १०)

प्रथम संस्करण, संवत् २०११

प्रकाशक—ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वनारस । सु द्र क—ओम् प्रकाश कपूर, ज्ञानमण्डल यन्त्रालय, वनारस ४५४६–११

कृष्ण कुमार

को

(जिनकी सहायता विना मेरे लिए यह पुत्तक समाप्त करना असम्भव हो जाता)

भूमिका

प्रस्तुत पुस्तक, जैसा कि उसके नामसे विदित है, पिछले १०० वर्षोंकी भारतीय राजनीतिका इतिहास है। इन १०० वर्षोंमें भारतका राजनीतिक मंच बहुधा संघर्षमय और रक्तरंजित रहा। अनेक दलों और व्यक्तियोंने अपने-अपने ढंगसे राष्ट्रीयताको, स्वराज्य सम्बन्धी संघर्षको तथा अपने जाति-हितोंको प्रोत्साहन दिया।

अंग्रेजी राज्य स्थापित होते ही लोग उसके विरुद्ध सग्रस्त्र विद्रोहकी तैयारी करने लगे। प्रायः सदैव ही भारतके किसी न किसी कोनेमें अंग्रेजी राज्यको उखाड़ फेंकनेकी योजनाएँ वनती रहीं। 'वें विद्रोह न व्यापक थे और न सुसंघटित; इसीलिए वे असफल रहे। दूसरी ओर प्रायः आरम्भसे ही अंग्रेजी शासनके प्रभावमें आये शिक्षित वर्गने वैधानिक संघर्षका रास्ता अपनाया। दोनों ही प्रकारके संघर्षोंसे अंग्रेज शासक परेशान रहे। जबसे वैधानिक संघर्ष उनके लिए चिन्ताका कारण बना तभीसे उन्होंने भारतके रहनेवालोंमें आपसी मतभेदोंको प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। इसके फलस्वरूप साम्प्रदायिकताकी राजनीतिका एक नया अध्याय खुल गया। ज्यों-ज्यों संघर्ष आगे बढ़ता गया त्यों-त्यों नयीनयी राजनीतिक पेचीदिंगियाँ पैदा होती गयों।

यदि हम इस कालके राजनीतिक इतिहासपर एक सरसरी दृष्टि डालें तो देखेंगे कि १८५७-५८ के राष्ट्रीय विद्रोहके बाद भी वहाबी मुसलमान अंग्रेजी शासनको उखाड़नेके लिए संघटन और सशस्त्र संग्राम करते रहे। दूसरे प्रकारके संघर्षका आरम्भ, जिसका रूप वैधानिक था, १८३७ में जमींदारी एसोसिएशनकी स्थापनाके साथ हुआ । इसके बाद नयी-नयी संस्थाएँ वनती और विगड़ती रहीं। संघर्षका स्थायो सिलसिला १८७६ में गुरू हुआ जब मुरेन्द्रनाथ बनजीने राजनीतिमें पदार्पण किया और इण्डियन एसोसिएशनकी नीव डाली। अंग्रेजों द्वारा भारतका आर्थिक शोपण और भारतीयोंका अपमान अधिकाधिक वढ रहा था, जनता परेशान थी। अतः एक वार फिर लार्ड लिटेनके शासनकालमें सशस्त्र विद्रोहकी तैयारी होने लगी । ऐसी स्थितिमें स्वयं वाइसराय डफरिनने मोचा कि कांग्रेस जैसी संस्थाका जन्म होना चाहिये जिससे सम्पूर्ण देशके शिक्षित लोगोंका ध्यान वैधानिकताकी ओर आकृष्ट हो जाय। पर जिस वेगसे कांग्रेस आगे वढ़ी वह अधिकारियोंके लिए असहा हो गया और उन्होंने मुसलिम सम्प्रदायवादको जन्म दिया। वंगभंग, आतंकवाद, हिन्द्-मुसलिम दंगे, मुसलिम लीगकी स्थापना, ये सब उसी नीतिके फलस्वरूप अस्तित्वमें आये । प्रथम महायुद्धके कालमें तो विदेशोंसे प्राप्त हथियारोंसे अंग्रेजी सत्ताको समाप्त करनेके कई प्रयत्न किये गये। वास्तवमें इस प्रकारकी तैयारी तो भारतीयों द्वारा इंगलैण्ड, अमेरिका, जर्मनी आदि देशों में १९ वॉ शतान्दीके अन्तसे ही हो रही थी । परन्तु प्रथम महायुद्धके वाद गान्धीजीके नेतृत्वमें राष्ट्रीय संग्रामकी गति पहाड़से उतरती हुई नदीकी भाँति सहसा तेज हो गयी और अगस्त १९४७ तक उसमें सर्वदा नया वल आता गया।

जब मेंने देखा कि भारतकी इस रोमांचकारी राजनीतिका वर्णन कहीं एक स्थानपर प्राप्त नहीं है, तो मैंने सोचा कि समय मिलनेपर मैं विखरी हुई सामग्रीको एक पुस्तकके रूपमें एकत्र करूँगा । मैंने दो वर्षतक परिश्रम किया और प्रस्तुत पुस्तक उसीका फल है। मैंने विभिन्न भाषाओं, विशेषकर अंग्रेजीकी सैकड़ों पुस्तक-पुस्तिकाओं और पत्र-पित्रकाओं यह सामग्री लेकर निष्पक्षतापूर्वक पाठकोंके सामने रख दी है, जिससे गत १०० वर्षोंकी राजनीतिकी गतिविधि आसानीसे समझमें आ जाये। मैंने प्रस्तावनामें १८५७ के विद्रोहके ३५० वर्ष पूर्वके इतिहासकी एक झलक भी पृष्ठभूमिके रूपमें दे दी है। यह तो राजनीतिके विद्वान ही बता सकते हैं कि मैं अपने प्रयत्नमें कहाँतक सफल हुआ हूँ।

इस पुस्तकके तैयार करनेमें मुझे श्री कृष्णकुमार मिश्र, श्री सुरेशचन्द्र भिश्र व छुमारी मिसला मिश्रसे असाधारण सहायता मिली हैं। इनके सिवा श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तवने भी पुस्तकके सम्पादनमें विशेष परिश्रम किया है। में इन सब मित्रोंका अति आभारी हूँ।

विषय-सूची

प्रस्तावना—विक्टोरियासे पूर्वके इतिहासकी एक झलक	***	१
१—वहावी क्रान्ति व कुका विद्रोह	•••	३८
- २—िहन्दू सुधार आन्दोलन एवं राजनीतिक नाग्रति	•••	५५
३—वैयानिक आन्दोलनका आरंभ	•••	६१
४आर्थिक शोषणके राजनीतिक परिणाम	•••	७२
🕂 ५—भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 🗸	•••	98
र्-भारतीय कांग्रेसकी शक्ति-चृद्धि	•••	206
७ आतंकवादका आरम 🗸	***	१२९
८—मुस्लिम सम्प्रदायवादी राजनीति	•••	१४७
९—वंगभंग और वहिष्कार आन्दोलन	•••	१५८
१०—मुसिळिम लीग	•••	१७५
११कांग्रेसमें फूट	•••	१८५
१२—कान्तिकारियोंका कियाकलाप	•••	१९६
१३—दक्षिणी अफ्रिकाका सत्याग्रह	***	२१६
१४—कांग्रेस-लीग-एका—लखनऊ-समझौता	***	२२८
१५गदरका षड्यंत्र	•••	२४१
१६—होमरूल आन्दोलन	***	२५२
१७पंजाव हत्याकाण्ड	•••	२६८
१८—[खलाफत व असहयोग आंदोलन	***	२८४
र्९—स्वराज्य पाटीं	•••	३०२
२० साम्प्रदायिक वैमनस्य पुनः आरंभ	•••	३१६
२१—सःयाग्रह	. •••	३३७
२२लगानवन्दी आंदोलन	• • •	346
२३—फिर आतंकवाद	••,•	३७२
२४—समाजवादी व कम्यूनिस्ट पार्टियाँ	***	३७६
२५कांग्रेस द्वारा पदग्रहण	***	३८३
२६—भारतीय रियासतोंमें आन्दोलन	• • •	383
२७—मुसलिम लीगका अभियान	• • •	३९९
२८युद्धविरोधी सत्याग्रह तथा किप्स-प्रस्ताव	• • •	888
२९अगस्त-विद्रोह	•••	४ई०
२०आजाद हिन्द फीज	•••	४४३
२१—कैविनेट मिशन	***	886
३२—भारत स्वतंत्र	***	४६६
33	***	808



प्रस्तावना

विक्टोरियासे पूर्वके इतिहासकी एक भलक

पिछले सौ वपोंकी भारतीय राजनीतिका उचित मृत्यांकन, उसके विकासका पूरा ज्ञान, उसके ठीक पहलेकी परिस्थितिके समझे विना सम्भव नहीं । मुगल साम्राज्यका उत्कर्प और पराभव तथा ईसाई ताकतोंका उदय और अस्त वे बुनियादें हैं, जिनपर इस कालकी भारतीय राजनीतिकी इमारत खड़ी है । और ये दोनों बुनियादें लगभग साथ ही साथ पड़ीं । मुगलोंके पैर जमनेके लगभग चौथाई शताब्दी पहले ही दक्षिणमें पुर्तगाली आ चुके थे । उस समय देशकी जो हालत थी उसने इन दोनोंका स्वागत ही किया—एकका व्यापारमें, दूसरेका शासनमें । इन दोनोंके सत्तासम्पन्न होनेके लिए देशकी परिस्थित आक्चर्यजनक रूपसे अनुकूल थी ।

१६वीं सदीके आरम्भमें यहाँ एक वैसी ही उथल-पुथल चल रही थी जैसी केन्द्रीय शासन-शक्तिके हासके बाद इस देशमें कई बार हुई। तुगलक खानदानके पतनके बाद, तुगलक साम्राज्य भी छिन्न-भिन्न होकर ऐसी इकाइयोंमें वँट गया था जिनमेंसे हर इकाई एक स्वतन्त्र देशकी तरह व्यवहार करती थी। दिल्लीका वादशाह अपने आसपासके सिर्फ एक छोटेसे इलाकेपर राज्य करता था। आपसी लड़ाइयाँ, होप, और वैमनस्य उस समयके राजनीतिक दृश्यका मुख्य अंग था। इस आपसी ईर्ष्या, द्वेष, मय और वैमनस्यसे उत्पन्न परिस्थिति लालची विदेशियोंके लिए वड़ी सुविधाजनक थी। सिर्फ कुछेक हजार दिलेर, वेहतर हिथयारोंसे छैस विदेशियोंने आसानीके साथ एकके वाद दूसरा क्षेत्र जीतना शुरू किया। यदि ये इकाइयाँ संयुक्त होतीं तो उनका मुकावला करना असंभव हो जाता; चूँकि वे विभाजित थीं, वे वाल्के घरोंदोंकी तरह अरअरा कर गिरती गयीं । विदेशियोंने उनके पारस्परिक भय और द्वेपका फायदा उठाकर उन्हें एक दूसरेके खिलाफ भड़का कर एक दूसरेसे मिलने नहीं दिया। भारतको एक शासनसत्तामें संगठित करनेके प्रयास एक हजार सालसे विफल होते आ रहे थे। कभी कभी कोई कुशल राजा अपनी महत्त्वाकांक्षाकी पृत्तिके लिए अपना साम्राज्य देशके वड़े भागपर फैला लेता। इस साम्राज्यमें देशके विभिन्न भागोंको एकेके आधारपर एक राजनीतिक सूत्रमें वाँघनेकी इच्छा नहीं होती थी। साम्राज्यका अस्तित्व उक्त महत्त्वाकांक्षी राजाके गुणोंपर निर्मर रहता था। जब कोई कमजोर युवराज गदी सम्हालता, साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो जाता । मुगलों और पुर्तगालियोंके आनेके समय देशकी यही हालत थी।

१५वीं सदीके आखिरी दिनोंमें पुर्तगालियोंने भारत आनेका एक समुद्री रास्ता हूँ ह निकाला पृक्षिमी तटके निवासियोंने देखा कि ये विदेशी अरव व्यापारियोंका जहाजी वेड़ा नष्टभ्रष्ट किये डाल रहे हैं क्योंकि वे भारतीय निर्यात व्यापारकी इजारेदारी अरव व्यापारियोंसे छीन लेना चाहते हैं। छः सौ वपोंसे यह इजारेदारी अरवोंके पास थी। वे मक्का जाने आने वाले तीर्थयात्रियोंके यातायातका प्रवन्ध भी करते थे। वे यात्रियोंको जहा और व्यापारके मालको स्वेजमें उतारते थे। स्वेजसे केंटोंपर लदकर यह माल सिकन्दरिया जाता और वहाँसे वेनिस और जैनेवाके व्यापारी उसे भूमध्यसागरके तटीय देशोंमें अपनी नावोंमें पहुँचाते। दक्षिण भारतके बहुतसे राजा इस व्यापारमें दिलचस्पी रखते थे क्योंकि इन्हें हर विक्रीपर कर मिलता था। उन दिनों वाहर भेजी जानेवाली चीजोंके व्यापारका सबसे बड़ा अड्डा कालीकट था। कालीकटमें उन दिनों अरवोंकी वस्तियाँ थीं। अरव लोग मक्कासे कीमती सामान लाकर यहाँ उतारते और यहाँसे कालीमिर्च, मसाले, व दूसरी चीजें अपने साथ ले जाते और तुर्कां व पूरे यूरोपमें थे चोजें विकर्ती। अरवोंके धन और प्रभावके कारण देशी जनतामें उनकी अधिक प्रतिष्ठा थीं।

्युर्तगालियोंने भारतीय समृद्धि और व्यापारकी कहानियाँ सुनी थीं। इस दौलतकी खोजमें वे साहसिक यात्रापर निकल पड़े। वास्कोडगामाने होपकी खाडी (अफ्रिकाके दक्षिणमें) होकर भारतके लिए एक समुद्री रास्ता खोज निकाला, और वह करनेमें सफल हो गया जो कोलम्बस करना चाहता था पर न कर सका । र्यः अगस्त सन् १४९८ को बास्कोडगामाने सामान और हथियारोंसे भरा अपना वेड़ा कालीकटके किनारे लगाया । पुर्तगाली एक हाथमें वन्दूक और दूसरेमें विकीकी चीजोंका झोला लेकर आये थे। अरव उनसे भिन्न थे। वे भारतीय राजनीतिमें नहीं पड़ते थे और देशी राजाओंसे उनके मैत्री व सदभावना-पूर्ण सम्बन्ध थे । पुर्तगालियोंने अर्योंको प्रतिद्वनद्वी माना और अर्योंने पुर्तगालियोंको । पुर्त-गाली लेखकोंके अनुसार अरव व्यापारियोंने राजाओं और राजदरवारोंमें अपने प्रभावका इन नवागन्तुकोंके विरुद्ध प्रयोग किया। उस जमानेमें राजाओं और उनके अहलकारींको दी गयी भेंटों और सोगातोंका वडा महत्त्व था। इनसे वड़े काम निकल्ते थे। वास्कोडगामाको अपने विरूद हो रही साजिशोंका आभास हुआ और वह होशियार हो गया। अपने आगमनके उद्देश्योंको छिपानेके लिए उसने यह कहानी गढ़ी कि हमारा वेड़ा तो बहुत वड़ा था पर हम मुख्य वेडेसे विछुड़ गये और उसीको हुँढते हुए यहाँ आये हैं? । लेकिन कालीकटके राजा जमोरिनने पुर्तगालियोंका स्वागत ही किया । जमोरिन उनसे प्रभावित हुए । पर अरव व्यापारियोंने जमोरिनके कर्मचारियोंको समझाया कि बहुत दूरके एक देशसे आये ये पुर्तगाली सिर्फ व्यापार करनेकी दृष्टिसे यहाँ नहीं आये हैं। वे देशकी देख समझकर लौट जायंगे और फिर हथियारों है है हो कर बड़ी संख्यामें छोटेंगे और ताकतसे देशपर कब्जा कर हेंगे तथा उसे खूटेंगे।

यह चेतावनी जमोरिनतक पहुँचायी गयी, पर वह असमञ्जसमें ही पहे रहे और सोचते रहे कि पूर्तगालियोंको व्यापारकी अनुमित देनेमें कोई बुराई होनेकी आशंका नहीं है। वास्कोडगामाने पूरी परिस्थितिको परखा, उसे अपने विरुद्ध पाया और उसने तय किया कि देश लौटकर ऐसा बेड़ा मेजूँगा जो कालीकटके राजा और असब व्यापारियों, दोनोंसे नियट सके। अगले वर्ष-पेड़ोअलवरेज कवरालके नेतृत्वमें भयानक तोप-वन्तृकोंसे लैस तेरह जहाजोंका एक शानदार वेड़ा, १२०० पूर्तगालियों और साथ ही राजाके लिए सौगात लेकर कालीकट

१. एफ० सी० डैन्वर्सः दि पुर्वगीन इन इण्डिया, भाग १, ५० ४८

पहुँचा। इन १२००में पुर्तगालके उस जमानेके सबसे वहादुर और मशहूर मल्लाह भी थे। कवरालको हुनम था कि वह जोर-जबरदस्तीसे अरवोंका व्यापारप्रमुख नष्ट कर दे और राजाको कीमती सौगातें देकर शान्तिपूर्ण तरीकोंसे व्यापारकी अनुमति हासिल कर ले। जैसे ही यह वेड़ा भारतीय समुद्रमें पहुँचा उसने अरव वेड़ेपर डटकर हमला वोल दिया। अरव जहाज नए-भ्रष्ट हो गये और उनके व्यापारकी कमर टूट गयी। पुर्तगाली हमले और नौ-सैनिक शक्तिकी खबर कालीकटके राजाके पास पहुँची और उसने फीरन उनसे मैत्री-संधि कर ली।

, पुर्तगालियोंने देशकी अर्थव्यवस्थामें अपना महत्त्व आते ही समझ लिया वि समझ गये कि विद्या हथियारों और अनुशासनवद्ध अपने सिपाहियोंकी मददसे अपना व्यापार और इसकेंपर अपना प्रभुत्व हम वेड़े मजेमें वढ़ा सकते हैं। और इसमें वे चूके नहीं। ईन्छ ही वपोंमें पूरे पिहचमी तटपर थोड़ी थोड़ी दूरपर उनके किले दिखाई पड़ने लगे।

हिन्दू राजाओंको उन्होंने समझा लिया था कि हम आपकी रक्षा और सहायता करेंगे। ये राजा तवतक खतरा न समझ सके जवतक इन किलोंसे तोपें न'चमकने लगीं।

✓सन् १५०० में उन्होंने कालीकटमें कारखाना खोला । तीन साल वाद उन्होंने वहीं एक किला वनाया जिसका प्रधान मशहूर पुर्तगाली अलफोंसों डि अलबुकर्क था । प्रीन् १५०६ में अल्बुकर्कने गोआपर कब्जा कर लिया। अव राजा लोग पुर्तगालियोंकी शक्ति समझने लगे थे । अरव व्यापारका अन्त हो ही चुका था; राजाओंने पुर्तगालियोंको दरवारींमें बुलाना ग्रुरू किया । कोचीनका राजा भी इनमें शामिल था । कोचीनमें पुर्तगालियोंने अपने राजनीतिक पड्यन्त्रके लिए उचित वातावरण पाया । उन्होंने राजासे कहा "कालीकटपर आपका कब्जा करवानेके लिए इम आपको हथियार और सिपाही देंगे।" भारतीयोंको तवतक वन्दक आदि आग्नेयास्त्रोंका प्रयोग नहीं मालुम था । पुर्तगाली यह प्रयोग जानते थे । इसलिए पुर्तगालियों-का सशक्त मित्रकी भाँति कृतज्ञतापूर्वक स्वागत हुआ । कोचीन और पुर्तगार्ल्योंकी संयुक्त फौजने कालीकटपर हमला बोल दिया । कई वार इन लोगोंको मुँहकी खानी पड़ी पर अन्तमें ये लोग विजयी हुए। कालीकट खुब लूटा गया और राजाका महल जला दिया गया। "भारत पहुँचनेके वाद पुर्तगाल्योंका हर कृत्य ऐसा था जिससे यूरोपीय देशोंके प्रति बुरी भावना वनती थी। उनके प्रसिद्ध सेनानी अल्बुकर्कका विना किसी झगड़ेके ओरमंजपर हमला वोल देना, जमोरिनमें संधि करनेके फौरन वाद कालीकटके एक जहाजपर कब्जा कर लेना, वरावर समुद्री डाकुओं जैसा व्यवहार करना और जो नाव, वजरा, जहाज मिले उसपर कम्जा कर लेना-ऐसी वातें हैं जिनसे पता चलता है कि पुर्तगाली राष्ट्रोंके अधिकारोंकी अवहेलना और उल्लंघन करनेकी एक सुनिश्चित योजना वनाये हुए थे। उनकी ये करन्तें इतिहासमें वेमिसाल थीं।"

जिन नये देशोंका पता लगाएँ उनमें कैथोलिक (ईसाई) धर्मका प्रचार करनेके लिए पुर्तगाली पोपसे वचनवद्ध थे। पीपकी इस आज्ञाका उन्होंने स्फूर्ति व कड़ाईसे पालन किया। जहाँ उनका प्रभुत्व या प्रभाव था वहाँ लोग जबरदस्ती ईसाई बनाये गये। देशी जनताके धर्ममन्दिर "नष्ट कर दिये गये। ऐसा लगता है कि उन्होंने आग और तल्यारके जरिये

रिपोर्ट आव दि सिलेक्ट कमेटी आन दि अफेयर्स आव दि ईस्ट. इण्डिया कम्पनी, भाग ६, अपेण्डिक्स २०, ए० २०० (१८३२).

प्रचार करनेका प्रयत्न किया ।" पुर्तगालियोंको हुगलीमें रहने और एक कारखाना वनानेकी इजाजत मिल गयी थी। वहाँ उन्होंने "पड़ोसके मुसलमानों और यात्रियोंको परेशान करना और सताना ग्रुह्म किया "समुद्रतटके जिन बन्दरगाहोंपर वे प्रमुख रखते थे वहाँ वे धन-जनको हाथ नहीं लगाते थे, पर जब कोई व्यक्ति नावालिक वचोंको छोड़कर मरता था तो उसकी सम्पत्ति और वचोंको वे अपने कब्जेमें ले लेते थे। ये बच्चे चाहे सैटयदके हों, चाहे ब्राह्मणके हों, उन्हें ईसाई और गुलाम बना लिया जाता था।"

धीरे-धीरे पुर्तगालियोंने चीन जापानसे होनेवाले व्यापारको भी हिथिया लिया, पिक्सिसे होनेवाला व्यापार तो पहले ही उनके अधिकारमें आ चुका था। कुछ समुद्री रास्ते पुर्तगालके राजाकी इजारेदारी घोषित कर दिये गये। पूर्वी अफीका, चीन और मसालेके द्वीपोंको जाने वाले भारतीय जहाज रोके जाते और सिर्फ पुर्तगाली परिमट पाने पर ही आगे वढ़ पाते। "उनकी इस नीतिका उद्देश्य था भारतीय मालके अस्य और फारसकी खाड़ी होकर यूरोप पहुँचनेमें वाधा डालना और इस पुराने रास्तेको तोड़कर पूरा माल अपने लग्ने रास्ते ले जाना। इस लग्ने रास्तेको किफायतसे चलानेके लिए ज्यादासे ज्यादा माल ले जाना जहरी था, और उसके लिए दूसरे ज्यापारियों और दूसरे रास्तोंपर रोक जहरी थी। इस प्रकार वे पूरे व्यापारको अपने उस राजनीतिक प्रभावके मातहत लाना चाहते थे जो उन्हें भारतीय द्वीपों और प्रायद्वीपके किनारेकी रियासतोंपर अपने हिथारों और युद्धप्रणालीके कारण मिला था।""

पुर्तगाली व्यापारकी एक वड़ी मद थी गुलामोंकी विक्री । "दुर्माग्यवश पुर्तगाल और यूरोपके अन्य देश गुलामी और गुलाम व्यापारके अन्यायके प्रांत अभी सचेत नहीं हुए थे। अफ्रीकामें पुर्तगाली युद्धोंके समय हवशी और मूर लोग. युद्धवन्दियोंकी तरह पकड़े जाते थे और गुलामोंके रूपमें लिसवनमें वेच दिये जाते थे। भारतमें पुर्तगालियोंने गुलामोंकी खरीदके लिए अड्डे वना रखे थे। गोआमें हर पुर्तगाली परिवारमें गुलाम स्त्रियाँ पायी जाती थीं। इन गुलाम स्त्रियोंको कभी-कभी मिटाई वेचने और दूसरे तरीकोंसे अपने स्वामियोंके लिए रुपया कमानेके लिए वाजार भी जाना पड़ता था। 3%

वादमें तो यह गुलाम व्यापार नैतिक पतन और अत्याचारकी पराकाष्ट्रापर पहुँच गया था। हुगलीमें कारखाना वनानेकी इजाजतके वाद वहाँ उन्होंने किला वनाकर तोपें लगा दी थां। ''तभी गोआ तथा अन्य पुर्तगाली शहरोंके पतित वादशाहों और गुण्डों, फौजी भगोड़ों और मटोंसे निकाले गये महन्तोंने गंगाके मुहानेके टापुओंपर छोटी छोटी छोंगियाँ लेकर समुद्री डाकुओं, छटेरों और वुर्दाफरोशोंकी तरह रहना शुरू किया था। ये लोग सुन्दरवनमें महामारीकी तरह छाये हुए थे। ये लोग डेल्टापर वसे गाँवोंपर छापा मारते और पूरे गाँवकी आवादीको गुलाम वनाकर पकड़ ले जाते। बारातें पकड़ ले जानेका इन्हें विशेष शौक था। उसमें गहना, कपड़ा भी हाथ लगता था। हुगलीके पुर्तगाली इतने नीच थे कि डाकुओंसे इन अभागोंको खरीद लेते और गोआ भेज देते थे। गोआमें रोज गुलामोंके नीलाम होते।

^{9.} वही पुस्तक, (रिपोर्ट आव दि सिलेक्ट कमेटी ...) भूमिका, पृ० ३६

२. इलियट और डासन, दि हिस्टरी आव इण्डिया ऐज़ टोल्ड वाइ इट्स ओन हिस्टोरियन्स, भाग ७, पृ० २११

३. ऐनल्स आव दि आनरेविक ईस्ट इण्डिया कम्पनी, भाग १, पृ० ४१

४. ं जे. टालवॉयज़ व्हीलर, इण्डिया अण्डर विटिश रूल (१८८६) ए० १९

मुन्दरवनके बदमाश छुटेरे और हुगलीके पवित्र व्यापारी दोनों अपनी आत्माकी शान्तिके लिए अपने इन शिकारोंको ईसाई बना छेते । वे शानसे कहते, हमने इनकी आत्माको नर्कसे बचाया है।" छेकिन इसी जमानेमें मुगलोंने शासनसूत्र अपने हाथमें छे लिया था और उन्होंने गुलामोंकी विक्रीपर रोक लगा.दी।

१६वी शताब्दीके शुरू होते होते तैमूरलंगका भारतीय साम्राज्य खत्म हो चुका था और देशकी अराजकता बाहरी संगठित शक्तियोंको यहाँ धावा बोलनेके प्रलोभन दे रही थी। तैमरका वंशज वावर तुर्की तोपोंकी मददसे कावल और समरकन्दपर कव्जा जमा चुका था। सन् १५२५ में वह भारतके उत्तरी मैदानपर उत्तर आया । कुछ भारतीय मुस्लिम राजाओंने उसे भारतपर आक्रमण कर उसे फतह कर छेनेकी दावत भी दी थी। इससे वावरकी जीत आसान हो गयी । उसे दिल्लीके कुछ अमीरोंने भी सहायताका वचन दिया था । पानीपतके मैदानमें एक वहुत वड़ी फौज उसके मुकावलेके लिए आयी, पर अधिक अच्छे हथियारों और भारतीय मददसे वावरकी विजय हुई और उसने दिल्लीपर कब्जा कर लिया । भारतमें वह एकके वाद दुसरी लड़ाई जीतता गया और उसने सुगल साम्राज्यकी नींव डाली। अकवरके जमानेमें (१५५६-१६०५) मुगल साम्राज्य अपने चरम उत्कर्षपर पहुँचा । न्याय, माल और शासनकी सुगठित प्रणालियाँ प्रचलित हुईं। अकवरमें राज्य चलानेकी विलक्षण प्रतिभा थी। इतिहासमें वह इस कालका सबसे शानदार, आकर्षक और विशिष्ट व्यक्ति माना जाता है। "उन सभी पक्षपातों से मुक्त जिनसे समाजमें झगड़े और भेद पैदा होते हैं, दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु, दूसरी जातियों और देशोंके लोगोंके प्रति निष्पक्ष, अकवर ही ऐसा था जो अपने साम्राज्यके परस्पर विरोधी तत्वोंको एक स्त्रमें वाँधकर उसे सशक्त और समृद्ध इकाई बना सकता था-उसकी प्रतिभा चतुर राजनीतज्ञको तरह एकीकरणको प्रतिभा यी। उसका सामाज्य मुगल, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, हिन्दू सवर्ण, अछूत या राजपूत साम्राज्य नहीं, भारतीय साम्राज्य था।" विभिन्न शासकोंसे वैवाहिक या राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर उसने अपने राज्यकालमें शान्ति कायम रखी।

रैयतकी तरफ मालगुजारी वस्ल करनेवालोंका क्या रवैया हो, इस सम्बन्धमें जारी किये गर्ने एक आदेशसे अकवरके दृष्टिकोणकी झलक मिलती है।—"वे अपनेको काश्तकारका सबसे बड़ा दोस्त समझें, उन्हें वीचके दलाल रखनेकी जरूरत नहीं होनी चाहिये, जरूरत पड़नेपर जरूरतमन्द किसानको वे रूपया उधार दें और उसकी वस्ली सहज और छोटी किस्तोंमें करें, कुशल प्रवन्धके लिए वे इनाम दें, मालगुजारी हमददीं और सद्भावनासे वस्ल की जाये, परेशान करनेवाले कर न लगाये जायें, जितनेपर तय हुआ हो उससे ज्यादा कर न वस्ल किये जायें।"

पुर्तगाली अकवरके क्रपापात्र हो गये थे, पर वादमं अकथरने अनुभव किया कि विदेशी नागरिकोंको देशकी अर्थ और नीतिकी व्यवस्थामें हस्तक्षेप करने देना बुद्धिमानी नहीं है। वह उन्हें निकाल वाहर करना चाहता था, लेकिन दूसरे कामोंमें व युद्धोंमें व्यस्त रहनेके कारण वह ऐसा न कर सका। उसकी आशंका सस्य निकली जब सन् १५९५ में पुर्त-

*

1

१. वही पुस्तक, पृ० २०

२, एच० जी० वेल्स

२. . ई० पस० होट्डन, दि मुगल एस्पेरर्स भाव हिन्दुस्तान, ए० १५३

गालियोंने उसके वेटे सलीमको इलाहाबादका स्वतंत्र राजा वननेके लिए सहायता दी।
पूर्तगाली और वादमें आनेवाले अन्य विदेशी व्यापारी मुगल वादशाहोंके कोधसे सिर्फ इस
कारण वचे रहे कि वे नगण्य शक्तिवाले थे औरू दूर-दूर बस्तियोंमें रहते थे। उन्हें खत्म
करनेके लिए एक वड़ी फौज मेजना वड़े खर्चका काम था और साथ ही वीचमें पड़नेवाली
अन्य रियासतोंसे मुपतकी लड़ाई होती।

अकवरके जमानेमें ही यूरोपके दो अन्य देशों (हालैण्ड और इक्कलैण्ड) के नागरिक भारत आये। इनका आगमन पूर्तगालियोंकी लगभग १०० सालकी व्यापारिक इजारेदारीके वाद हुआ। जनतक हालैण्ड स्पेनके अधीन था, वह भारतीय माल तिन्नतसे खरीदता रहा। लेकिन स्पेनसे स्वतन्त्र होने और सन् १५८० में स्पेन और पुर्तगालके मिल जानेपर लिस्वनके वाजार उसके लिए वन्द हो गये। उच्च व्यापारियोंके जहाज पूर्तगाली सरकारने छीन लिये थे और उनके मल्लाहोंको केंद्र कर लिया था। एक कैंदी उच्च कतानने जेलमें ही भारतीय समृद्धि और व्यापारका वर्णन पुर्तगाली नाविकोंसे सुना। उसने पहली वार उच्च-भारत व्यापार सम्बन्धोंकी कल्पना की। यह कतान जेलसे भाग निकला, अपने देश आया और उसने भारतीय व्यापारसे अजित पुर्तगाली समृद्धिका वर्णन किया। उच्च लोग उत्साहित होकर आठ जहाजोंका एक वेड़ा बनाकर पूर्वके लिए रवाना हो गये। इनमेंसे चार जहाज होपकी खाड़ी होकर चले और चार उत्तरी पूर्वी रास्तेसे। होपकी खाड़ी आनेवाले जावा जा निकले। उन्होंने पूर्वसे उच्च व्यापारका सूत्रपात किया। सन् १५९८ तक उच्च पूर्वी द्वीप-समूहमें अच्छी तरह जम चुके थे। भारतमें उन्होंने कालीकट और मद्रासमें कारखाने खोले। धीरे-धीरे उनके और कारखाने भी वनने लगे।

यह पूर्तगाली व्यापारका पराभव-काल था। इस अवनितके कारण वताते हुए उनके भारत-स्थित गवर्नर अलफाँ जो डी सो जाने लिखा है—''पूर्तगाली एक हाथमें तलवार और दूसरेमें सलीव (सूली) लेकर भारत आये। यहाँ उन्होंने सोना देखा, और सलीव फेंककर सोना भरने लगे। जब जेवें इतनी भर गयीं कि एक हाथसे सम्हल न सकीं, तो उन्होंने तलवार भी फेंक दी। वादमें आनेवालोंने उन्हें इसी हालतमें पाया और आसानीसे हरा दिया।"

डचोंने पुर्तगालियोंके जहाज जला दिये, उनकी वस्तियोंपर कब्जा कर लिया, उन्हें खदेड़ दिया। विदेशी व्यापार वढ़ानेकी दृष्टिसे अकबरने पुर्तगालियोंको प्रोत्साहित किया था। उसे विदेशी वहुमूल्य धातुओं, घोड़ों और ऐशो-आरामकी दूसरी चीजोंकी जरूरत थी। पर जब पुर्तगालो उत्पात देखें तो उसने डचोंसे दोस्ती कर ली। अकबरके बेटे जहाँगीरने न्र्जहाँके कारण अँगरेजोंको अधिक पसन्द किया। न्रजहाँ नील और कढ़े हुए कपड़ोंका व्यापार करती थी जो अँगरेजी व्यापारियोंके द्वारा निर्यात होते थे।

पुर्तगाली वैभवकी गाथाएँ इङ्गलैण्ड भी पहुँचीं । अँगरेज व्यापारी जल्दीसे जल्दी पूर्वके लिए कूच करना चाहते थे । पचास वर्षतक अँगरेज नाविक उत्तरी पिक्चिमी रास्तेसे हिन्दुस्तान पहुँचनेकी असफल कोशिश करते रहे । सन् १५७८ में सर फ्रांसिस ड्रेकने भारतसे लौट कर तिब्बत जाते हुए एक पुर्तगाली जहाजको पकड़ लिया । उस जहाजपर मिले नक्शोंसे होप अन्तरीपके रास्तेका पता ड्रेकको लग गया ।

सन् १५९९ में कुछ व्यापारियों, छहारों, वजाजोंने २०१३३३ पौंड पूर्वसे व्यापार करनेके लिए इकटठे किये और एक संघ बनाया । अगले वर्ष उन्हें महारानीसे एक चार्टर (अधिकार-पत्र) मिल गया, जिसके अनुसार (यदि राष्ट्रहितमें हुआ तो) वे १५ वर्षके लिए पूर्वके साथ व्यापार करनेका एकाधिकार पा गये। यदि यह व्यापार इंगलैंडके लिए लाभदायक न हुआ तो चार्टर दो सालकी नोटिसपर खत्म किया जा सकता था। वैभव-सम्पन्न व शक्तिशाली मुगल साम्राज्यकी उत्तराधिकारिणी ईस्ट-इंडिया कम्पनीकी बुनियाद इस प्रकार पड़ी। कम्पनीके डायरेक्टरोंने तय किया कि ''जिम्मेदारीके किसी भी कामपर किसी भलेमानुसको नियुक्त न किया जाय।'' उन्होंने यह भी इच्छा प्रकट की कि हमें अपने ढंगके आदिमियोंकी मददसे ही व्यापार करने दिया जाय, नहीं तो यह आम धारणा वन जाने पर कि यह भलेमानुसोंकी कम्पनी है, बहुतसे साहसिक ओर दुर्दमनीय व्यक्तियोंका सहयोग कम्पनीको न मिल सकेगा।

भारत पहुँचनेवाले पहले वेहेकी कमान कप्तान हॉकिसके हाथमें थी जो सन् १६०८ में स्रतके वन्दरगाहमें आकर लगा। हॉकिस इंगलेंडके वादशाह जेम्स प्रथमका एक पत्र भारतके नाम लाया था। तव जहाँगीर वादशाह था। हॉकिसको अच्छा सत्कार और सम्मान मिला। पर मुगल दरवारमें पुर्तगाली पादिरयोंको अंग्रेजोंके खिलाफ साजिश करते देखकर वह स्रत लीट गया। इतिहासकी पुनरावृत्ति हुई और सन् १६१२ में कप्तान टामस वेस्टके अधीन चार अंग्रेजी जहाजोंका वेड़ा पुर्तगालियोंसे मोर्चा लेने आ धमका। जैसे १०० साल पहले पुर्तगालियोंने अरव वेड़ेको खत्म किया था, वैसे ही अंग्रेजोंने पुर्तगालियोंके वेडेपर कब्जा कर लिया। पुर्तगालियोंके व्यवहारसे जनता पहलेसे ही खिन्न थी। डच पहले ही वादशाहकी, विशेषकर न्रजहाँकी निगाहसे गिर चुके थे। अंग्रेज डच-पुर्तगालियोंकी खाली जगहोंपर व्यापारकी इजारेदारी करने आ पहुँचे और उनका स्वागत हुआ। ६ फरवरीको ईस्ट इंडिया कम्पनी और वादशाहके वीच संधि हुई जिसके अनुसार एक अंग्रेज राजवृत मुगल दरवारमें रहने लगा।

कोई २०-४० सालमें ईस्ट इंडिया कम्पनीके कारखानोंका एक जाल-सा भारतीय समुद्रके किनारोंपर विछ चुका था। सन् १६२२ में अंग्रेजोंने ईरानके शाहसे दोस्ती कर फारसकी खाड़ीमें आधिपत्य जमा लिया। इससे पुर्तगाली प्रतिष्ठाको वड़ा धका लगा, और अगले ४० वर्षोंमें पुर्तगाल अव्वल दरजेसे गिरकर तीसरे दरजेकी व्यापारिक शक्तिके रूपमें रह गया।

सूरत उन दिनों मुगल व्यापारका महत्त्वपूर्ण केन्द्र था । मुगल व्यापारियों के जहाज फारसकी खाड़ी और लालसागरके लिए यहाँसे रवाना होते थे । ब्रिटिश नाविक और वद-दिमाग अंग्रेज कभी-कभी एशियावासियों के लिए नफरत जाहिर करते..... कुछ बाहरी अंग्रेज कम्पनीके चार्टरकी अवज्ञा कर मनमाना व्यापार करते, मुसलमान तीर्थ-यात्रियों के जहाज लूट लेते, उनके साथ दूसरे अत्याचार करते । मुगल अधिकारी इसके लिए कम्पनीके कर्मचारियों को दोषी टहराते । उन्होंने बड़ी संख्यामें अपने सिपाही मेजकर अंग्रेज वस्तीपर घेरा डलवा दिया और काफी जुर्माना न मिलनेतक खाना, पानी, व्यापार सव बंद करवा दिया।

सन् १६३९ में डे नामक एक अंग्रेज व्यापारीने कारोमंडल तटपर एक हिन्दू राजासे ५०० पींड सालाना किरायेपर ६ मील लम्बी और एक मील चौड़ी जमीनकी पट्टीको पट्टेपर ले लिया । यहाँ एक किला बना जिसमें तोषें चढ़ायी गयीं । किलेका नाम था फोर्ट सेण्ट जार्ज । इसीके आसपास एक व्यापारिक केन्द्र वन गया और वादमें यही केन्द्र मद्रासके नामसे मशहूर हुआ ।

बाहजहाँकी वादबाहतके जमानेमं हुगलीमं और उसके आसपास पुर्तगालियोंके उत्पात और अत्याचार एकएम वह गये। वादबाहने वंगालके स्वेदाग्को पुर्तगालियोंको संजा देनेका आदेश दिया। बाही फौजने हुगलीको वेर लिया। पुर्तगाली मारे गये, कैद हुए और हुगलीसे उनका नाम निद्यानतक मिट गया। अंग्रेजोंने इनकी जगह वंगालमें व्यापार करनेकी अनुमित माँगी और प्राप्त भी कर ली। लेकिन उन्हें भारी कर देने और हुगलीतक अपने जहाज न लानेकी दार्त माननी पड़ी।

तभी अंग्रेजोंके सोभाग्यसे शाहजहाँकी पुत्री वीमार पड़ी । शाहजहाँ उन दिनों अपनी वेटीके साथ दक्षिणमें ही था । वजीरने स्रतसे एक अंग्रेज डाक्टर वोटनको बुलाया जिसने शाहजादीका इलाज कर उसे चंगा कर दिया । शाहजहाँने डाक्टरको मुँहमाँगा इनाम देनेका वादा किया । उसने देशभिक्तकी एक वहुत ऊँची मिसाल पेश करते हुए कहा कि अंग्रेजोंको वंगालमें विना कर दिये व्यापार करने और कारखाने खोलनेकी इजाजत दी जाये । डाक्टरको शाही फर्मान मिल गया जिसे लेकर वह शाहजहाँके वेटे शाहग्रजाके, जो उन दिनों वंगालमें स्वेदार था, दरवारमें पहुँचा । उन्हीं दिनों ग्रुजाके हरममें एक महिला वहुत ज्यादा वीमार थी । डाक्टर वौटनने उसे भी चंगा कर दिया और शाहग्रजाने कृतज्ञतापूर्वक डाक्टरको हर सम्भव सहायता वंगालमें स्थायी रूपसे अंग्रेजी व्यापारप्रमुख कायम करनेके लिए दी ।

जहाँगीरके दरवारमें आये ब्रिटिश राजदूत सर टामस रोने सन् १६१६ में लिखा था— "यहाँ १०० से अधिक जातियाँ और धर्म हैं, पर वे अपने सिद्धान्तों या पूजाविधिपर झगड़ते नहीं । हर एकको अपने ढंगसे अपने ईश्वरकी आराधना करनेकी पूरी छूट है । धर्मके कारण सताया जाना यहाँ अज्ञात है।"

सारी शासनसत्ता मुगल वादशाहोंमें केन्द्रित थी। उनका कथन ही कानृत था और वादशाहका विरोध अधिक सवल हथियार ही कर सकते थे। शासनकाममें वे अमीरोंसे मदद लेते थे।

शाहजहाँका राज्य जनताके लिए वड़ा समृद्धिशाली वताया जाता है। मालगुजारी वादशाहकी आमदनीका मुख्य स्रोत थी। यह शाही खर्चके लिए काम आती थी; जनताके हितमें, उसे सुविधाएँ देनेके लिए नहीं।

हजारीं वपोंसे मालगुजारीपर वादशाहका न्यायोचित अधिकार माना जाता था। वड़े-वड़े धर्ममीर और नैतिक लोग भी स्वीकार करते थे कि यह तो राजाका अंश है, उसे वह चाहे जैसे खर्च करें। किसानोंका भी यहीं दृष्टिकोण था। इस अधिकारके वदलेंमें राजाका क्या कर्चल्य है, यह प्रश्न ही नहीं उठता था। जो वादशाह मालगुजारीकी दर न वढ़ाता, किसानोंको जिसके नौकर परेशान न करते और जो गाँवके जीवनमें हस्तक्षेप न होने देता, उसे ही जनता अच्छा शासक मानती थी। किसान लोग वस उतनी ही उपजको अपना हक मानते जो मालगुजारीसे वच रहती। युद्धमें विजयी राजा विजित राजासे जो जुर्माना, चौथ आदि वस्त्ल करता था वह किसानोंकी गाढ़ी कमाईसे ही आता।

जान पिंकरटन : ए जेनरल कलेक्सन आव दि बेस्ट ऐण्ड मोस्ट इण्टरेस्टिंग वायजेज,
 पृ० ३२१, ४९५ (१८११)।

इन खर्चोंसे जो कुछ बचता उसीसे ग्रामीण जीवनकी अर्थव्यवस्था चलती। इस आर्थिक ढाँचेसे जो जीवनस्तर बना बही जनताके सुख और सन्तोपका मापदण्ड हो गया। इसी बचतमेंसे गाँव अपनी रक्षाका भी बन्दोवस्त करते। इसीमें अपने सामाजिक, सांस्कृतिक व स्वायत्तवासन सम्बन्धी काम पूरे करते। सरदार, स्वेदार और लड़ाकू राजा युद्धके समय भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शान्ति भंग न करना चाहते। कुछ विजयी राजाओंने तो फौजों द्वारा हुए गाँवके नुकसानोंको पूरा करनेके लिए श्वतिपृतिके रूपमें रकमें भी दीं। "उस जमानेमें राज्यतन्त्र या राजा मालगुजारी वस्ल करने और पुलिसका काम करनेके बाद अपने कर्त्तव्यकी इतिश्री समझ लेते। निर्माणकार्य या सामाजिक व आर्थिक विकासके कोई काम राज्य अपने हाथमें न लेता। जवतक वादशाहकी आशा-उल्लंघन या कोई दूसरा वड़ा सुर्म न हो जाय, राज्य ग्राम्य जीवनमें हस्तक्षेप न करता। अगर गाँव सरकारको परेशान न करता तो सरकार गाँवको न छेड़ती। गाँव सदियों पुराने जीवनका दर्श शान्तिमय ढंगसे चलाते जाते।"

मुगलकालके इतिहासमें इस वातके उदाहरणोंकी कोई कमी नहीं है कि वादशाह फसलमें अपना हिस्सा वस्ल कर लेनेके वाद जनताको शेप भागका उपयोग करनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता ही न देते विक्क इसके लिए भी सचेए रहते कि इस स्वतन्त्रताका कोई अपहरण न करने पाये। इस सम्बन्धमें वे ऊँची नितकता और उत्तरदायित्वकी भावना रखते। कर्मचारियोंको आदेश थे कि वे शाही नीतिको ईमानदारीके साथ अमलमें लाये। मालगुजारीका वकाया छोटी-छोटी किस्तोंमें वस्ल किया जाता। एक वार जमीनके एक खित्तेका दरसे ज्यादा लगान शाही खजानेमें जमा देखकर शाहजहाँ इतना कोधित हुआ कि उसने उस अफसरको वरखास्त कर दिया और ज्यादा जमा हुई रकम कारतकारको लीटा दी।

"शाहजहाँ और औरंगजेवके जमानेके कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि रैयतकी शिकायत बादशाहतक पहुँचने पर, कड़ाईसे ज्यादा मालगुजारी इकट्ठी करनेवाले अफसर और कमी कभी तो स्वेदारतक बरखास्त कर दिये गये।" मुगलकालमें हर नये स्वेदारको हुक्म मिलता था कि "रैयतको खेती और पैदाबार बढ़ानेमें बढ़ाबा दो ताकि वे पूरे दिल्से खेतीमें लग सकें। उनसे कुछ ऐंटनेकी कोशिश न करो। बाद रखो कि रैयत ही आमदनीका स्थायी साधन है… "यह देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ताकतवर गरीवको दवाने न पायें।" यह नाथ सरकारकी तरह ही स्टेनले लेनपूलने लिखा है— "इस बातका ख्याल रखा जाता था कि जिनसे ज्यादा अनुचित कर बस्ल कर लिया गया हो, उन्हें अपनी शिकायत अपरतक पहुँचानेमें मुश्किल न पड़े, जो ज्यादा रक्म बस्ल कर लें उन अफसरोंको कड़ी कड़ी सजा दी जाती थी।" इतने लम्ने-चोड़ और फैले हुए साम्राज्यों वादशाहका हुक्म कड़ाईसे पालन कराना, उसके अनुसार कार्य कराना बड़ा कटिन था, और इसलिए इधर उधर अनेक भ्रष्टाचार इत्यादिके मामले वने रहते थे।

एक जमानेसे मालगुजारीकी दर धीरे-धीरे बढ़ायी जा रही थी । हिन्दू राज्यकालमें यह कर कुल उत्पादनका छठाँ हिस्सा था । मुसल्मि शासनकालमें कर बढ़ता ही गया । अकबरफे

१. यदुनाथ सरकार, दि मुगल ऐडिमिनिस्ट्रेशन, ए० १३-१४

२. मिडीवल इण्डिया अंडर मुहम्मडन रूल, पृ० २६३-६४

कालमें 'मालगुजारी' उत्पादनका एक तिहाई हो गयी, और और गजेवके कालमें उपजका ५० प्रतिशत हो गयी।

कहा जाता है कि शाहजहाँ कालीन भारतकी धन-दोलत और समृद्धि दूर देशों के लोगों को आक्ष्यं में डाल देती थी। विशेष त्योहारों और अवसरोंपर तस्त ताउसपर वैठे को हन् र व जवाहरातसे सजे हुए शाहजहाँ के व दरवार के टाठ-वाट देखकर बुखारा, (ईरान) फारस, तुर्की, इटली, फांस आदिके विदेशी राजदूतों की वाँ खें चौंधिया जाती थीं। परन्तु उस ऐश्वर्य और खुशहालीको जनताकी खुशहालीका प्रमाण नहीं समझना चाहिये। फिर भी वँधे हुए कर अदा कर देने के बाद जनताको कोई परेशान न करता था और लोग वेफिकी, शान्ति और स्वतन्त्रतासे जीवनयापन करते थे। गाँव स्वावलम्बी और स्वतन्त्र आर्थिक इक्षाई होते थे। प्रत्येक गाँवमें एक वहे-वूढ़े लोगोंकी समा होती थी जिसे पंचायत कहते थे। स्थानीय आवश्यकतानुसार यह पंचायत न्याय, कानून और शासनका सब कार्य देखती थी। गाँवके कामगर इत्यादि उस आर्थिक जीवनका अंग होते थे। उन्हें या तो पैदावारका एक माग मिलता था, या मालगुजारी से मुक्त जमीन। गाँवकी इस संघटित व्यवस्थाका एक वड़ा लाभ यह था कि कोई भूखों नहीं मरता था। किसी के पास यदि किसी फसलमें कोई काम न होता तो भी संघटित प्रणाली से उसे भोजन तो मिल ही जाता था! राजसिंहासन-पर वादशाह आते रहते और राजवंश वदलते रहते पर जनताक जीवनमें कोई उलट-फर न होता था।

चाहे क्टनीतिके कारण हो या वास्तवमें जनताकी भावनाओं के आदरके लिए, मुगल सम्राटोंने अपने व्यवहारसे लोगोंको विश्वास दिला दिया था कि उनके धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप न किया जायगा और इस नीतिसे दिली-सम्राटोंको भी विश्वास हो गया था कि जनता राजनीतिक मामलों में उदासीन रहेगी। इस प्रकार संघर्षकी परिधि महत्त्वाकां श्वी पदाधिकारियों व पड़ोसी राज्योंतक ही सीमित रहती थी।

परन्तु जहाँगीर और शाहजहाँ वह पक्षपातरिहत व्यवहार और दृष्टिकोण न निभा सक्के जो उनके प्रख्यात पूर्वज अक्रवरकी नीति थी । कुछ अवसरोंपर ऐसा प्रतीत होता है कि वे हिन्दु और सिक्खोंके प्रति अनुदार थे ।

सिखधर्मकी नींव गुरु नानकने पन्द्रहवीं शताब्दीमें डाली थी। गुरु नानक वास्तवमें एक सुधारक थे। उनके अनुयायी राजनीतिक प्रति उदासीन रहते थे। वे हिन्दू मुसलमान दोनोंसे कहते थे कि "हम न हिन्दू हैं न मुसलमान; हम सब एक ही मालिकके वन्दे हैं।" सिखोंके गुरु वास्तवमें अपने विश्वासके प्रति निष्ठा व साहसके इतिहासमें ज्वलन्त उदाहरण हैं।

चौथे गुरुके समयतक सिख लोग नितान्त धार्मिक और सुधारक समुदायकी तरह रहे। परन्तु पाँचवें गुरु अर्जुनदेवसे जहाँगीर नाराज हो गया। उनका अपराध सिर्फ यही था कि उन्होंने जहाँगीरके विद्रोही पुत्र खुसरोको शरण और सहायता दी थी। गुरु अर्जुन-देवको इस 'विद्रोह व धृष्टता" के लिए मृत्यु-दण्ड मिला।

शाहजहाँके समयके इतिहासमें कई मिन्दिरोंके मिरजदमें परिवर्तन किये जानेका विवरण मिलता है। हो सकता है कि इसकी जिम्मेदारी औरंगजेवपर हो क्योंकि ये घटनाएँ दक्षिणकी हैं जहाँ इस समय औरंगजेव स्वेदार था। मुछा छोग भी कभी-कभी कुचकों और गन्दी हरकर्तोमें भाग लेते थे, पर यह सव अपवाद मानकर नजरअन्दाज कर दिया जाता था और इस तरह हिन्दू मुसलमानोंके आपसी सम्बन्ध सद्भावपूर्ण वने रहते थे।

मुस्लिम दरवारों में और हिन्दू राजाओं, दोनोंके यहाँ हिन्दू व मुसलमान दोनों ही शासकीय एवं सैनिक पदोंपर नियुक्त होते थे और अवसरानुसार अपने प्रमुओंकी खातिर हिन्दू मुसलमानोंके और मुसलमान हिन्दुओंके कंधेसे कंधा मिड़ाकर अपने धर्म-भाइयोंसे रणक्षेत्रमें लोहा लेते थे। उनको भाड़ेके सिपाही कहना अन्याय होगा। हिन्दू और मुसलमान एक ही जन-कुटुम्बके थे। यह तो वहुत बादमें हुआ कि मुसलमान लोग इस्लामी राज्योंके धार्मिक रूपसे समर्थक बन गये। उन दिनों हिन्दू मुसलमान जनसाधारण मेल-मिलाप और सोहार्दके साथ आपसमें मिलकर रहते थे। ब्रिटिश शासनकालकी तरह हिन्दू मुस्लम दंगे उस समय कभी नहीं हुए।

गुरु अर्जुनदेवके प्रति जहाँगीरके निर्दय व्यवहारने सिखोंको सैनिक रूपसे संघटित होनेके लिए प्रेरित किया। स्वयं अर्जुनदेवने भी ऐसा ही अनुभव किया और अपने पुत्र और उत्तराधिकारी हरगोविन्दको यथासंभव एक वड़ी और संघटित सेना रखनेका आदेश दिया। शहीद गुरुका यह आदेश उनकी अन्तिम इच्छा वन गया और प्रतिशोधकी भावनासे प्रेरित गुरु हरगोविन्दने अपने शिष्योंमें सैनिक उत्साह भरा जिससे थीड़े ही समयमें उनके पास एक सुसजित और दढ़ सेना तैयार हो गयी। इस सेनाकी प्रायः ही शाही सेनासे मुठभेड़ होती, और बहुधा जीत भी सिखोंके हाथ रहती। एक वार गुरु गोविन्दको पकड़नेमें जहाँगीर सफल भी हुआ पर वे किसी प्रकार निकल भागे।

शाहजहाँके बाद उत्तराधिकारका फैसला लगभग सदैव ही तलवारने किया। विजयी युवराज खूनकी नदी पार करके ही गद्दीतक पहुँचता था। स्वयं शाहजहाँने अपने भाइयों व रिश्तेदारोंके खूनसे हाथ रंगकर ही तल्त प्राप्त किया था। इन अभागोंके कटे सिर जनताको आतंकित करनेके लिए शहरमें घुमाये जाते थे। अकवरके बाद प्रायः प्रत्येक युवराजने सिंहासन-प्राप्तिके लिए पितासे विद्रोह किया। जहाँगीरने पिताके सबसे अधिक प्रिय सहायक अबुल-फजलको मरवा डाला और स्वयं अकवरके खिलाफ विद्रोह किया। शाहजहाँने भी जब वह शाहजादा था, पिताके विरुद्ध विद्रोह किया था। उसे तभी क्षमा किया गया जब उसने जमानतके रूपमें अपने दो पुत्रोंको, जिनमें एक औरंगजेव था, न्र्जहाँके पास रख दिया।

जिस समय मुगल खानदान आपसी वैर और युद्धों में लगा हुआ था, यूरोपीय व्यापारी भारतमें अपनी स्थित मजवूत बनानेमें लगे थे, पर शाही सैनिक शक्ति फिर भी बहुत मजवूत थी और यह करपना भी न हो सकती थी कि यूरोपनाले भारतमें अपना सिन्का जमा सकेंगे। और गंजेनके शासनकालमें फांसके व्यापारी भी भारतमें आये, और स्वभावतया, डच, पुर्तगाली और अंग्रेज व्यापारियोंके साथ देशके वाहरी व्यापारमें हिस्सा बटाने लगे। सन् १६६४में फांसीसी मन्त्रो कोलवर्टने "कम्पनी-डी-इण्डीज" नामक एक व्यापारिक संस्था संघटित की जिसे फांसके राजा चौदहनें छुईने ५० वर्षतक भारतसे व्यापार करनेका एकाधिकार दे दिया। उसने इस कम्पनीको सभी प्रकारके करोंसे मुक्त कर दिया, और दस वर्षोतंक उसके सारे घाटे और हरजाने सरकार द्वारा भरे जानेका बचन भी दे दिया।

अन्य यूरोपीय व्यापारियोंकी माँति फ्रांसीसी भी पहले स्रतमें आये और उन्होंने १६६८ में वहाँ एक कारखाना कायम किया । वे भी काफी तौरपर सरास्त्र थे । फ्रांसीसी व्यापारियोंके भारतमें आनेसे पहले ही एक भारतीय सरदारने एक पुर्तगाली किले, सेण्ट टोमको जीत लिया था । फ्रांसीसी वेदेने सन् १६७०में इस किलेपर धावा वोल दिया और उसे जीत लिया । कुछ ही काल वाद एक डच वेदेने इस किलेको फ्रांसीसियोंसे छीनकर फिर गोलकुण्डाके भारतीय सुस्तानके हवाले कर दिया ।

अकवरके वादके तीन मुगल वादशाहों के कालमें अंग्रेज व्यापारियोंने अपनी जड़ें मजबूतीसे जमा ली थीं और सत्रहवीं शताब्दों के उत्तराई में उनका व्यापारिक केन्द्र मद्रास एक स्वतन्त्र उपनिवेश वन गया । अंग्रेजों के इस केन्द्रके पास एक भारतीय वस्ती भी पनपने लगी जिसपर अंग्रेज हुकूमत करने लगे । कम्पनीके हाथों वम्बई प्रायः विना प्रयास ही आ गया । सन् १६६१ में पुर्तगालके राजाने इंगलैण्डके राजा चार्ल्स द्वितीयको वम्बईका इलाका अपनी पुत्रीके दहेजमें दे दिया और चार्ल्सने वम्बईको कम्पनीके हाथ वेच डाला । कम्पनीने अपना स्रतका केन्द्र वन्द करके वम्बईमें नया केन्द्र जमानेका निश्चय किया जो टापू होनेके कारण अधिक सुरक्षित वन्दरगाह था और जहाँसे लाल सागर व अरवकी खाड़ीका व्यापार भी सुगम था । इसके अलावा स्रतका व्यापारिक महत्त्व भी राजपूतों और औरंगजेबकी शत्रुता, हमलों, और नित्यके झगड़ोंके कारण घट रहा था । इन युद्धों और लूटमारके कारण आगरा और स्रतके वीच व्यापार कठिन हो गया था । दक्षिणमें शिवाजोंके उत्थानके फल-स्वरूप कुछ सुगली इलाकोंकी व स्रतकी स्थित बहुत अरिक्षित हो गयी थी ।

ऐसा लगता है कि स्रतमें ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी ख्याति अच्छी न थी। एक अंग्रेज लेखकने लिखा है—"अंग्रेजोंकी हिंसा और वेईमानीके कारण हिन्दू और मुसलमान दोनों ही अंग्रेजोंको उन वड़े कुत्तोंसे भी अधिक जंगली व भयानक समझते थे जिन्हें अंग्रेज रखवालीके लिए अपने साथ लाये थे। वे अपने वापको भी घोखा दे सकते थे और उसी तत्परतासे वन्दूकों चला सकते थे जिस प्रकार वे माल या रुपया लूट सकते थे'।" एक दूसरे स्थानपर वही लेखक कहता है—"परन्तु टेरीके अनुसार ईसाई धर्मको भारतके लोग बहुत ओछा समझते थे।" टेरीने यह भी स्वीकार किया है कि "भारतीय स्वयं बहुत ईमानदार और वादेके पक्के होते हैं। अगर किसी वस्तुके लिए दूकानदार द्वारा बतायी हुई कीमतसे बहुत कम दामपर देनेको कहा जाता तो अक्सर वे जवाव देते—क्या हमें ईसाई समझ लिया है जो तुम्हें घोखा देंगे।"

वंगालमें जहाँ अंग्रेजोंने अपना एक कारखाना खोल दिया था, न्यापार बहुत ही लाभदायक था। कम्पनी सिर्फ वंगालके लामसे वम्बई, मद्रास तथा अन्य कारखानों व किलेबन्दीका खर्च पूरा कर लेती थी। इसी समय औरंगजेबकी शक्तिशाली सत्ता कम्पनीके रास्तेका रोड़ा बन गयी। उस समय शोरा, कच्चा रेशम, अफीम और ढाकेकी मलमल ही व्यापारकी मुख्य वस्तुएँ थीं। "यह मलमल इतनी बारीक और बढ़िया बनती थी कि हाथकी अँग्ठोंके बीचसे एक पूरा थान निकाला जा सकता था। सभी सुन्दरियोंकी यह अभिलापा होती थी कि उनके विवाहकी पोशाक इस हल्के मलमलकी बनी हुई हो।" औरंगजेबने, जो राजनीतिक कारणोंसे अन्य मुस्लिम देशोंसे मित्रता बनाये रखना चाहता था, शोरेका व्यापार इसलिए रोक दिया कि यही शोरा युद्धोंमें मुसलमानोंके विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता

१. रेवरेण्ड फिलिप ऐण्ड्रसन—दि इंगलिश इन वेस्टर्न इण्डिया, पृ० ८८

था । सम्राटका यह कार्य कोई अनोखा न था; पर अंग्रेज अपनी शक्ति और महत्त्वके धमण्डमें फूले हुए थे, अतः उन्होंने इस आदेशके विरुद्ध झगड़ा करनेकी ठान ली ।

उनको क्रुड करनेकी एक बात और हो गयी । कम्पनीको व्यापारिक रिआयतें उदार शाहलहाँने एक भावकतापूर्ण अवसरपर दे डाली थां । ये रियायतें भारतीय व्यापारियोंके लिए तथा राज्यकी करवस्लीमें अत्यन्त हानिकर सिद्ध हो रही थीं। कोई भी इस प्रकारकी रिआयत सदैवकें लिए नहीं दी जा सकती। औरंगजेवके जमानेमें शाइस्ताखाँने, जो उन दिनों बंगालका स्वेदार था, कम्पनीके मालपर एक नया कर लगा दिया।

अंग्रेज क्रोधसे भर गये। उन्होंने खोयी हुई रिआयतोंको अपनी सैनिक शक्तिके जोरसे फिर प्राप्त करनेका इरादा किया। उनके पास आधुनिकतम हथियार थे, जिन्हें वे शिक्षित सिपाहियों सहित मराठों तथा औरंगजेव तकको दिया करते थे। मौका अच्छा था, क्योंकि उस समय औरंगजेवकी फौजें युद्धके अन्य मैटानोंमें फँसी हुई थीं। इसीसे अंग्रेजोंने वंगाळपर हमळा करनेकी हिम्मत की।

सर जोसियाह चाइल्डको जो कम्पनीके डाइरेक्टरोंके अध्यक्ष थे, कम्पनीके घाटेकी रिपोर्ट मेजी गयी। उन्होंने इंगलेण्डके सम्राट्की आंश्रासे मुगल फौजपर हमला करनेका आदेश दे दिया। तुरन्त ही "यथासम्भव सबसे बड़ा लड़ाकु बेड़ा जमा करके मारत खाना कर दिया गया। यह बेड़ा ब्रिटेनसे पूर्व आनेवाले बेड़ोंमें सबसे बड़ा था। वेहेकी कमान एडिमरल निकलसनको दो गयी। वेहेमें १२ सामरिक जहाज, २०० तोपें और ६०० सैनिक थे। ४०० सैनिकांकी एक दुकड़ी उन्हें मद्राससे मिलनेवाली थी। निकलसनको आदेश था कि वह फौरन धेरा डालकर चटगाँवको जीत ले और फिर आस-पासकी भूमिपर कब्जा हासिल करे। जमींदारोंको बहला-फुसला ले, एक टकसाल चाल करे और अराकानके राजाके साथ सन्धि कर ले, अर्थात् संक्षेपमें इसका अर्थ यह हुआ कि निकलसन वहाँ अंग्रेजी राज्य स्थापित करे।"

चाइहडने यह भी आदेश दिया था कि चटगाँवके घेरेके अतिरिक्त मक्का जानेवाले जहाज भी पकड़ लिये जायँ। चाइहडने सोचा कि औरंगजेय तंग होकर समझीतेके लिए वाध्य हो जायगा। उसका ख्याल था कि अति धार्मिक होनेके कारण सम्राट् मक्काका रास्ता वन्द होनेसे बयड़ा जायगा। परन्तु "सर जोस्थिश चाइहड औरंगजेवकी चालाकी और योग्यताका टीक अन्दाज न लगा पाया। उस तीक्ष्ण बुद्धिवाले सम्राट्के जास्स सब ओर फैले हुए थे। कभी-कभी तो वह अनेक घटनाओंका आभास इतना सही और पूर्ण रूपसे लगा लेता था कि लोग सोचने लगते थे कि शायद सम्राट्का किसी दैवीशक्तिपर अधिकार करूर है।"

व्योंही अंग्रेजी जहाजोंने मुगली जहाजोंको पकड़ना शुरू किया, औरंगजेबने स्रतके कारखानेके कर्मचारियोंको पकड़वा लिया और धमकी दी कि यदि मुगली जहाज छोड़ेन जायँगे और साथ ही एक वड़ी रकम हरजानेके रूपमें न दी जायगी तो सब कर्मचारियोंको मौतके घाट उतार दिया जायगा। अंग्रेजोंके सामने शुकनेके सिवा कोई चारा न रहा।

ऐडिमिरल निकल्सन तो अपने उद्देश्यमें असफल रहा, परन्तु अपनी महत्त्वाकांका

१. मार्शमैन, हिस्ट्री आव इण्डिया, जिल्द १, ५० २५१

२. जे. टालवॉयज व्हीलर, इण्डिया भण्डर बिटिश रूल, पृ० २६

पूरी करनेके लिए दृढ़प्रतिज्ञ डाइरेक्टरोंने कप्तान दीथके नेतृत्वमें नयी कुमक मेजी। हीथने आते ही हुगली कारखानेके छंचालक जॉब चारनॉक और सभी कर्मचारियोंको व्यापारिक माल सहित हटा लिया और फिर तमाम मुगल जहाजोंको पकड़कर उनपर अधिकार कर लिया। हुगली नदीके मुहानेपरके एक नगरपर गोलावारी की। शाइस्ता खाँ घवड़ाया; जलयुद्धका उसे विलकुल अनुभव न था। उसने डरकर समझौतेकी शतें अंग्रेजोंके सामने पेश कर दीं। अंग्रेजी बेड़ा तब अराकानकी ओर बढ़ा और उसने वहाँके राजाको हराया; किन्तु अन्तमें अंग्रेजी बेड़ा हार गया और अंग्रेजोंको मुगलोंके सभी जहाज वापस करने पड़े। उन्हें एक बड़ी रकम हरजानेके रूपमें भरनी पड़ी।

अचम्मेकी बात है कि स्रत और हुगलीकी हारके वाद ही अंग्रेजोंने वंगालमें हृदताके साथ अपनी नींव डाली । अंग्रेजों द्वारा भविष्यमें ग्रान्तिपूर्वक रहने और सम्य व्यवहारकी प्रतिज्ञा करने पर उन्हें हुगली नदीके किनारे जमीनकी एक पट्टी खरीदनेकी हजाजत दे दी गयी। धरतीका यह दुकड़ा तीन मील लम्बा था और उसमें तीन गाँव भी थे। यही स्थान बादमें कलकत्तेके रूपमें विकसित हुआ और यहाँ एक किला बना लिया गया।

तत्कालीन इतिहासकी एक बड़ी भारी भूल यह हुई कि औरंगजेवने अंग्रेजी हमलेको नगण्य समझकर उसकी उपेक्षा की। उसको यह विश्वास ही न होता था कि अंग्रेजी व्यापारी किसी समय मुगल साम्राज्यके लिए वास्तिवक खतरा बन सकते हैं। जब कभी अंग्रेजी एडयन्त्रों और उनके बुरे इरादोंकी उसके सामने शिकायत की जाती तो वह धृणात्मक हँसी हँसकर उसे टाल देता था। जब उसे यह समाचार दिया गया कि अंग्रेज व्यापारी हुगलीके किनारे खरीदे हुए अपनी तीन गाँवोंकी किलेबन्दी कर रहे हैं तो उसने हँसकर कहा 'संभव है मेरे भारतीय प्रजाजन उनसे झगड़ते हों। वे व्यापारी जो अपनी मातृभूमिसे इतनी दूर अकेले पड़े हैं क्यों न अपनी रक्षाका प्रवन्ध करें। मैं कोई भी हस्तक्षेप न करूँगा।''

इस खतरनाक आत्म-विश्वासने वह बीज वो दिया जो काला-तरमें अंग्रेजी साम्राज्यके एक विशाल वृक्षके रूपमें विकसित हुआ।

औरंगजेवको अपनी शक्तिपर बड़ा विश्वास था किन्तु उसकी धार्मिक असहिण्युता एवं हठधमीका यह परिणाम हुआ कि अपने-अपने इलाकोंमें राजपूत, जाट, मरहठे व सिख वादशाहतके खिलाफ उठ खड़े हुए और औरंगजेव जिन्दगी भर लगातार उनसे - लड़नेमें फँसा रहा।

दक्षिणमें शिवाजीकी शक्ति बढ़ती गयी। उन्होंने पूरे २० वर्षतक औरंगजेवको हैरान रखा। शिवाजीके विरोधी इतिहासकार खफी खाँ के अनुसार "शिवाजीने अपने राज्यमें अपनी प्रजाकी इज्जत और मान वनाये रखनेका सदैव प्रयत्न किया, और अपने हाथ पड़े मुसलमान-स्त्रियों, बच्चोंकी इज्जतकी सदा रक्षा की। इस सम्बन्धमें उसके आदेश वड़े कड़े थे, और जब कभी किसीने उन आदेशोंकी अवज्ञा की, शिवाजीने उसे कड़ा दण्ड दिया।

उसने यह नियम बना लिया था कि युद्ध-कालमें जब उसके सिपाही लूट मार करें तो मिरजद, पवित्र कुरान और धार्मिक पुस्तकों और स्त्रियोंकी कोई हानि या अपमान न करें। जब कभी पवित्र कुरानकों कोई प्रति उसके हाथ पड़ती, वह उसे श्रद्धा और सम्मानसे रख देता और अपने किसी मुसलमान अनुयायीको दे देता।"

शिवाजीने कर लगानेकी प्रणालीको नियमित रूप दिया । मालगुजारी किसी अटकल-पर न लगाकर हर फसलकी उपजकै अनुपातमें लगायी जाती थी । भूमिका वर्गीकरण किया जाता था, और लगान हर फलसके बाद नियत किया जाता था ।

औरंगजेवके कालमें ही मुगलोंके प्रति सिखोंकी हणा भी पराकाष्टापर पहुँच गयी।
गुरु तेगवहादुरको, जिन्होंने शाही फौजसे मुटभेड़ ली थी, पकड़कर दिल्ली लाया गया। उनसे
कहा गया कि उनकी सजा धर्म-परिवर्तन या मौत है, वे इन दोनोंमेंसे एक चुन लें।
उन्होंने मृत्यु अधिक श्रेयस्कर समझी। इस गुरुके विल्दानने सिखोंको मुगलोंके खिलाफ
सैनिक ढंगसे संघटित होनेके लिए प्रेरित किया। गुरु गोविन्दसिहने जो तेगवहादुरके पुत्र
और उत्तराधिकारी थे, इसका जिम्मा लिया और एक इलाका जीत लिया। अवतकके सीधेसादे धार्मिक सिख अव लड़ाक हो गये और मुगलोंके लिए काँटा वन गये।

और गजेवके कठमुल्ले दरवारियोंको छोड़कर कोई भी उससे प्रसन्न नहीं था। उसमे अपने पिताको केंद्रमें डाला और अपने लड़कोंको भी विद्रोहके अभियोगमें जेलमें वन्द कर दिया। वह शिया मुसलमानोंसे हिन्दुओंसे भी अधिक घृणा करता था, यद्यपि शिया फिरकेंके सुसलमानोंसेंसे ही उसे योग्यतम उद्याधिकारी और वहादुर सेनापित मिले थे।

लेकिन फिर भी औरंगजेवको अपनी फाँज और शासकीय विभागोंमें हिन्दू, शिया तथा गैरमुस्लिम रखने पड़ते थे। वह उन लोगोंका विश्वास सुन्नी अफसरोंकी भाँति ही करता था। इसका सवृत यह है कि कभी-कभी ऐसी फाँजका सेनापित मी हिन्दू ही होता था, जो किसी हिन्दू राज्यपर धावा करने जाती थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दक्षिणके एक युद्धसे मिलता है। औरंगजेवका पुत्र मुअजम दक्षिणकी फाँजका, जो शिवाजीके इलाकेपर इमला करनेके लिए भेजी गया थी, सेनापित था। मुअजम असफल रहा। तव औरंगजेवने उसे हटाकर जयसिंहको सेनापित नियुक्त किया। जयसिंह शाहके प्रति अपनी निष्ठा दिखानेमें एक उचित सीमाको भी लाँच गया। उसने शिवाजीके अफसरोंको वहुत सी स्वर्ण मुझाओंका लालच देकर फोड़नेकी कोशिश की। पर वह इस कार्यमें युरी तरह असफल रहा। दोके सिवा सोनेके लोभमें कोई भी न आया, और ये दो भी मराठे नहीं थे।

यद्यपि औरंगजेवके जमानेमें प्रथम बार हिन्दुओंने वहैंसियत हिन्दूके अपना संघटन ग्रुक्त किया, पर मिली-जुली सेनाओंकी प्रथा जारी रही । शिवा जीकी सेना और कार्यालयोंमें सुसलमान भी थे, और इसी प्रकार औरंगजेवकी सेना और कार्यालयोंमें हिन्दू भी थे । इस विश्वाल देशके विभिन्न क्षेत्रोंमें, लगभग प्रत्येक गाँव और प्रत्येक नगरमें, हिन्दू और सुसलमान पड़ोसियोंकी भाँति शताब्दियोंसे प्रेमपूर्वक रहते आ रहे थे । कुछ हिन्दू विरोधी सुस्लिम शासकोंकी नीति दोनों सम्प्रदायोंके बीच कोई भेदभाव नहीं पेदा कर सकी । हिन्दू व सुस्लिम जनताने दर्जनों अच्छे और बुरे शासक गदीपर बैठते और हटते देखे थे, और अनुभवन से समझ लिया था कि किसी मुस्लिम शासकको हिन्दू विरोधी नीतिसे मुस्लिम जनताका कोई लाभ नहीं होता।

लगातार विद्रोह, क्रांति, युद्ध और हिन्दू राष्ट्रीयताके उदय होनेके वावजूद और गजेव साम्राज्यके डॉचेको वायम रखनेमें समर्थ रहा। "वह दुर्गुणों, काहिली और ऐशो-आरामसे अपनेको दूर रखता था। उसकी बुद्धि-प्रखरता अद्वितीय थी। वह राज-काज उतनी ही लगन और उत्साहसे करता था जितनी साधारण व्यक्ति ऐश करनेमें वर्तते हैं। कोई भी साधारण अहलकार सार्वजिनिक कार्योंमें, उसके समान परिश्रम नहीं कर सकता था और न उतनी तवजह से काम कर सकता था। उसका धैर्य और सहनशक्ति उतनी हो बढ़ी-चढ़ी थी जितनी उसकी अनुशासन-प्रियता। उसका संयम संतों जैसा था। फौजी मार्च या युद्धकी किठनाइयोंका वह एक अति अनुभवी प्यादेकी माँति चुपचाप मुकावला करता था। कोई भय उसे निरुत्साह नहीं कर सकता था, न कोई दया या दुर्वलता उसके हृदयको पिघला सकती थी। धार्मिक और नैतिक पुस्तकोंके अध्ययनसे जो ज्ञान अर्जित किया जा सकता है उसका वह सम्पूर्ण अधिकारी था।"

औरंगजेन अपने समयका एक महान् सुधारक था। जनसाधारणका नैतिक स्तर् ऊँचा उठानेके लिए उसने अनेक कान्न और नियम जारी किये थे। उसने तमालू, भंग और शराबका उत्पादन, विकी और प्रयोग कान्न द्वारा बन्द करवा दिये। वेश्याओं और नर्तिकयोंको शादी कर गृहस्थ बननेकी या देश छोड़ देनेकी आज्ञा दी। अश्लील गानोंका गाना जुर्म घोषित कर दिया। हिन्दुओंमें प्रचलित सती प्रथापर रोक लगा दी।

परन्तु ऐसे सुधारक बादशाहक ५० वर्षके राज्यकालका परिणाम असफलता और अराजकता हुआ । उसके जीवनकालमें ही साम्राज्यके ढाँचेमें दीमक लग गयी, और वह भर-भराकर गिर पड़नेकी स्थितिपर पहुँच गया । यह दृढ़ पुरुष जो भय और दण्डके जोरसे स्वेदारों व अन्य अफसरोंसे अनुशासन और सम्मान हासिल करता था, १७०७ में इस संसार-से उठ गया । अब प्रांतीय स्वेदार लोग एक-एक करके अपनेको दिल्ली-शासनसे स्वतन्त्र घोषित करने लगे, और उनकी इस नीतिने साम्राज्यका विनाश आसान कर दिया । एक बार फिर इतिहासने भारतको उसी राजनीतिक अराजकतामें देखा जो तुगलक साम्राज्यके मंग होनेके बाद बाबरके हमलेके समय पैदा हो गयी थी ।

औरंगजेबके बाद मुगल खानदानमें कोई ऐसा योग्य वादशाह न हुआ जो साम्राज्यके छिन्न-भिन्न टुकड़ोंको फिरसे एकत्र कर सकता। लगभग ३० वर्षमें ही मुगल सम्राट्केवल दिल्लीके आस-पासकी भूमिका ही शासक रह गया।

औरंगजेवके उत्तराधिकारियों में कुछमें उसका हिन्दू-विरोध पाया जाता है। परन्तु शासकों की मनोवृत्तिका हिन्दू-मुसलमानों के आपसी सम्बन्धपर कभी कोई प्रभाव न पड़ा। इस समय ब्रिटिश शासनकाल जैसे दंगे कभी नहीं हुए। मुसलमानों के दो वगों में एक हिन्दू के जपर एक वार दंगा अवश्य हो गया था। वह इस प्रकार हुआ—

"८ मार्च, १७२९ की शामको मुंशी शुभकरण, जो दरवारके जौहरी थे, अपने घर जा रहे थे। उनके रास्तेमें जूते वेचनेवालोंकी दूकानें पड़ती थीं। ये लोग सब पंजाबी कहर मुसलमान थे। उस समय वहाँ, मौसमकी प्रथाके अनुसार, हिन्दू मुसलमान सभी पटाखे छोड़ रहे थे। पटाखेकी एक चिनगारी जौहरीकी पालकीमें जा गिरी और उससे शुभकरणकी दरवारी पोशाकमें छेद हो गया। इसपर पालकीकी वगलमें चलनेवाले सिपाहियोंने विरोध किया; वात बढ़ी और उनमें और जूतेवालोंमें झगड़ा हो गया। सिपाहियोंके पास हथियार थे, और जूतेवाले अपने डंडोंसे लड़ रहे थे। पर क्योंकि जूतेवालोंकी संख्या बहुत अधिक थी, उन्होंने एक सिपाहीको पकड़कर उसकी ढाल-तलवार छीन ली। क्षुच्ध शुभकरणने घर पहुँच अपने आदिमियोंको जूतेवालोंसे बदला लेनेके लिए मेजा। शामको सिपाही अपने मित्रोंको

१. यदुनाथ सरकार, हिस्ट्री आव औरंगजेब भाग १, भूभिका, पृष्ठ १४

साथ लेकर ज्तेवालोंके मोहल्लेमं पहुँच गया। इन लोगोंने जाते ही एक लड़केको पीटना ग्रुरू कर दिया और इतना मारा कि वह मरणासन्न हो गया। वहाँके लोग इस लड़केको मुंशीके घर ले गये। मुंशी घवड़ा गया और उसने शाही खानसामा, शेर अफगन खाँ पानीपतीके महल्में जाकर शरण ली, जो कतवेमें उससे वड़ा था। उसके बाद एक मीड़ वादशाहके पास गयी और न्यायकी माँग की। वादशाहने अपराधीको गिरपतार करनेकी आशा दी, पर शेर अफगनने आशापालन करनेसे इनकार कर दिया। फिर शुक्रवारके दिन मसजिदमें भीड़ इकट्ठी हुई। शान्ति वनाये रखनेके लिए वर्जीरको घटनास्थलपर भेजा गया। शेर अफगन भी अपने अफगान साथियोंके साथ वहाँ पहुँच गया। भीड़ काफी उत्तेजित हो सुकी थी। एक दूसरेपर हमला शुरू हो गया, बहुतसे व्यक्ति घायल हुए। "रि परन्तु इस झगड़ेमें किसी हिन्दूका बाल बाँका न हुआ।

जब दिल्ली-दरवार पड्यंत्रोंमें व्यस्त था, पंजावमें सिख और दक्षिणमें मराठे अपनी-अपनी शक्ति संविदित कर रहे थे। शिवाजीसे मिलो राष्ट्रीयताकी भावना एवं सैनिक संविद्यके कारण मराठे एक प्रवल शक्ति वनते जा रहे थे। कुछ समयतक तो ऐसा लगा कि मुगल विजेताओंका सूर्य अस्त होकर उसकी जगह मराठा भाग्य-सूर्य उदय होनेवाला है। वे प्रायः समस्त भारतमें, तंजारसे वंगाल और दिल्लीतक हर स्वेदार व राजासे चौथ वस्ल करते थे। मुगल स्वेदार जो अपनी स्वतंत्रता घोषित कर चुके थे, मराठांसे बहुत ढरते थे।

मुगल राज्यके पतनके समय अंग्रेजी व फ्रांसीसी कम्पनियोंकी स्थित एक-सी ही थी। वंगालमें फ्रांसीसियोंके पास चन्द्रनगर या और अंग्रेजोंके पास कलकत्ता। कर्नाटकमें फ्रांसीसियोंके पास पांडिचेरी था और अंग्रेजोंके पास मद्रास । पश्चिमी घाटपर अंग्रेजोंका व्यापारिक केन्द्र वम्बई था और फ्रांसीसियोंका माही। अंग्रेजोंकी शक्ति व वैभवका आरम्भ हुआ दक्षिणसे, और वह अपनी पूर्णावस्थाको पहुँचा वंगालमें। दक्षिणमें उस समय वही हक्य उपस्थित हो गया था जो बहुधा दिर्छामें देखनेको मिलता था अर्थात् आपसी झगड़े और खनखरावी।

सन् १७१७ में मध्य भारतके दक्षिणी भागका एक वड़ा इलाका दिल्ली समार्ने एक गवर्नरके मातहत, जो 'निजामुल मुल्क' कहलाता था, कर दिया था। दिल्ली दरवार-की दुर्वलताका लाभ उठाकर निजामने प्रायः समस्त दक्षिणी भारत अपने कच्छोमें कर लिया, और स्वेदारकी जगह स्वतन्त्र शासक वन वैठा। कर्नाटकका नवाव उसके मातहत था। इस निजामने प्रायः ३१ वर्ष राज्य किया और उसका शासन पुराने सशक्त मुगलोंकी तरह अर्थत संबटित था। उसकी मृत्यु (१७४८) के पश्चात् दक्षिणमें अराजकता फेल गयी। अंग्रेज तथा फाँसीसी अलग अलग राजाओंका पक्ष लेकर झगड़ोंमें सम्मिल्ति हो गये। असलमें इन विदेशियोंने अपनी स्वार्थसिद्धिके लिए झगड़ेकी आग और भड़का दी। यूरोपमें ब्रिटेन-फांस युद्धके कारण भारतमें भी दोनों जातियाँ, एक दूसरेको निकालकर अपना प्रभुत्व जमानेके लिए, लड़ने लगीं। कुछ समय बाद यूरोपमें शान्ति हो गयी, तब अंग्रेजों तथा फांसीसियोंमें भारतमें भी सन्व हो गयी और उन्होंने एक दूसरेके जीते हुए स्थान वापस कर दिये।

इतिहासकार रावर्ट ऑर्मके अनुसार अंग्रेज भलीभाँति जानते थे कि भारत राजनीतिक हलचल और अरक्षित दशामें पड़ा हुआ है। वे अपनी शक्ति, कूटनीति और तिकड़मका

१. विक्रियम इरविन, कैटर मुगल्स, भाग २, पृ० २५७-२५८

वल समझते थे। इसिलए वे स्थानीय चुंगीकै नियमों आदिकी परवाह न करते और मन-माने ढंगसे व्यापारिक व्यवहार करते थे। किसी राजा या नवावकी परवाह न करते थे।

सन् १७५६में १९ वर्षीय युवक सिराजुद्दौला अपने नाना अलीवदीखाँकी मृत्युके परचात् वंगालकी गद्दीपर वैठा । मुगल साम्राज्यके पतनके कालमें वंगालका स्वेदार, वंगाल, विहार और उड़ीसाका स्वतन्त्र शासक वन वैठा था । "वंगालका स्वा उन दिनों संसारके सबसे अधिक उपजाक स्वोंमें समझा जाता था । इसकी भूमि मिससे भी अधिक उपजाक मानी जाती थी।"

सिराजुद्दौलाने वंगालमें अंग्रेजी इलाकोंपर हमला वोलनेका विचार किया। वह मुख्यतया तीन कारणों हमलेके लिए प्रोरित हुआ। (१) देशके निर्धारित नियमों के विरुद्ध अंग्रेजोंने नवावके इलाकेमें वड़ी मजवूत किलेबन्दी की है; (२) उन्होंने दस्तकके अधिकार का दुरुपयोग किया है—उन्होंने ऐसे लोगोंको दस्तक देना शुरू कर दिया जो उसके हकदार नहीं हैं। इसके फलस्वरूप नवावकी चुंगीकी आयमें काफी घाटा हो गया। (३) अंग्रेज ऐसे लोगोंको अपने यहाँ संरक्षण प्रदान करते हैं जो नवावके नौकर थे और जो कुछ अमियोगोंके लिए अदालतके सामने पेश किये जानेवाले थे। कम्पनीने उनको वापस करनेसे इनकार कर दिया।

इन कारणोंसे िसराजुद्दौलाने अंग्रेजोंको निकाल देनेका वीड़ा उठाया, और जूत १७५६में अंग्रेजी किलेपर हमला वोल दिया। अंग्रेजोंने विना किसी मुकावलेके आत्म-समर्पण कर दिया। कलकत्ता उनके हाथोंसे निकल गया और अंग्रेजी व्यापार प्रायः नष्ट हो जानेकी स्थितिपर पहुँच गया।

अव वंगालके इतिहासमें थोखा, जालसाजी, दमन और देशद्रोहका अध्याय आरम्भ हुआ; इन्हीं चार "साधनों" को सहायतासे भारतमें अंग्रेजी राज्यकी नींव पड़नेवाली थी। सिराजुद्दौला द्वारा पराजित होनेके पश्चात् अंग्रेजींने फुल्टा नामक स्थानमें जाकर शरण ली। उन्होंने सिराजुद्दौलासे प्रार्थना की कि उन्हें उस स्थानमें कुछ दिनोंतक रहने दिया जाय और वादा किया कि जब समुद्री यात्राके लिए मौसम टीक हो जायगा तो वे तुरन्त मद्रास चले जायँगे। इस बहाने उन्होंने गड़बड़ी करनेके लिए समय हासिल कर लिया। उन्होंने मद्रासमें कम्पनीके उच्च अधिकारियोंके पास अपनी पराजय और वर्तमान स्थितिकी स्वना मेज दी। मद्रासके अधिकारियोंके पास अपनी पराजय और १५०० भारतीय सिपाहियोंकी फौज रावर्ट क्लाइव और वाटसनके नेतृत्वमें वंगाल भेज दो। यह छोटी-सी फौजी दुकड़ी सिराजुद्दौलाकी ५०,००० मजबूत सिपाहियोंकी सेनाके सामने कुछ भी नहीं थी। इस समय फांस और इक्लिण्डमें पुनः युद्ध ग्रुरू हो गया था और भारतमें भी इसकी प्रतिक्रिया होनेकी आशंका थी। परन्तु कुछ भी हो भारतमें अंग्रेजी व्यापार और प्रतिष्ठा फिरसे कायम करना लाजमी था और यह काम विना धूर्ततापूर्ण तरीकोंके सम्भव नहीं था।

सिराजुद्दौलाने एक हिन्दू राजा मानिकचन्दको कलकत्तेका कन्जा दे दिया था। माल्म होता है कि सिराजुद्दौला जिम्मेदारीके लिए हिन्दुओंपर अधिक विश्वास रखता था। जब पुर्नियाके नवाव शौकतजंगने उसके विरुद्ध विद्रोह किया तो सिराजुद्दौलाने नवाबी पदके लिए एक हिन्दू युगलिकशोरको नियुक्त किया।

१. रैमजे म्योर, दि मेकिंग आव विटिश इण्डिया (१९२३) पृ॰ २९

क्राइव अपनी फौजके साथ २२ दिसम्बर, १७५६ को हुगली नदोके दहानेपर आ पहुँचा और उसने शीध ही नवाबकी एक विशाल सेनाको हराकर कलकत्ता फिरसे जीत लिया। रेवरेन्ड लांगकी पुस्तक, "सिलेक्शन फॉम दि गवर्नमेंट रेकार्ड् स" के अनुसार अंग्रेजोंने मानिकचन्दको खरीद लिया था। कुछ वपों वाद जब कम्पनीने मानिकचन्दके पुत्रको एक अच्छी जगहपर नियुक्त किया तो सिफारिशमें यह कहा गया कि मानिकचन्दने पिछले ३० वपोंमें कम्पनीकी बहुत सहायता की है।

सिराजुद्दौला सन्धिकी शर्ते तय करनेके लिए ४ फरवरी १७५७ को कुछ संरक्षक और एक छोटी-सी फौजी टुकड़ीके साथ कलकत्ता पहुँचा। उसके साथ उसका सेनापित मीर जाफर भी था जो अपने दिल्में स्वयं नवाव वननेकी कामना छिपाये हुए था। कलकत्ता पहुँचने पर सिराजुद्दौलाको अपने कुछ मुख्य अफसरों, विशेषकर मीर जाफरमें, शत्रुभावके चिह्न दिखाई पड़े। उसे मीर जाफरका वर्ताव बहुत आक्चर्यजनक लगारे।" अंग्रेजी अधिकारियोंने नवावके मुख्य अफसरोंकी साजिशसे उसकी फौजको अचानक रातमें धेरनेकी और नवावको गिरफ्तार कर लेनेकी योजना वना ली थी। परन्तु नवावको इन साजिशोंका कुछ भास हो गया और अपने एक विश्वासपात्र समर्थककी सलाह मानकर वह चुपकेंसे शिवरसे निकल भागा। अंग्रेजोंको इस बातका पता न लगा, और जब योजनाके अनुसार रातमें इमला हुआ तो नवावका कहीं पता न चला। एक बार फिर सिराजुद्दौलाने फौज एकत्र करके अंग्रेजोंसे मुकावलेको सोची, पर उसके मुख्य सलाहकारोंने जो कम्पनीसे रिश्वत ले चुके थे, उसे अंग्रेजोंके साथ सन्धि करनेकी सलाह दो। जो सन्धि हुई उसकी दो शर्ते इस प्रकार थीं—(१) अंग्रेजी कम्पनीका सम्पूर्ण माल विना किसी प्रकारकी चुंगी या अन्य करके मुक्तरूपे बंगाल, विदार व उड़ीसामें कहीं भी मेजा जा सकेगा। (२) कम्पनीको विला किसी रोक-टोकके अपनी रक्षाके लिए कलकत्ते की किलेबन्दी करनेका अधिकार होगा।

नवावको यह शर्त भी स्वीकार करनी पड़ी कि उसके मुर्शिदाबाद-स्थित दरवारमें कम्पनीका रेजीडेण्ट रहा करेगा। वाट्स इस पदपर नियुक्त कर दिया गया। बाट्सका असल काम दरवारके आकांक्षी तथा असन्तुष्ट व्यक्तियोंको स्वयं उनके तथा कम्पनीके हितके लिए फोड़ना था।

अव क्लाइवपर संधिकी शर्तें न पूरी करनेका अभियोग लगाया गया। वाटसनने शिकायत की कि नवाव शर्तोंका पालन नहीं कर रहा है। परन्तु स्वयं क्लाइवने स्वीकार किया है कि "सिराजुद्दौलाने सिन्धकी प्रायः सभी शर्तें पूरी की।" असलमें अंग्रेज चाहते थे कि सिराजुद्दौला फ्रांसीसी उपनिवेश उनके हवाले कर दे। सिराजुद्दौलाने उत्तर दिया कि "यह काम मेरी प्रतिष्ठाके विरुद्ध है। में ऐसा न करूँगा।" इस उत्तरसे अंग्रेज कृद्ध हो गये।

इसी वीच एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण सिराजुद्दीला मुसीवतमें फँस गया। उसे खबर मिली कि दिल्ली-सम्राट, बंगाल, विहार व उड़ीसाको अपने प्रमुखमें लानेके लिए वंगालकी ओर वढ़ रहा है। भयभीत नवाबने कम्पनीसे सहायता माँगी। कम्पनीने सहायता देनेका तुरन्त बादा कर लिया—वादा पूरा करनेके लिए नहीं किया गया था। वंगालके नवावपर काबू पा लेनेके वाद अंग्रेजोंको वस एक परेशानी बाकी रह गयी—वह थी फांसीसी प्रतिद्दियोंको निकाल भगानेकी। क्लाइव और वाट्सन अव इसी दिशामें काम कर

१. स्क्रेपटन, रिफ्लेक्शन्स, पृ॰ ६६

रहे थे। वाट्सके सहकारी स्कैपटनके लेखानुसार, वाट्सने, मुर्शिदावाद दरवारके अफ-सरोंको रिक्वत देकर एक जाली चिट्ठी तैयार की। उस चिट्ठीमें नवावकी ओरसे लिखा गया कि अंग्रेजोंको फांसीसी उपनिवेश चन्द्रनगरके विषयमें कोई मी काररवाई करनेकी पूरी आजादी है। सराजुद्दौलाको शाही हमलेके विषद्ध सहायता देनेके वहाने अंग्रेजोंने चन्द्रनगर पर हमला कर दिया और उसे जीत लिया। चन्द्रनगरमें कुछ नवावी फौज भी थी, जिसकी कमान नन्दकुमारके हाथमें थी। स्कैपटनका कहना है कि नन्दकुमारको भी रिक्वत दी ग्यी थी और इसीलिए उसने अपनी फौज चन्द्रनगरसे हटा ली थी।

अंग्रेजोंने चन्द्रनगर तो ले लिया, पर उन्हें सिराजुद्दौला बुरी तरह खटक रहा था; वे समझते थे कि सिराजुद्दौला अब भी उनके रास्तेमें वाधक होता है। वाट्सने सिराजुद्दौलाको हटानेकी तरकीव निकाल ली। उसने मीर जाफर (जो अंग्रेजोंसे मिला हुआ था) और एक पूँजीपित अमीचन्दका अपनी तरकीबको सफल बनानेके लिए प्रयोग किया। एक दिन वाट्स अचानक मुर्शिदाबाद दरबारसे गायब हो गया। इस अनोखी घटनाने सिराजुद्दौलाके दिलमें सन्देह पैदा कर दिया। उसने अपनी फौजको तैयारीका हुक्म दे दिया, और स्वयं मीर जाफरके पास जाकर बफादारी और प्रीतिमावके लिए प्रार्थना की। मीर जाफरने कुरान हाथमें लेकर कसम खायी कि में सदैव नवावके प्रति वफादार रहूँ गा। उसने इसी प्रकारकी कसम कलाइवके प्रति खायो थी। सिराजुद्दौलाको अब मीर जाफरपर सन्देह न रह गया और उसने उसे उस फौजकी कमान सौंप दी जो अंग्रेजोंसे लड़नेके लिए तैयार की गयी थी। अंग्रेजी फौज चन्द्रनगरसे १३ जून १७५७ को रवाना हुई। लड़ाई शुरू हो गयी परन्तु ज्यों हो नवावकी फौजें निर्णयात्मक हमला करने जा रही थीं, मीर जाफरने उन्हें लीट पड़नेका आदेश दे दिया। सिराजुद्दौला अब सब राज जान गया और अपनी जान बचाकर माग गया।

२५ जून १७५७ को मीर जाफरने, मुर्शिदाबादके शाही महलका कब्जा प्राप्त कर लिया। परन्तु क्लाइव नगरसे ६ मीलकी दूरीपर ही टहरा रहा। वह नगरमें प्रवेश करते हुए डर रहा था। इसकी वजह उसने वादको पार्लमेण्टरी कमेटीके सामने गवाही देते हुए बतायी; ''उस समय वहाँके निवासी दर्शकोंकी संख्या कई लाख थी; यदि वे चाहते तो डण्डों और पत्थरोंसे ही यूरोपीय लोगोंको खत्म कर सकते थे।''

जब लोग अपने-अपने काममें लग गये और वायुमण्डल शान्त हो गया तो क्लाइवने २०० यूरोपीय और २०० भारतीय सिपाहियोंके साथ नगरमें प्रवेश किया। उसी दिन संध्या समय वह मीर जाफरसे मिला। मीर जाफर लिहाजके मारे गदीपर न वैठा, और तभी वैठा जब क्लाइवने स्वयं उसे बैठाया। तब क्लाइवने नये नवाबको सलाम किया।

• खजानेका रुपया गिना गया—१ करोड़ ५० लाख था। मीर जाफरने अपनी सिन्धमें १ करोड़ ७० लाख रुपये कम्पनीको देनेका वादा किया जिसका आधा तुरन्त दे दिया, और शेष आधा तीन वार्षिक किश्तों द्वारा। ६ जुलाई १७५७ तक कम्पनीके डाइ-रेक्टरोंकी सिमितिको ७२,७१,६६६ नकद रुपये मिल गये। इस धनको ७०० वक्सोंमें वन्द कर नदी मार्ग द्वारा सिपाहियोंकी संरक्षतामें निदया मेज दिया गया। इससे पहले कभी भी विटिश राष्ट्रको इतनी वड़ी रकम एक मुश्त नहीं मिली थी।

१. रिक्के क्शन्स, पृ० ७०

२. ऑर्म्स हिस्टरी आव इन्दोस्तान, माग २, पृ० १८७-८८

सन्धिकी निम्नलिखित शर्तोंसे स्पष्ट है कि नया नवाव कम्पनीके हाथकी कटपुतली वन गया —

- (१) िराजुद्दौलाने जो शतें स्वीकार की थीं, मैं उन सबका पालन करूँगा।
- (२) अंग्रेजोंके दुस्मनींको में अपना दुस्मन समझुँगा चाहे वे भारतीय हों या यूरोपीय।
- (३) 'राष्ट्रोंके स्वर्ग' वंगालमें तथा विहार और उड़ीसामें फ्रांसीसियोंका जो भी सामान और फैक्टरियाँ हैं वे अंग्रेजोंके कब्जेमें रहेंगी और इन स्वोंमें में फ्रांसीसियोंको कभी भी वसने न हुँगा।
- (४) कलकत्ताकी विजय और लूटसे अंग्रेजी कम्पनीको जो भी हानि हुई और उसकी फौजपर जो खर्च हुआ उसके हरजानेके रूपमें में एक करोड़ रुपया दूँगा।
- (५) कलकत्ते के अंग्रेज निवासियोंका जो सामान छ्टा गया या उसकी क्षतिपूर्त्तिके लिए ५० लाख रूपया दूँगा।
- (६) कलकत्तेकी हिन्दू , मुसलमान तथा अन्य प्रजाका जो सामान ल्टा गया था उसकी क्षतिपूर्तिके लिए में २० लाख क्षया दूँगा।
 - (७) इसी प्रकार अमेरिकनोंके सामानके लिए में ७ लाख रुपया दुँगा।

इन रकमोंको वितरण करनेका पूरा अधिकार वाट्स, क्लाइव तथा कींसिलके अन्य सदस्योंको होगा।

- (८) कलकत्तेकी सीमाके चौतरफाकी खाईमें स्थित जमींदारींकी भूमि तथा खाईके वाहर ६०० गज भूमि में कम्पनीको दूँगा।
- (९) कलकत्तेके दक्षिणकी भूमि तथा काल्पीतक सब भूमि कम्पनीकी जमींदारी हो जायगी, और उस इलाकेके सभी अफसर कम्पनीके मातहत होंगे। कम्पनी इन क्षेत्रोंसे जमीं-दारकी माँति मालगुजारी वस्ल करेगी।
- (१०) जब कभी मुझे अंग्रेजी सहायताकी जरूरत होगी, मैं उसका खर्चा बरदाक्त करूँगा।
- (११) ज्यों ही मैं तीनों स्वोंकी सरकारका कार्यभार संभाल ल्रा, उक्त वर्णित रकमें अदा कर दी जायँगी।

संधिमें दर्ज रक्तमंकि अलावा, मीर जाफरने गद्दीपर बैठनेके बाद कम्पनीके मुख्य नौकरोंको लम्बी लम्बी मंटें भी दीं। सन् १७७२ की सिलेक्ट कमेटीने ऐसी रक्तमोंका अनुमान १२ लाख ५० हजार पौण्ड लगाया था जिसमेंसे अकेले हाइवको २ लाख ३४ हजार पौण्ड मिले थे। परन्तु वे ऐसी मेटें थीं जिनका या तो "सब्त मिल गया या लेनेवालोंने मंज्र कर लिया था।" शायद इनके अलावा और भी रक्तमें प्राप्त की गयी होंगी। सन् १७५९ में कम्पनीने क्लाइवको सन्धिकी ९ वीं शर्तमें विणत चौबीस परगनेकी आय प्राप्त करनेका अधिकार दे दिया। मीर जाफरने ५ लाख ६० को एक और रक्तम उसको दी जिससे उसने अपंग सिपाहियोंके लिए एक कोप खोल दिया।

कहा जाता है कि कुछ समय बाद सिराजुद्दीला पकड़ा गया और मीरजाफरके पुत्रने, नवाबकी मंशाके विरुद्ध, उसे मौतके घाट उतार दिया ।

दक्षिणमें फ्रांसीसी फिरसे अंग्रेजोंके मुकावलेंमें खड़े हो गये । उन्होंने दिसम्बर १७५८ में मद्रासपर घेरा डाल दिया और उसे १६ फरवरी १७५९ तक जारी रखा। आंग्ल-फ्रांसीसी कशमकश १७६० तक चलती रही, लेकिन अन्तमें फांसीसी हार गये। उनका मुख्य इलाका पाण्डिचेरी उनसे अंग्रेजोंने छीन लिया। यद्यपि यूरोपके सप्तवधीय युद्धके बाद पाण्डिचेरी और चन्द्रनगरके इलाके फांसीसियोंको लौटा दिये गये, परन्तु उनका प्रभाव भारतमें खत्म हो गया।

इसी तरह अन्य यूरोपीय प्रतिद्वन्द्वी, डच लोगोंका भी प्रभाव क्लाइवने खत्म कर दिया। हुगलीमें डच लोगोंकी एक फैक्टरी थी। कहा जाता है कि मीर जाफरके आमन्त्रणपर वे कई युद्ध के जहाजों और सात आठ सौ यूरोपोय सैनिकोंके साथ हुगलीमें प्रकट हुए। अंग्रेजोंने एक भारी फौजसे उनका मुकाबला किया और उन्हें हरा दिया। डचोंको इस युद्धका हर-जाना देना पड़ा और उनकी फैक्टरी कायम रहने दी गयी। इस प्रकार अंग्रेजोंके प्रतिद्वन्द्वियोंकी कहानी समाप्त हुई और अंग्रेज भारतीय रंगमंचके निष्कण्टक मालिक हो गये।

मीर जाफर जब गहीपर बैठा तब बंगालका स्वा कम्पनीके कर्मचारियोंकी ल्ट और उनके करमुक्त व्यापारके कारण निर्धन हो चुका था। वेचारा मीर जाफर क्लाइवके जालका निस्सहाय शिकार हुआ था। "यदि संधिकी शतें नवाबसे जबरदस्ती पूरी न करायी जातीं, तो संधिमें दी हुई बड़ी बड़ी रक्षमें बस्ल हो ही नहीं सकती थीं। हजारों हीले हवालोंसे यह साफ हो चुका था कि नवाबके पास यदि जरा भी शक्ति होती तो वह एक भी शर्त पूरी न करता'।" सेना मीर जाफरके काबूके बाहर हो रही थी क्योंकि उसके पास सेनाको वेतन देनेतकके लिए पैसा नहीं था। सरकारी व्ययके लिए रपया एकत्र करनेके लिए उसे प्रजाका शोषण करना पड़ता था। स्वा अस्त-व्यस्त और अरक्षित दशामें था। नवाबके कुछ प्रमुख हाकिमोंको यह देखकर क्षोभ व दुःख होता था कि नवाब अंग्रेजोंकी कठपुतली बन गया है। ये लोग नवाबकी खोई हुई प्रतिष्ठा और शक्तिको पुनः प्राप्त करानेके लिए बहुत इच्छुक थे।

परन्तु तभी एक ऐसी घटना हुई जिससे क्लाइवको अपनी महत्ता और बढ़ानेका अवसर मिला। १७५८में मुगल शाहजादा अलीगौहरने जो दिल्ली दरवारमें वंगाल, विहार और उड़ीसा तीनों स्बोंका युवराज माना जाता था (हालाँकि व्यावहारिक रूपमें उसका इन स्वोंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं था) विहारपर हमला कर दिया। यह हमला उसने नवाबको दबाकर उससे मालगुजारीका शाही हिस्सा वस्ल करनेके अभिप्रायसे किया था।

मीर जाफर अपने पूर्वजोंकी माँति इन स्वोंका स्वतन्त्र शासक था। वह इस हमलेसे भयभीत हो उठा। उसने कम्पनीसे भारतीय और अंग्रेजी सेनाकी सहायता माँगी। और क्लाइवकी ओरसे उसे तुरन्त सहायताका आश्वासन मिल गया। वंगाल, विहार और उड़ीसान से मुगल युवराजको दूर रखनेमें स्वयं अंग्रेजोंकी भी भलाई थी। यदि मुगल प्रमुख हो जाता तो अंग्रेज इतने वहे भूखण्डके मालिक बनकर नहीं रह सकते थे। इसलिए उन्होंने तुरन्त ही अपनी कूटनीतिक चालें और सेना-संचालन आरंभ कर दिया। उन्होंने मुगल युवराजसे गुप्त लिखा-पढ़ी गुरू की जिसका मीर जाफरको पतातक न चला। क्लाइवने युवराजसे वादा कर दिया कि भविष्यमें मालगुजारीका शाही हिस्सा उसे मिला करेगा। अंग्रेजोंके सैनिक प्रदर्शनसे अलीगौहर इतना प्रभावित और उनके व्यवहारसे इतना संतुष्ट हो गया कि वह हमलेका

हाळवेळका १७६०का स्मृतिपत्र (वंसीटार्स नैरेटिव आव दि ट्रांजेक्शन्स इन बेंगाळ १७६०-६४) भाग १, ए० ४६

इरादा छोड़कर अवध लौट गया । मुगल युवराजको जो इन स्वोंसे हाथ धो वैटा धा, क्लाइवका यह वादा अति सुविधाजनक प्रतीत हुआ । क्लाइवकी इस नीति और चातुर्वने युवराजकी नजरोंमें अंग्रेजोंकी महत्ता, आवश्यकता और सैनिक शक्तिकी धाक जमा दी । ७ जनवरी १७५९ को क्लाइवने विलियम पिटको जो पत्र लिखा था उसके अनुसार मुगल युवराजने क्लाइवसे कहा था कि वह वंगाल, विहार व उड़ीसाकी दीवानी कम्पनीको ही इस शर्तपर दे देगा कि कम्पनी मालगुजारीका एक निश्चित भाग सम्राटको देती रहेगी और वाकी आय स्वोंमें ही रोक लेगी । कम्पनीको इन स्वोंपर अपना प्रभुत्व जमानेका यह अनोखा सुअवसर मिला । अव कम्पनीको वाजान्ता वह सब काम करनेका मौका मिला जो उसके अफसर वास्तवमें वहाँ पहलेसे ही कर रहे थे ।

जब अंग्रे जोंने समझ लिया कि मीर जाफरको काफी निचोड़ा जा चुका है; अब वह उन्हें कुछ न देगा तब उन्होंने सीचा कि अब कोई नया नवाब गद्दीपर बैटाया जाय। उनकी नजर मीर जाफरके दामाद मीर कासिमपर पड़ी। उससे वातचीत की गयी और वह फौरन राजी हो गया। अंग्रे जों और मीर कासिममें एक गुप्त सन्धि हुई जिसके अनुसार प्रकटमें मीर जाफर ही नवाब रहे पर उसके सारे अधिकार मीर कासिमको दे दिये जायें। जब मीर जाफरसे कहा गया कि वह मीर कासिमको अपना नायब बनाकर सारी शक्ति उसे सींप दे तो उसने इनकार कर दिया। परन्तु उसके अस्वीकार करनेसे होता ही क्या; अंग्रेज तो अन्तिम निर्णय कर ही चुके थे। एक रातको अंग्रेज सिपाहियोंने मीर जाफरका महल घेर लिया। पहले तो मीर जाफरने सोचा कि उसे अंग्रेजींका मुकाबला करना चाहिये, पर तुरन्त ही उसकी समझमें आ गया कि उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह सामना कर सके। उसने आत्म-समर्थण कर दिया और मीर कासिम नवाबी गद्दीपर आसीन हो गया। नये नवाबने दो लाख पींड कम्पनीके प्रमुख अधिकारियोंको नकद दिये। यह धन कम्पनीकी कैंसिलके आट सदस्वोंने आपसमें बाँट लिया। इसके अलावा उसने वंगालके तीन जिले—वर्दवान, मिदनापुर और चिटगाँव कम्पनीको दे दिये।

परन्तु मीर कासिम और अंग्रेजोंकी मित्रता अधिक दिन नहीं चली। मीर जाफरके मुकाबलेंमें मीर कासिम कहीं अधिक योग्य और दूरदर्शी शासक था। उसने शासनमें कुछ सुधार भी किया। परन्तु भीर कासिमको पूरा मौका ही नहीं दिया गया। शुरूसे ही कलकत्ता कौंसिलके अधिकतम सदस्य उसे शक और सन्देहकी दृष्टिने देखते थे। उन्हें मीर कासिमका योग्य शासन खटकने लगा क्योंकि अब उन्हें लूटने खसीटनेका मौका कम मिलता था।

स्त्रेमें अराजता फैल रही थी। मीर कासिम अंग्रेज गवर्नर वंसीटार्टका ध्यान वहुधा इस परिस्थितिकी ओर आकृष्ट करता था। उसका कहना था कि "कासिम वाजारले पटना, ढाका व कलंकत्तेतक पूरे इलाकेमें अंग्रेज अफसर और उनके गुमारते वहैंस्थित तहसीलदार, जमींदार और तालुकदारके काम करते हैं, कम्पनीका झंडा लगाते हैं, और उन्होंने मेरे अफसरोंको विष्कुल शक्तिहीन कर दिया है। कोई पहले सोच भी नहीं सकता था कि कम्पनीके गुमारते नवावी अफसरोंको गिरफ्तारतक किया करेंगे।"

वंसीटार्टको स्वयं भी इन उत्पातोंका ज्ञान था। वह अंग्रेज व्यापारियोंकी ल्टपाट

१. रैमने म्यूर, वहीं पुस्तक गृष्ट ६७-६८

२. वही पुस्तक, पृष्ट ६८

और अत्याचारोंको रोकना चाहता था । पर कौंसिलमें उसे अपने विरुद्ध वहुमतका भय था । इसलिए वह लाचार था ।

स्वयं हाइवने, जब वह सन् १७६५ में दुबारा भारत आया, लिखा था—"ऐसी अव्यवस्था, अराजकता, गड़बड़ी, रिश्वतखोरी, लूटखसोट और आचारभ्रष्टता वंगालके अलावा किसी देशमें देखी सुनीन गयी होगी, और न ऐसे अनुचित और लूटखसोटके उपायोंसे इतनी सम्पत्ति और धन जमा किया गया होगा। वंगाल, विहार और उड़ीसाके तीन स्वे, जिनसे ३० लाख पोंडकी आय है, मीर जाफरके कालसे कम्पनीके नौकरोंके प्रमुखमें हैं। इन नौकरोंने (जिनमें सैनिक और नागरिक दोनों ही हैं) नवावसे लेकर छोटे जमींदारोंतक सभीसे, जबरदस्ती रूपया एंटा है। कम्पनीके नौकरोंके कारनामे इतने पतित हैं कि हर हिन्दू व मुसलमान उनके नामतकसे नफरत करता है।"

मीर कासिम मीर जाफरसे भिन्न था । वह अंग्रे जोंके प्रत्येक अन्यायके सामने झकनेको तैयार न था । उसकी जिदपर कम्पनी अपने करहीन व्यापारमें कुछ नियमोंका पालन करनेके लिए तैयार हो गयी । उसने यह भी शर्त मान ली कि कुछ वस्तुओंपर कम्पनी भी ९ प्रतिशत कर देगी जब कि भारतीय २५ प्रतिशत कर देते थे । परन्तु इस समझौतेके वाद भी अंग्रेज व्यापारी नियमविरुद्ध काम करते थे और नियत किया हुआ कर नहीं देते थे । अन्तमें हारकर मीर कासिमने व्यापारको सब प्रकारके कर और चुंगीसे मुक्त कर दिया । इस आशके परिणामस्वरूप भारतीय व्यापारी भी अंग्रेजोंके समान करमुक्त व्यापार करने लगे । इस परिस्थितिके तीन परिणाम हुए—

(१) करमुक्तिके कारण भारतीय न्यापारी भी अंग्रेजोंसे प्रतियोगिता करने लगे—पहले करके कारण वे अपना माल अंग्रेजोंके समान सस्ता नहीं वेच सकते थे। (२) अंग्रेजी न्यापारको इससे बहुत धका लगा क्योंकि उनका एकाधिकार समाप्त हो गया। (३) नवावंकी आमदनी बहुत घट गयी।

इस न्याय और समताके कार्यने अंग्रेजोंको मीर कासिमका दुश्मन वना दिया और वे उसे भी गद्दीसे उतारनेको साजिश करने लगे। नवाव उस समय विहारमें था। अंग्रेजी सेनाओंने पटनापर हमला कर दिया। पहले हल्लेमें अंग्रेजोंकी करारी हार हुई और सैकड़ों सैनिक खेत रहे। वे हतोत्साह हो गये, पर भाग्यने उनकी मदद की।

मीर कासिमकी सेनामें एक अंग्रेज सिपाही था जो अंग्रेजी सेनाका ही भागा हुआ अपराधी था। एक रात वह चुपचाप अंग्रेजी सेनासे आ मिला। उसने नवावके गुप्त इरादों और सैनिक कार्यक्रमोंका सब हाल अंग्रेजोंको वता दिया। फीरन ही अंग्रेजी सेनाको तैयारीका हुक्म दिया गया और रातमें ही उस दगावाज अंग्रेज सिपाहीके वताये हुए तरीकोंसे नवावकी सेनापर हमला कर दिया गया। मीर कासिम वेखवर था, उसे ऐसी स्थितिमें घेर लिया गया कि वह कुछ भी न कर सकता था। वह छिपकर अवधकी ओर भाग गया। अंग्रेजोंने अब योग्य मीर कासिमके मुकावलेंमें दब्बू मीर जाफरकी कीमत पहचानी और उसे फिर नवाव वना दिया। एक वार फिर मीर जाफरको जो कुछ भी अंग्रेजोंने माँगा देना पड़ा। उसने भारतीयोंपर फिर २५ प्रतिशत व्यापार-कर लगा दिया और अंग्रेजी व्यापार विव्कुल करमुक्त कर दिया। अंग्रेजोंने नवावसे ६७॥ लाख रुपया लड़ाईका हरजाना वसल किया।

१. मैलकम, लाइफ आफ क्लाइव, भाग २, पृष्ठ ३७९

उसे ५ लाखकी एक और रकम उस घाटेकी पूर्तिके रूपमें देनी पत्नी जो अंग्रेज व्यापारियोंको भारतीय व्यापारते कर हटानेके फलस्वरूप हुआ था। कहा जाता है कि अंग्रेजोंने ५ लाख की जगह ५३ लाख वस्ल किये! जनवरी, १७६५ में मीर जाफरकी मृत्यु हो गयी। कहते हैं कि "अंग्रेजोंकी वेजा माँगों और वस्लीके वेजा द्यावने उसकी मीतको नजदीक ला दिया।"

अठारहवीं शतान्दीके अन्तिम चरणमें उत्तर भारतमें कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटी, उनका विवरण जाननेके लिए हमें पिछले इतिहासके पन्ने उलटने पडेंगे। मराठांने अहमद बाह अन्दालीके अफ़सरोंसे पंजाब छीन लिया था और अब उनका आधिपत्य समस्त उत्तरी भारतमें दिल्ली तक फैल गया था । जब इस घटनाका समाचार अन्दालीको मिला तो उसने भारतपर फिर एक वड़ी सेना लेकर इमला किया। इसी समय भारतीय इतिहासका एक महत्त्वपूर्ण अध्याय लिखा गया । मराठोंने भारतकी विखरी हुई शक्तियोंको (जिनमें हिन्दू और मुखलमान दोनों ही थे) शत्रुके विरुद्ध इकट्टा किया । भारतीय शासकोंकी नसोंमें देशभक्तिका अपूर्व उत्साह हिलोरं हे रहा था। पानीपतमें शत्रुसे हटतापूर्वक हटनेके हिए उन्होंने अपने आपको एक सूत्रमें संघटित किया। परन्तु जो एका मराठोंने स्थापित किया था, उन्होंने स्वयं ही उसे तोड दिया । दिल्लीका सिंहासन उस समय खाली था-मगल वादशाह अवधर्मे अपनी रक्षाके लिए छिपा हुआ था। मराठोंके रंग-ढंगचे उनके अन्य साथियोंको सन्देह हो गया कि वे दिख़ीका राज्य हड़पना चाहते हैं। इस सन्देहका परिणाम भरंकर हुआ । मराठोंके कुछ मित्र राजे दूसरोंको अकेला छोड़कर मैदानसे चले गये। वाकी लोग अपनी शक्तिभर अञ्चलिका मकावला करते रहे; किन्तु वे हार गये। फिर भी अञ्चली-की विजय उसके पुराने इलाकोंतक ही सीमित रही। १७६१ की इस पानीपतकी लड़ाई ने मराठोंका मुगलोंके उत्तराधिकारी वननेका स्वप्न छिन्न-भिन्न कर दिया। कुछ समयतक तो ऐसा लगा कि उत्तरी भारतसे मराठांके पैर उखड़ गये, पर केवल थोड़े समयके लिए। दक्षिणमें वे अब भी बड़ी सैनिक शक्ति थे और अंग्रेज उनसे हरते थे। १८ वीं शताब्दीके उत्तराईमें भारतीय राजनीतिक रंगमंचपर तीन वड़ी शक्तियाँ थीं—मराटे, हैदरअली (वादमें उसका वेटा टीपू मुल्तान) और अंग्रेज। अंग्रेजींके पास अपने प्रतियोगियोंको कमजोर करनेका एक ही तरीका था-भारतीय नरेशोंको एक दूसरेके विरुद्ध लड़ाकर स्वयं लाभ उठाना ।

उधर मीर कासिमने अवधके नवाव गुजाउद्दोलाको सलाह दी कि वह दिल्ली सम्राटके नामसे वंगालके इलाकोंपर हमला करके उन्हें जीत ले। मराठोंने भी इस योजनाको पसन्द किया और गुजाउद्दोलाको मदद करनेका बचन दिया। गुजाउद्दोला मुगल सम्राट, मीर कासिम, और मराठोंको साथ लेकरवंगालकी ओर बढ़ा। सम्मिल्त सेनाकी संख्या ५०,००० यी और उसके पास काफी मजबूत तोपोंकी एक बड़ी संख्या थी। वंग्रे जोंको अवतक जितनी सेनाओंका सामना करना पड़ा उन सबसे यह अधिक मजबूत यी। अंग्रे जी सेनामें केवल १२०० यूरोपीय और ८००० भारतीय सिपाही थे। उसी समय अंग्रे जी सेनाके भारतीय सिपाहियोंने विद्रोह कर दिया, जिससे अंग्रे जी सेनापितको एक बहुत बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ा। परन्तु उसने अत्यन्त निर्दयतापूर्वक उसका दमन किया। पूरी अंग्रेजी सेना

१. सर विलियम हन्टर, स्टेटिस्टिकल अकाटण्ट आब वंगाल, भाग ९, ए० १९१।

२. ब्रिटिश रूळ इन इण्डिया. पृ० ३९

शुजाउदौलाकी सम्मिलत सेनाके मुकाबलेमें कुछ भी नहीं थी और वह अंग्रेजोंको आसानीसे हरा सकती थी। परन्तु अंग्रेजोंके पाँचवे कालमने अवधकी सेनामें फूट डाल दी। प्लासीवाली चालाकियाँ यहाँ भी चली गयीं। उनका स्वामाविक परिणाम अंग्रेजोंकी विजय हुई। मुगल सम्राट आतंकित हो गया। उसे सलाह दी गयी कि यदि वह अपना सिंहासन कायम रखना चाहता है तो अंग्रेजोंकी शरणमें आ जाय। भयभीत वादशाहने ऐसा ही किया। वक्सरकी यह लड़ाई अंग्रेजोंकी १७६४ में जीती। शुजाउद्दौला और अंग्रेजोंकी संघि हो गयी जिसके अनुसार नवावने अंग्रेजोंको ५० लाख रुपया युद्धके हरजानेमें दिये और इसके साथ ही गाजीपुर तथा उसके आस-पासका इलाका भी दे दिया।

वक्सर-युद्धके पश्चात् अंग्रे जों और वादशाहमें भी एक सिन्ध हुई लिसके अनुसार सम्राट् शाहआलम दितीयने वंगाल, विहार और उड़ीसाकी दीवानी कम्पनीको प्रदान कर दी और कम्पनीने सम्राट्को २६ लाख रुपयेकी वार्षिक पेन्श्रन देना स्वीकार किया। एक दूसरे शाही आदेश द्वारा सम्राट्ने वर्दयान तथा अन्य जिलोंपर कम्पनीका कब्जा मान लिया, और उन सभी जागीरोंके निमित्त जो कम्पनीने कर्नाटकके नवावसे प्राप्त की थीं, शाही स्वीकृति प्रदान कर दी। सम्राट्ने कम्पनीको उत्तरी सरकारके जिले भी दे दिये। परन्तु आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि ये सब शतें ऐसे व्यक्तिके साथ की गयी थीं जिसका दिली सिंहासनसे कोई शारीरिक सम्बन्ध नहीं रह गया था। दिलीके बाहर वह नाममात्रका सम्राट्था।

औरंगजेवकी मृत्यु (१७०७) के बाद १८०६ तक केवल दो ही सम्राट् ऐसे हुए जिन्होंने ६ वर्षसे अधिक राज्य किया। एक था मोहम्मदशाह (१७१९-१७४८) और दूसरा था शाहआलम (१७५९-१८०६)। शाहआलम असलमें बरावर उन शक्तियोंका कैदी या पेंशन-मोगी रहा जो तख्त और ताकतके परस्पर-विरोधी दावेदार थे। वे.लोग शाह-आलमका नाम अपने-अपने स्वार्थोंके लिए इस्तेमाल करते थे।

भारतीयोंपर कम्पनीकी प्राथमिक विजयका एकमात्र उद्देश्य धन-प्राप्ति था, साम्राज्य-विस्तार नहीं । साम्राज्य-विस्तारको क्लाइवने व्यापारके लिए हानिकारक बतलाया था । १७६५ में उसने कहा था—"अगर हम लोग साम्राज्यके चक्करमें पड़ जाकँगे तो हमें एकके बाद दूसरा इलाका जीतना पड़ेगा। इसका परिणाम हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा क्योंकि तब पूरा साम्राज्य हमारे विरुद्ध हथियार लेकर खड़ा हो जायगा और हमारा कोई भी मित्र न रह जायगा। इसलिए, अति आवश्यकता पड़नेके अतिरिक्त, हमें कभी भी उन इलाकोंसे अधिक अपना साम्राज्य नहीं बढ़ाना चाहिये जो कासिमअली खाँसे हमें प्राप्त हुए हैं।"

उपर्युक्त कथनसे यह बात आसानीसे समझमें आजाती है कि वंगाल, विहार और उड़ीसापर कम्पनीका एकच्छत्र आधिपत्य होनेपर भी क्लाइवने नवावीका ढोंग कायम रखा। दीर्घकाल तक क्लाइवके उत्तराधिकारियोंने उसकी नीतिका पालन किया। उन्होंने वह वह राज्योंपर कब्जा पात किया, पर कठपुतली नवावों या राजाओंको कायम रखा। ऐसा मालूम होता है कि उन नवावों और राजाओंके प्रति जनताकी निष्ठा जरूर रही होगी। उसी नीतिके अनुसार क्लाइवने मरते हुए शाहआलमके भीतर कृत्रिम सांस डालकर उसे सम्राट्के रूपमें जीवित रखा और उसकी आड़में वह कम्पनीका प्रभुत्व बढ़ाता रहा। मुगल सम्राट्का नाम

अव चाद् सिक्कें की भाँति इस्तेमाल किया जा सकता था क्योंकि उसके स्थानपर कोई अन्य व्यक्ति गदीपर न बैठा था। उसके नामसे विना किसी रोकटोक के कम्पनी मालगुजारी वस्त कर सकती थी। यह एक वड़ी भारी मनोवैज्ञानिक चाल थी क्योंकि वादशाहके नामपर लोग कर या मालगुजारी देनेमें आनाकानी नहीं करते थे। कम्पनीके निजी स्वार्थके लिए यह जरूरी था कि वह वादशाहको २६ लाख रुपये सालानाकी पेंशन देती रहे, और इसीलिए उसने अवधके नवावसे वादशाहको इलाहाबाद और कौड़ाके सूवे दिलवा दिये जिससे उसकी शाही शान वनी रहे।

कुछ वपाँतक कम्पनीने वंगालमें भी नवाबी प्रथा कायम रखी, हर नये नवाबसे वह लम्बी-लम्बी रक्षमें वस्ल करती रही। पर जब अंग्रेंजोंने समझ लिया कि अब उनकी रिथित मजबूत हो गयी है तो उन्होंने नवाबको पैंशन देकर हटा दिया। हैिंटग्सके जमानेमें कम्पनीने वंगाल, विहार और उड़ीसांके शासनकी बागडोर स्वयं वाजाव्ता संभाल ली। इसी बीच शाईआलम अपना सिंहासन और प्रतिष्ठा फिरसे प्राप्त करनेके प्रयत्नमें लगा हुआ था। जब उसने देखा कि उसकी मनोकामनाकी सिद्धिमें अंग्रेज कोई मदद नहीं दे रहे हैं तो उसने मराठोंकी सहायतासे गही प्राप्त कर ली। पानीपतकी पराजयके दस वर्ष वाद मराठोंका प्रभाव उत्तरमें फिर बढ़ रहा था। अंग्रेज अपनी मजबूती समझकर पहले ही शाहआलमकी पैंशन बन्द कर चुके थे।

कम्पनीके शासनने वंगालके धनधान्यपूर्ण स्वेको वरवाद और कंगाल वना दिया। स्वबं क्लाइवने यह वात अपने एक पत्रमें जो उसने ३० सितम्बर १७६५ को कम्पनीके डाइरेक्टरोंके नाम लिखा था स्वीकार की है—''निर्दयता और अत्याचारोंका जो सिलिस कम्पनीके कर्मचारियों व उनकी आड़में यूरोपीय एजेण्टों व भारतीय उप-एजेण्टोंने शुरू किया है, वह इस देशमें अंग्रेजोंके नामपर स्थायी कलंक रहेगा।''

वंगालकी दीवानी जो नवावीके अन्तिम वर्ष १७६४-६५ में ८ लाख १८ हजार पोण्ड यी, अंग्रेजी शासनके प्रथम वर्ष १७६५-६६ में ही १४ लाख ७० हजार हो गयो। इस रक्षममें वह धन शामिल नहीं है जो कम्पनीके अफसरोंने अपने व्यक्तिगत लामके लिए वस्ल किया। सन् १७८७ में विलयम फुलर्टनने (जो ब्रिटिश पार्लमेण्टके एक सदस्य थे) वंगालकी दशाका वर्णन करते हुए लिखा था—''पहले जमानेमें वंगालके प्रदेश पूर्वी राष्ट्रोंके अन्नके मण्डार और व्यापारके केन्द्र माने जाते थे। हमारे शासनके कुप्रवन्धसे २० वपोंमें ही उनके बहुतसे भाग उजाड़ दिखाई पड़ने लगे हैं। खेत अब जोते वोये नहीं जाते; बढ़े-बड़े भ्रखण्डींपर अब जंगली झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं; किसान ल्टा जाता है, कारीगर सताये जाते हैं, अकालका आगमन वार-वार होता है; जनसंख्या घटती जा रही है।''

वारेन हेस्टिंग्सके शासनकालमें राजाओं से रुपया वस्ल करने के निर्दय तरीके अपनाये गये। आमतौरपर हेस्टिंग्सकी नीति यह थी कि वह एक राजाको दूसरेसे लड़ाया करता था और इसमें रुपया बना लेता था, साथ ही विजयी राजाको अपने इलाकेमें ब्रिटिश सेना रखनेको वाध्य करता था। बनारसके राजा चेतिसह भी हेस्टिंग्सके शिकार हुए ओर उसकी एकके वाद दूसरी इच्छा पूरी करते गये, पर अन्तमें हेस्टिंग्स उनसे नाराज भी हो गया क्योंकि उन्होंने पाँच लाख रुपये देनेकी माँग नामंजूर कर दी थी। इसपर हेस्टिंग्सने जुर्मानेके तौरपर पाँच लाखकी माँग बढ़ाकर ५० लाखकी कर दी और यह रकम बस्ल करने

कै लिए वनारसपर हमला बोल दिया। वहाँ हेस्टिंग्सको अकस्मात् चेतसिंहकी प्रजाका भी सामना करना पड़ गया जो सुशासनके कारण चेतसिंहकी मक्त हो गयी थी। प्रजाने अंग्रेज अफसरों व उनके हिन्दुस्तानी सिपाहियोंको वेकाबू कर दिया और मार डाला। इसपर हेस्टिंग्सने वहुत वड़ी सेना भेजकर जनताके विद्रोहका दमन किया।

अवधकी वेगमोंसे रुपया एँउनेके हेस्टिंग्सके तरीके और भी निंच थे। खुद वेगमके लड़के व नातीको गवर्नर-जनरलने गुप्त धनमेंसे १२ लाल पौंड हेस्टिंग्सके लिए देनेको वाध्य किया। अवधका नवाव रुहेलोंसे लड़नेमें आना-कानी कर रहा था पर हेस्टिंग्सने उसे पड़ी पढ़ाकर लड़ाया। अंग्रेजी मेदियोंके कारण रुहेले हार गये और अवधका नवाव जीत गया। रुहेलोंका इलाका अवधकी नवावीमें शामिल हो गया पर असली जीत अंग्रेजोंकी रही, कम्पनीको ४० लाल रुपया इनाम और २ लाख १० हजार लड़ाईके खर्चके तौरपर मिला। एक अंग्रेजी फीज नवावके खर्चपर अवधमें रहने लगी। इसके कारण नवाव कम्पनीकी कठपुतली वन गया। पर तो भी क्लाइवकी नीतिका अनुसरण करते हुए हेस्टिंग्सने रुहेल-खण्डको कम्पनीके कटजेमें न लेकर नवावके अधीन ही रहने दिया।

वंगालमें हेस्टिंग्सका शासन उसके अत्याचारोंके लिए मशहूर है। कम्पनीके कर्मचारी विलियम वोल्ट्सने लिखा है—"देशके असंख्य गरीव कारीगर और बुनकर वगैरह कम्पनीके गुलामोंकी तरह उसकी इजारेदारीमें हैं जिनपर ऐसी-ऐसी मुसीवतें और अत्याचार किये जाते हैं, जिनकी कल्पना भी मुक्किल है। उनपर जुमाने होते हैं, उन्हें वेंत लगते हैं, उन्हें कैदमें सड़ाया जाता है, उनसे जबरदस्ती पट्टे लिखाये जाते हैं "इन अत्याचारोंके कारण देशमें बुनकरोंकी संख्या बहुत घट गयी है "!"

ईस्ट इण्डिया कम्पनीका राजनीतिक प्रभाव अव कलकत्ते विस्लीतक फैला हुआ था और ताल्जुवकी वात तो यह है कि इस प्रभावको जनता या राजे महस्स भी नहीं करते थे। पर तव दक्षिण काफी मजवूत था—शायद उतना ही मजवूत जितना ग्रुरुके मुगल वादशाहों- के जमानेमें उत्तर मजवूत था। मैस्रका राजा हैदरअली बढ़ा शक्तिशाली था और एक वहे इलाकेपर मरहठोंका राज्य था। वहाँ प्रमुख जमाना अंग्रेजोंके लिए आसान न था। अंग्रेजोंको इर था कि अगर कहीं ये दोनों निजामसे मिल गये तो हमारे इरादे मिट्टीमें मिल जावँ । वस, उन्होंने इनमें फूट डालनेका फैसला कर लिया। उन्होंने निजामसे सिन्ध की और कुछ मरहठे सरदारोंसे मिलकर हैदरअलीके खिलाफ लड़ाईकी घोषणा कर दी। अंग्रेजोंकी पहली वार मात हुई। हैदरअली अधिक होशियार और साधनसम्पन्न था; उसने अंग्रेजोंके इन दोनों साथियोंको फोड़ लिया। अंग्रेज लौट गये और हैदरअलीको मौतके बादतक यथारिथित वनी रही।

हैदरश्लीका पुत्र टीपू सुल्तान भी अपने वापकी तरह वहादुर और अंग्रेजोंका पका दुश्मन था । उसे हराये विना अंग्रेजोंकी वन नहीं सकती थी । अंग्रेज उसे अगर सीधे नहीं हरा सकते थे तो प्रामी और वक्सरकी चालवाजियोंने ही बाज क्यों आते ? उन्होंने निजामको मरहठोंके विरुद्ध संरक्षण दिया था और इसलिए वह उनके प्रभावमें था। उनके मातहत दोस्त था। मरहठोंको अंग्रेजोंने इस वादेपर तोड़ लिया कि टीपूकी हारके वाद मैस्रका एक भाग उन्हें दे दिया जायगा। मैस्रके पुराने दोस्त अब अंग्रेजोंके साथ थे। रहा वचा काम मेदियों और गहारोंने पूरा कर दिया। "टीपूके यूरोपीय कर्मचारी अब अपना कौशल और ज्ञान उसे

ही नष्ट करनेके लिए प्रयोग करनेको किटवढ थे—वही कौशल और ज्ञान नो वे अभीतक टीपूकी रक्षामें लगा रहे थे। अंग्रेनों, निनाम और मरहटोंने मिलकर टीपूके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी—या नैसा कि कुछ इतिहासकारोंका कहना है टीपू द्वारा घोषित लड़ाईमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। तीन स्मूलतक लड़ाई चली। पहली वार तो गहारों और दुश्मनोंके मजवृत नमावके वावज्द टीपूने उन्हें करारी शिकस्त दी पर वादमें उसे हार माननी पड़ी। संधिके शर्तनामेंके अनुसार टीपूको अपना आधा राज विनेताओंको देना पड़ा और ३६ लाख पाँड "लड़ाईका खर्च" भी उसपर लगाया गया नो किस्तोंमें अदा होना था। "संधिके अनुसार ही टीपूको रकमको अदायगी और इलाकेके तयादलेकी गारण्टीमें अपने दो वेटोंको अंग्रेनोंके पास शरीरवन्धकके रूपमें रख देना पड़ा।" इस प्रकार सन् १७९२ में अंग्रेनोंके इलाकेमें २० हजार वर्गमील और बुड़ गये।

सात वर्ष वाद झूटे आरोप लगाकर टीपूपर फिर हमला किया गया। टीपूने जमकर मुकाबला किया पर इस वार यह कमजोर तो था ही, खुद उसके सेनापित-पूर्णियाको अंग्रेजों- ने इस वादेपर खरीद लिया था कि टीपूके राज्यका कुछ हिस्सा उसे दे दिया जायगा और वह स्वतंत्र राजा बना दिया जायगा। उसके कुछ और वफादार नौकरोंको भी रुपये या वेहतर नौकरियोंके लालचने गद्दार बना दिया था। टीपू लड़ाईके मैदानमें मारा गया और उसके लड़के कैद कर लिये गये। मैस्रका २६ हजार वर्गमिलका नया इलाका अंग्रेजी प्रभुत्वमें आ गया लेकिन हाइवकी नीतिका अनुसरण करते हुए हैदरअलीके पहलेवाले राज्यंशका एक पंचवर्णीय वालक गद्दीपर वैटा दिया गया। नया मैस्र राज्य पुरानेकी छायामात्र था, फिर भी उससे प्रजाकी धारणा बनती थी कि पुरानी व्यवस्था ही चल रही है और अंग्रेज देशके भीतरी शासनमें दिलचस्थी नहीं लेते।

१९ वीं सदीके पहले सालमें ही वेलेस्लीने विना रक्तपात, तंजीर, कर्नाटक, स्रत और अवध अंग्रेजी कन्जेमें ले लिये। तंजीर और कर्नाटक से युवराज "अंग्रेजी संरक्षणमें राजा" थे। उनपर कम्पनीके दुक्मनोंसे साँठगाँठ करनेका अभियोग लगाया गया और उनके प्रतिवादोंके वावजूद उन्हें गद्दीसे हटाकर पंकानें दे दी गयी। अंग्रेजोंका सितारा दक्षिणमें बुलन्द ही रहा था अतः वे इन प्रतिवादोंकी परवाह क्यों करते ?

सन् १७९८ में वजीर अली अवधका नवाव था। अंग्रेज उससे खुश नहीं थे, और सआदत अलीको गद्दी देना चाहते थे। सआदत अलीने अंग्रेजी फीज अवधमें रखनेके लिए कम्पनीको ७६ लाख रपये सालाना देनेकी शर्त कब्ल कर ली, और अंग्रेजींने उसे गद्दीपर वैठाकर वजीर अलीको केंद्र कर लिया। पर वंगालके नवाबोंकी तरह सआदत अली भी बहुत दिनों तक अंग्रेजींका कृपापात्र न रह सका। अंग्रेजींने उससे अपनी भारतीय फीजमें भारी छटनी करने और अंग्रेजी फीजको बढ़ानेके लिए कहा, और जब उसने यह प्रत्ताय माननेमें अनाकानी की तो उसपर मुसीबत आ गयी। अंग्रेज उससे चिढ़ गये। उसके सामने दो ही रास्ते थे—या तो गद्दी छोड़ दे या कम्पनीको खुश करे। उसे अवधका आधेने अधिक हिस्सा (करीब ३० हजार वर्गमील) कम्पनी को देना पड़ा। इस इलाकेमें निचले दोशावका पूरा हिस्सा (गंगा और यमुनाके बीचका क्षेत्र), इलाहाबाद और गंगा व वावराके किनारे

१. विलियम मेलवोर्न जेम्स—एए ८८

२. थानंटन हिस्टरी आव ब्रिटिश इंडिया

वनारसकी सीमातकका सब भ् खण्ड शामिल था। अंग्रेजोंने अवधके शासकींसे जो बादे और संधियाँ की थीं उनके बिल्कुल विरुद्ध यह इलाका लिया गया था। इंगलैंज्डके भारतीय दफ्तरके राजनीतिक व गुप्त विभागके मन्त्री, सर जॉन के ने लिखा है—"ऐसा प्रतीत होता था मानो ब्रिटिश सरकारने वादे तोड़नेकी इजारेदारी ले की थी। अगर अहदनामोंकी शतोंके भंग करनेके दण्डमें अंग्रेजोंकी जमीनें जन्त हो जातीं, तो ब्रह्मपुत्रसे सिन्धुतक ब्रिटिश सरकारके पास भूमिका एक दुकड़ा भी न बचता।"

उन्नीसवीं शताब्दीमें केवल मराठे ही अंग्रे जोंके (भारतीय) प्रतिद्वन्द्वी रह गये थे। मराठे मुगल साम्राज्यके उत्तराधिकारी होनेवाले थे, और १८ वीं शताब्दीमें तमाम भारतमें फैल गये थे। उनकी स्थिति १८१८ तक मजबूत रही, लेकिन फिर अंग्रे जोंने धीरे-धीरे उनकी शक्ति समाप्त कर दी। अपने समकालीन अन्य शासकोंसे भिन्न, मरहठे देशमित्त और राष्ट्री-यताकी भावनासे ओतप्रीत थे। कुछ मराठे शासक अत्यन्त उदार और प्रजापालक थे। उन्होंने कृषिमें सुधार कियो, सार्वजनिक कार्योंका निर्माण किया, और सिंचाईके साधनोंका प्रसार किया। लेकिन जैसा कि जवाहरलाल नेहरूने कहा है, मरहठोंने उत्तरी और मध्य भारतके उन विशाल क्षेत्रोंमें, जिनमें वे फैले हुए थे, अपनी शक्तिको संगठित नहीं किया। वे आये और गये, पर उनकी शक्तिने जड़ें नहीं पकड़ीं!...उन्होंने अपने व्यवहारसे वीर राजपूतोंको कुद्ध कर दिया, अतः इन्हें अपना मित्र और सहायक समझनेके वजाय मराठोंको इनका प्रतिद्वन्द्वी या अंसतुष्ट जागीरदारोंकी तरह मुकावला करना पढ़ा। मरहठोंमें आपसमें भी गहरी प्रतिद्वन्द्विता थी, और पेशवाके नेतृत्वमें एकताके वावजुद वे आपसमें झगड़ा करते थे। प्रायः महत्वपूर्ण अवसरोंपर वे एक दूसरेकी मदद न करते थे, और इसीलिए अलग-अलग हरा दिये जाते थे।"

पेशवा मरहठा राजाका प्रधान मंत्री होता था। परन्तु कालान्तरमें उस परिवारके लोग स्वयं राजा वन वैठे । स्वतन्त्र मरहठे शासकोंने पेशवाकी छत्र-छायामें एक राज्य-संघ कायम कर लिया । वड़ी-वड़ी रियासतोंके प्रमुख ये थे—ग्वालियरका सिंधिया, इन्दौरका होस्कर, वड़ौदाका गायकवाड़ और नागपुरका भोंसला। पेदावाका इन सरदारोंपर वैसा दवाव या आधिपत्य न था जैसा ब्रिटिश पार्लमेण्ट और कम्पनीके डाइरेक्टरोंका भारत स्थित अंग्रेजोंपर था । पेशवाका आधिपत्य और अधिकार उसके व्यक्तित्वपर निर्भर करता था । भारतीय राजनीतिमें व्यक्तित्वका सदा ही वड़ा महत्त्व रहा है; दुर्वल उत्तराधिकारी होनेसे वड़े-बड़े राजनीतिक उथल-पुथल हो जाते थे। मरहठा राज्योंको एक दुईल सूत्र आपसमें वाँधे हुए था; अपने तरीकोंसे अंग्रेजोंके लिए उस सूत्रको तोड्ना आसान था। मुगल साम्राज्यके उत्तराधिकारी वननेका मरहठा स्वप्न किस प्रकार व्यक्तित्वकी शिलापर टकराकर चूर हो गया, इसका एक उदाहरण महादाजी सिंधियाके व्यक्तित्वसे मिलता है। एक मजवृत सेना लेकर वह सन् १७८४ में दिल्लीमें दाखिल हुआ, और दुर्वल सम्राट शाहआलमकी सारी शक्ति अपने हाथमें हे हो। उसने शाहुआहमके हस्ताक्षरसे पेशवाको मुगह साम्राज्यका डिप्टी नियुक्त करवा दिया और अपनेको पेरावाका डिप्टी नियुक्त करवाकर मुगल फौजकी कमान हासिल कर ली। अपने इस नये पदसे उसने छोटे-छोटे जाट और राजपूत राज्योंको भी जीतना गुरू कर दिया। लेकिन जब वह उत्तर भारतमें साम्राज्य-विस्तार

38

में लगा हुआ था, उसे पूना जाना पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गयी। उसके बाद उत्तरमें मरहटोंका कोई नामलेवा तक न रह गया।

जव कि अंग्रेज उन दिनों बड़ी आसानीसे भारतीय शासकोंपर अपनी फीजं लाद रहे थे, मरहठे उस फीजको लेनेसे इनकार करते रहे । अंग्रेज चाहते थे कि विना युद्धके मरहठे भी उनके प्रभुत्वमें आ जार्ने परन्तु मरहठोंके अंग्रेजी फीज न रखनेके हढ़ निश्चयने अंग्रेजी योजनाको नेकार कर दिया । अंग्रेज मरहठोंसे कई टक्करें ले चुके थे और उनकी वीरता परख चुके थे । परन्तु भाग्यवश उन्हें जल्दी ही एक अवसर मिल गया, या यों भी कहा जा सकता है कि उन्होंने खुद अपने लिए सुअवसर पैदा कर लिया । सन् १८०२ में जसवन्तराव होत्कर और पेशवा वाजीराव दितीय गृहयुद्धमें व्यस्त थे । पेशवाकी स्थित कमजोर थी, अतः उसने अंग्रेजोंकी सहायक फीज रखना स्वीकार कर लिया । पेशवा और कम्पनीमें संधि हो गयी जिसकी शतोंके अनुसार पेशवाको कम्पनीकी सेना मिली, उसने कुछ इलाके अंग्रेजोंको दे दिये, और कम्पनीको उसकी वाह्यनीति निर्धारित करनेका भी अधिकार मिल गया । पेशवाके घुटने टेक देनेसे मरहठा संघके जहाजमें छेद हो गया; उसे डुवानेका अंग्रेजोंका काम सरल हो गया ।

सन् १८०३ में अंग्रेज फिर मुगल वादशाहको अपने प्रभावमें ले आये और १२ लाख सालानाकी पेंशन उसके लिए वाँघ दी । उन्होंने अन्य शासकीय कामोंके साथ-साथ मालगुजारी वसूल करनेका जिम्मा ले लिया । इसी मालगुजारीमेंसे वे बादशाहको पेंशन देते थे । पेशवाक टूट जानेके बाद अंग्रेजोंने अन्य मरहठा सरदारोंको भी, उन्हें आपसमें लड़ाकर, उनके शासन व फीजोंके मुख्य व्यक्तियोंको भ्रष्ट करके, शाहआलमको सम्राटकी वास्तविक शक्ति और प्रतिभा प्रदान करनेका वादा करके (जो कभी पूरा नहीं हुआ), छोटे छोटे राजाओं व सरदारोंको अस्पष्ट आक्वासनके बूतेपर फोड़कर, और मरहठा दरबारोंमें फूट डालकर, या तो हरा दिया या अपने वशमें कर लिया । पेशवाके आत्मसमर्पणके बाद उसे आठ लाख रुपये सालानाकी पेंशन उसकी मालगुजारीसे ही बाँघ दी गयी, जो १८१८ से १८५१ तक वरावर चलती रही । परन्तु जब पेशवा वाजीराव मर गया तो उसके येटे नानासहबसे कह दिया गया कि पेंशन अब वन्द कर दी जायगी । नानासहबने पेंशन पानेके तमाम शान्तिमय उपाय किये, परन्तु सफल न हुआ । अन्तमें वह अंग्रेजोंका भयानक शत्रु हो गया । वह १८५७ के गदरके प्रमुख संगठन-कत्तांओंमें था ।

भारतीय रियासतों में पंजाब और अवध सबसे आखिरमें ब्रिटिश राज्यमें मिलाये गये। १८ वीं सदीके उत्तरार्थमें सिख लोगोंने पंजाबमें बहुत-सी छोटी-छोटी रियासतें बना लो थीं। ईरानी आक्रमणकारी, अहमदशाह अब्दालीने पिटयालाके शासकतो पहले अपने मातहत राजा स्वीकार किया, फिर पाँच वर्ष बाद उसे महाराजा मान लिया। सन् १७६४ के करीब सिख राजाओंने भी मरहठोंकी तरह संघ बना लिया। सतलज नदीके दोनों ओर सिख रियासतें थी। नदीके एक ओरकी रियासतोंने, मरहठोंकी पराजयके बाद, अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया था। दूसरी ओरकी रियासतोंपर महाराजा रणजीतसिंह हुकूमत करते थे। रणजीतसिंहकी मृत्युके पश्चात् अंग्रेजोंने एक-एक करके पंजाबकी समस्त रियासतोंको जीतकर कम्पनीके राज्यमें मिला लिया। इन युद्धोंमें जीतके मुख्य साधक स्वाधी देशद्रोही ही थे। सन् १८५६ में अचानक ही अवधमें कम्पनीकी फीजें घुस पढ़ी। वेबस होकर नवाबको आत्म-समर्पण करना पढ़ा।

सन् १८१८ में मराठोंके दमनके वाद कम्पनी अपनेको देशकी प्रमुख राजनीतिक शक्ति मानने लगी। इसलिए उस वर्षसे उसने मुगल वादशाहको नजरें (भिक्त सूचक मेंट), देना वन्द कर दिया। सन् १८०६ में शाहआलमकी मृत्युके वाद कम्पनीने वादशाहके सीमत शासन अधिकारोंमें मी इस्तक्षेप आरम्भ कर दिया था। वादशाहकी मृत्युके वाद नया उत्तराधिकारी भी कम्पनीका ही नामजद व्यक्ति होता था। परन्तु लगता है कि इस प्रकारके नाममात्रके वादशाहके प्रति भी जनताकी काफी भिक्त थी क्योंकि सन् १८३५ तक कम्पनी अपने सिक्के वादशाहके नामसे ही चलाती रही। अंग्रेजोंकी शक्ति अब इतनी वढ़ सुकी थी कि बादशाहको गहीसे उतारनेके लिए उनका वस उँगली उठाना काफी था। लेकिन ऐसा माल्यूम होता है कि वादशाहके गहीसे हटाये जानेके परिणामस्वरूप उन्हें विद्रोहकी आशंका थी—ने इस खतरेके लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने वहादुरशाहको गद्दीपर कायम रहने दिया। निदान सन् १८५७ के गदरके वाद वादशाहके पदकी पूर्ण रूपसे समाप्ति कर दी गयी।

भारतीय राज्यों स्थित अंग्रेज रेजीडेन्ट वहाँ के लोगों को अप्ट करते थे। नेहरूने लिखा है—"इन रेजीडेण्टों का दरवारों में खास काम रिखतें देना और मिन्त्रयों तथा अन्य अफसरों को अप्ट करना था। एक इतिहासकारका कथन है कि कम्पनीका जास्सी विभाग अत्यन्त कुशल तथा पूर्णरूपेण संघटित था। उसे प्रत्येक दरवारी प्रतिद्वन्द्वी या सरदारकी गतिविधि और राजाओं की सेनाको पूरी खबर रहती थी। परन्तु भारतीय शासक अंग्रेजी गतिविधिसे पूर्णत्या अनिभन्न रहते थे। कम्पनीक मेदिये निरन्तर अपने काममें लगे रहते थे। संकट या धमासान युद्धके समय ये लोग अपने स्वामीको घोखा देकर अंग्रेजोंसे आ मिलते थे। यही कारण था कि अधिकतर लड़ाइयों में अंग्रेजोंकी विजय वास्तविक युद्ध आरम्भ होनेके पहले ही हो जाती थी। हासीके युद्धमें यही हुआ। सिख युद्धोंतक इस नीतिकी वार-वार पुनरावृत्ति हुई।"

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वेलेस्ली (१७९८-१८०५) मारतमें साम्राज्यकी योजनाएँ पूरी करनेकी भावनासे प्रेरित होकर आया था। "ग्रुक्ते ही उसका सिद्धान्त यह था कि अंग्रेज भारतमें सर्वोच्च शक्ति वन जायँ, और सब भारतीय नरेश अपनो राजनीतिक स्वतन्त्रता अंग्रेजोंको सींपकर नाममात्रके राजा रह जायँ।"

राज्योंकी आन्तरिक स्वतन्त्रता खण्डित हो चुकी थी, और उनकी दुर्वलतापर ही अंग्रे जोंकी सर्वोच्च सत्ताकी नींव पड़ रही थी। सहायक संधि प्रथाने, जहाँ देशी राजाओंको बाहरी खतरेसे और स्वयं उनकी प्रजाक सम्भावित विद्रोहसे सुरक्षित कर दिया था, वहाँ उनको कर्तव्यच्युत भी कर दिया—शासनकी दशा खराव होती जाती थी।

सहायक सिंध प्रथाकी बुराइयों पर टिप्पणी करते हुए टामस मनरोने लिखा है—
"जहाँपर भी यह प्रथा लागू होती है वहाँकी सरकारोंको निकम्मा, कमजोर और अत्याचारी
बना देती है, कुलीन वगाँकी स्वाभिमानकी भावनाको खत्म कर देती है और समस्त जनताको पतन और गरीवीकी ओर ले जाती है । भारतमें कुशासन या बुरो सरकारको खत्म
करनेके दो ही तरीके रहे हैं—शाही घरानेमें क्रांति या जनताका सगस्त्र विद्रोह । परन्तु
अप्रेजी सेनाकी उपिखितिके कारण इन दोनों तरीकोंमें से एक भी प्रयोगमें न लाया जा

जवाह्रलाल नेहरू, डिस्कवरी आव इ्विड्या, ए० ३२७-२८

सकता था। यह प्रथा राजाओंको काहिल बना देती थी क्योंकि वे अपनी रक्षाके लिए अजनवी शक्तिपर भरोसा करने लगे थे; इस प्रथाने उन्हें निर्द्यी और लालची बना दिया था क्योंकि अंग्रेजी फौजके वलपर वे अपने प्रति प्रजाकी प्रणाकी परवाह न करते थे। जहाँ भी सहायक संधि प्रथा चली, थोड़े ही दिनोंमें उजड़े गाँव और गिरती हुई जनसंख्या इस प्रथाके सबूतके तौरपर मिलने लगे।"

सन् १८१३ से १८५७ तकके दूसरे चरणमें कम्पनीके एजेन्टोंने साम्राज्य-विस्तारकी यड़ी-वड़ी योजनाएँ वनायाँ । वे अपनेको केन्द्रीय भारतीय सरकारका उत्तराधिकारो मानने छगे । छार्ड हैस्टिंग्स (१८१३-१८२३) के चले जानेके बाद अंग्रेजी रेजीडेन्टोंका देशी राज्योंमें प्रभाव ऐसी तेजीसे वड़ा कि वे शासनाधिकारी या प्रवन्धककी हैसियतसे काम करने छगे और स्वयं राजा लोग उनके घर हाजिरी देने लगे । ऐसे राजाओंकी रियासतें विलयनसे वच गयीं और ब्रिटिश शासनके अन्ततक कायम रहीं । सन् १८५७ के विद्रोहमें उनमेंसे वहुतोंने अंग्रेजोंकी धन-जनसे मदद की ।

हैिस्टिंग्सके बाद प्रत्येक गवर्नर-जनरल अधिकाधिक देशी रियासतोंको अंग्रेजी राज्यमें मिलाता रहा, परन्तु लार्ड डल्हौजी (१८४८-५६) ने इस रपतारको बहुत तेज कर दिया, जिसके फलस्वरूप असन्तोपके बीज उगने लगे जो शीव्र विद्रोहके रूपमें प्रकट हुए। सतारा, नागपुर, कुर्ग, झाँसी और अवधके एकके बाद एक किसी न किसी बहाने मिलाये जानेके कारण जनता, राजाओं व सिपाहियोंमें प्रतिहिंसाकी आग भड़क उठी।

अंग्रेजोंने कई रियासतें तो उनके राजाओंकी मृत्युके पश्चात् गद्दीके उत्तराधिकारकी गड़वड़ीमें हड़प लीं। इस गड़वड़में अंग्रेज गद्दीके दावेदारोंमेंसे किसी एककी मदद करने लगते और उसके सफल होने पर उस महत्त्वाकांक्षीसे पहले ही तय की गयी शतोंके अनुसार खुद राजनीतिक शक्ति हथिया लेते जिससे नया राजा कठपुतली मात्र वनकर रह जाता।

भारतीय इतिहासमें युद्ध कोई आश्चर्यजनक वात न थी, पर उनका परिणाम ऐसा आधिक संकट या नैतिक पतन कभी नहीं हुआ जैसा कि अंग्रेजी जीतके वाद हुआ। जनरल नेपियरके शब्दोंमें, जो सिन्धपर अंग्रेजी कब्जेके वाद १८४३ में वहाँका प्रथम गवर्नर नियुक्त हुआ ''अंग्रेज भारतमें आतंकवादी आक्रमणकारीकी हैसियतमें थे……उनसे बढ़कर जालिम और कमीनी शक्तिने शायद ही कभी भारत जैसे महाराष्ट्रपर शासन किया हो। भारत-विजय और हमारे सभी नृशंस कारनामोंका एकमात्र कारण था धन-लिप्सा। कहा जाता है कि पिछले साट वपोंमें अंग्रेजोंने भारतीयोंसे एक अरव पीण्ड रुपये वस्ल किये हैं। इस रक्षमका प्रत्येक शिलिंग खूनसे सना हुआ था जिसे पींछकर हत्यारोंने अपनी जेवमें रख लिया। पर कितना ही उसे घोओ या पोंछो, उसका धन्त्रा तो कभी न मिटेगा। वह धन्त्रा हमेशा बना रहेगा और यदि स्वर्गमें ईश्वर है तो हमें उस खूनका जवाब देना होगा।''

कुछ इतिहासकारोंका मत है कि भारतमें ब्रिटिश राज पहला विदेशी शासन था क्योंकि इसके पहले इस देशका आर्थिक शोपण किसी दूसरे देशके लिए नहीं हुआ । यह भारतके लिए नया अनुभव था । "भारतने पहले कभी अपनी स्वाधीनता नहीं खोयी थी । वह कभी ऐसे वर्गके शासनमें नहीं आया था जो हमेशा विदेशी बना रहा ।" इसके पहलेके सभी आक्रमणकारी विदेशी होते हुए भी भारतमें ही वस गये थे, और इस देशको उन्होंने अपना घर बना लिया था । इसलिए खेतीबारी व उद्योगकी उन्नति और प्रजाकी भलाईके अन्य कार्योंको वे अपनी जिम्मेदारी समझते थे ।

परन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनीका एकमात्र ध्येय था पैसा कमाना; इस देशको जीत लेनेके वाद भी उसका यही उद्देश्य वना रहा । धन कमानेकी ग्रुरुआत हुई भारतके सुन्दर व वारीक कपड़े तथा मसालोंके इंगलेण्ड तथा अन्य यूरोपीय देशोंके लिए निर्यातसे । अंग्रेज व्यापारी यहाँसे सस्ते भावपर जवरदस्ती और निर्दयतासे माल वस्त्ल करके वाहर भेजते थे । उस समय इंगलेण्डमें कपड़ेके कारखाने नहीं थे और भारतका कता व विना कपड़ा इंगलेण्ड-के लोग वड़े चावसे खरीदते थे । परन्तु जय इंगलेण्डमें विजलीकी शक्तिसे चलनेवाले करबोंका आविष्कार हो गया तो वहाँ कपड़ा बड़ी मात्रामें वनने लगा, और वजाय भारतसे वहाँ निर्यात होनेके कपड़ा वहाँसे उद्या वहाँ जाने लगा ।

अव कम्पनीको यह धुन हुई कि इंगल्लेण्डका कपड़ा मारतमें विके । मारतका चर्ला और करवा उद्योग नष्ट किया गया जिससे मजबूर होकर लोग इंगलेण्डका बना हुआ कपड़ा खरीदें । बुनकर और जुलाहोंका वर्ग समाप्त हो गया; उन्होंने यह काम छोड़ दिया । उन्होंने खेतीका सहारा पकड़ा और भूमिसे रोजी कमानेवालोंको संख्या वढ़ गयी । जवाहरलाल नेहरूके अनुसार "लाखों बुनकर वेकारी और गरीबीसे भूखों मर गये।" कहा जाता है कि १९वीं बाताब्दीके मध्यमें ५५ प्रतिशत व्यक्ति जीविकाके लिए खेतीपर निर्भर रहते थे । ब्रिटिश कपड़ा उद्योगके विकाससे और भारतीय उद्योग चौपट होनेपर यह संख्या बढ़ती गयी। सन् १८३४ में गवर्नर जनरल लार्ड विलियम वेन्टिकने लिखा था कि "भारतीयोंकी दयनीय दशा और मुसीवतकी मिसाल दुनियाके व्यापारमें कहीं नहीं मिलती। बुनकरोंकी हिंडुयोंसे समस्त भारतीय मैदान भरे पड़े हैं।" मालगुजारीके वढ़ जानेसे इस गरीवी और मुसीवतमें और भी अधिक दृद्धि हो गयी। अंग्रेजी शासनमें मालगुजारीकी दर बढ़ती ही गयी। अंग्रेजी सरकारने शोपकोंका एक नया वर्ग (जमींदार) पैदा किया। इन्हें धीरे-धीरे धरतीका वास्तिक मालिक बना दिया गया। इनका काम किसानोंसे मालगुजारी वस्ल करना और उसका एक निर्धारित भाग अंग्रेजी सरकारके कोपमें जमा करना था।

सन् १८२९ में वेन्टिकने कहा था कि जमींदारोंकी एक वड़ी जमात पैदा करके अंग्रेजी सरकारने अपने शासनके ऐसे समर्थक वना लिये हैं जिनका जनतापर जोर और प्रभाव है।

"यह तथ्य बहुत महत्त्वपूर्ण है कि जो सूबे सबसे अधिक कालतक अंग्रेजो शासनमें रहे वे ही सबसे अधिक कंगाल हैं जैसे वंगाल, विहार और उड़ीसा।" पंजाब बहुत बादको अंग्रेजी शासनमें मिलाया गया। इसिलए वह तुलनात्मक दृष्टिसे अधिक सम्पन्न रहा। अतीतसे चलो आयी पंचाबत प्रथाको खत्म करके अंग्रेजोंने भारतीय ग्रामके धार्मिक और सामाजिक जीवनमें गड़बड़ी पैदा कर दी। सर टामस मनरोके अनुसार "प्रत्येक भारतीय गाँवमें नियमित रूपसे निर्वाचित म्यूनिसिपल सिमिति होती थी जो माल (दीवानी) व गाँवकी रक्षाका प्रबन्ध करती थी, और यही काफी हद तक न्याय प्रशासनका काम भी करती थी। राज बदलते रहते थे पर इन संस्थाओं में कोई आक्रमणकारी इस्तक्षेप नहीं करता था।

१, नेहरू, डिस्कवरी ऑव इण्डिया, पृ० ३४८, ३४९,

२, नेहरू, वही पृष्ठ।

मरहठों और मुगलोंके शासनमें भी इन्हें वही मान्यता और सम्मान प्राप्त रहा । पर अंग्रेजी शासनने इन संस्थाओंकी अवहेलना की और इन्हें उखाड़कर फ़ेंक दिया । देशी पंचायतोंकी जगह विदेशी जज नियुक्त कर दिये गये।"

पंचायत प्रथाके अन्त और जमींदारी प्रथाके आरम्मने प्रजाके स्वाभिमान और अपनी रक्षा करनेकी योग्यतापर एक और कुटाराघात किया।

खैर, अच्छा बुरा जैसा भी हो और भारतीय उसे पसन्द करते हों या नहीं, अंग्रेजी राज कायम हो गया। परन्तु भारतीय जनताने उसे अंगीकार नहीं किया। सन् ५७ के विद्रोहसे पहले, ५० वपोंमें भारतीय सिपाहियों व जनताने कई वार ब्रिटिश शासनका सुकावला किया। सन् १८०६ में मद्रासकी सेनामें एक गम्भीर विद्रोहका संगठन किया गया। सन् १८२४ में ४७ वीं वंगाल इनफैन्ट्री (पैदल सेना) ने हमलेके लिए वर्मा जानेसे इनकार कर दिया। इस सेनाका यूरोपीय तोपचियों द्वारा दमन करके उसे खारिज कर दिया गया। मेटकाफने १८२४ में लिखा था "समस्त भारत हर समय हमारे पतनकी प्रतीक्षा कर रहा है। भारतके प्रत्येक कोनेमें लोग हमारे नाश्चर खुशियाँ मनायंगे।" सन् १८१४ में उसने कहा था: "हमारी स्थित भारतमें हमेशासे डाँवाडोल रही है। हम एक ही धक्केंमें उखाड़े जा सकते हैं। हमारी जड़ें यहाँ जमी ही नहीं हैं।" सन् १८२० में मराठोंपर विजय प्राप्त होनेके वाद उसने इसी प्रकारका भय प्रकट किया था—"क्या कभी भी हम भारतीय जनतामें अपनी सरकारके प्रति लगन पैदा करनेका उपाय निकाल सकेंगे! और क्या हम भारतीय उच्च वगोंके हितोंको अपने हितोंके साथ मिलाकर ऐसा कर सकते हैं! क्या इस भारतीय उच्च वगोंके हितोंको अपने हितोंके साथ मिलाकर ऐसा कर सकते हैं! क्या उनके और अपने हितोंको एक साथ मिलाना सम्भव है! यदि इन सव प्रक्नोंका उत्तर मुझसे पूछा जाय तो मैं कहूँ गा 'नहीं'।""

सन् १८५६में विद्वोहके टीक पहले लार्ड कैनिंग भारतका गवर्नर-जनरल होकर आया। वह मजा हुआ राजनीतिज्ञ था। देशकी राजनीतिक नाष्ट्रीकी उसे खूव परख थी। उसने आते ही कहा—"में चाहता हूँ कि मेरा शासनकाल शान्तिमय हो। परन्तु में यह कैसे भूल सकता हूँ कि यद्यपि भारतीय आकाश शान्त और उज्ज्वल दिखलाई पड़ता है, उसमें हथेली वरावर वादलका दुकड़ा कभी भी उठ सकता है और वह बढ़ते बढ़ते विशाल रूप धारण कर सकता है जो हमारे विनाशका कारण वन सकता है।" कैनिंगका सन्देह ठीक उतरा। अगले वर्षके भारतके उज्ज्वल आकाशमें वादलका एक छोटा सा दुकड़ा उटा और उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया।

वैसे तो विद्रोहका संगठन बहुत दिनोंसे चल रहा था, परन्त तास्कालिक कारण "चर्यां के कारत्स" वन गये। एनफील्ड राइफलोंमें जो कारत्स भरे जाते थे, उनपर चिकनाईवाले कागजका एक खोल मढ़ा रहता था जिसे कारत्स भरनेके पहले दाँतोंसे काटना पढ़ता था। यह ख्याल था कि यह चिकनाई गाय और सुअरकी चर्वासे वनायी जाती थी। इससे हिन्दू और मुसलमान दोनोंकी ही धार्मिक भावनाओंको ठेस पहुँचती थी। सिपाहियोंने उन कारत्सोंका प्रयोग करनेसे इनकार कर दिया।

१. मनरो, भाग १, पृष्ट १०२, १०३

२. हवल् व्वत्रु० हंटरके 'दि इण्डिया आव दी कीन ऐण्ड अटर एसेन्'में टव्धत, पृ० ५४-५५

सिपाहियोंकी भावनाओंको ठेस पहुँचानेवाली दूसरी बात थी अंग्रेजोंका भारतीयोंको ईसाई धर्ममें दीक्षित करनेका प्रयत्न । ईस्ट इण्डिया कम्पनीके डाइरेक्टरोंके अध्यक्ष मेंगल्स ने ब्रिटिश पार्लमेण्टमें कहा था "हिन्दुस्तान जैसे विराट देशका आधिपत्य ईश्वरने हमें इसिलए सौंपा है कि हम वहाँ एक कोनेसे दूसरे कोनेतक ईशुमसीहकी विजयपताका फहरा दें ताकि सारा भारत ईसाई हो जाय । इस काममें किसीको कोताही नहीं करनी चाहिये।" धर्म-पिर-वर्तनका काम खास तौरसे सेनामें चला । वहाँ पदोन्नित व दूसरे हित साधनोंके लिए धर्म-पिरवर्तन एक प्रकारकी रिश्वत वन गया।

वंगालमें ब्रिटिश शासनको लगभग सौ साल तक वरदास्त करनेके कारण लोग उसके आदी होते जाते थे। परन्तु उत्तरी स्वोंमें जोश वाकी था और विद्रोहकी भावना बढ़ रही थी। "गंगा पारके इलाकेमें ही नहीं, दोआवके जिलोंमें भी ग्रामीण जनता उठ खड़ी हुई थी, और शीव ही ऐसा कोई गाँव, नगर और मनुष्य न बचा जो अंग्रे जोंके विरुद्ध खड़ा न हो गया हो।"

उन्नीसवीं शताब्दीके पूर्वार्झमें कई बार समझदार अंग्रेजोंने चेतावनी दी कि जिस ढंगसे अंग्रेज भारतमें व्यवहार कर रहे हैं वह किसी भी दिन विद्रोहकी आगको भड़का देगा।

नानासाहव विद्रोहके प्रमुख संघटनकर्ता थे। वे पेत्रावा बाजीरावके गोद लिये हुए पुत्र थे और अंग्रे जोंने उन्हें पेत्रावाकी मौतके बाद पेन्द्रान देनेसे इनकार कर दिया था। नानासाहवने देदाभरमें पूर्ण विद्रोहका संघटन करनेका निर्णय कर लिया, और इसके लिए ३१ मई १८५७ की तारीख निह्चित कर दी गयी। जान के लिखता है—"महीनोंसे, असलमें वर्षोंसे, लोग विद्रोहका जाल फैला रहे थे। देशके एक कोनेसे दूसरे कोनेतक, एक दरवारसे दूसरेतक, नानासाहवके आदमी रहस्यमय भाषामें विभिन्न राजाओं और नवाबोंके पास गुप्त रूपसे विद्रोहके निमन्त्रण पहुँचाते थे।"

वड़ी वड़ी आमसभाएं की जाती थीं, जिनमें विद्रोही संगठनके नेता लोग भाषण करते थे और लोगोंको ब्रिटिश शासन उखाड़ फेंकनेके लिए आह्वान करते थे। जो लोग अवतक यह समझे बैठे थे कि भारतीयोंमें देशप्रेमकी भावना नहीं है, स्वाभिमान और राष्ट्री-यताकी इस लहरने उनकी आँखें खोल दीं।

अंग्रेजी सेनाके भारतीय सिपाही जिन्हें परम्परासे किरायेके टट्टू समझा जाता था जोशके साथ विद्रोहकी तैयारी करने लगे और विद्रोहके नेताओं के अनुशासनको सहर्प मानने लगे। वे निर्धारित तिथि, ३१ मई को अंग्रेजोंके विरुद्ध विद्रोह शुरु करनेके लिए राजी हो गये। परन्तु कारत्सोंकी घटना और अंग्रेज अफसरोंके व्यवहारने दो रेजीमेन्टोंके सिपाहियों-को खिजाकर सहनशीलताकी सीमापर पहुँचा दिया। उन्होंने पहले दो अफसरोंके खिलाफ विद्रोह कर दिया।

इस प्रकार विद्रोह मेरठमें १० मई को ही आरंभ हो गया । वहादुरज्ञाहको भारतका वादज्ञाह घोषित कर दिया गया । दिल्लीको स्वतंत्र किया गया और फिर तो एककै वाद दूसरे इलाके स्वाधीन होते गये । स्वतंत्रता संग्रामकी सेना तेजीसे वढ़ रही थी । जो अंग्रेजी इलाका स्वतन्त्र किया जाता उसकी सेना विद्रोहियोंके साथ चल पड़ती । परन्तु इन छोटी-

१. जान के, इण्डियन म्यूटिनी, भाग २, ५० १९५.

२. जान के, वही पुस्तक भाग १, ५० २४.

छोटी जीतोंसे भारतीयोंमें यह गलतफहमी पैदा हो गयी कि शत्रु परास्त हो गया और देशका बहुत वड़ा भाग स्वतंत्र हो गया ।

इस वीच अंग्रेजोंने अपनी विखरी हुई शक्तिको इकट्ठा किया और देशी राजाओंसे कहा कि अंग्रेजोंको मदद देनेमें ही उनका कल्याण है। उनमेंसे बहुतसे ट्र गये। अंग्रेजोंने सक्ज वाग दिखाकर सिखों और गोरखोंको भी अपनी ओर मिला लिया। फिर तो लड़ाईका रुख ही वदल गया। अंग्रेजोंके पैर पुनः जमने लगे और विजयके दौरमें उन्होंने अकथनीय प्रकारके दमन और अत्याचार किये। इनका योड़ा-सा आभास नीचेके उद्धरणोंसे मिलता है—

स्र चार्ल्स डिल्कने अपनी पुस्तक 'ग्रेटर ब्रिटेन'में लिखा है—''दमनके दीरानमें गाँवके-गाँव जला दिये गये । निर्दोष गाँववालींका वह कल्लेक्षाम किया गया कि मुहम्मद तुगलक भी उससे शर्मा जायगा।''

चार्स्स वालने अपनी पुस्तक 'इण्डियन म्यूटिनी'में लिखा है—"जनरल हैवलावने सर हा हीलरकी मौतका भवंकर बदला लेना ग्रुक किया" इंड-के-झंड भारतीय फॉसीपर चढ़ाये गये। कुछ विद्रोही नेताओंने फॉसीके तस्तिपर चढ़नेके समय भी ऐसा महान् व्यवहार और शान्त चित्तता दिखलायी जो वे ही व्यक्ति दिखा सकते हैं जो सिद्धान्तपर मर मिटनेवाले होते हैं।"

माँटगोमरी मार्टिनने लिखा है—''जब हमारी सेनाने नगरके अन्दर प्रवेश किया तो जितने भी व्यक्ति उसे मिले उसने सबको तलवारसे मौतके घाट उतार दिया। उनकी संख्या बहुत बड़ी थी क्योंकि कुछ घरोंमें तीस-तीस चालीस-चालीस व्यक्ति छिपे हुए थे।"

रसेलकी डायरीके पृष्ठ ३०८ पर लिखा हुआ है—''कुछ सिपाही जिन्दा वचे थे, उन्हें भी निर्दयतापूर्वक मार डाला गया। उनमेंसे एकको पैरांसे घसीटकर बाहर रेतीले मेदानमें ले जाया गया। वहाँ कुछ अंग्रेजोंने उसके चेहरे और शरीरपर संगीने भोंकी। फिर इँघन इकट्टा करके एक छोटी-सी चिता बृनायी गयी और जब सब सामान तैयार हो गया तो उसे जिन्दा चितामें ढकेल दिया गया। यह इब करनेवाले अंग्रेज थे। कई अफसरोंने भी यह काण्ड होते देखा। किसीने इस्तक्षेप न किया। इस नारकीय नृश्वंसताकी भवंकरता तब और यह गयी जब उस अभागे सिपाहीने बड़ी कोशिशसे जलती चितामेंसे निकलनेकी कोशिश की। एकाएक वह उछलकर निकल आया। वह इतना जल चुका था कि उसका गांस हिंदुर्योंसे अलग लटक रहा था। वह कुछ ही कदम भाग पाया था कि उसे पकड़कर चितामें फेंक दिया गया और वहाँ संगीनोंसे उसे रोके रखा गया। वह अभागा उसी चितामें स्वाहा हो गया।''

इस प्रकारके अत्याचारोंके वर्णनीं हितहासकी पुस्तकें भरी पड़ी हैं। लेयर नामक पार्लमेन्टके एक सदस्यने (२५ अगस्त १८५८) टाइम्स अखवारमें लिखा था कि इस प्रकारके अत्याचार गदरमें भारतीयोंने नहीं किये थे। उसने लिखा था—"हिन्दुस्तानियोंके ऊपर अंग्रेज औरतों और वच्चींपर अत्याचार करनेके जो आरोप लगाये गये हैं वे सब गड़ी हुई कथाएँ हैं।"

जय विद्रोहका दमन हो चुका तो अंग्रेजोंने वहादुरशाहकी खबर ली। उसके गुरु पुत्र और रिक्तेदार मार डाले गये। वहादुरशाह और उसकी वेगमको केंद्र करके रंग्न जेलमें बन्द कर दिया गया जहाँ तैमूर वंशके अन्तिम बादशाहकी १८६३ में मृत्यु हो गयी।

भारतकी पुनर्विजयका युद्ध १८५८ के अन्त तक चलता रहा । अवधमें तो १८५९ जनवरीमें जाकर शान्ति और व्यवस्था कायम हो पायी ।

अध्याय १

वहावी क्रान्ति व क्का विद्रोह

सन् १८५७-५८ के सशस्त्र विद्रोह (गदर) के पश्चात् ईस्ट इण्डिया कम्पनीका राज्य समात हो गया, और पहली नवम्बर, १८५८ को ब्रिटिश सम्राजीने, एक शाही घोषणा द्वारा भारतका शासन अपने हाथोंमें ले लिया। घोषणामें कहा गया था कि महारानीकी "प्रजाके लोग चाहे वे किसी भी जाति, रंग व धर्मके हों विना किसी रोक टोक और भेद-भावके सरकारी नौकरियोंमें उनकी शिक्षा, योग्यता और कार्यक्षमताके अनुसार भरती किये जाश्वें।" भले ही महारानीने यह घोषणा सच्चे हृदयसे की हो, परन्तु उनकी भारतीय और ब्रिटिश सरकारोंने इसके प्रत्येक शब्दका जानवृझकर उल्लंघन किया और भारतीयोंको बड़ी-वड़ी सरकारों नौकरियोंसे वंचित रखा। जिस समय यह घोषणा की गयी थी विद्रोहकी आग पूर्णतया न बुझ पायी थी, परन्तु स्थिति काबूमें आने लायक हो गयी थी और अंग्रे जोंमें फिरसे आत्म-विश्वास जायत हो गया था। मुगल साम्राज्यका अन्तिम दीपक सदैवके लिए बुझ चुका था, और अञ्चानसे अज्ञान व्यक्ति भी अब समझ गया था कि भारत एक यूरोपीय कौमके अधीन हो गया है।

सन् १८५७-५८ के "स्वतंत्रता संग्राम" के बाद कुछ वर्षों तक भारतीय लोग अस्यन्त भयभीत रहे । विद्रोहके विफल होनेसे जो राष्ट्रीय अपमान हुआ उसे मन मारकर लोग सहन कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ अंग्रे जोंके घोर अत्याचारने जनताके दिल दहला दिये । जंगली जातियोंको भी शर्मिन्दा करनेवाले कल्ले-आत्म हुए, फांसियाँ, और अन्य यातनाएँ दी गयीं।

इतिहासका यह हृदय-विदारक अध्याय भी समाप्त हुआ और लोग धीरे-धीरे जीवनके धन्धों में फिरसे व्यक्त हो गये । लेकिन मुसलमानों के एक धार्मिक सम्प्रदायने जिसे वहावी कहते हैं विद्रोहकी मशाल जलाये रखी, और यही कारण था कि मुसलमानों के मध्यमवर्गकी परेशानीका काल और वढ़ गया। असफल विद्रोह या कान्ति जनताके लिए दमनका कारण होती है, परन्तु इस वहावी आन्दोलनके कारण मुसलमानों परसे अंग्रे जोंका विश्वास पूर्णतया उठ गया।

वहाबी लोगोंने तथा मुसल्मानोंके अन्य मुल्लाओंने पहले मुसल्म जनताको अंग्र जों-से असहयोग करनेका पाठ सिखाया । उन्होंने फतवों द्वारा मुसल्मानोंको आज्ञा दी कि वे अंग्र जी पढ़ना लिखना न सीखें, ऐसा करना पाप है। इस एक वातके कारण मुसल्मान लोग साधारणतया हिन्दुओंसे शिक्षा, राजनीति और आर्थिक उन्नतिमें वीसों वर्ष पिछड़ गये। इस ऐतिहासिक घटनामें हमें हिन्दू और मुसल्मि राजनीतिके दो विभिन्न स्त्रोंमें वहनेके आदि कारण मिलते हैं। ज्यों-ज्यों भारतीय राजनीतिका विकास हुआ, त्यों-त्यों इन स्त्रोंके वीचका फासला चौड़ा होता गया।

वहावी आन्दोलन क्या था । उन्नीसवीं शताब्दीके मुसलिम इतिहास और राजनीतिमें दो नेताओंका प्रमुख स्थान है—सैयद अहमद और सर सैयद अहमद खाँ। सैयद अहमद वहावी आन्दोलनके नेता थे। १८३१ में उनकी मृत्यु हो गयी और उनके बाद आन्दोलन-का संचालन उनके शिष्य करते रहे।

सैयद अहमद मुसलमानोंके उन धार्मिक नेताओंकी परंपरामेंसे थे जो शाह बली-उल्लाहके काल (१७१९ ई०) से आरंम होती है, और जो मारतमें फिरसे मुसलमानोंकी सत्ता जमानेके लिए धार्मिक और राजनीतिक आन्दोलन करती रही। सैयद अहमद राय-वरेलीके रहनेवाले थे। उनके जीवनकालमें पंजावमें सिखोंका राज्य था। उन्होंने मुन रखा या कि सिख राजा रणजीतिसहके राज्यमें सिख लोग "मुसलमानोंके साथ बुरा वर्ताव करते हैं, उन्हें धार्मिक कर्तव्य पूरे करनेते रोकते हैं, और उनके इवादतके स्थानोंको अपिवत्र करते हैं। इसिलए सैयद अहमदने उनके राज्यको दारुलहर्व घोषित कर दिया और उसके विरुद्ध जिहाद करनेका निर्णय किया। यद्यपि मराठोंने मी तभी अपना राज्य स्थापित किया था, परन्तु वे मुसलमानोंके धार्मिक कामोंमें बाधा नहीं डालते थे। उनके राज्यमें मुसलमान लोग अपने धर्म, कर्ममें स्वच्छन्द थे। उन्होंने मुसलिम काजियोंको भी उनके स्थानोंपर कायम रखा। इसिलए मुसलमान लोग मराठों और राजपूर्तोंके राज्योंको दारुल हर्व नहीं विलक्ष दारुल-इसलाम मानते थे।" दारुल-इसलाम उस राज्यको कहते थे जहाँ इसलाम धर्मके पालनमें कोई वाधा न थी; उसका विपरीत राज्य दारुल-इर्व कहलाता था जिसके विरुद्ध शत्रताका व्यवहार और जिहाद करना धर्म समझा जाता था।

रणजीतिसिंह स्वयं मुसलिम-विरोधी न था। उसके अति विश्वासपात्र लोगोंमें उसका मुसलिम मन्त्री पीरजादा अजीजउद्दीन भी था। उसके तोपखानेका प्रधान अधिकारी भी इलाहीवख्श नामक एक मुसलमान था, जिसके नामसे तोपखाना इलाहीवख्श तोपखाना कहलाता था।

मुसलमानोंके प्रति बुरा वर्ताव वहावी आन्दोलनके जिहादका एक कारण हो सकता है, पर यह आन्दोलन बुनियादी तौरपर राजनीतिक था जिसका आरम्भ वलीउल्लाहकी "तहरीक" से हुआ था। मुसलिम धार्मिक और राजनीतिक नेता जानते थे कि भारतपर फिरसे विजय प्राप्त करनेका सदास्त्र आन्दोलन उत्तरमें अफगानिस्तानकी सहायतासे आरम्भ होना चाहिये, और स्वयं भारतमें मुसलमान लोग इस ध्येयकी ओर तैयारी करें। उन दिनों मुसलमानोंको, अथवा किसी भी जातिको, संघटित करनेके लिए धार्मिक नारे बहुत जरूरी होते थे। वस एक बार यह समझ लेनेके बाद कि सैयद अहमद इस्लामका एक बड़ा भारी पीर है, मुसलमान उन्हें पूजने लगे, उनके अन्धमक्त हो गये और हजारोंकी संख्यामें पंजायके जिहादके लिए उनके पीछे हो लिये।

निम्नलिखित वर्णनसे पता चलता है कि मुसलमानीपर उनका कितना प्रभाव था— "उनकी आध्यात्मिक शक्तिसे लोग इतने प्रभावित थे कि उनके चेले नीकरोंकी भाँति उनकी सेवा करते थे। विद्वान और उचपदके लोग साधारण नौकरोंकी भाँति नंगे पाँव उनकी पालकीके पीछे दौड़ते थे। पटनामें कुछ अधिक समयतक टहरनेके कारण उनके अनुयायियों की संख्या इतनी वढ़ गयी कि प्रवन्धके लिए एक नियमित सरकार त्थापित करनेको आव-स्वकता प्रतीत हुई। सैयद अहमदने बड़े-बड़े नगरोंमें, लो उनके रास्तेम पड़ते थे, व्यापा-

१. राजेन्द्र प्रसाद, इण्डिया डिवाइडेड, पृष्ट ८७

२. तुफील अहमद, मुसलमानोंका रौशन मुस्तकविल (उट्टू) पृष्ट १०९

रियोंसे कर वस्ल करनेके लिए गुमाइते नौकर रखे। कलकतेमें तो इतनी भारी संख्यामें लोग उनके पास आये कि उनके लिए अलग अलग हाथ फेरकर शिष्य वनानेकी रस्मको निभाना असम्भव हो गया। इसलिए अपने लम्बे चौड़े साफेको फेंकते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इसे छू भर लेगा मेरा शिष्य हो जायगा। ""

अपने अनेक अनुयायियोंको साथ लेकर सैयद अहमद सिंध होते हुये काबुलके लिए रवाना हुए । कन्धारके फाटकपर उस नगरके धनी लोगों और साधारण जनताने उनका शानदार स्वागत किया । इन दोनों नगरोंमें लोगोंने उनकी फौजमें भरती होनेके लिए काफी उत्साह दिखाया । धीरे-धीरे एक लाख न्यक्ति जिहादके लिए तैयार हो गये। यह विश्वास करना किटन है कि अफगानिस्तानके बादशाहको उसके राज्यमें इतनी बड़ी सैनिक तैयारीका पता नहीं था जो पंजावपर हमला करनेके लिए हो रही थी। संभव है कि वह पंजाव-विजय में दिलचस्पी रखता हो, उसमें परन्तु अपने उन पूर्वजोंकी शक्ति न थी जिन्होंने भारतपर सदियों पहले सफलतापूर्वक हमले किये थे, इसलिए वह शायद चाहता था कि वहाबियों द्वारा या उनकी आड़में किसी तरह पंजाव अपने राज्यमें मिला लिया जाये।

दूसरी ओर अंग्रेज भी पंजावको इड़पना चाहते थे और सोच रहे थे कि वहावी आन्दोलन उनकी योजनाके लिए सहायक होगा । इसलिए जब कि वे हर रिवासती झगड़ेमें हस्तक्षेप करते थे, वे वहाबी-सिख संग्रामकी ओरसे उदासीन रहे । "उन दिनों मुसलिम लोग मुसलमान जनतासे सरेआम सिखोंके विरुद्ध जिहाद करनेके लिए कहते थे। हजारों सशस्त्र मुसलमान और असंख्य हथियार जिहादके लिए जमा किये गये। लेकिन जब अंग्रेजी कमिस्तर और मजिस्ट्रेटको इस विषयकी सूचना दी गयी और उन्होंने सरकारको सूचित किया तो सरकारने उनसे साफ कह दिया कि वे इस मामलेमें हस्तक्षेप न करें।" मुहम्मद जाफरने निश्चित रूपसे लिखा है कि "इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि सरकार (ब्रिटिश सरकार) सैयद अहमदके विरुद्ध होती तो उन्हें हिन्दुस्तानसे कोई सहायता न पहुँच पाती। लेकिन अंग्रेजी सरकार उन दिनों मनसे यही चाहती थी कि सिखोंकी शक्ति किसी प्रकार कम हो।"

परन्तु जिहादके प्रति अंग्रेजोंको उदासीनता, उन्होंके लिए पंजाव विजयके वाद मुसीवत सावित हुई । वहावियोंने अंग्रेजी राज्यको भी दारल हुई घोषित कर दिया और मुसलमानोंसे कहा कि ऐसे राज्यके प्रति उनके सामने दो ही रास्ते हैं—जिहाद या हिजरत । हिजरतसे मतलव दारल हुई का इलाका त्याग देनेसे था । इसलिए लोगोंने जिहादका रास्ता पसन्द किया । वहावियोंने पहलेसे ही सीमान्तकी स्वात घाटीके सिताना नामक स्थानमें अपना स्थापित केन्द्र बना रखा था । वहाँ वे लगभग पञ्चीस वर्षोतक सिक्खोंके विरुद्ध धार्मिक युद्ध चलाते रहे थे । इस सुसज्जित युद्ध-मशीनको उन्हें केवल अपने नये शत्रुको अंग्रेजकी ओर बुमा देना था । हण्टरने अपनी पुस्तकोंमें सितानाके वहावी केन्द्रको वागी कैम्प या

९. डब्लू. डब्लू. हण्टर, इण्डियन मुसलमान्स, पृ० १३

२. राजेन्द्रप्रसादके ''इण्डिया हिवाइडेड'' में उद्धत, ए० ३७ (सर सैयद अहमद खाँके इन्स्टीट्यूट गजट ता० ८ प्रितम्बर, १८७१ में प्रकाशित एक लेखसे।)

३. मुहम्मद जाफर "सवानत् अहमद दिया", पृ० १३९

देशद्रोही कैम्प कहा है। इसके विषयमें सन् १८७१ में उसने लिखा था—"वर्षोते वागी कैम्पने हमारी सीमाको खतरेमें डाल रखा है। समय-समयपर घर्मान्ध लोगोंके छुण्ड हमारे कैम्पके ऊपर हमला करते हैं, हमारे गाँव जला देते हैं। हमारी प्रजाका करल करते हैं और हमारी फीजोंको लड़ाइयोंमें फँसाते हैं। हर महीने यह विरोधी दल वंगालसे फीज मर्ती करता है। वहावियोंके ऊपर लगातार चलाये गये अभियोगोंसे सिद्ध होता है कि पडयन्त्रका जाल हमारे समस्त स्वोंमें फैल गया है। पंजाबके ऊपरके पहाड़ोंसे लेकर उस स्थानतक जहाँ गंगा समुद्रमें गिरती है, जगह-जगहपर विद्रोहियोंने अपने अडडे बना रखे हैं।

उनसे एक संघटनका पता चलता है जो नियमित ढंगसे धन-जनसे गंगाके डेल्टामें दो हजार मील दूर बहाबी कैम्पको भेजता है। बड़े बुद्धिमान और धनी लोग इस पड़यन्त्रका संचालन करते हैं। जिस कौशलपूर्ण ढंगसे रूपया भेजा जाता है, उसने देशद्रोहके एक बड़े खतरनाक ब्यापारको सुचारु और सुरक्षित वैंक ब्यवस्थाके रूपमें परिणत कर दिया है। "

बिदिश भारतीय प्रदेशोंमें पटना, वहाबी काररवाइयोंका केन्द्र था। वहाँ ग्रप्त कार्य इस सफाई और कुशलतासे किये जाते थे कि वहुत वपीं तक अधिकारियोंको यह पता न लग सका कि मैनद्रोही काररनाइयों में पटनेका कितना महत्वपूर्ण स्थान है। जब पटना संघटन गुप्त रूपसे पक्का हो गया तो नगरके खास-खास निवासी खुळे आम सरकार-विरोधी प्रचार करने लगे। ब्रिटिशराज्यको उखाङ फेंकनेके लिए पटना नगरमें एक अभृतपूर्व उत्साह दिखाई देने लगा। मैजिस्ट्रेटने रिपोर्ट की कि वागियोंको संख्या नित्यप्रति बढ्ती जा रही है। पुलिस भी वागियोंसे मिल गयी । वागी नेता लोग अंग्रेजी सत्तासे न इरते थे । उनमेंसे एकने जिसके घरमें ७०० आदमी जमा थे, घोषित कर दिया था कि अब मैजिस्ट्रेटकी कोई भी जाँच न होने दंगे और उसका मुकावला शक्तिसे करेंगे । सन् १८५३ में, अंग्रेजोंके कई हिन्दुस्तानी सिपाहियोंको वागियोंके साथ पत्र-व्यवहार करनेके अपराधमें सजा दी गयी थी। सीमान्तपर वागी नेताओंने १८५२ में अंग्रेजोंकी भारतीय सेनाके साथ सम्पर्क स्थापित कर लिया था। इस विपयके कुछ पत्र पकड़े भी गये थे। इन वर्षोंमें अंग्रेजी प्रदेशोंसे भाग-भागकर लोग वागी कैंग्पमें शामिल होते थे। सन् १८६२ में उनकी संख्या इतनी वढ गयी कि पंजाब सरकारने भारत सरकारको एक और सीमान्त युद्ध करनेका परामर्श दिया । सन् १८६३ में अंग्रेजों और बागियोंमें भयानक युद्ध हुआ। बागी पीछे ढकेल दिये गये और सरकारको कुछ समयके लिए चैन मिला । परन्तु वहायी उत्साह अजेय रहा ।

हण्टरका कहना है कि "वहावी आन्दोलन दक्षिणी भारत तक असर पहुँचा चुका या। हम द्रोहियोंने नहीं डरते, परन्तु डरका कारण हमारे साम्राज्यका राजद्रोही जनसमूह और सीमान्तके धर्मान्ध कवायली हैं जिन्हें वार-वार वागियोंने हमारे विच्छ उभारकर धर्म- युद्धके लिए अपनी ओर मिलाया है। सच तो यह है कि जब हम सीमान्त बरतीको फौजी शक्तिसे उखाड़ फैंकनेकी कोशिश करते हैं तो हमारी मुसलिम रियायाके धर्मान्धवर्ग धन और जनके असीम मण्डारसे इसे और अधिक शक्तिशाली बना देते हैं। जिने हम युझी राख समझकर छोड़ देते हैं उसे वे मानो तेल डालकर फिर लपट बना देते हैं।"

इण्टरके अनुसार सीमान्तके विद्रोह-शिविरमें केवल मुसलमान थे। परन्तु सर सैयद

१. हण्टर पृ० ९

[.]२. हण्टर, पृ० ४२, ४३, ४४

अहमद खाँ इस विचारसे सहमत न थे। सन् १८५७-५८ के विद्रोहमें सर सैयद अंग्रेजोंकी तरफ थे, और उनके जीवनका बड़ा भाग मुसल्मानोंको अंग्रेजोंका वफादार वनानेमें वीता था। उनके कथनानुसार सीमान्तके वागियोंमें हिन्दू-मुसल्मान दोनों ही सम्मिल्ति थे। सन् १८७१ में हण्टरने अपनी किताव "इण्डियन मुसल्मान" में लिखा था कि "भारतके मुसल्मान बहुत कालसे ब्रिटिश सत्ताके लिये खतरा रहे हैं और माल्स होता है सदैव रहेंगे।" इस पुस्तकके प्रकाशनके वाद सर सैयदने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी जिसमें उन्होंने हण्टरके कथनका खण्डन किया। उनका कहना है कि "१८५७ के विफल होनेके वाद कुछ परेशान विद्रोही अंग्रेजी दमन और सजाके कारण मुल्का व सितानामें, नेपालकी तराईमें, ओर वीकानेर और राजपूतानाके जंगलोंमें वस गये। जो उत्तर-पश्चिम सीमान्तकी ओर भाग गये थे उनमें सब जातियोंके हिन्दू और विभिन्न फिरकोंके मुसल्मान भी थे, और क्योंकि वे सब एक ही खतरेसे वचनेके लिए भागे थे स्वाभावतः साथ-साथ रहे। इन्हीं लोगोंने मुल्का तथा अन्य स्थानोंपर कब्जा कर लिया, परन्तु यह कहना जैसी कि हण्टरकी राय है, कि वे सरकारके विद्रद्व धार्मिक युद्ध करनेके लिए वहाँ इकट्ठा हुए थे, विश्वासके योग्य नहीं है क्योंकि इस जमावमें सब जाति-भाँतिके हिन्दू और मुसल्मान थे।"

सर सैयद ठीक कहते थे कि हिन्दू मुसलमान मिलकर कोई धार्मिक युद्धकी योजना कैसे बना सकते थे क्योंकि उनके धमोंमें बहुत अन्तर है। वास्तवमें उनका विद्रोह राजनीतिक था, और क्योंकि "जिहाद" शब्दका प्रयोग "पिवत्र युद्ध" के लिए होता आया था, इसिलए वे सब बिटिश शासनको उखाड़ फेंकनेके संग्रामको जिहाद ही कहते रहे। परन्तु आश्चर्यजनक बात यह है कि उन विद्रोहियोंमें जिनपर सीमान्त संबंधी कृत्योंके विषयमें अभियोग चलाये गये, एक भी हिन्दू न था। अगर वास्तवमें हिन्दू सीमान्तके उपनिवेशोंमें थे तो इस बातके दो ही कारण हो सकते हैं—(१) शायद उनकी संख्या बहुत कम थी और इसी लिए विद्रोहमें उनका हिस्सा नगण्य रहा; और (२) शायद अंग्रेज सरकार हिन्दू मुसलमान दोनोंको एक साथ शत्रु बनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि यदि अभियोगोंमें कुछ हिन्दू भी शामिल कर लिये जाते तो सम्भवतः हिन्दू जनता भी उनके विरुद्ध हो जाती। उस समय अंग्रेजों की नीति हिन्दुओंको खुश रखनेकी थी।

विद्रोह (१८५७) के बाद बहाबी आन्दोलन बीसों वर्षोतक ब्रिटिश सत्तासे मुठभेड़ लेता रहा। हण्टरने उस समयके खतरेका इस प्रकार वर्णन किया है—"स्वयं मुसलमानोंने जो कागजात प्रकाशित किये हैं उनसे प्रत्यक्ष हो जाता है कि भारतीय साम्राज्य एक भारी खतरेसे गुजर रहा है। उनको पढ़नेसे प्रत्येक निष्पक्ष व्यक्तिको विश्वास हो जायेगा कि जब कि अधिक साहसी मुसलमान खुल्लमखुल्ला देशद्रोहके कार्यमें लगे हुए थे, सम्पूर्ण मुसलिम जातिके दिमागमें इस वृहत् प्रश्नने उथल-पुथल मचा रखी है। शायद ही कभी इतने बड़े पैमानेपर लोग प्रभावित हुए हों। विद्रोह करना सब मुसलमानोंका कर्तव्य है, इस बातको बहुत सुन्दर और सार्वजनिक ढंगसे इस्लामी कान्तका रूप दे दिया गया है।"

विद्रोहके नेताओंने वहुत-सा साहित्य प्रकाशित किया जिसमें विद्रोहियोंको निश्चयात्मक युद्ध करनेके लिए उत्साहित किया गया और भविष्यवाणी की गयी कि अंग्रेजोंका पतन

१. सी. ऐफ. आई ग्रहम, ''दि लाइफ ऐण्ड वर्क ऑव सैयद अहमद खान'' पृ० २२१

२. हण्टर, पृ० ६०

समीप है। यह साहित्य गुप्त रीतिसे हाथों हाथ इधर-उधर वेचा गया। इस प्रचारका प्रभाव साहित्यके पाठकों तक सीमित न था, वरन् अनुभवी उपदेशकों द्वारा जो विद्रोहके संचालनमें वड़ी सावधानीसे शिक्षित किये गये थे, वंगालके प्रत्येक जिलेमें फैलाया गया। वहावी प्रचारमें निरन्तर कहा जाता था कि यदि मुसलमान ब्रिटिश शासनके विरुद्ध युद्ध में भाग लेंगे, तो वे सदाके लिए नकसे छुटकारा पा जायेंगे।

महारानी विकटोरियाके विरुद्ध विद्रोह फैलानेके लिए वहावियोंने सम्पूर्ण देहातोंमें एक स्थायो प्रचारसंघटन स्थापित कर रखा था । विद्रोहके जिलाकेन्द्र पटना प्रचार कार्यालय- से नियमित सम्पर्क रखते थे । प्रत्येक जिला इकाईका जनधन इकट्ठा करनेका अलग संघटन था । सन् १८७० में ऐसे दो जिलासंघटन अंग्रेज अधिकारियोंके हाथमें पड़ गये । उनके प्रधान प्रचारकोंको आजीवन कारागारको सजा दे दो गयी और उनकी सम्पत्ति जन्त कर ली गयी । उन दिनों कोड़े मारनेकी सजाका वहुत चलन था । जिन अपराधियोंको कोड़े मारे जाते थे उन्होंके साथ विद्रोहियोंकी भी गिनती होती थी । इस सजाकी नृशंसताका वर्णन वंगाल सिविल सर्विसके एक सदस्य, सर हेनरी काटनने इस प्रकार किया है—

"अपराधी हाथ पैरोंसे एक तिकोनी टिकटीपर नंगा वाँध दिया जाता है, जिससे वह हिल न सके। तव कमरसे नीचेके भागमें उसके खूब वेंत लगाये जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि वेंत पड़नेसे उस स्थानकी खाल और मांस कट-कटकर दुकड़े हो जातो हैं। कभी-कभी मनुष्य असहनीय कष्टसे बेहोश हो जाते हैं, और मैंने अधिकृत रूपसे सुना है कि बहुतसे आदमी वेंत यातनासे मर जाते हैं। बंगालमें प्रत्येक दलके बाहर इस नृशंसताकी याद दिलाने वाली तिकोनी टिकटियाँ दिखाई देती हैं। मुझे यह सब स्वीकार करनेमें घोर वेदना हो रही है। मैं इस विषयपर अधिक लिखना नहीं चाहता, क्योंकि यह अति भयंकर है और मैं इसे न्यायके लिए दी गयी सजा नहीं मान सकता। इससे अधिक वर्बरतापूर्ण सजा विचारमें ही नहीं आ सकती और मैं शर्म और शोकसे स्वीकार करता हूँ कि मुझे भी इस हुतमको देनेकी आदत पड़ गयी थी। मैं लगातार अपने न्यायके निर्णयोंमें कोड़े लगवानेकी सजा देता था।"

जिस समय इण्डियन व्हिपिंग ऐक्ट (को हे लगानेका कान्न) पारित किया गया था (१८६४) उस समय वहावी आन्दोलन जोरोंसे चल रहा था। आजीवन कारागार या मृत्यु—दण्ड इस सजाके सामने कुछ भी नहीं था, और यह सजा जेलकी चारदीवारीके अन्दर, जनताकी दृष्टिसे बहुत दूर, दी जाती थी। बाहर लोग अभियोगोंकी मुनवाईके विषयमें तो जानते थे लेकिन जो वर्षरताका व्यवहार जेलके अन्दर होता था उसका किसीको पता न चलता था। अंग्रेज जाति ही इस प्रकारकी सजा कान्तसे न्यायसंगत बना सकती थी।

अव हम फिर मुख्य विषयपर आते हैं। उन्नीसवीं शताब्दीके उत्तरार्थमें १८६० से १८७२ तक बहुतसे वहाबी अपराधियोंपर मुकदमे चलाये गये। उनपर देश-द्रोह और महारानीके विरुद्ध युद्ध करनेके चार्ज लगाये गये और उनको आजीवन कारागारकी सजा दी गयी। सन् १८६४ के मुकदमेकी सुनवाईमें, जो कि सन् १८८३ के वहाबी युद्ध संवंधित था, दूर-दूरके सूर्वोमें फैले हुये एक सुसंबटित पडयन्त्रका पता लगा। लोगोंको अचम्भा होता था कि किस प्रकार वहावियोंने इस संघटनको गुप्त रखा और इसके द्वारा आत्मरकाका

१. सर हेनरी काटन, "इण्डियन ऐण्ड होम मेमोरीन", पृ० ८०

२. यही पुस्तक, पृ० ७९

सुचारू प्रवन्ध किया। इस मुकदमेमें ११ मुसल्मानोंपर "घोर राज द्रोह" का चार्ज लगाया गया था। "इनमें मुसल्म समाजके प्रत्येक वर्गके प्रतिनिधि थे, अर्थात् उच कुलोंके मौलवी, एक फौजका ठेकेदार मंगी, सिपाही, उपदेशक, खानसामा और किसान।" ८ को आर्जी-वन कारागार और ३ को फाँसीकी सजा दी गयी।

इस मुकदमें मुख्य अपराधी याहिया अली थे, जो पटना प्रचार-केन्द्रके प्रधान अधिकारी थे। वे इस केन्द्रसे स्वयंसेवकोंको भरती करके सीमान्तके उस पार विद्रोही-शिविरमें भेजते थे। उनको फाँसीकी सजा दी गयी थी जो वादको कम करके आजीवन काला-पानी कर दी गयी थी। न्यायाधीश, सर हरवर्ट ऐडवर्ड सने उनके वारेमें अपने फैसलेंमें कहा था—"यहिया अलीने अपने सैकड़ों और हजारों देशवासियोंको राजद्रोह और विद्रोहके लिए वहकाया है। उन्होंने अपने पडवंत्रों द्वारा सरकारको सीमान्त-युद्धमें फँसाया जिसके कारण सैकड़ों मनुष्योंकी जानें गयीं। वह एक उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, और यह वहाना नहीं कर सकते कि उन्होंने वह सब काम नासमझीमें किया। जो कुछ भी उन्होंने किया है, विचार-पूर्वक, हढ़प्रतिज्ञ होकर तथा कटु राजद्रोहकी भावनासे प्रेरित होकर ही किया। वह एक ऐसे धर्मान्ध कुलके हैं जो परम्परासे ही अराजमक्त रहा है।"

पूर्वी वंगालके प्रत्येक जिलेमें विद्रोह-आन्दोलन जोरों छे फैला हुआ था। पटना छे लेकर वंगालके समुद्रतक मुसलमान किसानों की यह हालत थी कि वे नियमित रूप छे प्रति सप्ताह विद्रोही शिविरके लिए कुछ दान निकाल देते थे। सन् १८६४ के अभियोगके बाद, जिसकी सुनवाई अंवालामें हुई थी, वागियों को करत्तें इतनी वढ़ गयीं और उनका क्षेत्र इतना व्यापक हो गया कि सन् १८६८ में सरकारको १८१८के रेगुलेशन ३ के अधीन विना अभियोग चंलाये गिरपतार करनेकी शिक्तका प्रयोग करना पड़ा।

वहावियोंपर किये गये अत्याचारोंका कुछ पता मुहम्मद जाफर थानेश्वरीकी उर्दू पुस्तक "कालापानी या तारीख अजीव" से चलता है। मुहम्मद जाफर २० वर्षका कालापानी काटकर घर लीटे थे। वह भी अंवाला अभियोगके एक अपराधी थे। दिसम्बर १८६३ में जब उन्हें पता चल गया कि वे शीव ही गिरक्तार कर लिये जावँगे तो वे फरार हो गये। थानेश्वर और देहलीमें सैकड़ों मकानोंकी तलाशी ली गयी पर वे न मिले। उनके भाई और माताको उनका पता जाननेके अभिप्रायसे पुल्सिन खूव पीटा। अन्तमें वह अलीगढ़में पकड़े गये। उनके साथियोंके विषयमें पूछा गया, और जब वार वार वह यहीं कहते गये कि "में अपने साथियोंके बारेमें कुछ भी न वताऊँगा", तो उनको इतना पीटा गया कि वे वेहोश हो गये। इस पिटाईके दूसरे दिन फिर पारसन नामक पुल्सि सुपरिन्टेन्डेन्ट उनकी हवालातकी कोठरीमें प्रकट हुआ और उनसे कहा कि यदि वह सव हाल बता देंगे तो उनको एक वड़ी सरकारी नौकरी दे दी जावगी। "मेरे फिर इनकार करने पर पारसन साहव मुझे सुबह ८ वजेसे रातके ८ वजेतक पीटता रहा। मेरे सगे माईको इतना मारा गया कि वह मेरे खिलाफ गवाही देनेके लिए तैयार हो गये।" मुहम्मद जाफरका कहना है कि वहावियोंको पकड़नेकी आड़में पुल्सिने "पेशावरसे वंगालके उत्तर-पूर्व भागतक शायद ही कोई इज्ञतदार मुसलमान छोड़ा हो जिससे उसने रूपया वस्त न किया हो।"

१. हण्टर, पृष्ठ ८३

२. हण्टर, पृष्ठ ९३

सन् १८६८ में वहावी आन्दोलन फिर इतना जोर पकड़ गया कि उसका दमन करनेके लिए सरकारको पुनः वड़े पैमानेपर तैयारी करनी पड़ी । सरकारको अब अनुभव होने लगा कि केवल हिंसात्मक दमन, अभियोगों और कड़ी सजाओंसे आन्दोलन दवनेवाला नहीं है। इसलिये उसने उसकी जड़पर कुल्हाड़ी चलानेकी योजना बनायी। प्रत्येक जिल्में विद्रोही नेताओंकी स्ची तैयार की गयी। खास-खास उपदेशकोंको हिरासतमें ले लिया गया, और इस प्रकार जो जादू-सा असर वे जनतापर डालते थे वह खत्म किया गया। उनकी गुप्त कारखाइयोंके विषयमें गवाही इकट्टा की गयी। यह पता लगानेके लिए कि विद्रोही कोपमें कोन लोग रुपया देते हैं काफी लान-बीन की गयी।

सन् १८६४ से १८७१ तक पाँच वहे बहाबी अभियोग चलाये गये । जिन जिलों में ये चलाये गये थे वे एक दूसरेसे सैकड़ों मीलकी दूरीपर थे, लेकिन षड़यन्त्रमें वे सब सम्बन्धित थे । सीमान्तके प्रत्येक युद्धके बाद भारतमें बहाबी अभियोग चलाये जाते थे और प्रत्येक मामलेसे बहुतसे मामलोंका पता चलता था ।

सन् १८७१ के वहावी अभियोगके जमानेमें अंग्रेजोंके विषद मुसलमानोंका रोप पराकाष्ट्रापर पहुँच गया था। उस वर्षके सितम्बर मासमें वंगालके मुख्य न्यायाधीश, जॉन पैक्सटन नॉरमैनको एक मुसलमानने करल कर दिया। हण्टरका कहना है कि अंग्रेजोंका इतना विरोध १८५७ के विद्रोहके बाद कभी न था। सन् १८७३ में वाइसराय मेयोको शेरअली नामक एक वहावीने मार डाला। मेयो अण्डमन गये हुए थे और वहाँ जब वह नावपर चढ़ रहे थे तो शेरअलीने उनका काम तमाम कर दिया। मेयो मर तो गये, परन्त वहावी आन्दोलनको एक मनोवैज्ञानिक ढंगसे खत्म करनेकी योजना वह पहले ही बना सुके थे और उसपर काररवाई भी शुरू हो गयी थी।

मेयोने वहाबी आन्दोलनके फैलनेके आदि कारणींपर, जो मजहबी थे, विचार किया । उसने सोचा कि यदि मुसलिम विद्रोही अपने मुल्लाओं द्वारा यह पतवा निकलवा सकते हैं कि अंग्रेजी राज्य दारुल-हर्व है, तो कुछ ऐसे मुल्ला भी मिल सकते हैं जो इस राज्यको दारुळ-इसळाम घोपित कर दें। ऐसे फतवेसे जिहादकी जरूरत ही नहीं रह जाती। यह काम हण्टरको सिपुर्द किया गया । उन्होंने वहाबी आन्दोलनपर एक पुस्तक लिखी—"भारतीय मुसलमान—क्या वे धार्मिक दृष्टिसे महारानीके विरुद्ध विद्रोह करनेके लिए वाधित हैं ?" वहावी आन्दोलनकी एक रूपरेखा देनेके बाद इण्टरने अपनी पुस्तकमें यह सुझाव दिया कि मुसलमान विद्रोहके लिए वाधित नहीं है। देशमें एक वहस खड़ी हो गर्या कि भारत दादल-हर्व है या दारुल-इसलाम । कोई भी खुल्लमखुला यह न कह सकता था कि अंग्रेजी राज्य दारुल-हर्व है। जो कोई ऐसा कहता उसे जेलमें वन्द कर दिया जाता। प्रत्यक्ष है कि वहम एकतरका थी । दकियानृसी और नीम-दिकयानृसी मुख्ला 'दाइल-हर्न' और 'दाइल-इस्लाम' शब्दोंकी नयी व्याख्या और विवेचना करने छगे। उन्होंने जीरदार शब्दोंमें कहना ग्रुरू किया कि वहावियोंने जो मानी लगाये हैं वे भ्रामक हैं। उन्होंने वोपणा की कि, चूंकि भारतमें इस्लाम मजहवको सञ्चे रूपमें माननेकी आजादी है, अंग्रेजी राजके खिलाफ जिहाद करना शरियतके खिलाफ होगा, मक्काशरीफके कुछ मुक्तियोंके फतवे मँगवाये गये, जिनके अनुसार ''जवतक देशमें इस्लामकी कुछ खास रिवायतें कायम हैं, वह 'दारल-इस्लाम' है।'' भागल-पुरके कमिदनरके निजी सचिवने उत्तर भारतके मुल्लाओं के पास जा-जाकर उनकी राय माँगी

जिन्होंने कहा कि "ईसाई यहाँ मुसलमानोंकी हिफाजत करते हैं और जहाँ मुसलमान महफूज हैं, वहाँ जिहाद नहीं हो सकता।" सन् १८६३ में वहावियोंके मुकदमोंके वक्त नवाव अव्दुल लतीफ द्वारा कलकत्तेमें स्थापित 'मुह्मडन लिटरेरी सोसायटी' (मुस्लिम साहित्य गोष्टी) वहाबी आंदोलनका विरोध करती थी। यह सोसायटी अंग्रेजोंकी समर्थक थी और इसने भी इस व्याख्याका समर्थन किया कि भारत दारुल-इस्लाम है। सोसायटीने (जिसे उस वर्गके लोग चलाते थे, जिसका अस्तित्व अंग्रेजी कृपापर निर्भर था) मुस्लिम आलिमों (विद्वानों) की घोषणाएँ भी एकत्र की । खुद नवाव अब्दुल लतीफने वक्तव्य दिया कि "ब्रिटिश राज इतना मजवूत है कि उसका मुकावला नहीं हो सकता, वह इतना फायदेमन्द है कि उसे दरगुजर नहीं किया जा सकता । जो मुसलमान तरकी करना चाहते हैं, उन्हें अंग्रेजोंसे मिल-कर उन अवसरोंका फायदा उठाना चाहिये जो विदेशी मध्यमवर्गके लिए मिल रहे हैं।" सोसायटी अंग्रेजी शिक्षाको प्रोत्साहन देती थी। सर सैयद अहमदलाँने भी इस विवादमें भाग लिया था और ४ अप्रैल सन् १८७१ के "पायनियर" में सम्पादक के नाम पत्रमें लिखा था। "मुसलमान चाहे दारल-हर्वमें रहते हों या दारल-इस्लाममें, जो सरकार उनके दीन और इवादतमें दखङ नहीं देती, उसके खिलाफ वगावत करना शरियतके खिलाफ है।" इससे लगभग दस साल पहले सर सैयदने एक पुश्तिका 'दि लायल मुहम्हैन्स आव इंडिया' (भारतके वफादार मुसलमान) लिखी थी, पर उन दिनों वहावियोंके विद्रोहकी तैयारियाँ जोरोंपर थीं, इसलिए उस कितावका मुसलमानींपर असर न हुआ था। अब परिस्थिति वदल चुकी थी।

मुसलमानों — खास तौरपर वहावियोंकी काररवाइयोंने सरकारको इतना नाराज कर दिया था कि मुसलमान लरकारी नौकरियोंके अयोग्य समझे जाते थे। अंग्रेजीका ज्ञान न होना उनकी दूसरी अयोग्यता थी। मौल्वियोंने फतवे निकाले थे कि फिरंगीकी भाषा सीखनेसे दोजख (नर्क) मिलेगा । अंग्रेजी न पढ़नेके कारण वकालत और डाक्टरी जैसे पेशे भी उनके लिए वन्द थे। छोटी सरकारी नौकरियाँ आसानीसे पा जानेवाले हिन्दुओंको मुसलमान ईर्ध्या करते थे । मुस्लिम प्रवक्ता इस भावनाको खुलेक्षाम व्यक्त भी करते थे । कलकत्तेने प्रकाशित फारसीं अखवार 'तूरवीन'ने १४ जुलाई सन् १८६९ को लिखा था "हर किस्मकी छोटी-वड़ी नौकरियाँ धीरे-धीरे मुसलमानोंसे छिनती जा रही हैं और दूसरी जातिवालोंको,खास तौर-पर हिन्दुओं को दी जा रही हैं। सरकारको अपनी प्रजाकी सभी जातियोंको एक ही आँखसे देखना है; पर आज वक्त यह है कि सरकार अपने गजटोंमें नुसल्मानोंको ओहदोंने दूर रखती है। हालमें, सुन्दरवनके कमिस्तरके दपतरमें कई जगहें खाली हुई थीं, पर हाकिमने उनके विज्ञापनमें ही लिख दिया था कि ये नौकरियाँ हिन्दुओं के अलावा और किसीको न मिलेंगी। संक्षेपमें, मुसलमान इतने गिर गये हैं कि सरकारी नौकरीकी योग्यता रखते हुए भी उन्हें इन नौकरियोंसे, हुक्म जारी कर, अलग रखा जाता है। मुसल्मानोंकी इस असहाय द्शापर कोई भी ध्यान नहीं देता और ऊँचे हाकिम तो मुसलमानोंका अस्तित्व भी स्वीकार नहीं करते। 135

नवावी शासनमें मुसलमानोंको ऊँचे पद मिलते थे और हर फौजी व सिविल ओहदा उन्हें उपलब्ध था। अव इनके दरवाजे उनके लिए वन्द थे। उन्हें भौमिक सम्पत्ति भी प्राप्त

१. 'दि इण्डियन सुसलमान्स'में उद्घत पृष्ट १७५

न थीं। इस्तमरारी बन्दोवस्तके विशेषक जेमस ओ' किनीलीके अनुसार अंग्रेजोंने 'हिन्दू परगना-हाकिमोंको (जो अवतक महत्वहीन नौकरियोंपर थे) जमीनके माल्काना हक देकर जमीदार बना दिया और उन्हें दौलत इकट्ठी करनेका मौका दिया, नवाबी शासनमें यह दौलत मुसलमानोंको मिलती।"

फारसी राजकाजकी भाषाके पदसे बहुत पहले ही हट गयी थी। अब बंगलाने उर्वृकी भी जगह ले ली थी। नये परिवर्तनोंने मुस्लिम कान्नके अवशेष भी मिटा दिये; इसे मुसल-मान व्यक्तिगत और धार्मिक तिरस्कार समझते थे। हेनरी डडवेलके अनुसार "मात्र दृष्टिकोणसे आगे बढ़नेवाला पहला पहला असन्तोष मुख्यतः (यद्यपि पूर्णरूपेण नहीं) मुसलमानोंका था। उदाहरणार्थ, कहा जाता है कि सन् १८५९ में शिक्षा-विभागमें नियुक्त मुसलमान इस विवादमें तल्लीन थे कि ब्रिटिश सरकारकी नौकरी करना धर्म-विरुद्ध है या नहीं। पंजाबमें एक मुस्लिम फकीर राजद्रोहात्मक साहित्य वाँटते पकड़ा गया था और उसे फाँसी दे दी गयी थी। देशके इस या उस कोनेमें, हमेशा अंग्रेजी शासन पलट देनेकी साजिशें कुछ लोग किया करते। जिनका असन्तोष सबसे प्रत्यक्ष था वे मुसलमान थे।"

अंग्रेजी दृष्टिकोणसे मुस्लिम समस्याका हल सीधा व साफ था—'उन्हें नयी व्यवस्थाके प्रति निष्ठावान बनाना चाहिये: अपनी शिक्षाप्रणालीकी मुस्लिम माँगको स्वीकार करना चाहिये ; उन्हें अंग्रेजोंसे ज्यादा अच्छा न्यवहार मिलनेकी आशा होनी चाहिये: और उनकी शक्ति अंग्रेजी राजके अन्तर्गत 'रचनात्मक' ढंगसे आनी चाहिये।' मेयोने अपने एक नोटमं लिखा था--'इसमें कोई संशय नहीं है कि जहाँतक मुस्लिम जनताका संम्वन्ध है, हमारी वर्त्तमान शिक्षा-प्रणाली अधिकांशतः असपल रही है। हम न केंवल मुस्लिम समाजके वहे और महत्त्वपूर्ण अंगका विश्वास और सहानुभूति प्राप्त करनमें ही असफल रहे हैं, बल्कि इस वातकी भी आशंका है कि हमने उनमें अभक्तिके भाव पैदा कर दिये हैं। तो, वपोंके अनुभवके वाद यह मानते हुए कि हम मुस्लिम समाजको अपनी शिक्षा-प्रणालीकी ओर आकर्षित करनेमें असफल रहे हैं और यह भी मानते हुए कि उनमें हमने इतनी अभिक्त पैदा कर दी है कि हिन्दुओंको हमारी शिक्षासे प्राप्त होनेवाली भौतिक सुविधाओंके प्रति वे उदासीन हैं, यह देखना रह जाता है कि इस मुस्किलका हल क्या है। मुसलमान तवतक . शिष्ट नहीं होता जनतक उसे अरवी व उर्दुकी कुछ शिक्षा न मिल जाय । वह पण्डितसे पढ़ने हिन्दू स्कूल जायगा नहीं । इसलिए हमें उसके जातीय पक्षपातके सामने कुछ छकते हुए अपने काफी स्कूलों व परीक्षाओंमें, उर्दू, फारसी व अरवीको अधिक स्थायी और महत्त्वपूर्ण स्थान देना चाहिये। हमें वंगला स्कूलोंकी तरह उर्दू स्कूलोंकी भी आधिक सहायता करनी चाहिये, अपने कालेजोमें मुस्लिम छात्रोंके लिए दर्जे और वजीफे खोलने चाहिये और हर तरहेंसे उन्हें उन लाभदायक सरकारी नौकरियोंमें आनेका समान मोका देना चाहिये, जो आज हिन्दुओंकी एक तरहसे इजारेदारी वनी हुई हैं। 1938

मेयोकी नयी नीतिका खुले दिलसे स्वागत हुआ । सर सैयद अहमदखाँके रूपमें इस नीतिको लागू-करानेके लिए एक साहसी और संकल्पवद सहायक मिला ही हुआ था। यह

१. अशोक मेहता व अच्युत पटवर्धन द्वारा 'दि कम्यूनल ट्रायंगिल' में गृष्ट ८३ पर उद्घत ।

२. 'ए स्केच भाव दि हिस्टरी आव इण्डिया फ्रौम १८५८ हु १९१८" पृष्ट २५१-२

रे, बी॰ डी॰ वसु हारा 'इण्डिया अण्डर दि ब्रिटिशकाउन'में पृष्ट १२९-३० पर उद्धत ।

साहसके साथ, कभी-कभी जानका खतरा मोल लेकर भी, उन मौलवियोंके फतवोंका विरोध करते रहे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षाको गैरमजहवी घोषित किया था। मेयोकी नीतिने सर सैयद-को ब्रिटिश अनुयायी नहीं बनाया था ; वे हमेशासे ब्रिटिश सरकारके प्रति निष्ठावान् थे-संभवतः ईमानदारीसे निष्ठावान् थे क्योंकि वे समझते थे कि अंग्रेजी राजकी जड़ें इस देशमें स्थायी रूपसे जम गयी है। सन् ५७ के महान् विद्रोहके समय भी, जय अंग्रेजी सत्ताकी जड़ें हिल गयी थीं, तय भी उनका विश्वास अटूट रहा। अपनी इस अंग्रेज-भक्तिको उन्होंने परा-काष्ठापर तव पहुँचा दिया, जव उन्होंने अंग्रेजोंकी आ ओचना इस वातपर की कि वे हिन्दू-मुस्लिम भेदभावका फायदा उठाकर भारतीय सेनाकी वफादारीकी गारण्टी नहीं कर होते। उन्होंने कहा कि "भारतमें अंग्रेजी सैन्य संघटन सदैव दोषपूर्ण रहा है; उसका एक वड़ा दोष यह रहा है कि उसमें काफी अंग्रेज सिपाही नहीं रहे। जब नादिरशाह खुरासान जीतकर फारस और अफगानिस्तान दोनोंका मालिक बना, वह इमेशा दो बरावर-वरावर शक्तिकी सेनाएँ रखता था। एकमें ईरानी व कजलबादा होते थे, दूसरीमें अफगान। जब ईरानी फौजमें बगावत होनेका अन्देशा होता अफगान फौज उसे द्वानेके लिए मौजूद रहती ; इसी तरह ईरानी अफगान सेनाके विद्रोह दमनके साधन रहते । अंग्रेजोंने भारतमें इस दृष्टान्तके अनुसार दीम नहीं किया । इसमें सन्देह नहीं कि सिपाही वफादार थे और सरकारी काम अंजाम देते थे। पर सरकारको इसका विश्वास कैसे हुआ कि वे कभी भी सरकारी आदेशोंके खिलाफ काम नहीं करेंगे ? सरकारने यह जरूर किया था कि एक ही सैनिक इकड़ीमें दोनों जातियोंके सिपाही रख दिये थे ; वरावर हेल-मेल रहनेसे दुकड़ीकी दोनों 'जातियाँ' लगभग एक हो गयों।' यह होना अपेक्षित और स्वामाविक ही है कि वरावर साथ रहनेसे एक रेजिमेण्टके सिपाहियोंमें दोस्ताना और भाईचारा हो जाय। वे अपनेको एक इकाई समझने लगते हैं । इसीलिए हिन्दू मुस्लिम भेद इन रेजिमेण्टोंमें मिट गये । अगर रेजिमेण्टके कुछ िषपाही कोई काम करते, तो वाकी भी उसीमें लग जाते। अगर हिन्दू और मुसलमान सिपाहियोंके अलग-अलग रेजिमेण्ट वनाये जाते, तो उनमें भाईचारेकी भावना पैदा न होने पाती । ""

सर सैयदका वचपन और जवानी मुगल दरवारमें कटी थी और वहाँ उन्होंने 'वादशाहकी स्थितिका खोखलापन, उसकी छायाशक्तिका झ्ठ और अंग्रेजी शक्ति' देखी थी। सन् १८३७ में २० वर्षकी उम्रमें ही अपने रिक्तेदारोंको नाराजकर वादशाहकी नौकरी छोड़कर अंग्रेजोंकी नौकरी कर ली थी।' पहले वे क्लर्क थे, पर वादमें मुंसिफ हो गये। वे अंग्रेजी नहीं जानते थे, पर अन्यथा विद्वान् थे और कई वहुमृत्य पुस्तकें लिखी थीं। उनकी दूसरी पुस्तक 'आक्योंलोजिकल हिस्टरी आव दि रुइन्स आव डेल्ही' पर उन्हें रायल एशियाटिक सोसायटी' की सदस्यता (फैलोशिप) मिली। वह इतने अंग्रेजपरस्त थे कि उन्हें उनकी तुलनामें भारतीय जानवर माल्म पढ़ते थे। सन् १८५७ के विद्रोहमें उन्होंने अंग्रेजोंकी मदद की थी और इससे मुसलमान उनसे कुद्ध हो गये थे। विद्रोहमें इस सहायताके लिए उन्हें अंग्रेजोंसे ढेरों प्रशंसा और काफी माली इनाम मिले। उत्तरी-पिक्चमी स्त्रेके एक लेपिटनेण्ट गवर्नरने उनके वारेमें लिखा था—"सन् ५७ में अंग्रेज सरकारके थे. सर सेयद अहमद खाँ—'दि कोजेज आव दि इण्डियन रिवोल्ट' (उद्दं में), ग्रेहम द्वारा

अनुदित और उद्धत, पृष्ठ ५४-५५

प्रति भिक्त और अदम्य साहसका ऐसा महान् परिचय किसी औरने नहीं दिया जैसा सरसैयदने; जैसी लगन और निष्ठा उन्होंने दिखायी उसका वर्णन करना कठिन है।" उन्हें
अपने और अपने बढ़े लड़केकी उम्रभरके लिए २००) माहबारकी खास पंदान मिली और
कुछ दूसरे इनाम मिले। सन् १८६९ में तीसरे दुर्जेंका 'स्टार आव इण्डिया' का खिताय
मिला। उसी साल उन्हें दो सालके लिए २५० पाँड सालाना की एक पंदान 'गद्रमें की गयी
सेवाओंके लिए' और मिली। सन् १८६४ में उन्होंने गाजीपुरमें (जहाँ वे सबजज थे) अंग्रेजी
किताबोंका उर्दू में अनुवाद करने और मुसलमानों व अंग्रेजोंके बीच अधिक निकटके सम्बन्ध
स्थापित करनेके लिए एक सोसायटी बनायी। इस सोसायटीमें सरकारी ओहदोंपर नौकर
मुसलमान शामिल थे और कुछ स्थानीय अंग्रेज अफसर भी दिलचस्पी लेते थे। बादमें इस
सोसायटीका नाम हुआ 'अलीगढ़ साइण्टीफिक सोसायटी'।

सन् १८७० में सर सैयदने उद् में एक साहित्यिक व राजनीतिक अखत्रार निकालना ग्रुक्त किया, जो आठ साल चला । अखत्रार मुख्यतः अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजींसे सहयोगका प्रचार करता था । मक्काके मोलवियोंके फतवे सर सैयदके खिलाफ गरज उटे । उन्हें अनेक गुमनाम पत्र मिले, जिनमें अज्ञात लेखकोंने लिखा था कि इमने कुरान हाथमें लेकर कसम खायी है कि तुम्हें मार डालेंगे । उनमेंसे एकने लिखा था कि 'लार्ड मेयोको मारनेवाहूग शेर अली मूर्ख था; सर सैयदको मारकर वह विहस्त जाना पका कर सकता था।" इन धमिकयोंकी परवाह किये विना वे अपना काम करते रहे । सन् १८७० में ही उनके प्रयत्नोंसे भारतीय मुसलमानोंमें शिक्षा-प्रसारके लिए एक कमेटी वनी । जब उन्होंने शिक्षा-प्रचार ग्रुक्त किया उस समय भारतीय कुल २६ मुसलमान प्रेजुएट थे, जब कि हिन्दू प्रेजुएटोंकी संख्या १६२५ थी । सन् १८७१ में बंगालमें 'जिम्मेदारीके पदों' पर ७७३ भारतीय थे, जिनमें वंगालको जनसंख्यामें वरावरी करनेवाले मुसलमानोंको कुल ९२ पद मिले हुए थे । इससे स्पष्ट हो जायगा कि सरकारी नौकरियों और शिक्षामें मुसलमान जितने पिछड़ गये थे उसे सर सैयदके प्रयत्न भी पूरा नहीं कर सकते थे ।

धीरे-धीरे मुसलमानोंने अंग्रेजी शिक्षाका महत्त्व समझा और मुस्लिम कालेजकी स्थापनाके लिए चन्दा इकट्ठा करने लगे। सन् १८७५ में सर सैयदने मुसलमानोंके लिए एक हाई स्कूल स्थापित किया। सन् १८७८ में यह स्कूल दूसरे दर्जेका कालेज हो गया और कलकत्ता विश्वविद्यालयसे सम्बद्ध हो गया। कालान्तरमें यह कालेज मुसलमानोंके सामाजिक, धार्मिक, शिक्षा-सम्बन्धी व राजनीतिक कार्योका केन्द्र बन गया। शिक्षाका माध्यम उर्दू था, पर अंग्रेजी भाषाके ज्ञानपर बहुत जोर दिया जाता था। प्रिसिपल व अधिकतर अध्यापक अंग्रेज थे। यह कालेज कई बातोंमें अंग्रेजी शिक्षा संस्थाओंकी नकल करता था। नमाजके लिए छात्र मस्जिद जाते थे। सुन्नी और शिया छात्र अलग-अंग नमाज पहते थे।

कालेजके संस्थापकने सन् १८७७ में लार्ड लिटनको एक मानपत्र देते हुए कहा था—"देशवासियोंको शिक्षित करना ताकि वे अंग्रेजोंकी उदाराशयता समझ सकें, भारतीय मुसलमानोंको ब्रिटिश सरकारकी योग्य और उपादेय प्रजा बनाना; उनमें ऐसी निष्टा जाव्रत

१. ब्रेहम द्वारा उद्धत, पृष्ट १९

२, वही पुस्तक पृ०, २०४.

करना जो विदेशीसत्ताकी दासतामृलक अधीनतासे नहीं, सदाशय सरकारकी उदारताके ज्ञानसे उत्पन्न होती है—कालेजके संस्थापकोंके ये ही उद्देश्य हैं।"

यह वात अजीव जान पड़ेगी, पर हिन्दुओं और मुसलमानोंके पृथक रेजिमेण्ट वनानेकी सलाह देनेवाले सर सैयद अहमदखाँ सम्प्रदायवादी नहीं थे। उन्होंने मुसलमानोंको 'राष्ट्र'
और 'राष्ट्रीयता'का ज्ञान कराया था और इन शब्दोंकी परिधिमें वे हिन्दुओं व मुसलमानों
दोनोंको शामिल करते थे। वे कहते— "कौम, वह जो एक मुल्कमें रहें "याद रहे कि
हिन्दू और मुसलमान धार्मिक शब्द हैं; अन्यथा इस मुल्कमें रहनेवाले सभी हिन्दू, मुसलमान,
ईसाई इस देशके होनेके नाते एक कौम हैं। जब ये सब समूह एक हैं तो जिससे उन सबके.
देशका पायदा होगा, उससे उन सबका भी फायदा होगा । अब वह वक्त गुजर चुका
है जब धर्ममें भेद होनेके कारण किसी देशके वासी दो कौमें गिने जाते थे।"

पंजाबके हिन्दुओं के बीच भाषण करते हुए एक वार उन्होंने कहा था— "आप अपने लिए जिस 'हिन्दू' शन्दका इस्तेमाल करते हैं वह मेरी रायमें सही नहीं है, क्योंकि यह किसी धर्मका नाम नहीं है " "हिन्दुस्तानका हर रहनेवाला अपनेको हिन्दू कह सकता है। इसलिए मुझे दुःख है कि आप मुझे हिन्दू नहीं मानते, हालाँ कि मैं भी हिन्दुस्तानका एक वाशिन्दा हूँ।"

हिन्दू भी उनको राष्ट्रीय नेता मानते थे। उन्हें वे मानपत्र देते थे। वाइसरायकी कार्य-कारिणीके सदस्यकी हैसियतसे उन्होंने मुसलमानोंके साथ कोई पक्षपात नहीं किया। अग्रेज सरकारसे जब कभी वे राजनीतिक अधिकार या सरकारी नौकरियाँ माँगते, तब भारतीयोंके लिए, सिर्फ मुसलमानोंके लिए नहीं। आगरेके दरवारसे वे उटकर चले आये थे क्योंकि क्षेंग्रेजोंकी बैठनेकी जगह मंचपर बनायी गयी थी और भारतीयोंकी नीचे। तहजीवुल अखलाक में उन्होंने लिखा था 'कोई कौम इज्जत और सम्मान तबतक नहीं पा सकती जबतक वह शासक जातिकी वरावरीपर नहीं पहुँच जाती और अपने मुलककी सरकार चलानेमें हिस्सा नहीं बँटाती। कलकीं या ऐसी छोटी नौकरियाँ करनेके लिए दूसरे देशोंके लोग हिन्दुओं और मुसलमानोंकी इज्जत नहीं कर सकते। किसी कदर, जो सरकार अपनी प्रजाकी इजत नहीं करती, उसकी भी इजत नहीं होती। मेरे देशवासियोंका सम्मान तो तभी होगा जब वे शासक जातिके बरावरके दर्जेपर आयेंगे'

लेकिन भारतमें अँग्रेजी राज-तो "लड़ाओं और राज करों" की नींवपर कायम होना था। अगर सर सैयद जैसे उसके समर्थकों की इच्छा थी कि वह कायम रहे तो उन्हें भी ऐसा स्यवहार करना चाहिये था जो इस नीतिके अनुकूल हो। सर जॉन सीलीने अपनी पुस्तक 'दि एक्सपेंचन आव इंगलैण्ड' में लिखा था—"आप देखें, गदर तो काफी हद तक दवाया गया, भारतकी जातियों को एक दूसरेसे लड़ाकर। जवतक यह किया जा सकता है और जनताकी सरकार (वह चाहे जो भी सरकार हो) की नुकताचीनी करने और उसके खिलाफ उठ खड़े होनेकी आदत न पड़ जाय, इंगलेण्डमें वैठकर भारतपर शासन किया जा सकता है और

तुफैल अहमद 'सुसलमानींका रौशन सुस्तकविल' पृ० २८३ 'मजसुआ-ए-लेक्चर्स सर सैयद अहमद' के पृ० १६७ से उद्ध्त

२. वही पुस्तक पृ० २८३। सर सैयदके 'सफरनामा पंजाव' के पृ० १३९ से उद्ध्त

३. डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद द्वारा पृष्ठ ९३ पर 'इंडिया डिवाइडेड' में उद्धत

इसमें अचम्मेकी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर स्थित बदले और जनता किसी तरह एक राष्ट्रीयताके सूत्रमें वॅथ जाय तो हमें साम्राज्यके खतरेकी बात नहीं सोचना चाहिये विक साम्राज्यकी उम्मीद करना ही छोड़ देना चाहियें।

इसलिए यह साफ है कि अंग्रेजोंको यह समझानेके लिए किसी सर सेयदकी जरूरत नहीं थी कि सेनाका संघटन ऐसा हो कि मोका पड़नेपर भारतीयोंको भारतीयोंसे लड़ाया जा सके। अंग्रेज एक व्यापारिक कम्पनीकी हैसियतसे भारत आये थे और यहाँ मालिक वन वैठे थे और इसके लिए उन्होंने हर उचित अनुचित तिकड़म लगायी थी। सन् ५७के विद्रोहने सावित कर दिया था कि हिन्दू और मुसलमान मिलकर अंग्रेजोंके कठोर दुइमन हो सकते थे। "फूट डालो और राज करों"की नीति सबसे पहले फीजमें चलायी गयी। सर जॉन (बादमें लाई) लारेंसने जो विद्रोहको दवानेवालोंमें था और बादमें बाइसराय हुआ था, सर सेयद अहमदकी तरह ही कहा था कि "गदरके पहलेकी फीजके दोपोंमें जो सबसे खराय और हमारे लिए घातक सिद्ध हुआ वह था वंगाल फीजकी एकता और माईचारा। इसकी दवा पहले तो भारतीय और यूरोपीय फीजका संतुलन है और फिर भारतीय जातियोंकी फीजोंका संतुलन है।"

सन् १८५९ में फौजके संघटनकी जाँचके लिए एक शाही कमीशन—पील कमीशन वैटाया गया। कमीशनके सामने हुई गवाहियोंमें इसी ऊपर लिखी रायका प्रतिपादन किया गया। कमीशनकी रिपोर्टके आधारपर सन् १८६१ में फौजका पुनस्संघटन हुआ। जैसा कि 'डिफंस आव इंडिया' के लेखक नीरदचन्द्र चौधरीने लिखा है, फौजमें विभिन्न जातीय व साम्प्रदायिक तत्त्वोंको ''इस प्रकार संघटित किया गया है कि उनकी जाति या सम्प्रदायके प्रति मिक्त तो कायम रहती है, साथ ही वे एक दूसरेकी शक्ति और विशेषताओंका संतुलन करते रहते हैं।''

अँग्रेज किस तरह हर मौके, यहाँतक कि हर संकटका इत्तेमाल जातीय भेदमाव बढ़ानेके लिए करते थे, इसका उदाहरण सन् १८७४ के पारसी-मुसलमान दंगेमें मिलता है।

हाकिमोंकी उपेक्षासे वम्बईमें एक मामृली झगड़ेने वढ़कर भीषण साम्प्रदायिक दंगेका रूप ले लिया। हाकिम वेदामींसे अलग खड़े यह दंगा देखते रहे, मानों जिस देदापर वे राज करते हैं, वहाँ शान्ति व सुरक्षा कायम करनेसे उनका कोई सरोकार न हो!

सन् १८७३ के अन्तमें, जब मुसलमानोंको खुदा करनेकी अँग्रेजी नीति चाल् थी, टीके लगानेवाले एक पारसीने गुजरातीमें एक किताब लिखी, जिसपर कुछ मुसलमानोंको यह आपित हुई कि किताबमें इजरत पैगम्बरके सम्बन्धमें एक अपमानजनक इद्यारा है। उन्होंने पुलिसको इत्तिला दी और उसने फौरन किताब जन्त कर ली। पारसी लेखकने 'अनजानेमें हुए अपराध' के लिए क्षमा भी माँग ली। पर कुछ मुसलमान इससे सन्तुष्ट न हुए और उन्होंने खूनसे बदला लेनेकी ठानी। वे पारसी पूजाबरोंमें यस गये, प्रार्थनाकी किताब पाइ- हालीं और पिवत अग्न बुझा दी। कुछ पारसी परिवारोंको सताया भी गया। दोनों सम्प्रदायोंमें खुले आम बलवा हुआ, जिसमें कई जानें गयी। इस बलवेकी एचना पुलिसको पहले

W.UM. 147 -MS

९. 'दि एक्सपेंशन ऑव इंगलेण्ड,' पृष्ट २७०

२. दि कम्युनल ट्रायंगिल' में पृष्ट ५४ पर उद्धत

ही दे दी गयी थी पर तब भी, ऐन मौकेपर पुलिस नदारद थी। हाकिमोंने हालत विगड़ते देखी और स्थिति काबूसे वाहर जाते देखकर भी फौज न बुलायी।

संख्यामें कम होनेके कारण पारसी मुसलमानोंका मुकावला नहीं कर सकते थे । उन्होंने वम्बईके गवर्नर सर फिलिप वुडहाउसके पास एक प्रतिनिधिमंडल भेजा । पर उनके साथ सहानुभ्ति प्रकट करनेकी जगह गवर्नरने कहा—"तुम पारिसयोंको सरकारपर निर्भर रहनेकी जगह अपनी रक्षा अपने आप करना सीखना चाहिये।" इस सलाहका मतलब यही था कि अगर मुसलमान पारिसयोंपर हमला करें तो पारसी मुसलमानोंपर जवाबी हमला वोल दें। पुलिस कमिक्नर फ्रेंक स्टर तो एक कदम और आगे वढ़ गया। पारिसयोंका अपमान करते हुए उसने उनकी एक भीड़को संबोधित करते हुए कहा—जहन्तुममें जाओ, तुम पारसी लोग; तुम्हींने झगड़ा उकसाया है। मैं तो चाहता हूँ कि एक-एक पारसी मार डाला जाय। में पूरी पुलिस हटा लंगा और तुम लोगोंकी कोई मदद न कहँगा।" दूसरे दिन पारिसयोंकी एक सार्वजनिक सभामें उनके नेता फीरोजजाह मेहताने गर्वनरकी सलाहपर क्षोभ प्रकट किया; अंग्रेजी राजके बफादार होनेके नाते, असहाय होकर कहा—"सज्जनो! मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमने जो उपचार माँगा है, वह हमें मिलेगा, क्योंकि अँग्रेज सरकार और महारानी विक्टोरिया स्वयं जानती हैं कि पारसी जाति सबसे अधिक स्वामिभक्त और बान्तिप्रिय जाति है।"

भारतमें तव साम्प्रदायिक दंगे शुरू हो गये थे। सन् १८७१-७२ में जब वहावी आन्दोलन अपनी चरम सीमापर था, संयुक्त प्रान्तमें वरेली व कुछ और जगहोंपर हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए थे मानों अंग्रेज-विरोधी मुसलमानोंका ध्यान वटानेके लिए हुए हों।

लेकिन अंग्रेज सरकार अमीतक निराश थी। हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्ध अच्छे थे। छिट-फुट दंगोंका सामान्य वातावरणपर ज्यादा असर न हुआ था। यहाँ एक और विद्रोही वर्गका जिक कर देना असामयिक न होगा। सन् १८७२ में नामधारी सिख (जिन्हें कुका भी कहते हैं) सरकारके कोपका भाजन यने और उनमेंसे बहुतसे या तो तोपके मुँहसे बाँधकर भी कहते हैं) सरकारके कोपका भाजन यने और उनमेंसे बहुतसे या तो तोपके मुँहसे बाँधकर आंत उनमेंसे वहतसे या तो तोपके मुँहसे बाँधकर पा का है पाये, या कालेपानीमें डाल दिये गये। नामधारी सम्प्रदाय वावा वालकराम और उन कि शिष्य भाईराम सिहने (जो महाराज रणजीतसिंहकी फौजमें थे) चलाया था। खालका उनके शिष्य भाई रामसिंहकी जात्मा दुखी थी क्योंकि सिखोंने "विलासी जीवन अपना रामसे मिले। माई रामसिंहकी आत्मा दुखी थी क्योंकि सिखोंने "विलासी जीवन अपना रामसे मिले। माई रामसिंहकी आत्मा दुखी थी क्योंकि सिखोंने "विलासी जीवन अपना रामसे मिले। उन्होंने सिख जातिके सुधारका वत ले लिया। उनके पवित्र और परोपकारी लिया था"। उन्होंने सिख आकर्षित हुए। उनके अनुयायियोंकी संख्या वढ़ी और नामधारी जीवनकी ओर बहुतसे सिख आकर्षित हुए। उनके अनुयायियोंकी संख्या वढ़ी और नामधारी जीवनकी और वहुतसे सिख आकर्षित हुए। उनके अनुयायियोंका एक वार अमृतसरके कुछ अधिकतर हिन्दू व सिख इसमें शामिल होते थे। नामधारियोंका एक वार अमृतसरके कुछ वृच्छोंसे झगड़ा हो गया और कई वृचड़ मार डाले गये। नामधारियोंपर मुकदमा चला और उनमेंसे कुछको फाँसी मिली।

कूका सम्प्रदाय सामान्यतः अंग्रेजींसे सहयोग नहीं करता था। नामधारी न्यायके लिए अदालत भी नहीं जाते थे। वे सरकार या उसके मुहकमींसे कोई सरोकार नहीं रखते थे। लोग जानते थे कि 'कूका अंग्रेजी राजसे अप्रसन्न हैं'। भाई रामसिंहने उन्हें सिखोंके

गोकुलचन्द नांर्ग — 'ट्रांसफर्मेशन आव सिखिज्म' पृष्ठ ३३३

विगत वैभवकी याद दिलायी । सन् १८७२में उनकी एक मजवृत हुकड़ीने मलेरकोटला रियासतपर हमला किया । हुकड़ी हरा दी गयी, विद्रोह शान्त कर दिया गया, लेकिन उसकें वाद जो कुछ हुआ वह इस वातका ही उदाहरण है कि अंग्रेज सिविलियन कैसे जानवरकी तरह व्यवहार करने लगते थे । सर हेनरी काटनने लिखा है—"१४ जनवरी सन् १८७२को लगभग १०० कृकाओंका (सिखोंका एक सम्प्रदाय जो ब्रिटिश राजसे अपसन्न थे) एक गिरोह मालोघपर हमलाकर खुली हिंसापर उत्तर आया और सतलजपारकी मलेरकोटला नामक रियासतकी राजधानीपर उसने आक्रमण कर दिया । जमकर लड़ाई हुई और दोनों ओर काफी लोग हताहत हुए । आक्रमण विफल हुआ और वाकी बचे ५६ कृका (जिनमें २२ घायल थे) पटियाला रियासतमें माग गये । वहाँ १५ जनवरीको उन्होंने हथियार डाल दिये और एक रात उन्हों शेरपुरके किलेमें रखा गया । उनके हथियार डाल देनेसे ही कृका-विद्रोह खत्म हो गया ।

"१६ जनवरीको छुधियानाके डिप्टी कमिश्नर कोवनने कैदियोंको मलेरकोटला बुलवाया । वह भी वहाँ पहुँच गया । उसी शामको उसने अपने अफसर-कमिश्नरको लिखा कि शान्ति स्थापित हो चुकी है और 'मैं कल सबेरे कैदियोंको तोपसे उड़ा देने या फाँसी देनेका प्रस्ताव करता हूँ।'

"अगले दिन (१७ जनवरी) को कमिश्नर फोरमाइथका जवाय कोयनको दोपहरतक मिल गया; जिसमें कहा कथा था कि छुधियानासे फीजी पहरा भेजनेतक कैंदियों को होरपुरमें ही रखा जाय। कोयनका कहना है कि मैंने यह चिट्टी जेवमें रख ली और फिर उसके वारेमें सोचा भी नहीं। शामको ४ वजे कृका बन्दी कोटला लाये गये और उसी वक्त किसी मुकदमें, सफाई, सुनवाई, सबूत बगैरहका बहानातक किये बगैर कोयनने उनमेंसे ४९ को तोपके मुँहसे वेंघवाकर उड़वा दिया। शामको ७ वजे जब ४९ में से आखिरी ६ कृका तोपसे वाँचे जा रहे थे, कमिश्नर फोरसाइथका हुवम आया कि कैंदी मुकदमेंके लिए भेजे जावें। सरकारको अपनी सफाई देते हुए कोवनने लिखा—फोरसाइथका पत्र पढ़कर मैंने कर्नल पर्किसको दे दिया और कहा कि जो कैंदी तोपसे वाँधे जा चुके हैं, उनकी सजा स्थिगत करना असम्भव है, इससे हमारे आसपास मौजूद लोगोंपर वहुत बुरा असर पड़ेगा'। तोपसे वाँचे छः कृका भी उड़ा दिये गये। ५० वाँ कृका पहरेसे छूटकर भागा और उसने कोवनकी दाढ़ी पकड़कर उसपर हमला करनेकी कोशिश की, पर उसे वहीं मौजूद देशी अफसरोंने तलवारसे फीरन काट डाला।

"इस घटनामें कोवनकी कारगुजारी यह थी। किमक्तर फीरसाइथने वार-वार उससे कहा था कि जान्तेकी कान्ती खानापूरी जरूर कर छो। १७ को ही उसने सरकारको तार दिया था—'में घटनास्वलपर हूँ और मामलेको कायदेसे और जरूदी निपटा हूँगा। अधा-धारण कारवाईकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे उत्तेजना बढ़ेगी जो न हो तो ही अच्छा है।' लेकिन जब १८ तारीखको कोवनके खतसे उसे इस भीषण दुखानत घटनाकी स्चना मिली, उसने कोवनको लिखा—'प्रिय कोवन, जो कुछ तुमने किया में उसका समर्थन करता हूँ और उसके लिए अपनी स्वीकृति देता हूँ। तुमने प्रशंसात्मक ढंगसे काम किया है। में आ रहा हूँ।' वह आया और कान्नके मुताबिक १६ केदियोंको फाँसोकी सजा दे हो। वे १६ मी लटका दिये गये।

"इस घटनापर भारत सरकारने एक विस्तृत प्रस्ताव स्वीकार किया। कहा जाता है कि इस प्रस्तावका मसिवदा वाइसरायकी कार्यकारिणीक कानून-सदस्य जिस्ट्स स्टीफेनने तैयार किया था। 'वाइसराय महोदय व उनकी कार्यकारिणो यह दुखद घोपणा करनेकी आवश्यकता समझते हैं कि मिस्ट्र कोवनका तरीका गैरकान्नी था, उसके लिए कोई सार्वजिन स्थिति या आवश्यकताका दवाव नहीं था; इस मामलेमें ऐसी घटनाएँ हुई जो वर्वरता-पूर्ण हैं'; इसलिए वाइसरायने 'खेदके साथ' आदेश दिया कि 'मिस्ट्र कोवनको नौकरीसे अलग कर दिया जाय।' फोरसाइथकी कड़ी आलोचना की गयी और एक दूसरे स्वेमें उसका तवादला हो गया जहाँ उसका ओहदा व तनख्वाह वही रही जो उसे लुधियानेमें मिलती थी। वादमें वह सर डगलस फोरसाइथ हुआ।"

सर डगल्सने अपनी आत्मकथामें इस घटनासे अपना सम्बन्ध वताते हुए लिखा है—''देशी रियासतोंके सुपरिटेण्डेण्ट व किमश्नर होनेकी हैिसियतसे मुझे मौतकी सजा देनेका अधिकार था, जो कोचनको नहीं था। मैंने उसे छुधियानेसे लिखा कि विद्रोहियों-का मुकदमा करो, पर सजा तवतक न दो जवतक मैं न आ जाऊँ। पर कोचनने मनमानी की, मेरा खत जेबमें डालकर उसपर काररवाई करनेसे इनकार किया और कानून अपने हाथमें लेकर कैदियोंको मौतकी सजा दे डाली।...इसलिए मैंने कोचनको काररवाईकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनेका निश्चय किया और ऐसी परिस्थितिमें उसने जो कुछ किया उसका समर्थन करते हुए मैंने एक पत्र उसे लिखा...मैंने उसकी मददके लिए हर संभव कोशिश की और उसके नौकरीसे निकाले जाने पर भारतमें ही उसे एक बहुत अच्छी नौकरी दिला दी।''

मलेरकोटला काण्ड यहीं खत्म नहीं हुआ। पंजाब भरके नामधारी-सम्प्रदायको आतंकित करनेका सरकारी आंदोलन चला। नामधारियोंके पंजाब भरके नेता एक रातमें एकाएक पकड़ लिये गये और कुछ रंगून व कुछ अण्डमान मेज दिये गये। अनुपाततः कम महत्वपूर्ण नेता पंजाबकी जेलोंमें भर दिये गये। गुरु रामसिंह रंगून मेजे गये और उन्हें फिर कभी भारत न आने दिया गया। वे अपने अनुयायियोंमें अँग्रे जोंके खिलाफ विद्रोहकी भावना भरनेके लिए जिम्मेदार थे। वे धार्मिक नेता भी थे और राजनीतिक नेता भी। काफो दिनों वादतक नामधारियोंकी निगरानी होती रही।

सन् ५७ के विद्रोहमें सिख आमतीरपर अँग्रे जोंके साथ थे । जैसा कि सर गोकुलचन्द्र नारंगने लिखा है "दिल्लीमें मारे गये नवें गुरुका नाम ले लेकर और औरंगजेवके उत्तरा-धिकारियोंके उस मौतका वदला लेनेकी अपीलें निकालकर सिखोंको उभारनेकी चाल चली गयी।" सिखोंका अंग्रेज-भक्त वर्ग अपने भाइयोंका कत्लेआम होते और वह भी अंग्रेजके हाथों होते देखकर अचम्मेमें पड़ गया। सिखोंके शान्तिमय जीवनमें एक लहर आयी—सिर्फ एक लहर। शीध ही फिर सब कुछ शान्त हो गया।

१. सर डगलसकी आत्मकथा, पृ॰ ३६,३७,४२,४३

२ नारंग, पृष्ठ ३३६ ।

अध्याय २

हिन्दू सुधार आन्दोलन एवं राजनीतिक जाग्रति

सन् १८५७-५८के विद्रोहके पश्चात् हिन्दू समाजमें कुछ धार्मिक और सामाजिक सुधारकोंका प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने यह सोचकर कि अंग्रेजी राज तो अब कायम हो ही चुका है उसका यथाशक्ति उचित प्रयोग करनेकी कोशिश की। अंग्रेजी शिक्षाके अध्ययनसे वे आजादी, धर्म, राजनीति, और सामाजिक रीति-रिवाजोंकी पाश्चात्य विचारधाराके सम्पर्कमें आये। उन्हें एक नये प्रकारके जीवनका आभास और अनुभव हु आ और इसका उनपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनको हिन्दू समाजमें अनेक बुराइयाँ तथा दोप दिखाई देने लगे। अदम्य धार्मिक उत्साह व लगनके साथ वे उन बुराइयोंको दूर करनेके लिए समाजसुधारके कार्यमें लग गये। वे जानवृह्मकर राजनीतिसे दूर रहे क्योंकि उन दिनों राजनीतिका मतंलव था हिंसात्मक तरीकों द्वारा ब्रिटिश राज खत्म कर देना।

धीरे-धीरे उनका धार्मिक सुधारकार्य विस्तृत होता गया और उन्होंने अन्तमें उस क्षेत्रमें प्रवेश किया जिसे वैधानिक राजनीति कहा जाता था। उन्होंने जो मार्ग अपनाया उसे ५० वृप पहले राजा राममोहन राय (१७७४-१८३३)ने दिखला दिया था। हिन्दू दिकया- न्सीपनके विरुद्ध उन्होंने वड़ा त्याग करके वह रास्ता ग्रहण किया जिसके लिए उन्हें अपने नाते रिस्तेदारोंतकसे अलग होना पड़ा।

जैसा कि ऐंड्रूज और मुकर्जीने लिखा है हिन्दू समाज "उन दिनों दयनीय और मरणासन हालतमें था। सिद्यों के मुसलिम प्रमुखने हिन्दुओं को प्रेरणाशक्ति व कर्मटताको दया
दिया था। पूर्वी वंगालमें विशाल जन-संख्या मुसलमान हो गयो थी, यशि उसके जीवनदर्शन और रहन-सहनकी हिन्दू पृष्टभूमिका लोप नहीं हुआ था। इस प्रकार ऐतिहासिक रूपसे
जब ईस्ट इण्डिया कम्पनीने अपनी शक्ति जमाना आरम्भ किया, हिन्दू समाज दुर्बलताकी
चरम सीमातक पहुँच गया था"।

नवावी शासनकालमें सरकारी नौकरियों में हिन्दू और मुसलमानोंका अनुपात विभिन्न शासकोंकी मनोवृत्ति व रुखपर निर्भर करता था। इस्लामके पश्चपाती शासकोंके जमानेमें सभी महत्त्वपूर्ण पद सिर्फ मुसलमानोंको ही दिये जाते थे, परन्तु कुछ शासकोंके जमानेमें हिन्दुओंको भी वड़ी-बड़ी जगहें मिलती थीं। धर्मान्ध मुलाओंको प्रेरणासे चलनेवाली यह नीति हिन्दुओंको शासनके विरुद्ध कर देती थी। उसके फलस्वरूप हिन्दू मध्यम वर्गका एक भाग ब्रिटिश शासनमें अपनी उन्नतिका स्वप्न देखने लगा और सरकारने भी अपने हितसाधनके लिए हिन्दू-पश्च-पातकी नीति अपनायी और मुसलमानोंका खुल्लम-खुला विरोध किया। सरकार्य नोकरियोंके इच्छुक हिन्दुओंने इसका हार्दिक स्वागत किया। उनके लिए यह केवल निजी आर्थिक प्रश्नथा। पेट भरनेके खातिर सरकारी नौकरी करनेवाले व्यक्तिके लिए राष्ट्रीय समस्याएँ गीण हो जाती हैं विशेपकर जब उसके पूर्वजोंके साथ सरकारी नौकरीमें भेदमाव वग्ना गया हो।

१. सी. एक, ऐंडू ज व गिरिजा मुकर्जी, दि राइज ऐण्ड य्रोथ आव दि कांग्रेस ए० २२

अँग्रेजी राज्य स्थापित होनेके पहले हिन्दू और मुसलमान एक होकर वंगालतकमें अँग्रेजोंसे लड़े थे। धर्मान्ध शासकोंकी संकीर्ण नीति भी उन्हें अँग्रेजोंसे देशको वचानेकी वड़ी जिम्मेदारीसे विरत नहीं कर सकी थी। परन्तु अँग्रेजोंकी पूर्ण विजयके पश्चात् सरकारी नौकरीका प्रश्न पढ़े-लिखे मध्यमवर्गके दिमागमें प्रमुख हो गया।

हिन्दू समाजके इस रहोवदलके जमानेमें राजा राममोहनराय प्रकट हुए। उन्हें "भारतीय राष्ट्रीयताका पैगम्बर और आधुनिक भारतका पिता" कहा जाता है। इतिहास-कारोंने उन्हें "अति स्पष्टदशीं धार्मिक नेता और अगुगामी राजनीतिक विचारक माना है।" वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने शासन और न्याय विभागोंको पृथक करनेकी आवाज उठायी, और वे ही प्रथम भारतीय थे जो पालंमेण्टकी एक समितिके सम्मुख गवाही देनेके लिए इंगलैण्ड गये। समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्वकी पाक्चात्य विचारधाराका प्रभाव उनपर इतना पड़ा कि इंगलैण्डके रास्तेमें जब उन्हें एक फ्रांसीसी जहाज दिखाई पड़ा, जिसपर आजादीका झण्डा फहरा रहा था, तब उन्होंने उसपर जाकर फ्रेंच राष्ट्रके प्रति, जिसने समस्त प्रकारकी गुलामीके विरुद्ध क्रांतिका झण्डा उठाया था, भारतकी श्रद्धांजिल देनेका निक्चय प्रकट किया। जब वे फ्रांसीसी जहाजपर चढ़ रहे थे तो वे फिसलकर गिर गये और उनके पैरमें ऐसी चोट आयी कि वे जनमभरके लिए लँगड़े हो गये।

एक अत्यन्त प्राचीन परम्परा-भक्त ब्राह्मण परिवारमें पैदा होकर होश संभालते ही उन्होंने अपनेको मूर्तिपूजा और संस्कारके वीचमें पाया। उनकी शिक्षा-दीक्षा पटनामें हुई जो उस समय इस्लाम धर्मका केन्द्र था। शिक्षा समाप्त करके जब वे घर लौटे तो मूर्तिपूजा तथा परम्परागत रीति-रिवाजोंसे उनका विश्वास पूरी तरह उठ चुका था। उनका कहना था कि उपनिषद अद्देतवादकी शिक्षा देते हैं जिसमें मूर्तिपूजाका कोई स्थान हो नहीं है।

''कहा जाता है कि अपनी जवानीमें वे अँग्रेजोंको वहुत नापसन्द करते थे। परन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी नौकरीमें अच्छे अनुभवसे और डिगवी जैसे योग्य अँग्रेजोंके सम्पर्कमें आनेके बाद वे अपनी राय बदलने लगे।"

उनमें धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहा था और १८०३ तक उनके सुधार सम्बन्धी विचारों की उनके जीवनपर इतनी गहरी छाप लग गयी कि उनकी स्त्री और माताने उनके साथ रहनेसे इनकार कर दिया। कम्पनीकी नौकरीसे वे १८१४में पृथक हो गये और १८१५में उन्होंने "आत्मीय सभा"को स्थापना को। उन्होंने कई पुस्तकें प्रकाशित, की जिनके द्वारा पढ़े-लिखे लोगोंमें विचारोंका आदान-प्रदान हुआ और विवाद ग्रुक्त हुआ। उनकी आत्मामें सती जैसी प्रथाओंके विरुद्ध विद्रोह-भाव था और उन्होंने उसके विरुद्ध आन्दोलन किया। मुख्यतः उनके प्रचारके फलस्वरूप ही लाई विलियम वैटिंकने एक आज्ञा जारी करके सती प्रथाको निषिद्ध घोषित कर दिया।

सन् १८२८ और १८३३के बीचके कालमें उनके सुधार और सामाजिक कार्य परा-काष्टापर पहुँच गये। इसी कालमें इंगलेण्डमें भी-सुधार-आन्दोलन चल रहा था। ब्रिटिश उपनिवेशोंमें गुलामी प्रथापर रोक, नयी जनतांत्रिक पार्लमेण्ट, भारतमें धार्मिक और जातीय समानताका चार्टर, जैसे सुधारोंकी घोषणा इसी आन्दोलनके फलस्वरूप हुई थी। भारतीय चार्टरमें कहा गया था कि "धर्म, जन्मस्थान, जाति, रंगमेद आदिकी वजहसे किसी भी

१. ऐंड्रूज व मुकर्जी, वहीं पुस्तक; पृ० २४

भारतीयको किसी भी सरकारी ओहदे या नौकरीके लिए अयोग्य न समझा जायगा।" यह घोषणा कभी कार्यान्त्रित नहीं हुई, इंमेशा इसका उब्लंघन किया गया। भारतीयोंको कोई भी बड़ी जगह नहीं दी गयी।

राममोहन राय नहीं चाहते थे कि भारत-शासनका भार ब्रिटिश सम्राट कम्पनीसे ले ले। उनके निर्जा सचिवके लेखानुसार उनका तर्क यह था कि औपनिवेशिक मामलोंमें संवंधित मन्त्री सार्वभीम सत्ताका प्रयोग करता है और पार्लमेण्टके सदस्योमेंसे अधिकतर उसके अधीन-से रहते थे। इसलिए प्रस्तावित तबदीलीके माने होंगे एक ऐसे शासकीय दरेंको, जिसमें शक्ति-के दुरुपयोगपर अनेक प्रतिवन्ध लगे हुए हैं, छोड़कर सार्वभीम सत्ताके अधीन हो जाना।

उन दिनों भारतमें ईसाई पादिरयोंका बहुत जोर था। वे भारतीय धर्मोंको गलत रूपमें प्रदिश्ति कर ईसाई धर्मको ही एकमात्र मुक्ति-मार्ग बताते थे। उनका प्रभाव मिटानेके अभिप्रायसे राममोहन रायने ''ब्रह्मसमाज''की स्थापना की जिसका उद्देश्य हिन्दुओंको यह बताना था कि रीति-रियाजोंके कुसंस्कारोंका पालन हिन्दू धर्म नहीं है, परन्तु हिन्दू धर्म उनसे भिन्न मानवको ऊँचा उठानेवाला है। राममोहन रायकी मृत्युके तीस वर्ष वाद जिस व्यक्तिने जोशके साथ ब्रह्मसमाजका आन्दोलन चलाया वह थे केशवचन्द्र सेन। उन्होंके प्रयत्नोंसे सिविल विवाह कान्त बना जिसके अन्तर्गत कोई भी गैर ईसाई जो यह घोषित कर दे कि वह न हिन्दू है, न मुसलमान, न पारसी और न यहूदी, सिविल विवाह कर सकता था। उन्होंने एक विधेयक तैयार किया जिसमें यह उपवन्ध किया गया था कि विवाहके समय लड़कीकी उम्र क्म-से-कम १४ वर्षकी होनी चाहिये।

वादको ब्रह्मसमाजके प्रमुख सद्स्योंमें इस वातपर मतभेद होने लगा कि मुधारकी क्या सीमा और क्या तरीके होने चाहिये। मतभेद वढ़ा और नयी संस्थाओंका जन्म हुआ, जैसे प्रार्थना समाज, भारतीय ब्रह्मसमाज, साधना समाज। यादके वपोंमें इन संस्थाओंने भारतीय राष्ट्रीय कांब्रेसको कई वड़े बढ़े नेता प्रदान किये। धीरे-धीरे ये सभी समाज अंग्रेजी पढ़े- लिखे लोगोंकी गोष्टियाँ वनकर रह गयीं जिनके सदस्यों और जनतामें कोई सम्पर्क न था।

ब्रह्मसमाजके समान ही आर्यसमाज एक दूसरा धार्मिक आन्दोलन था जिसने भविष्य-की राजनीतिपर एक अमिट छाप डाली। आर्यसमाज वताता था कि ज्ञान और प्रकाशके लिए भारतको पिरचमी दर्शन नहीं, वेदोंपर आश्रित होना चाहिये। ब्रह्मसमाजकी तरह आर्य-समाज भी ईसाई प्रचारके विरुद्ध चुनौती वनकर आया। उसके प्रवर्चक स्वामी द्यानन्द कहते थे कि यदि भारतीय वेदोंके अनुसार अपने आचरण सँभाल लें तो उनकी हीनताकी भावना जाती रहेगी। जैसे-जैसे समय बीतता गया आर्यसमाज पड़े-लिखे उत्साही युवकींका केन्द्र वनता गया। इसने भी भविष्यकी राजनीतिको कई नेता दिये।

आर्यसमाजके कृत्योंके एक पहल्ते मुसलमानोंको कुद्ध कर दिया—यह पहल् था अहिन्दुओंकी शुद्धि । आर्यसमाजियोंकी यह वहस थी कि यदि इस्लाम और ईसाईधर्ममं अन्य धर्मोंके अनुयायी प्रवेश पा सकते हैं, तो हिन्दूधर्मका दर्शाजा भी अन्य धर्मावलिश्योंके लिये खुला होना चाहिये । यह तर्क अकाट्य था । वेदोंमें धर्म-परिवर्तनपर कोई रोक नहीं है । इस तर्कको ऐतिहासिक मजवृती भी प्राप्त थी । वैदिक धर्म प्राचीनतम था; अन्य धर्मोंका प्रादुर्भाव हजारों वर्ष वाद हुआ । अनेक पुस्तके और पुस्तिकाएँ यह सिद्ध करनेके लिए निकाली गर्यी कि अन्य सभी धर्मोंकी अच्छी वातोंका आधार वैदिक धर्म ही है । आर्यनमान

जियोंके सम्मुख मुसलमान और ईसाई प्रचारकोंका उदाहरण था जो अपने धर्मावलिम्वयोंकी संख्या वहानेमें बड़े जोशके साथ काम करते थे। लगभग ९० प्रतिशत भारतीय मुसलमान हिन्दू धर्मसे ही इस्लाममें गये; हिन्दुओंको मुसलमान बनानेका काम नित्य प्रति चलता रहता था। रीति-रिवाजोंके कारण हिन्दूधर्ममें अनेक बुराइयाँ आ गयी थीं, जैसे वालिववाह, जिस्का परिणाम था युवती विधवाओंकी संख्यामें वृद्धि, विधवाविवाह निपेध, और अस्पृश्यता। और इन दोषोंसे मुक्त इस्लाम धर्म इन दुःखी व्यक्तियोंको शरण देता था। इस प्रकार हिन्दु ओंकी संख्याकी कमीसे मुसलमानोंकी संख्या वृद्धि होती जाती थी। स्वामी दयानन्दने इन बुराइयोंकी जड़पर कुल्हाड़ी चलायी। उनके अनुयायी यह प्रचार करते हुए घूमने लगे कि विधवाओंका पुनर्विवाह होना चाहिये, वेदोंमें अस्पृश्यता वर्जित है, हिन्दुओंके सव वर्गोको (जिनमें तथाकथित अद्यूत भी शामिल हैं) आपसी व्यवहार और खान-पानमें कोई भेद-भाव नहीं करना चाहिये।

परन्तु आर्यसमाजका धर्म-परिवर्तनका कार्य कुछ अधिक सफल न रहा; इसका उल्टा परिणाम यह निकला कि मुसलमान आर्यसमाजको अपना शत्रु समझने लगे। क्योंकि अँग्रेज शासक हिन्दू-मुसलमानके आपसी भेदभावको वढ़ानेमें हर तर्राकेका इस्तेमाल करते थे, धर्म परिवर्तनका प्रचार भारतके राष्ट्रीय और राजनीतिक जीवनके लिए हानिकारक ही सिद्ध हुआ। उसके फलस्वरूप दोनों जातियाँ कमजोर होती गर्यी और अँग्रेजी शक्ति बढ़ती गयी। लेकिन, जैसा कि श्रोमती एनी वेसेण्टने कहा है, "द्यानन्द प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम घोषणा की कि भारत भारतीयोंका हैं।"

दूसरी धार्मिक संस्था जिसने अप्रत्यक्ष रूपसे भारतीय राजनीतिपर प्रभाव डाला, रामकृष्ण मिद्यन थी। रामकृष्ण वंगालके प्रायः अद्यिक्षित ग्रामीण पुरोहित थे। उनका मत था कि
विभिन्न धर्म एक ही लक्ष्यपर पहुँचनेके लिए विभिन्न मार्ग हैं। स्वामी दयानन्दकी भाँति
उन्होंने भी भारतीयोंको वताया कि उन्हें पादचात्य संस्कृतिकी नकल नहीं करनी चाहिये,
और इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीयताकी भावना जाग्रत की। परन्त दयानन्दके विपरीत वे
परम्परागत हिन्दू पूजा-पद्धतिके पक्षपाती थे। उनके मतानुसार भगवानकी पूजा और प्राप्ति
हिन्दुओंके प्राचीन ढंगसे हो सकती थी जिसकी ईसाई प्रचारक हँसी उड़ाते थे।

उन्नीसवीं सदीके उत्तरार्द्धमें भारतीय विद्वान् देशके प्राचीन गौरवका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए आध्यात्मिक क्षेत्रमें खोज कर रहे थे। वेदों और उपनिषदोंका देशकी प्रचलित भाषाओं में अनुवाद किया गया; धर्म और दर्शनपर बहुतसे ग्रन्थ लिखे गये।

उधर विद्रोहके परचात् अनेक किव और लेखक जनतामें आजादोकी भावना जाग्रत करनेका प्रयत्न कर रहे थे। सन् १८५९ में रंगलाल वनर्जीने 'पिंचनी' नामक एक नाटक लिखा जिसका नायक अपना प्रभावशाली भाषण इस प्रकार करता है—"कीन ऐसा व्यक्ति है जो अपमानज्नक गुलामीमें रहना चाहेगा! कीन ऐसा है जो गुलामीकी वेड़ियाँ पहनना पसन्द करेगा! युगोंतक गुलामीमें रहना नरक समान है, एक दिनकी भी आजादी सुख की पराकाष्टा है। उस व्यक्तिका जीवन और शक्ति धन्य है जो अपनेको उत्सर्ग करके देशको आजाद कराता है।"

वैसे तो रवींद्र ठाकुरके प्रायः सभी कुटुम्वियोंने राष्ट्रीय भावनाओंको जाग्रत करनेमें योग

१. हेमेन्द्रनाथदास गुप्त द्वारा 'दि इण्डियन नैशनल कांग्रेस' में पृ० १६ पर उद्धत

दिया, परन्तु उन सबमें देवेन्द्रनायका स्थान उच्चतम है। वे अंग्रेजी चमकसे प्रभावित नहीं हुए और यह आरोप कभी स्वीकार नहीं किया कि भारतीय नीचे दर्जेंके लोग हैं। कुण्णनगर कालेजके प्रिंसिपल, लीवने एक समाचार-पत्रमें देवेन्द्रनाथके विषयमें इस प्रकार लिखा था— "यह वयोग्रद्ध गर्वीला पुरुष अंग्रेजोंकी प्रशंसातक स्वीकार नहीं करता।" देवेन्द्रनाथने "तत्ववोधिनी पत्रिका" नामक समाचारपत्रकी स्थापना की। उसके विषयमें प्रसिद्ध किं और नाटककार ज्योतीन्द्रनाथ ठाकुरने लिखा है—"राष्ट्रीय भावनाका प्रचार 'तत्ववोधिनी'का आरंभ होनेके साथ बढ़ने लगा। अक्षयकुमार दत्तने भारतके प्राचीन गौरवपर कहानियाँ और लेख लिखकर लोगोंके हृदयोंमें देशभिक्तकी भावनाएँ जाग्रत की।"

राजनारायण वसु और नवगोपाल मित्रने (जो आदि ब्रह्मसमाजो थे) देशभिक्त और राष्ट्रीय विचारोंका प्रचार करनेके उद्देश्यसे 'हिन्दू मेला' आरम्भ किया। नवगोपाल 'नैशनल पेपर' नामक पत्रके सम्पादक थे। अन्य राष्ट्रीय आन्दोलनोंसे भी उनका सम्बन्ध था। उन्हें 'नैशनल' (राष्ट्रीय) शब्द इतना प्रिय था कि उसके कारण उनका नाम ही 'नैशनल नवगोपाल' पड़ गया। रवीन्द्रनाथ ठाकुरने अपने ''संस्मरणों''में लिखा है कि नवगोपालका ''अट्टर देशप्रेम एक आध्यात्मिक उत्साह था। देशके नामपर उनकी आँखें चमकने लगतीं, वे उत्साहसे उद्यल पड़ते, और चाहे उनकी आवाज सुरमें मिलती यान मिलती वे सबके साथ गाने लगते—

'हमने वाँघा है हजारों हृदयोंको एकताके सूत्रमं

'हमने समर्पित किये हैं हजारों जीवन वस एक कार्यके लिए''।

'हिःद्मेला' संघटित करनेके लिए एक समिति स्थापित की गयी । इसका एकमात्र उदेश्य लोगोंको राष्ट्रीय गौरवका बोध कराना था ।

इस मेलेके विषयमें राजनारायण वसुने लिखा है—"जब में एक अँधरे तंग कमरेमें समितिका काम करता था तब संाच भी नहीं पाता था कि इसका फल विशाल चेत्र मेला या हिन्दुओंका इतना वड़ा संग्रह होगा।" प्रथम मेला सत्येन्द्रनाथ टाकुरकी एक कविताके पाटते ग्रुक्त हुआ जिसका रुपान्तर यह है—"इम सब भागतीय एक स्थानपर इकट्टा होकर, एकचित्त और एक स्वरसे भारतकी गौरव-गाथाका गान करते हैं। भारत जैसा देश और कीन है जिसके पर्वत हिमालयके समान ऊँचे हीं, जहाँकी भूमि ऐसी उर्वरा हो, जहाँ इतनी विशाल नदियाँ हीं, जहाँ मणिमुक्ताकी सहस्रों खानें हों। आओ गारें मिलकर गारें भारतके विजय गान" इत्यादि।

उसके बाद तो जैसे राष्ट्रीय कविताका युग आ गया। बीसों नाटककारोंने देश-भक्तिके नाटकोंकी रचना की। रंगभूमि राष्ट्रीय भावनाओंके प्रचारका इतना बड़ा शक्ति-शाली माध्यम बन गयी कि सरकारको आशंका होने लगी और उसने रंगभूमिके दमनकें लिए हुँमेटिक परफार्मेन्स ऐक्ट (नाटक नियन्त्रण कान्न) बनाया।

शायद राष्ट्रीय लेखकोंमें सबसे उँच स्थान बंकिमचन्द्रका था। उनके लेखोंमें ने एक उद्धरण यहाँ दे देना ठीक होगा-"भारतका भविष्य अन्धकारमय रहेगा, जवतक सब भारतीय जातियाँ एक मत, एक नीति और एक ध्येयसे ओतप्रोत नहीं होती। यह एकता निर्म

१. वहीं पुस्तक ए० ३१

२. वही पुस्तक पृ०३२

अंग्रेजी भाषाके साध्यमसे ही आ सकती है क्योंकि संस्कृत अब एक मृत भाषा है। अंग्रेजी ही एक ऐसी भाषा है जिसे वंगाली, पंजाबी, महाराष्ट्री इत्यादि सभी समझते हैं। इस भाषाकी डोरीसे हम सब एक सूत्रमें वँघ सकते हैं। इसिटए अंग्रेजी भाषाका प्रचार यथा-सम्भव वढ़ाना चाहिये। परन्तु विल्कुल अंग्रेज बन जाना अच्छा न होगा। वंगाली कभी भी अंग्रेज नहीं वन सकता।

"वन्दे मातरम्" वंकिम बाबूका रचा हुआ प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत है जो लाखों बार कांग्रेसकी सभाओं में गाया गया और जिसने लाखों व्यक्तियोंको कांग्रेसकी ओर आकृष्ट किया। यह गीत बंकिम बाबूके उपन्यास 'आनन्द मठ'में (जो १८८२में लिखा गया था) आता है।

एक अन्य संघटन जिसने राष्ट्रीय उत्थानमें मंगलकारी और मूल्यवान योग दिया, समाज सुधार आन्दोलन था। इस सुधार आन्दोलनका श्रीगणेश भी वंगालमें ही हुआ। शिशपद वनजां (१८४०-१९२४) इस आन्दोलनकी जान थे। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर (१८२०-१८९१) भी सामाजिक सुधारमें उत्साह और आत्मत्यागसे काम करते थे। वे विख्यात विद्वान थे, उनके संसर्गसे सामाजिक आन्दोलनको काफी प्रतिष्ठा मिली। महादेव गोविन्द रानडे, मलावारी और नारायण चन्दावरकरने महाराष्ट्रमें राष्ट्रीय विचारोंका प्रसार किया। रामवाई सरस्वतीने भी सुधार आन्दोलनमें महत्त्वपूर्ण कार्य किया। दक्षिणमें आन्दोलनका संचालन रघुनाथ राव, वीरेसलिंगम और 'इण्डियन सोशल रिफार्मर'के संपादक नटराजनने किया। आन्दोलनका काम स्त्रियोंकी स्थितिमें सुधार करना और हिन्दू समाजके सभी बड़े और छोटे वर्गोंमें समानताकी मनोवृत्ति पैदा करना था।

१. हेमेन्द्रनाथदास गुप्त, 'दि इंडियन नेशनक कांग्रेस', पृ० ४१

R. Social Reform movement.

अध्याय ३

वैधानिक आन्दोलनका आरम्भ

वंगालमें वैधानिक राजनीतिका आरम्भ १८३७ में खापित जमींदारी ऐसोसियेशनसे माना जाता है। यद्यपि उसकी खापना मुख्यतः जमींदारों के स्वस्वों और अधिकारों की रक्षां लिए ही हुई थी, बादको उसके कार्यक्षेत्रका विस्तार बढ़ा और वह जनसाधारणके हितों की बातोंपर भी गौर करने लगी। उसकी पहली वैठकमें जो १२ नवम्बर १८३७ को हुई, निश्चय किया गया कि जमींदारी ऐसोसियेशन सब प्रकारके लोगोंकी संस्था होगी, जाति, रंग, देशका कोई भेद-भाव इसमें न होगा। पार्थक्यकी हर भावनाको त्यागकर यह संस्था व्यापक और उदार सिद्धान्तोंपर चलेगी। ऐसोसियेशनकी सदस्यताके लिए एक ही योग्यताकी जरूरत होगी; इसके सदस्य वही हो सकेंगे जो थोड़ी बहुत भूमिके स्वामी ही। अर्थ इसके सदस्योंमें ब्रह्म-समाजके कतिपय प्रमुख नेता थे। राजा राजेन्द्रलाल मित्रके शब्दोंमें इस ऐसोसियेशनने ही 'पहली बार लोगोंको वैधानिक ढंगसे लढ़ना और प्रतिधा व साहससे अपने अधिकारोंकी माँग करना व अपना मत प्रकट करना सिखाया। ''

२० अप्रैल, १८४३ को एक दूसरी संस्था जिसका नाम "वंगाल ब्रिटिश इण्डिया सोसायटी" था, स्थापित हुई। इसका उद्देश्य सम्पूर्ण ब्रिटिश भारतमें वसनेवालोकी असली दशा, देशके कान्स, संस्थाओं और साधनोंके विषयमें जानकारी इकट्टी वरना और उसे प्रसारित करना तथा अन्य शान्तिमय और कान्सी उपायोंको काममें लाना था जिनमें समस्त प्रजाजनके हित और न्यायोचित अधिकार बढ़ें और उनकी भलाई हो।" सोसाइटीने निश्चय किया कि वह सिर्फ ऐसी कारस्वाइयोंको अंगीकार करेगी और ऐसी सिफारिशं करेगी "जो भारतके सम्राट और उनकी सरकारके प्रति पूर्ण निष्ठासे ओतप्रोत होंगे और जिनसे देशके कायदे-कान्नोंकी अवशा न होगी। सोसायटी ऐसे प्रयत्नोंका विरोध करेगी जिनका उद्देश्य कान्सी प्रशासनके विरुद्ध कारस्वाई करना हो या समाजकी शान्ति या हितमें खलबरी पैदा करना हो।" परन्त सोसाइटीने कुछ प्रगति नहीं की। इन दोनों संस्थाओं के सदस्य सिर्फ उच्चर्गके भारतीय और गैरसरकारी अंग्रेज थे।

परन्तु अंग्रेजोंको जब्दी ही ये संस्थाएँ छोड़ देनी पड़ीं । इसके दो कारण थे। (१) सन् १८५० में भारत सरकारने केन्द्रीय विधानसभामें एक विल उपस्थित किया जिसका उद्देश्य गरीव किसानोंको गैरसरकारी अंग्रेजोंके अत्याचारसे वचाना था। नील ओर चाय वागानोंके अंग्रेज मालिकोंका व्यवहार इन गरीव और असहाय किसानोंके साथ घोर अत्याचारपूर्ण था। और जब किसानोंके कष्ट सार्वजिनिक आन्दोलनका रूप लेने लगे तो सरकारको इस्तक्षेप करना पड़ा। (२) उन दिनों भारतके किसी भी भागके रहनेवाले अंग्रेज अपराधीके

१. वही पुस्तक पृ० ९८

२. 'राजा राजेन्द्रलाल मित्रा'न स्पीचेज', पृ० २५

विरुद्ध केवल कलकत्त्रोमें ही मुकदमा चलाया जा सकता था क्योंकि कान्तके अनुस्प कलकत्ता अदालत ही उसके मुकदमोंकी सुनवाई कर सकती थी। सरकारने महस्स किया कि कान्तमें ऐसा सुधार कर दिया जाय कि अंग्रेज अपराधीका मुकदमा भी भारतीयोंकी माँति, उसके निवास-स्थानकी अदालतमें ही पेश हो सके। तदनुसार काँसिलमें विल उपस्थित कर दिया गया। अग्रेज लोग बहुत चिढ़ गये और उन्होंने आन्दोलन करनेकी ठान ली। सरकारने मज़बूर होकर विल वापिस ले लिया। अंग्रेजोंके इस स्वार्था और संकीर्ण दृष्टिकोणने भारतीय जनताको उनके विरुद्ध कर दिया। पहलेका सौहाई विद्वेषमें बदलने लगा। इस परिवर्तित मनोवृत्तिका फल यह हुआ कि ३१ अक्टूबर, १८५१ को एक नितान्त विशुद्ध भारतीय संस्था— विटिश इण्डियन ऐसोसियेशन'—कायम कर दी गयी।

उसी वर्षे जगोनाथ शंकरसेट और दादाभाई नौरोजीने वम्बई ऐसोसिएशनकी स्थापना की । इसने सर मंगलदास नाध्भाईके नेतृत्वमें काफी प्रगति की । वंगालके रामगोपाल घोष और ऋष्णदास पालकी माँति नाथ्भाईको भी वम्बई कारपोरेशनमें अनेक संग्राम लड़नेके उपलक्ष्यमें, 'जनताके धर्माधिकारी' के नामसे पुकारा जाने लगा । परन्तु वम्बई ऐसोसिएशन दस वर्षसे अधिक न चल पायी, जब कि ब्रिटिश इण्डियन ऐसोसिएशन ५० वर्षोतक कायम रही । वम्बई ऐसोसिएशनको नौरोजी फरदूनजीने १८७२में नया जीवन दिया, पर वह शीष्ठ ही खत्म हो गयी। र

विदिश इण्डियन ऐसोसियेशनका उद्देश्य उसकी सर्वप्रथम सालाना रिपोर्टमें इस प्रकार वताया गया था—''भारतके स्थानीय प्रशासनमें और पार्लमेण्ट द्वारा निर्धारित शासनपद्धतिमें सुधार करवाना''। उस समय ईस्ट इण्डिया कम्पनीका चार्टर वदलनेवाला था। जनताके नेताओंने यह निश्चय किया कि पार्लमेण्टके सामने सरकारी शासनपद्धतिमें परिवर्तन और सुधारकी माँग एकमतसे रखनी चाहिए। इस उद्देशके लिए एक संस्थाकी स्थापना करना आवश्यक था। इसलिये ब्रिटिश इण्डियन ऐसोसियेशनकी बुनियाद पड़ी। सन् १८५२ में ऐसोसियेशनने पार्लमेण्टके पास एक अर्जी मेजी जिसमें कहा गया था कि भारतीय इस निश्चयपर पहुँचे हैं कि उन्हें ब्रिटेनसे सम्यन्ध स्थापित होनेसे उतना लाम नहीं पहुँचा जितने लामकी आशा करना उनका अधिकार है।

अर्जीकी मुख्य माँगें वे थीं—(१) माल-व्यवस्थाकी कड़ाई दूर करना; (२) न्याय प्रशासनमें सुधार (३) जनसाधारणके जान-मालकी रक्षा; (४) ईस्ट इण्डिया कम्पनीके व्यापारिक एकाधिकारोंसे भारतीयोंको राहत दिलाना; (५) देशी उत्पादनको प्रोत्साहन, (६) जनताकी शिक्षाका उचित प्रवन्ध; (७) शासनके ऊँचे पदोंपर भारतीयोंकी नियुक्ति करना ।

अजींमें निम्नलिखित सुझाव भी दिये गये (१) भारतीय शासन सम्बन्धी मामलों के संचालनके लिए एक कमेटी नियुक्त की जाय। (२) केन्द्रीय सरकारका नियन्त्रण सिर्फ राजनीतिक और फौजी मामलों में, प्रेसीडेन्सियों के गवर्नरों के ऊपर तथा भारतीय विधायिका सभाओं द्वारा वनाये कान्नों को रद्द करनेपर हो। (३) भारतीय विधायिका सभाएँ केवल उन लोगों से जिनको राजनीतिक और प्रशासनकी शक्ति दी गयी है, जुदा ही न हों वरन् उनमें जनप्रिय लोग भी हों जो भारतीय जनमतका प्रतिनिधित्व कर सकें और जिन्हें भारतके लोग अपना समझें। (४) कलकत्तेमें एक विधान परिषद स्थापित होनी चाहिये जिसमें १७

१. अम्विकाचरण मजुमदार, इण्डियन नैशनल इवौल्यूशन, पृ० ६

सदस्य हों, अर्थात् तीन-तीन सदस्य हर प्रेसीडेंसीके जाने-माने प्रसिद्ध-प्रसिद्ध व्यक्तियों मेंसे लिये जावें, एक-एक सदस्य प्रेसीडेंसीके गवर्नसें द्वारा ऊँचे अपसरों मेंसे नियुक्त किया जाय और एक सदस्य सम्राट द्वारा मनोनीत हो जो परिपदका अध्यक्ष हो और जिसपर सरकारका कोई द्वाव न हो।

त्रिटिश इण्डियन ऐसोसियेशन ही प्रथम संस्था थी जिसने भारतमें अंग्रेजी राजके आर्थिक तथा राजनीतिक फलका अध्ययन किया । पार्लमेण्टको जो अर्जी ऐसोसियेशनने भेजी थी उसमें उसने समरत शासन-विभागोंका सिंहावलोकन किया तथा सुधार सम्बन्धी अपने सुझाव दिये। उसने अंग्रेजी न्यायप्रणाली, पुलिस, दीवानीमें फीजदारी कान्नों और मैजिस्ट्रेटोंकी आलोचना की। आर्थिक क्षेत्रमें उसने कम्पनीके व्यापारिक एकाधिकारोंको समाप्त करनेकी माँग की, विशेषकर नमक व्यापारकी इजारेदारीको। माल व्यवस्थाक सम्बन्धमें अर्जीमें लिखा गया था कि यद्यपि जमीन व अन्य कर जो अंग्रेजी सरकार वस्त करती है मुसलमानी शासनकालसे कहीं अधिक हैं, परन्त तव भी अंग्रेजी सरकार आने जानेके थल व जल मागोंके साथनोंपर बहुत छोटो रकम खर्च करती है। उसने पादरियों तथा अन्य बड़े-बड़े धार्मिक पदाधिकारियोंको सरकारी खजानेसे भारी वेतन दिये जानेपर कड़ी आपित की, विशेषकर इसलिए कि कम्पनीकी सरकार हिन्दू नुमुसलमान तथा ईसाइयों की एक मिली जुली आवादीपर शासन करती थी।

ऐसोसियेशनकी स्थापनाके फीरन वाद ही इसके मन्त्री देवेन्द्रनाथ ठाकुरने मद्रासमें भी ऐसोसियेशनकी शाखा स्थापित करनेके विचारसे मद्रासके नेताओंसे लिखा-पढ़ी आरम्भ की । ११ दिसम्बर, १८५१ को उन्होंने मद्रासचालोंको सुझाव भेजा कि पार्लमण्टके पास भेजी जानेवाली अजियोंका महत्त्व और भी बढ़ जायगा यदि कम्पनीके नये चार्टर यदलनेके समय सम्पूर्ण भारतके विभिन्न लोगोंकी ओरसे वे अजियाँ एक साथ भेजी जाने या ऐसी संस्थाकी ओरसे भेजी जाने जो समस्त भारतके प्रतिनिधित्वका दावा कर सके।"

इस पत्रका मद्रासमें असर हुआ और वहाँ ऐसोसिएशनकी शाखा खुल गयी जिसका उद्देश्य था—''समस्त वैधानिक और कान्नी उपायों द्वारा भारतके ब्रिटिश शासनमें उत्तर मता और सुधार लानेका प्रयत्न करना ताकि भारत और ब्रिटेन दोनोंके हितेंकि रक्षा हो और भारतीय प्रजाकी दशा सुधरे।"

अवधमें इस ऐसोसिएशनकी शाखा खुल गयी। वहाँ यह उद्देश रखा गया— "महारानीको भारत सरकारको सहायताके लिए, विशेषकर अवधमें, हर वैधानिक व कान्नी उपायका प्रयोग करना ताकि यह सरकार भारत और ब्रिटेन दोनों देशोंकी जनताको भलाईमें कारगर और कामयाय हो सके।" जमीदारोंकी बढ़ी संख्या इस ऐसोसिएशनमें शामिल हो गयी।

परन्तु ऐसोसिएशनका अखिल-भारतीय रूप न वन सका । इम ऐसोमिएशनकी स्यापना और सन् ५७ के विद्रोहक बीचके कालमें अंग्रेजीं और भारतीयोंका जाति द्वेप अपनी पराकाष्ट्रापर पहुँच गया था।

विद्रोहके बाद ऐसोसिएशनमें परिवर्तन हुआ । इसका राजनीतिक रूप समान हो गया; जमीदारों के हितोंकी रक्षा करना ही अब इसका उद्देश्य रह गया। वह सरकारी छैर-

१, राजा राजेन्द्रलाल मित्रा'ज स्पीचेज ए० १०२—३

ख्वाहोंकी जमात वन गयी । सन् १८५९ में इसने पार्लमेण्टसे देश भरमें इस्तमरारी वन्दोन्वस्त लागू करनेकी प्रार्थना की । अर्जीमें कहा गया था कि भारतमें विद्रोहके वादकी गड़-वड़ने "वन्दोवस्तवाले जमींदार वर्गका राजनीतिक महत्त्व सावित कर दिया है। यह महत्त्व जमीनके उन मालिकोंके महत्त्वसे कहीं ज्यादा है जो विभिन्न नामों व उपाधियोंसे उन स्वोंमें जाने जाते हैं जहाँ इस्तमरारी वन्दोवस्त नहीं है। विद्रोहके अतिसंकट कालके खैरख्वाहों और गैर-खैरख्वाहोंकी तुलना करनेसे पता चल जायगा कि इस्तमरारी वन्दोवस्तसे वह शक्तिशाली वर्ग पैदा होता है जो अपने और शासकोंके हितोंको एक ही समझता है, और जो अपनी स्थितिसे संतुष्ट है। जो व्यवस्था इस्तमरारी वन्दोवस्तसे भिन्न है उसकी वृत्ति और परिणाम भी भिन्न है, यह सावित हो चका है।"

इस्तमरारी वन्दोवस्त जमींदारोंके लिए अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुआ, परन्तु किसानों-का जैसा कि इस पुस्तकके एक अन्य अध्यायमें वताया गया है, इससे बहुत अहित हुआ। सन् १८६० में ऐसोसियेशनने फिर पार्लमेण्टको अर्जी भेजी जिसमें इस्तमरारी वन्दोवस्तकी माँगको दुहराया।

फिर भी, विद्रोहसे पहले ऐसोसियेशन देशकी प्रमुख संस्था थी। वंगालके कई प्रमुख नेताओंने इसी संस्थाके द्वारा सार्वजनिक जीवनमें पदार्पण किया और ख्याति पायी। इन नेताओंमें थे ऐसोसियेशनके मुखपत्र 'हिन्दू पैट्रियट'के संपादक हरिश्चन्द्र मुकर्जी, ऋष्णदास पाल, प्रसिद्ध वक्ता रामगोपाल घोप, राजा दिगम्बर मित्र, महाराजा रामनाथ, सर ज्योतीन्द्र मोहन ठाकुर, महाराजा वहादुर सर नरेन्द्र ऋष्ण, राजा राजेन्द्रनारायण देव, तथा राजा राजेन्द्रलाल मित्र।

ऐसोसियेशनमें अब भी कृष्टोदासपाल जैसे व्यक्ति थे जो आवश्यकता पड़नेपर जनताके हितोंके लिए बहादुरीसे लड़ सकते थे, परन्तु ऐसोसियेशन अपने पुराने जीवनकी छायामात्र रह गया था। अब किसी दूसरी संस्थाकी आवश्यकता थी। सन् १८७५ में शिशिरकुमार घोप तथा उनके भाई मोतीलाल घोपने 'इण्डियन लीग'की स्थापना की। डाक्टर शम्भूनाथ मुकर्जी इसके अध्यक्ष हुए। डाक्टर मुकर्जीका नाम उस समयके एक साहितिक कार्यके साथ जुड़ा हुआ है। सन् १८७६ में कलकत्तेके टाउनहालमें, वंगालके लेपटोनेण्ट गवर्नर सर रिचर्ड टेम्पलके सभापतित्वमें एक सभा की गयी। सभाका उद्देश्य इस प्रस्तावपर विचार करना था कि वाइसरायके नामपर (जो अवकाश प्राप्त करके इंगल्लेण्ड वापिस जा रहे थे) एक स्मारक बनवाया जाय। डाक्टर मुकर्जी तथा उनके नौ साथियोंने उस प्रस्तावमें एक संशोधन पेश किया जिसका अपत्यक्ष अभिप्राय था कि जनताको वाइसरायमें विश्वास नहीं है। संशोधन स्वीकार नहीं हुआ। उस समयके पढ़े लिखे लोगोंमें वाइसरायमें पित अत्यन्त क्षोभ था क्योंकि उन्होंने नाटकोंपर प्रतिवन्ध लगानेवाला कानून जारी किया था और उसके द्वारा रंगमंचको दवा दिया था। बादको मोतीलाल घोप 'अमृत वाजार पत्रिका'के संपादक हो गये, जिसने वादमें राष्ट्रीयताके विकासमें अच्छा हिस्सा ग्रहण किया।

इण्डियन लीग जनप्रिय न वन सकी । इसका एक कारण पदाधिकारियोंका आपसी मतभेद भी था । लेकिन यह मानना पड़ेगा कि इण्डियन लीग प्रथम संस्था थी जिसमें जमीं-दारोंका वोल-वाला नहीं था और जिसमें मुख्यतः मध्यम वर्गाय लोग ही थे ।

इसी समय भारतीय राजनीतिक गगनमें एक नये सितारेका उदय हुआ। वे थे

सरेन्द्रनाथ वनजी । सरकारी नौकरीकै शुरूमें ही एक गलतीने उन्हें राजनीतिमें ला खड़ा किया । सन् १८७१ में सिविल सर्विसकी परीक्षा सफलतापूर्वक पास करनेके बाद, २२ नवम्बरको वे सिलहटके सहायक मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए । परन्तु शीव ही उनके एक क्लर्कने उन्हें मुसीयतमें डाल दिया । उस द्भतरमें क्लकोंने कुछ ऐसी प्रथा चला रखी थी कि यदि किसी फीजदारीके मुकदमेको अधिक कामके कारण या किसी अन्य वजहसे स्थगित करवाना हो तो अभियुक्तको फाइलमें फरार दिखा देते थे और ऐसिस्टेण्ट मजिस्ट्रेटरे मुकदमा स्थागत करा होते थे। परन्तु एक अभियुक्त युधिष्ठिरके मामलेमें उचाधिकारियोंने यह चालाकी पकड़ ली।' मुरेन्द्र-नाथ वनजॅकी ईमानदारीपर सन्देह हुआ और उन्हें वरखास्त कर दिया गया । राजनीतिक चेतनाका युग था; लोगोंने कहना गुरू कर दिया कि वनजी भारतीय हैं, वस इसलिए उनको वरखास्त कर दिया गया है। परन्तु वनजींकी हानिसे देशका वड़ा लाभ हुआ। वह एक ऐसी संस्था वनानेके प्रश्नपर गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे जो शिक्षित मध्यम वर्गकी भावनाओंका प्रतिनिधित्व करे और जो उस वर्गमें सार्वजनिक कामोंकी लगन पैदा करे। वे सोचते थे कि जमींदारोंकी संस्था होनेके कारण ब्रिटिश इण्डियन ऐसीसियेशन किसी आन्दो-लनका नेतृत्व नहीं कर सकती। यह तथ्य स्वयं ऐसोसियेशनके नेताओंने भी स्वीकार किया। एक वर्षकी तैयारीके वाद इण्डियन ऐसोसियेशनके नामसे नयीं संस्थाका जन्म २६ जुलाई १८७६ को हुआ। वनजीने उसके सिद्धान्तोंको इस प्रकार वताया। (१) देशमें स्वतन्त्र जन-मत तैयार करना; (२) समस्त भारतीयों व विभिन्न जातियोंमें राजनीतिक हितों और आकां-क्षाओं के आधारपर एकता पैदा करना; (३) हिन्दू और मुमलमानों के बीच मित्रभाव बढ़ाना, और (४) जनसाधारणको राजनीतिक आन्दोलनोंमें शासिल करना।

वादमें इस ऐसोसियेशनके एक नेताने इसके सिद्धान्तोंकी व्याख्या करते हुए कहा— "विटिश नरेशके प्रति वफादारी और वैधानिक सरकारकी स्थापनाके लिए आन्दोलन करना ही ऐसोसियेशनके दो सिद्धान्त हैं जिनको हमने सदा बढ़ाया है।"

सरकारी नौकरीं हटाये जानेके कारण कुद्ध होकर वनजींने राजनीतिमें प्रवेदा नहीं किया था । देशसेवाकी उनमें तीव आकांक्षा थी । उनपर मैजिनीके देखोंका भारी प्रभाव पड़ा था । उन्होंने लिखा है—''मैजिनीको देशमिक्तकी पवित्रता, उनके सिद्धान्तोंकी उचता, मानवमात्रके लिए उनका व्यापक प्रेम, उनके हृदयोद्वार भरे शब्दोंने जैसा मुझे प्रभावित किया है ऐसा में कभी नहीं प्रभावित हुआ । मैजिनीने इटली निवासियोंको एकताका पाट पहाया । हम भारतीय एकता चाहते थे । मैजिनीने युवकों द्वारा काम किया । में चाहता था कि वंगालके युवक भी अपनी शक्ति समझें और अपनेको देशकी मुक्तिके लिए तैयार करें । जब कभी मैंने मैजिनीके ऊपर भाषण किये, मैंने सावधानीके छाथ नवयुवकों सहा कि वे उनके (मैजिनीके) कान्तिकारी विचारों हुर रहें, परन्त उनके त्याग तथा आत्मविद्धानका अनुकरण वैधानिक प्रगतिके लिए करें"।

इस ऐसोसियेशनकी स्थापनाके एक वर्षके भीतर ही बनजीको एक जनान्दोलन आरम्भ करनेका अवसर प्राप्त हो गया । भारतीयोंको इण्डियन सिविल सर्विसमें नीकरी मिलनेका प्रश्न था । आन्दोलनका तथा उसके उद्देशका वर्णन करनेके पहले इण्डियन सिविल सर्विसके सम्बन्धमें जान लेना जरूरी हैं । इससे आन्दोलनको समझना सरल हो जायगा ।

१. सुरेन्द्रनाथ वनर्जी, ए नेशन इन दि मेकिंग, पृ० ४०

सन् १८३३ में त्रिटिश पार्लमेण्टने यह वोपणा की थी कि "कोई भी भारतीय धर्म, जन्मस्थान, जाति, रंग, या ऐसे ही किसी अन्य कारणसे, ईस्ट इण्डिया कम्पनीके मातहत किसी नौकरीके लिए अयोग्य न टहराया जायगा।" परन्तु जब कई युवकोंने ब्रिटेन जाकर सिविल सर्विसके लिए योग्यता प्राप्त कर ली और फिर भी उन्हें नियुक्त नहीं किया गया तो उन्हें भारी निराशा हुई। निराशाने कम्पनीके विरुद्ध कोध महका दिया और कम्पनीके नये चार्टरके विरुद्ध जो १८५३ में आनेवाला था, एक आन्दोलन संघटित किया गया। तीनों प्रेसीडेन्सी स्वोंके लोगोंके हस्ताक्षरोंसे पार्लमेण्टके पास अर्जियाँ भेजी गयीं जिनमें माँग की गयी कि कम्पनोका कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाय। वंगालसे भेजी गयी अर्जी केवल विरोधात्मक ही नहीं थीं, उसमें कई रचनात्मक सुझाव भी दिये गये थे जैसे (१) दोहरी सरकार समात करके एक भारतीय सचिव व एक भारतीय कौंसिलकी नियुक्ति हो; (२) भारतके लिए एक अलग विधान सभा बनायो जाय; (३) प्रेसीडेन्सी स्वोंको एक प्रकारका प्रांतीय स्वशासन दे दिया जाय; (४) निम्नश्रेणीके सरकारी नौकरोंके वेतन बढ़ाये जाय और उच्च श्रेणीके कम किये जायँ; (५) सिविल सर्विसोंके हार समस्त व्रिटिश प्रजाके लिए खोल दिये जाँय और नियुक्तियाँ प्रतियोगिताको परीक्षाओंके फलके आधारपर हों।

इस अर्जीका असर हुआ और १८५४ में प्रतियोगिता परीक्षाका कायदा वना दिया गया। सन् १८५५ में दादा भाई नौरोजी (१८२५-१९१७) ने प्रतियोगिता परीक्षा दिल्लोमें भी किये जानेका इंगलैण्डमें आन्दोलन गुरू किया। नौरोजीने भारत और इंगलैण्डमें सव मिलाकर करीव ३० संस्थाओंका. संघटन किया था। इनमेंसे बहुतोंका उद्देश्य भारतको राजनीतिक प्रगतिकी स्रोर अग्रसर करना था। कुछ शिक्षा सम्बन्धी सुधारोंके लिए और कुछ स्त्रियोंकी दशामें सुधार करनेके लिए कायम की गयी थीं। इंगलैण्डमें स्थापित 'ईस्ट इण्डियन ऐसोसियेशन' का काम भारतीय आकांक्षाओंको ब्रिटिश जनताके सामने रखना था।

भारतीयों को सफलतापूर्वक प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेता देख अंग्रेज अधिकारियों को चिनता होने लगी। इसलिए १८६० में उम्मेदवारों की अधिकतम उम्र घटाकर २२ वर्ष कर दी गयी, लेकिन जब इस छोटी अवस्थामें भी भारतीय युवक इंगलिण्ड जाकर परीक्षामें उत्तीर्ण होते रहे, तो १८६६ में उम्र फिर घटा कर २१ वर्ष कर दी गयी। मानो प्रतिकारकी भावना काम कर रही हो, सन् १८६० में अधिकतम उम्र उस समय कम की गयी जब इण्डिया कौंसिलकी एक पाँच सदस्योंवाली कमेटीने यह सिफारिश की कि प्रतियोगिता परीक्षा भारतमें भी इंगलिण्डके साथ होनी चाहिये। नौरोजिक आन्दोलनके फलस्वरूप १८६१ में पार्लमेण्टने भारतके गवर्नर जनरलको यह शक्ति प्रदान की कि वह विना प्रतियोगिता परीक्षाके ही एक सीमित संख्यामें भारतीयोंकी भत्तीं कर सकता है। परन्तु भारत सरकारने इस कानूनके विरोधी नियम बनाकर इसका प्रभाव खत्म कर दिया और इसके अन्तर्गत केवल एक या दो भारतीय भर्ती किये गये। सन् १८७७ में लार्ड लिटन ने (जो अति प्रतिक्रियावादी वाइसराय था) यह सिफारिश की कि सिवल सर्विस भारतीयोंके लिए विल्कुल वन्द कर दी जाय। प्रकट रूपमें यह वन्द तो नहीं हुई, पर अधिकतम वय २१ से घटाकर १९ कर दी गयी।

यह उम्रका नया घटाव उस समय हुआ जव इण्डियन ऐसोसियेशन वन चुका था।

वनजीने इस प्रक्रमपर आन्दोलन खड़ा कर दिया । ऐसोसियेशनने एक प्रस्ताव किया कि अखिल भारतीय आन्दोलनका संघटन किया जाय। शुरुवात कलकत्तेमें २४ मार्च १८७७ को एक सार्वजनिक सभासे हुई जिसकी अध्यक्षता सर नरेन्द्रकृष्ण वहादुरने की । सम्पूर्ण भारतसे इस आन्दोलनमें भाग लेनेकी अपील की गयी और सब सुवींको इस प्रश्नपर एक हो जानेके लिए आमन्त्रित किया गया । ऐसा प्रयत पहले कभी नहीं हुआ था । सुवींमें दीरा करनेका काम वनजीको सौंपा गया। वे बड़े उत्साह और कर्तव्यपरायणतासे धन इकटठा करने और प्रचार करनेमें जुट गये। वनर्जा उस समय मेट्रोपोल्टिन इस्टीट्यटमें प्रोफेसर थे। गर्मीकी छड़ी हो गयी थी। इसिलए वे नगेन्द्रनाथ चटजीको (जो उस समय वंगाली भाषाके ओजस्वी वक्ता थे) साथ लेकर उत्तरी भारतके दौरेके लिए निकल पड़े। पहले वे आगरा गये जहाँ सिविल सर्विस स्मृतिपत्रका उर्दू अनुवाद जनतामें याँटा गया। लाहीरमें हिन्दू, मुसलमान और सिख सभीने उनका स्वागत किया । एक विराट सभा हुई जिसमें कलकत्ते-का प्रस्ताव और स्पृतिपत्र पारित किये गये। लाहोरमं उन्होंने दृण्डियन ऐसोसियेशनकी शाखा भी स्थापित करवा दी जिसका नाम लाहौर इण्डियन ऐसोसियेशन रखा गया। वनजींका ख्याल है कि पंजायमें यह पहला राजनीतिक संघटन था जिसने सय वर्गोंके लोगोंके लिए एक सामान्य कार्यक्षेत्र प्रस्तुत कर दिया। लाहौरके राजनीतिक जीवनको अंग्रेजी दैनिक 'द्रिव्यून'से काफी योग मिला; वनजींके अनुरोधसे सरदार द्यालसिंह मजीठिया-ने 'हिन्यून'का प्रकाशन शुरु किया था।

अपने त्फानी दीरेमें वनजी अमृतसर, मेरठ, इलाहाबाद, दिन्ली, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, वनारस, वम्बई, स्रत, अहमदाबाद और पूना गये। इन सब स्थानोंमें महती सभाएँ हुई और कलकत्तेका प्रस्ताव व स्मृतिपत्र पारित हुए। मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊमें ऐसोसियेशनकी शाखाएँ भी स्थापित हुई। वे मद्रास भी गये थे, परन्तु वहाँ किसी वजहसे सभा नहीं हो सकी।

उत्तरी भारतके दौरेमें वनजीने प्रमुख भारतीयोंने सम्पर्क स्थापित किये और भारतीय एकताका वीजारोपण किया। उनका कहना है कि जिन छोगोंसे वे मिले उन सबमें सर सन्यद अहमद खाँ "सबसे प्रसिद्ध" व्यक्ति थे। सर सन्यदने अलीगढ़की सभाका सभापितस्य किया और कलकत्ता प्रस्ताव पारित करनेके अलावा माँग की कि प्रतियोगिता परीक्षा भारतमें भी होनी चाहिये। बादमें इन्हीं सर सन्यदने साम्प्रदायिक कारणींसे इस परीक्षाके भारतमें किये जानेकी माँगका विरोध किया।

बिटिश शासनमें पहली वार देशने एक स्त्रमें वँधकर एक आवाज उटायी। सिवल सर्विस आन्दोलनने देशमें संघटित राजनीतिक कामके लिए पथप्रदर्शन किया। वंगला इस जायितका नेता था। इसके विषयमें वंगाल सिविल सर्विसके सर हेनरी काटनने (जो यादको कांग्रेसके अध्यक्ष हुए) लिखा है—"पहे-लिखे लोग ही देशके मस्तिष्क और आवाज होते हैं। आज पेशायरसे चटगाँवतक वंगाली वावू जनमतपर कावू किये हुए हैं। और यद्यपि उत्तरी-पिक्सी भारतके लोग शिक्षा और राजनीतिक स्वाधीनताकी भावनामें अपने वंगाली भाइयोंसे कहीं ज्यादा पिछडे हुए हैं, परन्तु धीरे धीरे वे भी दक्षिणी स्वांकी भाँति उनके वौद्धिक नियन्त्रण और पथप्रदर्शनमें आ रहे हैं। चौथाई शताब्दी पहले इस वातकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि पंजावमें किसी वंगालीका असर हो सकता है। लेकिन

यह सच है कि पिछले वर्ष एक वंगाली उपदेशकने अंग्रेजीमें भाषण करके अनोखी विजय प्राप्त की है। और आजकल सुरेन्द्रनाथ बनर्जीका नाम उठती हुई पीढ़ियोंमें मुल्तानमें भी उतना ही उत्साह जाग्रत करता है जितना ढाकामें।"

सम्पूर्ण भारतमें एक मत स्थापित करके इण्डियन ऐसोसियेशनने इङ्गलैण्डमें आन्दोलन करनेकी ठानी । सिविल सर्विसके प्रश्नपर एक-अखिल-भारतीय स्मृतिपत्र ब्रिटिश लोकसभा-के पास भेजा गया और लालमोहन घोष भारतके प्रतिनिधि चुने गये। लालमोहन घोष अति उच्च कोटिके कुशल वक्ता थे। इंगलेण्ड पहुँचते ही उन्होंने वड़ी लगनसे काम ग्रुरू कर दिया। जान ब्राइटकी अध्यक्षतामें एक वड़ी सभा हुई—ब्राइट उस समय ग्लेडस्टनके बाद सर्वोत्तम वक्ता समझे जाते थे। वे इंगलेण्डमें भारतके बढ़े हितैषी भित्र थे—सन् १८४७ से १८८० तक वे पार्लमेण्टमें भारतके पक्षमें बरावर लड़ते रहे। घोषके भाषणकी प्रशंसा करते हुए ब्राइटने कहा कि "में अब न बोल्हँगा, इस सुन्दर भाषणका प्रभाव में विगाड़ना नहीं चाहता"। इस काररवाईका तुरत असर हुआ और २४ घण्टेके अन्दर ही लोकसभामें वे रूल पेश कर दिये गये जिनके द्वारा भारतीय स्टेट्यूटरी सर्विसकी स्थापना की गयी।

यह आन्दोलन चल ही रहा था कि भारतीय राजनीतिमें एक और जोरदार लहर आयी । यह थी सरकार द्वारा देशी पत्रोंका गला घोटना । लार्ड हेस्टिंग्जके कालमें, पत्रोंको काफी आजादी थी; उन दिनों अधिकतर यूरोपियन ही पत्रोंके मालिक थे। सन् १८२३ में अस्थायी गवर्नर जनरल जॉन ऐडमने एक आर्डिनेन्स (कानून) द्वारा भारतके पत्रोंपर कड़े प्रतिबन्ध लगा दिये । तमाम पत्रोंके लिए यह आवश्यक हो गया कि वे गवर्नर-जनरलसे लाइसेन्स (अनुज्ञापत्र) प्राप्त करें । इस आर्डिनेन्स (या अध्यादेश) के प्रथम शिकार कलकत्ता जरनलके सम्पादक, विकंघम और उनके सहायक सैन्फोर्ड आरनौट हुए। विकंघमको २ माहकी नोटिस देकर इंगलैण्ड रवाना कर दिया गया और आरनीटको गिरफ्तार करके इंगलैण्ड जानेवाले एक जहाजपर वैठा दिया गया। उनका दोष यह था कि वे सरकारकी आलोचना किया करते थे। राजा राममोहन राय उस समय इंगलै॰डमें थे। उन्होंने इस कान्नके खिलाफ पहले तो ईस्ट-इण्डिया कम्पनीके डाइरेक्टरोंके सामने अर्जी पेरा की, फिर, इंगलैण्डके वादशाहसे अपील की, पर कुछ न हुआ। परन्तु १८३५ में अस्थायी गवर्नर-जनरल सर चार्ल्स मेटकाफने प्रेसको फिर मुक्त कर दिया। टामस मुनरोने (जो कम्पनीके एक मुलाजिम थे) यह मुझाव दिया था कि निरंकुश शासन और स्वतन्त्र प्रेस एक साथ नहीं चल सकते। वे कहते थे—"स्वतन्त्र पत्रोंका प्रथम कर्तर्व्य क्या है ! देशको वाहरी जुएसे मुक्त कराना" ।

फिर भी मेटकाफने हिम्मतसे काम लिया और पत्रोंको वहुत आजादी दे दी। सन् ५७ के विद्रोहमें फिर पत्रोंने जोर पकड़ा। और उनपर एक नियत समयके लिए प्रतिवन्ध लगा दिये गये।

सन् १८७५ के वादके वर्षोंमें भारतीय भाषाओं के पत्रोंने सरकारपर ही नहीं वरन् अंग्रेजी राजपर आक्रमण करना ग्रुरू कर दिया । इससे अधिकारीगण भयभीत हो गये । विद्रोहके जमानेके अंग्रेजी अत्याचारोंने कुछ वर्षों तक पत्रोंको चुप कर दिया था । परन्तु

१. हेनरी कॉटन, न्यू इण्डिया, पृ० १५-१६

२. सर जॉन कर्मिंग, पोलिटिकल इण्डिया, पृ० ३५

ज्यों ज्यों समय वीतता गया, भारतीयोंके प्रति अंग्रेजोंका रवैया सख्त होता गया—वे भार-तीयोंकी आकांक्षाओंके साथ सहानुभृति रखनेके वजाय उनका अपमान करने लगे। इसलिए भारतीय पत्रोंने अंग्रेजोंके विरुद्ध शत्रुताका रवैया अख्तियार कर लिया। सन् १८७५ में 'अमृत वाजार पत्रिका'ने जो सदासे अंग्रेज-विरोधी पत्र था, वढ़ोदाके गायकवाड़ द्वारा वहाँके अंग्रेज रेजीडेण्ट कर्नल पैयरको कल्ल करनेके कथित प्रयत्नपर लिखा कि "एक मामृलीसे कर्नलको जहर देना उतना भारी अपराध नहीं है जितना एक पूरे राष्ट्रको शक्तिहीन कर देनेमें है जिससे सरकार विना किसी संकटके शासन कर सके।"

भारत सरकारके कान्न सदस्यके भाषणसे जो उन्होंने उस समय राजकीय विधान परिपद् (हम्पीरियल कोंसिल)में किया था, पता चलता है कि सरकारका भारतीय भाषाओं के पत्रोंके विषयमें क्या विचार था। उन्होंने उस भाषणके दौरानमें कहा था। "ऐसे देशी पत्रोंकी एक वड़ो और वढ़ती हुई संख्या है जिनका उद्देश उत्तेजक सिद्धान्तोंका प्रसार करना, सरकार और उसके यूरोपीय अफसरोंके प्रति पृणा पैदा करना, और शासक जाति तथा देशकी जनताके वीच विरोधी भावनाओं को उभाइना है। इस प्रकारके लेख कोई नयी चीज नहीं है परन्तु चार-पाँच वर्षीसे उनमें उत्तरोत्तर दृद्धि होती जा रही है। पिछले वारह महीनों में तो यह गति वहुत हो तीत्र हो चली है, क्यों कि लेखक समझते हैं कि उन्हें कोई सजा तो मिलेगी नहीं। उनके लिखनेके मुख्य विषय ये हैं—अंग्रेजी सरकारका अन्याय, दमन और अत्याचार, उसमें भारतीयों के प्रति सहानुभृतिका अभाव, भारतमें वसे हुए अंग्रेजोंकी उद्दण्डता और घमंड। इन लेखकोंकी रायमें कोई ऐसा पतित, निकृष्ट और धूर्ततापूर्ण अपराध नहीं है जो अंग्रेजी शासक आदतन न करते हों।"

कानृत सदस्यने आगे कहा—"हालमें इस रवैयेमें और प्रगति हुई है; अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूपसे लोगोंको उमाड़कर अंग्रेजी शासनको उखाड़ फेंकनेकी हिदायत दी जाती है। उनसे कहा जाता है कि दुर्वल डरपोक अंग्रेजोंमें अब भारतपर शासन करनेकी योग्यता नहीं रह गयी है।"

देशी भाषाओंके पत्रोंके विरुद्ध कानून पास करनेके लिए गवर्नर जनरलने निम्न आशयका तार भारत-सचिवके पास भेजा था—

"राजद्रोहात्मक हिंसाकी ओर, जिसका आजकल देशी पत्र खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, स्थानीय सरकारें हमारा ध्यान बराबर आकर्षित कर रही हैं । सिर्फ मद्रास सरकारको ऐसी कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वहाँ देशी भाषाके पत्र नहींके बराबर हैं; बाकी सभी सरकारों की माँग है कि एक सख्त कानून बनाया जाय । परिपद् भी एक मतसे यही चाहती है । हम सब, गत कुछ महीनोंसे सख्त कदम उठानेकी बात सोच रहे थे, परन्तु मेरी और अन्य स्वाई सरकारोंकी रायमें देशी पत्रोंकी भाषा जो हमेशासे शरारत भरी रही है, अब बहुत खतरनाक हो गयी है, और भारतीय समाज समझता है कि अन्य स्थानोंकी घटनाओंके कारण हमारी शक्ति अब बहुत दुर्बल हो गयी है। इसल्ए अब सार्वजनिक हितके कारण सरकारके लिए यह बहुत जरूरी हो गया है कि देशी पत्रोंके राजद्रोही इत्योंको रोका जाय,

१. एडवर्ड टामसन् दि रिकान्सट्क्शन आव इण्डिया, पृ० ५८

२. सर वरनी कवेट, ए हिस्टरी आव इण्डियन नैशनलिस्ट मुवमेन्ट, ए० २२

अन्यथा, इस कालकी अजीव स्थितिमें उनका खतरा वढ़ता ही जायगा।" इस "अजीव स्थिति"का वर्णन वादके अध्यायमें किया गया है।

देशी भाषा-पत्र कान्न (वरनाक्यूलर प्रेस ऐक्ट) राजकीय विधान परिपद्की एक ही वैठकमें १४ मार्च १८७८ को पास कर दिया गया। एक दिनमें पास करनेके लिए कायदों को अध्यक्षकी आजासे मुअत्तल कर दिया गया। किसीने भी विरोधकी आवाज नहीं उठायी। भारतीय सदस्य, महाराजा सर ज्योतीन्द्रमोहन ठाकुरने भी विलक्षे पक्षमें राय दी। सुरेन्द्रनाथ वनर्जीके कथनानुसार, "ऐसा कहा जाता है कि ठाकुरसे वाइसरायने पक्षमें राय देनेके लिए बुलाकर कह दिया था।"

इस कान्त द्वारा मैजिस्ट्रेटोंको यह अधिकार मिल गया कि वे भारतीय भाषाओंके पत्र-सभादकोंसे प्रान्तीय सरकारोंकी आजासे, कह सकते थे कि वे या तो अपने पत्रोंमें छपनेवाली सामग्रीका पूफ सेन्सर करानेको भेजे या प्रतिज्ञा लिखकर दें कि वे कोई ऐसा लेख या खतर न छापेंगे जिससे सरकारके प्रति अविश्वास पैदा हो या जिससे विभिन्न जातियोंमें द्वेष भावना फैले । द्वारारती दफा १२४ ए ने जो भारतीय दण्ड विधानमें १८७० में जोड़ी गयी थी, सरकारको इस प्रकारको काफी द्वाक्त दे रखी थी । परन्तु इस दफाका प्रयोग किसी अपराधके होनेके वाद ही हो सकता था; इसल्लिए वर्नाक्यूलर प्रेस ऐक्टकी जरूरत पड़ी । इस ऐक्टसे अपराधकी रोकथाम पहले हो की जा सकती थी । इस ऐक्टकी तात्कालिक प्रतिक्रिया यह हुई कि 'सोम प्रकाश', 'नव विभाकर', 'साधारणी' तथा ऐसे ही अन्य पत्रोंने, जिन्होंने राष्ट्रीय जाग्रतिमें काफी भाग लिया था, स्वतः प्रकाशन वन्द कर दिया । अमृतवाजार पत्रिका होशियारीसे इस ऐक्टके पंजेसे निकल गया; उसने अपना प्रकाशन वजाय वंगालीके अंग्रेजीमें शुरू कर दिया ।

विद्रोहके वाद समाचारपत्रोंकी संख्या बढ़ने लगी। सन् १८७० में ब्रिटिश भारतमें ६४४ समाचारपत्र थे जिनमेंसे ४०० देशी भाषाओं में निकलते थे। अभयचरण मजुमदारका कहिना है कि "बंगालमें छोटे-छोटे बहुतसे बंगाली समाचारपत्र निकले, जिनमें हर प्रकारकी खबरें और टीका टिप्पणी होती थी। कभी-कभी ये खबरें और टिप्पणियाँ गलत भी होती थीं, पर इनका सम्बन्ध सदैव देशके नये जोशसे होता था। शामको दर्जनों अनपढ़ लोग इन पत्रोंको सुननेके लिए दूकानोंपर इकटा हो जाते थे"।

ब्रिटिश शासनके आरम्भसे ही भारतमें दो वगोंके राजनीतिक नेता थे। एक तो वे जो किसी भी प्रकार अंग्रे जी शासनको भारतसे उखाड़ फेंकना चाहते थे, दूसरे वे जिन्होंने उस शासनको स्वीकार कर लिया था, और धीरे-धीरे उसे स्वशासनमें विकसित कर लेना चाहते थे। उग्रदलवाले अखवारोंका पूरा लाभ उठाते थे। कभी-कभी उग्रदल और नरम दलवाले साथ-साथ भी काम करते थे। दोनों सोचते थे कि वे दूसरेकी सहायताने अपनी विचारशाराको प्रोत्साहन दे रहे हैं। कभी-कभी नरम दलवालोंसे मिलकर उग्रदलवाले खुल्लम-खुल्ला काम करने लगते थे और नरमदलकी नीतिमें भी परिवर्तन करवा देते थे। कभी-कभी नरमदलवालोंमें उनका प्रभाव इतना वढ़ जाता था कि उस दलवाले उन्होंके विचारोंको अपना लेते थे, और उन्होंके नेताओंको अपने नेता मानने लगते थे। इस प्रकार नरमदलीय-

१. लार्ड लिटन्स, इण्डियन ऐडमिनिस्ट्रेशन पृ० ५०६-५०७

२. अभयचरण मजुमदार, इण्डियन नैशनल इवौल्यूशन ए० २२

मतने सरकारी आद्यासे अधिक तेजीके साथ प्रगति की । और परिणामस्वरूप सरकार और नरमदलके मतमें काफी चौड़ी खाई वन गयी।

इन दोनों दलोंके कृत्योंने जो असन्तोप उत्पन्न कर दिया था वह समाचारपत्रोंमें परिलक्षित हो रहा था। सरकार परेशान थी। कुछ संवादक वम्बई तथा कलकत्तेने निर्वासित कर दिये गये। वर्नाक्यूलर प्रेस ऐक्ट (जो गलावोंटू कान्तके नामसे प्रसिद्ध हुआ) भारतीय राजनीति तथा राष्ट्रीय प्रगतिके रास्तोमें वाधक सिद्ध हुआ। शिक्षित वर्ग अत्यन्त विचलित तथा खुव्ध हो उठा। कुछ वह वहे नेता भयभीत से माल्म पड़ने लगे और उनकी पस्तिहिम्मतीके कारण जनताका उत्साह भी ढीला पड़ने लगा।

इस कान्तके विषद्ध इिष्डियन ऐसोसियेशनने आन्दोलन उठावा और एक सार्वजनिक सभा करनेकी घोषणा की गयी। जिस शामको सभा होनेवाली थी उस दिन प्रातः के पत्रोंमें समाचार निकला कि रूसके साथ युद्धको सम्भावनाके कारण ब्रिटिश प्रधानमन्त्री डिजरेली ने ६००० भारतीय सैनिक माल्टा भेज दिये हैं। नेताओंको आशंका होने लगी कि शायद सुरक्षाके विचारसे सभा करनेकी आशा न मिले। परन्तु सभाके संयोजकोंने सभा करना निक्चय कर लिया और उसका जो कुछ भी परिणाम हो उसके लिए वे तैयार हो गये।" सभा विना किसी रोक-टोकके हुई जिसमें वर्नाक्यूलर प्रेस ऐक्ट्के विरोधमें एक प्रस्ताव पारित किया गया।

सन् १८७८ में एक अन्य आपित्तजनक कान्त वनाया गया जिसने भारतीयोंको और भी कुद्ध कर दिया। वह था इण्डियन आर्म्स ऐक्ट (शस्त्र कान्त्र)। इस कान्तने भारतीयोंको हथियारोंसे बंचित कर दिया। इसके अनुसार कोई भारतीय विना लाइसेन्सके कोई घातक हथियार नहीं रख सकता था। इस कान्तका उल्लंघन करनेवालेके लिए ३ वर्षकी कैद या जुमीना या दोनोंका उपवन्ध किया गया था। भारतीय नेताओंने इस कान्तका भी विरोध किया।

इन दोनों कान्नोंके विरोधमें ग्लेडस्टनका भी सहयोग प्राप्त था। उस समय वे विरोधी दलके नेता था। पर जब वे प्रधान मन्त्री हुए तो उन्होंने वनांक्यूलर प्रेस ऐक्ट तो रह कर दिया लेकिन आर्म्स ऐक्टको उन्होंने भी नहीं हुआ।

हेनरी ढाडवेल, ए स्केच भाव दि हिस्टरी आव इण्डिया फ्राम १८५८ ह, १९१८, पृष्ट २५९

अध्याय ४

आर्थिक शोषणके राजनीतिक परिणाम

त्रिटेन जिस ढंगसे भारतीय अर्थन्यवस्था संचालित कर रहा था, उसमें उसका मुख्य लक्ष्य था अधिकतम मुनाफा कमाना । महारानी द्वारा शासनकी वागडोर सँभालनेके पहले ही ईत्ट इण्डिया कम्पनीने भारतीय वस्त्र-उद्योग नष्ट कर दिया था और ब्रिटेन अपने यहाँ वना कपड़ा भारतको निर्यात कर रहा था । ब्रिटिश वस्त्र-उद्योगके लिए कईकी जरूरत थी और यह कई ब्रिटेन भारतसे प्राप्त करने लगा था । भारतीय-तट-कर नीति लगभग पूरी तरहसे ब्रिटिश पूँजीपतियों द्वारा निर्धारित होती थी । ब्रिटिश पालंमेण्टमें उनका प्रभाव था और यह नीति ब्रिटिश व्यापार तथा उद्योगका हित देखकर तथ होती थी । भारतीय वस्तुओंका यूरोपको निर्यात भारी कर लगाकर द्वाया जाता था, ब्रिटिश वस्तुओंका भारतमें आयात नाममात्रके करों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता था । इतिहासकार होरेस विल्सनके शब्दोंमें ब्रिटिश कार-खानेदार अपने ऐसे प्रतियोगियोंके दमन और अन्ततः विनाशके लिए राजनीतिक अन्यायका सहारा लेता था, जिनसे वरावरीकी होड़में वह कभी टक्कर न ले पाता।

भारति वड़ी मात्रामें अन्न इंगलैण्ड भेजा जाता था, जिससे यहाँ दुर्मिक्ष पड़ने लगे । अन्नका यह निर्यात हर वर्ष बढ़ता ही गया । सन् १८५९में गेहूँ, चावल व दूसरे अनाजका २८ लाख पाँडका निर्यात हुआ और सन् १८७७में यही निर्यात बढ़कर ८० लाख पाँडका हो गया ।" यदि भारतीय जनता पेट भर खाती होती तो अतिरिक्त अन्न बचता ही नहीं । अन्न का निर्यात भारतमें बहुतसे भूखे पेटोंका प्रतीक था" किन्तु अन्नकी कमी इस निर्यातसे कहीं अधिक श्री क्योंकि भारतमें बसे अंग्रेजोंने हजारों मील उपजाफ भूमिमें गल्लेको खेती बन्दकर कई और जूटकी खेती शुरू कर दी थी । बंगालके बहुतसे चावल पैदा करनेवाले जिले अव जूट पैदा करने लगे थे । भारतके बड़े बड़े इलाकोंमें गेहूँ और चावलकी फसलोंकी जगह रूई ले रही थी । भारतीय किसान वही पैदा करनेको बाध्य था जो उसका साम्राज्यवादी मालिक चाहता था । भारतीय जनता भूखी रहे या अकालग्रस्त हो, अन्नका निर्यात जारी रहता था । दुर्मिक्षके दिनोंमें भी निर्यात बदस्तर जारी रहता था ।" सन् १८७६-७७में जब देशमें विकराल "दुर्मिक्ष आसन्न था अन्नका निर्यात पहले वर्षोंसे अधिक ही हुआ ।"

ग्रामीण अर्थ-व्यवस्थाका ढाँचा ऐसा कर दिया गया था कि किसान अपनी उपज वेचनेको बाध्य थे, यद्यपि वे जानते थे कि वर्षके वहे भागमें उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। लगान बढ़ा दिये थे और उसे अदा करनेके लिए काइतकारोंको उपजका वड़ा हिस्सा वेच देना पड़ता था। फिर ब्रिटेनसे आयी वस्तुओंका दाम भी देना होता था, जो यहाँसे अनाज और कचा माल भेजकर अदा किया जाता था।

१. रमेशचन्द्रदत्त 'इण्डियन ट्रेड, मैन्यूफेक्चर्स एण्ड फाइनेंस' पृष्ठ १

२. डटल्टू इटल्टू हण्टर 'इण्डिया आव दि नवीन एण्ड आदर ऐसेन' पृष्ठ १४८

३. रमेशचन्द्रदत्तःपृष्ट १४३

वंगालमें इस्तमरारी वन्दोवस्तने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिससे सन् १८५९ में किसान विद्रोह हो गया । यह वन्दोवस्त अंग्रेजी राजकी वड़ी देन गिना जाता था क्योंकि इससे जमींदार वार-वार मालगुजारी वढ़नेके खतरेसे वच गये थे । गल्हेके दाम वढ़ रहे थे और काश्तकारोंकी आमदनी वढ़ रही थो क्योंकि लगान नहीं वढ़ा था । किसानकी इस आपेक्षिक समृद्धिने जमींदारोंको लालची वना दिया और १९ वीं शताब्दीके मध्यमें इन्होंने लगान वढ़ाने शुरू किये । फल यह हुआ कि जमींदारको तो वँधी हुई मालगुजारी ही देनी होती थी परन्तु वे किसानोंसे वढ़े हुए भावोंके अनुपातसे भी अधिक लगान वस्ल करने लगे । सन् १८५९ में सरकारने लगान वृद्धि पर रोक लगानेकी एक हल्की-सी कोशिश की पर उससे काश्तकारोंका विशेष लाभ नहीं हुआ ।

वंगालके दुखी किसानोंने ऐसी स्थितिमें, लगानवन्दी आन्दोलन करनेका निर्णय किया। वे सव उसका फल भोगनेके लिए भी तैयार हो गये। वंगालके सवसे शान्त जिले पावनामें किसान-विद्रोहकी स्थिति पैदा हो गयी। लेकिन यह विद्रोह पूरी तरहसे वैधानिक था। आवेशके कुछ नगण्य उफानोंको छोड़ दें तो किसानोंकी सारी नीति यही मालूम पड़ती थी कि 'हम लड़ेंगे नहीं और हम लगान भी नहीं देंगे; हम दिखलकार कारतकारोंके हक माँनेंगे; लगानकी हर रकम वसूल करनेके लिए उम जमींदार लोगोंको मुकदमा लड़ना पड़ेगा; अर्जीदावेसे लेकर जमीनके नीलामतक, ये मुकदमें हम हर स्तरपर लड़ेंगे; कानूनके हर पेच, फेर और वाक् छलको अस्त्र बनाकर हम देर लगावँगे; उम्हें आखिरकार डिगरी मिल जायगी, पर डिगरी पानेमें तुम तबाह भी हो जाओगे; हमारी हालत तो खराब है ही और तुम्हें लगान देनेके लिए अपनी आखिरो गाय वेचनेसे अच्छा है कि हम गाय वेचकर तुमसे अदालतमें लड़ लें।' वंगालके दो तिहाई—६० लाख—लोग १० शिलंगसे कम ही सालाना लगान देते हैं। ऐसे छोटे किसानोंके देशमें मुकदमें लड़ लड़कर लगान वसूल करना असंभव है। और किसानोंकी एकता तथा संघटनने सचमुच ही बहुतसे जमींदारोंको वर्बाद कर दिया।''

अगले साल, सन् १८६१ में वंगालके काश्तकारोंने फिर मोर्चा लिया ! इस वार यह यह मोर्चा नीलके यूरोपीय प्लाण्टरोंके खिलाफ था ! विहार और वंगालमें कुछ उद्योगी यूरोपीयों द्वारा शुरू की गयी नीलकी खेतीके पीछे एक दर्द भरी, यातनाओंकी कहानी छिपी हुई है ! किसानोंकी एक वहुत वड़ी संख्याको धोखा देकर इनसे लग्नी अवधिके लिए नीलकी खेती करनेके इकरारनामें लिखा लिये गये थे । वादमें वेचारोंको पता लगा कि नीलकी खेतीमें सुनाफा नहीं होता । पर इन इकरारनामोंके वलपर दमन और दवाय डालकर उन्हें नीलकी खेती करनेको मजबूर किया गया, यद्यपि वे यह खेती छोड़ना चाहते थे । वंगाल सरकारके कागजातसे पता चलता है कि प्लाण्टरोंके साथ पुलिस और मजिस्ट्रेटोंतककी मिली भगत थी । वंगालके लेपिटनेण्ट गवर्नर भी प्लाण्टरोंके पक्षमें थे । लेकिन अन्तमें, किसानोंकी दयनीय दशा और अमानुषिक अत्याचार देखकर अफसरोंको भी अपना रुख बदलना पड़ा।

कारतकारोंकी सहनज्ञीलता सीमातक पहुँच चुकी थी। आखिरकार उन्होंने साहस वटोरकर गोरे मालिकोंके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इन इकरारनामोंके यावजूद उन्होंने ंनील वोनेसे इनकार कर दिया। कुछ जगहोंपर उन्होंने हिंसासे काम लिया, कुछ दूसरी जगहोंपर उन्होंने नील-कोटियाँ जला दीं; पर हिंसाकी ऐसी घटनाएँ कम ही थीं। विद्रोहका

१. डब्लू. डब्लू. हण्टर 'इण्डिया आव दि क्वीन एण्ड अदर एसेज' ए० १४३

संघटन इतना अच्छा था कि अधिकारियोंको विगड़ती हुई हालतसे परेशानी होने लगी। काश्तकारोंकी संघटित एकतासे लार्ड कैनिंग जैसे वाइसराय भी बेचैन हो उठे, जिन्होंने १८५७ के विद्रोहमें बड़ी-बड़ी घटनाएँ देखी थीं। आन्दोलनके बारेमें आपने लिखा— "एक हमतेतक तो मुझे इतनी चिन्ता रही जितनी दिल्ली-विद्रोहके बाद कभी नहीं हुई थी। मुझे लगता था कि किसी मूर्ब प्लाण्टर द्वारा क्रोध या भयसे चलायी गयी एक गोलीसे दक्षिणी बंगालके हर कारखानेमें आग लग जायगी।"

भाग्यसे, इस वर्ष बंगालके लेपिटनेण्ट गवर्नर सर जॉन पोटर प्राण्ट थे जिन्होंने कारत-कारोंकी मॉगका न्याय देखकर उन्हें मदद पहुँचानेका निश्चय किया। जिलोंके अपने दौरमें सर जॉनने रैयतीकी भीड़ोंको सरकारसे यह हुक्म जारी करनेकी मॉग करते देखा था कि उन्हें नील बोनेको विवश नहीं किया जाय। सर जॉनके अनुसार—"यह समझना भूल ही होगी कि दस-दस हजार स्त्री पुरुषों व वच्चोंके इन प्रदर्शनोंका कोई गम्भीर अर्थ नहीं है। इतने बड़े देशमें एक उद्देश्यसे एक साथ ऐसे स्मरणीय प्रदर्शन करनेकी शक्ति और संघटन गम्भीर विचार करने योग्य हैं।"

जिन दो भारतीयोंने देशभरका ध्यान नीलकाण्डकी ओर आकर्षित किया वे थे दीनवन्धु मित्र व हरिश्चन्द्र मुखर्जी । दीनवन्धुने एक नाटक लिखा नीलदर्पण और शायद ही कभी किसी नाटकका इतना व्यापक प्रभाव पड़ा हो । उसमें यूरोपीय प्लाण्टरों द्वारा नीलके काश्तकारों और उनके परिवागेंपर किये गये अत्याचारों और नशंसताओंका वड़ा मार्मिक चित्रण किया गया था । नील-प्रदेशका उसमें इतना सही वर्णन था कि नाटक सैकड़ों जगह खेला गया और जिसने भी उसे देखा वह इस अत्याचारके अन्तके लिए प्रोरित हो गया । प्लाण्टरोंके विरुद्ध और नील-किसानोंके पक्षमें विशाल जनमत तैयार हो गया ।

किसानोंकी दुर्दशासे कई ईसाई पादिरयों और अंग्रेज अफसरोंके मित्र भी पिघल गये। इनमें रेवरेण्ड जेम्स लॉग भी थे जिन्होंने किसानोंके लिए जेल भी काटी। वंगाल सरकारके सेकेटरी सेटनकरके कहने पर माइकेल मधुसदन दत्तने नील दर्पणका अंग्रेजीमें अनुवाद किया और पादरी लॉगने उसमें अपनी भूमिका जोड़कर उसे प्रकाशित किया। करने सरकारी मुहरसे इस अनुवादकी २०० प्रतियाँ इंगलेण्ड भेज दीं। इससे प्राण्टर कोधित हो उठे और उन्होंने 'इंगलिशमैन' के सम्पादक वाल्टर ब्रेटसे लॉगके विरुद्ध मानहानिका दावा करवा दिया। लॉगने अपनी भूमिकामें 'इंगलिशमैन' व एक दूसरे अंग्रेजी दैनिककी आलोचना करते हुए लिखा था—''चाँदीकी कितनी आकर्षक शक्ति है! घृणित जूडाने चाँदीके २० दुकड़ोंके लिए ईशुमसीहको घोखा देकर भयावह पोंटियस पाइलेटके सिपुर्द कर दिया था। इसमें क्या आकर्षक हजार दुकड़े पानेके लिए निर्धन रैयतको तुम्हारे चंगुलमें डाल दें।''रे

लाँगको १०००) जुर्माने और एक मासकी कैदकी सजा मिली। उनके लिए जुर्माना फीरन अदा कर दिया गया और वह खुशी-खुशी जेल चल दिये। जेल जाते समय उन्हें कहते सुना गया कि ऐसे कामके लिए मैं हजार बार जेल जानेको तैयार हूँ।

१. डाक्टर हेमेन्द्रनाथदास गुप्तकी 'दि इण्डियन नेशनल कांग्रेस' के पृष्ठ १९ पर उद्धत

२. वही पुस्तक पृष्ठ १९-२०

३. दासगुप्त द्वारा पृष्ठ २५ पर उद्घत

हरिश्चन्द्र मुखर्जी ब्रिटिश इण्डियन ऐसोसियेशनके प्रभावशाली सदस्य थे और 'हिन्दू पेट्रिअट' के सम्पादक थे। उन्होंने अपने पत्रमें किसानोंकी हिमायत ही नहीं की, वे आन्दोलनके नेता भी हो गये। उन्होंने अपने लेखों और समझाने-बुझानेसे सरकारको राजी कर लिया कि नीलके किसानोंकी शिकायतोंकी जाँच करनेके लिए एक कमीशन वैटाया जाय। मुखर्जी ही निद्या और जैसोरसे किसानोंको लाये, जहाँ नील-कप्ट सबसे उप्रथा और उनसे कमीशनके सामने गवाहियाँ दिलवायीं। नीलकी खेतीवाले फरीदपुरके भृतपूर्व मिलस्ट्रेट ई. डब्ल्ट्र. एल. टेल्ट्रने कमीशनके सामने गवाही देते हुए कहा—'पादिर्योंको यह कहनेपर काफी देपका सामना करना पड़ा है कि 'इंसानके खूनसे रंगे वगैर नीलको एक पेटी भी इझलेण्ड नहीं पहुँचती'। इसे एक कथाका रूप दिया गया है। पर यह मेरा अपना कथन है और मैं इसके सबसे व्यापक अर्थमें भी इसे अपना स्त्रीकार करता हूँ। फरीद पुर जिल्में मिलस्ट्रेट होनेके नाते मेरे पास बहुतसे रैवतोंको भेजा गया जिनके आरपार भाले छेद दिये गये थे। मेरे सामने उन रैयतोंके शरीर आये हैं, जिन्हें मिस्टर फोर्ड (एक प्राण्टर) ने गोलीका शिकार बनाया। मैंने रिपोर्टे लिखीं हैं कि किस प्रकार दूसरे लोग भालोंसे थायल किये गये, फिर गायव कर दिये गये। इस तरह नीलकी खेती करनेका में रक्तपातकी प्रणाली ही मानता हूँ।"

कमीशनने नील-किसानोंकी शिकायतींको सही पाया। उसके अनुसार इस खेतीसे किसानोंका कोई फायदा नहीं था; प्लाण्टर उन्हें सबसे उपजाक भूमिमें नील बोनेको वाष्य करते थे, कारखानोंके कर्मचारी उन्हें तरह तरहसे सताते थे। कमीशनने किसानोंके पक्षमें रिपोर्ट दी और बंगालके लेफ्टिनेण्ट गवर्नरने लगभग पूरीकी पूरी रिपोर्ट मान ली। नीलकी खेती खत्म हो गयी और किसानोंने राहतकी साँस ली।

विहारमें भी किसानों की ऐसी ही हालत थी । लेकिन वहाँ हरिश्चन्द्र मुखर्जीकी तरह उनके लिए आन्दोलन करनेवाला कोई नहीं था । इसलिए वहाँ किसानों के दुर्दिन कायम रहे । आखिरकार, १८६७ में जौकिटिया (चम्पारन) के कारतकारोंने नील योनेसे इनकार कर दिया और दूसरी फसलें वो दीं । दूसरे गाँवों के लिए यह एक इशारा था कि वे भी ऐसा ही करें । लालसरैया के आस-पास किसानों में ऐसा उवाल आया कि वहाँ की नील कोठी जला दी गयी । १८६७ के चम्पारन गजटमें लिखा है—एक बार तो रेयत और प्लाण्टरों के झगड़े के उप्रकृप धारण करने की आशंका पैदा हो गयी । इसका कारण एक ओर तो किसानों की नाकाफी आमदनी था और दूसरी ओर कारखानों के नीकरों द्वारा उनपर किये गये अत्याचार, अनुचित रूपसे धन वसूल किया जाना तथा अन्य परेशानियाँ थीं ।

पर किसानों को नहीं के बराबर ही सुविधाएँ मिलीं। १८७५ में पटने के किमश्तरने प्रस्ताव किया कि उनकी हालत जाँचने के लिए एक कमीशन बैठा दिया जाय, पर प्रस्ताव नामंजूर हो गया। सरकारको आशंका थी कि इससे हलचल मच जायगी। १८७७ में किमश्तरने फिर लिखा कि स्थानीय कर्मचारियों को बहुत असन्तोप दिखाई पड़ रहा है। १८८५ में उसने फिर लिखा—"जनहितकारी कानून बनाने के प्रयत्नों के बावजूद, यहाँ एक ऐसी प्रथा भी जन्म ले रही है, जिसमें रैयत अपनी पूरी जमीन और घरतक एक ऐसी अवधिके लिए रेहन रख देती है, जो उसकी मौतके बाद भी खत्म नहीं होती। इससे छुटकारा पाने के

१. डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद — 'सत्याग्रह इन चम्पारन' पृष्ठ २३

लिए उसे कर्जकी अदायगो करनी पड़ती है। सामान्य शब्दों में रैयत अपनी आत्मा और शरीर वेचकर लाचार दासतामें वेंध जाती है।" पर विहारके नील-किसानों के दुख-दर्द तव तक जारी रहे जवतक १९१७ में गाँधीजीने आकर उनका समर्थन नहीं किया।

देशकी सत्ता कम्पनीके हाथसे निकलकर महारानी विक्टोरियाके हाथमें जानेके वाद प्रथम १२ सालोंमें "भारतका आर्थिक शोषण चौगुना हो गया था।" विद्रोहके कारण और उसके वाद अन्य कारणोंसे सरकारी खर्च वढ़ गया था, जिसके लिए नये करोंकी जरूरत थी। और चूंकि व्यापारपर कर लगानेसे ब्रिटिश वाणिच्यपर कुप्रभाव पड़ता, भूमि-कर और लगान बढ़ा दिये गये। सरकारी आयका एक प्रत्यक्ष साधन आयात-निर्यात-कर बढ़ाना होता, पर इसका ब्रिटिश उद्योगपित विरोध कर रहे थे। आयातकरसे ब्रिटेनसे वनकर आये तैयार मालके दाम वढ़ जाते, निर्यातकरसे यहाँसे ब्रिटेन जानेवाला कच्चा माल महगा पड़ता।

विद्रोहके वादके १८ सालोंमें सरकारी आय ३ करोड़ ६० लाख पाँडसे वड़कर ५ करोड़ १० लाख पाँड हो गयी। इसमेंसे ब्रिटेनमें खर्च होनेवाली रक्षम ७५ लाखसे वड़कर एक करोड़ पाँड हो गयी। अपने १०० वर्षके राजमें कम्पनीने भारतपर ६ करोड़ ९५ लाख पौण्डका सार्वजनिक कर्ज लाद दिया था। लेकिन विक्टोरिया शासनके १९ वर्षोंमें कर्जकी यह रकम दुगुनी—१३ करोड़ ९० लाख पाँड हो गयी।

विकटोरिया राजके पहले १२ वर्षमें कर वदाकर ढ्योड़े कर दिये गये थे। २९ मार्च सन् १८७१ में वम्बई ऐसोसियेशनने ब्रिटिश लोकसभाको जो स्मृतिपत्र भेजा था उसमें लिखा था-"पिछले १२ सालोंमें नमक-कर मद्रासमें २०० फीसदी, वम्बईमें ८१ फीसदी और रोप भारतमें ५० फीसदी बढ़ गया है; शकरपर १०० फीसदी ड्यूटी बढ़ा दी गयी है; शरावपर आवकारी दुगुनी हो गयी है, स्टाम्प ड्यूटी वार-वार वढ़ायी गयी है और अव वह इतनी ज्यादा और परेशान करनेवाली है कि उसके कारण बहुधा न्याय नहीं मिल पाता। हालमें भारी कोर्टफीस और दो फीसदी उत्तराधिकार-कर भी लगा दिया गया है। जमीनपर ६॥ फीसदीकी सेस लग रही है; गाँवसेवा सेसकी दर भी इतनी ही ऊँ ची है; देहाती कस्वा सेस, व्यापार और पेशेवर कर, मकान टैक्स, चुंगी तथा बहुतसे दूसरे म्युनिसिपल व स्थानीय कर देशके विभिन्न हिस्सोंमें लागू हैं, जिनकी सम्मिलित रक्षम कूरता और निर्दयतापूर्ण रूपसे बड़ी है। बहुतसे सूर्वोको भारत सरकारसे मिल्नेवाले अनुदान कम कर दिये जानेसे जो घाटा पड़ रहा है, उसे पूरा करनेके लिए अव फिर नये स्थानीय कर लगानेका प्रस्ताव है। हम आवेदकोंका मत है कि अंग्रेजी राजमें कई वर्षसे अत्यधिक कर ही भारतके लिए विनाश-कारक सावित हो रहे हैं; अधिकारियोंने सरकारी खर्च कम करनेकी पूरी कोशिश नहीं की है। ये खर्च हर साल बढ़ते गये हैं यहाँतक कि सन् '५६-'५७ के मुकाबले वे १ करोड़ ९० लाख पोंड वढ़ गये हैं।"

इस स्मृतिपत्रका ब्रिटिश सरकारपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उल्टे आगे आनेवाले सालोंमें ये कर और बढ़ा दिये गये।

ब्रिटिश कम्पनियाँ बड़ी-बड़ी जमीनें लेकर उनपर चाय वागान लगा रही थीं।

१. ढाक्टर राजेन्द्रयसाद, 'सत्याग्रह इन चम्पारन' ए० १७

२. रमेशचन्द्रदत्त इण्डियन ट्रेंड, मेन्यूफेनचर एण्ड फाइनेंस, पृ० १३८

३, दत्तः एष्ट १७६-१७७

ब्रिटिश हितमें यह ब्रिटिश पूंजी भारतमें लग रही थी। प्लाण्टरोंको इन वागानोंके लिए वड़ी संख्यामें मजदूर चाहिये थे और वे चाहते थे कि मजदूर प्राप्त होनेकी कानृनी गारण्टी मिल जाय। वागानके लिए मजदूरींकी भरतीका एक विशेष कानृन बना दिया गया, जिससे गरीव और निरीह लोगोंपर दमन और अत्याचारका एक नया तरीका ग्रुह हुआ । इस कानूनको गुलामीका कानून कहा जाता था । वच्चे और औरतें अक्सर फ़ुसलाकर या भगाकर वागानमें पहुँचा दो जाती थीं। अपढ़ और अनजान लोगोंसे मजदरी-के इकरारनामें करा लिये जाते थे और उनके वागानसे भाग निकलनेकी कोशिश करने पर उन्हें गिरफ्तार कर सजाएँ दी जाती थीं । कानूनने उन्हें उन मालिकोंकी गुलामीमें बाँध दिया था । रमेशचन्द्र दत्तके अनुसार "वंगालकी फौजदारी अदालतोंमें, मजदूर प्राप्त करनेके लिए धोखाधडी, वेजा दवाव और जवरदस्ती भगा है जानेकी पृणित घटनाओंका पता है। आसामके चाय वागानोंके इतिहासमें इन स्त्री-पुरुपोंपर बहुधा हुए वलाकारों व अत्याचारोंके धव्ये लगे हुए हैं। उत्तरदायी और उच पदासीन अधिकारियोंने इन कानृनोंके खत्म करनेकी इच्छा प्रकट की है और सिफारिश को है कि चाय वागानके मालिक मजदरोंके वाजारमें माँग और खपतके साधरण नियमींके अनुसार मजदूर भरती किया करें। हैकिन पूंजी-पतियोंका प्रमाव वहत मजवृत है, किसी वाइसराय या भारतके लिए 'सेकेटरी आव स्टेट'ने इन कानुनोंको खत्म करनेकी हिम्मत नहीं की है और न आज भी भारतमें मौजूद इस अर्द-दासताकी प्रथाको खत्म करनेकी कोशिश हुई है। र नृशंसता और अत्याचारोंकी अनेकों घटनाओंकी रिपोर्ट सरकारको दी गयी, लेकिन ब्रिटिश प्रंजीपतियोंको नाराज न कर सकने-वाली सरकार इस मामलेमें अपनेको असहाय समझती रही।

भारतसे वाहर, ब्रिटिश हितोंमें लड़ी गयी लड़ाइयोंका. खर्च भारतपर लाद दिया गया। देशके साधनोंके अनुपातमें फौजी खर्च कहीं ज्यादा बढ़ गया। ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ रहा था। फौजी महत्वके स्थानोंको ब्रिटेनके लिए सुरक्षित रखनेके लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थीं, लेकिन इन सबका खर्च भारतको देना पड़ता था। ब्रिटिश राज्यको भारतमें स्थिर और स्थायी बनानेके लिए खर्च की गयी चार करोड़ पींडकी रकम 'गदरका कर्ज'के रूपमें भारतसे वस्त् करनेकी और क्या तुक हो सकती थी ? इसी तरहसे चीन, अफगानिस्तान, ईरान, अवीसीनिया आदिमें लड़ी गयी साम्राज्यवादी लड़ाइयोंमें इस्तेमाल किये गये भारतीय सिपाहियोंका खर्च ब्रिटिश सरकारको देना था, न कि भारतको। पर भारत असहाय था।

कुछ अंग्रेज खतरा उटाकर भी सच बोलते थे। सन् १८६०मं मद्रासके गवर्नर सर चार्ल्स ट्रेबेल्यिनको गवर्नरीसे हटा दिया गया क्योंकि वे बढ़े हुए खर्च और कराँका बार बार प्रतिवाद कर रहे थे। १८५९मं उन्होंने तम्बाक्षर लगनेवाले करका विरोध किया। १८६०मं उन्होंने तीन बार बढ़ते हुए करींका प्रतिवाद किया। अपने चौथे प्रतिवादके लिए उन्हें गवर्नर पद छोड़कर कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने सिफारिश की थी कि "अपनी वर्तमान सुविधाओं-की शक्तिका प्रयोग कर यदि हमने अप्रिय और अनिष्टकर टैक्स जनतापर लाद दिये तो हम ऐसी स्थितिमें पड़ जावँगे जो देशी फौज कम करनेके लिए उपयुक्त न होगी। हम एक साथ ही जनता और फौज दोनोंको असन्तुष्ट नहीं रख सकते। "

१. दत्त, वही पुस्तक, पृष्ट १४६

२. दत्त-इण्डियन ट्रेड, मेन्यूफेनचर एण्ड फाइनेंस, पृष्ट १७१

१८७६में लार्ड लिटन भारतके गवर्नर-जनरल होकर आये और उन्होंने फौरन ही साफ साफ वता दिया कि सरकार किसानोंकी हित-रक्षा क्यों नहीं क़रेगी। ११ मई १८७६को उन्होंने सेक्रेटरी आव स्टेट (मारत सचिव)को लिखा-"मेरा विखास है कि भारतमें आने वाले योग्य और अनुभवी अफसरोंकी वुनियादी राजनीतिक भूल यह है कि वे समझते हैं कि हम 'अच्छी सरकार' द्वारा भारतको अपने कब्जेमें रख सकते हैं, यानी रैयतकी हालत सुधार कर, सही और सचा न्याय कर और सिंचाई आदिके कामोंमें वड़ी-वड़ी रक्षमें खर्च कर, उनके अनुसार अच्छी सरकार भारतपर कव्जा कायम रख सकती है। राजनीतिक दृष्टिसे भारतीय किसान एक गतिहीन, निश्चल पिण्ड है, अगर वह कभी भी चलेगा तो अपने ब्रिटिश हित-चिन्तकोंके इशारे और अनुशासनमें नहीं, अपने देशी राजाओंके इशारेमें — वे राजा चाहे जितने जालिम क्यों न हों। भारतीय जनमतके अकेले राजनीतिक प्रतिनिधि वे वाबू हैं जिन्हें हमने शिक्षा देकर देशी अखवारोंमें अर्द्ध-राजद्रोहात्मक लेख लिखना[,] सिखाया है और यह वावूवर्ग अपनी गलत स्थितिके सिवा और किसीका प्रतिनिधित्व नहीं करता । अपने इतालवी प्रान्तोंके शासनमें अस्ट्रियाने जो गलती की, वह देखिये। वे प्रांत इटलीके सबसे सुशासित भाग थे। आस्ट्रियाने वहाँके किसानोंके हितोंकी रक्षा की, पर वहाँके 'कुलीन' जागीरदारसे डरकर उनका दमन और अपमान किया। जब इस कुलीनवर्गने समझ लिया कि अस्ट्रियाके शासनसे उसका हित नहीं सध रहा, तो उसने उसके खिलाफ साजिश की; किसान या तो इसमें उदासीन रहा और या फिर अपने देशी नरेशोंका अनुसरण कर विदेशी हितचिन्तकोंके विंचद होकर उसपर हमला वोल दिया। पर भारतीय मुखिये और राजे सिर्फ कुलीन जागीर-दार ही नहीं हैं। वे शक्तिशाली सामन्त हैं।

"आज हमारे सामने जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, वह है भारतीय सामन्तवर्ग-का कुशलतापूर्वक, पूर्णरूपेण अपने हितमें उपयोग । में स्वीकार करता हूँ कि यह समस्या शीं और सरलतापूर्वक हल नहीं होगी । क्योंकि, एक ओर तो हमें उनकी स्वेच्छा-प्रेरित और सद्भावनापूर्ण निष्ठा चाहिये, जो किसी ढंगसे ब्रिटिश सत्तामें उनके हित और सहाज-भूतिके समन्वयपर निर्मर है; और दूसरी ओर हम निश्चय ही, उन्हें ऐसी कोई राजनीतिक शिंक नहीं दे सकते जो हमारी शक्तिसे स्वतंत्र हो । सौभाग्यवश, यह वर्ग भावनाओंसे वहुत आसानीसे प्रभावित होता है और उन 'प्रतीकों'के प्रभावको वड़ी जल्दी ग्रहण करता है, जो वस्तु-स्थितिमें कुछ भी नहीं हैं।"

अपने वाइसराय रहनेके कालमें, लार्ड लिटनने इसी नीतिका अनुसरण किया। इतना ही नहीं, उनके वादकी सभी सरकारोंने छोटे-मोटे परिवर्तन कर इसी नीतिका पालन किया। लार्ड लिटनने उस वक्त भारतसे गेहूँ इंगलेण्ड मेजा, जब यहाँ अकाल पड़ रहा था और लाखों करोड़ों भारतीय कुत्तोंकी मौत मर रहे थे। सन् १८७७ में अपनी एक्जीक्यूटिव कांउ-सिल (कार्यकारिणी) के अधिकतर सदस्योंकी रायके विरुद्ध, उन्होंने सती वस्त्रपर लगनेवाला आयात कर खत्म कर दिया और इस प्रकार भारत सरकारकी आयका काफी वड़ा साधन खत्म हो गया। कांउसिलके सदस्योंने इस प्रकार धौंसमें स्वीकृति लेनेका प्रतिवाद किया पर वाइसरायको उनकी राय उकरानेका अधिकार था। यह निर्यात कर उस समय तोड़ा गया

१. लेडी वेटी वालफर, लार्ड लिटन्स इंडियन ऐडिमिनिस्ट्रेशन १८७६-१८८० पृष्ठ १०९-११०

था, जब दक्षिण भारत १८७७ के अकालके बाद उठकर खड़ा भी न हो पाया था और उत्तर भारतमें १८७८ का अकाल पड़ रहा था, लगानमें नये सेस हालमें ही बढ़ाये गये थे, वजटमें घाटा था; विशेष कर लगाकर बनावा गया 'अकाल बीमा कोष' न जाने कैसे गायब हो गया था और सीमान्त प्रदेशमें अशान्ति थी।

असलमें, लाई लिटनकी नियुक्ति ही वे सब अधियं और गन्दे काम करनेके लिए हुई थी, जिन्हें उनके पहले आनेवाले लार्ड नार्थब्रुकने करनेसे इनकार कर दिया था और जिस इनकारकी वजहसे उन्हें इस्तीफा देकर वापस जाना पड़ा था । नार्थवृककी जल्दी वापसी का कारण आयात-कर मिटानेका मामला ही था। लिटनकी नीति और ज्ञासन समझनेमें आसानी होगी अगर नार्थत्रककी वापसीके कारणींपर एक निगाह डाल ली जाय । १९ वीं सदीकी आठवीं दशान्दीमें भारतमें कुछ सती कपड़ेके कारखाने वन गये थे। ब्रिटिश फिल मालिकोंने उन्हें अपना प्रतिस्पदीं माना। जनवरी सन् १८७४ में मैनचेस्टरके व्यवसायी मंडलने भारतमंत्रीको एक त्मृतिपत्र मेजकर भारत जानेवाले सतपर रे। और कपहेपर ५ फीसटी आयात करका विरोध किया और उसे खत्म करनेकी माँग की। इन व्यापारियोंका तर्क या कि भारतमें यह आयात-कर लगाना मानो इंगलैण्डके सत और कपहेके व्यापारपर रोक लगा देना है। यह स्पृतिपत्र भी वड़े ठीक समयपर भेजा गया था। इंगलैण्डमें आम चुनाव होनेवाले थे और वहाँकी पार्लमेण्ट उस समय भंग की जा चुकी थी जब ग्लैडस्टनकी सरकार अपने अंतिम दिनोंमें जनतामें अप्रिय हो रहो थी। लंकाद्यायरके बोटोंकी वडी कीमत थी और कोई भी राजनीतिक दल वहाँके उद्योगपतियोंको नाराज नहीं कर सकता था कंजरवेटिव (अनुदार) दल उद्योगपतियोंका विश्वासभाजन था, वही जीता और १८७४ में डिजरेलीने अपनी सरकार बनायी । १८७५ में डिजरेलीके भारतमंत्री लाई सेलिसवरीने अपने सचिवको भारत सरकारसे आर्थिक कान्नोंके संबंधमें बातचीत करनेके लिए यहाँ भेजा । सेलिसवरीका आग्रह या कि सती मालपर लगनेवाला आयात कर धीरे-धीरे विलकुल खत्म कर दिया जाय । नार्थत्रक और उनकी कार्यकारिणीने परवरी सन् १८७६ में इस आग्रहके उत्तरमें लिख भेजा कि यह कर हटाना उचित न होगा क्योंकि "आठ लाख पींड सालानाकी आमदनीवाले इस करको खत्म कर भारतीय अर्थ-व्यवस्थापर ऐसा गंभीर प्रभाव डालनेवाले आदेशका कोई पूर्व दृष्टान्त नहीं है।"

इस घटनाके बाद नार्थब्रुकको इस्तीफा देना पड़ा और लिटनकी नियुक्ति हो गयी। १८७७ में ब्रिटिश लोक-सभाने एक प्रस्ताव द्वारा भारत सरकारको आदेश दिया कि वह सुती कर खत्म कर दे।

लाई लिटनने पूरे मनोयोगसे जमींदारों व सामन्तोंको मुविधाएँ देकर भारतीय किसानों और गरीबोंके दमनकी नीति लागू करनी शुरू कर दी। ३० अप्रैल सन् १८७६ को लिटनने प्रधानमन्त्री डिजरेलीको लिखा—भारतीय राजाओं, महाराजाओंसे भेंटमें मुझे जिम बातने सबसे अधिक आकृष्ट किया वह उनका वंशगत उपाधियों और पूर्वजोंके यशको महस्वपूर्ण मानना है। यहाँ यह बड़ा सामन्ती कुलीन वर्ग है, जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते, जिसे खुश करने और जिसपर शासन करनेको हम उत्सुक हैं, पर ब्रिटिश ताजके आसपास सामन्ती समृहकी तरह जिसे समेटने बटोरनेके लिए हमने अवतक प्रायः कुछ मी कोशिश नहीं की है। जिन राजाओंसे मेरी बातचीत हुई उनमेंसे हर एक अपने वंशकी प्राचीनता, पुराने

जमानेमें केन्द्रीयसत्ता द्वारा मिले उसके परिवारके महत्वका मुझे विश्वास दिलाना चाहता था। उनमेंसे बहुतोंने अपने खर्चपर, बढ़े चावसे संपादन कर अपनी वंद्याचिल्याँ और परिवारके लेख-प्रमाण छपवाये हैं और मुझे उनकी प्रतियाँ दी हैं। यह बढ़ा विलक्षण और मनोरंजक है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि सलामीकी तोपोंकी संख्यामें बृद्धि, दरवारमें अधिक सम्मानित स्थान, वाइसराय द्वारा उनके यहाँ जाने आदिके ब्रिटिश सरकार द्वारा किये गये छोटे अनुप्रहों और सम्मानींका वे सब उतना ही आदर करते हैं, जितना मालगुजारी या अधिकार क्षेत्रकी भूमिमें विस्तारके उन ठोस फायदोंका जो अकबर या औरंग जैवने उनके परिवारोंको कराये थे। ""

इन सामन्ती 'कुलोनों' को वेवक्ष वनानेका अवसर भी शीध हाथ लग गया। इसी साल डिजरेलीने ("जो अचानक ही एक नये साम्राज्यवादकी ओर झक पड़ा था") सुझाव दिया कि "इंगलेण्डकी महारानी भारतकी साम्राज्ञी कहलाये।" "विक्टोरियाको यह वात बहुत पसन्द आयी और आयेदिन वह अपने प्रधानमन्त्रीसे इस नयी उपाधिकी संगतिपर जोर देने लगी। डिजरेलीने असहमति प्रकट की पर विक्टोरिया नहीं मानीं। १८७६ में अपनी और अपने मंत्रिमंडलकी अनिच्छाके वावजूद डिजरेलीको ब्रिटिश लोक व लार्ड सभाओं के प्रचण्ड अधिवेशनमें नयी परेशानी मोल लेनी पड़ी। उन्होंने शाही उपाधिमें परिवर्तन करनेका बिल पेश किया और दोनों सदनोंमें उसके कोधमय विरोधका उन्होंने असीमित शक्ति सामना और विलका समर्थन किया। महारानी विक्टोरिया डिजरेलीसे खुश हो गयीं।" विल पास होकर कानून वन गया।

लाई लिटनने इसका स्वागत कियां और १८७७ में एक शाही दरवार लगाकर महारानी विक्टोरियाकी नयी उपाधियोंकी घोषणा की और उसका उत्सव मनाया। दरवार भी पिछले दरवारकी तरह उस समय हुआ जब देशमें अकाल पड़ रहा या जिसमें दक्षिण भारतके ५० लाख व्यक्ति मरे थे और राष्ट्रीय भारतने इसका विरोध किया। महाराष्ट्रमें भूखसे मरनेवालोंने तीव्र निराद्यामें जमीन्दारों, महाजनों और दूसरे आतताइयोंपर हमला बोल दिया। एक बडी उथल-पुथल मच गयी जिसमें हजारोंने भाग लिया। यह एक पूरा पक्का कृषि-विद्रोह था। पुलिसने लगभग एक हजार व्यक्तियोंको पकड़ा, जिनमेंसे आधे सजा पा गये। पर लिटनको इसकी परवाह न थी। वह राजा महाराजाओंको खिताव वाँटकर उन्हें अपनी ओर मिलानेकी योजना पूरी करनेमें लगा था। ''अभीतक जिन सेवाओं' को पूरी स्वीकृति नहीं मिली थी, अब वे पुरस्कृत हुई; जिन प्राचीन परिवारोंको पेंशनें मिलती थीं और जिनकी असंदिग्ध निष्ठाने उनकी योग्यता बढ़ा दी थी, उनकी पेंशनोंकी रकमें चढ़ा दी गर्यी; वहुतसे मुख्य-मुख्य देशी राजाओंको वढ़ी हुई आजीवन तनख्वाहं मिलने लगीं; और हर उस राजाको, जिसे सलामी लेनेका अधिकार मिला था, महारानीके नाममें एक-एक रेशमी झण्डा मिला जिसपर एक ओर शाही चिह्न और दूसरी और उस राजाका अपना चिह्न अंकित था। ये पताकाएँ राजाओंके स्तवेके अनुसार विभिन्न रंगोंकी थीं; हर सरकारी या राज्य उत्सवमें इन राजाओंके आगे ये पताकाएँ ले चलनेका नियम वन गया; दरवारकी

१. लेडी बेटी वालफर, लार्ड लिटन्स इंडियन एइमिनिस्ट्रेशन पृष्ठ १०८

२. लिटन स्ट्रेची 'क्वीन विक्टोरिया' पृष्ठ २१३

३. लेडी बेटी बालफर, वहीं पुस्तक पृष्ठ २१३

यादगारके तौरपर सोने और चाँदिक पदक भी महारानीकी ओरसे राजाओं व कुछ दूसरे चुने हुए छोगोंको दिये गये। छगभग २०० कुछानों और सम्भ्रान्त नागरिकोंको सम्मानित छपाध्याँ भी दी गयीं जिनकी भारतीय बहुत कद्र करते हैं। आनरेरी मजिस्ट्रेटों, म्युनिसिपल कींसिलोंके सदस्यों आदिको देशभरमें बहुतसे सम्मानके सर्टाफिकट बाँटे गये; भारतीय फीजके अफसरों, ओहदेदारों व जवानोंके वेतन व भत्ते बढ़ा दिये गये; बहुतोंको ओ. बी. आई. के खिताब बाँटे गये।

अब देशकी आम बिद्रोहात्मक परिस्थितिपर एक नजर डाल हैं। दो प्रमुख अंग्रेज अफसरोंने (जो वादमें भारतीय राजनीतिक जीवन और राष्ट्रीय अभिलापाओंसे निकटरूपसे सम्बद्ध रहे) मिली सुचनाओं के आधारपर रिपोर्ट दी कि बिद्रोह तेजीके साथ संघटित किया जा रहा है। उन्हें आशंका थी कि १८५७ की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी। ये अंग्रेज अफसर ये एलन औक्टेवियन हाम और विलियम वेडरवर्न ! हा म भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके पिताकी तरह माने जाते हैं, वेडरवर्न कांग्रेसके प्रसिद्ध अध्यक्ष हुए । वेडरवर्नने ह्यमकी जीवनी-में लिखा था-अपनेमें ही मगन, शिमलेकी पहाडियोंपर रहनेवाले विदेशी नौकरशाहों और मैदानोंको कठिन परिश्रम करनेवाली करोड़ों जनताके बीच एक गहरी खाई थी । १८७८-१८७९ में देशभरमें आर्थिक और राजनीतिक कप्ट मिलकर असंतोप और अशान्ति पैदा कर रहे थे: जनताक भौतिक कष्ट, कुछ लोगोंके बौद्धिक असंतोषसे मिलकर इस अशान्तिको संकट-की सीमातक पहुँचा रहे थे। एक ओर गरीबी और अकाल, महामारीसे पीड़ित कृपक समुदाय निराश होता जा रहा था; उसकी वात नहीं सुनी जाती थी और स्थितिमें किसी सुधारकी आशा नहीं रह गयी थी; दूसरी ओर स्कूटों और कालेजोंमें पश्चिमीं शिक्षाका परिवर्तनकारी प्रमाव बुद्धिजीवियोंमें घर कर रहा था; इस शिक्षामें राजनीतिक इतिहास उन्हें सिखा रहा था कि ब्रिटिश जनता स्वतन्त्रताका फल भोगनेमें केवल श्रम और विद्रोह द्वारा ही समर्थ हो सकी । नयी पीढ़ीका हृदय कान्तिकारी और हिंसात्मक परिवर्तनके स्वमोंसे प्रेरणा और स्फर्ति पाने लगा । मिस्टर ह्यम इस संकटापन्न दिथितको अच्छी तरह समझ रहे थे। ऊपर शान्त सतहके नीचे जो धाराएँ प्रभावित हो रही थीं, उन्हें उनका असाधारण ज्ञान था; और वे जानते थे कि जनतामें उथल-पथल होनेका संकट आसन है: और वे यह भी समझते थे कि यह उथल-पुथल उस द्यान्तिपूर्ण उन्नतिको नष्ट कर देगी जिसपर भारतकी भलाई निर्भर है। पुरानी बोतलोंमें नवी शरावका खमीर उठ रहा था, कभी भी यह बोतलें फट सकती थी और शराव वह निकल सकती थी।""

लेकिन ख्मके पास (जिन्होंने १८५७-५८ के विद्रोहके दमनमें हिस्सा लिया था) इस बातके पक्के सवृत मौजूद थे कि एक और विद्रोह आसन्न है । खूमकी जीवनीके 'धर्मनिष्ठ भारतीय' शीर्षक अध्यायसे उस समय की परिस्थित सही तौरपर समझमें आ जाती है । वेडर-वर्नने लिखा—''१८५७ के गद्रमें मिस्टर खूमके अनुभव, शौर्य और युक्तिसाधना देखनेके वाद, आसन्न संकटको सत्यतामें उनके निजी विश्वासके महत्वपर शक नहीं किया जा सकता । विभिन्न स्वोंमें फैले उनके वहुतेरे मित्रोंका समर्थन भी स्थितिके उनके मृत्यांकनको प्राप्त था । लेकिन, इसके अलावा भी उन्हें स्वना और चेतावनी एक विशेष स्त्रसे—भारतमरमें पेले

१. लेडी वैटी बालफर पृष्ठ १११-११२

२, उब्ह्य. वेढरवर्न, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, पृष्ट २

धर्मके भक्त नेताओंसे मिली थी। ह्यूमके कागजातमें भारतीय समस्याके सबसे महत्वपूर्ण अंग लाखों सदस्यवाले अर्घधार्मिक संघटनों सम्त्रन्धी एक स्मृतिपत्र भी है, जो स्थितिपर बहुत प्रकाश डालता है। धार्मिक जीवनयापन करनेवाले असंख्य साधुओं, फकीरों और वैरागियोंके सम्वन्धमें ह्यूमका विचार था कि उनमें अधिकांश वदमाश और ठग हैं। पर जहाँ तल्छट है वहाँ सोना भी है और इन सम्प्रदायोंके गुरुओंमें प्राचीन यहूदी द्रष्टाओंकी तरह महान व्यक्ति भी हैं जो भौतिक आकांक्षाओंसे निर्लित और निष्काम होकर अधिकतम भलाई करनेकी आकांक्षा रखते हैं। इन धार्मिक गुरुओं या नेताओंको अपने चेलोंके द्वारा ऊपरी शान्त सतहके नीचे वहनेवाली धाराओंकी पूरी सूचना प्राप्त रहती है, जनमत वनानेमें उनका वड़ा हाथ रहता है। लिटनके वाइसरायकालका जव अन्त हो रहा था, तभी मिस्टर . ह्मम इन गुरुओंके सम्पर्कमें आये l सहानुभूतिका आधार अंशतः धार्मिक रहा होगा, लेकिन इन लोगोंके हा मसे मिलनेका व्यावहारिक कारण उनकी यह आशंका थी कि देशभरमें, समाजके निम्नतम स्तरतक पहुँची यह अधुभ अशान्ति ऐसा भवंकर उद्देलन उत्पन्न कर देगी जो भारतके भविष्यके लिए विनाशकारी होगा; और उनका विचार था कि सरकारतक पहुँच रखनेवाले हा म जैसे लोग यदि जनताकी नैराश्यकी भावना दूर करनेके लिए सिकय न हुए तो यह विपत्ति आकर रहेगी। उनका कहना था— जंगल विलक्कल सुला है; ठीक हवा चलनेपर ऐसे जंगलोंमें आग आश्चर्यजनक तेजीसे फैलती है; और यह हवा इस समय तेजीसे चल रही है।' ह्यूमने लिखा है—'स्थिति मुझे इन शब्दोंमें समझायी गयी। छोटे पैमानेपर, गदरमें इसी प्रकारकी घटनाओंके अनुभवने मुझे देश और जनताका परिचय करा दिया था; गरीव, धर्वहारा जनताकी सची और विश्वसनीय स्थितिके पुष्ट प्रमाणोंपर मुझे विश्वास था; इन दोनोंके वाद मुझे इसमें न तव संशय था और न अव है कि एक भवंकर कान्तिके घोर संकटमें हम पड़े हुए थे।'

''और ये पुष्ट प्रमाण क्या थे, इसका उनके शब्दोंसे अच्छा वर्णन असम्भव है— 'लार्ड लिटनके जानेके १५ महीने पहले, मुझे जिस प्रमाणने आसन्न कान्तिके संकटका विश्वास दिलाया, वह यह था । वर्मा, आसाम और कुछ छोटे हिस्से छोड़कर रोप सारे देशके सम्बन्ध-में सात मोटी-मोटी पुस्तकें दिखायी गयीं जिनमें असंख्य इन्दराज थे; तरह तरहकी सूच-नाओं, रिपोटोंके (जो जिलों, तहसीलों, कस्त्रों, शहरों, गाँवों आदिमें सिलसिलेवार वँटी हुई थां, लेकिन ये जिले वर्तमान शासकीय जिलोंसे भिन्न थे) उद्धरणोंके अंग्रेजी अनुवाद -भी पुस्तकोंके साथ थे । ये असंख्य इन्दराज ३० हजार संवाददाताओं द्वारा इकट्ठी सूचना-के आधापर किये गये थे। मैंने उन्हें गिना नहीं, वे असंख्य थे; उत्तरी पश्चिमी सूबेके एक उपद्रवी जिलेके गाँवों और शहरोंकी मुझे गहरी जानकारी थी, और वहाँके सम्वन्धमें किये ३०० इन्दराजोंमेंसे काफीको मैं पूर्णतः या अंशतः पहचान सका; ये लोगोंके नाम आदि थे।' यहाँ जिस जिल्लेका जिक है, वह निर्विवाद रू से इटावा है, जहाँ मिस्टर ह्यूम कई साल तक मुख्य अधिकारीके रूपमें काम कर चुके थे। उन्होंने लिखा है कि ये पुस्तकें उनके पास सिर्फ एक संताह रहीं; छः को उन्होंने सरसरी तौरपर पलट डाला; लेकिन एक कितावको जिसमें उत्तरी-पश्चिमी स्वे, अवध, विहार और बुन्देलखण्ड व पंजावके हिस्सींका वर्णन था, उन्होंने सावधानीसे पढ़ा; जहाँतक सम्भव हो सका उन्होंने उन जिलोंके इन्द-राजोंकी जाँच भी की, जहाँके सम्बन्धमें उन्हें काफी जानकारी थी। बहुतसे इन्दराज गरीव

और निम्न श्रेणीके लोगोंकी वातचीतकी रिपोटोंके रूपमें थे। "इन सबसे वही प्रकट होता था कि इन गरीवोंमें एक नैरादयकी भावना घर कर गयी थी; वे स्मझते थे कि वे भृखों मर जाउँगे और वे 'कुछ' करना चाहते थे "वे 'कुछ' करनेवाले थे और उसके लिए अपनेमें एकता वढ़ा रहे थे; और यह 'कुछ' थी हिंसा क्योंकि अनेक इन्दराज पुरानी तलवारों, भालों और टोपीदार वन्दूकोंके निकालनेसे सम्बन्धित थे। अनुमान यह नहीं था कि शुरू ज्रुहमें यह तैयारी हमारी सरकारके खिलाफ विद्रोहके रूपमें प्रकट होगी, या सही अर्थमें यह विद्रोह ही होगा । भविष्यवाणी यह थी कि अकरमात् छिटफुट अपराध-महाजनोंके यहाँ डाके, बाजारोंकी लूट, घृणित व्यक्तियोंकी इत्या आदि-शुरू हो जाउँगे। 'अधभूखे गरीव लोगोंकी वर्तमान हालत देखकर अनुमान लगाया गया था कि गुरूमें कुछ घटनाएँ. सैकडों नयी घटनाओंके लिए इजारेका काम करंगी; इससे आम अराजकता फैलेगी और सरकार व सम्मानित वर्गोंका काम रक जायगा । यह भी निहिन्त माना गया था कि हर जगह छोटे छोटे जस्थे पत्तेपर पडी पानीकी व्दोंकी तरह मिलकर वड़े गिरोहोंमें परिवर्तित हो जायँगे, देशभरके खोटे लोग भी इसमें शामिल हो जायँगे और शीव ही ये गिरोह बड़े पैमानेपर संघटित होने लगेंगे; कुछ पढ़े-लिखे लोग सरकारसे कटुता (शायद अनुचित कटुता) के कारण निराशाके उन्माद—इस उथल-पुथलमें शामिल हो लेंगे, जहाँ तहाँ उसका नेतृत्व करेंगे, इस उथल-पुथलको सूत्रवद आन्दोलनका रूप देंगे और इसे राष्ट्रीय विद्रोहके रूपमें संचालित करंगे।'

"यह थी वह विशिष्ट चेतावनी जो मिस्टर ह्यूमको मिली थी। देशव्यापी उपद्रवकी यह भविष्यवाणी वादमें मेरी आँखोंके सामने हुई वम्यईकी घटनाओंसे सच सावित हुई; दिक्खनके दंगोंके नामसे जात कृषकविद्रोहकी ग्रुक्जात छिटफुट डकैतियों और महाजनोंपर हुए हमलोंसे हुई। धीरे-धीरे डकैतोंके ये गिरोह मिलकर इतने मजवृत हो गये कि पुल्सिस उनका सामना न कर सकी और पूनाकी पूरो घुड़सवार, पैदल, तोपखाना आदि फींज उनके खिलाफ लगानी पड़ी। पित्वमी घाटके पहाड़ी जंगलोंमें, फींजके सामने वे तितर-वितर हो जाते, पर फिर कहीं सुविधाजनक स्थानपर इकट्ठे हो जाते। महावलेश्वर और मथेरनके पहाड़ोंसे रातमें हमें उनके शिविरोंको रोशनो हरतरफ दिखाई पड़ती। उनका एक पढ़ालिखा नेता था जो अपनेको शिवाजी दितीय वताता और सरकारको चुनौतियाँ भेजा करता। उसने वम्बईके गवर्नर सर रिचर्ड टेग्पिलको मारनेवालेको ५००) के इनामकी घोषणा की थी और उसका दावा था कि वह उसी ढंगपर एक राष्ट्रीय विद्रोहका नेतृत्व कर रहा है, जैसे पहले मरहठा शक्ति संघटित हुई थी।"

फिर १८७९ में मरहटा आन्दोलन ग्रुल हुआ जोकि १८६२ के आन्दोलनकी पुनरावृत्ति था। इतिहासकार हेनरी डढवेलके अनुसार यह आन्दोलन वहावी आन्दोलनके ढंगका था; वहावियोंकी काररवाइयोंका केन्द्र पटना था, मरहटोंका पूना। मरहटोंकी अपनी स्वतन्त्र सत्ताकी यादगार मुसलमानोंके मुकावलेमें ज्यादा ताजी थी। असलमें, अगर अंग्रेज हस्तक्षेप न करते तो मुगलों और मुस्लिम सत्ताके अन्तके वाद् मरहटे ही भारतके शासक हुए होते। डडवेलने लिखा है—यद्यपि मरहटे "धर्मोन्मादसे प्रेरित या उत्तेजित नहीं थे, लेकिन यह कमी मरहटा इतिहाससे उत्पन्न जातिगर्वकी मावनासे पूरी हो जाती थी। १८६२ में

१. विलियम वेदरवर्न ... पृष्ट ७८-८२

षड्यन्त्रोंका पता लगा था। वार्टिल फेटने केंनिंगको लिखा था—"यह आन्दोलन उसी असन्तोषकी एक शाखा है, जिसके चुने नेता नाना, तात्या टोपे आदि थे और जो आज भी मरहठाप्रदेश और मध्य भारतमें सुलग रहा है।" जहाँतक मुझे मालूम हो सका है, यूरोप या अमेरिकामें युद्ध जैसी किसी एक चिनगारीसे विन्ध्याचल और तोधुन्प्रके वीचके प्रदेशभरमें अलग-अलग किन्तु संघटित वलवे सुलग उठते। आन्दोलनकी खवर उसके भीपण रूप धारण करनेके पहले ही लग गयी, लेकिन यह आग पृरी तरह बुझी नहीं। १८७९ में अपगान युद्ध से प्रेरणा पाकर इसी भावनासे दक्षिणमें डकेंतियोंकी भरमार हो गयी। आन्दोलनका नेता सरकारके खिलाफ घोषणाएँ जारी करता। लेकिन उसे चन्द हमतोंमें ही दवा दिया गया और उसे सिर्फ एक ही ठोस सफलता मिल पायी—पूनामें पेशवाके प्रसिद्ध शीशमहलको जला डालनेमें।" इसी वर्ष प्नामें रमोसियोंका (जो मरहठा सेनाके अंग थे) विद्रोह हुआ।

दक्षिणके ये उपद्रव किसानोंकी उपेक्षा और सरकारके प्रति कुलीनवर्गमें निष्ठा जगानेके लिए उन्हें सुविधाएँ देनेकी ब्रिटिश नीतिके ही फल थे। अदालतें महाजनोंकी रक्षा करती थीं, क्योंकि कानून उनके पक्षमें था, कर्जदार किसान अक्सर अपनी जोतोंसे वेदखल कर दिये जाते थे और अपना सबकुछ वेचकर उन्हें जमींदारोंका पेट भरना पड़ता था। महाजनोंका चंगुल किसानोंपर इस तरह जकड़ रहा था कि जमीन धीरे-धीरे सदस्त्रोरोंकी सम्पत्त बनती जा रही थी और किसान गुलामोंकी हीनावस्थाको पहुँच रहे थे। दमदूपत (मूल ऋणका दुगुनेसे ज्यादा न लेनेका नियम) खत्म हो गया। महाजन अदालतोंकी मददसे अपनी लूट जारी रखते। फल यह हुआ कि बम्बईमें १८७५ में किसानोंमें घोर असन्तोप पैदा हो गया और जनता एक कानूनी अन्यायको दूर करनेके लिए उठ खड़ी हुई। पूनाके ४५ और अहमदनगरके २२ गाँवोंमें उसने महाजनोंको रक्के, पट्टे लौटा देनेको वाध्य कर दिया और इन दस्तावेजोंको खुलेआम जला डाला गया। १८७८ में फर असन्तोप भड़का और सरकार किसानोंकी हालत सुधारनेके लिए कानून बनानेके लिए वाध्य हो गयी। इस कानूनसे सुदलोरीपर कुछ रोक लगी और कर्जके बदले जमीनोंपर कृष्टा करनेको गैरकानूनी माना गया।

१८९७ में वजीरी उठ खड़े हुए । उनके दमनके लिए मेजी गयी ब्रिटिश फौजने टोकी घाटीपर कटजा कर लिया। इसके वाद ही स्वातके कवीलोंने मलाकन्दपर और मोहमन्दोंने पेशावरके गाँवोंपर हमले किये और अफरीदियोंने खैवर दरेंपर कटजा कर लिया। ''थोड़े ही दिनोंमें—टोकोंसे बूनर तक सारे सीमाप्रान्तमें आग-सी लग गयी जिसे बुझानेमें ६० हजार सिपाही छः महीने तक न्यस्त रहे।"

लिटनके नृदांस और अत्याचारी शासनका अन्त इंग्लेण्डमें सरकार वदलनेके साथ ही हुआ । २८ अप्रैल सन् १८८० को ग्लेडस्टन फिर ब्रिटेनके प्रधानमन्त्री हुए और नयी सरकारकी नीति भारतमें ठीक तरहसे लागू करनेके लिए लिटनको इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह लार्ड रिपन नियुक्त हुए । रिपनका राज कुछ दर्शनीय या चमत्कारिक चीजोंके लिए मशहूर हुआ । सन् १८८२ में रिपनने लिटनका वर्नाकुलर प्रेस ऐक्ट रह करवा दिया । भारत सरकारने घोषणा की कि हालात वदलते जानेके फलस्वरूप यह कानून रह किया

१. ए स्केच आव इण्डियन हिस्टरी १८५८ टु १९१८

जातां है । लेकिन आर्म्स ऐक्ट (शस्त्र कान्न) जैसाका तैसा वना रहा । ग्लैंड्स्टन भी उसे छूनेको तैयार नहीं थे ।

रिपनने नर्म दलवालोंको खुश करनेमें सफलता पायी और उनका राज भारतीय जनताको लिटनके प्रतिगामी राजके बाद एक मुक्ति सा माल्म पड़ा। मुरेन्द्रनाथ बनजीने इस सिलिस्टिमें लिखा है—लिटनके राजने "जनताका उदासीनताका रुख बदल दिया था और सार्वजनिक जीवनको उससे एक स्फूर्ति मिली थी। राजनीतिक प्रगतिके विकासमें दुरे या कृर शासक बहुधा एक गुप्त वरदानके रूपमें आते हैं। उनके कारण समाजमें ऐसी जागतिं आती है, जैसी वर्षोंके प्रचार और आन्दोलनसे भी न उत्पन्न हो।"

राज्यकी वागडोर हाथमें छेते ही रिपनने यह चर्चा कर दी कि महारानीने मुझे भारतके म्युनिसिपल शासनको टीक करनेको कहा है । नर्म दलवालेंको इसमें सरकारकी यह सबी
इच्छा दिखाई दी कि सीमित क्षेत्रमें ही सही पर वह भारतीयोंको शासन चलानेमें छेना
जरूर चाहती है । वे इसके लिए प्रचार और जनमत तैयार करनेमें जीजानसे लग गये ।
इण्डियन एसोसियेशनके प्रचार साधन इसी काममें लग गये । एक गस्ती चिटठी भेजी गयी;
फिर छोटे कस्वोंके करदाताओंके पास प्रतिनिधि भेजे गये जो म्युनिसिपल संस्थाओंमें चुनाव
और जन-प्रतिनिधि लानेके आधारपर म्युनिसिपल सुधारकी वात इन करदाताओंको समझाते ये और उनसे कहते थे कि सरकारसे ये माँगें करो । इन प्रतिनिधियोंने वंगालके भीतरी
जगहोंमें जा जा कर समाएँ कीं । सुरेन्द्रनाथ बनजीं स्वयं स्वायत्त शासनके फायदे समझाते
हुए वंगालके कस्योंका दौरा करने लगे । उस जमानेमें खुफिया पुल्सि नहीं थी, राजनीतिक
कार्यकर्त्ताओंके पीछे भेदिये नहीं घूमते थे और सार्वजनिक सभाओंकी रिपोर्टे नहीं लिखी
जाती थीं।

१८ फरवरी सन् १८८१ में कलकत्तेके टाउनहालमें एक सभामें प्रस्ताव द्वारा सुरेन्द्रनाथ वनजींने सिफारिश की कि स्वायत्त शासन संस्थाओंका विधान ऐसा हो जिससे इन संस्थाओंमें जनताके चुने हुए प्रतिनिधि आ सकें; उनका अध्यक्ष भी चुना हुआ हो, मिजिस्ट्रेट या कलक्टर हरगिज नहीं; और, इन संस्थाओंके कार्यक्षेत्र व अधिकार बढ़ा दिये जायें क्योंकि वे प्रस्तावित स्थानीय वोडोंमें शामिल होनेवालो हैं।

हालाँकि १८७० के पहले ही स्थानीय शासनमें स्वशासनका एक पुट दे दिया गया, रिपन इस दिशामें एक लम्या डम भरना चाहते थे। भारत सरकारने १० अक्तूबर १८८१ को स्या सरकारोंको गस्ती चिट्टियाँ भेजकर प्रस्तावित सुधारोंपर उनकी राय माँगी। उनसे पूछा गया कि—''(१) गैरसरकारी और जहाँ सम्भव हो चुने हुए सदस्योंकी सिमितियोंको प्रान्तीय आमदनी और खर्चकी कौन-सी मद दी जा सकती हैं; और जो मदें 'स्थानीय' खातेमें होते हुए मी प्रान्तीय सरकारके प्रशासकीय जिम्मे हैं, उनमें कौन-सी इन सिमितियोंके हवाले की जा सकती हैं; (२) मदोंका यह बटवारा किस तरह किया जाय ताकि वह जनताको अधिक ग्राह्म हो और स्थानीय व म्युनिसिपल संस्थाओंको अधिक लाभदायक हो; (३) अधिक और वेहतर स्थानीय स्वशासनके लिए कौन-कौनसे कान्त वनाये जायँ, या दूसरे काम किये जायँ, (४) पूरे साम्राच्य भरमें स्थानीय व म्युनिसिपल

१. बनर्जी पृष्ठ ६३

करोंकी समान दरं निश्चित करने, अनुचित या कड़े कर रोकने और जनतामें प्रिय और उसे याह्य तरीकोंको अपनानेके लिए क्या किया जाय।"

१८८२ में भारत सरकारने एक प्रस्ताव द्वारा स्थानिक वोडोंके अधिकार और कार्यक्षेत्र वढ़ा दिये तथा देहातोंमें नये वोर्ड वनाये। इण्डियन एसोसियेशनका कहना था कि इस सरकारी प्रस्तावसे लगभग वे सभो माँगें पूरी हो गयीं जो टाउनहालकी सभामें पेश की गयी थीं।

रिपन सचमुच उन खरावियों और शैतानियोंको जहाँतक हो सक दूर करना चाहते थे, जो लिटनने भारतमें की थाँ। पर रिपनकी अपनी सीमाएँ थाँ। वे अंग्रेजी राजकी नीति तो वदल नहीं सकते थे जिसकी बुनियाद ही भारतको लूटकर ब्रिटेनका घर भरना थी। रिपनने किसानोंका वोझ कम करनेके लिए इस सिद्धान्तको उठाया कि सरकार लगान तो वड़ा सकती है, पर यह लगान बृद्धि गल्लेकी कीमतोंके अनुपातमें होनी चाहिए। लगान तय करनेके लिए यह सिद्धान्त उचित ही था पर दिसम्बर सन् १८८४ में जब रिपन वाइसरायकी गद्दी छोड़कर ब्रिटेन वापस गये तो उसके एक महीनेके भांतर ही यह सिद्धान्त पलट दिया गया। रिपनके पहले आये अंग्रेजोंने आर्थिक क्षेत्रमें जो अनुचित रवैया अख्तियार किया था (जैसे आयात निर्यात कर नीति) वह कायम रहा। भारतको ब्रिटिश उपनिवेश वनानेकी नीति जार्रा रही।

रिपनके शासनकालमें ही भारतमें रहनेवाले गोरे अंग्रेजोंने एक इलचल मचायी । सिरिपिरे गोरोंको, जो रिपनको 'भारतका पक्षपति।' कहा करते थे, गोरे और कालेका मेद लेकर वावेला मचानेका मौका मिला। आई॰ सी॰ एस॰ (इण्डियन सिविल सिवस) की प्रतियोगितामें वैठनेको उम्र घटा देनेके वावजूद कुछ भारतीय उसमें आ गये थे। उन्हें ज्यादातर अदालती काम करनेके लिए जुडीशियल सिवसमें रखा जाता था, प्रशासकीय कामके लिए गोरे अफसर ही रहते थे। सन् १८८३ तक कुछ भारतीय अफसर इतने पुराने हो गये थे कि उन्हें जिला व सेशन जजी मिलती। पर उस जमानेके कान्तके अनुसार कोई भी भारतीय जर्ज वम्बई, कलकत्ता और मद्रास छोड़कर अन्यत्र कहीं भी किसी अंग्रेजका मुकदमा नहीं कर सकता था। आई॰ सी॰ एस॰ अपुसरोमें सर एशले ईडन व वी॰ एल॰ गुप्त जैसे लोगोंकी धारणा थी कि सरकारी नौकरोमें भारतीय और अंग्रेजोंके वीच इस कान्तसे हेपपूर्ण मेदभाव होता है। दूसरा तर्क यह था कि 'भारतीय अपसरोको अंग्रेजोंके मुकदमें करनेका अधिकार न मिला तो यह गलत रिथित पैदा हो सकती है कि यूरोपीय जोइ॰ मिलस्ट्रेटोंको वे मुकदमें करनेका अधिकार होगा, जो उनके अपसर, भारतीय जजोंको प्राप्त नहीं है। वम्बई, कलकत्ता व मद्रासके प्रेसीईसी शहरोमें भारतीय मिलस्ट्रेटोंको जो अधिकार है, वह दूसरे शहरोंके भारतीय जजोंको भी नहीं है। अर दूरे सहे हो से सहे हो सहे हो से सहे हो से सहे हो सहे हो से सहे हो से सहे हो से सहे हो से सहे है। अर दूरे से सहते से सहे हो से सहे है। अर दूरे से सहे हो से सहे हो से सहे है। अर दूरे से सहे हो सहे है। अर दूरे सहे से सहे हो से सहे है। अर दूरे से सहते से सहि सहे हो से सहते से सहते से सहते हैं से सहते से सहते से सहते हैं सहते से सहते से सहते हैं से सहते स

रिपनकी सरकारने यह गलत स्थिति दूर करनेका निश्चय किया। न्यायमन्त्री सर कोर्टने एक विलका ससविदा तैयार किया। इस विलका उद्देश्य जजोंमें रंग या जातिक आधारपर जो भेदभाव थे उन्हें दूर करना था। नील और चाय वागानोंके गोरे मालिक, जो अपने मजदूरोंपर हर तरहके जुल्म करते थे, इस विलको अपनी निजी हानि मानने लगे।

१. मुखर्जी—इण्डियन कांस्टीट्यूशनल होक्यूमेण्ट्स पहला भाग पृ० ६३९

२. लाइफ एण्ड वक्स आव रमेशचन्द्रक्त ए० ९४

इन गोरे मालिकोंने एक तरहसे भारतमें फिरसे दासप्रथा चाल् कर दी थी। और वे अपनेको कान्तसे परे या ऊपर मानते थे। इसलिए डब्ल्. ब्ल्ण्टने इस विलक्षा दूसरा उद्देश वतायां!—"उन गैरसरकारी अंग्रेजों—विशेषकर वागान मालिकोंकी दण्ड निश्चित्तका अन्त करना जो अपने देशी नौकरोंसे बुरा वर्ताव करते थे और कभी-कभी उन्हें मार तक डालते थे।"

कलकत्तेके अंग्रेज व्यापारियोंकी इस विलमें प्रत्यक्ष या सीधी दिलचरपी नहीं थी, पर उसके विरोधमें वे भी वागान मालिकोंकी तरह बहुत उग्र थे। उन्होंने रिपनका सत्कार करना वन्द कर दिया और अपमान भी किया। इस विलको लेकर कलकत्तेका यूरोपीय समाज इतना उद्देलित हो उठा कि कुछ अंग्रेजोंने यह पड्यन्त्र भी रचा कि "गवर्नमेण्ट हाउस (वाइसराय भवन) के सन्तरियोंपर कावूकर वाइसरायको जवरदस्ती पकड़कर चाँदपाल घाटसे जहाजपर चढ़ाकर इङ्गलैंण्ड रवाना कर दिया जाय।" कलकत्तेके कुछ अंग्रेज पूरी गम्भीरताके साथ यह पड्यन्त्र पूरा करनेकी सोच रहे थे। विलके विरोधमें आन्दोलन ग्रुक किया गया और एक 'रक्षा संघटन' भी कायम किया गया जिसका मुख्य दफ्तर कलकत्तेमें और शाखाएँ देशके विभिन्न भागोंमें थीं। आन्दोलन चलानेके लिए डेढ़ लाख रुपयेका चन्दा इकट्टा किया गया। कलकत्तेके टाउनहालमें एक सभा की गयी जिसमें ऐसे भाषण किये गये जो "इतने असंयित्त थे कि शिष्टाचारके विरद्ध पड़ते थे। ऐसी सभाएँ वंगालभरमें की गर्यी। अंग्रेजोंके अखवार—खास तौरपर 'इंगलिशमेन' तो विलक्कल वौखला गया। 'रक्षा संघटन' के स्वयंसेवकोंको सरकारी नौकरीसे सामृहिक इस्तीके देनेके लिए उभारा गया। कुछ लोगोंने फीजी कैण्टीनोंमें जाकर उनकी राय भी टोकी वजायी अर्थात दूसरे शब्दोंमें फीजमें वगावत पैदा करनेकी कीशिश्य की।"

इस विलकी सीधी जिम्मेदारी लार्ड रिपनपर व थी। वंगाल सरकारने विलका सुझाव दिया था, वृसरे स्वोंकी सरकारोंने उसका समर्थन किया था और ब्रिटिश सरकारके भारत-सचिव व उनकी परिपदने उससे रजामन्दी जाहिर की थी। पर इस वक्त इमलेके शिकार हुए लार्ड रिपन। वे व्यव्र हो उटे और वोले—"अगर मुझे यह माल्म होता कि मैकालेको हुगलीमें हुवो देनेकी धमकी देनेके समयसे अवतक अंग्रेजोंने न कुछ सोला है और न वे कुछ भूले हैं, तो शायद में इस मामलेमें अभी हाथ न डालता।" इस उपद्रवमें पड़नेका उन्हें दुःख था। उन्हें शुकना पड़ा। निदान भारत-सचिवकी स्वीकृतिपर भारत सरकारने अगस्तमें घोपणा की कि "वहे हुए अधिकार सिर्फ सेशन जर्जो और जिला मजिस्ट्रेटोंको मिलेंगे और हाईकोटोंको मुकदमा एक अदालतसे दूसरी अदालतमें हटा ले जानेका अधिकार होगा।" यह प्रस्ताव दिसम्बरमें कीसिलमें पेश हुआ पर अंग्रेज आन्दोलनकारियोंको इससे सन्तोप नहीं हुआ। सरकारको और शुकना पड़ा। सन् १८८४ में एक और कानृत बना जिसमें भारतीय जर्जो व जिला मजिस्ट्रेटोंको यूरोपीय मुजरिमोंके मुकदमेका अधिकार इस

९. डब्लू ंपुस, ब्लण्ट इण्डिया अण्डर रिपन, पृ० ५

२. रु.सियन बुल्फ 'लाइफ आव लार्ड रिपन' माग दृसरा पृ० १२८

ર. ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

४, वही पुस्तक ए० १२६

शर्चपर मिला कि अपराधी जूरी वैठलानेकी माँग कर सकता है और ज्रियोंमें कमसे कम आधे यूरोपीय या अमरीकी होंगे।

यह कान्त सरकारकी इज्जत रखनेकी तरकीव थी। वहुत से ऐसे जिले थे जहाँ जूरी बनानेके लिए काफी अंग्रेज या अमरीकी होते ही नहीं थे। ऐसे मुकदमे दूसरे जिलोंमें भेजे जाते थे। पर सरकार तो किसी तरह इस कठिन स्थितिसे छुटकारा चाहती थी और जब मामला इस तरह रपादफा हुआ तो उसने आरामकी साँस ली।

लेकिन इस सबके वावज्द इलवर्ट विल्ने भारतिस्थित अंग्रेजोंमें जो क्रोध पैदा कर दिया था वह पूरी तरह शान्त न हुआ । भारतीयोंके प्रति उनकी धृणा और अधिक उन्न और प्रत्यक्ष हो गयी । भारतीयोंको किसी भी ढंगके स्थानिक स्वशासन देनेकी वे खिल्ली उड़ाते थे । रिपनके स्वायत्त शासन सुधारोंको वे अन्यावहारिक और कुविचारपूर्ण वताते । उनका तर्क था कि देशी लोग स्वशासनके अयोग्य और असमर्थ हैं । उनकी खुदगर्जीने उनके विवेकको इतना अन्धा वना दिया कि वे ऊँचे सरकारी पदोंके लिए होनेवाली खुली प्रतियोगिताका भी विरोध करने लगे । उन्हें आशंका थी कि ऐसी प्रतियोगितासे 'वावू' अफसर वन जावँगे । वावुओंको वे किरानियोंकी हैसियतसे स्वीकार करते थे, पर अपने समान अफसर वनने देनेसे घृणा करते थे।

इलवर्ट विलक्षे मामलेमें सरकारको शिकस्त देकर अंग्रेज भारतीयोंका वेझिझक और वेशमींसे अपमान करनेकी छूट पा गये। 'इण्डिया अण्डर रिपन—ए प्राइवेट डायरी'के लेखक डब्लू, सी. ब्लण्ट सन् १८८४ में भारतमें थे। उन्होंने अपने अनुभव इस प्रकार लिखे हैं—

"इंगलैण्डमें लोग इसपर विश्वास नहीं करेंगे, पर आज सन् १८८४ में भी भारतमें ऐसा कोई होटलवाला नहीं है, जिसकी हिम्मत हो कि किसी देशी मेहमानको टिका ले। उन्हें देशी लोगोंसे कोई जाती घृणा नहीं है, पर वे अपने गोरे अतिथियोंके नाराज हो जानेके डरसे ऐसा नहीं कर पाते। जाड़ोंमें जब में वम्बईमें था, वहाँके देशी समाजके लोगोंने मेरा अत्यधिक सम्मान किया और मेरे साथ बड़ी मेहरवानीसे पेश आये। शहरके ममुख मुस्लिम मुहम्मदअली रोजेने भी मेरे साथ बड़ा आदरपूर्ण व्यवहार किया। वे यूरोप घूमे हुए थे, अंग्रेजी लिवासमें रहते थे और उन्होंने हमारा दृष्टिकोण और शिष्टाचार यहाँतक अपना लिया था कि वे चार घोड़ोंवाली टमटमपर विना कोचवान चढ़ते थे और सभी सार्वजनिक कार्योंमें दान देते थे। लेकिन तब भी एक दिन उन्हें भोजनके लिए आमंत्रित करनेपर मुझे बताया गया कि यह नहीं हो सकता—कम से कम दुले सार्वजनिक हालमें तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे अंग्रेज मेहमानोंके नाराज हो जाने और होटल छोड़ जानेकी आशंका है।

"वंगाल और उत्तरी भारतमें दशा और अधिक खराव है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि कोई भी भारतीय, उसकी वेशभूषा अथवा पदवी कितनी ही उच क्यों न हो, उन जगहोंपर जहाँ अंग्रेज लोग घूमने जाते हैं विना अपमानके भयके नहीं घूम सकता। अपमान और वेहज्जतीका खतरा रेल्यात्रामें तो वहुत है। मेरी जान-पहचानके लगभग सभी भारतीयोंने अपने प्रति रेल्यात्रामें हुए दुर्भावपूर्ण दुर्व्यवहारके कटु अनुभवोंकी कहानियाँ मुझे सुनायीं। इस कारण उच्च पदाधिकारियों व स्वाभिमानी लोगोंको लाचारीसे यात्राके लिए खास डिल्वोंका इन्तजाम करना पड़ता है या फिर वे तीसरे दरलेमें सफर करते हैं। उन्हें

विशेष रूपसे दूसरे दर्जेंके डिब्वेका भय लगता है। में ये वातें न कहता अगर इनकी सच्चाईमें मुझे जरा भी शक होता। लेकिन मुझे इनकी सच्चाईका पूरा विश्वास है और इसकी ताईद कलकत्तेकी सुप्रीम विधान सभाके दो सदस्योंने भी की, जिन्होंने अपने अनुभव मुझे वताये।"

अपमानजनक भेदभावकी यह कहानी कोई नयी न थी ! यह तो जबसे अंग्रेज भारतके निरंकुश शासक हुए, तबसे चला आरहा था ।

भारतमें जो यूरोपीयन व्यापारी या शासककी हैसियतसे आये थे, उनके आचार विषयक नियम बहे विचित्र थे! एक यूरोपीयनकी जिन्दगीकी कोमत कई भारतीयों के बरावर थी! यूरोपीयनकी जिन्दगी पिवत्र थी और भारतीयों की नगण्य। "अंग्रेजों द्वारा भारतीय खगातार पीड़ित और करल किये जाते रहे पर अपराधीको या तो कोई सजा ही नहीं मिलती थी या फिर पूरे यूरोपीयन समाज द्वारा माँग की जानेपर हल्का-सा दण्ड दे दिया जाता था।" यहाँपर एक और छेखक सर थियो-डर मॉरीसनका हवाला दिया जा सकता है। वे लिखते हैं "यह एक महासत्य है जिसे छिपाया नहीं जा सकता कि अँगरेजों द्वारा भारतीयों की हत्या की जानेकी घटनाएँ अकेली हुकेली नहीं हैं। अमृतवाजार पित्रकाके एक अंकमें (११ अगस्त १८९८) ऐसी तीन वारदातों का जिक्क है जिनमें हत्यारों को पूरी कान्ती सजा नहीं मिली। यूरोपीयनों के मुकदमों में शहरों से जूरी बुलाये जाते हैं। उनमें विजेता जातिके होनेका अहंकार सबसे ज्यादा है, उनकी नैतिक भावना इस बातकी अनुमित नहीं देती कि एक अंग्रेजको किसी 'निगर' की हत्या करनेके अपराधमें अपनी जान देनी पड़े।"

मॉरीसन के ही अनुसार तोपसेनाके तीन सिपाहियोंने डा॰ सुरेशचन्द्र नामी एक आदमीकी हत्या वड़े अमानुषिक ढंगसे की थी परन्तु उनको केवल सात-सात सालकी कड़ी कैदकी सजा मिली। एक फौजी अफसरने इस न्यायपर कहा था ''भारतके अलाया संसारके किसी भी भागमें इन तीनों फौजियोंको फाँसी दे दी जाती।''

परन्तु आद्यर्यकी वात है कि लाई कर्जनने जो अपने प्रतिक्रियावादी शासनके लिए वदनाम है, इन वातोंपर कड़ा रुख अपनाया, और अपराधियोंको कड़ी सजा दी। भारतमें आगमनके फौरन वाद ही लाई कर्जनको माल्म हुआ कि एक ब्रिटिश वटालियनके कई फौजी सिपाहियोंने एक औरतके साथ वलात्कार किया, यहाँतक कि उसकी मृत्यु हो गयी। वहाँपर जो फौजी अधिकारी मीज़द थे, उन्होंने मामलेको दया दिया। मुकामी सरकारी अफसरोंने भी मामलेकी उपेक्षा की। वादमें अंग्रेजी सिपाहियोंका चालान किया गया, पर मुकदमा कानृनी दाँव-पंचमें खतम हो गया। परन्तु कर्जनने इस वातपर विशेष जोर दिया कि अपराधियोंको यों ही नहीं छोड़ देना चाहिये! उनको फौजसे निकाल दिया गया। फौजके उचाधिकारियोंको सख्त चेतावनी दी गयी और कुछ लोगोंसे सेनाकी कमान छीन ली गयी। रेजिमेंटको दो सालके लिए अदन भेज दिया गया और रेजिमेंटकी दो सालकी छुट्टियाँ और सब आमोदप्रमोद वन्द कर दिये गये। सिविल सरकारी अफसरोंको भी चेतावनी दी गयी और आखीरमें.....वाइसरायने एक विश्वित जारी की जिसमें सरकार द्वारा इस घटनापर क्षोभ और ग्लानि प्रकट की। "

१. 'इंडिया अंडर रिपन', पु० २६३.

२. मॉरीसन—इम्पीरियल रूल इन इण्डिया पृ० २७-२९ ३. वही पुस्तक, पृ० २९

४. रोनाल्डरो—दि लाइफ आफ लार्ड कर्जन, जिल्द दो, पृ० ७२

लार्ड कर्जनने अदालतों द्वारा हत्यारोंको सजा न मिलनेपर वड़ा आश्चर्य प्रकट किया। ऐसी ही एक घटनाका जिक जिसमें दो भारतीयोंकी हत्या हुई थी, भारत-सिवचसे करते हुए उन्होंने लिखा था "में नहीं कह सकता कि आप इन घटनाओंके वारेमें क्या सोचते हैं परन्तु मेरे दिलमें इनसे सख्त चोट लगती है।" परन्तु कर्जन भी अपने देश-वासियोंके नैतिक स्तरको उठानेमें असमर्थ रहा। सन् १९०२ में, नवीं लांसर्स (सियालकोट) नामक एक फौजी रेजिमेंटके दो फौजियोंने एक देशी वावर्चीको केवल इस अपराधपर कि वह "उनकी कामवासनाको तृप्तिके लिए औरत नहीं ला सका", इतना पीटा कि वह मर गया। फौजी अधिकारियोंने इसपर कोई काररवाई नहीं की। जब कर्जनको इस घटनाका पता लगा तो उसने जाँचका हुक्म दिया परन्तु अपराधियोंको विशेष सजा न मिली। कुछ अनुशासनकी काररवाई करके मामला खत्म कर दिया गया।

जव पंजावमें राजनीतिक वातावरण अशान्त था तो लाहोरके ऑंग्ल-भारतीय दैनिक अखबार दी सिविल एण्ड मिलिटरी गजटने अपने कालमोंमें भारतीयोंको जी खोल कर गालियाँ दीं । पढ़े लिखे भारतीयों के लिए "वलवलाते वी० ए०" "वर्णसंदर वी० ए०" "गुलाम" "धुड्सवार भिखारी" "दास जाति", "कलंको जाति" जैसे अपराव्दोंका व्यवहार किया गया! जब इस शर्मनाक बातका ध्यान नायव गवर्नरको दिलाया गया तो उसने "लेखोंके लहजेपर अफसोस जाहिर किया परन्त उनपर कोई काररवाई करनेसे इन्कार कर दिया"। ऑंग्ल-भारतीय अखवारोंको गाली देनेकी पूरी छूट थी, जब कि इससे बहुत हलके कस्रोंपर हिन्दोस्तानी सम्पादकोंको कैदकी सजा हो जाती थी। ऑग्ल-भारतीय अखवारोंने हत्याएँ करनेके लिए उकसाया परन्तु कान्तने इसका ख्याल न किया। कलकत्तेसे निकलनेवाले अखवार 'ऐशियन'का एक नमृना देखिये। एक वदनाम मैजिस्ट्रेट किंग्जफोर्ड एक क्रान्ति-कारीकी गोलीसे वच गया और दो यूरोपीय महिलाओंकी उसी गोलीसे मृत्य हो गयी। इसपर उक्त अखवारने लिखा—"मिस्टर किंग्जफोर्डको अव अच्छा अवसर मिला है। हमारा विचार है कि नजदीकसे उनका निशाना कभी नहीं चूकेगा। हम उन्हें सलाह देते हैं कि वे माउजर पिस्तौलका इस्तेमाल करें......हम आशा करते हैं कि मिस्टर किंग्जफोर्ड मन भरकर शिकार करनेमें कामवाव होंगे। हमें उनके इस अवसर पानेपर ईर्घ्या होती है। उन्हें हर अपने या अपने मकानके पास आनेवालेको मार डाल्नेका पूरा-पूरा हक हासिल है। और उनकी अपनी भलाईके लिये हम विस्वास रखते हैं कि विना कोटकी जैवसे पिस्तौल निकाले ही वह सीधा निशाना लगानेमें क्षमता रखते हैं।"

परन्तु कर्जनने भारतकी सबसे अधिक वेइज्जती की। कलकत्ता विश्वविद्यालयमें ११ परवरी १९०५ को दीक्षान्त भाषण करते हुए कर्जनने कहा "निस्संदेह पश्चिमके नीति-शास्त्रमें सञ्चाईका प्रमुख महत्व हो चुका था; जब पूर्वने इसको बहुत बादमें अपनाया। यहाँ तो चालाकी और दाँव पेंच ही सदा आदर पाते रहे हैं।" इस भाषणकी प्रतिक्रिया-स्वरूप वंगालके नौजवान आतंकवादी वन गये। देशभरमें क्रोधकी लहर फैल गयी। अखवारों में इसके जवाव लिखे गये और इसके विरोधमें खान-खानपर सभाएँ हुई।

१. वहीं पुस्तक, पृ० २४४

२. नेविंसन-दी न्यू स्पिरिट इन इण्डिया ए॰ २२९

पाँचवाँ अध्याय

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

कुछ समयसे भारतीय नेता सोच रहे थे कि देशमें एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था संघटित की जाय । भविशेषकर १८७७ के दिल्ली दरवारके वक्तसे लोगोंके दिमागमें यह विचार उठने लगा था । सुरेन्द्रनाथ वनजाँ, जमशेदजी जीजीभाई, विश्वनाथ माण्डलिक, मंगलदास नाय्भाई, नौरोजी फरइनजी जैसे लोग जव कभी आपसमें मिलते, तय वे एक दूसरेंसे कहते—"अगर निरंकुश बाइसरायकी शान-शौकत बढ़ानेके लिए राजों-महाराजोंको एक तमाशा खड़ा करनेके लिए वाध्य किया जा सकता है, तो क्या जनताको संघटित कर वैधानिक उपायों द्वारा निरंकुश शासनकी मावनाको रोका नहीं जा सकता ?"

पर जनताको संघटित करनेमें एक न एक वाधा आती रही। तभी, इलवर्ट विल आन्दोलनने भारतीय राजनीतिकी गति तेज कर दी। आखिरकार सन् १८८३ में एक अखिल भारतीय संस्था वनानेका विचार कार्यरूपमें परिणत हो गया और कलकत्तेमें भारतीय राष्ट्रीय कानफरेंस हुई। इसमें विभिन्न स्वांके प्रतिनिधियोंने भाग लिया। अध्यक्ष आनन्दमोहन यसुने कहा—"राष्ट्रीय पालमेण्टके रास्तेकी पहली मंजिल हमने इस सम्मेलन द्वारा पार कर ली। इस सम्मेलनकी समरणीय वात सुरेन्द्रनाथ वनजीं द्वारा की गयी—संभावित (कवेनेण्टेड) सिविल सर्विसोंको तीव आलोचना थी। उनके भाषणके सम्बन्धमें विलक्षीड ब्लण्टने कहा— "मैंने अपने जीवनमें जो अच्छे-अच्छे भाषण सुने हैं, उनमेंसे एक यह था।" कानफरेन्समें तड़क-भड़कवाले कोई प्रस्ताव पास नहीं हुए।

लगभग इसी समय हूं मके दिलमें भी ऐसी संस्था बनानेके विचार उठे थे। वे एक राष्ट्रीय संस्था संघटित करनेमें लग गये जो जनताकी मानसिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक भलाई करनेका काम करे। भार्च सन् १८८३ में कलकत्ता विश्वविद्यालयके ग्रेजुएटों को एक गरती चिट्ठी भेजकर उन्होंने कामकी ग्रुक्तात की। वे चाहते थे कि इन ग्रेजुएटों में कमसे कम ५० ऐसे संस्थापक सदस्य निकल आवें जो राष्ट्रीयताके लहलहाते वृक्षके बीजका काम दे सकें। इस गरती चिट्टीमें ह्यूमने लिखा था— 'विद देशके सार, आप पर्नेलिखं लोगों में भी पचास ऐसे व्यक्ति नहीं निकलते जिनमें स्थागकी समुचित शक्ति हो, जिन्हें देशके लिए समुचित प्रेम और गर्थ हो, जिनमें इतनी सची, आत्मत्यागमूलक देशभिक्त हो कि देशको शेष जीवन अर्पण कर सकें, तो फिर भारतके लिए कोई आशा नहीं है। भारतमाताके पुत्र विदेशी शासकके हाथों में कटपुतली ही बने रहेंगे और बने रहना चाहिये… अगर आप अपने और अपने देशके लिए अविक स्वाधीनता, अधिक निष्पक्ष प्रशासन, राजकाजमें अधिक हिस्सा पानेके लिए जमकर संघर्ष नहीं कर सकते तो हम आपके मित्र गलत सावित होंगे और हमारे प्रतिद्वन्द्वी सही।" !!

इस अपीलकी देशके हर हिस्सेमें वड़ी ही उत्साहवर्षक और अनुकृल प्रतिक्रिया हुई १. ए. सी. मजूमदार इण्डियन नेशनल एवोल्यृशन, ए० ३३ और शीघ्र ही 'इण्डियन नेशनल यूनियन' नामक संस्थाका जन्म हुआ। यूनियनकी पहली वैठककी रिपोर्टके इस उद्धरणसे उसके लक्ष्य और उद्देशोंपर काफी प्रकाश पड़ता है— "यूनियनका जितना संघटन हुआ है, उसमें यह सर्वसम्मत भावना माल्स्म पड़ती है कि इस संस्थाका मूल मन्त्र ब्रिटश ताजके प्रति अट्ट श्रद्धा है। जब जरूरत पड़े, यूनियन सभी वैधानिक तरीके काममें लाकर उन सभी बड़े छोटे अफसरोंका विरोध करनेको तैयार रहेगी जो ब्रिटिश पार्लमेण्ट द्वारा भारतके शासनके लिए नियत और ब्रिटिशताज द्वारा अनुमोदित सिद्धान्तोंके विरुद्ध काम करते हैं, या उन सिद्धान्तोंको लागू नहीं करते। किन्तु साथ ही, यूनियनका विश्वास है कि भारतका ब्रिटेनसे सम्बन्ध भारतके राष्ट्रीय विकासके लिए अत्या-वश्यक है। कमसे कम इतनो अवधितकके लिए तो आवश्यक है ही जितनी राजनीतिक दिष्टिसे देखी जा सकती है।" यूनियनकी सदस्यताके लिए आवश्यक शतोंमें थीं—सार्व-जितक और वैयक्तिक जीवनमें सदा ईमानदारीका व्यवहार, भारतीय जनताके भौतिक, नैतिक, राजनीतिक और वौद्धिक स्तरको ऊँचा उठानेकी लगन, प्रखर बुद्धि जो शिक्षासे विकसित हुई हो, आवश्यकता पड़ने पर जनहित और परमार्थके कामोंमें स्वार्थ और व्यक्तिगत तिक सित कुई हो, आवश्यकता पड़ने पर जनहित और परमार्थके कामोंमें स्वार्थ और व्यक्तिगत हितोंको कुरवानीके लिए तत्परता और चिरावती स्वतन्त्रता व विवेककी गम्मीरता।

प्रित ऐसा संघटन वनानेके लिए जो सभी सदस्योंको सबसे अधिक प्रिय हो सके' यूनियनके सदस्योंका एक सम्मेलन पूनामें विचार-विमर्शके लिए बुलाया गया। कराची, अहमदाबाद, सूरत, वम्बई, पूना, मद्रास, कलकत्ता, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा व लाहौरमें स्थानीय समितियाँ बनीं और इन्होंने पूना सम्मेलनमें शामिल होनेके अश्वासन मेजे। यह सुझाव भी आया कि यूनियनकी केन्द्रीय समिति बननेके पहले एक जनरल सेकेटरी चुना जाय जो जगह जगह जाकर सम्मेलनके कार्यका निरीक्षण कर सके, विभिन्न स्थानीय समितियोंके अनुभव एक दूसरेको बता सके और यूनियनके कामका आम तौरपर निरीक्षण कर सके √ह्यूम पहले जनरल सेकेटरी बने।

एक राष्ट्रीय संस्थाके संघटनकी तैयारियाँ पूरी करके, ह्यूम इंगलैण्ड गये ताकि मित्रोंसे मन्त्रणा कर सकें कि भारतीय मसलों और आकांक्षाओं में ब्रिटिश जनता और पार्लमेण्टको दिलचस्पी दिलाने के क्या तरीके हो सकते हैं १ वहाँ उन्होंने सबसे पहले गैरसरकारी भारतीय समाचारों के ब्रिटिश पत्रों में प्रकाशनका उचित प्रवन्ध किया। रायटर के तारों से ही खबरें इगलेंड पहुँचती थीं और आम शिकायत यह थी कि रायटर के तार भारतीय दृष्टिकोणको ठीक तरहसे पेश नहीं करते तथा उनमें हमेशा एक सरकारी रंग रहता है। ह्यूमने भारतीय 'टेली ग्राफ यूनियन'का संघटन किया। इसका काम यह था कि महत्वपूर्ण भारतीय मसलोंपर ब्रिटेन के ऐसे पत्रों को तार भेजना जो उन्हें प्रकाशित करें। उन्होंने विभिन्न पत्रों के सम्पादकों से वातचीत की और लगभग पौन दर्जन समाचारपत्र (जिनमें मैंचेस्टर गार्जियन जैसे प्रमुख पत्र भी थे) इस यूनियन से आयीं खबरें छापने को तैयार हो गये। लेकिन पैसेकी कमीसे यह यूनियन चल नहीं सकी।

ह्यमने ब्रिटिश राजनीतिक जगतके प्रमुख लोगोंसे भी पूछा कि पार्लमेण्टके सदस्योंको भारतीय मामलोंमें दिलचस्पी कैसे दिलायी जाय। ब्रिटेनमें तब हालमें ही आम चुनाव होने-वाले थे। पार्लमेण्टके एक सदस्य रोड (वादमें लार्ड लोर बने) ने ह्यूमको एक पत्र लिखकर

१, वेड्रवर्न-एलन् ऑक्ट्रेवियन सूम, पृष्ठ ५२

सुझाव दिया कि हर निर्वाचन क्षेत्रके दो तीन मतदाता अपने उम्मीदवारींसे वादा करा है कि वे भारतीय मसलींमें दिलचस्पी होंगे। इन वादोंको अखवारींमें छपवा दिया जाय। रीडका विस्वास था कि इतना आसान वादा सभी उम्मीदवार कर देंगे, उनमेंसे दस फीसदी इस वादे को पूरा भी करेंगे और इस प्रकार भारतीय मसलोंपर होनेवाले विवादोंके समय पार्लमेंटमें श्रोता तो मिलने लगेंगे। अखवारोंमें उनके वादे छप जानेके कारण वे उन्हें तोड़नेमें भी हिचकंगे। ह्युमका काम था हर निर्वाचन क्षेत्रमें ऐसे मतदाता इकड़े करना जो उम्मीदवारोंसे ये वादे ले सकें। ह्यूमने यह काम शुरू भी किया, पर उन्हें इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली।

वैधानिक राजनीतिकी एक अखिल भारतीय संस्था वनानेकी किटन समस्याके लिए हामको प्रेरणा किससे मिली और उसके दिमागमें यह वात ऐसे घर क्यों कर गयी यह जान ने के लिए हामके जीवनपर दृष्टिपात करना होगा। हामके पिता देशमक्त और सुधारक थे; वे वारह वर्षतक ईस्टइण्डिया कम्पनीमें थे और उसके वाद पार्लमेंटके सदस्य हो गये थे। ३० वर्षतक वे पार्लमेंटके उप्रदल्के नेता गिने जाते रहे। हाम स्वयं कम्पनीकी नौकरीमें आये। पिताके वहुतसे गुण उनमें थे। वे उन इने-गिने अंग्रेजोंमें थे जो भारतमें अंग्रेजी राज कायम तो जरूर रखना चाहते थे, पर साथ ही यह भी चाहते थे कि यह राज भारतीयोंकी भलाईमें दत्तचित्त हो। सन् ५७ के विद्रोहके नौ वर्ष पहले वे वंगाल सिविल सर्विसमें भरती हुए थे। २६ वर्षकी अवस्थामें वे इटावा जिलेके सबसे यहे हाकिम हो गये थे। इटावेका क्षेत्रफल १६९३ वर्गमील था, जनसंख्या ७ लाख २२ हाजार थी और मालगुजारी १ लाख ३६॥ हजार पोंड थी। जब विद्रोह हुआ वे इटावेमें ही थे। इटावा भी दूसरे जिलोंकी तरह भारतीयोंके अधिकारमें आया। हामने इटावा खाली करने और वादमें फिर उसपर अधिकार करनेमें वड़े साहसका परिचय दिया।

इटावेके हाकिमकी हैिलयत है हुमने वहाँकी जनताकी शिक्षा और मलाईमें वही दिलचस्पी ली। आवकारी होनेवाली आमदनीको वे "पापको कमाई" कहते थे। जब साल-वसाल जिलेकी यह आमदनी वहती गयी, उन्होंने अपने ऊँचे हाकिमोंकों लिखा— "अमृत्पूर्व गरीवी और मुसीवतको देखते हुए, हालका वन्दोवस्त आर्थिक हिएसे वहुत सफल माना जा सकता है। लेकिन मुझे आवकारी होनेवाली आयमें वृद्धिका दुःख है। प्रति वर्ष में इस पापी व्यवस्थाका असफल विरोध करता हूँ कि जिसमें पहले ऐसे लोगोंका एक वड़ा वर्ग पैदा हुआ और अब जिसमें वह वर्ग पलता-पनपता है जिनका जीवनमें एकमात्र ध्येय यह है कि अपने साथियोंको शरावी और उसके अनिवार्य निष्कर्प रूपमें दुराचारी व अपराधी बनायें। दुर्गायवद्य, ये लल्जानेवाल वरावर सफल होते रहते हैं, हर साल शरावियों की संख्या और शरावकी खपत बढ़ती जाती है। पिछले २० वर्ष शराविशों कितने भयंकर रूपसे बढ़ गयी है, यह उन्होंको माल्म हो सकता है जो मेरी तरह देशी समाजकी गतिविधि जाननेकी फिक्र करते हैं ! और, हम अपनी प्रजाको तो पापाचारमें प्रवृत्त करते हैं, पर उनके विनाशसे हमें कोई आर्थिक लाम नहीं होता। पापकी इस कमाईके संवन्धमें पुरानी कहावत चरितार्थ होती है कि पापसे इकट्ठी दोलत फलती नहीं। आवकारीसे अगर एक रुपयेकी आमदनी होती है तो तजनित अपराधों के दमनमें सरकारको दो रुपये वर्श करने पढ़ जाते हैं।"

अपने सिद्धान्तों और विचारोंके लिए स्मिको दण्ड भोगना पड़ा । उनकी पदअवनित

१. वही पुस्तक पृष्ट २०-२९

हुई और दूसरे कम-उम्र अफसरोंको उनके पहले तरको दी गयी। लेकिन ब्रिटिश ताजकी निष्ठावान् प्रजाकी हैसियतसे ह्यूमको भारतमें अंग्रेजी राजके लिए खतरा नजर आया और वे भारत और ब्रिटेन दोनों देशोंकी, अपने ढंगसे, सेवा करनेमें लगे रहे।

भारतीय राजनीतिमें तब दो मुख्य विचारधाराएँ थीं। एक मतके लोग हिंसा द्वारा अंग्रेजी राजका अन्त कर देना चाहते थे। दूसरे मतके लोग अंग्रेजी राजका अन्त नहीं चाहते थे। वे सिर्फ भारतीय शासनमें भारतीय प्रतिनिधित्व चाहते थे जो वढ़ते वढ़ते इतना वढ़ जाय कि ब्रिटिश ताजके अन्तर्गत भारत स्वशासन प्राप्त कर है। ह्यूमको मिले प्रमाणींसे और वादके किसान विद्रोहोंसे स्पष्ट है कि हिंसात्मक शक्तियोंने कई बार सुदृढ़ संघटन बनाकर त्रिटिश शासनपर चोट करनेकी तैयारी की। पढ़े-लिखे लोगोंकी वैधानिक राजनीति मामूली वात थी और सरकार भी उससे विचलित नहीं थी। ईएनने किसी हद तक विद्रोहकी तलवारको कुण्टित कर दिया था और क्रान्तिकारियोंका बढ़ाव रोक दिया था। पर यह े प्रत्यक्ष था कि यह ज्ञान्ति अस्थायी है। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मुट्ठी भर लोग ही वैधानिक राजनीतिकी प्रगतिसे परिचित थे और उनका प्रभाव भी शहरोंके थोडेसे लोगोंतक सीमित था । लेकिन हिंसात्मक शक्तियोंका एक देशव्यापी संघटित जाल अंग्रोजी सत्ताके अस्तित्वको चुनौती दे रहा था । ये शक्तियाँ जनतासे अपील करती थीं, उसे सुखमय भविष्यका आद्यासन दिलाती थीं और जनता उनका विश्वास करती थी। उनका आश्वासन था कि अंग्रेजी राजका तख्ता पलट दिया जायगा और देशमें फिर एक वार समृद्धि आ जायगी। अपनी . अवस्था सुधारनेके लिए जनता और शिक्षित वर्ग हिंसा और विद्रोहसे खींचकर किस प्रकार वैधानिक राजनीतिमें लगाये जायँ, ह्यमकी वही समस्या थी। इस समस्याका इल यही था कि एक ऐसी सहढ अखिल भारतीय संस्था वनायी जाय जिसे जनता अपनी प्रतिनिधि संस्था मानने लगे और जिसका अस्तित्व लोगोंको भरोसा दिलाये। इससे यह संस्था जोर पकड़ती जायगी और जनता हिंसासे विस्त होकर इसी संस्थाकी ओर आकृष्ट होगी।

रिपनके उत्तराधिकारी लार्ड डफरिन भी ऐसी संस्था चाहते थे जो जनताकी भावनाओं को वैधानिक ढंगसे पेश कर सके । हा मकी जीवनीके लेखकके अनुसार "हा म स्वयं अपना सुधार प्रचार सामाजिक स्तरसे शुरू करना चाहते थे, पर लार्ड डफरिनकी सलाहसे उन्होंने — राजनीतिक संघटनको प्राथमिकता दी । लगता है कि लार्ड डफरिनने उनसे कहा था कि शासनाध्यक्षकी हैसियतसे मुझे जनताकी सच्ची इच्छाएँ जाननेमें वड़ी. कठिनाई होती है, और शासनकी दृष्टिसे, एक ऐसे उत्तरदायी संघटनकी स्थापना जनतेवाका काम होगा जिससे सरकार भारतीय जनमतके सम्बन्धमें जानकारी करती रह सके।"

्कांग्रेसके प्रथम अन्यक्ष उन्लू. सी. वनजींने अपनी पुस्तक 'इण्ट्रोडक्शन टु इण्डियन पौलिटिक्स' (भारतीय राजनीतिकी भूमिका) में (जो सन् १८९८में छपी थी) ह्यू म-डफ-रिन मन्त्रणांके सम्बन्धमें और भी स्पष्ट रूपसे लिखा था कि 'सम्भवतः बहुतसे लोगोंके लिए यह नयी खबर होगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस—जैसी वह बनी और जैसे वह चल रही है, असलमें लई डफरिनकी कृति है, जिसे उन्होंने अपने गवर्नर-जनरल रहनेके समयमें बनाया।' उनका सुझाव था कि भारतीय राजनीतिक नेता हर वर्ष एकत्र होकर सरकारको वताया करें कि शासन कहाँ दोषपूर्ण है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। उनका यह भी कहना

१. वेढरवर्न, ए० ऑ० ह्यूम ए० ५९-६०

था कि ऐसे सम्मेल्नोंमें गवर्नरको सभापित न बनाया जाय क्योंकि गवर्नरकी उपस्थितिमें लोग सम्भवतः खुलकर वार्ते न कर सकें। ह्यूम डफरिनके तकोंसे प्रभावित हुए और जव उन्होंने कलकत्ता, वम्बई, मद्रास आदिके राजनीतिज्ञोंके समक्ष अपनी व डफरिन दोनोंकी योजनाएँ रखीं तब सर्वसम्मितिसे डफरिनकी योजना स्वीकार कर ली गयी और उसीको कार्यान्वित किया जाने लगा। डफरिनने ह्यूमसे वादा करा लिया था कि जवतक में भारतमें हूँ, मेरा नाम इस सिलसिलेमें न लिया जाय। यह वादा पूरा हुआ। जिनसे ह्यूमने सलाइ मद्यविरा किया, उन्हें छोड़कर और किसीको इस वातका पता भी नहीं चला।

कांग्रेसके जन्मकी कथा इस विवरणके साथ ही एण्डूज व मुकर्जिके इस कथनको पढ़ लेनेसे स्पष्ट हो जायगी कि ह्यू मने "समझ लिया या कि जनताके दुख दूर करनेके लिए भारत सरकारको प्रेरित करना असम्भव ही है। आत्मतृष्टिके वातावरणमें मुपुनसे हाकिम अपनी मानसिक शान्ति मंग नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सन् १५७ में विद्रोहका दमन कर दिया था और इससे उनमें सुरक्षाकी मावना व्यात थी। इतिहासकी पुनरावृत्ति वढ़े विलक्षण ढंगसे होती है; क्योंकि सन् ५७ में जिस तरह हाकिम जनमत और जनभावनासे अनिभन्न थे, विद्कुल उसी प्रकार अव थे। यह सन्तोपकी भावना ह्यू मकी सबसे वड़ी किटनाई थी। वे हार कर शिमला गये और वहाँ सर्वोच्च अधिकारियोंको वताया कि परिस्थिति किस प्रकार विस्कोटक हो रही थी। सम्भव है, ह्यू मकी इस यात्राने वाइसरायको जो कुशल शासक और चतुर व्यक्ति थे स्थितिकी गम्भीरताका परिचय करा दिया हो और उन्होंने ह्यू मको कांग्रेसकी स्थापनाकी प्रेरणा दी हो। जैसा कि विदित्त है, अखिल भारतीय आन्दोल्लनके लिए समय विलक्कल परिषक था। शिक्षित वर्गर्की सहानुम्ति व सहायता प्राप्त किसान विद्रोहके स्थानपर नयी विकासमान शक्तियोंको एक राष्ट्रीय मन्त्र मिल गया।"

इस परिस्थितिमें, विशेष कर जब शिक्षित भारतीय वैधानिक आग्दोलन द्वारा भारत-की राजनीतिक प्रगतिमें व्यस्त थे, ह्यू मकी यो जुएटोंको भेजी गर्या गरती चिट्टी कुछ अनोखी लगेगी । उसका एक चाक्य था— यदि देशके सार, आप पड़े-लिखे लोगोंमें भी पचास ऐसे व्यक्ति नहीं निकलते, जिनमें त्यागकी समुचित शक्ति हो, जिन्हें देशके लिए समुचित प्रेम और गर्व हो, जिनमें इतनी सची, आत्मत्यागमूलक देशभक्ति हो कि शेष जीवन देशको अपित कर सकें, तो फिर भारतके लिए कोई आशा नहीं है।

भारतीय राजनीतिक रंगमंत्र खाली नहीं था । देशकी उत्रतिकी लगन लगाये सेकड़ों देशमक उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे थे । जैसा कि ऊपर कहा जा जुका है । हुल्यूट जिल्ल विरोधी आन्दोलनसे भारतीयों में एक चेतना आ गयी थी और एक अखिल भारतीय संघटनका विचार सबके हृदयों में घर कर चुका था । महासमें सन् १८७८ में स्थापित अंग्रेजी हैनिक 'दि हिन्दू' ने राजनीतिक चेतना जगायी थी और ६ साल बाद सन् १८८४ में महास महाजन सभाका जन्म हो चुका था । शुरुआत कुछ सरकारी नौकरोंके एक छोटेसे सम्मेलनसे हुई जिसमें महास नेटिब एसोसियेशन बनाना तय हुआ । फिर आनन्द चारत्र, वीरराववाचार्य, रंगैयानायडू, जी० सुब्रह्मण्य ऐयर और एन० सुब्बाराड आदि प्रमुख लोगोंने 'दि हिन्दू' की स्थापना की । महास महाजन सभाको भी इन्हीं लोगोंने जन्म दिया । पश्चिममें सन् १८७० में ही पूना सार्वजनिक सभा संघटित हो चुकी थी । यह रानाडे और गणेशदक्त

१. दि राइन एण्ड योथ भाव दि केंग्रिस-१ए १२८-९

जोशीकी अगुआईमें चल रही थी। राव वहादुर कृष्णजी लक्ष्मण नूलकर, सीताराम हरि चिपल्णकर जैसे पमुख व्यक्ति इसमें शामिल थे। सभा एक त्रैमासिक पत्रिका पाठकोंकी राजनीतिक शिक्षाके लिए निकालती थी। इसमें अधिकांश लेख रानाडेके लिखे होते थे। जेम्स कैलकने लिखा है—"समाने पश्चिमी भारतको जगानेमें बड़ा काम किया; इसने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मसलोंपर जनमन भी बनाया।"

जनवरी सन् १८८५ में वम्बईके प्रेसिडेन्सी एसोसियेशनकी नींव पड़ी । इसके सूत्रधार वदरुद्दीन तैयवजी, फीरोजशाह मेहता, काशीनाथ च्यम्बक तैलंग और ह्यूम थे। वंगालमें सर यतीन्द्रमोहन टैगोरके नेतृत्वमें 'नेशनल लीग' नामक एक नबी संस्थाका जन्म हुआ।

राष्ट्रीय और राजनीतिक जागरणमें समाचारपत्र भी अपना योग दे रहे थे। इन पत्रोंमें प्रमुख थे—इण्डियन मिरर, हिन्दू पेट्रियट, अमृतवाजार पत्रिका, दि वेंगाली, मुम्बई समाचार, सोमप्रकाश, मुलभ समाचार, सकल्य प्रकाश, मराठी सुवोधिका पत्रिका, गुजराती द्रपतरदुम और दि हिन्दू।

अदालतको मानहानिके अभिमोगमें सुरेन्द्रनाथ वनर्जीको मिली कैदकी सजासे एक और जोश पैदा हुआ । उनकी रिहाईपर सभाओं, जुल्सों और मानपत्रोंको धूम मच गयी। जहाँ भी वे भाषण करने जाते छात्रोंसे पूछते—तुममेंसे कौन गेरीवाल्डी और मेजिनी वनना चाहता है ? और उत्तरमें सभी कहते—हम, हम सव।

मैस्र रियासतने आगे बढ़कर नेतृत्व प्रदान किया । रियासतके प्रधान मन्त्री दीवान रंगाचारुत्ने सन् १८८१ में प्रतिनिधि असेम्बलीकी स्थापना की । यह असेम्बलीकोई विधायिका या व्यवस्थापिका सभा न थी । यह तो व्यवस्थामें जनसहयोगके लिए एक जनप्रतिनिधि संघटन था । रंगाचारुत्ने क्लार्ककी हैसियतसे जीवन आरम्भ किया था और तरक्की करते-करते वे भारतकी प्रमुख रियासतके, जो क्षेत्रफलमें इंगलैण्डके बरावर थी, दीवान बन गये थे । उन्होंने नौकरशाही मनोवृत्तिसे अपने मस्तिष्कको संकुचित नहीं बनाया था । भारत व बिटेनकी सारो परम्पराओं अध्ययनके बाद उन्होंने यह तरीका निकाला था जिससे जनता किसी हदतक शासन-व्यवस्थाके सञ्चे सम्पर्कमें आ पाती। रे

दिसम्बर सन् १८८३ में, थियोमोफिकल सोसायटीके वार्षिक सम्मेलनके बाद दीवान वहादुर रवुनाथ रावने अपने मित्रोंकी एक विशेष वैठक वुलायी, जिसका उद्देश्य था भविष्यमें भारतको स्वराज्यके मार्गपर ले चलनेके लिए शासन व्यवस्थामें सुधार करनेके हेतु राजनीतिक आन्दोलन चलाना और इसके लिए देशके सभी राजनीतिज्ञोंके एकत्र करनेके उपयोगपर विचार करना।

दिसम्बर सन् १८८४ में, विश्ववन्युत्व' और थियोसोफिकल सोसायटीके उद्देशोंकी पूर्तिके लिए आद्यार, मद्रासमें वार्षिक सम्मेलन हुआ, जिसमें अनेक वक्ताओंने सुझाव रखा कि यह सम्मेलन ही भविष्यकी भारतीय पार्लमेण्टका केन्द्र हो। इस सम्मेलनमें भाग लेनेवालों में ह्यूम, जानकीनाथ घोपाल और इण्डियन मिरर सम्पादक नरेन्द्रनाथसेन भी थे। ह्यूम सोसायटी के उत्साही सदस्य थे और उसके सम्मेलनोंमें वरावर भाग लेते थे। सन् १८८४ के सम्मेलनमें जिन प्रतिनिधियोंने भाग लिया था वे नरेन्द्रनाथ सेनके शब्दोंमें 'समाजिक और वौद्धिक दृष्टिसे

१. महादेव गोविन्द रानाडे, पृष्ठ २५

२. के, टी, पौल-दि ब्रिटिश कनेक्शन विथ इण्डिया ए० ७५

समाजके नेता होने योग्य थे !' इनमें छु छ वादमें मद्रासमें दीवान वहादुर राववेन्द्ररावके निवास-स्थानपर एक इए और 'भारतमाताकी रक्षा' के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन चलानेका विचार पुष्ट किया । उन्होंने आट सदस्योंकी एक समिति बनायी जो इस विचारको कार्यक्रपमें परिणत करनेवाली थी । इस समितिमें नरेन्द्रनाथसेनके आंतरिक्त जानकीनाथ घोपाल, दीवान रघुनाथराव, एस सुब्रह्मण्य ऐयर (जो वादमें मद्रासके चीफ जिस्टस हुए) भी थे । सिमितिने हर प्रान्तके प्रमुख व्यक्तियोंको अखिल भारतीय संस्थाकी आवश्यकता वताते हुए पत्र लिखे । इस प्रस्तावका बहुतसे लोगोंने स्वागत किया ।

लेकिन इस विचारको कार्यान्वित करनेमें एक वाधा यह समझी गयी कि इस कार्यसे अप्रत्यक्ष रूपसे थियोसोफिकल सोसायटीका नाम जुड़ गया था। सोसायटीकी प्रधान मैडम ब्लावाट्स्की रूसी थीं और उस समय रूस व इंगलैण्डमें अनवन थी। हा,मने सोचा कि किसी भी ऐसे राजनीतिक सम्मेलनको अधिकारी संशयकी दृष्टिसे देखेंगे और उसके विरुद्ध हो जावँगे जिसमें थियोसोफिस्टोंका प्राधान्य होगा।

इस कठिनाईका हल अपने आप सामने आ गया ILसन् १८८४ में लार्ड डफरिन भारत आये और वे स्वयं अंग्रेजी शासनके लिए एक ऐसे उपायकी खोजमें थे, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, जिससे जनताका असन्तोष दूसरे रास्ते निकल जाय। समय रहते ही ह्यू म उनसे मिले। दोनोंकी राय हुई कि एक राजनीतिक सम्मेलनकी स्थापना हो और यह तय पाया कि दिसम्बर सन् १८८५ में एक अखिल मारतीय सम्मेलन बुलाया जाय।

इसी बीच, सन् १८८३ की तरहका वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन दिसम्बर सन् १८८५ में कलकत्तेमें हुआ । ह्या झारा आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका बम्बईमें हुआ पहला जलसा और यह सम्मेलन एक ही समय हुए । दोनोंके संयोजकोंको एक दूसरेके सम्मेलनोंका तबतक पता न चला जबतक दोनों सम्मेलन हो न लिये।

कलकत्तेके राष्ट्रीय सम्मेलनकी संयोजक कई संस्थाएँ थीं—यथा, ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशन, इण्डियन एसोसियेशन, नेशनल लीग, सेण्ट्रल मुहेमडन एसोसियेशन (जिसकी स्थापना मुसलमानोंकी राजनीतिक संस्थाके रूपमें हालहीमें कलकत्तेमें हुई थी) । ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशनके दपतरमें २५, २६ व २७ दिसम्बरको यह सम्मेलन हुआ । इसमें गंगाल, आसाम, वम्बई, विहार पिक्समोत्तर सीमाप्रान्त और उड़ीसाके लगभग २०० प्रांतिनिधियोंने भाग लिया । ये प्रतिनिधि अपने अपने प्रान्तके वहे जमीदार, उद्योगपित आदि समृद वर्गोंके थे । हाकिमोंमें नेपालके राजदूत और वंगाल सिविल सर्विसके एच. ने. एस. कॉटन थे । मुस्लिम कुलीन वर्गका प्रतिनिधित्व अमीर अली कर रहे थे । पहले दिनकी वैठकका सभापितत्व श्री दुर्गावरण लालने किया, दूसरे दिनका जयकृष्ण मुखर्जीने और तीसरे दिनका महाराजा नरेन्द्रकृष्णने ।

पम्मेलनमें छः प्रस्ताव स्वीकार किये गये जिनके द्वारा विधायिका कींसिलींके पुनर्गटन, शस्त्र कानूनमें संशोधन, सरकारी खर्चमें कमी, सिवल सर्विसकी भारत व इंगलेण्ड दोनों जगह परीक्षा और उम्रकी केंद्र कम करने, न्याय व प्रशासनके पृथक करने और पुलिसके पुनर्गटनकी माँगें की गयी थीं । पहला प्रस्ताव सुरेन्द्रनाथ वनजींने पेश किया था । इसका समर्थन करते हुए कॉटनने कहा—'सरकारी नौकरियों और उनके बाहर भारतमें भी, मेरे स्वालमें ऐसे बहुत लोग न मिलेंगे जो विधायिका कींसिलींके पुनर्गठनका विरोध करते हीं और मुझे विश्वास है कि इंगलेण्डमें सभी उदार राजनीतिज्ञ इसी मतके हैं।'

ए॰ सी॰ मज्मदारके अनुसार कलकत्ता सम्मेलनने कांग्रेसके जन्मका हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने लिखा—"कलकत्ता सम्मेलन पूरी तरह सफल रहा। आखिरी दिन यह खतर मिलनेपर कि अगले दिनसे वम्बईमें पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका जलसा ग्रुक हो रहा है, सभी खुश हो उटे, और सम्मेलनकी ओरसे बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय संघटनके जन्मका स्वागत करते हुए ग्रुभकामनाका एक सन्देश वहाँ भेजा गया।" ह्यूमकी भाँति काँटन भी बढ़ते हुए भारतीय असन्तोपसे अवगत थे और उच्चाधिकारियोंसे उन्होंने सिफारिश की थी कि पढ़े लिखे भारतीयोंको विश्वासभाजन बनाया जाय।

जनमतक अनेक नेता अपने-अपने ढंगसे एक अखिल भारतीय राजनीतिक संघटन वनानेके लिए प्रयत्नशील थे, लेकिन ह्यूमने यह- काम वहे पैमानेपर शुक्त किया। दूसरे उन्हें वाइसरायका विश्वास प्राप्त था, इसलिए वे तेजीसे अपना काम आगे वढ़ानेमें स्वतन्त्र थे। उन्होंने धार्मिक उत्साइसे काम किया और एक ओर जहाँ उन्होंने भारतको उसकी सबसे वड़ी राजनीतिक संस्था प्रदान की, वहीं उन्होंने अपने देश ब्रिटेनका भी हित साधा; क्योंकि उन्होंने भारतीय असन्तोषकी वाढ़ बाँध बाँधकर रोक ली, नहीं तो इस वाढ़से अंग्रेजी राज्यके वह जानेका खतरा था। उनका काम परमार्थसेवाका प्रशंसनीय उदाहरण था। अदूरदर्शी अंग्रेज अफसर उन्हें गलत समझते थे, पर वे चुपचाप अपना काम करते रहे और उसी कामसे उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्यको आसन्न संकटसे बचा लिया। और जहाँतक भारतीय पक्षका सम्बन्ध है, ह्यूमकी यह काररवाई उसके विपरीत नहीं पड़ी, क्योंकि वह उसी कामको बढ़े पैमानेपर करते रहे जो वैधानिक ढंगपर चलनेवाले भारतीय स्वयं कर रहे थे। यह कहा जा सकता है कि वे भी सशस्त्र कान्ति द्वारा अंग्रेजोंको भारतसे निकालनेक विरुद्ध थे।

्रेलन्दनमें ६ अगस्त सन् १९१३ के दिन ह्यूम स्मारक सभामें वोलते हुए गोखलेने कहा था कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी स्थापना नहीं कर सकता था। यह बात अगर छोड़ भी दी जाय कि इतने वड़े कामके लिए ह्यूम जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्वकी आवश्यकता थी, अगर किसी भारतीयका ऐसा व्यक्तित्व होता भी और वह यह आन्दोलन चलानेके लिए आगे आं जाता तो हाकिम उसे ऐसी संस्था न बनाने देते। राजनीतिक आन्दोलन उन दिनों ऐसी संशयकी निगाहसे देखे जाते थे कि यदि कांग्रेसका जन्मदाता इतना महान अंग्रेज और प्रमुख गैरसरकारी व्यक्ति न होता तो हुकूमत इस आन्दोलनके दमनके लिए कोई न कोई तरीका हूँ द निकालती।

लेकिन इसमें भी कोई संशय नहीं है कि कांग्रेसके जन्मके समय भारतकी राजनीतिक परिस्थिति अंग्रेजोंके अनुकूल न थी, जो कॉटनके निम्नलिखित वर्णनसे स्पष्ट है—

"जो व्यक्ति विना झिसक दावा करे कि भारतीय जनता अंग्रेज सरकारकी मित्र है, वह अवश्य ही साहसी है। ऊपरके लक्षणों से अवश्य यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय राजाओं महाराजाओं की भिक्त में संशय नहीं है, जो हालके संकटमें आक्रमणके प्रतिरोधके लिए अपनी फीजें सरकारको सौंपनेको तैयार हो गये। साम्राज्यके सबसे शान्तिमय स्वेक समृद्धशाली कुलीन सामन्तोंकी निष्ठामें भी संशय नहीं है, जिन्होंने इसी कामके लिए अपना धन और साधन सरकारको सौंपनेकी इच्छा प्रकट की। एक स्वरसे अपनी भिक्त प्रकट करनेवाले अखवारों और देशरक्षाके लिए अंग्रेजोंके साथ कन्धा भिड़ाकर लड़नेवाले

१. मजूमदार, वही पुस्तक पृष्ठ ६१

स्वयंसेवकोंको भरती करनेवाले नेताओं में भी सरकारके प्रति निष्टा प्रकट होती है। (रूससे आसन युद्धकी ओर यहाँ इक्कित है)। लेकिन में इन प्रकट लक्षणोंसे आश्वस्त हो जाने वाले पाटकोंको सावधान करना चाहता हूँ। उन विभिन्न वर्गोंके हितांपर दृष्टिपात करनेसे इन प्रकट सद्धावनाओं के अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। अपनी फीजें सरकारको सींपनेवाले देशी महाराजे बुद्धिमानीसे काम ले रहे हैं। 'वें जानते हैं कि अव्वल तो इस भेंटके स्वीकार किये जानेकी सम्भावना नहीं है; दूसरे लाई डलहोजीकी रियासतें हृड़प लेनेकी नीतिका यद्यपि व्रिटिश पार्लमेण्ट और ब्रिटिश राष्ट्र दोनोंने खण्डन किया है, पर भारत आये हाकिम उस नीतिका पोषण करते हैं और वरावर देशी राजाओंकी फीजें तोड़ देनेका सुझाव रखते हैं """वेहतर होगा कि इम अंग्रेजी-भापी शिक्षित भारतीय समाजके व्यापक असन्तोप और कटोरताको पूरी तरह समझ लें और अखवारोंकी व अन्य लोगोंकी भक्तिशप्योंको अनावश्यक महत्त्व न दें (जैसा कि दिया जा रहा है)।""

कांग्रेसका जन्म इस प्रकार हुआ-

मार्च सन् १८८५ में एक गृहती चिट्टी मेजी गयी जिसमें कहा गया था कि "इण्डियन नेशनल यूनियनका एक सम्मेलन पूनामें २५ से २१ दिसम्बर तक होगा, जिसमें युंगाल, वम्बई व मद्रास प्रेसीडेंसी स्वोंके सभी भागोंके प्रतिनिधि और अंग्रेजीभाषी प्रमुख राजनीतिज्ञ भाग लेगे।"

इस चिट्ठीमें लिखा था कि इस सम्मेलनका उद्देश राष्ट्रीय प्रगतिके लिए कार्य करनेवाले सभी सच्चे लोगोंका आपसी परिचय होना और अगले वर्षके लिए राजनीतिक कार्यक्रम निश्चित करना है। यह प्रत्यक्ष उद्देश था। चिट्टीमें लिखा था कि अप्रत्यक्ष रूपसे यह सम्मेलन देशी पार्लमेण्टका केन्द्र वन जायगा और टीक तरह चलनेपर यह संस्था कुछ वर्षीं ही उन लोगोंक लिए एक जवानकी काम करने लगेगी जो कहते हैं कि मारत अब भी किसी प्रतिनिधित्वपूर्ण शासनके अयोग्य है। सम्मेलन पूनामें होनेवाला था, पर आखिरी वक्तपर यह स्थान बदलना पडा । यह दिनके ठीक पहले पूनामें हैजेकी कुछ छिटफुट घटनाएँ हुईं और लगो कि महामारी फूट पड़नेवाली है। सम्मेलन दो तीन दिन देरसे-- २८ दिस-म्यरको दोपहर १२ वजेसे वम्बईके गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कालजमें शुरू हुआ । चिट्ठीमें इसे इण्डियन नेशनळ युनियनका जलसा कहा गया था, पर सम्मेलनके कुछ ही दिन पहले ह्यमके सुझावपर इसका नाम वदल दिया गया और वह इंण्डियन नेशनल कांग्रेसका अधिवेशन हो गया । अधिवेदानमें पहले वक्ता स्वयं हा म थे जिन्होंने उमेदाचन्द्र वनजीका नाम सभा-पतित्वके लिए पेश किया । इस प्रस्तावका समर्थन और अनुमोदन सुब्रहाण्य ऐयर और के. टी. तैंहंगने किया। एक अंग्रेज बकीहके हर्ककी हैसियतसे बनर्जी सन् १८६४ में इंगलैण्ड गये थे । सन १८६७ में उन्होंने वैरिस्टरी पास की और वहाँसे लीटकर वैरिस्टरी करने लगे। कलकत्ता हाईकोर्टमं शीव ही उनका नाम चमक उठा और वे सरकारके स्थायी काननी सलाहकार बना लिये गये। उन्हें न्यायाधीश नियक्त करनेका प्रस्ताव तीन बार किया गया पर उन्होंने इनकार कर दिया।

अधिवेशनमें ७२ प्रतिनिधियोंने माग लिया था । इनमें तीन वंगालने, अटारह वस्पर्रने,

१. न्यू इण्डिया, पृष्ट २०, २९, २२

२. एनीवेसेण्ट 'हाऊ इण्डिया फॉट फॉर फ्रीडम', पृष्ट ३

आठ मद्राससे, दो कराचीसे, छः स्रतसे, आठ पूनासे, तीन लखनऊसे, दो आगरासे और एक प्रतिनिध वीरमगाँव, वनारस, शिमला, इलाहावाद, लाहौर, अम्वाला, अहमदावाद, वरहामपुर (मद्रास), मसुलीपइम्, चिंगलीपइम्, तंजौर, कुम्भकोनम्, मदुरा, तिन्नेवली, कोयम्बटोर, सलेम और कुदापुरसे आये थे। शिमलेसे खुद ह्यूम प्रतिनिधि थे। प्रतिनिधियोंमें प्रमुख थे—वनजीं, दादाभाई नौरोजी, नरेन्द्रनाथ सेन, डल्स्यू० एस० आप्टे, अगरकर, गंगाप्रसाद वर्मा, रहीमतुल्ला सायाणी, तेलंग, फीरोजशाह मेहता, दीनशावाचा, वी० एम० मलावारी, एन० जी० चन्दावरकर, रंगैया नायह, सुबहाण्य ऐयर, आनन्द चारल्, वीर राधवाचार्य और केशव पिल्लइ। जिन पत्रोंके सम्पादक अधिवेशनमें शामिल हुए थे वे थे— जानप्रकाश (पूना सार्वजनिक सभाका त्रैमासिक पत्र), नवविभाकर, इण्डियन मिरर, नसीम, हिन्दुस्तानी, दि द्रिल्यून, इण्डियन यूनियन, इंस्पेक्टर इन्दुप्रकाश, हिन्दू व दिक्रेसेण्ट। सर विलियम वेडरवर्न, जिस्टस जार्डाइन, कर्नल फिल्प्स और प्रोफेसर वर्ड सवर्थने प्रतिनिधियोंका हार्दिक स्वागत किया। लगभग हर राजनीतिक संस्थाका प्रतिनिधि कांग्रेसमें था। अपने अध्यक्षीय भाषणमें वनर्जीने कहा—"भारतभूमिमें, इतिहासकी यादमें, ऐसा महत्त्वपूर्ण और विस्तृत प्रतिनिधित्वपूर्ण सम्मेलन नहीं हुआ।"

सम्मेलनको पूर्ण प्रतिनिधित्वपूर्ण घोषित करते हुए आपने कांग्रेसके उद्देश्य इस प्रकार

(अ) साम्राज्यके विभिन्न भागोंमें रहनेवाले भारतके सच्चे सेवकोंमें मित्रता और नैकट्य स्थापित करना,

(व) सभी देशप्रेमियोंमें आपसी मैत्रीपूर्ण वातचीतके द्वारा जाति, धर्म व प्रान्तगत पक्षपातोंको मिटाना और राष्ट्रीय एकताकी उन भावनाओंको विकसित व संघटित करना जिनका जन्म हमारे प्रिय लार्ड रिपनके स्मरणीय राज्यमें हुआ,

(स) देशके अपेक्षतया महत्वपूर्ण और आवश्यक सामयिक सामाजिक प्रश्नोंपर देशके शिक्षित वर्गोंके प्रौढ़ विचारोंपर खुलकर वाद-विवाद करना।

वनजींने दावा किया कि "मुझसे और यहाँ एक न मेरे दोस्तोंसे ज्यादा व्रिटिश सरकार के स्वच्चे हितचिन्तक और पक्के वफादार लोग और कहीं नहीं हैं।" उन्होंने, "भारतकी मलाई के लिए" ग्रेट ब्रिटेनने जो अच्छे काम किये हैं, उनकी प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि ब्रिटेनने हमें सुरक्षा दी, व्यवस्था दी, रेलें दीं और आशीर्वाद सक्त पश्चिमी शिक्षा दी। इसके बाद वनजींने कहा कि भारतीय जनता चाहती है यूरोपमें प्रचलित शासन-सिद्धान्तों के अनुसार ही भारतमें सरकार बने। इस इच्छासे ब्रिटिश सरकार मित उसकी अटूट निष्ठामें कोई व्याघात नहीं होता। वह तो सिर्फ यह चाहती है कि उसे भी शासनमें उचित और वैध प्रतिनिधित्व और भाग मिले और शासनतन्त्र और अधिक व्यापक प्रतिनिधित्व करे।

खुले अधिवेशनमें एक प्रस्ताव स्वीकार कर माँग की गयी कि वर्तमान व सर्वोच विधायिका कोंसिलोंका सुधार और विस्तार हो जिनमें काफी संख्यामें चुने हुए सदस्य हों (और ऐसी ही कोंसिलें पंजाव, अवध व पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तके लिए भी बनायी जायें)। प्रस्तावमें यह भी माँग की गयी थी कि सभी वजट इन कोंसिलोंके विचारार्थ पेश किये जाया करें। सदस्योंको अधिकार प्राप्त हो कि वे शासनकी विभिन्न शाखाओंके विषयमें कोंसिलमें प्रश्न पृष्ठ सकें । ब्रिटिश लोकसभाकी एक स्थायी सिमिति वनायी जाय, जो इन कोंसिलोंके वहुमत द्वारा शासनकी काररवाईके विरुद्ध भेजे गये प्रतिवादींपर विचार किया करे । यह उपवन्ध जरूरी है क्योंकि कार्यकारिणीको कोंसिलोंके वहमतको रह करनेका अधिकार होगा।

इस प्रस्तावपर कई भाषण हुए । दादाभाई नौरोजीने कहा कि जिन सुधार और प्रश्न पूछनेके अधिकारके लिए प्रार्थना की गयी है, उसके स्वीकृत होनेपर सरकार बहुत सी गलत फहमी और परेशानीसे बच जायगी । सुब्रहण्य ऐय्यरने कहा कि निर्वाचनका अधिकार न होने से कोंसिलोंके गैरसरकारी सदस्य शक्तिहीन रह जाते हैं । रानाडेकी राय थी कि भारत सचिवकी सलहकार कोंसिलमें नामजद और निर्वाचित दोनों तरहके सदस्य हों । अधिवेशन समाप्त होनेपर कुछ प्रतिनिधियोंने बैटकर इस सवालपर विचार किया कि इस प्रस्तावपर जनमत किस प्रकार केंद्रित किया जाय । उन्होंने प्रस्तावकी दस हजार प्रतियाँ अंग्रेजीमें और एक लाख प्रतियाँ विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं एपवाकर बटवायों । इक्कलैण्डमें भी कीवडन क्रवकी मददसे प्रस्तावकी प्रतियाँ बाँटी गयीं ।

एक अन्य प्रस्ताव द्वारा माँग की गयी कि "यहाँ और इङ्गलैण्डमें भारतीय शासनकी को व्यवस्था है, उसकी जाँचके लिए एक शाही कमीशन बैठाया जाय जिसमें भारतीयोंका भी उचित प्रतिनिधित्व हो और यह कमीशन भारत व इंगलैण्ड दोनों जगह गवाहियाँ ले।" तीसरे प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश सरकारके भारतसचिवकी सलाहकार काँखिल भंग करनेकी माँग की गयी। दो प्रस्ताव फौजी खर्च सम्बन्धी थे। एकमें कहा गया था कि "फौजी खर्चमें प्रस्तावित वृद्धि अनावश्यक है और राज्यकी आमदनी देखते हुए वर्तमान परिस्थितिमें अधिक भी है।" दूसरे प्रस्तावमें कहा गया था कि खर्च घटाया जा सकता है और यह छटनी करके व तटकर और लैंसंकर फिरसे लगाकर किया जा सकता है।

कांग्रेसने उत्तरी वर्मापर आधिपत्यका विरोध किया (उस समय सरकार वर्मापर अधिकार करनेके लिए लड़ाई लड़ रही थी) । लेकिन कांग्रेसकी राय थी कि अगर सरकार उत्तरी वर्मापर कब्जा कर लेनेपर तुली ही हुई है तो उसे पूरे वर्माको भारतसे अलगकर लंकाकी तरह उसका एक अलग उपनिवेश शाही संरक्षणमें बना देना चाहिये। उपितने माण्डलेके राजा थी बाके विरुद्ध युद्ध लेड़ रखा था। थी बाने २७ नवम्बर सन् १८८५ को हथियार डाल दिये और उसके अगले दिन माण्डलेपर अंग्रेजी कब्जा हो गया। जनवरी सन् १८८६ में पूरा वर्मा भारतमें मिल गया।

कांग्रेसमें यूरोपियन एसोसियेशनके अध्यक्ष डी. एस. हाइटने प्रसाव पेश किया था कि सिविल सर्विस परीक्षा भारत और इंगलैण्ड दोनों जगह साथ साथ हुआ करे। यह प्रसाव भी स्वीकार कर लिया गया था।

सभी राजनीतिक संस्थाओंको कांग्रेसके प्रस्तावोंकी प्रतियाँ भेजी गर्या और उनसे अनुरोध किया गया कि इन प्रस्तावोंमें उठाये गये प्रश्नोंको हल करनेके लिए वे भी आवश्यक कदम उठावें।

कांग्रेसका तीन दिनका अधिधेशन 'कांग्रेसके पिता ह्यम' की जयकारसे समान हुआ और ह्यमने इस अभिवादनके उत्तरमें महारानी विक्टोरियाकी जयकारके नारे लगाये।

्रकांग्रेसका अगला अधिवेशन सन् १८८६ में २७ से २० दिसम्बर तक कलकत्तेमें हुआ। इसमें ४४० प्रतिनिधि आये जिन्हें सार्वजनिक सभाओं और विभिन्न संस्थाओं द्वारा

चुना गया था। जिन संस्थाओंने प्रतिनिधि नहीं भेजे उनमें नवाव अन्दुल लतीफ और सैयद अमीर अलीकी संस्थाएँ थीं। लेकिन, अमीर अलीने एक पत्रमें लिखा था—"हमें विश्वास है कि कांग्रेसके इस अधिवेशनमें ऐसे कदम उठानेपर विचार होगा जिनसे भारतीय जनताकी हालत सुधरे और हमें ऐसा कुछ करनेसे दुख होगा जिससे लगे कि हम इस सुन्दर उद्देश्यको मदद नहीं कर रहे हैं।

मुसलमान समाजके ३३ प्रतिनिधि आये थे। इनकी अनुपाततः कम संख्याका एक कारण तो यह बताया गया कि उनमें उच्च शिक्षाका अभाव है, दूसरे कलकत्तेके तीन प्रमुख मुसलमानोंने कांग्रेसके विरुद्ध खुलेआम वक्तव्य देकर 'सरकारमें विश्वासकी नीति' अपनायी थी। लेकिन कलकत्तेका मुहेमडन एसोसियेशन कांग्रेसके संयोजकोंमेंसे एक था।

पहले अधिवेशनमें मुरेन्द्रनाथ वनजींको अनुपिश्चिति खटकती थी। इस साल वे आये और फिर १९१७ तक वरावर हर साल आते रहे। २५ वर्षीय नघयुवक रवीन्द्रनाथ ठाकुरने अपने एक गीतसे अधिवेशनका श्रीगणेश किया।

कलकत्ता अधिवेशनका प्रवन्ध वम्बईसे वेहतर था । ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशनके अध्यक्ष राजा राजेन्द्रलाल मित्रके सभापतित्वमें एक स्वागत समिति भी वनायी गयी थी।

दूसरे अधिवेशनके अध्यक्ष दादाभाई नौरोजो थे। उसी साल वे हलवर्न (फिसवरी) से ब्रिटिश पार्लमेन्टमें चुने गये थे। देशके राजनीतिक जीवनसे वे बहुत दिनोंसे सम्बद्ध थे। सन् १८८५ में वे वम्वईकी विधायिका कौंसिलमें नामजद हुए थे। अधिवेशनसे सिर्फ दो दिन पहले उन्हें बताया गया था कि आप अध्यक्षता करेंगे । पर तो भी उन्होंने लम्बा भाषण तैयार कर लिया। उन्होंने ब्रिटिश शासनकी प्रशंसा और कांग्रेसके उद्देशोंका समर्थन करते हुए कहा- 'यह हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे शास्त्रमें रह रहे हैं, जो हमें इस तरह मिलने देता है। ब्रिटिश जनता और महारानीके 'सम्य बनानेवाले' राजमें हम वेरोकटोक मिलते हैं और वेशिक्षक और निडर होकर अपने दिलकी वात कहते हैं। यह सिर्फ ब्रिटिश राजमें हो सम्भव है। ' जब उन्होंने 'सीधा' सवाल किया-क्या कांग्रेस बिटिश सरकारके विरुद्ध द्रोह और वगावत पैदा करनेकी संस्था है ? सभी तरफसे प्रतिनिधि चिल्लाये—नहीं, नहीं । नौरोजीने इसपर कहा-"तो हम मदौंकी तरह ऐलान कर दें कि हमारा रोम-रोम राजमक्त है (हर्पध्विन); अंग्रेजी राजसे जो लाम हुए हैं, वे हमें मालूम हैं; हमें जो शिक्षा दी गयी है, उसका मृत्य इम परखते और जानते हैं; हमें जो नया प्रकाश मिला है, हमें अधेरेसे जैसे प्रकाशमें लाया गया है और वृताया गया है कि वादशाह जनताके लिए होते हैं, प्रजा वादशाहके लिए नहीं, उसका मूल्य हम समझते हैं। और यह सबक हमने सीखा है एशियाके निरंकुश शासनोंके अँधेरेमें स्वतन्त्र अंग्रेजी सम्यताकी रोशनी पाकर।" नौरोजीने आश्वासन दिया कि कांग्रेस त्रिटिश राजके विरुद्ध हो ही नहीं सकती, "हम अंग्रेजी राजके खिलाफ द्रोह नहीं करना चाहते।"

भारतकी गरीवीकी चर्चा करते हुए उन्होंने विचार प्रकट किया कि यदि काँसिलोंमें भारतीय प्रतिनिधित्व वढ़ जाय तो स्थिति सम्हल सकती है। आपने कहा—'दुर्भाग्यवश, भारतकी समृद्धिके सम्बन्धमें गलत धारणाएँ वनी हुई हैं; अगर काँसिलोंमें उचित प्रतिनिधित्वकी माँग मान लो जाय तो हमारे प्रतिनिधि काँसिलों और शासकोंको वे कारण समझावें जिनसे देशमें सबसे बड़ी बुराई—जनताकी गरीवी बढ़ रही है और उसे दूर करनेके

तरीके वतावें। अगर गरीवी वढ़ती ही जाती है तो ब्रिटिश राजके सारे फायदे और अंग्रेज शासकों से सभी महान् कार्य वेकार सावित होंगे।" - उन्होंने वताया कि सन् १८४८ से रैयतकी हालत वरावर विगड़ती गयी है और चार करोड़ व्यक्ति एक वक्त खाना खाकर जिन्दा रहते हैं, अक्सर यह एक वक्तका खाना भी नसीव नहीं होता। सुब्रहाण्य ऐयरने इस . कथनकी पुष्टि करते हुए कहा कि 'माल विभागके हाकिमोंकी रिशवतखोरीपर कावृ पाना असम्भव है।' कांग्रेसके इस अधिवेशनमें एक प्रस्ताव द्वारा 'भारतीय प्रजाके एक वहें भागकी वढ़ती हुई गरीवीपर गम्भीर आशंका' प्रकट की गयी।

इस अधिवेद्यनके प्रस्ताव पिछले अधिवेद्यनके प्रस्तावोंसे मिलते जुलते थे। केन्द्रीय व स्थानीय विधायिका केंसिलोंके सुधार और विकासकी माँग दोहरायी गयी, लेकिन प्रस्तावकी सरकारकी दृष्टिमें स्वीकार्य बनानेके लिए उसे इतना नमें कर दिया गया कि जो कुछ प्रस्तावके एक हिस्सेमें माँगा गया था, दूसरा हिस्सा उसे लगभग काट-सा देता था। कोंसिलोंमें आधे प्रतिनिधियोंके निर्वाचित होनेकी माँग की गयी थी, पर यह निर्वाचन सीधा जनता द्वारा न होकर म्युनिसिपेंलिटी, स्थानिक वोर्ड, व्यापारी मण्डल और विश्वविद्यालयों द्वारा स्थानीय कोंसिलोंमें और स्थानीय कोंसिलों द्वारा केन्द्रीय कोंसिलमें करनेका सुझाव रखा गया। साथ ही, सरकारको अधिकार दिया गया था कि वह चाहे तो कोंसिलोंके निर्वयोंको पलट दे; सिर्फ द्यार्त यह थी कि द्यासन द्वारा पलटे गये निर्वयोंकी अपील भारत सरकार और व्रिटिश पार्लमेण्टकी स्थायी समितिमें की जा सके। प्रस्तावमें कहा गया था कि इस तरह निर्वय पलटनेपर शासन अपनी इस काररवाईके लिए महीनेके भीतर स्पष्टीकरण इस स्थायी समितिके पास मेज दे।

कांग्रेसके इस दूसरे अधिवेशनके लिए सन्तोपका विषय यह अवश्य था कि पिछले सालके प्रस्ताव और लाई डफरिनके प्रयत्नोंके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकारने सन् १८८६ में पिटलक सर्विस कमीशनको स्थापना कर दी थी। अधिवेशनकी एक उपसमितिने सरकारके इस फैसलेपर अपनी रिपोर्टमें सिफारिश की कि सिविल सर्विस परीक्षा एक साथ ही भारत व इंगलैण्डमें हुआ करे; परीक्षामें बैटनेकी अधिकतम उम्र १९ से बढ़ाकर, २३ वर्ष कर दी जाय और कँचे सिविल पद प्रतियोगिता द्वारा भरे जाया करें। संक्षेपमें कांग्रेस सिर्फ यह चाहती थी कि सरकारी नौकरियाँ योग्यता और क्षमताके आधारपर मिलें और उनके लिए हर व्यक्ति उम्मीदवार हो सके। सन् १८८५ के अधिवेशनकी जो एक अन्य माँग अंशतः स्वीकार कर ली गयी थी वह थी पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तके लिए कोसिलकी स्थापना।

न्याय, प्रशासनके क्षेत्रमें, कांग्रेसने माँग की कि मुकदमों में ज्री वैठालनेकी प्रथाका विकास हो और ज्रीका फैसला मान्य हो। ज्री प्रथा सन् १८७२ तक तो प्री तरह प्रचलित थी, लेकिन उसी साल (जब वहावियों के मुकदमों में जर्जों की निष्धताकी परीक्षा होती थी) ज्रियोंका फैसला देनेका अधिकार छीन लिया गया था; हाईकोर्टके सेशन जर्जोंको ज्री निर्णय अमान्य कर देनेका अधिकार मिल गया था। कलकत्ता अधिवेशनमें इसे न्यायके लिए अहितकर घोषित करते हुए ज्रियोंको पहलेवाला स्थान दिलानेकी गाँग की गयी। इस प्रत्तावपर बोलते हुए मुरलीधर (पंजाव) ने कहा—मैं जो सोचता हूँ और जो मेरी धारणाएँ हैं, उन्हें में वेधड़क कह देता हूँ इसलिए मुझे राजनीतिक आन्दोलनकारी माना जाता है और मुझे केदकी सजा मिली है; इस तरहके मामलोंको ज्रीकी रक्षा मिलनी चाहिये।

वादके कई अधिवेशनोंमें यह माँग दोहरायी गयी, पर वृह मानी नहीं गयी। न्यायको प्रशासनसे अलग करनेकी माँगका भी यही हुआ; वह भी मानी नहीं गयी।

इसी अधिवेशनमें अवधिक राजा रामपाल सिंहका यह महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव भी स्वीकार हुआ कि सरकारसे स्वयंसेवकोंकी मरतीकी अनुमित देनेका अनुरोध किया जाय, ताकि ये भारतीय स्वयंसेवक संकटके समय सरकारकी सहायता कर सकें। प्रस्ताव पेश करते हुए राजा साहवने अपने भाषणमें कहा—सरकारने जो कुछ मलाई की है, उसके लिए हम आभारी हैं, पर हम इसके लिए आभार-प्रकाश नहीं कर सकते कि वह हमारा चरित्र और प्रकृति पतित कर दे, हमारे साहस और शौर्यको लगातार कुचलती जाय और सिपाहियों और योद्धाओंकी जातिको कलम धिसनेवाली मेंड़ें बना दे। परमात्माको धन्यवाद है कि हालत अभी इतनी नहीं विग्राड़ी है। हममें हर जगह अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो तलवार उठानेको तैयार हैं, अपने घरों और उस सरकारकी रक्षाक लिए जरूरत पड़नेपर सिर कटानेको भी तैयार हैं जिसने हमें इतना कुछ दिया है……हम वर्तमान नीतिपर क्षोभ प्रकट करते हैं। ऊँच और नीच, हम सब शस्त्रोंका प्रयोगतक भूलते जा रहे हैं। पचास वर्ष पहले युद्धकी आकांक्षा न करते हुए भी, मैदानमें अपने जोहर दिखानेके विचारमात्रसे हर नौजवानका सीना फूल उठता था। अब, मुझे डर है कि अधिकांश नवयुवक इस तरहकी आव- स्वकतापर मिश्रित भावनाओंसे विचार करेंगे।"

प्रस्तावके आर्थिक पहेल्पर वोलते हुए राजा रामपाल सिंहने कहा—"देश गरीव होता जा रहा है; उसकी एक बड़ी वजह स्थायी फोजका बेतहाशा खर्च है। आज नहीं तो कल खर्च का यह भारी वोझ या तो देशकी कमर तोड़ देगा या सरकारकी। लेकिन अगर भारतीय स्वयंसेवकोंको ढंगसे प्रोत्साहन दिया जाय तो इस फोजी खर्च को काफी हदतक कम किया जा सकता है और साथ ही साथ रक्षाके दृष्टिकोणसे देश और भी मजबूत हो जायगा।"

सरकारने इस मुझाव और विचारको आगे नहीं वढ़ने दिया। कांग्रेस वननेसे कुछ साल पहले भी यह सवाल उठा था और सर सैयद अहमद खाँतकने इसका समर्थन किया था,' पर हाकिमोंने इसका कड़ा त्रिरोध किया और इन विरोधियोंमें पुलिसका उच्चाधिकारी ग्रेहम भी था, जिसने वादमें सर सैयदकी जीवनी लिखी।

कांग्रेसने यह भी निश्चय किया कि हर महत्त्वपूर्ण स्थानपर स्थायी कांग्रेस समितियाँ वना दी जायँ।

अधिवेशन वाइसराय लार्ड डफरिन द्वारा दिये गये एक प्रीतिमोजके बाद समाप्त हो गया।

तीसरा अधिवेशन दिसम्बर सन् १८८७ में मद्रासमें हुआ। इसकी तैयारियाँ मईसे ही ग्रुरू हो गयी थीं। इन तैयारियों में जनसम्पर्ककी ग्रुरूआत हुई। १२० सदस्योंकी स्वागत- समिति-वनी-जिसमें हर जाति और धर्मके लोग थे। उसके अध्यक्ष वने राजा सर टी. माधव- राव। "देस हजारसे अधिक आवादीवाले हर शहरमें एक उप-समिति वनानेको कहा गया और जोरदार राजनीतिक प्रचार ग्रुरू हुआ। बीर राधवाचारियरकी तिमल पुस्तिका 'कांग्रेस प्रश्नोत्तरीकी ३०,००० प्रतियाँ वाँटी गर्यों। इस प्रचारका फल यह हुआ कि ५॥ १०,००० प्रतियाँ काँर फाँर फीडम, पृष्ठ २३, २४, २५

हजार रुपये तो इकत्री, दुअत्रीसे लेकर डेढ़ रुपये तक देनेवाले ८ हजार लोगोंसे इकटठे हुए। जिन्होंने २०) तक दिये उनसे ८ हजार और मिले। माण्डले, रंगृन, सिंगापुर और पूर्वी द्वीपसमृह तकसे गरीय लोगोंने चन्दे जमा कर-करके मेजे। मद्रास अधिवेशनमें ४५ रैयत व १९ कामगर प्रतिनिधि आये। ७६० प्रतिनिधियोंमेंसे ६०७ ने अधिवेशनमें आकर माग लिया। वदक्दीन तैयवजी (जो सन् १८९५ में वम्बई हाईकोर्टके जज हुए) अधिवेशनके अध्यक्ष बनाये गये। उनकी शिक्षा लन्दनमें हुई थी और वे सन् १८६७ से वैरिस्टरी कर रहे थे। १८८० में वे अंजुमन-ए-इसलामके सेकेटरी चुने गये थे और वादमें अंजुमनके अध्यक्ष मी हुए थे। १८८२ में वे वम्बईकी विधायिका कौंसिलके सदस्य नामजद हुए थे। उनकी अध्यक्षताका काल वह था जब सर सैयद अहमदके अनुयायी मुसलमानींको राय दी थी कि वे कांग्रेसमें शामिल होनेसे रोक रहे थे। वाँकीपुरमें नवाय अब्दुल लतीफने मुसलमानींको राय दी थी कि वे कांग्रेसमें शामिल न हों। लेकिन तब भी काफी संख्यामें मुस्लिम प्रतिनिधियोंने इस अधिवेशनमें भाग लिया। इनमें प्रमुख थे मौलवी सर्फुदीन, अमीर हैदर, तफज्जुल हुसैन (जो पटनाके वकीलों के वार एसोसियेशनकी एक स्भामें प्रतिनिधि चुने गये थे)। सर्फुदीन वादमें कलकत्ता हाईकोर्टके जज भी वने थे।

तैयवजीके भाषणका काफी भाग, इसीलिए, मुस्लिम समस्यापर विचार करनेमें लगा । उन्होंने कहा-"राष्ट्रीय प्रतिनिधित्वके हमारी संस्थाके चरित्रपर शंका प्रकट करते हुए कहा गया है कि पिछले दो अधिवेशनोंमें देशके एक वड़े समाज—मुस्लिम समाजने भाग नहीं लिया ! अव्वल तो यह लांछन केवल आंशिक रूपमें ही सच है और वह भी देशके एक भागके सम्बन्धमें-जिसका कोई अस्थायी, स्थानीय या विशिष्ट कारण हो सकता है (हर्पध्विन)। दूसरे, ऐसी कोई शिकायत न्यायपूर्वक इस अधिवेशनके खिलाफ नहीं की जा सकती; आर में आप लोगोंके सामने ईमानदारीके साथ कुव्ल करता हूँ कि तन्दुरुस्तीकी इस हालतमें आप लोगोंके विचार विनिमयके सभापतित्वको गम्भीर जिम्मेदारी ओढ हेनेमें मेरी एक बहबती इच्छा यह रही है कि में व्यक्तिगत रूपसे ही नहीं, विलक वम्बईकी अंजुमन-ए-इस्लामके प्रतिनिधिकी हैसियतसे भी यह कह सकुँ कि भारतकी विभिन्न जातियोंकी स्थितिमें ऐसा कुछ नहीं है जो एक जातिके नेताओंको आम सुधारोंके लिए प्रेरित होनेसे रोके। मुझे विश्वास है कि ये महान आम सुधार और अधिकार जो सभीके हित और फायदेके हैं, सर्वसम्मितिसे सरकारके सामने पेश करनेसे ही मिल जायँगे. मेरी तो समझमें नहीं आता कि मुसलमान अन्य जाति व धर्मोंके देशवासियोंके साथ कन्धेसे कन्धा भिड़ाकर सर्वसाधारणके हितोंके लिए काम क्यों न करें। बम्बई प्रान्तमें तो हम लोग इसी सिखान्तपर काम कर रहे हैं। और मद्रास, बंगाल, पंजाब, पश्चिमोत्तर प्रान्तते आये प्रतिनिधियोंके पद, चरित्र, रुतवे, गुण और योग्यता देखकर कोई सन्देह नहीं रह जाता कि सारे भारतके मुस्लिम समाजके नेताओंका भी (कुछ अपवादों - सम्भवतः महत्वपूर्ण अपवादोंको छोड़कर) यही मत है।" इस भाषणपर वार-वार हर्पध्वनि हुई ।

सन् १८८० के करीव रूसको मध्यपूर्वके देशों में गतिविधि देखकर भारतिथत विटिश अधिकारी बहुत चिन्तित थे और इस सम्बन्धमें भारतीय शिक्षित समाजको प्रतिक्रिया जाननेको उत्सुक थे। निचले दर्जेके अंग्रेज अफसर कांग्रेससे नाराज रहते थे और उसके नेताओंको राजद्रोही बताते थे। अध्यक्षने फिर ब्रिटिश सरकारके प्रति वकादारीकी घोषणा करते हुए कहा कि शिक्षित भारतीय वर्गका रोम-रोम वफादार है। उन्होंने उन अखवारोंकी निन्दा की जो ब्रिटिशविरोधी भावनाएँ व्यक्त करते थे। उन्होंने प्रतिनिधियोंको अपनी माँगोंमें संयम वरतनेकी सलाह देते हुए मुख्य विवादके आरम्भमें ही कहा कि प्रतिनिधित्वपूर्ण शासन-संस्थाओंकी जो माँगों हम करते आये हैं, उनके स्वीकार होनेपर, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ उपस्थित प्रतिनिधियोंमेंसे बहुतसे अपने-अपने क्षेत्रोंमें चुन लिये जावँगे। मद्रासमें कांग्रेसके प्रचार और जन-चेतना उत्पन्न करनेके लिए गरीव जनतासे भी कांग्रेसकोषमें एक एक आना लिया गया।

इस वार भी अधिवेशनका मुख्य प्रताव केन्द्रीय व प्रान्तीय विधायिका कैंसिलों के विस्तारके संबंधमें था। सुरेन्द्रनाथ बनर्जीने अपना सुन्दर भापण भी इसी प्रस्तावपर किया था। वारोसालके अदिवनीकुमार दत्तका भाषण भी आनन्दमय आद्र्चर्यके साथ सुना गया जब उन्होंने कहा—''४५ हजार व्यक्तियों के दस्तखतों की एक अपील में आपके समक्ष विचारार्थ रखता हूँ। जब इन लोगोंने इस पत्रपर हस्ताक्षर किये में उनके उत्साह और उनकी शक्तिपर खुशीसे फूल उटा। एक तथाकथित हरिजनने आकर कहा—हुजूर! हमारे अपने आदमी कावून बनावेंगे। कितने वड़े भाग्यकी बात है। एक गरीव मुसलमानने मुझे एक चवन्नी देते हुए अनुरोध किया कि इसे मैं इस काममें खर्च कहूँ। एक किसानने अपने पड़ोसी से कहा—देखो! जैसे हमारी पंचायत चलती है और हम उसके फैसले मानते हैं, वैसे ही हमारे आदमी कावून बनावेंगे और हम खुशी-खुशी उन्हें मानेंगे। सजनो! आप देखें कि जनता इस मामलेंमें कितनी उत्सुक है।"

नार्टन नामक मद्रासके एक मशहूर वकीलने (जिनकी फीस कलकत्ते चले जानेपर हजार रुपया रोज हो गयी थी) अपने जोशीले भाषणमें कहा—"कल मुझसे एक ऐसे सजनने, जिनकी विद्वत्ता और चिरत्रका में सम्मान करता हूँ कहा कि कांग्रेसके विचार-विनिमयमें शामिल होकर मेंने 'छिपे राजद्रोही'का नाम पा लिया है। अगर अन्यायके खिलाफ विद्रोह करना, और अपने देशके शासनमें अपना उचित हिस्सा माँगना राजद्रोह है, अगर क्रू शासन व प्रजापीड़नके खिलाफ आवाज उठाना राजद्रोह है, अगर उत्पीड़न और अन्यायके खिलाफ गदर कर देना राजद्रोह है, अगर सजाके पहले मुनवाईकी माँग करना, अगर व्यक्तिकी स्वतन्त्रताकी माँग करना और धीरे-धीरे, पर हमेशा बढ़नेवाले सुधारोंकी माँग करना राजद्रोह है तो मुझे राजद्रोही होनेमें खुशी है और अपने आपको ऐसे प्रमुख 'राजद्रोहियों'के समाजमें पाकर तो मुझे दुगुनी, तिगुनी खुशी है ।"

नार्टनने भारतीयोंको राय दी कि वे शासन-सुधारके अपने लक्ष्यपर डटे रहें।

मद्रास अधिवेशनमें स्वीकृत शस्त्र-कान्न सम्बन्धी प्रस्तावपर वड़ी गर्म वहस हुई | सुरेन्द्रनाथ वनजीं व विपिनचन्द्र पालने शस्त्र-कान्न रह करनेकी माँग की | पर त्रैलक्ष्यनाथ मैत्रने सुझाव रखा कि कान्नमें संशोधन कर हर व्यक्तिको स्थानीय अधिकारियों या म्युनिसि-पल अधिकारियों से अनुमति लेकर शस्त्र खनेका अधिकार दे दिया जाय | इस वहससे ह्यू मको वड़ी परेशानी हुई क्योंकि उन्हें डर था कि शस्त्र-कान्नको रह कर देनेकी माँगके कारण डफरिन कांग्रेससे नाराज हो जावँगे | अन्तमें जो प्रस्ताव पास हुआ, उसमें कहा गया था कि

१. एनी वेसेंट हाऊ इंडिया फॉट फॉर फीडम, पृ० ४०-४१

शस्त्र कानृत जनताकी सरकार-भक्तिपर अनावश्यकरूपसे आक्षेप करता है, इसलिए उसकी धाराएँ सरकारको संशोधित कर देनी चाहिये।

ह्यू मकी इस प्रस्ताव सम्बन्धी परेशानी 'नवजीवन' नामक मासिक पत्रिकामें प्रकाशित एक पत्रसे प्रकट हैं। अधिवेशनमें शामिल एक सजनने पत्रमें लिखा था— 'मिस्टर ह्यू मकी पीड़ा और वैचेंनी शस्त्र कान्न रह करनेके प्रस्तावपर विवादके समयसे ही दृष्टिगोचर हुई जब वे एकके बाद दूसरे व्यक्तिके पास दौड़ने लगे; उसकी अनिच्छा और दूसरी कई छोटी वातोंमें उनके रख व रवैये ने सावित कर दिया कि वे सिर्फ भारतकी भलाई ही नहीं सोचते, अपनी जातिके हितोंका भी खूब ध्यान रखते हैं।'

सिद्धान्तपर अडिंग रहनेका एक अच्छा उदाहरण कांग्रेसने वंगालके राजा शिश-होखरेखर रायके एक प्रस्तावपर यह दिया कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था है और सिर्फ उन्हीं मसलोंको लेगी जिनका पूरे राष्ट्रसे सम्बन्ध है। राजा साहबका प्रस्ताव या कि गोहत्या बन्द की जाय। प्रतिनिधियोंने अपने रवैये और भाषणोंसे स्पष्ट कर दिया कि प्रस्ताव मुस्लिम अल्पमत-को अप्रिय होगा और प्रस्ताव गिर गया।

कांग्रेसका अपना कोई विधान नहीं था और जब उसे बनानेका सुझाव आता तो सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे लोग कहते—इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्यकी पार्लमेण्टका विधान नहीं है तो हम इसपर माथापची क्यों करें ? कांग्रेसके नियम बनानेके लिए एक कमेटी भी बनायी गयी और उसने नियमोंका मसविदा भी पेश किया पर मसला वहीं रह गया ।

पिछले दो अधिवेशनोंकी तरह इस वार भी प्रतिनिधियोंकी गवर्नरके यहाँ दावत हुई । "गवर्नरने ख्व आतिथ्य सत्कार किया और बहुत मिलनसारी प्रकट की । प्रतिनिधियोंके मनोरंजनके लिए खास इन्तजाम किया गया, भारी नास्ता था और गवर्नरका वैण्ड वज रहा था।" नार्टनने एक दावत दी जिसमें गवर्नर भी आमंत्रित थे। गवर्नर अधिवेशनमें भी शामिल होना चाहते थे, पर डफरिनने उनसे कहा कि वेहतर होगा कि तुम ख़ुद ही प्रतिनिधियोंको दावत दो।

अधिवेशनमें पुराने प्रस्ताव फिर पास हुए । जो नये थे उनमें माँग की गयी थी कि आय-करके लिए जो निम्नतम आमदनो है उसे बढ़ा दिया जाय और घाटा विदेशी महीन स्ती कपहेपर आयात-कर लगाकर पूरा कर लिया जाय, भारतीयोंको टेकनिकल शिक्षा देनेकी व्यवस्था की जाय और फीजी शिक्षण संस्थाएँ यहाँ खोलकर उनमें भारतीयोंको सैनिक शिक्षा दी जाय; इस प्रकार शिक्षित भारतीयोंको केंचे फीजी ओहदे दिये जायँ।

अध्याय ६

भारतीय कांग्रेसकी शक्तिवृद्धि

चेधानिक राजनीतिकी परिधिक अन्दर कांग्रेसने १८८७ में अपने कार्यका विस्तार इतना कर दिया कि वह शिक्षित वगोंके अतिरिक्त जनसाधारणकी संस्था वन गयी। तीन अधिवेशनोंने यह सिद्ध कर दिया था कि कांग्रेसमें खुळे ढंगसे अपने विचार व्यक्त करनेका अवस्य और स्थान है। वक्ताओंने सरकारकी आर्थिक नीतिकी कड़ी आळोचना की और उसको भारतीय जनताका शोषक वताया। इन वातोंसे सरकारकी चिन्ता वढ़ी और उसने कांग्रेसके प्रभावका प्रतिकार करनेकी कोशिश शुरू कर दी —कुछ कांग्रेस-विरोधी संस्थाओंको जन्म दिया गया। सरकारने दमन करना भी आरम्भ कर दिया और अपने मातहत आदिमयोंको कांग्रेसके कार्योमें भाग छेनेसे रोका। विना इल्जाम लगाये हुए लोगोंसे अच्छी चाल चलनके लिए भारी रकमके मुचलके लिये जाने लगे। "एक कहर कांग्रेस-विरोधी जिला अफसरके मना करनेके वावजूद जब एक व्यक्तिने कांग्रेसके मद्रास अधिवेशनमें हिस्सा लिया तो उससे शान्ति कायम रखनेके लिए २०,००० र० की जमानत माँगी गयी। उसने जमानत दाखिल कर दी और चुपचाप चला गया। उसको खतरा था कि यदि उसने इसकी अपील की और जीत भी गया तो जिला अधिकारी उसको परेशान और अपमानित करनेके दूसरे साधनोंका प्रयोग करेंगे। पंजावके केवल एक जिलेमें, एक सालके अन्दर पाँच-छः हजार आदिमयोंसे नेक-चलनी आदिके मुचलके लिये गये।" री

सन् १८८८ में कांग्रेस और अधिक कियाशील हो गयी । उस वर्षके अधिवेशनकी रिपोर्ट इस वाक्यसे ग्रुरू होती है—''इण्डियन नेशनल कांग्रेसके चौथे अधिवेशनका आरम्भ ही सरकारके विरोधमें किये गये उग्र भाषणोंसे हुआ।''

तीब साल बीत गये और प्रतिवर्ण जनताकी आवाज कांग्रेस मंचसे उग्रतर होती गयी, परन्तु सव व्यर्थ ! "संवेदनाशोल हा म अधिकारियोंकी आडम्बरपूर्ण सहानुभूतिको ढोंग और मजाक समझते थे क्योंकि जनताको भलाईके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा था! हा मको जनताकी हीन दशासे बहुत कृष्ट होता था, विशेषकर जब कि उनके विचारमें ये तकलीफ दूर की जा सकतीं थीं । उन्हें भारतीय गाँवोंकी असली हालतका पता था और उन्होंने स्वयं एकके बाद दूसरा अकाल और उसके भयानक परिणाम देखे थे। भूखे किसानोंके कृष्टोंसे भी परिचित थे''' भारतीय जनताके अकाल और बीमारियोंसे दुःख पानेका वास्तिवक कारण उनकी गरीवी है। और यह दरिद्रता रोकी जा सकती है अगर सरकार अपनो कोंसिलमें अनुभवी प्रतिनिधि, जिनको इस दुर्दशाका मूल कारण ज्ञात है, ले ले। परन्तु सरकारने कोई काररवाई नहीं की। ऐसी दशामें क्या किया जाय १ दुर्दशाका फीरन ही कोई उपाय होना चाहिये था। क्योंकि अकाल और महामारीसे लोग हजारों और लाखोंकी संख्यामें नहीं बिल इससे भी वड़ी संख्यामें मर रहे थे। सरकारको इसका कुछ न कुछ उपाय करनेके

१. एनी वेसेण्ट, वही पुस्तक, पृष्ठ ३६

निमित्त मजबूर करनेके लिए यह आवस्यक था कि भारतीय जनताके नेता शान्त कदम उठायें जैसे कि इंगड़िण्डमें वहाँके निवासियोंके लिए ब्राइट और कॉबडेनने अपने खाद्य-आन्दोलनमें उठाये थे।

अपनी जवानीके दिनोंमें ह्यू मने इस आन्दोलनकी प्रगति देखी थी। उन्होंने वताया कि किस प्रकार हाउस ऑव कामन्सने कॉर्न-लॉ-लीगके नुमाइन्दोंकी वात सुननेसे भी इनकार कर दिया था। और तब कॉवडेनने अपने प्रचारमें कुछ सारगिमत शब्द कहे जिनका इंग्लेण्डवासियों पर आगे चलकर वड़ा असर पड़ा। कॉवडेनने कहा—"नुमाइन्दोंने हाउस ऑव कॉमन्सको समझाना चाहा, परन्तु हाउस ऑव कॉमन्सने समझनेसे इनकार कर दिया और अब हम पूरे राष्ट्रको समझायेंगे, यही हमारा सबसे कारगर तरीका होगा।" ह्यू मने कहा "हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे शिक्षित भाइयोंने पृथक् पृथक् रूपसे, हमारे अख़नारोंने व्यापक रूपसे तथा हमारी राष्ट्रीय महासभाके समस्त प्रतिनिधियोंने—एक स्वरसे सरकारको समझनेकी चेष्टा की है। किन्तु सरकारने, जैसा कि प्रत्येक स्वेच्छाचारी सरकारका रवैया होता है, समझनेसे इनकार कर दिया। अब यह हमारा काम है कि इम देशमें अलख जगार्थे ब्रिटेनको तथा इस महाद्वीपके राष्ट्रीको समझायें ताकि हर भारतीय जिसने भारतमांकी छातीका दूध पिया है हमारा साथी, सहयोगी तथा सहायक वन जाय और यदि आवश्यकता पड़े तो कॉबडेन और उसके वहादुर साथियोंकी तरह आजादी, न्याय तथा अपने अधिकारोंके लिये जो महासंग्राम हम छेड़ने जा रहे हैं उसका वह सैनिक वन जाय।"

जनतामें अब प्रचार किया जाने लगा और इस प्रकार भारतीय राजनीतमें यह एक नया पृष्ठ खुला । "ह्यू मने जुटकर काम ग्रुरू कर दिया । जनताके हर वर्गसे धनकी सहायता माँगी । लोगोंमें पर्चे, इस्तहार और छोटी-छोटी कितावें बाँटीं, बक्ता भेजे और क्या बड़े शहर, क्या देहात, हर जगह प्रचार सभाएँ करायीं । इस प्रकार पूरे देशमें १००० से ऊपर सभाएँ की गर्यी । इनमेंसे बहुतोंमें उपस्थित ५००० से अधिक थी । पाँच लाखसे अधिक कितावें बाँटी गर्यी । इनमेंसे दो उल्लेखनीय पुस्तिकाओं 'कांग्रेससे कुछ प्रक्रन और उत्तर' व 'मौलवी फरीद-उद्दीन और कमबख्तपुरके रामबख्शमें बातचीत'का बारह भारतीय भाषाओंमें अनुवाद कर बाँटा गया । इन पुस्तिकाओंमें हितोपदेशके ढंगपर यह दिखलानेकी चेष्टा की गयी थी कि जब सरकारके मुख्य कर्ता-धर्ता उस देशमें न रहकर जिसपर वे शासन करते हों, अन्यब दूर रहते हों, तो इसमें अनेक बुराइयाँ आ ही जाती हैं, चाहे सरकारके इरादे कितने ही नेक क्यों न हों।"

ह्यू मके इस कार्यसे, जिससे जनतामें जागार्त हो रही थी, अधिकारी चौकरने हो गये । उनके अंग्रेज दोस्त उनसे मिले और गभीरतासे उन्हें समझाया "तुम ऐसी शक्तियोंको जगा रहे हो जिन्हें तुम सम्हाल न पाओगे।" ३० अप्रैल १८८८ को इलाहावादमें एक विराट सभामें भाषण करते हुए उन्होंने उसका जवाब दिया। जो 'इण्डियन नेशनल कांग्रेसकी उत्पत्ति और उद्देश्वांपर एक भाषण' शीर्षकसे छपा। उन्होंने कहा कि "कांग्रेसका वास्तविक उद्देश्व (१) लोगोंका ध्यान निजीस्वार्थ और छोटे-मोटे झगड़ोंसे हटाकर, उसे राष्ट्रकी प्रगतिपर केन्द्रित कर परोपकार और माईचारेकी प्रवृत्ति बढ़ाना है; (२) जो इसमें हिस्सा हैं उनको न

१. वेंडरवर्न, पृ० ६१-६२ व ६३

२. वही किताय पृष्ट ६३

सिर्फ भाषण और तर्क करनेकी विष्क ठीक ढंगसे सोचने और अपनी रायोंको व्यक्त करने और दूसरोको समझा सकनेकी शिक्षा देना; (३) न सिर्फ छोगोंके अन्दर सचाई और खोजकी छगन पैदा करना, विष्क उनके अन्दर संयम, विनम और उदारता पैदा करना है; असलमें उनमें सच्ची वैधानिक प्रवृत्ति पैदा करना; (४) वहे पैमानेपर देशको प्रतिनिधिसभाओंकी काररवाह्यों और काम करनेके ढंगसे अवगत कराना, और (५) इस ज्ञानकी वृद्धिके साथ-साथ इंगलैंडके निवासियों और सरकारको यह दिखलाना है कि भारत जिन सभाओंमें प्रतिनिधित्यकी माँग करता है, उनका प्रवन्ध और संचाहन करनेकी क्षमता भी रखता है।"

भाषणमें आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेसकी शिक्षाओं से कोई राजनीतिक खतरेकी बात नहीं है। "जनताको अग्रेजी शासनके फायदे समझाये जाते हैं। उसे यह भी वताया जाता है कि शान्ति सय अंग्रेजी शासनपर ही देशकी समृद्धि और सुरक्षा निर्मर है। लोगोंको शिक्षा दी जातों है कि यद्यपि उनकी परेशानियाँ और तकलोफें जिनकी वे शिकायत गरते हैं सही हैं, फिर भी अंग्रेजी शासनसे हुए लाभोंको देखते हुए वे नगण्य हैं। यदि वे शान्तिमय ढंगसे भारत सरकार, इंगलेण्डकी सरकार ओर इंगलेंड वासियोंसे माँग करें तो ये शिकायते दूर हो सकती हैं और हो जावेंगी। लोगोंको समझा दिया जाता है कि गैरकान्नी या विष्ठवी ढंगके आन्दोलन चलाना अनुचित है। उनके दिलोंमें यह विश्वास जमा दिया गया है कि एकता, धेर्य और वैधानिक ढंगसे आन्दोलन करने पर उनकी जो भी न्यायोचित माँगें होंगी अन्तमें पूरी हो जावेंगी। इसके विपरीत जल्दवाजी और हिंसारमक ढंगसे काम करनेपर न सिर्फ उनका उद्देश्य नए हो जायगा विल्क वे खुद भी वर्वाद हो जावेंगे।"

भारतके प्रति सद्भाव रखकर हा मने राजनीतिमें प्रमुख भाग लिया था। लेकित यह नया दौर जनताका शान्तिमय और वैधानिक प्रार्थनापत्र पेश करनेका था, क्योंकि हा मका विचार था कि कभी भी जनता हिंसात्मक उपायोंका अवलम्बन ले सकती है। अंग्रेज अधिकारी जन-आन्दोलनोंका निर्दयतासे दमन करनेमें विश्वास रखते थे। हा मका लक्ष्य था जनताको शासनमें कुछ अधिकार दिल्वाकर जन-आन्दोलनोंको उठनेसे रोकना। अधिकारियोंको उनका मत अमान्य प्रतीत हुआ और वे कांग्रेसको संदेहकी दृष्टिसे देखने लगे। आंग्ल-भारतीय समाज और इसके अखवारोंने तो, जबसे कांग्रेसका काम ग्रुक हुआ तभीसे उसका मजाक उड़ाना और गाली देना ग्रुक कर दिया था। इनमें पायनीयर और इंगलिशमैन उल्लेखनीय है भारतीय सिवल सर्विसने कांग्रेसके प्रति अपनी पृणाको विल्कुल नहीं छिपाया। परन्तु शासनके उच्चाधिकारियोंकी कांग्रेसके प्रति सदानुम्तिके कारण तीन वर्षोतक वे अपने जीहर दिखानेसे असमर्थ रहे। वेडरवर्नने सरकारी प्रतिक्रियाके वारेमें लिखा है—"में उन लोगोंके इथकं छोंके वारेमें, जो जल्दी ही उत्ते जित हो जाते हैं और स्वेन्छारी शासक हैं, जो गुमचर विभागमें विश्वास रखते हैं, जिन्होंने इस आन्दोलनके खिलाफ मुसलमानोंमें वर्गीय विद्वेप फैलाया है, जो कांग्रेसका दमन करना चाहते थे, और जिन्होंने हा मके देश निकालेकी सिपारिश की, कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता।" संदेहशील पुरुपोंमें एक मुख्य व्यक्ति सिपारिश की, कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। या संदेहशील पुरुपोंमें एक मुख्य व्यक्ति

१. वेडरवर्न, ए० ऑ० ह्यूम १ष्ट ६४-६५

२. वही पुस्तक, पृनं ६%

३. वहीं पुस्तक, पृ० ६७

उत्तरी पिट्टिमी सीमाप्रान्ति गर्नर सर ऑकलेप्ड कौलिवन ये लो महासमें कंग्रेसके तीसरे अधिवेशनतक, जहाँ भारतीय राजनीतिने नयी करवट ली थी, कांग्रेसके प्रति मिनता रखते थे। १८८८ में जनताके बीच किये जानेवाले प्रचारने उन्हें उद्देलित कर दिया और उन्होंने ह्यू मके साथ इस विपयमें लम्या पत्रव्यवहार किया। उनका पत्र छपे हुए बीस पृष्टोंसे अधिक था और ह्यू मका उत्तर लगभग ६० पृष्ठोंका। सर ऑकलेंडका विचार या कि भारतकी उस समयकी राजनीतिक परित्थितिमें 'उग्न' प्रचार असामयिक था और इससे उद्देश्यके असफल हो जानेकी संभावना थो। आगे उन्होंने लिखा कि "उन्न और निन्दात्मक उपायोंको अपनाना अवस्य हानिकारक सिद्ध होगा क्योंकि इससे सरकार और उसके कर्मचारियोंके खिलाफ एणा पैदा होगी। और चूँकि आन्दोलनकी प्रतिक्या भी होगी इसलिए देश दो परत्पर विरोधी पक्षोंमें वँट जायगा।" कांग्रेसके स्खपर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पक्षके लोग अनिधकृत रूपसे भारतीय जनताकी प्रतिनिधित्वका दावा करते हैं। अन्तमें उन्होंने यह सलाह दी कि सुधारकोंको केवल समाज सुधारमें लगना चाहिये क्योंकि जनताकी भलाईके लिए राजनीतिक सुधारसे ज्यादा समाज सुधारमें लगना चाहिये क्योंकि जनताकी भलाईके लिए राजनीतिक सुधारसे ज्यादा समाज सुधारकों जलरत है।

वेडरवर्न द्वारा ह्यमके उत्तरके उद्धरणोंसे उस समयकी देशकी राजनीतिक परिस्थितिका अच्छा चित्र मिलता है। ''हामने जवाव दिया कि किसानोंके वास्तविक दुःखोंकी तरफ आँख वन्द कर लेनेसे कोई फायदा नहीं । हर आदमी, जिसको जरा भी गाँवोंका शान है, जानता है कि वहाँके लोग आपसमें किस कदर कद्व होकर बात करते हैं। अत्यधिक खचीली और अनुपयक्त दीवानीकी अदालतोंके निर्दय और रिश्वतखोर पुलिस, लगान वस्ल करनेके कड़े ढंगों, आर्ग्स और फौरेस्ट ऐक्टके वर्बर ढंगसे लागू करने आदिके सम्बन्धमें उनकी आलोचनाएँ कितनो तीव होती हैं। इस समय आवश्यकता है—सस्ते, सही और सुलभ न्यायकी, ऐसी पुलिसकी जिसे लोग अपना मित्र और रक्षक समझ सकें, ज्यादा सहानुभृतिपूर्ण व सदय लगान वस्लीके ढंगकां, आर्म्स और फौरेस्ट ऐक्टके अधिक नर्गांसे लाग किये जानेकी । इसी नीतिके अनुसार प्रचार-पुरितकाओं में समझाया जाता है कि "वर्तमान भयानक बराइयोंके प्रति उदासीन मत बने रहो, न उनकी अवहेलना करो। हर गाँवमें आपको लोगों-के ऐसे स्वाभाविक नेता मिलंगे जो हमारे उपकारोंके लिए, (जो अच्छे काम हमने उनके लिए किये हैं) अनुगृहीत हैं । परन्तु साथ ही उनमें, हमारे उन कामों के प्रति, जिनको हम अपने नेक इरादोंके वावजूद, अपनी अज्ञानतासे गलत ढंगसे करते हैं, शिकायत गरी हुई है। इसीलिए अपनी प्रचार-पुरितकाओंके जिरये हम इन बुद्धिमान लोगोंको सहानुभृतिपूर्ण ढंगसे समझाते हैं। इम उनकी मुसीवतोंको स्वीकार करते हैं। पर इम उन्हें अधिक मुलायम शन्दोंमें चित्रित करते हैं । हम उन्हें बताते हैं कि अंग्रेज सरकार संसारमें सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसका बुनियादी सिद्धान्त जनताकी इच्छाओंके अनुकूल, शासन-नीति बनानेका है। एम उन्हें जोरदार शब्दोंमें समझाते हैं कि शासनकी श्रुटियोंके लिए इका-दुका गवर्नर या अफसर दोषी नहीं हैं बल्कि यह शासनकी प्रणाली और प्रथा ही दोषयुक्त है। राजभक्ति और वैधान निक ढंगसे आवाज उठाकर वे इस शासन-प्रणालीमें भी मुधार करवा सकते हैं और उनके बहुतसे दुःख भी जिनका उनको सामना करना पड़ता है, कम हो सकते हैं। सरकार और उसके कर्मचारियोंके खिलाफ नफरतं फैलानेके इलजामका यह जवाव है।"

''दूसरा प्रश्न कांग्रेस आन्दोलनके प्रतिक्रियास्वरूप देशके दो परस्पर निरोधी पर्धी

नैंट जानेका है। यहाँपर सर सैयद अहमद व उनके मित्रोंके कांग्रेसके व्यक्तिगत विरोधकी याद करना अनावश्यक है। मिस्टर हा म इस विरोधको महत्त्व नहीं देते थे। उनका विचार था कि छोटी-सी नगण्य संख्याको छोड़कर सम्य और बुद्धिमान वर्ग कांग्रेसके साथ है। उन्होंने कांग्रेस विरोधी संस्थाकी सख्तीसे आलोचना की जिसमें जैसा कि वे समझते थे, थोढ़ेसे ऑग्ल-भारतीय, अधिकांशतया अफसर सम्मिल्ति थे और ऑग्ल-भारतीय अखवार इस विरोधकी सहायता करते थे।" कांग्रेसके विरोधी कौन हैं १ कुछ ईमानदार पर अल्पबुद्धि, धोर रुढ़िवादी, कुछ ऐसे मनुष्य जो अपने हृदयोंमें अंग्रेजोंसे घृणा करते हैं या कुछ ऐसे लोग जो गुप्त रूपसे अंग्रेजोंके शत्रुओंकी नौकरीमें हैं; और कुछ अवसरवादी आदमी जो वास्तवमें कांग्रेस विरोधी नहीं हैं परन्तु जो इस कामको सिर्फ इसिलए करते हैं कि शायद इससे वे कुछ लाम उठा सकें। उनकी यह धारणा थी कि कांग्रेस देशमें फूट पैदा करनेके बजाय एकता पैदा करती है। ऐसे लोगोंमें, जो इससे पहिले कैवल झगड़ने या लड़नेके लिए ही मिलते थे, इनमें भाईचारा और सौहार्द्र पैदा करती है। इस सिलसिलेमें उन्होंने सलेमका हृधन्त दिया जो कुछ ही समय पूर्व तक हिन्दुओं और मुसलमानोंके वीच धार्मिक वैमनस्यका क्षेत्र वना हुआ था।

"उनके विचारमें कांग्रेस-विरोधको बाहरसे, नासमझ अधिकारियोंसे जो अभी तक 'फूट डालो और राज्य करो' के सिद्धान्तका अनुसरण करते थे; तथा सरकारके शत्रुओंसे, जो अंग्रेजी साम्राज्यके झण्डेके नीचे सब पार्टियों और विचारके लोगोंके एक करनेवाले आन्दोलनसे घृणा करते थे, वल मिलता था। आगे उनका ख्याल था कि संयुक्त आन्दोलनसे सबसे अधिक फायदा मुसलमानोंको होगा क्योंकि इससे वे वर्तमान प्रगतिके पथपर अग्रसर हो सकेंगे। उनका विश्वास था कि मुसलमानोंकी सद्बुद्ध उन्हें सही रास्ता दिखायेगी और तीन ही सालमें कांग्रेस-विरोधी पार्टी खत्म हो जायेगी।

ह्यू मने स्वीकार किया कि काँग्रेस आंदोलनमें खतरेकी संभावना है, भारतके लिए यह एक नया प्रयोग है और परिस्थित पूरे तौर पर अनुकूल नहीं है। उन्होंने यह भी समझाया कि यदि संभव होता तो वे स्वयं कुछ वपोंके लिए प्रचारको स्थिगत कर देते परन्तु उन्होंने लिखा 'जिन लोगोंने इस आंदोलनको प्रारिभक प्रेरणा दी थी, उनके सामने दूसरा चारा न था। पिर्चिमी विचारोंकी उपज, यह हलचल, शिक्षा, अन्वेषण और आधुनिक बंत्र बहुत तेजीसे अपना प्रभाव फैला रहे थे। और यह वात बहुत महत्त्वपूर्ण हो गयी कि इन प्रभावोंके विस्तारके लिए वैधानिक और सही रास्ता निकाला जाय वजाय इसके जैसा कि कुछ भी हो गया था, कि आगको अंदर ही अंदर मुलगने दिया जाय। मेंने हमेशा स्वीकार किया है कि कुछ स्वोंमें, किन्हीं विचारधाराओं अनुसार, आंदोलन असामियक है। परन्तु सबसे महत्वपूर्ण विचार अँग्रंजी साम्राज्यकी भविष्यकी एकस्त्रताकी रक्षाका है। जव काँग्रं सकी स्थापना की गयी थी तो असली सवाल इसके असामियक होनेका नहीं विक्त इसका था कि क्या इतनी देर हो गयी है कि अब देश इसके लिये प्रस्तुत नहीं है ?…… हमारे अपने ही कायोंसे उत्पन्न, जवरदस्त बढ़ती हुई भावनाओंका उवाल निकालनेके लिए एक साधनकी—एक निर्मादारकी—आवश्यकता थी और इसारे इस कांग्रेस आंदोलनसे ज्यादा कारगर कोई 'निर्ममद्वार' नहीं हूँ ढ़ा जा सकता था। इस दिशामें खूम, जैसा कि उन्होंने स्वयं कारगर कोई 'निर्ममद्वार' नहीं हूँ ढ़ा जा सकता था। इस दिशामें खूम, जैसा कि उन्होंने स्वयं

लिखा है, विशेष उत्मुकतापूर्वक प्रयत्नशील थे। भारतीयोंके त्वभाव, उनकी रुद्वादी भावनाओं, उनकी कान्त माननेकी प्रवृत्ति, उनकी आश्चर्यजनक सहनशीलता, और शालीनताके गुणोंको (वशतें कि वे निराशाको भावनामें आकर अपनी पुरातन शांतिको न छोड़ दें) ध्यानमें रखते हुए ह्यूमको यह विश्वास था कि वे उनको यह वतला कर कि दुखों। से त्राण पानेकी आशा नहीं छोड़नी चाहिये, और शांतिमय तथा अनुशासनपूर्ण हँगसे आवाज उठानेपर मुसीवतोंका कुछ हल भी निकल सकता है, वे उचित पथप्रदर्शन कर रहे थे।

''खतरा इसलिए अधिक बढ़ जाता है कि निरंकुश सत्ता मुट्ठी भर ऐसे विदेशियों के हाथमें रहती हैं जो जनताकी भाषा, राष्ट्रीयता, विचारों ने विलकुल अपरिचत हैं तथा जो दूसरों की भावनाओं, और धारणाओं की परवाह न करते हुए अपने को विजेता राष्ट्र योषित करते हैं। परिणाम यह होता है त्थानकी घटा उदय होते देखकर भी वे सजग नहीं होते और सन् १८५७ के विद्रोह या काबुलकी दुःखदाई घटनाको आकिस्मिक वज्रपात समझ वैठते हैं। इसीलिये ह्यूम साहव जैसे मनुष्यों की, जो परिस्थितिको समझते हैं, चेतावनियाँ पर ध्यान देना भारतमें अंग्रेज साम्राज्यके कायम रहने के लिये आवश्यक है । निस्संदेह जब कभी विपत्ति आतो है, अंग्रेज बहादुरीसे उसका सामना करते हैं और अंतमें आमतीर पर विजयी भी होते हैं परन्तु इस तरह अंघों की तरह भटकते हुए चलने में धन, जन और शिक्त को बढ़ी वर्यादी होती हैं"।

अव तो डफरिन भी काँग्रेसको 'विनार प्रकट करनेका हानिरहित साधन' माननेको तैयार नहीं थे और अपने शासन-कालकी समानि पर एक भोजके अवसरपर उन्होंने काँग्रेस-की धोर निन्दा की । उन्होंने काँग्रेसको 'ऐसा नगण्य अल्पमत' कहा 'जिसको एक शानदार और विभिन्न कर्षोवाले साम्राज्यके शासनकी वागडोर हिंगेज नहीं दी जा सकती' । उन्होंने यह भी कहा — 'जिल्हाल मुझे उसका भारतीय जनताक प्रतिनिधित्वका दावा वेत्रुनियाद माल्म होता है। यदि वह भारतीय जनता या यूँ कहिये करोड़ों वेजवान इन्सानोंका सज्जा प्रतिनिधित्व करती होतो तो वजाय आमदनीपर लगनेवाले करमें कमीकी माँग करनेके, जैसा कि वह चाहती है, उसे जनता-करमें दस गुनी वृद्धि करानेका स्पष्ट आदेश देती।''

लेकिन जानेके पूर्व डफरिनने अपनी कार्यकारिणींक तीन सदस्योंकी एक समिति राजनीतिक सुधारोंके प्रश्नपर विचार करने और सुझाव पेश करनेके लिए नियुक्त कर दी। इस कमेटी द्वारा प्रस्तावित योजनामें, जो अन्तमें भारत सचिवके पास मेजी गयी थी, सिफारिश की गयी थी "प्रान्तीय परिपदोंका विस्तार किया जाय, उनके अधिकार यहाये जाय, उनके कार्यक्षेत्रमें दृद्धि की जाय, निर्वाचन-पद्धतिका आंशिक आरम्भ कर दिया जाय और राजनीतिक संस्थाओंकी हैसियतसे उनको उदार बनाया जाय।"

ऑग्ल-भारतीय अखवारों द्वारा भारतीय राष्ट्रीयतापर अनेक आक्षेप किये गये। श्री अभ्विकाचरण मञ्जमदारके बन्दोंमें "पायनीयरने कांग्रेसके खिलाफ राग अलापना द्युरु किया और चिल्लाहट मचानेवाले अन्य सब अखबारोंने एक स्वरसे उसका अनुकरण किया। उन्होंने आन्दोलनकी घोर निन्दा की और कहा कि यह आयरिश फेनियनबादकी तरह है और वैसे

१. वेडरवर्न, वही पुस्तक पृष्ठ ७०-७३

२. रिपोर्ट ऑन इण्डियन कॉन्स्टीट्यूशनल रिफार्म्स १९१८, ए० ४२

ही इसके तरीके हैं। छन्न-वेशमें यह ऐसी राजद्रोही संस्था है जिसे न तो जनताका प्रति-निधित्व प्राप्त है और न जिसका कोई मूल्य है। 1718

इस राजनोतिक उतार-चढ़ावकी पृष्टभूमिमें कांग्रेसका, चौथा अधिवेशन इलाहावादमें होनेवाला था। उत्तरी-पश्चिमी स्त्रेके गवर्नर सर ऑकलैंड कॉलिवन थे। इन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन इलाहावादमें न होने देनेके लिए हर मुमिकन रुकावट डाली। खुने अधिवेशनके लिए खुसरोवाग चुना गया था परन्तु सरकारके अनुमित न देनेपर इस स्थानको छोड़ना पड़ा। इसके वाद किलेके समीपकी जगहपर नजर पड़ी। मगर यह जगह स्वास्थ्यकी निगाहसे उचित न थी। तीसरा स्थान कैन्टूनमेंट चुना गया परन्तु इसकी भी अनुज्ञा सरकारने न दी। परन्तु चौथी जगह एक नवावकी कोठी 'लौदर कोंसिल'को थोड़ी-सी दिकतोंके वाद, स्वागत समितिके अध्यक्ष अयोध्यानाथने पट्टेपर ले लिया। इसपर अधिकारकी गारण्टीके लिए सर लक्ष्मीश्वर सिहने इसको खरीद लिया और कोग्रेसके लिए खाली रखा। कॉलिवनने एक और अड़ंगा लगाया—आदेश-पत्र द्वारा सरकारी नौकरोंको कांग्रेस-अधिवेशनमें भाग लेनेसे रोक दिया। अधिवेशनके समय वह स्वयं देहातके दौरेपर चला गया।

सन् १८८८ का अधिवेशन पिछले अधिवेशनोंके मुकावलेमें अधिक सजीव था। इसमें १२४८ प्रतिनिधियोंने भाग लिया था, जिनमें २२१ मुसलमान, २२० ईसाई, ६ सिख ७ पारसी और वाकी हिन्दू थे। इलाहाबाद अधिवेशनके सभापति स्काटलैण्डनिवासी जार्ज यूल निर्वाचित हुए। वे कलकत्तेके एक प्रमुख व्यापारी थे और उस समय 'वेंगाल चेम्त्रर आफ कामर्स'के अध्यक्ष भी थे। शेख रजा हुसैन खाँने उनके चुनावके समर्थनमें लखनऊके सुन्नियोंके धार्मिक नेताका फतवा पेश कर दिया। खाँ साहवने कहा "यह मुसलमान नहीं वित्क उनके सरकारी आका हैं जो कांग्रेसकी मुखालफत करते हैं।" अपने अध्यक्ष-पदसे दिये लम्बे भाषणमें यूलने एक ही विषय 'विधान-परिपदोंमें सुधार' पर प्रकाश डाला । उन्होंने इस तर्ककी निन्दा की कि भारत प्रतिनिधि-सभाओं के योग्य नहीं है। अपने पक्षमें इन्होंने थोरोल्ड रोनरकी पुस्तक 'दी ब्रिटिश सिटीजन' का एक उद्धरण पेश किया, जिसमें कहा गया था कि "मैं इस वातका विश्वास नहीं करता कि सौ साल पहिले दसमें एक आदमीसे अधिक, या वीसमें एक औरत पढ़ना-लिखना जानती थी । नौजवानीके दिनोंमें मैं जब हेम्पशायर नामक गाँवमें था तो वहाँ चालीस सालसे ऊपर उम्रके किसानोंमें शायद ही एकाध आदमी लिखना-पढ़ना जानता हो। उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा देना भी व्यर्थ समझा गया।" यूलने आगे कहा "यदि एक या दो सदी पहिलेकी यात लें तो इंगलैण्डमें मुट्ठीभर आद्मियोंको छोड़कर, वूढ़ोंसे लेकर वचोंतक, रईस गरीव सव बुरी तरह अज्ञानताके अँधेरेमें फँसे थे, फिर भी वहाँ 'हाउस ऑफ कामन्स था।' इसी तर्कको लेकर उन्होंने कहा कि "यदि किसी देशमें थोड़ेसे भी ऐसे आदमी हैं जो मता-धिकारका विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं, तो उन्हें केवल इस आधारपर इस अधिकारसे वंचित रखना कि वाकी लोग अयोग्य हैं, गलती होगी।" इस तरहसे उन्होंने भारतको प्रति-निधि सभाओंके अधिकार दिलानेकी सिफारिश की और कहा "हम चाहते हैं कि विधान-परिपदोंको जहाँतक सम्भव हो इतना बढ़ाया जाय कि उनमें देशके विभिन्न हितोंकी नुमा-इन्दगी हो जाय । परिषदोंमें आधे सदस्य निर्वाचित और आधे सरकार द्वारा नियुक्त किये

५. अस्विकाचरण मजुमदारकृत 'इण्डियन नेशनल इवोल्यूशन' ए० ८२

जायँ। और इस यह दार्त माननेको तैयार हैं कि ज्ञासन-विभागको विद्येपाधिकार प्राप्त हो।"

पिछले वर्षों में स्वीकृत प्रस्ताव फिर मंजर किये गये । नये प्रस्तावों में (१) एक जाँच-समितिकी माँग की गयी, जो असन्तोपजनक और दमनकारी पुलिसके मीज़दा संघटनकी जाँच करे। (२) नशीली वस्तुओंकी बढ़ती हुई खपतपर चिन्ता प्रगट की गयी और सरकारसे प्रार्थना की गयी कि वह इनका बढता हुआ प्रयोग रोकनेकी कोशिश करे। (३) भारतकी औद्योगिक स्थितिकी जाँचके लिए एक मिले-जुले कमीदानकी माँग की गयी। (४) नमक-करमें कसीकी साँग की गयी। (५) सरकारसे शिक्षाके लिए वजटमें अधिक धन देनेकी प्रार्थना की गयी। और (६) जमीन बन्दोवस्तमें बार-वार रहोबदल होनेसे जो किसानोंकी तकलीफ वढ जाती है उसके वारेमें तय किया गया कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ इस विपयका अध्ययन करें और अगले अधिवेशनमें अपनी रिपोर्ट पेश करें । वहसके लिए कोई भी ऐसा विषय, विषय-समिति निदिचत नहीं करेगी जिसपर हिन्दू या मुसलमान प्रतिनिधि एकमतसे या लगभग एकमत होकर आपत्ति करें।" लखनऊ 'पंच' के सम्पादक सजाद हसैनने पुल्सिपर बहुत व्यंगात्मक भाषण किया। आपने कहा "सरकारने भारतीयोंपर बहुत उपकार किये हैं। पुलिस भी एक उपकार है। कैसी पुलिस ! ऐसी पुलिस जो चोरी तथा वदमाशींसे भी ज्यादा ईमानदार नागरिकोंके लिए कप्टपद है। लोगोंको पुलिस द्वारा चोरीकी जाँचमें डकैतीसे भी अधिक परेशानी उठानी पडती है।" इसी प्रकार मदन मोहन मालवीयने महारानीकी १८५८ की घोषणाके वारेमें जिसका अक्सर उदाहरण दिया जाता था, कहा कि "यह ईमानदारीसे ग्रभेच्छाओंके साथ नहीं बल्कि तात्कालिक नीतिवश की गयी है।"

इस अधिवेशनकी एक खेदजनक घटना थी वनारसके राजा शिवप्रसादका व्यवहार । उन्होंने कांग्रेसकी खुलेआम निन्दा कर अधिकारियोंका ध्वान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था । किसी प्रकार उन्होंने वनारसके इलाकेसे अपनेको इलाहावाद कांग्रेसके लिए प्रतिनिधि चुनवा लिया हालाँ कि उसी इलाकेके अन्य प्रतिनिधियोंने इसका जोरदार विरोध किया था और किसी प्रकार भी उनके साथ 'प्रतिनिधिके लिए नियुक्त स्थान' पर वैटनेको राजी न हुए । तब उनको वाहर वैटनेको स्थान दिया गया । मुरेन्द्रनाथ वनजींके शब्दोंमें ''राजा शिवप्रसाद अधिकारियोंके विश्वासी मित्र थे और उनका कांग्रेसमें भाग लेना आइचर्यन्तनक था । परन्तु यह केवल एक कृटनीतिक चाल थी । वे वास्तवमें वहाँ प्रशंसा करनेके लिए नहीं विका भर्सना करनेके लिए गये थे । इस कारण बेटले (?) नॉर्टनने अपने तिरस्कार और नफरत भरे भापणमें उनको खूब फटकारा ।'' परिपदमें मुधारके बारमें आये प्रस्ताय और लाई इफरिनके कांग्रेस सम्यन्धी विचारोंपर बहसके दौरानमें राजा सहवने एक प्रस्ताय पैश करना चाहा जिसमें सरकारसे से प्रार्थना की गयी थी कि वह राज-दोहात्मक भापणोंपर रोक लगा दे । इसपर प्रतिनिधियों और दर्शकोंको बहुत रोप आया बहाँतक कि उस दिनकी काररवाईके खात्मेपर, उनको स्वागत-सिमित द्वारा दिये गये रक्षकोंकी सुरक्षामें अपने मकान भेजा गया।

यहाँवर थोड़ा-सा जिक्र इंगलेंडमें किये गये कांग्रेसके कामका कर देना चाहिये।

१. वेसेण्ट-वही पुस्तक, पृष्ट ६८

२. वनर्जी-वही पुस्तक, पृष्ट १०९

इंगलेंडमें कांग्रेसकी स्थापनाके लिए सबसे पहिला कदम १८८७ में उठाया गया जब कि दादाभाई नौरोजी जो इस समय इंगलेंण्डमें ही रहते थे, कांग्रेसके एजेण्टकी हैिलयतने काम करनेको तैयार हो गये। "उनको धनकी सहायता नहीं दी गयी, और चूँकि वे व्यापार करते थे, इस कारण कांग्रेसके काममें थोड़ा ही समय दे सकते थे। वस्तुतः थोड़ा सा ही काम किया जा सका।" फिर भी सन् १८८८ में काममें निक्चय ही कुछ प्रगार्त इन्लूण सीण वनर्जा और अर्डले नॉर्टनके इंगलेंण्डमें दादाभाई नौरोजीके पास पहुँच जानेते हुई। ये लोग भारतके प्रमुख हिमायती चार्क्त बेडलॉकी सहायता प्राप्त करनेमें सफल हो गये। २५ केवन स्ट्रीट, स्ट्रेण्डपर कांग्रेसका दपतर खोला गया और देशमें जोरदार तरीकेंते काम ग्रल कर दिया गया। तीसरी कांग्रेसकी रिपोर्टकी दस हजार प्रतियाँ और अन्य भाषणोंके हजारों पर्चे और पुस्तिकाएँ छपवाकर वाँट दी गर्या। अपने भारत-प्रेमके कारण भारतके सदस्य'के नामसे मशहूर, बेडलॉने इंगलेंण्डके विभिन्न भागोंमें भारतके सम्बन्धमें मुफत भाषण किये। हालॉकि भारतीय एजेन्सीको 'पब्लिक हॉल', विज्ञापनका व दूसरे छोटे-मोटे खर्चे उटाने पड़े। "इस काममें सात महीनोंके अन्दर १७०० पाँड खर्च हो गये।"

ह्यूम यह वात अच्छी तरह समझ रहे थे कि कांग्रेसकी, भारतके साथ न्याय करनेकी वार-वारकी अपीलींसे अंग्रेज अधिकारियोंके कानींपर जूँ भी नहीं रंगती। उन्हें इस वातका पूरा यकीन हो गया था कि शिमलामें स्थित चरकारसे नाममात्रकी भी सुधार करनेकी कोई उम्मीद नहीं । दूसरा चारा इंगलैण्डमें प्रचारकार्यको अधिक शक्तिशाली करना था । इसी विचारके अनुसार उन्होंने १० फरवरी १८८९ को पत्र द्वारा इंगलैण्डमें कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को उचित पैमानेपर प्रचार-कार्य करनेका महत्व समझाया । उन्होंने वतलाया ''हमारो आशा केवल हम लोगोंके प्रति किये गये अनाचारों तथा वर्तमान शासनके अन्यायों और अदूरदर्शिताके खिलाफ इंगलैण्डकी जनताकी चेतना जाग्रत करनेमें निहित है। हमारा न्यूनतम काम काफी धन इकट्ठा कर अपने सबसे योग्य बक्ताओंका शिष्टमंडल वरावर इंगलैंड भेजनेका है ताकि वे वहाँपर देशके निमित्त आवाज उठाते रहें—अपनी इंगलैण्ड रिथत कमेटीको इस काविल वना दें कि उसकी सभाओंका कम टूटने न पाये, जहाँ भारतके सच्चे चित्रका वर्णन किया जाय। ब्रिटेनको परचों, पुस्तिकाओं, अखवारों और पत्रिकाओं तथा हेखों से भर दें—एक इन्द्रमें अपने आंदोलनको 'विजयी, एण्टी कॉर्न ला-स्टीग' की भाँति द्यक्तिद्यास्टी वना दें।"^र ह्यूम का इंगर्लेण्डमें १८८९ के वीच प्रचार-कार्यके खर्चका तखमीना २५०० पोंड था । उनकी योजना स्वीकार कर ली गयी । २७ जुलाई सन् १८८९ को इंगलैण्डमें विलियम वेडस्वर्गके सभापतित्वमें एक कमेटी वनायी गयी जिसमें दादाभाई नौरोजी, डब्लू॰ एस॰ केन॰ एम॰ पी॰, डब्लू॰ एस॰ ब्राइट मेकलारेन एम॰ पी॰ ये। इसके मंत्री, डब्ट्० डिग्बी नियुक्त हुए। वादमें इस कमेटीमें जान ऐल्सि॰ एम॰ पी॰, जार्ज यूल०, डब्लू० सी० वेनर्जी, सर चार्क्स स्वेन एम० पी०, सर हरवर्ट रॉवर्ट्स एम० पी०, हा० जी० वी० क्लार्क और मार्टिन बुड भी शरीक हो गये। १८८९ की काँग्रेसके प्रस्ताव द्वारा इस कमेटीका विधान भी स्वीकृत हो गया और इसको चलानेके लिए ४५००० रु० यह रुपया मांतीय काँग्रेस कमेटियाँ आनुपातिक ढंगते चन्दे करके मंत्र हुआ

१. वनजीं, वहीं पुस्तक, पृष्ट ८७

२. वही पुस्तक देखो पृष्ट ८५-८६

देनेवाली थीं । इस कमेटीका नाम 'दि ब्रिटिश कमेटी ऑव दि इन्डियन नेशनल कांग्रेस' रखा गया ।

जब इलाहाबादके कांग्रेस अधिवेशनने हंगलेंडमें कॉंग्रेसके कामके लिए धनकी अपील की तो क्यों और छोटे सिक्कोंकी वर्षा होने लगी। मुरलीधरने मंचपर नगद ५५५ रू० जमा कर इसकी पहल की। २०००० क० से ऊपर तो वहीं जमा हो गये और बादोंको मिला कर यह रकम ६४००० क० हो गयी। कॉंग्रेसने हंगलेंड जाकर पार्लमेंटके सदस्योंको उस समयकी भारतकी दशा समझानेके लिए उमेशचन्द्र बनजों, आर० एन० मुधालकर, सुरेन्द्रनाय बनजों, अर्डले नार्टन और ह्यू मका एक शिष्टमण्डल नियुक्त किया।

कांग्रेसकी अपनी रिपोर्टके निम्नलिखित उद्धरणसे १८८८ में कांग्रेसकी स्थितिका पता चलता है—

"कांग्रें सी विचारधाराका देशके दिमागपर इतना गहरा असर पड़ चुका है कि संसारकी कोई शक्ति उसे मिटा नहीं सकती । अगर कल हजारों कांग्रे सियोंको देश-निकाल दे दें तो भी यह विचारधारा पनपती ही जायगी, एकके बाद दूसरेके दिमागपर कब्जा करती जायगी, यहाँतक कि भारतीय जनताके प्रत्येक पुरुष, औरत और वच्चेपर अपना अधिकार जमा लेगी । इसकी शक्ति वसायर बढ़ती जायगी । भारतीयोंके लिए कांग्रे स लाभदायक है और उनके लिए इसके उद्देश्य उदार व शान्तिमय हैं । सरकारी विरोध और दमनसे न सिर्फ इसके विकासमें वृद्धि होगी विलक्ष इससे वैधानिक व शान्तिगय आन्दोलनका रूप बदल कर गुप्त कान्तिकारी व गैरकान्ती हो जायगा।"

१८८९ की कांग्रेस सर विलियम वेडरवर्नकी अध्यक्षतामें वम्बईमें हुई। वे सिविल-सर्विसके कर्मचारी थे और सरकारकी सेवा उन्होंने जिला मैजिस्ट्रेट, जज, विधानपरिपद्के सदस्य व अन्य पदोंपर रह कर की थी। सन् १८८५ में उन्होंने सिविल सर्विससे इस्तीफा देकर भारतमें समाजसेवाका काम अपना लिया। भारतीय राजनीतिक असन्तोपको एक धाराका रूप देनेमें उन्होंने ह्यू मका साथ दिया।

वेडरवर्नने कहा कि "भारतीय कर-देनेवालोंकी मुख्य दिलचरणी इन वातोंमें हैं— शान्ति कायम रहे, मितव्यिवतासे काम लिया जाय और शासन-व्यवस्थामें मुधार हो। लेकिन ये सब चीजें फीजी तथा मुलकी दोनों ही सरकारी वगोंको नापसन्द हैं। उत्साही और सामानसे लैस सेना शान्ति कय चाह सकती है, यह तो युद्ध चाहती है। धोर कीन अवलमन्द आदमी सरकारी कर्मचारियोंसे मितव्यियताकी आशा कर सकता है? किपायतके मानी उनकी तनस्वाहींपर चोट है, फिर शासन सम्बन्धी मुधारोंको ही वे कय पसन्द कर सकते हैं? क्योंकि इससे उनकी हुक्मतमें कभी जो आ जाती है। इन हालातमें मुझे यह कहनेमें कोई हिचक नहीं है कि भारतीय कर-दाता और सरकारी कर्मचारियोंके हित परस्पर विरोधी हैं… इमको स्वीकार करना पड़ता है कि इंगलैण्डमें संबटित शक्ति हमारे विरोधियोंके हाथमें है। इण्डिया ऑफिस हमारा बहुत सख्त विरोधी है, लग्दनके अखवार भी हमारे पक्षमें नहीं हैं। पार्लमेण्टके वे सदस्य, जिनको भारतका अनुभव है, ज्यादातर अधिकारियोंके साथ हैं। नये प्रजातन्त्रवादके पोपक भारतीय अभिज्ञपाओंके समर्थक हैं और जहाँ कहीं भी मजदूरींकी सभाओंमें भाषण किये गये हैं, वे तैयार ही नहीं, उत्सुक हैं कि भारतके साथ न्याय किया जाय। १८८९ के अधिवेशनमें ठीक १८८९ प्रतिनिधियोंने भाग लिया था। अकेले वम्बईने ८२१ प्रतिनिधि मेजे जब कि १८८५ के अधिवेशनमें वहाँके प्रतिनिधि केवल ३८ थे। प्रथम अधिवेशनमें सिर्फ दो मुसलमान प्रतिनिधियोंने माग लिया था और १८८९ में इनकी संख्या २५८ हो गयी। इस सालके प्रतिनिधियोंमें गोपालकृष्ण गोखले, वालगंगाधर तिलक, विपिन चन्द्र पाल व लाजपत राय जैसे भविष्यके नेता व कुछ स्त्रियाँ थों।

वम्बईके गर्वनरने कॉल्विनकी बनिस्वत अच्छा व्यवहार किया। बहुतसे सरकारी कर्म-चारी भी वेश बदल कर कांग्रेस अधिवेशनमें शामिल हुए। वे ब्रेडलॉको, जो इस समय भारत में हो था, और अधिवेशनमें भाषण करनेवाला था, खासतौरपर सुननेको आये थे। प्रतिवर्ष बढ़ती हुई प्रतिनिधियोंकी संख्याको कम करनेके लिए कांग्रेसने एक नियम बनाया कि आइन्दासे कांग्रेस कमेटियाँ प्रति दस लाख मनुष्योंकी आवादीपर केवल पाँच प्रतिनिधि मेज सकेंगी। परन्त आमतौरपर इस नियमका पालन कड़ाईसे नहीं होता था।

अधिवेशनका मुख्य प्रस्ताव इस्व मामूल परिषदों में सुधार और इनके विस्तृत करने के वारे में था। परन्तु इस मर्तवा प्रस्ताव में इसके वारे में एक योजना भी पेश की गयी। अध्यक्षको यह अधिकार दिया गया कि वे "कांग्रेसकी यह प्रार्थना चार्ल्स ब्रेडलॉ तक पहुँचा दें कि वे इस योजना में इंगित विचारों के आधारपर एक विल तैयार करें और उसको हाउस ऑफ कॉमन्समें पेश करें।"

योजनामें ये सझाव थे-

- (क) केन्द्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में कम-से-कम आधे निर्वाचित सदस्य हों और एक चौथाईसे अधिक ऐसे सदस्य न हों जो अपने पद-विशेषके कारण लिये गये हों। शेष सदस्य सरकार द्वारा नामजद हों।
 - (ख) मालगुजारीके जिले ही सामान्यतः निर्धारित क्षेत्र मान लिये जारूँ।
- (ग) कुछ खास योग्यताएँ रखनेवाले इक्कीससे ऊपर उम्रवाले सव प्रजाजनोंको सताधिकार प्राप्त हो ।
- (घ) हर जिलेमें मतदाता एक या उससे अधिक निर्वाचन-संस्थाओं के लिए मतदान
- (च) इस प्रकारसे चुने हुए सब जिलोंके प्रतिनिधि जो किसी-न-किसी निर्वाचन-क्षेत्रमें शामिल हैं कैन्द्रीय विधान सभाओंके लिए अपने क्षेत्रकी आवादीपर प्रति पचास लाखपर एक मेम्बर चुने व अपने प्रांतकी विधान सभाओंके लिए प्रति दस लाखपर एक मेम्बर मेजें। यह चुनाव इस तरीकेसे किया जाय कि जब कभी भी पारसी, ईसाई, मुसलमान या हिन्दू अल्प-मतमें हों तो चुने हुए पारसी, ईसाई, मुसलमान या हिन्दू मेम्बरोंकी संख्याका अनुपात कुल मेम्बरोंमें उनकी आवादीके अनुपातसे कम न हो। दोनों विधान सभाओंके मेम्बरोंके निर्वाचनके लिए कुछ योग्यताएँ और अयोग्यताएँ हों जो वादमें निर्धारित कर दी जावँ।

इस प्रस्तावपर जो संशोधन पेश किये गये यद्यपि वे स्वीकार नहीं किये गये, फिर भी उनपर ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि उनसे उस कालकी जनताकी भावनाओंका पता चलता है। हा म 'अल्पमतवाली घारा' को निकलवा देना चाहते थे। उनका तर्क था कि 'भारतींय भारतीय हैं। उसमें अल्पमत और वहुमतका प्रश्न क्यों उठाया जाय ?'' परन्तु इसको काफी लोगोंका समीयन नहीं मिला। अवधके हिदायत रस्लने सुझाव दिया कि हालाँकि हिन्दू

बहुमतमें हैं परन्तु परिषदींमें हिन्दू और मुसलमान सदस्वोंकी संख्या वरावर होनी चाहिये। उन्हींके सहधमीं लखनऊके हामिदअली खाँ, वार-एट-लोंने इसका विरोध करते हुए जवाव दिया कि हिन्दू मुसलमानोंका प्रश्न नहीं उठाना चाहिये। एक दूसरे मुसलमान प्रतिनिधि वाजिदअली विवाजीने तैशमें आकर कहा कि "परिपदोंमें मुसलमान मेम्बरोंकी संख्या हिन्दू मेम्बरोंसे तिगुनी होनी चाहिये।" एक चौथे मुसलमानने इन मुझावोंका विरोध करते हुए कहा "हम यहाँ एक समान-उद्देश्यके लिए इकट्ठे हुए हैं। और ऐसे अवसरपर मुसलमानोंको मूल जाना चाहिये कि वे मुसलमान हैं और हिन्दुओंको कि वे हिन्दू हैं। विकि जाति, विचार, और रंगके मेद-भाव मूलकर हम सबको अपनेको भारतीय कहना चाहिये।" और जव हिदावत रस्लके संशोधनपर मत लिया गया तो मुसलमान प्रतिनिधियोंने भी इसके विरोधमें मत दिया।

सन् १८८९ की काँग्रेस द्वारा नियक्त शिष्टमंडल मार्च १८९० में इंगलैंडकी स्वाना हो गया और अप्रैलमें वहाँ पहुँच गया । शिष्टमंडलके प्रत्येक मेम्बरने अपना सफर खर्च और होटलका लच स्वयं उटाया था। इंगलैंड, वेल्स और स्काटलैंडके वहे-वहे शहरोंगें इण्डियन नेशनल काँग्रेसकी ब्रिटिश कमेटी हारा आयोजित वडी-वडी सभाओंमें इस शिष्टमंडलके सदरयोंने भाषण किये । मैनचेस्टरके चैम्बर ऑफ कामर्सकी एक सभामें सुरेन्द्रनाथ वैनर्जाके भाषण करनेके बाद एक आदमीने उठकर कहा कि "आजतक भारतके विषयमें कभी भी मुझे ऐसी गहरी अनुभूति नहीं हुई थी जैसी आज हुई ।" शिष्टमंडलके सदस्य अर्डले नार्टनने अवसरका लाभ उठाकर आक्षफोर्ड यूनियनमें काँग्रेस प्रस्ताव पेश किया। प्रस्तावमें कहा गया था—"सभा इस वातपर खेद प्रगट करती है कि हाउस ऑफ कामन्सके सामने पेश 'निर्वाचन-नियम-विल' को मान्यता नहीं दी गयी।" नार्टनने इस विलको पेश करते समय एक जोरदार भाषण किया। विरोध पक्षका नेतृत्व लॉर्ड ह्यू सेसिलने किया। भारतकी अशिक्षाका पिछडापन उनके तकोंके तरकशका सबसे भयानक तीर था और इसका जवाब बनजींने दिया। उन्होंने कहा "सन् १८२१ में इंगर्लण्डमें स्कूलोंकी संख्या क्षेवल १८,४६७ थी और विद्यार्थियोंकी ६५०,०००। और १८८१ के पहिले वे भारतके स्कूलों और विद्यार्थियोंकी संख्याके वरावर नहीं पहुँच पाये थे ! फिर भी १८८१ में इंगलैण्डके निवासियोंको पूर्ण विकसित पार्लमेंन्टकी संस्थाएँ प्राप्त हो गयी थीं। इम तो इससे बहुत कम माँग रहे हैं। '' जब इसपर मत-विभाजन हुआ तो विष्टमंडलको यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि प्रस्ताव बहुमति स्वीकार कर लिया गया। "इससे यह प्रगट हो गया कि कांग्रे सका सुधारका कार्यक्रम इतना नम्र था कि अंग्रेजी जनताके रूढिसे रूढिवादी वर्गकी भी यह मान्य था।"

वनजीके भाषणका एक छोटा-सा हिस्सा यह विखळानेके लिए कि किन जोरदार शब्दोंमें उन्होंने यूनियन द्वारा प्रस्तावके स्वीकार किये जानेके पक्षमें भाषण किया यहाँ उद्धृत करते हैं—उन्होंने कहा, "वहसके दौरानमें कहा गया है कि अंग्रेजोंके भारत आगमनके पूर्व भारतवासी वर्षर या. अर्द्ध-वर्षर लोगोंका गिरोह-थे! मेरा एवाळ है कि इसी भाषाका प्रयोग किया गया था। में इस सभाको याद दिळाना चाहता हूँ कि भारतीय हिन्हू—जिए जातिका होनेका मुझे भी गौरय प्राप्त है—एक उच पुरातन रक्तके वंशज है। और जिस समय यूरोपके सबसे सम्ब राष्ट्रोंके पूर्वज जंगलों और कन्दराओंने घूम रहे थे,

हमारे पूर्वजोंने वड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित कर लिये थे, वड़े वड़े नगर वसाये थे, आचार-विचार विषयक नियम बना लिये थे, एक धर्म-पद्धतिका प्रतिपादन कर चुके थे, और सुन्दर भाषाको जन्म दे चुके थे, जिसकी प्रशंसा आज भी सम्य संसार करता है। आप लोगोंको सिर्फ यह रास्ता पारकर बोडलियन पुस्तकालयमें जाकर बैठनेकी आवश्यकता भर है। वहाँ आप भारतके प्राचीन-उद्योग घन्धों, संस्कृति और नीति-शास्त्रके इतिहासका अवलोकन कर सकते हैं। इस कारण मुझे यह कटाक्ष समयोचित नहीं माळूम पड़ता। और यदि यह कटाक्ष प्रतिनिधि संस्थाओंके लिए की गयी हमारी याचनाओंके प्रति विद्वेष पैदा करनेकी भावनासे किया गया था, तो यह इससे अधिक अनुपयुक्त नहीं हो सकता था । क्योंकि स्वशासन संस्थाएँ आर्य जातिकी सभ्यताकी प्रमुख अंग थीं और हम आर्योंके वंदाज हैं। हमारे इस प्रस्तावके. विद्वान्-विरोधीने अपने कुछ उद्धरणोंकी पुष्टिमें सर्हेनरी मेनकी पुस्तकोंका हवाला दिया है। में भी उनकी विद्वत्ताके सामने शुकता हूँ। उनके भारत विषयक शानको स्वीकार करता हूँ । भारतके विषयमें उनकी क्या राय है ? स्वशासन संस्थाओंका व्यावहारिक उदाहरण .. सबसे पहिले हमें भारतसे मिलता है। वहाँकी गाँव पंचायतें इतनी प्राचीन हैं जितनी कि वहाँकी पहाड़ियाँ'। जब हम प्रतिनिधि-संस्थाओं या उनमें आंशिक सुधारकी माँग करते हैं, तो यह माँग उनके हतिहासकी परम्पराके विलक्कल अनुरूप है तथा भारतमें अँग्रेजी शासनकी प्रथाके भी अनुरूप है।"

परिषदोंमें सुधारके लिए भारतीय प्रचारकार्य इंगलेंडमें १८९०, १८९१ व १८९२ में बहुत जोरदार तरीकेंचे होता रहा। सन् १८९० में ब्रेडलॉने १८८९ की कांग्रेस द्वारा इंगित योजनाके आधारपर एक विधेयक तैयार कर, इंगलैण्डकी पार्लमेंटमें पेश किया। परन्तु इस विधेयकपर वहसके लिए समय नहीं दिया गया। सारा समय दूसरे कामोंमें व्यतीत हो गया। उन्होंने दूसरा प्रयास किया, परन्तु व्यर्थमें और ३० जनवरी १८९१ को उनकी मृत्यु हो गयी। ब्रेडलॉके विधेयकमें परिपदोंके गैरसरकारी मेम्बरॉके चुनावके लिए एक निर्वाचकमंडल (Electoral College) पद्धतिकी माँग की गयी थी। शासक-वर्गको यह विलक्कल अमान्य था । इसीलिये उसी साल सन् १८९० में भारत सचिव लार्ड कासने 'हाउस ऑफ लाई स'में एक दूसरा विधेयक सरकारकी तरफसे पेश किया। इस विधेयक द्वारा प्रशासनकी जैसेका तैसा रखनेकी कोशिश की गयी थी। केवल गवर्नर जनरलको केन्द्रीय परिपदके गैर-सरकारी मेम्बरोंकी संख्या बढ़ानेका अधिकार दे दिया गया। १८६१ के परिषद-विधान द्वारा गवर्नर जनरलको अपनी सलाहकार समितिमें कमसे कम छः और अधिकसे अधिक बारह सदस्योंको वढ़ानेका अधिकार मिला, वशर्ते कि नामजद किये हुए सदस्योंमें कमसे कम आधे गैरसरकारी हों। लार्ड कासके विधेयक द्वारा यह संख्या वढ़ा कर कमसे कम दस और ज्यादासे ज्यादा सोलह कर दी गयी। इस तरह यह गुंजाइश रखी गयी कि अगर गवर्नर जनरल ृचाहे तो गैरसरकारी मेम्बरोंकी संख्या पुरानीवाली ही रखें। मद्रास और वम्बर्इकी स्थानीय संस्थाओंके सदस्योंकी संख्या १८६१ के कानृत द्वारा कम से चार और आठ थी, नये विधेयकमें यह संख्या आठ और बीस कर दी गयी। बंगालके लिए यह संख्या वीस नियत कर दी गयी और उत्तरी पश्चिमी प्रांतके लिये पन्द्रह । इस विलमें यह भी अधि-कार दिया गया कि परिषदोमें वार्षिक आर्थिक लेखे-जोखों पर वहर हो सकेगी और ''गवर्नर जनरल या प्रांतीय गवर्नरीं द्वारा बनाये गये नियमोंके अंदर कुछ सवाल भी पूछे

जा सकेंगे।" यह विधेयक १८९० या १८९१ में भी स्वीकार न किया जा सका। १८९२ में ही जाकर यह कान्त वन सका। डफरिन सरकार द्वारा प्रस्ताचित सुधारों की खलनामें भी इस कान्तमें बहुत कम सुधार थे। जबिक कांग्रेसके लगातार कई अधिवेशनों में स्वीकृत मुख्य प्रस्तावका माग्य अनिश्चित था और लार्ड कॉसका विधेयक राजनीतिक भारतके लिए निराशा ही प्रदान करनेवाला था, तब दिसम्बर सन् १८९० में कलकत्त्रमें कांग्रेसका छठाँ अधिवेशन हुआ। वंगाल सरकारने एक आदेशपत्र निकालकर सब सचिवों और विभागोंके प्रधान व मातहत कर्मचारियोंको कांग्रेस-अधिवेशनमें दर्शकर्वा हैसियतसे भी जानेकी मनाही कर दी। कर्मचारियोंके कांग्रेसकी समाओं में भाग लेनेपर सख्त प्रतिवन्ध लगा दिया गया। लेपिटनेण्ट गवर्नर और उसके सलाहकारोंको भेजे गये दर्शकों कि निमन्त्रण-पत्र वापस कर दिये गये। कांग्रेस अधिकारियोंने वाहमरायको इस विपयमें लिखा। वाहसरायने कहा कि भारत-सरकारके आदेशको वंगाल-सरकारने गलत समझा है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस आन्दोलन "अपने तौरपर पूर्ण न्याययुक्त है" और "भारत सरकार यह स्वीकार करती है कि कांग्रेस देशका प्रतिनिधित्य करती है, प्रायः उसी तरह जिस तरह प्र्रोपमें अधिक उन्नत उदार दल है, जिससे भिन्न और जिसके समकक्ष अनुदार दल है। दोनों वरावरीसे काम करते हैं।"

कलकत्ता अधिवेदानके अध्यक्ष फीरोजशाह मेहता थे। 'वम्बई प्रेसीडेन्सी एसोसिवेदान' के वे जन्मदाता थे और कांग्रेसके जन्मसे ही उसके साथ थे। वम्बईके म्युनिसिपल कारपोरेशन के वे अस्यन्त सफल सदस्य थे और एक नामो वकील भी थे।

१८९० की कांग्रेसकी रिपोर्ट सरकारपर अभियोगोंके साथ खत्म हुई, जिसकी खास वातें थीं—भारतके प्रशासनमें जहाँ कुछ गुण भी हैं, वहीं हजारों दोप भी । देशके पच्चानवे फी सदी उच्च, प्रमुख और जिम्मेदार पदींपर यूरोपियनोंका एकाधिकार है। कुल जनसंख्याका पाँचवाँ हिस्सा मुखमरोकी दशामें है। लगभग सभी स्वदेशी उद्योग और कलाएँ जतम कर दी गयी हैं। विनाशक ऊँचे करेंकी 'अस्थायी वन्दोवस्त' की प्रणालीके शिकंजेमें खेती धीरे-धीरे नए हो रही है। जनता पस्तिहम्मत बनायी जा रही है। भारतमें अमीरांके खिलाफ गरीबोंको या पुल्सि व अधिकारियोंके खिलाफ गैर-सरकारी लोगोंको कहीं भी सचा न्याय नहीं मिलता '''

१८९१ में कांग्रेसका अधिवेशन मद्रासके पी. आनन्द चारल्झी अध्यक्षतामें नागपुरमें हुआ। वे अपनी इण्डिया कींसिलकी कड़ी आलोचनाके लिए प्रसिद्ध थे। सन् १८९५ में वे केन्द्रीय व्यवस्थापक सभाके सदस्य हो गये और उन पद्पर १९०३ तक काम करते रहे।

आनन्द चारल्ने प्रतिनिधियोंको सलाह दी कि "वे जनताके वीचमें पहिलेखे अधिक जमकर काम करें। उनके हृदयोंमें कांग्रेची संदेशको पहुँचा दें जो राष्ट्रीय भावनाका दूसरा नाम है।"

नागपुरके अधिवेदानमें एकके बाद दूसरे वक्ताने खड़े होकर गाँवोंकी आँखों देखी बुरी दशाका मार्मिक और सजीव चित्र खींचा । जंगलातके नये कान्नने आदमियों और जानवरीं-को उनके प्राकृतिक अधिकारसे वंचित कर दिया या । महासके एक प्रतिनिधि पीटर पॉल

१. वेसेण्ट-वही पुस्तक, पृष्ट १०६-१०७

पिल्लईने कहा "व्यवस्थापकोंने कलमके एक ही इशारेंसे जंगलात कान्तके रैयतके जातीय अधिकारोंको खत्म कर दिया—उन अधिकारोंको जिन्हें वे सिदयोंसे भोगते चले आ रहे थे—जिन्हें पूर्वकालकी सरकारें स्वीकार करती थीं—और जिनको अंग्रेजी सरकार स्ववं भी पहिले मानती थी। आवश्यकतासे लाचार होकर लोग सर्वग्राही जंगलके कान्नेंकी अवज्ञा करनेको वाध्य होते हैं। मेरे जिलेंमें इस कठोर कान्नकी मामूली अवज्ञा करनेपर हजारों फीजदारीके मुकदमे चल रहे हैं।"

साल भरकी काररवाइयोंका संक्षिप्त वर्णन वेतेन्टने बहुत अच्छी तरहसे किया—"यदि असलमें पूछा जाय तो अंग्रेजी शासनके विरुद्ध किसानोंको जितना इस जंगलके कानूनने किया है, उतना किसी चीजने नहीं। नमक-कर बुरा है। जमीनोंके कर-निर्धारणके बन्दो-वस्तका तरीका निर्दयतापूर्ण और कटोर है परन्तु 'जंगलका कानून' तो हर कदमपर कुटारा-घात करता है, और वेचारा किसान, अपने पूर्वजोंकी माँति, जिनके साथ पीढ़ियोंसे यही होता चला आ रहा था, अपराधी करार दे दिया जाता था। मिस्टर पिल्लईने दिखाया कि १८९० में सरकारने किसानोंसे डेढ़ लाख रुपया चरागाह-करके रूपमें वस्ल किया और साढ़े तीन लाख जुर्मानेमें जो उन्होंने जानवरोंके जन्त चरागाहोंमें चले जानेपर वस्ल किया था। एक जिले, उत्तरी आरकाटमें सन् १८९१ में तीन लाख जानवर चारेकी कमीसे मर गये। यह संख्या जानवरोंकी साल भरकी औसत मृत्यु संख्याके अलावा थी।"

वक्ताओं में श्री एस. बी. भाटे भी थे, जिन्होंने कहा कि उनके जिलेमें जंगलके कानृनके लागू करनेके कारण जानवर भूखे मर रहे हैं। अस्थायी तौरपर भी चारागाहके इस्तेमाल-की अनुज्ञा नहीं है। किसान अपने जानवरोंको हटा रहे हैं। दस-दस वारह-वारह रूपये-पर जानवर वेचे जा रहे हैं। एक दूसरे प्रतिनिधिने जिसने अपनेकों एक गरीव पहाड़ी जिलेके एक गरीव गाँवका आदिम निवासी वताया, कहा कि "जंगलोंने मनुष्यको जो वह चाहता था इंधन, लकड़ी, घास, पत्थर, नमीन, पत्तियाँ, छाल, जड़ें दीं परन्तु ये सभी चीजें ईरवरने नहीं, लोभी मनुष्यने छीन ली हैं । सैकड़ों पीढ़ियोंसे वे इन चीजोंका उपयोग निर्द्दनद्वतासे करते चले आ रहे ये और अब वे प्रकृतिकी दी हुई चीजोंसे वंचित कर दिये गये हैं । हिन्दू और मुसलमान शासकों के समयमें जो जंगल उनके लिए आशीर्वाद थे, वही अत्र अभिशाप वन गये हैं।" एक मर्तवा फिर गाँवोंका आर्थिक संघटन चरमराने लगा था। किसानके खेत पहाड़ियोंपर थे, परन्तु वह बनों, जंगलों, झाड़ियों और झरमुटोंका प्रयोग नहीं कर सकता था। वह अपने ही पेड़ोंकी पत्तियाँ भी नहीं इस्तेमाल कर सकता था हालाँ कि उसीने लगाया था। फिर जानवर कहाँ चरें /। सरकारी-सुरक्षित जंगल घेरे नहीं गये थे। स्वामाविक था कि जानवर उनमें घुस जाते थे, वेचारे मालिकोंपर जुरमाना होता था। एक देहातीने, जिसको डाक्टर उपलब्ध नहीं था, जंगलसे कुछ जड़ी वृटियाँ इकट्ठी करनेकी कोशिश की और उसपर जुर्माना कर दिया गया।" कांग्रेसने जंगलोंके कान्नके शिकंजेसे लोगोंको मुक्ति दिलानेके लिये वार-वार प्रस्ताव पास किये, परनतु चूँकि जंगलोंसे अंग्रेजी शासकोंकी जेवमें काफी धन जाता था, इसिंख्ये कांग्रेसकी प्रार्थनापर उन्होंने ध्यान नहीं दिया।" आर॰ ए॰ मधोलकरने कहा कि बारह सालकी अविधमें अकालते एक करोड़

१. बेसेन्ट वही, पुस्तक पृ० १३२

२. वही पुस्तक पृष्ट-१३२-३३

त्रीस लाख आदमी मर गये। उन्होंने अपनी वातकी पुष्टिमें सर चार्स्स ईलियटका हवाला दिया जिन्होंने कहा था कि "आधे खेतिहर किसान साल साल भरतक यह नहीं जानते कि भर पेट खाना किसे कहते हैं।"

पंजावके मुरलीधरने उन लोगोंकी भत्सीना की जो अपना शोपण होने देते हैं। उन्होंने कहा "तुम तुम, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपने भाइयोंके हृदयका रक्त चूसकर मोटे होनेवाले इन पतित राक्षसोंका साथ देनेसे सन्तुष्ट हो । ('नहीं नहीं'का शोर)। मैं कहता हूँ, 'हाँ'। अपने चारों तरफ देखो —ये सब शामियाने और झाड़-फानृस—ये यूरोपकी बनी कसियाँ और मेजं-ये विदया विदया कोट और टोप, ये अंग्रेजी कोट, सियोंकी फॉकें और टोप, ये चाँदीकी मृठकी छड़ियाँ, यह अपने घरोंके आराम और आराइशका सामान, यह सब क्या है ? क्या ये भारतकी दुर्दशांके स्मारक नहीं हैं ? क्या ये भारतकी भुखमरीके यादगार और प्रतीक नहीं हैं ? हर वह रुपया जो तुम यूरोपकी वनी चीजोंपर खर्च करते हो, वह रुपया है जो तुम अपने गरीव और ईमानदार बुनकर भाइयों, जिनकी जीविकाका साधन भी अब खत्म हो रहा है, के हाथसे छीनते हो ? स्वतन्त्र व्यापार ! राष्ट्रींके बीच न्यायसंगत कार्य !! ओफ इन झुटे दावोंसे मैं किस कदर नफरत करता हूँ, गरीव भारत और मोटे पुँ जीवादी इंगलैंडमें क्या न्यायसंगत व्यापारका कार्य हो सकता है ? यह वैसी ही यात है जैसी एक वच्चे और शक्तिशाली आदमीके वीच न्यायपूर्ण लड़ाईकी, जैसी खरगोश और अजगरकी न्यायसंगत लडाईकी! इसमें सन्देह नहीं कि यह सब अर्थशास्त्रके ऊँचे सिद्धान्तोंके अनुरूप है, मगर मेरे दोस्तो ! यह याद रखो कि इसके माने अपने भाइयांके में हका ग्रास छीनना है।"

१८९२में दादाभाई नौरोजी अपने विरोधीको तीन वोटोंसे इराकर पार्लमंटकै लिए चुन लिये गये । वे हाउस आफ कॉमन्सके प्रथम और अन्तिम भारतीय सदस्य थे । पार्लमंटके चुनाव-आन्दोलनमें भारतके सवालने काफी बड़ा स्थान ग्रहण किया । सेलिसवरी व मेकलीन जैसे आदिमयोंने भारतीयोंके विरुद्ध गन्दा प्रचार किया । ओल्ड्समें किये गये भाषण में मेक्लीनने हिन्दुओंको गुलाम और मुसलमानोंको 'टेकेपर लिये गये गुलाम' नामसे सम्बोधित किया । भारतकी सुधारोंको माँगोंके वारेमें वे जोरोंसे यह कहते थे कि "हमने भारतको तलवारके जोरसे जीता है और उसीके जोरसे हम उसे अपने अधीन रखेगे ।" नौरोजीने इसका विरोध किया—"मिस्टर मेक्लीन सहदा लोग, भिन्न भिन्न परिपदों में निर्वाचित सदस्यों के अनुपातकी भारतीय प्रार्थनाको गलत ढंगसे पेदा करते हैं । मुझे यह बात दुहराते हुए दुःख होता है कि मिस्टर मेक्लीन जैसे लोग जाति-विद्वेष, हणा और वदलेकी भावना फैलाकर भारतमें अँगरेजी सत्ताको कमजोर बनानेमें या उसे खत्म करनेमें सबसे वह साधक सिद्ध होंगे।"

लेकिन इंगलेण्ड-स्थित भारतीय विद्याधियोंने अधिक जीरदार विरोध किया । मैनलीन के शन्दोंको उन्होंने भारतकी वेइज्जती समझा । उन्होंने ओल्डममें एक सभा बुलायी और वहाँ मैक्लीनके व्यवहारकी भर्ताना की । चितरंजनदास, जिनका भारतीय राजनीतिमें वादमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा, उस समय, कुछ हो महीनों वाद होनेवाली सिविल गर्विमकी परीक्षाके लिये तैयारी कर रहे थे । उन्होंने भारतके मित्रोंको एक्सीटरमें इकटा किया और अपेर उनके बीचमें बोलते हुए कहा "महाश्रयो, मुझे यह जानकर दुःख हुआ कि एक मतंबाने ज्यादा पार्लमेंटरी भाषणों में यह बात कही गयी है कि इंगलेंडने तलवारके जोरसे भारतको जीता

है और तल्वारके जोरपर वह भारतकी अधीनताको बरकरार रखेगा (शर्म) । इंगलेंड्ने, महाश्यो, ऐसा कोई कार्य नहीं किया । यह उसकी तल्वार नहीं थी और न संगीन थी, जिसने इस शानदार और वृहत् साम्राज्यको जीता है । और न यह विजय सैनिक श्र्रताके वल्पर मिली है । यह मुख्यतया नैतिक विजय या नैतिक उत्कर्ष था, जिसका इंगलेंण्डको सही गर्व हो सकता है ।" 'भारतका सवाल' चुनाव आन्दोल्नमें विवादका आम सवाल वन गया । सी. आर. दासको कई स्थानोंसे सभाओंमें भाषण करनेका निमन्त्रण मिला । ओल्डमकी सभामें उन्होंने विधान परिपदकी "सफेद झूठ, धोखेकी टट्टी और निर्धक आडंबर" कहकर निन्दा की । हमारे यहाँ परिषदोंमें ऐसे आदमी हैं जिनको वहाँ होनेका कोई अधिकार नहीं है और ऐसे आदमी परिपदोंमें नहीं लिये गये हैं जिनके विना किसी देशकी भी विधान परिषद पूर्ण नहीं हो सकती । हम ठीक ढंगके भारतीयोंको चाहते हैं, परन्तु हिज ऐनसेलेंसी वाइसरायने इस बातकी विशेष परवाह की है कि सिर्फ एक खास साँचेके लोगोंको परिषदमें नामजद किया जाय, वे आदमी जो या तो कम बुद्धिके हैं या उनसे सहमत हैं—वे आदमी जो मेरे असंख्य देशवासियोंसे विल्कुल अनिमज्ञ हैं और जिनको आप लोग इस देशमें रईसीके नमूने कहेंगे।"

१८९२ की काँग्रेसका स्थान इलाहाबाद चुना गया और नौरोजी अध्यक्षताक िलए मनोनीत हुए ! परन्तु पार्लमेन्टके चुनावमें उनके विरोधीने मत-पर्जोकी दुवारा जाँचके लिए आवेदन किया जिसके कारण उनको इंगलैण्डमें स्कना पड़ा । इसलिए प्रथम काँग्रे हेने अध्यक्ष डक्ट्, सी. वैनर्जी इस अधिवेदानके भी अध्यक्ष बनाये गये । लार्ड काँसका भारत विधेयक अब कानून बन गया था और वैनर्जीने इसको "पहली खुद्याखन्नरी" बताया ! परन्तु उन्होंने आगे कहा "यह कानून वास्तवमें कुछ ज्यादा देनेका वादा नहीं करता" फिर भी "इस कान्नके अन्तर्गत बननेवाले नियमोंसे इसमें काफी विस्तारकी गुंजाइहा है।" काँग्रेसने 'राजभिक्ती भावना' से इण्डियन काँउन्सिल-ऐक्टको इस खेदके साथ, कि इस कानून द्वारा लोगोंको परिषदोंमें अपने निर्वाचित प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार नहीं दिया गया, स्वीकार-कर लिया।

नौरोजीके विरूद चुनाव याचिका खारिज कर दी गयी। अव उन्होंने अपनेको भारतके मामलोंमें पार्लमेंटके सदस्योंमें दिलचस्पी पैदा करनेके काममें लगा दिया और करीव डेढ़ सौ सदस्योंको एक पार्लमेंटकी समिति वन गयी। इंग्लैंडमें प्रचार करनेके लिए 'इण्डिया' नामक पत्रिका भी निकाली गयी।

१८९३ में लाहौरमें होनेवाले कांग्रेसके नवें अधिवेशनके अध्यक्ष फिर नौरोजो चुने गये जब नौरोजी हिन्दुस्तानके लिए रवाना हो रहे थे तो पार्लमेंटके करीब सत्तर अस्सी वामपश्ची और आयरलैण्डके छदस्योंने उनको पूरी सहायताका वचन दिया। उनके नेता हेविटने नौरोजीकी रवानगीसे दो दिन पूर्व उनसे कहा था "काँग्रेसमें जाकर अपने सहयोगियों से यह कहना मत भूलिये कि पार्लमेंटमें आयरलैंडके होमहलके सदस्य भारतीय जनताकी माँगके समर्थनमें आपके साथ हैं।" इनके अलावा "नौरोजीने कहा कि ऐसे सदस्य भी काफी वड़ी संख्यामें हैं जिनको हम अपना सहायक समझते हैं और जिनको हम जल्द ही भारतीय पार्लमेंट-समितिके सदस्य वनानेकी आशा भी करते हैं।" समितिकी सदस्यता यह कर डेढ़ सौ हो गयी।

भारतके नौजवान दादाभाईमें अगाध श्रद्धा रखते थे। जब वे घोड़ोंसे जुती एक

गाड़ीमें काँग्रेस पंडाल ले जाये जा रहे थे, तो कुछ विद्यार्थी वहाँ दोड़ते हुए आये और घोड़ोंको खोल कर खुद ही अध्यक्षकी सवारी खींचने लगे। सर विलियम हण्टरने टाइम्समें इस पर लिखा "स्वदेश पहुँचने पर जैसा स्वागत श्रीदादाभाई नौरोजीका हुआ, उसकी तुलना वाइसरायके भी केवल एक वारके स्वागतसे की जा सकती है। लाहीरमें महाराणा रणजीत सिंहके बाद ऐसा शानदार स्वागत किसीका भी नहीं हुआ।"

अपनेसे पहलेके अध्यक्षोंके भाषणोंसे नौरोजीके अध्यक्षपदसे किये गये भाषणमें स्वागत-योग्य भिन्नता थी क्योंकि इसमें देशकी आर्थिक और राजनीतिक दशापर प्रकाश डाला गया था। उन्होंने कहा कि १८६१ के अधिनियम द्वारा कोई भी सदस्य, गवर्नर जनरलकी पूर्व स्वीकृतिके विना सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक आय, या- इसपर किसी तरहका प्रभार डालनेके सम्बन्धका प्रस्ताव पुरःस्थापित नहीं कर सकता और न शाही फीजों या जहाजी वेडेके अनुशासन या उनके कायम रखनेके खर्च सम्बन्धी कोई भी प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है। इसके मानी यह हए कि जहाँतक हमारे धनके खर्च करने आदिका सवाल है, विधान परिषदका होना न होना वरावर है। (शर्म, शर्मके नारे)। पहलेसे पेश किये प्रस्ताव या उनसे सम्बंधित बहसके अलावा सदस्योंको अन्य विषयोंपर प्रस्ताव पेश करनेकी अनुज्ञा नहीं मिल सकती । इसलिए सरकार या उसके विभागोंसे उनके कामोंके लिए जवाबतलब करनेका कोई अवसर ही नहीं मिल सकता । भारत सचिवकी काररवाइयोंमें इतनी ताकत और प्रामा-णिकता होती है जैसे ऐक्ट बना ही न हो । यह निरंक्षश सत्ताका एक उदाहरण है। १८९२ के ऐक्ट द्वारा, आर्थिक मामलोंपर वहसके समय मत्विभाजन कराने, या इस ऐक्टमें पृछे गये किसी भी प्रश्नका उत्तर देने, या राय और प्रस्ताव वेश करनेका अधिकार किसी भी सदस्यको न होगा । कानृन अथवा नियम बनानेके उहें इयसे की गयी सभाओं में इस ऐक्टके अन्तर्गत वने नियम न तो वदले जा सकेंगे और न उनमें संशोधन किये जा सकेंगे।"

मालवीयजीने, जो उन चन्द लोगोंमें थे, जो हर कांग्रेसमें लोगोंको याद दिलातें रहते थे कि अंग्रेजोंने किस तरह भारतका शोषण किया था, १८९३ की कांग्रेसमें भाषण करते हुए कहा "वे बुनकर कहाँ हैं १ वे भिन्न-भिन्न उद्योग-धन्धोंसे अपना पेट पालनेवाले लोग आज कहाँ हैं १ और वे औद्योगिक वस्तुएँ कहाँ हैं जो प्रतिवर्ण इंगलैण्ड और दूसरे यूरोपीय देशोंमें वड़ी संख्यामें भेजी जाती थीं १ वे सब बीती वातं हो चुकी हैं। यहाँपर बैठे सब लोग विलायती कपड़े पहने हुए हैं। आप जहाँ भी जायें, हर जगह आपको विलायती माल व अंग्रेज कारीगरोंकी वनी चीजें भरी मिलंगी। देशी आदिमयोंके पास दयनीय जीविकानका एक ही साधन, खेती, बचा है। वे इस एकमान साधनने नहींके वरायर लाम उटाते हैं। नोकिरयों और व्यापारमें लोगोंको जितना पचास साल पहले लाम और मुनापा होता था आज उसका सीवाँ हिस्सा भी नहीं मिलता। फिर यह किस प्रकार संभव है कि देश सुखी हो १।"

जी. सुत्रमण्य ऐयरने जो अर्थशास्त्रके विद्वान थे, आँकड़ों और तथ्योंसे कांग्रेस अधिवेशनोंमें अंग्रेजों द्वारा भारतकी लूटखसोटका पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार कोलारकी सोनेकी खानोंसे हर साल बीस करोड़ रुपवेका सोना इंगलेण्ड भेजा जाता है और एक समय आयेगा जब मैस्रमें सिवाय कंकड़ पत्थरोंके और कुछ भी बाकी

१. वेसेण्ट, वही पुस्तक, पृष्ट ४२

न बचेगा। अपने लेखोंकै कारण उनको जेलमें वन्द कर दिया गया जहाँसे वे रोगसे जीर्ण-शीर्ण होकर लोटे।

लाहीर अधिवेशनके अपने एक भाषणके कारण श्री जी० के० गोखले सरकारके कोप-भाजन वन गये। भारत और इंगलैण्डमें सिविल सर्विसकी एक साथ परीक्षाएँ होनेके प्रश्नके ऊपर, और भारतीयोंके लिए जो कुछ भी नौकरियोंके द्वार खुले हैं उनकों वन्द करनेकी सरकारकी नयी नीतिकी निन्दा करते हुए उन्होंने कहा "अगर हर चीजको अविश्वासकी निगाहसे देखनेवाली हकूमत जल्द ही नहीं बदलती तो इस दरिद्र देशका भविष्य अधकार-मय है।" इस चेतावनीके उल्टे अर्थ लगाये गये और गोखलेको "शत्रु समझा जाने लगा तथा उनके पीछे खुफिया पुलिस लगा दी गयी।"

हर ऐसी बुराई, जिससे सरकार व दूसरे अंगरेजोंकी जेवमें धन जाता था और जिससे अंगरेजी सत्ताको कायम रखनेमें सहायता मिलती थी, सरकार द्वारा प्रश्रय पाती थी। कांग्रे सका विरोध भी इस नीतिमें वाधक नहीं वन पाया। वार-वार कांग्रे सने सरकारका ध्वान दिलानेकी कोशिश की कि पुलिस लूटती और जुतम करती है। जमीनोंकी लगान वस्लीका अस्थायी ढंग किसानोंको तबाह किये दे रहा है, न्याय और प्रशासनके संयुक्त होनेका वेजा फायदा उठाकर मैजिस्ट्रेट जिनको भी पाते हैं उन्हें डराते धमकाते हैं, और उनपर जुल्म करते हैं, राजद्रोहके नामपर लोगोंको जेलोंमें भर दिथा जाता है। पर इस सब विरोधका कोई फल नहीं निकला।

लगभग हर अधिवेशनमें कांग्रेसने इंगलैण्ड और भारतमें एक साथ सिविल सर्विसकी परीक्षा लेनेको माँग उठायी और जब १८९३ में लोकसभाने एक प्रस्ताव द्वारा इसको स्वीकार भी कर लिया तो भारत सिवयने अड़ंगा लगा दिया। उनका कहना था कि प्रस्तावके उत्पर वोट जर्ह्दों ले लिये गये थे। इस सिलिसिलें उन्होंने भारत और प्रान्तीय सरकारोंकी सम्मति चाही। सिवाय मद्रासके हर प्रान्तने इसका विरोध किया। भारत सिववने परीक्षा विषयक प्रस्तावको पाइलोंमें बन्द करके रख दिया। इसके विपरीत, सिविल-सर्विसमें जो कुछ थोड़ी-सी नियुक्तियाँ भारतीयोंकी हुई थाँ, सरकारने भारतीयोंको उनसे भी विचत करनेकी ठानी। १८९३ में सिविल-सर्विसमें एक हजार यूरोपियनोंके मुकावलेंमें रिर्प वीस भारतीय थे। कर्जन द्वारा नियुक्त पुल्सि-समितिने भारतीयोंको विशेष पुल्सिसे भी विचत कर दिया। यूरोपियनोंके लिए भारत शिकारगाह वन गया। विसमार्क जैसे आदिमयों-को भी भारतमें नौकरी करनेका लालच होने लगा। ''मै अंगरेजी झंडेके नीचे भारतमें नौकरी करना चाहता था' विस्मार्कने अपनी जवानीमें कहा था ''मगर फिर मैंने सोचा कि आखिर भारतीयोंने मेरा क्या विगाड़ा है ?''

१८९४ में मद्रास कांग्रेसमें आयरहैण्ड निवासी श्री अल्फ्रोड वेव (पार्लमेंटके सदस्य) अध्यक्ष निर्वाचित हुए । उन्होंने करण शब्दोंमें भारतकी दिखता और इंगलैंडकी प्रतिदिन बढ़ती हुई अमीरीका वर्णन किया । जब कि इंगलैण्डकी जनताकी सालाना आमदनी प्रति पनुष्य ३३ पौण्ड १४ शि० थी,भारतीयोंको केवल २ पौ० या उससे कुछ अधिक थी । १८४० और १८८८के वीच इंगलैण्डकी सालाना बचत ११०,०००,००० पौण्ड या ३००,००० पौंडसे

१. बेसेण्ट, वही पुस्तक पृ० १४७

२. वर्ररेण्ड रसेलकी पुस्तक फ्रीडम एण्ड ऑर्गनाइलेशनसे उद्धत ए० ४१६

ऊपर प्रति दिनकी आँकी गयी । यह सब धन और दौलत कहाँ से आयी ? वेबने स्वयं इसका उत्तर देते हुए कहा "१८८२ और १८८२में भारतमें फौजों के ऊपर खर्चा १,८३,५९,००० ६० हुआ (इसमें अफगानिस्तानके ऊपर होनेवाला १७००० ६० और मिसके ऊपर होने वाला १३,०८,००० ६० भी शामिल है)।१८९३में यह खर्च २७% बद्कर २३,८७७,००० ६० हो गया परन्त इस बढ़े हुए खर्चेका लाभ आँगरेजी और देशी फौजोंको वरावर वरावर नहीं हुआ । यूरोपीयन अफसरोंकी पंशनं ३७ भी सदी बढ़ा दी गयीं और देशी अफसरोंको केवल ११ भी सदी । आँगरेजी आम फौजी सिपाहियोंपर १३ भी सदी ज्यादा खर्च किया जाने लगा जब कि देशी आम फौजीशोंपर पहलेंसे भी ४ भी सदी कम।

"तुमसे कर द्वारा वस्ल किये हुए रुपवेसे वाहर किये जानेवाले खर्चकी रक्तम १८८२ में १,७३,६९००० रु० से बढ़कर १८९२में २,२९,११,००० रु० हो गयी। पिछले सालों में यह धन तुम्हारे कुल खर्चेका २२ फीसदी होता था, वादमें यह २५ फीसदी हो गया। कोई भी देश हमेशा इतना वड़ा बोझा नहीं उठा सकता। यह बढ़ोतरी सुद्रा-विनिमयकी दर बदलनेके कारण नहीं हुई।"

अधिवेशनमें दो नये लगनेवाले करोंपर काफी उत्तेजना रही। करोंमेंसे एक भारतमें वननेवाले दर्दके मालपर विदेशी मालके वरावर कर लगाना था—यह बात साफ थी कि करोंमें वरावरी लंकाशायरके कपड़ोंके मिल मालिकोंके इशारोंपर की गयी यी—और दूसरा १८६१के भारतीय पुलिस ऐक्टमें संशोधनके कारण, जिससे गड़वड़ोंके क्षेत्रोंमें रखी जानेवाली दण्ड-पुलिसका खर्चा करके रूपमें वस्तृल किया जाता । अंग्रेजों द्वारा शासित देशी रियासतोंमें अखवारों पर लगाये गये प्रतिवन्धों और इन नये करोंका कांग्रेसने काफी विरोध और निन्दा की। १८९१में विना राज प्रतिनिधि पोलिटिकल एजेंट की आशाके किसी भी अखवारके छपाने, सम्पादन व प्रकाशनपर सरकारने एक विज्ञिप द्वारा रोक लगा दी। इस कानृतकी अवज्ञा करनेवालेको रियासतसे निकालेकी सजा मिल सकती थी।

१८९५में पूनामें होनेवाले अधिवेशनमें मुरेन्द्रनाथ वैनर्ज ने अध्यक्षपद्मे भाषण करते हुए तथ्यों और आँकड़ोंसे यह सिद्ध कर दिया कि १८९२के मुधार सिर्फ ढोंग हैं और वास्तव में इंगलैण्ड भारतको आर्थिक दृष्टिसे वर्षाद कर रहा है।

पूना काँग्रंसमें (१) सर्वाच विधान-परिपदमें पेश किये गये वकालती विधेयक, (legal practitioners bill) पर जिसके द्वारा प्रान्तोंमें वकीलोंको जिला जर्जी और मालगुजारीके कमिश्नरोंके अधीन कर दिया गया था, विरोध प्रकाश किया। (२) सरकार से प्रार्थना की गयी कि वह तीसरे दर्जेके मुसाफिरोंकी शिकायतें दूर करे। (३) सर्वोच्च परिपदमें मध्य-प्रदेशका एक प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओंसे सलाह किये विना !नामजद करनेकी निन्दा की गयी और इसकी अवनतिकी तरफ जाना वतलाया। (४) सरकार में मांग की गयी कि दक्षिणी अफ्रीकाके भारतीयोंकी कटिनाइयाँ दूर को जायँ (६) माँगकी गयी कि भारतके वाहर हुए युद्धोंके खर्चका सारा भार भारतपर न डाला जाय।

१८९६ का अधिवेशन कलकत्ते में हुआ, जिसकी अध्यक्षता, वम्बईके वकील और उसी साल केन्द्रीय विधान परिपदके निर्वाचित सदस्य श्री रहीमतुल्ला एनः सायनीने को । उन्होंने वम्बई विश्वविद्यालयके फेलोकी हैसियतसे, वम्बई कारपोन्शनके अध्यक्षके पदसे और वम्बई विधान परिपदके सदस्यकी हैसियतसे, तीस वर्षोंने सार्वजनिक कार्मोमें

हिस्सा लिया था । इसी अधिवेशनमें श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुरने 'वन्दे मातरम' गाया था जो वादमें राष्ट्रीय गीत वन गया । ''जिस समय कविने अपनी कोयल सी सुरीली आवाजमें यह गाना गाया जिसके साथ बाजा उनके भाई ज्योतीन्द्रनाथ बजा रहे थे, उस समय अधिवेशन मन्त्रमुग्ध सा हो उठा । उपस्थित श्रोताओं की रगों में विद्युत् लहरी-सी दौड़ गयी।''

इसी साल देशके वह भागमें फिर एक भयंकर अकाल पड़ा। विहार, उत्तर-पिक्चिमी स्वा, पंजाब, मध्यप्रदेशके कुछ भागों, वम्बईके कुछ जिलों, मद्रास और मैस्रमें पानी न बरसा और स्वा पड़ गया। एकदमसे गल्लेकी कीमत पचाससे सौ फी सदी वढ़ गयी। वे लोग जो रोज कुआँ खोदते और पानी पीते हैं, बुरी दशामें थे। कई जगहोंसे गल्लेके लूटने और दंगा-फसाद होनेको खबरें आयों। जैसा कि श्रीसायनीने अपने भाषणमें वतलाया, सरकारी आँकड़ोंके अनुसार भारतमें हर साल ५०७ ६ लाख टन गल्ला पैदा होता है और हर आदमी पीछे तीन पाव प्रतिदिनके हिसाबसे भारतकी आवश्यकता ५०८ लाख टन गल्ला पोलानकी थी जिसका मतलव यह हुआ कि भारत अपनी जल्रत भरके लिए गल्ला पैदा कर लेता था, मगर चूँ कि भारतको हर साल २९ लाख टन अनाज विदेशोंको लाचारीसे निर्यात करना पड़ता था, एक करोड़ जनताके खानेके लिये अनाज नहीं वचता था। कमीवाले सालमें इस एक करोड़ जनताकी भुखमरीका असर दूसरे कई लाख आदमियोंपर पड़ता था, और वे सबलोग अधमूखे और दुर्दशायस्त रहते थे। निर्यात पैदावारपर एक जबरदस्त वोझा था जिसके कारण अकालके लिए अनाज इकट्टा नहीं किया जा सकता था।

१८९६ की कांग्रे सक मुख्य प्रस्तावमें देशकी दुर्दशा दिखलायी गयी थी। प्रस्तावमें कहा गया था "कांग्रे सका यह अधिवेशन लगभग पूरे देशमें अकाल पड़नेपर घोर चिन्ता प्रकट करता है और इस अकाल-स्थित व पिछले सालोंके अकालोंका मूल कारण जनताकी भवंकर दिदताकों मानता है। अत्यिधिक कर, लोगोंकी आमदनीको ज्यादा आँककर ज्यादा कर लगाने और इस प्रकारसे भारतकी दौलत लूटकर फौजी व अन्य सरकारी विभागों द्वारा फजूल खर्चीसे उसका दुरुपयोग करनेको नीति भारतीय जनताकी मबंकर गरीबीका असली कारण है। लोग इतने गरीव हो गये हैं कि अनाजकी जरा-सी कमी हो जानेसे वे एकदमसे असहाय हो जाते हैं। उनको सरकारी मदद या निजी दानकी सहायताके बलपर ही भुखमरीसे वचाया जा सकता है। कांग्रे सकी रायमें, किफायत और कम खर्चेकी नीति अपनाकर, देशके साधनोंका सदुपयोग कर, विभिन्न देशी उद्योग धन्धों और कलाओंको प्रोत्साहन देकर, जो आज लगभग खत्म हो गयी हैं, नये उद्योगधन्धे व कलाओंको खोलकर अकालकी पुनराच्चित्त रोको जा सकती है।" भारतको अनाजका निर्यात कर वाहरसे कारखानोंका माल मँगाना पड़ता था।

कांग्रेसने यह भी माँग की कि (१) जवतक जाँच समिति द्वारा किसी राजा या सरकारका कुशासन या बुरा व्यवहार सिद्ध न हो जाय, उसको गद्दीसे न उतारा जाय। (२) वम्बई और मद्रासकी प्रशासन कार्यकारिणीमें भारतीय सदस्योंको लिया जाना चाहिये।

अध्याय ७

आतंकवादका आरम्भ

.१८९७ में भारतीय आकाशपर प्राकृतिक संकटोंके—भूकम्प व प्लेगकी महामारीके— काले यादल छाये हुए थे। राजनीतिक वातावरणमें भी राजनीतिक हत्याओं, वालगंगाघर तिलककी केंद्र, कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओंके निष्काशन, तथा स्वशासन संस्थाओंके अधिकार-क्षेत्रमें संकीर्णताकी नीतिसे उथल-पुथल मची हुई थी। जैसा कि स्वामाविक था, इस दीरके समय राजनीतिक सिक्षयतामें भी काफी वृद्धि हुई। यद्यपि तिलक अपने कांग्रेस अधिवेशनों के भाषणों और अपनी दो पत्रिकाओं — मराठीमें कैसरी और अंग्रेजीमें मराठा — दारा प्रसिद्धि पा चक्के थे. वे भारतीय राजनीतिमें १९९७में एक नये नक्षत्रकी भाँति चमके । अकाल पहिले ही बरवादी ला चुका था और उसके वाद कोढ़में खाजकी तरह प्लेगने भी एक वहे क्षेत्रको आकान्त कर दिया। वस्वई और पुनामें प्लेगके कारण त्राहि त्राहि मच गयो। सरकारने प्लेगकी रोक-थामके लिए कुछ उपाय किये और श्री डन्लू सी. रंडको प्लेग कमिश्नर नियुक्त किया । प्लेगवालींके लिए अलग जगहें नियत कर दो गयीं जहाँ इस रोगसे पीडित रोगी ले जाये जाते थे। तिलक्तने इस कार्यमें सरकारको सहयोग दिया और स्वयं भी एक प्लेग-अस्पताल खोल दिया । परन्तु जब बीमारोंके सहायतार्थ नियुक्त फीजियोंने औरतोंकी वेइण्जती करने और पूजाके स्थानोंको गन्दा करनेके अलावा आदिमयोंको तरह-तरहसे परेशान करना ग्रह्म कर दिया तो तिलकने अपना सहयोग वापस ले लिया और इस मामलेकी चर्चा अपने पत्रोंमें की । दक्षिण भारतके दो सरदारी वलवन्त राव नात् और हरि-पंत रामचन्द्र नातुने प्लेग द्वारा लायी हुई वर्यादी और फोजियोंकी ज्यादतीका एक विस्तृत विवरण, इंगलैण्डमें कांग्रेस नेता श्री गोपालकाण गोखलेको लिखकर भेज दिया। गोखलेन इसका निम्नलिखित संक्षिप्त विवरण अंग्रेजी अखबारोंमें प्रकाशित करवाया-

"प्रतीत होता है कि दूसरे तरीकोंके होते हुए भी फीजी सिपाहियोंने मकानोंका निरीक्षण, विना जरूरत, जबरदस्ती बुसकर किया था। दुकानदारों व मकानमालिकोंकी अनुपरियतिमें दुकानों व मकानोंके ताले तोड़ डाले और मकान व सामानकी रक्षापर जरा भी
ध्यान नहीं दिया। फीजियोंके खिलाफ शिकायतींपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। एक फीजी
ने एक हिन्दू महिलापर आक्रमण किया और जब श्री नातृने इसकी शिकायत सब्त
सहित अधिकारियोंसे की तो भी इसको दवा दिया गया। फीजियोंके ऊपर बद्य न चल्नेके
कारण उनके विरुद्ध शिकायतोंकी अवहेलना की जाती है। एक आदमीके बीमार पड़नेपर
इसके पास-पड़ोसके लोगोंको संकामक कैम्पोंमें जबरदस्ती ले जाकर विना सामानके छोड़
दिया गया। उनके पास तन डॅकनेको कपड़ा भी न था और घरोंपर उनकी गाय, भेंग और
घोड़े विना देख-रेख करनेवालोंके मों ही छोड़ दिये गये थे। विना आबस्यकता एक आदमीको अस्पताल भेज दिया गया। जाँचमें माल्म हुआ कि उसको प्लेग नहीं हुआ है, मगर घर
वापस आने पर उसे माल्म हुआ कि उसका सारा सामान तहस-नहत कर दिया गया है।

उसकी वीवी व उसके रिश्तेदारोंको जवरदस्ती संकामक कैम्पोंमें भेजकर वहीं रोक लिया गया है। फोजियोंने मन्दिरोंको भ्रष्ट किया और श्री नात्का विश्वास है कि उनके निजी मन्दिरको केवल इस कारण अपवित्र किया गया कि उन्होंने फोजियोंकी शिकायत करनेका साहस किया था। एक बुड्ढे आदमीके जाँच करनेवालोंको यह विश्वास दिलानेपर भी कि वह प्लेगसे पीड़ित नहीं है उसे जाँचमें वाधा पहुँचानेके नामपर कई घण्टे जेलमें वन्द रखा गया। वाधासे मतलव यह था कि उसने विश्वास दिलानेमें देर की। स्वयंसेवकोंको सेवाका पुरस्कार क्या मिला ? अपमान। उनके मुझावोंको उनकी घृष्टता समझा जाता था। यह वात आप सव लोगोंको माल्यम है कि आपकी मुसलमान प्रजा अपनी औरतोंके परदेके मामलेमें किस कदर ज्यादा भावुक है, और जब श्री नात्ने यह मुझाव पेश किया कि मुसलमान घरोंकी जाँचके लिए मुसलमान स्वयंसेवकोंकी सेवाएँ इस्तेमाल की जावँ तो उन्हें जवाव मिला कि उनका यह व्यवहार अनिधकार चेष्टा है और उनकी भी सेवाएँ समाप्त कर दो गयीं। श्री नात्ने इस मामलेकी शिकायत हाकिमोंसे को और कहा कि जाँच पड़ताल के तरीके सरकारी नियमोंकी भावनाके विरुद्ध हैं, जिनके कारण वड़ा असंतोष पैलता जा रहा है। ""

अपने इस 'अपराध'के कारण नात् भाइयोंको १८२७ के पुराने और छुप्तप्राय वम्बई-कानूनकी पचीएवीं धारा, जिसकी तुलना १८१८ के वंगाल-कानूनसे की जा सकती है, के अन्तर्गत, दो वपाँके लिए देश-निकालेकी सजा मिली। भारत वापस आने पर गोखले भी, अंग्रेजी अखवारोंमें प्रकाशित अपने वक्तव्योंके कारण, मुसीवतमें पड़े और उनको क्षमायाचना करनी पड़ी। सवाल यह उठा कि क्या गोखले अपने वक्तव्योंको प्रमाणित कर सकते हैं ? अवश्य! परन्तु फिर भी उन्होंने क्षमा माँग ली, क्योंकि उनके वक्तव्य, नात् भाइयोंके अलावा, कितपय गण्यमान्य व्यक्तियोंकी दी हुई खबरोंके आधारपर थे, और साबित करनेके लिए उन्हें इन सब व्यक्तियोंके नाम बताने पढ़ते। इसीलिए गोखलेने क्षमा माँगना अयस्कर समझा। गोखलेके जीवनी-लेखकके अनुसार "यह चर्चा आम तौरपर फैली हुई थी कि टाइम्सके सम्पादकने गोखलेका माफीनामा लिखा था और श्री रानाडेकी सम्मितसे गोखलेने उसपर विना हिचक दस्तखत कर दिया।" आगे वे लिखते हैं "इस माफीनामेके कारण जनमत गोखलेके इतना खिलाफ हो गया कि अमरावती कांग्रेसमें उनका साहस भाषण करने तकका नहीं हुआ और अगर वे वोलनेका साहस करते भी तो जनता उनके 'कायरपन' पर उन्हें विना लिखत किये न सुनती।"

२२ जून १८९७ को सम्माजीकी रजत जयंती मनायी गयी। उसी दिन जब रातके अंधेरेमें प्लेग किमरनर श्री रेंड, उनके सहकारी लेकिस, लेफ्टिनेण्ट आइस्ट और उनकी पत्नी राज-भवनसे लौट रहे थे, किसीने अंधेरेसे निकलकर रेंडको गोली मार दी और वे तत्काल वहीं देर हो गये। दूसरी गोलियोंके लक्ष्य आइस्ट और लेकिस थे। लेकिस तो बच गये परन्तु आइस्ट मारातीय अखवारोंके गुटने इन हत्याओंके पीछे दुर्भिसन्धि हुँद निकाली। संसारन्यापी इस

१. १८९७ की कांग्रेसमें राष्ट्रपति श्री सी० शंकरन नायरका भाषण

२. एन० सी० केलकर—लाइफ एण्ड टाइस्स ऑफ लोकमान्य तिलक, पृष्ठ-४१७

३, वही पुस्तक-पृष्ठ ४१५

उत्सवके दिन हुई इन राजनीतिक हत्याओंने, अखवारोंके गुटके अनुसार, यह सिद्ध कर दिया कि इनके पीछे ऐसा गहरा पड़बंत्र था जिसकी तैयारी केवल पढ़ेलिखे चालाक व्यक्ति कर सकते थे। पनामें यटित हर घटनाको इस पहुबंत्रका अंग मान लिया गया। देशी अखवारों और शिक्षित भारतीयोंपर आक्षेप किये जाने लगे जिनमें ऐसी कट्टता थी जैसी गदरके बाद पहले नहीं देख पड़ी थी। प्रति-वन्यक कानुनोंकी जोरोंसे भाँग की जाने लगी। भारतीयोंको शिक्षा देनेकी नीतिका विरोध किया जाने लगा। इंगलैण्डके अखवारींको भड़काया गया । यहाँतक कि यूरोपियनोंमें त्रास फैल गया । दिक्षित भारतीयों तथा देशी अखवारींपर किया गया हमला कायरतापूर्ण और अत्यन्त कटु था। इस वातपर खेद प्रकट किया गया कि देशी लोग गदरका सबक भूल गये हैं और यह सुझाव दिया गया कि वैसा ही सबक पाने पर ये लोग सीधे हो जायेंगे । यह दुराग्रह किया गया कि देशी अखवार राजद्रोही हैं और वे ही हत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। आंग्ल-भारतीय अखवारोंने प्लेग सम्बन्धी सरकारी नियमोंकी कड़ी आलोचना करनेवाले तिलकको सजा देनेकी माँग की । अंगरेजी अखबारोंके अनुसार, इस द्वेपपूर्ण हमलेसे आंग्ल-भारतीय समाजमें फैले हुए बासने, व अँगरेजी जनताको गुरसा दिलानेमें मिली हुई दुर्भाग्यपूर्ण सफलताने भारत-सचिव लाई सेण्डहर्स्टको सस्त कदम उठानेके लिए लाचार कर दिया । ऐसा समझा जाता है कि यदि उनपर यह दवाव न पड़ता तो वे इतनी कठोरता न वरतते।": र

अव तिलक और कुछ भारतीय पत्रिकाओं के सम्पादकों की वारी आयी। उनको कैद करके भिन्न-भिन्न सजाएँ दो गयों। एक देशी अखवारने प्रकाशन वन्द करते समय इन शब्दों में विदाई ली—"आजकी परिस्थितमें अखवार चलाना सम्भव नहीं है। इसलिए, हम लोग जो अपना पेट दूसरे उपायों से भर सकते हैं, आपसे विदाई लेते हैं। अब हमको प्रकाशित खबरों और लेखोंकी जवाबदेहीं के लिए हिण्टी कमिस्नरके वँगलेपर रोज हाजिरी देनेकी कोई जरूरत नहीं है।"

१८९६-९७ के अकाल और महामारी से उप्र राजनीतिको बहुत बढ़ावा मिला। अग्रान्तिकी एक नई लहरके लक्षण प्रकट होने लगे थे, जिसको समझनेके लिए हमें तिलक और उनके कार्यों अवगत होना पहेगा। १९१० में प्रकाशित अपनी किताय हिल्दयन-अनरेस्ट'के लिए जब वैलेंटाइन शिरोल सामग्री इकट्ठो कर रहे थे तो उन्हें सलाह दी गयी थी कि यदि वे भारतीय अग्रान्तिके मनोविज्ञानका अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें तिलकके जीवन चरित्रसे ग्रुक करना चाहिये। शिरोलके कथना नुसार, ''यह सलाह अम्हय थी क्योंकि यदि कोई भी आदमी 'भारतीय चेतना'का जनक होनेका दाया कर सकता है तो वह वालगंगाधर तिलक हैं।''

तिलक चितपावन ब्राह्मण थे, और उस समयके चितपावन ब्राह्मणीके वारमें द्विरीलने कहा है कि "उनकी महान शासनात्मक योग्यताओंका लोहा मानना पड़ता है। सरकारी कर्मचारियों में आज भी उनकी संख्या उसी प्रकार अधिक है जिस प्रकार कि नाना पड़नबीस (जो स्वरं चितपावन ब्राह्मण थे) के जमाने में थी। हमारे समयके सबसे अधिक विद्वान और प्रगतिशील भारतीय चितपावन ब्राह्मणों में से हैं और उनमें से अनेकने अंग्रेजी सरकारकी लेवा राज-भक्ति और ईमानदारीसे की है। द्वायद यह सही है कि उनमें से अधिकां हो दिलों में

१. राष्ट्रपति श्री नायरका भाषण

पिछले सौ सालोंसे, पेशवाके पतनके वादसे, अंग्रेजी शासनके विरुद्ध पृणाकी परम्परा चली आ रही है—एक अमर-आशा कि शायद किसी दिन यह हुकूमत खत्म हो और उनकी सत्ता का सितारा चमके । यदि गदर-कालीन नाना साहव (चितपावन ब्राह्मण) और उनके साथियोंके श्र्रताके कारनामों या १८९७ के प्नाके रामोशी विद्रोहको छोड़ भी दिया जाय तो भी ये प्नाके ही अखवार थे जो ज्यादातर ब्राह्मणों द्वारा निकाले गये थे, जिन्होंने अंग्रेजी शासन और शासकोंके खिलाफ लड़ाईकी अगुआई की, जिसके परिणामस्वरूप १८९७ का 'प्रेस-एक्ट' बना।'' पेशवाओंके शासनकालमें राज्यके मुख्य पदोंपर चितपावनोंका ऐसा एकि धिकार हो गया था कि मरहठा साम्राज्य वास्तवमें चितपावन साम्राज्य वन गया था। शिरीलके अनुसार रेंड और आइस्ट की हत्याएँ करनेवाला कोई चितपावन ब्राह्मण ही था।

जब तिलक्तने १८८०-९० के पूर्वार्द्धमें सार्वजनिक कार्मोमें हिस्सा लेना शुरु किया उस समय रानाडे वम्वईके एक प्रसिद्ध नेता थे। रानाडे नरमदलीय राजनीतिज्ञ थे, परन्तु तिलक सब्र रखनेमें असमर्थ थे। रानाडेके विरोधमें वे उग्रदलीय हो गये। उन्होंने अपने आपको, अंग्रेजी शासनके विरुद्ध लोगोंके दिलोंमें नफरत फैलाकर उन्हें लड़नेके लिए तैयार करनेके काममें सम्पूर्ण शक्तिसे लगा दिया। "वे 'सीधी-लड़ाई'के महत्वके प्रशंसक थे और उस समयकी कांग्रे समें प्रचलित वैधानिक लड़ाईके ढंगको हेय समझते थे। आहाय यह कि भारतमें वामपक्षी दलके वास्तविक जनक तिलक ही थे।" नौजवानोंके संघटन बनाये गंये जहाँ उनको लकड़ी चलाने व कुरती लड़नेकी शिक्षा दी जाती थी। १९१८ में सरकार द्वारा नियक्त राजद्रोह जाँच समितिकी रिपोर्टके अनुसार उत्सवींपर पर्चे वाँटे जाते थे जिनमें "मरहठोंको शिवाजीकी भाँति विद्रोह करनेको उकसाया गया। पचोंमें ऐलान किया गया था कि विदेशी सत्ताकी गुलामी हर दिलको चोट पहुँचाती है और उनको उकसाया गया कि विदेशी सत्ताको उखाड़ फेंकनेके लिए पहला कदम धार्मिक विद्रोह है।" तिलकके मतमें भूँग्रेजोंको हटानेके लिए कोई भी हथियार अच्छा है, और इसके लिए उन्होंने अँगरेजोंके खिलाफ व देशभक्तिकी भावना भरनेके लिए नाटकों, त्योहारों व धार्मिक उत्सवोंका माध्यम चुना । इसी प्रकारका एक माध्यम गणपति-उत्सव था।" दक्षिणके प्रत्येक प्रमुख केन्द्रमें गणपति समाज स्थापित किये गये । प्रत्येक गणपति समाजकी अपनी नाटक व भजन-मण्डली हुआ करती थी। उत्सवोंपर गाने गाये जाते थे व नाटकं खेले जाते थे, जिनमें पोराणिक कथाओं की आड़में विदेशी हुक्मतके खिलाफ गृणाका प्रचार किया जाता था। इनमेंसे एकमें जान-वूझकर लार्ड कर्जनपर व्वंग किया गया था। नाटकमें यद्यपि चरित्र सब पौराणिक थे मगर अपार दर्शकोंकी भीड़में सब समझते थे कि नाटकका असल इशारा किसकी तरफ है। सब इस रूपकका असली उद्देश समझ रहे थे—इंगलैण्डकी एक कमजोर सरकारने वाइसरायके हाथ सब सत्ता सौंप दो है और वे उसका इस्तेमाल भारतका अपमान करनेमें कर रहे हैं। नरमदल्वादी वैधानिक उपायोंके पक्षमें थे। उग्र दलवादी उस समयकी प्रतीक्षा कर रहे थे जब इन नरम उपायोंकी व्यर्थता सिद्ध हो जायगी, तब तीब आघातोंका अवसर आयेगा । अत्याचारी शासकको विना कठिनाई ठिकाने लगा, उसके साथियोंको

१. इण्डियन अनरेस्ट, पृ० ४०

२. जॉन किमग द्वारा सम्पादित 'पोलिटिकल इण्डिया' का एल० एफ० रश्चुक विलियम्स द्वारा लिखित 'इण्डियन नेशनल कांग्रेस' अध्याय

तल्वारके बाट उतार दिया जायगा । स्वदेशको स्वतन्त्र कर उग्रदल्वादी आक्रमणकारियोंसे देशकी रक्षा करनेमें समर्थ होंगे । रूपकका असली आश्वयं यह था जो सब दर्शक समझ रहे थे । दर्शक अत्याचारी शासकके ऊपर शृथू करते, नरम दलवालोंकी कायरतापर रोप प्रगट करते, उग्रदलवालोंकी वीरताकी प्रशंसा करते और अन्तमें अत्याचारियोंके मर्दनपर उनमें सन्तोपकी लहर दौढ़ जाती । तिलकने इस शक्तिशाली नाटकका उपयोग अपने पक्षका औचित्य दिखानेके लिए किया ।"

इन नाटकों में बिदेशियों को म्लेच्छ और उनसे सहयोग करनेवालों को शतुके रूपमें दिखलाया जाता । उत्तेजनापूर्ण जुल्ल निकाले जाते और पुलिसके खिलाफ नारे लगाने के लिए इन अवसरों का उपयोग किया जाता । इन नारों से पुलिसवालों को कोष आता, कमी-कभी मुकदमें भी चलाये जाते थे। इस सम्बन्धमें अधिकारियों द्वारा की गयी काररवाईका इस्तेमाल जनताको और जागरूक करने तथा प्रदर्शन करने के लिए किया गया।

लोगोंके दिलोंमें शिवाजीकी याद ताजा करके तिलकने शिवाजीको एक बार फिर जीवित शक्ति बना दिया। इसका आरम्भ उन्होंने नष्टप्राय पड़ी हुई शिवाजीकी समाधिको ठीक करनेके मुझावसे किया। आत्मसम्मान जगानेके लिए उन्होंने लोगोंको भरसंना की कि उन्होंने अपने राष्ट्रीय नेताके अन्तिम विश्राम-खलको नष्ट हो जाने दिया है। शिवाजीको अग्रिम पंक्तिमें लाकर तिलकने राष्ट्रव्यापी प्रचार शुरू किया जिसके परिणामस्वरूप १८९५ में दिशाणों राजनीतिक और सामाजिक कार्योंके कई केन्द्रोंमें उत्सव मनाये गये।

क्या शिक्षत और क्या अशिक्षित, दोनोंमें ही तिलक दिन प्रति दिन अधिक प्रसिद्ध होते जा रहे थे। १८९५ में स्थानीय संस्थाओंकी ओरसे यम्बई विधान परिपदमें भी वे अपना सरकार विरोधी आंदोलन चलाते रहे। भारतमें वे अकेले सदस्य थे जिनके भाषण निर्भय और ओजस्वी होते थे। १८९६ में जब देशके कई भागोंको एक जबरदस्त अकालने प्रस्त लिया तो तिलकने दक्षिणमें 'कर-न-दो' आन्दोलन चलाया—उनके सन्देशवाहकोंने जगह-जगह जाकर प्रचार किया कि सरकारने एक सीमा नियत कर दी है जिससे ज्यादा प्रमल खराब होनेपर लगान विलक्षल भाफ कर दिया जायगा। रैयतोंने उनका यकीन किया और जब सरकारी कारिन्दे वहाँ लगान बस्लीके लिए गये तो उन्होंने पैसा देनेसे इन्कार कर दिया। वात बढ़ी "यहाँतक कि बम्बईमें सम्मार्गर्का मृति नष्ट कर डाली गयी, चर्च मिशन हालको आग लगानेकी कोशिश की गयी और नरम दलवाले हिन्दुओंपर जिन्होंने इस कार्य-क्रममें साथ देना अर्खाकार किया, बहुधा हमले किये गये।"

अंग्रेज-विरोधी आन्दोलनको चलानेके लिए तिलकको रूडिवादियोंसे भी हाथ मिलानेमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। १८९० में भारत-संचिवने सरकारसे केन्द्रीय परिपदमें सम्मित-विधेयक (कंसेन्ट विल) पेश करनेको कहा जिसके द्वारा हिन्दू-कन्याओंकी विवाह-योग्य उम्र दससे बढ़ाकर वारह की जानेवाली थी। इस विधेयकको अपने धर्मपर किया गया आक्रमण घोषित कर वंगालके अखवारोंने विरोधका त्कान खड़ा कर दिया। बिटिश इण्डिया एसोसियेशनने भी इसमें साथ दिया। अखवारोंमें इसकी अनुआई, अग्रेजी साप्ताहिक अमृत-वाजार पत्रिकाने की। कुछ समय वाद इस आन्दोलनमें सर रमेशचन्द्र

१. सर फ्रांसिस यंग हस्बेण्ड, ढान इन इण्डिया (१९३०) पृष्ट ३६-३७

२: शिरौल 'इंडियन अनरेस्ट', ए० ४०-४८

मित्तर (हाईकोर्टके न्यायाधीश और वादमें विधान-परिपदके सदस्य) और महराजा जतीन्द्र मोहन ठाकुर-जैसे लोग भी सम्मल्ति हो गये। इस विधेयकिके विरोध-प्रदर्शनमें कलकत्तेमें एक सभा की गयी जिसमें एक लाखसे अधिक व्यक्तियोंने भाग लिया। सम्प्रति-विधेयकका विरोध भिवष्यके राजनीतिक आन्दोलनकी तैयारी था। महाराष्ट्रमें इस आन्दोलनका नेतृत्व तिलक्षने किया। विधेयकके पक्षमें डा० भंडारकर, न्यायाधीश तेलंग, एन० जी० चन्द्रावरकर जैसे हिन्दू सुधारकोंके होते हुए भी, तिलक संघटन और प्रचार-कार्यमें आगे वढ़ते गये। केसरीमें विधेयकके पक्षमें खड़े होनेवाले हर हिन्दूको हिन्दुक्के प्रति विश्वासघाती और स्वधम त्यागी कहा गया। इसका सामाजिक पहल् जो कुछ भी रहा हो, तिलकने विधेयकको अपने अग्रेज-विरोधी प्रचारका एक और हथियार बना लिया। यूरोपियन लेखक तिलकको भारतीय-चेतनाका, अग्रुणी' मानते थे।"

अव हम तिलक के अपर चलाये गये मुकदमे और सजापर ध्यान दें। जैसा कि कहा जा चुका है तिलक ने (शिवाजीका) अपने आंदोलन की धुरी बनाया था और लोगोंकी भा चुकता को उभा ड़ने के लिए, तिलक के अनुयायी शिवाजीकी स्तुतिमें ऐसे गीत गाते थे:— "भा उकी तरह गुणगान करने से स्वतंत्रता नहीं मिल जायगी। आजादी के लिए शिवाजी व वाजीकी भाँति साहसी कार्य करने पड़ेंगे। यह बात समझते हुए तुम लोगोंको कमर कसकर ढाल तल बार उठानी पड़ेगी। और राष्ट्रीय युद्ध के अवसरपर हम जीवनकी बाजी लगा देंगे। अपने धर्मको नष्ट करने वाले के रक्त से हम धरती सींच देंगे। जब तुम स्त्रियोंकी भाँति घरोंमें बैठकर कहानियाँ सुनोगे, हम बीर गतिको प्राप्त होंगे।"

जिन दो लेखोंपर आपित्त की गयी थी वे सम्पादकीय नहीं थे, विश्व उनमें एक 'शिवाजीके उद्गार' शीर्षक किवता थी और दूसरा दो प्रोफेसरोंके शिवाजीके ऊपर दिये गये भाषणोंकी रिपोर्ट थी। लवेटके अनुसार किवतामें शिवाजीको नींदसे जागकर एक समयमें अपने साम्राज्यकी वर्तमान दुर्दशापर शोक प्रकाशित करते दिखाया गया था। अत्याचारीका नाश करके उन्होंने संसारका भार हलका किया था और देशको स्वराज्य दिलाया था। परन्तु अव विदेशी देशका धन लूटे लिये जा रहे थे, सुख-समृद्धि नष्ट हो चुर्का है, और इनके स्थानपर अकाल और महामारी देशको राहुकी तरह प्रसे हुए हैं। ब्राह्मणोंको कैद किया जाता है, गायोंका प्रति दिन वध होता है। विना संतोषजनक कारण वताये हुए भी 'श्वेत पुरुप' न्याय-दंडसे वच जाते हैं। औरतोंको रेलके डिक्वोंसे धसीट लिया जाता है। जब अंग्रेज भारतमें व्यापारीकी हैसियतसे आये थे तो शिवाजीने उनकी रक्षा की थी और अव अँग्रेजोंको वारी थी कि शिवाजीकी प्रजाको संतुष्ट रखकर कृतज्ञता प्रदेशित करें।"

दूसरे लेखमें एक प्रोफेसरने लिखा था कि "शिवाजी नैतिक आचार-विचारसे परे मनुष्य थे। हर मराठे और प्रत्येक हिन्दूको शिवाजी-उत्सव मनाना चाहिये। हम सब अपनी खोयी हुई आजादीको पुनः प्राप्त करनेकी चेष्टा कर रहे हैं।" दूसरे प्रोफेसरने लिखा कि फांसको क्रान्तिमें भाग लेनेवालोंने यह अभियोग अस्वीकार किया कि उन्होंने हत्याएँ की हैं, विलक दावा किया कि उन्होंने केवल अपने रास्तेके काँठोंको हटाया है। वही तर्क महाराष्ट्रके लिए क्यों नहीं ठीक है ? अन्तमें तिलककी टिप्पणी छपी—'महापुरुपोंपर सर्वसाधारणके

^{ু .} लवेर-वही पुस्तक (?) पृष्ठ ४८

[.] २, वही पुस्तक पृष्ठ ५०

नैतिक आचार-विचारके नियमोंके प्रतिवन्ध नहीं लाग् हो सकते । शिवाजीने अफजल खाँका वध करके पाप किया या नहीं ? इसका उत्तर स्वयं महाभारतमें मौजूद है । गीतामें धीकृणाने अत्याचारी भाई-वन्धुओं और गुरुआंको भी मारनेका उपदेश दिया है ।

इन लेखों के प्रकाशित होने के टीक एक सप्ताह वाद पृनामें हत्याएँ हुई । ऑग्ल-भारतीय अखबारोंने तत्काल ही राय दो कि हत्याएँ इन लेखों हारा प्रेरित हैं। अधिकारी इससे सहमत थे। तिलकपर मुकदमा चला और १४ सितम्बर १८९७ को उन्हें १८ महीनेकी कड़ी कैंदकी सजा सुना दी गयी। न्यायसम्बोंमें पाँच यूरोपियन, तीन भारतीय और एक यहूदी थे। यूरोपियनों और यहूदियोंने उनको दोषी पाया और भारतीयोंने निर्दाप। श्री तिलक प्रथम राजनीतिक बन्दी थे। इससे देशभरमें उत्साहकी लहर दोड़ गयी।

जेलमें तिलक्क साथ एक साधारण कैदीकी माँति व्यवहार किया जाता जिससे उनका स्वास्थ्य काफी लराव हो गया और उनका वजन तेजीसे घटने लगा। वम्बईके एक वकीलने इंगलैण्डमें हॉवर्ड एसोसियेशनके मन्त्रीको इसकी स्चना दी। यह संघटन जेलके जीवनको सुधारनेकी चेष्टा करता था। तिलक्के मामलेकी जाँचके परिणामस्वरूप हॉवर्ड एसोसियेशनने भारतमें राजनीतिक वन्दियोंके साथ व्यवहारपर एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्तावमें कहा गया था कि ''प्रेस-कान्न (प्रेस-लॉज) की वास्तविक और कथित अवज्ञा करनेपर दिये गये दण्डोंके सम्बन्धमें भारतसे कई स्चनाएँ अभी हालमें ही हॉवर्ड एसोसियेशनकी कमेटीके पास आर्यों हैं। इस कमेटीकी रायमें इस प्रकारके अपराधोंकी राजनीतिक अपराधोंकी श्रेणीमें समझना चाहिये न कि मामूली फीजदारीके अपराधोंकी। और उनको दण्ड देते समय यह वात ध्यानमें रखना चाहिये।''

तिलक्को पहले बम्बई जेलमें रखा गया लेकिन वादमें उनका तबादला यरवदा जेलको कर दिया गया। उनका यरवदा जेल भेजा जाना विलकुल गुप्त रखा गया, परन्तु कल्याणके त्टेशनपर एक प्लेगका डाक्टर उनकी जाँच करनेवाला था। जैसे ही टाक्टरने डिस्वेका दरवाजा खोला, प्लेटफार्मपर खड़े हुए कुछ लोगोंने वन्द डिस्वेकी खिड़कियोंसे अन्दर झाँका। उन्होंने अपने नेताको पहचान लिया और यह खबर जंगलकी आगकी भाँति देल गयी। दर्शनको उत्सक तिलक्के प्रशंसकोंको भीड़ प्लेटफार्मपर तत्काल ही जमा हो गयी।

यों कांग्रेसकी ओरसे उस सालके अधिवेशनमें तिलककी सजाके ऊपर कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया, परन्तु कांग्रेसजनोंने न्यक्तिगत रूपने अपने हृदयोंके उद्गरोंको न्यक्त किया । उमेशचन्द्र बनजींने कहा—"न्यायाधीश स्ट्रेचोकी राजद्रोहकी परिभापाके पश्में कुछ कहा ही नहीं जा सकता और जनमतकी दृष्टिसे तो यह पृणित है ही।"

नात् भाइयोंके देश-निकालेपर भी कांग्रेसने सतर्कतासे एक प्रस्ताव पास किया, जिनमें कहा गया था—"वश्रिव सम्बई सरकारने जिम्मेदारीसे ही १८२७ के वम्बई कान्तके २५० वं विनियमनके अन्तर्गत नात् भाइयोंको गिरपतार किया था, फिर भी कांग्रेसकी रायमें चूँकि गिरपतारीको पाँच महीने हो गये हैं इसीलिये न्यायकी दृष्टि, और जनतामें फेली हुई वेचैनी और असंतीपको शान्त करनेके लिए सरकारका यह कर्तस्य हो जाता है कि नात् सरदारींपर फीरन ही सुकदमा चलाया जाये। यदि सरकारके पास न्यायालयको संतुष्ट करने योग्य नात्

१. केलकर-वही पुस्तक, पृष्ट ४२०

२. केलकर-वही पुस्तक, पृष्ठ ४१६-१७

भाइयोंके विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण नहीं है तो उनको मुक्त कर दिया जाये।" लेकिन राष्ट्रपति श्री शंकरन नायरने स्पष्ट रूपसे कहा कि "यदि सरकार आपको अपनी मरजीसे, विना अभियोग चलाये गिरफ्तार कर सकती है, जेल भेज सकती है और आपकी जायदाद जन्त कर सकती है, तो व्यक्तियोंकी धन जनकी स्वतन्त्रता सिर्फ एक मजाक है, ढोंग है, यह स्वेच्छा-चारी निरंकुश शासनके सवसे बुरे दिनोंकी याद दिलाता है।"

प्रोफेसर सेक्स मुलर, सर विलियम हण्टर, सर रिचर्ड गार्थ; विलियम केन, दादा माई नौरोजी और रमेशचन्द्र दत्तके हस्ताक्षरोंसे सरकारको एक आवेदन पत्र मेजा गया जिसके फलस्वरूप तिलक मियादसे छः महीने पहले ही छोड़ दिये गये। "तिलकने स्वयं शर्त रखी कि यदि कभी भी फिर उनको राजद्रोहके अभियोगमें सजा मिले तो उस सजामें यह छः महीनेकी छूट भी जोड़ दी जाये।"

रेण्ड-हत्याकाण्डमें पुलिसको यह स्चना मिल गयी कि दामोदर चाफेकर व वालकृष्ण चाफेकर दो माइयोंने रेन्ड हत्याएँ की हैं। उनपर मुकदमा चला और उनको फाँसी दे दी गयी। परन्तु इसके परिणाम स्वरूप दो हत्याएँ और हो गयीं। चाफेकरोंके अमिलमित्र द्रविड़ भाइयोंने पुलिसको मेद बताया था। द्रविड़ भाइयोंमेंसे एक जालसाजीके लिए सजा भुगत रहा था। उसको पता था कि रेण्ड और आइस्ट्रेकी हत्या चाफेकर वन्धुओंने की हैं। २०,००० ६० के इनामके लालचसे उसने यह मेद पुलिसको बता दिया। ८ फरवरी १८९९ को दो व्यक्ति-चाफेकर वन्धुओंका सबसे छोटा माई वासुदेव और उसका एक मित्र-द्रविड़के घर पहुँचे और उपर वैठे हुए लोगोंको आवाज दी कि उनको जूनने, जो रेण्ड हत्याकाण्डकी जाँचके लिए विदोष अफसर नियुक्त हुए थे, बुलाया है। द्रविड़ नीचे आकर बुलानेवालोंके साथ चल दिये। जैसे ही चारों आदमी रास्तेमें पड़नेवाले मन्दिरके पास पहुँचे, वासुदेव और उसके मित्रने पिस्तौल निकालकर भेदियोंको गोली मार दी। अस्पतालमें उनका प्राणान्त हो गया। पुलिस नायव-इंस्पेक्टर जब वासुदेवसे सवाल पूछ रहा था तो उसने कोधमें आकर पहले नायव-इंस्पेक्टर और फिर रेन्डपर गोली चला दी, मगर वे दोनों वच गये। वासुदेव और उसके मित्र दोनोंने अभियोग स्वीकार कर लिया और फाँसीपर झूल गये।

राजनीतिके इस नये पहल्से सरकार भयभीत हो उटी और उसने ताजीरात हिन्दकी १२४ अ धाराका संशोधनकर राजद्रोहकी परिभाषामें "हिज मैजेस्टी या सरकारके विरूद्ध घणा या उपेक्षाका प्रचार या प्रचारकी कोश्रिश करनेवाला प्रत्येक आदमी " शामिलकर दिया। सरकारके प्रति 'अंसतीप' शब्दके क्षेत्रमें शत्रुताके हर प्रकारके भाव और अभिक्त भी शामिलकर दिये। कर दिये गये। यह संशोधित कान्न (Act) १८९८ में लागू कर दिया गया।

भारतीय राजनीतिक वातावरण दिन-प्रतिदिन अधिक उग्र होता जा रहा था। उस समयके भारत सिचव लायड जार्ज हैमिलटनके शब्दोंमें 'भारतमें अंग्रेज वास्त्रके देरके ऊपर वैटे हुए थे।' दंड पुल्सिके दस्ते राजनीतिक अशान्तिके क्षेत्रोंमें तैनात कर दिये गये। डाकखाना-कान्न (पोस्ट आफिस ऐक्ट) में संशोधन कर डाक-वाबुओंको यह अधिकार दे दिया गया कि वह किसी भी सन्देह योग्य (राजद्रोहात्मक) चिट्ठी या डाकसे जानेवाले

१. डा॰ पद्दाभि सीतारामैया—दी हिस्ट्री आफ इण्डियन नेशनल कांग्रेस (१९४६) भाग १ पृष्ट ९५

सामानको रोक सकते हैं। जनताके प्रवल विरोधके वावज्द इस नये नियमको, राजद्रोह-कान्नमें उसका क्षेत्र विस्तृत करनेके लिए, शामिल कर लिया गया।

१८९८ में भी प्लेग त्रात्र-त्राहि मचाये हुए था। और अधिकारियों के दमनकारी व्यवहार-चे रोपमें आकर कुछ मुखलमान बुनकर उनके विरोधमें उठ खड़े हुए। कई बुनकरींको पुलिसने गोली मार दी।

गणितके अध्यापक और वंगाल विधान-परिपदके सदस्य आनन्दमोहन वसुकी अध्य-धतामें १८९८ में कांग्रेसका अधिवेदान मद्रासमें हुआ। अधिवेदानका एक महत्वपूर्ण प्रत्ताव, देशके कुछ भागोंमें सरकार द्वारा नियुक्त, दमनके लिए बनायी गयी गुप्त प्रेस समितियों (सीकेट प्रेस कमिटीज) के सम्बन्धमें था। ये समितियाँ अखवार नियन्त्रकके रूपमें काम करती थीं। इस कदमको 'ब्रिटिश इण्डियापर लानत' कहकर निन्दा करनेवाले प्रस्तावन को अधिवेदानमें उपस्थित लन्दन समाचार समितिके प्रतिनिधि श्री. डब्द्, ए. चेम्यर्सने पेदा किया। श्री. चेम्बर्सने अपने भाषणमें कहा 'गुप्त प्रेस समितियोंके बनाये जानेसे मुझे इतना आद्रचर्य हो रहा है कि कोई भी अंग्रेज इस समितिका समर्थन नहीं कर सकता। इस बातकी स्वप्नमें भी कल्पना नहीं की जा सकतो कि अँग्रेजों द्वारा शासित विसी भी देशमें ऐसा हो सकता है, पिर भी हम इन्हीं वातोंके लिए रूस व जर्मनीकी निन्दा करते हैं।

काँग्रेस अधिवेशन जब हो रहा था तभी लॉर्ड कजर्न भारतके वाइसराय होकर आये। उनके आनेपर काँग्रेसने प्रस्ताव पास किया कि "वह अधिवेशन लॉर्ड कजर्नका स्वागत करता है, भारतीयों के प्रति श्रीमान्के सहानुभ्तिके शब्दों के लिए कृतज्ञता प्रगट करते हुए आशा करता है कि उनके शासनकालमें अँग्रेजोंकी श्रेष्ठ परम्पराके अनुकृल प्रगति और देशी लोगोंमें विश्वासकी गीतिका अनुसरण किया जायगा।"

मुरलीधर व मालवीयके भाषणों, उस समयकी आधिक परिस्थिति, जिसका विश्वसनीय विवरण श्री रमेशचनंद्रदक्तकी कई पुस्तकोंमें मिलता है, और समकालीन वक्ताओं और लेखकों-के लेखोंकी तुलनामें यह प्रस्ताव कुछ अजीव-सा था। यहाँ तक कि राष्ट्रपतिके पदने किये गये भाषण भी इतने अधिक नम्र नहीं थे।

१८९९ का लखनऊ काँग्रेस अधिवेशन हिन्दू मुस्लिम संस्कृतिका संगम था। अधिक संख्यामें मुसलमान प्रतिनिधि इस अधिवेशनमें उपस्थित थे। ७८९ में २०० मुसलमान प्रति-निधि थे। श्री रमेशचन्द्र दत्त जिन्होंने १८९७ में भारतीय सिविल सर्विससे त्यागपत्र दे दिया था, इस अधिवेशनके अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने अपने श्रीताओंको भाष्ट्रकतासे नहीं यहिक आकर्षोंसे प्रभावित किया।

भारतमें अकालका राध्य फिर मनुत्योंके जीवनसे होली खेल रहा था और अनाजमें लदे जहाजपर जहाज इंगलेंण्डको मेजे जा रहे थे। इसपर टीका करते हुए धीदत्तने कहा "कभी कभी इस बातका दाबा किया जाता है कि भारतकी गरीबी और अकाल, जैनी नंनारके किसी भी मुशामित देशमें नहीं हैं, केवल आवादीके अधिक बढ़ जानेसे है। यह अनत्य है। यदि आप ऑकड़ोंको देखें तो आपको पता लगेगा कि भारतकी आवादी उस तेजीने नहीं बढ़ रही है जैसे जर्मनी वा इंगलेंण्ड व अन्य यूरोपियन देशोंकी। भारतीय किनानोंकी दुर्दशा और कर्जमें हुवे होनेका मूल कारण, बंगाल व कुछ दूसरे इलाकोंको छोड़कर, अध्यिक भूमिकर है, जिसके कारण किसान अच्छी फर्ले होनेपर भी दुर्दिनके लिए कुछ भी नहीं

वचा पाते । कताई और बुनाईके हमारे गाँवके उद्योग, इंगलैण्डके कारखानोंसे प्रतियोगिता न कर पानेके कारण मिट गये हैं । हमारे किसानों और औद्योगिक वर्गके ग्रामीणोंको भी केवल भ्मिपर ही निर्भर रहना पड़ता है । वहीं उनका जीवन-आधार है । " "चूँकि किसानके पास जमानत देनेके लिए कोई सामान नहीं है, इसीलिये उसे कम व्याजगर स्पया उधार नहीं मिल सकता और उसे २५% या २७% व्याजपर ऋण लेना पड़ता है।" उन्होंने कहा कि फौजी व्यय, मुद्रा नीतिं और राष्ट्रीय कर भारतकी मालगुजारीपर भयंकर वोझा है। ''ब्रिटेनमें १८६० से राष्ट्रीय ऋण घटाकर साढ़े सत्तरह करोड़ रु० कर दिया गया है "परन्तु भारतमें यह ऋण उसी अविधमें दस करोड़ वढ़ा दिया गया है और इंगलैण्डको व्याजके भुगतानके लिए भेज दिया जाता है जिसके कारण भारतकी मालगुजारी और आयपर अनावश्यक जवरदस्त बोझा पड़ रहा है। अभी हालमें ही मुद्रा समिति (Currency committee) ने मुद्रा-नीति इस ढंगकी वनायी जिससे लाखों किसानोंका अहित ही हुआ है। उनके कर्ज और बढ़ गये हैं और बचत कम हो गयी है।" भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि 'शासनमें यह ब्रुटि है और इमारा दुर्भाग्य है कि जिला अधिकारीगण गाँववालीं या उनके स्वाभाविक नेताओं से नहीं के वरावर सम्पर्क रखते हैं। प्रत्येक कार्यमें उनको पुलिसकी शरण लेनी पड़ती है। गाँवमें कोई मुसीवत आयी हो, जाँच पुलिस करेगी। हैजा फैला है तो दवा पुल्सि वाँटेगी। यदि गाँवका जलाशय घट जाय या पानीकी कमी पड़ जाय तो पुलिस सहायता संघटित करती है। अगर कोई पेड़ गिर पड़े और गाँवका रास्ता रक जाय तो (मैंने स्वयं इस प्रकारकी घटनाएँ देखी हैं) गाँववाले, जवतक पुलिस सहायता न करे, असहाय वने रहते हैं। यह कितना दुर्भाग्य है कि वह देश जिसने सर्वप्रथम गाँव-समाज, गाँव-पंचायतं और गाँवोंमें स्वद्यासन संस्थाएँ स्थापित की थीं और २००० सालोंतक इनको सफलतासे चलाया था, इस तरहसे असहाय हो जाय और उस देशपर अवांछनीय पुलिस द्वारा शासन किया जाय।"

श्री दत्तने सुझाव दिया—"दुर्भिक्षसे उत्पन्न मुसीवतको, संकटोंको और मृत्युओंको रोका जा सकता है। सुख-सम्पत्ति बढ़ायी जा सकती है, पूरे राष्ट्रकी भक्ति और उत्साहपूर्ण सहायता प्राप्त हो सकती है। यह सम्भव है केवल एक शर्तपर—देशको स्वराज्यका वरदान मिल जाय।"

कांग्रेसने एक प्रस्ताव द्वारा सरकार्हें माँग की कि देशकी आयपरसे वोझा कम किया जाय, व्यय घटा दिया जाय, करोंमें कमी हो और देशी उद्योग-धन्धोंका विकास किया जात्र।

अलखनक अधिवेशनमें कांग्रेसका विधान बना लिया गया। विधानमें कांग्रेसका उद्देश था ''वैधानिक उपायों द्वारा भारतीय साम्राज्यकी जनताके सुख और हित-लामकी चेष्टा करना।'' विधानकी अन्य धाराएँ थीं—

(१) राजनीतिक संघटनों, या दूसरी संस्थाओं द्वारा और सार्वजनिक सभाओंमें प्रति-निधियोंका निर्वाचन होगा। (२) अखिल भारतीय कांग्रेस महासमितिमें पैंतालीस प्रतिनिधि होंगे जिनमेंसे चालीसको प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ चुनकर मेजेंगी। यदि किसी प्रान्तमें कांग्रेस कमेटी नहीं है तो वहाँके प्रतिनिधि महासमितिके लिए नुमाइन्दे चुनेंगे। महासमितिके सदस्योंका कार्यकाल एक अधिवेशनसे दूसरे अधिवेशनतक होगा। (३) महासमितिकी बैठक वर्षमें कम-से-कम तीन बार हुआ करेगी और इसकी नियम व कान्न वनानेका अधिकार होगा। (४) प्रांतीय कांग्रेस कमेटियाँ, प्रान्तीय अधिवेद्यन करेगी और अपना कार्यक्षेत्र बद्या-कर जिला कांग्रेस कमेटियाँ स्थापित करेगी (५) इंगलेण्डमें एक ब्रिटिश कांग्रेस कमेटी बनायी जायगी जिसका एक बैतिनक मन्त्री होगा। कमेटीपर वर्षमें पाँच हजार रुपये व्यय किया जायेगा जिसको पिछले और आगामी अधिवेद्यनकी स्वागत समितियाँ आपसमें बाँट लेंगी।

सन् १९०० अधिक संकटमय था, लेकिन बभ्वइंके पत्रकार और वकील श्री एन. जी चन्दावरकरकी अध्यक्षतामें लाहोरके कांग्रेस अधिवेदानमें वातावरण उदासीन सा रहा । इस वर्षका दुर्भिक्ष अधिक भर्षकर था, जैसा कि वाइसराय लाई कर्जनने कहा "भारतवर्षमें इतना भवंकर अकाल कभी नहीं पड़ा।" सर्युक्त प्रान्तमें (अब उत्तर प्रदेश) प्लेगसे बरावर लोग सर रहे थे। हस्य मामल अधिकारियोंका व्यवहार उत्तेजनापूर्ण विमुखताका था। अप्रैल १९०० में कानपुरके प्ढेग-कैम्पपर एक भीड़ने इमला कर दिया जिसमें पाँच पुलिसवाले मारे गये । गौरांग प्रभुओंने न्यायमें खुलकर अनिधकार विध्न डाला जैसा कि इन दो उदाहरणोंसे स्पष्ट हो जाता है। १९ अगस्त १८९९ को छपराके जिला पुलिस सपरिटेंडेंट कौरवेटने एक छिपाही नरसिंहके चूतड़ोंपर ठोकर मारी, और जिला इञ्जिनियर सिमिकिन्सने उसके सरपर कोड़ा मारा । कोरवेटने फिर उसके मुँहपर घँसा मारा जिससे वह एक दीवारसे टकराकर गिर गया । नरसिंहका अपराध केवल जिला इञ्जीनियरके लिए येगार करनेसे इनकार करना था। उसको अस्पतालमें भरती किया गया जहाँ जाँच करनेपर गाउम हुआ कि उसके घाव भवंकर थे। शिकायतके डरसे कीरवेटने नरसिहको नीकरी। छोड़ देनेको कहा । नौकरी न छोड्नेपर उखपर मुकदमा चलानेकी धमकी भी दी गयी। नरसिहने इस हुक्मको न माना । उसपर मुकदमा चलाया गया । मुकदमेंके निर्णायक मैजिन्ट्रेट मीलबी जाफिर हुएँनने द्वावमें आकर उसको दो महीनेकी सरत केंद्रका हुनम मुना दिया। उसने जिला और सेशन जज आयरहैण्ड निवासी श्री पैनलको अदालतमें अपील कर दी। श्री पैनल ने अपील तो मंज्र कर ली मगर उसकी वजहते खुद मुसीवतमें पड़ गये। उन्होंने अपने फैसलेमें कहा—''दुर्भाग्यवश यूरोपियनों द्वारा देशी लोगोंपर हमला और मारपीट अनीग्वी नहीं है। और जबतक जातीय श्रेष्टताका भाव विद्युत न हो जाये तबतक यह मारपीट न्यस होनेवाला नहीं है। उनको सजा देना सही है परन्तु अधिक कड़ी सजा देनेसे परत्यर जागीय सम्बन्धींके अन्छे होनेकी जगह ज्यादा खराव होनेकी सम्भावना है, और उससे उद्देशकी हानि ही होगी । देशी छोगोंमें अधिक समझदार आदर्श खुद ही यूरीपियनीके इस देशमें आकर पैदा हुए घमण्डका और उसके परिणामस्वरूप पैदा हुई मारपीटका ख्याल रखते हैं।"

७ अक्टूबरको दिये गये इस निर्णयमे प्रान्तभरके अधिकारियों से सत्वन्ती सच गयी । यहाँतक कि लेफिटनेण्ट गवर्नर सर जॉन बुहवर्न भी इसमे चिन्तित हो उठे और वाइमराय लाई कर्जनमें पैनलके इस कार्यको 'जॉचको स्वतन्त्रता' का दुरुपयोग समझा ओर उनको तार द्वारा नोआखालीको स्थानान्तरित कर दिया।

कुछ समय बाद बुडवर्न नोआखाली गये और अपने निली कमरेमें पैनलके बुलाकर कहा "तुम्हारा निर्णय देखकर मुझे तुम्हारी न्याय-विभागमें नीकरी करनेकी योग्यतापर सन्देह होता है। न्याय-अधिकारी उसी प्रकार मेरे मातहत हैं जिस प्रकार प्रशासकीय अधिकारी और मैं चाहता हूँ कि वे कायदेसे काम करें। ध्यान रखना कि मैं तुम्हारी मलाईके ही लिए कह रहा हूँ। और तुम्हारा फैसला पढ़कर मुझे शक होता है कि क्या तुम उतने ही निष्पक्ष हो जितना तुम्हें होना चाहिये। जिस प्रतिशोधमय जलनसे तुम पुलिस और जिला अधिकारियोंके पीछे पड़ गये, इससे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी उनकी लड़ाई है।"

पैनल-आप ऐसा सोच सकते हैं, परन्तु उस निर्णयका मृह्य कांग्रेसके दो अधि-वैश्वनोंके बरावर है।

वुडवर्न—मैंने तो एक निष्पक्ष व्यक्तिकी हैिस्यतसे यह राय दो है।
पैनल—मैं जानता हूँ कि आपकी सरकारने सत्यको दवानेकी भरसक चेष्टा की है।
लेपिटनेण्ट गवर्नरने जरा गरम होकर कहा—मेरी सरकारने! सावधान पैनल, तुम जो कुछ कह रहे हो सोच समझकर कहो।

पैनल—आपने कान्नी सलाहकार (लीगल रिमेम्बरेन्सर) से महाविरा किया था कि क्या गवाहोंको मेरे सामने पेश करनेकी कोई आवश्यकता है।

्र बुडवर्न—हाँ । मुझे कानृनी सलाहकारसे मशदिरा करनेका पूरा अधिकार था। सामला विलकुल तुच्छ था।

पैनल-तुन्छ मामला ! क्या में इस मामलेको हाईकोर्ट ले जाऊँ ?

बुडवर्न—नहीं पैनल, में हाईकोर्टसे किसी विवादमें नहीं पड़ना चाहता, में तो तुमसे निजी तौरपर बात कर रहा हूँ।

एक दूसरे मामलेमें पैनलने अपने फैसलेमें लिखा "इस प्रकारके मामलेमें, इस देशमें, अधिकारियों के खिलाफ गवाही देनेका केवल ऐसे लोग साइस कर सकते हैं जो अपने घरों के जलाये जानेका, दूकाने दूटी जानेका, अपने रिश्तेदारों के सरकारी नौकरियों से निकाल दिये जानेका, और स्वयंके व अपने घरवालों के ऊपर झूटा मुकदमा चलाकर जेल भेज दिये जानेका खतरा उंटा सकते हैं।"

नीआखालीमें पैनलने पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट रेलीकी झ्ठी गवाही देनेक अमियोगमें गिरपतार करवा दिया | रेलीने झ्ठी गवाही देकर एक हत्यारेको रिहा करवानेकी चेष्टा की थी | पैनलने हत्यारेको फाँसीकी सजा दी | इस मामलेने पैनलको लोगोंकी दृष्टिमें बहुत के चा उठा दिया और १५ फरवरी १९०१ को जब पैनलने फैसला सुनाया तो १०००० आदमी उसकी जय जयकार करते, धर्मावतार और सच्चा न्यायकर्ता कहते उसके वैंगले तक गये | परन्तु सरकारकी सिफारिशपर हाईकोर्टने पैनलको मुख्यल कर दिया और तार द्वारा रेलीको जमानतपर छोड़ देनेका हुनम दिया | पैनलके कलकत्ता रवाना होते वक्त सब तरहके लोगोंकी पन्द्रह हजारकी भीड़ उनके पीछे उनके घरसे स्टेशनतक गयी | जिस रास्तेसे पैनलकी गाड़ी जा रही थी; उसके दोनों ओर लोग खड़े हुए थे |

१९०१ के कलकत्तेमें हुए कांग्रेस अधिवेदानमें कांग्रेसकी प्रशासनसे न्याय विभागको अलग कर देनेकी साँगका औचित्य सिद्ध करनेके लिए पैनल काण्डका जोरदार प्रमाण दिया गया। कलकत्ता कांग्रेसकी अध्यक्षता दीनशा ईंदुल्जी वाचाने की। आप कांग्रेसके जन्मसे उन्हा साथ देते रहे। और प्रारम्भमें ही आपका नाम कांग्रेसके आतिशा वाज पड़ गया था। राष्ट्रपतिने अपने भाषणमें कहा—"मॉर्ल्ड शब्दोंमें उन्मत

साम्रार्ज्यवाद दमनकारी, प्रतिगामी और दौतानियतकी नीतिका अनुसरण करता हुआ इस समय अधिक द्यक्तिशाली हो रहा है। निस्तन्देह हमारी सरकार अच्छो है परन्तु उसमें कई बुराइयाँ भी हें।" श्री वाचाके लग्ने भाषणमें देशकी आर्थिक दशा और दुर्भिक्षका विवेचन था। विना जनताको जरा भी लाभ पहुँचाये हुए करोड़ों रुपया अकाल सहायतापर वर्वाद कर दिया गया। उन्होंने गोकुलदास पारखके विधान परिपट्में किये गये भाषणका उल्लेख किया कि अधिकारीगण गरीय रैयतपर अत्याचार कर रहे हैं और दाहिने हाथसे तकावी वाँटकर वाथे हाथसे उगाही वस्ल कर रहे हैं। कांग्रेसने सर्वश्री तिलक, मालबीय व अन्य सात आदिमयोंकी एक कमेटी भारतवर्षकी आर्थिक दशाकी जाँच करनेके लिए नियुक्त की। रमेशचन्द्रदक्तने सरकारकी आर्थिक नीतिकी निन्दा करते हुए कहा कि दुर्भिक्ष शोषणकी नीतिका अनिवार्य परिणाम है।

१९०२ का अधिवेशन गुजरातकी राजधानी अहमदावादमें हुआ जिसकी एक करोड़-की आवादीका है भाग दो अकालोंमें मर चुका था। परन्तु उसी समय देशकी राजधानीमें सम्राट एडवर्ड सतमकी ताजपोशीको खुर्शामें एक महान दरवारका जशन और उत्सव मनाया जा रहा था। राष्ट्रपति सुरेन्द्रनाथ वैनजींने सम्राटके प्रति उचित सम्मानपर वोलते हुए कहा कि 'वह समय गुजर गया जब चकाज़ोंध और चिकत करनेके लिए तड़क-भड़कका आडम्बर, भारतके लोकमतपर कोई स्थायी प्रभाव डाल सके।'' परन्तु उनके उत्तराधिकारी श्री लालमोहन घोपने १९०३ के मद्रास अधिवेशनकी अध्यक्षता करते हुए सीधा आक्रमण किया। उन्होंने पूछा 'क्या तुम समझते हो कि इंगलण्ड, फांस या अमेरिकाकी सरकार एक खोखले आडम्बरपर इतना अधिक धन फूँ कनेका साहस करेंगी! जब कि देशमें दुर्भिक्ष और महामारी मनुष्योंके जीवनसे होली खेल रही हों और यमदूत खुशी मनानेवालोंके कानोंके ऊपर ढोल बजा रहे हों। जहाँ तक जनताका सम्बन्ध है, उसके लिए इससे ज्यादा निर्दय और कटोर क्या हो सकता है कि एक श्रेष्ठ सरकार संसारके सबसे गरीब लोगोंपर सबसे ज्यादा कर लगाये और इस तरहसे एकितत धनको व्यर्थके नाच तमाशों और आतिशवाजोंमें फूँ क दे जबकि जनता भूखों मर रही हो।''

उसके बाद श्रीघोषने अँग्रेजी शासनकी तुल्ना भूतपूर्व शासनींने करते हुए कहा "यद्यपि आज हम डाकुओं अउपद्रवेंसि बचे हुए हैं—आज हमें लूटपाट, हत्याओं, जान-मालके जानेका डर नहीं है, प्रतिहन्दी सरदारों और राजाओं के बीच घरेल और आपसी झगड़े और राज्योंके हथियानेके पड़यंत्रों और रक्तपातसे हम बचे हुए हैं, लेकिन हमको यह न भूलना चाहिये कि तक्ष्वीरका एक दूसरा रुख भी है। परिणाम एक ही है, चाहे लाखों करोड़ों जानें युद्ध और अराजकताके कारण नष्ट हों वा अकाल और सुखमरीते।"

अहमदाबाद कांग्रेसने कर्जनकी प्रतिगामी शिक्षानीतिकी निन्दा करते हुए एक प्रस्ताव पास किया । कर्जनने शिमलामें १९०१ में एक शिक्षा-सम्मेलन बुलाया था जिसमें केवल बूरोपियन शिक्षा-विशेषज्ञोंको आमन्त्रित किया गया । सम्मेलन-सभा गृप्त थी और उसकी काररवाई कभी प्रकाशित नहीं की गयी । सम्मेलनके फलस्वरूप एक विश्वविद्यालय कमीशन (यूनिवर्सिटी कमीशन) नियुक्त हुआ जिसने सिकारिश की कि (१) मान्यमिक-शिक्षा कॉलेजोंको तोड़ दिया जाय । (२) प्रयन्थक संघ (सिण्डिकेट) हारा कॉलेजोंमें न्यूनतम शुक्क निर्धारित कर दिया जाय जिसका असली अर्थ शुक्कोंका बढ़ना था और

(३) कान्नी पढ़ाईको खत्म कर दिया जाय। कार्यक्षमताका स्तर वढ़ानेके लिए ऊँची शिक्षाका क्षेत्र संकुचित करनेका प्रयत्न किया गया। जैसा कि कमीशनके सदस्योंने स्वयं स्वीकार किया कि उनकी सिफारिशोंके मानी शिक्षाके क्षेत्रको संकीर्ण करना और ऊँची शिक्षाको सीमिति करना था। प्रतिरोध-आन्दोलनोंको आंशिक सफलता प्राप्त हुई और माध्यमिक शिक्षा संस्थाएं वन्द नहीं की गयीं।

सर वर्ने ख्वेटने कमीशनकी सिफारिशोंका औचित्य सिद्ध करनेके लिए कहा कि ''गैर सरकारी लोगोंके हाथमें माध्यमिक शिक्षाके नियंत्रणमें अत्यधिक अवनितके कारण शिक्षा-स्तर बहुत गिरा है'' परन्तु शिक्षा सम्मेलनको गुप्त रखनेमें जो सावधानी बरती गयीं, और उस समयकी राजनीतिक परिस्थितिका ल्वेटने जो विश्लेषण किया है, इन दोनोंसे पता चलता है कि ऊँची शिक्षाके क्षेत्रको संकुचित करनेका असली कारण शिक्षा-स्तरमें गिरावटका भय नहीं बिक राजनीतिक था। दरवारके बादकी राजनीतिक परिस्थितिपर ल्वेटने लिखा है ''वास्तवमें इस दरवारमें चालीस सालके शान्तिमय और बिना झगड़ेके युगका अन्त होता है यह युग सरकारकी सफलता और अप्रतिम सत्ताका युग था। शिक्षाका क्षेत्र बढ़ा, व्यापार बढ़ा, मालगुजारीकी अच्छो व्यवस्था हुई, चारों ओर इस दौरमें प्रगति हुई। पाञ्चात्य शिक्षा-प्राप्त लोगोंमें असंतोष अभी गहरी नींद सो रहा था। आर्थिक स्थितिकी बिगड़ी हुई स्थितिकी विचित्रतासे नौजवानोंके जीवनकी किटनाइयाँ और मुसीवतें बढ़ रही थीं। सिद्दयोंके रीति रवाज टूटने लगे थे। सामाजिक उत्सवों, मेलों और जातीय सम्मेलनोंसे अधिक जनता अव राजनीतिक सभाओंमें जाने लगी थी। परिवर्तनकी भावना जोर पकड़ रही थी, वर्तमानसे असंतुष्ट लोगोंमें 'नयेसे पुराना अच्छा' सिद्धांत अधिक जमता जा रहा था।''

राष्ट्रपतिके भाषणमें आँकड़ों द्वारा सिद्ध किया गया था कि भारतकी आर्थिक दुर्दशा-का कारण अंग्रेजी सरकारकी लूट थी। उसमें ल्वेट द्वारा कथित सर्वमुखी प्रगतिकी असत्यता दिखाई गयी थी।" ल्वेटकी पूरी पुस्तकमें सिर्फ अधिकारियोंका पक्षपात किया गया था और उन्होंको उचित दिखानेकी चेष्टा की गयी थी।

न्याय विभागकी दशापर श्री घोषने सर हेनरी कॉटनका उल्लेख किया "अगर इन अपराधों के लिए अँगरेजींपर अभियोग चलाया जाता है तो आम तौरपर क्या परिणाम होता है श बहुधा इन अभियोगों में निर्णयों को न्यायपर कलंक ही कहा जा सकता है। यह सही है कि वह किसीको फाँसी दिल्लाने के लिए उत्सुक नहीं था लेकिन फिर भी यह तो कहना पड़ेगा कि अनिगनत अभियोगों में अपराधियोंपर ऐसा नृशंस और कठोर हत्याओं का अभियोग होता है कि फाँसीके सिवा और कोई दंड हो ही नहीं सकता लेकिन वे ठीक लंगके और निष्पक्ष न्याय न होने की कमजोरी के कारण बच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है श क्यों कि अभियोगों की जाँचके लिए नियुक्त जूरीगण (Jury) उन्हीं के देशवासी होते हैं।"

कर्जन सरकार अपनी प्रतिक्रियावादी नीतिपर ही चल रही थी। सरकारने राजद्रोह ऐक्ट (Sedition act) लागू किया। लोगोंकी आजादीपर एक और आघात सरकारी गोपनीयता ऐक्ट (official secrets act) लागू करके किया। जिनके द्वारा यह अभियोक्ताकी जिम्मेदारी नहीं रही कि अपराधोंको सिद्ध कर बिक्क अभियुक्तको अपनी निर्दोषिता प्रमाणित करनी पड़ती थी।

१. छवेट ए, हिस्ट्री आफ इण्डियन नेशनिलस्ट मूवमेंट एष्ठ ५४

नवाव सैयद मुहम्मद और जी० के० गोखलेने (दोनों केन्द्रीय परिपदकें सदस्य थे) हस ऐक्टकी घोर निन्दा की और इसको "ष्टणित ही नहीं विल्क अत्यन्त अन्याय पूर्ण" वताया जिसके वारेमें "धेर्य या संयमसे वात नहीं की जा सकती" कांग्रेसने इस विलका विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पास किया । मद्रासमें वंगालकी ही भाँति स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के अधिकारों में कभी कर दी गयी । एक दूसरे नियम द्वारा विस्वविद्यालयों का स्वशासन अधिकार छीन लिया गया । लेकिन कर्जनके प्रतिगामी शासनका सबसे बुरा कदम वंग-भंगका निर्णय था ।

वीसवीं कांग्रेस वस्वईमें, जैसा कि कांग्रेसकी अधिकृत रिपोर्टमें कहा गया था, कर्जनकी दमन और प्रतिकियावादी नीतिकी बढ़ती हुई अनिश्चितताके वातावरणमें हुई। सुरेन्द्रनाथ वनजींने लिटनके शासनको छिपे हुए रूपमें आशीर्वाद बतलाया क्योंकि इसने भारतीयोंको कर्मशील बना दिया था।

१९०४ के वम्बई अधिवेशनकी अन्यक्षता सर हेनरी कॉटनने की । उन्होंने एक विचारगिमत भाषण किया जिसमें उन्होंने कहा कि साम्राज्यका यही रवेथा है कि वह ऐसे पूर्ण स्वशासी राज्योंका संघ हो जो समान उद्देशों और अपने हितोंके कारण केन्द्रीय सत्तामें सिमालित हो।'' इसलिए उन्होंने मुझाव रखा कि भारतको स्वतंत्र राज्योंका एक संघ होना चाहिये—भारतका संयुक्त राष्ट्र।'' इस सम्मतिकी गर्वके साथ अवहेलना की गयी। इसके अनिवार्य परिणाम-स्वरूप भारत स्वतंत्र देशोंमें विभाजित हो जाता जिनमें प्रत्येक राज्य दूसरे राज्यसे स्वतंत्र हो जाता। परन्तु विभाजनके राश्वसने भारतमें अपने मजवृत कदम जमा ही लिये।

अधिवेशनके प्रथम प्रस्तावमें कर्जनकी उस घोषणाकी ओर ध्यान खींचा गया जिसमें उन्होंने भारतीयोंको अंग्रेजी शासनके अन्तर्गत ऊँची जिम्मेदारियाँ निमानेके अयोग्य घोषित किया था, जिसका गुन उद्देश्य वास्तवमें भारतीयोंको ऊँची नौकरियों और पढ़ोंसे वंचित करना था, उन पढ़ोंपरसे भी जिनपर वे काम कर रहे थे। प्रान्तीय नौकरियों (प्रार्वश्रक सिवेंछेज) में भी सरकारने प्रतियोगिताकी जगह नामजदगीकी अवस्था कायम कर दी। इसका कारण राजनीतिक था। सरकार इसका निर्णय कि किस प्रकारके मनुष्य लाभ-दायक सिद्ध होंगे, अपने हाथमें ही रखना चाहती थी। कर्जनको भारतीयोंमें विश्वास नहीं था और कार्यक्षमता बढ़ानेकी आड़में उन्होंने विश्वविद्यालय-प्रवन्धक समितियों (यूनिवर्सिटी सिनेटस) को अधिकारी वर्गको सींप दिया और पूर्ण रूपसे उनका यूरोपीय- करण कर दिया।

कई वर्ष वाद कांग्रेसने फिर एक प्रस्ताव द्वारा 'देशके शासन व मामलेंके नियन्त्रणमें अधिक अधिकारोंकी माँग की ।'' इस प्रस्तावपर वोलते हुए मदनमोहन मालवीयने कहा कि सुधार अच्छे हैं, परन्तु परिपदोंको अधिक अधिकार मिलने चाहिये और उनमें विस्तार होना चाहिये। प्रस्तावमें माँग को गयी थी कि (१) भारतके प्रत्येक प्रान्त वा प्रेमीडेन्सीको अंगरेजी लोक-सभामें (हाउस ऑव कामन्य) कम-से-कम दो सदस्योंको भेजनेका अधिकार हो। (२) केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान-परिपदोंमें, गैर सरकारी सदस्योंको मंख्या बढ़ा दो जाय और उनको यह अधिकार रहे कि वे तमाम आर्थिक-मसलोंपर मत-विभाजन करा सकें, भले ही गवर्नर या बाइसरायके हाथमें विपेशाधिकार रहने दिया जाय। (३) भारतीय

प्रतिनिधि (जो विधान-परिषद्के निर्वाचित सदस्यों द्वारा नामजद हों) लंदनकी भारत-परिषद (इण्डिया कोंसिल) में रखे जायँ तथा भारत सरकारकी प्रशासन-परिषद, (Executive Council) और वम्बई व मद्रासकी सरकारमें भी नियुक्त किये जायँ।

राष्ट्रपतिको कांग्रेसके प्रस्तावोंको छेकर वाइसरायसे मिलनेका अधिकार दिया गया। परन्तु कर्जनने राष्ट्रपतिसे मिलनेसे इनकार कर दिया। इसपर कांग्रेसने अंगरेजी जनताके सामर्न भारतकी तकलीफें रखनेके लिए लाला लाजपत राय और गोखलेका एक विष्टमण्डल इंगलेण्ड भेजा। १९०५ में दोनों नेताओंने इंगलेण्डमें भ्रमण किया, लोगोंसे मिले, सार्वजनिक सभाओंने भाषण किये, परन्तु उन्हें अंगरेजी सरकार या अंगरेजी जनतासे कोई सहानुभूति न मिली। वे निराश होकर वापस लीट आये। लाजपत रायको अंगरेजींकी इस उपेक्षासे बहुत दुःखे हुआ। वे यह विश्वास लेकर लीटे कि भारतको अपनी ही शक्तिका भरोसा करना चाहिये।

भारतीयों की ऊँचे पदोंपर नियुक्तिके विरोधमें कुछ अंगरेज छोग इस प्रकारकी वातें करते थे "भारतीय और कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, या स्कॉटलैंडके विश्वविद्यालयों के स्नातकों के वौद्धिक स्तरमें विशेष अन्तर नहीं है। लेकिन फिर भी वे विद्वानों और मनुष्यों को हैसियतसे बहुत हीन हैं। जो कुछ भी हमारी दृष्टिमें नैतिक शिक्षा और उचित उद्देश्यों की शिक्षा है वह उनमें नहीं है। हिन्दू वृद्धि अंग्रेजी साहित्य व पाश्चात्य विचारों से ओत प्रोत होनेपर भी विकसित नहीं होती। हिन्दू चरित्रपर जब अंग्रेजी विद्वानों की छाप पड़ती है तो वह अपना भी स्वाभाविक गुण खो देता है। कलकत्ता, वम्बई या मद्रासके स्नातक समान स्थितिमें ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिजवालों को गणित या अध्यात्मवादमें हरा सकते हैं, लेकिन हारा हुआ अंग्रेज बढ़कर मनुष्यों का स्वामी वनेगा क्यों कि वह स्वयं अपना विधाता है, और अपने लिए एक सुन्दर भविष्यकी रचना करेगा क्यों कि उसके उद्देश महान हैं। जब कि उसका विजेता सरकारी कर्का, एक अत्याचारी जमींदार या सिर्फ विषयी वनकर रह जायगा।

वद्यपि जनतापर कांग्रेसका प्रभाव बढ़ रहा था परन्तु सरकारपर इसका कोई असर नहीं था। स्पष्ट है कि कांग्रेस इतनी नम्न संस्था समझी जाती थी कि जिसकी वरावर उपेक्षा की जा सके। पीछे छौटना ग्रुरू हो गया था। स्थानीय स्वायत्त शासनमें गैर-सरकारी प्रतिनिधित्व कम कर दिया गया। १८९२ के परिपद सम्बन्धी सुधार व्यर्थ सिंद्र हुए क्यों कि उनसे भारतका राजनीतिक और आर्थिक शोपण रोकनेमें रंचमात्र भी सहायता नहीं मिळी। जो थोड़ेसे गैर-सरकारी सदस्य भारतीय परिषदों में बैठते थे उनका कोई प्रभाव न था। अतः उनके वहाँ न होनेसे भी कोई विशेष अन्तर न पड़ता। पूरे वीस सालसे कांग्रेस जनता है दुःख-दर्द और तकछी भोपर प्रस्ताव पास करती रही और वैधानिक सुधारों की माँग करती रही परन्तु सरकार कानों में तेल डाले वैठी रही। दोनों (सरकार और कांग्रेस) अपने अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थाँ। कांग्रेसके जन्मके पूर्व देशके कुछ हिस्सों में छोगों ने लड़नेका निश्चय किया भी, और सरकारकी सत्तासे विद्रोह कर दिया। शासकवर्ग भी चिन्तित होकर यह सोचनेपर विवश हो जाता था कि जनताको कैसे सन्तुष्ट रखा जाय। जैसा कि हम देख चुके हैं लिटन (वॉइसराय) के प्रतिक्रियावादी शासनने जनताके एक ऐसे वर्गको जन्म दिया जो कुछ करनेकी ठाने हुए था। यह सब अब अतीतकी कहानी वन ऐसे वर्गको जन्म दिया जो कुछ करनेकी ठाने हुए था। यह सब अब अतीतकी कहानी वन

१. जार्ज-स्मिथ-ट्ये टव इण्डियन स्टेट्समैन पृष्ठ २७०-७१

चुका था । सोभाग्यवद्य कर्जनके और अधिक प्रतिक्रियावादो द्यासनने कांग्रेसके अन्दर एक उम्र पार्टी पैदा कर दी । वे राजनीतिज्ञ जो वास्तविकता समझते थे सम्राज्ञीके आधी शताब्दी-व्याप्त शासनके कड़वे अनुभवेंसि समझ चुके थे कि भारतीयोंके साथ वरावरीके व्यवहारका वादा करनेवाला १८५८ का घोषणापत्र केवल, जैसा कि मालवीयजीने कांग्रेस अधिवेदानमें कहा था, एक क्टनीतिक चाल थी, जिसे पूरा करनेका इरादा कभी नहीं किया गया था।

जैसा कि डा॰ पद्याभी सीतारमैयाने कहा है, उस कालके राजनीतिज्ञ "सरकारके दात्रु नहीं थे। यह न सिर्फ उनकी बार बारकी घोषणाओं से व्यक्त होता है बिल्क समय-समयर ऐसे देशभक्तों से साथ सरकार द्वारा किये गये अनुप्रहों से और प्रतिष्ठित पदों के दिये जाने से भी सिद्ध होता है। स्वाभाविक था कि न्याय-विभाग ही इन अनुप्रहों के लिए जुना जाता।" कुछ राष्ट्रपतियों और सिक्षय कांग्रेसियों को न्यायाधीश बना दिया गया। बहुई। तैयव जी (१८८७ के राष्ट्रपति), शंकरन नायर (१८९७), चन्दावरकर (१९००) और के. टी. तेलंग इनमें से थे। कुछको बाइसराय और गवर्नरकी कार्यकारिणी सिमितिका सदस्य नियुक्त कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता था कि कांग्रेस सरकारके अन्तर्गत ऊँचे पद प्राप्त करनेका एक माध्यम यन गया है। इस प्रकारके कार्योंसे राजनीतिपर प्रभाव पड़ता था और पड़ा।

सन् १८९६ से तिलक कांग्रेसका स्तर उठानेका प्रयत्न कर रहे थे। जब १८९९ में उन्होंने बम्बईके गवर्नर लाई सेण्डहर्र्यके कुशासनकी निन्दाका प्रस्ताव पेश करनेकी अनुमति चाही तो विरोधका एक तृफान खड़ा कर दिया गया। "उन्होंने प्रतिनिधियोंको चुनाती दी कि वे प्रमाणित करें कि सेण्डहर्स्यका शासन जनताको वर्याद नहीं कर रहा है। उन्होंने नीकर-शाहीके कारनामों और हथकण्डोंका हवाला देते हुए पृष्टा कि क्या 'में बढ़ा चढ़ाकर कह रहा हूँ ?' परन्त राष्ट्रपति आर. सी. दत्त व कुछ अन्य प्रतिनिधि तिलककी प्रस्तावनाके विरुद्ध थे। और जब तिलकने तर्कपर तर्क और प्रमाण देना शुरू किया कि प्रस्ताव पेश करने से रोका नहीं जा सकता तो राष्ट्रपतिने धमकी दी कि यदि तिलक जिद करेंगे तो 'में त्यागपत्र दे हूँगा'।"

परन्तु वादमें दादाभाई नौरोजीको भी अंग्रेजी शासनमें कोई विश्वास नहीं रहा। उन्हीं नौरोजीने, जिन्होंने दूसरी कांग्रेसमें राष्ट्रपतिक पदसे सम्राजीके घोषणापत्रपर बोलते हुए एलान किया था कि "प्रत्येक शिशुको, जबसे उसे समझ आने लगती है और वह तुतलाना शुरू कर देता है, इसे कंठाग्र करा देना चाहिये", कुछ वर्षों वाद लिखा कि "भृतपूर्व शासक कसाईकी भाँति इधर उधर आघात करते थे परन्तु अंग्रेज कुशल सर्जनकी भाँति अपने वंज्ञानिक हथियारोंसे सीधे दिलपर वार करते हैं और मजा यह कि घाव दिखलाई भी नहीं पड़ता क्योंकि तुरत ही सभ्यता, उन्नित और दुनिया भरकी लच्छेदार वातोंकी मरहमकी मोटी तह घावको ढंक लेती है।"

आयरलैण्ड संबंधी आर्थर-वालफोरके भाषणोंमें, जिसका आर॰ पी॰ करन्दीकरने १९०४ की वम्बई कांग्रेसमें उल्लेख किया था, भारत सरकारकी औंबोगिक नीतिक परि-णामोंके वारेमें कहा गया है कि "एक एक करके हर उन्नित कर सकनेवाले उचोगका जन्मते ही गला घोंट दिया गया है या हाथ पैर वाँधकर इंगलेण्डमें विरोधी हितांके हवाले कर दिया

१. हरिन्द्रनाथ मुखर्जीकी; इंण्डिया स्ट्रगल्स फॉर फीडम, से टर्धत ५६-२९

गया है। यहाँतक कि धन उत्पन्न करनेवाला प्रत्येक स्रोत दृदतासे वन्द कर दिया गया है और पूरे राष्ट्रको विवश होकर स्वेतीपर निर्मर होना पड़ा है।" उन्हीं दिनों एक राजनीतिज्ञने अंग्रेजी और मुसलमानी शासनोंकी इस प्रकार तुलना की "शिक्षा, रक्षा और रेलोंके लिए अंग्रेजी शासन अधिक अच्छा है, परन्तु भारतकी धनसम्पत्तिकी दृष्टिसे मुसलमानी शासन अंग्रेजर था, मुसलमान भारतीय वन गये और उनका धन भारतकी ही सम्पदा रहा जब कि अंग्रेज देशकी सम्पत्तिको लूटकर विदेश ले गये।"

अध्याय ८

मुस्लिम सम्प्रदायवादी राजनीति

मुसलमानी राजनीतिके सिलसिलेबार विवरणके लिए हमको १८८०-९० के इतिहासपर दृष्टिपात करना पड़ेगा। यद्यपि कांग्रेसने अपना जीवन राजमिक्तपूर्ण विरोधीके रूपमें आरम्भ किया था, फिर भी नौकरद्याही और गैरसरकारी यूरोपियन इनकी जरा-सी भी आलोचना सुननेको तैयार नहीं थे। उनकी द्यञ्जता आंग्ल-भारतीय अखवारोंके कालमोंमें व्यक्त होती थी और अलीगढ़ कालेजके अंग्रेज प्रिंसिपल वेकने अखवारोंको कांग्रेस-विरोधी सामग्री व लेख देनेमें प्रमुख भाग लिया। वेकने १८८३ में प्रिंसिपलका पद ग्रहण किया और शुरू ग्रुरू में सुसलमान उनको अंग्रेजोंका गुतचर समझते थे। परन्तु यह भाव थोड़े ही दिनोंमें विलीन हो गया और वेक मुसलमानोंके सबसे अच्छे मित्र समझे जाने लगे। इंगलेण्डमें एक भाषणमें उन्होंने कहा कि "भारतके लिए पार्लमेण्टरी प्रणाली नितान्त अनुचित है और प्रतिनिधिसंस्थाओं (रीप्रेजटेटिच इन्स्टीट्यूयन) के आरम्भ किये जानेका प्रयोग असफल और व्यर्थ सिद्ध होगा। मुसलमान हिन्दू बहुमतकी अधीनतामें रहेंगे और इस बातको मुसलमान बहुत बुरा मानेंगे। मुझे तो यह विश्वास है कि वे खामोशीसे इसको स्वीकार नहीं करेंगे।"

पहला काम जो वेकने किया वह अलीगद्रे प्रकाशित 'इंस्टीट्यूट गजट' का प्रवन्ध अपने हाथमें लेना था। सर सैयद अहमद खाँ इस अखगरके सम्पादक व प्रवन्धक थे। वेकने 'गजट' के कालमीं का इस्तेमाल वंगाली हिन्दुओं और सर सैयद अहमद खाँके वीच दुइमनी पैदा करने के लिए किया। "उस समयतक सर सैयद अहमद खाँके विचार वंगालियों के वारेमें वहुत के चेथे। वे समझते थे कि वंगालियों के ही कारण शिक्षामें बहुत उन्नति हुई है और देशमें स्वतन्त्रता और देशमिककी भावना फैली है। वे कहा करते थे कि "वे स्व जातियों के सिरमौर हैं और उन्हें (सर सैयद अहमद खाँको) वंगालियों पर नाज है।"

वंगालियों को गालियाँ देकर वेकने अपनी राजनीति ग्रुल कर दी। उन लेखीं की जिम्मेदारी सर सैयदके सर जाती थी। उनमें तथा सर सैयद अहमद खाँके बीच यहुत दूरीका अन्तर था। स्पष्टतः उन्होंने यह बात जाननेकी कोई कोशिश नहीं की कि इन लेखींका असली लेखक कीन है! वे समझे कि चूँकि सर सैयद पत्रके सम्पादक हैं इसलिए यदि ये लेख उन्होंने स्वयं नहीं लिखें हैं तो लेखोंका अनुमोदन अवस्य किया है। दोनोंके बीच एक खाई पैदा कर दी गयी जो प्रतिदिन बढ़ती ही गयी।

"परन्तु कुछ ही समय बाद बंगाल नेशनल लीग नामक एक संखाका जन्म हुआ और 'स्टार इन दी वेस्ट' जैसे पत्रोंका प्रकाशन शुरू हुआ जिनकी नीति लड़ाकू और भाषा व शैली अपमानजनक थी और जिन्होंने लोगोंमें राजद्रोह और विष्लवकी एक नयी भावना फैलायी ।

१. सुहम्मद नोमानकी 'सुस्लिम इण्डिया' से उद्पृत, पृष्ट ५२

२. तुफेल अहमद, मुसलमानींका रौशन मुस्तकविल, पृष्ट २९१

सर सैयदने वंगालियों द्वारा आरम्भ किये हुए उद्देलनसे अपना नाता तोड़ लेना अधिकं श्रेयस्कर समझा क्योंकि वे यह नहीं चाहते थे कि ऐसे किसी भी प्रकारके उद्देलनमें मुसलमान भी शरीक समझे जायाँ। मुसलमानोंके वीच आंदोलन करनेके माने विद्रोह खड़ा कर देना था और सर सैयद यह खतरा मोल लेनेके लिए तैयार नहीं थे।"

सर सैयदमें धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था, जैसा कि उनके मध्य प्रांतके स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक (लोकल सेल्फ गवर्मेन्ट) सम्बन्धी वहसके दौरानमें, किये गये भाषणसे प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि "मुझे इस वातका पूरा यकीन है कि हिन्दोस्तानका कोई भी हिस्सा इस काविल नहीं है जहाँपर प्रतिनिधि संस्थाओंके तरीकेका पूरा इस्तेमाल किया जा सके। प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा प्रतिपादित स्वायत्त शासनका उस्ल शायद सवसे महान और उत्तम शिक्षा है जो भारतको इंगलैण्डकी उदारता सिखायेगी। परन्तु इंगलैण्डसे प्रतिनिधि-संस्थाओंकी प्रणालीको उधार लेते वक्त इंगलैण्ड और भारतके सामाजिक-राजनीतिक अन्तरकी सवसे महत्वपूर्ण वात ध्यानमें रखना परम आवश्यक है। भारतकी वर्तमान समाजिक एवं राजनीतिक दशा सदियोंके निरंकुश अनिवंत्रित राज्यकम व कुशासन एक जातिके ऊपर दूसरी जातिकी, एक धर्मके ऊपर दूसरे धर्मकी प्रधानता और प्रभुत्व के इतिहासका परिणाम है। जनताके विचारों, परम्पराओं और उसकी वर्तमान राजनीतिक व आर्थिक दशापर उसके अतीतके इतिहासका वहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मनुष्यता सिखलानेवाला अँग्रेजी शासन अभी भी अँग्रेजी प्रभुत्व द्वारा लायी हुई शान्तिके पूर्वकालीन युद्ध, रक्तपात, वैमनस्य और लड़ाई-झगड़ेकी यादको दिमागसे हटा नहीं पाया है। भारत स्वयं एक महाद्वीप है जिसमें विभिन्न विचारधाराओं व भिन्न-भिन्न जातिके लोग वसते हैं। धर्मकी मदान्धताने पड़ोसियोंको भी अलग रखा है। जाति-भेद अभीतक सदाक्त और प्रधान है। एक ही जिल्हेमें विभिन्न कौमों और मतोंके लोग मिल्हेंगे। यदि एक तबकेके पास धन व व्यापार है। दूसरेके पास अक्ल और तालीम। एक तवका संख्यामें दूसरेसे वड़ा हो सकता है । आवादीके एक हिस्सेका वौद्धिकस्तर शेष आवादीसे बहुत ऊँचा हो सकता है । एक समाज जिला वोडों और स्थानीय वोडोंमें प्रतिनिधित्व प्राप्त करनेके महत्वको बख्वी समझ सकता है, जब कि हो सकता है कि दूसरा इससे विलक्कल ही विमुख हो। ऐसी हालतीं-में इस बातसे इन्कार करना मुमिकन नहीं है कि प्रतिनिधि संस्था-प्रणालीके भारतमें ग्रुरू करनेमें काफी मुक्किलें उठानी पड़ेंगी और इससे पैदा होनेवाले सामाजिक व राजनीतिक खतरोंको नजरन्दाज नहीं किया जा सकता निर्वाचनसे प्रतिनिधित्व तय करनेकी पद्धतिके माने जनसंख्याके वहुमतके विचारों और हितोंका प्रतिनिधित्व है और इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे देशोंके लिए जहाँ एक ही जाति और विचारधाराके लोग वसते हैं यह प्रणाली सर्वोत्तम है, लेकिन श्रीमान्! भारत ऐसे देशमें जहाँ जाति व्यवस्था अभीतक सशक्त है, भिन्न-भिन्न जातियोंका संगम नहीं वन पाया है, धार्मिक वैमनस्य अभीतक प्रखर है, जहाँ आवादीके हर हिस्सेको आधुनिक अर्थमें शिक्षा, वरावरीसे और ठीक अनुपातमें, नहीं मिली है, मैं दावेके साथ कहता हूँ कि जिलावोडों और खानीय वोडोंमें विभिन्न हितोंके प्रतिनिधित्व-के लिए निर्वाचनके सिद्धान्तको आरम्भ करनेसे भयानक बुराइयाँ फैलेंगीं जो आर्थिक विषमताओंसे कही अधिक भयंकर होगीं। जवतक कौमी और धार्मिक मतभेंद, जाति

१. मुहस्मद नोमान वही पुस्तक, पृष्ट-५०

व्यवस्थाके भेद-भाव, भारतके सामाजिक और राजनीतिक जीवनके महस्वपूर्ण अंग हैं और वहाँके रहनेवालोंके बासन-सम्बन्धी व देशकी भलाई-सम्बन्धी विचारोंपर प्रभाव डालते हैं, निर्वाचन प्रणाली नहीं अपनायी जा सकती। बड़ा समाज छोटे समाजके हितोंपर काविज हो जायेगा और अज्ञान जनता ऐसे नियमोंके लिए जो कौगी और विचार- धाराओंके अन्तरको पहलेसे अधिक वैमनस्यतापूर्ण और प्रखर बनानेवाले हैं सरकारको उत्तरदायी टहरायेगी।

इस भाषणने हिन्दुओं और मुसलमानोंके वीचका अन्तर स्पष्ट कर दिया। एक तरफ तो ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो हिन्दू थे और प्रजातान्त्रिक संस्थाओंके शुरू किये जानेके लिए व्यग्र थे और उनके लिए उत्साहसे प्रयत्न कर रहे थे। दूसरी तरफ विरोधमें सर सैयद ये जो मुसलमानोंके एकमात्र सलाहकार समझे जाते थे। घीरे-धीरे अलगावकी भावनाएँ वर्दाओर एच० जे० एस० कॉटनने एक प्रवंध (थीसिस) तैयार कर लिया 'जिसमें हिन्दू और गुसलमान' अलग-अलग दो राष्ट्र हैं, यह मत प्रतिपादित किया गया। उन्होंने लिखा कि—

''हिन्दु और मुसलमानोंके परस्पर सम्बन्धकी अस्लियतकी तरफ, उस ईर्ष्याकी तरफ भी जो दोनोंके बीचमें है और जो अंग्रेजो शासनके मातहत भी प्रत्यक्ष है, धर्मान्धताके स्यानीय उवालोंकी तरफ, इस्लामके वफादार अनुयायी भक्तोंकी करण और कालीके मृति-पुजकोंके प्रति पैदाइशी उपेक्षाकी तरफ, आँखें बन्द कर छेना असम्भव है। इसलिए इस ु दावेके लिए यथेष्ट आधार है कि एक समाज दूसरेकी अधीनता सहन नहीं कर सकता । वाकई, मैं खुद भी यह बात नहीं मानता कि दोनोंमें शायद संमिश्रण हो जाय या किसी भी समाजमें ऐसा नेता मिल जाय जिसकी दोनों पश्लेंके प्रति समान सहान्त्रभृति हो । वास्तवमें दोनों पक्षोंके नेता अलग होनेके लिए काफी इदसक सहमत हैं। भौगोलिक दृष्टिसे भारतके कई भागोंमें मुसलमान क़लीन सामन्ती वर्ग इस प्रकारने बँटा हुआ है कि अपने हिन्दू प्रतिद्वनिद्वयों से सगड़ा बचा जाना मुमकिन है। इसलिए यह श्रीयस्कर प्रतीत होता है कि अंग्रेजी सरकार इस स्वामाविक प्रवृत्तिको मदद दे। संगा-ग्यवश नीची श्रेणीके वर्गोंपर इस पृथकताका कोई प्रभाव नहीं परेगा और जनताक बढ़े भागको एकीभृत होनेकी कठिनाइयाँ न उठानी पहेंगीं । उदाहरणके तीरपर बंगालके दोआवेके ज्यादातर हिस्तेमें शान्तिषय और सीधे साथे लोग आयाद हैं, वे चाहे हिन्द हों या मुसलमान, दोनोंमें बहुत लम्बे समयसे साथ साथ रहनेके कारण धनिष्ठ संबंध हैं। इस्लामके माननेवालीं, जो निस्सन्देह जनसंख्यामें अधिक हैं, तथा उस भूभागके प्राचीन निवासियोंमें भाषा, रीति रीवाजकी दृष्टिसे बहुत कम अन्तर है, अतः देशके हुस विभाजनरे कोई कठिनाई नहीं पैदा होती; लेकिन देशके दूसरे भागोंमें, आमतीरपर मुसलगान अब भी उनी प्रकार समाजके प्रभावशाली गुख्य सदस्य हैं जैसे कि मुसलमान राजवंशके जमानेमें । उन्होंने अपनेको काफिरोंसे विलक्कल ही पृथक कर लिया है, जिनके साथ उनको रहना पड़ता है।

यह १८८६ में लिखा गया था, उन कथित अनुभवींपर, जो थी कॉटनने वंगाल सिविल सर्विसके एक अफसरकी हैसियतसे कई वर्षोमें प्राप्त किये थे। अंद्रेजी द्यासनमें, उच्च वर्गके हिन्दुओं और मुसलमानोंमें पहली खाई तब पैदा हुई उब

१. मुहम्मद नौमान, 'सुसलिम इण्डिया'से उद्धत-पृष्ट ३४-३६

वंगालके मुस्लिम खानदानोंकी जायदादें, उनसे लेकर, हिन्दुओंको दे दी गयीं। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि मुसलमान किस प्रकार अंग्रेजी शिक्षाका वॉयकॉट कर हिन्दुओंसे वहुत पिछड़ गये थे—इस वातने मुसलमानोंको राजनीतिक विकासकी तरफ उदासीन कर दिया! यहाँतक कि अंग्रेजोंने ही मुसलमान नेता वर्गको यह सूझ दी कि संख्यामें कम मुसलमान शिक्षित वर्ग हिन्दुओंके साथ कन्धेसे कन्धा मिलाकर राजनीतिक प्रगतिके पथपर न चल सकेंगे। वहाबी आन्दोलनके दमनके वादके दस साल राजनीतिक दृष्टिसे एक वातके लिए महत्वपूर्ण हैं; इस कालमें लड़ाक़ और हर त्रिटिश-विरोधी मुसल-मान सम्राज्ञीकी राजभक्त प्रजा वन गया; और राजभक्त शिक्षित हिन्दुओंमें धीरे-धीरे ऐसी भावना पनपने लगी जिससे अंग्रेज चिढ़ने लगे । जहाँ अंग्रेजोंने ताकतके जोरपर वहावी-आन्दोलनका दमन कर दिया था, वे एक वैधानिक उद्देलनको दवा नहीं सके; क्योंकि वे स्वंबं अपने मतके तर्कके अनुसार वैधानिक उद्देलन और हिंसात्मक आन्दोलनको समान नहीं समझते थे। इसका यह अर्थ नहीं कि वे इससे परेशान नहीं थे, सिर्फ इस उद्रेलनको दवानेका तरीका भिन्न था । इस मामलेमें दमनकै उपाय फौजी न होकर सिविल थे। उदाहरणके लिए सिविल शासनकी एक चाल भिड़ा जनताक एक हिस्सेको दूसरेके खिलाफ कर देना है, एक घामिक सम्प्रदायको दूसरे सम्प्रदायसे वढ़ा देना है। हालाँकि हिन्दू राजभक्तोंका एक वहुत बड़ा हिस्सा उतनी ही लगनसे अंग्रेजी शाउनका समर्थन करता था जितना कि मुसलमानोंका, हिन्दू नेताओंने नयी चेतनाएँ उत्पन्न कीं, और अंग्रेज अधिकारियोंका यह सन्देह स्वामाविक या कि हिन्दू चाहे कितने ही राजमक्त क्यों न हों, वे अपने समाजके नेताओंसे अवस्य प्रेरित और प्रमावित होंगे। चूँकि मुसलमानोंमें हिन्दू नेताओंके समकक्ष नेता नहीं ये इसलिए अंग्रेजोंके दिलोंमें यह धारणा जम गयी कि वे हिन्दुओं से अधिक मुसलमानोंका विश्वास कर सकते हैं।

प्रथम कांग्रेस अधिवेशनके एक वर्ष वाद अलीगढ़में प्रथम मुद्दमडन शिक्षा सम्मेलनमें कांग्रेसके विरोधमें संघटित आवाज उठायी गयी । इस सम्मेलनमें सर सैयद अहमद खाँने भाषण किया । उन्होंने विचारोत्तेजक वातें कहीं "में उन लोगोंसे सहमत नहीं हूँ जो यह विश्वास करते हैं कि सियासी वहमें कौमी-तरक्कीमें मददगार सावित होंगी । में सिर्फ तालोमकी तरक्कीको कौमको तरक्कीका जरिया मानता हूँ।" सर सैयदके रोंगटे मुसलमानोंके विद्रोहके वादके कान्तिकारी कार्योंके परिणामोंको सोचते ही खड़े हो जाते ये और वे मुसलमानोंके एक वार फिर राजनीतिके भँवरमें कृद पड़नेका खतरा उठानेके लिए तैयार नहीं ये चाहे वह राजनीति काँग्रेसकी ही तरहकी क्यों न हो । पिछली घटनाओंपर खेद प्रकट करते हुए ये कहते कि यदि ये घटनाएँ न हुई होतीं तो "हमारे कितने हो नौजवान" आज "महत्वपूर्ण फीजी व सरकारी पढ़ोंपर आसीन होते ।"

अगले वर्ष मुहम्डन शिक्षा कांग्रेस (जिसका नाम वादमें मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन हो गया; दिसम्बर १८८७ में छलनऊमें हुई जहाँपर सर सैयदने अपना पहला कांग्रेस विरोधी भाषण किया। यह क्टनीतिक भाषाके आवरणमें लिपटा हुआ था और श्रोताओंके वहे हिस्से, अमीर और कुलीन सामन्ती वर्गके मुसलमानों, की भावनाओं और मनोदशाके अनुकूल था। "आप लोग, मुझे विश्वास है" उन्होंने कहा "यह कभी भी गवारा न करेंगे कि ऐरे गैरे नत्थू खैरे वो. ए. और एम. ए. की डिग्रियाँ हासिल कर

हेनेके बाद विधान परिपदों में वैटं और आपके ऊपर हुक्मत करें। जरा कयास कीजिये कि वाइसराय साहब इन लोगोंको 'मेरे सहयोगी' या 'मेरे माननीव सहयोगी' कह कर सम्बोधन करेंगे। सरकार इसके लिए कभी भी राजी न होगी। वाइसराय इन लोगोंको खानेपर या सरकारी उत्सनोंपर कभी दावत नहीं दे सकते जहाँ ड्यूक और अर्ल जैसे आदरणीय महापुरुप तदारीफ लावेंगे।" सर सैयद विधान परिपदों में वृद्धि करने और उनमें निर्वाचित भारतीयों के शामिल किये जानेकी कांग्रे सकी माँगके विरोधम वोल रहे थे।

्डसके बाद उन्होंने कांग्रे सकी इस माँगको लिया कि भारत और इंगलैंड दोनों जगह इण्डियन सिविल सर्विसकी परीक्षाएँ एक साथ लेकर देशके शासनमें उन्हें उचित हिस्सा दिया जाय । उन्होंने उसी तैशमें बोलते हुए कहा "भारतके आला खानदानोंके लोग यह कैसे गवारा कर सकते हैं कि सामान्य होग, जिनकी पैदाइशसे वे अच्छी तरह वाकिफ है, उन पर हुक्मत करें ? अंग्रेजोंकी बात दूसरी है क्योंकि यहाँ वैठकर इतनी दूरीसे हम अन्दाज नहीं लगा सकते कि कौन किस तबकेसे आता है। फिर इंगलैण्ड प्रतियोगता-परीक्षाके लिए उचित स्थान है क्योंकि वहाँकी आवादीमें एक ही तरहके लोग हैं: लेकिन हिन्दोस्तानमें तो कई कोमें वसती हैं। फिर हिन्दोस्तान एक और वजहसे प्रतियोगिता परीक्षाओं-के लिए अयोग्य स्थान है; यहाँके विभिन्न निवासियोंके शिक्षा स्तर्रोमें वहत अन्तर है—शिक्षाकी दृष्टिसे मुसलमान पिछड़े हुए हैं; और इस स्त्रे (यू.पी.) के हिन्दू वंगालियोंके मुकाविलेमें शिक्षामें पिछड़े हुए हैं।" सरसैयद उत्तरी भारतके उच और मध्यम वर्गीय मुसलमानोंके निर्वि-वाद नेता थे; और स्वाभाविक था कि उनके उद्गारोंपर राजनीतिक वहस छिड़ जाय । अपने मतकी पुष्टिमं सर सैयद खुलकर कुरानका हवाला दिया करते थे, जिसे वे अपने लोगोंका सबसे वड़ा दोस्त मानते थे। लखनऊके मुहम्डन शिक्षा कांग्रेसके अधिवेशनके फीरन वाद ही उन्हें सरका खिताव मिला। यह आदर उस समय वहुत महत्त्वका समझा जाता था।

जब १८८८ में यू. पी. के लेक्टिनेण्ट गवर्नरने इलाहावादमें कांग्रेसका अधिवेशन न होने देनेके लिए भरसक रोड़े अटकाये, कांग्रेस विरोधी आन्दोलनने काफी जोर पकड़ा। उस वर्ष कुछ हिन्दुओंने गौवध विरोधी आन्दोलन आरम्भ किया और अलीगढ़-विचारके लोगोंको इससे कांग्रेसके खिलाफ एक और हथियार मिल गया। वावजूद इसके, लिपयाना, जलंधर होशियारपुर, कपृर्थला, अमृतसर, छपरा, गुजरात, जम्मृ, फिरोजपुर, कसर, मुल्तान, अम्याला, सहारनपुर, मुण्जफरनगर, दिल्ली, रामपुर, वरेली, मुरादाबाद वगैरहके मुल्लिम मजहबी नेताओंके दस्तखतोंसे एक फतवा जारी किया गया जिसमें घोषणा की गयी थी कि मुसलमान काँग्रेसमें शामिल होनेके लिए आजाद हैं। ये सब नेता खुद काँग्रेस अधिवेशनमें भाग लेनेको उत्सुक थे। लेकिन इनमें प्रतिनिधियोंकी नियमित योग्यताओंकी एक कभी थी—ये अंग्रेजी नहीं जानते थे।

१८८८ के कांग्रेस विरोधी कार्योंकी चरम सीमा कहर राजमकों द्वारा 'संयुक्त भारतीय देशमक्त संघ' (लिमिटेड इण्डियन पेट्रिआटिक एसोसियेशन) नामी एक संस्थाको जन्म देना था। प्रत्येक व्यक्ति इस संघका सदस्य हो सकता था। इसके उद्देश्य थे—(१) पार्छमेण्टके सदस्योंको विश्वास दिलाना कि भारतीय जनता कांग्रेसके साथ नहीं है

१. तुपील अहमद—वही पुस्तक पृष्ट २८८-८९

और 'इसके गुमराह करनेवाले वक्तन्योंका' विरोध करती है। (२) कांग्रेस विचारधाराके विरोधमें प्रचार करना।

संघकी पहली मीटिंगमें निश्चय किया गया कि अंग्रेजीमें एक पित्रका निकाली जाय और इसकी नीति निर्धारित करनेके लिए यूरोपियन सम्पादक नियुक्त किया जाय। इस अभिसिन्धके पींछे वेकका कृटनीतिज्ञ दिमाग था, यह वात इससे सिद्ध हो जाती है कि इसे बनानेके बारेमें मेजे गये गरती खतोंपर उनके ओर सर सैयदके दस्तखत थे। संघके सदस्य मुख्यतया, मुसलमान नवाय, हिन्दू राजे, खिताब पाये हुए लोग और कुछ अंग्रेज थे। इसका वार्षिक सदस्यता छुक्क एक पौण्ड था। राजा शिवप्रसाद इसके सबसे कर्मट सदस्योंमेंसे थे। उन्होंने सरकारको यह मुझाव देकर कि कांग्रेसको गैरकानूनी करार दे दिया जाय सबसे वाजी मार ली। सर सैयदको अपनी सफलतापर बहुत हर्ष हुआ और उन्होंने अपने जीवनी-लेखक कर्नल ग्रैहमको लिखा "……… मैंने तथाकथित राष्ट्रीय कांग्रेस (नैशनल कांग्रेस) की मुखालफतमें एक बहुत वड़े कामकी जिम्मेदारी ली है, और एक संघ बनाया है।"

लेकिन एक सीमित क्षेत्रके वाहर सर सैयद और वेककी आयाज नहीं मानी जाती थी । वहुतसे मुसलमान अभीतक कांग्रेस अधिवेशनों में भाग ले रहे थे और उनमें शामिल होना उन्होंने जारी रखा । १८८७ में सर सैयदने लखनऊमें अपना पहला कांग्रेस विरोधी भाषण किया । इस वर्षके कांग्रेसके अधिवेशनके अध्यक्ष वम्यईके मशहूर मुसलमान बदरुद्दीन तैयव जी थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशनमें वग्वईके अंजुमने इस्लामकी नुमाइन्दगी की । उन्होंने इस मतकी मुखालफत की कि मुसलमान कांग्रेसमें न शरीक हों।

ं लेकिन वेकने अभी तक हिम्मत न हारी थी। अलीगढ़ कॉलेजके, जहाँसे वाकी सब मुस्लिम शिक्षा-संस्थाओंके मुकाबिलेमें ज्यादा मुसलमान स्नातक (ग्रेजुएट्स) निकलते थे, प्रधानाष्यापककी हैसियतसे वेकके पास मुसलमानोंके दिमागकी चार्भो थी। उन्हें शिक्षणकार्यसे अधिक उनके व्यक्तित्व वनानेमें अधिक दक्षता प्राप्त थी। यदि उन्हें अपने अभीष्टकी सिद्धिके लिए सचाईको तोड़ना-मरोड़ना भी पड़े तो भी वेक मुसलमानोंको हिन्दुओं-के खिलाफ खड़ा करनेके किसी मौकेसे न चूकते थे। स्पष्ट था कि ईमानदारी या अन्तरात्मा उनको कभी कष्ट नहीं देती थी। १८८९ में चार्ल्स ब्रेडलॉने मारतीय प्रशासनमें सुधार आरम्भ करनेका सवाल पार्लमेंटमें उठाया। जैसा कि हम देख चुके हैं, ब्रेडलॉके विधेयक (विल) का आग्रय भारतमें प्रजातन्त्रवादका एक उस्लका ग्रुरू करना था। वेकने तुरन्त ही ब्रेडलॉके विघेयक के खिलाफ मुसलमानी-लोकमत जागरित करना आरम्म कर दिया । चूँकि उन्हें अपनी सफलतामें किंचित् सन्देह था, लिहाजा उन्होंने चालवाजीकी शरण ली। लगमग उसी समय हिन्दुओंने गो-वध-विरोधी उद्देलन शुरू किया था। वेकने अनेक मुसलमानोंकी तरफसे एक स्मृतिपत्र तैयार किया जिसमें यह सावित करनेकी चेष्टा की गयी थी कि भारत प्रजातान्त्रिक संस्थाओं के अयोग्य है। अलीगढ़-विद्यार्थियों के जत्थे भिन्न-भिन्न शहरोंमें हस्ताक्षर-आन्दोलन चलानेके लिए भेजे गये। स्वयं वेक नौजवानोंकी एक टोलीके साथ पहिले ही दिल्ली खाना हो गये। वहाँ वे प्रसिद्ध जामा मस्जिदके फाटक-पर बैठ गये और वहींसे अपने विद्यार्थियोंको राहगीरोंके पास जाते देखते, जुमेकी नमाजसे

१. ग्रेहम—लाइफ एण्ड वर्क ऑफ सर सैयद अहमद खाँ, पृष्ठ २७३

लोटे मुसलमानोंको समझाया जाता कि स्मृतिपत्रमें (जो अंग्रेजीमें था) सरकारसे मुसल-मानोंके गौ-कुशीके इककी हिफाजत करनेकी प्रार्थना की गयी है, क्योंकि हिन्दू उन्हें उससे वंचित करनेकी योजना बना रहे हैं। इस प्रकारसे २०७३५ हस्ताक्षर इकट्ठे किये गये और पार्लमेंटके सामने स्मृति-पत्र पेश कर दिया गया।"

इस स्मृतिपत्रकी न[े] तो किसी माने हुए मुस्लिम नेताने अगुआई की थी और न इसपर किसीके हस्ताक्षर ही थे।

जब वेक हिन्दू और मुसलमानोंके बीच दरार डालनेकी जीतोड़ कोशिशों कर रहे थे, वाइसराय लार्ड डफरिनने प्रस्तावित सुधारोंमें मुसलमानोंके लिए पृथक प्रतिनिधित्वका मुझाब रखकर इस प्रयत्नको पूरा कर दिया। डफरिनकी भारत सरकार और अंग्रेजी सरकारने इसको बहुत होशियारीसे हासिल किया। उन्हें इस बातका भय था कि शायद पार्लमेण्ट पृथक निर्वाचनको स्वीकार न करे। अधिकृत सुधार विधेयक (रिफार्म्ज बिल) में इसकी व्यवस्था नहीं की गयी थी और न ऐक्टमें ही कहीं इसका जिक्र था। लेकिन विनियमन (रेगुलेशन्स) बनानेवालोंको दिये गये निर्देशोंमें पृथक निर्वाचनकी व्यवस्था की गयी थी।

१८९० के कांग्रेस अधिवेशनमें सुधार प्रस्तावपर बोलते हुए एक सुसलमान सदस्य सैयद सर्फुद्दीनने इसका तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सुसलमान अल्प-संख्यक हैं और सुधारोंसे उनका अहित होगा, इस तर्कमें जरा भी दम नहीं है। उन्होंने कहा "आप पटना शहरको ही लीजिये, म्यूनिस्पैलिटीमें २० सीटे हैं बावजूद इस बातके कि हिन्दू बहु-संख्यक हैं, वे अधिकतर मुसलमानोंको ही चुनते हैं। बीसमें तेरह मुसलमान सदस्य हैं। वम्बईमें हिन्दू जबरदस्त बहुमतमें हैं, फिर भी वहाँ पाँच पारसी, तीन यूरोपियन, दो हिन्दू और दो मुसलमान सदस्य हैं। इमारे देशमें अभी तक बहुमत और अल्पमतके प्रश्नके ऊपर कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न हुई है और न इस प्रकारका कोई सवाल उठना ही चाहिये।"

डा॰ अम्बेडकरने कहा है कि इस व्यवस्थाक आरम्भके लिए कीन जिम्मेदार था, यह एक रहस्य है। पृथक निर्वाचनकी योजना किसी संघटित मुसलमान संघके आन्दोलनका परिणाम तो थी नहीं। तब यह किसने ग्रुरू की १ यह कहा जाता है लाई डफरिनने इसका आविष्कार किया था, जिन्होंने १८८८ में ही विधान परिपदके प्रतिनिधित्वके प्रक्रनपर इस बातपर जोर दिया था कि इंगलैण्डकी तरहकी प्रतिनिधित्व-प्रणाली भारतमें लागू नहीं की जा सकती। यहाँपर हितोंको प्रतिनिधित्व देना होगा।

एक सवाल और उठता है कि किस बातने लार्ड इफरिनको यह योजना पेश करनेको मेरित किया ! ऐसा समझा जाता है कि मुसलमानोंको कांग्रेससे अलग करनेका विचार, जो तीन वर्ष पहले ही उत्पन्न हो चुका था, इसके लिए उत्तरदायी है। जो भी हो, इस ऐक्ट द्वारा मुसलमानोंके लिए प्रथक प्रतिनिधित्व पहली बार भारतीय संविधानका एक अंग वन गया।"

१. वही पुस्तक पृष्ट--३००

२. अम्बेडकर-पाकिस्तान ऑर पार्टीशन ऑफ इण्डिया-पृष्ट-२४०

सर मुह्म्मद शफीका 'माइनॉरिटीज सब कमेटी ऑफ दी फर्स्ट राउण्ड टेवुल कॉन्फ्रेंस'
 (इण्डियन पुडिशन) का भाषण पृष्ट-५७

थ. राजा नरेन्द्रनाथका भाषण, वही पुस्तक, पृष्ट ६%

विना किसीके माँगे हुए १८८८ में डफरिनकी सुधार-समितिने पृथक् प्रतिनिधित्वके सिद्धान्त का प्रस्ताव सामने रखा। वेक द्वारा चलाया हुआ इस्ताक्षर आन्दोलन इसके वाद हुआ और यह साफ समझा जा सकता है कि वेकने वाइसरायसे सम्पर्क स्थापित कर लिया था और अपने लोकतन्त्र विरोधी प्रस्तावोंके पक्षमें किसी प्रकारका दिखाऊ तर्क उपस्थित करनेका प्रयत्न कर रहे थे।

१८९३ में वेकने कहा कि तिलक्के गणपित-उत्सवोंसे मुसलमानोंकी भावनाओंको दुःख पहुँचता है। ३० दिसम्बर सन् १८९३ को सर सैयदकी सहायतामें उन्होंने उत्तरी भारत का मुहम्मडन आंग्ल प्राच्य सुरक्षा संघ (दि मुहम्मडन एंग्लो ओरियण्टल डिफेन्स एसोसियेशन आच अपरइंडिया) कायम किया। यद्यपि वेकका भारतीय देशभक्त संघपर पूरा प्रभाव था, फिर भी अपनी अभीष्ट सिद्धि वे उसकी सहायतासे नहीं कर सकते थे, क्योंकि गैर मुसलमान भी इसके सदस्य थे। इसलिए उन्होंने 'देशभक्त संघ'को खत्म करके केवल मुसलमानोंका एक संघटन खड़ा कर दिया, जिसके मन्त्री वे स्वयं वने।

अपने उद्घाटन-भाषणमें उन्होंने कहा "भारतीय देशभक्त संघ दोषयुक्त सावित हुआ, क्योंकि इसके कायोंने जन उद्घे लनोंका रूप ग्रहण कर लिया था। इसमें पचास संघ सम्मिलित थे। इसके अलावा यह सिर्फ मुसलमानोंका ही संघटन नहीं था, हिन्दू भी इसके सदस्य थे। इम यह प्रस्ताव करते हैं कि इस नये संघमें, जिसको हम बना रहे हैं, किसी भी शाखाको न शामिल किया जाय। और न कोई सार्वजनिक सभा की जाय। संघकी परिषदको समस्त अधिकार दे देने चाहिये।"

वेकने एक अंग्रेजी पत्रिकामें लिखा "इस देशमें पिछले कुछ वर्षोंमें दो आन्दोलन हुए हैं। पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं और दूसरा गोवध विरोधी आन्दोलन। पहला आन्दोलन अंग्रेजोंके खिलाफ है और दूसरा मुसलमानोंके। कांग्रेसका ध्येय अंग्रेजोंके हाथोंसे' देशकी वागडोर छीनकर हिन्दुओं के हाथ सौंप देना है। यह हथियार कानून (Arms Act) को वापस लेनेकी माँग करती है, फौजी व्ययमें कमीकी माँग करती है जिसका नतीजा सीमा प्रान्तकी सुरक्षामें कमजोरी होता है। मुसलमानोंको इन माँगोंसे कोई सहातुभूति नहीं हो सकती। गोवध रोकनेके लिए हिन्दुओंने मुसलमानोंका वहिष्कार तक करना प्रारम्भ कर दिया है.....जिसका नतीजा आजमगढ़ और वम्बईके दंगोंका रक्तपात है। यह अंग्रेजों और मुसलमानोंके लिए अत्यावस्थक हो गया है कि वे इन आन्दोलनकारियोंसे लड़नेके लिए एक हो जाब और गैर मुनासिय प्रजातान्त्रिक शासन-प्रणालोको लागू होनेसे रोकें क्योंकि वह देशकी जहनीयतके विपरीत और गैर जरूरी है। इसलिए हमारी सम्मतिमें सरकारके प्रति वफादारी और आंग्ल-मुस्लिम गठवन्थन होना चाहिये।"

सुरक्षा संघके उद्देश्य थे (१) मुस्लिम-भारतके विचारींसे अंग्रेजोंको आमतौरसे और सरकारको विशेष तौरपर अवगत कराना व मुसलमानोंके राजनीतिक अधिकारींकी सुरक्षा करना। (२) भारतमें अंग्रेजी शासनको मजवूत करनेके लिए वनाये गये नियमोंकी पूरी

तुफैल अहमदकी उसी पुस्तकसे अशोक मेहता और अच्युत पटवर्धन द्वारा 'दी कम्यूनल ट्राइएंगिल'में अनुवादित, पृष्ठ २६

२. वही पुस्तक पृष्ठ ५९

हिमायत करना । (३) मुसलमानोंमें राजनीतिक उद्देलन पैलनेसे रोकना । (४) शान्ति-स्थापनाकी सहायता करना और जनतामें राजमिक्की मावना पैदा करना ।

कांग्रेस और हिन्दू विरोधी उद्देलनमें वेकने कोशिश की कि अंग्रेज मुसलमानींका पक्ष लें। कांग्रेस, उन्होंने कहा, अंग्रेजोंके विरुद्ध है और हिन्दू मुसलमानों के। वे मुसलमानोंको यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि कांग्रेस हिन्दू समाजके एक हिस्सेके लिए राजनीतिक सत्ता चाहती है लिहाजा कांग्रेसको फौजी न्ययमें कमीकी माँगका मुसलमान समर्थन न करें क्योंकि इससे हुकूमत कमजोर हो जायगी। वे यह सिद्ध करनेमें संलग्न ये कि अंग्रेज और मुसलमानोंके हित एक ही हैं क्योंकि गोवध-विरोधी आन्दोलन दोनों समाजोंके लोगोंके भोजनका प्रधान भाग छीननेका एक राजनीतिक पैतरा है, जिससे उन्हें नुकसान पहुँचाया जा सकता था। उनका नारा था कि ब्रिटिश और मुसलमान दोनोंको अपने समान खतरे कांग्रेस व हिन्दूके खिलाफ एक हो जाना चाहिये। इस प्रकारके तर्कसे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत प्रजातान्त्रिक संखाओंके अयोग्य है। वेककी राजनीतिका यह दौर सर सैयद व दुधा अपने अनुयायियोंसे कहते थे कि गायकी कुर्वानी करके अपने हिन्दू भाइयोंको नाराज करना अनुचित है क्योंकि गो-कुशीसे उनकी दोस्ती स्थादा कीमती है।

वेकने पार्लमेंटमें पेश करनेके लिए एक और आवेदनपत्र लिखा और उसपर हजारों मुसलमानोंके दस्तखत करवाये। इसमें काँग्रेसकी भारत और ईगलैंप्डमें सिविल सर्विस परी-क्षाओंके करनेकी साँग टुकरा देनेकी प्रार्थना की गयी थी। ब्रिटिश हुक्मतका खुद भी इस साँगको मान लेनेका कोई इरादा नहीं या और उसने सधन्यवाद मुसलमानोंकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुरक्षा संघ (डिफेन्स एसोसियेशन)की परिपदके सामने सरकारका जवाब पेश किया गया और परिपदने भारत सच्चिवके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित की।

वेकके, मुसलमानोंके वगैर प्रतियोगिता-परीक्षाओंमें वैठे सिविल सर्विसमें सीधे भर्ती कर लिये जानेके प्रयासने उसको बहुत जन-प्रिय बना दिया ।

१८९५ में वे इंगलैण्ड गये । उनके वहाँ लगातार किये गये भाषणों में भारतीय राज-नीतिको गुमराह करनेवाला विवरण था । उन्होंने कहा कि (१) मुसलमान और अँगरेज दोस्त वन सकते हैं लेकिन हिन्दू और मुसलमान नहीं । (२) मुसलमान कभी भी ऐसी शासन प्रणाली स्वीकार न करेंगे जिसमें बहुसंख्यक हिन्दू उनपर हुकूमत करें । (३) भारतीयों को प्रजात कि शासन-प्रणाली पसन्द नहीं है— वे राजतन्त्रको श्रेयस्कर समझते हैं । (४) विद्रोहके वीच और वादके मुसलमानों के सियासी तर्जे अमलने मुस्लिम समाजको हिन्दुओं की उद्देलनकारी राजनीति के प्रति सावधान कर दिया है, और मुसलमानों को राजभक्त बना दिया है । (५) मुसलमान एक साथ परीक्षाएँ लेनेके विरोधी हैं क्यों कि इसके फलस्वरूप निष्यक्ष अँग्रेज हाकिमों के स्थान-पर मुसलमान-विरोधी हिन्दू आजावेंगे ।

अलीगढ़ कॉलेजकी १८९७ की फरवरी माहकी पित्रकाके अनुसार सुरक्षा संघकी अपनी वापिक रिपोटमें वेकने इस वातकी तरफ इशारा किया या कि संघकी परिपदकी अगली मीटिंगमें सर सैयद काँग्रेसकी फौजी-खर्चेमें कमीकी माँगके खिलाफ तजवीज पेश करेंगे। सर सैयदने वास्तवमें ऐसा ही किया। इनका प्रस्ताव था कि संघकी रायमें भारतमें एक राष्ट्रीय सेना होनी चाहिये लेकिन यह संघ फौजी व्ययमें किसी भी कमीके खिलाफ है। वे और एक कदम आगे गये और सीमाओंपर सेना वढ़ानेकी माँग की।

सितम्बर १८९९ में वेककी मृत्यु हो गयी। जैसा कि हाईकोर्टके प्रधान-न्यायाधीश सर आर्थर स्ट्रैचीने उनको मृत्युपर कहा या भारतीय रंगमंचसे साम्राज्यकी जह समानेवाला एक अंग्रेज चला गया। उनके साथ ही मुहम्मडन सुरक्षा संघ भी छुप्त हो गया। सर सैयदका देहान्त एक वर्ष पूर्व ही हो गया था।

वेकके देहान्तके पश्चात् अलीगढ़ कालेजके प्रधानाध्यापक श्री थियोडोर मॉरीसन हुए । आप वहींके भृतपूर्व प्रोफेसर थे और वेकने आपको राजनीतिक कामोंकी शिक्षा दी थी। वारतवमें उनको शिक्षा तो पहले ही लन्दनमें ग्रुरू हो चुकी थी जहाँ उन्होंने 'देशमक्त संघ' (पेट्रियॉटिक एसोसियेशन) की शाखा खोल दी थी, वादमें आप लन्दनमें वेकके प्रधान प्रतिनिधि वन गये। मुस्लिम विद्यार्थियोंको नौकरी दिलानेके लिए रोजगार दिलाऊ दफ्तर खोलकर मॉरीसनने प्रधानाध्यापकीका कार्यकाल आरम्म किया। यह अलीगढ़-कॉलेजकी परीक्षाओंके अनुरूप ही या ताकि विद्यार्थीं अपनेको मविष्यका सरकारी नौकर समझें और राजनीतिक आन्दोलनसे वचे रहें।

बेकके पदिवहोंपर चलते हुए मॉरीसनने घोषणा की कि भारतमें प्रजातन्त्र अल्प-संख्यकोंको लकड़हारों और भिश्तियोंकी दशामें पहुँचा देगा। मुसलमानीको यह सलाह ऐसे समयमें दी गयी जब कि हिन्दी-उर्दू विवादमें हारकी वेदनासे उत्तेजित होकर मुसलमान एक राजनीतिक संघटन बनानेकी सोच रहे थे। संक्षेपमें कहानी यह है कि-कुछ हिन्दुओंकी प्रार्थनापर यू० पी० सरकारने १८ अप्रैल १९०० को एक प्रस्ताव प्रकाशित किया जिसमें सरकारी दफ्तरों और अदावतोंको देवनागरी लिपिमें लिखी दरखास्तें स्वीकार करनेका आदेश दिया गया था। इन कामोंके लिए अभीतक उर्दूको ही मान्यता प्राप्त थी। आदेशमें यह भी कहा गया था कि आइन्दासे अदालती सम्मन और सरकारी घोषणाएँ हिन्दी उर्दू दोनोंमें जारी की जायँ; और सरकारी नौकरियोंके लिए दोनों भाषाओंका ज्ञान आवश्यक है। इस प्रस्तावका अर्थ अलीगढ़-विचारधाराके मुसलमानोंने यह निकाला कि उद्का दर्जा घटा दिया गया है। मुस्लिम-रोप प्रगट करनेके लिए प्रान्तमें कई जगह विरोध-समाएँ की गयीं। सरकारके प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित कर्नेके लिए हिन्दुओंने अलग सभाएँ की । कई महीनोंतक अखनारोंमें यह विवाद उप्रतासे चला जिससे हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीचकी खाई वढ़ गयी। १३ मई १९०० को छतारीके छपतअली खाँकी अध्यक्षतामें हुई एक सभामें यू० पी० के एक लेपिटनेण्ट गवर्नरसे इस प्रस्तावको वापस हेनेकी प्रार्थना करनेका निश्चय किया गया । इसी प्रकारकी एक सभा अगस्तमें लखनऊमें हुई जिसमें अलीगढ़ कॉलेजके मन्त्री नवाव मोहसिनुल-मुल्कने एक जोरदार भाषण किया जिसपर लेपिटनेण्ट गवर्नरने आक्षेप किया । नवाव साहवसे अलोगढ़-कॉलेजके मन्त्रिपद और अंजुमने-उर्दू की राजनीतिमेंसे चुनने-को कहा गया । उन्होंने अंजुमने उद् से हाथ खींच लिया। इस घटनाने मेहदीहसन और वकारल मुल्क जैसे मुस्लिम नेताओंको मुसलमानोंके लिए एक राजनीतिक संघटन कायम करनेके लिए प्रेरित किया। वेककी मुसलमानोंको राजनीतिमें हिस्सा न लेनेकी सलाहका उल्लेख करते हुए मोह्सिनुलमुल्कने इस प्रस्तावका विरोध किया।

मॉरीसनने भी इसका विरोध किया । इन्स्टीट्यूट-गजटमें प्रकाशित एक पत्रमें उन्होंने

लिखां कि प्रस्तावित योजनाका अर्थ कांग्रेसके कदमोंपर चलना होगां । उन्होंने तर्क दिया कि उच्च रिथितिक लोग सरकारकी नाराजीके भयसे किसी राजनीतिक संवटनमें नहीं सम्मिलित होंगे । इससे मुसलमानोंमें भेदभाव पैदा हो जायगा । पचीस सालसे सरकार मुसलमानोंके साथ अधिक आदरका व्यवहार करती आ रही है और सियासी संवटनसे मुसलमानोंके हितों-को फायदा होनेकी जगह नुकसान ही ज्यादा होगा । उनको अपना मित्रिय सरकारके हाथोंमें सींप देना चाहिये और कांग्रेसकी नकल नहीं करनी चाहिये । सरकारी नौकर मुसलमानोंकी चुपचाप मदद करते हैं और राजनीतिक माँगें उटा कर वे अपनेको इस मुविधा-विद्येपसे वंचित कर लेंगे।

नवाय मोहसिनुल मुल्कने मॉरीसनकें इस खतको मुसलमानोंके लिए निर्देश माना और प्रस्तावित योजना समाप्त कर दी गयी।

लेकिन योजनाके समर्थकोंने अलीगढ़के राजनीतिक वातावरणको अनुकूल न समझ-कर सैयद मुहम्मद शरीफुद्दीनकी अध्यक्षतामें एक मीटिंग लखनऊमें बुलायी। नवाव वका॰ क्ल मुल्कने अगुआई करते हुए कहा कि कुछ समयसे मुसलमानोंके अधिकारोंपर हमला किया जा रहा है। उन्होंने उर्द-हिन्दी-विवादका जिक किया और तय मुहम्मडन राजनीतिक संघटन वनानेकी योजना पेश की जिसके उद्देश्य निम्नलिखित थे। (१) मुसलमानीका मत सरकारके सामने विनम्रतासे पेश करना । (२) मुसलमानोंको यह समझा देना कि उनकी भलाई अंग्रेजी ग्रासनपर निर्भर है। (३) मुसलमानोंको कांग्रेसकी प्रतिनिधि-संस्थाओं और एक साथ परीक्षाएँ लेनेकी माँगमें शामिल होनेसे रोकना। इस मीटिंगमें विभिन्न जिलोंमें शाखाएँ संघटित करनेके लिए एक समिति नियुक्त कर दी गयी। नवाय वकावल मुल्कने कई जिलोंका दौरा किया, वहाँ सभाएँ कीं और मुसलमानोंको राजनीतिमें दिलचरपी लेनेको उत्साहित किया। वे पहला काम जो करते वह जिला मजिल्ट्रेटसे मिलना था। लेकिन मुखलमान राजनीतिसे डरे हुए थे, यहाँतक कि अलीगढ़में २६ जुलाई १९०३ की मुहम्डन-राजनीतिक संघटनकी एक सभामें सभापति श्री आफताव अहमदको अपने श्रोताओंसे कहना पड़ा कि सरकार मसलमानोंके राजनीतिक कार्योंमें भाग लेनेसे घट हो जायगी, यह डर येतु-नियाद है: बिल वे तो पहलेसे कहीं ज्यादा राजभक्त हो जायँगे। परन्तु यह संघटन चल नहीं सका और पाँच वर्षोंमें ही मृतप्राय हो गया।

॰ अध्याय ९

वंगभंग और वहिष्कार आन्दोलन

अंग्रेजों के पैर भारतमें मजबूतीसे जमनेके बादसे ही स्वतन्त्रताकी लड़ाईमें बंगालने अगुआई की थी। ब्रिटिश भारतका वह राजनीतिक दृष्टिसे सबसे ज्यादा सचेत स्वा था। पर वहाँ एक अनोखी स्थित दृष्टिगोचर हुई जिसमें अंग्रेजोंको राजनीतिक प्रगति रोकनेकी आशािकरण नजर आयी। सन् १९०५ में बंगालका जो भाग पूर्वी बंगाल बना वह पिक्सिमी वंगालकी सुकाबले राजनीतिक, आर्थिक और शिक्षाकी दृष्टिसे पिछड़ा हुआ था। पूर्वी बंगालकी अधिकांश आवादी मुसलमानोंको थी और 'फूट डालो व राज करो' की नीति अपनाकर लार्ड कर्जनने इस इलाकेको पिक्सिमी बंगालकी आन्दोलन-मूलक राजनीतिसे अलग काट देनेका फैसला किया। कर्जनका विश्वास था कि मुसलमानोंको अधिक मुविधाएँ देनेसे वे राजनीतिसे विमुख रखे जा सकते हैं। अविभाजित बंगालमें अधिक योग्य होनेके नाते अधिक तर नौकरियाँ हिन्दुओंको ही मिलती थीं। पर यदि मुस्लिम बहुमतका एक स्वा अलग बनाया जा सके तो मुसलमानोंको सरकारी नौकरियोंमें अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकता था। फर्जनने ठीक ही सोचा था कि यह तर्क मुसलमानोंको पसन्द आयगा और उन्हें बंगाल विभाजनका समर्थक बनाया जा सकेगा। उनका विश्वास था कि इस ढंगसे वंगालका आधा स्वा कलकत्तेकी राजनीतिक छूतसे बच जायगा।

विभाजन प्रशासकीय सुविधाके नामपर किया जानेवाला था। यह सही भी है कि वंगालका स्वा इलाकेमें वहुत बड़ा था। सन् १८७४ में आसाम वंगालसे अलग कर दिया गया था और उसमें सिलहट, ग्वालपाड़ा और काचार के तीन वंगलाभाषी जिले शामिल कर दिये गये थे; पर तब इसकी आलोचना नहीं के बराबर ही हुई थी क्योंकि जनमतकी तब शक्ति नहीं थी। बादमें, १८९२ के सुधारोंके बाद सरकारने प्रस्ताव रखा कि चटगाँवको भी वंगालसे निकाल दिया जाय, पर प्रवल विरोधके कारण यह प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं किया गया। वंगालकी कर्जन योजनामें पूरा उत्तरी वंगाल और फरीदपुर व बारीसालके जिले पूर्वी वंगालमें आते थे। अगर प्रशासकीय सुविधाके लिए विभाजन इस प्रकार किया जाता जिससे वंगला भाषी जनताका विभाजन न होता तो वंगालियोंको कोई विरोध न होता पर कर्जन-योजनामें वंगला भाषी जनता भी वँटती थी। योजनाका उद्देश्य तो राजनीतिक था ही, ''उसका विचार, विवाद और निर्णय सब गोपनीय ढंगसे हुए—जनताको कार्नोंकान खबर किये वगैर।'' जनमतके नेताओंने समझा कि उनका अपमान हुआ है, उन्हें धोखा दिया गया है और उनकी वेइज्जती हुई है।

सन् १९०२ में यह योजना प्रकाशमें आयी और जुलाई सन् १९०५ में विभाजनकी वाजान्ता अनुमित मिली। इस वीच वंगाल ही नहीं पूरे भारतमें अभृतपूर्व राजनीतिक चेतना पैदा हुई। दिसम्बर सन् १९०२ से अक्तूबर सन् १९०५ तक दोनों वंगालोंमें दो हजारसे ज्यादा सार्वजनिक सभाएँ हुई जिनमें ५०० से लेकर ५०,००० तक श्रोता भाग लेते थे। सरकार निराश हुई, क्योंकि विरोधकी पहली वाढ़में हिन्दू और मुसलमान दोनोंका उत्साह वरावर था। ढाकाके नवाव सर सलीमुल्लाहने "आन्दोलनके ग्रुरुमें ही विभाजनका 'पाशविक प्रवन्ध' कहकर विरोध किया। था।"

लेकिन कर्जन दृढ़पतिज्ञ व्यक्ति ये और उन्होंने मुसलमानोंको विभाजन समर्थक वनानेका जिम्मा अपने ऊपर लिया। कर्जनके जीवनी लेखक लवेट कोजरने लिखा है—
. 'उन्होंने शायद ही कभी ऐसी कोई प्रतिज्ञा की हो, जिसे वे प्रा न कर सके हों। सन् १८८७ में जब वे भारत आये थे लाई डफरिनके साय खाना खाकर लीटते वक्त गवनंभेण्ट हाउसके शानदार फाटकपर रक कर उन्होंने कहा था—''अगली बार जब में इस फाटकके भीतर प्रस्ता तो वाइसराय वनकर।'' और सन् १८९८ में ४० वर्षकी अवस्थामें वे बाइसराय वनकर ही उस फाटकमें बुसे। उनसे कम उम्रके वाइसराय सिर्फ डल्होंजी ही थे जो ३६ सालकी उम्रमें ही गवर्गर-जनरल वनकर आये थे।

फरवरी सन् १९०४ में वे जनताकी नाड़ी टटोलने पूर्वी वंगालके दौरेपर निकले। हर जगह उन्हें वच्चोंके झुण्ड "हमें आसामी न वनाओ" की तिस्तियाँ स्याये मिले। यात्रामें हर जगह कर्जन प्रमुख मुसलमानींसे मिले और मैमनसिंह, चट्गाँव व ढाकामें मुसलमानींकी वड़ी-वडी समाएँ कर उन्होंने भाषण कर उन्हें समझाया कि वंगाल-विभाजनमें मेरा उहेश्य प्रशा-सकीय सुविधा देखना भर नहीं है, मैं एक मुस्लिम एवा बनाना चाहता हूँ, जहाँ इस्लाम प्रधान होगा, जहाँ इरलामके अनुयायियोंका वोलवाला होगा। यही वात ध्यानमें रखते हुए मैंने ढाका कमिरनरीके वाकी दो जिले भी अपनी योजनामें शामिल करनेका फैसला कर लिया है।" अपने एक भाषणमें कर्जनने कहा कि विभाजनसे "पूर्वा वंगालके मुसलमानोंको वह एकता प्राप्त होगी जो मुसलमान वादशाहों और स्वेदारोंके राजके बाद नसीव नहीं हुई थी । (१९९१) लेकिन बंग-भंगका अपना स्वप्न पूरा होते देखनेके पहले ही कर्जनको पता चला कि शीघ ही उन्हें इस्तीमा देना पढ़ेगा । उन्होंने इस्तीमा दिया भी पर उसके पहले शिमलामें केन्द्रीय विचायिका कींसिलकी वैठकमें (जिसमें सिर्फ सरकारी सदस्य ही भाग ले सके) विभाजन सम्बन्धी कानून पास करा लिया। नवम्बर सन् १९०५ में उन्होंने वाइसरायपद छोडा पर वंग-भंग कानून १६ अक्तूबरको ही लागू करा दिया गया था । महीनोंने प्रमुख मुसलमानींको वाइसरायकी नीतिका अनुसरण करनेके लिए बहलाया-फुसलाया या दवाया जा रहा था। खुद नवाव सलीमुलाइने अपना मत बदल दिया, शायद इसलिए कि उन्हें सन्ती दरपर एक लाख पैंड उघार दे दिया गया था। वड़ी संख्यामें सरकारी नीकरियाँ मुसलमानोंके लिए सुरक्षित कर दी गर्यो । बहुत-सी जगहें इसलिए खाली रखी गर्या कि उपयुक्त मुस्लिम उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे।^६

१. खबेट फ्रेनर—'इण्डिया अण्डर कर्जन एण्ड आफ़्टर' पृष्ट ७

२. वहीं पुस्तक, पृष्ठ ३८०

मजूमदार, इ'डियन नैशनल इवॉल्यृशन, पृष्ठ २२२

४. नेविनसन-दि न्यू स्पिरिट इन इंडिया एए १९१

५. गुरुमुख निहाल सिंह—'लैण्डमार्क्स इन इण्डियन कार्न्स्टीट्य रानल एण्ड नेरानल डेवलपमेण्ट', पृष्ट ३१९

६. नेविनसन-वही पुस्तक, पृष्ट १९२

लेकिन तब भी मुसलमानोंका वड़ा भाग अड़िग रहा और इसमें कुलीन सामन्तीवर्गके लोग भी शामिल थे। सन् १९०६ के कांग्रेस अधिवेशनमें सर सलीमुलाहके भाई नवावजादा ख्वाजा अतीकुलाहने कहा—"मैं आपसे बताता हूँ। यह कहना ठीक नहीं है कि पूर्वी वंगालके मुसलमान वंग-भंगके पक्षमें है। असिलयत यह है कि विभाजनका समर्थन कुछ प्रमुख मुसलमान अपने हितसाधनके लिए कर रहे हैं।" कलकत्तेके केन्द्रीय मुहमडेन एसो-सियेशनने भी यही मत प्रकट किया और अपने सेकेटरी नवाव अमीर हुसेन द्वारा इसे. सरकारके पास भेज दिया। अमीर हुसेनने लिखा—"मेरी समितिकी रायमें वँगलाभाषी जातिके किसी भागको बहुत बड़ी आवश्यकताके विना पृथक नहीं किया जाना चाहिये और समितिकी रायमें अभी ऐसी किसी आवश्यकताका अस्तित्व नहीं है।"

एक अंग्रेजी पत्रमें सर हेनरी कॉटनने लिखा— "पूर्वी वंगाली समाजके दोनों वर्ग अधिकांशतः एक स्वरसे विभाजनकी निन्दा और विरोध कर रहे हैं। लेकिन अपढ़ और असंयत मुस्लिम भीड़को हठीले या धर्मान्ध दूर्तोने हिंसाके लिए उभारा है। यह दिखानेका निष्फल प्रयास किया गया कि कुछ मुस्लिम नेता विभाजनके पक्षमें हैं।"

सरकार और ब्रिटिश सरकारके भारत सचिवको सैकड़ों स्मृतिपत्र भेजे गये; उनमेंसे एकपर पूर्वी वंगालके ७०,००० व्यक्तियोंके हस्ताक्षर थे। कुछ वंगाली नेताओंने मिलकर या वाइसरायको तार भेजकर उनसे यह अनुरोध करनेका निश्चय किया कि यदि वंगाल-विभाजन अनिवार्य ही है तो योजनामें इस प्रकार संशोधन कर दिया जाय कि सारी वंगला-भाषी जनता एक स्वेमें आ जाय। लेकिन कर्जन अपने निश्चयपर अड़े रहे, क्योंकि जैसा सरेन्द्रनाथ बनजोंने कहा—"इसके पीछे एक राजनीतिक चाल है" जो तारमें प्रस्तावित संशोधनसे पूरी नहीं होती।

विभाजनके विरुद्ध आन्दोलन जैसे-जैसे बढ़ता गया कर्जन भारतमें बदनाम होते गये। यह आन्दोलन ब्रिटिश पार्लमेण्टमें मी चला जहाँ हर्बर्ट रावर्धने विवाद छेड़ा, पर कर्जन अंडे रहे। योजनाके विरोधको उन्होंने 'बनाया हुआ' बताया।

इंगलैण्डमें भी कर्जन 'फूट डालो और राज करो' की नीतिके लिए भी अति दुस्साइसी या संशयात्मक सफलतावाले व्यक्ति गिने जाने लगे। भारतसचिव बौडिरकसे वे लड़ चुके थे और बौडिरिकको परेशान होकर अपना पद छोड़ना पड़ा था। बौडिरकको "कर्जनके कारण वहुत परेशानी उठानी पड़ी थी और उनकी धारणा थी कि वाइसरायके रवेये और रखके कारण उनका काम वहुत हदतक रक गया था।" सन् १९०५ में इंगलेण्डमें उदारदलीय सरकार बनी और मॉलेंने भारत-सचिवके पदपर काम करना पसन्द किया। उसके बाद शीघ ही कर्जनको अपना पद छोड़ना पड़ा और उनकी जगह लार्ड मिण्टोने नवम्बर सन् १९०५ में आकर कार्यभार सँभाला। लेकिन केन्द्रोय सचिवालयमें 'कर्जन वातावरण' अब भी मौजूद था और कर्जन लन्दनसे वैठे दिल्लीके निर्णयोंपर असर डाल्नेकी कोशिश कर रहे थे।

१. नेविनसन, वही पुस्तक पृष्ट १९१

२. मजूमदार—"इंडियन नेशनल इवॉल्यूशन" पृष्ठ २२३

३. जे० डी० रीस द्वारा 'दि रीभल इण्डिया'में पृष्ठ १७८ पर उद्घृत

थ. वनर्जी, वही पुस्तक, (ए नेशन इन मेकिंग ?) पृष्ठ १८८

५, मेरी, काउण्टेस आव मिण्टो, 'इण्डिया, मिण्टो एण्ड मॉर्ले' १९०५-१९१०, पृष्ठ १९

मिण्टोको इस हस्तक्षेपसे परेशान होकर भारत-सचिव मौर्टेको लिखना पड़ा कि कर्जन वहाँपर वैठे उन निर्णयोंपर असर डाल्नेके लिए आन्दोलन सा चला रहे हैं जिनसे उनका यहाँ सीधा सम्यन्ध था; और इससे स्वभावतः सन्देह होता है कि वे अपने समर्थकोंसे यहाँ सम्पर्क स्थापित किये हुए हैं।' मिण्टोने 'उस विरोधी देशी भावना' की भी शिकायत की जो कर्जनने ''वंगालके विभाजन और अपने तत्सम्बन्धी भाषणोंसे पैदा कर दी थी।''

मिण्टो शान्ति-स्थापनाके उद्देश्यसे आये थे, पर उनके पल्ले पड़ा विद्रोहके वादका सबसे अशान्त युग । जैसा कि ईदरके महाराजा सर परताप सिंहने कहा—कर्जनने मिण्टोके लिए शूल-शैया तैयार की थी, उनके विस्तरपर काँटे विद्या दिये थे और मिण्टोको उन काँटों-पर लेटना ही था । असंतोष और अशान्तिके जो बीज कर्जनने वोये थे वे मिण्टोके कार्यकाल-में फले-फूले । हिंसा, सैनिक विद्रोह, राजनीतिक हत्याओं, वमवाजी और राजद्रोहके खुलेआम प्रचारका एक दौर-सा चल पड़ा और सरकारने इसका जवाब कड़े दमनसे दिया ।

२० जुलाई सन् १९०५ को वंगभंगकी सरकारी घोषणा हुई, जिसने हजारों नौजवानोंको अंग्रेजोंके खिलाफ आर्थिक युद्ध होड़नेकी प्रेरणा दी। कांग्रेसके मंच, समाचारपत्रों
और पुस्तकोंसे भारतीय जनताने अनिगनत वार सुना था कि विटिश उद्योग और व्यापारके
हितमें अंग्रेज शासक जो आर्थिक शोषण कर रहे हैं उससे देश तेजीसे गरीय होता जा रहा है।
इसलिए अंग्रेजी मालका विहष्कार अपने आप ही एक हथियारकी तरह जनताके सामने आ
गया। स्वदेशी आन्दोलन—देशी उद्योगका पुनस्त्थान और विकास—इस हथियारका
दूसरा हिस्सा था। वायकाट या विहष्कारसे ब्रिटिश सामानका आयात कम होता था और
देशी उत्पादनको वढ़ावा मिलता था।

७ अगस्त सन् १९०५ को स्वदेशी आन्दोलनका श्रीगणेश हुआ। उसीके साथ ही विभाजनके विषद पहला प्रदर्शन भी हुआ। यह प्रदर्शन ऐतिहासिक था। कलकत्तेके नवयुवक जे॰ चौधुरीके नेतृत्वमें कालेज स्कायरसे टाउनहालतक एक गंभीर जल्स बनाकर चले। भारतीय दूकाने बन्द थीं। भीड़ इतनी वड़ी थीं कि उसे तीन मिन्न-भिन्न सभाओं में वितरित करना पड़ा। इन तीनों सभाओं में सुरेन्द्रनाथ बनर्जीन भाषण किये।

सार्वजिनिक सभाएँ और सम्मेलन राजनीतिक कार्य-क्रमके दैनिक अंग वन गये। तय यह सोचा गया कि सिर्फ इनसे ही काम न चलेगा और कोई ठीस कदम उठाया जाय। एक सुझाव यह भी आया कि भारतीय सभी अवैतिनिक पद—जैसे कि आनरेरी मिजिस्ट्रेंट और जिला बोडों व म्युनिसिपैलिटियोंकी सदस्दतासे इस्तीफे दे दें। पर इसमें आंदिक असफलता-की आशंका थी, इसलिए नेताओंने इस सुझावको कार्यक्रमका अंग नहीं बनाया।

कुछ अंग्रेजों और अंग्रेजीके पत्रोंने भी विभाजनका विरोध किया। 'स्टेट्समेन'ने विभाजनपर क्षोम ही प्रकट नहीं किया, विस्क दायकाट आंदोलनकी निन्दा करनेकी जगह उसका औचित्य सिद्ध करनेकी कोश्रिश की। उसने लिखा—'यायकाटके प्रस्तायक निस्संदेह चीनी उदाहरणसे प्रेरित हुए हैं और उन्हें आशा है कि अंग्रेजी मालका विहिष्कार उतना ही प्रभावकारी और अंग्रेजोंके लिए क्षतिकारी होगा, जितना अमरीकी वस्तुओंका चीनी विहिष्कार दिखाई पड़ता है। इस धारणापर कई कारणोंसे अंग्रेज मुस्करा उटेगे। लेकिन तब भी पूरे आन्दोलनको गैरईमानदारीसे भरा एक उवाल मान लेना सरकारकी भूल होगी। इसके

३: मेरी, वही पुस्तक, पृष्ट ४९

विपरीत, कुछ समयसे यह स्पष्ट हो रहा है कि वंगालवासी विरोधके दूसरे अधिक प्रभावकारी तरीके सीखते जा रहे हैं। राजनीतिक आन्दोलनमें वर्त्तमान-परित्थितिने जो व्यावहारिकता ला दी है, उसे सरकारने अवस्य देखा होगा।'

लेकिन सरकार अपना निर्णय वदलनेको तैयार नहीं थी। हर तरफ निराशा छा रही थी। जनताको सरकार वदलनेका अधिकार नहीं था। उसने दूसरा सबसे कारगर तरीका बिटेनके खिलाफ आर्थिक दबाव हालनेका तरीका अपनाया। जनताकी इस मनी-दशामें वायकाटका चीनी उदाहरण अपनाया गया था। जैसा कि वनर्जीका ख्वाल था, वायकाटका विचार कई नेताओं के मनमें एक साथ उठा। पवनामें एक सार्वर्जानक सभामें पहली वार इसकी चर्चा की गयी; फिर तो असंख्य समाओं में यह बात दोहरायी गयी। अखवारों में अमरीकी सामानके चीन द्वारा वहिष्कारकी कथाएँ छपने लगीं और भारतीयों से ब्रिटिश मालके खिलाफ यही हथियार उठानेकी अपीलें की जाने लगीं। समाओं में ब्रिटिश सामानके विहन्कार और स्वदेशीको अपनानेके प्रस्ताव पास होने लगे।

सवसे अधिक उद्देखित विद्यार्थी समाज था जो अपने उत्साहमें कभी कभी 'अति' कर वैठता था । उसमें अभृतपूर्व उमंग थी । वनजींने अनेक सार्वजिनक सभाओंमें छात्रोंके समक्ष भाषण किये और छात्रोंने लगनके साथ उनके वताये मार्गका अनुसरण किया। अगर कोई लड़का विदेशी कपड़े पहनकर आता, तो उसके कपड़े फाड़ डाले जाते रिंपियन कालेजमें एक परीक्षामें उत्तर लिखनेके लिए जो कापियाँ छात्रोंको मिली वे विदेशी कागजकी थीं। छात्रोंने कापियाँ छूनेसे इनकार कर दिया। लड़कोंका विरोध इतना उप्र था कि उसकी अवहेलना खतरनाक हो सकती थी। देशी कागज लाया गुरा और फिर परीक्षा वदस्त्र हुई। 138 सुरेन्द्रनाथ बनजींकी पाँचवर्षीया नातिनने एक सम्बन्धी द्वारा भेजे गये एक जोड़ा जूते यह कहकर वापस कर दिये कि ये विलायतके वने हैं। एक छ। सालकी वन्ची वीमारीमें संनिपातमें चिल्ला उठी कि 'में विदेशी दवा नहीं खाऊँगी।' अक्सर विवाहोंमें मिली ऐसी विदेशी मेंटें अस्वीकार कर दी जातीं जो भारतमें भी वन सकती थीं। पण्डित और पुरोहित बहुधा ऐसी पूजापर वैठनेसे इनकार कर देते जिसमें देवतापर चढ़ानेके लिए विदेशी सामग्री होती । जिन दावतींमें विदेशी नमक या शकरका प्रयोग होता अति,य भोजन करनेसे धनकार कर देते। जनमत इतना शक्तिशाली हो उठा कि कोई वंगाली विदेशी कपड़ा खरीदनेकी छोचता तक नहीं था; जो उसके सस्तेपनके कारण उसे खरीदनेको मजवूर भी होते, वे भी रातमें खरीददारी करते।

भारतीय उद्योगको प्रोत्साहन मिला । जुलाहोंको अपना खोया हुआ पेशा मिल गया और उन्होंने वहिष्कार आन्दोलनको दुआएँ दीं । एकके बाद एक, साबुन, माचिस, स्ती कपड़ेके कारखाने खुलने लगे । जुलाहोंकी खुशी चन्दरोजा थी । जब देशी मिलें वड़ी मात्रामें उत्पादन करने लगीं, करघेका कपड़ा फिर उसी तरह गायव हो गया, जैसे मैनचेस्टरका माल आनेपर हुआ था । स्वदेशी बैंक और बीमा कम्पनियाँ चल निकलीं ।

नवयुवक, खासतौरपर छात्र, घूम-घूमकर स्वदेशीका प्रचार किया करते थे। चारों ओर अभृतपूर्व राजनीतिक चेतना दिखाई देती थी; हाकिम इससे आदांकित थे। जिला मजिस्ट्रेटोंने सभी शिक्षा-संस्थाओंके प्रधानोंको चेतावनी भेजी कि अगर आप अपने छात्रोंको

१. बनर्जी, ए नेशन इन दि मेकिंग, ए० १९६

वायकाट, धरना आदि "तथाकथित स्वदेशी आन्दोलनसे सम्बन्धित तुराइयोंसे नहीं रोकते तो आपकी संखाकी सरकारी सहायता वन्द कर दी जायगी, छात्र-वृत्ति प्रतियोगिताकी सुविधा छीन ली जायगी और विश्वविद्यालय मान्यता छीन लेगा। यह गहती चिट्टी कलकत्ते स्कूलों, कालेजोंको नहीं मेजी गयी थी, शायद इसलिए कि ज्यादा उपद्रव न हो। लेकिन चिट्टीसे मुफिस्सलमें भी उत्तेजना फैली। इस आदेशका विरोध और उल्लंघन करनेके लिए एक संस्था वन गयी। इस गहती चिट्टीकी लांछना करते हुए 'स्टेट्समेन' ने लिखा—'हम उस मूर्ख अफसरका नाम जानना चाहेंगे जिसकी रायपर लेपिटनेण्ट गवर्नरने इस आदेशको स्वीकृति दी। इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि सरकारको गलत राय दी गयी है। यह राय या तो ऐसे व्यक्तिने दी है जो स्थितिसे विलकुल अनजान है, या फिर पिछले कुछ हफ्तोंकी सनसनीसे जो बुरी तरह डर गया है। "सरकार ऐसी वच्चों जैसी और निरर्थक नीतिमें भटक पड़ी है जिसका व्यावहारिक नतीजा सिर्फ यह होगा कि 'शहीदोंकी फौज खड़ी हो जायगी।' स्टेट्समैनकी चेतावनी भविष्यवाणी सिद्ध हुई। इस आदेशके फलस्वरूप सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलोंका भी वायकाट शुरू हो गया। वंग जातीय विद्यापरिषद्की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य 'राष्ट्रीय ढंगसे, राष्ट्रीय नियन्त्रणमें राष्ट्र-नियितकी पृतिके लिए शिक्षा देना' था। परिषद्ने पूर्वी वंगालमें ही २४ राष्ट्रीय हाईस्कृल खोले।

सरकार जनमतके इस प्रवल उवालमे आशंकित हो दमनका रास्ता अपनाने लगी। शान्ति व सुरक्षाके नामपर जनताकी भावनाकी अभिव्यक्ति रोकनेकी लगातार कोशिश की जाती रही और हमेशाकी तरह दमननीति पलटकर दमनकारियोंपर आधात करने लगी। "जितने ज्यादा दमनकारी हथियार उठाये गये, जनताकी उत्तेजना और असन्तोप उतना ही बदता गया और हर हथियार उसे रोकनेमें असफल रहा।"

विहक्तर सभाओं और प्रदर्शनोंमें जोश लानेके लिए वन्देमातरम् गाया जाता । ज्यादा जोश और सैनिक वृत्तिके गाने मिलते तो हिन्दू युवक उन्हें और भी उत्साहसे प्रहण करते । 'वन्देमातरम्' हाकिमोंके लिए भयका एक कारण वन गया । पूर्वी वंगालके नये स्वे की सरकारने इस गानेको गैरकान्नी करार दिया और सड़कोंपर इसका गाना जुमें हो गया ।

व्यक्तिगत वातचीतमें लाई मिण्टो स्वीकार करते कि वंग-विभाजन गलत हुआ । सुरेन्द्रनाथ वनजीं उन्होंने साफ-साफ कहा—"तुम्हारे प्रान्तकी तरह मेरे देशका विभाजन होता तो में भी तुम्हारी तरह सोचता।" पर जब इण्डियन एसोसियेशनका एक प्रतिनिधिमण्डल उनसे मिला तो उन्होंने कह दिया—'विभाजन तो हो चुका अब कुछ नहीं हो सकता।"

'पूर्वी गंगाल' १६ अक्त्वरको अस्तित्वमें आनेवाला था। नेताओंने उसे राष्ट्रीय शोक दिवसकी तरह मनाना तय किया। उस दिनका एक कार्य-क्रम बनाया गया। उस दिन वीमारोंको छोड़कर और किसीका खाना नहीं पकेगा, सब काम-काज बन्द रहेगा, सब लोग सबेरे नंगे पैर जाकर गंगा-स्नान करंगे, बंगालके एक्तिकरणके लिए बरावर प्रयत्न करते रहने-का सब लोग प्रण करंगे। यह कार्य-क्रम कलकत्तेमें मुफस्सिलके नेताओंकी रायसे बनाया गया था। इसका खूब प्रचार किया गया। कलकत्तेमें बंगालकी एकताके प्रतीकस्वरूप एक भवन स्थापित करनेका मुझाव मुरेन्द्रनाथ बनजींने दिया। उस भवनके लिए एक जमीन भी चुन

१. वही पुस्तक, पृ० १९६

ली गयी । शामको उसी खलपर एक सार्वजितक सभा हुई। पर पूरे कार्यक्रममें सबसे हृदयप्राही और पवित्र राखी वन्धन था। भ्रातृत्व भावनाके प्रतीक खरूप हर न्यांता हर दूसरे व्यक्तिको लाल धागे वाँध रहा था। सबेरेसे ही गंगाके किनारे राखियोंका हर लिये स्त्री-पुरुपोंकी भीड़ स्नान घाटोंपर इकटरी होने लगी। लोग मित्रों और सम्वित्वयोंको तो राखी बाँध ही रहे थे, अजनिवयोतकको वाँघ देते थे। भवनका शिलान्यास श्री आनन्दमोहन वसने 'वन्दे मातरम् के गगनभेदी नारों के बीच किया। उन्हें उनकी मृत्यु-होयासे कुरसीपर वैठाकर लाया गया था। सारे दिन सड़कों और वाजारोंमें 'वन्देमातरम्'की ही गूँज सुनाई पड़ती रही। विभाजन-विरोधी आन्दोलनके लिए उस दिन एक राष्ट्रीय कोप खोला गया जिसमें एक पिनाणान विरावा आन्दालनक विष्य हुई समाप्ते हुई समाप्ते हिनमें ही छोटे-छोटे चन्दों छे ७० हजार कपये इकट्ठे हो गये। भवन-स्थलपर हुई समाप्ते रिटायर हुए जज सर गुरुदास वनजी भी थे जिन्होंने अपने ओजपूर्ण भाषणमें वंगभंगका विरोध किया। विभाजनने समाजके हर वर्गको इतना विश्वव्य कर दिया था कि राजनीतित्र व गैरराजनीतिज्ञमं कोई अन्तर न रह गया था। शिलान्यासके पहले सर आहातीय चीष्ट्ररीने नीचे हिखी बोपणा पढ़ी (इसे प्रसाव नहीं कहा गया था) । श्री चौधुरीकी अंग्रेजी घोपणाका

"वंग राष्ट्रके सार्वजनीन विरोधके बाद भी सरकारने वंगालका विभाजन कर दिया है, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरने वँगलामें अनुवाद करके सुनाया— तो हम शपथ हेते हैं और घोषणा करते हैं कि हम वंगमंगके दुष्पिरणामोंको दूर करनेके हिए पा रम रायम रा र जार भाषणा भरता र एक हम यगमगण उप्पारणामाणा दूर करनका रहारी । ईहवर हमारी यथाशक्ति सब कुछ करेंगे और अपने राष्ट्रकी एकता कायम खेंगे। ईहवर हमारी

किसीने आपित की कि घोषणा तो सिर्फ सरकार कर सकती है, इसिलए इसे घोषणा सहायता करे।"

नेताओंने वंगभंगके अस्तित्वको हो स्वीकार नहीं किया और अगला प्रान्तीय ग्राजनीतिक सम्मेलन वारीसाल (पूर्वी वंगाल) में किया। पूर्वी वंगालमें आन्दोलनका राजनातिक वन्मलन वारावाल (पूर्वा वसाल) म किया। पूर्वा वसालम आन्दालनका और भी ज्यादा जोर था। वहाँ हर शहरमें करहेमातरम् के नारेवर रोक लगा दी गयी थी। न कहा जाय, पर वह सुनी नहीं गयी। जार ना जापा जार ना । पहा हर बाहरण वर्षमाधरण क नारभर राज लगा हा गया था। समेलनको सम्मेलनको सम्मेलनको स्थित संयोजकोने सम्मेलनको स्थलताको हिएसे हाकिमोंसे समझौता कर रामाण्यक वाराणाल ।स्थत स्ववास्थान सम्मल्नका स्वरूलताका हायत हा।कमास समझाता कर लिया था कि वड़ी सड़कोंपर 'क्रव्हेमातरम्' के नारे नहीं लगाये जाउँगे। वाहरसे आये प्रति ाल्या या । म युवा प्रवृत्ता प्रमाणरण के वार युवा लगाय जायगा। आवरण आय आप आते हमानेका निधियोंने भी अनिच्छा से इस समझौतेको माना। पर उन्होंने कहा कि सम्मेलन में नारे लगानेका हिमारा अधिकार अञ्चल है। "आशंका यह थी कि पुलिस हस्तक्षेप करेगी और सम्मवतं हमारा आवकार अलुज्य है। आयाका वह या ।क प्राक्ष्य हसाल्य करगा आर सम्मवतः वह या। क प्राक्ष्य करगा आर सम्मवतः वह कि के कि के कि सी हालतमें पुलिसके वह वह वह प्रायोग भी। किन्तु समीको ताकीद कर दी गयी थी कि वह है। उन्हें स्वाविक कर हो गयी थी कि वह है। उन्हें स्वाविक कर हो गयी थी कि वह है। उन्हें समीको ताकीद कर हो गयी थी कि वह है। उन्हों समीको ताकीद कर हो गयी थी कि वह है। उन्हों समीको ताकीद कर हो गयी थी कि वह है। उन्हों समीको ताकीद कर हो गयी थी कि वह है। उन्हों समीको ताकीद कर हो गयी थी कि वह है। उन्हों समीको ताकीद कर हो गयी थी कि वह है। उन्हों समीको ताकीद कर हो गयी थी कि वह है। उन्हों समीको ताकीद कर हो गयी थी कि वह है। उन्हों समीको ताकीद कर हो गयी थी कि वह है। उन्हों समीको ताकीद कर हो गयी थी कि वह है। उन्हों समीको ताकीद कर हो गयी थी कि वह है। उन्हों समीको ताकीद कर हो गयी थी कि वह है। उन्हों समीको ताकीद कर हो गयी थी कि वह है। उन्हों समीको ताकीद कर हो गयी थी कि वह है। उन्हों समीको ताकीद कर है। उन्हों समीको ताकीद कर हो गयी थी कि वह है। उन्हों समीको ताकीद कर हो गयी थी कि वह है। उन्हों समीको ताकीद कर हो गयी थी कि वह है। उन्हों समीको ताकीद कर हो गयी थी कि वह है। उन्हों समीको ताकीद कर हो गयी थी कि वह है। उन्हों समीको ताकीद कर हो गयी थी कि वह है। उन्हों समीको ताकीद कर है। उन समीको ताकीद कर है। उ प्रयोगका जवान न हैं और छाठी या छड़ी भी हेकर न चहें। अ जुल्स अध्यक्ष श्री ए० रस्ल अगर उनकी पत्निक नेतृत्वमें चला। लाठियाँ हिये पुलिस पहलेसे ही तैयार खड़ी थी। जल्हसपर जार उनका वर्णाक नर्राक्त पूर्ण । जाव्या विव पुल्सिमें न था । उसने नेताओंको तो निक्छ जाने हमला करनेके लिए अवसर हुँ हुनेका वैव पुल्सिमें न था । उसने नेताओंको तो विक्छ जाने हमला कर्मका लिए अवतर हु ज़्नका वय आल्वान न या। उत्तन म्याजाका ता । नकल जान हिया, पर जैसे ही अहातेसे निकलकार नोजवानोंका समूह जुल्हामें शामिल हुआ, जन्म हिया, पर जैसे ही अहातेसे निकलकार नोजवानोंका समूह जुल्हामें शामिल हुआ, प्रभाग गर्याय स्वर्णाय स्वर्णित निकाली स्वर्णेमात्रम् की आवाज भी नहीं निकाली स्वर्णेमात्रम् की अवाज स्वर्णेमात्रम् स्वर्णेमात्रम्यात्रम् स्वर्णेमात्रम् स्वर्णेमात्रम् स्वर्णेमात्रम् स्वर्णेमात्र चाण गुरू कर रूपा, हालाक स्वरान अवतक वृत्त्वातरम् का आपाण ना नहा निकाला वृत्त्वातरम् का आपाण ना नहा निकाला वृत्त्वातरम् के वोचे हाले गये। एक लड़केको भी। वृत्त्वेमात्तम् को विहले जुल्सवालोके हाथोंमें वृधे थे, वे नोच हाले गये। एक लड़केको भी। वृत्त्वेमात्तम् को विहले जुल्सवालोके हाथोंमें वृधे थे, वे नोच हाले गये। एक लड़केको ना । न्यूनाप्पर्यं जा । न्यून अस्रायायाय हानाम नव ना न्याय आर्था वह वन्देमातरम् । तालावमे फेंक दिया गया । उसका अपराध यही धा कि हर हाठी प्रहारपर वह वन्देमातरम्

। लगाता ना । सुरेन्द्रनाथ वनजींको गिरफ्तार कर अंग्रेज मजिस्ट्रेटके घर हे जाया गया । मजिस्ट्रेटने सुरेन्द्रनाथ वनजींको का नारा लगाता था।

वनजी व उनके साथ आये कालीप्रसन्न काव्य-विशारद दोनोंका अपमान किया। काली प्रसन्न पुरोहित थे और कुरता आदि नहीं पहिनते थे। जैसे ही वे वँगल्में वुसने लगे, मिलस्ट्रेट चिछाया— 'तुम कैदी हो, वैठ नहीं सकते, तुम्हें खड़ा रहना होगा।' वनजींने कहा—'में आपके घर आपसे अपमानित होने नहीं आया। में अपेक्षा करता हूँ कि मुझसे शिष्टाचारका व्यवहार किया जायगा।' उनका यह उत्तर 'अदालतकी मानहानि' मान लिया गया और उनसे माफी माँगनेको कहा गया। माफी माँगनेसे इनकार करनेपर वनजींपर २००) जुर्माना ठोंक दिया गया। फिर उनपर एक गैरकानृती जुल्समें शामिल होने और वे नारे लगानेका अभियोग लगाया गया जो कानृती तौरपर विजित थे। वनजींने समय माँगा वह नहीं मिला, उन्होंने गवाह पेश करनेकी अनुमित माँगी वह नहीं मिली, उन्होंने पुल्स कप्तानसे जिरह करनी, चाही, उसकी भी इजाजत नहीं मिली। इस अभियोगमें भी उनपर २००) जुर्माना हुआ।

सुरेन्द्रनाथ वनजीं मिजस्ट्रेटके घर ले जाये जाने के बाद उन्हीं की रायपर सम्मेलनकी काररवाई जारी रही । कार्यक्रम खस्म हुआ, प्रतिनिधि 'वन्देमातरम्' की गगनमेदी ध्विन करते हुए वारीसालकी सड़कोंपर फेल गये । पुलिसने इस्तक्षेप नहीं किया । लेकिन दूसरे दिन सम्मेलनके सभाभवनमें आकर पुलिस कप्तानने आख्वासन माँगा कि कार्यक्रमके अन्तमें प्रतिनिधि सड़कोंपर 'वन्देमातरम्' के नारे नहीं लगा वेंगे । अध्यक्षने प्रतिनिधियों से राय ली आंर आख्वासन देनेसे इनकार कर दिया । इसपर कप्तानने मिजस्ट्रेटका आदेश पढ़कर सुनाया जिसमें सभाको गैरकान्ती घोषित किया गया था । प्रतिनिधि सभाभवन छोड़कर 'वन्देमातरम्' के नारे लगाते हुए तितर-वितर हो गये । वे फिर एक घरमें एकत्र हुए जहाँ वनजीं, विर्यनन्वन्द पाल और काव्य-विशारदने अपने भाषणों में वंगभंग विरोधी आन्दोलन चलाते रहने और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोगकी श्राय पालन करने की अपील की ।

वारीसाल सम्मेलनमें सरकारी व्यवहार देखकर नवयुवकोंका मन वैधानिक राजनीतिसे विचलित होने लगा और स्वराज्य प्राप्तिके लिए वे अराजकता और आतंकवादकी सोचने लगे। दमनचक और जोरसे चला। 'स्वदेशीके प्रचारकों और कार्यकर्चाओंपर मुकदमें चलाये जाते, उन्हें दुःख दिये जाते, सार्वजनिक समाओंपर रोक लगायी जाती; शान्त मुहल्लोंमें फीजी पुलिस तैनात कर दी जाती और ये पुल्सिवाले शान्त नागरिकोंपर हमले किया करते। वनारीपुरा (वारीसाल) के बहुतसे निवासी तो गुरखा सिपाहियोंके अत्याचारों-के कारण गंभीरतापूर्वक वहाँसे भाग निकलनेकी सोचने लगे। भले आदिमयोंपर 'स्वदेशीकी चिट्टियाँ' बाँटने और राजद्रोहके झुटे मुकदमे चलाये जाते।'' इन घटनाओंकी नोजवानोंपर क्या प्रतिक्रिया हुई, यह एक उदाहरणसे स्पष्ट हो जायगा। एक दिन दो नवयुवक मुरेन्द्रनाथ वनजींसे एकान्तमें मिले और कहा—"एक अति गंभीर मसलेपर हम आपकी सम्मित लेने आये हैं। हमने सर वेम्पफील्ड फुलर (पूर्वी वंगालके गवर्नर) को मार डालनेकी योजना वनायी है, और हम आज रातको ही रवाना हो रहे हैं। आप क्या कहते हैं?'' उन्होंने कहा कि हम फुलरको इसलिए मार डालना चाहते हैं कि उसके गुरखा सिपाहियोंने यनार्रा पुरामें हमारी माँ विह्नोंकी इन्जत लूटी है। हम इसका वदला फुलरसे लेंगे। इसमें जो

१. वनजीं, वही पुस्तक, पृष्ट २३३

खतरा है वह हम उठावेंगे और अपनी माँ वहिनोंके सम्मानके लिए जरूरत पड़नेपर मरेंगे भी । बनजींने उन्हें यह योजना त्याग देनेकी सलाह दी और बताया कि फुलर तो इस्तीफा दे ही चुके हैं। योजनाकी निश्चित असफलताका जिक्र करते हुए बनजींने उन दोनों नव-युवकोंसे बचन ले लिया कि वे इस कामसे विरत हो जावेंगे।

ये दो नवयुवक तो सरकारकै विरुद्ध उत्पन्न घृणाके प्रतीक मात्र थे । वंगालमें अनेक आतंकवादी संस्थाओंकी स्थापना हो गयी और उनके संघठन वंगालके वाहर भी वनने लगे।

वैधानिक स्तरपर वारीसाल काण्डकी निन्दा वंगाल व दूसरे प्रान्तोंमें सार्वजनिक सभाओंमें की गयी। एक मन्दिरके अहातेमें सुरेन्द्रनाथ बनर्जीके स्वदेशी अपनानेके भाषणके बाद दस सहस्र व्यक्तियोंने खड़े होकर शप्य लो कि 'ईश्वर साक्षी हो; आनेवाली पीढ़ियोंके समक्ष हम प्रण करते हैं कि जहाँतक सम्भव होगा हम घरकी वनी चोजोंका ही प्रयोग करेंगे और विदेशी वस्तुओंका वहिष्कार करेंगे। ईश्वर हमारी सहायता करे।' यही शपथ वादमें बहुत सी सार्वजनिक सभाओंमें दोहरायी गयी।

पुलिस द्वारा वारीसाल-सम्मेलन भंग होनेका वर्णन करते हुए सुरेन्द्रनाथ वनर्जीने लिखा है—जो व्यक्ति सार्वजनिक आन्दोलनके प्रति उदासीन रहते थे, उन्होंने भी स्वदेशी अपनानेकी शपथ ली और उसे दैनिक जीवनमें कार्यान्वित किया। जो लोग किताबी कीड़े समझे जाते थे, वे भी अपना वैराग्य छोड़ कर्म-भूमिमें उत्तर आये और स्वदेशी व विभाजन विरोधी आन्दोलनोंमें भाग लेने लगे। "वंगभंग-विरोधी आन्दोलनमें भाग लेनेवाले मुसलमानोंकी संख्या कम ही थी। उन्हें तो बताया गया था कि वंगभंग मुसलमानोंकी आर्थिक व राजनोतिक भलाईके लिए ही किया गया है।

समयके व्यतीत होनेसे विभाजनका जरूम भरा नहीं, उल्टे आन्दोलन दिन व दिन जोर ही पकड़ता गया। सभाएँ, प्रदर्शन और हड़तालें सामाजिक जीवनका सामान्य अंग वन गयी थीं। दूसरी ओर फुलर-शासन और अधिक दमनकारी होता जा रहा था। वह खुले आम कह रहा था—रक्तपात हो सकता है। सन् १९०७ तक आन्दोलनने तीन भिन्न रूप ग्रहण कर लिये थे—रचनात्मक, राजद्रोहात्मक और क्रान्तिकारी।

समाचारपत्रोंका भी महत्वपूर्ण योग था। इनका नेतृत्व विपिनचन्द्र पाल और अर-विन्द घोष कर रहे थे। पाल सन् १९०३ से ही अपने साप्ताहिक पत्र 'न्यू इिष्डया' द्वारा राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय शिक्षा और नयी चेतनाका प्रचार कर रहे थे। अरविन्दने भी उत्साह-पूर्वक इसी विचारधाराका प्रचार शुरू किया।

दिसम्बर सन् १९०८ में सरकारने वंगभंग विरोधी आंदोलनके नौ नेताओंको निष्का-सनकी सजा दी। ये थे कृष्णकुमार मित्र, पुलिनविहारी दास, श्यामसुन्दर चक्रवर्ती, अश्विनी-कुमार दत्त, मनोरंजन गुहा-ठाकुरटा, सुबोधचन्द्र मिल्लक, शचीन्द्रप्रसाद वसु, सतीशचन्द्र चटजीं और भूपेशचन्द्र नाग। अखबारोंपर तो आयेदिन मुकदमें चलते थे।

३० वर्ष पहले, भारतीय राजनीतिका श्रीगणेश सुरेन्द्रनाथ वनर्जांके देशन्यापी दौरेसे इस मांगपर हुआ था कि भारतीयोंको सिविल सर्विसोंमें लिया जाय और अव लोगोंसे सरकारी नौकरियोंका बहिष्कार करनेके लिए कहा जा रहा था। वायकाट आंदोलन वंगालसे शुरू हुआ और वहाँसे मद्रासमें फैला। विपिनचन्द्र पालने मद्रास जा कर 'नयी-चेतना' कई भाषणों द्वारा प्रसारित की और भारतमें राजनीतिक सिद्धान्तोंका एक कार्यक्रम पेश किया। पाल वड़े बुद्धिमान, मेधावी और चरित्रवान व्यक्ति थे। वे यूरोप और अमरीका का काफी भ्रमण कर चुके थे। उनके मद्रासके भाषणोंकी पुस्तकके कई संस्करण हाथों हाथ विक गये और इसके प्रभाव खरूप वहाँकी राजनीतिमें एक उग्र दलका संवटन हुआ। पाल जो नयी चेतना उत्पन्न करनेके लिए उत्पुक थे वह एक उदाहरणसे स्पष्ट हो जायगी। उन्होंने एक भाषणमें कहा-अापको हाईकोर्टकी जजी या विधायिका कोंसिलकी मेम्बरी मिल सकती है, शायद कार्यकारी-कोंसिलकी सदस्यता भी मिल जाय। आप विधायिका कोंसिलोंका विस्तार चाहते हैं ? या ब्रिटिश लोकसभामें अपने कुछ प्रतिनिधि भेजना चाहते हैं ? आप सरकारी नौकरियोंमें भारतीयोंका और वड़ा प्रतिनिधित्व चाहते हैं ! हमें देखना यह चाहिये कि ५०, १००, २०० या २०० भारतीय हाकिम क्या इस सरकारको भारतीय सरकार वना देंगे र ... सभी हाकिम भारतीय हो जायँ तब भी वे नीति नहीं निर्धारित कर सकते, शासन चला नहीं सकते, वे तो सिर्फ हुन्म बजाते हैं । एक कोयलके वोल्नेसे जैसे वस्सात नहीं आ जाती, वैसे ही हजारों भारतीय हाकिम भी ब्रिटिश सरकारको देशी या भारतीय सरकार नहीं बना सकते । हाकिम गोरा हो या काला उसे परम्पराएं निवाहनी होती हैं, कानून और नीतिका पालन करना पड़ता हैं और जनतक ये परम्पराएँ न तोड़ी जायँ, विदान्त न बदले जायँ, नीति न बदली जाय, गोरे हाकिमोंकी जगह काले हाकिम रखा देनेसे स्वराज नहीं हो जायगा।"

सरकारी नौकरियोंके वायकाट पर वोलते हुए उन्होंने कहा-'वे कहते हैं-क्या तुम सभी सरकारी नौकरियोंका वायकाट कर सकते हो ? पर हममेंसे यह किसीने कहा ही कव था कि सरकारकी सेवाके लिए एक भी भारतीय न मिलेगा ? जो हम कर सकते हैं वह यह है कि हम सरकार चलाना असम्भव कर दें, उन्हें हिन्दुस्तानी नौकर हुँढ़ना अस-म्भव भले ही न हो। शासन चलाना कई तरहसे रोका जा सकता है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि हर डिप्टी मजिस्ट्रेट कहे कि मैं इस सरकारकी नौकरी नहीं करूँगा। इसका यह मतलव भी नहीं है कि अगर कोई सरकारी नौकरीसे इस्तीफा दे देगा तो उसकी जगह खाली रह जायगी । लेकिन अगर यह भावना देशमें फैल जाय तो सरकारी नौकरोंमें भी यही भावना आवगी और तब एक दिन पूरा दपतरका दपतर हड़ताल कर सकता है। इससे सरकार नहीं टूटेगी पर उसके रास्तेमें अनेक वाधाएँ आवँगी और ये जटिलताएँ या वाधाएँ देशके हर भागमें आने लगीं तो सरकार लगभग ठप हो जायगी। असली चीज तो सरकारकी प्रतिष्ठा है और इस वायकाट आन्दोलनसे उस प्रतिष्ठाके ही मृत्लपर आघात होता है I·····हम **हर** सरकारी नौकरको उस स्तरपर गिरा सकते हैं मानों वह भारतीय नागरिकताके गीरवसे वंचित हो गया हो' 'किसी भी व्यक्तिका सम्मान इसलिए न किया जाय कि वह हाकिम या मुंसिफ या हुज्र सरिस्तेदार है। कोई भी कान्न हमें मजवृर नहीं कर सकता कि घर आने-वालेको हम कुरसी दें ही । मैं अपने घरपर एक मामुली दुकानदारको कुसीं दूँ और डिप्टी मजिस्ट्रेट या सब-जनको न दूँ, कोई व्यक्ति अपनी बेटी किसी गरीव भिखारीको व्याह दे और मजिस्ट्रेटके वेटेको न ब्याहे तो यह करनेका उसे परा अख्तियार है, वह इसमें कान्तकी सीमाके वाहर है।

"निष्क्रिय प्रतिरोध या सत्याग्रहको इंगलैण्डमें कान्ती मान्यता प्राप्त है। सिद्धान्त रूपमें यह भारतमें भी वैध है और अगर कोई नया कान्त बनाकर इसे गैरकान्ती करार दिया गया तो यह कानून वैयक्तिक स्वतन्त्रताके मूल अधिकारीके विरुद्ध पड़ेगा, यह खतर-नाक रास्तेपर चलना होगा । इसलिए मुझे तो लगता है कि स्वराज्य प्राप्तिके लिए जो नकारा-त्मक या निपेधात्मक काम करना है, वह वायकाटसे पूरा हो जायगा। लेकिन स्वराज्यके लिए ठोस और सकारात्मक प्रशिक्षणकी भी आवश्यकता है। यह हमें प्रामीण जीवन के संघटनसे प्राप्त होगा । सरकारसे स्वतन्त्र और उसके समानान्तर अपनी जनप्रिय शासन-व्यवस्था स्थापित करनेका काम हमें अपने कार्यक्रममें शामिल कर लेना चाहिये "यही हमारा असली कार्यक्रम रहेगा।"

विपिनचन्द्र पालको 'साम्राज्यके भीतर स्वराज्य'की माँग जो १९०६ में कांग्रेसके अध्यक्ष दादाभाई नौरोजीने पेदा की थी पसन्द नहीं थी । उन्होंने कहा—'क्या साम्राज्यके भीतर स्वराज्यकी माँग व्यावहारिक लक्ष्य हो सकती है ? इसका अर्थ क्या है ? इसका अर्थ होगा कि या तो हमें सञ्चा स्वराज्य न मिलेगा या इंगलैण्डका सञ्चा साम्राज्य यहाँ न रहेगा।

उनकी भाषणमालासे मदासमें आन्दोलन और उपद्रवोंकी आग भड़क उठी। २७ जुन सन् १९०७ को वाइसरायने भारत सचिवसे विपिनचन्द्र पालको निष्कासन-की सजा देनेकी अनुमति माँगी। उन्होंने लिखा-"पालका व्यवहार दानवी है और उसके खतरेको हम नजर अन्दाज नहीं कर सकते।" वाइसरायका कहना था कि मुकदमे चलानेकी नीति स्थिर है पर कलकत्तेमें ऐसा कोई ज़्री नहीं मिलेगा जो विपिनचन्द्र पालकी धारा १२४ ए (राजद्रोह) में अपराधी घोषित कर दे। "विषिनचन्द्र पाल जैसे खास मामलोंमें" निष्कासन ज्यादा सीधा, कारगर तरीका होगा वनिस्वत मुकदमा चलानेके और इसपर उतना ध्यान भी आकृष्ट न होगा, तथा जनतापर फौरन असर पहेगा।"

बाइसरायने आगे लिखा "" 'हम सबकी धारणा यही है कि भारतीय सेना इस छूतसे वच जाय । फौजी अफसरोंकी रिपोर्ट है कि सिपाहियोंमें उत्तेजक पर्चे खुले आम वँट रहे हैं। इसका और पता लगानेके लिए मैंने सन्देहजनक पत्रोंको रोककर खोलनेकी अनुमति देदी है। वहुत सा राजद्रोहात्मक और उत्तेजक साहित्य पकड़ा गया है। खुिफया विभागकी रिपोर्ट है कि रूस और रूंसी अफसरोंसे भी द्रोहात्मक पत्र-व्यवहारके सवूत मिले हैं। "

विभाजनके बाद जिस दूसरे नेताकी ख्याति और सम्मान बहुत बढ़ा वह तिलक थे। उनकी अदम्य कार्यशक्ति, स्वाधीनता प्राप्तिके लिए उनकी आत्माकी वेचैनी, उनकी व्याव-हारिक साधनसम्पन्नता और सबसे अधिक उनकी धवल और श्रेष्ठ निष्ठाने उनके वंगाली श्रोताओंपर गहरा प्रमाव डाला। सन् १९०५ और १९०६ के कांग्रेस अधिवेशनोंमें प्रतिनिधियोंके वीच उनका व्यक्तित्व ही सबसे ज्यादा चमका। ब्रिटिशराजके खिलाफ आर्थिक शस्त्रकी तरह स्वदेशीके वह पहले समर्थक थे। वायकार आंदोलनमें उन्हें सरकार विरोधी तत्वोंको उभारनेका अभूतपूर्व अवसर दिखाई दिया...तिलकको विपिनचन्द्र पाल व अरविन्द घोष जैसे उत्साही व्यक्तियोंका सहयोग प्राप्त था—ये लोग उनके राजनितिक शिष्य थे।"

तिलक राष्ट्रीय-भारतके नेता वन चुके थे। उनके उग्र अनुयायियोंकी संख्या दिन-वन

मेरी मिण्टो, वही पुस्तक पृष्ठ १४७-४८ 9.

वही पुस्तक पृष्ट १४८

३ वेलेण्टाइन शिरौल 'इंडियन अनरेस्ट' पृष्ठ ५०

दिन बढ़ती जा रही थी। इन अनुयायियों में बड़ी बौदिक शक्तिबाले नेता भी थे। वे अपने देशवासियों व उनकी चित्तवृत्तिसे परिचित थे। शिवाजी और गणेशपूजाको तत्कालीन राजनीतिसे सम्बद्ध कर देनेसे वे उत्सव प्रभावकारी मनौवैज्ञानिक हथियार वन गये। उनके तरीके वंगालमें भी काममें लाये गये और स्वदेशी व वहिष्कार कालीके संरक्षणमें रख दिये गये। और तिलकके तरीके अपनानेवालों में प्रमुख थे नरमदलीय सुधारवादी सुरेन्द्रनाथ वनजीं। उन्होंने भी तिलककी तरह स्कूलों व कालेजोंके छात्रोंकी व्यायामशालाएँ खुलवायीं जहाँ राजनीतिक प्रचार होता। उग्र-पन्थी वंगालियोंने सुरेन्द्रनाथ वनजींको वंगनरेशकी उपाधि दी। यह तव हुआ जब सोनेकी छतरीके नीचे उन्हें एक जल्सका नेतृत्व करते हुए ले जाया गया। जल्सके आगे-आगे कालीकी एक प्रतिमा जा रही थी जो एक अंग्रेजका शरीर रींद रही थी। यह विजयी भारतमाताकी ब्रिटेनपर विजयका प्रतीक थी।"

पूर्वी बंगाल सरकार वरावर आगमें वी डालनेका काम कर रही थी। "छोटे अफसर सिर्फ हिन्दुओं को ही सताते थे। हिन्दू ही सरकारी नौकरियोंसे अलग रखे जाते थे। हिन्दू स्कृलोंको मिलनेवाली सरकारी सहायता ही वन्द की जाती थी। अगर मुसलमान उपद्रय करते तो पुलिस हिन्दुओं के वरोंकी तलाशी लेती और हिन्दू मुहल्लोंमें ही गुरखा फीज तैनात की जाती।

मिण्टोके (जो शान्ति खापनाके लिए उत्सुक थे) कार्यकालमें पूर्वा वंगालमें कर्जनकी नीतिसे ही काम हो रहा था। फुलर नये वाइसरायकी नीतिसर नहीं चलते थे। कर्जनके जमानेमें एक हुकम निकला था कि छात्र विभाजन-आंदोलनमें भाग न लें। पूर्वा वंगालके कुछ क्कूलोंके छात्रोंने जान-वूझकर इस आदेशका उल्लंघन किया। फुलर सरकारने तीन सी लड़कोंके नाम काट देनेका हुक्म निकाला, लेकिन भारतसचिव मीलंके प्रस्तावयर नाम कटना कक गया। इसपर फरवरी सन् १९०६ में फुलरने कलकत्ता विश्वविद्यालयको लिखा कि उन दो स्कूलोंसे मान्यता छीन ली जाय जिन्होंने उस आदेशका उल्लंघन किया था।.... "वाइसरायने यह समझकर कि इससे भारतीयों में आवेश व उद्देग और बढ़ेगा, फुलरको वार-वार सलाह दी कि वह विवेकसे काम ले और नये नियम लाग् होनेसे पहले कके रहें। पर दवनेमें असमर्थ और तिकड़मसे अपना उद्देश पूरा करनेकी धुनमें फुलरने भारत सरकारके पास अपना इस्तीफा मेज दिया। वाइसरायने तुरन्त इस्तीफा स्वीकार कर लिया; इससे फुलर अचम्मेमें पड़ गये।"" मिण्टो, जो फुलर-शासनको गम्भीर खतरा मानते थे, कुछ आश्वस्त हुए।

एक ओर वंगालकी जनता—अधिकांशतः हिन्दू जनता—अपना आन्दोलन उप्रतर करती जा रही थी। दूसरी ओर पूर्वी वंगाल सरकार हिन्दू सुस्लिम वलवे करवा रही थी। चाहे इसका उद्देश्य मुसलमानोंको यह समझाना हो रहा हो कि हिन्दू उनके दुस्मन हैं और एक पृथक् मुस्लिम प्रान्त आवश्यक है। कर्जन रंग-मंचसे हट चुके थे, पर उनके द्वारा नियुक्त डेफ्टिनेण्ट गवर्नर फुलर उनकी नीति पूरी तरहसे लागू कर रहे थे। "मुल्ले देहातों में दस्लामके

१. मेरी मिण्टो, वही पुस्तक प्रष्ट १२१

२. नेविनसत, वही पुस्तक पृष्ट २०२

३. वकन-'ढार्ड मिण्टो' पृष्ट २३७

थ. मेरी मिण्टो, वही पुस्तक पृष्ट ५२

पुनरतथान और ब्रिटिश सरकारके मुसलमानोंके पक्षमें होनेका प्रचार करते घूमते थे। ये मुलले कहते कि अदालतें तीन महीनेके लिए वन्द कर दी गयी हैं, और इस वीच हिन्दू विधवाओंको भगाने, हिन्दू दूकाने लूटने या हिन्दु ओंपर हमले करनेकी कोई सुनवाई नहीं होगी। लाल रंगकी एक पुस्तिका, जिसमें इसी तरहकी अनाप-शनाप वातें लिखी थीं, खूव खुलकर वाँटी गयी।" फुलर मजाकमें इशारा किया करते कि मेरी दो वीवियोंमेंसे मुसलमान वीवी मुझे ज्यादा प्यारी है। "मुसलमान सचमुच ही यकीन करने लगे कि अंग्रेज अफसर उनकी सभी ज्यादित्योंकों माफ करनेको तैयार हैं।" लेकिन वलवे फुलरके जानेके वाद भी जारी रहे।

"१९१० में राजधानी मुस्लिम भीड़के अधिकारमें तीन दिन और तीन राततक रही जव रईस मारवाड़ी सराफ ऌटे गये। हाकिम लोग खुश होकर इन घटनाओंका हवाला देते, हुए कहते कि अंग्रेज शासक चले गये या उन्होंने थोड़ी भी दिलचरपी कम कर दी तो . हिन्दुओंकी यही हालत होगी।" अफसर जनताको समझाते कि वंगाली देश-भक्तों द्वारा चलाये गये स्वदेशी और वहिष्कार आन्दोलनके कारण ही यह अराजकता फैल रही है। लेकिन पूर्वी वंगालमें ही एक अंग्रेज मजिस्ट्रेटने खुलेआम कहा कि उपद्रव वायकाट आन्दो-लनका नतीजा नहीं हैं। यह हो भी नहीं सकता था, क्योंकि स्वदेशी आन्दोलनसे गरीव मुसलमानोंको वड़ा फायदा हुआ था; इन मुसलमानोंमें अधिकतर जुलाहे और मोची थे। एक मुस्लिम स्पेशल मजिस्ट्रेटने कुछ मुस्लिम उपद्रवियोंके मुकद्मेंके फैसलेमें लिखा—'दंगा या बलवा करनेका कोई वहाना या उत्तेजना नहीं थी। उसका उद्देश्य केवल हिन्दुओंको परेशान करना था।" एक दूसरे मुकदमेंके फैसलेमें उक्त मजिस्ट्रेटने लिखा—"सवृत पक्षकी गवाहियों से पता चलता है कि अभियुक्त (एक मुसलमान) ने मुसलमानों की एक भीड़ में एक नोटिस पढ़कर सुनाया और कहा कि सरकार और ढाकाके नवाव वहादुरने हुक्म निकाल दिया है कि हिन्दुओंको छूटने और सतानेके लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायगा।" इसलिए कालीकी एक प्रतिमा खिण्डत करनेके बाद मुसलमानोंने हिन्दू व्यापारियोंकी दूकानें ल्टीं। एक अन्य यूरोपीय मजिस्ट्रेंटने लिखा-''कुछ मुसलमानींने डुग्गी पीटकर एलाने किया कि सरकारने हिन्दुओंको छ्टनका हक दे दिया है।" एक स्त्रीको भगानेके मुकदमेमें इसी मजिस्ट्रेटने लिखा-"सारी घटना इस एलानकी वजहसे हुई कि सरकारने हिन्दू विधवाओं से निकाह कर छेनेकी इजाजत मुसलमानोंको दे दी है।" छेकिन निष्पक्ष मुसलमान भी थे जो समझते थे कि सरकारकी 'फूट डालो और राज करो' की नीति पूरे जोर-शोरसे लागू है।

कुमिल्ला उपद्रवकाण्डके मुकदमेमें एक जजने खुले आम मुसलमानोंके साथ पक्षपात किया। हाईकोर्टने उसकी आलोचना करते हुए कहा—"जज महोदयने गवाहोंको दो—हिन्दू और मुसलमानवर्गोंमें विभाजित कर एक वर्गकी बात मानकर और दूसरेकी वात अस्वीकार कर जो तरीका अपनाया है, उसकी कटुतम आलोचना की जायगी। जज महो-दयको सिर्फ उस सबूतकी ओर ही ध्यान देना चाहिये था, जो उनके सामने पेश किया गया;

१ नेविनसन, वही पुस्तक पृष्ट १९२

२, वही पुस्तक पृष्ठ १९१

३, मजूमदार, वही पुस्तक पृष्ठ २५३

४. नेविनसन, वही पुस्तक पृष्ट 1९३

और जनताक किसी वर्गके साथ उनकी जो सहानुभृति पहलेसे बनी हुई है, उसे मुकदमेमें परिलक्षित न होने देना चाहिये था। ''र

कर्जनकी नीति सफल हुई। वंगालके दंगोंने देशभरका ध्यान आकृष्ट किया और हिन्दू हिन्दूके लिए व मुसलमान मुसलमानके लिए सहानुभृति व समवेदना प्रदर्शित करने लगा। ऐसे मामलोंमें समझदारीका निष्पक्ष दृष्टिकोण रखनेवाले हमेशा कम ही होते हैं।

गोपालकृष्ण गोखलेकी अध्यक्षतामें कांग्रेसका अधिवेदान सन् १९०५ में बनारसमें हुआ । अधिवेदानमें पेदा कर्जन द्यासनकी रिपोर्टके सम्बन्धमें कहा गया था-कांग्रेसका यह अधिवेशन देशके राजनोतिक जीवनमें बड़े संकटके समय हो रहा है। लार्ड लिटनके वाइस-राय-कालके अन्धकार युगके बाद कभी भी देश इतना असन्तुए, हताश और विचलित व व्यग्र नहीं थाः कभी भी इतने राजनीतिक व दूसरे दुर्भाग्योंका शिकार नहीं हुआ थाः कभी भी उच्चाधिकारियोंकी ओरसे ऐसी घृणा और झुउं प्रचारका निशाना न बना था—उसकी अति साधारण माँगें अस्वीकार की गयां और उनकी खिल्ली उडायी गयी, उसकी न्यायोचित प्रार्थनाओंपर गर्वोन्मत्त 'नहीं' कह दिया गया, उसकी महान अभिलापाओं और आकां-थाओंको ठोकर मारी गयी या वकवास कहकर टाल दिया गया, उसके उचादशं सिंहा-सनसे गिराकर पैरों तले रींद दिये गये—देशकी हालत कभी भी इतनी संकटापन्न नहीं हुई थी जितनी कर्जनराजके दूसरे कुग्रहमें । सार्वजनिक विरोधके बावजूद सरकारी गोपनी-यताका कानृत बना । इस कानृनकी सर्वत्र निन्दा हुई, सभी भारतीय और आंग्ल भारतीय समाचारपत्रोंने इसकी निन्दा की, हर ओरसे विरोधपत्र आये, लेकिन लार्ड कर्जन न माने और वह काला कानून वन गया। शिक्षाका अंगभंग हुआ तथा वह लँगड़ी कर दी गयी. वह और भी खर्चीली और सरकारी ढंगकी कर दी गयी; और राष्ट्रीय हितोंकी गुलाम वनानेका सबसे प्रभावकारी हथियार—विश्वविद्यालय कानृन, बना दिया गया। बेटिंक, मैकौले, हैलीफेक्स आदिके महान कामको, जिसका पिछले ५० वर्षोंमें देशके लिए बहुत आनन्ददायक परिणाम निकला था, खत्म करनेको नहीं तो कमसे कम उसे, रोकनेकी नीति तो अवस्य ही काममें लायी जाने लगी।

वातावरणका तनाव अध्यक्षके भाषणसे भी स्पष्ट था। जितनी एक मुधारवादी नरम-दलीय नेतासे आद्या की जा सकती थी, गोखलेने उससे ज्यादा आलोचनात्मक और स्पष्ट भाषण किया। वाइसरायकी हैसियतसे सन् ५७ के ठीक पहले लाई केनिगने जो चेतायनी दी थी, गोखलेके भाषणके पहले वाक्यमें उसीकी गूँज थी। उन्होंने कहा—''जय आजसे चार महीने पहले मुझे यह पद स्वीकार करनेका निमन्त्रण मिला था, हमें क्षितिजपर वादलका एक छोटा सा हाथमरका डुकड़ा ही दिखलाई पड़ता था। तबसे बादल घर चुके हैं और त्पान आ गया है; सामने चटाने हैं और समुद्रकी कोधित गरजती लहरें थेपेड़ मार रही हैं, जब मुझे कांग्रे सकी नावकी पतवार सम्हालनेको कहा गया है।''

कर्जन राजपर टीका करते हुए गोखलेने कहा—ऐसं द्यासनका उदाहरण हूँ इनेके लिए हमें अपने देशके इतिहासमें औरंगजेबके शासनकालतक पीछे लीटना होगा। वहीं हमें इतने तीक्ष्ण रूपसे वैयक्तिक और इतने अधिक केन्द्रीभृत शासनका प्रवास देखनेको मिलेगा; वहीं औरंगजेब जैसी उद्देश्य पूर्तिकी लगन, वहीं कर्त्तः अपरायणताकी सर्वोपरि चेतना, वही

१. वनर्जी वही पुस्तक पृष्ठ २१८

आश्चर्यजनक कार्यशक्ति, वही अकेलेपनका वोध, वही दमन और अविश्वासकी नीतिका पालन जिससे सब ओर खीझ और क्रोध पैदा हो गया।"

वंगभंगके परिणामोंके सम्बन्धमें गोखलेने कहा—''हमारी राष्ट्रीय प्रगतिके इतिहासमें, वंगालके विभाजनके परिणामस्वरूपं पैदा हुआ जनरोष और भावनाका महान् उद्रेक चिर-स्मरणीय रहेगा । अंग्रेजी राज्यकी स्थापनाक वाद पहली वार भारतीय समाजक सभी वर्ग जाति और धर्मके भेद मूलकर, किसी वाहरी दवावके विना, सभीके साथ हुए अन्यायका प्रतिरोध करनेकी एक भावनासे अभिभृत होकर आगे बढ़े। उस प्रान्तपर एक सच्ची राष्ट्रीय चेतनाकी लहर छा गयी है और उसके प्रभावसे पुरानी वाधाएँ - कमसे कम कुछ समयके लिए तो ढह ही गयी हैं; वैयक्तिक ईर्ष्या तिरोहित हो चुकी है, दूसरे विवाद स्थगित हो गये हैं। नृशंस और निर्वन्ध नौकरशाहीके दमनचकका वंगालने जिस साहसके साथ सामना किया है उससे पूरा भारत आनन्दित और कृतार्थ हो उठा है। सहानुभृति और राष्ट्रीय आकांक्षाओं-के कारण देशके विभिन्न भाग एक दूसरेके निकट आ गये हैं और इस प्रकार वंगालकी पीड़ा और कप्ट निष्प्रयोजन और व्यर्थ ही नहीं गये। जिस तरहकी वाद हालमें वंगालमें देखी गयी, उसमें कहीं कहीं किनारों के ऊपरतक पानी भर जाना अनिवार्य-सा है। जब विशाल जनसमुदाय अकस्मात् अन्धकारसे प्रकाश, दासतासे स्वतन्त्रताकी ओर बढ़ता है, कहीं कहीं 'अति' हो जाना स्वाभाविक ही है। इनसे हमें अत्यधिक परेशान होनेकी आवश्यकता नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक वात तो यह है देशके सार्वजनिक जीवनको बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त हुई है-और इसके लिए देश वंगालका ऋणी और आभारी है।"

लेकिन तब भी नरमदलीय नेता कोई वड़ा कदम उठानेको तैयार नहीं थे। वे काँपते थे और उग्र-कांग्रे सी आगे बढ़नेके लिए उतावले हो रहे थे। इन उग्र कांग्रे सियों में महान् नेता भी थे जो भिखारीकी झोली नहीं फैलाना चाहते थे, जिनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएँ निर्वाध थां, कोई सीमा नहीं जानती थीं। उन्होंने एक नयी संस्था-नेशनलिस्ट पार्टी (राष्ट्रीय दल) की स्थापना की और कांग्रे से शिविरमें ही खुलां अधिवेशन कर भविष्यका अपना कार्यक्रम तय करना शुरू किया। इस समामें तिलकने अपना सविनय प्रतिरोधका सिद्धान्त प्रतिपादित किया। समाने स्वयं-सहायताके सिद्धान्तका प्रचार करने और जनताको देशी वस्तुओं प्रयोग और वहिष्कार आंदोलनके लिए प्रेरित करनेका निश्चय किया। प्रतिनिधियोंने ब्रिटिश सरकारसे शासन और सार्वजनिक कार्योंके हर क्षेत्रमें असहयोग करनेके प्रशन्पर भी विचार किया।

इस घटनाने कांग्रेसके शान्त वातावरणमें उद्देखन उत्पन्न कर दिया। विषय समितिकी वैठकमें नरमदलीय व राष्ट्रीय पाटीं नेताओं में मतमेद पैदा हो गया। लगभग कांग्रेस अधिवेशनके समय ही ब्रिटिश युवराज प्रिंस आव वेल्स सपत्नीक भारत आये थे। परम्परानुसार कांग्रेस (नरमदलीय) उनका 'सम्मानपूर्वक, विनयपूर्ण, भिक्त और कर्जव्यमय स्वागत' करना चाहती थी। 'राष्ट्रीय' नेताओं ने इस प्रस्तावका विरोध किया, क्यों कि वे ऐसी हर वातके विरुद्ध थे। संकटापन्न स्थिति पैदा हो गयी। लेकिन कांग्रेसके पुराने नेताओं ने समझौतेका यह रास्ता निकाला कि जब यह प्रस्ताव पेश हो तिलक गुट वैठकसे उठकर चला जाय। तिलक गुट उठ गया और कांग्रेसकी एकता कायम रही। फूटका डर एक और प्रस्तावपर पैदा हुआ। वायकाट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षापर नरमदली उस ढंगका प्रस्ताव पास नहीं करना

चाहते थे, जिस ढंगका 'राष्ट्रीय' नेता । लेकिन यहाँ नरमदलीय नेता झक गये और अधिवेशन शान्तिपूर्वक समाप्त हो गया ।

अधिवेदानका कींसिलींके विस्तारकी माँगवाला मुख्य प्रस्ताव ने. चौधरीने वेदा किया, जिन्होंने वंगमंगके सम्बन्धमें कहा कि यदि केन्द्रीय कौंसिल मात्र वाद-विवादका अखाडा न होती तो यह कानून विलक्क दूसरे ढंगका होता । भारतीयोंका हाकिमोंके लिए उत्तर कुछ इस प्रकारका था- 'हमारा यह सुझाव है; तर्क हमारे पक्षमें है; न्याय हमारे पक्षमें है; वोट तुम्हारे पक्षमें हैं; जो चाही करो।' मुख्य प्रस्तावमें कहा गया था कि "समय आ गया है जब केन्द्रीय और प्रान्तीय विघायिका केंसिलेंकेऔर अधिक विस्तारकी आवश्यकता है।" प्रस्तावमें सिफारिश की गयी थी कि ''निवांचित और गैरसरकारी सदस्य्रोंकी संख्या और बढायी जाय और कोंसिलोंके सामने आनेवाले आर्थिक प्रश्नोंपर उन्हें मतविभाजनका अधि-कार हो: शासनाष्यक्ष उनके निर्णयोंपर निपेवाधिकारका प्रयोग कर सकेंगे।" इसी प्रस्तावमें माँग की गयी थी कि (अ) हर प्रान्तको ब्रिटिश लोकसभामें दो प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार हो, (आ) जानी गानी योग्यता और अनुभवके कमसे कम तीन भारतीयोंकी भारतसचिवकी परिपदका सदस्य बनाया जाय, और (इ) गवर्नर जनरलकी कार्यकारी कींसिलके दो सदस्य भारतीय हों और मद्रास व वम्बईकी कार्यकारी कोंसिलोंमें एक एक भारतीय सदस्य हो । समय समयपर भारतकी हालतकी ब्रिटिश लोकसभा हारा जाँच की जो प्रणाली ईस्ट ह्ण्डिया कम्पनीके समय चल रही थी, एक अन्य प्रस्ताव द्वारा उसे फिरसे चालू करनेकी माँग की गर्या । जैसा कि पहले भी कई बार कहा गया था, समझा यह जाता था कि इससे भारतीय द्यासनतन्त्रकी जाँचका अवसर मिलता रहेगा।

वंगभंगपर बन्देमातरम्की ध्वनिके बीच प्रस्ताव पेश करते हुए सुरेन्द्रनाथ वनजीने कहा कि जवतक विभाजन खत्म न कर दिया जाय, आन्दोलन जारो रहेगा । वह आन्दोलन नहीं रका, तब भी नहीं रका जब बंगमंग समाप्त हो गया और दोनों बंगाल मिलकर फिर एक हो गये ।

कांग्रेसने भारत सरकार और भारत सिचवरे अपील की कि वे प्रवन्ध वदलें या उसमें सुधार करें। एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं के विहम्कारको न्यायसंगत बताते हुए वंगाल सरकारकी दमननीतिकी निन्दा की गयी। कांग्रेसने यह भी तय किया कि गोखले इंगलिंग्ड जाकर वहाँकी सरकारका ध्यान कांग्रेसके प्रस्तावींकी ओर आइए करें।

वादिववादमें जिन्होंने सिक्षय भाग लिया, उनमें मदनमोहन मालवीय और लाजपतराय भी थे। कर्जनके अत्याचारी शासनसे उत्पन्न विरोधभावनाको कुचलनेके लिए काममें लाये गये दमनचककी निन्दा करते हुए उन्होंने वंगालका अनुकरण करनेकी अपील की। एक मुस्लिम प्रतिनिधि ए० एच० गजनवीने पूर्वी वंगालके गवर्नर सर वेम्पपील्ड फुलरके 'उत्तेजक और सिन्नपाती व्यवहार' का पर्दाफाश करते हुए उनकी धमकी, उनके सल्जनोंके प्रति असम्य व्यवहार और निर्दयतापूर्वक अपमान करकेकी घटनाओंका वर्णन किया। बनारस अधिवेहानमें ७५६ प्रतिनिधियोंने भाग लिया था। इनमें केवल १७ मुसलमान थे।

मिण्टो कांग्रेसको सन्देहको दृष्टिसे-देखने लगे थे और उसकी जगह किसी अन्य संखाके समर्थनकी सोच रहे थे—सम्भवतः कांग्रेस वेसी ही किसी संस्थाकी विसवा जन्म सन् १८८५ में संविटत हिंसा (जिसके काफी सवृत ह्यूमको मिल गये थे) का खतरा दूर करनेके लिए हुआ था। २८ मई सन् १९०६ के अपने पत्रमें मिण्टोने भारत सिववको लिखा था— "जहाँतक कांग्रेसका सम्बन्ध है…… हमें उसके वेहतर नेताओं को मान्यता देनी चाहिये और उनसे मित्रता करनी चाहिये; लेकिन तो भी मुझे भय है कि उसके आन्दोलनमें वहुतसे ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकारके प्रति कोई निष्टा नहीं रखते, विलक्कल वफादार नहीं हैं; भविष्यके लिए उनसे खतरा है.....कांग्रेसके उद्देशों के जवायके तौरपर कोई संस्था खड़ी करने के प्रभपर में इधर काफी दिनों से सोच रहा हूँ। देशी महाराजाओं की समिति या उसी किस्मकी किसी और संस्थासे हमारा काम चल सकता है। एक प्रिवी कौंसिल हो जिसमें राजाओं के अलावा कुछ और वड़े लोग भी हों, जो सालमें एक वार एक हफ्ते या पखवारे के लिए दिखी या कहीं और मिला करें। वाद-विवादके विपयों और कार्यसंचालनपर काफी गौर करना पड़ेगा; हमें कांग्र ससे भिन्न विचार वहाँ लाने होंगे।"

मीलेंको यह मुझाव पसन्द आया और उन्होंने अपने जवावमें लिखा कि मेरा निजी तार किसी भी दिन तुम्हारे पास पहुँच सकता है कि तुम एक भारतीय ह्यूमा (रूसी पार्लमेण्ट) स्थापित करनेका प्रवन्ध करो । मौलेंने अपने पत्रमें यह भी लिखा था कि "मैं विना सोचे समझे, आँखपर पट्टी वाँधकर निरंकुश शासनके रास्ते भी नहीं चलना चाहता।"

लेकिन मौलेंके इसी पत्रमें एक और महत्वपूर्ण अंश है जिसे कांग्रे सकी जगह लेनेवाली संस्था, या कम-से-कम एक अन्य वड़ो समस्याको ओर इंगित माना जा सकता है। उन्होंने लिखा था—भारतमें जो नयी चेतना पैदा हो रही है और फैलती जा रही है उससे हमें सभी सावधान कर रहे हैं। लारंस, शिरौल, सिडनी लो सभी वही राग अलापते हैं। तुम भी पुराने ढंगसे शासन नहीं चला सकते; कांग्रेस संस्था और कांग्रेस सिद्धान्तोंके वारेमें दुम्हारे कुछ भी विचार क्यों न हों, तुम्हें उनसे निवटना है। तुम विश्वास रखों कि शीन ही सुसलमान भी तुम्हारे खिलाफ कांग्रेससे अपना भाग्य जोड़ देंगे, वगैरह वगैरह। '' इसका इलाज साफ था। मुसलमानोंको कांग्रेसमें शामिल होनेसे रोकना जरूरी था। इसके कुछ ही महीनों वाद अखिल भारतीय मुस्लिम लीगका जन्म हो गया।

१ मेरी मिण्टो, वही पुस्तक पृष्ट २८-२९

२ वही पुस्तक पृष्ट ३०

३, सर वाल्टर लारेंस (कर्जनके प्राइवेट सेकेटरी)

४. सर वेलेण्टाइन शिरौल (टाइम्सके संवाददाता)

५, सर सिंडनी हो (शाही यात्राके समय आये विशेष संवाददाता)

अध्याय १०

मुस्लिम लीग

यंगभंगके वाद भारतीय राजनीतिमें इतनी तेजी आयी और वह इतने क्रान्तिकारी ढंगसे आगे वही कि अँग्रेंज शासकोंको सब प्रकारकी आशंकाएँ घेरने लगी । उनको इस वातकी फीरन आवश्यकता प्रतीत होने लगी कि सरकार-भक्त मुसलमानोंको एक राजनीतिक संघटनमें संघटित कर कांग्रेसके मुकाबलेमें खड़ा किया जाय। अंग्रेजोंके मित्र अलीगढ़के जागीरदार हाजी मुहम्मद इस्माइल खाँने ३० जुलाई १९०६ को नैनीतालसे एक खत नवाय मोहिसिनुल-मुल्कको लिखा कि विधान-परिपदोंको बढ़ानेकी बात सोची जा रही है और मुसलमानोंको भी अपनी माँगें सरकारके सामने पेश कर देनी चाहिये। उस समय श्री थियोडर माँगीसनके उत्तराधिकारी आचींबाल्ड शिमलामें थे। उन्होंने वाइसरायके निजी सेकेटरीसे बात करके नवाय मोहिसिनुल-मुल्कको इस तरहका खत लिखा— "वाइसरायने मुसलमानोंके एक शिष्टमण्डलसे मिलना स्वीकार कर लिया है। वाइसरायको पेश किये जानेवाले मान-पत्रपर सब स्वोंके प्रभावशाली व महत्वपूर्ण, मुस्लिम नेताओंके हस्ताक्षर होने चाहिये। इसमं चुनावकी नहीं बिल्क नामजदगीको प्रणालीकी व्यवस्था करनेकी प्रार्थना करनी चाहिये क्योंकि मुसलमानोंको लाभ कैवल नामजदगीको प्रणालीकी व्यवस्था करनेकी प्रार्थना करनी चाहिये क्योंकि मुसलमानोंको लाभ कैवल नामजदगीको ही होगा। जमींदारोंकी रायको उचित महत्व देना आवश्यक है। समय कम है और यदि हम एक आन्दोलन खड़ा करना चाहते हैं तो हमें जल्दी करना चाहिये।"

खतमें उन्होंने मुसलमानोंके हितको प्रत्येक महायताका आश्वासन दिया परन्तु कहा कि वे स्वयं परदेकी आड़में रहेंगे। इस सिलिसिलेमें आगे वात करनेके लिए नवाय मोहिसतुल-मुल्कको तार द्वारा शिमला बुलाया गया। मौलाना अबुल कलाम आजादने अपने एक भाषण में शिमलाके पैतरोंकी चर्चा करते हुए कहा "में इस वातका जिन्दा सुवृत हूँ कि जब जनताके उद्देलनके फलस्वरूप, १९०६ में कुछ सुधार किये जानेवाले थे, स्वर्गाय नवाय मोहिसिनुल-मुल्कको वम्बईसे, जहाँ वे अपने एक मित्रके यहाँ टहरे हुए थे, तार द्वारा शिमले खलाया गया। शिमलेमें उनकी मुलाकातका नतीजा यह हुआ कि आगा खाँको अपनी यूरोक यात्रा स्थिति कर अदनसे वापस लीटना पड़ा। मुसलमानोंकी तरफते हैदराबाद (दक्षन) के सैयद विलगरामीने पृथक निर्वाचन पद्धतिकी माँग करते हुए एक स्मृतिपत्र तैयार किया। ये सब दाँवपेच शिमलासे ही खेले गये थे।" (शिमला भारतकी ग्रीप्मकालीन राजधानी था)। १९२३ की कांग्रेसमें मौलाना मोहम्मद अलीने राष्ट्रपतिके पदसे भाषण करते हुए शिमला-तमाशेको 'हुक्मी-तमाशा' बताया। आश्रय यह कि, जैसा डा. अम्बेडकरने कहा है, स्मृति-पत्रकी तैयारी अँग्रेजी सरकारने करवायी थी।"

यही नवात्र मोहिसिनुल-मुल्क, जिनको यू. पी. के लेपिटनेंट गतर्नरने 'राजनीतिक

अन्दुल मजीद खाँ, कम्यूनलिज्म इन इण्डिया-इट्स ब्रोय एण्ड ओरिजिन—पृष्ट २३

२. अम्बेडकर, वही युस्तक पृष्ठ, ४२८

कायों के लिए सन् १९०० में डाँटा था, अब भारत सरकारके इशारेपर हाथ वाँधे खढ़े रहते थे। वाइसरायकी सेवामें पेश करनेके लिए आवेदनपत्रपर उन्होंने थोड़ेसे वक्तमें लगभग ४००० मुसलमानोंके हस्ताक्षर इकट्ठे कर लिये। तब मुस्लिम सामन्तोंके ३५ सदस्योंके एक शिष्टमण्डलने वाइसरायकी सेवामें एक लम्बा स्मृतिपत्र पेश किया। जो संक्षेपमें यह था:—

"श्रीमान्की कृपासे,—प्राप्त हुई आजाके सुअवसरसे लाभ उठाकर इम (जिनके हस्ताक्षर नीचे हैं) अमीर जागीरदार, ताल्छकेदार, वकील, जमींदार, न्यापारी व अन्य लोग सम्राटकी भारतके विभिन्न भागोंकी मुहम्मडन प्रजाका प्रतिनिधित्व करते हुए, अत्यधिक नम्रता और विनयपूर्वक निम्नलिखित स्मृतिपत्र कृपापूर्ण विचारार्थं श्रीमान्की सेवामें प्रस्तुत करते हैं।

"१९०१ की जनसंख्या गणनाके अनुसार मारतके मुहम्डन ६ करोड़ २० लाख या सम्राटके भारतीय उपनिवेशकी कुल जन संख्याका है और दें के वीचका भाग हैं। और यदि हिन्दू समाजमेंसे नगण्य धर्मावलम्बी, व असभ्य ब्रह्मवादी लोगोंके भागको और ऐसे तत्वके लोगोंको भी जो आम तौरपर हिन्दू शुमार किये जाते हैं पर वास्तवमें हिन्दू नहीं हैं, घटा दिया जाय तो मुहम्डनोंका बहुसंख्यक हिन्दु ओंसे अनुपात बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं कि किसी भी प्रतिनिधित्व प्रणालोंमें चाहे उसका क्षेत्र सीमित हो या चहुद, ऐसे समाजको जिसकी जनसंख्या रूसको छोड़कर किसी भी प्रथम श्रेणीकी यूरोपियन सत्तासे अधिक है और जो राज्यके महत्वपूर्ण अंग हैं, उचित प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिये।

"श्रीमान्की आज्ञासे हम कुछ और भी कहना चाहते हैं। हम अनुरोध करते हैं कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व पद्धित या ऐसी किसी भी व्यवस्था, जिससे उनके प्रभाव या हैसियतपर असर पड़े, को लागू करते समय मुहम्डन समाजकी स्थितिको आँक सिर्फ उनकी जनसंख्याको नहीं, विहक उनके राजनीतिक महत्व और साम्राज्यकी सुरक्षाके लिए की गयी सेवाओंको ध्यानमें रखते हुए, करनी चाहिये। हम आज्ञा करते हैं कि श्रीमान् विचार करते समय भारतमें मुसलमानोंकी सौ वर्ष पूर्वकी प्रतिष्ठित स्थितिको, जिसकी परम्पराएँ अभी उनके दिलों में टूटी नहीं हैं, अवस्य ध्यानमें रखेंगे।...

"हमें आशा है कि श्रीमान हमको प्रारम्भमें ही यह कहनेमें क्षमा करेंगे कि प्रतिनिधि संस्थाएँ जिस प्रकारकी यूरोपीय देशोंमें प्रचलित हैं, भारतीय जनताक लिए नयी हैं। हमारे समाजके कई विचारशील सदस्योंकी सम्मितमें यदि भारतकी सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक परिस्थितियोंको ध्यानमें रखते हुए प्रतिनिधि सस्या-प्रणालीको उनके अनुकूल सफलतासे लागू करना है तो अत्यधिक यत्न, सावधानी और दूरदर्शितासे कार्य करना पड़ेगा। और यदि अत्यधिक सावधानी और यत्नसे काम न लिया गया तो इसके अर्थ और विपत्तियोंके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय हितोंको, वैमनस्यपूर्ण वहुसंख्याकी मरजीपर छोड़ देना होगा। …

" इस वातको कोई सम्भावना नहीं है कि निर्वाचक मण्डल (जैसे कि वे इस समय विद्यमान हैं) द्वारा किसी भी सुसलमान उम्मीदवारका नाम सरकारकी स्वीकृतिके लिए पेश किया जायगा। ऐसा तभी सम्भव है जब कि वह उम्मीदवार सभी महत्वपूर्ण मसलें पर बहुसंख्यकोंका समर्थन करे। न हमें अपने गैर-मुस्लिम भाइयोंकी इस इच्छामें कोई बुराई नजर आती है कि वे अपनी बहुसंख्याकी शक्तिका पूरा फायदा उठाकर केवल अपनी

जातिके सदस्योंके लिए मतदान करें, या उन लोगोंके लिए मतदान करें जो हिन्दू न होते हुए भी वहुसंख्यक हिन्दुओंके पश्चमें वोट देंगे क्योंकि उनको भविष्यके चुनावोंके लिए उन्हींकी ग्रुमेच्छाओंपर अवलिम्बत रहना पड़ेगा।"

स्मृतिपत्रमं ये माँगं गिनायी गयी थां (१) मुसिलमोंको उनकी संख्याके उचित अनु-पातसे सरकारी नौकरियाँ मिलं; (२) नौकरियोंमें भर्तीके लिए प्रतियोगिता समाप्त कर दी जाय; (३) प्रत्येक हाईकोर्ट व चीफ कोर्टमें मुसलमान जजोंकी नियुक्ति हो; (४) जैसा कि पंजाबके कई शहरोंमें होता है, म्युनिसिपिल्टियोंके चुनावके लिए यह अधिकार दिया जाय कि हिन्दू मुसलमान अलग-अलग अपने-अपने प्रतिनिधि चुनकर मेजें; (५) विधान-परिपदके लिए चुनाव करनेवाले निर्वाचनमण्डलोंमें, महत्वपूर्ण मुसलमान जमींदार, वकील, स्यापारी व दूसरे हितोंके प्रतिनिधि, जिलाबोडोंके मुसलिम सदस्य और विस्वविद्यालयोंके मुसलिम स्नातक (ग्रेजुएट) (जिनकी स्थित कमसे कम पाँच सालकी हो) हों।

वाइसरायका जवाब भी स्मृतिपत्रकी भाँति लम्या था। इसके ज्यादातर हिस्सेमें मुसलमानोंके अतीतके इतिहासका, सर सैंयदकी सेवाओं और अलीगढ़-आन्दोलनका वर्णन था। उत्तरके प्रासंगिक वाक्य ये थे—

"में यह बतलानेकी कोशिश तो नहीं कलँगा कि विभिन्न धर्मावलिम्बयोंका प्रतिनिधित्व किस प्रकार हो ? लेकिन मुझे इसका पूरा विश्वास है, जैसा कि में समझता हूँ कि आपको भी है, कि इस द्वीपकी जनसंख्याके बगोंकी परम्पराओं और विश्वासोंको विना ध्वानमें रखे हुए कोई भी प्रतिनिधि-निर्वाचक-प्रणाली जिसका उद्देश व्यक्तिगत मताधिकार देना हो, पूर्ण रूपसे असफल सिद्ध होगी......में मुसलिम समाजको पूरे तौरपर आश्वासन देता हूँ कि मुझसे सम्बन्धित किसी भी प्रशासन-पुनर्निमाणमें उनके हितों और अधिकारोंकी रक्षा की जायगी।"

शामको वाइसरायकी स्त्री मेरी मिटोको एक सरकारी अफसरका निम्नलिखित पत्र मिला जिसका अर्थ साफ है और काफी महत्त्व रखता है। "श्रीमान्की तेवामें एक पंक्ति मेजकर में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज बहुत बड़ी घटना हुई है। कुशल नीतिज्ञताका एक कार्य आज हुआ है जिसका प्रभाव भारत और भारतीय इतिहासपर वपोंतक रहेगा। छः करोड़ बीस लाख आदिमयोंको राजद्रोहियोंकी पंक्तिमें शामिल होनेसे रोक देनेका यह कार्य कम महत्वपूर्ण नहीं हैं।" वे अपने १ अक्टूबर १९०६ के जर्नलमें लिखती हैं कि "आजका दिन बहुत घटनापूर्ण रहा। जैसा कि मुझसे किसीने कहा—भारतीय इतिहासमें यह युगप्रवर्त्तक माना जायगा।" भारतभरमें फैली हुई असन्तोपकी भावनासे हम परिचित्त हैं, सब बगों और विचारोंके लोगोंमें फैली हुई अशान्तिको हम जानते हैं " आन्दोलनकर्ता इस भावनाको फैलाने और पोपण करनेमें पूरी तरह तत्पर हैं। स्वाभाविक है कि इस वृहद् समाज (मुसलमानों) का सहयोग प्राप्त करनेका उन्होंने भरसक प्रयास किया है। नौजवान पीड़ी अनिहिचत सी थी, कांग्रेसके अप्रणी-आन्दोलनकारियोंका साथ देनेकी तरफ उसकी अधिक

स्मृतिपत्र भीर वाइसरायके उत्तरका पूरा विवरण अम्बेडकरकी उसी पुस्तकमें मिलेगा, पृष्ठ ४२८-४२९

२. मुसलमानीकी

३. मेरी मिटो, वही पुस्तक-पृष्ट ४७-४८

प्रवृत्ति थी। एक पुकार उठी कि राजमक्त मुसलमानोंका समर्थन नहीं करना चाहिये और आन्दोलनकारी उद्देलनके जरिए अपनी माँगें हासिल कर लेंगे।" अव इसमें जरा भी संशय नहीं रह जाता कि राजमवन शिमलामें शिष्टमण्डलकी पूरी योजना वनी थी और विजलीकी तेजीसे यह कार्यान्वित की गयी।

अव इम इस स्थितिमें हैं कि १८८५ में कांग्रेसके जन्मके वादसे मुस्लिम राजनीति और उसकी धाराओंका विश्लेषण कर सकें। कुछ खिताव प्राप्त और कुलीन सामन्तीवर्गके लोग जिन्होंने निजी तौरपर या राजनीतिक सभाओंमे कभी भी मुस्लिम समाजके लिए चिन्ता प्रगट नहीं की थी, मुसलमानोंके स्वयं-नियुक्त नेता वन गये।

उनका एकमात्र उद्देश्य अंपनी ऊँची स्थितिको वरकरार रखना और मुसलिम समाजके एक वहुत ही सूक्ष्म भागके लिए सरकारी ओहदे प्राप्त करना था। अपने हितोंकी रक्षाके लिए सरकार-भक्तिका राग अलापना उनका उद्देश्य था। काँग्रेसकी तरफके लोग भी अपने वर्गीय हितोंके लिए समान रूपसे सतर्क थे परन्तु वे इस स्तरसे ऊँचे उठे और उन्होंने ब्रिटिश सरकारपर भारतमें आर्थिक वर्वादी लानेका आरोप लगाया । लगातार वर्षोतक काँग्रेसने अंग्रेजों द्वारा भारतके आर्थिक शोषणकी तरफ सरकारका ध्यान खीचा और सुधारोंकी माँग की । आमतौरसे मुसलमान हिन्दुओंसे ज्यादा गरीव थे; वंगालमें किसानोंकी दशा वहुत बुरी थी। करघोंके सहारे जीवन-वृत्ति यापन करनेवाली मुसलमान जनता भूखों मर रही थी। लेकिन तथाकथित मुस्लिम नेताओंने इनके वारेमें कभी एक शब्द भी नहीं कहा । यदि वे एक शब्द भी कहते तो वह राजनीति समझी जाती, जिसे वे एक तरहका 'हौआ' समझते थे। वे सरकारको रुष्ट करनेका साहस नहीं कर सकते थे। "मुगल शासन-कालमें प्राप्त अपनी पूर्वजोंकी खानदानी प्रतिष्ठाके बलपर वे सरकारी पदोंपर अपना स्वत्व चाहते थे । उस समय लोगोंकी खानदानी स्थितिके ऊपर ऊँची पदवियाँ और उपाधियाँ बहुत आसानीसे प्राप्त हो जातीं थी। अंग्रेजी शासनकालकी भाँति ऊँची पदवियाँ और उपाधियाँ प्राप्त करनेके रास्तेमें प्रतियोगिता-परीक्षाका रोड़ा न था। यदि हिन्दू और विशेषतया नीची श्रेणीके हिन्दू, परीक्षामें उनको नीचा दिखा देते तो वे इतने नाराज हो जाते कि वे नयी पद्धति और प्रजातन्त्रकी घोर निन्दा करने लगते क्योंकि इन्होंके अन्तर्गत प्रति-योगिता-परीक्षाएँ आरम्म हुई थीं। वेक और उनके उत्तराधिकारियों, जैसे उनके अलीगढ़ कॉलेजके शिक्षकोंने, उनकी मनःस्थितिका अध्ययन किया और उन्हें अपने लिए (मुसलमानोंके लिए) सीधी नियुक्तियोंकी माँग करनेकी सलाह दी । कालान्तरमें मुसलमानोंकी यही राजनीति वन गयी-प्रजातन्त्र और प्रतियोगिता-परीक्षाएँ मुस्लिम-हितोंके विरुद्ध थीं।

जीवन-वृत्तिके साधनके वाद मुसलमानोंके इस वर्गको सबसे प्रिय-इस्लाम था। कुछ मुस्लिमोंने इसका फिरसे अध्ययन किया और कुरान व अरवके पैगम्बरकी स्तुतिमें प्रशंसनीय साहित्य लिखा।

राजनीतिमें स्वतन्त्रता और समानताकी भावनाकी नयी विचारधारासे उनका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं था। अधिक से अधिक वे इन वातोंकी कुरानमें उत्पत्ति हूँ इनेका प्रयास करते। उनमेंसे कुछ धार्मिक निरपेक्षताको जीवनका एक स्वतन्त्र पहल मानते थे, कई विषमताओंके सामने वे असहाय थे और यह अधिकारपूर्वक कहा जा सकता है कि मुस्लिम

१. मेरी मिंटो, वही पुस्तक, पृष्ट-४५

नेता राजनीतिसे धर्मको कभी अलग नहीं कर सकते थे। इन्होंमेंसे एक नवाय मोहिसिनुल मुक्क थे। 'मुस्लिम राष्ट्रकी अवनित के कारणों' पर भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि उनका (मुस्लिम) समाज तवतक उन्नितिको आधा नहीं कर सकता जवतक वे सिर्फ अपने पूर्वजोंकी प्रतिष्टामें ही गौरवान्वित महसूस करेंगे और जवतक वे हिन्दुओंकी नये ज्ञानप्राप्तिकी तत्परताकी स्पर्धा नहीं करेंगे।" परन्तु उनके दूसरे भाषणसे माल्स पड़ता है कि वे निराद्या और असहायत्व महसूस कर रहे थे। "सजनों" उन्होंने कहा, "इस वातको वार-वार याद रित्ये कि हमको अपने प्रयासोंमें कोई विद्योप सफलता नहीं मिलेगी जवतक आदरणीय व माननीय उल्लेमाओंकी संस्था (पुराने हंगके विद्वान-मुसल्यान) हमारी सहायता नहीं करती। हमारे समाजका बहुत बड़ा तवका हमारी बात नहीं सुनता। जनतातक विकसित विचार पहुँचानेके लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। लेकिन पूरे समाजके हदयोंपर आधिपत्य रखनेवाली संस्थाकी आवाजको पैद्यावरसे वरमातक, कदमीरसे मद्रासतक प्रत्येक मुसल्यान ध्यानसे सुनेगा। सजनो! इसमें जरा भी संद्या नहीं है कि मुसल्यान चाहे कितने ही अज्ञानी और अविवेकी क्यों न हों उनके हृदय इस्लामकी मुह्व्यतसे ओत प्रोत हैं, उनके विचारोंपर धार्मिक-उत्साहका बहुत प्रभाव है.......उलेमाओंकी व्याख्याके अलावा उनके लिए इस्लाम और कुछ नहीं है।"

मोहिसिनुल-मुल्कके विचारोंके लोग बहुत थोड़े थे। वे राजनीतिमें क्दनेका साहस न कर सके। न सिर्फ यह, उनका अंग्रेजोंसे इतना गहरा नाता था कि अंग्रेजोंके हुक्मपर वे मुसलमान जनताके एकमात्र नेता होनेका दावा कर सकते थे। भारतीय जनताकी आर्थिक दुर्दशाकी तरफ ध्यान खींचनेवाले संघटनको वे मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था माननेको तैयार नहीं थे।

मुसलमानों के इस तबकेका अपने प्रतिरूप हिन्दू तबकेसे सरकारी नौकरियाँ पाने के लिए संवर्ष चलता था। मुगल शासनकालमें प्राप्त एकाधिकारसे आज हिन्दू इनको वंचित कर रहे हैं, इस भावनाने पुनस्त्थानवादकी प्रवृत्तियों को जागरित किया। अपनी उन्नित और इस्लाम उनके जीवनका मुख्य ध्येय वन गया था। ऐसे मुसलमान, जैसा नैहरूजी कहते हैं "अपनी राष्ट्र-भृमिको अन्यत्र हूँ इनेकी कोशिश करते थे। कुछ इदतक वे अपनान और सुगलकालमें अपनी राष्ट्रीय जड़े देखते थे। सांस्कृतिक जन्म-भृमिकी यह खोज कुछ मुसलभानोंको (उनमेंसे कितने ही मध्यम वर्गके थे) इस्लामके इतिहास और उस कालकी ओर छे गयी जब इस्लाम वगदाद, रपेन, कानस्टेंटिनोपल, सेन्ट्रल एशिया व अन्य जगहोंपर विजियानी और रचनारमक शक्ति था। मक्काकी इज-यात्रा भी इसी प्रकारकी चीज थी जिसकी यादसे मुसलमान अपनेको गौरवान्वित महसूस करते थे। भारतके मुगल-सम्राट भारतके वाहरकी किसी भी आध्यात्मिक शक्ति या खलीपाको मान्यता नहीं देते थे। १९ वीं शतान्दिक पूर्वार्थमें जब मुगल सत्ताका पूर्ण पतन हो गया तब भारतीय मस्जिदों नुक्षके स्वतानोंका नाम लिया जा सका। गदरके बाद यह पूरे तौरपर प्रचलित हो गया। "रें

उन्हें हिलाल्से मुहत्वत थी क्योंकि वर्षोतक वह उनके मुख और समृद्धिका प्रतीक

१. जी० एन० नरेसन एण्ड कं० की 'एमिनेण्ट मुसलमान' पृष्ट ८५

२. वही पुस्तक, पृष्ट ८३-८४

३. नेहरू-डिस्कवरी आफ इण्डिया-पृष्ट २९७

रहा । अपनी जन्म-भूमिसे ज्यादा उन्हें तुर्कीसे प्रेम था जहाँ खळीफा रहता था। १९ वीं शताब्दीके उत्तरार्धमें तुर्कीके सुल्तान हमीदने सर्व-इस्लामवादके आन्दोलन (पान-इस्लामिक मूचमेंट) को प्रोत्साहन दिया। भारतीय मुसलमानोंके ऊँची स्थितिके लोगोंने इसका साथ दिया। लेकिन सर सैयदने, जिनको कोई भी चीज उनके दृढ़ निक्चयसे डिगा नहीं सकती थी, इस योजनाका विरोध किया और कहा कि यह ब्रिटिश हितोंको हानि पहुँचा- येगी। उन्होंने अपने सहधर्मियोंको सलाह दी कि उनके धर्ममें राजमक्त रहनेका उपदेश दिया गया है। लेकिन फिर भी ऊँची श्रेणीके मुसलमान सर्व-इस्लामवादके आन्दोलनसे आंकपित होते रहे।

अंग्रेजी अखवारोंने शिमला-योजनाकी सफलताको वहुत वड़ी सफलता मानकर हर्प प्रकट किया। उन्होंने मुसलमानोंकी वृद्धिमत्ताकी तारीफ की और कांग्रेस व वंगालके आन्दोलनोंकी हँसी उड़ायी। जिस दिन शिमला नाटक खेला गया उसी दिन लन्दन-टाइम्सने अपने कुछ कालमोंमें भारतीय समस्या और मुसलमानके वारेमें काफी लिखा और वेकके इस सिद्धान्तका जोरदार समर्थन किया कि भारत प्रजातान्त्रिक संस्थाओंके अयोग्य है। दूसरे दिन, र अक्तूबरको, टाइम्सने वंगाल उद्देलनकारियों और मुसलमान राजनीतिज्ञता-की उलना की। एक दूसरे अखवारने हिन्दुओं और कांग्रेसकी निन्दा की और मुसलमानोंको शूरवीर कौम कहकर प्रशंसा की।

वाइसरायके निमंत्रणपर प्रथम बार देशके विभिन्न भागों के कुळीन सामन्तीवर्गके लोग शिमलामें इकट्ठे हुए । स्पष्टतः यह मीटिंग अखिल भारतीय मुसलमान संघटन वनानेकी भूमिका थी। अलोगढ़की राजनीति अव देशव्यापी होनेवाली थी। ढाकाके नवाव सलीमुला खाँने 'ऑल इण्डिया मुस्लिम संघ' (Muslim All India Confederacy) के नामसे एक राजनीतिक संघटन बनानेका प्रस्ताव रखा । इसके लिए उन्होंने मुस्लिस नेताओंकी एक मीटिंग ढाकामें २० दिसम्बर १९०६ को बुलायी। ढाका वंग-मंगके खिलाफ आंदोलनका मुख्य केन्द्र हो रहा था। वहाँपर कर्जन द्वारा पैदा किये गये तीव हिन्दू-मुसल्मानों के मतभेदों-को, जिनको लेपिटनेंट गवर्गर फुलरने और उमारा था, देखते हुए ढाका प्रथम अखिल-भारतीय मुसलमानोंके सम्मेलनके लिए आदर्श स्थान था। नवाव वकारल मुस्क इसके अध्यक्ष थे। सम्मेलनमें स्वीकृत प्रथम प्रस्ताव द्वारा ऑल इण्डिया मुस्लिम लीगके नामसे मुसलमानोंका एक राजनीतिक संघटन वनानेका निक्चय किया गया। एक दूसरे प्रस्तावमें कहा गया कि वंग-भंग मुसलमानोंके हितमें है। इस प्रस्तावकी एक प्रति सरकारके पास भेज दी गयी। दी टाइम्सने भारतीय राजनीतिके इस नये मोड़पर फिर संतोष प्रकट किया । टाका सम्मेलनके करीव तीन मास वाद अलीगढ़में हुई विद्यार्थियोंकी एक समामें नवाव वकारल मुल्कके भाषणसे लीगकी राजनीतिक आकांक्षाओं और अँग्रेजी शासनके प्रति दृष्टिकोणकी एक झांकी मिलती है। उन्होंने कहा "ईस्वर न करे यदि भारतसे अंग्रेजी द्यासन गायव हो जाय तो हिन्दू ऐश करेंगे और हम लोगोंको वरावर हर समय अपने जान, माल, और इज्जतका खतरा वना रहेगा। मुसलमानोंको इस खतरेसे वचनेका सिर्फ एक रास्ता है—अँग्रेजो शासनके कायम रखनेमें मदद करना । मुसलमान अगर दिल्से अंग्रे जोंके साथ हैं तो यह शासन जरूर वरकरार रहेगा । मुसलमानोंको अपनेको अँग्रेजी सेना समझना चाहिये, वरावर सम्राटकी सेवामें अपना खून वहाना चाहिये और जिंदगी कुर्वान करनेके लिए हमेशा तयार रहना

चाहिये।" फिर कांग्रेसका जिक करते हुए उन्होंने कहा कि "हमें कांग्रेसियों को आंदोलनकारी राजनीतिको नहीं अपनाना चाहिये। अगर हमारी कोई माँगें हैं तो हमें नम्रतासे सरकारकी सेवामें पेश करना चाहिये। लेकिन याद रखो कि अंग्रेजी शासनके प्रति राजभक्त रहना तुम्हारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। तुम जहाँ कहीं भी हो, चाहे फुटवालके मैदानमें या टेनिसके खेलमें, अपने आपको अँग्रेजी फीजका सिपाही समझो। तुमको ब्रिटिश साम्राज्यको रक्षा करनी है और इसके लिए शत्रुसे लोहा लेना पड़ेगा। अगर तुम यह समझ लो और इसको पूरा करो तो तुम्हारा नाम भारतीय ब्रिटिश इतिहासमें सुनहले अक्षरोंमें लिखा जायगा। आनेवाली पीढ़ियाँ तुम्हारा नाम आदरके साथ समरण करेंगी और तुम्हारी कृतज्ञ रहेंगी।"

सन् १९०७ में कराचीमें लीगका वार्षिक अधिवेशन हुआ—यह इसका प्रथम अधिवेशन था। एक विधान तैयार किया गया, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य थे—(१) भारतीय मुसलमानोंमें अंग्रेजी सरकारके प्रति निष्ठाकी भावना पैदा करना और सरकार द्वारा उठाये गये कदमोंसे अभिप्रायके वारेमें पैदा हुई गलतफहिमयोंको दूर करना; (२) भारतीय मुसलमानोंके राजनीतिक और दूसरे अधिकारोंकी रक्षा करना; उनकी आकांधाओं और आवश्यकताओंको नम्र भाषामें सरकारके सामने पेश करना; (३) जहाँतक सम्भव हो, विना ऊपर वताये गये उद्देश्योंको हानि पहुँचाये हुए मुसलमानों और दूसरी जातियोंके बीच मित्रताके भाव पैदा करना।

विधानमें एक स्थायी अध्यक्षका स्थान स्वीकृत हुआ था। इस स्थानपृतिके लिए आगा खाँ ही उपयुक्त समझे गये और वे इस पदपर १९१३ तक रहे जब कि लीग उनके नियन्त्रणसे बाहर चली गयी और कांग्रेसकी नीतिपर चलने लगी। अध्यक्षकी अनुपिखितिमें एक अस्थाई सभापित लीगकी बैठकोंका सभापितत्व करता था। १९०६ और १९०७ के बीच कैन्द्रीय लीग व शाखाओं में पास हुए प्रस्तावों में कैवल एक बातपर जोर दिया जाता रहा—सरकारी 'हलवे और माँड़' में ज्यादा हिस्सा मिलनेकी माँग करना। 1"

सर सैय्यद अली इमामकी अध्यक्षतामें अमृतसरमें दिसम्बर १९०८ में लीगका दूसरा अधिवेशन हुआ । उन्होंने अपने भाषणमें लीग और कांग्रे सक विरोधी अन्तरको स्पष्ट किया । उन्होंने इस वातका दावा किया कि मातृभूमिक लिए अद्धा और भक्तिमें मुसलमान किसीसे पीछे नहीं हैं । लेकिन जहाँ कांग्रेस औपनिवेशिक स्वशासनकी माँग करती है, वहाँ लीग कैवल शासनमें लगातार मुधारोंकी माँग और उदार-प्रणालीके अन्तर्गत शिक्षत भारतीयोंकी स्वाभाविक आकांक्षाओंकी पूर्तिसे सन्तुष्ट हो जायगी। "क्या इस आदर्श स्वशासनकी माँगने, चाहे वह जितने मुन्दर आवरणमें रखी जाय, वेचैनी नहीं पैदा की है ? और क्या इस वेचैनीने आदर्शवादियोंको किकर्तव्य-विमृद्ध नहीं कर दिया है ? और क्या संतुलनके नष्ट हो जानेसे उप्रवादिताका जन्म नहीं हुआ है और क्या इस अपाक्तता, वम, गुप्त संगठनों और हत्यायोंको जन्म नहीं हुआ है ?" इसके बाद उन्होंने कहा "कांग्रेस घोषणा करे कि उसकी राजनीतिमें अमलो तीरपर अँग्रेजी शासनके प्रति भक्ति ही भारतके प्रति भक्ति है, और वर्तमान प्रशासनमें सुधार तभी सम्भव हैं जब कि अंग्रेजी नियन्त्रण स्थापित रहे…जब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इंडियन

१. तुफेल अहमद, वही पुस्तक पृष्ट ३६३, ६४

२. एक भारतीय मुसलमान, मुसलमान्स एण्ड इण्डियन पौलिटिक्स पृष्ट iii १२-क

नेशनल कांग्रेस) हमारे सामने एक ऐसी नीति पेश नहीं करती जिसपर अमल किया जा सके, ऐसी नीति जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं, तवतक मुस्लिम लीगको एक पवित्र कर्तन्य पूरा करना है। वह कर्तन्य अपने समाजको, जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ऐसे संघटनमें शामिल होनेकी राजनीतिक गलतीसे बचाना है, जो लॉर्ड मॉलेंके कथनानुसार मानो चंद्रमा प्राप्त करनेके लिए चिल्लाता है।

उन्होंने स्वीकार किया कि वहुतसे सवालोंपर कांग्रेस और लीगमें कोई मतमेद नहीं है। उन्होंने ऐसे चौदह सवालोंको गिनाया। (१) न्याय और प्रशासकीय विभागोंको पृथक कर देना; (२) अपमानजनक औपनिवेशक आर्डिनेंसोंका रद किया जाना; (३) प्राथमिक शिक्षाका प्रसार; (४) उच नौकरियोंमें अधिक संख्यामें भारतीयोंका लिया जाना; (५) स्वास्थ्य व सफाईका उचित प्रवन्ध होना; (६) स्थानीय स्वायत शासनके मामलोंमें अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेपका वन्द होना; (७) फौजी व्ययमें उचित कमी होना; (८) भारतकी युद्धप्रिय (लड़ाकू) जातियोंको स्वयंसेवकोंकी मान्यता देना; (९) भारतीयोंको फौजमें कमीशनें देना; (१०) भारतकी आयसे इंगलैण्डमें या इंगलैण्डके हिसावमें हुए खर्चका ठीक-ठीक लेखा-जोखा रखना और न्यायोचित खर्च करना; (११) जमीनके लगानको सीमित करना; (१२) गाँव पंचायतोंका कायम किया जाना; (१३) भारतीय कला और उद्योगकी सुरक्षा करना और उसको प्रोत्साहन देना; (१४) जातीय भेद-भाव मिटा देना।

१९०८ के लीग अधिवेशनवेशनमें पास हुए प्रस्तावोंमें माँग की गयी थी—(१) स्थानीय वर्गोंमें साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वका विस्तार होना। (२) प्रिवी काँउसिलमें एक हिन्दू और एक मुसलमानकी नियुक्ति होना। (३) राज्यकी सव नौकरियोंमें मुसलमानोंको हिस्सा देना।

कांग्रेसके वंग-भंग विरोधी प्रस्तावका विरोध किया गया, ट्रांसवालमें भारतीयोंके प्रित दक्षिण-अफ्रीकाकी सरकारकी नीतिकी निन्दा की गयी। "सम्प्रदायगत चुनावपर लीगने जोर दिया" साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके लिए भारत और इंगलैंण्ड दोनों जगह, अखवारों और समाओं द्वारा प्रभावशाली उद्देलन किया गया। सर सैयद अमीरअलीकी अध्यक्षतामें लन्दनमें लीगकी एक अंग्रेजी शाखा स्थापित की गयी। भारत सचिवसे मिलनेके लिए एक शिष्टमण्डल मेजा गया। वाइसरायके सामने एक स्मृतिपत्र पेश किया गया। अंग्रेज हुके और मिन्टो-मार्ले-सुधारोंमें इस स्मृतिपत्रकी माँगें भी शामिल कर ली गयी।

राष्ट्रीय नेताओंने जिनमें कुछ मुसलमान भी शामिल थे, पृथक निर्वाचनका विरोध किया। एक वैरिस्टर नवाव सादिकअली खाँने लखनऊमें एक सभामें कहा "वर्गाय और धार्मिक प्रतिनिधित्वका सिद्धान्त इस योजनाको सबसे दुष्टतापूर्ण वात थी। ""मुसलमानोंके हितमें यह अच्छा नहीं है कि उन्हें यह सिखाया जाय कि उनके राजनीतिक हित हिन्दुओंसे भिन्न हैं। "मेरी नाकिस रायमें मुस्लिम दृष्टिकोणसे भी यह सिद्धान्त वहुत ही दुष्टतापूर्ण और बुरा है।" मिण्टो-मार्ले सुधारोंके ठीक दो वर्षों वाद, अंग्रेज राजनीतिक रेमजे मैकडोनल्डने भारतपर लिखी पुस्तकमें कुछ भेद खोले हैं। उन्होंने कहा "मुस्लिम समाजके कुछ दूरदर्शी सदस्य यह महसूस करने लगे हैं कि उन्होंने गलती की। वहुतोंने मुझसे दुखित होकर अपने नेताओंके रवैयेकी वात की कि किस प्रकार वे नेता आंग्ल-

१, हिन्दुस्तान रिन्यू अप्रैल १९०९ पृष्ठ ३५६

भारतीय अधिकारियोंका खेल खेलनेको राजी हो गये हैं । दूसरी तरफ जो कुछ हो गया था उससे जो लोग अमीतक सहमत थे, उनमें भी इस वातका भान हो रहा था कि आगे खतरे आनेवाले हैं और अच्छा होता अगर उन लोगोंने इस तरहकी माँग न की होती।"

उन्होंने आगे लिखा है—"मुस्लिम नेता कुछ आंग्ल-भारतीय अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहित हैं। इन अधिकारियोंने शिमला और लंदनमें साँठ-गाँठ की है और मुसलमानोंके साथ विशेष पश्चपात करके हिन्दू और मुस्लिम समाजोंमें वैमनस्य पैदा किया है। यह जानकर और पैशाचिक हंगसे "लड़ाओं और राज्य करों" सिद्धान्तके अन्तर्गत किया गया है या यह केवल एक भयानक गलती है— ऐसी गलती जो एक बार फिर सिद्ध करती है कि हमारे कुछ जिम्मेदार अधिकारी भारतको कितना कम समझते हैं या अपने कार्योंके परिणामोंका अन्दाजा लगा पाते हैं—यह बात लोग अभी नहीं बता सकते क्योंकि लाई मिण्टोंके भापणों और लाई मोंलेंके विरोधी भाषणों तथा दोनोंके सरकारको भेजे गये परस्पर विरोधी समाचारोंके सच्चे अर्थ अभीतक गुप्त रखे गये हैं।"

अप्रैल १९०९ के हिन्दोस्तान-रिच्यूमें एक मुसलमान सञ्जनने लिखा "मेरे सह-धर्मियोंका भारतमें एक न पटनेवाली खाई पेदा करनेका प्रयत्न स्तृत्य नहीं है। इससे अनिवार्य रूपमें बुराइयोंका स्रोत खुल जायगा और भारतको महाविषम गम्भीर परिस्थितिका सामना करना पड़ेगा।" ये सञ्जन सही सावित हुए, १९१९ के मुधारोंने सिखों और कुछ परि-गणित जातियोंमें भी पृथक् निर्वाचनका सिद्धान्त लागू कर दिया।

जनवरी १९१० में लीगका अधिवेशन दिर्छीमें आगा खाँकी अध्यक्षतामें हुआ। अध्यक्षते १९०९ के सुधारोंपर सन्तोप प्रकट किया और कहा कि अगर अब आन्दोलनको जारी रखा गया तो प्रस्तावित सुधार वापस लिये जा सकते हैं।

लीगका प्रधान कार्यालय अलीगढ़में स्थापित किया गया, परन्तु १९१० में इसकी लखनऊ हटाना पड़ा, क्योंकि लीगके एक नेताने एक गवर्नरको नाराज कर दिया था। २२ फरवरी १९०९ को यू० पी० के० लेपटीनेण्ट गवर्नर सर जॉन हीवेट अलीगढ़ कॉलेजके संस्थक थे। कॉलेजकी प्रवन्ध समिति द्वारा पेश किये गये मानपत्रका जनाव देते हुए उन्होंने विचार प्रगट किया कि किसी कक्षामें साटसे अधिक छात्र न हों और न किसी अध्यापकको आमतीरपर चार घण्टोंसे अधिक पढ़ाना पड़े, अध्यापकोंकी संख्या अनुपयुक्त थी। कॉलेजके मन्त्री नवाव वकाचल मुक्तने प्रधानाध्यापकसे दैनिक कार्यक्रम माँगा। राजनीतित्र प्रधानाध्यापकने इसको अपने काममें हस्तक्षेप माना और बजाय मन्त्रीको कार्यक्रम देनेके उन्होंने त्यागपत्र मेज दिया जिसकी एक प्रति उन्होंने लेपिटनेण्ट गवर्नरको मेज दी। इसके बाद बहु खुद ख्यनऊ जाकर लेपिटनेण्ट गवर्नरसे मिले और उनके सम्मुख अपना मामला रखा। नवाव बकाचल मुक्कको ख्यनऊ बुलाया गया और उनसे प्रधानाध्यापक द्वारा लगाये गये कुछ आरोपोंका उत्तर माँगा गया। दोनों पक्षोकी बात सुननेके बाद लेपिटनेण्ट गवर्नरसे अपना फैसला दिया जो अधिकांशतया मन्त्रीके खिलाफ था। मन्त्रीको गवर्नरके आदेशपर दस्तखत देनेको कहा गया। उन्होंने दस्तखत कर दिये। अपमानका यह बूँट निगलना प्रयन्धक समिति ('दृस्टीज') के लिए यड़ा कटिन था। उन्होंने एक मीटिंग बुलाकर

१. मैकडोनल्ड, दि अवेक्निंग आव इण्डिया पृष्ट १२९

२. वही पुस्तक, पृष्ट १७६-१७७

यह राय रखी कि संरक्षक है हिस्यतसे लेफिटनेण्ट गवर्नर कॉलेज मामलों सं दखल नहीं दे सकते । भारतके विभिन्न नगरों में सभाओं द्वारा इस विरोधका समर्थन किया गया। विरोध-प्रस्तायकी प्रतियाँ लेफिटनेंट गर्वनरको मेजी गर्यो । लेफिटनेंट गर्वनरकी कूटनीतिज्ञताने स्वयं उनको इस विरोध-प्रदर्शन, जिसकी वह राजभक्त मुसलमान नेताओं से आशा नहीं करते थे, के सामने झकनेको वाध्य किया; स्वयं उनके सुझावपर उनसे एक शिष्टमंडल मिला और उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया । परन्तु वे मुसलमानों में अपनी तरहके इस पहले आंदोलनका मूल कारण सोचने लगे ? क्या मुसलमानों हिम्मत, मुस्लिम लीगने वहायी है ? इसलिए उन्होंने आगा खांपर, जो लीगके अध्यक्ष थे और लीगकी धनसे सहायता करनेवालों में मुख्य थे, दवाव डाला कि वे लीगका प्रधान कार्यालय अलीगढ़से हटाकर लखनक ले आयें।

घटनावदा इस मामलेके कारण यरोपियन प्रधानाध्यापक द्वारा मुस्लिम राजनीतिका संचालन खत्म हो गया।

अध्याय ११

कांग्रेसमें फुट

१९०६ में कांग्रेसका अधिवेदान राजनीतिक चहल-पहलके केन्द्र कलकत्तेमें हुआ जिसमें १६६३ प्रतिनिधियों और २०,००० दर्शकोंने माग लिया। इतने प्रतिनिधि सन् १८८९ से नहीं आये थे। दर्शकोंका पण्डाल खचाखच भरा था।

दादाभाई नौरोजी अन्यक्ष चुने गये। इस समय उनकी अवस्था ८१ वर्षकी थी। वे तब इंगलेण्डमें थे। काँग्रेसकी आन्तरिक राजनीतिमें खाई बढ़ रही थी और पृष्टका टर हो रहा था, इसीलिए पुराने नेताओंने नौरोजीको अध्यक्षता करनेके लिए राजी किया था। तिलकके जीवनी-लेखक अठवलेके अनुसार नौरोजीको लानेका मुख्य कारण यह था कि तिलक अध्यक्ष न हो सकें। नरमदलीय और 'राष्ट्रीय' नेताओंमें अनवन सी थी। 'राष्ट्रीय' नेता वायकाटका अर्थ केवल अँग्रेजी वस्तुओंका बहिष्कार ही नहीं लगाते थे, बित्क द्यासन और सार्वजिनक कार्योंके सभी क्षेत्रोंमें अँग्रेजोंसे असहयोग भी उसीमें द्यामिल समझते थे। नेशनिलस्ट पार्टी प्रचार करती थी कि सभी सरकारी खिताब वापस कर दिये जायँ, लोग सरकारी अदालतोंमें सकदमें न ले जायँ, कोंसिलों और स्वायत्त शासन संस्थाओंमें कोई शामिल न हो। ब्रिटिश मालके विह्कारके साथ देशी उद्योग चलाना भी पार्टीके कार्य-क्रमका अंग था। ''शासन व्यवस्थाका संबिटत प्रतिरोध करना और स्वयँ-सहायताकी नीतिमें सरकारी अहंगेवाजी हो तो सविनय प्रतिरोध करना पार्टीका सिद्धान्त था। यह प्रतिरोध आवश्यकता पट्नेपर आक्रामक भी हो सकता था। और, यह प्रतिरोध कोई एक लास शिकायत दूर करानेके लिए नहीं, देशमें एक स्वतंच जनतान्त्रिक सरकारकी स्थापनाके लिए था।'' नेशनिलस्ट पार्टीको लोग उम्र दल, गरम दल और कांग्रेसके पुराने सुधारवादी नेताओंको 'नरमदल' कहते थे।

१९०६ के जाड़ोंतक गरम और नरमदलोंके वीचकी खाई इतनी चीड़ी हो चुकी थी कि नौरोजी जैसे विशाल व्यक्तिलाके अभावमें कांग्रेस अधिवेशनके शान्तरूपसे हो जानेमें संशय हो रहा था। नौरोजी राजी हो गये और जो त्पान १९०६ में आनेवाला था, यह एक सालके लिए टल गया। लेकिन विपय समितिकी बैठकमें बड़े क्षीम और उपद्रवके हस्य हुए। सभामें शान्ति रखना मुक्किल हो गया और अगर नरमदलीय लोग बोल पाये तो सिर्फ अपने आग्रह और हटते।

नयी मावना अध्यक्षके भाषणते भी प्रकट थी । दादाभाई बुढ़ापेके कारण खड़े न रह सकते थे, इसलिए गोखलेने उसे पढ़कर मुनाया । हेनरी केम्पवेल-वेनरमेनके इस उद्धरणते भाषण शुरू हुआ कि 'जनताकी अपनी सरकारकी एवजमें अच्छी सरकार नहीं हो नकती ।' कलकत्ता कांग्रेसको बालिंग कांग्रेस बताते हुए आपने कहा—अब गंभीरतापूर्वक सौचना है कि भारतीयोंकी हालत है क्या और होनी क्या चाहिये। आजादीते कम-ते-कम ये

१. अरवले 'लाइफ भाव लांकमान्य तिलक' पृष्ट १५६

२. आचार्य नरेन्द्रदंव 'कांग्रेस कमेमरेशन वॉल्ट्रम' में लेख पृष्ट १४६

अधिकार तो मिलते ही हैं कि सरकारी नौकरियों में देशी लोग रखे जाते हैं, कार्यकारी और विधायिका कौंसिलों में उनका प्रतिनिधित्व होता है और देशों के वीच उचित आर्थिक सम्बन्ध होते हैं। उन्होंने कहा—आन्दोलन करो, आन्दोलनका अर्थ है स्चना देना, बताना, प्रचार करना। "देशकी जनताको बताना है कि उसके क्या अधिकार हैं और वे क्यों और कैसे प्राप्त किये जा सकते हैं। इंगलैण्डका तो जीवन ही एक व्यापक आन्दोलन है। सबेरे आप समाचार पत्र खोलें, पूरा अखवार कांग्रेस, सम्मेलन, समाओं, और प्रस्तावोंसे भरा मिलेगा, वहाँ हजारों स्थानीय और राष्ट्रीय आन्दोलन चला करते हैं। वहाँ प्रधान मन्त्रीसे लेकर छोटेसे छोटे राजनीतिज्ञ—सभी सब कार्मोंके लिए आन्दोलन करते हैं। पार्लमेण्ट, सभाएँ, अखवार—वहाँ सब आन्दोलन ही हैं।" और कलकत्ता अधिवेशनके वादके वर्षोंमें भारतमें भी सब और आन्दोलन ही चला।

वायकाट आन्दोलनका समर्थन करते हुए नौरोजीने कहा—''जवतक २० करोड़ रुपया दूसरे देशके पुत्रोंकी तनस्वाहों, पंशनों आदिमें जाता रहेगा और भारतके पुत्र भूखे और गरीव होते रहेंगे, यहाँ आर्थिक नियमोंकी वात करना जलेपर निमक छिड़कना है।"

वंगभंगके विरोध और विह्मार आन्दोलनके पक्षमें आये प्रस्तावपर वोलते हुए मदनमोहन मालवीयने प्रस्तावक विपिनचन्द्र पालसे मतभेद प्रकट किया और कहा कि वाय-काट आन्दोलन और स्वोंमें नहीं चलाना चाहिये। उन्होंने आशा प्रकट की कि दूसरे प्रान्तोंमें वायकाटकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसपर गोखलेने पिछले वर्षके प्रस्तावकी ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि हम उस प्रस्तावसे वॅथे हुए हैं। इस मामलेपर नरम व गरम दलोंमें फूट पड़ने लगी पर जैसे तैसे समझौता हो गया।

नरमदलको अब भी विश्वास था कि अंग्रेज भारतके साथ न्याय करेंगे। लार्ड मिण्टो भी जानते थे कि नरमदलको खीज और निराशामें गरम दलसे मिलने देनेसे रोकना जरूरी है। इसका सबसे अच्छा तरीका कुछ ऊँचे पदोंपर भारतीयोंको वैठा देना और सुधारोंकी एक और किस्त दे देना था। उन्होंने भारत सचिव मॉलेंको लिखा कि केन्द्रीय विधायिका और कार्यकारी कोंसिलोंमें कुछ भारतीय रख लिये जाय और सुधारोंका प्रस्ताव तैयार कर लिया जाय। ब्रिटिश सरकार इससे आगे जानेको तैयार नहीं थी और भारत सचिवने इसकी सूचना गोखलेको दे दी थी। अगस्त सन् १९०६ को मॉलेंने मिण्टोंको लिखा था— कल मेरी गोखलेसे पाँचवीं और आखिरी वातचीत हो गयी। उन्होंने अपना लक्ष्य स्पष्टतः बता दिया कि भारत स्वशासित उपनिवेश हो। मैंने भी अपना विश्वास उनपर प्रकट कर दिया कि काफी दिनोंतक—इतने दिनोंतक जितने दिन मुझे भारत सचिव नहीं रहना है—यह लक्ष्य स्वप्न ही रह सकता है। 'हाँ, उस दिशामें बढ़नेके लिए न्यायोचित सुधारों का यह वहुत सुन्दर अवसर है।'"

मॉर्लेने यह भी लिखा था कि राजनीतिक सुधारों से लाख दरजे ज्यादा माँग इस वातकी है कि हर तरहके ऊँचे पदोंपर भारतीय नियुक्त किये जाय । चार महीने वाद मिण्टो और मॉर्ले दोनों -वाइसरायकी कार्यकारी कौंसिलमें एक 'देशी सदस्य' रखनेको राजी हो गये। यह अर्द्ध सरकारी समझौता ही था और इसे सरकारी रूप देते हुए मॉर्लेने जनवरी सन् १९०७ में लिखा कि यह अनिवार्य तो है लेकिन शायद यह "एक खतरनाक यात्राकी

१. मेरी मिण्टो—'इण्डिया, मिण्टो एण्ड मॉर्ले', पृष्ठ ९९

शुरुआत भी है।" वाइसरायकी केंसिलमें इस प्रस्तावका कड़ा विरोध हुआ। इस विरोधके जवावमें मिण्टोंने कहा—मेरी रायमें, अपने आस-पास होनेवाली घटनाओंकी जानकारीके वाद, इम जहाँ हैं, वहीं तो टहर नहीं सकते।"

एक तरफ देशमें असन्तोपकी ज्वाला उठ रही थी और दूसरी ओर भारत दिथत यूरोपीय समाज सुधारोंका घोर विरोधी था। इन विरोधी भावनाओंके वीच दवे लाई मिण्टोकी दिमागी हालतका पता उनके ८ मई सन् १९०७ के पत्रसे लगता है, जो उन्होंने भारत सचिवको लिखा था—"भारतीय दावोंको स्वीकार करनेका यूरोपीय समाजपर क्या असर पड़ेगा यह कहना मुक्किल है। में समझता हूँ कि अगर ये सुधार सालके शुरूमें लागृ हो गये होते तो यह उथल पुथल और विश्लोभ रोका जा सकता था, या कम-से-कम इसे रोकनेमें हम ज्यादा सक्षम होते।"

किसी भारतीयको वाइसरायकी कौंसिलमें लेना वहे साहसका काम समझा जाता था। खुद मिण्टोने १९ मार्च सन् १९०७ को मॉलेंको इस सिलसिलेमें लिखा था—"इस सुझावसे सम्वित्यत पत्र जितनी कठिनाइयों और सम्भावनाओंसे भरा हुआ है उतनी कठिनाइयों और सम्भावनाओंसे भरा पत्र कभी भी भारतसे इंगलेंण्ड नहीं गया। यह ऐसे भविष्यके सम्बन्ध में है, जिसके सम्बन्धमें निश्चय-पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता।"

मार्चमें ही सुधारोंके सम्बन्धमें गोखले वाइसरायसे मिले थे और कहा था कि पूरीकी पूरी नयी पीड़ी गरमदलमें जा रही है। लेकिन अंग्रेज भारतीय राजनीतिक उथल-पुथलकों समझते हुए भी शासन सत्ताका एक अंग्र भी हस्तान्तरित करनेको तैयार न थे। सुधारोंके मसौदेके साथ मिण्टोने जो पत्र मॉलेंको लिखा था, उसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि 'भारत सरकारको निरंकुश रहना ही चाहिये; सार्वभीम सत्ता अंग्रेजोंके हाथोंमें ही रहनी चाहिये और किसी भी किस्मकी देशी प्रतिनिध सभाको नहीं मिलनी चाहिये। कोई भी सभा भारतीय जनताका प्रतिनिधित्व करनेका दावा नहीं कर सकती जवतक कि भारतकी ९० फीसदी अपढ़ जनता यह नहीं समझती कि 'उत्तरदायी सरकार' होती क्या है और जवतक वह किसी भी जुनावमें प्रभावकारी ढंगते भाग लेनेमें असमर्थ है।'' जैसा कि उन्होंने अपनी पत्नीको लिखा मिण्टोको डर था कि 'हाकिमोंकी अङ्क्षेत्राजीकी दीवार हर उस काममें स्कावट हालती है जिसका तोड़-मरोड़कर भी वह अर्थ निकल आये कि अंग्रेज हाकिमोंके अधिकारोंमें हस्तक्षेप हो रहा है।''

बढ़ते हुए आतंकवाद (अगले अध्यायमें इसका विवरण दिया गया है) और गरमदलवालोंके प्रचार आन्दोलनने वाइसरायपर क्या असर डाला था, यह उनके उस पत्रसे स्पष्ट है जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम सबको लगता है कि हम इस देशमें एक यात्राके बीचमें रुके यात्री भर हैं और इस पड़ावसे हमें शीध कृत्र कर देना है। और मॉलेंने लिखा—"जिस ढंगसे तुमने वहाँकी स्थिति लिखी हैं, उससे स्पष्ट है इमारा महान् राज्य कितना कुत्रिम और क्षणमंगुर है। हम सोचते हैं कि यह टिकेगा केंसे? यह टिक नहीं सकता और हमारा काम सिर्फ इतना है कि अगली व्यवस्था—यह चाहे जो भी हो, कुछ सुधरी हुई हों।" उसी पत्रमें उन्होंने आगे लिखा था—"क्या तुम्हारों सुधार

१. मेरी मिण्टो, वही पुस्तक पृष्ट १०४

नीति, मेरी कौंसिलमें देशी सदस्योंके रखे जाने, विकेन्द्रीकरण, टेक्सोंमें कमी, और दूसरे भलाईके कामोंसे ब्रिटिश राजके वारेमें उनके विचारोंमें रत्ती वरावर भी अन्तर आवगा ?"

कुछ महीने वाद दो भारतीय भारत सचिवकी कौसिलके स्दस्य बना लिये गये और १९०८ में एक सदस्य वाइसरायकी कार्यकारिणीमें रख लिया गया। तिलक, पाल और अरिवन्द घोपकें नेतृत्वमें गरमदलके लोग कांग्रेसकी पूरी राजनीतिको हो वृसरी दिशामें मोड़नेके लिए प्रयत्नशील थे। न सुनी जानेवाली अर्जियाँ लगानेसे उनका विश्वास उठ चुका था। उन्होंने सुना कि वायकार आन्दोलनके सिलसिलेमें हुई कुछ अशान्तिमय घरनाओं से नरमदलीय नेता बहुत घत्रड़ा गये हैं और १९०७ के अधिवेशनमें वायकारका प्रत्ताव नहीं लाना चाहते। तिलक करियद्ध थे कि ऐसी कोई योजना सफल न होने दी जायगी। इसिलए उन्होंने अरिवन्द घोषके समापतित्वमें राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाकर कांग्रे सके अगले अध्यक्षके चुनावके पहले ही कांग्रे ससे माँग की कि कलकत्ता अधिवेशनके प्रत्तावोंका समर्थन हो। इस प्रकार उन्होंने नरमदलीय नेताओंके उपर्युक्त इरादेको विफल करनेका प्रयास किया।

अवं कांग्रेसके इतिहासका तूमानीकाल आ गया था। १९०७ का अधिवेशन नाग-पुरमें होनेवाला था और स्थानीय कार्यकर्ता उसकी तैयारियों में हमे थे। स्वागत समितिकी एक वैठक बुलायी गयी जो गड़वड़-घोटालेमें ही भंग हो गयी। 'राष्ट्रीयदल' के लोगोंने मस्ताव किया कि नागपुर अधिवेशनके अध्यक्ष तिलक हों। नरमंदलको यह प्रस्ताव असा-धारण माल्म पड़ा क्योंकि अवतक उन्हींके उम्मीदवार सर्वसम्मतिसे चुने जाते रहे। उन्होंने डाक्टर रासविहारी घोषका नाम चुना था और स्थापित परम्परामें राष्ट्रीय दलका यह न्याचात वे सहन नहीं कर सकते थे। ये मतभेद खत्म नहीं हए और अन्तमें अधिवेशन नागपुरसे हटाकर स्रतमें किया गया। २६ दिसम्बरको स्वागताध्यक्ष त्रिमुबनदास मालवीयकें भाषणसे काररवाई शुरू हुई। देशकी राजनीतिक परिस्थितिके सम्बन्धमें उन्होंने कहा-पिछले अधिवेशनके वादसे हम बढ़े आपत्तिकालसे गुजर रहे हैं। प्रमुख भारतीयोंपर सन्देह किया गया है और उनपर राजद्रोह, उपद्रव आदिके गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, जो अधिकांशतः आधारहीन हैं। इस साल किसी तरह शासकों के दिलमें यह वात घर कर गयी कि विद्रोहके वादका ५० वाँ साल होनेके कारण भारतीय फिर विद्रोह करनेकी तैयारीमें हैं; इससे वे घवरा गये । इस काल्पनिक विद्रोहको रोकनेके लिए उन्होंने बहुतसे प्रतिगामी और दमनकारी, कदम उठाये। पुराने भूले हुए ऐसे कानून हुँ इ निकाले गये जिनके अस्तित्वका लोगोंको ध्यान ही नहीं रह गया था और उन्हें लोगोंको दण्डित करनेके काममें लाया गया। होगोंपर अस्पर आरोप हमाये गये और अभियुक्तोंको न समय दिया गया, न अवसर जिसमें वे अपराधोंका खण्डन करते या अपना वचाव कर सकते l कुछ जगहोंपर यों ही मान लिया गया कि यहाँके निवासियोंके मनमें राज-द्रोहात्मक भावनाएँ हैं और वहाँ सार्वजनिक समाओंपर पावन्दी लगा दी गयी। और अब एक और खतरनाक कानृन हमपर लाद दिया गया है, जो गजटमें घोषणा करने भरसे सारे देशमें लागृ हो जायगा। यह कानून है— "राजद्रोहात्मक सभा कान्न।"

स्वागताच्यक्षके भाषणके बाद पण्डालमें कुछ समयतक विलकुल सन्नाटा रहा । तव

१. मेरी मिण्टो, बृष्ठ १५३

दीवान वहादुर अम्वालाल एस. देसाईने जान्तेसे डाक्टर रासविहारी घोषका नाम अध्यक्ष पद-के लिए प्रस्तावित किया। कुछ प्रतिनिधियोंने 'नहीं, नहीं' कह कर विरोध प्रदर्शित किया पर देसाईके भाषणमें इससे अधिक व्याघात नहीं हुआ। लेकिन जब सुरेन्द्रनाथ बनर्जी इस प्रस्तावका समर्थन करनेके लिए खड़े हुए, तब इतना शोर मचा कि उनका भाषण सुना ही न जा सका। स्वागताध्यक्षने अन्तमें बैठक अगले दिनके लिए स्थगित कर दी ताकि तबतक लोगोंका आवेश खत्म हो ले।

गरमदलको खबर लगी थी कि अधिवेशनमं पेश होनेवाले प्रस्तावांमं स्वराज्य, वाय-काट, राष्ट्रीय शिक्षा जैसे विषयों के प्रस्ताव शामिल नहीं किये गये ताकि सरकार नाखुश न हो । गरमदलवाले कांग्रे सकी धीमी रपतारसे असंतुष्ट थे; उन्होंने फेंसल्य किया कि जो हो चुका है, उससे पीछे तो हरिगज नहीं लोटने दिया जाय । २३ दिसम्बरको स्र्तमं ही एक सार्वजिनिक सभामं भाषण करते हुए तिलकने नरमदलकी पीछे लोटनेकी नीतिको राष्ट्रहितके लिए वातक 'वताया । दूसरे दिन ५०० 'राष्ट्रीय' प्रतिनिधियोंकी एक सभा अरिवन्द घोषके सभापितित्वमें हुई जिसमें निश्चय हुआ कि हर वैधानिक तरीकेसे कांग्रेसको पीछे लोटनेसे रोका जाय; जरूरत पड़े तो अध्यक्षके चुनावका भी विरोध किया जाय । २५ दिसम्बरको राष्ट्रीय प्रतिनिधियोंकी फिर बैठक हुई और वही निर्णय दोहराया गया; अवतक इन प्रतिनिधियोंको संख्या ६०० हो चुकी थी । पर नरमदल और कांग्रेसके सिचवालयने न तो इन लोगोंको आपत्तियाँ ही गम्भीरता-पूर्वक सुनीं और न इनको समझौतेकी वातचीतपर ही ध्यान दिया ।

२७ दिसम्बरको बैठक शुरू होनेपर तिलक्ते स्वागताध्यक्षको एक पर्चा भेजा जिसपर लिखा था-"अध्यक्षके नामके समर्थनके बाद में प्रतिनिधियोंके समक्ष इसी प्रस्तावपर बोलना चाहता हैं। मैं एक रचनात्मक सुझावके साथ काम स्थिगत करनेका प्रस्ताव पेदा करूँगा। कृपया मेरे नामकी घोषणा कर दें।" स्वागताध्यक्षने कोई जवाब नहीं दिया। तिलक्षने फिर याद दिलाते हुए एक पर्चा भेजा पर उसका भी जवाय नहीं मिला । तिलकको अपनी वात कहनेका मौका नहीं मिला । इसलिए जब डाक्टर घोप अध्यक्ष घोषित कर दिये गये, तिलक स्वयंसेवकोंको भक्तेलते हुए मंचपर पहुँच गये । उसी वक्त डाक्टर घोप अध्यक्षकी कुरसीपर वैठ रहे थे। तिलकने जैसे ही भाषण शुरू किया, एकदम शोरगुल मचने लगा। नरम दलवाले चिछाते कि तिलक वैठ जारूँ, गरमदलवाले कहते कि तिलकको मुना जाय। जव तिलक मंचसे नहीं हुटे तो घोप और मालवीयने उन्हें हुटानेका आदेश दिया। स्वागत समितिका एक मंत्री मंचपर आकर उन्हें हटाने लगा, पर तिलकने उसे धकेलते हुए कहा कि मुझे अपनी वात सुनानेका अधिकार है। उन्होंने कहा कि में मंच तवतक नहीं छोट्टँगा जवतक मुझे जवरदस्ती घसीटकर मंचसे हटा नहीं दिया जायगा । इसके बाद जो हुट्दंग शुरू हुआ उसमें भीरोजशाह मेहताको एक जुता लगा, किसीने यह जुता मंचपर फेंबा था। कुरसियाँ फेंकी गयीं । घोषने दो बार बड़ी हिम्मतसे अपना भाषण शुरू किया टेफिन 'नहीं', 'नहीं' की आवाजोंने उन्हें चुप कर दिया । जब शान्ति खापनाकी आशा न रही, अध्यक्षने वैठक स्थगित कर दी और पुल्सि बुलायी गयी, जिसने फीरन आकर हाल खाली करा दिया। प्रसिद्ध लेखक हेनरी नेविनसन अधिवेशनमें मीज्द थे, उन्होंने लिखा है—"हवामें कुरसियाँ गोलोंकी तरह छूट रही थीं । लाठियाँ लड़ रही थीं । फूटे सिरोंसे खून वह रहा था । कटिन. और अस्पष्ट संघर्ष था । दस हजार कुर्सियोंपर बेटे दस हजार व्यक्ति; न कोई बरदी और

न कोई पहिचान; नरम और गरममें अन्तर करनेका कोई उपाय नहीं—सिवा उनके चेहरेके भावके।"

तिलक चाहते थे कि वैठक स्थगित कर दी जाय और अध्यक्षके चुनावपर उत्पन्न मतभेद दोनों दर्लोंके प्रमुख प्रतिनिधियोंकी एक संयुक्त समझौता-समितिमें तय हो जायँ। अगले दिन उन्होंने लिखकर आस्वासन दिया कि "मैं और मेरे दलके लोग डाक्टर घोषके चुनावका विरोध छोड़ देने और पुरानी वातोंको भूलनेको तैयार हैं, पर शर्त यह है कि एक तो स्वराज्य, स्वदेशी, वायकार और राष्ट्रीय शिक्षा सम्बन्धी गत वर्षके प्रस्तावींपर टिका जाय और ईमानदारीसे उन्हें दोहराकर उनका समर्थन किया जाय, दूसरे यदि डाक्टर घोषके भाषणमें कुछ ऐसे अंश हैं जो नेशनिलस्ट पार्टीको नागवार लगें, तो उन्हें निकाल दिया जाय। "स्रत अधिवैद्यनसे टीक पहले गोखलेने कांग्रेसके विधानका एक मसीदा तैयार किया था जिसमें कांग्रेसका 'अंतिम लक्ष्य' "भारतके लिए उसी प्रकारका स्वदासन प्राप्त करना, जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्यके दूसरे राष्ट्र-सदस्योंको प्राप्त है" वताया गया था। इस अन्तिम लक्ष्यको नेशनलिस्ट पार्टी व्यावहारिक राजनीतिसे परे मानती थी और वह स्वराज्यकी माँगपर अडिंग थी। पर गोखलेको डर था कि नेश-निल्हर पार्टीका प्रस्ताव स्वीकार करनेसे, वातावरणके उस तनावमें, सरकार बुरा मान जायगी । अपनी इस आशंकाको उन्होंने एक पत्रमें इस प्रकार लिखा था - आप इस सर-कारके पीछे जो निज्ञाल शक्ति छिपी हुई है, उसे नहीं समझते । अगर कांग्रेस आपके सुझाव मान ले तो सरकार पाँच मिनटमें कांग्रेसका मुँह वन्द कर सकती है और गला घोंट दे सकती है। ''विधायिका कोंसिलमें मार्च सन् १९०६ में गोखलेने वजटपर जो भाषण किया था उससे उनका सुधारवाद अधिक स्पष्ट हो जाता है । उन्होंने कहा था-"शिक्षित वर्गोंको समझाने-का प्रश्न ऐसा है " जिसे हल करनेमें ब्रिटिश राजनीतिज्ञता और द्रदर्शिताके पूरे साधन लग जाउँगे। इन वर्गोंसे सुलह करनेका सिर्फ एक रास्ता है, और वह है उन्हें अपने देशके शासनमें ज्यादा ज्यादा लगाना ' आज इस देशको जिस चीजकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वह है ऐसी सरकार जो तत्वतः राष्ट्रीय हो, चाहे उसे चला विदेशी ही रहे हों।"

अधिवेशन स्थिगत होनेके वाद नरमदल प्रेमुख नेता, जैसे डाक्टर घोष, फीरोज-शाह मेहता, गोखले, दीनशा वाचा, मदनमोहन मालवीय, कृष्णस्वामी ऐयर आदि एकत्र हुए और उन्होंने अगले दिन २८ दिसम्बरको एक राष्ट्रीय सम्मेलन करनेकी नोटिस प्रसारित की। इस सम्मेलनमें सिर्फ वे ही प्रतिनिधि आमन्त्रित किये गये थे जो मानते थे कि (१) भारतको वैसा ही स्वशासन दिलाना उसका राजनीतिक ध्येय है जैसा ब्रिटिश साम्राज्यके अन्य सदस्य राष्ट्रोंको प्राप्त है और भारतको अन्य ऐसे राष्ट्रोंके समकक्ष ब्रिटिश साम्राज्यके अधिकारों और दायित्वोंका समान भाग मिलना चाहिये, (२) इस दिशामें केवल वैधानिक तरीकोंसे प्रगति करनी चाहिये। १६०० में से ९०० प्रतिनिधियोंने इस उद्देश्यको माना और सम्मेलनमें शामिल हुए। डाक्टर घोप अध्यक्ष बनाये गये। सम्मेलन ने १०० से अधिक सदस्योंकी एक समिति कांग्रेसका विधान बनानेके लिए नियुक्त की। अगले साल १८ व १९

प्डवर्ड टॉमसनकी 'दि रिकंस्ट्रक्शन आव इण्डिया' में पृ० ९७ पर 'मोर चॅंजेज, मोर चांसेंज'के पृष्ट २७० से उद्धत

२. चूकनके 'लार्ड मिण्टो' में २३१ पृष्टपर उद्धत

अप्रैलको इस समितिकी वैठक इलाहावादमें हुई और नो विधान तैयार किया गया, उसमें कांग्रेसका लक्ष्य 'ऐसी शासन-प्रणालीका भारतमें प्रचलन नैसी ब्रिटिश साम्राज्यके अन्य स्वशासित देशों में है', बताया गया। यह विधान १९०८ के अधिवेशनमें पेश हुआ पर वह पास १९११ में हुआ। इस बीच विधान नियमोंकी खानापूरीमें पड़ा रहा। पर स्रतमें अलग हुए राष्ट्रीय नेता १९१६ तक कांग्रेसमें नहीं लीटे।

१९०८ में सुधारोंकी दूसरी किस्त—मॉर्ले-मिण्टो सुधारोंकी घोषणा हुई। इनके द्वारा विधायिका केंसिलोंका विस्तार और गैर-सरकारी सदस्योंके अप्रत्यक्ष चुनावकी व्यवस्या हुई। केन्द्रीय केंसिलों सरकारी सदस्योंका बहुमत कायम रखा गया, पर प्रान्तीय केंसिलों में निर्वाचित सदस्योंकी संख्या सरकारी सदस्योंके कुछ ज्यादा रखी गयी। सुधारोंकी एक खास बात चुनावमें साम्प्रदायिक मतदाता प्रणालीके सिद्धान्तकी स्वीकृति थी। इसे राजनीतिक नेताओं व समाचारपत्रोंने हिन्दुओं व मुसलमानोंको अलग करनेकी चाल वताया। जर्मा-दारोंको विद्येप प्रतिनिधित्व मिला हुआ था। यद्यपि कोंसिलोंका विस्तार हुआ था और उनमें और अधिक भारतीय आनेको थे, पर वे पहलेकी तरह ही बाद-विवादकी संस्थाएँ मर बनाकर रखी गयी थीं। उन्हें सरकारके सालाना वजटपर विचारकर उसमें संशोधनके सुझाव देनेका अधिकार तो था पर बहुमतसे पास करनेके वाद भी कौंसिलें ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थीं जो सरकार न करने देना चाहती हो।

मॉलेंने ब्रिटिश लोकसभामें ईमानदारीके साथ स्वीकार किया कि भारतको संसदीय पद्धतिकी सरकार कभी भी न प्राप्त होगी । उन्होंने कहा—"यदि में भारतमें संसदीय पद्धतिकी सरकार चलानेकी कोशिश करता हूँ, या कोई यह कहता है कि सुधारोंके इस अध्यायने सीधे या अप्रत्यक्ष रूपसे भारतमें संसदीय पद्धतिकी सरकार स्थापित हो रही हैं, गो में इस कामसे हाथ खोंच लूँगा।" या अपित में इस पद या इस जीवनकी सामान्य अवधिन्ने २० गुनी ज्यादा अवधि पा जाऊँ, तब भी इस लक्ष्यकी ओर बढ़नेकी तो में एक अणके लिए भी नहीं सोचूँगा।"

लेकिन तब भी नरमदलने इन मुधारींका हार्दिक स्वागत किया। गोखलेने उन्हें 'उदार और उचित' की संज्ञा दी और अनुरोध किया कि उन्हें अनुग्रहीत होकर स्वीकार किया जाय। लेकिन कान्तिकारियों और उम्र दलवालोंके लिए तो मॉलेंका यह भाषण एक चुनौतो था। आनेवाले दस वर्षोंमें वम और पिस्तौलकी राजनीतिने सरकारके नाकों दम कर दिया।

भारत सिचवके पद्यर मॉलेंके उत्तराधिकारी लार्ड कृते भी मॉलेंकी नीति ही जारी रखी और जून सन् १९१२ में ब्रिटिश लोक-सभामें दो भाषणोंमें उन्होंने भारतीयों से कहा कि वे स्वशासनकी कोई आशा न रखें। उन्होंने कहा—"भारतमें एक वर्ग ऐसा है, जो दूसरे उपिनवेशोंको मिले स्वशासनकी तरहका स्वशासन मारतमें भी चाहता है। मुझे नहीं लगता कि भारत भविष्यमें भी उस ओर बढ़ेगा। एक दूसरी जातिके लोगोंको हमारी इस लोक-सभाके नियन्त्रणसे वाहर स्वशासन देनेका प्रयोग नहीं किया जा सकता, चाहे उस जातिकी सेवामें हमारी जातिके सवसे उत्तम लोग ही क्यों न लगे होंक्या यह सोचा भी जा सकता है कि आस्ट्रेलिया या न्यूजीलेण्डकी तरह, भारतीय साम्राज्यकी भविष्यमें कोई ऐसी स्थित हो जायगी जब कोई अंग्रेज अफसर वहाँ न रहे—विशेषकर जब भारतसे हमारे रिवर, धर्म

या कोई ऐसे वन्धन नहीं हैं जो भौतिक बन्धनोंका स्थान हे सकें ?.....मुझे तो यह केवल १९२

अव हम जरा पीछे छोटें। दिसम्बर सन् १९०८ में ब्रिटिश सरकारने छोक-समामें भारतके लिए सुधार विल पेश करना तय किया था; पर तभी वाइसराय लार्ड मिण्टो वंगालमें कल्पनालोककी वात मालूम पड़ती है।"

आतंकवादके दमनके लिए एक कड़ा कानून बनानेकी सीच रहे थे।

११ दिसम्बर १९०८ को वाइसरायकी (केन्द्रीय) विधायिका कोंसिलने एक वैठकमें ही फीजदारी कातृन संज्ञोधन विल पास कर दिया। इस विल हारा सरकारने "कुछ था गार्था नार्था नार्या नार्था नार्या नार्था नार्था नार्था नार्था नार्था नार्था नार्था नार्था नार्या नार्था नार्थ जनपाना अन्यस्ताना साहणा दूरना पान नारण जार जानजाना सामित हमते बाद भारत संस्थाओंपर रोक लगाने के अधिकार, अपने हाथमें हे लिये। इसके एक हमते बाद भारत वायपन पाड प्रनाम नास्य प्रभार नियं नवा विश्वा । रूप विश्वा था होकं समामें हिस्से बाद की गयी थी। मिण्टोने ३० नवम्बरको ही माँहेंको हिसा था होकं समामें हुधारोंकी घोषणांके पहले ही दमनकारी कान्न वन जाना चाहिये। में वहुत उत्सुक हूँ कि छवाराका वावणाके पहले ही यहाँका अरुविकर काम समाप्त हो जाय। हम पहले दवा दे दें आपक़ी घोषणाके पहले ही यहाँका अरुविकर काम समाप्त हो जाय। आर उसकी बाद उसका कड़वा स्वाद दूर करनेके लिए जो कुछ भी कर सकते हों करें। आर उपका कार उपका कार्य आपका पारणाक अप रहा कहा नारा क्या जा का का पारा का का मारा का जाका है मरीजर्क मुँहमें रह जायगा। में चाहता हूँ कि गरती होगी। आखरी घूँटका जायका ही मरीजर्क मुँहमें रह जायगा। में चाहता हूँ कि भण्या होता । जाजरा प्रज्या जाजरा श्राप्ता हो जाया उर्ण पर जाया। म चाहता हूं कि अपना होते पाये, ऐसी ही अपकी घोषणाका स्वागत यहाँ शंखध्वित्ति हो उसका प्रभाव कम न होने पाये, ऐसी ही

फोजदारी कान्त्के संशोधनके दो दिनके भीतर दस वंगालियोंको विना मुकदमा चलाये काले पानी भेज दिया गया। और उसके पाँच दिन बाद, पूर्व निरुचयके अनुसार कोशिश में कर रहा हूँ। १९१

सूरत अधिवेशन स्थगित माना गया और अगले सालका महास अधिवेशन भी २३वाँ अधिवेशन ही माना गया। महास अधिवेशन विलक्षुल नरमदलीय अधिवेशन था। भारत सचिवका सुधार विल आया। डाक्टर घोष फिर अध्यक्ष हुए । उन्होंने अपने प्राष्ट्रणमें मुघारोंके प्रस्तावका स्वागत जिया । एक प्रस्ताव द्वारा कांग्रेसने उन्हें सुधारों की वड़ी और उदार किस्त जो देशवासियों को राजकाजमें काफी हिस्सा देने और शासन तन्त्रको जनताकी भावना व आवश्यकताक का राजकाजन काना । हरण प्र जार सायम प्राप्त जनपाक नायम प्र जायस्वकाल वर्षे एक घोषणा द्वारा ५० वर्षे अनुकूल बनानेके लिए जरूरी थीं, बताया। उसी साल बादशाहने एक घोषणा द्वारा ५० वर्षे अध्यूष्ण बनागना विष्य अस्ति ना क्षेत्र विद्याया और वैधानिक सुधारोंकी आशा दिलायी। पहले विकटोरिया द्वारा किये वादोंकी दोहराया और वैधानिक सुधारोंकी आशा दिलायी। पहल विकटारिया क्षारा किय यायाका प्राध्याया जार प्रयानिक अपेती 'निष्ठापूर्ण श्रद्धांजित' वादग्राहके इस सन्देशका स्वागत करते हुए कांग्रेसने उनके प्रति अपेती 'निष्ठापूर्ण श्रद्धांजित'

१९०९ के लाहोर अधिवेशनके लिए मदनमोहन मालवीय अध्यक्ष चुने गये। अधि वेशन ग्रुह होनेके कुल छ दिन पहले उन्हें इसकी सूचना दी गयी। असहमें लोगोंका ह्यारा प्रसम् अल हानम अल्ल हा प्रमा प्रमा हा प्रमा हा प्रमा हा स्वार अवकारा ग्रहण करनेका कि सेहताको अध्यक्ष बनानेका था, पर वे राजनीतिसे अवकारा ग्रहण करनेका कि सेहताको अध्यक्ष बनानेका था, पर वे राजनीतिसे अवकारा ग्रहण करनेका कि सेहताको अध्यक्ष बनानेका था, पर वे राजनीतिसे अवकारा ग्रहण करनेका कि सेहताको अध्यक्ष बनानेका था, पर वे राजनीतिसे अवकारा ग्रहण करनेका था, पर वे राजनीतिसे अवकारा ग्रहण करा था, पर वे राजनीतिसे अवकारा ग्रहण करनेका था, पर वे राजनीतिसे अवकारा ग्रहण करनेका था, पर वे राजनीतिसे अवकारा था, पर वे राजनीतिसे अवकारा था, पर वे राजनीतिस्थ था, पिराजशाह महताका अन्यव वनानका याः पर व राजनाति अवकाश अहण करनका निम्ना कर विद्या था । मालतीय तत्र वीमार् निम्नय कर चुके थे और उन्होंने यह आमन्त्रण अस्त्रीकार कर दिया था । मालतीय तत्र वीमार् अर्षित की । शिव्यव कार अस्त्र अध्यक्ष भाषण हिल्लनेका परिश्रम उनके स्वास्ध्यके हिए उचित नहीं था । पर तब भी

१. मेरी मिण्टो, पृष्ठ २५५

टन्होंने ६३ पृष्ठोंका छपा हुआ लम्बा और प्रशंसनीय भाषण तैयार कर लिया । इसमें उस समयकी आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितिकी विशद चर्चा की गयी थी ।

लाहीर अधिवेशनने 'धर्मके आधारपर स्थापित पृथक निर्वाचन पद्धतिसे असहमतिकी तीत्र भावना वसक करते हुए उस कान्नके अधीन वने नियमोंसे 'देश व्यापी घोर असन्तोप' का वर्णन किया । इस असन्तोपके कारण थे, (अ) एक विशेष धर्मके अनुयायियों (मुसलमानों) को मिला "अत्यधिक और अनुचित प्रतिनिधित्व" (व) मुस्लिम व गैर-मुस्लिम प्रजाम अनु-चित, अपमानजनक और द्वेपपूर्ण मेद-भाव; और (स) प्रान्तीय कौंसिलोंमें इस ढंगसे गैर-सरकारी बहमतका रखा जाना जिससे वह न्यावहारिक रूपसे अप्रमानकारी और अवास्तविक रह जाय । अपने भाषणमें मालवीयजीने कहा कि मुस्लिम अल्पसंख्यकोंको पृथक निर्वाचनके साथ ही सामान्य निर्वाचनमें भी मतदानकी सुविधा मिली हुई है, लेकिन पंजाय और आसाममें हिन्दू अल्पसंख्यकोंको ये सुविघाएँ प्राप्त नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ३०००) सालाना आयकर देनेवाले मुसलमानको तो बोट मिला हुआ है, पर २००,०००) सालाना आयकर देनेवाले हिन्दको नहीं । पाँच साल पहले वी॰ ए॰ पास करनेवाले मुसलमानीको तो वोट मिला है पर २० साल पहले बी. ए. हुए गैरमुस्लिमोंको यह हक नहीं है। मुधार सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करते हुए मुरेन्द्रनाथ वनर्जीने कहा कि १९०९ के कान्नके अन्तर्गत वने नियमें। ने सुधारको व्यर्थ कर दिया है। उस साल भारत सचिवने भारत सरकारको लिखा था कि शहरी व देहाती स्थानिक संस्थाओंको सच्ची स्वायत्त शासन संस्थाएँ बनानेकी जरूरत है। कांग्रेसने इसपर सन्तोष प्रकट किया ।

'राष्ट्रीय' प्रतिनिधि न आने और शिक्षासंस्थाओंपर रोक लगनेके कारण लाई।र अधि-वेशनमें उपस्थिति वहुत कम थी । कुल २४३ प्रतिनिधि आये हुए थे ।

१९१० के इलाहाबाद अधिवेशनमें ६३६ प्रतिनिधि आये। अध्यक्ष सर बिलियम वेडरवर्न चुने गये थे। अपने भाषणमें उन्होंने यूरोपीय अफसरों और शिक्षित भारतीयों, हिन्दुओं और मुसलमानों तथा नरम और गरम दलोंके बीच उत्पन्न मतभेदोंको मिटानेकी आवश्यकतापर जोर दिया। इस साल पृथक् निर्वाचन जिला व म्युनिसिपल बोहोंमें भी लाग् कर दिया गया था। कांग्रेसने एक प्रस्ताव द्वारा स्वायत्त शासन संस्थाओं में पृथक् निर्वाचन चलानेकी जोरदार निन्दा की।

१९११ में वादशाह और महारानी भारत आये और उनके लिए दरवार किया गया जिसमें दो महत्त्वपूर्ण वोपणाएँ हुई । एकने वंगभंगको खत्म कर दिया । उसकी जगह विहार व उड़ोसाका एक अलग स्वा बना दिया गया । दूसरी वोपणासे भारतकी राजधानी कलकत्ते के वजाय दिल्ली बना दी गयी । कांग्रेसका अधिवेशन विण्युनारायण धरकी अध्यक्षतामें खुशीके वातावरणमें हुआ । घर वैरिस्टर और कलकत्ता कारपोरेशनके सदस्य थे । पहले रैमने मैकडो नल्डको अध्यक्ष बनानेका इरादा था, पर उनकी पत्नीकी मृत्युके कारण वह पद प्रहण न कर सके । धरने अपने भाषणमें कहा—"हमारे दुर्भाग्यका कारण हमारी आकांशाओं और आदशोंके प्रति अहलकारी समाजकी अनुदार एवं उपेक्षापूर्ण मनोवृत्ति है; और अगर यह मनोवृत्ति न बदली तो भविष्यमें गम्भीर संकट आ सकता है । एक और नये भारतका खजन हो रहा है, दूसरी ओर यह मनोवृत्ति बढ़ रही है; इससे संकटापत्र रियति पैदा हो गयी है । एक और भारतका शिक्षत समाज है, जो नये शन और अपने राजनीतिक अधिकारोंकी नयी

चेतनासे युक्त है, लेकिन एक दिकयान्सी शासन-प्रणालीसे वॅधा हुआ है; दूसरी ओर रियर स्वायोंसे युक्त अहलकारी वर्ग है, जो उद्धत स्वभाव, निरंकुश शासनकी परम्परा और ज्ञानके प्रति संशयको भावनामें पड़ा है, जाति-पार्थक्यके कारण जनजीवनसे कटा हुआ है और एक ऐसी शासन-प्रणालीके अन्तर्गत धन और शिक्तका भोग कर रहा है जो आजके उदार सिद्धान्तोंमें नहीं खपती।"

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आन्दोलनकी टकरमें मुस्लिम लीगको प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

विधायिका कोंसिलोंमें जमींदारों व मुसलमानोंके अत्यधिक प्रतिनिधित्व और पृथक निर्वाचन-प्रणालीका विरोध करते हुए धरने कहा—जमींदार अधिकसे अधिक अनुदार प्रवृत्ति- के ही हो पाते हैं— इंगलैण्डके जमींदारोंकी तरह नहीं जो पढ़े-लिखे, कुशाय बुद्धि और राजनीतिके जानकार होते हैं: भारतीय जमींदार एक वर्गकी हैसियतसे ज्ञानमें पिछड़े, पुरातन विचारोंमें लीन और जीवनके चरम उत्कर्षको प्राचीनताके घने कुहरेमें देखनेवाले हैं। कोंसिलोंमें उनके आधिक्यसे सरकारके सुधारकार्यमें कोई सहायता नहीं मिल सकती; कृषिकान्तोंके सम्बन्धमें तो यह वर्ग वाधास्वरूप है। उनका उपयोग अहलकारी वर्ग अधिक प्रगतिशील लोगोंकी टक्करमें कर सकता है और जमींदारोंका यह उपयोग वहुधा हुआ भी है, जब शिक्षतवर्गने कोई ऐसी माँग रखी है, जिसे सरकारने दुकराना चाहा है; पर वे जनताके विचारों या भावनाओंका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करते।

सुधारोंमें मिले कोंसिलोंके गैरसरकारी प्रतिनिधित्वके बहुमतको मरीचिका बताते हुए आपने कहा कि उनमें जमींदारों, राजाओं और रईसोंका ही बहुमत होगा और इन लोगोंको जनताके हितोंसे दिलचस्पी नहीं है। संयुक्त प्रान्तकी कोंसिलका उदाहरण देते हुए आपने कहा—'गैरसरकारी सदस्योंका लगभग हर प्रस्ताव वहाँ भारी बहुमतसे गिर गया क्योंकि कुछ निर्वाचित और सभी नामजद सदस्य सदैव सरकारकी सहायताके लिए तत्पर रहते थे।' आपने हर प्रान्तीय कोंसिलमें निर्वाचित सदस्योंके प्रत्यक्ष और साफ बहुमतकी माँग की।

ऑकड़े देकर आपने सिद्ध किया कि स्वायत्त शासनमें पृथक् निर्वाचन शरारतसे भरा है; संयुक्त निर्वाचनसे मुसल्मानोंको भी लाभ है। उदाहरणार्थ, संयुक्तप्रान्तमें मुसल्मानोंकी जनसंख्या कुल १४ प्रतिशत है लेकिन जिला वोडोंमें उनके प्रतिनिधि २३ फीसदी हैं। "४५ में से २९ जिला वोडोंमें मुस्लिम सदस्योंका अनुपात उनकी आवादीके अनुपातसे ज्यादा है!" आपने आगे वताया कि जिला वोडोंके ६६३ सदस्योंमें ४४५ हिन्दू और १८९ मुसलमान; म्युनिसिपल वोडोंमें ५६२ हिन्दू और ३१० मुसल्मान।

१९१२ में आर. एन. मधोलकरकी अध्यक्षतामें वाँकीपुरमें कांग्रेसका अधिवेशन हुआ। इस साल दो दुखद घटनाएँ हुई थाँ। 'कांग्रेसके पिता' कहे जानेवाले ह्यू मकी (जो २२ वर्ष-तक लगातार कांग्रेसके जनरल सेकेटरी रहे) ३१ जुलाईको मृत्यु हो गयी थी। देशभरमें शोक मनाया गया और सार्वजनिक सभाओं में भारतके प्रति उनके उपकारोंके लिए कृतज्ञता प्रकाशके प्रस्ताव पास किये गये।

दूसरी घटना नये वाइसराय लार्ड हार्डिजपर उनके दिल्ली जानेके समय वम फेंके जानेकी थी। कांग्रेसने तार भेजकर वाइसरायके वच जानेपर वधाई दी और वमकाण्डकी निन्दा की।

मधीलकर वकील थे। वे १८८८ में कांग्रेसमें ज्ञामिल हुए थे और तबसे वरावर उसके उत्साही कार्यकर्ता रहे। १८८८ में ही उन्होंने बरार सार्वजितक सभाकी स्थापना की थी और १८९८ तक उसके सेके टरी रहे। अपने भाषणमें उन्होंने कांग्रेसजनोंसे जनताकी सची राजनीतिमें भाग लेनेकी अपील की। आपने कहा—कांग्रेसके नेताओंको जनताको जगानेकी और और अधिक ध्यान देना चाहिये; जनताको जगाकर, उसकी दिलचरपी और चेतना स्थायी रूपसे ऊँचे स्तरपर रखकर संघटनकी मजवृत द्याखाएँ खोलकर जनवाणीको और मुखर बनाना होगा। भारतीय द्यासन और झासन-व्यवस्थाके व्यावहारिक पहल्पर ज्यादा ध्यान देकर उन्हें ब्यावहारिक प्रक्तींके हल हुँदने होंगे। सामाजिक प्रगति और नेतिक व आध्यात्मिक पुनर्जागरणके विना कोई भी सची और टोस राजनीतिक प्रगति नहीं हो सकती।"

वॉकीपुर अधिवेशनमें बहुतसे मुस्लिम प्रतिनिधियोंने भी भाग लिया था। स्वागताध्यक्ष मजहरल इक थे। लेकिन लगता है कि वे भारतीय मुसलमानोंकी प्रतिनिधि संस्था मुस्लिम लीगको ही मानते थे। उन्होंने कहा—"उदार चेता मुसलमानोंका एक सशक्त और विराष्ट्र संघटन वन चुका है; इस संस्थाके उद्देश्य और लक्ष्य वे ही हैं जो कांग्रेसके अधि संस्था भविष्यमें भारतीय मुसलमानोंका नेतृत्व करेगी।"

'राष्ट्रीय' नेताओं और कार्यकर्ताओं के निकल जानेके वाद कांग्रेस और अधिक नरम हो गयी, क्योंकि उसके नेता समझते थे कि उन्हींके प्रयासोंके फलस्वरूप मुधारोंकी दूसरी किस्त मिली।

१९११ के उत्तरार्डमें, अखवारोंमें एक खबर यह छपी कि भारत सरकारने मारत सिवको लिखा है कि भारतको प्रान्तीय स्वराज्य दे दिया जाय । खबरमें लिखा था— "यहाँकी सभी किटनाइयों और समस्याओंका एकमात्र हल यह माल्म पड़ता है कि प्रान्तोंको धीरे-धीरे स्वज्ञासन दिया जाय, यहाँतक कि देश भरमें स्वराज्य-प्राप्त प्रान्त वन जायें; हाँ भारत सरकार उनके छपर रहे और शासनमें हस्तक्षेपका अधिकार उसे रहे।" यश्चिप भारत सचिव लाई कू ने इस समाचारका खण्डन किया था, कांग्रेस वरावर विश्वास करती रही कि प्रान्तीय स्वराज्य आ रहा है। कांग्रेस पण्डालके वाहर वहें अक्षरोंमें कू, जार्ज पंचम और हाँडिजके नाम लिखे गये, जिससे यह बताया गया कि प्रान्तीय स्वराज्यका वादा इन महानुभावोंके कारण ही मिल सका। स्वयं अध्यक्ष्ते कहा—सज्ज्ञनों! इस लक्ष्य और कांग्रेसके लक्ष्यमें वड़ा साहस्य और समानता है। यह सही है कि लार्ड कू ने भारत सरकारके पत्रका महत्व कम करनेकी कोशिश की। लेकिन उनके सहायक श्री मोंटेगृने (जिनका हमने मारत आगमनपर स्वागत किया था, और जो उदारदलके उदीयमान नेता हैं) परवर्गके अन्तमें केम्ब्रिजमें जो भापण किया था, उसमें इस महान् पत्रके सिद्धान्तका प्रतिपादन ही किया गया है।" विलियम आर्थर जैसे अंग्रेजोंतकने कांग्रेस विचारोंकी विनयपूर्ण दीनताकी आलोचना की (१५ जनकरी सन् १९१३ के 'डेली न्यूज एण्ड लीडर' में)।

अध्याय १२

कान्तिकारियोंका क्रियाकलाप

कर्जनके प्रतिक्रियावादी शासन और बंगमंग व कांग्रेसकी वन्ध्या वैधानिक राजनीति ने सचेत नवयुवकों तथा कुछ समाचार-पत्रोंको निराश, विकल व आतुर वना दिया। कांग्रेस-की ब्रिटिश सरकारके पास भेजी जानेवाली वार्षिक प्रार्थनाओंसे उनका विश्वास उठ चुका था। वे कुछ करना चाहते थे ज़िसे ह्यू मके शब्दोंमें कहें ती-ऐसा कुछ करना चाहते थे, जिसका अर्थ हिंसा होता । विदेशी शिकञ्जेसे जन्मभूमिको स्वतन्त्र करनेकी प्रेरणा उन्हें इस वातसे भी मिली कि दो सालमें ही सन् १८५७के महान विद्रोहकी अर्द्शती होनेवाली थी। समाचारपत्र इस भावनाके अग्रदूत थे। जनताको विद्रोहके लिए प्रेरित करते हुए समाचार-पत्र, पुस्तिकाएँ एवं पर्चे वड़ी संख्यामें वाँटे गये। सन् १९०४ में हुआ यह श्रीगणेश निरीह और निर्दोष-सा ही था पर उसकी व्यापकता और तीव्रतासे अधिकारी परेशान हो उठे। रीसेने लिखा है- 'यह आन्दोलन "पूरे देशमें देशी भाषाओं के पत्रों द्वारा ऐसी सफलता के साथ फैलाया गया, जिससे ब्रिटेनकी चुनाव प्रचार एजेंसियाँ ईर्घ्या करने लगें।" खास जोर वायकाट आन्दोलन पर था । हर जगह जनतामें प्रचार किया गया कि अंग्रेज देशको वर्वाद कर रहे हैं और घूस ले रहे हैं। वहिन्कार आन्दोलनके दो नमूने यहाँ दे दें। "पूर्वी वंगालमें वकीलोंके पुस्तकालयों द्वारा एक गश्ती चिट्ठी प्रसारित करायी गयी, जिसमें अंग्रेजोंको झ्ट्रे, धोखेवाज कहा गया था जो हमारा जीवन वर्वाद कर रहे हैं, हमारे उद्योग वर्वाद कर रहे हैं और अपने यहाँका वना माल यहाँ भर रहे हैं, हमारे खेत छूट रहे हैं, हमें वीमारी, प्लेग और अकालके मुँहमें डाल रहे हैं, जो हमारा खून पी रहे हैं "क्या हम इसे और वरदास्त करेंगे ?' 'संजीवनो' नामक पत्र ने लिखा—'अरे भाई ! अंग्रेजी माल छूकर हम अपने हाथ गन्दे नहीं करेंगे। इसे अंग्रेजी गोदामोंमें पड़ा सड़ने दो और दीमकों व चूहोंका भोजन वनने दो।"

फिर जैसे जैसे विद्रोहकी पचासवीं वर्षगाँठ निकट आती गयी, आग्दोलन जोर पक-इता गया, अखवार अपने सम्पादकीय लेखोंका स्वर तेज करते गये। 'विहारी'के सम्पादकने विलिफिड ब्लण्टकी एक कविताकी चर्चा करते हुए लिखा कि भारत गुलाम हो गया है और स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका उपाय तलवार ही है, जो अन्तमें मियानसे निकालनी ही होगी। वम्बई हाईकोर्टने उन्हें दो सालकी सजा दी। इसके पहले उन्होंने फिरंगियोंके राजको 'पृथ्वीपर नरक' और अंग्रेजोंको नृशंसतामें नीरो, नादिरशाह, तैमूर लंग और खुद शैतानसे भी वदतर लिखा था। 'विहारी' के एकके बाद एक-तीन संपादकोंको सजा हुई। यह १९०६, १९०७ व १९०८ में हुआ। दि 'डेकन हेरल्ड' ने एक घोषणापत्र

१. जे. ही. रीस 'दि रीभल इण्डिया' पृष्ट १७१

२. वही पुस्तक, पृष्ठ १७४

३. वही पुस्तक, गृष्ठ १^९११-९२



'वन्देमातरम्' के अलीगढ़ स्थित संवाददाताको सात वर्षका कालापानी इसलिए हुआ कि उनकी भेजी एक खबर 'राजद्रोहात्मक' मानी गयी थी और उनपर 'राजद्रोहात्मक पर्चा' वॉटनेका अभियोग लगा था। वम्बईमें 'हिन्दू स्वराज्य', 'विहारी' व 'अरुणोदय' के सम्पादकों को भी कैदकी सजाएँ दी गयीं।

१९०७ के इन मामलोंमें दो विशिष्ट हैं। 'वन्देमातरम' के मुद्रक और सम्पादकीय विभागके सदस्य अरिवन्द घोषपर अगस्तमें राजद्रोहका मुकदमा चला। विषिनचन्द्र पालको सन्त्र गवाहकी हैसियतसे बुलाया गया। पर उन्होंने यह कहकर गवाही देनेसे इनकार कर दिया कि मेरी रायमें यह मुकदमा देशहितमें नहीं है। इसपर उन्हें छ महीनेकी कैदकी सजा दे दी गयी। लेकिन अरिवन्दके विरुद्ध राजद्रोहका अभियोग सावित न हो सका और उन्हें रिहा कर दिया गया। मुद्रकको तीन महीनेकी कैद मिली। दूसरा मामला 'सन्त्या'के सम्पादक ब्रह्मवान्धव उपाध्याय व युगान्तरके सम्पादक भूपेन्द्रनाथ दत्त का है। उपाध्यायने मुकदमेंकी मुनवाईमें भाग लेनेसे इनकार कर दिया और अपने लिखित वक्तव्यमें कह दिया—"में इस मुकदमेंमें भाग नहीं लेना चाहता क्योंकि में नहीं मानता कि ईश्वर हारा नियत स्वराज्य प्राप्तिके मिशनमें अपना ग्रन्छ योग देनेके लिए में किसी विदेशीके सामने उत्तरदायी हूँ — विशेषकर जब ये विदेशी हमारे शासक हों—और जिनका हित अनिवार्य रूपसे हमारे सच्चे राष्ट्रीय विकासमें वाधक हो।" उपाध्यायकी अस्पतालमें मृत्यु हो जानेके कारण उनका मुकदमा खत्म हो गया। दत्तको एक वर्षका कठोर कारावास मिला।

भारतमें चाल इस आतंकराजसे भारत सचिव मॉलें भी उद्दिग्न हो उठे। १४ जुलाई सन् १९०८ को उन्होंने मिण्टोको लिखा—मुझे स्वीकार करना पड़ता है कि राजद्रोह आदिके लिए जो भयंकर सजाएँ दी जा रही हैं उन्हें देखकर में त्रस्त और उद्दिग्न हो उठा हूँ। मैंने आज पढ़ा कि वम्बईमें पत्थर फेंकनेके लिए साल-साल भरकी सजा मिल रही है। यह तो सचमुच ही अत्याचार है। तिन्नेवली-त्तीकोरिनके दो न्यक्तियोंको जन्मभरके लिए कालेपानी और दस वर्षको जो सजाएँ मिली हैं, उनका समर्थन असम्भव है। ये सजाएँ वरकरार नहीं रह सकतीं। में किसी भी हालतमें ऐसे राक्षसपनका समर्थन नहीं कर सकता। में तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम इन गलतियों और खामियोंकी ओर ध्यान दो। ज्ञान्ति कायम रखना आवद्यक है, लेकिन अति दमनसे ज्ञान्ति स्वापित नहीं होती, वह ज्ञान्तिका रास्ता नहीं है, विक वमका रास्ता है।"

वीसवीं सदीके शुरूके सालोंमें भारतीय कान्तिकारियोंकी हलचलोंका कैन्द्र लन्दन रहा। क्यामजी कृष्ण वर्मा चुपचाप लन्दन चले गये थे और वहाँ कुछ दिनोंतक अज्ञातवास करनेके बाद उन्होंने १९०५ में इण्डिया होम रूल सोसायटी (भारत स्वराज्य संघ) की स्थापना की। इसका दफ्तर जिस इमारतमें रखा उसका नामकरण 'इण्डिया हाउस' (भारत भवन) किया गया। उन्होंने अपनी सोसायटीका मुखपत्र 'इण्डियन सोस्योलोजिस्ट' भी निकाला जो साप्ताहिक था। इसमें प्रकाशित घोषणांक अनुसार सोसायटीका उद्देश भारतके लिए स्वराज्य प्राप्त कराना और उसके लिए इंगलैण्डमें हर सम्भव उपाय द्वारा प्रचार करना था।

१. पृथ्वीशचन्द्र राय-'लाइफ एण्ड टाइम्स आव सी० आर० दास' पृष्ठ ५७

२. मॉर्ले 'रिकलेक्शंस' माग दो, पृष्ठ २६९-७०

द्यामजी कृष्ण एक निर्धन मंसाली परिवारमें ४ अक्तूबर सन् १८५७ को पैदा हुए थे। विद्यार्थीकालमें वे द्यानन्दके सहायकों के रूपमें आर्यसमाजकी ओरसे 'मापण-यात्राएँ' करते रहे। एक अंग्रेज अध्यापकने उन्हें १८७९ में इंगलैण्ड मेज दिया। वे केम्ब्रिज विश्वविद्यालयसे ग्रेजुएट वनकर वकालत करने भारत लीटे। संस्कृतके उन्हट विद्वान् होनेके नाते भारतसिवने उन्हें सन् १८८१ में विलिनके 'पूर्वी-प्राचीन-भाषा सम्मेलन' में भारतका प्रतिनिधित्व करने मेजा। वहाँसे लीटकर वे रतलाम, उदयपुर व ज्नागढ़में दीवान आदिके पर्दोपर रहे। ज्नागढ़से एक अंग्रेज अफसरने (जिसपर वर्माने अनुग्रह किया था) उन्हें निकलवा दिया। उनपर तिलककी राजनीतिका गहरा प्रभाव पड़ा था और तिलककी गिरपतारीके वाद वे स्थायी रूपसे लन्दन चले गये।

इण्डिया हाउसमें स्यामजी कृष्णने कुछ कान्तिकारियोंकी भरती की। इनमें प्रमुख थे विनायक दामोदर सावरकर। उनकी अवस्था उस समय केवल २२ वर्षकी थी। वे पहले कान्तिकारी थे जिन्हें कालेपानीकी सजा हुई थी। जिसे हम मोटे तौरपर 'राजनीतिक जीवन' कह सकते हैं, वह सावरकरने दस वर्षकी अवस्थामें ही ग्रुक्त कर दिया था। एक हिन्दू- मुस्लिम दंगेकी खबर सुनकर जिसमें हिन्दुऑपर काफी अत्याचार हुए थे, सावरकरका ख़्त खील उठा और उन्होंने बदला लेनेकी ठान् ली। अपने स्कूली साथियोंको लेकर उन्होंने गाँवकी मस्जिदपर हमला बोल दिया। इस घटनाका प्रभाव उनपर आजीवन बना रहा। १८९९में १६ वर्षकी अवस्थामें उन्होंने एक क्रान्तिकारी देशमक संघटन स्थापित किया। ग्रुक्तमें इनमें केवल तीन सदस्य थे, पर १९०० में 'मित्रमेला' के रूपमें यह संघटन खूब विकसित हो गया। ''नासिककी हर सार्वजनिक राजनीतिक संस्थामें मित्रमेलाका जोर हो गया और मेलाने धार्मिक उत्सर्वोंको राजनीतिक व राष्ट्रीय उत्सर्वोंमें परिवर्तित कर दिया। मेलाके कार्यक्लापसे जिला-अधिकारियोंको सोना दूमर हो गया।''

१९०१ में मित्रमेलाकी एक बैठकमें इस प्रस्तपर विचार हो रहा था कि महारानी विक्टोरियाकी मृत्युपर शोक और नये बादशाह एडवर्ड प्रति निष्ठा प्रकट की जाय या नहीं। कुछ सदस्य ढुलमुल यकीन हो रहे थे। तभी सावरकर उठकर बोले—"इंगलेण्डके महाराज और महारानी हमारे शत्रुओं के महाराज और महारानी हैं। उनमें निष्ठा प्रकट करना गुलामीकी शपथ लेना है।" सावरकरके जीवनी लेखक के अनुसार भारतमें विदेशी वस्त्रोंकी होली सबसे पहले १९०५ में सावरकरने ही आयोजित की। १९०४ में जब सावरकर कालेज में पढ़ रहे थे, मित्रमेला एक कान्तिकारी संघटन वन गया और उसका नाम 'अभिनय भारत' हो गया। इसी समय खबर मिली कि विलायत में पढ़नेके इच्छुक छात्रोंको स्थामजी कृष्णवर्मा छात्रवृत्ति दंगे। सावरकरने इसके लिए अर्जी दी और इसे पाकर ये जुन सन् १९०६ में लन्दन रवाना हो गये।

१९०५ के ग्रुहमें सावरकर महात्मा श्री अगम्य गुरु परमहंसके आन्दोलनमें गामिल हो गये थे। महात्मा सारे भारतमें निर्भाक रूपसे सरकारके विरुद्ध भाषण करते थे और कहते थे कि सरकारसे नहीं डरना चाहिये। "इस आन्दोलनके एक अंगके रूपमें पृनामें सन् १९०६

१. धनंजय कीर, 'सावरकर एण्ड हिज टाइम्स' पृष्ट ९

२. वही पुस्तक, पृष्ट ६०

में, कुछ छात्रोंने एक संस्था कायम की, सावरकरको उसका अध्यक्ष वनाया और उन्हें महात्मासे मिलने बुलाया।"

सावरकरके सुझावपर नौ सदस्योंकी एक समिति आन्दोलनके उद्देश्य पूरे करनेके लिए वनायी गयी। महात्माजीने राय दी कि संस्थाके लिए एक इक्त्री कोप खोला जाय; जब काफी पैसा इकट्ठा हो जाय तब महात्मा उसे खर्च करनेका ढंग वताते। पर सावरकरके लन्दन चले जानेके उपरान्त यह संस्था निष्क्रिय हो गयी।

लन्दनमें सावरकरने 'फी इण्डिया सोसायटी' (स्वतन्त्र भारत संव) स्थापित की । यह संख्या खुले रूपसे चलती थी और इसके द्वारा अभिनव भारतके लिए सदस्य छोटे जाते थे । इनमें मैडम कामा, सेनापित वापट, मदनलाल घींगरा, रिवशंकर शुक्ल, सिकन्दरहयात खाँ, भाईपरमानन्द, हरदयाल, हेमचन्द्रदास आदि भी थे । ज्ञानचन्द्र वर्मा इसके सेक्रेटरी थे । दादाभाई नौरोजीकी भूतपूर्व सचिव मैडम कामा पहली भारतीय थीं जिन्होंने १९०७ में जर्मनीमें एक सोशलिस्ट सम्मेलनमें भारतीय राष्ट्रीय झण्डा फहराया था । झण्डा फहराते हुए उन्होंने कहा — "यह भारतकी स्वतन्त्रताकी पताका है; देखिये, इसका जन्म हो चुका है; भारतीय नवयुवकोंके विलदानके रक्तसे यह पताका पित्र हो चुका है; में उपिश्यत सज्जनींसे अनुरोध करती हूँ कि वे खड़े होकर भारतीय स्वाधीनताके इस झण्डेको सलामी दें । दुनियाके स्वतन्त्रताधिय लोगोंसे में इस झण्डेके नामपर अपील करती हूँ कि वे मानवजातिके पचमांशको स्वतन्त्र करानेमें सहयोग दें ।" उपिश्यत लोगोंने खड़े होकर झण्डेको सलामी दी ।

'अभिनव भारत' का एक काम था क्रान्तिकारी साहित्य प्रकाशित करना और पिस्तौलें इकट्ठी कर भारत भेज देना। एक वैटकमें सेनापित वापट और हेमचन्द्रदासको वम वनाना सीखनेका काम सौंपा गया। ये दोनों पेरिसमें एक रूसी क्रान्तिकारीसे यह सीख आये और उससे वम वनानेकी एक पुस्तक भी खरीद लाये। वापट, दास और होती-लाल वर्मा इस पुस्तककी कई साइक्लोस्टाइल प्रतियाँ लेकर भारतके लिये रवाना हो गये। अभिनव भारतकी भारतीय व लन्दन शाखाओं में सम्पर्क स्थापित हो चुका था। सर वेलेण्टाइन शिरीलने तभी लन्दन टाइम्समें लिखा था—"दक्षिणमें ग्रप्त संस्थाओं का जाल सा विद्या है।" अभिनव भारतका अपना खुिक्या विभाग भी था। इसने वम्बईमें तिलककी विरम्तारीके सम्बन्धमें ब्रिटिश सरकारका एक सन्देश भी हस्तगत कर लिया था। लन्दन शाखा क्रान्तिकारी कामों के अतिरिक्त वैधानिक आन्दोलन भी करती थी। २० दिसन्वर सन् १९०८ को लन्दनमें एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। सम्मेलनने शीव लागू होनेवाले मिण्टो-मॉर्ले सुधारों को 'धोखा, निराशा और अपमान'का लोत वताया क्योंकि इनसे 'भारतमें साम्प्रदायिक तनाव' बढ़ता था। सम्मेलनके मुख्य प्रस्तावमें भारतके लिए पूर्ण राजनीतिक आजादीवाले स्वराज्यकी माँग की गयी।

विटिश समाचार-पत्र और राजनीतिज्ञ इंगलैण्ड खित भारतीयोंके कामोंसे चिन्तित हो रहे थे। दि स्टेण्डर्डने लिखा—"इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि हमारे विश्वविद्यालयोंमें जो कुशाग्रबुद्धि व मेधावी भारतीय छात्र वकालत पढ़ रहे हैं, उनमेंसे काफी भारतको नयी पीढ़ीको सशस्त्र विद्रोहकी भावनासे प्रेरित करनेमें लगे हैं।" ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इतने परेशान थे कि वम्बर्डके भूतपूर्व गवर्नर लार्ड लेमिंगटनके सभापतित्वमें उन्होंने एक सभा की जिसमें

१. महाराष्ट्र प्रकाशन संस्था 'सावरकर चरित्र', पृष्ठ ६७

कान्तिकारी भारतीयोंको 'सामाजिक' बनानेके प्रश्नपर विचार किया गया । सभाके एक वक्ता सर विलियम ली वानंरने भारतीय कान्तिकारी कुञ्जविहारी भट्टाचार्यके लिये 'गन्दा निगर' शब्दका प्रयोग किया । इस सम्बोधनसे वहाँ उपिक्षित भारतीय इतने कुपित हो गये कि 'संध्या' व 'युगान्तर'के भूतपूर्व सम्पादक वासुदेव भट्टाचार्यने उटकर सर विलियमके मुँहपर तमाचा मार दिया । वासुदेवपर मुकदमा चला और वीस रुपये जुर्मानेकी सजा हुई ।

भारत सचिव मार्लेने एक समिति नियुक्त की, जिसका काम था वे तरीके हुँदुना जिनसे भारतीय छात्र उन आन्दोलनकारियोंसे तचाये जा सकें जो नये छात्रोंकी प्रतीक्षामें रहते हैं, उन्हें ऐसे घर देते हैं जहाँका वातावरण ही ब्रिटिश सरकारके प्रति विद्रोहकी भावनाचे ओताशित रहता है। १९०७ के उत्तरार्धमें श्यामजो कृष्णवर्मा पेरिस चले गये और वहीं वस गये। पर 'इण्डियन सोशलीजिस्ट' लन्दनसे ही निकलता रहा। पत्रके दिसम्यरके एक अंकमें निकला कि—"लगता है कि भारतमें चलाये जानेवाले आन्दोलन अनिवार्यतः गुप्त आन्दोलन होंगे और अंग्रेज सरकारका दिमाग दुस्त करनेका उपाय रूसी तरीके इस्तेमाल करना ही है। यह रूसी तरीका तत्रतक लगातार और तीन रूपसे इस्तेमाल किया जाय जवतक अंग्रेज दमनका शिकंजा दीला न कर दें और हमारा देश छोड़कर भाग न जावें। इस आन्दोलनके नियम और ढंगके सम्बन्धमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, वे तो स्थानीय परिस्थितियाँ देखकर ही तय होंगे। लेकन आमर्तारपर यह कहा जा सकता है कि रूसी तरीके अंग्रेज अफसरोंकी जगह देशी अफसरोंसे शुरू किये जावें। रूसी तरीका वमवाजीका था। पत्र सरकारका कोपभाजन वन गया। मुद्रकको जलाई १९०९ में केंद्र हो गयी। दूसरेने मुद्रण शुरू किया और उसे भी सितम्बरमें केंद्र हो गयी। तव पत्र परिससे प्रकाशित होने लगा।

मई १९०८ में इण्डिया हाउसने ५७-५८ के विद्रोहकी जयन्ती मनाथी। निमन्त्रण-पत्र मेजे गये और इंगलेण्ड भरसे लगभग सो भारतीय छात्र इकट्ठे हुए। इन्हें दो दो पुस्तिकाएँ—'मेव वार्तिग' (गम्मीर चेतावनी) और 'ओह मार्टर्स' (हे शहीदो) दी गयीं और उन्हें अपने मित्रोंके पास भारत भेजनेको कहा गया। इनकी जो प्रतियाँ भारत आयीं उनमेंसे कुछ लंदनसे प्रकाशित दैनिक ''लण्डन डेली न्यूज' के पत्रोंमें लिपटी थीं, जिनसे पता लगता था कि वे लन्दनसे वितरित हुई हैं।''

जूत १९०८ में लन्दन विस्विवद्यालयके एक भारतीय छात्रने वम बनाने, उसमें इस्तेमाल होनेवाली सामग्री और वम प्रयोगके औचित्यपर भाषण किया। उसने श्रीताओं सहा—"जब आपमेंते कोई अपनी जानकी बाजी लगाकर वम प्रयोगके लिए तैयार हो तो वह मेरे पास आ जाय, में उसे पूरा तरीका बता हूँ गा।" १९०९ में सावरकर इण्टिया हाउसके नेता हो गये और रिववारकी बैठकों में उनकी पुस्तक "५७ का भारतीय स्वतन्त्रताका युद्ध—एक भारतीय राष्ट्रीवादी कृत' के अंद्रा पढ़नेकी परम्परा वन गर्या। उसी वर्ष 'इण्टिया हाउसके सदस्य लन्दनमें रिवाक्वर चलानेका अभ्यास करने लगे, और १ जुलाई १९०९ को इण्डिया हाउससे सम्बन्धित मदनलाल धींगरा नामक युवकने भारत सन्विदके राजनीतिक

1000

१. रीस 'दी रियल इण्डिया', पृष्ट १६७

२. सेडीशन कमेटी रिपोर्ट, पृष्ट ४

३. वही पुस्तक, पृष्ट ६

सहकारी कर्नल सर विलियम कर्जन वाइलीकी हत्या लेन्द्रनकी इम्पीरियल इंस्टीट्यूटमें हुई एक सभामें कर दी। "" धींगरा वंग-भंग करानेवाले लार्ड कर्जनको मारना चाहते थे पर वे असफल रहे।

धींगराके राजभक्त पिताने भारत सिचवको तार दिया कि में ऐसे पुत्रपर लिखत हूँ। सर मनचेरजी भौनागरी, आगा खाँ, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, विपिनचन्द्र पाल जैसे कुछ नरमदली भारतीयोंने एक सभा कर इस हत्याकी निन्दा की। सभाक्षे अन्तमें अध्यक्षने कहा—'यह सभा सर्वसम्मतिसे मदनलालजी धींगराकी निन्दा करती है।' लेकिन भीड़मेंसे एक आवाज उठी—'नहीं, सर्वसम्मतिसे नहीं।' अध्यक्षने क्रोधमें पूछा—'नहीं कौन कहता है! तुम्हारा नाम क्या है!'' उसी आवाजमें उत्तर आया—'भें हूँ। मेरा नाम सावरकर है।'' इसके बाद सभामें भय छा गया। भावनाके उद्देगमें एक अधगोरेने सावरकरपर अपट कर उनके माथेपर घूँसा मारा। सावरकरके खून बहने लगा।'' मदनलालको १७ अगस्त १९०९ को फाँसी दे दी गयी। आयरलैण्डके पत्रोंने धींगराके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए बड़ेन वड़े पचें बाँटे, उनमें एक था—'आयर्लेण्ड मदनलाल धींगराके प्रति श्रद्धा प्रकट करता है जिसने अपने देशके लिए अपनी जान दी।''

कुछ समयके लिए भारतीय छात्र बिटिश अधिकारियोंको काँटेकी तरह खटकने लगे। अपने लेखों व प्रचारके कारण वीरेन्द्रनाथ चहोपाच्याय व स्यामजी कृणवर्माकी डिगिरियाँ छिन गयों। वाहलीकी हत्याके बाद ब्रिटिश खुफिया पुलिस सावरकरके पीछे पड़ गयी। सावरकर लन्दनकी भारतीय कान्तिकारी संस्थाओंकी जान थे। वे एक जगहसे दूसरी जगह धूमते फिरते। यहाँतक कि उनका स्वास्थ्य खराय हो गया और मित्रोंके जोर डालनेपर जनवरी १९१० में वे पेरिस-चले गये। लेकिन १३ मार्च १९१० को वे फिर लन्दन वापस आ गये। विक्टोरिया स्टेशनपर जब वे ट्रेनसे उतर रहे थे, वम्बईसे तार हारा आये एक वारण्टपर वे गिरपतार कर लिये गये। १८८१ के भगोड़े अपराधी कान्तके अन्तर्गत यह वारण्ट निकला था। उनपर अभियोग थे—"मारतके सम्राटके विरुद्ध युद्ध छेड़ना या युद्ध छेड़नेमें मदद देना; ब्रिटिश भारतपरते या उसके कुछ भागसे सम्राटकी सार्वभीम सत्ता हटाने का पंड्यन्त्र करना; शस्त्रास्त्र इकट्ठे कर उन्हें वितरित करना और जैक्सनकी हत्यामें मदद देना; लन्दनमें शस्त्र इकट्ठे कर वहाँसे युद्ध छेड़ना; भारतमें जनवरीसे मार्च १९०६ तक और लन्दनमें १९०८ से १९०९ तक राजद्रोहात्मक भाषण करना। अर्थ उन्हें वापस भारत भेजनेकी आहा हो गयी।

उन्हें लेकर भारत आनेवाला वहाज जब मार्साइमें लंगर डाल रहा था, सावरकर सिपाहियोंको घोखा देकर भाग निकले और समुद्रमें कृद पड़े। सिपाही भी पीछे कृदे पर उन्हें पकड़ नहीं पाये। सावरकर मार्साइके ढाल बन्दरके किनारे लगे और घाटपर चढ़ गये। वह लगभग ५०० गज दौड़े, पर गाड़ी किरायेपर करनेके लिए उनके पास

१. सेंडीशन कमेटी रिपोर्ट, पृष्ठ ६

२. कीर, वही पुस्तक, पृष्ठ 🖣 ६

३. सावरकरकी 'छण्डनचे-त्रातमीपत्र', पृष्ठ १०८

४. गाई ए, एल्ड्रेंड 'दि हेरल्ड आव रिवोल्ट', पृष्ट १९९

पैसा नहीं था । वे विदेशमें थे और अन्तरराष्ट्रीय कान्नके अनुसार उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था । लेकिन जहाजके सिपाही उन्हें पकड़कर फिर जहाजपर ले गये ।

१५ सितम्बर १९१० को वम्बईकी डॉगरी जेलमें नासिक पडयन्त्र केस शुरू हुआ । उसमें सावरकरके अतिरिक्त ३६ अन्य अभियुक्त थे। मुकदमा ६८ दिन चला और २३ दिसम्बरको कैसला हो गया। सावरकरको आजन्म कालेपानी और सम्पत्ति जन्तीकी सजा मिली। कुछ अभियुक्त रिहा हो गये; कुछको छः महीनेसे लेकर १५ वर्षतककी केंद्र हुई। फैसलेमें कहा गया या—'अभिनव भारत हसी कान्तिकारी संस्थाओं के आधारपर बना संबटन था। जिन तरीकांसे लड़ाईकी तैयारी की जानेका मुझाव था, उनमें पड़ोसी देशों से हथियार खरीदकर इकट्ठा करना, मौका पाकर उन्हें इस्तेमाल करना, गुत्त रूपसे हथियार बनानेके लिए थोड़ी-योड़ी दूरपर छोटे छोटे कारखाने स्थापित करना और दूसरे देशों से चुपचाप हथियार खरीदकर चोरीसे उन्हें व्यापारी जहाजों में भारत मेजना शामिल था।'

जनवरी १९११ में सावरकर फिर अदालतके सामने पेश किये गये और उन्हें जैक्सनकी हत्यामें आजन्म कालेपानीकी सजा मिली | फ्रांसीसी पत्रोंमें सावरकरकी गैरकान्नी गिरफारी-का विरोध हुआ और फ्रांसकी सरकारने माँग की कि सावरकर फ्रांस वापस भेजे जात्र । पर अंग्रेज सरकार नहीं मानी | सावरकर ५० वर्षके लिए अण्डमान द्वीपसमृह भेजे गये । यहाँ सावरकरकी भेंट १८५७ के कुछ जीवित बचे हुए विद्रोहियोंसे हुई ।

भारतमें कितिकारियोंका काम विद्रोहके ५० वं साल १९०७ में सरगर्मीसे शुरू हुआ या। पहले वंगालकी घटनाओंका ही वर्णन किया जाय। १९०२ में गायकवाड़ कालेज-के उपाच्यक्ष अरिवन्द घोपके भाई वारीन्द्रकुमार घोप (उम्र २२ वर्ष) वड़ीदासे कलकत्ते आये। वारीन्द्रके पिता सरकारी नीकरीमें डाक्टर थे। वारीन्द्र इंगलेण्डमें पैदा हुए थे। भारतमें ब्रिटिश सरकारका तख्ता हिंसात्मक उपायींसे पलटनेके लिए आवश्यक कान्तिकारी आन्दोलनकी वंगालमें नींव डाल्टनेके लिए वे कलकत्ते आये थे। जो संस्थाएँ उस समय चल रही थीं, उन्होंके द्वारा उन्होंने कान्तिकारी विचारोंके प्रसारका प्रयत्न किया; पर उसके फलसे वे असन्तुष्ट रहे। तब वे दो सालतक जिले-जिलेका दीरा करते और स्वाधीनताके लिए प्रचार करते घृमे।

१९०७ के आरम्भमें उन्होंने १४, १५ नवयुवकोंको लेकर एक गुट स्वापित किया । इनमें उल्लासकर दत्त भी थे। उन्होंने रिवाल्कर और राहिष्णलें जमा की । उल्लासकरने विस्कोटक सामान बनाना सीखा। इस गुटका नाम रखा गया अनुशीलन समिति। इसका केन्द्र कलकत्ता था। बादमें ढाकामें भी एक शाखा खुली। ढाकाकी समितिका इतना विस्तार हुआ कि बंगालके गाँवों और कस्वोंमें इसकी पाँच सी शाखाएँ स्वापित हो गयी।

कान्तिकारी दलों में दाका समिति सदैव सबसे शक्तिशाली संघटन रही। इसकी नींव पुलिन विहारीदासने डाली थी। "दास और भूपेन्द्रचन्द्र राव दाकाके नेशनल रक्लमें अध्या-पक थे, यह स्कूल भरती और ट्रेनिंगका मुख्य केन्द्र था।" दूसरा केन्द्र था दाकेका सोनारंग नेशनल स्कूल। इसे मास्त्रनलाल सेनने चलाया था। दासके कालेपानी भेजे जानेके बाद सेन ही समितिके नेता हुए। "सिमिति सबसे अधिक मुसंघटित दाका और सैमनसिंहमें थी, पर घड़ उत्तर पश्चिममें दीनाजपुरसे लेकर दक्षिण पूर्वके चटगाँव और कृचिवहारसे दक्षिण पश्चिम में मिदनापुरतक सिक्रय थी।" वंगालके वाहर इसके सदस्य आसाम, विहार, पंजाव, मध्यप्रान्त, संयुक्तप्रान्त और पूनामें काम करते थे। वे सब एक दूसरेसे सम्पर्क रखते थे।

इन संस्थाओं के अलावा कम संघटित गुट थे जो इन्हीं सिद्धान्तोंपर उचित वाता-वरण पैदा करने, कान्तिकारियोंकी भरती और उनके कामोंमें योग देते रहते थे। गीत, साहित्य, समाचार पत्र, गुप्त सभाओं, संघटनों, उपदेशों आदि द्वारा जनमत प्रमुद्ध कर उचित वातावरण पैदा किया जानेवाला था "असन्तोष उत्पन्न किया जानेवाला था—असन्तोष जिसे इतिहासमें विद्रोह कहा जाता है।"

कान्तिकारियोंने कई पत्र शुरू किये पर उनका मुख्य पत्र युगान्तर ही था। अलीपुर षडयन्त्रकेसके फैसलेमें सेशन जजने लिखा था (और वादमें चीफ जिस्टसने इसे दोहराया था) कि ये पत्र 'विटिश जातिके प्रति घृणाकी कडु भावना, एक एक पंक्तिमें कान्तिकी प्रेरणा और ऐसी सामग्री छापते हैं जिससे इस वातका निर्देश मिलता है कि कान्ति किस तरह की जा सकती है।"

वंगालके क्रान्तिकारियोंने वहावियोंकी तरह आन्दोलनमें शिक्षितोंके साथ आम जनता को भी लानेके लिए धर्मका सहारा लिया। आम जनताके लिए धर्ममें वड़ो प्रेरणा थी। शक्ति को देवी कालीसे प्रेरणा ली गयी। मेजिनी और जेरीवाल्डीके उदाहरण सामने अवश्य थे, पर दुष्ट और पातकी—अंग्रेजी राज, के विरुद्ध धर्मग्रन्थोंकी वाणी और फतवोंने कान्तिकी चिनगारीको न्यापकता प्रदान कर दी। अंग्रेजोंके विरुद्ध युद्धको न्याय्य वताते हुए पुस्तिकाएँ निकाली गयीं। इन पुस्तकों में हथियार बनाने और रुपया इकट्ठा करनेके लिए राजनीतिक डकैतियाँ डालनेके सुझाव दिये जाते थे।

नवयुवकोंकी भरतीके छिए हाई स्कूल और किसी हदतक कालेज सबसे अच्छे केन्द्र माने जाते थे। क्रान्तिकारी साहित्य अध्यापकों व छात्रोंमें बाँटा जाता और उसके बाद लोगोंसे व्यक्तिगत रूपसे बात की जाती। मई १९०७ में बिद्रोह करनेकी जीतोड़ कोशिश हो रही थी, पर वह हुआ नहीं; सब जगह एक साथ आग नहीं भड़की। हाँ, जहाँ तहाँ हिंसा तमक विस्फोट जरूर हुए।

अक्तूबर १९०७ में लेपिटनेण्ट गवर्नरकी ट्रेन उड़ा देनेके दो षड्यन्त्रोंका पता पुलिसको लगा। दिसम्बरमें उनकी ट्रेन सचमुच ही, मिदनापुरके पास, एक बम द्वारा पटरीसे उतार दी गयी। वमके घड़ाकेसे पाँच फुट चौड़ा और पाँच फुट गहरा गड्ढा पटरीपर हो गया। पूर्वी वंगालके एक अंग्रेज अफसर एलनपर भी हमला किया गया। उसे सांघातिक चोट लगी, पर वह बच गया। ११ अप्रैल १९०८ को चन्द्रनगरके मेयरके घरपर बम फेका गया।

लेकिन २० अप्रैलको भीषण घटना हो गयी। मानिकतल्लेकी क्रान्तिकारी पार्टांके खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी नामक दो नवयुवकोंने मुजफ्फरपुरमें एक गाड़ीपर यह समझकर वम फेंका कि उसमें जिला जज किंग्सफर्ड वैठे हैं। किंग्सफर्डने कलकत्तेके चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटकी हैसियतसे युगान्तर, 'वन्देमातरम', सन्ध्या और बनशक्तिके संपादकोंको कड़ी सजाएँ दी थीं। सुशीलकुमार सेन नामक तरुण क्रान्तिकारीको १५ कोड़ोंकी सजा भी किंग्स-फर्डने दी थी। पर गाड़ीमें वे नहीं थे। उसमें भारतीय समर्थक अंग्रेज प्रिंगिल केनेडीकी पत्नी और पुत्री थीं जो मर गयों। वोस व चाकी पकड़ लिये गये। चाकी जिन्दा नहीं पकड़े

जा सके, उन्होंने पुलिसके हाथमें पहते ही गोली मार ली। बोस तवतक छात्र थे। उन्हें फाँसी दे दी गयी। उनका स्वागत शहीदकी तरह किया गया। "उनकी तसवीरकी वही विकी हुई और उप बंगाली युवक वे घोतियाँ पहनने लगे जिनकी किनारियों में खुदीराम बोस-का नाम बुना रहता था।" जिस दिन खुदीरामको फाँसी लगी "वंगालके बहुतने स्कूलोंके छात्र नंगे पैर, नंगे बदन और उपवास करते हुए स्कूल आये। जमालपुरमें यह प्रदर्शन एक सप्ताहतक रहा।"

मई व जून १९०८ में तिलक्षने अपने पत्र 'केसरी'में श्रीमती व कुमारी केनेडीकी हत्या, राजनीतिमें वसके प्रादुर्भाव आदिपर कई लेख लिखे। इनमेंने दो लेख राजदोहात्मक माने गये। उन्हें छः वर्षका कालापानी हुआ। जजने पैसलेमें लिखा कि लेखोंमें "राजदोह लवालव मरा है; उनमें हिंसाका उपदेश दिया गया है। उनमें हत्याका वर्णन प्रशंसात्मक भावसे किया गया है और भारतमें वसके प्रयोगका स्वागत किया गया है मानों वह भारतके भलेके लिए आया हो।"

केनेडी इत्याकाण्डके सुत्र हुँ दुते हुए पुलिसको क्रान्तिकारी तैयारियोंके कई और सुराग मिल गये। २ मईको कलकत्तेके कई घराँपर छापा मारकर पुलिसने यम, डाइना-माइट, कारत्स और पत्र पकड़े । मुरारीपृक्कर रोड (मानिकतला) के एक मकानमें वमके एक कारलानेका पता लगा । इसे कुछ बंगाली नवयुवकोंने 'सीधी काररवाई' कर सरकारको टप कर देनेके लिए बनाया था । उसी दिन समितिके मस्तिष्क वारोन्द्रकुमार घोप और उनके कुछ साथी पकड़े गये। अगले कुछ दिनोंमें कुछ और लोग भी गिरफ्तार हुए जिनमें अरविन्द धोप भी थे । मुजप्परपुर वसकाण्ड और मानिकतला वस कारखानेके सिलसिलेमें कुल ३६ व्यक्ति पकड़े गये । इनपर सम्राटके खिलाफ युद्ध छेड्ने और उसके लिए राख्न इकटठे करने व पडयन्त्र करनेका सुकदमा चला । यहाँ पांहिचेरीके सन्त अरविन्द घोपके सम्बन्धमें दें। शब्द अनुपयुक्त न होंगे । वे १८९० में सिविल सर्विसकी परीक्षामें वैठे थे और उन्होंने अच्छा स्थान भी प्राप्त किया था पर घुड्सवारी न जाननेके कारण वे लिये नहीं गये। वंगभंग आन्दोलनने उन्हें बंगालमें आकर्षित किया और वे १९०६ में 'वन्देमातरम'के सम्पादकीय विभागमें काम करने लगे । उन्होंने राजनीतिके प्रचारके लिए वेदान्तको साधन बनाया । "उनके लेखीं व भाषणींसे यह निष्कर्ष निकालनेका प्रयस्त किया गया कि उन्होंने इन नवसुवकोंके राजनीतिक ध्येयके रूपमें भारतके लिए पूर्ण स्वाधीनताका प्रचार किया और उन्होंने पर्यन्त्रकारियोंकी ल्ह्यप्रातिमं योग देनेके लिए ऐसा किया ।" अरियन्दका मुकदमा चित्तरंजनदास (सी.आर. दास) ने लड़ा । उन्होंने अदालतमें कहा — "अगर आप अरविन्दको पर्वन्त्रकारी मानते हैं तो पत्रोंके कुछ अंशोंको उनके जुर्मके सवृतके रूपमें पढ़ा जा सकता है। पर यदि आप इन प्रकार दोषी मानकर न चलें और उन्हें बेगुनाह मानकर चलें, जो कि आपका कर्तव्य है तो इन अंशोंका निरीह अर्थ भी होता है। विशेषकर तत्र उनके धार्मिक दृष्टिकोणका ध्यान रखा जाय।''' अरविन्द छूट गये, हेकिन उनके भाई वारीन्द्र और उल्हासकर दत्तको पाँसीकी सजा

१. शिरोल वही पुस्तक, पृष्ट ९७

२. 'वॅगाल 'प्हुकेशन रिपोर्ट' पृष्ठ ४०८-९

२. पृथ्वीशचन्द्र राय 'लाहुफ एण्ड टाह्म्स आव सी. आर. दास' पृष्ट ५९

४. वहीं पुस्तक पृष्ट ६६

हुई । वादमें हाइकोर्टने इसे घटाकर आजन्म कालापानी कर दिया । उपेन्द्रनाथ वनर्जांको मी आजन्म कालापानी हुआ । दूसरे अभियुक्तोंको भी विभिन्न सजाएँ मिलीं । इन्तुभूषणको दस वर्षकी कैद हुई । इस अलीपुर षड्यन्त्रकेसमें अधिकतर छात्र और अध्यापक हो पकड़े गये थे । वीरेन्द्रनाथ घोप कुल १७॥ साल के थे, नरेन्द्र बख्जी १८ साल के, विभूतिभूषण सरकार, २० वर्षके, उल्हासकारदत्त २२ के । हाईकोर्टने पैसलेमें कहा कि सम्राट्के विरुद्ध युद्ध छेड़नेके लिए हथियार, वारूद, कारत्स और राजद्रोहका साहित्य इकट्ठा किया गया था । अलीपुर पड्यन्त्रकेसकी जाखांके रूपमें ही नरेन्द्रनाथ गुसाई हत्याकाण्डका मुकदमा चला । गुसाई अलीपुर केसका अभियुक्त था और उसने पुलिसको अपने साथियोंके पते दे दिये थे । इस शपथ-खण्डनके लिए केसके दो अभियुक्तों—कन्हाईलाल दत्त व सत्येन्द्रनाथ वसुने तिकड़मसे हथियार जेलमें मँगाकर गुसाईकी हत्या कर दी । दत्त और वसु दोनोंको फाँसी हुई । जब इन दोनोंके शव सेण्ट्रलेजेलसे समशान ले जाये जा रहे थे, कालीवाटमें सड़कके दोनों ओर पचास हजार व्यक्ति खड़े थे । "इन राजनीतिक हत्याकारियोंकी शवयात्रापर हुए प्रदर्शनका सरकारपर इतना असर पड़ा कि उस दिनसे राजनीतिक विन्दयोंके फाँसी पानेपर उनकी अन्तिम किया जेलके वाहर करनेपर रोक लग गयी।"

कान्तिकारियों की गाथा से हटकर, यहाँ संक्षेप में अण्डमन जीवनकी एक झाँकी दे दी जाय। दो एक उदाहरण ही काफी होंगे। इन्दुभूपण राय वीमार पड़ गये थे। पर दवा देनेशी जगह जेलर वैरीने उन्हें तेल के कोल्हू में वैलकी जगह जोत दिया। उसी कोल्हू पर सावरकर काम कर रहे थे। "वड़े कष्ट और वड़ी कोशिशकों वाद इन्दुभूषण घूम रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ रहा था।" सावरकरने अपना हाल वताकर उन्हें सांत्वना देने और प्रसन्न चित्त करनेकी कोशिश की। पर कुछ हुआ नहीं। "दूसरे दिन इन्दुभूपणकों कष्टसे छुटकारा मिल गया। उनकी मृत्यु हो गयी।" उपेन्द्र वनर्जीको भी कोल्ह्रमें जोता गया। उनका सारा शरीर दुखता था और उनकी मानसिक स्थित ऐसी हो गयी थी कि समचेदनाका एक शब्द सुनकर वे रो पड़ते थे। उछासकर दत्तको विजलीसे पीड़ा पहुँचायी जाती थी। वे कराहते थे, आर्तनाद करते और ऐसे दर्द भरे स्वरमें चीखते थे कि सुनकर कलेजा मुँहको आता था। उन्हें पागलोंके अस्पतालमें भेजा गया। वहाँसे वे छूट गये।

९ नवम्बरको किसीने प्रफुछ चाकीकी मौतका वदला छेनेके लिए उन्हें गिरफ्तार करनेवाले पुलिसके थानेदारको मार डाला । वंगालके जीवनमें राजनीतिक हत्याएँ आयेदिनकी घटनाएँ वन गयी थीं। १० परवरी १९०९ को अलीपुर केसके सरकारी वकील को किसीने गोलीसे मार डाला। २४ जनवरीको अलीपुर केसकी अपीलमें मौजूद पुलिसके एक डिप्टी सुपरिटेण्डेण्टको हाईकोर्टसे निकलते वक्त मार डाला गया था। वंगालके लेपिट-नेण्ट गवर्नर सर एण्डू फ्रेजरकी जानपर ७ नवंबर १९०८ को असफल हमला हो चुका था। जिसे आक्रमणकारी समझा गया उसे १० वर्षकी कड़ी कैदकी सजा मिल चुकी थी। १९०८ में राजनीतिक डकैतियोंके अनेक मुकदमे चल रहे थे। इनमेंसे कुछमें हत्याएँ भी हुई थीं। मई १९०८ से अप्रैल १९०९ तक न जाने कितने वमकाण्ड हुए। नवम्बर १९०८ में तीन गैरसरकारी व्यक्ति मारे गये। यह माना गया कि यह भी क्रान्तिकारियोंका काम है।

१. वही पुस्तक, पृष्ठ ७२

२. कीर, 'सावरकर एण्ड हिन टाइम्स', पृष्ठ ११३

उसी समय पुलिसको बमोंके एक कारखानेका पता चला। "यह अफवाह भी फेल गयी कि वाइसरायको उनके दफ्तरमें ही मारनेका प्रयत्न किया जायगा। सरकारी माल-खानेसे राइफिलें ले जाकर गवनंमेण्ट हाउसमें मेजों, कुर्सियों वगैरहके नीचे छिपा दी गयों। वहाँके अमलेको मोकेपर क्या करना चाहिये, यह भी बता दिया गया।" पर हुआ कुछ नहीं।

इस परिस्थितिका सामना करनेके लिए दिसम्बर १९०८ में जान्ता_फोजदारी कान्नमें संशोधन करनेका बिल पास किया गया। अगली जनवरीमें ढाका अनुशीलन समिति, स्वदेशी बान्धव समिति, बती समिति, सुहृद समिति, साधना समिति आदि संबटन गैर कान्नी करार दिये गये।

१९०९ में दस ऐसी राजनीतिक डकैतियाँ पड़ों जिनमें अस्त्र-शस्त्रसे सुसिज्जत होकर २५-३० नवयुवक ढाटा या नकाव बाँधकर या नकली दाढ़ी लगाकर धावा बोलते थे। पुल्लिसने इस सिलसिलेमें अनेक घरोंकी तलाशी ली और आखिरकार एक घरसे भरे हुए ३५ रिवाल्वर व कारनूस वरामद किये। एक व्यक्तिके पास पोटेशियम साइनाइड नामक घातक विपकी टिकियाँ मिलीं जो सम्भवतः आवश्यकता पड़नेपर आत्महत्या करनेके लिए तैयार की गयी थीं।

यहाँ एक डकैतीका वर्णन कर दिया जाय । ११ अक्नूबरको सात आठ नवयुवक ढाकेमें रेलके एक डिक्वेमें चढ़ आये । उस डिक्वेमें तीन व्यक्ति सात थेलों में २३०००) लिये बैठे थे । दो पर गोली चली—उनमेंसे एक मर गया । तीसरेको छुरा लगा । नवयुवकों में थेले डिक्वेके बाहर फेंक दिये और खुद कृदकर भाग गये । बादमें लगभग आधा रुपया मिल गया पर नवयुवकों मेंसे एकको छोड़कर बाकी हाथ नहीं लगे । इस एकको आजन्म कालेपानीकी सजा मिली । नंगला (जैसोर) की एक डकैतीमें १४ व्यक्तियोंपर सम्राट के विरुद्ध लड़नेके पड्यन्त्रका मुकदमा चला और स्वको तीनसे लेकर सात सालतकका कालापानी मिला । १९१० में दो पड्यन्त्र केस चले जिनमें ९० व्यक्तियोंपर सम्राटके विरुद्ध लड़नेके अभियोग लगे । ये हवड़ा और ढाका पड्यन्त्र केस थे । पहलेमें ५० अभियुक्त थे पर छ को डकैतियों में अलगसे सजा हो गयी थी इसलिए मुकदमा ४४ पर चला । सात मुकदमें के दौरानमें छोड़ दिये गये । मुकदमा बहुत दिनोंतक चला पर अन्तमें सिर्फ छ को सजा हुई क्योंकि अदालतने दो मुखविरोंके वयानोंको अविश्वसनीय माना ।

पर दाका पड़यन्त्र केसमें कई वातोंका पता चला । जुलाई १९१० में ४८ व्यक्तियों पर डकैतियाँ डालने और सम्राटके विरुद्ध लड़नेके अभियोगमें मुकदमा चला । इस गुटके नेता पुलिनविहारी दास थे । ये लोग ढाका अनुशीलनसमितिके सदस्य थे और दो शप्यों हारा गोपनीयताका बचन दे चुके थे । एक शप्य द्वारा सदस्य संकल्प करते थे कि वे समितिके कभी पृथक न होंगे, उसके हितोंकी रक्षा करेंगे और अपना चरित्र कलंकहोन रखेंगे समितिके अधिकारियोंके आदेशोंका निष्टाके साथ पालन करेंगे, व्यायाम व कवायदमें लगनते भाग लेंगे, आत्मरक्षाकी कला हर उस व्यक्तिसे छिपायेंगे जो समितिका सदस्य नहीं है और देश व अन्ततः विश्वके कल्याणके लिए काम करेंगे । दूसरी शप्यमें सदस्य योपणा करते थे कि वे समितिकी आंतरिक वातें किसीको नहीं वतायेंगे । फैसलेमें जिस्टिस मुखर्जीन लिखा या—

१. मेरी मिण्टो, वही पुस्तक पृष्ठ २५८

"दलकी अन्तिम श्रापथ लेनेवाला परिचालकके आदेश (विना कोई सवाल पृष्ठे) पालन करने, परिचालकको वरावर अपना पता देते रहने, समितिके विरुद्ध पड्यन्त्रोंका पता दलके नेताको देने और उनके आदेशपर उन्हें विफल करने, नेताके आदेशपर कर्तन्यस्थानपर पहुँ-चने, किसी कामको हेथ न समझने, संयम और त्यागकी भावना पैदा करने और आदेशोंको गुप्त रखनेका वचन देता था।" सदस्य सम्बन्धियों और मित्रोंको नेताकी अनुमित विना पत्र भी नहीं लिख सकते थे। सदस्योंके पास आनेवाले और सदस्यों द्वारा लिखे गये पत्र नेताको दिखाने पड़ते थे। सदस्य अपने परिवार व मित्रोंसे अल्पा रहनेको वाध्य थे और यदि उन्हें कहीं से रुपया मिल जाता तो वह समितिकी सम्पत्ति माना जाता।" यह शपथ काली माँके समक्ष ली जाती थो। विशेष शपथमें कहा जाता था—"मैं ईश्वर, अगिन, माँ, गुरु और नेताको साक्षी कर शपथ लेता हूँ कि मैं अपना जीवन संकटमें डालकर कैन्द्रका सब काम कहँगा। यदि मैं शपथ पालनमें असफल होऊँ तो ब्राह्मण, माँ और हर देशके महान देश-मक्तोंका शाप मुझे तत्काल नष्ट कर दे।"

समितिका अपना सुसंघटित कार्यालय या जिसमें सदस्योंके विगत इतिहासतक के रिजस्टर रहते थे। प्रान्तीय संघटनके अधोन जिला, नगर और ग्राम समितियाँ काम करती थीं। सिमिति और सदस्योंके व्यवहार तथा कार्यके लिए नियम वने थे। अवज्ञाका दण्ड मृत्यु था जो कई वार दिया भी गया था। सिमितिक निरीक्षक गाँवोंका विवरण तैयार करते थे, जिसके लिए छपे हुए फार्म थे। इन फार्मोपर सूचना संग्रहके लिए २१ वातें छपी थीं। सिमितिकी अपनी छपी हुई एक कार्यतालिका भी थी। हर गाँवके विवरणके साथ उस गाँवका नक्या रहता था जिसमें सड़कें, निदयाँ, नहरं, मकान, वाग आदि वने रहते थे। इससे पता चलता है कि सिमितिका काम कितनी सूक्मतासे होता था। इस सबका उद्देश्य यह या कि पूरे वंगालको क्षेत्रोंमें बाँट दिया जाय और हर महत्वपूर्ण जगहपर सिमितिकी शाखा हो। कान्तिक लिए धन एकत्र करना था। लेकिन नियमानुसार, डकैतियोंको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। नियम १० के अनुसार ''हिंसात्मक उपायोंसे धनसंग्रह निषद्ध है।'' नियम ११ के अनुसार आयका मुख्य साधन चन्दा था। कसी क्रान्तिक ढंग और तरीकोंका अध्ययन किया जाता था और उन्हें अपनाया जाता था। गोपनीय पत्रादिके लिए संकेत भाषाका प्रयोग होता था। ''दाका अनुज्ञीलनसमितिके उदाहरण और उपदेशके फलस्करप अगले दस वर्षमें अनेकों हत्याएँ, डकैतियाँ व राजनीतिक अपराध हुए।''

ढाका षड्यन्त्र केसमें १५ व्यक्तियोंको दोसे सात सालतककी कड़ी कैदकी सजाएँ मिलीं।

लम्वे मुकदमों और कड़ी सजाओं के वावजूद कान्तिकारियों के कामों में शिथिलता नहीं आयी । हर तलाशी में राजद्रोहका साहित्य मिलता । फरवरी १९१० में एक और प्रेस सम्बन्धी कानून 'भारतीय प्रेस एक्ट' वना । इस कानूनसे सरकारको हर किसी छापेखानेसे जमानत माँगनेका अधिकार मिल गया । "इस कानूनने राजनीतिक साहित्यका प्रकाशन गुप्त छापेखानों पहुँचा दिया।"

१९११ में क्रान्तिकारी ढंगकी १८ घटनाएँ हुईं। २१ जनवरीको सोनारांग नेशनल स्कूल (ढाका) के छात्रों व अध्यापकोंने एक डाकियेसे रुपयोंका थैला छीन लिया। १४ छात्र व अध्यापक गिरफ्तार हुए; सातको कैद या जुर्मानोंकी सजाएँ हुईं। ११ जुलाईको सोना- रांगमें ही पुलिसके तीन मेदियोंका करल कर दिया गया। इनमेंने एकने डाकियेवाले मामलेंमें पुलिसकी मदद की थी। सोनारांग स्कूल १९०८ में स्थापित हुआ या और इसके पाठ्यक्रममें व्यायाम, लाठी भाँजना, बढ़ईगीरी व बुहारगीरी अनिवार्य विषय थे। १९११ में जो पाँच व्यक्ति मारे गये उनमें तीन सिपाइी थे जो राजनीतिक पृछताछ किया करते थे, एक सब्त पत्र का गवाह था और एक तिन्नेरवेलीका कलक्टर एस था। र मार्चको काउले नामक अंग्रेजकी मोटरपर १६ वर्षके एक वालकने वम फंका। यह वम जो फूटा नहीं, असलमें कलकक्तेकी खुफिया पुलिसके अफसर डेनहमके लिए था।

१९१२ में डकेतियों व हत्याओंकी तथा पुलिसद्वारा गोली-वारुद वरामद करनेकी घटनाओंकी भरमार रही। एक मजिस्ट्रेटका पुत्र गिरीन्द्रमोहन दास शहतोंकी वरामदर्गाके समय गिरफ्तर हुआ। गिरीन्द्रके पास एक वक्समें हथियार और कान्तिकारियोंके कागजपत्र वरामद हुए । उसके पिताने सन्दृक खोलकर उसका सामान पुलिसको देनेको कहा था। गिरीन्द्रको डेढ़ सालकी कड़ी केंद्र हुई। १३ दिसम्बरको पुलिसके एक मेदियेपर वर्ग पंका गया। "चन्द्रनगरमें ऐसे वम वनते थे और क्रान्तिकारियों द्वारा सारे देशमें बाँटे जाते थे; वम उस मेदियेके वरमें उस कमरेमें फूटा जहाँ वह आम तौरपर सोया करता था। दीवालका एक हिस्सा उड़ गया पर मेदिया वच गया।" उसी महीने वाइसराय लार्ड शांडजके नयी राजधानी दिल्लीमें प्रवेशके समय उनपर एक वम फेंका गया जिससे वे बुरो तरह धायल हो गये और उनका एक कर्मचारी मर गया। वम फेंकनेवालेका पता नहीं चला। वादमें साल्स हुआ कि रासविहारी वसुने वह वम फेंका था।

२९ सितम्बर १९१३ को कलकत्तेके कालंज स्नवायरमें झीलके किनारे हैंड कास्टेबिल हिरिपदरेवको तीन नीजवानोंने गोलीसे मार डाला । आक्रमणकारी भीड़में खो गये । कोई गिरपतारी नहीं हुई, कोई सुराग नहीं मिला । देवको कान्तिकारियोंकी एक द्याखाका पता लग गया था, इसलिए उसे खत्म कर दिया गया । अगले दिन द्यामको मेमनसिंहमें पुलिसके एक इंस्पेक्टरको बमसे मार डाला गया । इस इंस्पेक्टरने ढाका समितिका पता लगानेकी बहुत कोशिश की थो । आई. सी. एस.के गीर्डनको मार डालनेकी योजना भी बनायी गयी—पर बमके एकाएक फूट जानेके उसे ले जानेवाला ही मर गया । 'पिकरिक एसिड' का बना एक घातक बम रानीगंजके थानेमें फेंका गया पर वह फटा नहीं।

१९१३ में दो महत्वपूर्ण मुकदमे चले—वारीसाल पडरंत्र केस और वारोगाल पड्यन्त्र पूरक केस । ३७ व्यक्तियाँपर राजद्रोह और डाके डालनेका अभियोग चलाया गया । इनमेंसे अधिकतर लोग वारीसाल अनुशीलन समितिके सदस्य थे । ढाका सांगितिकी शाला होनेके वावजद्र इसका अपना मुद्रद संघटन था । यह पूर्वी वंगालमें जिले जिले में शालाएँ स्थापित कर रही थी । "संघटन पूरा और मुख्यबस्थित था । 'सिद्रान्त'का प्रचार छात्रोंमें जोरंगे होना था । सदस्य घीरे-घीरे शपयें लेकर अंतरंग गोष्टीमें आते थे । सांगितिके अलग-अलग विभाग थे, जैसे शख विभाग, कर्म विभाग, हिंमा, संघटन, आम विभाग आदि ।'' जिला संघटन योजनाके अंतर्गत सिद्रान्तमें दीक्षित अध्यापकोंके देश भरमें पेलने और शिक्षा संस्थाओंसे छाँटकर छात्र भरती करनेकी वात थी । वारीसाल पट्यन्त्र केममें मभी अभियुक्त नौजवान थे; उनकी उम्रों १९ से २९ सालतक थीं । १२ व्यक्तियोंको दो से बारह गालतककी कड़ी कैदकी सजाएँ मिलीं । नवम्बर १९१२ में कलकत्तेके राजावाजार मुहल्डेमें पुलिसने एक

घरपर छापा मारकर क्रान्तिकारी साहित्य और सिगरेटके टीनोंमें बनाये जाने वाले वम बरामद किये । उस घरमें सोये हुए चार व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये; बादमें दो व्यक्ति और गिर-फ्तार हुए । उस घरमें जो साहित्य मिला उसमें 'साहसी देशमक्तों द्वारा रक्तपात व हत्याओं के रास्ते भारतको स्वतन्त्रता दिलानेका प्रचार था । छहों व्यक्तियोंको सजा हो गयी।

अगस्त १९१४ में कलकत्ते वन्दूक वनाने एक कारखाने—रोडा एण्ड कम्पनीका एक वाचू ५० मौजर पिस्तौलों और ४६००० कारत् सोंक एक वक्सके साथ गायन हो गया। वादमें यह सामान विभिन्न क्रान्तिकारी गोष्ठियों में वँटा। पुलिसके अनुसार अगस्तके वाद हुए डाके और हत्याको ५४ घटनाओं में मौजर पिस्तौलों का प्रयोग हुआ। जूनमें एक मेदियेको चटगाँ वमें बीच याजारमें गोली मार दी गयी। अगले महीने एक मेदियेको ढाके में गोली मार दी गयी। ट्रामसे उतरते हुए एक वड़े तिराहेपर कुछ नौजवानों ने खुफिया पुलिसके एक इंस्पेन्टरको मार डाला। तिराहेकी भीड़ में खड़े कुछ पुलिसवालों ने इन नवयुवकों का पीछा किया। इन पीछा करनेवालों में भी एक मार गिराया गया। पुलिसके एक डिप्टी सुपरिण्टें डेंटक भितर और वाहर दो वम फूटे। एक हेट कांस्टेवल मर गया; दो सिपाही व सुपरिण्टें डेंटका एक रिक्तेदार घायल हुआ पर वह खुद वच गया। किन्तु उसपर हमले जारी रहे और १९१६ में वह दिनदहाड़े मार डाला गया। १९१४ में एक हत्या और १४ डाकों की रिपोर्ट पुलिसमें हुई।

१९१५ से १९१७ तक पुलिसवालोंको हत्याओं और डाकोंमें बहुत वृद्धि हुई। दर्जनों क्रान्तिकारी कैद या फाँसी पा गये। जिनके घर डाके पड़ते थे, कभी-कभी उन लोगोंको पत्र मिलते कि आजादी मिलनेके वाद रुपया लौटा दिया जायगा। इस तरहका एक पत्र 'संयुक्त भारतके स्वाधीन राज्यकी वंगाल शाखा'के छपे फार्मपर एक सर्राफको मिला, जिससे ९८९१) छीने गये थे। सर्राफके यहाँ जो गहने वन्धक रखे थे, उन्हें हाय नहीं लगाया गया किन्तु क्रान्तिकारियोंको बादमें सूचना मिली कि दो आभूषण वन्धक थे, जो लूटमें आ गये हैं। सर्राफको फीरन पत्र लिखा गया कि ये दोनों आभूषण उसे शीघ वापस मिल जावँगे।

क्रान्तिकारी दूसरे प्रान्तोंमें भी सिक्रय थे, पर उनका वहाँ उतना जोर नहीं था जितना वंगालमें।

पंजाव

पंजावमें ब्रिटिश भक्तिकी परम्परा थी। '५७ के विद्रोहमें पंजावने अंग्रेजोंका साथ विया था और उन्हें फिरसे भारतपर आधिपत्य जमानेमें सहायता दी थी। ब्रिटेनकी साम्राज्य विस्तारकी लड़ाइयोंमें पंजाव अपने वेटोंको लड़ने भेजता रहा। १९०७ में यह भक्ति परम्परा कुछ डाँवाडोल-सी हो उठी और अधिकारियोंको चिन्ता होने लगी। कुछ छिट-फुट असफल कोशिशें फौजमें बगावत पैदा करनेके लिए की गयी थीं। ये विद्रोहकी आम भावनाका वातावरण पैदा करनेकी योजनाका अंग थीं। ५ मार्च १९०७ को लार्ड मिण्टोने भारत सचिवको पत्र लिखा कि "राजद्रोहियोंका प्रभाव निस्सन्देह वढ़ रहा है और मुझे डर भारत सचिवको पत्र लिखा कि "राजद्रोहियोंका प्रभाव निस्सन्देह वढ़ रहा है और मुझे डर भम्बोधन करते हुए एक पर्चा वाँटनेकी खबर मैंने आज सुनी। इस पर्चेमें बताया गया है कि सम्बोधन करते हुए एक पर्चा वाँटनेकी खबर मैंने आज सुनी। इस पर्चेमें बताया गया है कि अंग्रेजी राज उखाड़ फॅकना कितना आसान है। देशी फौजपर कुप्रभाव डालनेकी चेष्टाकी

यह पहली साधिकार सूचना मुझे मिली है। यह पर्चा कुछ ऐसे देशी लोगोंका भेजा हुआ है जो अब अमेरिकाम हैं। 1981

अप्रैलमें अंग्रेज विरोधी उत्तेजना इतनी वहीं कि अधिकारियोंको उन ५७ की ५० वीं वर्षगाँठपर विद्रोहकी पुनरावृत्तिकी आशंका होने लगी । शहरों और कस्वोंमं-विशेषकर लाहोर, अमृतसर, रावलिंग्डी, फीरोजपुर व मुलतानमें अनेक सभाएँ हुई। वकीलों, अध्यापकों और दूसरे शिक्षित वर्गोंसे वक्ता अपने आप पैदा होने लगे और खुढे आम, निडर होकर अपनी भावनाओंको व्यक्त करने छगे । इसके लिए ये जेल भी गये। सैकड़ों लोग पकड़े गये। वाइसरायने भारत सचिवको तार दिया जिसमें परिस्थितिका वर्णन इस प्रकार किया गया था-तीन दिन पहले मुझे इयटसन (पंजाबके गवर्नर) से पंजाबकी वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिके सम्बन्धमें एक आवस्यक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट मिली । " " उनके वर्णनसे आशंका उत्पन्न होती है । चारों तरफ उप्रदर्श लोग खुलेआम बरावर राजद्रोहका प्रचार कर रहे हैं—समाचारपर्शेमें भी और वडी वडी सार्वजिनिक सभाओंमें भी।"राजद्रोहके इस आन्दोलनके दो रूप हैं। लाहीर अमृतसर, पिण्डी, फीरोजपुर, मुलतान व दूसरे शहरोंमें "ने खुलेआम ऊँचे अफसरोंकी हत्याका मुझाव दिया है और उसने व दूसरोंने जनतासे विद्रोह कर अंग्रेजॉपर हमला वोल देने और आजाद हो जानेकी सलाह दी है। देहातों में किसानों व छोटे जमींदारोंपर प्रभाव डालनेकी वाकायदा कोशिय हो रही है; और इन्हीं लोगोंमेंसे फीजके सिपाही मिलते हैं। विदीव ध्यान सिखों और पंशन-यापता फीजियोंपर दिया जा रहा है। सिखोंके गाँवोंमें बगावतके पर्चे वॅट रहे हैं; और फिरोजपुरमें एक सार्वजनिक स्मामें सिख रेजिमेण्टको बुलाया गया था, सैंकड़ों मीज़्द्र भी थे जब खुळेआम बगावतका प्रचार किया गया। सिखोंसे कहा जा रहा है कि उन्होंने गदरमें हमारी मदद की और अब हम उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि आजादीकी लड़ाईमें देशके साथ दगा करनेका यही नतीजा उन्हें मिल रहा है। कहा जा रहा है कि हम कपास और गन्नेके उद्योगोंको कुचल देना चाहते हैं, कहा जा रहा है कि हमने जनताका रुपया लेकर उसे कागज थमा दिया है। गाँववालों से पूछा जाता है कि हमारे चले जाने के बाद उन नोटों को कीन भुनायगा ? लीगों से कहा जाता है कि वे लगान, सिचाई आदिके कर सरकारको न दें, जब सरकारी अफसर दौरेपर आयें तो उन्हें रखद, गाड़ी आदि न दें। देशद्रोही कहकर देशी विपाहियों च पुलिसवालोंकी खिल्ली उड़ायी जाती है और उनसे सरकारी नीकरी छोड़नेकी क्समें ली जाती हैं।"

वाइसरायने लिखा कि यह प्रचार आर्य समाजकी एक गुप्त समिति द्वारा किया जा रहा है; समाज धार्मिक संखा है पर "पंजावमें उसमें प्रवल राजनीतिक प्रवृत्ति" भी है। उनका खयाल था कि इस पूरे आन्दोलनका केन्द्र और नेतृत्व लाजपतरायमें निहित है और उनका प्रमुख अनुचर अजितिसिंह है जो राजदोह फैलाता धूमता है। "अजिनिसंह पहले एक स्कूलमें मास्टर था और पार साल कथित रुखी जास्म लेक्टिकने उसे नीकर रखा था।"

s. मेरी मिण्टा, 'इण्डिया, मिण्टो एण्ड मॉलें' पृष्ट 1२२

२. मेरी मिण्टो, वहीं पुस्तक पृष्ट १२४-२५

मेरी मिण्टो, वही पुरंतक पृष्ट १२५

९ मईको लाजपतराय गिरफ्तार कर लिये गये, और उनके कुछ दिन बाद अजित सिंह भी पकड़ लिये गये। दोनों माण्डले भेज दिये गये और हालां कि वे एक ही घरमें बन्द थे, उन्हें एक दूसरेके वारेमें मालूम न था।

देशमें उस समय जो वातावरण था, वह तो था ही, पंजावमें खास तौरपर उत्तेजनाका कारण पंजावमें बस्ती वसानेका विल और वहाँ कई जगह फैली प्लेगकी रोकथाममें अफसरों की ज्यादती थी। यह विल चनाव नहरके इलाकेमें भूमि प्रवन्धमें परिवर्तन करनेके लिए था। साथ ही वरी दुआवेमें सिंचाईकी दर वढ़ानेकी भी वात थी। हालां कि वाइसरायकी अस्वी-कृतिके कारण विल पास नहीं हुआ, देहाती लोगोंने सरकारके विरुद्ध वैर-भाव नहीं छोड़ा। इन दोनों इलाकोंके गाँवोंमें सार्वजनिक सभाएँ कर ब्रिटिश विरोधी भावना फैलायी गयी। एक अखवारके मालिक और सम्पादकको सजा देनेपर दंगा हो गया। दो जगह अंग्रेजोंका अपमान किया गया। उत्तरी पित्चमी रेलवेके उस हिस्सेमें जो चनाव नहरके इलाकेमें था, नीचेके अमलेने इड़ताल कर दी। लाहौरमें ब्रिटिश विरोधी प्रचार उग्र हो उटा और गम्भीर अशान्तिकी स्थिति पैदा हो गयी।

लाजपतराय और अजितसिंह छः महीनेके बाद छोड़ दिये गये। अजितसिंह ईरान निकल गये। उनके भाई और लालचन्दं फलक नामक एक व्यक्ति अभक्ति प्रचारके अभियोग में जेल भेज दिये गये।

लेकिन पंजावमें आतंकवादी काररवाई १९१३ में शुरू हुई। १७ मईको लाहौरके लार स गार्डनके रास्तेमें एक वम रख दिया गया। इरादा उधरसे गुजरनेवाले अंग्रेजोंको मारने का था पर एक भारतीय अरदलीकी साइकिलके नीचे वम आ गया और अरदली मर गया। इस तथा कुछ अन्य घटनाओंके कारण कुछ लोगों पर लम्बा मुकदमा चला और अमीरचन्द, अवधिवहारी, वालमुकुन्द व वसन्तकुमार विस्वासको फाँसी दे दी गयी।

वम्यई

वम्बईमें पहले १८९७ में राजनीतिक हत्वाएँ हुई थीं, वहाँ क्रान्तिकारी आन्दोलनका श्रीगणेश १९०९ में 'लघु अभिनव भारत मेला' नामक पुस्तक में कुछ विद्रोही कविताएँ छपने छे हुई थीं और उन्हें इनके लिए आजन्म कालेपानीकी छजा हुई। हाईकोर्टने सजा वहाल रखते हुए कहा—''लेखकका मुख्य उद्देश्य शिवाजी जैसे योद्वाओं और हिन्दुओं के कुछ देवताओं के नाममें वर्तमान सरकारके विरुद्ध लड़ाईका प्रचार करना है। ये नाम इस असली बातके कहनेका वहाना हैं कि 'तलवार सम्हालों और इस सरकारको नष्ट कर दो क्यों कि यह विदेशी और अत्याचारी है।' लेखकका उद्देश्य और इरादा जाननेके लिए भगवद्गीता से लिये गये विचारों और भावनाओं को व्याख्यामें ले आना अनावस्यक है।''

लेकिन गणेश आतंकवादी आन्दोलनके संघटनमें लगे थे। उनके भाई विनायक सावरकरने फरवरी १९०९ में पेरिससे २० ऑटोमेटिक पिस्तौलें और उनके कारत्स इस्तगत किये थे। यह सामान "इण्डिया हाउसके रसोइये चतुर्भुज अमीनके एक वक्सके नकलो पेंदेमें छिपा हुआ आ रहा था।" अमीन गणेशको गिरफ्तारीके एक हफ्ते वाद ६ मार्चको वम्बई पहुँचे। गणेशको मालूम था कि सामान आ रहा है और अपनी गिरफ्तारीके दो चार दिन पहले अपने एक दोस्तसे इसका जिक्न भी किया था। पिस्तौलोंके आनेके चार दिन पहले

गणेशके मकानकी तलाशी ली गयी और उनके कागजोंमें अंग्रेजीमें ६० पत्रोंमें टाइप की हुई वम बनानेकी किया बतानेवाली किताब मिली । ऐसी ही किताब कलकत्तेके मानिकतला मुहत्लेमें मिली थी; पर गणेशकी प्रति अधिक पूर्ण थी । इसमें बमों, मुरंगों और इमारतोंके ४५ नक्शे भी थे ।

दिसम्बर १९०९ में गणेशक साथियोंने नासिकके जिला मजिस्ट्रेट जेन्सनको इत्याकी योजना बनायी । जेन्सनने ही गणेशपर मुकदमा चलाया था । यह योजना औरंगायादके एक नीजवानने पूरी की और जेन्सन अपने सम्मानमें मिले एक विदा भोजमें गोलीते गार डाले गये । जिस पिस्तौलसे जेन्सन मारे गये, पुलिसने उसे वही ब्राउनिंग औटोमेटिक बताया जो विनायक सावरकरने लन्दनसे भेजा था । सात व्यक्ति—सातों चित्पावन ब्राह्मण थे—मुकदमें में कैसे और तीनको फाँसी दे दी गयी । जेन्सनकी इत्याके बाद सरकार सिक्य हुई । कई तलाशियाँ हुई; कई लोग गिरफ्तार हुए; नासिक पद्यन्त्रकेस चला । ३८ व्यक्तियोंपर, उनमें से एकको छोड़कर शेप समी ब्राह्मण, अधिकतर चित्पावन ब्राह्मण थे, मुकदमा चला । २७ को विभिन्न अविधिनों के केंद्रकी सजाएँ मिलीं ।

नासिकसे ग्वालियरमें नव-भारत सिमितिके अस्तित्वका पता लगा। इसीके परिणामस्वरूप ग्वालियर पड्यन्त्र केस चल पड़ा जिसकी सुनवाईके लिए विशेष ट्रिन्यूनल बैठाया गया। ४१ व्यक्तियाँपर, जो सभी ब्राह्मण थे, नुकदमा चला। इनमेंसे २२ निवभारत सिमिति के सदस्य थे और शेप अभिनव भारत के। ग्वालियर सिमितिका नियम ४ इस प्रकार था—'स्वाधीनता, शिक्षा और आन्दोलनके उपदेश पूरे करनेके दो रास्ते हैं। शिक्षामें स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, शराव आदिका त्याग, धार्मिक उत्सव, भाषण, पुस्तकालय आदि शामिल हैं और आन्दोलनमें वन्तृक पिस्तीलका निशाना साधना, तलवार भाषना, यम व डाइनामाइट तैयार करना, रिवाल्यर प्रप्त करना और हथियारोंका प्रयोग खिखाना है। उपयुक्त समयपर किसी प्रान्तमें व्यापक विद्रोह होनेके अवसरपर, सभीको सहयोग देकर स्वाधीनता प्राप्त करनी है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा आर्च देश स्वाधीनता प्राप्त करने थे। इमें पूरा विश्वास है कि हमारा आर्च देश स्वाधीनता प्राप्त करने के योग्य है।' नवभारत सिमित अपनी तैयारियोंमें ही लगी थी कि उसके अधिकांश सदस्य ग्वालियर पड्यन्त्र केसमें एकड़ लिये गये और विभिन्न अवधियोंके लिए जेलीमें बन्द कर दिये गये।

मेरी मिण्टोके अनुसार अहमदाबाद भी "अद्यान्तिका केन्द्र था"; और यह अद्यान्ति वाइसरायपर फॅके गये दो वर्मोमें परिलक्षित हुई। लाई मिण्टो नपत्नीक दक्षिण और परिचम भारतका दौरा कर रहे थे। अहमदाबादमें उनकी पत्नीको लगा कि "स्टेशनपर भीजृद्र भीए उदास है और उसमें उत्साह नहीं है।" वाइसरायको देखने आये दर्शकोंमें एक छोटा लड़का भी था जो दोनों हाथोंमें एक एक शलजमके वरावर सफेद गेंद लिये हुए था। वह उन्हें इस तरह खुलेआम लिये हुए था कि किसीको सन्देह भी नहीं हुआ कि वे वस हैं। लड़केने तेजीसे एक हाथ धुमाकर वम फेंका, जो रेतीली सड़कपर गिरा। दूसरा वम फेंका, वह भी नहीं फूटा और निशानेसे दूर गिरा। लेकिन वाइसरायके चले जानेके वाद ही पता चला कि वे गेंदें वम थीं। एक भिक्तीने उन्हें उठाया और उसका दाहिना हाथ उट गया।

े अभिनव भारतकी एक शाखा सतारामें भी थी। १९१० में पुलिसने इसका पता लगाया और बहुतसे नीजवानोंको, जो सभी ब्राह्मण थे, पकड़ लिया। उन्हें विभिन्न रण्ड मिले। जिन और प्रान्तों में क्रान्तिकारी सिक्रय थे, वे थे संयुक्त प्रान्त, विहार, उड़ीसा, मध्यप्रान्त व मद्रास । यहाँ प्रेरणा और नेतृत्व वंगालसे मिला था और क्रान्तिकारियोंका यहाँका काम वंगाल व पंजायकी छाया मात्र था।

संयुक्त प्रान्तमें, १९०७ में शान्तिनारायण द्वारा इलाहाबादमें 'स्वराज्य' पत्र निकलनेके साथ क्रान्तिकारी राजनीति शुरू-हुई । पत्र लाजपतराय व अजितसिंहके माण्डलेकी नजरवन्दी हे रिहाईकी यादगारमें निकाला गया था। सरकारने इस पत्रको वहुत खतरनाक माना और उसके एक लेखको खुदीराम वोसकी प्रशंसा माना गया (खुदीरामके वमसे श्रीमती व कुमारी केनेडीको मृत्यु हुई थी)। उसके कुछ लेखोंको हिंसाका प्रचार माना गया और शान्तिनारायणको केद हो गयी। उनके वाद आनेवाले दो सम्पादकोंको भी केद हुई। १९१० में नये प्रेस कानून द्वारा मिले विशेष अधिकारोंसे सरकारने 'स्वराज्य' वन्द कर दिया। एक अन्य पत्र 'कर्मयोगी' भी इसी तरह वन्द कर दिया गया।

१९०८ में शचीन्द्रनाथ सान्यालने बनारसमें अनुशीलन समिति नामक एक गोष्ठी स्थापित की । इसके सदस्योंपर वादमें वनारस पड्यन्त्र केसमें मुकदमा चला । जत्र समितिके खिलाफ कानूनी काररवाई होने लगी, इसका नाम बदल कर 'यंग मेंस एसोसिएशन' कर दिया गया । सान्याल स्वयं छात्र थे और उनके ज्यादातर साथी भी पढ़ रहे थे । इस समितिमें भी धर्म राजनीतिसे सम्बद्ध हो गया और राजनीतिक हत्याओं के लिए गीताके उद्धरणींसे औचित्य हूँ हा गया। समिति धीरे-धीरे कान्तिकारी दलमें परिवर्तित हो रही थी। १९१४ के शुरूमें लाहोर पड्यन्त्र केसके अभियुक्त राशविहारी वसु बनारस आये और आन्दोलनका नेतृत्व करने लगे । उनके खिलाफ वारण्ट था और उनकी गिरफ्तारीपर इनाम था। उनका चित्र व्यापक रूपसे बाँटा जा चुका था। लेकिन वे लगभग एक सालतक वनारसमें रहे और पुलिसकी निगाहसे वचे रहे। वम बनाये गये, लेकिन ज्यादातर वे विशेष दूतों दारा वंगालसे मँगाकर इलाहावाद, मेरठ, लाहौर, जवलपुर आदिमें वितरित किये गये। वसुके सहकारी विष्णु गणेश पिंगलेको वम ले जाते हुए मेरठमें पकड़ा गया। यह २३ मार्चको हुआ। पिंगले १२ वीं भारतीय कैवलरीकी छावनीमें एक वक्समें दस बम लिये जा रहे थे जो "आधी रेजिमेण्टको उड़ा देनेके लिए काफी थे।" पिंगलेपर वादमें लाहीर पड्यन्त्र केसमें मुकदमा चला और उन्हें फाँसी हो गयी। २१ फरवरी सन् १९१५ को निश्चित हुए विद्रोह-के पंजाव पुलिसकी काररवाईसे असफल हो जानेके वाद बनारस समितिके सदस्योंका पता भी पुल्सिको लग गया और उनपर मुकदमा चला। बनारस पड्यन्त्र केसमें १० व्यक्तियोंको लम्बी लम्बी सजाएँ हुईं। शबीन्द्रनाथ सान्यालको आजन्म कालापानी मिला। कुछ दिनी वाद नवीं भोपाल इनफैण्टरीके भूतपूर्व हवलदार हरनामसिंहको क्रान्तिकारी पुस्तिकाएँ वाँटनेके अभियोगमें दस वर्षकी कैद हुई।

फरवरी कान्तिके लिए मध्यपान्तमें भी कुछ तैयारियाँ हुई । आन्दोलन चलानेके लिए राशिवहारी वसुने निलनीमोहन मुखर्जीको नियत किया था (जो वादमें वनारस पड़- यन्त्र केसमें अभियुक्त हुए)। वे सफल नहीं हुए । प्रयत्न जारो रहे पर कोई ठोस नतीजे नहीं निकले ।

विहार व उड़ीसाकी राजधानी वाँकीपुरमें शचीन्द्र सान्यालने वंकिमचन्द्र मित्रकी सहायतासे अनुशीलन समितिकी शाखा स्थापित की पर विशेष सफलता नहीं सिली।

अप्रैल १९०७ में विपिनचन्द्र पाल मद्रास गये ये और वहाँ कई व्याख्यान दिये जिनसे लोग ब्रिटिश-विरोधी हुए थे। उनकी यात्राके वाद ही वहाँ "राजद्रोहात्मक कारर-वाह्योंकी वाद-सी आ गयी और उसी साल रूसी गुप्त संखाओंके संवटन सम्बन्धी पुस्तिकाएँ वाँटी गयीं। निर्माण-विभागके कारखानेके कुछ छात्रोंके पास तलाशीमें ये पुस्तिकाएँ वरामद हुई थीं। तिन्नेवलीमें स्वराज्यके लिए तैयारी करनेकी अपील करते हुए मुब्रह्मण्य शिव व चिदाम्बरम् पिल्लेने भाषण किये। १२ मार्च १९०८ को वे गिरफ्तार कर लिये गये और दूसरे दिन तिन्नेवलीमें मीषण दंगा हो गया। "इस दंगेमें सरकारी सम्पत्ति ज्ञान वृझकर व्यापकरूपसे नष्ट कर दी गयी। सत्र-रिजट्मारके दफ्तरको छोड़कर शेप सभी सरकारी इमारतोंपर इसले हुए। वहाँके फर्नाचर और कागजात जला डाले गये। इमारतोंके कुछ हिस्से भी जल गये। ग्युनिसिपल दफ्तर जलकर राख हो गया। २७ व्यक्तियोंपर मुकर्दमा चला और उन्हें दंगेमें भाग लेनेके अभियोगमें सजाएँ मिलीं।

१७ जून १९११ को तिन्नेवलीके जिला मजिस्ट्रेटको गोली मार दी गयी जब वे रेलके एक डिक्बेमें बेटे थे। गोली वंची ऐयरने मारी थी। उन्हें फाँसी हो गयी। नौ अन्य व्यक्तियोंको सजाएँ हुई। इस इत्याके पहलेसे ही मद्रासमें कान्तिकारी आन्दोलन चलानेकी तैयारियाँ हो रही थीं। विद्रोहका साहित्य छापकर बाँटा जा रहा था। नीलकण्ठ ब्रह्मचारी और शंकर कृष्ण ऐयर "राजद्रोह व स्वदेशीका प्रचार करते हुए और प्रान्तके लोगोंसे स्वरास्थ्याप्तिके लिए संबकी रक्तकाथय लेनेको कहते हुए" घूम रहे थे। आन्दोलन जोर पकड़ रहा या और वीसियों नौजवान उसमें शामिल हो रहे थे। पर सरकारको पड्यन्त्रका पता जल्दी ही लग गया और वह उसे छिन्न-भिन्न करनेमें सफल हो गयी।

अध्याय १३

दक्षिणी अफ्रीकाका सत्याग्रह

अव भारतीय रंगमंचपर मोहनदास कर्मचन्द गान्धीका आविर्भाव हुआ । गान्धीजीसे राष्ट्रका प्रथम परिचय राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताके रूपमें १८९६ में हुआ । उस वर्ष वे एक विशेष उद्देश्य लेकर दक्षिणी अफीकासे भारत आये थे । वहाँ वे उपनिवेश सरकारके विरुद्ध अहिसात्मक ढंगसे संघर्ष कर रहे थे ।

दक्षिणी अफीकाके भारतीयोंकी कहानी संक्षेपमें इस प्रकार है।

१८६० में दक्षिणी अफ्रीकामें वसनेवाले यूरोपीयोंने भारत सरकारसे भारतीय मजदर भेजनेके वारेमें वातचीत गुरू की । "भारतं सरकारने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और भारतसे प्रतिज्ञावद (Indentured) मजदूरोंका पहला जत्था नेटालमें १६ नवम्बर सन् १८६० को पहुँचा।" यह व्यवस्था अर्धगुलामीकी थी, क्योंकि विना प्रतिज्ञानकी अविध समाप्त हुए, मजदूर मालिकोंकी गुलामीकी सेवासे मुक्त नहीं हो सकते थे। वे पीटे जाते और उनके साथ दुर्व्यवहार होता परन्तु वे नौकरीसे छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते थे। पहेंकी समाप्तिपर ये मजदूर प्रवासी यूरोपीयोंके लिए एक समस्या वन गये। आजाद होने पर वे स्वतन्त्र रूपसे व्यापार करने लगे और यूरोपीय उनको अपना व्यापारिक प्रतिद्वन्द्वी समझने लगे। नेटाल सरकारने इन 'स्वंतन्त्र' भारतीय मजदूरोंसे छुटकारा पानेकी एक तरकीव सोची। सरकारने पट्टेसे मुक्त प्रत्येक भारतीयपर २५ पौण्ड सालानाका (Poli-tax) लगानेका प्रस्ताव रखा । भारतके गवर्नर जनरलके हस्तक्षेप करने पर यह कर घटाकर ३ पौण्ड कर दिया गया । भारतीयोंने इस करके विरोधमें एक शक्तिशाली उद्देलन खड़ा किया जो निष्फल रहा। १८९३ में गान्धीजो एक मुकदमेंके सम्बन्धमें दक्षिणी अफ्रीका गये हुए थे। भारतीयोंको और अधिक तंग और परेशान करनेके लिए नेटाल सरकारने विधान सभामें भारतीयोंका मताधिकार छीननेका विधेयक पेश किया । गाँधीजीने सलाह दी कि भारतीयोंको अपने अधिकारोंपर हुए इस आक्रमणका डटकर सामना करना चाहिये। वे इससे सहमत हो गये और उन्होंने गान्धीलीसे इस आन्दोलनका नेतृत्व ग्रहण करनेकी प्रार्थना की । आन्दोलन शुरू हुआ और एक महीनेके अन्दर ही उपनिवेश सचिव (सेकेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉलो-नीज) लार्ड रिपनके सामने पेश होनेवाले स्मृतिपत्रपर दस हजार (१०,०००) हस्ताक्षर हो गये। दक्षिणी अफीकाके भारतीयोंका इस प्रकारके आन्दोलनका यह प्रथम अनुभव था और पूरे समाजमें उत्साहकी एक नयी उमंग भर गयी।"

इस आन्दोलनका तात्कालिक प्रभाव हुआ। "लार्ड रिपनने विलको निषिद्व कर दिया और घोषणा की कि अंग्रेजी साम्राज्यविधानमें रंग-मेद को कोई स्थान नहीं दिया जा सकता" परन्तु नेटाल सरकारने एक दूसरे संदिग्धार्थ विधेयक द्वारा अप्रत्यक्ष रूपमें वे अधिकार प्राप्त

१. एम० के० गान्धी-सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका पृष्ठ ३८

२. वही पुस्तक पृष्ठ ५०

कर लिये जो उसने इसके पूर्व विधान समामें विधेयक पेश करके हासिल करने चाहे थे और जिसका रिपनने निपेध कर दिया था। भारतीय मताधिकारसे वंचित कर दिये गये। भारतीयों का उद्देलन जन्म ले चुका था और मई १८९४ में नेटाल भारतीय कांग्रेसकी स्थापना हुई। यह स्मरणीय है कि इसका नामकरण कांग्रेसके ऊपर ही हुआ। गान्धीर्जा लिखते हैं—"मेंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इण्डियन नेशनल कांग्रेस) के किसी भी अधिवेशनमें भाग नहीं लिया था परन्तु कांग्रेसके वारेमें पढ़ा था। मैंने भारतके पितामह (ग्राण्ड ओल्ड मैन) दादा भाई नौरोजीको देखा था और में उनका प्रशंसक था। में कांग्रेसका मक्त था और इसके नामको फेलाना चाहता था। मैं अनुभवहीन था और मेंने कोई नया नाम हँ दनेकी चेष्टा नहीं की। इसलिए मेंने नेटालके भारतीयोंको अपने संघटनका नाम नेटाल भारतीय कांग्रेस (Natal Indian Congress) रखनेकी सलाह दी। मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इण्डियन नेशनल कांग्रेस) के वारेमें अपना सीमित और अपूर्ण ज्ञान उनके सामने रखा।"

वे सन १८९६ के मध्य में भारत लीट आये। दक्षिण अफ्रीकामें ग्रुक किये हुए कामके वारेमें गान्धीजी लिखते हैं "जब मैं भारतमें था, मेंने दक्षिणी अफ्रीकाके भारतीयों की दशाके
वारेमें एक पुस्तिका लिखी थी। लगभग सभी पत्रोंमें इसका जिक हुआ था और इसके दो
संस्करण निकले थे। भारतके विभिन्न भागोंमें इस पुस्तिकाकी पाँच हजार प्रतियाँ वाँटी गर्या।
इसी कालमें सर फीरोजशाह मेहता, न्यायाधीश वदस्हीन तैयवजी व महादेव गोविंद रानाडे
जैसे भारतीय नेताओंसे वम्बईमें और लोकमान्य तिलक और उनके साथी, प्रोफेसर भंडारकर,
गोपालकृष्ण गोखले व उनके साथियोंसे पूनामें मिलनेका सीभाग्य प्राप्त हुआ। मेंने वम्बई,
पूना और मद्रासमें भाषण किये।" गान्धीजीके दक्षिणी अफ्रीकाके सत्याग्रहमें दिये गये
विवरणसे भी हमें तिलक-गोखले राजनीतिका एक चित्र मिलता है। गान्धीजी पहिले तिलकसे
मिले। तिलकने उन्हें वताया कि "पूनामें दो दल हैं। एकका प्रतिनिधित्व सायंजनिक सभा
करती है और दूसरेका दक्षिण सभा (Deccan sabha)।" "सार्वजनिक सभा श्री
लोकमान्य तिलकके नियन्त्रणमें थी जब कि श्री गोखलेका सम्बन्ध दक्षिण सभासे था।"

जब गान्धीजीने तिलक्षे पूनामें एक सभा करनेके वारेमें वातचीत की, तो तिलक्षने कहा "वहाँ पर सभा करना आसान है। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपनी वात सभी पार्टियोंके सामने रखना चाहते हो और सभीका समर्थन चाहते हो। में तुम्हारा विचार पसन्द करता हूँ । परन्तु यदि सार्वजनिक सभाका कोई सदस्य मीटिंगकी अध्यक्षताके लिए चुना जाता है तो दक्षिण सभाका एक भी सदस्य सभामें भाग नहीं लेगा । इसी प्रकार यदि दक्षिण सभाका आदमी सभापितत्व करेगा तो सार्वजनिक सभाके लोग समामें नहीं आयेंगे। इसलिए तुम सभापितत्वके लिए ऐसा आदमी हुँद लो जिसका किसी पार्टी विद्येषसे सम्बन्ध न हो" गोखले और तिलक दोनोंकी सम्मतिसे निष्पक्ष व्यक्ति प्रोफेसर भण्डारकर इस पदके लिए चुने गये और एक सफल सभा हुई जिसमें दक्षिण अफीकाके भारतीयोंकी दीन दशाका वर्णन किया गया।

१. वही पुस्तक, पृष्ट ७४-७५

२. वहीं पुस्तक, पृष्ट ८१-८२

३. वही पुस्तक, पृष्ट ८३

इसके बाद गान्धीजी मद्रास व कलकत्ता गये, वहाँके मुख्य नेताओंसे मिले और अपने उद्देश्यके लिए उनका समर्थन प्राप्त किया। जब वे अपने कामसे भारतमें व्यस्त थे, नेटालसे उनको समुद्री तार द्वारा तुरत वापस लौटनेका अनुरोध मिला । भारतमें उनके उद्वेलनको नेटालके अखबारोंमें काफी प्रसिद्धि मिली। इस प्रसिद्धिसे नेटालके यूरोपीय समाजका जल्दी उत्तेजनामें आ जानेवाला वर्ग बहुत कुढ़ हो गया । जब गान्धीजी नेटाल पहुँचे तो इन लोगोंने कानून अपने हाथमें लेकर गान्धीजीको जिन्दा जला देनेका प्रयत्न किया। जब गान्धीजी एक एडवोकेंट लॉपटनके साथ डरवन जा रहे थे, कुछ यूरोपीय नौजवानोंने उनको देख लिया और 'गान्धी-गान्धी' चिल्लाने लगे। फौरन ही बुद्ध यूरोपीयोंकी एक भीड़ जमा हो गयी जो बढ़ती ही गयी। किसीने लॉफ्टनको पकड़कर गान्धीजीसे अलग कर दिया । उसके बाद भीड़ने गान्धीजी पर ईंटों-पत्थरीं और सड़े अंडोंकी बौछार ग्रुक कर दी। किसीने उनकी पगड़ी छीन ली, जब कि दूसरे लोग उनको ठोकरों और धूँसोंसे मार रहे थे। वे वेहोश हो गये और सहारेके लिए उन्होंने एक मकानक लोहेके छज्जेको पकड़ लिया। फिर भी यूरोपीय उनपर झपटे और घूँसे और ठोकरें मारते रहे । सौभांग्यवदा पुलिस सुप-रिंटेंडेंटकी बीबी जो गान्धीजोको पहचानती थी, उस समय वहाँसे गुजर रही थी। वह वहाँ पर आयी और अपना छाता खोलकर गान्धीजी और मीड़के बीचमें खड़ी हो गयी। इस कार्यने भीड़की उत्तेजनाको रोक दिया। फिर उनको पुल्सिक संरक्षणमें उस मकानतक पहँचा दिया गया, जहाँ उनको ठहरना था।

उनके यहाँ पहुँचनेके वाद ही यूरोपीयोंकी एक भीड़ घरके सामने इकट्टा हो गयी।
पुलिस सुपिरंटेण्डेण्ट एलेक्जेंडरको जो वहाँ पुलिसके एक जत्थेके साथ पहुँच गये थे, गान्धीजीका जीवन वचानेका एक उपाय सझ गया। उन्होंने गान्धीजीको एक काँस्टेविलकी वादी
पहननेकी सलाह दी। गान्धीजीने ऐसा ही किया। गान्धीजी इस उपायसे घरसे वाहर निकल
गये और जवतक वे सुरक्षित स्थानपर नहीं पहुँच गये एलेक्जेण्डर एक गाना गाकर भीड़का
मनोरंजन करते रहे। गानेका आशय यह था—गान्धीको खडे सेवके पेड़पर लटकाकर
काँसी दे दो।

इससे पूर्व भी दक्षिणी अफिकामें कई अवसरोंपर गान्धीजीका इसी प्रकार अपमान किया गया था।

वादमें कांग्रेसकी लंदन स्थित अंग्रेजी समिति (ब्रिटिश कमेटी आफ कांग्रेस, लन्दन) ने दक्षिणी अफ्रीकाके भारतीयोंके मसलेको अपने हाथमें ले लिया। नेटाल कांग्रेसने अंग्रेजी समितिसे मसलेको उटानेका अनुरोध किया था।

१८९४ से कांग्रेसने दक्षिणी अफ्रीकाक भारतीयोंके प्रक्तिपर ध्यान देना शुरू कर दिया था। उसी वर्ष कांग्रेसने एक प्रस्ताव द्वारा सम्राज्ञीकी सरकारसे प्रार्थना की थी कि वह दक्षिणी अफ्रीकाके उपनिवेशोंमें वसनेवाली सम्राज्ञीकी भारतीय प्रजाको मताधिकारसे वंचित करनेवाले नेटाल सरकारके विधेयकका निषेध कर दे।

१८९५ में फिर कांग्रेसके सम्मुख यह प्रश्न आया और अधिवेशनमें इस प्रश्नपर काफी वहस हुई। जी. परमेश्वरम् पिल्लैने दक्षिणी अफीकाकी सरकार द्वारा भारतीयोंपर लागू किये गये एक एक अयोग्यता प्रतिवन्धको गिनाया। जे. एम. सामन्तने एलान किया कि दक्षिणी अफीकाके भारतीयोंको मताधिकारने वंचित करनेवाला ऐक्ट (Act) पूरे

रॉष्ट्रका अपमान है। दुसरे वर्षके अधिवेशनमें श्री पिल्हैने ज्यादा स्पष्टतासे भाषण किया। उन्होंने कहा "दक्षिणी अफ्रीकामें हमें विना पारपत्रके यात्रा करनेकी आजा नहीं है, हम रातमें घूम फिर नहीं सकते, हमें पृथक वस्तियों में रहनेकी वाध्य किया जाता है, रेलों में प्रथम और द्वितीय श्रेणीके डिव्वोंमें प्रवेश करनेका हमें निपेध है। ट्रामोंसे हमें निकाल दिया जाता है। हमें सार्वजिनक सडकोंपर चलने नहीं दिया जाता, हमपर थुका जाता है, हमारी लानत की जाती है, हमें कोसा जाता है, हमें गालियाँ दी जाती हैं। इसके अलावा हमारे ऐसे ऐसे अपमान किये जाते हैं जिन्हें कोई भी इन्सान शान्तिसे वर्दास्त नहीं कर सकता।" १८९८ के कांग्रेस अधिवेदानको श्री पिल्हैने, जिन्होंने दक्षिणी अफ्रीकाके वारेमें प्रस्ताव पेश किया था, बताया कि भारतीय प्रवासियोंके ऊपर दिन प्रतिदिन अधिक सख्त प्रतिवन्ध लागू किये जा रहे हैं। १८९७ में कान्तने वाध्य किया कि भारतीय 'स्थायी वन्धन अथवां वृणित पॉल टैक्स'में से एकको स्वीकार करें। ट्रांसवाल सरकार उनको 'पृथक वस्तियों' में रहनेको मजवूर कर रही है। उनके लिए ये वस्तियाँ नगरके बाहर वसायी गयो हैं जहाँ कूड़ा फेंका जाता है और उनको "लाचारी हे कूड़ों के देरों के बीचमें रहना पड़ता है।" श्रीपिरुटैंने कहा कि भारत सचिव लॉर्ड हैमिरुटनसे कोई आया नहीं है, उन्होंने तो "हमें वर्वरोंकी कौम माना है।" १९०० और १९०१ में विरोधमें प्रस्ताव पास हुए। १९०१ में तो गार्ग्धा जी स्वयं अधिवेशनमें उपस्थित थे । उन्होंने अपनेको "दक्षिणी अफ्रीकाके एक लाख भारतीयोंकी ओरसे प्रार्थी घोषित किया'' और स्वयं प्रस्तावको पेश किया। यहाँ हमें पहली बार गान्धीजीके तरीकोंकी एक झलक मिलती है। उनके अपने शब्दोंमें 'कांग्रेस पण्डालमें गन्दगीकी कोई सीमा नहीं थी । हर जगह पानीके गड्ढो भरे हुए थे । पाखाने एकाध ही थे. वहाँ फेली हुई वदवृकी यादचे अभीतक मेरा जी मचला उठता है। मैने इस वातकी तरफ स्वयंसेवकोंका ध्यान दिलाया तो उन्होंने मुझे साफ जवाय दे दिया "यह इमारा काम नहीं है, यह मंगीका काम है।" मैंने झाड़ माँगी तो वह आदमी आश्चर्यने मुझे देखता रह गया। मैंने एक झाड़ ली और पाखानेकी सफाई कर दी। यह मैंने अपने लिए किया था। भीड इस कदर ज्यादा थी और पाखाने इस कदर कम थे कि उनकी वार-वार सफाईकी आवर्यकता थी । लेकिन यह मेरे वृतेके वाहर था ।"

अधिवेशन आरम्भ होनेके दो दिन पूर्व ही गान्धी जी कलकत्ता पहुँच गये थे। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि 'अनुभव प्राप्त करनेके लिए वे अपनी सेवाएँ कांग्रेस कार्यालयको अर्वित करेंगे। इसलिए वे कांग्रेसके दनतर गये। वहाँ क्या हुआ, इसका वर्णन इस प्रकार है— बाबू भूपेन्द्रनाथ वसु और श्रीयुत घोपाल मन्त्रो थे। में भूपेन्द्रवावृक्षे पास गया और अपनी सेवाएँ प्रस्तुत कीं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा 'मेरे पास कोई काम नहीं है। सम्भव है घोपालवावू तुम्हें कोई काम बता सकें। कृपाकर वहीं जाओ।' इसलिए में उनके पास गया। उन्होंने मुझे कपरसे नीचेतक देखा और मुस्कराकर कहा 'में तुमको सिर्फ लिखा पढ़ीका काम दे सकता हूँ। क्या तुम यह काम करोगे? ''अवस्य'' मैंने कहा ''में प्रत्येक काम करनेको तैयार हूँ अगर वह कार्य शक्ति वाहर नहीं है।' यही सही भावना है,

^{1.} वेसंण्ट—'हाऊ इण्डिया फॉट फॉर फीडम', पृष्ट २३७

२. वही पुस्तक, पृष्ट २७९-८०

३. गान्बीजी, आत्म चरित्र, पृष्ठ ६०५

नवयुवक, अपने चारों तरफ खड़े हुए स्वबंधेवकों से उन्होंने कहा, क्या तुमने इस नवयुवककी वात सुनी हें ? फिर मेरी तरफ मुड़कर कहा 'अच्छा! यह चिडियोंका टेर निवटाने के लिए पड़ा हुआ है, वह कुसों छे छो और आरम्भ करो।' श्रीयुत घोपाल चपरासी से अपनी कमीज के वटन लगवाया करते थे ? मेंने चपरासी के यह काम खुद करने की अनुमति चाही। चूँ कि वड़ों के लिए मेरे दिलमें वड़ी श्रद्धा थी इसलिए इस काममें मुझे वहुत आनन्द आता। जब उन्हें इसका पता लगा तो अपने लिए की गयी मेरी छोटी मोटी सेवाओं को करने से वे मुझे न रोकते। वास्तवमें इससे उन्हें प्रसन्नता ही होता। मुझसे कमीज के वटन लगाने के लिए कहकर वे अक्सर कहते ''तुमने देखा, अब कांग्रेस मंत्री के पास अपनी कमीज के वटन लगाने का मी समय नहीं हैं। उनके पास कुछ न कुछ काम हमेशा बना रहता है'' श्रीयुत घोषालकी सरलतापर मुझे हँसी आती, पर इससे ऐसे कामों के लिए मुझे कोई अर्घन नहीं उत्पन्न हुई।''

अपने ऊपर पड़े हुए कांग्रेस अधिवेशनके प्रमावींके वारेमें गान्धीजी लिखते हैं—"यहाँ मैंने समयकी वर्वादी देखी । खेद और क्षोमके साथ मैंने इस वातपर भी ध्यान दिया कि हमारे मामलोंमें अंग्रेजी भाषाको अभीतक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। काम करते समय शक्तिका अपन्यय रोकनेकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता था। एक आदमीका काम कई आदमी करते थे और बहुतसे जरूरी काम करनेके लिए कोई आदमी ही नहीं मिलता था।"

सन् १९०३ में सी॰ एफ॰ सीवराइट ऑस्ट्रेलियाके भारतीयोंकी ओरसे एक आवेदन-पत्र लेकर आये जिसमें उन अपमानजनक प्रतिवन्धोंसे मुक्त करानेकी प्रार्थना की गयीं थी जो उनपर लगाये गये थे। यह मसला भी दक्षिणी अफ्रीकाके भारतीयोंके सवालके साथ ही जोड दिया गया और इस विषयपर पास हुए प्रस्तावमें कहा गया था कि—कांग्रेसका यह अधिवेशन महामान्य सम्राट्के दक्षिण अफ्रोका, ऑस्ट्रेलिया व अन्य-अन्य अंग्रेजी उपनिवेशोंके भारतीयोंकी दारुण दर्शापर औपनिवेशिक सरकारीं द्वारा उनपर लगाये गये अयोग्यता प्रतिवन्धों, परेशान करनेवाले नियमों और उनके परिणामस्वरूप सम्राटकी भारतीय प्रजा होनेके नाते उनकी स्थिति सम्बन्धी अप्रतिष्ठा और अधिकारोंके अपहरणपर गहरी चिन्ता व दुःख प्रगट करता है। औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतीयोंके साथ पिछड़ी हुई व असभ्य जातियों के समान किये गये बुरे व्यवहारका कांग्रेस विरोध करती है; और प्रार्थना करती है कि उपनिवेशोंकी उन्नतिके लिए प्रवासी भारतीयों द्वारा किये हुए महत्त्वपूर्ण कार्य व भारतीयोंके उपनिवेसमें जाने और वहाँ वसनेसे भारत और उपनिवेश दोनोंको हुए आर्थिक लामोंको दृष्टिमं रखते हुए भारत सरकार कृपा करके सम्राटकी यूरोपीय प्रजाके अधिकारोंके अनुरूप औपनिवेशिक भारतीयोंको अंग्रेजी नागरिकताकै अधिकार और सुविधाएँ प्रदान करें।" १९०४ के कांग्रेस अधिवेशनमें कुछ प्रतिनिधियोंने उपनिवेशोंमें स्वयं भुगते हुए कप्टोंका वर्णन किया। कांग्रेस अधिवेशनने दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा घोर भारतीय विरोधी कानृनके लागू किये जानेकी धमकीका जोरदार विरोध किया।

अव हम उस दौरकी तरफ आते हैं जिसको भारतीय सत्याग्रह आन्दोलनोंका पूर्व-

१. वही पुस्तक, पृष्ट २०७-७८

२. वही पुस्तक, पृष्ठ २७८-८९

अभिनय कहा जा सकता है। सर्वप्रथम १९०६ में ट्रांसवाल सरकारके एक काले कानून (व्लैक ऐक्ट) के खिलाफ संघर्षमें सत्याग्रह शब्दका, अहिंसात्मक युद्धके हथियारके रूप-में जन्म हुआ था । जब जुळू विद्रोह और वोअर युद्धमें दक्षिण अफ्रीकार्मे भारतीय ब्रोपीय समाजकी सेवाएँ कर चुके तो ट्रांसवाल सरकारने एक आर्डिनेन्स जारी कर दिया जिसके द्वारा ट्रांसवालमें रहनेवाले प्रत्येक भारतीयको—स्त्री, पुरुष, वच्चे जो ८ वर्ष या उससे अधिककी हों, एदियावालोंके लिए नियुक्त रजिस्ट्रार (Registrar of the Asiatics) के पास अपनी रजिस्ट्री करानी पड़ती और रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र हासिल करना पड़ता। और जब कोई पुलिसका हाकिम माँगे तो रिजस्ट्री प्रमाणपत्र उसके सम्मुख पेश करना पहता । यह कानून वहत ही अपमानजनक था और इसका उद्देश्य ट्रांसवालमें भारतीयोंकी आयादीकी कम करना था। आर्डिनेन्सने रजिस्ट्रारको अधिकार दिया था कि वहाँ वसनेवाले प्रत्येक भारतीय-की उँगलियोंके निवान ले लें। भारतीय वहत परेशान थे। प्रमुख भारतीयोंकी एक सभा इस आर्डिनेंसके वारेमें सोच-विचार करनेके लिए बुलायी गयी । उपिथत लोगोंमेंसे एकने आवेगमें आकर कहा "अगर कोई मेरी बीबीसे प्रमाणपत्र माँगने आया तो मैं उसको गोली मार दूँगा और परिणाम भुगत लूँगा।" इसके बाद एक सार्वजनिक सभा की गयी जिसमें भारतीयोंने निरचयपूर्वक घोषित किया कि यदि यह आर्डिनेन्स कानृन बना दिया गया तो वह इसके सामने इकोंगे नहीं, और सब प्रकारके परिणामींको बरदास्त करनेके लिए तैयार रहेंगे। आर्डि-नेत्सका एक प्रकारका सविनय प्रतिरोध करनेका विचार किया गया। छेकिन गान्धीजीके मस्तिष्क्रमें आन्दोलनकी जो रूपरेखा थी वह सविनय प्रतिरोधसे कहीं कँची थी। उन्हें यह लाभारपद प्रतीत हुआ कि इस उच्च संघर्षका अंग्रेजी नाम हो। आन्दोलनका नाम सुझाने-के लिए छोटा-सा पुरस्कार रखा गया। सबसे अच्छा प्रस्ताव सदाग्रह (सद् + आग्रह) (अच्छे उद्देश्यमें दृढता) आया । गान्धीजीने अपनी धारणाके अनुसार इसमें सुधारकर इसे 'सत्याग्रह' नाम दिया जिसका अर्थ उन्होंने इस प्रकार वताया ''सत्य जिसमें प्रेम भी शामिल है और आग्रह माने दढता जिससे शक्तिका बोध होता है।" निष्किय प्रतिरोध अधिकारसे वंचितों और निर्वलोंका हथियार समझा जाता था। लेकिन गान्धीजीने कहा कि "किसी भी दशामें भारतीय आन्दोलनमें वर्वर शक्तिका कोई स्थान नहीं है।" और "सत्याग्रही कभी भी शारीरिक वलका प्रयोग नहीं करेंगे भले ही वे वलका प्रभावशाली प्रयोग करनेकी स्थिति-में हों।"

भारतीयोंने एक शिष्टमण्डल इंगलैण्ड भेजा ताकि सरकार काले कान्त'को रद कर दे। लेकिन इसके फौरन बाद ही ट्रांसवालमें एक जिम्मेदार सरकार वन गयी। इस सरकार द्वारा बनाया गया पहला नियम एशियाई रिजस्ट्री ऐक्ट (एशियाटिक रिजस्ट्रेशन ऐक्ट) था, जो २१ मार्च १९०७ को एक ही बैठकमें पारित कर लिया गया और १ जुलाई १९०७ को लागू कर दिया गया।

भारतीय नेताओंने रजिस्ट्रीके कार्यालयके सामने धरना देनेका निरुचय किया। बारहरें अटारह वर्षके स्ववंसेवक कार्यालय जानेवाली सड़कोंपर तैनात कर दिये गये। उनको समझा दिया गया कि वे कार्यालय जानेवाले प्रत्येक भारतीयके हाथमें एक-एक इस्तहार दे दें जिसमें इस काले कान्तके अन्तर्गत होनेवाले अपमानोंका पृरा-पूरा ब्योरा था। स्ववंसेवकोंको रजिस्ट्री कार्यालय जानेवाले किसी व्यक्तिको रोकना नहीं था; उनका काम शान्तिपूर्ण ढंगते

समझाना था "अगर पुलिस उनको गाली दे या मारे तो उसे शान्तिसे सहन करें। यदि पुलिस उनको गिरफ्तार करें तो उन्हें प्रसन्नतापूर्वक आत्मसमर्पण कर देना चाहिये।" लगभग ५०० व्यक्तियोंने आज्ञापत्र प्राप्त किये; यह संख्या बहुत कम थी और ट्रांसवाल सरकारको इससे निराशा हुई। सरकारने रिजिस्ट्रेशनके खिलाफ एक प्रमुख आन्दोलनकर्ता श्री रामसुन्दरको गिरफ्तार करनेका निश्चय किया। रामसुन्दरको एक माहकी सादी कैदकी सजा मिली। लेकिन भारतीय समाजके हितमें यह लाभदायक सिद्ध हुआ क्योंकि प्रमाण-पत्र लेनेके लिए अब कोई न जाता और सैकड़ों जेल जानेको प्रस्तुत थे?

काले कान्त (ब्लैंक ऐक्ट) के खिलाफ शिक्षा देनेवाला प्रचार कई भाषाओं में प्रकाशित—इण्डियन ओपिनियन(Indian opinion) नामक एक साप्ताहिक पत्रिका द्वारा किया गया । सरकार ऐक्टकी इतने बड़े पैमानेपर अवज्ञासे परेशान थी । उसने पूरे समाजको दण्ड देनेका फैसला किया । नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको भिन्न भिन्न सजाएँ सुनायी गयीं व उनपर जुर्माने किये गये । गान्धीजीने मैजिस्ट्रेटसे प्रार्थना की कि वह गान्धीको दूसरे लोगोंसे अधिक सजा दे "क्योंकि यदि और लोगोंने अपराध किया है तो मैंने (गान्धीजीने) गुरुतर अपराध किया है ।" नेताओंकी गिरफ्तारीके वाद सत्याग्रह आन्दोलनको नयी प्रेरणा मिली और सत्याग्रहियोंसे जेलें भरने लगीं।

जोहान्सवर्गसे निकलनेवाले दैनिक-पत्र 'दी ट्रांसवाल लीडर'के सम्पादक अलबर्ट कार्ट-राइट द्वारा सरकारने पन्द्रह दिन बाद समझौता-वार्ता ग्रुरू की । गान्धीजीको जनरल स्मट्ससे मिलनेके लिए जेलसे प्रीटोरिया ले जाया गया । स्मट्सने गान्धीजी और भारतीय समाजको वधाई दो कि वे लोग गान्धीजीकी गिरपतारीके बाद भी दृढ़ वने रहे। और कहा "तुम लोगोंको मैं कभी नापसन्द नहीं कर सका। तुम जानते हो कि मैं भी वैरिस्टर हूँ। अध्ययन कालमें मेरे साथ कुछ भारतीय विद्यार्थों पढ़ते थे। लेकिन मुझे अपना कर्तव्य पालन करना है। यूरोपीय इस कान्नको चाहते हैं, और तुम मुझसे सहमत होंगे कि उनमेंसे अधिकांशतः वोअर नहीं विक अंग्रेज हैं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही तुम लोगोंमेंसे अधिकांश अपनी इच्छासे रिजस्ट्री प्रमाण पत्र ले लेंगे, मैं काले कान्त (ब्लैक ऐक्ट) को रद कर दूँगा। जब रजिस्ट्रीको कानृती करार देनेवाले विधेयकका मसविदा तैयार हो रहा होगा, तुम्हारी आलोचनाके लिए एक प्रति में तुम्हें भेज दूँगा। में झगड़ेकी पुनरावृत्ति नहीं चाहता, और तुम्हारे लोगोंकी इच्छाओंका आदर करना चाहता हूँ। समझौता स्वीकार हो गया, गांधीजी व अन्य कैदी मुक्त कर दिये गये। लेकिन भारतीयोंको अब भी अपनी उँगलियोंके निशान देने पड़ते । इस वातसे बहुतसे लोग समझौतेके खिलाफ हो गये। एक पटानने एक सार्वजनिक सभामें गान्धीजीपर आरोप लगाया "हमने सुना है कि तुमने समाजके साथ गहारी की है और १५००० पौण्डपर हम लोगोंको जनरल स्मट्सके हाथ वेच दिया है। हम कभी भी उँगलियोंके निशान नहीं देंगे। मैं अल्लाहकी कसम खाकर कहता हूँ कि जो भी रिजस्ट्री-प्रमाणपत्र लेनेके लिए सबसे पहले जायगा, उसे मैं कत्ल कर दूँगा।" वास्तवमें घटनाएँ इसी प्रकार घटों भी । एक दिन जब गान्धीजी रिजस्ट्री प्रमाणपत्र लेनेके लिए रिजस्ट्री-कार्या-लय जा रहे थे तो रास्तेमें चटाई बनानेवाले मीर आलम नामक एक आदमी और उसके साथियोंने गान्धीजीपर डण्डोंसे हमला किया। वह 'हे राम' कहते हुए गिरकर वेहोश हो गये,

उसके बाद क्या हुआ, इसका उन्हें कुछ पता नहीं चला । जब उनकी मरहमपृश्ची हो रही थी, रिजस्ट्रो-अधिकारियोंके मना करनेके बावजूद और उनकी सलाहके खिलाफ वह उँग-लियोंके नियान देनेपर जिद करते रहे "मैंने पहला रिजस्ट्री-प्रमाणपत्र लेनेका प्रण किया है।" उन्होंने ऐसा ही किया। अपने आक्रमणकारियोंके लिए भी गान्धीजीने क्षमायाचना की, मगर कानृन, कानृन है। गान्धीजीकी देखा-देखी बहुतसे भारतीयोंने रिजस्ट्री-प्रमाणपत्र ले लिये। लेकिन समझौतेके विपरीत जनरल स्मर्सने काले कानृनको कायम ही नहीं रखा, बल्कि भारतीयोंके खिलाफ एक नया कदम और उठाया जिसमें यह उपबंध किया गया कि निश्चित तिथि (जिसकी भारतीयोंने अवज्ञा की थी) के बाद भी स्वेच्छासे प्रमाणपत्र लेनेवालोंके विरुद्ध कोई काररवाई नहीं की जायगी, और शेष व्यक्तियोंको कानृन सख्त सज्ञा देगा।

जनरल स्मट्सको वादेकी याद दिलाते हुए कई खत लिखे गये कि वे अपनी वातको पूरी करें, पर वे विलक्कल नहीं छके। संघर्षको पुनः आरम्भ करनेके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं था। हर जगह आदमी जेल जानेको प्रस्तत थे। स्मट्सको एक पत्र, जिसे उसने चुनौती माना, भेजा गया। पत्रमें लिखा था कि यदि एशियाई ऐक्ट (एशियाटिक ऐक्ट) रद नहीं किया गया तो रिजस्ट्री-प्रमाणपत्रोंको जला दिया जायगा, और भारतीय लोग "नम्रता परन्त हदतासे सब परिणामोंको भुगतनेके लिए तैयार हैं।" सरकारको 'कैसला' कर लेनेके लिए एक अवधि निश्चित कर दो गयी। अवधि समाप्त होनेके करीय दो घण्टे बाद, रिजस्ट्री-प्रमाण-पत्र जलानेका सार्वजनिक उत्सव मनानेके लिए एक सभा बुलायी गयी और करीय दो हजार प्रमाण-पत्र इकट्ठे कर लिये गये। मिट्टीके तेलसे भरे कड़ाहमें ये तमाम प्रमाण-पत्र झोंक दिये गये और आग लगा दी गयी।

यह दूसरे सत्याग्रह आन्दोलनकी शुरूआत थी। इस आन्दोलनके कार्यक्षेत्रमें एक द्सरा कान्न भी शामिल कर लिया गया । यह कान्न ट्रांसवाल आप्रवासी निरोध ऐक्ट (टांसवाल इमीग्रैण्टस रेस्ट्रिक्शन ऐक्ट) उसी वर्ष पास किया गया था जिस वर्ष काला कानून बनाया गया था । निरोध ऐक्ट (रेस्ट्रिक्शन ऐक्ट) का उद्देश्य नये आने-वाले भारतीयोंको ट्रांचवालमें प्रवेश करनेसे रोकना था। इसके द्वारा नेटालमें रहनेवाले भारतीयोंपर भी प्रतिवन्ध लग गया कि जवतक, वे ऐक्टकी कुछ निश्चित धाराओंको पूरा न कर हैं, उनको ट्रांमवालमें घुसनेका भी निपेध था। इन दोनों उद्देश्योंको लेकर चलनेवाला आन्दोलन आरम्भ हो गया। निरोध ऐक्ट (रेस्ट्रिक्शन ऐक्ट) का उल्लंघन करके नेटालके भारतीय ट्रांसवालमें वुस रहे थे और ट्रांसवालमें वसने-वालोंने नये प्रमाण पत्र हेनेसे इनकार कर दिया । अनुशासनबद्ध सत्याप्रहियोंने ये दोनों कानून तोड़े। वे गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये। गान्धीजी भी गिरफ्तार कर लिये गये परन्तु वे दूसरे वन्दियोंसे पृथक् रखे गये। खतरनाक कैदियोंके लिए निश्चित तनहाई कोठरीमें वे बन्द कर दिये गये। अधिकारींकी रक्षांके संघर्षमं रत भारतीयोंका उत्साह इन गिरपतारियोंसे श्रीण न हुआ । सरकार चक्करमें थी । चुँकि केलें ठसाटस भर चुकी थों, इसलिए सरकारको दूसरे साधन अपनाने पड़े। सत्याप्रही ट्रांसवालसे बाहर भेजे जाने लगे, कुछको निष्कासित कर भारत भेज दिया गया । इस देशनिकालेकी काउनी वैधतापर प्रश्न उठाया गया और जब यह अवैध करार दे दिया गया तो निष्कासन रोक दिया गया। सरकार अड़ी हुई थी और सत्याग्रह अब लम्बा संघर्ष बन रहा था।

१९१२ में गोखले दक्षिण अफ्रिका गये । वे जहाँ भी गये उनका शानदार स्वागत हुआ। आश्चर्य था कि उनकी सभाओंमें कुछ यूरोपीय भी सम्मिल्ति हुए। सरकारने भी गोखलेका आदर किया। वे सरकारके मन्त्रियोंसे मिले और उनसे दो वण्टेकी भेटके परचात् पूर्ण रूपसे संतुष्ट होकर लोटे । उन्होंने गांघीजीसे कहा—"तुमको एक वर्षमें अवस्य भारत वापस आ जाना चाहिये। हर चीज तय हो चुकी है। काला कान्न (ब्लैक ऐक्ट) रदः कर दिया जायगा । प्रवासी-कान्त (एसीग्रेशन ला) से जाति-भेद निकाल दिया जायगा । ३ पौण्डवाला कर समाप्त हो जायगा।" गान्धीजीके लिए, जिन्हें इस सरकारका भली भाँति अनुभव था, यह शत प्रति-शत विजयकी आशाका घूँट निगलना कठिन था। गान्धीजीने उत्तर दिया "मुझे बहुत सन्देह है। आप मन्त्रियोंको उतना नहीं समझते जितना में। आपकी तरह मुझे इस मामलेमें उतनी आशा नहीं है। परन्तु साथ ही मुझे कोई भय भी नहीं है। मेरे लिए यह काफी है कि आपने मन्त्रियोंने आखासन प्राप्त कर लिया है। आवस्य-कता पड़नेपर संवर्ष करना और यह प्रदर्शित करना कि हमारा पक्ष न्यायपूर्ण है मेरा कर्तव्य है। आपको दिया हुआ आखासन हमारी माँगींकी न्यायिषयता सिद्ध करनेमें सहायक होगा, और अगर आवश्यकता पड़नेपर संघर्ष करना पड़े तो इससे हमारी लड़नेकी भावनाको दूना वल मिलेगा । में नहीं समझता कि में एक वर्षके अन्दर भारत वापस लौट सकूँगा, कमसे-कम बहुतसे और भारतीयोंके जेल जानेके पूर्व तो में नहीं लोट सकूँगा।"

लेकिन गोखले गान्धीजीके इस भयको सही नहीं समझते थे और उन्होंने फिर कहा कि "जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वही होगा। जनरल बोधाने मुझसे वादा किया है कि काला-कान्न (ब्लैक ऐक्ट) रद कर दिया जायगा और ३ पीण्डवाला कर समाप्त कर दिया जायगा। मैं कोई भी वहाना नहीं सुन्ँगा, तुमको बारह महीनोंके अन्दर भारत अवस्य वापस आना पड़ेगा।"

गोखलेके वापस जानेके बाद जब आशाबादी भारतीय ३ पौण्डवाले करके रद किये जानेके लिए दक्षिणी अफ्रिकाकी पार्लमेंटमें आवश्यक नियम पेश किये जानेकी उम्मेद कर रहे थे, विधान सभामें अपनी जगहरे जनरल स्मट्सने कहा कि चूँकि नेटालके यूरोपीयोंको ३ पौण्डवाले करके रद करनेपर आपत्ति है, इसलिए यूनियन चरकार ३ पौण्डवाले करको रद करनेके लिए कान्न बनानेमें असमर्थ है।

इस कारण सत्याग्रह आन्दोलनका तोसरा कार्य ३ पौण्डका कर रद करवाना वन गया। इस नयी वातने सत्याग्रहको एक नया उत्साह प्रदान किया। सत्याग्रहमें भाग लेनेके लिए अब औरतोंने भी नाम लिखाना आरम्भ कर दिया। सितम्बर, सन् १९१३ में औरतोंके एक जत्थेने ट्रांसवालकी सीमा पार की और वह गिरफ्तार कर लिया गया। संवर्षमें औरतोंके भाग लेनेसे उत्साह पाकर और सरकारके रुखसे उत्तेजित होकर, ट्रांसवालकी सीमासे ३६ मील दूर न्यू कासिलकी कोयलेकी खानोंके भारतीय मजदूरोंने ३ पौण्डवाले करके विरोधमें हड़ताल कर दी। मजदूरोंकी संख्या करीव पाँच या छ हजार थी और सब सत्याग्रह करनेको तैयार थे। खानोंके मालिकोंने गान्धीजीको यह विश्वास दिलानेके लिए डरबन खुलाय कि करको रद कराना उनके वसके वाहरकी वात है। लेकिन गान्धीजीने कहा कि "मजदूरोंके पास सत्याग्रहके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। ३ पौण्डवाटा कर मालिकोंके हितमें लगाया गया है क्योंकि मालिक मजदूरींसे काम तो लेना चाहते हैं लेकिन यह नहीं चाहते कि वे स्वतन्त्र व्यक्तियोंके रूपमें काम करें। इसलिए ३ पौण्डवाले करको रद करानेके लिए मजदूर हड़ताल करते हैं तो मैं नहीं समझता कि यह मिल-मालिकोंके साथ कोई अन्याय या अनुचित वात है।"

गान्धीजीने तय किया कि सत्याग्रहियांकी यह 'सेना' २६ मील पैदल यात्रा करके ट्रांसवालकी सीमा पार करेगी । गान्धीजीके कथनानुसार यह भन्य यात्रा २८ अक्टूबर १९१३ को आरम्भ हुई । यात्राके लिए अनुशासनके नियम बना दिये गये जिनका प्रत्येक सत्याग्रही-को कड़ाईसे पालन करना पड़ता। २००० पुरुषों, १२२ औरतीं और ५० बच्चींका सत्याग्रहियोंका यह जत्था सीमाके पास चार्ल्सटाउनमें रुक गया । यहाँसे गान्धीजीने सरकार-को लिखा कि "सरयाग्रही ट्रांसवालमें वसनेकी दृष्टिसे नहीं आना चाहते, उनका उद्देश्य केवल मन्त्रीकी वादाखिलापीपर प्रभावशाली विरोध प्रकट करना और अपनी अप्रतिष्ठा या वेइ-ज्जतीपर क्षोभ प्रदर्शित करना है। यदि सरकार इमको चार्ल्यटाउनमें ही जहाँपर हम हैं, गिरफ्तार कर है तो हम सब तरहकी चिन्ता या आकुलतासे मुक्त हो जायँगे।" उन्होंने सरकारको यह भी आखासन दिया कि यदि कर रद कर दिया जाय तो हड़ताल समाप्त कर दी जायगी । इसके बाद गान्धीजीने इन्हीं बातोंके लिए स्मर्सको टेलीफोन किया, लेकिन जनरलके सचिवने उत्तर दिया, "जनरल स्मर्स तुमसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहते, तुम जो चाहे करो।" यात्रियोंमें दो औरतें अपने छोटे वच्चोंके साथ शामिल थीं। एक वच्चा तो सफरमें ही सर्दी लगनेसे मर गया और दूसरा बच्चा झरना पार करते समय अपनी माँ की वॉहोंसे गिरकर हुव गया । यात्रियोंमें गान्धीजी द्वारा सादा जीवन व्यतीत करनेके लिए परिवर्तित किया हुआ एक जर्मन कैलेनवॉख भी था। कैलेनवॉखको एक यूरोपीयने इन्द्र युद्धके लिए ललकारा । यद्यपि कैलेनवॉख कसरती था, उसने जवाब दिया "चूँकि मैंने शान्ति धर्मको अपना लिया है, इस कारण में तुम्हारी चुनौती स्वीकार नहीं कर सकता । जो भी चाहे मेरे साथ बरेसे बरा व्यवहार कर सकता है।'

यात्रा चलती रही । गान्धोजीको गिरफ्तार कर एक मजिस्ट्रेटके सम्मुख पेश किया गया । लेकिन गान्धीजीने जमानतके लिए दरखास्त दी और मजिस्ट्रेटको जमानत स्वीकार करनी पड़ी । जमानत इसलिए स्वीकार करनी पड़ी कि खूनके अपराधियोंके अतिरिक्त हाजिरीके लिए किसी भी अभियुक्तको जमानत दाखिल करनेका अधिकार प्राप्त था । गान्धी जी लोटकर फिर यात्रामें शामिल हो गये । अगले विश्राम-स्थलपर वे फिर गिरफ्तार कर लिये गये, परिणाम फिर वही हुआ । गान्धीजीके पाँच मुख्य सहकारी भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये । गान्धीजी तिवारा गिरफ्तार कर लिये गये । पोलक नामके एक यूरोपीयको गान्धीजीके स्थानपर यात्राका नेता नियुक्त किया गया । परन्तु दूसरे दिन ही १० नवस्वरको समस्त सरयाग्रहियोंको केद कर तीन विशेष रेलगाड़ियोंमें भरकर नेटाल वापस भेज दिया गया । पोलक और कैलेनबाँख भी जेलमें वन्द कर दिये गये । गान्धीजीपर डण्डोमें मुकदमा चलाया गया और उनको नौ माहकी सख्त कैदका हुक्म सुना दिया गया । गान्धीजीने स्वयं अपने विरुद्ध अभियोग सिद्ध करनेके लिए गवाह पेश करके सरकारी अभियोक्ताका कार्य आसान वना दिया ।

गान्धीजीकी गिरफ्तारीसे प्रवासी भारतीयोंमें एक उमंगकी लहर दौड़ गयी और उनमेंसे कितने ही नेटालकी सीमा पारकर ट्रांसवालमें घुसे। वे सब गिरफ्तार कर लिये गये।

अव उन तीन विशेष रेलगाड़ियोंका भी हाल देखा जाय। मजदूरींपर मुकदमा चलाकर उन्हें फौरन जेल भेज दिया गया। लेकिन साथ ही सरकारको यह खतरा पैदा हो गया कि अगर मजदूरोंको काम पर वापस नहीं भेजा गया तो खाने वन्द हो जायेंगी। इससे वचनेकी सरकारने एक तरकीव सोची। उसने खानोंके अहातोंको तारोंकी जालीसे े घेर दिया और कहा कि ये डण्डी और न्यूकॅसिल जेलोंके ही वाहरी हिस्से हैं। खानोंके मालिकोंके यूरोपीय कर्मचारी ही इन जेलोंके प्रहरी (वार्डर) नियुक्त कर दिये गये। लेकिन कैदी इस चक्करमें नहीं फँसे। उन्होंने काम करनेसे इनकार कर दिया। उनको वेरहमीसे कोड़े लगाये गये । घमण्डी लोग जिनको यह हुकूमत थोड़े ही दिनोंके लिए मिली थी, मजदूरोंको ठोकरें मारते और उनको गालियाँ देते। न सिर्फ यह बल्कि मजदूरोंको वे ऐसे कष्ट देते और ऐसा दुर्व्यवहार करते जिसका कहीं भी आजतक उल्लेख नहीं किया गया । परन्तु मजदूरीने यह तमाम कष्ट बड़ी शान्तिसे सहन किये । इन ज्यादितियों और निर्देयताकी खबर गोखलेको तार द्वारा भेजी गयी। गोखले संघर्षकी दिन प्रतिदिनकी खनरों के सम्पर्क में वरावर रहते । यदापि वे वहुत वीमार थे परन्तु उन्होंने रुग्ण-शय्यासे इस खबरका प्रचार किया । शोचनीय रुग्णावस्थाके होते हुए भी गोखलेने दक्षिणी अफ्रीका सम्बन्धी तमाम कामको देखभाल स्वयं करनेका आग्रह किया। आखिरकार समस्त भारत दक्षिणी अफ्रिकाकी घटनाओंसे उद्देखित हो उठा और यह प्रस्न सबसे मुख्य प्रस्न वन गया । इस समयके भारतके वॉइसराय हार्डिझने मद्रासके अपने १३ दिसम्बर १९१३ के भाषणमें न सिर्फ सार्वजनिक रूपसे दक्षिण अफ्रिकाकी सरकारकी कड़ी आलोचना की वृद्धि सत्याग्रहियोंका पूरे दिलसे संमर्थन किया, पृणित और अनुचित कानूनके विरुद्ध उनके सविनय अवज्ञा आन्दोलनके प्रति पूरी सहानुभूति प्रदर्शित की। ''इंगलैण्डमें लार्ड हार्डिञ्जके इस व्यवहारपर नुक्ताचीनी और आक्षेप किया गया । उन्होंने कोई पश्चात्ताप जाहिर नहीं किया विक अपने व्यवहार व रवैयेका औचित्य सिद्ध किया।"

हड़ताल, गिरफ्तारियाँ, केंद्र किये जाने और दमनकी खबर हर जगह फैल गयी "और हजारोंकी संख्यामें मजदूर अकस्मात और स्वतः प्रेरित होकर दक्षिण अफिकाके संघर्ष- की हिमायतमें उठ खड़े हुए।" सरकारने दमन, करल और खूँ की नीति अपनायी। उसने जबरदस्ती मजदूरोंको हड़ताल करनेसे रोका। घुड़सवार फौजियोंने मजदूरोंका पीछा किया और जबरदस्ती उनको कामपर घसीट लाये। मजदूरोंकी जरा सी भी काररवाईका जवाव रायफलकी गोली द्वारा दिया जाता था। मजदूरोंकी एक इकड़ीने जबरदस्ती कामपर वापस ले जाये जानेका विरोध किया। एक आधने पत्थर भी फेंके। उनपर गोली चला दी गयी। कुछ मारे गये और कई घायल हुए। लेकिन मजदूर इससे दवे नहीं। जो काम गोलियाँ नहीं कर सकीं वह समझाने बुझानेसे हो गया। एक पारसी सजनने मजदूरोंको कामपर वापस मेजनेका वीड़ा उठाया। उन्होंने मजदूरोंसे वात की और उन्हें कामपर वापस चले जानेके लिए समझानेमें सफल हो गये। दक्षिणी अफिकाके भारतीयोंका सवाल संसारव्यापी वन गया और यूनियन सरकार (यूनियन गवर्नमेण्ट) सभ्य संसारके लोकमतका विरोध न कर सकी। उसने (सरकारने) तमाम मसलेकी जाँच करनेके लिए एक जाँच-सिमिति नियुक्त

की और अपने दिलमें घृणित कान्नोंको रद करनेका निश्चय कर लिया। भारतीयोंने इस जाँच समितिका बहिष्कार किया क्योंकि उन्होंने जोर दिया था कि कम-से कम एक सदस्य भारतीय हो परन्तु यह प्रार्थना अस्वोकार कर दी गयी। समितिकी सिफारिशोंके आधारपर इण्डियन रिलीफ विल नामसे एक विधेयक पार्लमेण्टमें पेश किया गया। रे पोण्डवाला कर समाप्त कर दिया गया। वाकी दूसरी धाराएँ या तो रद कर दी गयीं या उनमें सुधार किये गये। गान्धीजी विजयी होकर १९१४ में भारत लीटे।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसमें गान्धीजी और उनके साथियों के साहिसक प्रयत्नोंकी तथा भारतके आत्मसम्मानकी रक्षाके लिए चलाये गये आन्दोलनमें उनके अद्वितीय- बल्दिनों और भारतीयोंकी शिकायत दूर करानेके प्रयत्नोंकी पूरी-पूरी प्रशंसा की गयी थी। कांग्रेसके इसके पहलेके अधिवेशनोंमें भी दक्षिणी अफिकाके प्रश्नपर बहस हुई थी तथा सहानुभूति और उत्साह-वर्धक प्रस्ताव पास हुए थे।

लेकिन दक्षिण अफ्रिकाके गान्धीजीके संवर्षका अन्तिम चरण अभी शेष था। १६ मार्च १९१६ को मदनमोहन मालवीयने केन्द्रीय विधान परिपदमें शर्तवन्दी प्रथा, जिसके अन्तर्गत भारतीय मजदूर दक्षिणी अफ्रिका मेजे जाते थे, खत्म करनेका प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव तो वॉइसराय महोदयने स्वीकार कर लिया परन्तु यह कहकर इसको वेकार कर दिया कि "यह व्यवस्था उचित समयकी अवधिमें तब खत्म की जायगी, जब मजदूरोंको भेजनेका इसकी जगहपर दूसरा उपयुक्त उपाय निकल आयेगा।" फरवरी १९१७ में मालवीयजीने फिर इस व्यवस्थाको तस्काल समाप्त करनेका प्रस्ताव पेश करनेकी अनुमित चाही, परन्तु वॉइसराय चेम्सफोर्डने अनुमित देना अस्वीकार कर दिया।

गान्धीजीने अब भारतव्यापी आन्दोलन चलानेका विचार किया और इसके लिए उन्होंने वम्बईसे यात्रा आरम्भ की। इम्पीरियल सिटीजनिश्चप एसोसियेशनके तत्वाधानमें एक सभा की गयी। सभाने एक प्रस्ताव द्वारा ३१ जुलाई अन्तिम तिथि निश्चित कर दी कि सरकार तवतक यह व्यवस्था समाप्त कर दे। दो सुझाव पेश किये गये थे, एक तो व्यवस्थाको 'तत्काल समात' करनेका था और दूसरा 'जितनी जल्दी' सम्भव हो। लेकिन गान्धीजीने कहा कि चूँकि इन वाक्योंके गलत अर्थ लगाये जा सकते हैं, इस कारण कोई तिथि अवश्य निश्चित कर देनी चाहिये। दूसरे सुझावोंके प्रस्तावकोंने गान्धीजीकी यह वात मान ली। वम्बईकी सभाने अगुआई की और देश भरमें सभाओं द्वारा यही प्रस्ताव स्वीकार हुआ। गान्धीजी कराची, कलकत्ता, अन्य दूसरी जगहें गये, वहाँ सभाएँ की और गान्धीजीके शब्दोंमें 'सभाओंमें असीम उत्साह था।' पुल्सिक खुफिये वरावर उनका पीछा करते रहे। एक मर्तवा तो उन्होंने गान्धीजीको कई रेल्वे स्टेशनोंपर परेशान किया।

लेकिन गान्धीजी फिर विजयी हुए । जुलाई ३१ के पहले ही सरकारने घोषणा कर दी कि भारतसे मजदूर अब विदेश न भेजे जायँगे।

अध्याय १४

काँग्रेस-लीग एका--लखनऊ समझौता

मुस्लिम लीगके दिसम्बर १९१० के नागपुर अधिवेशनके वादके दस वर्ष राष्ट्रीय एकता और अमृतपूर्व राजनीतिक चेतनाके दौरका समय है। इस दौरमें हम मुस्लिम नेताओं को अपने कन्धोंसे अंग्रेजी जुआ उतारकर कांग्रेसके साथ कदम मिलानेके लिए तेजीसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं। यह परिवर्त्तन नागपुर अधिवेशनके अध्यक्ष सैयद नवीड़क्लाके भाषणसे आरम्भ हुआ। उन्होंने नौकरशाहीपर आक्षेप करते हुए दावा किया कि सिविल सर्विक अफसर मतभेद पैदा करनेके लिये जिम्मेदार हैं। उन्होंने अभीतककी मुस्लिम राजनीतिको छोड़ दिया और कहा कि फौजी व्यय आवश्यकतासे अधिक है तथा माँग की कि सीमा-स्थित सेनाकी संख्यामें कमी की जाय। अधिवेशनने हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए कुछ व्याव-हारिक कदम उठानेका निश्चय किया। १९१० के कांग्रेस अधिवेशनके वाद हिन्दू और मुस्लिम नेताओंने जनवरी १९११ में इलाहाबादमें एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलनसे विशेष लाम तो न हुआ परन्तु भविष्यकी समझौता-वार्ताके लिए पृष्ठभूमि तैयार हो गयी।

कुछ ही समय वाद वंग-भंगका अन्त करनेकी सम्राटकी घोपणा हुई। हिन्दू प्रसन्न हुए । परन्तु मुसलमानोंके अंग्रेजोंके प्रति विश्वासको इस घोषणासे वहुत तीव धक्का लगा । मुसलमानोंका समाधान घोषणासे किस प्रकार होता, जब कि लार्ड कर्जनने उन्हें बार-बार वतलाया था कि पूर्वी वंगालका निर्माण उन्हींके लाभके लिए किया गया है और जिसके निर्माणमें हिन्दू और मुसलमानोंका इतना अधिक रक्त साम्प्रदायिक दंगोंमें वह गया हो। आगाखाँकी सलाहके वावजूद कि वंगभंगका अन्त मुसलमानोंके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, मुसलमानोंका बहुमत इसको बहुत वड़ा अपकार समझता था। नवाव सलीमुल्लाने, जिन्होंने मार्च १९१२ में हुए कलकत्तेके लीगके अधिवेशनकी अध्यक्षता की थी, सम्राटकी घोषणापर क्षोभ प्रकट करते हुए कहा कि नये प्रांत (पूर्वी वंगाल) से मुसलमानोंको कोई अतिरिक्त लाभ तो हुआ नहीं, हाँ, इस विभाजनने हिन्दू और मुसलमानोंके वीच एक खाई अवस्य पैदा कर दी है। उन्होंने दावा किया कि यह कहना असत्य है कि हिन्दू-मुस्लिम मतभेदोंका कारण विभाजन है। असली कारण तो अंग्रेजोंके विरुद्ध कान्तिकारी कार्योमें मुसलमानों द्वारा हिन्दुओंका साथ देनेसे इनकार करना था। अध्यक्षके भाषणमें निश्चित रूप में आत्म-आलोचनाका भाव सन्निहित था। चारों तरफ नैरास्य फैला हुआ था। मुसलमानों को अंग्रेजोंके वार्दोका अव भरोसा टूट रहा था। मुसलमानोंको हानि पूरी करनेके लिए यह कोशिश की गयी कि ढाका विस्वविद्यालयको मुस्लिम विद्वविद्यालय करार दे दिया जाय। इस सिलसिलेमें एक शिष्टमण्डल लेपिटनेण्ट गवर्नरसे मिला । लेकिन इस विचारका हिन्दुओंने विरोध किया स्योंकि ग्रद्ध इस्लामी विश्वविद्यालयके विचारको वे (हिन्दू) हानिकर समझते थे। अलीगढ़ कालेजको मुस्लिम विश्वविद्यालयमें परिणत करनेके लिए हिन्दू-मुसलमानों ने धन एकत्रित करना आरम्भ कर दिया था, क्योंकि कुछ मुसलमान अंग्रेजोंके प्रति संघटित

हो चुके थे और अंग्रेजी प्रकारका विश्वविद्यालय नहीं चाहते थे। इसी बीच हिन्दुओंका एक वर्ग हिन्दू विश्वविद्यालय कायम करनेमें प्रयत्नशील या । अधिक सुविधाओं के कारण बनारस-में वे हिन्द विश्वविद्यालय खापित करनेमें समर्थ हो गये, जब कि मुस्लिम-विश्वविद्यालय अभी-तक केवल स्वप्न ही था । सन् १९११ से दूसरे मुस्लिम देशोंकी घटनाओंने भारतके मुस्लिम नेताओं का प्यान अधिक आकर्षित करना आरम्भ कर दिया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि उनकी अंग्रेजोंके प्रति भक्ति अब खिलाफत आन्दोलनके केन्द्र तकींके प्रति परिवर्तित हो। गयी है। तुर्की साम्राज्य संकटोंसे गुजर रहा था, हिलाल खतरेमें था। १९११ के पतझड़में इटलीने तुर्कांके खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया और ट्रिपोलीपर विना किसी वहानेकी आड्के आक्रमण कर दिया । भारतीय मुसलमान भी इस घटनासे कृद्ध हो उठे क्योंकि उनका विस्वास था कि यदि पूर्णतया नहीं तो आंशिक रूपसे अंग्रेज भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। सन् १९१२ में वास्कानकी ताकतोंने जिन्होंने तुकींके खिलाफ ददतारे युद्ध करनेके लिए वाल्कन लीग (Balkon League) वना ली थी, युद्धमें ६ लाखरे जपर फौजी ितपाहियोंको लगा दिया और काँस्टेण्टिनोपलको छोड़कर शेप तुर्काको ध्वस्त कर दिया। "भारतीय मुसलमानोंमें तुकांके प्रति आश्चर्यजनक रूपमें सहानुभृति उगड़ पड़ी। यों तो आक्रमणसे पृरे भारतमें सहानुभृति और आकुलता पैदा हो गयी थी, परन्तु मुसलमानोंमें तो वेहद आकरता थी और प्रतीत होता था कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है। डा॰ एम. ए, अन्सारीके नेतृत्वमें डाक्टरोंका एक शक्तिशाली मिशन तुकों गया। गरीवोंने चन्दा दिया ! जिस तेजीसे इस कार्यके लिए रुपया इकट्टा हुआ, उस प्रकार भारतीय मुसलमानीने कंभी अपने उत्थानके लिए नहीं किया या। प्रथम महायुद्ध मुसलमानोंके लिए वडी गृद समस्याका समय था क्योंकि तुर्का धरी राष्ट्रीका साथ दे रहा था। भारतीय मुसलमान अस-हाय थे और कोई सहायता न दे पाये । युद्धकी समाति पर उनकी दवी हुई भावनाएँ खिला-फत आन्दोलनके रूपमें एकदम उवल पड़ीं।"

लेकिन तुर्कीकी आंतरिक राजनीतिक कारण भारतीय मुस्लिम नेता दो तरफ वॅट गये। तुर्कीके नौजवान, जिन्होंने पिहचमके राजनीतिक विचारोंको अपना लिया था, यह चाहते थे कि मुल्तान अन्दुल हमीद तुर्कीको आधुनिक बनायें। उन्होंने एकता और प्रगति संव (जिमको आमतौरपर 'नौजवान तुर्क' कहते थे) नामी एक संस्था स्थापित की और जब उन्होंने देखा कि मुल्तान उनकी माँगोंको माननेको तैयार नहीं हैं तो उन्होंने कांतिकारी कायोंका आश्रय लिया और मुस्तानपर आधिपत्य जमा लिया। भारतके अधिकांश मुसलमानोंको यह बात पसन्द नहीं आयी और उनकी सहानुभृति मुस्तानके साथ थी। लेकिन ऐसे भी मुसलमान थे, यद्यपि वे अल्पमतमें थे, जिन्होंने 'नौजवान तुर्क' (दंग टक्सं) के इस कार्यका स्वागत किया, क्योंकि इससे वैधानिक और जीमाजिक मुधारोंकी आया बलवती हो गयी थी और भारतीय मुसलमानोंके सामने अनुसरण करनेके लिए एक आदर्श उपस्थित हो गया। मौलाना आजाद भी हमी अल्पमतमें थे। आजादकी पारिमक शिक्षा काहिराके अल्य अन्हर विद्वविद्यालयमें हुई थी। वे अभी नवयुवक ही थे कि अपनी अरबी व फारसीकी विद्वत्ताके लिए प्रसिद्ध हो गये। इस्लामी परग्पराओं में पले मौलाना आजाद मिस्न, तुर्की, सीरिया, फिलस्तीन, इराक और ईरानके मुख्य मुस्लम

नेहरू-वही पुस्तक (दिस्कवरी ऑफ इण्डिया) पृष्ठ-३००

नेताओंके व्यक्तिगत सम्पर्कमें आये और इन मुल्कोंके राजनीतिक और सांस्कृतिक विकासने इनपर बहुत शक्तिशाली प्रभाव डाला। जिन युद्धोंमें तुर्की सम्मिलित हुआ, उनके लिए आजादके दिलमें बहुत हमदर्दा और दिलचस्पी थी। अपने विचारोंके प्रचारके लिए आजादने चौबीस वर्षकी उम्रमें 'अलहिलाल' नामका एक साप्ताहिक पत्र निकाला। पत्रके लेखोंको सरकार पसन्द नहीं करती थी। प्रेस कानून (प्रेस ऐक्ट) के अन्दर्गत अखवारसे जमानत माँगी गयी और आखिरकार सन् १९१४ में छापेखानेको सरकारने जन्त कर लिया। मौलाना आजादने एक दूसरा साप्ताहिक 'अल-वालग' निकाला जिसको सरकारने १९१६ में बन्द कर दिया। मौलाना आजाद कैद कर लिये गये और वे लगभग चार सालतक नजरबन्द रहे । १९१२ में अंग्रेजीमें एक दूसरा साप्ताहिक 'कॉमरेड' निकला । मौलाना मुहम्मद अली इसके सम्पादक थे। मौलाना अपने राजनीतिक जीवनके आर्ग्ममें 'अलीगढ़-विचार धारा' के अनुयायी थे, और उग्र राजनीतिके विरोधी थे। "१९११ में वंग-भंगके रद किए जानेसे उनको एक प्रबल आघात लगा और अंग्रेजोंकी नेकनीयतीमें उनका विश्वास डोल गया । वाल्कन युद्धने उनको उद्देलित कर दियां और उन्होंने उद्देगमें, तुकीं और इस्लामी परम्पराओंपर जिनका तुकीं प्रतिनिधित्व करता था, कई लेख लिखे। धीरे-धीरे वे अधिक अंग्रेज-विरोधी होते गये और प्रथम महायुद्धमें तुर्कांके प्रवेशसे यह कम पूरा हो गया। 'कॉमरेड' में प्रकाशित एक प्रसिद्ध लेख 'तुकींका निर्णय' ने अखवारका अन्त कर दिया। सरकारने 'कॉमरेड' का प्रकाशन वन्द कर दिया। इसके फौरन बांद ही सरकारने मौलाना मुहम्मद अली और उनके भाई शौकत अलीको जेलमें डाल दिया। ये दोनों युद्धकाल और उसके एक वर्ष बादतक नजरबन्द रहे । १९१९ के अन्तमें दोनों मुक्त हुए और तत्काल ही राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गये।"

इन घटनाओंका प्रभाव अलीगढ़ कॉलेजके विद्यार्थियोंपर पड़ना अनिवार्य था। १९१२ के बाल्कन युद्धसे वे इतने उद्देलित हो उठे कि कप्टमें पड़े हुए तुर्कीकी सहायताके लिए अपने खानेमेंसे पैसे बचाते। तुर्कीके पक्षमें उत्साहकी इस लहरसे कुछ मुस्लिम सरकारी नौकर घवड़ा उठे, यहाँतक कि उन्होंने तुर्की टोपियाँ पहनना छोड़ दिया।

१९१३ तक कांग्रेसके पार किये हुए पथपर लीग मी काफी आगे वढ़ चुकी थी। उसी वर्ष मार्चमें मुहम्मद शफीकी अध्यक्षतामें लखनऊमें लीगका वार्षिक अधिवेशन हुआ। इससे एक नवीन मुस्लिम राजनीतिक युगका आरम्भ होता है। लीगके विधानमें संशोधन कर इसको शुद्ध राजनीतिक संघटन बना दिया गया। अभीतक इसके उद्देश्य थे कि "भारतीयों में ताजके प्रति भक्ति बढ़ायी जाय, मुसलमानों के हितों की रक्षा की जाय, और विना ऊपर लिखे उद्देश्यों को हानि पहुँचाये भारतके लिए उपयुक्त स्वायत्त शासन हासिल किया जाय।" मुख्य प्रस्तावों में मजहरूल हक द्वारा पेश किया हुआ प्रस्ताव भी था जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय उन्नतिके लिए हिन्दू और मुसलमानों को कन्धेसे कन्धा मिलाकर काम करना चाहिये। बहुतसे कांग्रेसी नेता, जिनमें सरोजिनी नायह भी शामिल थीं, अधिवेशनमें उपस्थित थे। बहुतसे मुस्लिम नेता तो लीगको और आगे ले जाना चाहते थे। शिवली नौमानी जैसे लोगोंने लीगके विधानमें 'उपयुक्त' शब्दकी खिल्ली उड़ाते हुए कविताएँ लिखीं। लेकिन इन्हीं शिवली नौमानीने १९०८ में "एक बहुत विद्वत्तापूर्ण लेखमें

१. नेहरू, वही पुस्तक, पृष्ठ ३०२

यह सिद्ध किया था कि शासक सत्ताके प्रति भक्ति रखना मुसलमानोंका धार्मिक कर्तव्य है।"

सर इत्राहीम रहमतुल्लाकी अन्यक्षतामें दिसम्बर, १९१२ में लीगका वार्षिक अधि-वेशन आगरेमें हुआ | हिन्दू और मुसलमानोंके पारस्परिक सम्बन्ध अच्छे रखनेपर फिर जोर दिया गया | लेकिन आखिरकार लीग केवल मुसलमानोंका संघटन थी और इस वातका प्रतिविम्ब प्रस्तावोंपर पड़ना अनिवार्य था | एक प्रस्ताव द्वारा फैजाबादके जिलाधीशकी साम्प्रदायिक झगडा रोकनेके लिए गौ-वध रोकनेकी आज्ञाकी निन्दा की गयी | एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा स्थानीय संस्थाओं में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वको बढ़ानेकी माँग की गयी | कान-पुरकी १९१३ की एक घटनाने मुसलमानोंके अंग्रेजोंके प्रति कोधको और बढ़ा दिया | स्थानीय अधिकारियोंने अपनी सड़क बनानेकी योजनाके अन्तर्गत एक मस्जिदका कुछ हिस्सा गिरवा दिया | इस घटनासे मुसलमानोंके धार्मिक भाव उत्तेजित हो गये और वे फीरन ही घटनास्थलपर जमा हो गये | भीड़से तितर-वितर होनेको कहा गया और उसके इनकार करने पर गोली चला दी गयी | हिन्दुओंने गोलीकाण्डकी निन्दा और मुसलमानोंके प्रति सहानुभृति प्रकट की |

सन् १९१४ में लीगका कोई अधिवेशन नहीं हुआ। अगले वर्प श्रीमजहरूल हक्की अध्यक्षतामें अधिवेशन वम्बईमें हुआ। श्री जिन्नाके प्रस्तावपर, दूसरे समाजोंके साथ परामर्शकर राजनीतिक सुधारोंकी योजना वनानेके लिए एक समिति नियुक्त की गयी। कांग्रेस और लीगके एक दूसरेके इतना नजदीक आ जानेसे आगा खाँको वहुत परेशानी हुई और उन्होंने लीगसे त्यागपत्र दे दिया। १९१५ के वर्षमें मुसलमानों और अंग्रेजोंके वीचकी खाई और अधिक वढ़ गयी। तुर्की के पक्षका समर्थन करनेके अपराधमें, मुहम्मद अली, शोकल अली और अबुल कलाम आजादके अतिरिक्त और कई मुस्लिम नेताओंको कैदकर नजरवन्द कर दिया गया। ये नेता, सैयद फजलुल इसन, हसरत मोहानी, महमूद हसन, हुसैन अहमद मदनी व अजीज गुल थे। आखरी तीन नेता जहाजपरसे कैद करके मालटामें नजरवन्द कर दिये गये। किय मुहम्मद इक्वाल ऐसे भी लोग थे, जो इतने अधिक भयंकर न समझे गये और इस बजहसे वे वच गये। किय इक्वाल इस्लामके और तुक्तिके कहर समर्थक थे और उन्होंने ''तुक्मन नं० १'' अँग्रेजोंके विचद कई कठोर और ममंभेदी कविताएँ लिखीं।

तस्वीरका दूसरा रुख देखनेके लिए हमें सर सैयद अहमद और नवाव मोहिसनुल-मुहकके तुर्कीके प्रति भावोंको देखना पहेगा। मृत्युसे कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने पान-इस्लामी उन्मादमें बढ़े हुए मुसलमानोंकी अंग्रेज-विरोधी भावनाके विरुद्ध संवर्ष किया। उन्होंने 'अलीगढ़ इन्स्टीटयूट-गजट' में लेख लिखकर मुन्तानके खलीफाके पदके अधिकारका खण्डन किया और मुसलमानोंको यह समझाया कि यदि भारतके अंग्रेज शासक लाचारीसे तुर्कीके प्रति मैत्रीपूर्ण नीति न वरत सके तो भी उनके प्रति वकादार रहना चाहिये। सन् १९०६ में नवाव साहवने घोषणा की कि भारतीय मुसलमानोंके खलीफा तुर्कीके मुन्तान नहीं हैं। उन्होंने इसपर जोर दिया कि अंग्रेजोंके प्रति राजभक्त रहना मुसलमानोंका धार्मिक कर्तव्य है।

१९१५ में लीगके अधिवेशनके अध्यक्षने अपने भाषणमें कहा—"अंग्रेजी सम्राटकी सुरक्षामें देशकी जरूरतों और आवश्यकताओं के उपयुक्त स्वायत्त शासनकी माँगकी आवश्यकता है।" उनका भाषण इन शब्दोंके साथ खत्म हुआ "हमें दुःल है कि हमारे खलीफाकी सरकार हमारे सम्राटके साथ युद्धमें संलग्न है। हमें अपने साथी धर्मा-

विलम्वयोंको अंग्रेजी सैनिकॉस कन्धेसे कन्धा मिलाकर लड़ते देखकर प्रसन्नता होती। युद्ध के बारेमें अपनायी गयी इस्लामी देशोंकी नीतिके बारेमें किसीकी कोई भी राय क्यों न हो, भारतीय मुसलमानोंकी न कभी यह इच्छा रही है और न हो सकती है कि अंग्रेजी और इस्लामी सरकारोंके बीच शत्रुता पैदा हो जाय। और मुसलमानोंका यह सबसे वड़ा दुर्भाग्य है कि दोनोंमें शत्रुता पैदा हो गयी है। मेरी तफसीलमें जानेकी कोई इच्छा नहीं है लेकिन हमारे सहयोगी धर्मावलम्बियोंके बहुत बड़े बहुमत और काफी संख्यामें अंग्रेजोंका भी ख्याल है कि यह शत्रुता ब्रिटेनकी पिछली वैदेशिक नीति और क्टनीतिज्ञताकी असफलताका परिणाम है। खेर! जो भी हो, इस्लामके अनुयायियोंकी यह आन्तरिक उत्कट इच्छा है, कि जब भी अमन आये—और खुदासे दुआ माँगते हैं कि जल्दसे जल्द अमन कायम हो — मुस्लिम देशोंके साथ इस प्रकारका ब्यवहार न किया जाय जो उनके लिए अपमान-जनक हो।"

अगले वर्प लीग और कांग्रेसने अंग्रेजोंका सामना संयुक्त मोर्चा वनाकर किया। इस दौरतक आनेके लिए कांग्रेसके पिछले तीन वर्षोंके इतिहासपर दृष्टि डालना आवस्यक है। सन् १९१३ में कांग्रेसका अधिवेशन कराचीमें नवाव सैयद मुहम्मदकी अध्यक्षतामें संपन्न हुआ। वे खान वहादुर और जागीरदार थे, और सत्तरह वर्षीतक प्रान्तीय अथवा केन्द्रीय विधान परिपदोंके सदस्य रह चुके थे। वे १८९४ से कांग्रेसके अधिवेशनोंमें सम्मिलित होते आ रहे थे और १९१५ में इसके महामन्त्री वने। अपने अन्तरतलतक राजभक्त, उन्होंने अंग्रे जोंके पक्षका औचित्य सिद्ध करनेकी चेष्टा की । "हम जो कुछ भी उन्नति करनेमें समर्थ हो सके हैं" उन्होंने कहा, "और मैं कह सकता हूँ कि गत ५० वपोंमें हमने विलक्षण उन्नति की है, इन सबका अधिकतर श्रेय हमारी सरकारकी प्रगतिशील प्रवृत्तियों और जनताकी जरूरतों और आकांक्षाओंके प्रति सहानुभृतिको है।" उन्होंने तो यहाँतक कहा कि "लड़ाओ और राज्य करो" की नीति सरकारकी नहीं है। अपने समर्थनमें उन्होंने भारत सचिवके भाषणका (जो उन्होंने उसी वर्ष लोकसभामें किया था) उल्लेख किया जिसमें लॉर्ड मांटेग्यूने कहा कि "मैं यह बात जोर देकर कहता हूँ कि यदि मुस्लिम और हिन्दू समाजके नेता आपसमे मिल वैठकर, अपने वीचमें भिन्न परंपराओं और विचारोंमें मतभेदके कारण समय समयपर उठनेवाले सवालोंको तय कर लें तो सरकार उन्हें सहयोग देनेको सर्वदा प्रस्तत है।" नवाव सैय्यद मोहम्मदका विश्वास था "अंग्रेजी सरकारकी रक्षामें उन्नतिकी ऐसी कोई सीमा नहीं है जो हम पा न सकें।"

हिन्दुओं और मुसलमानोंके मतभेदोंका विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि मुसल-मानोंके राजनीतिक दृष्टिसे पिछड़े होनेका कारण उनका शिक्षामें फिसड्डीपन है। उन्होंने हिन्दुओंसे अपील की कि उन्नति और प्रगतिमें वाधक शिक्षाकी असमानताको हटावें।

कराची अधिवेदानने कांग्रेसके आगामी अधिवेदानके लिए कांग्रेस लीग-एकताका रास्ता पक्का कर दिया । कांग्रेस और लीगके अधिवेदानों में नेताओंने एकता करनेकी भावना प्रकट की । इस वातपर जोर दिया गया कि दोनों संघटनों और समाजोंके आदर्ज समान हैं । दोनों पक्ष इस वातका ईमानदारीसे विश्वास करते थे कि 'दोनों की समान मातृभूमिकी उन्नति सब लोगोंके स्वेच्छापूर्वक सहयोगपर निर्भर है ।"

[्]१. लवेटसे उद्धत, वही पुस्तक (ए हिस्ट्री ऑव दि इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेण्ट) पृष्ठ १०१-१०२

कांग्रेसने माँग की कि भारत सचिव और उसकी कार्यकारी सिमितिमें सुधार किया जाय और उनकी तनस्वाह अंग्रेजी खजानेसे दी जाय । यह प्रस्ताव मोहम्मद अली जिनाने पेश किया था । जिनाने भारत सचिवका जिक करते हुए कहा कि "वे भारतके किसी भी मुगल शासकसे बड़े मुगल हैं।" प्रस्तावमें माँग की गयी थी कि कार्यकारों समितिमें कुछ तो चुने हुए सदस्य हों और कुछ नामजद। निर्वाचित सदस्योंको केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिपर्दोंके निर्वाचित सदस्य चुनें।

१९१४ में जब प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हो गया तो कुछ लोगोंने राय दी कि कांग्रेस अधिवेदान करनेसे सरकारको हैरानी होगी। हेकिन कांग्रेस अधिवेदान, जैसा कि स्वागत समितिके अध्यक्षने कहा, सम्राटके प्रति अडिंग भक्ति और प्रेमका आखासन देनेके लिए हुआ। युद्धकी घोषणाके पूर्व कुछ कांग्रेसी नेताओंने जो उस समय भारत कार्यकारी (इंडिया कोंसिल) के प्रस्तावित सुधारोंके सिलसिलेमें लन्दनमें थे, एक शिष्टमण्डल वनाकर भारत राचिवके द्वारा एक पत्र सम्राटको लिखा। शिष्टमण्डलमें सर्वश्री एम. ए. जिना, लाजपतराय ,एन एम. समर्थ, बी. एन. शर्मा और एस. एस. सिनहा थे। उन्होंने "वाहरी दुश्मनके खतरेके समय अंग्रेजी सिंहासनको" भारतकी पूर्ण राजमक्तिका विश्वास दिलाया और कहा कि "भारतीय जनता स्वेच्छासे और सम्पूर्ण योग्यतासे सरकारके साथ सहयोग करनेको सहर्प प्रस्तुत है, और सरकारको अपनी सेवाएँ स्वीकार करनेका अवसर देनेकी इच्छुक है।'' गान्धीजीने भी जो युद्ध-घोषणासे पूर्व लन्दन आ गये थे, भारत उप-सचिव (अंडर सेकेटरी आव स्टेट फार इण्डिया) को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने लिखाः— "सम्राटके संकटके समय, हममेंसे बहुतोंने श्रेयस्कर समझा कि जब बहुतसे थॅंग्रेज अपना काम-धाम छोड़कर सम्राटकी सेवा करनेके लिए आ रहे हैं, तो हम भारतीय जो विटेनमें रहते हैं, और जिनके लिए सम्भव हो, तुरत ही विना चर्त लगाये साम्राज्यकी सेवाके लिए प्रस्तुत हो जावँ । अपनी तरफ़रे और उनकी तरफ़रे भी जिनके नाम परिशिष्टमें दिये गये हैं, अधिका-रियोंको हमारी सेवाएँ अर्पित हैं । हम आशा करते हैं कि कियुके माननीय मारिक्वस हमारा प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। इस सादर इस वातपर जोर देना चाहते हैं कि इस समय जो विचार सर्वप्रथम हमारा पथ-प्रदर्शन कर रहा है वह यह है कि हम जो कुछ भी धुद्र सहायता दे सकनेके योग्य समझे जायँ, दें, जिससे हम सिद्ध कर दें कि यदि हम इस महान साम्राज्यकी सदस्यताकी विशेष मुविधाओंका उपभोग करनेके इच्छ्क हैं तो उसकी जिम्मेदारियोंमें भी हिस्सा छेनेको तैयार हैं।

अवधिकी लगभग पूर्रा समासिपर तिलकको माण्डले केलसे रिहा कर दिया गया था । छूटने पर वे कांग्रेसमें फिर शामिल होना चाहते थे, परन्तु नरमदलीयकी हैिस्यतसे नहीं । उनका तीन सूत्री कार्यक्रम था (१) कांग्रेसका आपसी समझोता। (२) राष्ट्रीय दल (नैशनलिस्ट पार्टी) का पुनस्संयटन और होमकल (स्वशासन) के लिए उद्देलन प्रारम्भ करनेके लिए भूमि तैयार करना।

कार्यक्रमके पहले सूत्रको ही कार्यान्यित करनेके लिए आवश्यक था कि कांग्रेस प्रति निधियोंके:चुनावके क्षेत्रको विस्तृत किया जाय। १९०७ की फूटके बादसे कांग्रेसमें केवल नरम दलवाले ही रह गये थे और सिर्फ नरमदलीय विचारधाराकी संखाओंको प्रतिनिधियोंका चुनाव करनेके लिए निर्वाचक मण्डल (इलेक्टोरल कालेकेज) की मान्यता मिली हुई थी। तिलक चाहते थे कि कांग्रेसिवधानमें संशोधन कर दिया जाय ताकि राष्ट्रीय दलके लोगोंको भी प्रतिनिधि चुने जानेका अधिकार प्राप्त हो । कुछ नेता इस संशोधनसे सहमत थे परन्तु गोखलेने इसका विरोध किया । गोखले समझते थे कि तिलकके कांग्रेसमें सम्मिलित होनेका अर्थ पुराने संपर्पकी पुनरावृत्ति होना ही होगा । पहले उन्होंने संशोधनके पक्षमें अपना मत दिया था, परन्तु फिर सोचकर अपना विचार वदल दिया । वास्तवमें संशोधन श्रीमती वेसेण्टने पेश किया । वेसेण्ट अभी हालहीमें कांग्रेसमें शामिल हुई थीं और वे नरम और राष्ट्रीय दलके लोगोंको एक साथ लानेके लिए प्रयत्नशील थीं । १९१४ में भूपेन्द्रनाथ वसुकी अध्यक्षतामें कांग्रेस अधिवेशन मद्रासमें हुआ । प्रथम

वार सम्राटके प्रतिनिधि (मद्रासके गर्वनर) अधिवेशनमें सम्मिलित हुए और उसकी काररवाईमें भाग लिया। जैसे ही वे पंडालमें आये, उपिथत लोगोंने खड़े होकर उनका स्वागत किया। सम्राटके प्रति कांग्रेसकी वफादारोका विस्वास दिलाते हुए एक प्रस्ताव पेश किया गया। ऐसा प्रवन्ध किया गया कि यह प्रस्ताव उस समय पेश किया जाय जव गवर्नर महोदय अधिवेशनमें पधारें । इस प्रस्ताव द्वारा 'अंग्रेजी सरकारके प्रति अट्ट भक्ति' प्रगट की गयी। युद्धक्षेत्रमें भारतीय सिपाहियोंकी वीरतासे सुरेन्द्रनाथ वनर्जी जैसे लोगोंके हृदयोंमं यह आज्ञा पैदा हो गयी थी कि इसका राजनीतिक पुरस्कार मिलेगा। लेकिन दूसरे लोगोंका विचार था कि 'स्वशासन' भारतका अधिकार है और अधिकारस्वरूप ही यह हमें मिलना चाहिये, पुरस्कारके रूपमें नहीं । इसी विचारको और अधिक विकसित करते हुए श्रीमती वेसेण्टने अनुग्रह पुरस्कारके प्रश्नपर वोलते हुए कहा कि "यहाँपर भारतकी राज-भक्तिका पुरस्कार मिलनेकी वात कही गयी है। परन्तु भारत सौदा और मोल भाव नहीं करेगा कि अपने सपूर्तोंके रक्त और अपनी सुपुत्रियोंके अमृत्य आँसुओंके वदले हमको स्वराज्य दिया जाय । साम्राज्यकी प्रजा होनेके नाते भारत अपना अधिकार माँगता है, न्याय माँगता है। भारतने यह अधिकार युद्धसे पूर्व माँगा था । भारत युद्धकालमें वही माँग कर रहा है। भारत युद्ध समात होने पर भी यही अधिकार माँगेगा । लेकिन पुरस्कारके रूपमें नहीं, वल्कि अधिकारके रूपमें । इस सिलसिल्में कोई मिथ्या धारणा नहीं हो सकती।'' यद्यपि यह वात स्पष्टतया सामने नहीं आयी, परन्तु अधिवेशनमें किये गये भाषणोंकी पृष्ठभ्मिमें यह प्रश्न वरावर उठता रहा कि—भारत आखिर किस लिए युद्ध कर रहा है ? अगर भारत साम्राज्यके लिए युद्ध कर रहा है, तो उसका पद वही होना चाहिये जो साम्राज्यके अन्य सदस्य राष्ट्रीका है। कांग्रेसने एक प्रस्ताव पास किया-"वर्तमान संकटमें प्रदर्शित भारतीय जनताकी अटूट और गहरी राज भक्तिको देखते हुए, कांग्रेसका यह अधिवेशन सरकारसे अपील करता है कि वह इस भित्त और निष्ठाको स्थिर बनाये । सम्राटके भारतीय और दूसरे प्रजाजनों के बीचके ईर्घा उत्पन्न करनेवाले भेदोंको मिटाकर, २५ अगस्त १९११ को खरोतेमें किये गये वादोंको पूराकर, औ ऐसे कदम उठाकर जिनसे भारतको साम्राज्यसंघके योग्य सदस्यकी मान्यता मिल सके औ जनताके अधिकारोंका सम्पूर्ण और स्वतंत्र उपभोग किया जा सके, भारतकी राज भक्तिकं साम्राज्यके लिए बहुमूल्य एवं स्थायी सम्पत्तिमें परिणत कर दे।" प्रस्तावका समर्थन करते हुए श्रीमती वेसेण्टने कहा कि ''अगर कलका वढ़ा हुआ वोअर लोगोंका राष्ट्र जिन्होंने अंग्रेजोंक विरुद्ध युद्ध किया, इस योग्य समझा जा सकता है कि उसको स्वतन्त्रता मिले तो भारत, ज इंगलैण्डके लिए युद्ध कर रहा है और जिसकी महान प्राचीन परम्पराएँ हैं, क्यों नहीं इस योग हो कि उसे स्वतन्त्रता मिले, वसुने राष्ट्रपतिके पदसे भाषण करते हुए कहा कि 'देशका शासन अभीतक विदेशी सिविल-सर्विसके हाथमें है। लगभग १४०० सिविल-सर्विसके हाकिमोंमें केवल ७७ भारतीय हैं। उन्होंने माँग की कि भारतीयोंको हथियार रखनेका हक दिया जाय, फौजमें जिम्मेदारीके पद दिये जावँ, साम्राज्यकी सेवामें नेतृत्व ग्रहण करनेका अवसर मिले, और अपने घरोंकी रक्षाके लिए स्वयंसेवकोंकी सेना बनानेका अधिकार दिया जाय।" एक प्रस्ताव द्वारा हथियार-कानृत (आर्म्स ऐक्ट) में संशोधन करनेकी तथा अन्य प्रस्ताव द्वारा प्रान्तीय स्वराज्यकी माँग की गयी।

सन् १९१५ में कांग्रेसका तीसवां अधिवेशन वम्बईमें वाइसरायकी कार्यकारिणीके प्रथम भारतीय सदस्य सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिनहाकी अध्यक्षतामें हुआ। कांग्रेसके इतिहासमें प्रथम बार ऐसा प्रतीत होता था कि कांग्रेस नेतृत्विविहीन हो गयी है। श्री गोखले और फीरोजशाह मेहता दोनोंकी मृत्यु हो चुकी थी। वाचा और चन्दावरकर दोनों वृद्धावस्थाके कारण निष्किय हो गये थे। तिलक अभीतक कांग्रेसके सुरेन्द्रनाय वनर्जी "नयी विचारधारासे सहमत नहीं हो पाये थे। मदनमोहन मालबीय नरमदर्लीय विचारोंको लेकर कांग्रेसका नेतृत्व करनेकी स्थितिमें नहीं थे और न उनमें इतनी क्षमता थी कि वे अपने विचारोंको मनवा सकें।" गान्धीजी यद्यपि भारत आ चुके ये परन्तु वे राजनीतिमें भाग न छे सकते ये क्योंकि गोखलेने उनके ऊपर भाग न हेनेका प्रतिवन्ध हमा दिया था। मान्धीजीको सहाह दी गयी थी कि वे चुपचाप एक वर्षतक भारतीय राजनीतिक परिस्थितिका अध्ययंन करें । लेकिन गान्धीजीके वष्वई आनेसे प्रेसीडेन्सी (हाते) के गवर्नर लार्ड विलिंगडन व्यप्न हो उठे। जैसे ही वे वम्बई पहुँचे, गोखटेने उन्हें सूचना दो कि गवर्नर साहव उनसे भिटनेको इच्छुक हैं । वे गवर्नर साहवसे मिले । मामूली वात करनेके वाद गवर्नरने गान्धीजीसे कहा "में आपसे केवल एक बात चाहता हूँ और वह यह कि जब भी आप सरकार सम्बन्धी कोई कदम उठावें तो उसरी पहले मुझसे मिल जलर लं। गान्धीजीने उत्तर दिया "मैं यह आस्वा-सन तो आपको आसानीसे दे सकता हूँ, क्योंकि एक सत्याग्रहीके रूपमें मेरा यह सिदान्त रहा है कि जिन छोगोंसे मुझे संघर्ष करना है, उनके दृष्टिकोणको समझनेकी चेष्टा करूँ। और जहाँतक सम्भव हो उनके दृष्टिकोणसे सहमत हो सकूँ । दक्षिण अफिकामें, मैंने इस नियमका कड़ाईसे पालन किया था और यहाँ भी वहीं करूँगा। लाई विलिंगडनने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि "जब आपको इच्छा हो आप मेरे पास आयें और तब आप-को पता लगेगा कि मेरी सरकार जान वृक्षकर कोई गलती नहीं करती।" वातचीत गान्धी-जीके उत्तरके बाद खत्म हो गयी। गान्धीजीने कहा कि ''वही विश्वास मेरा संवल है।''

वम्बई कांग्रेस अधिवेशनमें फिर नरमदलीय विचारधाराका आधिपत्य रहा । राष्ट्रीय और नरमदलीय सदस्योंके बीच समझौता करानेके सारे प्रयत्न निष्फल रहे । स्वाभाविक था कि राष्ट्रपतिका भाषण सभी भृतपूर्व नरमदलीय राष्ट्रपतियोंके भाषणोंसे अधिक नरम हो क्योंकि सरकारसे उनका सम्पर्क बहुत गहरा रहा था । श्री सौतारामेयाने तो इस भाषणको "सबसे अधिक प्रतिक्रियाबादी भाषण कहा है" लेकिन अधिवेशनमें प्रतिनिधि बहुत संख्वामें सम्मिलत हुए थे । २२५९ प्रतिनिधियोंने इस सम्मेलनमें भाग लिया।

सीतारामैया—हिस्ट्री ऑक इण्डियन नेशनल कांग्रेस, जिल्द १-प्रष्ट-१२०

और स्रतको असफलताके वाद यह उपस्थित एक बहुत वड़ी कामयावी समझी गयी। श्री सिनहाने अपने भाषणके प्रारम्भमें कहा कि "आज यह मेरा पहला कर्तव्य है कि में एक वार फिर अपने आदरणीय और प्रिय सम्राटके चरणोंमें भक्ति प्रकट करूँ। "मेरा दूसरा कर्तव्य, अपने उन भाइयोंके प्रति हार्दिक कृतज्ञता और अति प्रशंसा प्रगट करना है जो साम्राज्यकी सुरक्षा हेतु यूरोप, एशिया, और अफिकाके युद्धसलमें प्राणोंकी वाजी लगाये हुए हैं। स्वराज्यकी माँगपर, राष्ट्रपतिने कहा "प्रतिनिधि वन्युओ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भारतकी आकांक्षाओंको 'स्वराज्य' का वही रूप सन्तुष्ट कर सकता है जिसका सुन्दर वर्णन राष्ट्रपति लिंकनने किया है, जनताका राज्य, जनताक लिए और जनता द्वारा।" जब में यह बात कहता हूँ तो निमिष मात्रके लिए भी मेरा यह आशय नहीं है कि हमारे उत्पर जो शताब्दियोंसे भिन्न-भिन्न होगोंका शासन रहा है उन सबमें अच्छा अंग्रेजी शासन नहीं है।"

सिनहाके भाषणके अंशसे काफी विवाद उठ खड़ा हुआ। उन्होंने कहा था "यदि आज अंग्रेजी राष्ट्र भारतको तत्काल ही विना किसी शर्त और कीमतके पूर्ण स्वराज्यका दान देनेको प्रस्तुत भी हो जाय—जिनका आज कांग्रेससे सर्वाधिक मतभेद है वही यह वात सबसे ज्यादा अस्वीकार करते हैं कि अंग्रेज इसके लिए तैयार हो जायँगे—तो कमसे कम मुझे इसमें सन्देह ही है कि इस प्रकारका दान छेनेके योग्य हम हैं भी, क्योंकि यह तो राजनीतिका साधारण सिद्धान्त है कि राष्ट्रोंको भी व्यक्तियोंकी भाँति आजादी ग्रहण करने योग्य वननेके लिए परिपकता प्राप्त करनेकी आवश्यकता है। किसी भी राजनीतिक संस्थाके लिए कोई चीज इतनी हानिप्रद नहीं है जितनी कि अपरिपकता। और न हमकी यही भूलना चाहिये कि स्वतन्त्र होते ही भारत अपनी प्राचीन गौरवमयी खिति पुनः प्राप्त कर लेगा।"

लेकिन सुरेन्द्रनाथ वनजीकी चेष्टासे कांग्रेसने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया था कि अब वह समय आ गया है जब कि सरकारको स्वराज्य देनेकी तरफ सुधारोंके कुछ ठोस कदम उठाने चाहिये, सरकारी व्यवस्थाको और अधिक उदार वनाना चाहिये ताकि जनताका सरकारी व्यवस्थापर प्रभावयुक्त नियन्त्रण हो सके, और इसके लिए 'प्रान्तीय स्वराज्य', जिसमें आर्थिक स्वतन्त्रता भी शामिल हो, तत्काल ही मिलना चाहिये । विधान परिपदोंको वढ़ाना चाहिये ताकि उनमें वास्तवमें जनताके सभी वर्गोंका वास्तविक प्रतिनिधित्व हो और सरकारी प्रशासनपर उनका प्रभावशाली नियन्त्रण हो। प्रस्तावमें यह भी माँग की गयो कि वर्तमान कार्यकारी परिषदों (एकजीक्यूटिय कौंसिल्स) का पुनःसंघटन किया जाय और जिन प्रान्तोंमें अभी ये संस्थाएँ नहीं हैं वहाँ वे फौरन शुरू की जाय"; भारत सचिवकी कार्यकारिणीमें सुधार किया जाय या उसे समाप्त कर दिया जाय; और स्थानीय स्वायत्त शासनको यथासम्मव आरम्म किया जाय। प्रस्तावमें अखिल भारतीय कांग्रेस महासमितिको यह अधिकार दिया गया कि वह सुधारोंकी योजना और शिक्षाप्रद तथा प्रचारात्मक अनवरत कार्यका एक कार्यक्रम तैयार करे। प्रस्तावका सबसे महत्वपूर्ण अंदा यह या कि सुधार-योजना वनानेके लिए कांग्रेस महासमिति, ऑल इण्डिया मुस्लिम लीग से परामर्श करे। श्रीमती वेसेण्टने प्रस्तावका समर्थन करते हुए कहा कि "यह प्रस्ताव, कांग्रेसके गत ३० वर्षोंके गौरवशाली इतिहासमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके सामने आये प्रस्तावोंमें सबसे महत्वपूर्ण है।" लीग और कांग्रेस

दोनों एक दूसरेसे परस्परिक सहयोगके लिए कटिनद्ध हो रही याँ। उसी समय हो रहे लीगके अधिनेशनमें कांग्रेसके कुछ प्रधान नेता सम्मिल्ति हुए। लीगने भी दूसरी राजनीतिक पार्टियोंसे परामर्श करके स्वराज्यकी योजना बनानेके लिए एक समिति नियुक्त की।" इस सहयोगकी भावनाने उग्रदलीय लोगोंको दुवारा कांग्रेसमें सम्मिल्ति होनेके लिए प्रेरित किया और अगले वर्ष वे कांग्रेसमें फिर आ भी गये। उनकी शक्ति भी काफी बढ़ चुकी थी। कांग्रेसने अंग्रेजी सरकारके प्रति भारतीय जनताकी निष्ठा प्रकट करते हुए; युद्धमें अंग्रेजोंके ध्येय और पक्षको न्यायपूर्ण समझते हुए; और वॉइसराय लाई हार्डिञ्जके कार्यकालको वढ़ानेकी माँग करते हुए प्रस्ताव पास किये।

कांग्रेसने ऐसे संवोंके तत्वाधानमें, जिनको स्थापित हुए दो वर्पसे कम न हुए हों तथा जिनके उद्देश—"साम्राज्यके अन्तर्गत वैधानिक उपायोंसे स्वराज्यकी प्राप्ति हो ", सार्वजिनक सभामें निर्वाचित कर प्रतिनिधि भेजनेकी अनुमति देकर, राष्ट्र-दलीय-लोगोंके कांग्रेसमें आनेका रास्ता साक कर दिया । तिलकने इसका स्वागत किया और उन्होंने फीरन अपने दलकी कांग्रेसमें शामिल होनेकी इच्छा प्रकट की।

सन् १९१५ के कांग्रेस अधिवेशनकी एक विशेष घटना विषय-समितिके निर्धाचनमें गान्धीजीकी हार थी । तय राष्ट्रपतिको गान्धीजीको नामजद करना पड़ा ।

भारतीय राजनीतिमें अब एक नवीन युगका आरम्भ होता है। अलीगढ़ कॉलेजके प्रधानाच्यापक वेकने, इतने परिश्रमसे कॉंग्रेसी उद्देलनोंसे मुसलमानोंको जो पृथक किया था, सन् १९१६ में वह सब मिट्टीमें मिल गया। कांग्रेस और लीग दोनोंने अपने वापिक-अधिवेशन लखनऊमें किये। दोनों संवटनोंने, जो अभीतक राजनीतिमें अलग-अलग चलते थे पृथकताकी नीति छोड़कर सुधारोंकी संयुक्त योजना पेश की। राष्ट्रपति अधिवकाचरण मजूमदार ने अपने भाषणमें गर्वसे कहा "हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न हल हो चुका है और दोनों जातियाँ स्वराज्यकी माँग संयुक्त रूपसे करनेको सहमत हो गयी हैं। अभी हालमें ही कलकत्तेमें अखिलभारतीय कॉंग्रेस महासमिति और लीगके प्रतिनिधियोंने दो दिनके विचार-विमर्शके बाद एक आवाजसे यह फैसला किया है कि भारतके लिए प्रतिनिधि-सरकारकी संयुक्त माँग पेश की जाय। अति आवश्यक समस्या सुलझ गयी है और मुख्य चीज हासिल कर ली गयी है।"

मजूमदार वकील और लेखक थे और कांग्रेसके लगभग जन्मसे ही उनका उससे सम्बन्ध रहा था। उन्हें सफल वक्ता होनेका दुर्लभ गुण प्राप्त था। उन्होंने वंग-भंग विरोधी आन्दोलनमें सिक्रय भाग लिया था। उन्होंने जनताको अनुशासित और स्वराज्यके लिए तैयार रहनेके लिए आहान किया। लीग और कांग्रेस दोनोंके संयुक्त विचार-विमर्शके फलस्वरूप वनी सुधारोंकी योजनाका मुख्य प्रस्ताव 'लखनऊ समझौता'के नामसे प्रसिद्ध है। योजनाके दो भाग थे। प्रथम भागमें मुस्लिम समस्यापर विचार किया गया था और द्वितीय भागमें प्रस्तावित सुधार थे। प्रथम माग, जिसको कांग्रेस, लीग और भारत सरकारने भी स्वीकार कर लिया था, इस प्रकार था।

"चुनाव द्वारा मुख्य अल्पमतवाली जातियोंके प्रतिनिधित्वका उचित प्रवन्ध होना चाहिये तथा मुसल्मानींका प्रान्तीय विधान परिपदींके लिए निर्वाचन विशेष निर्वाचकीं द्वारा निम्नलिखित अनुपातमें होना चाहिये।

⁽१) पंजाव-निर्वाचित भारतीय सदस्योंकी संख्याके आधे

(२)	संयुक्त	प्रान्त—निर्वाचित	भारतीय	सदस्योंकी	संख्याके	₽0	ंग्रतिशत
1-1					C 11 11	1 -	ગાપરાપ

(3)	• • •		11.4 (1.4/-	માં જાલ્	गक रण्यातशत
(३) बंगाल—	33,	"	33	23	४० प्रतिशत
(४) विहार—	55	35	>>	. 53	२५ मतिशत
(५) मध्यप्रान्त-	- ,,	33	"	>>	१५ प्रतिशत
(६) मद्रास—	33 ·	"	23	57	१५ प्रतिशत
(७) वश्वई—	"	"	55	. 33	के एक तिहाई

शर्त यह थी कि कोई भी मुसलमान उन निर्वाचनोंको छोड़कर जो विशेष हितोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले निर्वाचकों द्वारा हुए हों, अन्य किसी केन्द्रीय या प्रान्तीय विधान परिषदोंके निर्वाचनमें भाग नहीं लेगा।

यह भी रार्त थी कि किसी भी गैरसरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तावित विधेयक या प्रस्ताव या उसकी किसी भी धारापर जो एक या दूंसरी जातिक मसलोंसे सन्बन्ध रखती है—और इसका निश्चय केन्द्रीय या प्रान्तीय विधान परिपदोंमें उसी जातिके सदस्य करेंगे— विचार नहीं किया जायगा उस हालतमें जब कि सम्बन्धित जातिके तीन-चौथाई सदस्य उस केन्द्रीय या प्रान्तीय विधान परिषद्में उस विधेयक या उसकी किसी धारा या प्रस्तावका विरोध करें।"

सुधारोंकी योजनाके द्वितीय भागमें माँग की गयी थी कि साम्राज्यके पुनस्संघटनमें भारतको पराधीनताके पदसे उठाकर साम्राज्यका एक वरावरीका हिस्सेदार स्वशासित राज्य मान लेना चाहिये। प्रान्तीय विधान परिपदोंमें कुल सदस्यीका ४/५ भाग निर्वाचित और १/५ नामजद होना चाहिये। जितना सम्भव हो सके उतने विस्तृत मताधिकार द्वारा परि-षदके सदस्योंका सीधा निर्वाचन होना चाहिये।

प्रान्तीय गवर्नरों और उनकी कार्यकारिणीके सदस्योंको आमतौरपर भारतीय सिविल सर्विस (इण्डियन सिविल सर्विस) का सदस्य नहीं होना चाहिये । प्रशासन कार्यशक्ति गवर्नर जनरलमें और प्रान्तोंमें, गवर्नरके हाथों तथा मंत्रियोंमें निहित होना चाहिये जिनमेंसे कमसे कम आधे मन्त्रिगण विधान परिषदके सदस्यों द्वारा निर्वाचित हों। प्रान्तोंको आंतरिक मामलोंमें पूरा स्वराज्य होना चाहिये, और स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओंका चेयरमैन निर्वाचित होना चाहिये। केन्द्रीय विधान परिषद्के सदस्योंकी संख्या १५० होनी चाहिये, जिनमेंसे ४/५ निर्वाचित होने चाहिये और इन ४/५ सदस्योंका १/३ भाग पृथक निर्वा-चन प्रणाली द्वारा मुसलमानों द्वारा निर्वाचित होना चाहिये। भारत सचिव और उसकी कार्यकारिणीको समाप्त कर देनां चाहिये। केन्द्रीय विधान परिपदके लिए मत देनेवालींके क्षेत्रमें वृद्धि होनी चाहिये। भारतकी एक राष्ट्रीय सेना होनी चाहिये, और प्रत्येक जातिके लोगोंको इसमें प्रवेशका अधिकार होना चाहिये। लगभग इसी प्रकारका एक स्मृतिपत्र केन्द्रीय विधान परिपदके उन्नीस गैर सरकारी सदस्योंने वाइसरायको भेजा।

लेकिन कांग्रेस, जैसा कि लखनऊ अधिवेशनमें पास हुए प्रस्तावसे माल्म होता है, यह नहीं चाहती थी कि भारतको एकदमसे स्वराज्य दे दिया जाये। प्रस्तावमें कहा गया था "िक श्रीमान् सम्राट् कृपाकर यह घोषणा करें कि अंग्रेजी नीतिका यह उद्देश और विचार है कि भारतको जल्दी ही 'स्वराज्य' दे दिया जाय ।" यद्यपि मुस्लिम लीगको वस्तुतः मुसलमानोंका प्रतिनिधि मान लिया गया था, लेकिन कांग्रेस-मंचपर कुछ मुख्य मुसलमान

नेता विराजमान थे। उनमें मुहम्मदेशकी जिना, राजा महमूदाबाद, मजहरल हक और ए. रस्ल थे। अन्तिम सङ्जनने वंग-भंग विरोधी आन्दोलनमें मुख्य भाग लिया था। उपि स्थित नेताओंमें गान्धीजी भी एक कोनेमें बैठे हुए थे जिन्होंने अभीतककी काररवाईमें कोई सक्रिय भाग नहीं लिया था।

ल्खनक अधिवेशन ऐसे समय हुआ जब कि प्रथम महायुद्ध पूरी भीपणतासे हो रहा था और कुछ क्रान्तिकारी भारतमें सरकार विरोधी कार्यों के लिए दूसरे देशोंसे हथियार लानेका प्रयत्न कर रहे थे। यू. पी. की सरकारने कांग्रेसकी स्वागत-समितिको, अधिवेशनमें राजद्री-हात्मक भापण न करनेके लिए चेतावनी मेजी। वंगाल सरकार जरिये मनोर्नात अध्यक्षपर सरकारी आदेश जारी करवाया गया। परन्तु यू. पी. के गवर्नर सर जेम्स मेस्टन अधिवेशनमें समिलित हुए। अध्यक्षने उनका स्वागत किया जिसका सर जेम्सने एक संक्षिप्त भापणमें जवाब दिया।

विहारके शोपित किसानोंने एक वार फिर अपने यूरोपीय जमींदारोंके विषद सर उठाया। इस प्रश्नने राजनीतिक नेताओंका ध्यान आकर्षित किया। कांग्रेसने नील पैदा करनेवाले किसानोंके वारेमें, और नील वागानके मालिकोंके दुर्ध्यवहारकी निन्दा करते हुए प्रस्ताव पास किये और माँग की कि सरकारी और गैर-सरकारी लोगोंकी एक समिति इस खेतिहर झगड़ेकी जाँच करनेके लिए नियुक्त की जाय। गान्धीजीने इस झगड़ेके मूल कारणोंका अध्ययन करनेके लिए आगामी वर्ष कुछ समय विहारमें व्यतीत किया। विहारकी कहानी अन्यत्र लिखी जायगी।

जैसा कि हम दूसरी जगह वता चुके हैं, १८१८ के ऐक्टके तीसरे विनियमनका सर-कार खुलकर प्रयोग कर रहीं थी। वंगालके ५०० नजरवन्दों में ६० केवल इसी विनियमनके अन्तर्गत नजरवन्द थे। यह आम विश्वास था कि नजरवन्दों में बहुतसे निदीं प व्यक्ति भी थे, कांग्रेसने माँग की कि किसीको नजरवन्द करनेसे पहले सरकार स्पष्ट अभियोग वताये और अभियुक्तोंको अवसर दें कि वे विशेष अदालत (द्रिब्यूनल) के सामने इन अभियोगोंका उत्तर दें सकें।

१९१६ में फिर गान्धीजी विषय समितिकी सदस्यतासे वंचित होते होते बचे। लखनऊ अधिवेशनमें सम्मिलित प्रतिनिधियोंमें राष्ट्रीय दलके लोगों—तिलक अधिविशनमें सम्मिलित प्रतिनिधियोंमें राष्ट्रीय दलके लोगों—तिलक आदिमियों—का यहमत या। चूँिक विषय-समितिका चुनाव प्रान्तीय-आधारपर होता था इस कारण सम्भवतः तिलक अधिया ज्यादा निर्वाचित हो गये। जब गान्धीजीका नाम पेश किया गया तो किसीने एक राष्ट्रीय दलवालेका भी नाम पेश कर दिया और उस समय जैसा वातावरण विश्वमान था, उसमें गान्धीजीको अधिक वोट नहीं मिले। परन्तु तिलक उठकर घोषित किया कि गान्धीजी निर्वाचित हो गये।

मुहम्मद अली जिज्ञाने १९१६ के लीग अधिवेद्यानकी अध्यक्षता की । अपने भाषणमें उन्होंने भारतकी समस्याका विद्रलेषण किया कि "संक्षेपमें हमारे यहाँ अंग्रेज अफसरोंका एक कुशल अधिकारीवर्ग है जो केवल अंग्रेजी लोक-समाके प्रति उत्तरदायी है। जो उदार निरंकुश शासनके तरीकोंसे एक ऐसी जनतापर हुकुमत कर रहे हैं जो अपने भाग्यको अच्छी तरह जानती है और राजनीतिक आजादो पानेके लिए शान्तिमय तरीकोंसे संपर्य कर रही है। थोड़ेमें यह भारतकी समस्या है। यह अंग्रेज राजनीतिज्ञताका काम है कि वह इस समस्याका,

शान्तिमय, तत्काल और स्थायी हल निकालें।" उन्होंने कहा कि हिन्दुओं की माँति मुसल-मानों की आँखें भी भविष्यपर लगी हुई हैं। फिर उन्होंने सारगर्भ वातें कहीं कि "हमारे बहुत् प्रायद्वीपमें ३१ करोड़ ५० लाख मनुष्य रहते हैं, जिनमें विभिन्न जातियों, संस्कृतियों, और धर्मके लोग हैं। मनुष्यों का यह बृहत् समुदाय, एक ही प्राकृतिक और राजनीतिक वातावरणमें एकत्र होकर भी नैतिक और राजनीतिक विकासके विभिन्न स्तरों में है। इसके माने हैं कि दृष्टिकोण, उद्देश्य और प्रयत्नों में विभिन्नता होगी।" लेकिन उन्होंने जोर दिया कि भारतीय स्वराज्यके लिए अपनेको योग्य सावित करनेके लिए दृद्रप्रतिज्ञ हैं। हिन्दू-मुस्लिम समझौता भारतीय एकताके जन्मका द्योतक है। मुहम्मद् अली जिनाने कहा कि मुसल्मानोंके राज-नीतिक उद्देश्य पूर्ण रूपसे वही हैं जो हिन्दुओंके हैं। उन्होंने यह माँग की कि मुसल्मानोंको स्वयं अपना खलीफा निश्चित करनेका अधिकार होना चाहिये।

लीगके प्रस्ताव कांग्रेसमें पास किये गये प्रस्तावोंके लगभग अनुरूप थे। अधिवेशनमें एक दिन थोड़े समयके लिए लेपिटनेन्ट गवर्नर भी उपस्थित थे। जिनाने अपने आपकी और लीगके नेताओंको सात करोड़ मुसलमानोंका स्वीकृत नेता घोषित किया।

उसी वर्षके आरम्भमं मुसलमानोंकी पान-इस्लामिक भावनाको फिर ठेस पहुँची।
मकाके दारीफ ए. आजमने तुकींके सुल्तानके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह से लीगके
कुछ प्रधान नेताओंको, जो समझते थे कि 'दारीफ' ने अँग्रेजोंके प्रोत्साहनसे विद्रोह किया है,
खेद और क्षोभ हुआ। उन्होंने एक सार्वजनिक सभा की और "मकाके दारीफके नेतृत्वमें
अरव विद्रोहियों और उनके समर्थकोंको इस्लामका दात्रु" घोषित करते हुए निन्दाका
प्रसाव पास किया।

१ लवेट वही पुस्तक, पृष्ठ १०५

अध्याय १५

गदरका पड्यन्त्र

वहुत वपाँसे, जैसा कि इम पिछले अध्यायोंमें देख चुके हैं, विश्वके विभिन्न भागांमें रहनेवाले भारतीय भारतमें ब्रिटिश शासनको उखाड़ फेंकनेके उद्देश्यसे सशस्त्र कान्तिका संघ- टन करनेमें लगे हुए थे। सन् १९१४-१८ के महायुद्ध-काल्में उनके कायोंमें खास तौरपर भारी उमार आया और विदेशोंसे हथियार जमा करके देशमें विद्रोह खड़ा करनेके इस बीच कई असफल प्रयत्न किये गये।

अमेरिका और कनाडामें उस समय प्रायः १५ हजार भारतीय, अधिकांशतः सिख थे, जो जीविकाकी तलाशमें वहाँ गये थे और वहाँके विभिन्न पेशोंमें खपकर वहीं वस गये थे। एक पराधीन मानुभ्मिकी सन्तान होनेके नाते अमेरिकाके सामाजिक जीवनमें उनके विरुद्ध पञ्चपात होता था। वे यह समझने लगे ये कि उनके आत्मसम्मानके लिए पहले भारतका विदेशी गुलामीसे मुक्ति पाना अनिवार्य है। प्रसिद्ध कान्तिकारी हरदयालने इन लोगोंको इस उद्देशके लिए प्रयत्न करनेकी प्रेरणा प्रदान की थी।

हरदयाल दिल्लीके रहनेवाले थे । पंजाब विश्वविद्यालयमें कुछ दिनों अध्ययन करनेके वाद सन् १९०५ में वे एक सरकारी छात्र वृत्ति पाकर आक्सफोर्डमें अपनी शिक्षा पूरी करनेके लिए इंग्लैंग्ड चले गये। वहीं उनके विचारोंमें परिवर्तन हुआ, और अपने अन्तरतमकी भावनाक प्रति न्याय करनेके लिए उन्होंने अपनी छात्रवृत्ति यह कह कर वापस कर दी कि में शिक्षाकी अंग्रेजी पद्धतिको ही पसन्द नहीं करता। सन् १९०८ में वे स्वदेश छोटे और लाहौरमें एक राजनीतिक कक्षा आरम्भ की जिसमें उन्होंने आम वायकाट तथा सविनय अवज्ञा द्वारा सरकारको समाप्त करनेका उपदेश दिया। परन्तु सन् १९११ में वे सैनफांसिस्को गये जहाँ उन्होंने अमेरिकामें रहनेवाले भारतीयोंको विद्रोहके सिद्धान्तकी शिक्षा देनेके कार्यके लिए अपने आपको अपित कर दिया। उन्होंने सभाओंमें भाषण किये, और ऐसी संस्थाओंका संघटन किया जिनका संकल्प था कि "भारतसे ब्रिटिश शासन मिटा कर दम छंगे।" नवम्बर सन् १९१३ में सैनफांसिस्कोमें आयोजित एक सम्मेलनमें अमेरिकाफे विभिन्न भागोंसे आये हुए भारतीयोंने भाग लिया, १५ हजार डालर चन्दा जमा हुआ और "इण्डियन एसोमियेशन"की स्थापना की गयी । एसोसियेशनने सन् १८५७ के विद्रोहके स्मारकके रूपमें हिन्दी, उर्दू, मराठी और गुरुमुखीमें "गट्र" नामक एक पत्रिका प्रकाशित करनेका निश्चय किया । बाद-में एसोसियेशनका ही नाम उक्त पत्रिकाके नामपर "गदरपार्टा" हो गया जिसके अध्यक्ष खोहन सिंह मखना और मंत्री हरदयाल चुने गये । शीध ही पार्टीकी सदस्य संख्या ५००० तक बढ़ गर्या और अमेरिका तथा कनाडामें कुल मिलाकर इसकी ६२ शाखाएँ खुल गर्यों। जापान में भी वरकतुल्लाहने पाटोंकी शाखा स्थापित कर दी । उसके बाद शंत्राईमें गयुराप्रसादने और हांगकांगमें भगवानिसहने शाखाएँ खोलीं । दूर दूर देशों जैसे मलाया, जापान, चीन, फिलीपाइन, फिजी, अजे टाइनके भारतीय "गदर"का चन्दा भेजकर गाहक बनने लगे थे।

३१ दिसम्बर १९१३ के दिन सेकामेन्टोमें आयोजित एक सभामें दादाभाईने कहा.

कि जर्मनी इंग्लैण्डसे युद्ध छेड़नेकी तैयारी कर रहा है; अतः यही समय है जब हमें भावी कान्तिके लिए भारत जानेकी तैयारी करनी चाहिये। १६ मार्च सन् १९१४ को अमेरिकी अधिकारियोंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तािक उन्हें भारत वापस भेजकर भारत सरकारको सौंप दिया जाय। पर हरदयालने जमानतपर अपनेको रिहा करा लिया और चुपकेसे स्विट्जरलैण्ड भाग गये।

हरदयालके उपदेश जिन सिद्धान्तींका प्रयोग करते थे वे ब्रिटिश कोलम्बियाके सिखीं और अन्य भारतीयोंतक पहुँच चुके थे। सन् १९१३ के दिसम्बरमें वानकोवरमें आयोजित एक सभामें "गदर" से उद्घृत एक किविता पढ़ी गयी जिसमें भारतीयोंको ललकारा गया था कि अंग्रेजोंको भारतसे निकाल बाहर करें। ब्रिटिश कोलम्बिया, बेतनकी ऊँची दरीके कारण, वहतसे पंजावियोंको आशाका धुवतारा जान पड़ता था। पर भारतीयोंके लिए वहाँ वसनेकी आशा पाना आसान न था । एक सज्जन गुरुद्त्त सिंहने, जो सुदूरपूर्वमें व्यापार करते थे, संकल्प किया कि भारतीयोंपर लगी हुई पावन्दी तोड़कर रहेंगे, और ३५१ सिखों तथा २१ पंजावी मुसलमानोंको लेकर जापानी जहाज "कोमागेटा मारू" पर ४ अप्रैल १९१४ के दिन हांगकांगसे रवाना होकर वे २३ मईके दिन वानकोवर पहुँच गये। यह कनाडाके कानूनको साफ-साफ चुनौती थी जिसमें एशियावासियोंको कनाडामें प्रवेश करनेकी मुमानियत थी, जबतक कि उनके पास अपने देशकी सरकारसे प्राप्त पासपोर्ट और कुछ रुपया न हो। परन्तु गुरुदत्त सिंह और उनके साथियोंने इस आदेशकी उपेक्षा की और जहाजसे उतरनेका आग्रह किया । आदेशको लागू करनेके लिए पुलिस दल भेजा गया पर गुरुदत्त सिंह और उनके साथियोंकी गोलियोंकी मारसे पुलिसके छक्के छूट गये। वादमें सशस्त्र पुलिसने जहाज-को लंगर उठानेपर मजबूर किया और कुछ ही व्यक्तियोंको उतरनेको इजाजत मिली। इस पूरी घटनाने उन लोगोंका गुस्सा उभाइ दिया और वे कान्तिके विचारोंसे ओत-प्रोत होकर जहाज द्वारा भारत रवाना हो गये। इसी बीच भारत सरकारने भारतमें "अवांछनीय विदे-शियों'' का भारतमें प्रवेश रोकनेके उहे स्यसे "फारेनर्स आर्डिनेन्स" जारी किया और इसके तुरत बाद ''गदर-मनोवृत्तिवाले प्रवासी भारतीयोंकी वापसी पर गतिविधिपर नियन्त्रण रखनेके लिए "इंग्रेस आर्डिनेंस" पारित कर दिया ।

इन नियन्त्रणोंसे उत्तेजनाकी आगमें मानों घी पड़ गया। २४ सितम्बर, १९१४ को इन लोगोंका जहाज हुगलीमें घुसा, और जब २९ को वजवजपर लगा तो अधिकारियोंने यात्रियोंको आदेश दिया कि "आप लोग सीधे रेलगाड़ींमें चले जायँ जो तैयार खड़ी है और वादमें आप लोगोंको बिना किराया पंजाब पहुँचा देगी। उन लोगोंने इस सुविधाको स्वीकार करनेसे इन्कार किया और उन्होंने विरोधस्वरूप कलकत्तामें मार्च करनेकी कोशिश की। उन्हें जबरदस्ती पीछे धक्तेला गया। यह व्यवहार मानों यात्रियोंके लिए जापानी हमला आरम्भ करनेका विगुल था। सड़कपर जमकर युद्ध हुआ जिसमें १८ सिल मारे गये, वहुतसे तत्काल गिरफ्तार कर लिये गये और कुछकी तलाश जारी रही। वे भी वादमें पकड़ लिये गये।

इस घटनाने पंजावके सिखोंको सरकारके खिलाफ कर दिया और गयाके क्रान्ति कारियोंको भी इससे बड़ा वल मिला जो विदेशस्थित भारतीयोंसे वरावर यही आग्रह कर रहे थे कि भारतमें गदर आरम्भ ही होनेवाला है जिसमें भाग लेनेके लिए सबको स्वदेश पहुचना चाहिये। इसी अपीलके परिणामस्वरूप करीव ८ हजार प्रवासी भारतीय अपने घरोंको वापस लीटे। सरकार इन सब वापस आनेवालींपर मुस्तैदीसे नजर रख रही थी और जिनको सरकारने खतरनाक समझा उनमेंसे ४०० तो जेल भेज दिये गये तथा २९०० अपने अपने गाँवकी सीमाके भीतर नजरबन्द कर दिये गये।

"कोमागाटा मारू" जहाजके यात्रियोंकी कहानी दावानलकी तेजीसे पूर्वके सभी देशोंके स्वतन्त्रतायेमी भारतीयोंमें पैल गयी और मनीला, हांगकांग, शंघाई, और अमेरिकासे एकत्र होकर करीब १७३ भारतीय—मुख्यतः सिख—एक अन्य जापानी जहाज "तोसामारू" द्वारा कलकत्ता रवाना हो गये। जहाज २९ अक्त्यर, १९१४ को कलकत्ता पहुँचा। भारत सरकारको इस बीच अपने निजी स्त्रोंसे यह स्चना मिल चुकी थी कि यात्रियोंने अपनी वातचीतमें खुलेआम भारतमें पहुँचने पर विद्रोह आरम्भ करनेकी चर्चा की थी। भारत म्मिपर उतरते ही १०० तो जेल भेज दिये गये। जो वचे वे पंजाव पहुँचकर "कोमागाटा मारू" जहाजसे कुछ दिन पूर्व आये हुए अपने हमराहियोंको क्रांतिकी आग सुलगानेमें योग देने लगे। भावी क्रांतिका सन्देश पूरे पूर्वमें फूल गया और "गदर पड्यन्त्र" शीध ही ऐसे महान आन्दोलनमें परिणत हो गया जो ऐतिहासिक महान विद्रोहके बाद अभ्तपूर्व था क्योंकि इसमें भाग लेनेवाले पंजावके बीर बंशके लोग थे। "तोसामारू" के उन यात्रियोंमेंसे जिन्हें पंजाव जानेकी इजाजत मिल गयी थी, कुछ ही समय बाद ६ को फाँसी दी गयी, ६ को विविध पड्यन्त्र, सम्बन्धी सुकदमोंमें सजा मिली और ६ व्यक्ति गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिये गये।

अधिकारियोंने, अपनी समझमें, "तोसामारू" के उन्हीं वात्रियोंको पंजाव पहुँचने दिया था जो निरापद थे या उन्हें खतरनाक नहीं जान पड़े थे, पर वही लोग पक्के जीवटके कान्तिकारी सावित हुए। उन्होंने स्थानीय नेताओं से संपर्क किया और देशके विभिन्न स्वोंमें मोर्चे वनाकर, अगली काररवाईके लिये तैयार हो गये। पूरे जोर शोरसे तैयारी की गयी जिसको "दिव्ली पह्यन्त्र" के प्रख्यात नेता रासविहारी वसुने पूर्णता प्रदान की । २१ फरवरी १९१५ आम विद्रोह आरम्भ करनेकी तरीख नियुक्त की गयी और लाहौर उसका सदर दपतर तय किया गया । अमेरिकाके भारतीयों और स्वदेशके इन क्रान्तिकारियोंके बीच वरावर सम्पर्क रहा । दिसम्बर १९१४ में एक युवा मराठा, पूना जिलेका विष्णु गणेश पिंगले जो अमेरिकासे कुछ लिख कान्तिकारियों सहित भारत लीटा था, पंजावमें पहुँचा। उस युवकने पंजावके कान्तिकारियोंकी सभा बुलायी जिसमें जनकान्तिकी आम तैयारीपर भारतीय फीजोंको तोड़ने, हथियार प्राप्त एवं एकत्र करने, वम निर्माण, सरकारी खजाने लूटने और क्रान्तिके लिए धन जमा करनेके उद्देश्यरे डाके दालने, आदि पर यहस की गयी। पिंगलेने एक वंगाली वम-विशेषज्ञका परिचय कराया और वम वनानेका सामान प्राप्त करनेके लिए लोग यत्र-तत्र मेजे गये। उस समय रासविहारी वसु वनारससे आये और फरवरी १९१५ के आरम्भतक, अमृतसरमं रहकर वे सिख कान्तिकारियोंके साथ काम करते रहे । उत्तर भारत स्थित विभिन्न छावनियोंको, निर्धारित तारीखके टिए फौजी मदद प्राप्त करनेके उद्देश्यसे सन्देशवाहक भेजे गये। विद्रोहमें भाग टेनेवाटे ग्रामीणोंके दस्ते संबिटत किये गये। "वम तैयार किये गये, इथियार इक्टें किये गये, झण्डेतक तैयार रखे थे,

युद्धकी घोषणाका मसविदा बनाया गया, रेलों और तारोंको नष्ट करनेके लिए आवश्यक सामग्री जमा कर ली गयी।""

लेकिन ठीक उस समय, जब विस्फोटके पूर्वकी स्थित एकदम तैयार थी, एक गुप्तचरने प्रस्तावित विद्रोहकी व्योरेवार स्चना सरकारको पहुँचा दी। १८ फरवरीको, ऐसे लोगोंको जो नहीं जानते थे कि पंजाबमें सशस्त्र विद्रोहकी योजना वन चुकी थी—यह देखकर विस्मय हुआ कि ब्रिटिश फौजें पंजाबके सभी प्रमुख कस्वोंमें तैनात कर दी गयी हैं। ६ हजार नेपाली सैनिकोंकी नियुक्ति भी खतरेके क्षेत्रोंमें की गयी। "करीव ५००० व्यक्तियोंपरं, सिर्फ पंजाबके भीतर, राजविद्रोहके लिए मुकदमा चलाया गया। ५०० कान्तिकारियोंका कोर्ट-मार्शल हुआ और उन्हें फाँसी दे दी गयी, ८०० को कालापानीकी सजा मिली, १० हजारको विना मुकदमा चलाये नजरवन्द कर लिया गया और काफी वड़ी तादादको बहुत दिनोंतक फरार रहना पड़ा। सरकारने प्रायः ५०० कान्तिकारियोंको अंदमान भेजा। उनमें भाई परमानन्द प्रमुख थे।""

पूरी परिस्थिति समझानेके लिए कुछ घटनाएँ सविस्तर दी जा रही हैं।

१९ फरवरीको रासिवहारी वसुके प्रधान कार्यालयपर छापा मारा गया और ४ अन्य घरोंकी तलाबी ली गयी। १३ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और कुछ वम भी वरामद हुए। वहीं वरामद कागजातसे अधिकारियोंने यह नतीजा निकाला कि क्रान्तिकारियोंने लाहीर, फीरोजपुर और रावलिपण्डीमें एक साथ विद्रोह आरम्भ करनेकी सोची थी और वादमें उनका इरादा काफी व्यापक क्षेत्रमें—जिसमें वनारस और जवलपुरतक शामिल थे—विद्रोहकी लपटें फैला देनेका था। वंगालके कुछ क्रान्तिकारी, जो पंजावकी योजनाओं से अवगत थे, उसी तारीखसे पूर्वी वंगालमें ठीक उसी ढंगका विद्रोह आरम्भ करनेका इन्तजाम कर रहे थे।

इन रहस्योद्घाटनोंके वाद अधिकारियोंने विभिन्न खानोंपर छापे मारकर तथा गिरफ्ता-रियाँ करके आम-विद्रोहकी योजनाओंको काफी हदतक निष्फल कर दिया, पर प्राकृतिक रूपसे वस्तुखिति कुछ ऐसी थी कि देशमें शान्ति पुनः खापित करना करीव-करीव असम्भव था। २० फरवरीके दिन कुछ स्वदेश लौटे प्रवासियोंने जिन्हें थानेमें तलव किया गया था, एक हवलदारको मार डाला और एक दरोगाको घायल कर दिया। १९ फरवरीको एक योजनाके मुताविक रेलसे ४० व्यक्ति, कुछ सशस्त्र—"सम्भवतः फौजी शस्त्रागरों और डिपोपर हमला करनेके लिए" फीरोजपुर पहुँच गये थे परन्तु वे सफल नहीं हो सके क्योंकि खुफियाने अधिकारियोंको पहले ही सावधान कर दिया था। मार्च महीनेमें कुछ प्रवासी भारतीय अंग्रे जोंके खिलाफ विद्रोह करनेके लिए फौजोंको उभाड़ते हुए गिरफ्तार किये गये; छुधियानामें ६ वम पकड़े गये और अनेक राजनीतिक डकैतियाँ डाली गर्यो। स्वदेश वापस आने पर इन प्रवासियोंपर कड़ी नजर रखी जाने लगी और कलकत्ता तथा छुधियानामें कुल मिलाकर पुल्सिकी पकड़में आये ३,१२५ व्यक्तियोंमें ११९ जेलमें नजरवन्द कर दिये गये, ७०४ पर गाँवसे वाहर न निकलनेकी पावन्दी लगा दी गयी और शेष लोग, हालाँ कि उनकी भी निगरानी रखी

१. सेडीशन कमेटी रिपोर्ट, पृष्ठ १०८

२. धनक्षय कोर-"सावरकर एण्ड हिज टाइम्स" पृष्ठ १३६

३, वही पुस्तक, पृष्ट १०८

गयी पर, विना किसी पायन्दीके रहे । इकी-दुक्की इत्याएँ, डकैतियाँ, क्रान्तिकारी साहित्यका वितरण विभिन्न स्थानींपर चलता रहा ।

लाहौर व अन्य खानींपर आम गिरफ्तारियोंके बाद क्रान्तिकारियोंके ९ दलींपर भारत रक्षा कानुनके मातहत बैठायी गयी असाधारण पंच अदालतके सामने मुकदमा चलाया गया । इन मुकदमोंको "लाहौर पड्यन्त्र केस" कहा गया था । एक मामलेमें ६१ व्यक्तियों-पर, एक अन्यमें ७४ व्यक्तियोंपर और तीसरेमें १२ पर "बादशाहके खिलाफ जंग छेड़ने" का इल्जाम लगाया गया था। इन महत्वपूर्ण मुकदमोंमें सब्तपक्षसे ८५५ और सफाई पक्षसे १३१४ गवाह गुजरे थे। प्रायः सभी व्यक्तियोंको कड़ीसे कड़ी सजाएँ दी गयाँ। सिर्फ २९ अभियुक्त वरी किये गये । २८ को फाँसी हुई और वाकीको कालापानी या विभिन्न मीयादोंकी कैटकी सजा दी गयी। पहली अदालतने फैरलेमें लिखा कि "पंजावमें राज-द्रोहकी भावना सन् १९०७ से वर्तमान है।" मुकदमेक दौरानमें यह भी पता चला कि मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, फैजाबाद, लखनऊमें भारतीय सैनिकोंसे सपर्क स्थापित किया गया था हालाँ कि सफलता नाममात्रको मिली ''पर जो बीज वोया गया वह अवश्य ही कुछ मुसीवत ढाता अगर २१ फरवरीको एक साथ विद्रोह आरम्भ करनेकी योजना समयसे पहले ही खुल न गयी होती।" दूसरे पड्यन्त कैसके फैसलेमें कहा गया कि गाँवों में राज द्रोहके उपदेश सकियतापूर्वक दिये गये और फीजी रेजीमेण्टोंमें भारतीय सैनिकांको हिदायत दी गयी थी कि जैसे ही संकेत मिले, विद्रोह करने तथा मरने-मारनेके लिए अपनेको एकदम तैयार रखें। फरवरोकी निराज्ञाके वाद भी कान्तिकारियोंने अपने प्रयत्न जारी रखे और छदीले (१) नामक स्थानपर उन्होंने अड्डा जमाया । ११ जून १९१५ के दिन रेलके पुलको रक्षा करनेवाली एक रेजिमेण्टकी दुकड़ीपर हमला किया गया और २ व्यक्तियोंकी गोली लगनेसे मृत्यु हुई। पुलिसने ५ व्यक्तियोंको गिरपतार किया जिन्हें मुकदमेका दिखावा करनेके वाद, फाँसी दे दी गयी। सबूत पक्षके कथनानुसार पहले मुकदमेके अभियुक्त वे नेता और संघटनकर्त्ता थे जिन्होंने ''हत्या, मारकाट, और लूटपाट'' तथा सरकारको उलाइ फेंकनेका पड्यन्त्र और प्रयत्न किया था। पहले दलमें भाई परमानन्द भी थे। उन्होंने प्रथम महायुद्ध छिड्नेके बाद भारतका एक इतिहास लिखा था जिसका उद्देश्य पंच अदालतको नजरमें "ब्रिटिश- राजाधिराजकी सरकारके खिलाफ भारतमें अपमान एवं घृणा पैदा करके गदर पड्यन्त्रके सामान्य उद्देश्योंको आगे बढ़ाने"का ही था । तीसरे लाहोर पड-यन्त्र केसके गवाहने कहा कि कुछ कान्तिकारियाँने जिनमेंसे कम-स-कम र कनाडाने आये थे, वंकाकमें मिलकर वर्माकी ओरसे भारतपर हमला करनेकी योजना बनायी थी। अदालतने लिखा—"हमारे सामने स्पष्ट साक्षी है कि इस प्रकारकी नीयत थी अवस्य और वह सब गदर आन्दोलनका ही अभिन्न अंग थी जिसमें जर्मन गुप्तचरीं या दलालेंकी भी दिलचर्पा थी। यह भी एकदम स्पष्ट है कि गदर आन्दोलनके नेताने सैनफांसिस्कोमें जर्मनोंसे मिलकर ब्रिटिश सरकारको मसीवतमें डालनेके उदेश्यसे किसी योजनाका वीजरूप स्वाममें अंकरित एवं पल्लवित किये जानेके उदेश्यमे तैयार किया था।" निर्णयमें आगे कहा गया कि "हमने देखा है कि 'युगान्तर आश्रम'' (सैनफांसिस्को)में एक कागजके पोस्टरपरांलिखा था—जर्मनोंस मत लड़ो, वे हमारे मित्र हैं, और यह स्पष्ट रूपसे युद्धके बाद गदरका सिद्धान्तवाक्य था । हमने

१, वही पुस्तक, पृष्ठ ११०

१६-क

देखा है कि गदर कार्यालयों में प्रकाशित साहित्य हर जगहके भारतीयों में वितरित करने के लिए जर्मन प्रतिनिधि स्वयं ले गये थे, जर्मनीने भारतीय प्रतिनिधियों को अमेरिकासे अफगानिस्तान, स्याम, मनोला, तिव्वत और तुकां जाने के लिए और ब्रिटेन के विरुद्ध मुसीवत खड़ी करने के लिए खर्च दिया था, सैनफांसिस्को स्थित जर्मन प्रतिनिधिका रामचंद्रसे निकट सम्पर्क था और न्यूयार्क स्थित जर्मन राजदूत भारतीय क्रान्तिकारियों को अपने खर्चसे जर्मनी भेज रहे थे, तथा जिस प्रकार भी सम्भव हो सहायताका प्रवन्ध करते थे।"

हरदयालने अमेरिकासे अन्तर्धान होनेके वाद वर्लिनमें भारतीय रिवोल्यूशनरी सोसा-यटी खोल दी थी जिसका उदेश्य था—भारतमें गणतन्त्रकी स्थापना । इसकी वरावर वैठकें होती थीं जिनमें तुर्क, मिल्ली और जर्मन भी भाग लेते थे । सोसायट्रीका एक 'ओरियण्टल त्यूरो' था जो जर्मनीमें भारतीय युद्धवन्दियोंकी क्रांतिकारी साहित्यपर आस्था जागरित करता था । फैसलेके शब्दोंमें "जर्मन अधिकारियोंकी ओरसे भारतीय राजे-महराओंको लिखे गये उत्तेजनात्मक पत्र जिनका मसविदा जर्मन सरकारने तैयार किया, अन्दित और मुद्रित होते, थे और वैठकें होती थीं जिनमें भारत तथा जर्मनी दोनोंके समान उदेश्योंपर जोर दिया जाता था—इन सभाओंमें अध्यक्ष-पद कभी-कभी अत्यन्त उच्च जर्मन अधिकारी ग्रहण करते थे ।"

भारत सरकारने क्रान्तिकारियोंको सख्तसे सख्त लोमहर्पक दण्ड दिलानेके उद्देश्यसे भारत रक्षा कानृन पास करके कानृनकी साधारण पद्धति बदल दी थी। इस कानृनमें 'क्रान्तिकारी अपराधों'के सुकदमोंके लिए 'असाधारण पंच अदालतों'की व्यवस्था थी, कानृनमें न तो पंच अदालतोंके आगे किसी अन्य फैसले या क्षमादानकी गुंजाइश थी और न अपीलकी ही थी अतः किसीको भी जिसे पुल्सि क्रान्तिकारी समझे,सजा देना काफी आसान कर दिया गया या। भारत रक्षा कानृनके नियमोंको सख्तीसे लागू किया गया, काफी बड़ी तादादमें लोगोको विना मुकदमा चलाये जेलमें नजरबन्द कर दिया गया और जिनके बारेमें साधारण से साधारण शक हुआ उनपर विभिन्न प्रकारकी पावन्दियाँ लगा दी गयीं। कुछ पत्र-पत्रिकाओं पर्याश्वासक पूर्व सेन्सरके आदेश थे। तिलक और विपिनचन्द्र पाल जैसे नेताओं को पंजाबमें प्रवेश करनेकी अनुज्ञा नहीं थी। राजभक्त सिखोंकी सलाहकार समितियाँ बना दी गयी थीं जिनका काम अपने धर्म-बन्धुओंको क्रान्तिपथसे विरत्त करना था। पंजाबको कहानीके उप-संहारमें राजद्रोह कमेटीकी रिपोर्टने कहा कि "पंजाबमें गदर आन्दोलन ऐसी खितिपर पहुँच गया था कि न्यापक रक्तपात होते-होते वाल-वाल बच गया।" पंजाबके अफसरोंकी राय थी कि "अगर सरकारके पास भारत रक्षा कानृन और इंग्रेस आर्डनेन्स जैसे व्यापक शक्ति वाले हिथार न होते तो गदर आन्दोलनका इतनी शीवतापूर्वक दमन नहीं हो सकता था।"

कुरतुन्तुनियामें "जहान-ए-इरलाम" नामका एक और पत्र मई १९१४ में निकला । उसमें अरवी, तुर्की और हिंदीमें लेख रहते थे । इसके उर्दू अंद्राको पंजावके अबू सम्यद तैयार करते थे । महायुद्ध की घोषणाके वाद इस पत्रके उर्दू अंद्रामें हरदयाल लिखित एक ब्रिटिश विरोधी अग्रलेख था । २० नवम्बर सन् १९१४ के अंकमें अनवर पाद्राका एक भाषण छपा था जिसमें अन्य वार्तोंके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा था—"यही समय है जब भारतमें गदरकी घोषणा हो जानी चाहिये, अंग्रे जोंके तोपखाने व शस्त्रास्त्रोंपर जबरदस्ती कन्जा करके, उनके हथियार लूटकर उन्होंसे उनका खात्मा कर देना चाहिये। भारतीय ३२ करोड़ तो हैं ही और अंग्रेज सिर्फ २ लाख हैं—उन्हें मार डालना चाहिये, उनके पास फीज

नहीं है। कुछ ही दिनों में तुर्क स्वेज नहरका नाका रोक देंगे। यह व्यक्ति जो मरकर अपने देश, अपनी मातृभूमिको आजाद करायेगा, हमेशा अमर रहेगा। हिन्दुओ और मुसलमानो! तुम दोनों फीजके सिपाही और भाई-भाई हो, ये नीच अंग्रेज तुम्हारे तुस्मन हैं। तुम्हें जेहादकी घोपणा करके गाजी वनना चाहिये और अपने भाइयोंसे मिलकर अंग्रेजोंको मारकर भारतको आजाद कराना चाहिये।" इस समय हरदयाल कुस्तु-तुनियामें थे। "जहान-ए-इस्लाम" की प्रतियाँ छाहोर और कलकत्तामें विना मूल्य मिल सकती थीं।

नवम्बर-दिसम्बर १९१४ में फौजके एक अंशमें सिपाही-विद्रोह हो गया । यह सुद्र-पूर्वमें तुका सरकारसे भारतीयोंके सहयोगकी कहानी है। १९१३ में रंगृनके एक व्यापारी अहमदमुल्ला दाऊदको रंगन स्थित तुकी सरकारके प्रतिनिधिका पद मिला और इस पद पर वे महायुद्धके आरम्भतक रहे। दिसम्बर सन् १९१४ के अन्तिम सप्ताहमें रंग्नके एक गुजराती मुसलमान कासिंग मंसूरने रंगृनमें अपने पुत्रको एक पत्र मेजा जिसके साथमें तुर्कीके प्रतिनिधि दाऊदके नाम सिंगापुरकी दो रेजीमेंटोंमेंसे एक "मलय स्टेट्स गाइड्स" द्वारा भेजी गयी अपील तथा यह सूचना भी थी कि रेजीमेंट ब्रिटिश सरकारके विरुद्ध विद्रोह करनेके लिए तैयार है। यह पत्र ब्रिटिश अधिकारियोंके हाथ लग गया और मलय स्टेट्स-गाइड्सका दूसरी जगह तवादला कर दिया गया। फिर भी विद्रोह, योजनाके मुताविक, मलय स्टेट्सगाइड्समें न सही ५ वीं लाइट इनफैंटरीमें हो ही गया । ५ वीं लाइट इनफैंटरी जिसमें सभी मुसलमान और अधिकांशतः भारतीय थे, भारतसे हांगकांगके लिए रवाना होनेको थी और उसे ले जानेके लिए जहाज तैयार खड़ा था। "वटालियनकी सामरिक सामग्री एलेक्जेंडा वैरकोंपर लारियोंपर लादी जा ही रही थी कि एक गोलीका फायर हुआ और इसके वाद तुरन्त ही चिनगारी मानों ज्वाला वन गयी। राजभक्तिका दम भरनेवाले वहीं मार गिराये गये और विद्रोहयोंकी तीन दुकड़ियाँ वन गयीं। एक दुकड़ीको जर्मन नजरवन्दी शिविरके संतरियोंको पराभृत करके वन्दियोंको आजाद कराना था, दूसरीको ५ वीं इनफेंटरीके कर्नलके मकानपर इमला करनेका काम सौंपा गथा और तीसरी सिंगापुरसे आनेवाली कुमक-को रोकनेके लिए तैनात कर दी गयी। लेपिटनेन्ट मांटगोमरी, नजरबन्दी शिविरके कमांडर, गोलीसे उड़ा दिये गये । इसके वाद भयानक हत्याकाण्ड मचा । अनेक ब्रिटिश अफसर और कुछ जर्मन जानसे मारे गये। विद्रोही इसके बाद जिस गोरेको भी जहाँ मिले वहीं मार गिरानेके लिए आगे बढ़े । सबसे पहले एक मोटरकार मिली जिसे उन्होंने रोकनेके लिए हाथ दिया। जब वह न रकी तो उन्होंने मोटरके अन्दर बैटे हुए जिलाजज और एक अंग्रेज व्यापारीको गोळीका निशाना वनाया और वे तत्काल मर गये। इसी प्रकार न जाने कितनी मोटरं रोकी गयीं और उनमें सवार गोरे मार डाले गये। बादमें न्यू ब्रिज रोडपर उन्होंने एक कार रोकी जिसमें ५ व्यक्ति थे। उन्होंने दो अंग्रेजोंको मार डाला, तीसरेको मुर्दा समझकर छोड़ दिया, भारतीय शोफरको भी मार डाला, पर उसी दलमें एक महिला थी उसपर हाथ न लगाया । इसके वाद उन्होंने एक डाक्टर और उसकी पत्नीपर हमला किया-डाक्टरको गोली मार दी पर इस बार फिर उसकी पत्नीको छोड़ दिया। दूसरी टुकड़ीको तीन गोरे मिले जिनमें एक लेपिटनेन्ट ईलियट, स्वयं उन सैनिकोंके अफ़सर भी थे—चे तीनों मार डाले गये। इसके बाद सैनिक एक बंगलेसे होकर गुजरे जिसके बरामदेमें बैठे ३ अंग्रेज धूम-पान कर रहे थे—उन्हें भी मृत्युके घाट उतार दिया गया। अब विद्रोहियोंका उस स्थानपर

सोलहों आना कब्जा था — और ३ दिनतक यह कब्जा वना रहा । चौथे दिन नयी रेजिमेंटें आयीं और उन्होंने पूरे तांगलिनपर, एलेक्जेंड्रा वैरकों तथा नारमण्डानपर कब्जा किया। विद्रोहियोंके २ नेताओंको फाँसी दी गयी, ३८ को गोली मारी गयी — और ये सजाएँ सरे वाजार दी गयीं। ३०० के करीब विद्रोही भागकर जंगलोंमें जा छिपे। १

एक अन्य रेजीमेण्ट जिसमें विद्रोह होते होते वचा था वम्बईकी १३० वीं वल्ल्ची रेजीमेण्ट थी। नवम्बर १९१४ में इसके कुछ सिपाहियोंने अपने अफसरोंमेंसे एकको मार डाला, तव वतौर सजाके पूरीकी पूरी रेजीमेण्टका तबादला वम्बईसे रंगूनको कर दिया गया। वहाँ 'गदर' अखवारसे उसे क्रान्तिकी पूरी खूराक मिली और जनवरी १९१५ आनेतक वह नीचेसे ऊपरतक अंग्रेजोंसे नाराज और गदरके लिए तैयार हो चुकी थी। पर किसो प्रकार इसका सुराग लग गया और कटोर कारखाई द्वारा विद्रोह आरम्म होनेके पहले ही मसल दिया गया। वल्ल्ची रेजीमेण्टके २०० जवानोंका कोर्टमार्शल हुआ।

इसी वीच अलीअहमद सिदीकी और हकीम फहीम अली रंगूनमें एक गुप्त सोसायटी संघटित कर रहे थे जिसका उद्देश था ब्रिटिश शासनको उखाड़ फेंकनेमें मदद करना। वे 'रेड क्रिसेंट सोसायटां के सद्ध्यकी है सियतसे वालकन युद्धमें तुकी फोजको डाक्टरी मदद देनेके लिए भारतसे तुर्का गये थे। तुर्कांके महायुद्धमें शामिल हो जानेके वाद वे वापस आये और रंगूनमें वस गये। उन्होंने क्रान्तिके लिए धन और हथियार जमा किये। करीव करीब उसी समय हसनखाँ और सोहनलाल (वादमें सेनफ्रांसिस्कोसे आया हुआ प्रतिनिधि) वंकाकसे आये और रंगूनमें इसी उद्देश्यंसे एक मकान किरायेपर लेकर रहने लगे। विभिन्न कान्ति-कारियों में निकट संपर्क स्थापित हो गया पर सरकारको भी पता चल गया कि एक पड्यन्त्रको भूमिका तैयार हो रही है। क्रान्तिकारी वर्माकी फौजी पुलिसमें जिसमें १५ हजार आदमी थे-विद्रोह करनेकी योजना बना रहे थे। पाटकने "मेमियो स्थित माउंटेन वैटरीके कुछ लोगोंसे मिलकर इनकी सरकारकी सेवा करनेकी मूर्खतापर लथाड़ा।³³ अपने साथ वे जहाँन-ए-इस्लामकी एक प्रति, एक फतवाकी कई प्रतियाँ जिसमें "खुदाके वन्दोंसे नाखुदाओं-को वरवाद करनेकी अपील "थी- गदर अखवारका एक अंक, वम व वारूद वनानेकी पूरी विधिका व्योरा, तीन आटोमेटिक पिस्तौलें और २७० कारत्सें भी ले गये थे। पर एक वफादारने उन्हें गिरपतार करके अफसरोंके हवाले कर दिया। पाँच दिन वाद प्रायः इसी प्रकारके माल सहित उनके साथी नारायणसिंह भी मेमियोंमें गिरफ्तार कर लिये गये। रेजी-मेण्टमें पंजावके सिख और मुसलमान थे और मुसलमानोंके लिए फतवा काफी प्रभावशाली तरीका समझा जाता था।

रंगूनकी मुसिलम गदर पार्टीने अक्तूबर सन् १९१५ में वकरीदकें मौकेपर गदरकी योजना बनायी थी और अपील की कि "वकिरयों या गायोंके बजाय अंग्रेजोंकी कुरवानी दो।" पर यह विद्रोह मुलतवी कर दिया गया। "नवम्बरमें प्याववे स्थित फौजी पुलिसमें एक गदर योजनाका मेद खुला और गदरमें काम आनेवाले रिवाल्वर, डाइनामाइट और अन्य वस्तुएँ पकड़ी गर्यों।" कई व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

रंगूनकी इन काररवाइयोंके फलस्वरूप दो पड्यन्त्रके मुकदमे चले जो वर्मा पड्यन्त्र

त. लेफिटनेंट जनरल सर जार्ज मैकमन—"टरमायल एण्ड ट्रोजडी इन इण्डिया १९१४ एण्ड आफटर, पृष्ठ १०५-१३

केसके नामसे विख्यात हैं, और इनकी सुनवाई १९१६ में माँडलेमें विद्येप अदालतके सामने हुई थी। अदालतने फैसलेमें लिखा कि "इसमें दाक नहीं किया जा सकता कि पड्यन्त्रका आरम्भ सन् १९१२ में हुआ था, और इसका उद्देश्य सदास्त्र विद्रोह द्वारा भारतको ब्रिटिश राजसे मुक्त करना—अंग्रेजोंको भारतसे वाहर निकालना और देशका शासन देशको जनताको देना था।"

कान्तिकी लहर भारतके विभिन्न क्षेत्रोंमें और उसकी सीमाके वाहर भी फैल रही थी। अतः सीमा प्रदेशमें जो वहावी आन्दोलनके त्फानका केन्द्र हो चुका था—एक वार फिर उमार आया। पर वहावी उत्साह और भावना वापस न आ सकी अतः वे प्रवत्न भी निष्फल सिद्ध हुए। ब्रिटिश अधिकारियोंने आरम्भ होते ही इसे दवा दिवा।

फरवरी १९१५ में लाहीरके १५ विद्यार्थी कालेजकी पढ़ाई छोड़कर सीमान्त प्रदेशमें रहनेवाले विद्रोही भारतीयों—''मुजाहिदीन'' से जा मिले। वहाँसे वे काबुल गये, जहाँ वे नजरवन्द कर लिये गये। वे वादमें रिहा कर दिये गये, पर उनपर निगरानी रखी गयी और उन्हें घूमने-फिरनेकी पूरी आजादी नहीं थी। वादमें उनमेंसे तीनको रुसियोंने गिरपतार करके ब्रिटिश अधिकारियोंके हवाले कर दिया। उनकी योजना असफल हुई और उसके साथ ही वहावी आन्दोलनको पुनर्जीवित करनेका पहला प्रयत्न भी।

उसी वर्ष भारतमें एक योजना तैयार की गयी कि उत्तर पश्चिमी सीमापर आक्रमण करके और उसीके साथ देशमें विद्रोह आरम्भ करके ब्रिटिश शासनको समाप्त किया जाय। ''इस योजनाको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिए उत्रैदुल्ला एक धर्मपरिवर्तित सिख, जो सहारनपुर जिल्हेमें देववन्दके मुसलमान धर्मके स्कुलमें दीक्षा प्राप्त कर चुके थे, अगस्त सन् १९१५ के प्रारम्भमें तीन साथियों अन्दुल्ला, फतेहमुहम्मद और मुहम्मद अलीके साथ उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्तको पार कर गये । रवाना होनेसे पूर्व उर्वेदुल्लाने दिल्लीमें एक स्कृल स्थापित किया था और दो कितावं दस्ती तौरपर वाँटनेके लिए जारी की थीं जिनमें भारतीय मुसलमानींके धर्मके लिए अन्धे होकर मारने और मर जानेका उपदेश देते हुए जिहादको सर्वोपरि कर्त्तव्य वताया गया था।" उवैदुल्लाकी रवानगीके महीने भर वाद उनके देववन्द स्कूलके दो साथी मुहम्मद मियां अंगारी और महमृद हसन भी रवाना हुए— सीमा प्रान्तकी ओर नहीं हज्जाजके लिए, और १९१६ में अंसारी वहाँके तुर्का फीली गवर्नर गालिवपाशाके हाथीं लिखा हुआ जिहादका फतवा लेकर आये। रास्तेम मुहम्मदने इस दस्ताचेज ''गालिवनामा'' की नकलें भारतमें और सीमास्थित कवाइलियोंमें वॉटीं । उर्वेटुस्ला और उनके मित्र सीमा प्रदेशमें कुछ दिन टहरनेके बाद काबुल चले गये जहाँ वे टक्नं जर्मन शिष्टमण्डल से मिले । अंसारी भी उन्हीं लोगोंमें पहुँच गये । तय यह हुआ कि विद्रोहियोंको काम-चलाऊ भारत सरकारकी खापना कर लेनी चाहिये जो अंग्रेजोंके भगाये जानेके बाद फौरन काम सम्भाल ले । इस काम-चलाऊ सरकारका राष्ट्रपति राजा महेन्द्रप्रतापको और प्रधान मन्त्री वरकतुल्लाको वनाना तय हुआ । महेन्द्रप्रताप सन् १९१४ के अन्तमें भारतसे गये थे और जैनेवा जाकर वे हरदयालसे मिले थे। हरदयालने उनका परिचय जर्मन प्रति-निधिसे कराया था । बादमें उन्हें भारत सरकारने भारतसे निर्वामित कर दिया और स्वदेश वापस आनेकी अनुमति उन्हें सन् १९४७ में भारतकी आजादीके वाद मिली। वरकतुरुला श्यामजी कृष्ण वर्माके मित्र थे और अमेरिकी गदरपार्टीके सदस्य थे। वे कुछ समय तक

टोकियो विश्वविद्यालयमें हिन्दुस्तानीके प्रोफेसर रह चुके थे और वहींसे उन्होंने "इस्लामिक फेटरिनटो" नामके ब्रिटिश विरोधी पत्रका सम्पादन भी किया था जिसका जापानी अधिकारियोंने प्रकाशन वन्द कर दिया। वहाँसे वर्लास्त होनेके वाद वे अमेरिका पहुँचे। "कामचलाऊ भारत सरकार" ने अपना काम भी विधिवत आरम्भ कर दिया और रूसी तुर्किस्तानके गवर्नर तथा तदनन्तर रूसके जारको पत्र लिखे गये थे जिनमें रूसको ब्रिटेनकी मैत्रीका जामा उतारकर भारतसे अंग्रेजी राज्यका नामोनिशान मिटानेमें मदद करनेका निमन्त्रण दिया गया था। इन पत्रींपर महेन्द्रप्रतापके हस्ताक्षर थे। ये वादमें ब्रिटिश सरकारके हाथमें पड़ गये। काम-चलाऊ सरकारने दुकी सरकारसे मैत्री सन्धि करनेका भी प्रस्ताव किया था और एक फीज संघटित करनेकी त्योरेवार योजना भी तैयार की थी।

मार्चमें जितेन्द्रनाथ लाहिड़ी यूरोपसे बम्बई आये और जर्मन मददके वादे भी साथ लाये। वे कलकत्ता गये और वंगालके कान्तिकारियोंको उन्होंने यह सन्देश दिया तथा वटावियामें एक प्रतिनिधि भेजनेका आग्रह किया।

फलतः नरेन्द्र भट्टाचार्य अप्रैलमें सी० मार्टिनके फर्जा नामसे वहाँके जर्मनोंसे पूरी योजना तय करनेके लिए वटाविया भेजे गये । वटाविया पहुँचने पर मार्टिनका परिचय जर्मन प्रतिनिधिने एक थियोडोर हेलफरिचसे कराया जिसने वताया कि हथियारों और गोली वारूदसे लदा हुआ एक जहाज "मैवरिक" कराची भेजा जा चुका है। परन्तु मार्टिनके सुझावपर और जर्मन शंघाई राजदूतसे सलाह करके यह तय हुआ कि जहाज कराची न जाकर वंगाल जाये। कहा जाता था कि जहाजमें २००० रायफलें, प्रत्येकके लिए ४०० कारतूस और २ लाख रुपया था। मार्टिन जूनके मध्यमें इस मालको उतरवानेका इन्तजाम करनेके लिए भारत लौट आये । इस बीच मार्टिनने ''हैरी एण्ड सन्ध" के फर्जी नामवाली संस्थाको कई वार थोड़ा-थोडा करके कुल करीव ४२०००) भी भेजा। तय हुआ कि पूरा माल रे भागींमें बाँटा जाय और (१) हटिया, पूर्वी बंगाल (२) कलकत्ता और (३) वालासीर, भेजा जाय। विद्रोहकी पूरी योजना तय कर छी गयी। क्रान्तिकारियोंने विचार किया कि वे संख्यामें इतने काफी हैं. कि वंगालकी फौजोंसे निपट सकते हैं, परन्तु डर यह है कि कहीं वाहरसे मदद न आ जाय। इसिलए उन्होंने तय किया कि प्रमुख पुलेंको उड़ाकर वंगालमें वाहरसे आनेवाली तीनों रेल लाइनोंको रोक दें । जतीन्द्र मुकर्जा, भोलानाथ चटर्जा और सतीश चक्रवर्त्ता इस कामपर लगा दिये गये । नरेन्द्र चौधरी और फणीन्द्र चक्रवर्त्तांसे कहा गया कि वे हटिया जाव, वहाँ एक दल बनावें और पहले पूर्वी वंगालके जिलोंपर कब्जा करके फिर कलकत्तेपर धावा करें। कलकत्तेके दलका, नरेन्द्र भट्टाचार्य और विपिन गांगुलीके नेतृत्वमें काम यह था कि वह सबसे पहले कलकत्तेके आस-पासके सभी सरकारी शस्त्रास्त्रों व शस्त्रालयोंपर कब्जा कर लें। तय यह हुआ कि ''मैवरिक'' पर आनेवाले जर्मन अफसर पूर्वी वंगालमें ठहरेंगे और वहींपर लोगोंको क्रान्तिकारी फौजमें भर्ती करके उनको ट्रेनिंग दी जायगी।

सची वात यह थी कि जहाज "एस॰ एस॰ मैवरिक" में हथियार नामके लिए भी नहीं थे! योजना यह थी कि वह "एनी लारसन" नामक जहाजसे मिलकर उसपर लदे हुए शस्त्रास्त्र जो टाउशर नामक जर्मन द्वारा न्यूयार्कमें खरीदे हुए होंगे, ले लेगा। "मैवरिक" सैनफांसिस्कोकी एक जर्मन कम्पनी एफ. जेवसन एण्ड कम्पनी द्वारा खरीदा हुआ तेलकी टंकी वाला स्टीमर था। वह कैलीफोर्निया स्थित सैनपैड्रो नामक स्थानसे २२ अप्रैल सन् १९१५ के करीव विना किसी मालके रवाना हुआ । उसपर चालककी हैसियतसे २५ अफसर सभी भारतीय थे । उनमें एक पजावी हरिसंहके पास सन्दूकों में काफी "गदर" साहित्य था । "मैचरिक" सबसे पहले कैलीफोर्नियाके सैनजोसे डेलकावो पहुँचा और वहाँसे जावामें स्थित अनजेर वन्दरगाह जानेको अनुमति प्राप्त की । इसके बाद वह मैक्सिकोसे ६०० मील सोकोरो हीपको "एनी लारसन" बहाजसे मिलनेके लिए चला । पर यह मुलाकात कभी न हुई । "एनी लारसन" वाशिंगटन क्षेत्रमें हकीम वन्दरपर पहुँचा जहाँ उसपर लदा हुआ माल अमेरिकी अधिकारियोंने पकड़ लिया । इस प्रकार जर्मन सहायताका प्रथम अध्याय समाप्त हुआ । हेल्करिचने "मैवरिक" के चालकदलको अमेरिका वापस मेजा जिसमें हरिसंहके बजाय "मार्टन" मेजे गये थे । वहाँ मार्टिनको अमेरिकी सरकारने गिरफ्तार कर लिया ।

''मैबरिक''की असफलताके वाद भारतमें भारी परिमाणमें शस्त्रास्त्र चोरी-छिपे पहुँचानेके कई प्रयत किये गये परन्तु सभी वेकार सिद्ध हुए । शंवाई स्थित जर्मन प्रधान प्रतिनिधिने चार जहाजोंको बंगालकी खाड़ी भेजनेकी योजना बनायी। पहलेमें २० हजार रायफलें, ८० लाल कारतस. २ हजार पिस्तीलें, हथगोले व अन्य विस्फोटक तथा ^२ लाख रुपये थे— दूसरेमें १० हजार रायफलें १० लाख कारतृष और इथगोले व विस्फोटक पदार्थ आने थे। तीसरेका इंजन रास्तेमें खराव हो गया अतः वह आगे वढ़ ही न सका । चौथेके लिए योजना यह थी कि वह पहले पोर्ट व्लेयरपर आक्रमण करेगा । वहाँसे कान्तिकारी केंद्रियों और विद्रोही सिंगापुर रेजीमेंटके लोगोंको लेगा और तब रंगुनपर इसला करेगा। लेकिन जो भी लोग भारतसे शंघाई या अन्य स्थानोंको इन जहाजोंकी समुद्र-यात्राका इन्तजाम करनेके लिए गये थे वे सबके सब गिरफ्तार कर लिये गये और पूरी योजना वेकार हो गयी। परन्तु इसी बीच एक जर्मन पनडुची 'एमडेन'ने बंगालकी खाड़ीमें प्रवेश किया और कई ब्रिटिश मालके जहाजींपर हमला करनेके साथ-साथ भारतके पूर्वी तटपर गोलावारी भी की। अंदमानमें अफवाह थी कि 'एमडेन' पनडुट्यी सावरकरकी वहाँसे टेकर किसी जर्मन विमान द्वारा 'गदर'के प्रधान कार्यालयतक पहुँचानेके उद्देश्यसे आर्या है। इसी वीच उक्त 'एमडेन' पनइन्त्री नवम्त्रर १९१४ में नष्ट कर दी गर्या। अक्तूबर १९१५ में दो चीनो १२९ पिस्तीली और २०,८३० कारतूनों सहित, जिन्हें तख्तोंके वण्डलोंके भीतर छिपाकर कलकत्ता ले जानेकी उनको नील्सेन नामक जर्मनने हिदायत की थी, दांचाईकी म्यूनिसिपल पुलिसके हाथों गिरफ्तार हो गये। ब्रिटिश खुफिया दलको चौकसीने भारतीय क्रान्तिकारियोंकी करीय-करीव हर योजना निष्मल कर दी।

अध्याय १६

होमरूल आन्दोलन

कांग्रेसको डुलमुल नीतिसे उग्रपन्थियोंकी ही तरह असन्तुष्ट एक अन्य महान् व्यक्तित्व मानवतावादी दार्शनिक आयरिश महिला श्रीमती एनी वेसेण्टका था । राजनीतिमें प्रवेशसे दो दशान्दोंसे अधिक पहलेसे वे भारतमें समाजसेविका और धर्मसुधारकका काम कर रही थीं। वे एक अंग्रेन पादरीकी पत्नी यों, पर युवावस्थामें ही उन्होंने एक प्रगतिशील एवं नास्तिक सामयिक पुस्तकोंकी लेखिका तथा भाषणकत्रोंकी हैसियतसे अपना स्वतंत्र स्थान वना लिया था । वर्पोतक उन्होंने चार्स्स बैडलाके साथ काम किया और शनैः शनैः उनका आकर्पण समाजवादकी ओर हो गया। बैंडला समाजवादके विरोधी थे पर समाजसेवाके क्षेत्रमें दोनों साय काम करते रहे। वादमें वे एक रूसी महिला व्लाशन्स्कोसे सोखे हुए मानवधर्म सिद्धान्त (थियों छो भी) की ओर आकृष्ट हुईं। उन्होंने यूरोपक अनेक देशों और अमेरिकाकी यात्रा की थी। सन् १८९३ में वे थियोसोफिकल सोसायटीका काम करने भारत आयीं जिसकी वे सन् १९०७ में अध्यक्षा हो गयीं । १८९३ में भारतकी प्रथम यात्राके समय ही उन्होंने ६००० मील यात्रा की और भारतके विभिन्न मागोंमें पहुँचों । उनमें हिन्दू ग्रन्थोंके प्रति आकर्षण वढ़ा और प्राचीन भारतीय गौरवका पुनरुत्थान उनका संकल्प हो गया। सन् १९१४ तक वे पूरी तरह धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक कार्योंमें लगी रहीं। पर सन् १९१४ के वसन्तमें वे राजनीतिकी ओर मुड़ीं और उन्होंने अपने साथके कार्यकर्ताओंको मददसे ''दी कामनवील" नामते एक साप्ताहिक पञ्चालीचन पत्रिका निकाली । वादमें उसी वर्ष उन्होंने "न्यू इण्डिया" के नामसे एक दैनिक पत्र निकाला। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा था-"इस दैनिक ओर 'कामनवील' साप्ताहिकका जन्म होमललके संघर्षको बढ़ानेके लिए हुआ था।"-और वस्तुतः सन् १९१६-१७ में इन पत्रींने होमरूलका अण्डा ऊँचा किया भी।

होमलल आन्दोलनका आरम्भ इस प्रकार हुआ। सन् १९१५ में वेसेण्टने कांग्रेस और मुस्लिम लीगके सामने —जो दोनों संस्थाएँ उस समय करीव आ रही थीं —एक होमलल लीग आरम्भ करनेका मुझाव रखा। पहले तो कांग्रेस और लीगमें से किसीने भी इस ओर दिलचस्त्री न दिखायी, पर शीव ही दोनोंको इस आन्दोलनके महत्त्वका पता चल गया। वेसेण्टकी योजनाके अनुसार भारतको ब्रिटिश साम्राज्यके स्वशासित प्रदेशोंकी भाँति स्वशासन-भिलना चाहिये था। उनकी दलील थो "होमललका अर्थ यह नहीं है कि इंगलैण्ड और भारतका एकदम सम्बन्धविच्छेद हो जाय। इसका अर्थ केवल यह है कि भारतमाता अपने घरकी पूरी तरह स्वामिनी हो जाय।"

कांग्रेस, सालभरमें एक बार प्रस्ताव पास करके चुप होकर वैठ जानेवाली संस्था होनेके नाते बहुत कुछ एक रसमअदायगीका रूप धारण करती जा रही थी और हर कांग्रेसी यहाँतक नम्रतम उदारपन्थी, एस. पी. सिनहा भी यह अनुभव करने लगे थे कि लगातार काम करनेके

१. एनी वेसेण्ट--'होमहल एण्ड दि एम्पायर' (१९१७), पृष्ठ १०

लिए कुछ तरीका होना चाहिये। वम्बई कांग्रेसके अध्यक्षपदसे उन्होंने कहा था—"में यहाँ-पर उपस्थित आप लोगोंकी ही तरह या जायद कहीं अधिक अपनी मदद आप करनेके सिद्धान्तमें यकीन करता हूँ। इसलिए में कहता हूँ कि वर्षमें तीन दिन इस प्रकारकी वक्तुताओंकी महफिल जमाने मात्रसे सन्तुष्ट न होकर हमको लगातार कार्य करनेका कार्यक्रम वनाना चाहिये। कामसे मतलब सिर्फ राजनीतिक नहीं जिसमें सार्वजनिक सभाएँ की जायँ, विक्त कामका मतलब है दिलतों और कमजोरोंको कपर उठानेकी कोशिश।"

सन् १९१६ की गर्मियों में कांग्रेस और मुस्लिम लीगकी, इसी उद्देश्यके लिए खास तौरपर नियुक्त कमेटियों की बैठक हुई और होमल्ल स्कीम मंजूर की गयी। वेसेण्टने शीप्र ही समाओं तथा समाचारपत्री द्वारा होमल्लका प्रचारकार्य तेजीसे आरम्भ कर दिया। वही दिन थे जब क्रान्तिकारियों ने भारतकी मुक्तिके लिए दूसरा मोर्चा खोल रखा था और उनमेंसे कुछ विदेशोंसे—उदाहरणार्थ जर्मनीसे—जिससे उस समय ब्रिटेन और उसके मित्रराष्ट्रींका युद्ध चल रहा था—कौजी मदद पानेका प्रयत्न कर रहे थे। इसलिए वेसेण्टने यह तर्क उपस्थित किया—"होमल्ल भारतके युवकांके लिए एकदम आवश्यक है क्योंकि भारतका युवकसमाज उस शिक्षाके मातहत जो उसे प्राप्त हो रही है, गलत ढंगते शिक्षित एवं गुमराह किया जा रहा है। कालेजोंके उन लड़कां और स्कूलोंके उन बचोंके हृदयमें अशान्ति और असन्तोधकी ज्वाला है, जो समय-समयपर दुःखप्रद हड़तालोंके रूपमें फूट निकलती है और जिसे छात्रवर्गका कोई प्रेमी उचित नहीं कह सकता। बच्चे हताश हैं और बहुतसे तो क्षणिक पागलपनमें अपना पूरा जीवन वरवाद कर डालते हैं। । स्क्षिप आन्दोलनका एक विशिष्ट महत्त्व था और वह यह कि ब्रिटेनके लिए विना रक्तपातके भारतको स्वशासन प्रदान करना अधिक गौरवकी वात होगी।

होमहलको प्रेरणा मिली थी आयरलैण्डके आन्दोलनसे और विश्वास किया जाता था कि भारतमें भी विलक्कल उसी प्रकारकी राजनीतिक स्थिति हैं। यह भी यकीन था कि (स्र) भारतकी जनता और राजनीतिज्ञोंके वीच कुछ वैसा ही रिश्ता है जैसा आयरलैण्डके होमहल आन्दोलनके नेताओंका अपने देशकी अधिकतर जनतासे है और (य) अगर ब्रिटिश शासक यहाँसे हट जाई तो यहाँके विभिन्न धमों, जातियों और मतमतान्तरोंके भेदप्रमेद आपसमें टीक हो जाईंगे।

दो वपींतक होमहल आन्दोलन इतनी तेजीसे वदा कि वह कांग्रेसपर छा-सा गया। कांग्रेसकी ब्रिटिश कमेटी, अपने ही शब्दोंमें, सिर्फ एक पर्यवेश्वक या दर्शकमात्र रह गयी थी। वेसेण्ट एक अधिक सिक्ष्य संस्था चाहती थीं और १२ जून सन् १९१६ को उन्होंने इंगलैण्डमें सहायक होमहल लीगका संघटन किया। वह स्वतन्त्र संस्था नहीं थी विहक्ष कांग्रेसके स्व-शासन प्रस्तावके मातहत बनायी गयी थी।

तिलक इस नयी लहरमें इतना वह गये थे कि वेसेण्टके कार्यक्षेत्रमें कूदनेने पहले ही उन्होंने रवयं ही १२ अप्रैल १९१६ के दिन महाराष्ट्रमें होमरूल लीगकी खापना कर दी जिसका प्रधान कार्यालय पूना था। पर नौकरशाही उनकी जानी दुश्मन थी। जब कि वे छात्रों से फोजमें मतीं होनेकी अपील कर रहे थे उन्हें पंजाव सरकारका आदेश मिला जिसके मुताविक

१. वेसेण्ट, वही पुस्तक, पृष्ठ १३

२. लवेट, ए हिस्ट्री ऑव इंडियन नैशनल स्वमेंट (१) पृ० १०६

उन्हें पंजाव या दिल्लीमें घुसनेकी मुमानियत कर दी गयी। उसी समय उनसे २० हजारका जाती मुचलका और दस दस हजारकी दो जमानतें भी ली गयीं। पर इस दमनने उन्हें और अधिक लोकप्रिय बना दिया। वे जहाँ कहीं भी गये उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्हें थैलियाँ मेंट की गयीं। उनकी ६० वीं वर्षगाँठपर उन्हें १ लाखकी थैली मेंट की गयी जो उन्होंने राष्ट्रीय सेवाके लिए दान कर दी। लखनऊ कांग्रेसमें आते समय उनका लखनऊ रेलवे स्टेशन और कांग्रेस पण्डाल दोनों जगह शानदार स्वागत हुआ।

मई, जून सन् १९१६ में उन्होंने वेलग्राम और अहमद नगरमें सार्वजिनक समाओं में होमरूलपर भाषण किये। उन भाषणोंको बम्बई सरकारने ब्रिटिश शासनके विरुद्ध घृणा और अवमानना फैलानेवाला समझा और उन्हें एक सालतककी नेकचलनीके लिए भारी जमानत जमा करनेकी आशा दी गयी पर उस आशाको बादमें वम्बई हाईकोर्टने रद कर दिया। उन भाषणोंका सारांश यह था "जब राष्ट्रकी जनता शिक्षित होकर यह समझने लगती है कि वह अपने देशका प्रवन्ध स्वयं करे तो उसकी यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह दूसरों से अपने देशका शासन प्रवन्ध स्वयं अपने हाथों में ले ले। यही होमरूल है। इसीका नाम स्वराज्य है। तिलककी उम्र इस समय ६० वर्षकी थी और दूर देशमें ६ वर्षकी लंबी कैदके कारण उनका स्वास्थ्य काफी गिर गया था। पर उनकी आत्मा अब भी अशान्त थी। कांग्रेसकी राजनीतिसे उन्हें असन्तोष था। होमरूल आन्दोलनमें उन्हें आशाकी किरण दिखाई दी थी।

वेसेण्टने अपनी होमरूल लीगकी खापना मद्रासमें सितम्बर सन् १९१६ में की क्योंकि तिलक की संख्या महाराष्ट्रके भीतर ही सीमित थी। उन्होंने अपनी संस्थाका नाम अखिल भारतीय होमरूल लीग रखा और भारतके प्रमुख प्रान्तोंमें (पंजाबको छोड़कर) उसकी ५० स्थानोंपर शाखाएँ खुल गयीं तथा उसकी सदस्यसंख्या भी २-३ हजार हो गयी। वेसेण्टने अपना आन्दोलन समाचारपत्रोंमें लेखों और सभाओंमें भाषणों द्वारा जारी रखा। उन्होंने भारतकी विभिन्न समस्याओंसे सम्बन्धित लेखोंको पुस्तक मालाके रूपमें प्रकाशित किया जिनमें "इण्डियन पोलिटिकल पैम्फलेट्स", "नेशनल कांग्रेस सीरीज", "नेशनल होमरूल सीरीज" प्रमुख हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकों भी लिखी जिनमेंसे उस समय "भारत एक राष्ट्र" का सबसे अधिक प्रचार हुआ। उनकी पुस्तकाओंका भारतीय भाषाओंमें अनुवाद हुआ और वे बहुत बड़ी संख्यामें वितरित हो गयीं। परिणाम यह हुआ कि युवकोंमें राजनीतिक उत्तेन्जना और बढ़ गयी। उन्होंने श्रीमती वेसेण्टका सन्देश घरघर पहुँचाया। सबका उद्देश इस सिद्धान्तका प्रसार था कि भारतमें ब्रिटिश शासन स्वाधीनताके लिए घातक है और होम-रूलकी माँगके लिए प्रभावशाली तथा सक्तय संघटन होना चाहिये।

वे बहुधा कहा करती थीं—'मैं खूव समझती हूँ कि जव लोग सो रहे हों और खासतौरसे जब उनकी तबीयत भारी हो तब वे रातभर लगातार नगाड़ा बजा बजाकर जगाने-वालेको पसन्द नहीं करते। पर मेरा यही काम है कि मैं सोते हुए भारतीयोंको जगाकर उन्हें मातृभूमिकी सेवा करनेकी प्रेरणा प्रदान करूँ और वे हर ओर जाग रहे हैं—युवक तो वृद्धोंकी अपेक्षा तेजीसे जागकर उज्ज्वल भविष्यको पहचान रहे हैं। तुम्हें याद रखना चाहिये कि भारत क्या था। तुम्हें समझना चाहिये कि ईसाके जन्मसे ३ हजार वर्ष पहले भारत वाणिज्य और व्यापारमें महान् था।",

उनकी पत्रिकाओं में प्रकाशित कुछ लेखों को मद्रास सरकारने रंगभेद भड़कानेवाला समझा और उनसे प्रेस ऐक्टके मातहत भविष्यमें "अपने प्रकाशन ठीं कर रास्तेपर" रखने के लिए २०००) की जमानत माँगी गयी। यह जमानत शीं प्रही जन्त हो गयी और फिर इससे बड़ी जमानत माँगी गयी तो उन्होंने जमा तो कर दी पर हाईकोर्टमें जन्तीके खिलाफ अपील की। अपील खारिज हो गयी।

वादमें श्रीमती वेसेण्टको वम्बई और मध्य-प्रदेशमें बुसनेकी इन स्वॉकी सरकारोंने सुमानियत कर दी पर इसका उनके कामपर कोई असर नहीं पड़ा ।

वे उप्रवादी कांग्रेसजनों में इतनी लोकप्रिय हो गर्यी कि उनका नाम सन् १९१६ में कांग्रेसके अध्यक्ष-पदके लिए प्रस्तावित कर दिया गया लेकिन नरमदलीय उम्मीदवार अभ्विकाचरण मजुमदारके सुकावलेमें—जिन्हें श्रीमती वेसेण्टको प्राप्त २५ वोटोंके विरुद्ध ६१ वोट प्राप्त हुए—वे चुनावमें हार गर्थी।

कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा होमरूल आन्दोलनका समर्थन और उग्रवादियोंके प्रयक्षींके फलस्वरूप नरमदलीय नेताओंका भी इस ओर छकाव देखकर वेसेण्टने अपना आन्दोलन और तेज कर दिया। सरकारकी नजरमें उनके लेख ऐसे ये जिनमें शान्तिभंग होनेका अन्देशा था। उन लेखोंके एकआध उद्धरण यहाँ दिये जा रहे हैं—

"विदेशी कारखानोंके लिए भारतीय मजदूरींकी जरुरत है, भारतीय पूँजी युद्धके कर्णों द्वारा खींचकर विदेश ले जायी जा रही है जिससे अगर अफसरशाहीका यस चला तो भारतको आजादी नहीं मिलेगी। करोंका वोझ, जो कर युद्ध ऋणका सुद देनेके लिए होंगे, भारतको कमर तोड़ डालेगा। जब यह हालत होगी तब मारत भरकी जनता समझ लेगो कि मैंने युद्धके बाद होमरूलके लिए सतत प्रयत्न क्यों किया है। वही एक राम्ता है जिससे कि भारत वरवादीसे, दूसरोंको अमीर बनानेके लिए स्वयं कुल्योंकी काम बननेसे बच सकता है।"

भारतके क्रान्तिकारियों के सम्बन्धमें वेहेण्टने २३ मई १९१७ के "न्यू इण्डिया"में लिखा था "सब ओरने निराश होकर उन्होंने बुनुगोंका सब प्रकारका नियन्त्रण तोड़कर फेंक दिया, पड्यन्त्र आरम्भ किया और उनमेंने अनेक तो सदाके लिए पड्यन्त्रकारी बन गये। कुछको फाँसी हो चुकी है और छुछ अंदमान द्वीप समृहमें मृतकों के समान जीवन विताने के लिए भेज दिये गये हैं, कुछ यहाँ कैदमें हैं। अब विद्यार्थांवर्ग आश्चर्य पूर्वक यह देखता है कि ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री रूसवासी युवकों तथा युवित्यों के इसी प्रकारके कायों पर प्रसन्ता प्रकट कर रहा है जिन्होंने पड्यन्त्र किया, रेलें उड़ा दीं, जारको मार डाला, जिनकी आज शहीद कह प्रशंसा की जा रही है और उनमेंसे जो अब भी जीवित है उन्हें विजेताकी भौति रूस वापस लाया जा रहा है जिसकी आजादी उनके प्रयत्नों के प्रलस्वरूप संभव हुई। उनके नामोंको आज पवित्र माना जा रहा है और उनके बिल्दानोंकी विजय हुई है।"

२ मईके अंकमें प्रकाशित एक लेखमें उन्होंने ब्रिटेनकी भारतके प्रति सःयानासी आर्थिक नीतिके द्वारा भारतकी उत्तोरत्तर बढ़ती हुई तबाहीका विवेचन करते हुए अपील की थी—"अगर होमरूलकी स्थापनामें जब्दो नहीं की जाती और भारत 'साम्राज्यकी व्यापार प्राथमिकता' (इम्पीरियल प्रिफरेन्स) का संघर्ष आरम्भ होनेसे पहले आजाद नहीं हो जाता, तो भारत वरवाद हो जायगा।

होमरूलकी आवाज देशभरमें गूँज रही थी। मद्राससे यह आन्दोलन आरम्भ हुआ था; वहाँकी सरकारने एक आदेश द्वारा विद्यार्थियोंको राजनीतिमें माग लेनेसे रोक दिया।

जूनमें मद्रास सरकारने श्रीमती वेसेण्ट और उनके दो प्रमुख सहयोगियों, वाडिया और अरुण्डेल, पर दो आदेश तामील कराये जिनके द्वारा इन लोगोंको किसी भी सार्वजिनक सभामें भाग लेने या वोलने, कहीं भाषण करने, प्रवचन करने या किसी अपने लेख अथवा भाषणको प्रकाशित करने या करवानेकी मुमानियत कर दी। इनकी डाकपर सेन्सर लग गया और यह भी आदेश हो गया कि थोड़ेसे निर्धारित समयके वाद ये लोग आदेशमें बतायी गयो जगहके अतिरिक्त अन्यत्र कहीं न रहें। इस नजरवन्दी आदेशसे देश और विदेशमें बेड़ी उत्तेजना फैली। राजनीतिक नेताओं और समाचारपत्र-सम्पादकोंने इस प्रथको उठाया। भारत सरकारसे मद्रास सरकारका यह आदेश रद करनेके लिए अपील की गयी। पर जब इसका कोई नतीजा न निकला तो मद्रास प्रेसीडेन्सी और अन्य स्थानोंके राजनीतिक वर्गोमें व्यापक आन्दोलन आरम्भ हो गया। इस अवसरपर स्वनय अवशा और निरोधके सुझाव भी दिये गये और उनपर विवाद भी किया गया।"

श्रीमती वेसेन्टके जीवनीलेखकने स्वयं उन्होंके उद्गारोंका उद्धरण दिया है—''जव हम, नजरवन्द ऊटकमण्डमें जमा हुए तो एक तूफान उठ खड़ा हुआ जिसने ऊपरसे नीचेतक देशको हिला दिया और कई सौ मील प्रति वण्टेकी रफ्तारसे विटेन, रूस, फान्स और अमेरिकातकमें छा गया। वाइसरायकी विधान-परिषद् और विटेनकी कामन्स सभाओं में प्रक्नोंकी झड़ी लग गयी। एक वह अफसरने गम्मीरतापूर्वक कहा—'कौन जानता था कि एक वृद्ध स्त्रीके कारण इतनी उथल-पुथल होगी।' असंख्य जनताकी भीड़ और अनेक लोकपिय नेता होमरूल लीगमें शामिल हो गये। सभाएँ होने लगीं, प्रस्तावोंकी झड़ी लग गयी और कांग्रेसजनोंने हर जगह इस आगको भड़काया तथा आन्दोलनका नेतृत्व किया। तीन महीनेतक जवरदस्त आन्दोलन अवाध गतिसे चलता रहा"।' होमरूल लीगमें शामिल होनेवाले मुसलमानोंमें जिना भी थे।

नजरबन्दोंकी रिहाईके लिए "सिवनय अवजा" के तरीके अपनानेपर विचार किया गया। जुलाई १९१७ में कांग्रेस महासमिति और मुस्लिम लीग कौंसिलकी संयुक्त बैठक बुलायी गयी और तय हुआ कि दोनों संस्थाएँ अपनी प्रान्तीय शासाओंसे इस प्रश्नपर छ सताहके भीतर राय भेजनेको कहें। रासविहारी घोषकी अध्यक्षतामें नजरबन्दीका विरोध करनेके लिए आयोजित सार्वजनिक सभापर बंगाल सरकारने रोक लगा दी। कांग्रेस व लीग कमेटियोंकी उक्त संयुक्त बैठकने बंगाल सरकारकी इस कारस्वाईका विरोध करते हुए एक प्रस्तावमें विश्वास प्रकट किया कि वंगालकी जनता अपने अधिकार प्राप्त करनेके लिए हर कानूनी तरीकेसे काम लेगो। कमेटीने राजनीतिक स्थितिपर वक्तव्य तैयार किया। उसमें ये माँगों की गर्यी—(१) एक अधिकृत घोषणा द्वारा साम्राज्यकी सरकार भारतको ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत स्वद्यासित सदस्य वनानेकी नीतिकी स्पष्ट शब्दोंमें प्रतिज्ञा करे, (२) दोनों संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूपसे तैयार माँगों मंजूर करनेके लिए तुरत कारस्वाई हो, (३) सरकारी सुझाव प्रकाशित किये जाय और (४) दमननीति समाप्त की जाय।

१. टवेट, ए हिस्ट्री ऑव इंडियन नैशनल सूवमेंट (?) पृष्ट १३८

२. थियोडोर वेस्टरमैन—'मिसेन एनी वेसेण्ट, ए माइन प्रोफेट', पृष्ठ २०१

शीव्र ही भारत सरकारने प्रान्तीय सरकारोंको जनान्दोलनसे निपटनेकी हिदायतें एक गक्ती चिट्ठीमें भेज दीं और कुछ प्रान्तींमें दमनकारी तरीकोंकी चेतावनी भी दे दी गयी।

कुछ प्रान्तोंकी रायमें सिवनय अवज्ञा आन्दोलन अनुपयुक्त था, पर विहार और मद्रासकी कांग्रेस कमेटियोंने उसका समर्थन किया । विहार कमेटीने तो यह भी माँग की कि "एक तारीख तय कर दी जाय और सरकारसे माँग की जाय कि उस तारीखतक होमरूल लीगके सभी नजरवन्दी, अली वन्धुओं और मौलाना आजादको रिहा कर दिया जाय।" मद्रासमें वैधानिक आन्दोलन चलानेके लिए एक प्रतिज्ञाका मसिवदा तैयार किया गया जिसपर पहला हस्ताक्षर मद्रास हाईकोर्टके रिटायर्ड जज तथा भारतीय होमरूल लीगके अध्यक्ष सर सुब्रह्मण्यम् अय्यरने किया। उन्होंने वेसेण्ट और उनके सहयोगियोंकी नजरवन्दीके विरोधमें "सर" का खिताव छोड़ दिया। पर इसी वीच जब मद्रास आदि एक दो अन्य प्रान्तोंमें आन्दोलनको तैयारी हो रही थी, राजनीतिक स्थितिमें परिवर्तन हो गया।

२२ अगस्त १९१७ के दिन भारत सिववने पार्लमेण्टमें दो घोषणाएँ कीं । एक में कहा गया कि "विटिश सरकारकी नीति यह है कि भारतीयोंका प्रशासनकी हर शाखासे अधिकाधिक सम्यन्ध स्थापित किया जाय और धीरे-धीरे स्वशासकीय संस्थाओंका विकास किया जाय ताकि विटिश साम्राज्यके अभिन्न अंगकी हैसियतसे भारतमें उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन स्थापित करनेका उद्देश्य धीरे-धीरे पूरा हो जाय । घोषणामें यह भी कहा गया कि "इस नीतिकी प्रगति धीरे-धीरे ही मुमिकन है।" भारत सिववने यह भी कहा कि "में भारत सरकारसे इन मसलोंपर सलाह मशिवरा करने शीव ही भारत जा रहा हूँ।" दूसरी घोषणा यह थी कि भारत सरकारने फीजमें कमीशनके ओहदोंपर १ भारतीयोंकी नियुक्ति करनेका निश्चय किया है।

नजरवन्दीके आदेश समाप्त हो गये। इन दो वर्षोकी त्फानी हलचलने वेसेण्टको इतना लोकप्रिय बना दिया कि सन् १९१७ में वे कांग्रेसकी अध्यक्षा चुनी गर्या।

अध्यक्ष-पदसे भाषण करते हुए उन्होंने होमरूल आन्दोलनकी विवेचनामें कहा कि "होमरूल आन्दोलनकी शक्ति, महिलाओं को बहुत वड़ी संस्थाके इसमें आ जाने के फलस्वरूप जो अपने साथ नारीत्वकी असीम वीरता, सहनशक्ति और आत्मविल्दान इस आन्दोलनमें लायों—दस गुनी बढ़-गयो । होमरूल आज, दक्षिणके महान् मन्दिरों का पृजाओं तथा उनसे प्रभावित सुदूर देहातों के मन्दिरों के पृजापाट और देशके हर भागमें साधु-संन्यासियों के उपदेशमें और प्रवचनों का आधार घर-घर धर्मका अभिन्न अंग वन गया।" आन्दोलनने एक और तरीके से कांग्रेसका पथ-प्रदर्शन किया। देशका संघटन करने में होमरूल लीगने भाषाके आधारपर प्रान्तों का निर्माण स्वीकार किया।

नजरबन्दीसे रिहा होनेके बाद उन्होंने निरोधात्मक आन्दोलनको अनुपयुक्त कहा और कई बार बाइसरायसे मेंट करनेकी कोशिश को पर चेम्सफोर्ड उनसे पृणा करते थे और वारवार उनकी प्रार्थना टुकरा दी गयी। जिस समय होमहल आन्दोलन अपनी उच्चम अवस्थामें था, गान्धीजी कुछ चुने हुए कार्यकर्चाओंके साथ चम्पारनके खेतिहरोंकी पृरोपीय नीलवागानके मालिकोंके विरुद्ध शिकायतोंका पता लगा रहे थे। वे स्वयं अपने सहयोगियाँ

सिंहत ६ महीनेतक आन्दोलनसे एकदम अलग रहे पर वहीं भारतके पहले सत्याग्रह आन्दो-लनकी भूमिका आरम्भ हो चुकी थी।

चम्पारनके कुछ खेतिहर इस शर्तमें वँध चुके थे कि अपनी कुल भूमिके ३० मेंसे ३ हिस्सोंमें गोरे भूमिपतियोंके लिए नील वोकेंगे। इस पद्धतिको "तिनकठिया" कहा जाता था क्योंकि एक एकड़के ३० मेंसे ३ कट्ठोंमें नील वोनी पड़ती थी । इन खेतिहरोंसे उक्त वृत्ति जवरदस्ती मनवायी जाती थी क्योंकि नीलकी खेती उनके लिए कतई लाभप्रद नहीं थी और इन खेतिहरोंके प्रति हर प्रकारका अमानुषिक न्यवहार होता था। अगर कभी वे नीलकी खेती वन्द करनेका विचार करते थे तो उन्हें बुरी तरह पीटा जाता था और "मुर्गीखाने" में वन्द कर दिया जाता था—उनके जानवर खोल लिये जाते थे, घर लूट लिये जाते थे । नाइयों और धोवियोंसे उनका वहिष्कार कराया जाता था । कभी-कभी उनके अपने घरोंका आने-जानेका रास्तातक रोक दिया जाता था। गोरे भूमिपतियोंकी तरफसे ५० से ऊपर अनिधक्तत और गैरकानूनी कर वस्ल किये जाते थे, जैसे कि शान्तिका टैक्स, कोल्हू व खल्हिहानपर टैक्स आदि । अगर. मालिक वीमार है और उसे स्वास्थ्यके लिए पहाड़ जाना है तो खेतिहरोंसे विशेष टैक्स लिया जाता था। इसी तरहसे अगर वह घोड़ा, हाथी या मोटर खरीदना चाहता था तो उसके लिए भी असाधारण कर लिये जाते थे। इसके वाद जुर्माने होते थे। अगर खेतिहरसे किसी वातपर भूमिपति नाराज हो गया तो कानृनको अपनी मुट्टीमें टेकर वह भारी जुर्माना करता था जिसकी वस्ली निर्दयतापूर्वक की जाती थी। खेतिहर दुनियामें किसीके पास अपनी मुसीवतं दूर करनेकी अपील नहीं कर सकते थे। अफसरोंपर वागान-मालिकोंका प्रभाव था।

गान्धीजीको यहाँके किसानोंकी दुखभरी कहानी एक खेतिहर, राजकुमार शुक्लसे माल्म हुई और गान्धीजीने उनकी मुसीवत दूर करनेका वीड़ा उठाया । वहाँसे वे मुजप्परपुर गये जहाँ उनकी आचार्य कपालानीसे पहली मुलाकात हुई। कुपालानीने उसी समय गवर्नमेण्ट कालेजकी प्रोफेसरीके पदसे इस्तीफा दिया था। उन्होंने गान्धीजीसे विहारकी वर्णनातीत दशापर वात की, और मार्गकी कठिनाइयोंका भी संकेत किया। गान्धीजी चम्पारनके खेतिहरोंकी दशा और नीलवागानके मालिकोंके विरुद्ध उनकी शिकायतोंका पता लगानेका काम हाथमें ले चुके थे। इस कार्यके लिए उन्हें इजारों खेतिहरों से मिलना जरूरी था। जैसा उनका तरीका था वे जाँच आरम्भ करनेके पहले वागानके मालिकों और सरकारका दृष्टिकोण भी जानना चाहते थे । इसिलए वे वागान मालिक संघ (प्लांटर्स एसोसियेशन) के सेक्रेटरीसे मिले । उन्होंने गान्धीजीसे साफ शन्दोंमें कहा कि आप वाहरी आदमी हैं; आपको नीलके खेतिहरों और उनके मालिकोंके आपसी रिस्तोंसे कोई वास्ता नहीं है। अगर आपको कुछ कहना हो तो आप लिखकर दीजिये। गान्धीने नम्रता-पूर्वक उनसे कहा कि मैं अपनेको वाहरी आदमी नहीं मानता और मुझे खेतिहरोंकी हालत जाननेका पूरा हक है। उन्होंने तिरहुत डिवीजनके—जिसका एक जिला चम्पारन भी था—कमिश्नरसे भी वात की। कमिश्नरने पहले तो उन्हें आड़ेहाथों लिया और उनको सलाह दी कि वे तुरत तिरहुत छोड़कर चले जावँ । उनको चम्पारनसे वाहर चले जानेकी नोटिस दी गयी जिसका पालन करनेसे उन्होंने इनकार किया और कहा कि अपनी जाँच पूरी किये विना में यहाँसे नहीं जा सकता । मजिस्ट्रेटी आदेशका उछंघन करनेके जुर्मपर वे अदालतमें पेश किये गये

पर इससे पहले कि उनको सजा सुनायी जाती मजिस्ट्रेटको लेपिटनेंट-गवर्नरका आदेश मिला कि मुकदमा उठा लिया जाय। लेपिटनेण्ट-गवर्नरने गान्धीजीको अपनी जाँच जारी रखनेकी भी अनुमित दे दी। लेकिन जब जाँच कुछ हपतों चली तो सरकारने गान्धीजीसे सलाह लेकर एक सरकारी जाँच कमेटी बना दी जिसकी रिपोर्ट खेतिहरोंके पक्षमें आयी। बाग-मालिकों द्वारा वस्ले हुए अवैध करोंका एक अंदा वापस कराया गया और ''तिनकटिया'' पद्धति समाप्त कर दी गयी।

कुछ समय बाद गान्धीजीने खेडा (गुजरात)में एक छोटे सत्याग्रह आन्दोलनका नेतृत्व किया। व्यापक हपसे फसल खराव होनेके कारण किसान वहाँ मालगुजारी अदा करनेमें असमर्थ थे और अमृतलाल ठक्कर, मोहनलाल पण्ड्या और शंकरलाल पारिख जैसे किसान नेताओंने पहले ही इस मामलेमें हाथ डाल रखा था। सरकारी अनुमानके मुताबिक फसल रुपयेमें चार आनेसे कुछ अधिक हुई थी। पर वस्तुतः पैदाबार इससे कहीं कम थी। अधिकारियोंको मालगुजारीकी वस्ली स्थिगत करनेके प्रार्थनापत्र दिये गये पर वे सुननेको तैयार नथे। अतः गान्धीजीने लगानवन्दी आन्दोलन करनेका निश्चय किया। इस आन्दोलनमें उनके प्रमुख सहयोगी वल्लभमाई पटेल, शंकरलाल वैंकर, अनुस्या वहन, इन्दुलाल याज्ञिक और महादेव देसाई थे। किसानोंसे सत्याग्रहके लिए तैयार रहनेको कहा गया और उनसे निम्नांकित प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर कराये गये जिसे गान्धीजीने तैयार किया था—

"हम संकल्प करते हैं कि हम राजीसे वर्षकी सरकारी मालगुजारी कुल या अव-शिष्टांश अदा न करेंगे और सरकार जो भी कानूनी काररवाई करे उसे करने देंगे तथा माल-गुजारी न अदा करनेके फल हँसते हेंसते झेलेंगे। हमें यह पसन्द है कि हमारे खेत कुर्क हो जाय पर हम यह नहीं चाहते कि स्वेच्छासे लगान देकर हम अपने मामलेको झुटा वनायें और अपनी प्रतिष्ठा गवायें।"

अधिकांश किसान इस संकल्पार डटे रहे और सरकारी अफसरोंने उनके जानवर और जो भी चल सम्पत्ति मिल सकी, जन्त कर ली। खड़ी फसल वेच डाली गयी। परन्तु शीघ ही सरकारने मंजूर कर लिया कि सिर्फ खाते-पीते किसानोंसे लगान बस्ला जायगा इसलिए सरवायह आन्दोलन समाप्त कर दिया गया।

हाँ तो सन् १९१७ में कांग्रेसके कलकत्ता अधिवेशनकी चर्चा चल रही थी जिसकी, अध्यक्षता एनी वेसेण्टने की थी। अध्यक्षपदसे भाषण करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि पार्लमेण्टमें सन् १९१८ के भीतर एक विल लाया जाय जिसके द्वारा "भारतमें एक निश्चित तारीखपर जो सन् १९२३ में हो पर किसी हालतमें १९२८ के बाद न हो—राष्ट्रमण्डलके अन्य देशोंके अनुरूप (उपनिवेशोंके समान त्रिटेनसे अभिन्न सम्बन्ध रखते हुए) स्वशासनकी स्थापना कर दी जाय और वीचके ५-१० वधोंका उपयोग शासन-प्रवन्ध अंग्रेजोंसे भारतीयोंके हाथोंमें धीरे-धीरे लानेके लिए होगा।"

दिसम्बर सन् १९१७ में सरकारने "भारतमें कान्तिकारी आन्दोलनों सम्बन्धित अपराधपूर्ण पड्यन्त्रोंके तौर-तरीकोंपर रिपोर्ट देने और उनसे निवटनेके लिए आवश्यक कान्तकी रूप-रेखा सुधारने"के लिए जस्टिस रौलटकी अध्यक्षतामें एक कमेटी बनाबी जो रौलट कमेटीके नामसे विख्यात है।

कांग्रेसने दूरदर्शितासे काम लिया और तुरन्त इस सरकारी घोषणाकी निन्दा करते

हुए एक प्रस्तावमें कहा कि "कमेटीका उद्देश्य भारतको सहायता देनेका नहीं विस्क अफ-सरोंको वंगालकी तथाकथित क्रान्तिकारी लहर दवानेके लिए और अधिक दमनकारी अधिकार देना है।" वादकी घटनाओंने दिखा दिया कि यह आशंका सही थी। इसी प्रस्तावमें माँग की गयी कि सब राजनीतिक कैदियोंको क्षमादान किया जाय क्योंकि भारत रक्षा कानून और सन् १८१८ के नं० ३ रेगुलेशनके मातहत की गयी अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियोंसे जनतामें असन्तोप उभर रहा है।

कांग्रेसके मुख्य प्रस्तावमें आग्रह किया गया कि पार्लमे॰ट एक कानून द्वारा भारतमें तुरत उत्तरदायी शासन स्थापित करे और एक अविध नियत करे जिसके अन्दर पूर्ण स्वशासन स्थापित करे । यह भी माँग की गयी कि इस दिशामें प्रगतिके लिए पहले कदमके रूपमें सुधारोंकी कांग्रेस-लीग योजनाको कानूनी शक्ल दी जाय । दिसम्बर्गों कांग्रेस अधिवेशन होनेके पहले ही गान्धीजी कांग्रेस लीग योजनाको जनतामें लोकप्रिय बनानेके लिए आवश्यक कदम उटा चुके थे । उन्हींके आग्रहपर इस योजनाको भारतीय भाषाओंमें अनुदित किया गया और जनताको समझाया गया । सन् १९१७ समात होते होते करीव १० लाख जनता इस योजनापर दस्तखत करके इसका औचित्य स्वीकार कर चुकी थी ।

अपने पूर्वाधिकारियोंके विपरीत—जिनके लिए कांग्रे सकी अध्यक्षता तीन दिनकी तड़क-भड़क और इजतसे अधिक कुछ नहीं थी—श्रीमती वेसेण्टने इस पदको रोजकी जिम्मे-दारीका पद वना दिया । प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंको झकझोरा गया कि वे जनताको समझाने, उभारने और सुधार करनेका काम निरन्तर करें। खास तौरसे भारत सचिव श्री मांटेगूकी भारत-यात्राको देखते हुए कांग्रेस संघटनकी सिक्रयता और राजनीतिक गितिविधिकी प्रखरता आवश्यक भी थी। माण्टेगू १० नवम्बर १९१७ को आये और ६ महीने भारतमें रहे तथा इस वीच उन्होंने विभिन्न राजनीतिक नेताओं और संखाओंसे मिलकर पूछताछ की और उनके सुझाव लिये। हाला कि इस वीच कुछ जगहोंपर हिन्दू-मुस्लिम दंगे भी हुए पर कांग्रेस लीग एकता हढ़ वनी रही और दोनों संस्थाएँ अपनी संयुक्त योजनापर डटी रहीं। श्री माण्टेगूने अपनी डायरीमें लिखा—''मुस्लिम लीगने इस धारणापर आश्चर्य प्रकट किया कि दशहरा मुहर्रमके फसादातके फलस्वरूप कांग्रेसके प्रति मुसल्मानोंका समर्थन कम हो गया होगा। उसकी राय थी कि यह तो वस्ती चीजें हैं, इनका कोई असर नहीं पड़ता।''

कांग्रेसकी ही तरह मुस्लिम लीगके दृष्टिकोणमें भी देशका राजनीतिक भविष्य सर्वापरि था। लीगके अध्यक्ष श्री जिनाने सन् १९१७ में वम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी वैटकमें बोलते हुए कहा था—"उन लोगोंको जो भारतको जानते और समझते हैं यह साम हो गया है कि अब वह सिर्फ आज्ञा पालन नहीं करेगा। वह अपने मुआमलातका स्वबं प्रवन्ध करेगा—शान्ति, समृद्धि और मुरक्षा मात्रसे एक पीढ़ीके पहलेके लोगोंको सन्तोष हो जाता था पर आज ये काफी नहीं हैं।" आपने आगे कहा "यह बात सारी दुनिया मानती है कि अगर किसी राष्ट्रको तुम उसका भाग्य-निर्माण करनेवाली उसकी अपनी सरकारमें उसका पूरा हिस्सा नहीं लेने देते तो तुम उसकी शक्तियोंको विद्रोहकी ओर उभाइते हो, उसका चरित्र गिराते हो और उसके आत्म-सम्मानको मानों तपायी हुई सलाखसे कोंचते हो। बुद्धिके क्षेत्रमें ऐसी सरकार प्रगति नहीं, सर्वनाश लाती है।" आपने हिन्दुओं और मुसलमानोंमें "शीव्रातिशीव सत्ता हस्तान्तरण करानेके लिए हर वैधानिक और उचित तरीका

अपनाने और मजबृत एका कायम रखने"की अपील की । पृथक निर्वाचनके सम्बन्धमें आपने कहा—"जहाँतक में समझता हूँ पृथक निर्वाचनकी माँग कोई नीतिकी बात नहीं है पर यह मुसलमानोंकी दिलचस्पीकी बात जरूर है और ये इतने दिनोंसे सोये हुए खुमारमें पड़े हैं कि उनको जगाकर खड़ा करना जरूरी है।"

हिन्दू महासभाको लखनऊ-समझौतेसे आशंका हुई थी और उसने लखनऊमें एक अधिवेशन करके कहा कि कांग्रेसको हिन्दुओंकी ओरसे वोलनेका कोई हक नहीं है। पर शक्तिशाली कांग्रेसके सामने इस दुधमुँ है वच्चेकी वात कौन सुनता ?

कलकत्तेमं लीगके वार्षिक अधिवेशनमं भी इसी प्रकारके उद्गार प्रकट किये गये। अधिवेशनके मनोनीत अध्यक्ष मुहम्मदअली जेलमें थे, अतः अध्यक्षपद राजा महमूदाबादने ब्रह्ण किया जिन्होंने अपने भाषणमं कहा—''सबसे पहले देशका हित है। यह बहस फिज्ल है कि हम पहले भारतीय हैं या मुसल्मान। दरअसल हम दोनों हैं और हमारे लिए पहले पीछेका सवाल बेमानी है। लीगने मुसल्मानोंको अपने मुख्क और मजहब दोनोंक लिए समान रूपसे कुरवान हो जानेकी प्रेरणा दी है।'' लीगके रंगमंचसे गान्धीजी और सरोजिनी नायहने अलीवन्धुओंकी रिहाईकी माँगवाले प्रस्तावके समर्थनमें भाषण भी किया था।

पर कुछ राजनीतिसे मड़कनेवाले मुसलमानोंने मुस्लिम लीगके खिलाफ कमर कसी और कई शायद नवजात संघटनोंके प्रतिनिधिकी हैसियतसे भारत सचिवसे मिले भी पर उनकी वातचीतसे हो कलई खुल गयी कि उन्हें पढ़ाकर मेजा गया है। कुछ लोग अपनेको मद्रासके उलमा कहकर मांटेग्से मिलने गये थे। वाइसराय चेम्सफोर्डने एक सवाल पृछा—''क्या अपने विचार संक्षेपमें मुझे और भारत सचिवको वता सकते हैं?'' उत्तर फीरन आया "हम होमलल नहीं चाहता"।

माण्टेगृकी डायरीमें इसके वादका एक विवरण इस प्रकार है—''तव एक हॅसमुख वृद्ध जिसकी दादी मूँछ और चेहरा मोहरा काफी सधा और मँजा हुआ या वोला कि मैंने कुरान और उसके सब भाष्योंका, वायविल और अन्य धमेंग्रन्थोंका अध्ययन किया है लेकिन कहीं भी मुझे एक लाइन भी कांग्रेस-लीग-योजनाके समझौतेके पश्चमें नहीं मिली।" मुसलमानोंके एक और दलने कहा कि मुस्लिम लीगसे असहमत मुसलमान अखिल भारतीय मुस्लिम डिफेंस एसोसियेशन बनानेका विचार कर रहे हैं। संयुक्त प्रान्तके कुछ मुसलमानोंने कुछ महीने पूर्व सचमुच यू. पी. मुस्लिम डिफेंस एसोसियेशन बना भी डाला था। उन्होंने योजना यह पेश की थी कि ५० सीटें हिन्दुओं, ५० मुसलमानों और यूरोपीयोंको दी जायें। माण्टेग् शिष्ट-मण्डलने कलकत्ता, वम्बई, मद्रास और कई अन्य स्थानोंका दौरा किया और जिन लोगोंसे मुलाकात की उनमें जिना, मजहरूलहक, हसन इमाम, गान्धी, सरोजिनी नायह, श्रीमती वैसेण्ट, तिलक, मदनमोहन मालवीय, हिन्दू महासभाके प्रतिनिधि, सनातनी हिन्दुओंके प्रतिनिधि, भारतीय जमींदार संघ, और विहारके जमींदार उल्लेखनीय हैं।

लेकिन तिलक, विविनचन्द्र पाल और श्रीमती वेसेण्टपर सरकारकी भोंह अभी टेट्टी थी। तिलक और पालको सन् १९१७ में आदेश मिले कि वे दिल्ली तथा पंजावकी सीमामें

१. मुहम्मद नोमान—"मुस्लिम इण्डिया", पृष्ठ १६२-१६३

२. अशोक मेहता और अच्युत पटवर्धन—"दि कम्यूनल ट्रायंगल", पृष्ठ ३५

एडविन एस० मांटेगू—"एन इण्डियन डायरी", पृष्ठ ४६ १७-क

प्रवेश नहीं कर सकते । श्रीमती वेसेण्ट अधिकारियोंकी आँखोंमें काँटेकी तरह खटकती थीं और यह आशंका थी कि किसी भी क्षण उनकी गिरफ्तारी या गतिविधिपर पावन्दी या रोक लग जायगी । अप्रैल १९१८ में वाइसरायने ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीके कहने पर फ्रांसमें ब्रिटिश हारके बाद सरकारके पक्षमें जनमत तैयार करनेके लिए दिल्लीमें शासनाधिकारियों और गैरसरकारी नेताओंका सम्मेलन बुलाया । इस सम्मेलनमें सरकारी विधानपरिषद्के एक सदस्य खापडेंने एक प्रस्ताव पेश करके माँग की कि भारतमें "उचित किन्तु निर्धारित अवधिके भीतर' उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाय। वाइसरायने प्रस्तावकी इजाजत नहीं दी। गान्धीजी भी इस युद्ध-सम्मेलनमें आमन्त्रित थे। पहले तो उन्होंने जानेमें आगा-पीछा किया, पर वाइसरायके इस तर्कसे वे राजी हो गये कि 'आप युद्ध समाप्त होनेके वाद जो भी नैतिक प्रश्न उठाना चाहें उठावें और हमें जितनी बड़ी चुनौती चाहें दें, पर अभी ऐसा न करें।" गान्धीजीने लिखा है कि ''वाइसरायकी दिली ख्वाहिश थी कि फौजी भर्ती सम्बन्धी प्रस्तावका में समर्थन करूँ।" गान्धी राजी हो गये और हिन्दुस्तानीमें वोलते हुए उन्होंने कहा-"अपनी जिम्मेदारीका पूरी तरह एहसास करते हुए मैं प्रस्तावका समर्थन करता हूँ।" लोगोंकी यादमें इस प्रकारकी किसी सभामें कभी कोई हिन्दुस्तानीमें नहीं वोला था और लोगोंने इसके लिए गान्धीजीको वधाई दी। गान्धीजीको राय थी कि सरकारको लढ़ाईमें विना शर्त मदद दी जाय । उन्होंने फीजी भर्तीकै आन्दोलनमें मदद की । युद्धके प्रति उनके रवैयेका सारांश इन शब्दोंमें था-"हमारी आजादीका द्वार फान्सकी भूमिमं है। देशको मेरी सलाह यही होगी कि विना शर्त्त प्राणोंकी वाजी लगाकर अंग्रेजोंके साथ युद्ध जीतनेके लिए लड़े और उसके साथ ही जान हथेलीपर लेकर, अगर आवश्यकता हो तो, अपने अभीष्ट शासन-सुधारके लिए भी आन्दोलन करे। " गान्धीजीकी आरम्भिक हिचक वायसरायको लिखे इस पत्रमें व्यक्त हुई थी "मेरी अनुपस्थितिका एक और सम्भवतः सबसे वडा कारण यह था कि लोकमान्य तिलक, श्रीमती बेसेण्ट और अलीवन्ध जिन्हें में जनमतको व्यक्त करनेवाले सबसे शक्तिशाली नेताओं मानता हूँ, इस सम्मेलनमें आमंत्रित नहीं थे। मैं अब भी अनुभव करता हूँ कि उनकी राय न लेना एक बहुत भवंकर भूल थी और मैं विनम्नता-पूर्वक मुझाव देना चाहता हूँ कि उक्त भूल शायद सुधारी जा सके, अगर इन नेताओं को अपने सत्परामर्शका लाभ देकर मदद करनेके लिए प्रान्तीय सम्मेलनमें आम-न्त्रित किया जाय जो मैं समझता हूँ कि शीव ही होनेवाला हैं।" उन्होंने पहले ही मुहम्मद्भली और शौकतअलीकी रिहाईके लिए सरकारसे खतोकितावत आरम्भ कर दी थी। सन् १९१७ में वे मुस्लिम लीगके कलकत्ता अधिवेशनमें आमंत्रित किये गये थे जहाँ उन्होंने भाषण करते हुए अलीवन्धुओंकी रिहाईके लिए आन्दोलनको मुसलमानोंका फर्ज वताया था।

इसके वाद प्रान्तीय राजधानियों में युद्ध सम्मेलन हुए । वम्बई सम्मेलनमें तिलक और होमलल आन्दोलनके एक अन्य नेताको राजनीतिक विचार प्रकट करनेकी इजाजत नहीं दी गयी और उनके ३ हमदर्द विरोधस्वरूप हालसे उठकर चले गये। १६ जून १९१८ के दिन मद्रासमें होमलल दिवस मनाया गया क्योंकि उसी तारीखको श्रीमती वेसेण्ट और इनके सहयोगियोंकी नजरवन्दीकी वर्षगाँठ थी। समाकी अध्यक्षता श्रीसुब्रह्मण्यम् अय्यरने की थी

ग्रे और पारिख—"महात्मा गान्धी", पृष्ट ३८, के. टी. पालकी पुस्तक "त्रिटिश करे-क्शंस इन इण्डिया"में उद्घत, पृष्ठ ११८

और उन्होंने होमरूलकी माँगके लिए सविनय अवज्ञा आन्दोलनको पूर्णतया वैध तरीका वताया। श्रीमती वेसेण्ट इस समामें मौजूद थीं और उन्होंने वम्बई गवर्नर द्वारा होमरूल लीगके सदस्योंके अपमानका विरोध करते हुए कहा कि भारतीय ऐसी आजादीके लिए केंसे लड़ सकते हैं जिसमें उन्हें हिस्सा न मिले। आजादीके विना जिन्दगी किस कामकी। वम्बईके युद्ध सम्मेलनमें तिलकके उक्त व्यवहारके बाद वम्बई सरकारने अगस्त १९१८ में उनपर विना पहले मिजरुट्टेंसे इजाजत लिये कहीं भी लेक्चर न देनेकी पावन्दी लगा दी थी।

होमहत्रके समर्थकोंको बीब ही अंग्रेजोंसे एक और आघात लगा । सन् १९१७ में २० अगस्तवाळी बोपणाके बाद तुरत ही कुछ भृतपूर्व सरकारी नौकर अधगोरी तथा कुछ प्रति-गामियोंने इंगलैंडमें इण्डोब्रिटिश एसोसियेशनकी स्थापना भारतीयोंके विरुद्ध प्रचारके लिए की । उसका प्रतिरोध करनेके लिए तिलक और श्रीमती वेसेण्टने तय किया कि एक प्रतिनिधि-मण्डल ब्रिटेन भेजा जाय । पहला प्रतिनिधिमण्डल मार्च १९१८ के मध्यमें खाना हुआं और जब वह जिब्राल्टर पहुँच गया तो उसे बताया गया कि आप होगोंका पासपोर्ट—यानी विदेश यात्राका अनुमतिपत्र ब्रिटेनके युद्धकाळीन मन्त्रिमण्डलकी विशेष हिदायतके मातहत रद कर दिया गया । दूसरा प्रतिनिधिमण्डल कोलम्बींसे जहाजपर सवार होने वाला ही था कि उसे इसी प्रकारकी हिदायत मिल 'गयी। भारतमें गोरोंकी भी एक संस्था थी जिसका नाम पहले यूरोपियन डिफेन्स एसोसियेशन था पर वादमें सिर्फ यूरोपियन एसोसियेशन रह गया। सन् १९१७ में निकट भविष्यमें शासनसुधारकी सम्भावना देखकर इस संस्थाको अधिक सिकय होनेका प्रोत्साहन मिला । भारतभरमें उसकी शाखाएँ खुल गयीं और शासनसुधारके प्रस्तावोंकी निन्दा करते हुए प्रचार आरम्भ कर दिया गया। भारतके उच सरकारी अफसर—खास तौरसे आई. सी. एस: भी राजनीतिक प्रगतिके इसी प्रकार विरुद्ध थे। और जब शासन्स्थार रिपोर्टमें जिसे माण्टेग और चेम्सफोर्ड—तःकालीन भारत-सचिव एवं वाइसरायके नार्मोको मिलाकर माण्टफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं, विरोधको शान्त करनेके लिए यह कहा गया कि लोग आई, सी. एस. को व्यर्थ बदनाम करनेके लिए कह रहे हैं कि वे शासनसुधार नीतिके विरोधी हैं, तो उसी समय आई. सी. एस. वर्गने फीरन भारत-सचिवके पास दाखिल करनेके लिए एक स्मृतिपत्रका मसविदा आपसमें वितरित किया जिसमें उक्त कथनका खण्डन किया गया । १९१८ में आई. सी. एस. वर्गके कई एसोसियेशन वन गये और बासनसुधारके विरोधमें अनेक पत्र वितरित किये गये। मद्रासका एक इसी प्रकार-का पत्र किसी प्रकार 'न्यू इण्डिया' कार्यालयमें पहुँच गया जिसे ११ जनवरी १९१९ के अंकमें प्रकाशित कर दिया गया । इससे राजनीतिक क्षेत्र मानी सिहर उठे और देशके विभिन्न भागोंमें सभाएँ करके भारतीय सिविल सर्विसके इस रवैयेकी भत्संना की गयी।

माण्यमोर्ड सुधारकी रिपोर्ट ८ जुलाई १९१८ के दिन प्रकाशित हुई । इसका महत्त्व-पूर्ण प्रस्ताव यह था कि वर्माकों छोड़कर तत्कालीन भारतके महत्त्वपूर्ण प्रान्तोंमें दोहरा शासन—जिसका अर्थ था कि एक प्रान्तीय सरकारके प्रशासकीय अधिकारके दो अंग होंगे—एकमें होंगे ब्रिटिश नरेश द्वारा नियुक्त गवर्नर और उनके प्रशासकीय सलाहकार और दूसरेमें होंगे विधानपरिपद्के निर्वाचित सदस्योंमेंछे गवर्नर द्वारा नामजद मन्त्री या मन्त्रिदल । पहले अंगके अधिकारगत विपयोंको "सुरक्षित" और दूसरेके विपयोंको "हस्तान्तरित" कहा गया था । स्वशासन, सफाई, चिकित्सा, शिक्षा, निर्माण आदि विपय मन्त्रियोंके अधीन

रखनेका प्रस्ताव था। पर केन्द्रमें कोई दोहरा शासन नहीं था। सिर्फ वाइसरायकी कार्य-परिषद्में भारतीयोंकी संख्या वढ़ा दी जानेवाली थी। प्रान्तीय विधानपरिषदोंका विस्तार होना था और केन्द्रीय विधानपरिषदके वजाय एक विधानसभा और एक राज्यपरिषद बनाने-का भी प्रस्ताव था । देशी रजवाड़ोंकी भी एक परिषद् वननेको थी । पूरी योजनाकी खूव-स्रत वात यह थी कि बहस करनेवाली परिषदोंमें भारतीयोंकी तादाद जरूर बढ़ा दी गयी थीं पर असली अधिकार अंग्रेजोंके ही हाथमें रखे गये थे। देखनेमें जो शक्ति भारतीय मन्त्रियों और सलाहकारोंके हाथ आयी थी वह सिर्फ नामके लिए थी क्योंकि उन्हें वित्तपर कोई अधिकार नहीं था। स्वशासन अभी दूर था। इस सुधारके वाद भी भारतीय आर्थिक व्यवस्थाकी बागडोर पहलेकी तरह ब्रिटिश उद्योगोंके लाभार्थ संचालित होनी थी और आम जनताको पहलेकी तरह गरीबीकी चक्कीमें पिसना था। सिवा इसके कि इन सुधारोंसे कुछ भारतीयोंको देखनेके लिए कुछ इजतका ओहदा मिल जाय, जनताकी दशामें कोई परिवर्तन होनेवाला नहीं था, न उसे राजनीतिक आजादी मिलनी थो, न गरीबीसे राहत । रिपोर्टमें यह सिफारिश भी की गयी थी कि आई. सी. एस. वर्गमें उच्चवदोंवर ३३ प्रतिशत भारतीय होंगे-इस संख्यामें प्रतिवर्ष १॥ का इजाफा होता जायगा जवतक कि ब्रिटिश पार्लमेंट द्वारा नियुक्त कमीशन स्थितिकी पूरी तरहकी जाँच करनेके वाद अपने नये मुझाव न दे दे। यह कमीशन नयी भारतीय व्यवस्थापिकाओंकी पहली बैटकके १० वर्ष बाद नियुक्त होगा और यही भारत सरकार तथा प्रान्तोंकी वैधानिक स्थितिकी जाँच करेगा। ये सिफारिशें भारतके वहे लोगोंके लिए काफी आकर्षक थीं जो इनका उपयोग करके आर्थिक लाभ और सम्मान दोनों पा सकते थे। परन्तु, जैसा कि स्वाभाविक था, गरमदलीय लोगोंने इन्हें वेहद नापसन्द किया ।

रिपोर्टके निर्माताओंने पहलेसे जान लिया था कि इसे लोग नापसन्द करेंगे अतः इस बीच उन्होंने काफी कोशिशसे इस वातका इन्तजाम कर लिया था कि उनकी सिफारिशोंका भारतमें खागत हो जाय। वे यह भी जानते थे कि कांग्रेस गरमदलीय लोगोंके हाथमें चली गयो है और नरमदलीय लोगोंका उसमें अल्पमत रह गया है। इसलिए मांटेगूने मुझाव दिया कि भारतीयोंको एकत्र करके एक नया संघटन बनाया जाय जिसे इमारे प्रस्तावोंके पक्षमें प्रचार करनेके लिए सरकार हर सम्भव तरीकेसे मदद दे और जो हमें मदद देनेके लिए ब्रिटेनमें भी प्रतिनिधिमण्डल भेजे।" जब वे भारतमें थे तभी उन्होंने ऐसी संस्थाके संघटनके लिए काविले-इतमीनान इन्तजाम कर लिया था। उन्होंने इस विषयपर कई लोगोंसे और भूपेन्द्रनाथ वसु तथा सर सत्येन्द्र सिनहासे भी बात की। अपनी डायरीमें उन्होंने लिखा—"इमने एक नरमदलीय संस्थाके निर्माणके वारेमें बात की। उन लोगोंको काफी उत्साह था और उन्होंने समाचारपत्रोंके सम्पादन और कई अन्य वातोंकी चर्चा की। मेरा ख्याल है कि वे सीदा करनेको राजी हैं।" इसलिए योजनाके मुताबिक मांटफोर्ड रिपोर्ट छपनेके कुछ पहले कलकत्तामें नेशनल लिवरल लीगकी स्थापना की गयी। रिपोर्ट छपनेके दो दिनके भीतर सुरेन्द्रनाथ वनजीने इण्डियन एसोसियेशनकी बैठक बुलायी जिस संस्थाके साथ ही उन्होंने अपना सार्वजिनक जीवन आरम्भ किया था। वंगालके समझौतावादियोंकी वैठक

१. मांटेगू डायरी, पृष्ठ १०४

२. वही पुस्तक, पृष्ठ ११७

अगस्त १९१८ में नैशनल लिवरल लीगके तत्वावधानमें तथा राजा प्यारेमोहन मुखर्जीकी अध्यक्षतामें हुई। लीगने न सिर्फ शासन-सुधारकी उक्त रिपोर्टका स्वागत किया, समापित महोदय 'तो काफी आगे बढ़कर शंकापूर्ण वात कह गये। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन भारतमें उत्तरदायी शासनको स्थापनामें देर करके एकदम मुनासिव काम कर रहा है क्योंकि 'भारतमें ८० नस्लें हैं, जिनकी अलग-अलग भाषाएँ, यहाँके लोगाँके १०० मतमतान्तर हैं। उनमें एकता तो है ही नहीं, भाईचारा भी मुश्किलसे ही दिखाई पड़ेगा।'' इसी प्रकार बग्वईमें और अन्यत्र भी सुधारपरस्तोंने खुलेआम रिपोर्टकी सराहना की और जनताको सलाह दी कि वह इस रिपोर्टको मान ले।

रिपोर्टपर विचार करनेके लिए वम्बईमें कांग्रेसका असाधारण अधिवेशन अगस्त १९१८ में हुआ। नरमदलीय सुधारपरस्त पहले ही अपना अलग रास्ता बना चुके थे और उन्हें विश्वास भी था कि रिपोर्टको कांग्रेस नामंज्र कर देगी—अतः इस अधिवेशनमें वे नहीं आये। लेकिन इस समाचारसे उन उप्रपन्थियों की आँखें खुल गयीं जो सुधारवादियों का सहयोग पानेकी व्यग्रतामें ऐसा प्रस्ताव पास कर चुके थे जो उतना कड़ा नहीं था जितना वह वस्तुतः हुआ होता। कांग्रेसके इस अधिवेशनमें उपस्थित काफी थी—डेलीगेटों की संख्या ३,८४५ थी। चार दिनकी वहसके बाद इसन इमामकी अध्यक्षतामें कांग्रेसने दुवारा कांग्रेसलीग-योजनामें विश्वास प्रकट किया और घोपणा की कि साम्राज्यके मातहत फौरन स्वशासनसे रत्तीभर कम बातपर भारतीय जनताको सन्तोप नहीं होगा। कांग्रेसने रिपोर्टमें कुछ संशोधनों-की माँग की और माँग की कि कानून बनाकर यह गारण्टी दी जाय कि १५ वर्षके अन्दर भारतमें उत्तरदायी शासनकी स्थापना हो जायगी। कांग्रेसने एक प्रतिनिधिमण्डल इंगलेण्ड भेजनेका निश्चय किया। मुस्लिम लीगने भी राजा साहब महमूदाबादकी अध्यक्षतामें ऐसा ही प्रस्ताय पास किया।

कांग्रेसी नेताओंने सोचा था कि इस समझौतेकी भावनावाले प्रस्तावके पास करनेके बाद उदारपंथियों यानी माडरेटोंको मनाकर कांग्रेसमें वापस लाया जा सकेगा। पर माडरेट वापस आनेके लिए नहीं गये थे। नवम्बर १९१८ में वम्बईमें सुरेन्द्रनाथ वनजींकी अध्यक्षतामें अखिल भारतीय माडरेट सम्मेलन हुआ जिसमें माण्टफोर्ड रिपोर्ट हारा प्रदत्त सुविधाओंका उपयोग करनेका निश्चय किया गया।

जवतक दिसम्बर १९१८ में कांग्रेसके साधारण अधिवेशनका दिल्लीमें आयोजन हो—महायुद्ध समाप्त हो चुका था। तिलक कांग्रेसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे पर उन्हें एक मुकदमेके सिलसिलेमें इंगलैण्ड जाना पड़ा। उनकी जगह अध्यक्ष-पदपर पण्डित मदनमोहन मालवीय चुने गये।

मालवीयजीने अध्यक्षपदसे भाषण करते हुए मित्रराष्ट्रींकी विजयपर सन्तोष प्रकट किया और कहा—"हमें इस वातका और अधिक अभिमान है कि परीक्षा और किटन साधनाके दौरानमें युद्धने हमारी जनतापर जो भीषण मुसीवतें डार्ली उन्हें सहते हुए—उस समय भी जब आसमान बहुत धुँधला था (अर्थात् ब्रिटेनका भाग्य खतरेंमें था) भारतकी सम्राट्के प्रति वफादारी और साम्राज्यकी मरते दमतक वथासम्भव पूरी मदद करनेके संकल्पमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। इंगलेण्डमें अपने राज्याभिषेकके बाद जब सन् १९११

१. इण्डियन प्नुअल रिजस्टर ११९ भाग ४, पृष्ट १५०

में सम्राट्ने भारत पंधारनेकी कृषा की तो हमने प्रसन्नता-पूर्वक वफादारीकी दुवारा श्रापथ ग्रहण की । हम अब भी ब्रिटिश सम्राट्की प्रजा बने रहनेके हच्छुक हैं; लेकिन एक दूसरा पहल आत्मिनर्णयका है जो कम महत्त्वपूर्ण नहीं है अर्थात् ब्रिटिश सरकारकें मातहत रहते हुए अन्य स्वशासित प्रदेशों जैसी उत्तरदायी सरकारका अधिकार दिया जाय जो हमारे सभी घरेल् मसलोंकी व्यवस्था करें । हम तो अभी पूरी तरह वह भी नहीं माँगते । हम अपना शासन आप करनेकी वही व्यवस्था माँग रहे हैं जिसका संकेत हमने सन् १९१६ की कांग्रेस-लीग योजनामें किया था । हम आग्रह करते हैं कि उस स्वशासन अर्थात् उत्तरदायी सरकारका तौरतरीका उस आत्मिनर्णयके सिद्धान्तके मुताविक किया जाय जो इस महानाशकारी महायुद्धसे विजयी होकर निकला है। इतना करनेके लिए यह जरूरी नहीं है कि श्रीमांटेगू और लार्ड चेम्सफोर्ड द्वारा वड़े परिश्रम-पूर्वक तैयार शासन-सुधारकी योजनाको वलायेताक रखकर नयी योजना तैयार की जाय।"

कांग्रेसने समझौता-पंथियोंको सन्तुष्ट करनेके लिए समझौतावादी प्रस्ताव पास करनेकी परम्पराका इस अधिवेशनमें परित्याग कर दिया और माँग की कि प्रान्तोंमें पूर्णरूपेण उत्तर-दायी शासन फौरन स्थापित किया जाय । अधिवेशनमें उपस्थित एकमात्र माडरेट श्रीनिवास शास्त्री थे । उन्होंने एक संशोधन पेश किया कि पूर्ण प्रान्तीय स्वराज्यकी स्थापनाके लिए १५ वर्षका समय दे दिया जाय । श्रीमती वेसेण्टने उनका समर्थन किया लेकिन संशोधन गिर गया । कांग्रेसने शान्ति सम्मेलनमें अपने प्रतिनिधि मेजनेकी इच्छा प्रकट की और तिलक तथा हसन इमामको उसके लिए प्रतिनिधि नामजद किया । एक अन्य प्रस्तावमें भारत रक्षा कानून और प्रेसऐक्ट, राजद्रोही समा कानून, अपराधी कानून संशोधक अधिनियम, और अन्य दमनकारी कानूनों तथा आदेशोंको रद करनेका आग्रह करते हुए नजरवन्दों और राजनीतिक कैदियोंकी रिहाईकी माँग की गयी । रोलट कमेटीकी रिपोर्टकी जो अप्रैल १९१८ में सरकारके सामने पेश हो चुकी थी निन्दा की गयी । प्रस्तावमें कहा गया कि अगर कमेटीके सुझावके मुताविक नया कानून वनाना मंजूर किया गया तो यह भारतीयोंके मौलिक अधिकारों हस्तक्षेप होगा । कांग्रेसने यह भी निश्चय किया कि सम्राट्को वफादारीका सन्देश मेजा जाय और "युद्धमें सफलताके लिए वधाई दी जाय।"

दिह्छी कांग्रेसमें, अव इस वारेमें कोई शक नहीं रह गया था कि माडरेट लोग कांग्रेसमें वापस नहीं आवेंगे । इसिंहए उनको वाहरी आदमी मानकर उपेक्षाकी नजरसे देखा जाने लगा । कांग्रेसमें उनके विरुद्ध जो भावना थी उसको प्रतिष्विन देशमें भी थी—उन्हें खुलेआम गहार, नौकरी-परस्त आदि कहकर उनकी भत्सना की जाती थी। सार्वजिनक सभाओं में चीखपुकारके कारण उनका वोलना दूमर हो जाता था।

मुस्लिम लीगका अधिवेशन भी, दिल्लीमें वदस्त्र कांग्रेसके पण्डालमें ही, श्रीफजलले हककी अध्यक्षतामें हुआ । अधिवेशनके आरम्भमें ही एक सनसनी फैल गयी थी। सरकारने एक आर्डर मेजकर स्वागताध्यक्ष श्री एम॰ ए॰ अंसारीके छपे हुए भाषणको जन्त एवं अवैध घोषित कर दिया। लीगने एक प्रस्तावमें माँग की कि आत्म-निर्णयका सिद्धान्त, जैसा कि राष्ट्रसंघमें मंजूर हुआ है, ब्रिटेन द्वारा भारतमें भी लागू किया जाना चाहिये क्योंकि वह भी राष्ट्रसंघके प्रमुख सदस्योंमेंसे एक है। अध्यक्षपदसे वोलते हुए श्रीफजलुलहकने कहा कि ब्रिटिश

शासनमें भारतका भौतिक विकास रुका पड़ा है। आपने ब्रिटिश शासनकी निन्दा करते हुए कहा कि उसीके कारण देशकी सम्पत्ति निकलकर विदेशोंको मालामाल करती है।

हिन्दू मुसलमानोंकी राजनीतिक एकताका यह दौर कांग्रेस और लीग दोनोंके लिए अग्नि-परीक्षाका समय था। हिन्दू मुस्लिम दंगे, जिनका हम अभी विवरण देंगे, कई जगहोंपर हो चुके थे, फिर भी दोनों संघटन उससे अप्रमावित रहे। उन्होंने अपनी दृष्टि अपने एक लक्ष्य स्वराज्यपर स्थिर रखी थी।

लीगने एक प्रस्ताव और पास किया जिसमें तुकींके सुस्तानका असली खलीफाकी हैिस्यतसे मुसलमान तीर्थोंपर अधिकार वने रहने देनेकी आवश्यकतापर जोर दिया गया था। इससे कुछ महीने पहलेकी उस घटनाका भी जिक्र करना आवश्यक है जब कलकत्तेके मुसल-मानोंने ब्रिटिश अफसरोंपर हमला करनेकी धमकी दो थी । युद्धसे सम्बन्धित एक समाचारसे मुसलमानोंकी धार्मिक भावनाओंको ठेस पहुँची थी। एक पर्चा व्यापक रूपसे बाँटा गया था जिसमें मुसलमानींसे अत्यन्त उत्तेजनारमक भाषामें इस्लामकी रक्षाके लिए कमर कस एक सार्वजनिक सभामें आनेकी अपील की गयी थी। यह हुआ था सितम्बरके दूसरे सप्ताइमें। सभाके कुछ संघटनक त्तांओंको बंगाल गवर्नरने मिलनेके लिए बुलाया और आग्रह किया कि सभा न की जाय। यह प्रयत्न नाकामयाव रहा—इतना ही नहीं मुसलमानोंका रोप इस इदतक उमड़ा कि भीड़ राजभवनकी ओर चल दी। "गोरे डिप्टी कमिश्नरकी गर्दनमें छूरा मार दिया गया और कुछ कपड़ेकी दुकाने छूट ली गयीं।" पुलिसने भीड़पर गोली चलायी। भारतीय फौज बुलाकर ९ सितम्बरकी रातको शहरमें जगह-जगह तैनात कर दी गयी। प्रदर्शनकारियोंकी भोड़ फिर जमा हो गयी और उनपर फीजने गोली चलायी, पर इससे हालत और विगड़ गयी। तीन कारखानोंमें मजदरोंने काम करनेसे इनकार कर दिया और प्रदर्शनकारियोंसे मिलनेके लिए वे जलूस बनाकर चल दिये । उनपर भी कई बार गोली चलायी गयी और उन्हें कलकत्ता शहरमें वसने नहीं दिया गया।

भारतके मुसलमान नेता तुर्कांके प्रति ब्रिटेनके रवेयेको स्थांक दृष्टिसे देखते थे। इसी शंकाकी प्रतिध्वनि फललुलहकके अध्यक्षपद्वाले भाषणमें भी सुनाई दा। शब्द येथे— "मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर अंग्रेज इस मौकेका फायदा उटाकर तुर्की और उसके कारण आनेवाली यूरोपीय समस्याओंको जड़से खत्म कर दं—यह काफी गौरतलय सवाल है।" स्वीकृत प्रस्तावमें आशा प्रगट की गयी कि ब्रिटिश साम्राज्य और मुसलमान राज्योंके वीच पूर्ण समझौता और चिरस्थायी मैंत्री समानता और न्यायके आधारपर वनी रहेगी।

अखिल भारतीय होमरूल लीगने भी कांग्रेस और मुस्लिम लीगके ही समान आशय-का प्रस्ताव शासनसुधारके सम्बन्धमें पास किया और निश्चय किया कि कांग्रेसको सहयोग दे कर उसे ही मजबूत बनाया जाय।

१. लवेट, 'इंडिया शंहर कर्जन एंड आपटर' (?), पृष्ट १७९

अध्याय १७

पंजाब हत्याकाण्ड

सन् १९१९, जबसे भारतीय इतिहासमें यथार्थमें गान्धीयुग आरम्भ होता है, राजनीतिक त्पानोंका साल था। अमृतसरमें अंग्रेजोंकी वर्वरतासे—जो जालियाँवाला वागके हत्याकाण्डके नामसे अधिक प्रसिद्ध है—सारे सम्य संसारके रोंगटे खड़े हो गये। जिस तरहसे एक हजार निहत्थे हिन्दोस्तानी गोलियोंसे भृन डाले गये उससे ईमानदार अंग्रेजतक स्तन्ध रह गये। यद्यपि अंग्रेज भारतीयोंके साथ कभी सम्य आदिमियोंकी भाँति न्यवहार नहीं करते थे परन्तु अमृतसर-काण्ड तो इतना वर्वर था कि उसका वर्णन शन्दोंमें किया ही नहीं जा सकता।

जालियाँवाला इत्याकाण्ड अकृतज्ञ शासकोंको कहानी है। वैधानिक स्तरपर आन्दोलन चलानेमें विश्वास करनेवाले भारतके राजनीतिक नेताओंने स्वेच्छा और उत्साहसे युद्धमें अंग्रेजींका साय दिया । गान्धीजीने एक धर्मप्रचारक (मिशनरी) की भाँति लोगोंको भरतीके लिए प्रेरित किया । वे अंग्रेजोंके इस संकटके समय उनकी पूर्ण सहायता करनेके पक्षमें थे। युद्धमें सहायताके लिए जनता चुपचाप सत्र शोषण सहन कर रही थी। भारत सरकारने अंग्रेजोंके लिए दस करोड़ पोण्ड भेंट किये। लड़ाईके कारण गरीव और ज्यादा गरीब हो रहे थे और अमीरोंकी अमीरी वढ़ रही थी। साधारण जनता नित्यके वढ़नेवाले करोंके वोझसे तवाह हो रही थी । जब करोंसे काम न चला तो सरकारने मुद्रा-प्रसारकी नीति अपनायी। चीजोंके बढ़ते हुए दाम छोगोंको छडाईकी याद दिलाते थे—एक ऐसी छडाईका जिससे भारतका कोई सम्बन्ध ही न था। बड़े-बड़े सेठोंने अवसरका लाम उठाते हुए और ज्यादा धन जमा करना गुरू कर दिया। मुनाफाखोरी और सड्डेके कारण कीमतें और चढ़ गयीं। मिलमालिक अत्यधिक मुनाफा वटोर रहे थे मगर मजदूरोंको उचित तनख्वाहेंतक न मिलतीं । हड़तालें हुई । भूखी जनता द्वारा ल्टनेकी घटनाएँ हुई । लगातार महामारियोंके कारण भी आर्थिक संकट उग्रतर होता गया। सबसे पहले जुलाई १९१७ में प्लेगका प्रकोप हुआ जिसमें आठ लाख लोग कालके ग्रास वने। अगली गर्मियोंके इन्पर्एँजॉने तो जैसे युद्ध--क्षेत्रकी मृत्युसंख्याको चुनौती दे रखी थी। पाँच महीनेके अन्दर साठ लाख आदमी मरे। और फिर आयी अत्यधिक वर्षा; जिसका नतीजा न सिर्फ आर्थिक तवाही था, विक जिसकी वजहसे प्रचण्ड हैजा और मियादी वुखार फैले, जिन्होंने जी खोलकर मनुष्योंका शिकार किया। हर गरीव मुल्ककी भाँति भारतमें भी मृत्यु कष्टोंसे मुक्ति मानी जाती है। परन्तु जीवितोंकी दशा तो मरनेवालोंसे भी अधिक दयनीय थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पचास और अस्सी फीसदीके वीच जनता महामारियोंसे यसित थी । मानो यह काफी नहीं, १९१८ और १९ में लोग जीवन-दायक मॉनसूनसे भी वंचित रह गये। "ऐसा कोई प्रान्त न वचा जहाँ मॉनसूनकी कमीसे लोगोंने कष्ट न पाया हो—कहीं कम और कहीं पूरी तौरपर । जिसका परिणाम यह हुआ कि १९१८-१९ की फसलें पिछले दस सालमें सबसे ज्यादा तवाह थी।" भारतीय जनतामें कृष्टसहनकी शक्ति असीम होती है। अगर वह उठती है तो तालावकी

छहरोंकी भाँति जो त्फान खत्म होने पर खुद गायब हो जाती हैं। वे छोग किसी तरह जिन्दा थे मगर दशा इतनी गिर चुकी थी कि एक बुद्धिमान नेता उनसे जो चाहे करवा सकता था।

राजनीतिक क्षेत्रमें क्रान्तिकारी लोग अराजकताके काम तेजीसे कर रहे थे। परन्त जनता उदासीन थी, सिवा इसके कि कभी क्रान्तिकारियोंकी वहादुरीसे रोमांचित हो जाती । फिर भी भारतके देशभक्तों और विशेषतया बंगालके देशभक्तोंके साथ सरकारके अमान्यिक व्यवहारसे समचे देशमें रोधकी लहर पेल गयी। न्यायकी अपेक्षा तात्कालिक आवस्यकताको ही अधिक महत्त्व दिया जाता था । वंगालके वाँकड़ा जिलेके एक गाँवकी स्त्री सिन्धुवालाका मामला इसका ज्वलन्त उदाहरण है। एक 'खतरनाक' क्रान्तिकारीके कागजीमें एक पर्चीपर सिन्धुवालाका पंता पकड़ा गया । पुल्सिने एक घरपर छापा मारा और तलाशी ली: मगर उसे वहाँ उस नामकी कोई औरत न मिली। पुलिसवालोंको पता लगा कि एक विलक्कल ही भिन्न पुरुपकी पत्नीका नाम भी सिन्धवासा है। उनके सिए यह काफी था, और उन्होंने फौरन ही उस खोको गिरपतार कर लिया । पुलिसके बीच विरो हुई वह खी इतनी भगभीत हो गयी कि पूछने पर उसने पुलिस सुपरिंटडेंटको बताया कि उसके माईकी बीबीका नाम भी िंधुवाला है और वह एक दूसरे गाँवमें रहती है। दोनों सिंधुवालाओंको गिरपतार कर पैदल ही पुलिसके थानेतक ले जाया गया। उनको पन्द्रह दिनतक हवालातमें बन्द रखा गया। मगर चुँकि मुकदमा चलानेके लिए उनके खिलाफ कोई सबूत न मिल एका, इसिलए दोनों औरतें छोड़ दी गयीं। यह घटना जनवरी १९१८ की है। इस घटनासे लोगोंको अन्तरात्मा कराह उठी। विरोधसभाएँ की गयीं और वंगाल विधानपरिपद्में एक प्रस्ताव पेश किया गया। लोगोंका ध्यान वॅटानेके लिए अंग्रेजोंकी एक वैधानिक चाल जाँच समिति नियुक्त कर देना था। इस मर्तवा भी वंगाल सरकारने नजरवन्दियों के मामलीपर गौर करनेके लिए न्यायाधीश बीचकीपट और सर नरायन चन्द्रावरकरकी एक समिति नियक्त कर दी। वंगालकी लेलींमें उस समय ८०६ नजरबन्द केंदी थे। समितिने केवल छः आदिमियोंको छोड्नेकी सिफारिश की। समितिका तर्क था कि "सत्र व्यक्तिगत मामले आपसमें एक दूसरेसे इस तरह सम्बद्ध हैं कि ये एक ही वस्तुके अभिन्न अंग, कान्तिके अनवरत प्रवाहके सहसा हो जाते हैं। और जवतक आन्दोलनकी पूर्णतः समाप्ति नहीं हो जाती, तवतक उसे हम जीता जागता तथा विभिन्न अंगोमें लग्बमान ही मान सकते हैं।

१९१८ की गरिमयोंमें दक्षिण भारतके राजनीतिज्ञ और सरकारके पंदानयापता सर सुन्नकण्य अन्यरने विरोधस्वरूप अपना 'सर' का खिलाव त्याग दिया। एक वर्ण पूर्व उन्होंने अमेरिकाके प्रेसीडेण्ट विस्तनको एक पत्र लिखा था कि यदि भारतको राजनीतिक स्वतन्त्रता देनेका वादा कर दिया जाय तो वे लड़ाईके लिए एक करोड़ आदिमयोंको तैयार कर सकते हैं। भारतकी दशापर एक अनुच्छेदमें उन्होंने लिखा— "श्रीमान्, मुझे यह कहनेकी इजाजत दीजिये कि भारतमें बुशासन और दमनकी पूरी दशासे आप और दूसरे नेता पूरी अज्ञानतामें रखे गये हैं। विदेशी भाषाके बोलनेवाले विदेशी राष्ट्रके अधिकारी हमारे उपर जवरदस्ती अपनी इच्छा लादते हैं। वे स्वयं अत्यधिक तनस्वाहें व अन्य भने ले लेते हैं, हम शिक्षासे भी वंचित हैं, वे हमारा धन लूटते हैं, विना हमारी समितिके हमेशा वर्वाद कर देनेवाले भारी कर लिये जाते हैं, देशभक्तिकी भावनाके कारण हमारे हजारों साथी जेलोंमें

वन्द कर दिये गये हैं। जेलें इतनी गन्दी हैं कि अक्सर वन्दी ष्टणित वीमारियोंसे मर

भारत-सचिवने इस पत्रको 'अपमानजनक' वताया और वादमें जब सुब्रह्मण्य अय्यर उनसे मिले तो वाइसराय और भारत-सचिव दोनोंने उनकी भत्सीना की । वे वहाँसे वहुत खिन्न होकर छोटे और मद्रास सरकारको एक पत्र द्वारा अपने 'खिताव' त्याग देनेकी सूचना दे दी और अखवारोंमें यह खबर छपवा दी।

एक उदाहरण और देनेके बाद, १९१९ की पूर्णाहुतिके प्रत्यक्ष कारणोंपर दृष्टि डालेंगे। यहाँ हमें नीचतासे भरे घमण्डका एक उदाहरण मिलता है। पटना हाईकोर्टके भूत-पूर्व न्यायाधीश और १९१८ की कांग्रेसके विशेष अधिवेशनके अध्यक्ष हसन इमाम एक बार रेलके प्रथम-श्रेणीके डिब्बेमें यात्रा कर रहे थे। रास्तेमें एक स्टेशनपर बिहार सरकारकी नीकरी करनेवाले भारतीय सिविल सर्विसके अधिकारी क्लेटन भी उसी डिब्बेमें चढ़े। एक भारतीयको उसी डिब्बेमें यात्रा करते देखकर उन्हें इतना कोध आया कि वे हसन इमामकी छातीपर चढ़ बैठे। जब भूतपूर्व न्यायाधीशने इसपर आपित्त की तो उन्हें गालियाँ दी गर्थी।

जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं तुकीं-इटालियन और तुकी-वाल्कन युद्धमें अंग्रेजोंके रवैयेके कारण, मुस्लिम नेताओंने १९१३ में अंग्रेजोंसे नाता तोड़ लिया था। 'जमींदार' नामी अखवार प्रकाशित करनेवाले पंजाबके जफर खाँने, तुकीं-लाल हिलाल-आन्दोलन संघटित किया। यह ईसाई-विरोधी और अंग्रेज-विरोधी आन्दोलन था। जफर खाँका अखवार दिनों-दिन ज्यादा विरोधी और राजद्रोहात्मक होता जा रहा था। सरकारने १९१४ में इस अखवारको वन्द कर दिया। "जब तुकींके दो डाक्टर, 'लाल हिलाल'की तरफसे प्राप्त सहायताके बदले, लाहौरकी बादशाही मस्जिदमें दो कालीन मेंट करनेके लिए आये तो भारतीय मुसलमानोंकी तुकींके प्रति भावनाएँ और तीन हो उठीं।"

जाहिर था कि तुकांने अपना निकट भिवष्य निश्चित कर लिया था और उसीके अनुसार वहाँ कार्य किया जा रहा था। तुकांके युद्धमें शामिल होनेके फौरन वाद ही सुल्तानने धार्मिक युद्धकी घोषणा कर दी और 'जिहाद' में खलीफाकी मददके लिए दुनिया भरके मुसलमानोंका आह्वान किया। सहायताकी माँगके लिए भारतीय मुस्लिम नेता कुछ कर न सकते थे। तुकांके प्रति उनकी सहानुभूति थी परन्तु वे असहाय थे। मुस्लिम-अंग्रेज विरोध और हिन्दू-मुस्लिम एका वढ़ रहा था। परन्तु अंग्रेजोंके ऊपर मुसलमानोंके विरोधका कोई ठोस असर न पड़ा, उन्हें पंजावसे हिन्दू-मुसलमान दोनों तरहके लोग फौजी भरतीके लिए वरावर मिल रहे थे। लड़ाई खत्म होने पर मुसलमान तुकांके लिए और चिन्तित हो उठे। भारतीय मुसलमानोंकी चिन्ता उस समय और वढ़ गयी जब उन्हें माल्म हुआ कि मित्रराष्ट्र तुकां-साम्राज्यको छिन्न-भिन्न करने जा रहे हैं। उन्हें डर लगा कि खलीफाका पद अव खतरे में हैं।

युद्धके वादकी राजनीतिपर इन सब वातोंका प्रभाव पड़ा । सन् १९१९ की घटनाओंको आरम्भ करनेवाली रोल्टेट-कमेटीकी सिफारिशें थीं। यह

१. इण्डियन एनुअरु रजिस्टर (१९१९), भाग दो, पृष्ठ ४५

२. लेफ्टिनेन्ट जनरल सर जॉर्ज मेकमुन—'टरमोइल एण्ड ट्रेजडी इन इ्ण्डिया १९१**४** एण्ड आफ्टर' पृष्ठ ६७

कमेटी १० दिसम्बर १९१७ को नियुक्त की गयी थीं। असलमें, जनवरी १९१८ में कमेटीने गुप्त रूपसे अपनी वैठकें शुरू कीं । कमेटीकी नियुक्ति अंग्रेजोंकी चातुरीका एक नमूना थी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि लड़ाई १९१८ के अन्तके पहले ही खत्म हो जायगी और लड़ाईके खत्म होनेके छः महीना वाद भारत मुरक्षा कानूनकी अवधि खत्म होनेवाली थी । इस कानूनने अंग्रेजी न्यायके सिद्धान्तींको वस्तुतः समाप्त कर दिया था और नौकरशाहीके हायमें भारतीय-स्वाधीनता आन्दोलनमें काम करनेवाले भारतीयोंकी जिन्द्गियों और सम्पत्तिको कुचलने और लूटनेके लिए अनियन्त्रित ताकत दे दी थी। सरकार जानती थी कि जिन राजनीतिक दलोंने अंग्रेजोंको लड़ाईमें पूर्ण सहायता दी है, लड़ाई खत्म होने पर वे स्वराज्य-की माँग करेंगे—यह वह सिद्धान्त था जिसके लिए अंग्रेजोंने लड़ाई लड़ी थी और भार-तीयोंकी सहायता प्राप्त की थी। इसमें सन्देह नहीं कि अंग्रेनोंने भारतीयोंके लिए 'कुछ सुधार' अवश्य सोच रखे थे परन्तु चूँकि ये सुधार भारतीयोंकी आशासे वहूत कम थे इसलिए लाजिमी तौरपर असन्तोप बढ़ता । नौकरशाहीकी समझमें अराजकतावादियोंके नेतृत्वमें यह असन्तोप ऐसी परिस्थित पैदा कर देता जिसका मुकायला नौकरशाही असाधारण कानृन वनाकर ही कर सकती थी । रौलट-कमेटीका उद्देश्य एक तरफ तो गम्भीर राजनीतिक असन्तीपको दवानेके लिए भारत सुरक्षा कार्नुनसे अधिक कठोर कार्नुन बनाना था और दूसरी तरफ अंग्रेजी जनताको यह समझाना था कि यह कानृन वनाना आवश्यक है। रौलट कमेटीने दो प्रकारके—निरोधात्मक और दण्डात्मक—कानृन बनानेके मुझाव दिये। कमेटीने लिखा कि "राजद्रोहात्मक अपराधोंके मुकदमें विना जूरी या असेसरके तीन तीन जर्जोंकी वेंचें वनाकर किये जायें। इन मुकदमोंमें न अपीलका हक हो और न फर्द जुर्म वगैरह लगानेकी प्रारम्भिक काररवाई आवश्यक हो।" कमेटीने दण्डके सम्बन्धमें जो सुझाव दिये उनमें ये भी सिफारिशें थों-आवासपर प्रतिवन्ध लगा देना, व्यक्तियोंको समय-समयपर पुलिसके सामने हालिरी देनेके लिए बाध्य करना, विना कोई कारण वताये गिरपतार कर लेना और पुलिसके अलावा लोगोंको दसरोंकी हिरासतमें रख लेना । यह भी सिफारिश की गयी थी कि 'खतरनाक व्यक्तियों को भारत सुरक्षा कानूनके खत्म होनेके बाद भी नजरबन्द रखा जाय।

जनवरी १९१९ में भारत सरकारने घोषणा की कि केन्द्रीय विधानसभाके फरवरी अधिवेशनमें वह रौलट कमेटीकी सिफारिशों के मुताबिक कान्न बनायेगी । लोकमत प्रस्ताबित कान्न के विषय था। यहाँतक कि नरमदलीय लोग भी इसके खिलाफ थे। उस समय गान्धी- जी सख्त बीमार और उनके ही शब्दों में 'मृत्यु द्वारके निकट थे'। अभी गान्धीजी ठीक हो ही रहे थे कि उन्होंने अखवारों में रौलेट कमेटीकी रिपोर्टके बारेमें पढ़ा। कमेटीकी सिफारिशें देखकर वे चौंक उठे और उन्होंने बल्लभमाई पटेलसे कहा कि 'फौरन ही कुछ करना चाहिये।' उन्होंने मुझाव दिया कि "अगर ऐसे मुट्ठी भर आदमी भी मिल जाव जो प्रतिरोधकी प्रतिशापर हस्ताक्षर करनेको तैयार हों और उनके विरोधके बावजूद जब प्रस्तावित प्रस्ताविंको कान्तका रूप दे दिया जाय तो उन्हें फौरन सत्याग्रह शुरू कर देना चाहिये। यदि में स्वयं करण शब्यापर इसी तरह न पड़ा रहा तो में अकेला ही लड़ाई शुरू कर दूँगा और मुझे आशा है कि दूसरे अनुकरण करेंगे। परन्तु अपनी वर्तमान अमहाय अवस्थामें में अपनेको इस कामके लिए पूरी तौरपर अयोग्य समझता हूँ।"

१. गान्धी-वही पुस्तक (आत्मचरित्र ?) पृष्ठ ५५८

शंकरलाल वैंकर इस आन्दोलनका संघटन करनेमें फौरन ही जुट गये। सत्याग्रह करनेका निश्चय किया गया परन्तु सत्याग्रह कांग्रेसके नाममें नहीं शुरू किया जानेवाला या। गान्धीजी लिखते हैं—"चूँ कि वर्तमान संघटनों द्वारा सत्याग्रह जैसे सुन्दर हथियारके अपनानेकी कोई आशा नहीं रही, इसलिए मेरे जोर देने पर अलग एक संस्था—सत्याग्रह सभा—स्थापित की गयी। सत्याग्रह सभाके सदस्य मुख्यतया वम्बईके थे, इस कारणसे प्रधान कार्यालय भी वहीं रखा गया। परचे जारी किये गये, और हर जगह वड़ी वड़ी सभाएँ की गयीं। ये सभाएँ 'खेडा आन्दोलन' की सभाओंकी भाँति ही होतीं। गान्धीजी सभाके अध्यक्ष बनाये गये।

१८ मार्चको उन्होंने अनेक आदिमयोंके हस्ताक्षरों युक्त एक घोषणा छपवायी जिसमें उन्होंने कहा कि "हमारी सम्मितमें १९१९ का भारतीय दण्ड विधान संशोधन विधेयक नं० १ और १९१९ के दण्ड विधान असाधारण अधिकार विधेयक नं० २ अन्यायपूर्ण हैं और स्वतन्त्रता तथा न्यायके सिद्धान्तोंके विपरीत हैं तथा व्यक्तिके उन प्रारम्भिक अधिकारोंपर कुठाराघात करते हैं जिनपर भारत और राज्यकी सुरक्षा आधारित है। हम निष्ठापूर्वक प्रतिशा करते हैं कि यदि ये विधेयक कानून वन गये तो जवतक ये वापस नहीं लिये जाते हम सिवनय इन कानूनों तथा उन कानूनोंको भी तोड़ेंगे जिन्हें भविष्यमें नियुक्त होनेवाली कमेटी भंग करना उचित समझेगी। हम यह भी प्रतिशा करते हैं कि संघर्षमें हम सत्यका अनुसरण करेंगे और जन, धन तथा सम्पत्तिको कोई हानि नहीं पहुँचायेंगे।"

गान्धीजीने वाइसरायकों निजी और खुले खत लिखे जिनमें उन्होंने लिखा कि "सर-कारने मेरे लिए सत्याग्रहके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा है।" परन्तु वाइसराय नहीं छके।

इसी वीच चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और कस्त्री रंगा अय्यरने सत्याग्रहकी योजना-पर वहस करनेके लिए गान्धीजीको वम्बई बुलाया ।

गान्धीजी वहीं ये कि खबर आयी कि रीलेट-विधेयकको ऐक्ट बनाकर छाप दिया गया है। दूसरे दिन सबेरे गान्धीजीने राजगोपालाचारीको एक स्वप्त सुनाया। गान्धीजीने कहा कि "कल रात स्वप्तमें मुझे यह विचार सुझा कि हमें देशभरमें आम हड़तालका नारा देना चाहिये। सत्याग्रह आत्मशुद्धिकी एक विधि है और हमारा संवर्ष एक पवित्र संवर्ष है और मुझे यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि सत्याग्रहको आत्मशुद्धिके ही एक कार्यसे आरम्भ करना चाहिये। इसलिए भारतके सब लोग एक रोजके लिए अपने काम-धन्धे बन्द करके प्रार्थना और उपवासमें वह दिन वितावें। सम्भव है कि मुसलमान चौबीस घण्टेसे अधिकका बत न रखें। इसलिए व्रतको अविध चौबीस घण्टेकी होनी चाहिये। यह कहना बहुत मुश्किल है कि सब सूबे इस माँगके जवाबमें उठ खड़े होंगे; लेकिन मुझे बम्बई, मद्रास, विहार और सिन्धका पूरा भरोसा है। मेरा ख्याल है कि यदि यही प्रान्त शानदार ढंगसे हड़ताल मनाते हैं तो हमें सन्तुष्ट होना चाहिये।"

आम इड़ताल, व्यापारको वन्द रखने, उपवास और प्रार्थना करने, और देशभरमें सभाएँ करनेके लिए ३० मार्च १९१९ का दिन नियत कर दिया गया। वादमें यह दिन

१. गांधी, वही पुस्तक, पृष्ठ ५५९

३, वही पुस्तक, पृष्ठ ५६२

वदल कर ६ अप्रैल कर दिया गया । नरमदलीय स्वमावतः सत्याग्रहके विरुद्ध थे और श्रीमती वेरेण्टने गान्धीजीको आन्दोलन न आरम्म करनेको सलाह दी; परन्तु गान्धीजी इस कदमको वापस नहीं ले सकते थे। "पूरे भारतमें एक कोनेसे दूसरे कोनेतक, क्या शहर और क्या गाँव, सब जगह ६ अप्रैलको पूर्ण हड़ताल मनायी गयी।"

चूँकि दिल्लीमें तारीख बदलनेका तार देरमें पहुँचा इसिलए वहाँ हड़ताल २० मार्चको ही हो गयी । हिन्दू-मुस्लिम एकताके साथ दिल्लीकी यह हड़ताल अमृतपूर्व थी। हकीम अजमल खाँ और स्वामी अखानन्द इस इड़तालके संबरनकर्ता थे। अखानन्दको जामा मिस्जदमें मापण करनेको बुलाया गया। अखानन्दने वहाँ भाषण किया। "रेलवे-स्टेशनकी तरफ जाते हुए इड़तालियोंके जुल्सको पुल्सिने रोका और गोली चला दी जिसमें कई आदमी मर गये और दिल्लीमें दमनचक चलना शुरू हो गया। रेलवे स्टेशनके वाहर शा बर्जक करीव एक मीड़ इकट्ठी हो गयी। रेलवेके टेकेदारसे, जिसने अपना काम वन्द नहीं किया था, थोड़ा-सा झगड़ा होनेके वाद और भीड़के दो आदमी गिरफ्तार कर लिये गये, तव लोगोंने स्टेशनपर हमला कर दिया। फीरन ही अंग्रेजी सेनाकी मदद माँगी गयी और भीड़-पर कई मत्वा गोली चलायी गयी। बहुतसे आदमी हताहत हुए और कई घटनास्थलपर ही मर गये। कई दिनोंतक द्काने वन्द रहीं; रेलके मुसाफर भी कके रहे। स्वामी अखानन्दने गान्थीजीको एक तार मेजकर प्रार्थना की कि आप फीरन ही दिल्लीको रवाना हो जायें। गान्धीजीने उत्तर दिया कि मैं दिल्ली अवस्य आऊँगा; परन्तु वम्बई में ६ अप्रैलका प्रदर्शन समात होनेके बाद ही।

यम्बईमं भी दिर्छाकी ही भाँति हिन्दू-मुस्लिम एकताका प्रदर्शन हुआ ! मुसलमानोंके निमन्त्रणपर गान्धीजी और सरोजिनी नायहूने मिस्तदमें भाषण किये ! शहरमें पूर्ण हड़ताल रही और यह निश्चय किया गया कि ऐसे कान्नोंके खिलाफ स्विनय अवशा आन्दोलन चलाना चाहिये जिन्हें जनता आसानीसे तोड़ सके ! "नमक-कर अत्यधिक बदनाम या और कुछ दिनोंसे इसे रद करवानेके लिए एक शक्तिशाली आन्दोलन चल रहा था।" इसलिए गान्धीजीने मुझाव दिया कि "नमक-कान्न तोड़कर लोग समुद्रके पानीसे अपने अपने वर्रोमें नमक बनावं।"

उनका दूसरा मुझाव जन्त-साहित्यकी विकीक वारेमें था। गान्धीजीकी दो कितावें हिन्द स्वराज्य और सर्वेदय (रिक्तिको अन-टू-दी लास्टका गुजराती अनुवाद) जो जन्त कर ली गयी थीं इस कामके लिए मुलम हो गयीं। "इन कितावोंको छापना और खुले वाजारमें वेचना सिवनय अवज्ञा आन्दोलनका सबसे सहज रूप था। इसिलये ये कितावें एक वड़ी संख्यामें छापी गर्यी और यह निश्चय किया गया कि हड़तालको शामको विराट्स सभाके बाद ये कितावें वेंबी जावें। ६ तारीखकी ज्ञामको स्वबंधिवकोंकी एक सेना इन कितावोंको लेकर वेचनेके लिए पहुँची। वातकी वातमें सब प्रतियाँ निकल गर्या। इस विकीकी खामदनी सिवनय अवज्ञा आन्दोलनको चलानेके लिए उपयोगमें लायी जानेवाली थी।" इन कितावोंका दाम चार आना प्रति पुस्तक रखा गया, परन्त बहुतसे लोगोंने चार आनेकी जगह अपनी जेवका कुल पैसा इस उद्देश्यके लिए दे दिया। एक आदमीने तो एक

गांधी, वही पुस्तक, पृष्ट ५६३

२. वहीं पुस्तक, पृष्ट ५६६

कितावके लिए पचास रुपया दिया । परन्तु सरकारकी इस घोषणाने कि कितावकी अगली प्रतियाँ जन्त न मानी जाउँगी, जनताके उत्साहपर पानी फेर दिया । "इस खबरने आम निरुत्साह पैदा कर दिया।"

७ अप्रैलकी रातको गान्धीजी अमृतसर और दिल्लीके लिए रवाना हो गये। अगले दिन मशुराके निकट पलवालके स्टेशनपर उनके ऊपर सम्मन जारो कर दिया गया; जिसमें उनके पंजाव सीमामें प्रवेशपर निपेध लगा दिया गया; क्योंकि गान्धीजीके पंजावमें प्रवेश करनेसे शान्ति-भंगका अन्देशा था। गान्धीजीको रेलसे उत्तरनेकी आशा दी गयी। उन्होंने उत्तरनेसे इनकार कर दिया और कहा कि "में एक निमन्त्रणके उत्तरमें पंजाव जा रहा हूँ। में असन्तोप पैदा करनेके लिए नहीं बल्कि असन्तोपको शान्त करनेके लिए जा रहा हूँ। इसलिए मुझे दुःख है कि मेरे लिए इस आशाको मानना सम्भव नहीं है।" उनको रेलगाड़ीसे नीचे उतार लिया गया और पुलिसकी निगरानीमें वम्बई वापस मेज दिया गया; जहाँ वे मुक्त कर दिये गये।

परन्तु गान्धीजीकी गिरफ्तारीका समाचार वम्बई पहुँच चुका था और उत्तेजित लोगोंकी भीड़ शहरमें इघर-उघर घूम रही थी। इसलिए गान्धीजीने लोगोंको दर्शन दिया और एक सार्वजिनक सभामें भाषण किया। उन्होंने कहा कि "सत्याग्रह यथार्थमें एक सत्यवादीका ही हथियार है। सत्याग्रही अहिंसाका पालन करनेके लिए प्रतिज्ञावद्व होता है और जबतक लोग इसको मनसा, वाचा, कर्मणा माननेके लिए प्रस्तुत न हों तवतक में जनस्त्याग्रह नहीं कर सकता।" इस भाषणसे लोगोंकी उत्तेजना शान्त हो गयी।

लेकिन अहमदाबादमें यह गलत अफवाह उड़ गयी कि अनुस्या वेन गिरफ्तार हो गयीं। सामाजिक कार्यकर्त्रीं अनुस्या वेनका अहमदाबाद्में बहुत आदर था। मिलके मजदूरींमें इस अफवाहसे बहुत उत्तेजना फैल गयी और उन्होंने कुछ सरकारी दफ्तरींमें आग लगा दी, टेलीफोनके तार काट डाले और यूरोपीयोंपर हमला किया। एक पुल्सि सार्नेण्टको भीड़ने मार डाला। पड़ोसमें ही फौजियोंसे भरी एक रेलगाड़ीको पटरीसे उतार दिया गया। लोगोंपर वारबार गोलियाँ चलायी गर्यी जिनमें २८ आदमी मरे और १३५ घायल हुए। घायलोंकी टीक संख्या नहीं मालूम। अहमदाबादमें मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। वीरमगाममें एक अँग्रेजी अधिकारी मार डाला गया। लोग भयत्रस्त हो गये। लोगोंने हिसात्मक कामोंमें हिस्सा लिया था और अब उनसे इसका बदला मय सदके बसूल किया जा रहा था। अन्तोगत्वा गान्धीजी ज्ञान्ति स्थापित करनेमें सफल हो गये। उन्होंने एक सार्वजनिक सभामें भाषण करते हुए घोषणा की कि "पश्चात्तापस्वरूप मैं तीन दिनका उपवास करूँगा और जनतासे भी एक दिनका उपवास करनेकी अपील की। १३ अप्रैलको मार्शल लॉ वापस ले लिया गया।

कलकत्तेमें अंग्रेज-विरोधी प्रदर्शन किये गये, हमेशाकी तरह, लोगोंपर गोलियाँ चलायी गयीं जिनमें अपार धन-जनकी हानि हुई।

लेकिन पंजावमें एक महा दुःखद नाटक खेला गया; ऐसा दुःखद नाटक जिसकी मिसाल आयुनिक इतिहासमें नहीं मिलती, हालाँ कि विश्वास होना मुस्किल है कि पंजावमें १९२० तक गवर्नरका निरंकुश शासन था। दूसरे स्वोंकी माँति वहाँ कोई गवर्नरकी शासन

१. गांबी, वहीं पुस्तक, पृष्ठ ५६६

२. वही पुस्तक, पृष्ठ ५६७

परिपद् न थी। १९२० तक कांग्रेसको हर साल यह आशा होती कि पंजावमें भी शासन-परिपद् और एक विस्तृत विधान-परिपद् कायम की जायगी। परन्तु इस प्रार्थनापर कभी ध्यान नहीं दिया गया। पंजावकी दशाका वर्णन करते हुए एक अंग्रेज अधिकारीने लिखा कि ''हमको सिखाया गया था कि पंजावमें हमें प्रत्यक्षतया नम्र रहते हुए लोहेकी तरह सख्त होना चाहिये; कटोर शासन और नम्र शब्द तथा समझौता वार्ता। न कोई पक्षपात और न डराना-धमकाना ।" जालियाँवालावागके इत्याकाण्डके समय, सर माइकेल ओडायर पंजाबके गवर्नर थे। वे भारतीयोंकी राजनीतिक आकांक्षाओंका मजाक उड़ाते थे और उन्होंने निर्दयतासे प्रान्तके राजनीतिक जीवनका दमन किया था। उन्होंने तिलक और पाल जैसे उद्देलनकारियोंके पंजावमें युसने पर रोक लगा दी। फिर भी पंजाब एक पहेली था। एक तरफ तो अकेले पंजाब फीजी भरतीके आधेसे अधिक आदिमियोंकी पूर्ति करता और 'वह ऐसा महान् स्वा था जिसने युद्धमें वास्तविक सहायता दी' और दूमरी तरफ क्रान्तिकारी कार्योंका सबसे अधिक सरगर्मीका केन्द्र था। पंजाब कांग्रे स जाँच समितिकी इकट्ठी की हुई। गवाहियोंकी रिपोर्टके अनुसार भरती करनेके लिए जुल्मका सहारा लिया गया था।' इस प्रकारका उदाहरण एक तहसीलदारका है जो गाँवके सव आदिमियोंकी सूची वनवाता और तीन चार आदिमियोंके कुटुम्बसे एक या दी आदिमयोंको भरतीके लिए माँगता । अगर उतनी संख्यामें लोग स्वेच्छासे आ गये तव तो ठीक, अन्यथा कठोर दण्ड दिये जाते। लोगोंको नंगा करके घरकी औरतोंके सामने खड़ा कर दिया जाता या उन्हें काँटेदार झाड़ियोंसे घसीटा जाता । औरतोंको वतौर जमानत वन्द कर दिया जाता जनतक लोग भरती न हो जायँ। माइकेल डायरके शब्दोंमें तहसीलदारके कार-नामोंसे साफ प्रकट है कि वह अनिवार्य भर्ती कर रहा था। कुछ गाँववालोंने इस तहसील-दारको मार डाला । जैसा कि श्रीमती वेसेण्टने कहा है "सर माइकेल ओडायरके कठोर और दमनकारी शासन, उनके अत्याचारी भरतीके तरीकों, उनके जबरदस्ती वस्ल किये गये युद-चहायता-धन, और तमाम राजनीतिक नेताओं के ऊपर किये गये उनके जुल्मोंने अमन्तोपके जलते हुए अंगारींको सिर्फ हाँक रखा था जो ज्वालामें फूट पड़नेके लिए तैयार थे। वम्बईमें हुए कांग्रेसके १९१८ के अधिवेशनमें पंजाबके प्रतिनिधियोंने हमें वतलाया कि वे एक ज्वालामुखीके ऊपर वैठे हुए हैं और क्र दमनके किसी भी कार्यसे यह ज्वालामुखी उवल संकता है।"

परन्तु शुरूमें यह चेतावनी अनावस्यक सी माल्स हुई। अमृतसर, लाहाँर और दूसरे स्थानोंमें ६ अप्रैलकी हड़तालका दिन शान्तिसे गुजर गया। परन्तु १० अप्रैलके स्वरे अमृत-सरके डिप्टी कमीरनरने विना किसी कारणके पंजाबके दो प्रसिद्ध नेता डा० सत्यपाल और डा० किचलको अमृतसरसे निष्कासनके आदेश जारी कर दिये और उनको धर्मशाला नगरमें वन्द कर दिया। सवेरे ११॥ बजेतक यह खबर शहर भरमें फैल गयी। हड़तालका ऐलान कर दिया गया और दोनों नेताओंकी रिहाईकी माँग करते हुए एक वड़ी भीड़ डिप्टी कमिश्नरके वंगलेकी तरफ चली। रास्तेमें यह भीड़ बरावर बढ़ती गयी। भीड़ विल्कुल शान्त यी, न लाटी, न डण्डे—और न रास्तेमें मिलनेवाले यूरोपीयोंसे ही कोई छेड़छाड़ की गयी।" परन्तु पुलिसने रेलवे-कासिंगपर भीड़को रोककर जनताके धेर्यकी कड़ी परीक्षा ली।

९. आर० नीडम कस्ट, मेमॉयर्स आव पास्ट ईयर्स

पुलिसने प्रदर्शनकारियोंपर गोलियोंकी वर्षा कर उनको पीछे खदेड़नेकी कोशिश की । यह गड़वड़ीको शुरूआत थी । इस मर्तवा अधिकारियोंने शान्ति मंग की । मीड़ अनियन्त्रित और क्रुद्ध हो उठी । वह वदलेकी मावनासे उत्तेजित हो उठी और जिस किसी यूरोपीय—पुरूष या स्त्री—को पकड़ लेती उसपर हमला करती । भीड़ने नैशनल बैंक और ऐलाइन्स बैंकपर हमला कर उन्हें तहस-नहस कर डाला । उनके यूरोपीयन मैनेजरोंको मार डाला । इमारतोंको आग लगा दी तथा दो अन्य यूरोपीयोंको भी खत्म कर दिया । टाउनहाल और दूसरी सार्वजनिक इमारतोंको नए कर दिया, टेलीफोनके तार तोड़ डाले । श्रीमती शेरवुड नामकी एक ईसाई महिलाका भी अन्त कर दिया गया । इसपर फौज बुला ली गयी और उसने अन्धापुन्ध गोलियाँ चलायों । गड़बड़ीमें, जाँच समितिकी रिपोर्टके अनुसार, करीव दस आदमी मारे गये और बहुत अधिक संख्यामें वायल हुए । भीड़को तितर-वितर करनेके लिए हथियारवन्द गाड़ियाँ और हवाई जहाज इस्तेमाल किये गये । ११ तारीखकी रातको जनरल डायरने, जो जनरल वैयननके अधीन जिलेके सहायक कमांडर थे, आये और उन्होंने शहर स्थित सेनाका भार सम्भाला । १२ तारीखको बहुत वड़ी संख्यामें लोग गिरपतार कर लिये गये और सभी समाओं अथवा लोगोंके एक जगह जमा होनेपर प्रतिबन्ध लगा दिया गया ।

प्रतिबन्ध-सम्बन्धी यह घोषणा शहरके कुछ हिस्सोंमें तो पढ़ी गयी पर बाकीमें नहीं। १३ तारीखको राजनीतिक नेताओंने ४॥ बजे शामको एक सार्वजनिक सभा करनेका ऐलान किया। जनरल डायर और शहरके हाकिमोंने इस एलानकी ओर तो कोई ध्यान दिया ही नहीं और शहरके वीच एक खुले मैदान जालियाँवाले बागमें जनताको चुपचाप इकट्ठा होने दिया । इस मैदानक तीन ओर ऊँची पकी इमारतें थीं और सिर्फ एक ओरसे आने-जानेका एक सँकरा रास्ता था । जब लगभग २० हजार व्यक्ति^{*} इकठ्ठे हो गये और इंसराज नामक एक सजनने सभामें बोलना गुरू किया, तभी जनरल डायर ५० अंग्रेज और १०० भारतीय सिपाहियोंको छेकर उस बागमें घुस आये और "१०० गजकी रेंजसे विना चेतावनी-का एक शब्द बोळे हुए, घनी भीड़पर गोळी चळाने छगे " भीड़ घवड़ाकर फौरन तितर-वितर होने लगी, पर उसके बाद १० मिनटतक वे निर्ममतापूर्वक गोलियोंकी बौछार करते रहे । चूहेदानीमें फँसे चूहोंकी तरह, उवलते हुएसे इस मानव समृहपर १६५० गोलियाँ चलायी गयीं। लोग निकलनेके सँकरे रास्तोंकी ओर निष्फल दौड़ते; या गोलियोंकी वर्षासे वचनेके लिए पेटके बल लेट जाते। जनरल डायरने खुद अपने निर्देशसे ऐसी जगहींपर गोली-वर्षा करायी जहाँ भीड़ सबसे ज्यादा थी। "" गोल्वियाँ भारतीय सिपाहियोंने दागीं, जिनके पीछे गोरे राइफिलें साधे तैनात थे। गोली वर्षा १० मिनटतक होती रही और तभी रुकी जब वारूद खत्म हो गयी । डायरने कहा कि अगर मेरे पास और कारतूस व वारूद होती तो मैं और गोलियाँ चलवाता । कांग्रेस द्वारा नियुक्त जाँच-समितिके सामने एक प्रत्यक्षदशींने कहा कि इस गोलीकाण्डमें १००० व्यक्ति मारे गये । उपद्रव-जाँच समितिके (जो हण्टर कमेटीके नामसे मशहूर है) अनुसार ३७९ व्यक्ति मारे गये, १२०० व्यक्ति घायल हुए । बादमें

१. डिसआर्डर्स इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट, पृष्ट ३०

२. पट्टाभि सीतारमैया, हिस्ट्री आव इंडिं० नैश० कांग्रेस, पृष्ट १६४

३. सर वेलेण्टाइन शिरील 'इण्डिया ओल्ड एण्ड न्यू, पृष्ठ १७८

सरकार सेवासमितिके ऑकड़े माननेको तैयार हो गयी, जिसने ५०० शव गिने थे। डायरके हुनमपर घायल वहीं जालियाँवाला वागमें ही रातभर खाना-पानी या दवादारूके विना रोते कराहते पडे रहने दिये गये । डायरने घोषणा की कि "मेरा उद्देश्य पूरे पंजावमें आतंक जमा देना था।'' कुमारी दोरबुडकी हत्याका वदला छेनेके लिए डायरने हुक्म जारी किया कि जिस गलीमें वे मारी गयी थीं, वहाँ कोई भी राहगीर सीधा न चलने पाये, सब पेटके वल रेंगते हुए चलें। दण्ड यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद "स्त्रियों और पुरुपोंपर खुले-आम कोड़े और वेंत लगाने, अन्धायुन्ध गिरफ्तारियों में सम्पत्तिकी जन्ती और उन 'आदर्श दण्डों' का दौर गुरू हुआ जो वागियोंको दण्ड देनेके लिए उतना नहीं जितना उन्हें अप-मानित और आतंकित करनेके लिए खोज निकले गये थे।" १५ तारीखको अमृतसरमें मार्शल लॉ (फौजी शासनका कानून) घोषित कर दिया गया। एक हुनम निकालकर रेलोंके तीसरे दर्जेंके टिकटोंकी विकी बन्द कर दी गयी, जिसमें भारतीयोंका रेल चढ़ना ही वन्द हो गया । अंग्रेजोंके सिवा और सबकी साइकिलें छीन ली गर्यी । कड़ी सजाकी धमकी दे कर दुकानें व बाजार खुलवाये गये । किलेके पास और शहरके कई दूसरे हिस्सोंमें को हे मारनेके सार्वजिनक प्रदर्शनके लिए टिकरियाँ खड़ी की गयीं । मार्शल लॉ कमिश्नरोंने २९८ व्यक्तियों-का 'संगीन जुमों' में मुकदमा किया; ५१ को फाँसी, ४६ को आजन्म कालेपानी और ११५ को विभिन्न अवधियों के लिए कारावासका दण्ड दिया गया।

पंजावके पाँच दूसरे शहरोंमें भी मार्शल लॉ लागृ हुआ और वहाँ भी हाकिमींके नृशंस अत्याचारोंका बोलवाला हो गया । पहले लाहौरको ही लीजिये । १० अप्रैलको गान्धीजीकी गिरफ्तारीकी खबर आते ही शोकका काला झण्डा लेकर एक जल्स वहाँके मुख्य बाजारमें घूमा । भीड़के तितर-वितर होनेसे इनकार करने पर दो वार गोली चलायी गयी । १२ अप्रैलको एक वडी सडकपर, भीड़पर फिर गोली चलायी गयी। दो दिन बाद, १४ अप्रैलको कुछ नेताओं की गिरपतारी हुई । उत्तेजित जनताने दमनका जवाव हड़ताल जारी रख कर दिया । लेकिन १८ अप्रैलको दुकानें जनरदस्ती खुलवायी गयीं । हर सम्भन तरीकेसे लाहौरका अपमान किया गया । वकीलों, उनके दलालों और मुहर्रिरोंसे रजिस्ट्री कराने और विना अनुमति शहर न छोड़नेको कहा गया। जिन इमारतोंपर मार्शल लॉकी घोपणा छाप कर चिपकायी गयी थो, उनमें रहनेवालोंको धमकी देकर घोषणा-पत्रोंकी रक्षा करनेके लिए कहा गया । सडकांपर दोसे ज्योदा छोगोंके साथ-साथ चलनेपर रोक लग गयी। सार्वजनिक धाने, तन्दूर व नान-बाइयोंकी दूकाने वन्द कर दी गयों। कालेजोंके छात्रोंको कालेजसे कई मील दूर दिनमें चार वार हाजिरी देनी होती। अप्रैलकी तपती धृपमें इन छात्रोंको १९-१९ मीलतक चलना पड़ता । कुछ वेहोश होकर सड़कोंके किनारे ही गिर पड़ते । सनातनधर्म कालेजकी दीवालपर मार्शल लॉकी घोषणा चिपकी थी; किसीने उसे उखाड़ दिया। इसपर सभी अध्यापक और सभी छात्र, लगभग ५०० पकड्कर फीजी घेरेमें किलेतक ले जाये गये, यहाँ तीन दिनतक रोक रखे गयें और उनपर अमानुपिक अत्याचार किये गये । भारतीयोंकी मोटरकारें, मोटर-साइकिलं, विजलीके पंखें, सब फौजी इस्तेमालके लिए ले लिये गये । इक्के ताँगेवालोंकी पुलिस चौकियोंपर दिनमें चार वार हाजिरो होने लगी ताकि वे हड़तालमें भाग न ले सकें। कोड़ लगाना आम वात थी। एक गाँवके मुखियाको पेड्से वाँघकर गाँववालोंको शिक्षा देनेके लिए ही कोड़े लगाये गये। मार्शल लॉ कैसे लागृ किया गया इसका एक उदाहरण इस घटनासे मिलता है कि लाहौरके पास एक गाँवमें एक मुसलमानकी पूरी वारात—दूत्हा, मुल्जा, मेहमान सबको पकड़कर कोड़े लगाये गये क्योंकि उन्होंने वारात निकालनेकी हिम्मत की थी जब कि लाहौरमें मार्शल लॉ था।

कस्रमें ११ व १२ अप्रैलको हड़ताल हुई। १२ को वहाँ बाजारोंमें होता हुआ एक जल्स रेलवे स्टेशन पहुँचा । वहाँ भीड़ काबूके बाहर हो गयी और उसने दरवाने तोड़ डाले, खिड़िकयोंपर पत्थर फेंके, सिगनल व टेलीफोनके तार खराब कर दिये, कुसी मेज तोड़ डालीं, टिकटघर ऌट लिया और एक तेलगोदाममें आग लगा दी। जब यह उत्पात चल ही रहा था, एक ट्रोन आयी जिसमें कुछ अंग्रेज मुसाफिर थे। भीड़ने उनके साथ दुव्यंवहार किया। लेकिन भारतीय मुसाफिरोंके समझानेपर भीड़ ट्रेन छोड़कर हट गयी। लेकिन दो अंग्रेजोंने भीड़पर गोली चला दी। इसपर भीड़ने पत्थरोंकी मारसे दो अंग्रेज मार डाले। फौरन पुलिस बुलायी गयी। जिसने गोली चलाकर भीड़ तितर-वितर कर दी। लेकिन अंग्रे जोंकी मौतने हाकिमोंको वदलेकी भावनासे भर दिया और वे पहलेसे भी अधिक नृशंस हो गये। वड़ी संख्यामें लोग गिरपतार हुए, पूरे शहरके सारे मर्द लोग शिनाख्त परेडमें इकट्ठे किये गये। जनता घवड़ायी हुई थी कि न जाने किस वहाने कोड़े छग जायें। कसूर तहसीछका शासन कप्तान डवटनके हाथमें था; उन्होंने जनताको आतंकित करनेके लिए कुछ दण्डोंका आविष्कार किया । एक वारातके सभी सदस्योंको वेदयाओंकी मौजूदगीमें कोड़े लगाये गये । जब हण्टर कमेटीने पूछा कि कोड़े मारते वक्त वेश्याएँ क्यों बुलायी गयीं तो डवटनने वात टालते हुए कहा कि मैंने तो पुलिससे शहरके बदमाशोंको पकड़ लानेको कहा था, ताकि वे कोड़ेकी मार देखकर आतंकित हो जायँ। कुछ 'हलके' दण्ड भी थे—जैसे कि पकड़े हुए लोगोंका सिर जमीनसे स्पर्श कराना । डत्रटन अपने कैदियोंको घटनोंतक नंगा कराते और उन्हें तारके खम्मोंमें वाँधकर सार्वजनिक रूपसे कोड़े खगवाते। एक दूसरे अफसर कर्नल मेकरे उदाहरण पेश करनेके लिए स्कूलके बचोंके कोड़े लगवाते । "बड़े लड़कोंको सिर्फ इसलिए छाँट लिया जाता था कि वे मार ज्यादा सह सकते थे।" १५० व्यक्ति गिरफ्तार कर स्टेशनपर कटघरेमें वन्द कर दिये गये थे, शहरके सभी मर्द लगभग १००० उनकी शिनाख्तके लिए पकड़ बुलाये गये।

गुजराँवालामें किसी सरकारी पिटठूने बदमाशीमें रेलवेके दो पुलींपर एक बछड़ा और एक सूअर काटकर लटका दिया। यह १४ अप्रैलको हिन्दुओं और मुसलमानींको लड़ानेके लिए हुआ था। पर दोनों जातियोंकी दृढ़ एकता इस बदमाशीसे नहीं टूटी। जनताने फौरन समझ लिया कि पुलिसने यह साम्प्रदायिक झगड़ा करवानेके लिए किया है। जनतामें उत्तेजना जरूर फैली, पर हाकिमोंके खिलाफ। हिन्दुओं और मुसलमानींकी एक भीड़ने पुलोंको आग लगा दी। पुलिसने गोली चलायी, जिससे भीड़ और उत्तेजित हो गयी और उसने जिला कचहरी, तहसील, डाकबँगले, गिरिजाघर व रेलवे स्टेशनको आग लगा दी। तीसरे पहर लाहीर हवाई जहाज मँगा लिये गये और गुजराँवालापर वमवर्षा हुई।

जाँच-समितिको मिले सबूतकै अनुसार एक खेतमें काम करनेवाले २० किसानोंको मशीनगनसे मार डाला गया । किसीका भाषण सुनते हुए कुछ लोगोंपर एक वम गिराया गया । रायल एयर फोर्सके लोगोंने स्वीकार किया कि हवाई जहाजसे वम गिराते समय

१. 'डिसटरवेंसेज इनक्वायरी कमिटी', पृष्ठ ४८

अपराधी और वेकस्र लोगोंमें अन्तर नहीं किया गया; उन्होंने कहा, यह करना असम्भव था। गुजराँवालाक मार्शल लाँ अफसर कर्नल ओवायनने हुक्म निकाला कि अंग्रेज अफसरोंको देखते ही भारतीय अपनी गाड़ियोंसे उतरकर उन्हें सलाम करें। जो लोग इस आदेशका पालन नहीं करते थे या संयोगयश अफसरोंको देख नहीं पाते थे, उन्हें को है लगते थे, जुर्माने होते थे या दूसरे दण्ड दिये जाते थे। गिरफ्तारियाँ और विना मुकदमा किये जेलोंमें हुस देना साधारण वात थी। कुछ सम्भ्रान्त नागरिकोंको गिरफ्तार किया गया, कड़ो धूपमें मीलों चलाया गया और फिर एक ठेलागाड़ीमें वन्द करके लाहीर भेज दिया गया। उन्हें इसी हालतमें ४४ घण्टे रहना पड़ा। हिन्दू-मुस्लिम एकताकी मखील उड़ानेके लिए एक हिन्दू और एक मुसल्मानका जोड़ा बनाकर उन्हें जंजीरोंमें जकड़ दिया जाता। मार्शल लॉक समय वनी 'सरसरी' अदालतोंने २०० व्यक्तियोंको कोड़ोंकी मार और विभिन्न अवधियोंकी केंद्रकी सजा दी। मार्शल लॉ कमीशनने २२ को फॉसी, १०८ को आजन्म कालेपानी, वहुतोंको कैंद्रकी सजा दी। श्री ओवायनने जब देखा कि २४ घण्टेमें मार्शल ला खत्म होने-वाला है तो 'सरसरी' अदालतोंने मी विना मुकदमा चलाये बहुत से लोगोंको सजाएँ दे दी'।

होल्पुरामें विना किसी कारण मार्जल लॉ लगा दिया गया। वहाँके सिविल अफसर वसवर्थ-सिमधने स्वीकार किया था कि होल्पुरामें मार्जल लॉ आवश्यक न था। स्मिधने जिस तरह छात्रोंको दण्ड दिया, उसे वीसवीं सदीका कोई भी व्यक्ति सुने तो १णासे भर जायगा। स्कूलोंके हर वच्चेको, चाहे उसकी उम्र पाँच वर्षकी भी क्यों न हो, दिनमें तीन वार परेडकर प्र्नियन जैक झण्डेको सलामी देनी पड़ती थी। इन वचोंको अप्रैलकी धृपमें मीलों चलना पड़ता। कई वच्चे इससे वीमार पड़कर मर गये। कुछ वचोंसे कहलाया जाता—''मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं कोई अपराध नहीं कहला। मुझे परचात्ताप है, मुझे परचात्ताप है।'' स्मिथने एक परचात्तापगृह बनानेका भी सुझाव दिया, पर वह लाग् नहीं हुआ।

- कई अन्य शहरोंमें भी अत्याचार हुए । वजीरावादमें एक पुल और एक पादरीका घर जला हाला गया और तारघर तोड़ डाला गया । देहातोंमें भी अशान्ति फैल गयी । लोग अपनेको गान्धीजीका अनुयायी वताते और ब्रिटिश सत्तापर चोट करते । सरकारी सम्पत्ति जलाते और रेलवे स्टेशनोंपर तोड़-फोड़ करते । १७ अप्रैलको मलकवाल नामक स्टेशनपर एक ट्रेन पटरीसे उतार दी गयी जिससे दो व्यक्तियोंकी मृत्यु हो गयी १ गुजरातमें भी मृद्ध भीड़ने उत्पात किये । अधिकारियोंने गोली चलाकर जवार्व दिया । हजारों पोस्टर चिपकाये गये जिनमें जनता विद्रोह करनेकी अपील की गयी । हण्टर कमेटीने जिस पोस्टरका हवाला दिया, उसमें कहा गया था—"महात्मा गान्धी चिरजीवी हों । हम भारतमाताके पुत्र हैं । हम हार नहीं मानेगे । हम प्राण उत्सर्ग कर देंगे । हम रौल्ट विल् कभी नहीं मानेगे । गान्धीजी ! हम भारतवासी जान देकर भी आपके पीछे लड़ेंगे । जुल्म और वेरहमीका झण्डा गड़ा हुआ है । हाय अंग्रेजो ! तुमने हमें कैसा धोखा दिया……तुमने भारतीयोंपर गोलियाँ चलायी और उन्हें मार डाला—…अमृतसरमें हमारी लड़कियोंपर तुमने असहनीय अध्याचार किये……यहाँ बहुत-सी अंग्रेज महिलाएँ हैं जिनका अपमान हो सकता है ।"

लाहौर और पंजायमें रेलवेमें हड़ताल करानेकी कोशिश १० अप्रैटने ही हो रही थी। लेपिटनेण्ट जनरल सर जार्ज मेकमनके अनुसार "जब लाहौर शहर विद्रोहियोंके हाथोंमें था,

एक हिन्दुस्तानी रेलवे सिगनलरने दिल्लीमें अपने दोस्तोंके पास यह खवर भेजी कि ळाहौरपर भीड़का अधिकार है, भारतीय सिपाही विद्रोह करनेवाळे हैं, नार्थवेस्टर्न रेलवेके भारतीय कर्मचारी हड़ताल करनेवाले हैं और दक्षिणकी वड़ी रेलोंके कर्मचारियोंको भी ऐसा ही करना चाहिये। दो दिन वाद दिल्लीमें विद्रोहियोंके नेताओंने रेलवेके अपने साथियों-को यह सन्देश भेजा-"रीलट शन्दका संकेत पाते ही पंजाय स्थित भारतीय फीजी और अवध एण्ड रुहेलखण्ड व ईस्ट इण्डियन रेलवेके कर्मचारी हड्ताल कर देंगे। ग्रेट इण्डियन पेनिनगुला और वंगाल नागपुर रेलवेके कर्मचारियोंको फौरन तार द्वारा आवस्यक स्चना भेजो । 1978 यह सन्देश कई जगह पकड़ा गया। वीनामें यह फौजी क्वार्टर मास्टर जनरलके हाथमें पड़ा । वे दौरेपर थे और फौरन एक इंजनपर बैठकर सरकारको इत्तिला देने गये। १३ अप्रैलको निम्नलिखित सन्देश तार द्वारा सव जगह पहुँचा—"दक्षिणकी सभी रेलेंके कर्मचारी आज रातसे हड़ताल कर दें: गान्धीजी गिरफ्तार हो गये हैं-भारतीय भाइयोंकी ओरसे।" हालाँ कि अधिकारियोंको इस प्रस्तावित हड़तालकी स्चना समय रहते मिल गयी थी और उन्होंने उसे रोकनेके लिये कदम भी उठा लिये थे, पर कई जगह हड़ताल शुरू हो गयी । इरादा यह था कि फौजोंके एक जगहसे दूसरी जगह छे जानेमें वाधा पड़ जाय। अप्रैलके अन्ततक बहुत कम ट्रेनें चलाना अधिकारियोंके लिये सम्भव रहा और वह भी अधिकांशतः एंग्लो इण्डियन कर्मचारियोंकी मददसे ।

जनप्रिय नेता पकड़कर जेलोंमें टूँसे जा चुके थे। मार्शल लॉ के अधिकारियोंने निरीह निस्शस्त्र लोगोंको तरह-तरहकी यातनाएँ दीं। गान्धीजीके पंजाव प्रवेशपर रोक लगा दी गयी । उन्होंने कई वार वाइसरायसे पंजाव जानेकी अनुमति माँगी पर हरवार उत्तर मिला-'अभी नहीं'। गान्धीजी इस निषेधाज्ञाका उल्लंबन कर परिस्थितिको और जटिल नहीं वनाना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज पादरी और गान्धीजीके सहयोगी सी. एफ. एण्ड्रूज पंजाब पहुँच गये थे । उन्होंने गान्धीजीको जो पत्र लिखा उसमें पंजाबकी स्थितिका हृदय-विदारक वर्णन था । उसी पत्रते गान्धीजीको पता लगा कि मार्शल लॉके अन्तर्गत अत्याचार उससे कहीं ज्यादा थे जिनका वर्णन अखवारोंमें मिला था। लेकिन इसके पहले कि एण्ड्रूज जाँच कर सकें, उन्हें पकड़कर इंग्हैण्ड भेज दिया गया। पंजाय एक वड़ा केंदलाना वन गया था। वैरिस्टर नार्टन वहाँ जाकर कैदियोंकी कान्नी सहायता करना चाहते थे, पर उन्हें पंजावमें घुसने नहीं दिया गया। पंजावमें कानून नहीं चल रहा था। कैदी अपने वकील भी नियुक्त नहीं कर सकते थे। वॉम्बे कॉनिकलके सम्पादक वी. जी. हनीमैनको जिन्होंने पंजावकी परेशान जनताका समर्थन किया था, पकड़कर इंग्हैण्ड मेज दिया गया और अखवार वन्द कर दिया गया । समाचारींपर सेंसर और आवागमनपर प्रतिवन्ध लगावर पंजावको होष देशसे विलकुल अलग कर रखा गया था। वाइसरायको शासन-परिपद्के भारतीय सदस्य शंकरन नायरने लगातार मार्चललॉ लगाये रखनेका विरोध किया और अन्ततः विरोधस्वरूप शासन-परिषद्से इस्तीफा दे दिया। कवि रवोन्द्रनाथ ठाकुरने अपना सरका खिताव छोड़ दिया। उन्होंने सरकारको लिखा—"समय आ गया है जब सम्मानके ये चिह्न अपमानके सन्दर्भमें हमारी लज्जाको बढ़ाते हैं, और, जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मैं इस विशेष सम्मानसे रहित हो अपने उन देशवासियोंके समक्ष खड़ा होना चाहता हूँ जो तथाकथित अकिंचनताके कारण

मेकमन, "टरमॉइल एण्ड ट्रेंजेडी इन इण्डिया, १९१४ एण्ड आफ्टर" पृष्ट १७५

ऐसे अपमानके भाजन वन रहे हैं जो मनुष्यके योग्य नहीं हैं।" कांग्रेस इस अतीव दुखान्त नाटककी मृक और असहाय दर्शक थी। अखिल भारतीय कांग्रेस महासमितिकी अप्रैल, जून और फिर जुलाईमें बैठकें हुई। पर वह इस स्थितिमें नहीं थी कि उसकी आवाज सुनी जाती। अप्रेलकी बैठकके अनुसार विट्ठलभाई पटेल और एन. सी. केलकर बिटिश अधिकारियोंको भारतकी सही परिस्थित बताने इंग्लैण्ड गये। जूनकी बैठकके पहले ही बहुतसे लोगोंको फाँसीकी सजा मिल चुकी थी और वे फाँसीके फन्देके इन्तजारमें बैठे थे। महासमितिने बिटिश सरकारसे अपील की कि मार्शल लों शासनकी जाँच होने तक यह दण्ड रोक दिया जाय। जुलाईकी बैठकमें महासमितिने १९१९ का कांग्रेस अधिवेशन जालियाँवाला बाग काण्डके स्थान अमृतसरमें करना तय किया और अद्धानन्द, मोतोलाल नेहरू व मदनमोहन मालबीयको पंजाय जा कर घटनाओंकी जाँच करनेको कहा।

पंजावकी घटनाओंने वह रूप धारण कर लिया था जिसकी गान्धीजीने करपना भी नहीं की थी और उनका सत्याग्रह आन्दोलन रुका पड़ा था। वातावरण सत्याग्रह अनुकूल नहीं था। २१ जुलाईको उन्होंने एक वक्तत्यमें कहा—"वहुत सोच विचारके बाद मैंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन कुछ कालके लिए न ग्रुल करनेका ही निश्चय किया।" जिन लोगोंने आन्दोलन ग्रुल न करनेकी राय दी थी उनमें भारत सरकार, कुछ भारतीय नेता और उग्रदलके लोग मी थे।

देशके प्रमुख लोग और कांग्रेस पंजायकी इस प्रचण्डाग्निकी निष्पक्ष जाँचकी माँग कर रहे थे और सरकार अनसुनी कर रही थी। लेकिन जब मार्शल लॉ का क्रोध समाप्त हो गया और पंजाब परास्त, अपमानित व शान्त हो गया, सरकारने उपद्रव जाँच समितिकी नियुक्तिकी घोपणा की । आधी सद्भावना तो उसी विलसे खत्म हो गयी जो सरकार फीरन बाद उन अफ-सरोंकी रक्षा और क्षतिपूर्तिके लिए ले आयी जिनके कृत्योंकी यह समिति जाँच करनेको थी। कांग्रेस द्वारा जॉचके लिए भेजे गये नेता अभी पंजावमें ही थे। वादमें एण्डूज, जवाहरलाल नेहरू और पुरुपोत्तमदास टण्डन भी जाँचमें शामिल हो गये। अक्तूबरमें गान्धीजीके पंजाब प्रवेशपर धर्मा निषेधाज्ञा भी हट गयी और १७ अक्तूबरको गात्धीजी भी पंजाव पहुँच गये। यद्यपि इण्टर-कमेटीका कार्यक्षेत्र कांग्रेसकी माँगसे बहुत ज्यादा सीमित और संकीर्ण था, कांग्रेस नेताओंने उसे सहयोग देनेका फैसला किया। यह सहयोग बहुत थोड़े दिन चला। नेता चाहते थे कि मार्शल लॉके कुछ केंद्री भी कमेटीके समक्ष गवाहोंकी हैसियतसे लाये जायेँ। पर पंजाय सरकारने इन केंदियोंको पहरेमें भेजनेसे भी इन्कार कर दिया। कांग्रेसने भारत सरकार और ब्रिटिश सरकारके भारत सचिवको मी लिखा पर कोई फल नहीं निकला। तब कांग्रेसने हण्टर-कमेटीसे सहयोग वापस लेकर एक समानान्तर जाँच समिति वैटानेका फैसला किया । इस गैर-सरकारी समितिमें गान्धीजी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजनदास, अध्यास तैयवजी, फजहुल हक व एम. आर. जयकर थे। गान्धीजीने जो जाँच अपने दायमें ली, उसके सम्बन्धमें उन्होंने लिखा—''जैसे जैसे जाँच बढ़ती गयी, मुझे सरकारकी निरंकुराता और उसके अफ़सरोंके मनमाने तानाशाही रवैयेके ऐसे-ऐसे अत्याचारोंका पता लगा जिनके लिए में विलकुल तैयार न था और इसते मुझे वड़ी पीड़ा हुई। जिस वातने मुझे तब और अवतक सवसे अधिक आरचर्यमें डाल रखा है, वह यह है कि जिस प्रान्तने लड़ाईमें सबसे अधिक

सिपाही ब्रिटिश सरकारको दिये, वही प्रान्त इस प्रकारकी पाश्चिक ज्यादितयाँ चुपचाप कैसे सह गया।""

हण्टर-कमेटीके सामने अभी सरकारी गवांहियोंका रख यही था कि मार्शल लॉ शासनकी तात्कालिक आवश्यकताके लिए जरूरी नहीं था, बल्कि जनताके हृदयमें आर्तक जमानेके लिए था जिससे भविष्यमें अशान्तिकी आशंका न रहे।

इंगलैण्डमें भारत सरकारके लिए एक नया विल पेश था। लार्ड सेलवोर्नकी अध्यक्षतामें लार्ड व कामन सभाकी एक संयुक्त समिति माण्टेग्-चेग्सफोर्ड रिपोर्टपर विचार कर रही थी। इस समिति और विदिश्य जनताके समक्ष अपने दृष्टिकोण पेश करनेके लिए कई भारतीय राजनीतिक दलोंने अपने प्रतिनिधिमण्डल वहाँ भेजे, होमरूल लीग दो भागोंमें वँट गयी थी और उसके दो प्रतिनिधिमण्डल गये। कांग्रे सके दिल्लीवाले प्रस्तावसे असहमतिके कारण श्रीमती एनी वैसेण्टने नयी—नेशनल होमरूल लीग वना ली थी। उसके प्रतिनिधिमण्डलकी नेत्री स्वयं श्रीमती वेसेण्ट थीं। कांग्रे सके प्रतिनिधिमण्डलसे और इससे शुरूमें ही मतभेद हो गया। श्रीमती वेसेण्ट माण्टेग्-चेग्सफोर्ड योजनामें थोड़ा वहुत परिवर्तन कर उसे स्वीकार कर लेनेके पक्षमें थीं। कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली प्रस्तावके अनुसार प्रान्तोंमें फौरन पूर्ण उत्तरदायी सरकारोंकी स्थापनाकी माँग कर रहा था। विट्ठल भाई पटेल कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डलके नेता थे। लेकन ब्रिटिश पार्लामेण्टने जो बिल पास किया वह बहुतसे प्रतिनिधिमण्डलके नेता थे। लेकन ब्रिटिश पार्लामेण्टने जो बिल पास किया वह बहुतसे प्रतिनिधिमण्डलेंकी एक भी माँगके अनुकूल न था। वास्तवमें वह कानून माण्टेग्-चेग्सफर्ड रिपोर्टसे भी वदतर था।

१९१९ के अमृतसरमें होनेवाले कांग्रेस अधिवेशनके समय ब्रिटिश सरकारने नये सुधारोंकी शाही घोषणा की । अधिवेशनके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरूने इन सुधारोंको स्वीकार करनेकी राय दी। आपने कहा—''इन सुधारोंमें खुश होनेकी गुंजाइश नहीं है, पर, वे जो कुछ भी हैं, हमें स्वीकार करना चाहिये।"

देशमरमें लगातार विरोध होते रहनेके कारण मार्शल लॉके अधिकांश बन्दी अधिवेशनके पहले मुक्त कर दिये गये थे । अलीवन्धु भी रिहा कर दिये गये थे और वे लीधे अमृतसर अधिवेशनमें भाग लेने आये । सुधारोंको स्वीकार करनेके पक्षमें गान्धीजी भी थे जो उन्हें असन्तोषजनक मानते थे । तत्सम्बन्धी प्रस्ताव चित्तरंजन दासको पेश करना था, पर वे सुधारोंकी स्वीकृतिके विरुद्ध थे । अधिवेशनमें आये प्रतिनिधि सुधारोंके पक्ष और विपक्षमें बँट गये । गान्धीजीके साथ मदनमोहन मालवीय और मुहम्मद अली जिना थे । जब सभी सोचने लगे थे कि सुधारोंके सवालपर फूट पड़ जायगी, तभी एक संशोधनसे स्थित सम्हल गयी । प्रस्तावके मूल मसविदेमें दिल्ली अधिवेशनके निर्णयको दोहराते हुए शीघ उत्तरदायी शासन कायम करनेकी माँग की गयी थी । संशोधनमें कहा गया था—'इस अधिवेशनका विश्वास है कि उत्तरदायी शासनकी स्थापनातक जनता इन सुधारोंको इस प्रकार और जहाँतक सम्भव है, लागू करेगी कि पूर्ण उत्तरदायी शासनकी स्थापना शीघ हो सके ।" यह संशोधन पास हो गया ।

१. गान्धी—'दि स्टोरी आव माई एक्सपेरिमेण्ट्स विध दूध' पृष्ठ ५८४

२. मोतीलाल नेहरू—१९१९ के कांग्रेस अधिवेशनमें अध्यक्षपदसे किया गया भाषण

कांग्रे सके इस अधिवेशनमें कुल मिलाकर ५० प्रस्ताव स्वीकृत हुए । इनमें वाइसराय पंजाव हत्याकाण्ड . चेम्सफोर्डको विलायत वापस बुलानेकी माँग, माल व्यवस्थाकी जाँच, श्रमिस्थिति, रेलके तीसरे दर्जेके मुसाफिरोंकी दुर्दशा जैसे विभिन्न विषयोंके प्रस्ताव भी शामिल थे। इनमेंसे एक ₹८३ प्रस्तावका छोटा-सा इतिहास भी है। विषय समितिमें गान्धीजीने भीड़ोंके उत्पात और हिंसाकी निन्दा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया, जो गिर गया। इसपर गान्धीजीने कहा कि अगर कांग्रेसको यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है तो में कांग्रेसमें नहीं रह सकूँगा। उनकी वात मान ली गयी। प्रस्तावमें "उस गम्भीर उत्तेजनाको स्वीकार करते हुए जिसके कारण भीड़का आकिस्मिक कोध फूट पड़ा, अप्रैल्में पंजाब व गुजरातके कुछ स्थानींमें हुई उन ज्यादितयोंपर कांग्रेसका खेद व निन्दा प्रकट की गयी थी जिनके फलस्वरूप कुछ लोगोंकी जानें गर्यों, लोग घायल हुए व सम्पत्तिको क्षति पहुँची।" स्वदेशी सम्बन्धी प्रस्तावमें देशके "हाथकी कताई व बुनाईके प्राचीन उद्योगके पुनरुत्यान"की सिफारिश की गयी थी।

अध्याय १८

खिलाफत व असहयोग आन्दोलन

यहाँ युद्धमें तुर्काकी हार और 'मित्र राष्ट्रीं की संधि-शतों के अनुसार उसके साम्राज्यके बटवारेकी प्रतिक्रिया भारतमें बहुत गम्भीर हुई। तुर्कीके शाह अन्दुल हमीद आखिरी खलीफा थे। खिलाफतका केन्द्र होनेके नाते तुर्कांके प्रति मुसलमानोंकी आध्यात्मिक आस्या थी। भारतीय मुसलमान तुर्कीके प्रति श्रद्धाका भाव रखते थे और मित्र राष्ट्रों द्वारा हुए तुर्कीके अहि-तको न्यक्तिगत रूपसे अपना अहित मानते थे। प्रमुख मुसलमानोंने अपनेको तुर्काके पक्षमें होनेकी घोषणा की थी और इसके लिए वे जेल भी गये थे। भारतीय मुसलमानोंकी आशंका मिटानेके लिए ब्रिटिश प्रधान मन्त्री लायड जार्जने घोषणा की थी कि "तुर्क जातिकी प्रधान आबादीवाले एशिया माइनर व असके समृद्ध मैदानोंको तुर्कीसे छीन लेनेके लिए हम नहीं लड़ रहे हैं।" पर यह वादा पूरा नहीं किया गया और तुर्किक इलाके छीन लिये गये। विरोध और प्रतिरोधकी मावना जितनी मारतीय मुसलमानोंमें पैदा हो गयी, उतनी कहींके मुसलमानों-में नहीं हुई। पंजावका क्रोध ठंढा पड़ जानेके बाद जब कांग्रेसकी जाँच जारी थी, तभी दिलीमें . १९१९ में हिन्दुओं व मुसलमानोंका एक संयुक्त सम्मेलन खिलाफतके प्रश्नपर विचार करनेके लिए बुलाया गया। सम्मेलनके समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि मुस्लिम विरोधका रूप क्या हो, ताकि हिन्दू भी उसमें भाग ले सकें। सम्मेलनमें स्वीकृत प्रस्तावों में एक यह भी था कि हिन्दू और मुसलमान विदेशी वस्तुओंका बहिन्कार कर स्वदेशीका व्रत लें । लेकिन खिलाफत आन्दो-लनका रूप और दिशा अन्ततः गान्धीजीने तय की । गान्धीजीने कहा "मुसलमानींने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किया है। यदि संधिकी शतें उनके अनुकूल न हों (खुदा न करे कि ऐसा हो) तो वे सरकारसे सहयोग करना बन्द कर देंगे। इस प्रकार सहयोग वापस ले लेना जनताका अधिकार है। हम सरकारी खिताव धारण करते रहने या सरकारी नौकरियाँ करते रहनेको वाध्य नहीं हैं। यदि सरकार खिलाफत जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नपर हमें घोखा देती है, तो हम उससे असहयोग करनेको वाध्य हैं। इसलिए घोखा होने पर हमें सरकारसे असह-योग करनेका अधिकार है।" असयोगका शब्द पहली वार गान्धीजीने इसी सम्मेलनमें इस्तेमाल किया था। श्रोता बहुत प्रभावित हुए, सम्मेलन खत्म होने पर भी सभीके कानोंमें उन्होंके शब्द गूँज रहे थे। यह स्पष्ट था कि यदि खिलाफत आन्दोलन चला तो गांधीजी उसका नेतृत्व करेंगे।

इस सम्मेलनमें ही एक अन्य मुस्लिम संस्था—जमैयत-उल-उलेमाए हिन्द—का जन्म हुआ। "उत्माओं की धारणा थी कि सन् ५७ के विद्रोहमें मुस्लिम धार्मिक नेताओं (मौलवियों व मुल्लाओं) की सामूहिक शक्ति व प्रभाव खत्म हो गये थे, अब उनको फिर एक साथ मिलकर मैदानमें आना चाहिये।" उनका तर्क था कि "मुस्लिम धार्मिक नेता अत्याचारी शासनका सत्यकै लिए विरोध करते थे और राजमिककी राजनीतिसे दूर रहते थे। अब चूँकि

मुस्लिम राजनीति सुधर रही है, हम फिर मैदानमें आ रहे हैं। 191 दिसम्बर १९१९ में कांग्रेस, लीग, खिलाफत और जमैयतका अमृतसरमें संयुक्त सम्मेलन हुआ और उन्होंने प्रकट किया कि राजनीतिक और खिलाफतके मसलेंपर सब मिलकर आन्दोलन करेंगे।

अमृतसर कांग्रेसमें नेताओंने खिलाफतके प्रस्तपर विचार किया । १९ जनवरी १९२० को डाक्टर अंसारीके नेतृत्वमें एक प्रतिनिधिमण्डल बाइसरायसे मिला और उन्हें "तुर्कांके साम्राज्य और खलीफाकी हैसियतसे मुलतानकी सर्वोच्च सत्ता कायम रखनेकी आवस्यकता" समझायी। वाइसरायने कहा कि हमारी सरकार इस मसलेमें कुछ भी कर सकतेमें असमर्थ है। फरवरी १९२० में वम्बईमें दूसरा खिलाफत सम्मेलन हुआ। उसमें भी पुराना निर्णय दोहराया गया । मार्चमें मुहम्मदअलीके नेतृत्वमें एक प्रतिनिधि मण्डल इंग्लैण्ड भेजा गया । वह १७ मार्चको ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीसे मिला, पर कोई नतीजा नहीं निकला । प्रधान मन्त्री-के इस इनकारसे भारतमें वड़ी निराशा हुई और १९ मार्चको शोक-दिवस मनानेका निश्चय किया गया । गान्धीजी इस वातपर तैयार हो गये कि यदि तुर्कीं से सन्धिकी दातें भारतीय मुसलमानींको मान्य न हुईं तो वे खिलास्त आन्दोलनका नेतृत्व करेंगे। असलमें गान्धी-जीने १० मार्चको ही एक घोषणापत्र प्रकाशित कर दिया था जिसमें उन्होंने असहयोगकी रूप-रेखा और योजना बतायी थी । उन्होंने लिखा था—''जो अधिकार ममलमानोंके लिए मीत और जिन्दगीके सवालते ज्यादा महत्व रखते हैं उन्हें छीनकर इंग्लैंण्ड हमसे चुपचाप वरदास्त करते जानेकी आशा नहीं कर सकता । इसिलए हम ऊपर और नीचे दोनों ओरसे काम आरम्भ कर सकते हैं। जो सम्मानित और लाभप्रद पदोंपर हैं वे उन्हें छोड़ दें। जो छोटी सरकारी नोकरियोंपर निम्न कर्मचारी हैं, वे भी ऐसा ही करें । असहयोग प्राइवेट नीकरियोंपर लागू नहीं होता । जो असहयोगमें शामिल नहीं होते उनके वहिष्कारकी राय मैं नहीं दे सकता । असन्तोप और जनभावनाकी परीक्षा स्वेच्छापूर्ण असहयोगमें ही है । फीजी सिपाहियों से नौकरी छोडनेके लिए कहनेका समय अभी नहीं आया है। यह पहला नहीं आखिरी कदम है। यह कदम हम तभी उठा सकते हैं जब बाइसराय, भारत सचिव और प्रधान मन्त्री सभी हमें छोड दें। इसके अलावा, असहयोगका हर कदम वहत सोच विचार कर उठाना है। हमें घीरे-घीरे आगे ब़द्ना चाहिये ताकि भीषण उत्तेजनामें भी हम आत्म-नियन्त्रण कायम रख सकें।" १४ मई १९२० को जो ज्ञान्ति सन्धिकी अतें प्रकाशित हुई वे खिलापत और तुर्कीके लिए अपमानजनक थीं । गान्धीजीने घोषणा की कि इन इतिके सुधारके लिए वे असहयोग आन्दोलन संघटित करेंगे । २८ मईको वम्बईमें खिलाफत कमेटी-की जो बैठक हुई उसमें गान्धीजीकी खिलाफत योजना स्वीकार कर ली गयी। ३० मईको अखिल भारतीय कांत्रेस कमेटीकी बैठक बनारसमें हुई जिसमें असहयोग प्रस्तावपर विचार करनेके लिए कांग्रेसका एक विशेष अधिवेशन बुलानेका निश्चय हुआ ।

सरकार कांग्रेस और खिलाफतके नेताओं को सन्देहकी निगाइसे देखने लगी थी। मई १९२० में जवाइरलाल नेहरू (जो उस समय तक राजनीतिमें उतर चुके थे और असहयोग आन्दोलन छिड़नेकी प्रतीक्षा उत्साहपूर्वक कर रहे थे) अपनी वीमार माँ और पत्नीके साथ मस्री गये हुए थे। "वहाँ उन दिनों अफगान और ब्रिटिश प्रतिनिधियों के बीच (१९९९ के

जमेंयतकी उद्भें लिखी काररवाई लशोक मेहता व अच्युत पटवर्धनकी 'दि कम्युनल ट्रायंगिल इन इंडिण्या' में २६ वें प्रमुपर उद्ध्त

अफगान-युद्धके वाद) शान्ति-सिन्धिपर समझौतेकी वात चल रही थी।" एक शाम अकरमात् पुलिस कप्तान सरकारका एक पत्र लेकर नेहरूजीके पास पहुँचा और उनसे आस्वासन माँगा कि वे अफगान प्रतिनिधि मण्डलसे सम्पर्क स्थापित नहीं करेंगे। नेहरूजीने लिखा है—"यह मुझे कुछ अजव-सा लगा, क्योंकि एक महीने मस्री रहनेके वाद भी मैंने इस प्रतिनिधि मण्डलकी स्रत तक नहीं देखी थी।" उन्होंने आस्वासन देनेसे इनकार कर दिया। इसपर उन्हें मस्री छोड़ देनेका हुक्म मिला। तवतक सिवनय अवज्ञा आन्दोलन ग्रुक्त नहीं हुआ था और नेहरूजी मस्री छोड़कर चले आये। जब अफगान प्रतिनिधि मण्डलको अखवारोंसे इस घटनाका पता चला, उसने नेहरूजीकी माँ और पत्नीके पास प्रतिदिन फलफूल भेजना ग्रुक्त कर दिया। वादमें नेहरूजी अपने पिताके साथ सरकारी आदेशके वावजूद मस्री गये। पर तवतक आदेश वापस लिया जा चुका था।

देशमें सार्वजिनक आन्दोलनका वातावरण वनता जा रहा था। इस सम्बन्धमें प्रान्तीय कांग्रें स कमेटियोंकी राय माँगी गथी थी। २ जूनको इलाहाबादमें एक सर्वदल सम्मेलन भी वुलाया गया। कुछ मुस्लिम नेताओं और गान्धीजीकी एक सिमित कार्यक्रम तैयार करनेके लिए बनायी गयी। इस कार्यक्रममें स्कूलों और कालेजोंका विह्ष्कार भी शामिल था। अगस्तमें असहयोग आन्दोलनकी रूपरेखा स्वीकृत हो गयी और आन्दोलन शुरू हो गया। गान्धीजी और अलीवन्धु देशका दौरा करने निकले। खिलाफत आन्दोलनको १८००० मुसलमानोंकी अफगानिस्तानमें हिजरतसे भी काफी मदद मिली। सिन्धसे उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त तकके मुसलमान दाक्लइस्लाम अफगानिस्तान जाने लगे। पर अफगान सरकारने उन्हें घुसने नहीं दिया और उन्हें वापस लौटना पड़ा। बहुतोंकी जान गयी। ''पेशावरसे काबुलका रास्ता बचों, बूढ़ों और स्त्रियोंकी कन्नोंसे पर गया था जो रास्तेकी तकलीफों वरदादत न कर सकनेके कारण वहीं गिर पड़े और फर उठे नहीं। जब ये लोग लौटे, वेधरवार थे क्योंकि जाते समय अपना माल असवाव व धरवार कौड़ियोंके मोल यहीं वेच गये थे।"

असहयोगके सिल्सिलेमें इसी महीने केन्द्रीय विधायिका कौंसिल्के कुछ सदस्योंने इस्तीफा दे दिया। इसी वीच पहली अगस्तको तिलककी मृत्यु हो गयी थी।

४ सितम्बरको कलकत्तेमें कांग्रेसका विशेष अधिवेशन असहयोगके विरोधी लाल लाजपतरायकी अध्यक्षतामें ग्रुरू हुआ और ९ सितम्बर तक चला। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंने असहयोगके सिद्धान्तका समर्थन करते हुए अपनी राय अखिल भारतीय कांग्रेसके पास भेजी थी; हालाँकि इस सिद्धान्तके व्यवहारपर कुछ मतमेद था। जालियाँवाला वागमें अफसरोंके कुकृत्योंपर परदा डालनेके लिए बनी हण्टर कमेटीकी रिपोर्टने अधिवेशनमें और ज्यादा जान डाल दी। इस कमेटीके सभी सदस्य अग्रेज थे और कमेटीने बहुमतसे स्वीकार किया था कि "ड्वायरने 'निर्णयमें गम्भोर भूल की जो घटनाकी तर्क संगत आवश्यकताओंसे कहीं बड़ी थी...कर्त्तव्यकी ईमानदार पर गलत भावनासे प्रेरित होकर उन्होंने ऐसा किया।" इंगलैण्डमें भी अधिकारी इसी प्रकार भारतीयोंके प्रति उदासीन और पंजावके जवन्य कृत्योंके प्रति सहानुभृतिपूर्ण रवैया अख्तियार कर रहे थे। कांग्रेसने कमेटीकी रिपोर्टको ''पूर्णरूपेण अखी-

१, जवाहरलाल नेहरू 'आत्मकथा' पृष्ट ५०

२. 'इण्डिया इन १९२०' पृष्ठ ५२-५३

कार" करते हुए कहा कि रिपोर्ट 'अपूर्ण, एकतरफा और स्वार्थपूर्ण वातोंगर आधारित होनेके कारण अविद्वसनीय और अस्वीकार्य" है। अपने प्रस्तावमें कांग्रेसने कहा—"पंजावकी घटनाओंगर आवश्यक काररवाई न कर ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलने भारतीय जनताका विश्वास खो दिया है।"

अधिवेशनके मुख्य प्रस्तावमें खिलाफत सम्बन्धी अन्यायका संक्षेपमें वर्णन करते हुए, पंजावमें हुए अत्याचारोंके लिए कहा गया था— "कांग्रेसका मत है कि जयतक इन दो अन्यायोंका प्रतिकार नहीं होता तयतक भारतीयोंको संतोप नहीं होगा, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा कायम रखने और ऐसी घटनाओंकी पुनरावृत्ति रोकनेका एक ही प्रभावकारी उपाय है और यह है स्वराज्यकी स्थापना ।" इस अधिवेशनका यह भी मत है कि भारतकी जनताके लिए केवल एक ही रारता अब खुला हुआ है; वह है महातमा गांधी द्वारा ग्रुक्त किये गये शान्ति-मय असहयोग आन्दोलनकी नीतिको स्वीकार करना और उसका समर्थन करना, इस निरंतर प्रगति करनेवाले आन्दोलनकी नीति तयतक कायम रहेगी जवतक इन दोनों अन्यायोंका प्रतिकार न हो और स्वराज्यकी स्थापना न हो।"

कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेसके इतिहासमें इसलिए भी स्मरणीय है कि वहाँ सभी कार्य हिन्दुस्तानीमें करने और स्वदेशी वेश-भूषा अपनानेका निर्णय हुआ था।

इन्हीं दिनों नागपुरमें मुस्लिम लीगका अधिवेशन और खिलाफत सम्मेलन हुआ जिसमें सरकारसे असहयोगका समर्थन करते हुए प्रस्ताव स्वीकृत हुए । इससे एक महीने पहले दिल्लीमें जमैयतका अधिवेशन हुआ या, उसमें भी ऐसा ही निर्णय हुआ था। लीगके अध्यक्ष जिनाने अपने भाषणमें कहा-मिस्टर गान्धीने देशके सामने अपना असहयोगका कार्यक्रम रखा है और खिलाफत सम्मेलनने उसका समर्थन किया है। अब यह आपके ऊपर निर्भर है कि जमके सिद्धान्तको स्वीकार करें या न करें, और सिद्धान्त स्वीकार करनेपर यह कार्यक्रम स्वीकार करें या न करें। यह कार्यक्रम आपमेंसे हर व्यक्तिपर प्रभावकारी होगा, इसलिए अपनी राक्ति तीलकर और प्रश्नकी अच्छाई बुराई देखकर उसपर पैसला करना आपके हाथमें है। लेकिन, एक बार आगे बढ़नेका फैसला कर लेनेके बाद फिर किसी भी हालतमें पीले हौरनेकी वात नहीं उठनी चाहिये ("नहीं, कभी नहीं" की ध्वनि)।...उधर शिमलाकी कॅंबाइयोंपर आत्मसंतोपसे भरा एक बाइसराय बैटा हुआ है, जो "घर" से हालमें आये ब्रिटिश सरकारके एक 'चार्टर' की ताकतसे सुरक्षित एक बार हम 'अभागे मुसलमानों' से हमददीं जाहिर करता है और दूसरी वार महात्मा गान्धीकी 'मूर्खतामें सबसे आगे बढ़ी योजना' पर अफसोस जाहिर करता है। यही वह "वदला हुआ दृष्टिकोण" है जिसकी लड़ाईके उन संकटमय दिनोंमें इम बड़े-बड़े शब्दोंमें तारीफ सुनते थे, जब भारतका सीना और खून माँगा जा रहा था और वदिकस्मतीं दिया जा रहा था-दिया जा रहा था तुर्कीका विनाश करनेके लिए, दिया जा रहा था रीलट कानूनकी वेडियाँ खरीटनेके लिए !³⁷⁸

फिर भी जिना असहयोगके खिलाफ थे। एक वक्त था जब वे कांग्रेस और लीग दोनोंके लोकप्रिय नेता थे, पर वे कभी कांग्रेसमें लीट नहीं। कलकत्ता अधिवेशनके बाद वे और कुछ अन्य कांग्रेसों नेता कांग्रेससे अलग हो गये। जैसा कि नेहरू जीने लिखा है "कांग्रेस-

१. मुहम्मद नौमानकी 'मुस्लिम इण्डिया' में पृष्ट १९३ पर उद्धत

के नये मोड़—असहयोग व नया विधान जिनसे वह अधिक जनप्रिय संस्था वनी, उन्हें कत्तई पसन्द नहीं थे। खादी धारण करनेवाली, हिन्दुस्तानीमें भाषणोंकी माँग करनेवाली भीड़में वे अपनेको विलकुल अजनवी पाते। एक वार उन्होंने निजी तौरपर सुझाव भी दिया था कि सिर्फ मेट्रिक पास लोग ही कांग्रे समें लिये जायँ।" इस प्रस्तावका विरोध करनेवालोंमें चित्तरंजनदास, विपिनचन्द्र पाल और मदनमोहन मालवीय भी थे।

असहयोगका नारा सजीव हो चुका था, पर आक्चर्यकी वात है कि नागपुर अधि-वेशनके अध्यक्ष सी० विजयराधवाचार्य स्वयं उसके विरुद्ध थे। उन्होंने अपने भाषणमें कहा— "आपको इस वातका निर्णय करना है कि क्या यह हमारा धार्मिक कर्तव्य नहीं है कि जब हम देशके मुसलमानों और गैरमुसलमानोंके एकेपर गर्व करते हैं, हमें असहयोगके सिद्धान्तके कारण दो नये वर्ग नहीं खड़े करने चाहिये—दो ऐसे वर्ग जो इस मतमेदके कारण भावनाके उद्देग एवं द्वेषसे परस्पर भीषण रूपसे विभाजित हो जाउँ। इस आन्दोलनके हमारे अनुभवके अलावा ऐतिहासिक प्रमाण हमें यही वताते हैं कि इस तरहके आन्दोलनके एक घरेल्र संकट छिपा हुआ है—चाहे वह आन्दोलनके सन्त नेताकी इच्छा और आन्दोलनकी प्रस्तावित सीमाके विरुद्ध ही वयों न हो।"

लेकिन कांग्रेसने निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। "जो वर्ग अभी तक जनमत वनाते और उसका प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, उनके द्वारा श्रीगणेश करानेके लिए और चूँिक सरकार अपनी सत्ताको स्कूलों, अदालतों वा विधायिका कौंसिलोंके नियन्त्रण और खितावों व उपाधियोंके वितरण द्वारा मजवूत बनाती है और चूँिक यह वांग्रनीय है कि आन्दोलनके उद्देश्यकी पूर्तिके लिए निम्नतम कुरवानी की जाय, इसलिए कांग्रेसका यह अधिवेशन उत्साहपूर्वक अपील करता है कि—

- (क) सभी सम्मानित उपाधियों व खितावों च अवैतिनक पदोंको छोड़ दिया जाय और स्थानिक संस्थाओंके नामजद स्थानोंसे इस्तीफा दे दिया जाय;
- (ख) सरकारी हाकिमों या उनके सम्मानमें आयोजित सभी सरकारी व अर्थ सर-कारी सम्मेलनीं, दरवारों व स्वागत समाओंमें शामिल होनेसे इनकार कर दिया जाय;
- (ग) सरकारी नियन्त्रणवाली या सहायताप्राप्त शिक्षा-संस्थाओं से धीरे-धीरे अपने वच्चोंको निकाल लिया जाय और उनकी जगह हर स्वेमें राष्ट्रीय स्कूलों व कालेजोंको स्थापना कर उनमें वच्चोंको पढ़ाया जाय;
- (घ) वकील और मुकदमेवाज घोरे-घीरे सरकारी अदालतोंका विह्हकार करें और निजी विवादोंको सुलझानेके लिए गैरसरकारी पंच अदालतें कायम करें;
- (च) मजदूर, वावू, फौजी कर्मचारी आदि मेसोपोटामियाँमें नौकरीके लिए भरती होनेसे इनकार करें;
- (छ) नये सुधारोंवाली विधायिका कौंसिलोंसे लोग अपनी-अपनी उम्मीदवारी वापस लें और जो उम्मीदवार कांग्रेसकी रायके वावजूद चुनाव लड़ता है, उसे मतदाता बोट न दें;
 - (ज) विदेशी सामानका वहिष्कार किया जाय।

आखिरी शर्तको व्यावहारिक बनानेके लिए प्रस्तावमें राय दी गयी थी कि लोग

१. जवाहरलाल नेहरू 'ऑटोबायोग्राफी' पृष्ठ ६७

स्वदेशी वर्जीका प्रयोग करें और "हर घरमें हायसे कताई ग्रुरू करनेके लिए वड़े पैमानेपर उद्योग" को प्रोत्साहित किया जाय।

नयी कोंसिलोंके चुनावके टीक पहले यह प्रस्ताय प्रकाशित हुआ । इससे खलवली मच गयी । जो राष्ट्रीय उम्मीदवार अमृतसर प्रस्तावके अनुसार इन कोंसिलोंके लिए चुनाव लड़ रहे थे, वे फोरन चुनावसे हट गये । लगभग ८० फीसदी मतदाताओंने वोट नहीं डाले और बहुत-सी जगहोंपर वेलटवक्स खाली रह गये । वंगालके प्रसिद्ध वकील चित्तरंजन दास असहयोग आन्दोलनके लिए गान्धीजीके भाषणांसे प्रभावित नहीं हुए थे, पर उनके निजी सम्पर्कमें आकर उनके विचार बदल गये । दास १९२० के आसपास बंगालके सबसे वह नेता माने जाते थे, हालाँ कि वे राजनीतिमें १९१७ में ही आये थे और अपनी मृत्युतक आट साल राजनीतिमें पूरी तरह रत रहे । दासने कांग्रेसके विशेष अधिवेशनमें असहयोगका कड़ा विरोध किया था और वाधिक अधिवेशनमें भी कड़ा विरोध करनेका संकल्प प्रकट किया था । नागपुरमें उन्होंने गान्धीजीसे निजी समझौता भी किया था कि दोनों अपने अपने क्षेत्रोंमें अपना अपना प्रचार करनेको स्वतन्त्र होंगे । पर इसके फौरन वाद चित्तरंजन दास गान्धीजीके पूरे अनुयायी हो गये । गान्धीजीका प्रस्ताव अस्थीकार करानेके लिए वे अपने खर्चपर पूर्वी वंगाल और आसामसे लगभग ढाई सौ प्रतिनिधि लाये थे । पर अब ये प्रतिनिधि गान्धीजीके साथ थे । और सबको आश्चर्य हुआ, जब दास स्वयं यह प्रस्ताव पेश करनेके लिए खड़े हुए तथा उसके दूसरे विरोधी लाजपतराय उसका समर्थन करनेके लिए ।

कांग्रेस और देशके इतिहासमें नागपुर अधिवेशन एक नया मोड़ था। इस अधिवेशनने जनता से कहा कि वह अंग्रे जी सत्ता भय करना छोड़ दे और उससे असहयोग करे। ड्यूक आव कनाट शींग्र ही भारत आनेवाले थे। उनके स्वागत सम्मानमें होनेवाले आयोजनींका विहक्तार करनेकी अपील भी की गयी। कांग्रेसके विधानमें संशोधन कर उसका उद्देश बनाया गया—"शान्तिपूर्ण और वैधानिक उपायो हारा स्वराज्य प्राप्त करना।" असहयोग आन्दोलन पूर्ण रूपेण शान्तिपूर्ण होना था। गान्धीजीने अपने अनुयायियों से कहा—मन, कर्म और वचन सबमें अहिंसा वरतो। लेकिन देशको इस नये हथियारका प्रयोग अभी सीखना था और कई जगह सरकारी हिंसाका जवाब और अधिक हिंसासे दिया गया।

असहयोग आन्दोलनको धार्मिक स्वीकृति देनेके लिए जमैयत-उल-उलेमाने 'फतवा' निकालकर मुसलमानोंसे खिताव छोड़ने, त्कृलों व अदालतोंका वायकाट करने और चुनाबोंमें भाग न लेनेकी राय दी। इस फतवेपर इस्लामके ४२५ पण्डितोंके इस्ताक्षर थे। बादमें ४७० इस्ताक्षर इसपर और किये गये।

राजनीतिक इलचलका अद्वितीय वर्ष—१९२१ असहयोग आन्दोलनके लिए तिलक स्वराज्य फण्डमें चन्दा देनेकी कांग्रेसकी अपीलसे गुरू हुआ। इस कोपमें पहली वड़ी रकम— एक लाख रुपया देनेवाले जमनालाल बजाज थे, जिन्होंने हालमें ही राववहादुरी छोड़ी थी। कांग्रेस महासमिति और कार्य-कारिणीकी वैठकें देशको आन्दोलनके लिए तैयार करनेके लिए जल्दी-जन्दी होने लगीं। ३१ मार्चको वेजवाड़ामें महासमिति और कार्य-कारिणीकी संयुक्त वैठक हुई 'जिसमें तय हुआ कि कोपमें एक करोड़ रुपया जमा किया जाय और कांग्रेसके एक करोड़ सदस्य बनाये जायें। २० लाख चरखे वॉटनेका प्रनाद भी स्वीदृत

पृथ्वीशचन्द्र राय 'लाइफ एण्ड टाइम्स ऑव सी. सार. दास'—पृष्ट १५९

हुआ । यह हाथके कते-तुने कपहेका उत्पादन वढ़ानेके लिए था । जुलाईमें वम्वईमें जब फिर संयुक्त वैठक हुई तवतक कोषमें एक करोड़से १५ लाख रुपया अधिक जमा हो जुका था, २० लाख चरखे वॅट चुके थे और कांग्रेसके ५० लाख सदस्य वन चुके थे।

लेकिन अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलनमें ८ जुलाईको ही कराचीमें मुसलमानोंने असहयोगका पहला सबक दे दिया जब उन्होंने प्रसाव पास किया कि "आजकी हालतमें अंग्रेजी फीजमें भरती होना, रहना या भरती करना मुसलमानोंके लिए मजहवी तौरपर गैर-कान्नी और शरिअतके खिलाफ है। यह हर मुसलमान—खासकर उलेमाओंका फर्ज है कि वह फीजके हर मुसलमानतक यह मजहबी फरमान पहुँचायें।" सम्मेलनने यह भी स्वीकार किया कि यदि ब्रिटिश सरकार तुकींके खिलाफ लड़ाई छेड़े तो भारतमें मुसलमान स्वतन्त्रताकी घोषणा कर दें और भारतीय जनतन्त्रका झण्डा कांग्रेसके अगले अधिवेशनमें फहरा दें। सम्मेलनके समापित मुहम्मदअलीने एक ओजस्वी भाषण किया जो वादमें उनके ऊपर राज-द्रोहके मुकदमेका कारण बना।

२८ से २० जुलाईतक वम्बईमें कांग्रेस महासमितिकी जो वैठक हुई उसमें भारतीय जनताको राय दी गयी कि "यह हर नागरिकका जन्म-सिद्ध अधिकार है कि वह फौज व सरकारी नौकरीमें किसीके रहने न रहनेपर अपनी राय दे, और फौजियों व सरकारी नौकरोंसे ऐसी सरकारकी नौकरी छोड़ देनेकी अपील करे जो देशकी बहुसंख्यक जनताका विश्वास खो जुकी हो।" महासमितिने "हर कांग्रेस सदस्यसे पहली अगस्तसे विदेशी बस्त्रोंका बहुक्कार" करनेको भी कहा। वस्त्र आयातकोंसे अपील की गयी कि वे विदेशी आईर खारिज कर दें। यह भी निश्चय कर लिया गया कि असहयोग आन्दोलनमें भाग लेनेवालोंपर मुकदमें चलें तो वे उन मुकदमोंकी काररवाईमें भाग न लें और जमानत व मुचलके माँगे जानेपर वे भी न दें। हाँ, अदालतोंके सामने वे एक वयान देकर जनताके समक्ष अपनेको निर्दोष सावित कर सकते हैं।

कांग्रेस समितियाँ आन्दोलनको तैयारियाँ कर रही थीं, तभी सरकारने इसकै नेताओं का असर बढ़ने न देनेका फैसला कर लिया । वेजवाडाकी वैठकके पहले ही चित्तरंजन दास पर मैमनसिंह, राजेन्द्रप्रसादपर आरा, याकूब इसनपर कलकत्ता और लाजपतराय पर पंशा-वरमें न धुसने की पावन्दी लगा दी गयी थी। इसी प्रकारके आदेश कितने ही स्थानीय नेताओं पर भी लगाये गये थे। लाहौरमें राजद्रोहात्मक सभा कान्न लागू किया गया था। कांग्रेसजन पकड़ पकड़ कर जेलोंमें टूँसे जा रहे थे। सरकार घवड़ायी हुई थी, क्योंकि जन-आन्दोलनका निर्णय अभी न होनेके वावजूद नागपुर अधिवेशनके वाद ही उत्साही लोग सभाएँ व प्रदर्शन करने लगे थे।

"पूरी संयुक्त प्रान्तीय (अव उत्तर प्रदेशीय) कांग्रेस कमेटी (५५ सदस्य) अपनी एक वैठक करते वक्त गिरफ्तार कर ली गयी। जोशमें वहुतसे ऐसे लोगोंने भी गिरफ्तार होने पर जोर दिया जिन्होंने कांग्रेस या राजनीतिमें भाग नहीं लिया था।" सरकारसे असहयोगकी अपीलका ऐसा तात्कालिक प्रभाव हुआ कि अक्सर दपतरोंसे लौटते हुए वावू उत्साह और उमंगमें वह जाते और घरकी जगह जेल पहुँच जाते थे। "किशोर और नवयुवक पुल्सिकी गाड़ियोंमें जा बैठते और उत्तरनेसे इनकार कर देते। जेले भर रही थीं और जेल अधिकारी

१. नेहरू 'ऑटोबायग्रॉफी', (आत्मचरित्र) पृष्ठ ८०

इस असाधारण घटनासे चिकत और किंकर्त्तव्यिवमृद् हो रहे थे। कभी-कभी ऐसा होता कि पुलिसकी लारियाँ एक संख्याके वारण्ट और उससे ज्यादा व्यक्ति लेकर जेल पहुँचतां। इन वारण्टोंपर नाम भी नहीं होते और जेल अधिकारी यही न समझ पाते कि क्या करें। जेलके नियमोंमें ऐसी स्थितके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। धीरे-धीरे सरकारने आम गिरफ्ता-रियोंकी नीति छोड़ दी और सिर्फ चुने हुए लोगोंको पकडना ग्रुक किया। ""

संयक्त प्रान्तमें १९२० के जाड़ोंमें तीन किसान नेताओं की गिरफ्तारीके साथ किसान आन्दोलन ग्रुंह हुआ । "उनपर प्रतापगढ़में मुकदमा ग्रुह्ह होनेको था । पर मुनवाईके दिन किसानींकी भीड अदालतके मैदानमें भर गयी और अदालतसे जेलतक—जहाँसे अभियुक्त आनेवाले थे, का रास्ता भी किसानींसे भर गया । मजिस्ट्रेटने सुनवाई अगले दिनके लिए स्थगित कर दी। पर अगले दिन मीड़ और वढ़ गयी और उसने जेलको लगभग घेर लिया। अतः किसान नेता छोड दिये गये—सम्भवतः जेलमें ही सरसरी तौरपर मुकदमा करके।" प्रतापगढ़की ही घटनाकी पुनरावृत्ति जनवरी १९२१ में रायवरेलीमें हुई । कुछ किसान नेता गिरफतार कर स्थानीय जेलमें रखे गये थे। गिरफतारीकी खबर पाते ही बहुतसे गाँचोंके किसान जुल्स बनाकर शहरकी तरफ रवाना हो गये। लेकिन किसानोंकी वड़ी भीड़ शहरके वाहर ही एक छोटी नदीके दूंखरी तरफ रोक ली गयी । नेहरू रायवरेंलीमें आमन्त्रित थे, और वे भौरन घटनास्थलके लिए खाना हुए । रास्तेमें उन्हें जिला मजिस्ट्रेटका आदेश मिला कि आप वापस लौट जायँ । आदेशकी पुरतपर ही नेहरू जीने लिख दिया कि 'मुझे किस कान्तके अन्तर्गत यह आदेश दिया जा रहा हैं और आगे वहे । नदीके पुलपर उन्हें फीजने रोका । किसान भी उनके आस-पास इकट्ठे हो गये। नेहरूजीने वहाँ भाषण किया। लेकिन नदीके दूसरे तरफ इकट्ठे किसान तितर वितर होनेसे इनकार करते रहे । उनपर गोली चली । कई मारे गये। भीड़ हटानेके लिए नेहरूका एक शब्द काफी होता, पर अधिकारी नेहरूजीको वह नहीं करने देना चाहते थे जिसे करनेमें वे स्वयं असफल हुए थे।

इस तरफ दलित, शोषित किसान उठ रहे थे। "किसान बड़ो संख्यामें ट्रेनोंपर विना टिकट चलने लगे—खास तौरपर समय-समयपर होनेवाली सार्वजनिक समाओंमें जिनमें ६०-७० हजार लोगतक माग लेते थे, वे वड़ी संख्यामें विना टिकट चलकर जाते। वे खुलेआम रेलवेके अधिकारियोंकी अवजा यह कह कर करते कि अब पुराना जमाना गुजर गया है।" फैंजाबाद में कुछ गाँवोंके किसानोंने एक तालुकेदारकी सम्पत्ति लूट ली। उन्हें एक दूसरे जमींदारने भड़काया था जिसने निजी अदावतका बदला लेनेके लिए किसानोंको समझाया कि गान्धीजी यही चाहते हैं। स्पष्ट है कि इन दो तरीकोंके लिए कांग्रेसने कभी स्थीकृति नहीं दी थी। गोलीवर्षा, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियाँ सार्वजनिक जीवनकी आम वार्ते बनती जा रही थीं।

खिलाफतकी गूँज दूर दक्षिणके मलावार तटपर जा पहुँची और वहाँ मोपलाओंको अंग्रेजी सत्ताके विरुद्ध हिंसात्मक विद्रोह करनेको प्रेरित किया। मोपलाओंका विद्रोह इतना संकल्पपूर्ण था कि मलावारमें एक वहें इलाकेपर कई दिनतक अंग्रेजी सत्ता छप्त रही और

१. नेहरू 'ऑटोबायबॉफी', पृष्ठ ८०

२. वही पुस्तक, पृष्ठ ५९

३. वही पुस्तक, पृष्ट ५९

खिलाफतके शाह सुहम्मद हाजीके नेतृत्वमें खिलाफत राज स्थापित रहा। इस छोटेसे खिलाफत राज्यका अन्त स्वयं मोपलाओंने अपनी धर्मान्धतामें हिन्दुओंके खिलाफ तलवार उठा कर ला दिया। सुसलमानोंकी हैसियतसे वे यह मूल नहीं पाते थे कि हिन्दू काफिर हैं।

मलावार तटपर ऊँची पहाड़ियों और समुद्रतटके बीच घने वनोंसे आच्छादित छोटी पहाड़ियोंकी शृंखलाएँ हैं। यहीं नवीं सदीमें अरबोंने आकर बस्तियाँ बनायी थीं और द्रविड व अन्य हिन्दू वालिकाओंसे विवाह कर मोपला समाजको जन्म दिया था। अरव मुसल-मानोंके भारतसे व्यापार-सम्बन्ध बहुत पुराने थे। हटी और अविनीत मोपला स्थापित सत्ताके अन्तके लिए हिंसा ही एकमात्र उपाय मानते थे। उन्होंने अस्त्र-शस्त्र इकट्ठे व वितरित करने ग्रुक कर दिये और लड़ाईकी तैयारी होने लगी। २५ जुलाई सन् १९२१ को अधि-कारियोंको इसकी स्चना मिली। तलाशीका हुक्म हुआ। पुक्कोट्टरमें उपद्रव हो गया और पुलिस पराजित हुई। फ़ौरन बाद पाँच इजार मोपलाओंने परप्पनगडीपर हमला बोल दिया और एक अंग्रेज फौजी अफसर व एक पुलिस अफसरको मार डाला: रेलवेका स्टेशन जला डाला गया, पटरियाँ उखाड़ दी गयीं । दूसरे दिन एक अंग्रेज फीजी टुकड़ी और मोपलाओं में जमकर संघर्ष हुआ । इस दुकड़ीके हाथ-पाँच थोड़ी देरमें फूल गये और दो अंग्रेज अफसरों व कई सिपाहियोंके खेत रहनेके बाद कमान अफसरने बचावकी लडाई लडनी ग्ररू कर दी। आसपाससे और फौजी दुकडियाँ इस संघर्षमें झोंक दी गयीं, पर विद्रोहियोंने उनके पैर उखाड दिये। विद्रोही विजयके उल्लासमें आगे वढ़ते आ रहे थे। अब हिमालय और वर्मासे, गरखों, गढवालियों, काचिनोंकी फौजी दुकडियाँ भेजी गयीं जिनके हृदयमें इस्लामके अनु-रागकी गन्ध भी होनेको सम्भावना नहीं थी। दूसरे ये लोग जंगल युद्धमें प्रवीण थे। 'पहाडी वैटरी'का एक दस्ता भी वहाँ हड़वड़ीमें भेजा गया पर धने जंगलों में वह काम न आया। आखिरकार, यह तय हुआ कि वड़ी-बड़ी फौजी टुकड़ियाँ जंगलोंको घेर लें और धीरे-धीरे एक-एक इलाकेको मँझा डालें, जैसे शिकारमें जंगल खँगाये जाते हैं। लेकिन इस तरीके में अक्सर ऐसा होता कि छोटी फौजी दुकड़ी मोपलाओं के वहे दस्तेके सामने पड़ जाती । वेपूर नदीके किनारे २।८ गुरखा राइफिल्सकी एक दुकड़ी एक मोपला दस्तेके सामने पड़ गयी। मलावारमें पत्थरकी पुरानी मसिजदोंकी बहुतायत है। ये मसिजदें मोपला विद्रोहके इतिहासमें बड़ा महत्त्व रखती हैं। एक ऐसी ही मसजिदमें ५६ मोपला विद्रोही छिपे थे। गुरखा दुकडीके एक अफसर और छः सिपाहियोंकी मौत और दो अफसरों व १० सिपाहियोंके बुरी तरह घावल होनेके बाद ही मसजिदपर कव्जा हो सका । डटकर सामना करते हुए सभी मापला मारे गये।

"उत्तेजित मोपलाओंका सामना करना कितना मुश्किल था, यह वतानेके लिए पिछक्काह चौकीके हमलेका उदाहरण काफी होगा। यहाँ चौकीपर दो तरफ़ हमला हुआ। मोपलाओंके कमसे कम ६७ और अधिकसे अधिक १५० लोग खेत रहे, पर उस चौकीका एक अंग्रेज अफ़सर व आठ सिपाही मारे गये और दो अफ़सर व १७ सिपाही घायल हुए। ७ जनवरी सन् १९२२ को खिलाफ़तके बाह, मुहम्मद हाजी और उनके २१ अनुयायियोंको पकड़कर फीजी अदालतके हुक्मसे गोलीसे उड़ा दिया गया, छः मोपला २० जनवरीको गोलीसे उड़ा दिये गये। विद्रोहका यहीं अन्त नहीं हुआ, जनवरीके अन्ततक वहुतसे और मोपला पकड़कर विशेष अदालतोंके समक्ष पेश किये गये।"

^{9.} लेफ़िटनेण्ट; जनरल सर जार्ज मेकमन—'टरमॉइल एण्ड ट्रेजेडी इन इण्डिया इन १९१४ एण्ड आफ्टर' पृष्ठ २४८-४९

यह विद्रोह कितना न्यापक और वड़ा या इसंका अनुमान इससे लग सकता है कि ''उसमें २२६६ विद्रोही संघर्पमें मारे गये, १६१५ घायल हुए, ५६८८ पकड़े गये और ३८२५६ ने हथियार डाल दिये।''

अव सरकारी प्रतिशोध शुरू हुआ। मोपला कैदियोंको फोजी अदालतोंके सामने पेश किया जाता, फैसला होता और वे गोलीसे उड़ा दिये जाते। दमनका सबसे करू इति- हास सम्भवतः एक मालगाड़ीमें लिखा गया। लगभग ७० (एक कथनके अनुसार १००) मोपला वन्दी एक मालगाड़ीके एक डिक्बेमें वन्दकर कालीकटसे मद्रास लाये जा रहे थे। दक्षिण भारतकी गर्मी और लोहेका वन्द डिक्बा। जब पोदान्र स्टेशनपर डिक्बा खोला गया, ६६ वन्दी दम घुटनेके कारण मर चुके थे और शेष मरणासन्न थे।

अपढ़ मोपले अंग्रेजोंके विरुद्ध विद्रोह करते समय गाजी और 'धर्मप्रवर्तक' वनने लगे थे। वे हिन्दुओं को वर्वरतासे मार डालते या जवरदस्ती उनका खतना कर उन्हें मुसल-मान बना छेते। वे समझते थे कि खिलाफत कायम करनेका यही तरीका है। अपने व्याव-हारिक जीवनमें वे हिन्दू जमींदारींके दुश्मन बन गये थे। जैसा कि स्मिथने लिखा है "मोप-लाओं के जीवनमें कड़आहट थी; वे हिन्दुओं के दुश्मन थे; वे अंग्रेजों के दुश्मन थे; वे इस दुनियाके दुश्मन थे जिसने उन्हें इतने कप्ट दिये । उनकी धुन, उनकी ललक, उनकी व्यप्रता उस पीडित शोषित समाजकी व्यक्रता थी जो अपने उत्पीड़कके विरुद्ध विद्रोह कर रहा हो, उस समाजकी व्यव्रता थी जो धर्मान्ध हो पापको नष्ट कर सत्य और अच्छाईका राज्य स्थापित कर रहा हो।" कांग्रेस वाकिंग कमेटीके अनुसार "एक ऐसे धर्मान्ध गिरोह द्वारा हिन्दुओं-को वलात् मुस्लिम वनाया गया जो हमेशा खिलाफ़त और असहयोग आन्दोलनके विरुद्ध रहा, और जहाँतक हमारी स्वना है, सिर्फ ऐसी तीन ही घटनाएँ हुई । टेकिन एक प्रश्नके उत्तरमें मद्रात सरकारकी सचनाके आधारपर केन्द्रीय विघान सभामें वताया गया कि "वलात् धर्म परिवर्तनकी सम्भवतः हजारों घटनाएँ हुई पर प्रत्यक्ष कारणींसे सही अनुमान लगाना असम्भव होगा।" कांग्रेस कार्यसमिति (विकिंग कमेटी) ने मोपला हिंसाकी निन्दा- 🕒 की और एक प्रस्तावमें कहा कि ''उपद्रव उन्हीं इलाकोंमें हुए जहाँ खिलाफत व कांग्रेसके कामोंपर रोक लगी हुई थी।"

लेकिन अंग्रेजींका विरोध मोपला क्षेत्रींमें ही सीमित नहीं था। मद्रासके गवर्नर विलंगडनने १ सितम्त्रर १९२१ को मद्रास विधायिका कीसिलमें कहा—''मलावारमें तो स्थिति गम्भीर हैं ही, में माननीय सदस्योंको यह चेतावनी दे देना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ कि मलावार ही सरकारी चिन्ताका कारण नहीं है। 'सरकारों'के पूरे इलाके—खास तौरपर मुद्दानोंके क्षेत्रोंमें वहीं कपटपूर्ण प्रचार वैधानिक सत्ताको खोखला करनेके लिए, जातिविद्वेप पेदा करनेके लिए, जनतामें असहिष्णुता और वैधानिक सत्ताके विरुद्ध पृणा पेदा करनेके लिए काम करता रहा है।"

स्तिम्त्ररमें कराचीके खिलाफत सम्मेलनके भाषणों और प्रस्तावींके लिए अलीवन्धु व पाँच अन्य व्यक्ति पकड़े गये। वे पाँच थे डाक्टर सैफ़िद्दीन किचल, जगद्गुर शंकराचार्य

१. वही पुस्तक पृष्ठ २५०

२. डब्लू, सी, स्मिथ 'मॉडर्न इस्लाम इन इण्डिया' पृष्ठ २३%

२. विधान सभाकी काररवाई १६ जनवरी सन् १९२२

(शारदा पीठ), निसार अहमद, पीर गुलाम मुजाहिद और हुसैन अहमद। वे कराचीके एक मजिस्ट्रेटके समक्ष पेश हुए और उन्हें दो-दो वर्षकी कैदकी सजाएँ दे दी गयीं। मुहम्मद-अलीने अपने वयानमें कहा—'आखिरकार, इस मुकदमेंके मतलव क्या हैं ! किसके विश्वाससे हम भारतके हिन्दू और मुसलमान वाँधे हुए हैं ! मैं एक मुसलमानकी हैसियतसे कहता हूँ कि अगर में सही रास्तेसे हटता हूँ तो मुझे मेरी गलती समझानेके लिए एक ही रास्ता है, और वह है कुरान पाक।"

जव कराचीका मुकदमा चल रहा था, गान्धीजी त्रिचनापल्लीमें थे। जव उन्होंने सुना कि मुहम्मदअलीका भाषण उनके विरुद्ध एक अभियोग है, गान्धीजीने वह भाषण एक सार्व-जिनक सभामें दोहराया। कांग्रेस कार्यकारिणीने भी ५ अक्टूबरकी अपनी वैठकमें खिलाफत सम्मेलनका प्रस्ताव पास किया और सभी कांग्रेस समितियोंसे सार्वजिनक सभाएँ कर यह प्रस्ताव पास करनेको कहा। कांग्रेस कमेटियोंने १६ अक्टूबरको सार्वजिनक सभाएँ कर यह प्रस्ताव दोहराया। प्रस्तावमें कहा गया था कि "यह राष्ट्रहित और राष्ट्रप्रतिष्ठाके विरुद्ध है कि कोई भारतीय ऐसी सरकारकी नौकरीमें रहे जिसने जनताकी सही माँगोंको कुचलनेके लिए रोलट कानून आन्दोलनके समय पुलिस और फौजको इस्तेमाल किया हो, जिसने मिस्न, तुर्की, अरव व दूसरे देशोंकी राष्ट्रीय भावना कुचलनेके लिए फौजोंका प्रयोग किया हो।" कार्यसमिति सरकारो नौकरी छोड़नेवालोंके भरणपोपणका प्रयन्ध नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने सिर्फ उन्होंको नौकरी छोड़नेवालोंके भरणपोपणका प्रवन्ध नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने सिर्फ उन्होंको नौकरी छोड़नेको कहा जो विना नौकरीके काम चला सकें। पुलिस व फौजके सिपाहियोंको सुझाव दिया गया कि वे जीविकाके लिए कताई बुनाई आदिका सहारा लें।

कार्यसमिति अब भी आम स्विनय अवज्ञा आन्दोलनके लिए उपयुक्त समय आया नहीं मानती थी, लेकिन उसने उन व्यक्तियोंको अवज्ञा करनेको अनुमित दे दी थी जिनके स्वदेशी प्रचारपर प्रतिवन्ध लगाये जाते थे। अगले महीने—५ नवम्बरको कार्यसमितिने प्रान्तोंको अपनी जिम्मेदारीपर स्विनय अवज्ञा आन्दोलन छेड़ देनेकी अनुमित दे दी। इसमें लगान व करबन्दी भी ज्ञामिल थी। कुछ शतें लगा दी गयीं जिन्हें हर स्विनय अवज्ञाकारीको पूरा करना होता था। ये शतें थीं—वह विदेशी वस्त्र त्यागकर खहर धारण करे; वह कताई जानता हो; वह अहिंसा और हिन्दू मुस्लिम एकतामें विश्वास करता हो; वह अस्पृत्र व्या और छुआछूत दूर करनेके लिए काम करता हो।

नवम्बरके मध्यमें सिवनय अवज्ञाकी जगह भीषण हिंसा हो गयी। १७ नवम्बरको विटिश युवराज प्रिंस आव वेल्स वम्बई आये। कांग्रेसने पहले ही स्वागत सम्मान आदिका विहिष्कार करनेकी सलाह दे दी थी। वम्बई शहरमें इस विहिष्कारको सफल बनानेके लिए वड़ी चहलपहल रही। हजारों उत्तेजित व्यक्ति सड़कों व गिलयों में घूमते। भीड़ बढ़कर नियन्त्रणके वाहर हो जाती। चार दिनतक मुठभेड़ें होती रहीं। उपद्रव हुए और रक्तपात हुआ जिसमें ५३ मरे और ४०० घायल हुए।

स्वयंसेवकोंकी सिक्तयता युवराजके आगमनके साथ एकाएक वढ़ गयी, क्योंकि कांग्रेस और खिलाफतके स्वयंसेवकोंके द्वारा ही विह्निकारका संयोजन होना था। युवराज २५ दिस-म्वरको कलकत्ते पहुँचनेवाले थे। वहाँ अधिकारी स्वयंसेवकोंसे आशंकित हो उठे। स्वयंसेवक संवटन गैरकान्नी करार दे दिया गया और इसकी सरकारी घोषणाके साथ ही वंगालभर- में हजारों स्वयंसेवक गिरफ्तार कर लिये गये। इनमें चित्तरंजन दासकी परनी और वहन भी थीं। उसके वाद सरकारने आम गिरफ्तारियोंकी नीति अपनायी और लाजपतराय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू आदि सव जेलोंमें भर दिये गये। जेलमें दासके साथ ही सुभापचन्द्र वसु भी थे जो भविष्यमें महान नेता वने। युवराजके आगमन पर शान्ति कायम रखनेके लिए दिसम्बरतक देशमें २००० राजनीतिक कार्यकर्जा गिरफ्तार किये जा चुके थे। १९२२ के शुरूमें यह संख्या ३००० तक जा पहुँची थी।

नेहरूजी इड़तालकी नोटिस वॉटनेके अभियोगमें पक है गये थे। पर जेलमें तीन महीने वाद उन्हें सूचना मिली कि मुकदमेंपर पुनर्विचार करनेवाले अधिकारीके अनुसार उन्हें गलत सजा मिल गयी। उन्हें मुक्त कर दिया गया। पर कुछ ही दिनों वाद कुछ और लोगोंके साथ वे भी 'धमकी देने और रुपया वस्ल करने'के अभियोगमें गिरफ्तार कर लिये गये। वे विहिष्कार आन्दोलनके काममें लगे थे और इलाहावादके व्यापारी विलायती कपड़ा न खरीदने और न मँगानेकी शपथें ले रहे थे।

सरकार तथा कुछ अन्य व्यक्तियोंको डर था कि युवराजके कलकत्ते पहुँचने पर स्थिति कहीं गम्भीर न हो जाय। ये लोग गान्धीजी और वाइसरायके वीच समझीता करानेको उत्सुक थे। जिना और मालबीय मध्यस्य वन २१ दिसम्बरको वाइसराय लाई रीडिंगसे मिले। वातचीतिकी पहली द्यार्त राजनीतिक केंदियोंको रिहाई थी; लाई रीडिंग इसके लिए तैयार थे पर वे कुछ राजनीतिक वन्दियोंको, जैसे कि खिलाफत वन्दियोंको, नहीं छोड़ना चाहते थे। वातचीत भंग हो गयी और देशमें युवराजके स्वागतका वहिष्कार हुआ। कलकत्तेमें सारा काम, वाजार, व्यापार वन्द रहा और शहर वीरान सा लगता रहा। इसी तरहकी इड़तालें और प्रदर्शन दूसरे शहरों व कस्वोंमें भी हुआ।

उसके बाद अहमदावादमें कांग्रेस अधिवेशन हुआ । अध्यक्ष चित्तरंजन दास चुने गये थे, पर वे जेलमें थे, इसलिए इकीम अजमल खाँ अध्यक्ष वने । वे दिल्लीके नामी इकीम थे और देश-विदेश घूमे हुए थे। गान्धीजीके प्रभावमें आकर उन्होंने रोप जीवन देशको अपित कर दिया था। प्रिंस आव वेल्सके आगमनके सम्बन्धमें अजमल खाँने कहा—"युवराजसे हमारी कोई दुरमनी या झगड़ा नहीं है, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि दिवालिया सरकार युवराजके आगमनका सहारा लेकर अपनी साख कायम करनेकी कोशिश करे।" भोपलाओं द्वारा हिन्दुओंके वलात् धर्म-परिवर्तनकी उन्होंने निन्दा की। चित्तरंजन दासका लिखा हुआ भाषण श्रीमती सरोजिनी नायडूने पढ़ा। इस भाषणमें १९१९ के भारत कानृन (गवर्नमेण्ट अव इण्डिया ऐक्ट) पर देशका असन्तोप व्यक्त किया गया था और कहा गया था कि व्रिटेनको भारतीय सहयोग तभी प्राप्त होगा जब वह भारतका स्वाधीनताका अधिकार स्वीकार कर ले।

कांग्रेसने कार्यसंचालनका पूरा भार गान्धीजीको दे दिया और उन्हें कांग्रेस महा-समितिके पूरे अधिकार भी दे दिये। गान्धीजीका प्रस्ताव अधिवेदानका मुख्य प्रस्ताव था जिसमें भावी आन्दोलनकी रूपरेखा इंगित की गयी थी। प्रस्तावमें कहा गया था कि जहाँतक सम्भव हो कांग्रेसके अन्य काम स्थगित कर दिये जाबँ और १८ वर्षसे ऊपरके सभी सदस्य स्वयंसेवक वन जायँ। कांग्रेसकी राय थी कि हर जगह सभाजींपर लगी रोकका उछंघन कर सभाएँ की जावँ। पर ये सभाएँ कांग्रेसके कटोर अनुदासनमें हों; पहलेसे जिनके नाम घोषित हों वे ही लिखित भाषण करें, भाषणों अञ्चेजना या हिंसाको विलक्कल वचाया जाय। १८ वर्ष वे छात्रों — विशेषकर राष्ट्रीय संस्थाओं के छात्रों व अध्यापकों से स्वयंसेवक वनने की अपील की गयी। प्रस्तावमें "अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन के कार्यक्रमको पहले और अधिक गतिमान् व शक्तिमान् बनाकर उस ढंगसे चलाने का कांग्रेसका हट संकल्प" दोहराया गया था जिस ढंगसे प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ उसे चलाने का निर्णय करें। दूसरे प्रस्तावमें उन लोगों को सम्बोधित किया गया था जिन्हें असहयोगमें पूरा विक्वास न था। इन लोगों से अपील को गयी थी कि वे गरीव जनतामें कपास ओटने, बुनने व कातने का प्रचार कर उनकी स्थितिके सुधारमें सहायता दें।

इस अधिवेशनमें हसरत मोहानीने एक प्रस्ताव लाकर स्वराज्यकी परिभाषा 'पूर्ण स्वाधीनता — विदेशी नियन्त्रणसे विलक्ष्यल स्वतन्त्र' करनी चाही । पर गान्धीजीके जोर देने पर प्रस्ताव गिर गया । गान्धीजीने कहा— "दुनियाके सोचने-समझनेवाले लोग कहेंगे कि हम खुद नहीं जानते कि हम हैं क्या । हमें अपनी सीमाएँ भी जान लेनी चाहिये । पहले हिन्दुओं और मुसलमानोंमें पूर्ण और अविच्छित्र एकता हो जाने दीजिये । आज यहाँ कौन हैं जो विश्वासके साथ कह सके कि— 'हाँ, भारतीय राष्ट्रीयतामें अविभेद्य हिन्दू-मुस्लिम एकता पैदा हो गयी है । पहले हम अपनी ताकत समझ लें और उसे मजबूत कर लें; 'पहले हम अपनी गहराई नाप लें; हम ऐसे गहरे पानीमें न उतरें जिसकी गहराई ही हमें नै माल्यम हो और हसरत मोहानी साहबका प्रस्ताव हमें नामाल्यम गहराईमें ही ले जाता है।" गान्धीजीके भाषणके वाद हसरत मोहानीके प्रस्तावको काफी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ और वह गिर गया।

१९२१ में हसरत मोहानी लीगके अध्यक्ष हुए थे। वहाँ भी उन्होंने मुस्लिम श्रोताओं के समक्ष यही प्रस्ताव और अधिक ठोस रूपमें, और अधिक जोरके साथ पेश किया; इसपर उन्हें जेल हो गयी। उन्होंने कहा—

"१ जनवरी सन् १९२२ को भारतीय लोकतन्त्र—भारतके संयुक्त राज्यकी स्थापना-की घोषणा कर दी जाय । मुल्लिम लीग कमजोर हैं । लेकिन लीग, कांग्रेस और खिलापत कानफरेंसके ध्येय एक ही हैं । फर्क सिर्फ इतना है कि लीग सिर्फ मुसलमानोंके हकोंकी हिफाजत करना चाहती है । जरूरत इस बातकी है कि पहले स्वराज्य प्राप्त कर लिया जाय; हकोंकी हिफाजत बादमें होती रहेगी । लेकिन लीगका बहुमत दूसरी विचारधाराका है । अगर सरकार पंजाब और खिलाफतके मसलोंको न सुलझाये तो लीगका लक्ष्य पूर्ण स्वतन्त्रतासे भी आगे बढ़ना चाहिये ।

'मुसलमानोंको समझना चाहिये कि भारतीय जनतन्त्रकी स्थापनासे उनका दोहरा फायदा होगा; एक तो जनतान्त्रिक राज्यके नागरिकोंकी हैसियतसे उन्हें वे ही फायदे और हक मिलंगे जो दूसरे नागरिकोंको; और दूसरे अंग्रेजोंका प्रभावक्षेत्र कम हो जानेसे इस्लामी दुनियाको वह राहत मिल जायगो जो रचनात्मक कामोंके लिए जरूरी है।"

मोहानीका प्रस्ताव विषय-समिति और खुले अधिवेशन दोनोंमें गिर गया। ठण्डी पड़ती और पीछे हटती हुई लीगपर प्रस्ताव जैसे वमके गोलेकी तरह गिरा। १९२१ में लीगने असहयोग सम्बन्धी कोई प्रस्ताव पास नहीं किया। सात सालतक लीग और कांग्रेस साथ-

१, उद्धं भाषणका अनुवाद

साथ आगे वही थीं, पर अब जब असहयोग एक सत्य बन गना था, लीगते अपना अधि-वेशन भी उसी शहरमें नहीं किया, जहाँ कांग्रेस हो रही थी। सात साल तक दोनोंके वार्षिक अधिवेशन एक साथ होते रहे थे। जैसा कि इसरत मोहानीने कहा था, लीगके अधिकांश लोग दूसरी विचारधाराके थे और वे सविनय अवजा आन्दोलनकी आगमें नहीं कृदना चाहते थे। १९२२ में तो ऐसा लगा मानों लीगकी जीवनी शक्ति ही शीण हो रही हो, उस साल कोई वार्षिक अधिवेशन ही नहीं हुआ। १९२३ में लखनऊमें जो वार्षिक अधिवेशन हुआ उसमें इतने कम आदमी आये कि खुला अधिवेशन ही नहीं हो पाया। अगले तीन अधि-वेशनोंमें राजनीतिकी जगह साम्प्रदायिक वार्तोपर ही विचार होता रहा।

१९२२ की जनवरिक मध्यमें आन्दोलन टालनेके लिए सरकार और कांग्रेसमें समक्षोतिकी एक कोशिश और की गयी । वम्बईमें एक सर्वदल सम्मेलन हुआ जिसमें विभिन्न
पार्टियों के लगभग ३०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया । तीन दिनकी दैठकमें (१४ से १६ जनवरी तक) सम्मेलनने संधिका एक मसौदा तैयार किया जिसपर सरकार और कांग्रेस दोनों
के दस्तखत होने थे । सम्मेलनके प्रस्तावमें (१) सरकारकी दमननीतिकी निन्दा की गयी
थी, (२) खिलाफत, पंजाब हत्याकांड और स्वराज्यके प्रक्तोंपर एक गोलमेज सम्मेलन
बुलानेका सुझाव दिया गया था और इस गोलमेज सम्मेलनके लिए उचित वातावरण तैयार
करनेके लिए समी राजनीतिक विन्दर्योंकी रिहाई और प्रतिवन्धारमक आदेशोंके हटानेकी
माँग की गयी थी । कांग्रेस कार्यसमितिने १७ जनवरीकी बैठकमें सरकारसे सन्धिके लिए
तैयार होनेकी घोषणा की और आन्दोलन महीनेके अन्ततक शुरू न करनेका देसला
किया ।

गान्धीजीने वाइसरायसे दोस्तीके लिए अपना द्दाथ आगे वढ़ाया, हालाँ कि इससे आन्ध्रमें लगानवन्दी आन्दोलनका कार्यक्रम विगइ रहा था। आन्ध्र प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीने करवन्दीका फैसला १५ दिसम्बर १९२१ को ही कर लिया था। जनवरीमें वहाँके जिले आवश्यक स्चना एकत्र करनेमें लगे थे, जब गुण्ट्रने करवन्दी आन्दोलनका श्रीगणेश भी कर दिया। पूरा जिला कांग्रेसकी आवाजपर एकदम उठ खड़ा हुआ; मैदानोंमें लोगोंने लगान रोक लिया; पहाड़ियोंपर जानवर चरानेकी फीस रोक ली। जो किसान अब भी कहापोहमें लगे थे उन्हें एक घटनासे मनोवैज्ञानिक प्रेरणा मिली। पुलिसके एक दारोगाने किसी गाँवके एक प्रमुख किसानको गोलीका निश्चाना बना दिया। इसपर गाँववाले उभर पड़े और फौंज व पुलिसका आतंक भी उनसे लगान-अदा न करवा सका। गान्धीजीने सोचा कि आन्ध्रका करवन्दी आन्दोलन सर्वटल सम्मेलनके प्रस्तावके वातावरणमें खपता नहीं। इसलिए उन्होंने राय दी कि सभी कर २५ जनवरीतक अदा कर दिये जाब और वे अदा कर दिये गये। लेकिन वाइसराय सन्धि प्रस्तावके लिए तैयार नहीं हुए, उन्होंने वात किये विना ही उन्हें उकरा दिया।

कांग्रेस कार्यसमितिने ३१ जनवरीको परिस्थितिका सिंहावलोकन करते हुए सार्व-जिनक स्विनय अवज्ञा आन्दोलनको गुजरातके वारदोली तालुकेमें सीमित करनेका फैसला किया, क्योंकि वहाँ दक्षिण अफीकाके सत्याग्रहके बहुतसे अनुभवी लोग मौजूद थे। २९ जनवरीको विष्टलभाई पटेलके सभापितत्वमें एक तालुका सम्मेलन हुआ जिसमें आन्दोलनके लिए तैयारी प्रकट की गयी। देशभर्मे कहीं और करवन्दी आन्दोलन चलानेकी इजाजत नहीं नाम घोषित हों वे ही लिखित भाषण करें, भाषणोंमें उत्तेजना या हिंसाको विलक्कल वचाया जाय। १८ वर्ष वे छात्रों — विशेषकर राष्ट्रीय संस्थाओं के छात्रों व अध्यापकों से स्वयंसेवक वननेकी अपील की गयी। प्रस्तावमें "अहिंसासक असहयोग आन्दोलनके कार्यक्रमको पहलेसे और अधिक गतिमान् व शक्तिमान् वनाकर उस ढंगसे चलानेका कांग्रेसका दृढ़ संकल्प" दोहराया गया था जिस ढंगसे प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ उसे चलानेका निर्णय करें। दूसरे प्रस्तावमें उन लोगोंको सम्बोधित किया गया था जिन्हें असहयोगमें पूरा विश्वास न था। इन लोगोंसे अपील को गयी थी कि वे गरीव जनतामें कपास ओटने, वुनने व कातनेका प्रचार कर उनकी स्थितिके सुधारमें सहायता दें।

इस अधिवेशनमें हसरत मोहानीने एक प्रस्ताव लाकर स्वराज्यकी परिभाषा 'पूर्ण स्वाधीनता — विदेशी नियन्त्रणसे विलक्कल स्वतन्त्र' करनी चाही । पर गान्धीजीके जोर देने पर प्रस्ताव गिर गया । गान्धीजीने कहा— "दुनियाके सोचने-समझनेवाले लोग कहेंगे कि हम खुद नहीं जानते कि हम हैं क्या । हमें अपनी सीमाएँ भी जान लेनी चाहिये । पहले हिन्दुओं और मुसलमानोंमें पूर्ण और अविच्छित्र एकता हो जाने दीजिये । आज यहाँ कीन है जो विश्वासके साथ कह सके कि— 'हाँ, भारतीय राष्ट्रीयतामें अविभेच हिन्दू मुस्लिम एकता पैदा हो गयी है । पहले हम अपनी ताकत समझ लें और उसे मजबूत कर लें; 'पहले हम अपनी गहराई नाप लें; हम ऐसे गहरे पानीमें न उतरें जिसकी गहराई ही हमें नै माल्म हो और हसरत मोहानी साहबका प्रस्ताव हमें नामाल्स गहराईमें ही ले जाता है।" गान्धीजीके भापणके वाद हसरत मोहानीके प्रस्तावको काफी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ और वह गिर गया।

१९२१ में हसरत मोहानी लीगके अध्यक्ष हुए थे। वहाँ भी उन्होंने मुस्लिम श्रोताओं के समक्ष यही प्रस्ताव और अधिक टोस रूपमें, और अधिक जोरके साथ पेश किया; इसपर उन्हें जेल हो गयी। उन्होंने कहा—

"१ जनवरी सन् १९२२ को भारतीय लोकतन्त्र—भारतके संयुक्त राज्यकी स्थापना-की घोषणा कर दी जाय । मुल्लिम लीग कमजोर है । लेकिन लीग, कांग्रेस और खिलाफत कानफरंसके ध्येय एक ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि लीग सिर्फ मुसलमानोंके हकोंकी हिफाजत करना चाहती है। जरूरत इस वातकी है कि पहले स्वराज्य प्राप्त कर लिया जाय; हकोंकी हिफाजत वादमें होती रहेगी। लेकिन लीगका वहुमत दूसरी विचारधाराका है। अगर सरकार पंजाव और खिलाफतके मसलोंको न सुलझाये तो लीगका लक्ष्य पूर्ण स्वतन्त्रतासे भी आगे वढ़ना चाहिये।

"मुसलमानोंको समझना चाहिये कि भारतीय जनतन्त्रकी स्थापनासे उनका दोहरा फायदा होगा; एक तो जनतान्त्रिक राज्यके नागरिकोंकी हैसियतसे उन्हें वे ही फायदे और हक मिलंगे जो दूसरे नागरिकोंको; और दूसरे अंग्रेजोंका प्रभावक्षेत्र कम हो जानेसे इस्लामी दुनियाको वह राहत मिल जायगो जो रचनात्मक कामोंके लिए जरुरी है।"

मोहानीका प्रस्ताव विपय-समिति और खुले अधिवेशन दोनोंमें गिर गया। टण्डी पड़ती और पीछे हटती हुई लीगपर प्रस्ताव जैसे वमके गोलेकी तरह गिरा। १९२१ में लीगने असहयोग सम्बन्धी कोई प्रस्ताव पास नहीं किया। सात सालतक लीग और कांग्रेस साथ-

१. डद् भाषणका अनुवाद

साथ आगे बढ़ी थीं, पर अब जब असहयोग एक सत्य बन गमा था, लीगने अपना अधिने बेशन भी उसी शहरमें नहीं किया, जहाँ कांग्रेस हो रही थी। सात साल तक दोनोंके वार्षिक अधिवेशन एक साथ होते रहे थे। जैसा कि इसरत मोहानीने कहा था, लीगके अधिकांश लोग दूसरी विचारधाराके थे और वे सविनय अवज्ञा आन्दोलनकी आगमें नहीं कूदना चाहते थे। १९२२ में तो ऐसा लगा मानों लीगकी जीवनी शक्ति ही क्षीण हो रही हो, उस साल कोई वार्षिक अधिवेशन ही नहीं हुआ। १९२३ में लखनऊमें जो वार्षिक अधिवेशन हुआ उसमें इतने कम आदमी आये कि खुला अधिवेशन ही नहीं हो पाया। अगले तीन अधिवेशनों राजनीतिकी जगह साम्प्रदायिक बातोंपर ही विचार होता रहा।

१९२२ की जनवरीके मध्यमें आन्दोलन टालनेके लिए सरकार और कांग्रेसमें सम-झौतेकी एक कोशिश और की गयी। वम्बईमें एक सर्वदल सम्मेलन हुआ जिसमें विभिन्न पार्टियोंके लगभग २०० प्रतिनिधियोंने भाग लिया। तीन दिनकी बैठकमें (१४ से १६ जन-वरी तक) सम्मेलनने संधिका एक मसौदा तैयार किया जिसपर सरकार और कांग्रेस दोनों के दस्तलत होने थे। सम्मेलनके प्रस्तावमें (१) सरकारकी दमननीतिकी निन्दा की गयी थी, (२) खिलाफत, पंजाव हत्याकांड और स्वराज्यके प्रक्तोंपर एक गोलमेज सम्मेलन बुलानेका सुझाव दिया गया था और इस गोलमेज सम्मेलनके लिए उचित वातावरण तैयार करनेके लिए सभी राजनीतिक बन्दियोंकी रिहाई और प्रतिबन्धात्मक आदेशोंके हटानेकी माँग की गयी थी। कांग्रेस कार्यसमितिने १७ जनवरीकी बैठकमें सरकारसे सन्धिके लिए तैयार होनेकी घोषणा की और आन्दोलन महीनेके अन्ततक शुरू न करनेका फैसला किया।

गान्धीजीने वाइसरायसे दोस्तीके लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, हालाँ कि इससे आन्ध्रमें लगानवन्दी आन्दोलनका कार्यक्रम विगड़ रहा था। आन्ध्र प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीने करवन्दीका फैसला १५ दिसम्बर १९२१ को ही कर लिया था। जनवरीमें वहाँके जिले आवश्यक स्चना एकत्र करनेमें लगे थे, जब गुण्टूरने करवन्दी आन्दोलनका श्रीगणेश भी कर दिया। प्रा जिला कांग्रेसकी आवाजपर एकदम उठ खड़ा हुआ; मैदानोंमें लोगोंने लगान रोक लिया; पहाड़ियोंपर जानवर चरानेकी फीस रोक ली। जो किसान अब भी ऊहापोहमें लगे थे उन्हें एक घटनासे मनोवैज्ञानिक प्रेरणा मिली। पुलिसके एक दारोगाने किसी गाँवके एक प्रमुख किसानको गोलीका निशाना बना दिया। इसपर गाँववाले उभर पड़े और फौज व पुलिसका आतंक भी उनसे लगान-अदा न करवा सका। गान्धीजीने सोचा कि आन्ध्रका करवन्दी आन्दोलन सर्वदल सम्मेलनके प्रस्तावके वातावरणमें खपता नहीं। इसलिए उन्होंने राय दी कि सभी कर २५ जनवरीतक अदा कर दिये जायें और वे अदा कर दिये गये। लेकिन वाइसराय सन्धि प्रस्तावके लिए तैयार नहीं हुए, उन्होंने बात किये विना ही उन्हें उकरा दिया।

कांग्रेस कार्यसमितिने ३१ जनवरीको परिस्थितिका सिंहावलोकन करते हुए सार्व-जिनक सिंवनय अवज्ञा आन्दोलनको गुजरातके बारदोली तालुकेमें सीमित करनेका फैसला किया, क्योंकि वहाँ दक्षिण अफ्रोकाके सत्याग्रहके बहुतसे अनुभवी लोग भौजूद थे। २९ जनवरीको विहलमाई पटेलके सभापितत्वमें एक तालुका सम्मेलन हुआ जिसमें आन्दोलनके लिए तैयारी प्रकट की गयी। देशभरमें कहीं और करवन्दी आन्दोलन चलानेकी इजाजत नहीं

दो गयी थी । गान्धीजीको यह अधिकार प्राप्त था कि वे ठीक समझें तो किसी इलाकेमें असहयोग या करवन्दी सार्वजनिक आन्दोलनके रूपमें ग्रुरू करनेकी इजाजत दे सकते हैं। गान्धीजीने वाइसरायसे देशके लिए न्याय माँगनेकी एक और कोशिश की। १ फरवरीको उन्होंने वाइसरायको पत्र लिखा जिसमें "सम्पत्ति लूटने, निरीह व्यक्तियोंपर हमला करने, जेलमें कैदियोंके साथ पाशविक व्यवहार करने, कोड़े मारने" आदिमें प्रकट सरकारी दमनको शिकायत करते हुए कहा गया था "इस अन्यायपूर्ण दमनने (जो एक तरहसे इस अभागे देशके इतिहासमें अमूतपूर्व है) सार्वजिनक अवशा आन्दोलन तत्काल प्रारम्भ कर देना एक अनिवार्य कर्त्तव्य बना दिया है। कांग्रेस कार्यसमितिने इसे उन क्षेत्रोंमें सीमित रखनेका फैसला किया है, जिन्हें मैं समय समयपर छाँटता रहूँ; अभी यह वारदोलीमें सीमित है। मैं इस अधिकारसे गुण्टूर (मद्रास) के १०० गाँवोंमें तत्काल आन्दोलनकी अनुमति दे सकता हूँ। यदि वे अहिंसा, विभिन्न वर्गींकी एकता, हाथके वने खहरके उत्पादन और अस्पृश्यता-निवारणकी शतें पक्की तौरपर पूरी कर सकें।" गान्धीजीने एक दूसरे रास्तेका सुझाव रखते हुए अनुरोध किया—''लेकिन वारदोलीकी जनतासे आन्दोलन शुरू करनेके लिए कहनेके पहले में विनयपूर्वक आपसे—जो भारत-सरकारके सर्वोच अधिकारी हैं, अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अन्ततोगत्वा अपनी नीति वदल दें और अहिंसात्मक काररवाइयों के लिए दण्डित या विचाराधीन सभी असहयोग वन्दियोंको रिहा कर दें और देशमें अहिंसात्मक काररवाइयोंमें विलक्कल हस्तक्षेप न करनेकी नीतिकी घोषणा स्पष्ट शब्दोंमें कर दें —चाहे ये काररवाइयाँ खिलाफतके अन्यायके प्रतिकारके लिए हों, पंजाव हत्याकांडके लिए हों, स्वराज्यके लिए हों या किसी अन्य उद्देश्यसे हों, और चाहे वे भारतीय दण्डविधान, जान्ता फौजदारी या अन्य किसी दमनकारी कानूनकी धाराओं के अन्तर्गत मले ही आती हों; सिर्फ शर्त्त यह रहे कि यह काररवाई हर हालतमें शान्तिमय और अहिंसात्मक होगी। मैं आपसे यह भी अनुरोध कुरूँगा कि समाचार-पत्रोंपर लगे प्रशासकीय नियन्त्रण भी हटा लिये जाबँ और हालमें उनपर जो जन्तियों और जुर्मानोंके दण्ड हुए हैं वे वापस लिये जायँ। इस अनुरोध द्वारा मैं आपसे सिर्फ वही करनेके लिए कह रहा हूँ जो हर ऐसे देशमें होता है, जहाँ सम्य सरकार राज करती हैं।" अन्तमें गान्धीजीने लिखा-"'यदि इस पत्रके प्रकाशनके एक सप्ताहके भीतर आप आवस्यक घोषणा कर सकें तो मैं आन्दोलनके उग्र रूपको स्थगित करनेकी सलाह देनेको तैयार हूँ; फिर छूटे हुए वन्दी पूरी परिस्थितिपर नये ढंगसे सोच सकेंगे।"

वाइसरायका उत्तर पत्रोंमें प्रकाशित हुआ जिसमें सरकारी रवैयेको ठीक वताया गया था और गान्धीजीका अनुरोध अस्वीकार कर लिया गया था। गान्धीजी अव वारदोली कार्यकम पूरा करनेको स्वतन्त्र थे। पर ऐसा नहीं होना था। ५ फरवरीको चौरीचौरामें एक भीपण हत्याकाण्ड हो गया। चौरीचौरा गोरखपुर (संयुक्तप्रान्त) में एक गाँव है। वहाँके किसानोंने एक जुल्स निकाला था। जैसा कि उन दिनों हर जुल्सके साथ होता था, इस जुल्सपर गोली चलायी गयी। जुल्स मंग न हुआ। पुल्सिके कारत्स चुक गये। पुल्सिवाले थाने लौट गये। पर भीड़ने उनका पीछा किया, उन्हें थानेकी इमारतमें वन्द कर दिया और इमारतमें आग लगा दी। थानेमें २१ सिपाही और एक थानेदार था। वे सव भरम हो गये। इस घटनाने गान्धीजीको कँपा दिया। वे तो हर आन्दोलनकी पहली शर्च

शान्ति और अहिंसा मानते थे । उन्होंने वारदोली आन्दोलन स्थिमत करनेकी राय दी । १२ फरवरीको कांग्रेस कार्यकारिणोंने उनकी राय मान ली । कांग्रेसवनोंसे कहा गया कि वे गिरफ्तार होना और प्रतिवन्ध तोड़कर सभाएँ करना व खुल्स निकालना वन्द कर दें । इसकी जगह कांग्रेसके सदस्य बनाने, कताई-विनाई लोकप्रिय बनाने, राष्ट्रीय स्कूल स्थापित करने, पंचायतें स्थापित कर नशावन्दीका प्रचार करनेका काम ग्रुह्म हुआ । लेकिन २४ व २५ फरवरीको कांग्रेस महासमितिकी वैठक दिल्लोमें हुई जिसमें कार्यसमितिके प्रस्तावमें कुछ संशोधन हो गये । अब प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ विशेष कार्न्नोंके उल्लंबनके लिए विशेष जगहींपर विशिष्ट व्यक्तियोंको सविनय प्रतिरोध करनेकी अनुमति दे सकती थीं । विदेशो वस्त्रों और शरावकी दूकानोंपर शान्तिमय धरना देनेकी भी अनुमित दे दी गयी ।

लेकिन सार्वजिनक आन्दोलन न छेड़ने छे जिलमें कांग्रेस उच्च नेताओं में भी विस्मय और न्याकुलता आ गयी। मोतीलाल नेहरू और लाजपतराय जैसे लोगोंने गांधीजीको कोध-भरे पत्र लिखे। उनका तर्क था कि चौरीचौरा काण्ड दुर्भाग्यपूर्ण था, पर उससे कार्यक्रममें बाधा नहीं पड़ने देनी थी, उसे एक पृथक घटना मानकर आगे बढ़ना था। कांग्रेस महासमितिकी बैठकमें कुछ लोगोंने गांधीजीकी भर्त्सना करनेकी भी बात की। लेकिन कोध शान्त हो गया और गान्धीजीकी विजय हुई।

जैसा कि एण्ड्र जने लिखा, गान्धीजीने तो सत्याग्रह स्थागत कर अपनी महानताका परिचय दिया और स्थितिका साहससे सामना किया। सरकारने नीचे उतरकर आन्दोलनकी गड़- वड़ स्थितिका फायदा उठाकर ओछा और कायरतापूर्ण हमला कर दिया। १३ मार्चको गांधी जी गिरफ्तार कर लिये गये। "दुनियादारीके दृष्टिकोणसे यह क्टनीतिका अच्छा दाव था, पर इसमें पुरुपोचित शोंयंका नाम भी नहीं था।" गान्धीजीके सहयोगी शंकरलाल वेंकर भी उनके साथ गिरफ्तार किये गये थे। 'वंगइण्डिया' के तीन लेख गान्धीजी पर अभियोग लगानेके लिए छाँटे गये और उसमें यह दिखानेकी कोशिश की गयी कि गान्धीजी सरकारके प्रति अभक्ति फैला रहे थे। गान्धीजीने इस अपराधको स्वीकार किया।

अदालतके सामने गान्धीजीने एक लम्बा वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने वताया कि किस प्रकार वे १८९३ से ही त्रिटिश सक्ताकों सहयोग प्रदान करते रहे। उन्होंने कहा— १९१९ में अमृतसर कांग्रे सके समय मित्रोंकी चेतावनी और आशंकाक वावज्द में सरकारकों सहयोग देने और मांटेग् चेम्सफर्ड सुधार लाग् करनेके लिए लड़ता रहा। मुझे आशा थी कि प्रधान मन्त्री भारतीय मुसलमानोंको दिया गया अपना वचन पूरा करेंगे, पंजाबके घावपर मलहम लगावाने। में आशा करता था कि अपर्यात और असन्तोपजनक होते हुए भी ये सुधार भारतीय जीवनमें एक नयी आशाका सूत्रपात करेंगे। पर मेरी आशाएँ छिन्न-भिन्न हो गर्या। खिलाफत सम्बन्धी वादा पूरा नहीं होना था। पंजाबके हत्याकाण्डपर लोपापोती कर दी गयी और भारतकी अधभूखी जनता धीरे-धीरे निर्जीव होती जा रही है। वह नहीं जानती कि विदेशी शोपककी दलालीसे उसका गुजारा होता है, विदेशी शोपकका मुनाफा और दलाली जनताका खून चूसकर आती है। वह नहीं जानती कि कानूनके आधारपर वनी यह सरकार जनताके शोपणके लिए बनी है। कानूनी दाँव-पेंच और आँकड़ोंका जादू उन ककालोंका सबूत नहीं मिटा सकता जो देहातोंमें नंगी आँखसे देखे जा सकते हैं। मुझे कीई सन्देह नहीं

१. सी. एफ. एण्डू ज 'महात्मा गान्धीन आइंडिआन' पृष्ट २७९

है कि यदि ईश्वर है तो इग छैण्ड और भारतीय नगरवासियों, दोनोंको मानवताक विरुद्ध ऐसे अपराधके लिए जवाब देना पड़ेगा जिसका सम्भवतः इतिहासमें उदाहरण भी न मिलेगा। इस देशमें स्वयं कानृन भी विदेशी शोषककी सेवाके लिए बना है। पंजाब मार्शल लाके मामलोंकी मेरी निष्पक्ष जाँचने मुझे इस निष्कर्षपर पहुँचाया है कि कमसे कम ९५ फीसदी दण्ड बिलकुल गलत है। भारतमें राजनीतिक मुकदमोंका मेरा अनुभव मुझे बताता है कि १० मेंसे ९ मामलोंमें दिण्डत व्यक्ति निरीह होते हैं। उनका अपराध सिर्फ यही है कि वे अपने देशको प्रेम करते हैं। भारतीय अदालतोंमें १०० मेंसे ९९ मामलोंमें लंग्रेजोंके मुकाबलेमें भारतीयोंको न्याय नहीं मिलता। इसमें अतिश्वयोक्ति या अतिरंजना नहीं है। यह उस हर भारतीयका अनुभव है जो ऐसे मामलोंसे सम्बन्धित रहा है। मेरा मत है कि इस प्रकार जाने या अनजाने शोषकके हितमें यहाँ न्यायके साथ बलात्कार होता है।

"सवसे वड़े दुर्भाग्यकी वात यह है कि अंग्रेज और उनके साथी भारतीय यही नहीं जानते कि ने यह अपराध कर रहे हैं, जो मैंने ऊपर वताया है। मैं जानता हूँ कि बहुतसे अंग्रेज और भारतीय अफसर ईमानदारीसे यह समझते हैं कि वे दुनियाकी सबसे अच्छी न्याय प्रणाली व्यवहारमें ला रहे हैं और भारत धीरे-धीरे पर निश्चित रूपसे प्रगति-पथपर अग्रसर हो रहा है। वे नहीं जानते कि एक ओर आतंक फैलानेके सूक्ष्म किन्तु प्रभावकारी उपाय और शक्तिका संघटित प्रदर्शन और दूसरी ओर रक्षा अथवा प्रत्याक्रमणकी शक्तिका अप-हरण—दोनोंने मिलकर जनताको निर्जीव कर दिया है और उसने उस व्यवहार-प्रणालीको प्रोत्साहित किया है जिससे शासकों के अज्ञान और कपटको बढ़ावा मिला है। नागरिकों की स्वतन्त्रता छीननेकी जितनी धाराएँ हैं, भारतीय दण्ड विधानकी धारा १२४-अ उन सवकी सिरताज है; मुझे इसी धाराके अन्तर्गत अभियुक्त वननेका सौभाग्य प्राप्त है। सरकारके प्रति भक्ति अथवा निष्ठा कानूनसे उत्पन्न या नियन्त्रित नहीं होती। यदि किसी व्यक्तिको किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तुसे प्रेम नहीं है तो जवतक वह हिंसाको वढ़ावा नहीं देता, उसे अपने इस वैरको व्यक्त करनेका पूर्ण अवसर मिलना चाहिये। लेकिन जिस घाराके अन्तर्गत मुझपर व श्रीशंकरलाल वेंकरपर मुकदमा चल रहा है, उसमें सरकारसे वैर प्रकट करना ही अपराध है। मैं किसी एक हाकिमके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता, शाहके प्रति दुर्भावना या वैरकी भावनाका प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन ऐसी सरकारके प्रति निष्ठाहीनताकी भावना रखना में एक गुण मानता हूँ, जिसने अन्य किसी प्रणालीसे अधिक हानि भारतको पहुँचायी है। भारतमें ब्रिटिश राजमें जो पुरुषत्वहीनता उत्पन्न हुई है, वह पहले कभी नहीं थी। ऐसा विश्वास होने पर इस सरकार या शासन-प्रणालीके प्रति सद्भावना या निष्ठा रखना पाप है।

''वास्तवमें, मेरा विश्वास तो यह है कि ज़िस अप्राक्तिक हंगसे भारत और ब्रिटेन रह रहे हैं, असहयोग द्वारा उससे बचनेका उपाय बताकर मैंने दोनों देशोंकी सेवा की है। मेरे तुच्छ मतमें बुराईसे असहयोग करना उतना बड़ा कर्त्तहर्य है जितना अच्छाईसे सहयोग करना। अभीतक बुराई करनेवालेका हिंसात्मक विरोध असहयोगका विशिष्ट अंग रहा है। में अपने देश-वासियोंको यह समझानेका प्रयत्न कर रहा हूँ कि हिंसात्मक असहयोग बुराईको बढ़ाता है और चूँकि बुराई हिंसापर पलती है, बुराईसे असहयोगमें हिंसाका नितान्त अभाव आवश्यक है। अहिंसामें बुराईसे असहयोगके दण्डको स्वेच्छासे स्वीकार करना निहित है। इसलिए में उस कार्यके लिए अधिकतम दण्डकी प्रसन्नता-पूर्वक कामना करता हूँ जो

कान्तकी दृष्टिमें अपराध है और मेरी दृष्टिमें किसी भी नागरिकका परम कर्त्तव्य है। जज और असेसरो—आपके सामने दो मार्ग हैं; यदि आप समझते हैं कि जिस कान्तको आप लागू करते हैं वह बुरा है और वास्तवमें में निरपराध हूँ तो आप अपने पदोंसे इस्तीफा देकर इस बुराईसे असहयोग करें; यदि आप समझते हैं कि जिस शासन-प्रणाली व न्याय प्रशासनमें आप सहायक वन रहे हैं वह इस देशकी जनताकी मलाईके लिए है और इसलिए मेरा कार्य जनहितको आधात पहुँचानेवाला है तो आप मुझे अधिकतम दण्ड दें।"

लेकिन जजने अपना विचार गान्धीजीकी 'अपराध स्वीकृति' तक सीमित रखते हुए उन्हें छः वर्षकी कैंदकी सजा दी और कहा कि ऐसे ही अभियोगमें तिलकको भी इतना ही दण्ड मिला था। यह समझ कर कि वे गिरपतार कर लिये जायँगे, गान्धीजीने एक लेख हारा लोगोंको सलाह दी थी कि ''मेरी गिरपतारी और सजा पर हड़ताल, जुल्ल या प्रदर्शन न हो।'' इसलिए उनकी सजाकी खबर गम्मीर शान्तिसे सुनी गयी।

कांग्रेस महासमितिकी बैठक ७, ८ व ९ जूनको रुखनऊमें हुई । विचाराधीन प्रश्न था कि 'क्या सविनय अवज्ञा किसी रूपमें चलायी जाय या इसी किस्मका कोई और कदम उठाया जाय । मोतीलाल नेहरू, डाक्टर अंसारी, विट्ठलमाई पटेल, जमनालाल बजाज, राजगोपालाचारी और कस्त्री रंगा आयंगारकी एक समिति प्रश्नपर विचार करनेके लिए बनायी गयी । अध्यक्ष हकीम अजमल खाँ, इस समितिके भी अध्यक्ष थे । अपने सुझानोंके लिए तथ्य संग्रह करनेके लिए समितिने देशका दौरा किया । गुल्ट्र रेलवे स्टेशनपर समितिके सदस्योंका स्वागत करनेके लिए लगभग दो सौ स्वयंसेवक एकत्र थे । पुल्सिने उन्हें हिरासतमें ले लिया । समितिने सुझाव दिया कि आंग्र प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीको 'अपनी जिम्मेदारी पर सीमित सत्याग्रह करनेकी अनुमित दी जाय' । समितिने नयी विधायिका कोंसिलोंमें जानेके प्रश्नपर भी विचार किया, पर इस संबन्धमें मतभेद हो गया । अजमल खाँ, नेहरू व पटेल कोंसिल प्रवेशके पक्षमें थे ताकि कोंसिलको अप्रभावकारी बनाया जा सके; अंसारी, राज-गोपालाचारी व आयंगार कोंसिलोंके वहिष्कारको कायम रखनेके पक्षमें थे ।

समितिके सीमित सत्याग्रह और विधायिका सभाओं के वहिष्कारके सुझावोंको महा-समिति और वाद्में दिसम्बर्में गयामें होनेवाले वार्षिक अधिवेशनने स्वीकार कर लिया। खिलाफत कमेटी भी कौंसिलोंके वहिष्कारके अपने निर्णयपर दृढ़ रही।

अध्याय १९

स्वराज्य पार्टी

कांग्रेसके गया अधिवेशनकी अध्यक्षता चित्तरंजन दासने की। राष्ट्रपति अपनी जेवमें भाषणके साथ-साथ अपना त्यागपत्र भी रख ले गये थे क्योंकि वे परिषदों से सम्मिल्ति होनेके कार्यक्रमके पक्षमें थे। उन्होंने कहा कि "में परिषदों के वहिष्कारके विरुद्ध नहीं हूँ। मेरी तो बस यही राय है कि सुधार-प्राप्त परिषदें तथा उनकी संगिनी इस्पात-जैसी कड़ी भार तीय सिवल सर्विस भारतीय राष्ट्रके स्वभाव और परम्पराके प्रतिकृत हैं। यह कांग्रेसका कर्तव्य है कि परिषदों में शामिल होकर उनका अन्दरसे ज्यादा प्रभावशाली वहिष्कार करें।" चूँकि कांग्रेसमें परिषदों में सम्मिल्ति होनेका प्रस्ताव १७४० वोटों के विरुद्ध ८९० वोटों से गिर गया इसलिए चित्तरंजन दासने अध्यक्षपदि त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेसके अन्दर स्वराज्य पार्टो स्थापित कर ली। उनका उद्देश्य वैधानिक स्तरपर संघर्षको विधायिका समाओं में आगे बढ़ाना था। इस कार्यक्रमसे असहमत लोगोंका नाम 'अपरिवर्तनशील' रख दिया गया। राजगोपालाचारी इनके नेता थे। इन लोगोंने अपने आपको, सूत कातने, नशावन्दी, अछूतोद्धार और दूसरे सामाजिक सुधारोंके रचनात्मक कार्योंमें लगा दिया। यह साफ तौरपर फुट थी परन्तु दोनों पक्षोंकी सद्भावनासे यह प्रत्यक्ष होनेसे बचा ली गयी।

१९२३ के आरम्भमें कांग्रेस दो दलों में बँट गयी। प्रत्येक दल नीचेके साधारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने अपने कार्यक्रमों का समर्थक बनाना चाहता था। स्वराजियों के लिये जिनकी अन्तमें विजय हुई, परिषदों में सम्मिलित होना कांग्रेस कार्यों में सबसे मुख्य था परन्तु अपरिवर्तनशी लेंके लिए, अभी भी सिवनय अवज्ञा और रचनात्मक काम मुख्य थे। नागपुरमें सिवनय अवज्ञा उद्देलनका एक अवसर आया। वहाँ आरम्भ कर इसे अखिलमारतीय उद्देलनका स्वरूप दे दिया गया। पहली मईको कुछ स्थानीय नेता राष्ट्रीय झण्डेको जुल्लमें लिये जा रहें थे कि उनको पुलिसने मिजस्ट्रेटकी आज्ञासे रोक दिया। नेताओंने मैजिस्ट्रेटकी आज्ञाका उल्लंघन किया और फिर तो जुल्लम, आज्ञा-उल्लंघन और गिरफ्तारियाँ दैनिक काम बन गयीं। जब नागपुरके कांग्रेसी कार्यकर्ताओंकी संख्या क्षीण होने लगी तो संघर्ष चलानेके लिए दूसरी जगहोंसे स्वयंसेवकोंके जत्थे आये। आन्दोलनपर कांग्रेस कार्यसमिति और अखिल भारतीय महासमितिने स्वीकृतिकी मुहर लगा दी। नागपुर-झण्डा सत्याग्रह चलानेके लिए एक कमेटी बना दी गयी जिसने अगस्ततक सत्याग्रह चलानेके लिए एक कमेटी बना दी गयी जिसने अगस्ततक सत्याग्रह चलाया। अगस्तमें सत्याग्रह वापस ले लिया गया क्योंकि कांग्रेस जुल्ल निकालनेका अधिकार स्थापित करनेमें अंदातः सफल हो गयी थी। वल्लममाई पटेल सत्याग्रहके, आखिरी दौरमें, नेता नियुक्त किये गये थे।

दूसरी तरफ स्वराजी छोग भी परिषदों में सम्मिलित होनेके कार्यक्रमपर समर्थन प्राप्त कर रहे थे। वे अखिल भारतीय कांग्रेस महासमितिको, जिसकी मईके अन्तिम सप्ताहमें वम्वई-में वैठक हुई थी, यह समझानेमें सफल हो गये कि महासमिति एक प्रस्ताव द्वारा, परिपद- वहिष्कारके प्रस्तावका मतदाताओंमें प्रचार करनेका निषेध कर दे। 'अपरिवर्तनशीलें' ने इस प्रस्तावको गया कांग्रेसकै प्रस्तावका उल्लंघन माना और कांग्रेस कार्य-समितिसे उनके नेताओंने त्यागपत्र दे दिये । त्यागपत्र देनेवालोंमें राजगोपालाचारी, वल्लभभाई पटेल, राजेन्द्र प्रसाद, वृजिक्दिशोरप्रसाद, जी. वी. देशपाण्डे और जमनालाल वजाज थे । ये त्यागपत्र और दासका त्यागपत्र, जो अभीतक रोक लिया गया था, स्वीकार कर लिये गये। सितम्बर-तक विचारधारा पूर्णतया स्वराजियोंके पक्षमें हो गयी। स्वराजी, दिल्लीमें मीलाना अवुल कलाम आजादकी अध्यक्षतामें एक विशेष अधिवेशन बुलवाकर गयाके प्रस्तावमें परिवर्तन कर उसको परिपदोंमें सम्मिललित होनेके पक्षमें पास करवानेमें सफल हो गये। जब मुहम्मद अलीने परिपदोंमें सम्मिलित होनेके पक्षमें भाषण करते हुए कहा कि मुझे विस्वत्त स्वते पता चला है कि गान्धीजी भी परिपदमें समिलित होनेका विरोध नहीं करेंगे तो सफलताका भरोसा हो गया । इस संकेतका आधार, गान्धीजीका जेलसे अपने पुत्र देवदास गान्धी द्वारा भेजा हुआ सन्देश था। उन्होंने कहा था कि "मैं आपको कोई सन्देश नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि में बन्दीगृहमें हूँ। जेलसे लोगोंके सन्देश मेजनेको मेने सदैव ही गलत समझा है। लेकिन में कह सकता हुँ कि आपकी भक्तिने मुझे अभिभृत कर लिया है। मैं आपसे कहँ गा कि मेरे प्रति भक्तिसे अधिक आप देशके प्रति भक्तिको प्रश्रय दें। मेरे विचार सव लोग अच्छी तरह जानते हैं। जेल जानेसे पूर्व मैंने अपने विचार लोगोंपर व्यक्त कर दिये थे और उनमें तबसे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलता हूँ कि यदि आप-का और मेरा मतभेद भी हो तो उसके कारण हमारे आपसके अच्छे सम्बन्धींपर जरा भी असर नहीं पड़ेगा।" इस सन्देशसे मुहम्मद्अलीने जो निष्कर्प निकाला वह यद्यपि उचित नहीं कहा जा सकता, परन्तु उनके इन शन्दोंसे बहुतसे अनिश्चित-मत प्रतिनिधि उनके पक्षमें आ गये। काफी गरम वह एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कहा गया था कि यदि कांग्रेस-जन चाहें तो व्यक्तिगत तौरपर परिपदोंके लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। परन्तु वातावरण पूर्णतया अमीतक स्वराजियोंके अनुकूछ नहीं हुआ था, इसलिए वे इसके लिए सहमत हो गये कि चुनाव जीतनेके लिए वे कांग्रे स-प्रभावका उपयोग नहीं करेंगे । स्वराजियोंने चुनावके लिए एक निपुण और कुशल संवटन स्थापित कर लिया। धन इकट्टा किया और वड़ी संख्यामं कार्यकर्त्ता तैयार कर लिये । प्रस्तायका जो भी आशय रहा हो, स्वराजी गान्धीजीके आदमी समझे जाने लगे। इन लोगोंने परिपदोंमें अन्दरसे गतिरोध पैदा करने और कार्य न करने देनेका काम अपने जिम्मे लिया, परन्त व्यावहारिक रूपमें यह योजना असम्भव सिद्ध हुई।

१९२३ के चुनाव मुख्यतया उदारदलीय और स्वराज्य पार्टीने लड़े। अधिकांशतः उदारदलीय लोग परिपदोंके भृतपूर्व सदस्य थे। "चुनाव आन्दोलनमें उदारदलीय लोगोंको बहुत वड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं। अपने कार्यकालमें वे सही मानोंमें एक विरोधी दलके रूपमें काम करनेमें असमर्थ रहे। परिणामस्वरूप उनका संवटन और एकता दोनों ही टूटने लगे थे। उनके सुधारयुक्त प्रथम परिपद्के अन्दर काम करनेमें सिद्धान्त नहीं, विल्क व्यक्तिगत प्रस्न अधिक मुख्य रहे। इससे भी बुरी बात यह हुई कि उदारदलीय लोगोंका भारतीय राजनीतिकी मुख्य विचारधारासे कोई सम्पर्क नहीं रहा और वे विलक्षल अलगावमें पड़कर काम करते रहे। उन्होंने ऐसे समय विधान-परिपद्में समिलित होना स्वीकार किया था जब कि

'आत्म-विह्नदान' लोगोंका 'तिकयाकलाम बन गया था। ' ' ं लोगोंने उनको सरकारका हिमायती कहना ग्रुल कर दिया। यद्यपि वे परिषदोंके सदस्य थे परन्तु उनका अपने निर्वाचन- क्षेत्रके लोगोंसे विशेष सम्पर्क न था। बहुत से भूतपूर्व सदस्योंका भाषणतक सुननेसे लोग इनकार करते थे। इस हतोत्साह स्थितिमें अपनी आपसकी फूट और अस्तव्यस्त पार्टी संघटनके कारण अपनेसे अधिक अनुशासित प्रतिद्वन्दियोंसे उदारदलीय हार गये।"

फिर भी परिषदों में स्वराज्य पार्टीको कोई व्यावहारिक बहुमत न प्राप्त हो सका क्यों कि अपने स्थानीय प्रभावके कारण कई क्षेत्रों से स्वतन्त्र उम्मीद्वार निर्वाचित हो गये थे। "परिणामस्वरुप केवल मध्य प्रदेशकी विधान परिषद में स्वराज्य पार्टीको साफ तौरपर बहुमत प्राप्त हो सका। वंगालमें यद्यपि एक दलकी हैिस्यतसे स्वराज्यपार्टी सबसे बड़ी थी, लेकिन संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाये विना उस दलके लोग अपनी हुकूमत न बना सकते थे। वम्बई और यू. पी. में यद्यपि वे काफी संख्यामें विजयो हुए थे, फिर भी उन्हें परिषदों में बहुमत न प्राप्त हो सका। मद्रास, पंजाब, विहार और उड़ीसामें वे कमजोर थे। केन्द्रीय विधान परिषद में, जहाँ उन्होंने विशेष तौरपर चुनावके लिए ताकत लगायी थी वे निर्वाचित सीटोंकी आधी संख्या भी जीतने में असमर्थ रहे। इन सब वातों के वावजूद वे चुनावों के परिणामों से सन्तुष्ट थे, क्यों कि उन्होंने भारतीय बुद्धिजीवी वर्गके प्रवक्ता परसे उदारदलको हटा दिया था।"

दिसम्बरमें मुहम्मद अलीकी अध्यक्षतामें कोकोनाडामें कांग्रेसका वार्षिक अधिवेशन हुआ । उनका भाषण सर सैयद अहमद खाँके समयसे अवतकको मुस्लिम राजनीतका विश्ले-षण था। उन्होंने अपने विचारोंकों छिपाया नहीं, हार्लोक उनके विचार कांग्रेस विचारोंके प्रतिकूल थे । उन्होंने कहा कि 'पृथक निर्वाचन प्रणालीने' साम्प्रदायिक झगड़ोंको रोकनेके लिए बहुत कुछ किया है।" फिर भी उन्होंने स्वीकार किया में यह वात भूल नहीं जाता हूँ कि ''जब हिन्दू और मुसिलम समाजोंमें ईर्घ्या और भेद भाव बहुत बड़े चदे ही तो पृथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा ऐसे ही लोग चुने जायँगे जो विरोधी समाजके प्रतिस्थिपने कटु और उग्र विचारोंके लिए मशहूर हों।'' पृथक निर्वाचनके लिए उनका तर्क था कि ''संयुक्तनिर्वाचन साम्प्रदायिक झगड़ोंकी सबसे बड़ी जड़ है। इनके द्वारा दोनों समाजोंके वीचकी भेदभावकी खाई और बढ़ेगी । हर उग्मीदवार चुनावमें वोटोंके लिए अपने-अपने समाजोंसे अपील करेगा और दिरोधी समाजके प्रति अपनी कटुताके वलपर वोटोंके लिए अपना दावा सिद्ध करनेकी चेष्टा करेगा, फिर चाहे कितना ही लुका-छिपाकर, किसी सिद्धान्त, उदाहरणार्थ अपने समाजके हितोंकी रक्षाकी ओटमें यह दावा क्यों न किया जाय।" इसके बाद राष्ट्रपतिने एक-एककर वे परिस्थितियाँ गिनायीं जिनके कारण मुसलमान अंग्रे जोंसे नाराज हो गये थे। वंग भंगका रद किया जाना इन कारणोंमेंसे एक था, इसके बारेमें उन्होंने कहा "निस्सन्देह में कहता हूँ कि वंगालके विभाजनसे, यद्यपि यह नितान्त ही अनुचित था और लार्ड कर्जनने वंग-भंग वदलेकी भावनासे किया था, किसी हदतक मुसलमानोंका भला हुआ था। लेकिन फिर भी जव परिस्थिति सरकारके कावूके वाहर होने लगो तो उसने मुसलमानोंको 'गरम आल्,' की तरह छोड़ दिया। भारतके राजनीतिक इतिहासमें इतना नीच विस्वासघात दूसरा नहीं है। अपने पड़ोसियोंके खिलाफ पूर्वी वंगालके

१. इण्डिया इन १९२४-२५, पृष्ठ २९६-२९७

२. वही पुस्तक पृष्ठ २९८

मुसलमानोंने अपने शासकोंकी तरफसे लड़ाई लड़ी और जब शासकवर्गने देखा कि लड़ाई चलाना उसके हितमें नहीं है तो उसने फौरन ही सुलह कर ली और मुसलमानोंको उन लोगोंकी द्यापर छोड़ दिया जिनके खिलाफ सरकारने मुसलमानोंको मददगार फौजकी तरह इस्तेमाल किया था।" उन्होंने मुसलमानोंसे कहा कि "न्या हम विदेशी शासकोंसे सहयोग करेंगे और गैर-मुस्लिम देशवासियोंसे उसी प्रकार लड़ेंगे जिस तरहसे हम पहले लड़ते थे?"

यद्यपि कांग्रेसके रोजमर्राके कामोंमें अब सत्याग्रहकी अपेक्षा परिपदोंमें कामपर अधिक जोर दिया जा रहा था, फिर भी कांग्रेस 'सविनय अवज्ञा'पर जमी रही। मुख्य प्रस्तावमें कांग्रेसने प्रान्तीय कमेटियोंको हिदायत दी कि वे 'सविनय अवज्ञा'की तैयारी करें और 'ध्येयको जल्दी ही प्राप्त करनेकें लिए इस दिशामें फौरन कदम उठावें।''

५ फरवरी १९२४ को गान्धीजी शोचनीय स्वास्थ्यके कारण जेलसे अवधि पृरी होनेसे पहले ही छोड़ दिये गये। जेल-अधिकारियोंकी संरक्षतामें १२ जनवरीको सस्त अस्पताल प्नामें गान्धीजीके पेटमें अपेण्डीसाइट्रिसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशनके मध्यमें विजलीकी वत्ती खराव हो गयी और शेप ऑपरेशन कियाएँ गैसकी लालटेनकी रोशनीमें समाप्त की गयीं। दिहा होनेके वाद गान्धोजी स्वास्थ्य सम्भालनेके लिए समुद्रके किनारे वम्बई (जुह) चले गये; जहाँ कुछ ही समय बाद उनके आसपास स्वराजी व दसरे कांग्रेस नेता इकट्ठे हो गये। स्वराज पार्टांके नेताओं और गान्धीजीके वीच लम्बी लम्बी वहसं हुई और जब दोनोंमेंसे एक भी दूसरेको अपना दृष्टिकोण समझानेमें असमर्थ रहा तो दोनींने अपने अपने दृष्टिकोण अखवारींके जरिये जनताके सामने रखे। गान्धीजीने कहा ''हमारे बीचमें वास्तविक और मोलिक अन्तर हैं। मेरी अब भी यही राय है कि परिपदींमें सम्मिलित होना और असहयोग जैसा कि में समझता हूँ दोनों एक साथ नहीं चल सकते और परस्पर विरोधी हैं। देशके हितके लिए परिपदोंमें सम्मिलित होनेसें वाहर रहना अधिक अच्छा है। हालाँकि में अपने स्वराजी मित्रोंको अपनी वात स्वीकार करवानेमें असमर्थ रहा हुँ, फिर भी में यह समझता हुँ कि जवतक वे अपना दृष्टिकोण न वदलें उनकी जगह निस्स-न्देह परिपदोंके अन्दर है। यही हम सब लोगोंके लिए अच्छा है।" परन्तु चूँकि कांग्रेसने स्वराजियोंको परिपदोंमें काम करनेकी अनुमति दे दी थी इसलिए गान्धीजीने कहा कि "में स्वराजियोंके मार्गमें अवरोध अथवा उनके खिलाफ प्रचारमें भाग नहीं ले सकता यद्यि में ऐसी योजनाकी सकिय सहायता नहीं कर सकता जिसमें मुझे स्वयं विश्वास नहीं है। " परन्त उन्होंने इशरा किया कि यदि मैं परिपदोंमें सम्मिल्त हुआ तो गतिरोधकी नीति नहीं विक कांग्रेसके रचनात्मक कार्यक्रमको वल प्रदान करनेका प्रयत्न करूँगा। इसलिए में प्रस्ताव पेश करूँगा कि केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें (१) अपनी जरूरतोंके लिए कुल कपड़ा हाथसे कता और बुना खहर हैं। (२) विदेशी कपड़ोंपर भारी आयात कर लगावें (जिससे विदेशी। कपड़ा आना वन्द हो जाये।) (३) नशीली चीजोंकी आमदनी खत्म कर दी जाये और कमसे कम उसी अनुपातमें फौजी खर्चेमें कमी की जाये । अगर विधान परिपदोंमें स्वीकार हो जानेके वाद भी सरकार इन्हें लागू न करे तो में विधान परिपदोंको भंग करनेकी माँग करूँगा और इन्हीं वार्तोपर जनताका वोट माँगूँगा और अगर सरकार परिपदोंको भंग न करें तो मैं अपनी सदस्यतासे त्यागपत्र दे दूँगा और देशको 'सविनय अवरा' के लिए तैयार करूँगा । जन ऐसी अनस्या आ जायगी तो स्वराजी मुझे अपने नीचे काम करनेको तत्पर पार्चेंगे ।" स्वराजी नेता चित्तरं जनदास और मोतीलाल नेहरूने अपने वयानों में कहा कि परिपदों में समिलित होने और असहयोग में कोई परस्पर-विरोध नहीं है । वे 'अवरोध' की जो परिभाषा पेश करते हैं उससे उनके परिषदों के अन्दरके कामको समझने में मदद मिलती है । ''हमारी स्थिति'' उन्होंने कहा ''वैधानिक स्तरपर उतना अवरोध खड़ा करनेकी नहीं है जितना कि नौकरशाही सरकार द्वारा हमारे स्वराज-प्राप्तिक रास्तेमें अवरोध खड़ा करनेकी खिलाफ संघर्ष है, तो जब हम 'अवरोध' का नाम छेते हैं, दरअसल हमारा आशय इस संघर्ष से होता है ।'' उन्होंने अपने सहयोगके स्तरकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ''कैन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिषदों में जो भी जगह निर्वाचनसे मिले हमें इसे छेनेकी कोशिश करनी चाहिये । हमारी समझमें हमें न सिर्फ हर निर्वाचित जगह पर कब्जा करना चाहिये बिक्क हर उस कमेटी में भी काम करना चाहिये जिसमें हमें जगह मिल सके । छेकिन स्वराजियोंने गान्धीजीसे वादा किया कि जिस क्षण नौकरशाहीके स्वायी हठका, सविनय अवशिक्ष अलावा, कोई जवाव न होगा वे विधान परिषदोंसे अलग हो जावाँ ।

अव स्वराजी और अपरिवर्तनशीलों में कांग्रे सपर कब्जा करनेकी होड़ लगी। जूनके अन्तमें होनेवाली अखिल भारतीय कांग्रेस महासमितिमें अपरिवर्तनशीलों की जीत हुई, क्यों कि उन्होंने गान्धीजी के कहनेपर एक प्रस्ताव पास करा लिया था कि कांग्रेस संघटनों में निर्वाचित प्रत्येक व्यक्ति प्रतिमाह हाथका कता हुआ दो हजार गज सूत भेजेगा। लेकिन नवम्बरमें हुई महासमितिकी अगली मीटिंगमें स्वराजियों के अनुयायी अपरिवर्तनशीलों कहीं ज्यादा थे और गान्धीजीने दास और मोतीलाल नेहरू के सामने समर्पण कर दिया। उनके और गान्धीजीक संयुक्त हस्ताक्षरों से एक वक्तव्य असहयोगको बन्द करते हुए और स्वराज पार्टीको परिषदों में काम करनेकी पूरी आजादी देते हुए दिया गया। स्वराजियोंने कांग्रे सजनों के वहुमतको इस प्रकार अपने पक्षमें कर लिया कि इस प्रस्तावको कांग्रे सके वार्षिक अधिवेशनमें भी स्वीकार करा लिया हालाँ कि गान्धीजी स्वयं अधिवेशनकी अध्यक्षता कर रहें थे।

मध्यप्रान्त (मध्य प्रदेश) की विधानपरिषदमें स्वराज पार्टीको पूर्ण बहुमत प्राप्त था और उसने देंध शासनको असम्भव-सा बना दिया। अपनी नीतिके अनुसार स्वराजियोंने हस्तान्तरित विषयोंका उत्तरदायित्व लेना अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण उन विषयोंके लिए मन्त्री दूसरी पार्टियोंके लोग बनाये गये। अपनी घोषित नीतिके अनुसार विधान तोड़नेके लिए स्वराज पार्टीने मन्त्रिमण्डलके खिलाफ अविश्वासका प्रस्ताव पास कर दिया। जब वजट पेश किया गया तो स्वराज पार्टीने हस्तान्त्रित विषयोंकी सब माँगे अस्वीकार कर दीं। आवश्यक व्ययोंके लिए गवर्नरकों अपने विशेष अधिकारोंके अन्तर्गत अनुमित देनी पड़ी। परन्तु मिन्त्रियोंके स्थान रिक्त रहे। यह दशा १९२४ तक कायम रही। १९२४ में स्वराजियोंने अपना विरोध थोड़ा-सा कम कर लिया और आमतौरपर खर्चोंकी माँगे स्वीकार कर ली गयी परन्तु मिन्त्रियोंका वेतन घटाकर रे) सालाना कर दिया गया। वंगालमें स्वराजियोंने कुछ स्वतन्त्र सदस्योंसे, मुख्यतया मुसल्मानोंसे मिलकर, बहुमत बनाया और सरकारको तरफसे पेश किये गये प्रस्तावोंको अस्वीकार कर दिया। द्वैध शासनको टूटनेका खतरा पैदा हो गया। १९२४ के आरम्भमें, स्वराजी व स्वतन्त्र सदस्योंने संयुक्त होकर वंगाल सरकारको तीन वार हराया और मन्त्रियोंको तनक्वाहें देनेसे इनकार कर दिया। इन लोगों द्वारा पेश

किये गये प्रस्तावोंमें, १८१८ के विनियमन तीनके अन्तर्गत नृजरवन्द किये गये सभी नजर-वन्दोंकी तथा सभी राजनीतिक वन्दियोंकी रिहाईकी सिफारिश और दमनकारी कान्नोंके रद किये जानेकी माँग थी। लेकिन परिषदकी इच्छाओंके वावजूद सरकारने इन प्रस्तावोंको लागू नहीं किया।

केन्द्रीय विधान सभामें, यद्यपि स्वराजपाटी सबसे वड़ी पार्टी थी, परन्तु भवनके १४५ सदस्यों इनके कुल ४५ सदस्य थे। इन्होंने दूसरे लोगोंसे मिलकर 'समान मोर्चा' वनाया और ७० आदिमियोंको अपने साथ मिला लिया जो इस वातपर सहमत थे कि यदि सरकार, इन लोगोंकी वैधानिक प्रगतिकी माँगके प्रस्तावका सन्तोपजनक उत्तर न दे तो इस संयुक्त दल द्वारा जो बादमें राष्ट्रीय पार्टीके नामसे प्रसिद्ध हो गया, 'अवरोध'की नीति अखित्यार की जाये।

स्वराज पाटोंने १९९९ के ऐक्टको रद करनेके लिए अडंगा डालने की अपनी नीति छोड़ दी और विधान सभामें कई विषयोंपर उन्होंने सरकारसे सहयोग किया। स्वराजी सदस्य स्थायी समिति व अन्य कमेटियोंमें सम्मिलित होने लगे और काररवाइयोंमें भाग होने हमे । भारतीय फीजी शिक्षण केन्द्र (इंडियन सैण्डरर्ट) खोहनेकी सम्भावनाओं पर गौर करनेके लिए बनी कमेटीकी सदस्यता मोतीलाल नेहरूने स्वीकार कर ली। इस सह-योगका पहला नतीजा एक प्रस्ताव था जिसमें एक गोलमेज कान्फ्रेंस की माँग की गयी थी जो पूर्ण जिम्मेदार हुकुमत स्थापित करनेकी योजनाकी सिफारिश करे। लगभग सभी निर्वाचित गैर सरकारी सदस्योंने इसके पक्षमें बोट दिया । भारत सरकारने इस माँगको सना-अनुसना कर दिया जिससे संयुक्त दल सरकारके विरुद्ध और भी कडु हो गया । जब वजट पेश किया गया तो राष्ट्रीय दलने अनुदानकी माँगकी पहली चार मदें अखीकार कर दीं । वित्तविधेयक पेश करनेकी आजा न देना इसीका अनुसरण था। इसके बाद सरकारकी हार पर हार हुई। परन्तु संयुक्त दलके कारण, जहाँ स्वराज पार्टीको सरकारको हरानेका अवसर मिला था वहीं उसे अपनी 'अवरोध'की नीतिमें समझौता भी करना पड़ा। स्वर्जपाटींने १९२४ में सरकार द्वारा प्रस्तावित इस्पात उद्योग विधेयकका समर्थन किया। इस समय गैर स्वराजी सदस्योंमें अपनेको 'रचनात्मक विरोधी दल'की हैसियतसे कायम करनेकी प्रवृति साफ दिखलाई दे रही थी। स्वराजियोंके नेतृत्वमें काम करनेवाले राष्ट्रीय दलसे कुछ स्वतन्त्र सदस्य अलग हो गये । उन्होंने मुहम्मदअली जिनाके नेतृत्वमें एक स्वतन्त्र दल स्थापित किया और अपने सचेतक नियुक्त कर लिये । सरकार अब भी निर्वाचित सदस्योंके संयुक्त बोटोंके कारण हारती थी परन्तु ये हारें 'अवरोध'की नीतिके अन्तर्गत कम, हर प्रस्तावकी अच्छाई और वराई पर अधिक होती थीं । फिर भी विधान परिपदमें सब सरकार-विरोधी तत्वोंकी प्रतीक 'राष्ट्रीय पार्टी'में फूट पड़नेकी सम्भावना पैदा हो गयी थी।

इसी वीच स्वराजियोंके सामने एक बार फिर सब राजनीतिक पार्टियोंको एक करनेका अवसर आया । अक्टूबरमें वंगालके गर्वनरने गर्वनर जनरलको सलाह दी कि वे वंगालमें आतंकवादियोंका, जिन्होंने एक बार फिर जोरींसे काम करना गुरू कर दिया था, दमन करनेके लिए वंगाल शासनको एक ऑडिनेन्स जारी करके असाधारण शक्ति दे दें। इस सलाहके ऊपर गवर्नर जनरलने २५ अक्टूबरको एक ऑडिनेंस जारी कर दिया जिसके द्वारा वंगाल शासनको यह अधिकार मिल गया कि विशेष कमिस्नर क्रान्तिकारी संघटनोंसे सम्बन्ध रखनेवाले

लोगोंको सरसरी तौरपर मुकदमा करके सजा दे दें। यह ऑर्डिनेंस फौरन ही लागू कर दिया गया और एकदमसे बड़ी संख्यामें लोग विना जाँचके गिरपतार किये जाने लगे। गिरपतार किये गये लोगोंमें कुछ वंगाल-स्वराज पार्टांके सदस्य थे, जिनमें कलकत्ता कॉरपोरेशनके एक्जीक्यूटिव ऑफीसर भी थे। राजनीतिक पार्टियों और भारतीय अखवारोंने एक खरसे इस दमनकारी कानूनकी निन्दा की। "ऐसे वहतसे विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकीणके लोग. जिनकी स्वराजियोंके उद्देवशें कोई भी सहानुभूति न थी इस समान खतरेके खिलाफ स्वराजियोंसे एकता वनानेको प्रस्तुत थे।......नव्यवरके आरम्भमें गान्धीजी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरूके इस्ताक्षरोंसे एक वक्तव्य जारी किया गया जिसमें इस नयी दमन-नीतिके विरुद्ध देशके विभिन्न राष्ट्रीय कार्यकर्ताओंको देशके हितमें एक हो जानेकी आवश्यकता समझायी गयी थी। इस वक्तव्यमें यह भी सिफारिश की गयी थी कि वेलग्राममें होनेवाली कांग्रेस विदेशी कपड़ेके इस्तेमालको छोड़कर बाकी असहयोगके कार्यक्रमको स्थगित कर दे और स्वराजियोंको कांग्रोस संघटनके अभिन्न हिस्सेकी हैसियतसे विधान-परिषदमें काम करनेके लिए अधिकृत करे।" गान्धीजीको अपना दृष्टिकोण मनवानेकी सफलतासे उत्साहित होकर स्वराजियोंने सर्व-दल-नेता सम्मेलन बुलाया ताकि कांग्रेस छोडकर चले जानेवालोंको पिर कांग्रे समें शामिल होनेको राजी किया जाये और कार्यक्रमकी एक समान योजना बनायी जा सके। उदारदलीय और स्वतन्त्र सदस्योंको यह आशा थी कि चूँकि असहयोग स्थगित कर दिया गया है इसीलिए कांग्रे समें शामिल होना उनके लिए सम्भव है। २१ नवम्बरको सर्व-दलीय नेता सम्मेलन वम्बईमें हुआ जिसने एक प्रस्ताव पास कर सरकारके इस ऑर्डिनंस जारी करनेकी निन्दा की। परन्तु यह सम्मेलन विभिन्न दलोंको कांग्रेसमें वापस लानेमें असमर्थ रहा। फिर भी तमाम राजनीतिक पार्टियोंको फिर एक करने और कांग्रेसमें मिलानेके लिए, साम्प्रदायिक मसलेको सुलझा कर स्वराज्यकी एक योजना बनानेके लिए एक कमेरी नियुक्त की गयी । यह कमेरी तमाम पार्टियोंको एक करनेमें असफल रही. और पार्टियाँ अलग-अलग कायम रहीं।

गान्धीजीने कांग्रेसके वार्षिक अधिवैद्यानके अध्यक्ष-पदसे सब राजनीतिक पार्टियोंको कांग्रे समें शामिल हो जानेकी दावत दी। १९२४ का अधिवेद्यान वेलगाँवमें हुआ। गान्धीजीने असहयोग आग्दोलन वंद करनेके बादकी देशकी दशा बतायी। उन्होंने कहा "लेकिन हम ऐसी हालतका सामना कर रहे हैं जो हमें रक जानेको मजबूर करती है क्योंकि जहाँ लोगोंको व्यक्तिगत तौरपर असहयोगमें दृढ़ विद्वास है वहीं जिन लोगोंका इससे करीवका सम्बन्ध है उनमेंसे अधिकांद्रातः लोगोंको विदेशी कपडेके विह्कारके अतिरिक्त इसमें कोई श्रद्धा नहीं रही है। वीसियों वकीलोंने अपनी वकालत फिर ग्रुक्त कर दी है। कुछको तो अब यह पछ तावा होता है कि उन्होंने वकालत छोड़ी ही क्यों थी? जिन लोगोंने परिषदोंका विद्यास करनेवालोंकी संख्या वढ़ रही है। सैकड़ों लड़के और लड़कियाँ, जो सरकारी स्कूलों और कॉलेजोंको छोड़ चुके थे, अब पछताते हैं बौर उनमें फिर पढ़नेको जा रहे हैं। मैंने सुना है कि स्कूल और कॉलेज इन सबको भरती करनेमें अपनेको असमर्थ पा रहे हैं। उस समयकी देशकी दशा स्पष्ट करनेके वाद, गान्धीजीने स्वीकार किया कि कांग्रेसमें स्वराजी दल अगर वहुमतमें नहीं है तो एक शक्तिशाली और उत्तरोत्तर शक्तिशाली होने

वाला अल्पमत हैं। गान्धीजीने आशा प्रकट की कि दूसरी पार्टियाँ कांग्रेसमें शामिल होंगी और राष्ट्रकी नीतिपर प्रभाव डालनेके लिए कांग्रेसके अन्दर काम करेंगी। गान्धीजीने स्त कातने, हिन्दू-मुस्लिम एकता, अल्तू-उद्धार और मद्यानिपेधके रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर दिया। उप्रवादियोंको निराशा हुई जब गान्धीजीने कहा कि "पूर्ण स्वराज्यसे अधिक वे 'औपनिवेशक स्वराज्य' को पसन्द करेंगे।" उन्होंने जोर देकर कहा "में साम्राज्यके अन्तर्गत स्वराज्य पानेकी चेष्टा करूँ गा परन्तु यदि ब्रिटेनकी अपनी गलतियोंके कारण आवश्यक हुआ तो इससे सब नाते तोड़नेमें हिचकूँगान्भी नहीं।" गान्धी-दास-नेहल वक्तव्य द्वारा प्रतिपादित नीतिको ही वेलगाँव कांग्रेसने चलाया।

१९२५ में कांग्रेसमें स्वराज पार्टी इतनी अधिक शक्तिशाली हो गयी कि गान्धीजी, मोतीलाल नेहरूके हायोंमें जो केन्द्रीय विधान समामें पार्टीके नेता थे, नेतृत्व सौंप देनेको प्रस्तुत हो गये। यद्यपि उस साल विधान परिपदोंमें पार्टीके अभी तकके अपने ही साथियोंके हाथ कई हारें हुई और वह साल बहुत राजनीतिक उतार-चढ़ावका बीता, फिर भी स्वराज पार्टीने वह साल सरकारको एक करारी हार देकर हो शुरू किया था। जनवरीमें वंगाल विधान परिपदने वंगाल आर्डिनेंस, जिसको अविध समात्रप्राय थी, को रद कर दिया। उस परिपदने कुछ अतिक्रमके वाद जिस बीचमें मन्त्रियोंके वेतनका उपवंध स्वीकार कर लिया था, बादमें वजट बहसके दौरानमें उसे अस्वीकार कर दिया। परन्तु परिपदमें पार्टियोंकी बदली हुई स्थितिके कारण, स्वराज पार्टीको हमेशा जीतको आशा नहीं रहती थी। वह परिपदके अध्यक्षके चुनावमें केवल छः वोटोंसे हार गयी। इसी प्रकार, केन्द्रीय विधान सभामें सरकार और स्वराजियोंके बीच संतुलन रखना राष्ट्रीय दलसे अलग होनेवालोंके हाथमें था।

इस बातके वावजूद कि गान्धीजी न सिर्फ कांग्रेसके नेता थे विक १९२५ में कांग्रेसके अध्यक्ष भी थे, स्वराजी नेता विना उनसे पूछे नीतिकी घोषणा कर देते। फरीदपुरमें हुए वंगाल प्रान्तीय कांग्रेस सम्मेलनमें श्रीदासने सरकारके सामने कुछ शतोंपर सहयोग करनेका प्रस्ताव रखा। वे यह समझते थे कि अब सरकारका हृदय-परिवर्तन हो गया है। गान्धीजीका उनसे मतभेद था। दासको कुछ अति आशावादके कारण भारत सचिव लार्ड वर्कनहेडपर विश्वास था और उन्हें आशा थी कि उनके भाषण (जिसकी भारतमें बहुत प्रतीक्षा की जा रही थी) के कारण १९१९ के ऐक्टसे अवश्य कुछ अधिक सुधारयुक्त प्रगति होगी। दासका दार्जिलिंग में १६ जून १९२५ को देहान्त हो गया। ७ जुलाईको लार्ड वर्कनहेडने एक लम्बा भाषण किया जिसमें वे माण्टेग् चेम्सफोर्ड सुधारोंसे एक इंच भी आगे नहीं वहे। यद्यपि इस भाषण- से स्वराजी और दूसरे राजनीतिक विचारोंके लोग निराश हो गये, परन्तु निरुत्साह नहीं हुए और वे अब लन्दनमें दिये जानेवा-डे लार्ड रीर्डिग्के भाषणको उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब रीर्डिग बोले तो उन्होंने सिर्फ वर्कनहेडके ही मधुर भावोंको दोहरा दिया। वंगालमें दास द्वारा अर्जित 'तीनों खितावों'—वंगाल स्वराज पार्टीके नेता, वंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष और कलकत्ता कॉरपोरेशनके मेयर—के उत्तराधिकारी अब उदीयमान नेता जे. एम. सेन गुप्ता हो गये।

कांग्रेष महासमितिमें स्वराजी ज्यों-ज्यों उत्तरोत्तर वहुमत प्राप्त करते जा रहे थे त्यों-त्यों गान्धीजी शीव्रतासे पृष्ठभूमिसे हटते जा रहे थे। जुलाईमें हुई अखिल भारतीय महासमितिके वाद गान्धीजीने मोतीलाल नेहरूको लिखा कि वे अव राष्ट्रपतिका पद सँमालें,

क्योंकि वे अखिल भारतीय स्वराज्य पार्टीकै अध्यक्ष थे, जो इस समय कांग्रेसपर काविज थी। परन्तु स्वराजियोंकी प्रार्थनापर गान्धीजी अपनी कार्यकालकी अवधिकी समाप्तितक यानी १९२५ के अन्ततक काम करनेको सहमत हो गये। अगस्तमें उन्होंने लिखा "मुझे अव शिक्षित भारतीयों द्वारा निर्देशित कांग्रेसके पथमें नहीं आना चाहिये क्योंकि मैंने तो अपनेको पूर्ण रूपसे जनसाधारणको समर्पित कर दिया है और शिक्षित-भारतसे मेरे मौलिक मतमेद हैं। में अब भी काम करना चाहता हूँ परन्तु कांग्रेसका नेतृत्व नहीं । मेरी सम्मतिमें उन छोगोंके कार्यकी सबसे अधिक सहस्थता में यही कर सकता हूँ कि उनके रास्तेसे हट जाऊँ और शिक्षित भारतीयोंकी अनुमतिसे, कांग्रेसकी सहायतासे और कांग्रेसके नाममें एकाग्रतासे रचनारमक कार्यकममें दत्तचित हो जाऊँ।" स्वराजियोंका निश्चय था कि ग़ान्धी पन्यको रद कर दिया जाय, जिसकी भावना यह थी कि सूत कातनेवाले ही निर्वाचित कांग्रेस संघटनीं के सदस्य हो सकते हैं। २१-२२ सितम्बरको पटनामें हुई अखिल भारतीय महासमितिकी वैठकमें वे वेलगाँवके प्रस्तावको आमूल वदलवानेमें सफल हो गये। वेलगाँवके प्रस्तावमें साफ तौरपर दिया हुआ था कि कांग्रेस कार्यक्रम केवल रचनात्मक कार्यों तक ही सीमित है और विधान परिषदोंमें स्वराज पार्टी स्वयं वनाये हुए नियमोंके अन्तर्गत और स्वयं एकत्र चन्देसे काम करेगी । पटनाके प्रस्तावने स्थितिको इस प्रकार कर दिया "कांग्रेस वे सब राजनीतिक कार्य करेगी जो देशके हितके लिए आवश्यक हों, और इन कामोंके लिए सम्पूर्ण कांग्रेस संघटनों और धन कोपको काममें लायेगी। केवल अखिल भारतीय और प्रान्तीय खहर बोडोंके धन और सम्पतिको छोड़ दिया जायगा । यह धन-सम्पति मय बर्तमान आय-व्ययके हिसानके गान्धीजी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय कताई संघको दे दी जायगी। यह संघ कांग्रेस संघटनका अभिन्न अंग है परन्तु इसको अपने उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए इस धन व दूसरे धन कोषोंका उपयोग करनेकी पूरी स्वतन्त्रता है।" वर्कनहेडने इंगित किया था कि कांग्रेसको ग्रद्ध राजनीतिक संस्था वन जाना चाहिये। पटनाके प्रस्तावने इसको राजनीतिक संस्था वना दिया और गान्धीजी केवल मात्र रचनात्मक कार्यकर्ता रह गये ।.....अव कांग्रेस-जनोंके लिए स्त कातना अनिवार्य न था। "गान्धीजीने निश्चय कर लिया कि वर्जनहेडके जवावमें वह स्वराजियोंके साथ सम्भव सहयोग करेंगे और परिपद सम्बन्धी कामोंमें प्रत्येक सहायता देंगे।" गान्धीजीके इस हथियार डाल देनेसे अपरिवर्तनशील बहुत चिन्तित हो उठे और विहारके नेता राजेन्द्रप्रसादने गान्धीजीसे पटना-प्रस्तावपर हो रही वहसके दौरानमें पूछा कि कहीं गान्वी, नेहरू और दासके बीच कोई सन्धि तो नहीं हो गयी। गान्धीजीने उत्तर दिया कि दूसरे पक्षकी माँग स्वीकार करना मेरे लिए आत्म-सम्मानका प्रश्न वन गया है।

'असहयोग' अब आन्दोलनकां हथियार नहीं रह गया था, और उसकी जगह नये नेताओं और अन्य राजनीतिक पार्टियोंने वैधानिक उपायोंका इस्तेमाल आरम्भ कर दिया।" अप्रैलके अन्त और मईके ग्रुरूमें राजनीतिक कियाशीलता एकदमते बढ़ गयी। इसका आरम्भ मद्रासकी एक विराट् समामें श्रीमती वेसेण्टके भाषणसे हुआ। उन्होंने 'कॉम' नवेल्थ ऑफ इण्डिया विल'के लिए किस प्रकार उद्देलन किया जाय' पर भाषण किया था। यह उन्होंने स्वयं ही तैयार किया था। वैधानिक ढंगकी समाएँ और प्रान्तीय सम्मेलन खूव खुलकर हो रहे थे।

एक दृष्टि विधान-सभाओंपर भी डालनी चाहिये। अगस्तमें स्वराज पार्टीके उच्च

नेता विर्टलभाई जे. पटेल विधान सभाके अध्यक्ष निर्वाचित हुए । भारत सरकारके १९१९ ऐक्टके नियमके अनुसार विधान समाके निर्वाचनके प्रथम चार वर्षके अन्तमें नामजद अन्यक्ष-का त्यान विधान सभा द्वारा निर्वाचित अध्यक्षको मिलनेकी व्यवस्था थी । सितम्बर मासमें सुधारोंके प्रक्तपर स्वराजियोंने सरकारको करारी हार दी । मसला इस प्रकार उठा-दिसम्बर १९२४ में सरकारने, विधान समाकी लगातार माँगपर एक कमेटी नियुक्त की, जो इस वातकी जाँच करनेवाली थी कि 'गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्टको किस प्रकार कार्य रूपमें अधिक उदार वनाया ला सकता है। इस कमेटीके सभापति सरकारके गृहमन्त्री सर एले-क्नेज्डर मृहीमेन थे। कमेटी इन्हींके नामते प्रतिद्ध थी। इत कमेटीने एक वहुमत (सर-कारी) की रिपोर्ट पेश की और एक अल्पमत (गैर-सरकारी) की । स्वभावतः सरकारी रिवोर्ट 'गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ऐक्ट' की सीमाओं से वाहर नहीं जा सकती थी। परन्त अख्यमतकी रिपोर्टमें 'पूर्ण उत्तरदायी सरकार' की माँग की गयी | विधान सभामें जब वहु-मतकी रिपोर्ट पेरा की गयी तो स्वराजपाटींके नेता मोतीलाल नेहरूने एक संशोधन पेरा किया। संशोधनमें माँग की गयी थी कि प्रान्तोंमें हैंथ शासन खत्म करके उसकी जगह एकात्मक जिम्मेटार सरकार वनायी जाये और केन्द्रीय सरकार, फीजी व्यव, वैदेशिक नीति और राज-नीतिक महकर्मोको छोडकर रोप मामलीमें केन्द्रीय विधान सभाके प्रति उत्तरदायी हो । संशोधनमें यह भी तिफारिश की गयी थी कि नये संविधानकी विस्तृत योजना वनानेके लिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाय या ऐसा ही कोई अन्य उपाय किया जाय। दो दिनकी बहसके बाद मोतीलाल नेहरुके संशोधनने सरकारको ४५ वोटींके मुकाबलेमें ७२ बाटींसे हरा दिया । यह संज्ञोधन लागू नहीं किया गया । फिर भी स्वराज पार्टीने यह तो सावित ही कर दिया था कि विधान समाएँ केवल एक ढोंग हैं क्योंकि उनके वाकायदा स्वीकार किये हुए प्रस्ताय भी सरकारकी दृष्टिमं रहीकी टोकरीके कागजोंसे अधिक महत्य नहीं रखते । कमेटीकी सरकारी रिपोर्टका एक फायदा यह हुआ कि निर्वाचनके नियमीको बदलकर औरतोंको मी विधान समामें बैटनेका इक दे दिया गया ।

स्वराज पार्टीकी ढुलमुल नीति, कभी सहयोग और कभी अवरोध, के कारण स्वराज पार्टीके अन्दर अनिश्चित मत धीरे-धीरे—'प्रतिदान सहयोग' की नीतिकी तरफ जा रहे थे। इस दिशामें एक महत्त्वपूर्ण संकेत जुलाईमें मिला, जब लाजपत रायने एक प्रकाशित वक्तन्वमें कहा ''इस समय वीचका रास्ता अपनानेकी आवश्यकता है। हम सहयोगके लिए तैयार नहीं है। परिस्थितिवोंके अन्दर जो भी सबसे अच्छा, व्यावहारिक और सम्भव होगा, हमें वही करना चाहिये।'' उत्तरदायी सहयोगी (रेस्पांसिव कोआपरेटर्ज) कहते थे कि सहयोग करनेका पथ-प्रदर्शन तो स्वश्ं मोतीलाल नेहरूने किया है। उन्होंने सॅन्डहर्र्ट कमेटी, जो स्कीन कमेटीके नामसे आम तौरपर जानी जाती थी, की सहस्यता स्वीकार कर ली थी। अक्त्वरके आरममें मध्यप्रदेशकी विधान समामें स्वराज्य पार्टीके नेता एस. बी. ताम्बेने पार्टीके अनुशासनके विरुद्ध मन्त्रि-पद ग्रहण कर लिया। मध्यप्रदेशकी विधान समा अकेली विधान समा थी जहाँ स्वराज्य पार्टीको पूर्ण बहुमत प्राप्त था।

ताम्वे घटना स्वराज्य पार्टीके अन्दर आगे चलकर होनेवाली ट्ट-फूटका आभास मात्र थी । मध्य प्रदेशकी स्वराज पार्टीके अन्दर ऐसे दूसरे लोग भी थे जो ताम्बेके परिवर्तित मतसे सहस्त थे । वस्वई और महाराष्ट्रमें भी कुछ लोग इसी तरफ बढ़ रहे थे । एन. सी. केलकर., एम. आर. जयकर और डा. मुञ्जे जैसे स्वराज्य पार्टीके प्रधान नेताओंने अपने आपको नई नीति, उत्तरदायी सहयोगका समर्थंक घोषित कर दिया। मोतीलाल नेहरू और अलग होनेवालोंके बीच फिर बहुत गरमा-गरम बहस चली। पार्टीकी कार्यकारिणीकी बैठक नागपुरमें हुई और बैठकने ताम्बेके कार्यकी तीन्न निन्दा की। बादमें गुञ्जे, जयकर और केलकरने विधान सभाकी सदस्यतासे इस्तोफा दे दिया। क्योंकि वे लोग स्वराज्य पार्टीके उम्मीदवारकी हैसियतसे निर्वाचित हुए थे। कुछ समयसे दोनों दल अखवारोंमें और सार्वजनिक स्तरपर अपने झगड़ोंको ले आये थे। बम्बईमें दोनों दलोंके लोग मिले और इस बातपर सहमत हो गये कि तमाम विवादके सार्वजनिक प्रस्नोंको कानपुरमें होनेवाले कांग्रेसके वार्षिक अधिवेशनतक रोक देना चाहिये।

लेकिन कानपुर कांग्रेस अधिवेशन (१९२५) ने 'उत्तरदायी-सहयोग' के मानने-वालोंका समर्थन करनेके बजाय, अपनी नीतिको इतना अधिक उग्र कर दिया जहाँतक स्वराजी भी नहीं जा सकते थे। अध्यक्षा श्रीमती सरोजिनी नायडूने कहा कि ''श्रीमती वेसेण्ट द्वारा बनाया हुआ 'कामनवेल्थ ऑफ इण्डिया विल' भारतकी राष्ट्रीय-माँग वन गया है। " अब यह सरकारके ऊपर है कि वह कोई जवाबी कदम उठाये और उस सरकारी कदमपर ही हमारा भविष्यका रुख निर्भर है। अगर उसका जवावी कदम उदार और सचाईसे युक्त हुआ, और अगर सरकार सद्भाव एवं निष्ठासे काम करे. तो हमें अपनी वर्तमान नीतिमें परिवर्तनकी आवश्यकता पड़ेगी। परन्तु यदि हमें वसन्त अधिवेशनतक कोई जवाब न मिला या ऐसा जवाब मिला जो असली प्रश्नोंका जवाब नहीं देता और जिसे हमें अस्वीकार करना पड़े तो राष्ट्रीय कांग्रेसको अपने प्रभावके अन्दरके सब छोगोंको आदेश दे देना चाहिये कि वे केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान सभाओंसे त्यागपत्र दे दें और कैलाशसे कन्याकमारीतक, सिन्धुसे ब्रह्मपुत्रतक, भारतीय जनताको एक संयुक्त संघर्षके लिए शिक्षित, तैयार और जागरित करनेके लिए अथक और गतिशील प्रयत शुरु कर दे।" उन्होंने नौजवानोंको याद दिलाया कि ''हमारे सैकड़ों नौजवान देशप्रेमके कारण जेलमें सड़ 'रहे हैं। देशप्रेमके अपराधके लिए इस कानूनमें कोई छूट नहीं है।" उन्हें (सरोजिनी नायडू) विश्वास था कि "हमें स्वराज्य गान्धीके वताये रास्तेसे ही मिलेगा।" परन्तु देश, जैसा कि गान्धीजीने स्वीकार किया एक दूसरे आन्दोलनके लिए अभी तैयार नहीं था। गान्धीजीने कहा "मैं आज सविनय अवज्ञा आन्दोलन ग्रुरू कर देता यदि मैं समझता कि जनतामें चेतना और उत्साह है। परन्तु अफसोस है कि ऐसा नहीं है।"

कांग्रेस द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमको देखनेसे पता चलता है कि कांग्रेस स्वराजियोंकी कठपुतलीकी हैसियत छोड़कर एक वार फिर लड़ाकृ संघटन बननेकी चेष्टा कर रही थी। कार्यक्रम संक्षेपमें इस प्रकार था (क) देशमें कांग्रेसका कार्य, जनताको अपने राजनीतिक अधिकारोंकी शिक्षा देना और उन अधिकारोंको प्राप्त करनेके लिए संघर्ष करनेके लिए रचनात्मक कार्यों द्वारा आवश्यक शक्ति और ताकत इकट्ठा करना है। रचनात्मक कार्योंमें चरला और खहरका प्रचार, साम्प्रदायिक एकता बढ़ाना, अछूतोद्वार, दलित वर्गोंकी दशा ठीक करना, शरावकी बुराई दूर करना मुख्य थे। इनमें स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओंपर कटजा करना भी शामिल था। (आ) अगर सरकारने भारतके नये संविधानपर अपना फैसला फरवरी १९२६ के अन्ततक नहीं सुनाया और यदि कांग्रेस कार्यकारिणींके

सदस्यों व महासमिति द्वारा नियुक्त अन्य सदस्योंकी विशेष समितिको वह फैसला सन्तोषजनक न प्रतीत हुआ तो पार्टी उचित प्रणाली द्वारा सभामें सरकारको यह सूचना दे देगी
कि भविष्यमें पार्टी विधान सभामें न रहेगी और न उसकी काररवाइयोंमें भाग लेगी।
विधान सभा और राज्य परिपदके स्वराजी सदस्य विक्तविधेयकके विरुद्ध वोट देंगे और
तुरत ही विधान सभासे बाहर चले आकेंगे। ऐसी प्रान्तीय परिपदोंके स्वराजी सदस्य जिनका
उस समय अधिवेशन हो रहा होगा, अपनी जगहें छोड़कर चले आकेंगे और जहाँ अधिवेशन
उस समय अधिवेशन हो रहा होगा, अपनी जगहें छोड़कर चले आकेंगे और जहाँ अधिवेशन
उस समय न हो रहे होंगे वहाँके सदस्य भविष्यमें परिपदोंकी किसी भी वैठकमें भाग न लेंगे,
और विशेष समितिको सूचना दंगे। विधानसभा, विधान परिपद या प्रान्तीय परिपदोंमें
स्वराज्य पार्टीका कोई भी सदस्य—अपने खानको रिक्त घोषित होनेसे बचानेके अतिरिक्त,
प्रान्तीय बजटोंको अस्वीकार कराने या किसी नये कर सम्बन्धी बैठकको छोड़कर सभा,
परिपद या प्रान्तीय परिषद की, या उसकी किसी कमेटीकी बैठकमें भाग नहीं लेगा। परन्तु
यदि विशेष समितिकी सम्मितमें किसी विशेष आवश्यकताके कारण बैठकमें भाग लेना
जरूरी है तो वह विधान समात्री बैठकोंमें स्वराज पार्टीके सदस्योंको भाग लेनेकी अनुमित
देगी। (इ) प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंकी कार्य-कारिणयोंको, अगले वर्षके 'आम चुनाव'
के लिए उम्मीदवार तय करनेका अधिकार दे दिया गया।''

मदनमोहन मालवीय, जो 'उत्तरदायी सहयोग' के दलमें शामिल हो गये थे, इस कार्य-क्रममें एक संशोधन रखना चाहते थे। उन्होंने, प्रस्ताव रखा कि पूर्ण उत्तरदायी शासनकी प्राप्तिके लिए 'सहयोग अथवा अवरोध' की नीति आवश्यकतानुसार अपनाकर विधान सभाओंका यथासम्भव उपयोग किया जाय। यह संशोधन गिर गया। मुझे, जयकर, और केलकरने विधान सभाओंसे अपने त्यागपत्र देनेकी घोषणा कर दी। कांग्रेस-की काररवाई चलानेके लिए हिन्दीको माध्यम बनानेका निश्चय हुआ।

कानपुरसे लौटनेके फौरन बाद ही जयकरने अपने मतसे सहमत वम्बई, बरार और मध्यप्रदेशकी विधान-परिषदींके सदस्वोंका एक सम्मेलन १६, १७ जनवरी १९२६ को पूनामें खुलाया। सम्मेलन आगामी कार्यक्रम और 'उत्तरदायी सहयोग' दल द्वारा विधानसभाके आगामी जुनाव लड़नेका निस्चय करनेके लिए बुलाया गया था। इस सम्मेलन और वादकी वैटकोंके फलस्वरूप स्वराज्य पार्टीकी माँति ही शक्तिशाली (जैसा हम आगे चलकर देखेंगे) एक नयी पार्टोकी स्थापना हुई।

अव स्वराज पार्टीके सहयोगवादी, स्वतन्त्र और उदारदलीय लोगोंके उद्देशोंमें कोई विशेष अन्तर न रह गया था। कलकत्तेमें सर मोरोपन्त जोशीकी अध्यक्षतामें हुए उदार-दलीय सम्मेलनके वार्षिक अधिवेशनने एक वार फिर प्रयक्त किया कि सब दलोंमें एकता हो जाय और वे कांग्रे समें शामिल हो जायँ। यदि ऐसा न हो सके तो कम से कम अपर दिये हुए दल तो मिलकर एक हो जावँ। इस विषयपर वोलते हुए अध्यक्षने अपने भाषणमें कहा "यदि कांग्रेस वर्तमान स्थितिमें यह घोषणा करे कि 'सविनय अवशा' और 'कर न दो' कांग्रेस नीतिके अंग नहीं हैं तो सब दलोंका कांग्रेसमें आना आसान हो जायगा। तब कांग्रेस तीव्र राजनीतिक प्रचार—जिसका सरकारपर प्रभाव पहेगा—की ओर अपना ध्यान एकाग्र कर सकेगी। यदि यह किसी कारणसे असम्भव हो तो 'सीधी काररवाई' (डाइरेक्ट ऐक्शन) वालोंके खिलाफ वैधानिक राजनीतिवालोंका एक हो जाना तो व्यावहारिक राजनीतिकी दृष्टि

सम्भव ही है। उन्होंने यह सुझाया कि ''उदारदलीय, स्वतन्त्रों, 'उत्तरदायी सहयोग' वालों और परम्परावादियोंका एका तो हो ही सकता है।

वम्बई स्वराज्य पार्टीकी कार्यकारिणीने २० जनवरीको 'उत्तरदायी सहयोग' वापस लेनेका निश्चय किया । स्वराज्य पार्टी कमजोर हो रही थी, परन्तु कानपुर अधिवेदान हारा निश्चित कार्यक्रमको आगे ले जा रही थी ।

उदारदलवाले अपनी नयी योजनाओंपर काम कर रहे थे। ३ अप्रैलको उन्होंने संयुक्त दल वनानेके लिए तैयार राजनीतिक दलोंके नेताओंका एक सम्मेलन वम्बईमें बुलाया। एम॰ ए॰ जिनाकी अध्यक्षतामें एक नयी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी (जो राष्ट्रीय पार्टीके नामने भी प्रसिद्ध हुई) की स्थापना की गयी।

आस्चर्य इस वातका था कि एक समयके 'तूफानी कांग्रेसी' विपिनचन्द्र पाल भी 'सहयोगियों' में थे। राष्ट्रीय पार्टी (नेशनल पार्टा) का उद्देश्य शान्तिमय और वैधानिक तरी-कोंसे (कर न दो आन्दोलन और सविनय अवज्ञाको छोड़कर) औपनिवेदाक स्वराज्य पानेकी तैयारी करना था । स्वभावतः यह नया संयुक्त दल स्वराज्य पार्टीके लिए एक चुनौती था । मोतीळाळ नेहरूने पार्टीके दोनों पक्षोंको एक करनेकी कोशिशके लिए दोनों पक्षोंकी एक मीटिंग २१ अप्रैलको सावरमतीमें बुलायी । इस समझौतेके ऊपर कि "विधान समामें स्वराज्य पार्टी द्वारा फरवरी १९२४ में उठायी गयी माँगके जवावमें अगर सरकारने मन्त्रियोंको प्रमावकर रूपसे कर्त्तव्यपालनके लिए यथेए शक्ति और जिम्मेदारी दे दी, तो वह जवाव सन्तोषप्रद माना जायगा" थोड़े समय चलनेवाली एकता प्राप्त कर ली गर्या। यह सम-शौता 'सावरमती समझौते'के नामसे मशहूर है। परन्तु अभी समझौतेकी स्याही स्र्ली मी न थी कि कुछ कांग्रेसजनोंने, विशेषतः आन्ध्र कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष टी. प्रकाशमने इस समझौतेको कानपुर-प्रस्तावके विरुद्ध कहकर उसकी तीव्र निन्दा गुरू कर दी । और जब मोतीलाल नेहरूने अपने कांग्रेसके साधियोंको सन्तुष्ट करनेके लिए इसका रपष्टीकरण किया तो सहयोगवादियोंने कहा कि यह स्पष्टीकरण समझौतेके क्षेत्रके वाहर है। मोतीलाल नेहरूका न्पष्टीकरण यह था कि 'मन्त्री विधान स्माके प्रति पूर्ण उत्तरदायी हों तथा उनको हस्तान्तरित विभागोंकी नौकरियोंपर पूरा नियन्त्रण प्राप्त हो; और राष्ट्रीय-उत्थान सम्बन्धी विभागोंको उचित धन-सहायता मिले। अवकरने इस स्पष्टीकरणको समझौतेका उपहार वताया । समझौता रद हो गया ।

प्रान्तीय और केन्द्रीय विधान सभाके लिए आम चुनाय नवम्वर १९२६ में हुए। इस वारका 'चुनाव रंगमंच' पिछले चुनावसे विल्कुल भिन्न था।

दो माँगोंमें बँट जानेके कारण स्वराज पार्टी कमजोर हो गयी थी। सम्प्रदायबाद (जो आगामी अध्यायमें विस्तारसे वर्णित है) का वोल्वाला था। मतदाता, जो जनसंख्याके ४% थे, यह समझते थे कि असहयोग आन्दोलन समाप्त हो गया है और इसीके साथ हिन्दूर मुस्लिम एकता भी। साम्प्रदायकताका लगभग उतना ही प्रभाव हो गया था जितना कांग्रे सका। सम्प्रदायवादकी सबसे वड़ी जीत स्वराज्य पार्टीके अन्दरसे कुछ अनुभवी नेताओं का साम्प्रदायकताके रंगमें रँग जाना था। इसिल्ए १९२६ के चुनावोंके परिणाम स्वराज्य पार्टीको निराबा प्रदान करनेवाले थे। त्वराज्य पार्टीने १९२३ में हासिल की हुई जीत इस वार खो दी। मद्रास प्रेसीडेन्सीको छोड़कर, जहाँ उनकी पूर्ण विजय हुई, स्वराज्यपार्टी

हर जगह बुरी तरह हारी। दंगों और सम्प्रदायबादकै केन्द्रोंसे दृर मद्रासपर जैसे वदली हुई राजनीतिक परिस्थितिका कोई प्रमाव पड़ा ही नहीं। इसके अतिरिक्त 'अब्राह्मणों' की 'निस्टिस पार्टी' संकुचित दृष्टिकोणके कारण भृतपूर्व परिषद्में बुरा 'प्रभाव' छोड़ गयी थी । स्वराज्य पार्टीकी सबसे बढ़ी हार हुई पंजाब और संयुक्तप्रान्त (उत्तर प्रदेश) में जहाँ साम्प्रदा-विकता अपने सबरे भयानक रूपमें आधिपत्य जमाये हुई थी। स्वराज्य पार्टीकी तरफसे एक भी मुसलमानने चुनाव नहीं लड़ा। "स्वराज्य पार्टीसे सम्बन्ध न रखनेवाले विघान सभाके लगभग सभी हिन्दू सदस्वोंने मालवीय, जयकर और लाजपतरायके नेतृत्वमें एक राष्ट्रीय पार्टी, स्थापित कर ली । पिछली विचानसभाकी स्वतन्त्र पार्टी जिसके नेता जिना थे विलीन हो गयी। उदारदलवाले एक संघटित पार्टाकी हैसियतसे न रह गये थे। अब जिनाके पीछे दो हिन्दू और कुछ मुस्लिम सदस्य रह गये थे। मुस्लिम सदस्योंका बहुमत असंबद्धित रूपमें अलग बैठता था। सब प्रान्तोंमें मन्त्रिमण्डल बने, यहाँतक मद्राससे जहाँ स्वराज्य पार्टीको निर्णयात्मक शक्ति प्राप्त थी "" यू॰ पी॰ में 'सहयोगवादियों' और कहर हिन्दुओं के दृष्टिकोणोंका समर्थन करनेवाळोंने एक संयुक्त दुरु बनाया। यह दुरु कभी-कभी 'स्वतन्त्र कांग्रेस दल' इण्डिपेण्डेण्ट कांग्रेस पार्टी भी कहलाता था। पंजावमें नवस्वरके चुनावके हिन्दू उम्मीदवार लाजपत रायके साथ हो गये और ये लोग अपनेको 'हिन्दू महासभाई' कहने छगे।" वास्तवमें राष्ट्रीय पार्टा (नैशनिलस्ट पार्टा) हिन्दू महासभाइयों और सहयोग-वादियोंसे ही वनी थी । बहुतसे प्रश्नोंपर निर्वाचित सदस्योंने एक होकर सरकारको हराया ।

गोहाटीमें हुए १९२६के कांग्रेस अधिवेशनकी अध्यक्षता एस० श्रीनिवास ऐयरने की। अपने भापणमें उन्होंने केन्द्रीय सभा द्वारा की हुई राष्ट्रीय माँगपर जोर दिया। उस वर्षके अधिवेशनके मुख्य प्रस्ताव ये "स्वराज्य पार्टीको (१) मिन्त्रपद अस्वीकार कर देना चाहिये। (२) माँगोंको नामंत्रर कर वजटको अस्वोकृत कर देना चाहिये, (३) नौकरशाहीकी स्थितिको मजवृत करनेवाले सब प्रस्तावोंको अस्वोकृत कर देना चाहिये। परन्तु देशकी आर्थिक स्थिति, कृषि, उद्योग और व्यवसायकी उन्नित सम्बन्धी प्रस्तावोंका समर्थन करना चाहिये। खेतिहर किसानोंकी उन्नित तथा मजवृर्तिके अधिकारोंकी रक्षांके लिए कदम उटाना चाहिये। गीहाटीमें 'सहयोगवादी' काँग्रेससे अलग हो गये। इसी अधिवेशनमें काँग्रेस जनोंके लिए खहर पहनना अनिवार्य कर दिया गया।"

अध्याय २०

साम्प्रदायिक वैमनस्य पुनः आरम्भ

१९१२ में जैसा कि याद होगा, सर सैयदके विचारींके मुस्लिम नेता, ट्रिपोली और बाल्कन युद्धमें अंग्रेजी सरकारके तुर्कांके खिलाफ रवैयेसे, अंग्रेजोंके विरुद्ध होने छो थे। इसके वादके दस सालका युग भारतीय राजनीतिमें हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यका काल है। ताज्जुवकी वात यह है कि जहाँ यह युग भारतीय राजनीतिक इतिहासका सुनहला पृष्ठ है, वहीं यह दौर छिटफुट हिन्दू-मुस्लिम दंगोंके कारण वदनाम भी है। १८९३ और १९११ के बीच हिन्दू-मुस्लिम दंगे लगभग नहीं ही हुए । जैसा कि हम पहले देख चुकें हैं कांग्रेसके जन्म (१८८५) से ही अलीगढ़ विचारोंके मुस्लिम नेता कांग्रेसके खिलाफ रहे हैं परन्तु अभीतक कभी साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए। १९११, १९१२, १९१३, १९१६, १९१७ में गीवधके प्रश्नके ऊपर विहारके विभिन्न जिलोंमें भयानक दंगे हुए। जव हिन्दू और मुसलमान अंग्रे जोंके विरुद्ध एक हो गये तो ये दंगे क्यों हुए ? इस सवालका जवाव एक दूसरे सवालसे ही दिया जा सकता है। हिन्दू और मुसलमानोंके एकेपर अंग्रे जोंकी क्या प्रतिक्रिया हुई ? अंग्रे जोंको यह एकता पसन्द नहीं आयी और न यह उनकी योजनाके अनुकल थी। इस एकताकी चरम सीमा १९१६ का लखनऊ समझौता था जो दोनों सम्प्रदायोंके वीच हुआ एक राज-नीतिक समझौता था। छीग और कांग्रेसके इस समझौतेको बाकायदा स्वीकार कर छेनेके बाद, मुसल्मानोंको अपनी तरफ मिलानेकी चिन्ता और व्यथ्रतामें भारत सरकारने घोषणा की कि समझौतेमें वंगालके मुसलमानोंके साथ न्याय नहीं हुआ है। सरकारने तर्क दिया 'वंगालके मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व साफ तौरपर कम है। यह विवादास्पद है कि जब यह समझौता हो रहा था तो पूर्वी बंगालकी मुस्लिम जन-संख्याको उपयुक्त प्रतिनिधित्व देनेपर जोर दिया गया । वंगालके मुसलमानोंको उनके अनुपातके अनुसार प्रतिनिधित्व देनेके लिए (उससे अधिक नहीं) उन्हें ३४ स्थानोंके वजाय ४४ सीटें मिलनी चाहिये (समझौतेमें वंगालके मसलमानोंको ३४ सीटें दी गयी थीं)। मुस्लिम-लीगको मुसलमानोंके खिलाफ भडकानेके लिए यह एक बहुत होशियार चाल थी, मगर यह नाकामयाब रही। बादको लखनऊ सम-झौतेको १९१९ के ऐक्टमें भी शामिल कर लिया गया। पार्लमेंट द्वारा भारत सरकार सुधार विधेयक (१९१९) के प्रश्नपर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति (जॉइंट सिलेक्ट कमिटी) के सामने गवाही देते हुए, एक प्रश्नके उत्तरमें जिनाने कहा कि समितिको भारत सरकारका वंगाल-सम्बन्धी प्रस्ताव रद कर देना चाहिये। जिनाने आगे कहा कि ''मेरी रायमें मुसल-मानोंके लिए पृथक साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वका उपवन्ध खत्म कर देना चाहिये।" उन्होंने आशा प्रकट की कि वह दिन दूर नहीं जब पृथक निर्वाचन विलक्कल ही गायब हो जायगा। उनका प्रश्नकर्ता—एक अंग्रेज सज्जन—आश्चर्यचिकत हो गया। १९१८ में जिनाने रौलट विलक्षे विरोधमें कैन्द्रीय विधान परिपदकी सदस्यतासे त्यागपत्र दे दिया था।

प्रवर समितिके सामने दी हुई, जिनाकी दूसरी गवाहीसे साम्प्रदायिक दंगोंके कारणींपर

प्रकाश पड़ता है। एक प्रस्तका उत्तर देते हुए जिनाने कहा "अगर आप मुझरे पूछें तो 'ज्यादातर यह झगड़े गलतफहिमयोंकी वजहमें होते हैं; यह गलतफहमी पुलिसके एक या दूसरे सम्प्रदायका पक्ष हेनेसे पैदा हो जाती है क्योंकि इस पक्षपातके कारण दूसरा सम्प्रदाय कोधित हो उटता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि भारतीय रियासर्वोमें हिन्दू-मुस्लिम दंगोंकी खवरं नहीं सनाई पडतों । और इस समितिके सामने, मुझे विना नाम वतलाये यह वतलानेमें कोई संकोच नहीं है कि मैंने जब एक रियासतके राजासे इसका कारण पूछा तो उन्होंने मुझे वताया 'जब कभी हम छानबीन करते हैं तो हमें पता चलता है कि झगड़ेकी जड़ पुलिस ही है । पुल्लिस द्वारा हिन्दुओं या मुसल्लमानोंका पक्ष लेनेके कारण ही झगड़े होते हैं । इसका सबसे अच्छा उपाय जो हम करते हैं, वह यह कि जैसे ही हमें झगड़ेकी खबर मिलती है हम वहाँसे पुलिसके हाकिम (झगड़ा करानेके लिये जिम्मेदार) को वहाँसे हटा देते हैं और झगड़ा खत्म हो जाता है। यह सावित करता है कि पुलिसको किसी भी समय साम्प दायिक दंगे करानेके लिये इस्टेमाल किया जा सकता है। दोनों सम्प्रदायों के धर्मीधों को एक दसरेका सिर फोड़नेको उत्तेजित करनेके लिये किसी अधिक बुद्धिमान व्यक्तिकी तो आवश्यकता पड़ती नहीं । उदाहरणके तौरपर हिन्दू-मन्दिरोंमें गोस्तका दुकड़ा या मस्जिदोंमें स्थरका गोस्त रख देने भरसे और उसके बाद यह अफवाह उड़ा देनेसे कि हिन्दू या मुसलमान (जैसा भी हो) ने पूजाकी जगहको अपवित्र करनेके मतलवसे यह किया है, झगड़ा हो जाता है। किसी तीसरी पार्टीके लिए (जिसका हित दोनों सम्प्रदायोंको अलग-अलग -रखनेमें है) शगड़ा कराना कितना आसान है। हिन्दू-मुस्लिम दर्गोको प्रोत्साहन देनेके सर्वोत्तम अवसर दोनीं सम्प्रदायोंके त्योहार होते थे;--कांप्रेस-लीगके समझौतेके कालमें त्योहारींपर दंगे अधिक हुए । यह एक अजीव-सी बात है । क्या समझौतेके कालमें त्योहारोंका महत्व विशेष रूपसे वढ़ गया था ? अंग्रेज-शासक और लेखकगण उस समय यह कहते थे कि भारत स्वराज्यके रास्तेपर आगे बढ़ रहा है और हिन्दू और मुसलमान दोनों ही अपने-अपने राजनीतिक अधि-कारोंके प्रति जागरूक हो गये हैं; इसी लिए झगड़े अधिक होते हैं, इन तकांकी देनेवालोंके विचारमें स्वराज्यके लिए एक होनेवाले दोनों पक्षोंके नेताओंसे यह धर्मान्ध शायद ज्यादा देशभक्त थे । हिन्दू प्रधान विहार प्रान्तके दंगोंमें मुसलमानोंकी सबसे ज्यादा वर्वादी हुई । फौरन ही अप्रेज अधिकारियों और टेखकोंने यह मशहूर करना गुरू कर दिया कि विना अंग्रेजी सुरक्षाके मुसलमान हमेशा अरक्षित रहेंगे और स्वराज्यका अर्थ होगा हिन्दू राज । इसी प्रकारसे मोपला विद्रोहमें, मुस्लिम कोधका शिकार हिन्दू हुए—हालाँ कि सोपलाओंका उद्देश्य अंग्रेजी शासनको समाप्त करना था- हिन्दुओंको 'कांग्रेस-खिलापत गठवन्धन' के विरूद चेतावनी दी गयी। वंगाल और पंजावमें १९२१ और १९२२ में फिर दंगे हए। परन्तु कांग्रेस लीग एका वरावर तवतक कायम रहा जवतक कि लोग 'असहयोग' के प्रस्तपर एकेसे पिछड़ने लगी। उसकी जगह खिलाफत कमेटीने ले ली। दंगेके बावजूद, इस एकेको देखकर उन लोगोंको वहुत निराज्ञा हुई जो इस एकताको तोड़ देना चाहते थे।

परन्तु 'असहयोग' के स्थिगत करने या उसके असफल हो जाने और तुर्कांके राज-नीतिक वातावरणमें परिवर्तन हो जानेसे भारतका राजनीतिक रूप ही वदल गया। कुछ वपोंके अनवरत संपर्पके वाद तुर्कांका युवक आन्दोलन सत्तापर अधिकार जमानेमें सफल हो गया। सुल्तान अव्दुल हमीदको तख्त और खिलाफत छोड़ देनेको बाध्य होना पड़ा।

१९२३ में मुस्तफा कमालपाशाने मुलतानका पद ही समाप्त कर दिया और तुर्कीको एक गणतन्त्र राज्य घोषित कर दिया । उन्होंने लोगोंकी धार्मिक भावनाओंके आदरस्वरूप खलीफाका पद कायम रखा। परन्तु साथ ही यह विधान वना दिया कि भविष्यमें खलीफाका पद केवल अध्यात्म विषयोंतक ही सीमित रहेगा l सुस्तान अव्दुल हमीदके भाग जाने पर उनके भतीजे अन्दुलमजीद एफेन्दी खलीफा हुए। ''परन्तु जब भारतीय मुस्लिम नेताओंने एक पत्र द्वारा नयी सरकारसे खलीफाके साथ और अधिक अच्छा व्यवहार करनेकी प्रार्थना की, तो मुस्तफा कमाल पाशाने इस घटनाकी आड लेकर खलीपाका पद भी समाप्त कर दिया, और कहा कि इसके कायम रखनेसे तुकीके मामलोंमें वैदेशिक हस्तक्षेप होगा ।" इस खबरसे, जो भारतमें १० मार्च १९२४ को पहुँची, खिलाफतके नेता अति व्यम्र हो उटे और उन्होंने उत्तेजनामें तुर्की जानेके लिए एक शिष्ट-मण्डल नियुक्त कर दिया । परन्तु इस शिष्टमण्डलको यात्राकी अनुमति नहीं मिली । जैसा कि जवाहरलाल नेहरूने कहा है कि कमालपाशाके "धर्मविरोध, मुल्तान और खलीफाके पदको समाप्त कर देने, धर्मनिरपेक्ष राज्य कायम करने और धार्मिक पदोंको तोड़ देनेसे, मुसलमानोंके दिलों में गदरके जमानेसे वननेवाले धार्मिक साम्राज्यका स्वप्न नष्ट हो गया।" खिलाफत आन्दोलनका केन्द्र अन्यत्र था और जब उसके अन्तर्भागको ही अतातुर्कने नष्ट कर दिया तो कपरी ढाँचा भी चरमरा गया और मुस्लिम जनता आश्चर्यचिकत रह गयी। न सिर्फ यह, बिक्कि राजनीतिक कार्योंके प्रति उदासीनता हो गयी। 122 खिलाफत आन्दोलनके नेता महम्मद्रअली तो कभी भी राष्ट्रवादी नहीं वन सके और 'असहयोग' आन्दोलनके आरम्भके पूर्व ही उन्होंने इस वातकी सार्वजनिक रूपसे घोषणा भी कर दी थी। मद्रासमें १९२० के ग्रीष्ममें दिये गये भाषणारें मुहम्मद अलीने कहा था कि अगर अफगानिस्तान भारतपर हमला करता है तो भारतीय मुसल्मान अफगानिस्तानकी सहायता करेगा। भारतके मुसल्मानींको अफगानिस्तान-का पंचमांगी वनानेका यह एक नारा था। मौलाना अवुलकलाम आजादने इस भाषणकी प्रतिक्रियाको रोकनेकी कोशिश की। उन्होंने यह समझाते हुए कि अफगानिस्तान द्वारा भारतपर आक्रमणके समय मुसलमानोंका क्या रुख होना चाहिये, कहा "जब भारत स्वतन्त्र हो, सरकार कायम हो, दूसरे साम्प्रदायोंकी तरह मुसलमानोंको स्वतन्त्रताकी गारण्टी प्राप्त हो तो मुसलमानोंके लिए यह इस्लामका हुक्म वन जाता है कि आक्रमणकारियोंसे भारतकी रक्षा करें। आक्रमणकारी मुसलमान और स्वयं खलीफाकी सेना ही क्यों न हो। परन्तु गान्धीजीने इसे अपने ढंगसे समझाया । उन्होंने कहा ''अगर अफगानिस्तानके अमीरने अंग्रेजी सरकारके खिलाफ लड़ाई छेड़ी तो एक तरीकेसे मैं उनकी मदद करूँगा। यानी मैं अपने देशवासियोंको खुळेआम वताऊँगा कि एक ऐसी सरकारकी मदद करना अपराध है जिसने सत्तापर अधिकार रखनेके लिए राष्ट्रका विश्वास खो दिया है।" इन दोनों माषणोंमें प्रत्यक्ष रूपसे अन्तर है। मुहम्मदअली कभी भी प्रजातन्त्र, या धार्मिक निरपेक्षता अथवा भारतीय

१. स्टीफोन किंग हाल, अवर ओन टाइम्स १९१३-३८, पृष्ठ १८०

२. नेहरू, डिस्कंवरी ऑफ इण्डिया, पृष्ठ ३०२

३. वहीं पुस्तक, पृष्ठ ३०३

थ. तुफेल अहमद, मुसलमानोंका रोशन मुस्तकबिल, पृष्ठ ५१२

राष्ट्रीयताक वारेमें नहीं सोच सकते थे। उनके कराचीके भाषणके सम्बन्धमें जो मुकदमा उनपर चला था उसके सम्बन्धमें उन्होंने अदालतके सामने अपने बयानमें कुरानी धार्मिक राज्यके नक्दोको बहुत विस्तारसे समझाया। पर भारतीय स्वतन्त्रता या भारतीय आकांक्षाओं अथवा भारतको गरीवीके वारेमें, जिससे शायद हिन्दुओं से अधिक मुसलमान संकटमें थे, एक शब्द भी नहीं कहा। परन्तु खिलाफतके प्रश्नपर मुहम्मद अनी कांग्रेससे विल्कुल हिल-मिल गये थे। ये गान्धीजीके बहुत बढ़े प्रशंसक थे।

१९२३ के कांग्रेस अधिवेशनमें उन्होंने अध्यक्ष-पदसे भाषण करते हुए कहा "बहुतोंने महात्माकी शिक्षाओं और बादमें उनके व्यक्तिगत कष्टप्रद बलिदानोंकी ईसा मसीह से (ईश्वर उन्हें शान्ति दे) तुलना की हैं " महात्माके आगमनसे पहले भारतकी राजनीतिक दशा वैसी ही थी जैसी कि ईसाके पहले यरूशलमकी थी और भारतके दुखोंके निवारणका जो उपाय महात्माने बताया वही ईस्ने यरूशलमके लोगोंको बताया था। बलिदानोंके द्वारा आत्म शुद्धि, सरकारकी जिम्मेदारीके लिए नैतिक तैयारी, स्वराज्य प्राप्तिके लिए पहली शर्त आत्म अनुशासन यह महात्माके विचार और विश्वास थे।" परन्तु इन्हीं मुहम्मदअलीने अलीगढ़ और अजमेरमें एक वर्ष बाद भाषण करते हुए कहा—"मिस्टर गान्धीका चित्र चाहे जितना शुद्ध क्यों न हो, परन्तु धार्मिक दृष्टिकोणसे वे मुझे किसी भी मुसलमानसे होन नजर आते हैं चाहे वह मुसलमान चरित्रहीन क्यों न हो (अंग्रेडकरकी पुस्तक)।"

इस व्याख्यानकी रिपोर्टकी सचाईका बहुतोंने यकीन नहीं किया। कुछ समय बाद जब वे लखनककी एक सभामें व्याख्यान दे रहे थे तो उनसे पूछा गया कि क्या उनके दिल्लीके भाषणकी रिपोर्ट सही है ? उन्होंने जवाब दिया "हाँ, अपने धर्म और मतके अनुसार में एक व्यभिचारी और पतित मुसलमानको मिस्टर गान्धीसे अन्छा समझता हूँ।"

मुहम्मदअलीमें यह परिवर्त्तन तब आया जब स्वराज्य-राजनीतिने असहयोग आन्दोलनका स्थान ले लिया, तुर्कीमें खिलाफत खत्म हो चुकी थी और भारतमें हिन्द-मुस्लिम दंगोंका बोल-बाला था। अंग्रेज फिर हाबी हो गये। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि १९१३ से अवतककी राजनीतिक प्रगति खत्म हो गयी है; और एक बार फिर सविनय अवज्ञा आन्दोलनके असफल हो जाने और हिन्दु-मुस्लिम एकताके संयुक्त मोचेंके टूट जानेके बाद भारतीय राजनीतिक नेता, अंग्रेज एरकार्से भारतको जिम्मेदार स्वशासन देनेकी प्रार्थना कर रहे थे, यद्यपि प्रार्थनापत्रोंमें छिपी हुई धमकी भी होती थी। और अंग्रेज संकट गुजरनेके वाद, निकट भविष्यमें और सुधार करनेके लिए प्रस्तुत नहीं थे। अंग्रेज अधिकारियोंके सामने अब केवल एक ही समस्या थीं-अपनी पुरानी स्थितिको फिर प्राप्त कर लेना; यानी हिन्द और मुसलमानोंके बीच सन्तुलन कायम रखनेकी ताकत रखना । १९२२ और १९२३ में तो साम्प्रदायिक दंगोंकी एक बाइ सी आ गयी। "विशेषतया १९२३ में तो हिन्दू और मुसलमानोंके वीचर्का तनातनी बहुत अधिक बढ़ गयी। मार्च और अप्रैलमें अमृतसर, मुत्तान और पंजावके दूसरे हिस्सोंमें खुलकर दंगे हुए । मईमें अमृतसरमें और भयानक दंगे हुए। सिन्धमें भी झगड़े हुए। जून और जुलाईमें यू० पी० के मुरादाबाद, मेरठ और इलाहाबादके जिलोंमें हिन्दू-मुक्लिम झगड़े हुए । अजमेरमें एक गम्भीर दंगा हुआ । अगस्त और सितम्बरमें अमृतसर, पानीपत, जबलपुर, गोंडा, आगरा और रायबरेलीमें दंगोंके कारण स्थिति गम्भीर हो गयी । सब उपद्रवोंमें ज्यादा भयानक झगडा मोहर्रमके

सिलिसिलेमें सहारनपुरमें हुआ।" दिल्ली, नागपुर, लाहीर, लखनऊ, भागलपुर, गुलवर्गा, शाहजहाँपुर, कोकोनाड़ामें भी हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए। "१९२४ के आरम्भिक महीनोंमें दोनों तरफके साम्प्रदायिक अखवारोंने जी खोलकर एकदूसरेपर गालीगलीजकी वौछार की।" सितम्बर १९२४ में कोहाटमें (उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्त) एक भयानक दंगा हुआ। "लगभग १५५ आदमी मारे गये और घायल हुए। अनुमानतः नौ लाख रुपयेकी सम्पत्ति—मकान और सामान वर्वाद हो गया और बहुत ज्यादा सामान लूट लिया गया। कोहाटकी कुल हिन्दू आवादी कोहाट छोड़कर भाग गयी।" डा॰ सीतारमैयाके अनुसार "नौ और दस सितम्बरके गोलीकाण्ड और रक्तपातके बाद वहाँसे ४००० हिन्दुओंको एक विशेष रेलगाड़ी द्वारा हटाना पड़ा। इन ४००० में २७०० आदमी पिछले दो महीनेसे रावलिपण्डीके लोगोंकी द्यापर जीवित थे। शेष १४०० दूसरी जगहोंके थे।"

गान्धीजीकी आस्मा दुःखित थी । उन्होंने दिल्लीमें मुहम्मद अर्लाके निवास-स्थानपर रश दिनका अनशन आरम्भ किया। दोनों सम्प्रदायोंके नेता इस हिंसक उन्मादको रोकनेके लिए व्यय ये और गांधी जीके अनशनसे दोनों पक्षोंके नेताओं के लिए स्थितिपर गौर करनेके लिए फौरन मिलना बहुत जरूरी हो गया। सब सम्प्रदायोंके नेताओंने २६ सितम्बरसे २ अक्टूबर तक एक सम्मेलन किया। सम्मेलनके सब सदस्योंने प्रण किया कि आत्मा और धर्मकी स्वतन्त्रताकै सिद्धान्तोंको लागू करानेके लिए भरसक प्रयत्न करेंगे और उत्तेजनामें भी इन सिद्धान्तोंसे डिग जानेकी घोर निन्दा करेंगे । एक राष्ट्रीय पंचायतकी स्थापना की गयी जिसमें हकीम अजमल खाँ, लाजपतराय, जी. के. नेरीमेनर, डाक्टर एस. के दत्त और मास्टर सन्दरसिंह थे। इसके सभापति और संयोजक गान्धोजी नियुक्त किये गये। इस सम्मेलनने, धार्मिक विचारोंको मानने और व्यक्त करने, तथा धार्मिक कार्योंको सम्पादित करने, पूजाके स्थानोंकी पवित्रता, गोवध, मसजिदोंके सामने गाना-वजाना सम्बन्धी कुछ मीलिक अधिकार और इनकी कुछ सीमाएँ नियत कर दीं। अखवारोंको अपने लेखींमें सावधानी वरतनेकी चेतावनी दी गयी। छोगोंसे प्रार्थना की गयी कि गान्धीजीके अनशनके अन्तिम सप्ताहमें वे प्रार्थना करें । आठ अक्टूवरका दिन सार्वजनिक सभाओंमे ईदवरोपासना-के लिए नियत कर दिया गया।"" यह वत और सम्मेलन कुछ समयके लिए उपद्रवी तत्वींको जरूर रोक सकता था, परन्तु इस भयानक योमारी, जिसको वेरोकटोक वदाया जा रहा था, के लिये यह कोई स्थायी उपाय नहीं था। साम्प्रदायिक संघटन जो राष्ट्रीयताके वढ़ते हुए सूर्वके सामने अन्धकारमें छिप गये थे, फिरसे उभरने लगे। इनको दंगोंके कारण जीवन पोषण मिल रहा था। कुछ राष्ट्रीय नेता अव अपने अपने साम्प्रदायिक संघटनोंमें एकत्र होने लगे। अंग्रेजो-विरोधी संवर्षका स्थान अव मुसलमानींके हिन्दुओंसे मुरक्षित रहने और हिन्दुओं के मुसलमानों से सुरक्षित रहने के आन्दोलनोंने ले लिया। एक तरफ के लोग दूसरी तरफ

१. इण्डिया इन १९२४ २५, पृष्ठ ३००-३०१

२. वही पुस्तक, पृष्ठ ३२०

३, वही पुस्तक, पृष्ठ २२

४, हिस्ट्री आफ इण्डियन नेशनल कांग्रेस, भाग १, पृष्ठ २७५-७६

५. वही पुस्तक पृष्ठ २७६

के लोगोंके खिलाफ जो तैयारियाँ करते थे, वे अधिक शक्तिशाली नहीं थीं। उनका असर सिर्फ दूसरे पक्षको नाराज करना होता या, नाराज करनेवाले सम्प्रदायको इनसे कोई वास्तविक .. फायदा भी न होता था । वंगाल और पंजावर्मे, साम्प्रदायिक दंगोंने हिन्दू नेताओंके अन्दर यह भावना पैदा कर दी कि वे अरक्षित हैं क्योंकि वहाँ हिन्दू अल्प संख्यामें थे, विशेपतया इसिल्ए कि इन सूत्रोंके मुसलमान माँग कर रहे थे कि उनको स्थायी रूपसे वहसंख्यक मान लिया जाय । पंजानके एक हिस्सेमें यह भावना वहुत दिनोंसे यी और इसका प्रत्यक्ष रूप हिन्दू महासभा थी जो विना विदोप प्रभावके बरावर कायम थी। साम्प्रदायिक वातावरणके गरम होते ही यह संघटन एकदमसे प्रकाशमें आ गया । इसका पहला महत्वपूर्ण अधिवेशन १९२३ में मदनमोहन मालवीयकी अध्यक्षतामें वनारसमें हुआ । महासमाने एक प्रस्ताव द्वारा हिन्दुओंसे अछ्तोंको सार्वजनिक कुँओं, स्कूलों और मन्दिरोंको इस्तेमाल करनेको अनुमति देनेकी प्रार्थना की । हिन्दू महासभाकी प्रान्तीय व स्थानीय शाखाएँ संविटत की जाने लगीं। हिन्दुओंके बलपूर्वक धर्म-परिवर्तन, मोपलाओं द्वारा हिन्दुओंपर अत्याचार और वादमें मुल्तानक दंगोंसे, जिनमें "हिन्दुओंके पूजास्थल गन्दे और नष्ट-भ्रष्ट किये गये थे, बहुतसे हिन्दू मारे गये थे, बहुतसे हिन्दू घर छूटे और जन्म दिये गये थे।" इन वातोंसे श्रद्धानन्द जैसे हिन्दू नेताओंको यह आवश्यकता माल्म हुई कि मुसलमानोंको हिन्दुत्वमें वापस लानेके लिए 'शुद्धि आन्दोलन' शुरू किया जाय। इस प्रकारसे शुद्धि आन्दोलनका जन्म हुआ। इस आन्दोलनके वारेमें डा॰ राजेन्द्र नसाद कहते हैं' राष्ट्रीयतावादियों और मुसलमानीं दोनोंने स्वामी श्रद्धानन्दके 'शुद्धि आन्दोलन' की आलोचना की है। समय विशेषपर इसकी उप-यक्तताके वारेमें चाहे कोई कुछ भी कहे, परन्तु यह समझना मुश्किल है कि ईसाई या मुसल-मान इसकी आलोचना कैसे कर सकते हैं वे तो स्वयं धर्मपरिवर्तनके मिशनपर और हिन्दओं-को अपने धर्ममें मिलानेमें वरावर लगे रहते हैं। अगर हिन्दू भी गैर-हिन्दुओंको अपने धर्ममें छाते हैं तो इससे गैर-हिन्दुओंको कोई मतलब नहीं है और न उनको आपत्ति करनी चाहिये विशेषतया जब कि वे स्वयं धर्म-परिवर्तनमें संलग्न रहते हैं। हिन्दुओंको भी अपने धर्मका प्रचार करनेका अधिकार उसी प्रकार प्राप्त है जिस प्रकार दूसरोंको । परन्तु आदमी हमेशा तर्क, न्याय एवं ओचित्यकी भावनासे ही सब काम नहीं करता । मुसलमानोंमें शुद्धि आन्दो-छन और स्वामी श्रद्धानन्दके प्रति बहुत कडुता पैदा हो गयी, जिसके फलस्वरूप, कुछ समय बाद, स्वामी श्रद्धानन्द एक मुसलमान इत्यारेके शिकार हो गये। मुसलमानाने श्रद्धि-आन्दोलनके जवावमें 'तवलीग' और 'तन्जीमं' आन्दोलन चलाये।""

कांग्रेस संघटन दृढ़तासे अपना धर्म-निरपेक्ष और असाम्प्रदायिक रूप बनाये हुए था। १९२३ के अन्तिम तीन महीनोंमें प्रधान कांग्रेसजन साम्प्रदायिक तनातनी दूर करनेकी चेष्ठा करते रहे। कांग्रेसने 'राष्ट्रीय समझौता' तैयार करनेके लिए एक समिति नियुक्त की। परन्तु साम्प्रदायिक प्रश्नकी निष्पक्ष जाँचके लिए उपयुक्त बातावरणका अभाव था। वंगालमें चित्तरं जन दासने हिन्दू-मुस्लिम समझौतेका एक मसविदा तैयार किया (जो वंगाल समझौतेके नामसे मशहूर है), परन्तु इसके परिणामस्वरूप स्थिति और विगड़ी। समझौतेमें स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधित्वके लिए ६० और ४० सीटोंका प्रस्ताव रखा गया था। (बहुसंख्यकोंको

१. डा० राजेन्द्रप्रसाद—इण्डिया डिवाइडेड पृष्ट ११७

२. डा० राजेन्द्रप्रसाद—इण्डिया डिवाइडेड पृष्ठ ११७

६० और अल्पसंख्यकोंको ४० स्थान मिलें)। यह भी प्रस्ताव रखा गया कि सरकारी नौकरियों में ५५% जगहें मुसलमानोंको दी जायेँ। वातावरण समझौतिके अनुकूल नहीं था। इससे हिन्दू नेताओं में विरोधकी लहर दौड़ गयी। कुछ समय बाद समझौता मुस्लिम नेताओं को भी नाराज करनेका साधन सिद्ध हुआ। वंगाल विधान परिपद में एक प्रस्ताव पेश किया गया कि सरकारी नौकरियों में ८०% (अस्सी प्रतिशत) जगहें मुसलमानों के लिए मुरक्षित रखकर (जवतक कि प्रत्येक विभागमें उनका औसत समस्त संख्याका ५५ प्रतिशत न हो जाय) वंगाल समझौता फीरन लागू किया जाय। परन्तु दास इस प्रस्तावसे असहमत थे। उन्होंने कहा कि समझौतेकी शतें केवल स्वराज्य-प्राप्तिके वाद ही लागू की जा सकती हैं।"

१९२४ में हिन्दू महासभाका अधिवेशन वेलगाँवमें उसी पण्डालमें हुआ जहाँ कुछ दिन पूर्व कांग्रेसका अधिवेशन हुआ था। इस वर्षके अधिवेशनके अध्यक्ष भी कांग्रेस नेता मदनमोहन मालवीय ही थे, इस कारण कई प्रमुख कांग्रेसजन भी अधिवेशनमें सम्मिलित हुए। इनमें अली-वन्धु और अबुल कलाम आजाद भी थे। अपने भाषणमें मदनमोहन मालवीयने इस वातका खण्डन किया कि महासभा साम्प्रदायिक संघटन है। उन्होंने कहा कि किसी भी हिन्दूके लिए राष्ट्रीय कांग्रेसका विरोध करना शर्मकी वात होगी। उनका उद्देश्य तो कांग्रेसकी सहायता और उसको शक्ति प्रदान करना है। महासभाका संटघन करनेको आवश्यकता तो इसलिए पड़ी कि कांग्रेस राजनीतिक संस्था होनेके नाते समाजी और गैर राजनीतिक प्रश्नों, जिनका विभिन्न जातियोंपर प्रभाव पड़ता है, पर ध्यान नहीं दे सकती। मालवीयजीने इस वातपर जोर दिया कि महासभा सांस्कृतिक आन्दोलन है और वह "अहिंसामें विश्वास रखती है तथा शक्ति द्वारा नहीं विल्क प्रेम द्वारा विद्वेष और हिंसात्मक भावनाओंको जीतना चाहती है।" परन्तु अधिवेशनमें पास हुए प्रस्तावोंमेंसे एकमें कहा गया था "सभाका कार्य केवल, हिन्दुओंके सामाजिक और धार्मिक उत्थानतक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि सभा राजनीतिक प्रश्नोंपर भी हिन्दू मतको व्यक्त करेगी और जनताका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करेगी।"

नवम्बर १९२४ में गान्धीजीकी प्रेरणासे वम्बईमें 'एकता'पर फिर वातचीत ग्रुरू हुई । जिसके फलस्वरूप एक सर्व-दलीय-सम्मेलनकी स्थापना की गयी और एकताकी समस्याका अध्ययन करनेके लिए एक समिति नियुक्त कर दी गयी। इस सम्मेलनमें, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा, जस्टिस पार्टी, लिवरल फेडरेशन और भारतीय ईसाइयोंके प्रतिनिधियोंने भाग लिया। जनवरी १९२५ में समितिने ४० सदस्योंकी एक प्रातिनिधिक उप-समिति नियुक्त कर दी। उप-समितिका काम था—(१) ऐसे नियमोंके बनानेकी सिफारिश करना जिनसे सब पार्टियाँ कांग्रेसमें शामिल हो सकें; (२) विधान सभाओं और निर्वाचन संस्थाओंमें सम्पूर्ण समाजों, जातियों और उप-जातियोंके प्रतिनिधित्वके लिए एक योजना बनाना; (३) स्वराज्यके लिए एक योजना तैयार करना। इस उप-समितिको भी दो छोटी कमेटियोंमें विभाजित कर दिया गया। पहली उपसमितिको विधानपर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। इसने रिपोर्ट पेश भी कर दी, परन्तु दूसरी कमेटी, जिसका काम सम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी योजना तैयार करना था, सिर्फ एक वार वैठक कर सक्ती और विना किसी निष्कर्षपर पहुँचे हुए अनिश्चित कालके लिए विस्जित हो गयी क्योंकि लाजपतराय व अन्य हिन्दू प्रतिनिधि कमेटीकी किसी भी आगामी वैठकमें भाग लेनेको तैयार नहीं थे। लाजपतराय द्वारा 'लीडर'

में प्रकाशित एक लेखने विवादको समाप्त कर दिया। लेखमें लाजपतरायने कहा था कि में यह बात नहीं मान सकता कि हिन्दू मुस्लिम एकता, सिर्फ कुछ स्वोंमें हिन्दू बहुसंख्यक और कुछमें मुस्लिम बहुसंख्यक मानकर ही हो सकती है।

अव 'राजनीतिक भारत' का मृतिनिधित्व लीग और कांग्रेस ही नहीं करती भी। व्यक्तिगत नेता गलत प्रचार करके वातावरणको और दूषित कर रहे थे। उदाहरणके तौरपर मार्च १९२५ में एक सार्वजिनक समामें भाषण करते हुए डाक्टर किचल वोले "अगर हम इस देशसे अंग्रेजी शासन खत्म कर दे और फिर यदि अफगान या दूसरे मुसलमान भारत पर आक्रमण करते हैं तो, हम मुसलमान, देशको हमलेसे बचानेके लिए अपने वेटोंतकको कुर्वान कर देंगे।" परन्तु उन्होंने एक शर्त रखी। हिन्दुओंको सम्बोधन करते हुए उन्होंने कहा "अगर तुम 'तंजीम आन्दोलन' के रास्तेमें स्कावट डालोगे, और हमें 'हमारे अधिकार' नहीं दोगे तो हम अफगानिस्तान या किसी दूसरी मुस्लिम सत्ताक साथ समान मोर्चा वनाकर इस देशमें अपना राज्य स्थापित कर लेंगे।"

इस राजनीतिक अद्यान्ति काल्में मुस्लिम लीग करीव-करीव निष्किय रही । १९२४ में वह पुनर्जीवित हुई । इसी वर्ष २० दिसम्बरको वम्बईमें रजाअलीकी अध्यक्षतामें छीगका अधिवेशन हुआ। लीगने एक प्रस्ताव द्वारा तेंतीस प्रमुख मुसलमानोंकी एक समिति मुस्लिम समाजकी राजनीतिक माँग तैयार करनेके लिए नियुक्त की । यह प्रस्ताव जिनाने पेश किया था। प्रस्ताव पेश करते समय जिनाने ''इस आरोपका खण्डन किया कि वे लीगमें साम्प्र-दायिक व्यक्तिकी हैसियतसे आये हैं। व्यक्तिगत तीरपर उन्होंने जीर दिया कि वे हमेशा राष्ट्रीयतावादी रहे हैं। उन्हें स्वयं कोई संकोच नहीं था। उनकी तो इच्छा थी कि विधान सभाओंमें उनका प्रतिनिधित्व सबसे योग्य और उपयुक्त व्यक्ति करें । परन्तु दुर्माग्यवश उनके मुरिलम देशवासी इसके लिए तैयार नहीं थे। वस्तुस्थितिकी तरफसे वे आँखें वन्द नहीं कर सकते थे। वास्तविकता यह थी कि वहत वडी संख्यामें मुसलमान विधान सभाओं और नौकरियोंमें प्रथक प्रतिनिधित्व चाहते थे। वे लोग साम्प्रदायिक एकताकी वातें करते हैं. परन्त चाम्प्रदायिक एकता है कहाँ ? उपयक्त समझौता करके ही एकता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने तालियोंकी गड़गड़ाहटमें कहा, मैं जानता हूँ कि मेरे सहधर्मा स्वराज्यके लिए ् ल्डनेको तैयार हैं परन्तु वे कुछ संरक्षण चाहते हैं। जिनाका कुछ भी दृष्टिकोण क्यों न रहा हो, और वे यह जानते थे कि एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञकी हैिस्यतसे उन्हें स्थितिको भलीभाँति समझना पहला है, एकताके रास्तेमें असली वाधा दोनों सम्प्रदाय नहीं थे विक दोनों तरफके कुछ गड़वड़ी फैलानेवाले लोग थे। 198

वंग्वई अधिवेद्यनमें स्वीकृत एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा इस वातकी इच्छा प्रकट को गयी थी कि भारतके विभिन्न मुस्लिम संघटनों और भिन्न भिन्न विचारधाराओं के प्रतिनिधि निकट भविष्यमें दिल्लीमें मुस्लिम समाजकी आवश्यकता-पूर्तिके लिए "संयुक्त और व्यावहारिक कार्योक्ती योजना वनानेके निमित्त" एक सम्मेलन करें। जिनाने यह प्रस्ताव समझाते हुए कहा कि इस प्रस्तावका उद्देश्य, मुसलमानोंको हिन्दू समाजके लड़नेके लिए नहीं, बिक्क मातृभ्भिके लिए उनसे एक होने और सहयोग करनेके लिए संघटित करना है। उन्हें विश्वास था कि

१. टाइम्स नॉफ इन्डिया ता० १४-३-२५

२. दी इण्डियन क्वाटरली रिजस्टर १९२४ माग २ पृष्ठ ४८९

यदि "वे (मुखलमान) एक वार संघटित हो जायँ तो फिर हिन्दू महासभाके साथ वे अवस्य एकता स्थापित करेंगे और संधारके सामने घोषणा करेंगे कि हिन्दू और मुसलमान भाई-भाई हैं।" लीगने 'ग्रुद्धि' और 'संघटन' आन्दोलनोंकी निन्दा की और 'तंजीम' को न्यायपूर्ण वताया। एक प्रस्ताव द्वारा अधिकारियोंकी प्रशंसा की गयी जिन्होंने जाँचके वाद घोषणा की कि कोहाटके देंगे स्थानीय हिन्दुओंकी धमाधताके कारण हुए थे।

यद्यपि जिनाने, कांग्रेसके असहयोग, सविनय अवज्ञा और परिपद-वहिष्कार आरम्भ करनेके वाद, कांग्रेस छोड़ दी थी, पर उन्होंने कांग्रेसपर हिन्दू संस्था होनेका आरोप नहीं लगाया।

वास्तवमें जब उनके विरोधियोंने उनपर इस प्रकारके वक्तव्य (कांग्रेस हिन्दू संस्था है) का आरोप लगाया तो उन्होंने उसका खण्डन किया। इसकी पृष्टि र अक्तूबर १९२५ को 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में सम्पादकके नाम प्रकाशित उनके खतसे होती है। उन्होंने पत्रमें लिखा था—''में उस वक्तव्यका, जिसका एक वारसे ज्यादा आपने मेरे नामसे प्रचार किया है और जिसको एक वार फिर आपके संवाददाताने दोहराया है, खण्डन करना चाहता हूँ (यानी कांग्रेस हिन्दू संस्था है, यह कहकर मेंने उसकी निन्दा की है)। इसके प्रकाशित होनेके फौरन बाद ही मैंने आपके पत्र द्वारा इसका सार्वजनिक रूपसे खण्डन किया, परन्तु इस 'खण्डन' को आपके पत्रने प्रकाशित नहीं किया। इसलिए में प्रार्थना करता हूँ कि कृपा कर आप इसे प्रकाशित कर दें।"

तुर्कों होनेवाली गड़बिड़वाँ अभीतक खिलाफत सम्मेलनको परेशान कर रही थीं। १९२४, १९२५ में खिलाफत सम्मेलनकी सभाओं यह निश्चय किया गया कि दुनिया-भरके मुसलमान तय करके किसी दूसरे स्थानपर खलीफाका पद स्थापित करें। सम्मेलन अमीतक कांग्रेसकी नीतिमें विश्वास करता था, यद्यपि इसके कुछ सदस्य व्यक्तिगत तौरपर साम्प्रदायिक भावना व्यक्त करने लगे थे। परन्तु तुर्कीमें परिवर्त्तनके बाद भारतमें भी खिलाफत सम्मेलन कमजोर होता जा रहा था और अन्तमें १९३२ में वह बिल्कुल ही समाप्त हो गया। परन्तु दोनों समाजोंमें कुछ समझदार नेताओंकी प्रधानता होते हुए भी साम्प्र- दायिकता बढ़ती जा रही थी। २ मई १९२५ को फरीदपुरमें एक बंगाल-मुस्लिम सम्मेलन बुलाया गया जिसकी अध्यक्षता बंगालके भृतपूर्व मन्त्री फजलुल हकने की। उन्होंने अपने श्रोताओंको चेतावनी दो कि जैसे जैसे मारत स्वराज्यको ओर बढ़ता जायेगा वैसे-वैसे हिन्दू ज्यादासे स्थादा सत्तापर एकाधिकार जमाते जावँगे। उन्होंने मुसलमानोंको उचित समयमें संघटित होकर हिन्दू महासभाकी भाँति एक संघटन स्थापित करनेको सलाह दी और कहा कि समस्त वंगालमें संघटनोंका एक जाल-सा विद्या देना चाहिये। उन्होंने मुझावं दिया कि मुसलमान नीजवानोंको शारीरिक शिक्षा देनी चाहिये।

१९२५ के मुस्लिम-लीग अधिवेदानके अध्यक्ष सर अन्दुर्रहीमने कहर साम्प्रदायिक भाषण किया । 'इस भाषणसे पूरे भारतमें उत्तेजना फेल गयी।' सर अन्दुर्रहीमने कहा ''हिन्दुओं के आक्रमणके कारण मुसलमानों को हमेद्यासे ज्यादा मुस्लिम-लीगकी आवद्यकता है। हिन्दुओंने अपने उत्तेजनात्मक और आक्रमणकारी व्यवहारसे यह हमेद्याकी विनस्वत ज्यादा साफ कर दिया है कि मुसलमान अपना भाग्य उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते, और आत्म-रक्षा के सभी सम्भव साधनों को उन्हें अपनाना पहेगा। कुछ हिन्दू नेताओंने यह भी

कहा है कि मुसलमानों को भारतसे उसी प्रकार निष्कासित कर दिया जाय जिस तरहसे रपेन-वासियोंने मूरों को निकाला था।" अन्दुर्रहोमने कहा कि विना मुसलमानों की सहायता के हिन्दू कभी स्वराज्य स्थापित नहीं कर सकते। उन्होंने यह आक्षेप लगाया कि कुछ हिन्दू विदेशी संघटनों के साथ मिलकर पड्यन्त्र रच रहे हैं। इन संघटनों का काम भारतमें उपद्रव करवाना है। उन्होंने अपने मापणमें आगे कहा कि किसी भी मुसलमानने भारतीय क्रान्ति-कारियों का साथ नहीं दिया, उन्होंने असहयोग आन्दोलनको तीव निन्दा की और जोर दिया कि "भारतके भलेके लिए अंग्रेज अधिकारियों की आवस्यकता है।"

अधिवेशनके मुख्य प्रस्तावमें शाही कंमीशनकी नियुक्तिकी माँग की गयी जो भारत सरकारके १९१९ के गवर्नमेण्ट ऑव इण्डिया ऐक्टको दुवारा ठीक करनेका काम करें। कमीश्वनसे, अल्प-संख्याकी सुरक्षा, साम्प्रदायिक-निर्वाचन-प्रणाली, पंजाव, वंगाल और उत्तरी पिश्चमी प्रान्तमें मुस्लिम बहुसंख्याको कायम रखनेके कुछ मौलिक सिद्धान्तोंकी गारण्टी माँगी गयी। कमीशनकी माँग पहले जिनाने विधान सभा भवनमें पेश की थी।

स्वराज्य पार्ट ने जिनाकी इस माँगका समर्थन नहीं किया था, क्यें कि उनका (स्वराज्य पार्ट) गोलमेज सम्मेलनकी माँगका प्रस्ताव ज्यादा अच्छा था। इस प्रस्तावमें मारतीयों और अंग्रेजोंको वरावरका पद देनेकी माँग की गयी थी। इसिलए मुहम्मदअलीन लीगकी वैठकमें संशोधन पेश किया कि 'राज्य कमीशन'के स्थानपर 'गोलमेज सम्मेलन' कर देना चाहिये। परन्तु अध्यक्षने इस संशोधनको अस्वीकार कर दिया।

वास्तवमें १९२५ में ही हिन्दू महासमा-अखिल भारत-संघटन वन सकी । ११ अप्रैलको कलकत्तेमें हुई वैठकके अध्यक्ष लाजपतरायने सभाके उद्देश्य इस प्रकार वताये—(१) देश भरमें सभाको संघटित करना । (२) साम्प्रदायिक उपद्रवोंसे पीड़ित लोगोंको सहायता देना । (३) वल पूर्वक मुसलमान वनाये गये हिन्दुओंका पुनः धर्मपरिवर्तन करना । (४) व्यायामशालाएँ संघटित करना । (५) सेवा समितियोंका संघटन यानी समाज सेवाके लिए संघटन स्थापित करना । (६) हिन्दी भाषाका प्रचार करना । (७) हिन्दू-त्योहारोंको इस प्रकार मनाना कि हिन्दुओंके विभिन्न अंगोंमें भाईचारा और सौहार्द्र वढ़े । (८) मुसलमानों और ईसाइयोंके साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना । (९) तमाम राजनीतिक विवादोंमें हिन्दुओंके साम्प्रदायिक हितोंका प्रतिनिधित्व करना ।

हजारोंकी संख्यामें हिन्दुओंके, विशेषतया, वंगाल, विहार, आसाम, गुजरात और सीमाप्रान्तमें वलपूर्वक धर्मपरिवर्तन किये जानेसे, महासभा बहुत चिन्तित और व्यव्र हो उटी । इस प्रकारसे हिन्दुओंके अन्य धर्मोंमें चले जानेसे रोकनेके लिए महासभाने एक 'हिन्दू रक्षक संय' स्थापित करनेका निश्चय किया । कुछ समय वाद हिन्दू महासभाने आम चुनावमें अपने उम्मीदवार खड़े करनेका फैसला किया ।

१९२६ के आरम्भमें मॉण्टफोर्ड सुधारोंके अन्तर्गत उत्तरो पश्चिमी सीमाप्रान्तमें विधान परिपद कायम करनेके प्रश्नपर विना जरूरत साम्प्रदायिक कटुता वढ़ गयी।

इस कहताका स्त्रपात १९२२ में हुआ जब कि भारत सरकारने, सीमाप्रान्तको पंजाबमें मिला देनेके ओचित्यके प्रश्नपर व्यक्त की गयी सम्मितियोंसे यह निष्कर्प निकला कि "साबारणतया पंजाब और उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्तके हिन्दू सीमाप्रान्तके प्रंजाबमें विलीनी-

१. इण्डिया इन १९२५-२६ पृष्ट ७८

करणके पक्षमें थे, परन्तु मुसलमान इन दोनों प्रान्तोंकी स्वतन्त्र इकाइयोंके इच्छुक थे। मामला १९२६ की मार्चतक यूँ ही पड़ा रहा। मार्चमें मद्रासके एक मुस्लिम नेता सैव्यद्मुर्तजाने जो मुस्लिम लीगमें थे और विधान-परिषदमें स्वराज्य पार्टीके साथ थे, केन्द्रीय सभामें एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें माँग की गयी थी कि गवर्नर जनरल भारत सरकारके १९१९ के ऐक्टके विधान परिपदों, मन्त्रियोंकी नियुक्ति, और अल्प संख्याके सुरक्षा सम्बन्धी उपवन्धोंको सीमाप्रान्तपर भी लागू करें। विपिनचन्द्र पालने इस प्रस्तावका समर्थन करते हुए कहा कि सीमान्त प्रान्तके हिन्दुओंको चाहिये कि वे उस प्रान्तमें मुसलमानोंका वहुमत उसी प्रकार अंगीकार कर लें जैसे मुसलमानोंने हिन्दू बहुसंख्यक प्रान्तोंमें कर लिया है, परन्तु मालवीयजो, सर हरीसिंह गोंड, दीवान बहादुर रंगाचारियर जैसे प्रधान हिन्दू नेताओंने इसका विरोध किया। मालवीयजीका विरोध राजनीतिक महत्त्व रखता था क्योंकि वे एक प्रमुख महासभाई थे। उन्होंने सुझाव दिया कि १९२९ में नियुक्त होनेवाले शाही कमीशनके ऊपर यह प्रश्न छोड़ देना चाहिये। मुस्लिम-मत भी इसके ऊपर एक-राय नहीं था। उदा-हरणके तौरपर-नवाव अन्दुल कथूम प्रस्तावका अनुमोदन करते हुए भी, सीमाप्रान्तके लिए सिर्फ 'सलाइकार सिमिति' को वेहतर समझते थे।

हिन्दू लोग सीमाप्रान्तका पंजावमें विलयन क्यों चाहते थे ! इसका जवाव साफ तौर-पर यह मालूम पड़ता है कि वहाँ वे ५% की नगण्य संख्यामें थे और पंजावमें, जहाँ हिन्दू आवादी के करीव ५०% थे, विलयनके वाद भी ४०% हो जाते । परन्तु सरकारकी कोई इच्छा सीमाप्रान्तमें सुधारयुक्त परिषद् (रिफार्म्ड कोंसिल) जारी करनेकी नहीं थी, क्योंकि वहाँ वरावर फौजी निगरानीकी आवश्यकता रहती थी और अंग्रेज सीमाप्रान्तके लिए किसी भी प्रजातान्त्रिक संस्थाको खतरेसे खाली नहीं समझते थे । इस प्रश्नपर उस समय हिन्द-मुस्लिम विवाद व्यर्थ ही खड़ा हो गया ।

१९२५ और १९२६ में साम्प्रदायिक तनातनीने बढ़कर गम्मीर रूप घारण कर लिया ! यू० पी०, सी० पी०, वम्बई और कलकत्ता, हर जगह भीषण दंगे हुए और अपार धनजनकी हानि हुई । अप्रैल १९२६ में कलकत्ते में फिर दंगा हुआ । मुसलमान हिन्दू मन्दिरोंपर हमला कर रहे थे और हिन्दू मस्जिदोंपर । दंगा ५ अप्रैलको ग्रुरू हुआ और पिछले तीन दिनोंमें ही ११० आगजनीकी घटनाएँ हुई । सरकारी रिपोटोंके अनुसार ४४ आदमी मरे और ५८४ जरुमी हुए । दंगेका दूसरा दौरा अधिक भयानक था और पुल्सिको भीड़ तितर वितर करनेके लिए वारह दफा गोली चलानी पढ़ी। इस मर्तवा ६६ मरे और ३९१ घायल हुए । दंगोंकी खबरें अखवारोंके जरिए देशके एक कोनेसे दूसरे कोनेतक पहुँचीं, जिससे जनता विशेषतया साम्प्रदायिक संघटनोंसे सम्बन्ध रखनेवाले लोगोंका मानसिक सन्तु-लन विगड़ गया । दंगा खत्म होनेके कुछ ही समय वाद खिलाफत सम्मेलन और हिन्दू महासभा दोनोंने अपनी अपनी वैठकें कीं। खिलाफत सम्मेलनकी वैठक ९ मईको हुई जिसमें उसने अपनी नीति वदलनेका निश्चय किया। नीतिपरिवर्त्तनपर एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कहा गया कि खिलाफतकी जगहपर भारतीय मुसलमानोंकै घामिक, शिक्षासम्बन्धी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्नोंको महत्त्व दिया जायगा l एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा खिलाफत संघटनोंको भारतीय मुसलमानोंकी नैतिक, आर्थिक और .. अदालत-सम्बन्धी मदद देनेकी सलाह दी थी। सम्मेलनमें इतनी उत्तेजना थी कि जब एक

सदस्यने हिन्दुओंको 'भाई' कहकर सम्बोधित किया तो श्रोताओंके एक हिस्सेमें हुछड़ मच गया और माँग की गयी कि 'माई' शब्दको वापस लिया जाय क्योंकि काफिरोंके लिए इस शब्दका इस्तेमाल आपित जनक है। खिलापत सम्मेलन राष्ट्रीय धाराप्रवाहसे निश्चित रूपसे हट गया । १० मईको राजा नरेन्द्रनाथके सभापतित्वमें हुई महासभाकी बैटकमें कुछ मुसल-मानी द्वारा आर्यसमाजियोंके जुदुसीं, मन्दिरीं और गुरुद्वारींपर किये गये आक्रमणींकी धीर निन्दा की गयी और इनको अन्यायपूर्ण तथा अनुचित बताया गया। अन्दुल रशीद नामक मुसल्मान द्वारा २३ दिसम्बर १९२६ को चग्ण-शय्यापर पहे स्वामी अद्धानन्दकी इत्या हो जानेसे हिन्द-मुस्लिम वैमनस्य तथा विद्वेप और ज्यादा वढ़ गया । स्वामी श्रदानन्द उस समय अपनी लोकप्रियताके शिखरपर थे। वे कई मुसल्मानोंको, विशेपतया यू. पी. के राजपृत मुसलमानोंको पुनः हिन्दू धर्ममें वापस हे आये थे। मुसलमान उनके कार्यों और उनकी पत्रिका 'लिबरेटर' में प्रकाशित लेखोंको अपने धार्मिक प्रभावपर हमलावर मानते थे। इनके हत्यारेपर मुकदमा चला और उसे फाँसी दे दी गयी। ३० नवम्बर १९२७ के 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' के अनुसार देववन्दके प्रसिद्ध, थियोलॉजिकल कॉलेजके समस्त विद्यार्थियोंने पूरे पाँच दफा 'कुरान' पट्कर सिजदा किया और प्रार्थना की कि अब्दुल रशीदको जन्नतमें शान्ति मिले। रिपोर्टके अनुसार उन लोगोंने प्रार्थना की कि "या पाक परवरदिगार, मृतात्माको 'ऐ अल्ला-ए.-इल्लयीन' (सातवें विहिन्त) में एक जगह मिले।"

हत्यांके कुछ दिनों वाद एक पंजावी मुसलमान अब्दुल कादिर, जो पंजाव विधानपरिपदके अध्यक्ष भी रह चुके थे, की अध्यक्षतामें दिल्लीमें लीगका वार्षिक अधिवेदान हुआ।
उन्होंने 'हत्या' की निन्दा की और कांग्रेस-लीग एकेकी आवश्यकताका महत्त्व वतलाया।
उन्होंने कहा कि दोनों संघटनोंको एक साथ मिलकर मौजूदा विषम परिस्थितिको मुलझाना
चाहिये। छिटफुट दंगे हो ही रहे थे कि कुछ प्रभावशाली मुसलमानोंने जिनमें अधिकांशतः
केन्द्रीय सभाके सदस्य थे, मार्च १९२७ को दिल्लीमें इस प्रश्नपर गीर करनेके लिए कि क्या
पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचनकी जगह संयुक्त निर्वाचन लागू किया जा सकता है, एक सभा
की। सम्मेलनने ये निर्णय किये—(१) सिन्धको वम्बई प्रेसीडेंसीले अलग कर एक
पृथक प्रान्त बना देना चाहिये। (२) उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्त और वलोचिस्तानमें
कौरन शासन-सुधार किये जावँ। (३) अगर ऊपर लिखी हुई दोनों वातें हिन्दू स्वीकार
करें तो संयुक्त निर्वाचन पद्धति मुसलमानोंको मान्य होगी। (४) पंजाब और वंगालमें
प्रतिनिधित्व जनसंख्याके अनुपातपर होना चाहिये और केन्द्रीय विधान सभा तथा
परिपदमें मुस्लिम सदस्य संयुक्त निर्वाचन हारा चुने हुए सदस्योंकी संख्याके कमसे कम

अभी अखवारोंमें ये पेसले छपनेको दिये ही गये थे कि सम्मेलनमें उपस्थित मुसल-मानोंमेंसे दो-एकने इन पैसलोंसे अपनेको अलग करते हुए वक्तस्य दे दिये। परन्तु जिनाने एक वक्तत्य द्वारा माँग की कि या तो कुल सुझाव स्वीकार किये जादें या कुल रद कर दिये जावें।

मुस्लिम-सम्मेलनके तीन दिन बाद केन्द्रीय विधान समाके कुछ हिन्दू सदस्थोंने इन मुझाओंपर गौर करनेके लिए दिल्लीमें एक वैटक की । इस वैटकमें आगे वातचीतके लिए निम्नलिखित सिद्धान्त तय कर दिये । (१) भारतमें प्रत्येक विधान-समा और परिपदके लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनाव हो। (२) हर जगह जन-संख्याके अनुपातसे सीटें सुरक्षित की जायँ। (३) विधानमें निश्चित उपवन्धों द्वारा धार्मिक और अर्दे धार्मिक अधिकारोंकी रक्षाकी जाय। प्रान्तोंके विभाजनका प्रश्न फिलहाल यूँ ही छोड़ दिया जाय।

महासभाने भी इन सुझावोंपर गौर किया परन्तु कोई सम्मित नहीं व्यक्त की। उसका मत था कि सुझाव अभी परिषक्व नहीं है। परन्तु मईके मध्यमें वम्बईमें हुई अखिल भारतीय कांग्रेस महासमितिको बैठकने कुछ साधारणसे परिवर्तन करके (जिनसे मीलिक सिद्धान्तमें कोई अन्तर नहीं पड़ा) ये सब सुझाव सर्वसम्मितिसे स्वीकार कर लिये। कुछ हिन्दू कांग्रेसजनोंने इस स्वीकृतिपर आपत्ति की। जुलाईके अन्तमें स्थानीय स्वायत्त शासन विभागके मन्त्री मिलिक फीरोज खाँ नूनके नेतृत्वमें पंजाब विधान परिषद्के कुछ मुसल मानोंने, एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमें कहा गया कि जवतक हिन्दू-मुस्लिम दोनों समाजोंकी सम्मित न हो, पृथक निर्वाचन पद्धति कायम रखी जाय।

वीच-वीचमें हिन्दू-मुसलमान दंगे हो रहे थे। अप्रैल और दिसम्बर १९२७ के बीचमें वीस दंगोंकी रिपोर्ट आयी। यू. पी. में दस, वम्बईमें छः, और पंजाव, सी. पी., विहार, वंगाल उड़ीसामें दो दो और दिल्लीमें एक दंगा हुआ। नेतावर्ग अभीतक एकताकी कोशिश कर रहा था। जिनाके नेतृत्वमें केन्द्रीय विधान सभाके हिन्दू और मुसलमान सदस्य व कुछ अन्य लोगोंका एक सम्मेलन शिमलामें बुलाया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस महासमितिके तत्वाधानमें यह सम्मेलन कलकत्त्में अक्तूबरमें फिर हुआ। लम्बी वहसके बाद सम्मेलनने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें हिन्दुओंको अधिकार दिया गया कि वे मिरजदोंके सामने जुलूस निकाल सकते हैं, वाजा बजा सकते हैं, पर वहाँ रक नहीं सकते और इसी तरहसे मुसलमानोंको यह अधिकार दिया गया कि मुसलमान गो-वध तो कर सकते हैं, पर वे मन्दिरोंके नजदीक या सड़कोंपर गो-वध नहीं करेंगे। सम्मेलनने स्वेच्छासे या समझा बुझाकर विना बल-प्रयोगके धर्मपरिवर्तन अथवा पुनः धर्मपरिवर्तनका अधिकार मी दे दिया, परन्तु १८ वर्षकी उम्रके अन्दरवालोंके धर्म-परिवर्तनका पूर्ण निषेध कर दिया।

अबदूबर १९२७ के अन्तमें या नवग्वरके आरम्भमें भारतके प्रमुख राजनीतिक नेताओं को वाइसराय भवनसे एक रहस्यमय निमन्त्रण मिला जिसमें लिखा था कि वे ५ नवम्बर या उसके वाद शीध ही वाइसरायसे मिल छें। गान्धीजी उस समय दिल्ली से १००० मील दूर मंगलोरमें थे। उन्होंने यात्राका कार्मक्रम स्थिगत कर दिया और फौरन ही दिल्लीको रवाना हो गये। वाइसराय इरिवनने उनके हाथमें भारत-सचिव द्वारा १९१९ ऐक्टके अन्तर्गत प्रशासन और अन्य सम्वन्धित विषयोंकी जाँचके लिए वैधानिक कमीशनकी नियुक्तिकी घोषणाकी एक अग्रिम प्रति रख दी। गान्धीजीने वाइसरायसे पूछा कि क्या केवल इतना हो काम था जिसके लिए आपने मुझे बुलाया था १ इरिवनने कहा—"हाँ।" गान्धीजीने इसके प्रतिक्रियास्वरूप उत्तर दिया कि यह एलान तो इक्कीवाला लिफाफा भी उनके पास पहुँचा सकता था। पार्लमेण्ट और भारतमें ८ नवम्बरको यह घोषणा कर दी गयी। -१९१९ के ऐक्टमें इस कमीशनकी

१. इण्डिया-इन १९२७-२८ पृष्ठ २०

नियुक्तिका वादा किया गया। यों यह कमीशन १९२९ में नियुक्त होनेवाला था परन्त वैधानिक सुधारींकी लगातार माँगके कारण सरकारने इसे दो वर्ष पूर्व ही नियुक्त कर दिया ! परन्त अब कमीशनकी नियक्ति लोगोंके लिए एक महत्त्वहीन चीज हो गयी, क्योंकि कांग्रेस और केन्द्रीय विधान समाने गोलमेज सम्मेलन (राउण्ड टेड्रल कानफ्रेंस) की माँग की थी, जिसमें भारतीयों और अंग्रेजों दोनोंके प्रतिनिधि शामिल हों। सर जान साइ-मनकी अध्यक्षतामें काम करनेदाले इस कमीशनमें सात सदस्य थे और वे सबके तब अंग्रेज थे। कुछ तो इसी कारण और कुछ दूसरी दलहांने, पूरे देशमें कमीशनकी घोर निन्दा की गयी । मित विलिकिन्सनके अनुसार जालियाँवाला बागकी दुखान्त घटनाके बाद सारे देशमें जितनी इस कमी शनकी निन्दा की गयी उतनी अंग्रेजों के और किसी कामकी नहीं हुई। सब भारतीय अखवारीं और सब राजनीतिक विचारींके लोगीने एक स्वरते इस कमीशनको भारतीय राष्ट्रका अपमान वतलाया क्योंकि इसमें भारतीय प्रतिनिधि शामिल नहीं किये गये थे। मगर जयकर, केलकर, अणे और मुझे जैसे 'सहयोगी' नेताओंने कहा कि यदि भारतमं पुरक समिति (सप्लीमेण्टरी वाडी) की हैस्वितसे नियुक्त की जानेवाली 'इण्डियन कमेटी' की शतें सन्तोपजनक हों तो वे लोग सहयोग देनेको तैयार हैं। उनके अतिरिक्त सब राजनीतिक पार्टियोंने वमीशनका वहिष्कार करनेका निरुचय किया । दिसम्बर-के अन्तिम सप्ताहमें वस्वईमें राष्ट्रीय उदारदलीय नंघके दसवें अधिवेशनमें अध्यक्षपदसे भाषण करते हए सर तेजबहादुर समृने कहा कि उदारदल (लिवरल पार्टी) को न सिर्फ कमीशन-को अमान्य टहराना चाहिये विवक पार्लमेंट हारा भारतकी वैधानिक प्रगतिके प्रस्तपर पद्धित भावनाका भी विरोध करना चाहिये । हिन्दू महासभाके अधिवेशनमें भी इसी प्रकार-की भावना व्यक्त की गयी । परन्तु लीगके अन्दर वहिष्कारके प्रक्तपर फूट हो गयी । जिना वहिष्कार करना चाहते थे, परन्तु उस सालके मनोनीत अध्यक्ष सर मुहम्मद शकी तहयोग करनेके पक्षमें थे । लीगकी कार्यकारिणीने लाहौरमें वार्षिक अधिवेशन करनेका निरुचय किया । था, परन्तु बादमें कार्यकारिणीने एक विशेष मीटिंगमें तय करके यह स्थान बदलकर कलकत्ता कर दिया । सर सुहम्मद शफीने इस स्थान-परिवर्तनकी वैधानिकतापर आपत्ति की, और कल-कत्ता अधिवेशनकी अध्यक्षतामे इनकार कर दिया। इस झगड़ेमें लीगके दो अधिवेशन हुए— एक लाहीरमें और दूसरा कलकरोमें । लाहीर अधिवेदानमें स्वीकृत एक प्रस्तावमें कमीदान या अंग्रेजी पार्लमेण्टके सामने पेश करनेके लिए भारतका संविधान बनानेके लिए सब गैर-मुस्लिम जातियोंसे लीगके साथ सहयोग करनेकी प्रार्थना की गयी । अन्य प्रत्तावों द्वारा प्रथक निर्वाचन, सिन्धको बम्बईते थलन करने और उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्त और बलोचिस्तान-में सुघारोंकी माँग की गयी थी । छीगने भारतका उंतिधान बनाने और उसपर दूसरी पार्टियोंके साथ मिलकर गौर करनेके लिये ३० आदमियोंकी एक समिति बना दी। इस अधिवेदानमें भाग ढेनेवाढे प्रतिनिधियोमें वर मुहम्मद इकवाढका नाम उल्लेखनीय है। उनी वर्षके अन्तमें लगभग लाहीर अधिवैदानके समकालीन कलकत्तेमं लीगका अधिवेदान जिनाकी अध्यक्षतामें हुआ । यह अधिवेशन कमीशनके वहिष्कारके पक्षमें था । कलकत्ते में हिन्दू-मुस्लिम एकतापर ु भी जोर दिया गया । एक प्रस्तावमें कहा गया कि वर्तमान समयमें पृथक निर्वाचन अनि-वार्य है, परन्तु चाथ ही मुखलमान छंयुक्त निर्वाचनके लिए तैयार हो बादँगे यदि इसके लिए चीटें सुरक्षित कर दी नार्वे, परन्तु शर्त्त यह है कि सीमान्तप्रान्त और यहोचिरतानमें भी

शासन सुधार किये जायँ और सिन्धको एक अलग स्वा मान लिया जाय। कलकत्ता अधिनेशनने विना मुकदमा नजरवन्द किये गये लोगोंकी रिहाईकी माँग की। लीग अधिवेशनमें लीगकी कोंसिलको एक कमेटी नियुक्त करनेका आदेश दिया। इस कमेटीको अन्य राजनीतिक दलों और कांग्रेससे परामर्श करके संविधान बनाने तथा उसमें मुसलमानोंके अधिकारोंकी यथोचित सुरक्षा करनेका काम सौंपा गया। कलकत्ता अधिवेशनमें पंजाब मुस्लिम लीगके मंत्री बरकत अलीने भी भाग लिया। बरकत अलीने जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, सन् १९३० में भारतके विभाजनका जोरदार विरोध किया, परन्त बादमें पाकिस्तानके कष्टर समर्थक बन गये।

उसी वर्ष मद्रासमें एम. ए. अन्सारीकी अध्यक्षतामें हुए कांग्रेसके अधिवेशनमें निश्चय हुआ कि हर तरहसे और हर स्तरपर कमीशनका विहिष्कार किया जाय; जिस दिन यह कमीशन बान भारतमें आये उस दिन देश भरमें विरोध प्रदर्शन किये जायें, जहाँ यह कमीशन जाय वहाँ उसका विह्कार किया जाय और इस विह्कारको प्रभावशाली और सफल वनानेके लिए जोरदार प्रचार किया जाय। विधान संस्थाओं के निर्वाचित सदस्योंको कमीशनकी सहायता करनेसे इन्कार कर देना चाहिये और मिन्त्रमण्डलको हटाने या कमीशनके विह्कारको छोड़ कर सदस्योंको विधान संस्थाओंको किसी भी अन्य वैठकमें सिम्मिलत नहीं होना चाहिये। मद्रास अधिवेशनका विशेष महत्त्व है। इसी अधिवेशनमें, प्रथम वार भारतका लक्ष्य—पूर्ण स्वतन्त्रता घोषित किया गया। यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरूने पेश किया था। जवाहरलाल अभी अपनी यूरोप और कसकी यात्रासे लौटे थे और उन्होंने प्रतिनिधियोंको 'कॉमरेड' कहकर सम्बोधन किया। मई १९२७ में चार सालकी कैदके वाद सुभाषचन्द्र वसु भी जेलसे छूटे थे।

तीन साम्प्रदायिक पार्टियोंने, जिनका प्रभाव बहुत अधिक न था, कमीशनके साथ सहयोग करनेका निश्चय किया । ये पार्टियाँ-जिस्ट्स पार्टी, अखिल भारतीय अछृत फेडरेशन और केन्द्रीय सिख संघ थीं । इन्होंने निश्चय किया कि ये कमीशनके सामने अपने साम्प्रदायिक दावे रखेंगी।

सन् १९२७ के लीगके कलकत्तेवा अधिवेशनमें अध्यक्ष-पदिने भाषण करते हुए अबुल कलाम आजादने 'दिल्लीके प्रस्तावों 'की प्रशंसा की और 'लखनफ समझौते' की निन्दा । उन्होंने मुसलमानोंसे कहा कि "लखनफ समझौते' से उन्होंने अपने हितोंको वेच दिया था । गत मार्चके दिल्ली प्रस्तावोंसे प्रथम वार भारतमें मुसलमानोंके वास्तविक अधिकारोंको मान्यता मिलनेका अवसर मिला है । १९१६ के समझौतेमें 'पृथक्-निर्वाचन' द्वारा उनका प्रतिनिधित्व तो अवश्य प्राप्त हो गया, परन्तु मुस्लिम-समाजके अस्तित्वके लिए उनकी संख्या-शक्तिको मान्यता मिलनी आवश्यक है । दिल्लीने वह रास्ता दिखाया है जिससे आगे चलकर भारतमें मुसलमानोंको उचित हिस्सा मिलनेकी गारण्टी मिल सके । पंजाव और वंगालमें छोटे अनुपातमें उनका बहुमत जनमतगणनाकी संख्यामात्र है, परन्तु दिल्ली-प्रस्तावों द्वारा उनको पहली वार पाँच सुवे मिलते हैं, जिनमेंसे तीन (सिंध, सीमाप्रान्त और वलोचिस्तान) में मुसलमानोंका भारी बहुमत है । यदि मुसलमान इस वातका महत्व नहीं समझते तो वे जिन्दा रहनेके काविल नहीं । नौ हिन्दू प्रान्तोंके मुकावलेमें पाँच मुस्लिम प्रान्त होंगे और हिन्दू-मुसलमानोंक साथ जो भी व्यवहार इन नौ सुवोंमें करेंगे वही मुसलमान हिन्दुओंके साथ अपने पाँच

स्वोंमें करेंगे क्या यह भारी विजय नहीं है ? क्या मुसलमानोंकें हाथ अपने अधिकारींपर जोर देनेके लिए एक नया हथियार नहीं लगा है ?"

उधर भारत सचिव लार्ड वर्कनहेड भारतके राजनीतिक दलों में फूट डालनेके लिए साइमन कमीशनका इस्तेमाल करनेकी कोशिश कर रहे थे। १० दिसम्बर १९२५ को उन्होंने वाइसरायको लिखा कि "विद आप कमीशनका इस्तेमाल राजनीतिक सौदा करने या स्वराज्य पार्टीमें और अधिक फूट डालनेके लिए कर सकें "और यदि इस इस्तेमालसे आपको राजनीतिक सौदा करनेमें कोई मदद मिल सके तो आप जरूर करें और सरकार आपकी सहा-यता करेगी।"

कमीशनकी नियुक्तिकं साथ जब भारतीय राजनीतिक दलोंने उसका बहिष्कार करनेका निश्चय किया तो उन्होंने वाइसरायको लिखा "बहिष्कारकी मनोवृक्तिका मर्दन करनेके
लिए हम लोग हमेशा सहयोगके लिए मुसलमानों, अछ्तों, व्यापारी वर्ग तथा अन्य लोगोंपर
निर्भर रहे हैं। आप स्वयं और साइमन इस बातका सबसे अच्छा निर्णय कर सकते हैं कि
आप इस दिशामें आगे बढ़ं और विरोधकी दीवारको कमीशनके इस दौरेमें भी तोड़नेकी
कोशिश करें।" वकनंहेडकी आखिरी सलाहने उनका रुख विलक्कल स्पष्ट कर दिया।
फरवरी सन् १९२८ में उन्होंने लिखा कि "मेरी साइमनको यह सलाह है कि वे हर
स्तरपर कमीशनका विह्फार न करनेवाले प्रमुख लोगों, विशेषतया मुसलमानों और
अछ्तांसे मिलते रहें। में प्रतिनिधि माने जा सकनेवाले मुसलमानोंके साथ उनकी प्रत्येक
मेंटका बहुत अधिक प्रचार करना चाहता हूँ। इससे नीति स्पष्ट हो जाती है। नीतिका
उद्देश बृहत हिन्दू जन-संख्याके दिलोंमें यह डर बैठाना है कि मुसलमानोंने कमीशनपर
प्रभाव डाल लिया है और सम्भव है कि कमीशन पूरे तरीकेसे एक हिन्दू-हित विरोधी
रिपोर्ट पेश करे, जिससे मुसलमान कमीशनकी पूरी सहायता करें और जिनाका नेतृत्व
स्थापित हो जाय।"

यह कमीशन ३ फरवरी १९२८ की वम्बई पहुँचा । कार्यक्रमके अनुसार कई शहरों में हड़तालें हुई । वम्बईमें प्रदर्शन अधिक सफल नहीं रहा लेकिन मद्रासमें कमीशन-विरोधी प्रदर्शनांपर कई वार गोली चलायी गयी। कई मरे और बहुतसे घायल हुए। लाहीरमे लाजपत-रायके नेतृत्वमें कमीशनके विरुद्ध प्रदर्शन करनेके लिए एक बड़ी भीड़ इकटी हो गयी। पुलिसने भीड़पर लाटी और उण्डे चलाये। लाजपतरायको भी बहुत सख्त चोट आयी "और ऐसा विस्वास किया जाता है कि उनकी मौत इन चोटोंके कारण और जल्दी हो गयी।" लखनऊ में भी पुलिसने प्रदर्शनकारियोंपर लाटी और उण्डे चलाये। आहत व्यक्तियोंमें जन्नाहरलाल नेहरू भी थे। प्रदर्शन कई दिनोंतक चल्ते रहे और प्रा शहर युद्ध क्षेत्रना मालूम होता या। हथियारवन्द पुलिस और युद्ध कार्यकार पुलिस चाहरकी सड़कोंपर गन्नत लगाती और प्रदर्शनकारियोंपर हमले करती रही। "साइमन वापस जाओ" कहनेके अपराधपर पुलिसने घरों में वुस-वुसकर इमले किये, संभ्रांत राष्ट्रीय कार्यकर्ताओंको मारा और गिरफ्तार किया। लेकिन

१. वर्कनहेड, दि लास्ट फेज, भाग २--- पृष्ठ २५

२. वहीं पुस्तक, पृष्ठ २५४

३. वहीं पुस्तक, पृष्ट २५५

४. पट्टाभी, दि हिस्टरी आव नैशनल कांग्रेस, पृष्ठ ३२०

लखनऊके ताल्डुकेदारोंने केसरवाग वारादरीमें कमीशनको एक दावत दी। विह्ध्कार करने वालोंको दूर रखनेके लिए कैसरवाग वारादरीके चारों तरफ हजारोंकी संख्यामें पुलिसका पहरा था। लेकिन दावत शुरू होनेके साथ ही प्रदर्शन शुरू हो गया। गुन्त्रारे और पतंगें जिनपर 'साइमन वापस जाओ', 'भारत भारतीयोंके लिए हैं' लिखा हुआ था, वारादरीके ऊपर छा गये। पटनामें ५०००० लोगोंका साइमन-विरोधी प्रदर्शन हुआ। दिल्लोमें, जहाँ कमीशन सबसे पहले गया था, बड़ी संख्यामें लोगोंने 'साइमन वापस जाओ'के लिखे हुए पोस्टर लेकर कमीशनके विरोधमें पदर्शन किया।

साइमनने जिनको भारतीय विरोधका पहलेसे ही आभास था, भारतमें पहुँचनेकै फीरन बाद ही बाइसरायको स्चित कर दिया था कि कमीशनके सात अंग्रेज सदस्य केन्द्रीय विधान सभा द्वारा नियुक्त किये जानेबाले सात भारतीयोंके साथ मिलकर एक संयुक्त सम्मेलनकी खुली शक्ल अख्तियार कर लेंगे। भारतीय नेताओंने इस प्रस्तावको अवज्ञाके साथ उकरा दिया। लाजपतरायके पेश करने पर केन्द्रीय विधान सभाने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया कि कमीशन और उसकी योजना विधान सभाको विलक्कत ही असान्य है।

पूरी जिम्मेदार सरकार और अल्पमतके लिये उपयुक्त सुरक्षाओं के आधारपर मारतका विधान वनानेके लिए भारतीय नेताओंने फरवरी १९२८ में एक सर्व-दलीय सम्मेलन . किया । तीन महीनोंमें सम्मेलनकी पचीस वैठक हुई । काफी कठिन परिश्रमके वाद १८ मई-को मोतीलाल नेहरूके सभापतित्वमें पहली जुलाईतक भारतका विधान बनानेके लिए एक समिति नियुक्त कर दी गयी । अगस्तमें सम्मेलनने २८ अगस्तसे ३१ अगस्ततक लख-नऊमें इस रिपोर्टपर विचार किया । नेहरू-समितिकी रिपोर्ट और सम्मेलनके संशोधनोंके वाद जो भारतीय-विधानकी रूपरेखा वनायी गयी वह इस प्रकार है। "भारतमें इस प्रकार-की सरकार होनी चाहिये जिसकी कार्यकारिणी जननिर्वाचित और पूर्णाधिकारसम्पन्न विधान सभाओं के प्रति उत्तरदायी हो; यानी उसकी हैसियत किसी प्रकार भी स्वशासित उपिन्वेशसे कम न हो । अगर जाँचके वाद यह माल्म पड़े कि नया प्रान्त आर्थिक रूपसे स्वावलम्बी होगा तो सिन्धको पृथक प्रान्त बना देना चाहिये। विधान सभाओंके लिए संयुक्त निर्वाचन हो । केन्द्रीय विधान सभा और ऐसी प्रान्तीय विधान सभाओंमें जहाँ मुसलमान अल्पमतमें हैं, उनकी संख्याके अनुपातमें उनकी सीटें मुरक्षित रखी जायँ और उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्तमें हिन्दुओं के लिए । परन्तु मुसलमानों व अन्य-अल्पमतों को यह अधिकार रहेगा कि वे 'सुरक्षित-सीटों' के अतिरिक्त भी चुनावोंमें खड़े हो सकें। अगर वयस्क मता-विकारके आधारपर चुनाव किये जायँ तो पंजाब और वंगाल (मुस्लिम बहुसंख्यक स्वों) में सीटें सुरक्षित नहीं रखी जावँगी । इन दो सूत्रोंके वारेमें निश्चय किया गया कि यदि हमारी प्रस्तावित योजनापर १० सालतक अमल करनेके वाद कोई सम्प्रदाय चाहता है तो साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके प्रश्नपर पुनः विचार किया जायगा । केन्द्र और प्रान्तोंमें भी दस सालके वाद सुरक्षित स्थानोंकी पद्धति समाप्त कर दी जायगी।"

सम्मेलनमें सम्मिलित प्रतिनिधियोंपर दृष्टि डालनेसे माल्म हो जायगा कि इसमें सब प्रमुख और महत्व रखनेवाले राजनीतिक दल और हित शामिल ये और उन्होंने सम्मेलनके पैसलोंको स्वीकार कर लिया था। राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय उदारदल फेडरशन, मुस्लिम लीग, केन्द्रीय सिख लीग, होमरूल लीग, ऑल-इण्डिया कॉन्फ्रेन्स ऑफ इण्डियन किश्चियनस, जमैयतुल-उलेमा, ऑल इण्डिया स्टेट्स कान्य्रेन्स, विधान समाको कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी, हिन्दू महासभा, अवधका आंग्ल भारतीय संघ (ब्रिटिश इण्डियन ऐसोसियेशन आव अवध) कलकत्तेका भारतीय संघ (इण्डियन ऐसोसियेशन), महाराष्ट्रका चेम्बर ऑफ कॉमर्स, सिन्ध नेशनल लीग, दक्षिण सभा और स्वाधीन भारत संघके प्रतिनिधियोंने इस सम्मेलनमें भाग लिया था। सम्मेलनने नेहरू समितिको इस रिपोर्टको एक विधेयककी शक्ल देनेके लिए फिर नियुक्त किया और निश्चय किया कि इस सम्मेलनमें सम्मिलित व अन्य सभी राजनीतिक, व्यापारिक और मजदूर व अन्य संघटनों (जो देशमें वंक्षीमान हैं तथा जिनको स्थापित हुए कमसे कम दो वर्ष हो गये हैं) के प्रतिनिधियोंकी एक राष्ट्रीय सभा (नेशनल कॉनवंशन) दिसम्बर २२ को कलकत्ते में बुलायी जाय और उसमें नेहरू समिति द्वारा तैयार किया हुआ विधेयक पेश किया जाय। विभिन्न राजनीतिक व दूसरे संघटनोंको निमन्त्रण-पत्र मेज दिये गये।

इसी वीचमें मुस्लिम लीगके कुछ सदस्य नेहरू-रिपोर्टका विरोध संघटित करने लगे।
आगामी वर्षके लिए अध्यक्ष चुनने के लिए लीगकी परिपदकी बैठक जिनाके सभापित्वमें
नवम्बरमें हुई। सदस्य दो हिस्सोंमें वॅटे हुए थे। अवधके राजा महमूदाबादके नेतृत्वमें एक
दल नेहरू रिपोर्टके पक्षमें था और शोकतअलीके नेतृत्वमें दूसरा दल विरोधमें। १७ वोटोंके
मुकाबलेंमें ४२ घोटोंसे राजा महमूदाबादको अध्यक्ष निर्वाचित करवाके नेहरू रिपोर्टके
पक्षवालोंकी जीत हुई। दूसरे दलके उम्मीदबार मुहम्मदअली हार गये। दिसम्बरमें लीगके
वार्षिक अधिवेशनसे पहले पंजाब, बिहार और बंगालकी प्रान्तीय लीग कमेटियोंने नेहरूरिपोर्टका समर्थन करते हुए प्रस्ताव पास किये परन्तु वम्बईमें, जहाँ शौकतअलीकी प्रधानता
थी, यह रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गयी। मुस्लिम लीगके अधिवेशनमें इस रिपोर्टवर काफी
लम्बी बहस हुई परन्तु कोई फैसला न किया जा सका। अन्तमें यह निश्चय किया गया कि
मार्च १९२९ में होनेवाले विशेष अधिवेशनतक इसपर विचार स्थिगत कर दिया जाय।
फिर भी लीगने राष्ट्रीय सभा (नेशनल कॉनवेशन) में भाग लेनेके लिए तेहस प्रतिनिधि
नियुक्त कर दिये। इनमें जिना भी थे। खिलाफत सम्मेलनका भी कुछ इसी तरहका हाल
रहा, हालाँकि इसने भी अपने प्रतिनिधि भेजनेका निश्चय किया।

राष्ट्रीय सभामें जिनाने अजीव रवैया अख्तियार किया। सर्व-दलीय राजनीतिक सम्मेलनमें हुए साम्प्रदायिक समझौतेका आधार ही उन्होंने संशोधनों द्वारा खत्म कर देना चाहा। एक संशोधन द्वारा उन्होंने माँग की कि केन्द्रीय विधान सभामें मुसलमानींको निर्वाचित सदस्योंके तिहाई स्थान मिलने चाहिये। इसका साफ मतलव यह था कि सर्व-सम्मितिसे स्वीकृत फैसलेके खिलाफ जिना मुसलमानोंके लिए पक्षपात चाहते थे। बहुत बड़े बहुमतसे यह संशोधन गिर गया।

जिनाके एक दूसरे संशोधनमें कहा गया था कि जबतक वयस्क मताधिकार न हो तबतक पंजाव और वंगालमें संख्याके आधारपर मुसलमानोंके लिए स्थान सुरक्षित रखे जाचें और उन्हें अतिरिक्त स्थानोंके लिए चुनाव लड़नेका अधिकार न प्राप्त हो। यह संशोधन भी गिर गया। एक विचित्र बात यह थी कि मुस्लिम लीग और खिलाफत सम्मेलनके प्रतिनिधियोंने बोट देनेमें हिस्सा नहीं लिया। जमैयतुल-उलेमाने ज्यादा स्पष्ट विरोध किया। उसकी २८ दिसम्बरको मुरादावादमें हुई बैठकमें एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें कहा गया

कि—नेहरू-समिति गलत टंगसे बनायी गयी थी क्योंकि इसमें मुसलमानोंका यथोचित प्रतिनिधित्व नहीं था। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय समामें अपने प्रतिनिधि मेजना अखीकार किया और सर्व-दलीय मुस्लिम सम्मेलन (मुस्लिम आल पार्टीज कानफरेन्स) द्वारा रिपोर्टपर किये जानेवाले पैसलेका इन्तजार करनेका निश्चय किया।

शिमलेमें वैठे हुए अंग्रेजी-शासक कलकत्तेकी घटनाओं को वहुत उत्सुकतासे देख रहे थे। यह स्मरणीय है कि भारतीय राजनीतिमें पृथक निर्वाचन प्रणालीको गुरू करानेके लिए १९०६ में मुसलमानोंका शिष्टमण्डल शिमलामें ही खेली गयी एक चालका नतीजा था। यह भी याद होगा कि आगा खाँको जल्दीमें शिमला जाना पड़ा था, इस वार फिर आगा खाँके प्रभावको उपयोगमें लाया गया। संयुक्त निर्वाचनका अर्थ था हिन्दू-मुस्लिम एकता। अंग्रेज इस एकताके विरोधी थे। एक महीनेके प्रारम्भिक कार्यके वाद आगा खाँने अपनी अध्यक्षतामें १ जनवरी १९२९ को दिल्लीमें एक सर्व-दलीय मुस्लिम-सम्मेलन (आल्पार्टीज मुसलिम कानफरेन्स) बुलाया। इस सम्मेलनकी योजना बनानेवाले और संघटनक जी, विधान सभा, प्रान्तीय परिषदोंके कतिपय मुस्लिम सदस्य, और वे उल्मा और मुस्लिम लीगी थे जिनका अल्पमत था पर वे नेहरू-रिपोर्टके विस्त्व थे। सम्मेलनमें भाग लेनेवाले विभिन्न संघटनोंके प्रतिनिधि भारतीय मुस्लिम नेता संयुक्त निर्वाचनके पक्षमें थे। अंग्रेज गुप्त रूपसे इस सर्वदलीय मुस्लिम अधिक प्रतिनिधित्व (वेटेज) कायम रखनेकी माँग करते हुए एक प्रस्ताव पास किया।

१९२८ में मोतीलाल नेहरूकी अध्यक्षतामें कलकत्तेमें कांग्रेसका वार्षिक अधिवेशन हुआ। अधिवेशनमें हुई वहसमें इस सर्व-दलीय सम्मेलनके फैसलोंको प्रमुख स्थान दिया गया और कांग्रेसने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया—"कांग्रेसका यह अधिवेशन मद्रास अधिवेशनमें स्वीकृत पूर्ण स्वतन्त्रताके प्रस्तावपर स्थिर रहते हुए भी, इस विधान (नेहरू रिपोर्ट) को राजनीतिक प्रगतिमें एक बढ़ा हुआ कदम मानती है, विशेषतया इसलिए कि यह देशकी महत्त्वपूर्ण पार्टियोंके वीच हुए समझौतेके आधार पर वना है। अगर यह विधान ३१ दिसम्बर १९२९ या उससे पहले मान लिया जाता है तो कांग्रेस इसे स्वीकार कर लेगी। यदि उस तारीखतक यह स्वीकार न हुआ या उससे पहले रद कर दिया गया तो कांग्रेस देशको 'कर न दो' की सलाह देकर, या अन्य निश्चित किये हुए तरीकोंसे अहिंसा- समक असहयोग आन्दोलन संघटित करेगी।"

एक व्यावहारिक राजनीतिश्च होनेके नाते जिना समझते थे कि अधिकारी वर्गकी सहायता प्राप्त यह सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन दो दलोंमें विभाजित मुस्लिम लीगको निगल जायगा। इसलिए उन्होंने दोनों पक्षोंको फिरसे एक करने और एक ठोस-मुस्लिम दल वनानेका बीड़ा उठाया। मार्च १९२९ को हुई एक मीटिंगमें जब कि दोनों पक्ष साथ साथ वैठे हुए थे—सफी और उनके अनुयायी अभीतक अलग बैठे थे—जिनाने एक महत्वपूर्ण वोषणा की। उन्होंने मीटिंगमें मुसलमानोंकी सुरक्षाका एक मसविदा पेश किया जिसको वे भारतके भावी विधानमें शामिल करवाना चाहते थे। अभीतक संयुक्त निर्वाचनके प्रक्रमपर मुस्लिम नेताओंमें मतभेद था। जिनाने मुसलमानोंकी लिए केन्द्रोय विधान सभामें निर्वाचित सदस्योंके एक तिहाई स्थानोंकी माँग करके मुसलमानोंकी माँगको ऊँचा उठा दिया और

लीगों नेताओं को एक करने के लिए इसे ही मुख्य साधन बनाया । हितरक्षक प्रतिवंधों में पृथक् निर्वाचनको रखते हुए जिनाने सर्व-दलीय मुस्लिम सम्मेलनको मात दे दी । जिनाकी नीतिकी एक उल्लेखनीय बात यह थी कि उन्होंने अपने मतके पोपणके लिए अल्नेका खतरा कभी मोल नहीं लिया और न विरोधियों के मत-परिवर्तनकी चेष्टा ही की । वे अपने आपको फौरन ही बातावरणके उपयुक्त बना लेते थे । वे स्पष्टतः पृथक् निर्वाचनके विरुद्ध थे, फिर भी उनके मुस्लिम हितरक्षक प्रतिवन्धों (सेफगाई ज) में पृथक् निर्वाचन मौजूद्र था । वे प्रतिवन्धी आम तीरपर जिनाक चौदह सूत्रों के नामसे प्रसिद्ध हैं । वास्तवमें तो ये संख्यामें पन्द्रह हैं, पर पन्द्रहवाँ सूत्र पाँचवेंकी विराद व्याख्या मात्र हैं । जिना लीगके स्वीकृत नेता थे और उन्होंने १९२४ में लीगको पुनः जीवित किया था । यह जिनाका ही दम था जो नेहक-रिपोर्टके प्रस्तपर पैदा हुई फूटको दूरकर फिर लीगको संवटित करनेका प्रयत्न कर रहा था । जव-जव उन्होंने देखा कि गर्म बहसते लीगमें फिर फूट पड़नेकी सम्मावना है, तव-तव उन्होंने लीगको कोसिलकी वैठकोंको स्थिगत कर दिया । जिनाके १५ सूत्र निम्नलिखत थे—

- (१) भावी विधानकी रूप-रेखा संघात्मक हो और प्रान्तींको पूर्ण प्रान्तीय स्वाधी-नता प्राप्त हो ।
 - (२) सद प्रान्तोंको एक-सी स्वाधीनता प्राप्त हो I
- (३) देशकी सभी विधायिकाओं तथा अन्य निर्वाचित संस्थाओंका पुनिर्नाण प्रत्येक प्रान्तके अन्यसंख्यकोंके पर्याप्त और प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्वके निश्चयात्मक सिद्धान्तके आधारपर हो और ऐसा करनेमें किसी प्रान्तकी वहुसंख्यक जाति अल्पसंख्यक या समान-संख्यक न की जाय।
 - (४) केन्द्रीय विधानसभामें एक तिहाईसे कम मुस्लिम प्रतिनिधित्व न हो।
- (५) वर्तमान समयकी माँति ही पृथक् निर्वाचन-प्रणाली द्वारा साम्प्रदायिक दलोंका प्रतिनिधित्व होना चाहिये। साथ ही इसकी भी न्यवत्या होनी चाहिये कि यदि किसी समय कोई साम्प्रदायिक दल चाहे तो संयुक्त निर्वाचनके पक्षमें पृथक् निर्वाचनको त्याग दे।
- (६) किसी समय आवश्यकता पड़ने पर यदि प्रान्तोंका पुनः सीमाकरण हो तो उसका किसी प्रकार भी पंजाय, बंगाल और सीमाप्रान्तके मुस्लिम बहुमतपर असर नहीं पड़ना चाहिये।
- (७) प्रत्येक समाजको पूरी धार्मिक स्वाधीनता—अर्थात् धार्मिक विचार, पूजा, रीति रिवाज, प्रचार, संय बनाने और शिक्षा देनेके अधिकारींकी स्वाधीनता प्राप्त हो।
- (८) दिसी विधान मंडल या निर्वाचित संस्थामें कोई विधेयक, प्रस्ताय या उसका कोई अंश पास नहीं किया जायगा यदि उस संस्था-विशेषमें सम्बन्धित समाजके तीन चौयाई सदस्य उस विधेयक, प्रस्ताय अथवा उसके अंशको अपने समाजके हितोंके लिए हानिकारक समझकर उसका विरोध करते हैं या इस निषेधके स्थानपर दूसरे उपाय, जो सम्भव तथा व्यावहारिक हीं, इस विरोधको सुलझानेके लिए अपनाये जावँ।
 - (९) सिन्धको तम्बईसे पृथक कर देना चाहिये।
- (१०) दूसरे प्रान्तोंकी भाँति सीमापान्त और वलोचिस्तानमें भी सुधारोंको लागू कर देना चाहिये।

- (११) विधानके अन्दर राज्य और स्वशासन संस्थाओं की नौकरियों में कार्यक्षमताकी आवश्यकता देखते हुए मुसलमानों को उपयुक्त हिस्सा देनेकी व्यवस्था होनी चाहिये।
- (१२) विधानके अन्दर, मुसलमानोंके धर्म, संस्कृति, और व्यक्तिगत कान्नकी रक्षा तथा शिक्षा, भाषा, धार्मिक और व्यक्तिगत कान्नों, मुस्लिम सहायता संस्थाओंकी उन्नतिके लिए तथा मुसलमानोंको राज्य और खायत्त शासन संस्थाओं द्वारा दी हुई धन-सहायतामें उचित भागकी सुरक्षाएँ होनी चाहिये।
- (१३) केन्द्रीय अथवा कोई भी प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल विना उचित मुस्लिम प्रतिनि-धित्वके नहीं वनना चाहिये। मुस्लिम प्रतिनिधित्व कमसे-कम एक तिहाई होना चाहिये।
- (१४) भारतीय संघकी रियासतोंकी सम्मतिके विना केन्द्रीय विधानसभा विधानमें कोई भी परिवर्तन न कर सकेगी।
- (१५) वर्तमान समयमें, देशके विभिन्न विधान मंडलों व अन्य निर्वाचित संस्थाओं-में मुस्लिम प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा होना अनिवार्य है और चूँकि सरकार अपने वादेके अनुसार मुसलमानोंको यह अधिकार दे चुकी है, इसलिए विना मुसलमानोंकी रायके यह अधिकार उनसे छीना नहीं जा सकता और जवतक मुसलमानोंको यह सन्तोष न हो जाय कि उनके अधिकार और हित अपर दिये गये तरीकोंसे सुरक्षित हैं तबतक वे किन्हीं भी शतौंपर या विना शतौंके संयुक्त निर्वाचनके लिए राजी नहीं हो सकते।

नोट—जिन स्वोंमें मुसलमानोंका अल्पमत है, वहाँ उनकी संख्याके अनुपातसे अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होनेके प्रश्नपर बादमें विचार किया जायगा।

दिसम्बर १९२९ में पेशावरमें अपने वार्षिक अधिवेशनमें जमैयतुल-उलेमाने लीगकी माँगोंका समर्थन किया । राजनीतिक क्षेत्रमें कांग्रेसकी नोतिपर चलनेवाली जमैयतने पिछले वर्ष बार वार दंगोंके कारण अपनेको कांग्रेससे अलग कर लिया । परन्तु १९३० में सविनय अवज्ञा आन्दोलनके समय जमैयत फिर कांग्रेसके साथ आ गयी।

हिन्दू महासभाने, जो चुपचाप मुस्लिम राजनीतिक उतार-चढ़ावोंको देख रही थी, सर्व-दलीय सम्मेलनके बाद पुनः अपनी नीतिपर गौर किया, विशेषतया मुसलमानोंको दी जानेवाली उन सुविधाओंपर, जो राजनीतिक समझीतेके लिए महासभाने मान ली थीं और उसने फिर अपनी यह पुरानी नीति अपना ली कि मुसलमानोंके प्रति कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिये।

अध्याय २१

सत्याग्रह

साइगन बभीशनने अप्रैल १९२९ के मध्यमें अपना काम खत्म कर दिया और वह इंगलैण्ड वापस चला गया। कांग्रेसकी सरकार-विरोधी कार्यावलीने दूसरा रूप ले लिया। कलकत्ता अधिवेशनने गान्धीजीकी अध्यक्षतामें एक विदेशी-वस्त्र-विहिष्कार-समिति बनायी थी। समितिने बड़ी संख्यामें पुस्तिकाएँ व पर्चे निकालकर जनतासे विदेशी वस्त्रोंको त्यागने और जला डालनेकी अपील की थी। १९२९ के शुक्तमें जगह-जगह विदेशी श्रस्तोंकी होलियाँ भी जली थी। कलकत्तेकी होलीके कारण मार्चके दूसरे सप्ताहमें गान्धीजीपर मुकदमा चला। उनपर गड़बड़ी करनेका अभियोग था और उन्हें एक रुपया जुर्मानेकी सजा हुई।

प्रत्यक्ष था कि कांग्रेस आनेवाले संवर्षकी तैयारी कर रही थी। गान्धीजीकी इच्छा पूरी न होने देनेके लिए सरकारने बंद-बंदे नेताओंकी अन्धायुन्ध गिरपतारीकी नीति अप-नायी । राजनीतिक और मजदूर कार्नकर्त्ताओंपर न जाने कितने मुकदमें चले और सजाएँ हुईं। कलकत्तेमें काग्रेम कार्यकारिणीके सदस्य सुभापचन्द्र वसुपर मुकदमा चला। मजदूर नेता भी सिक्य थे । इस वर्ष बम्बईके सूनी मिलोंके डेढ़ लाख और बंगालके जुट मिलोंके २५००० मजदृरांने इड़ताल की थी। जनताको राष्ट्रीय आन्दोलनमं आनेके लिए प्रेरित करनेके उद्देश्यसे हिन्दस्तानी रोवादल हर माएके अन्तिम रविवारको राष्ट्रीय झण्डादिवस मनाता। इस दिन सवेरे आठ वजे देशभरमें राष्ट्रीय तिरंगा झण्डा फहराया जाता। उदारदल या नरमदलके नेता स्थितिको आशंकापूर्वक देख रहे थे और उन्होंने वाइसरायको सलाह दी कि संभावित आन्दो-लन रोकनेके लिए गान्धीजीते समझौता कर लिया जाय । ३१ अक्टूबरको बाइसरायने एक वक्तत्य द्वारा भारतको डोमीनियन स्टेट्स-औपनिवेशिक स्वराज्य देनेका वचन दिया पर इसके लिए कोई तिथि निहिन्तत नहीं की । उन्होंने अपने वक्तव्यमें इशारा किया कि भारतके भविष्यः के विधानके लिए एक गोलमेज सम्मेलन होगा। वाइसरायके वक्तव्यका कांग्रेसी नेताओंपर कोई प्रभाव नहीं पहा । फिर भी २२ दिसम्बरको गान्धीजीको बाइसरायसे मिलनेका निमन्त्रण मिला। उस दिन गान्धीजी और मोतीलाल नेहरू एकमत और जिना, विष्टलभाई पटेल व तेजबहादुर समृदूसरे नरमदलीय मतके प्रतिनिधियोंकी हैसियतसे बाइसरायसे मिले और खाली हाथ वापम लीट आये। गान्धीजीने वाइसरायसे पूछा कि क्या गोलमेज सम्मेलनमें पूर्ण 'औपनिवेशिक स्वराज्य'के आधार पर वात होगी ?' वाइसरायने इस प्रश्नके उत्तरमें स्पष्ट 'हाँ' कहनेमें असमर्थता प्रकट की ।

कांग्रेसका वार्षिक अधिवेशन निकट आ रहा था। दस प्रान्तोंने गान्धीजी, पाँचने वाहमभाई पटेल और तीनने जवाहरलाल नेहरूका नाम अध्यक्षपदके लिए प्रस्तावित किया था। गान्धीजी निर्वाचित घोषित हुए, पर उन्होंने फौरन इस्तीफा दे दिया और-नया अध्यक्ष चुननेके लिए बुलायी गयी कांग्रेस महासमितिकी वैठकमें सुझाव दिया कि जवाहरलाल नेहरू उनकी जगह अध्यक्ष बनाये जायँ। उनकी इच्छा पूरी हुई।

१९२९ का ऐतिहासिक अधिवेशन हर वर्षकी तरह दिसम्बर्से लाहीरमें जवाहरलाल नेहरूकी अध्यक्षतामें होना तय हुआ । नेहरूजीने अपने भाषणमें कहा—"आज ब्रिटिश साम्राज्य दुनियाके वहे-वहे इलाकोंकी जनताकी इच्छाके धिरुद्ध करोड़ों व्यक्तियोंपर शासन कर रहा है। यह सच्चा राष्ट्रमण्डल या कामनवेहथ तवतक नहीं वन सकता, जवतक साम्राज्यवाद इसका आधार है और दूसरी जातियोंका शोषण इसके जीवनका सहारा। वास्तवमें यह साम्राज्य धीरे-धीरे राजनीतिक रूपसे छिन्न-भिन्न हो रहा है।" नेहरूजीने आगे कहा—"भारत-के लिए पूर्ण स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है। इस कांग्रेसने न कभी यह स्वीकार किया है और न कभी स्वीकार करेगी कि ब्रिटिश पार्लमेण्ट हमपर शासन करे। हमें पार्लमेण्टसे कोई अपील नहीं करनी है लेकिन हम विश्वकी अन्तरात्मा और विश्वरूपी पार्लमेंटमें अवश्य अपील करते हैं और कहते हैं कि भारत अब विदेशी दासता स्वीकार नहीं करता, सहन नहीं करता।"

मुख्य प्रस्ताव द्वारा कांग्रेसने घोषणा की कि कांग्रेस विधानकी पहली धारामें आये द्याव्य 'स्वराज्य' का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता हैं. और औपनिवेशिक स्वराज्य सम्बन्धी नेहरू समितिकी पूरी योजना समाप्त हो गयी। प्रस्तावमें कांग्रेस-जन तथा अन्य उन लोगोंसे अपील की गयी थी, जो राष्ट्रीय आन्दोलनमें भाग लेनेवाले थे कि वे भविष्यके , चुनावोंमें हिस्सा न लें; विधान-मण्डलोंके कांग्रेसी सदस्योंसे इस्तीफा देनेको कहा गया था। प्रस्तावका आन्दोलन सम्बन्धी अंश इस प्रकार था—"कांग्रेस राष्ट्रसे अपील करती है कि वह उत्साहपूर्वक रचनात्मक कार्यक्रमको पूरा करे और कांग्रेस महासमितिको अधिकार देती है कि जब भी वह ठीक समझे सविनय अवज्ञा आन्दोलन ग्रुरू कर दे; इस आन्दोलनमें करवन्दी आन्दोलन भी शामिल हो सकता है; महासमिति सीमित या असीमित क्षेत्रोंमें जो शतें ठीक समझे उनके अनुसार आन्दोलन चलाये।" अल्प संख्यकोंके सम्बन्धमें प्रस्तावमें कहा गया था कि कांग्रेसको ऐसा कोई भी विधान स्वीकार न होगा जिसमें अल्प-संख्यकोंके लिए पूरे पूरे हित-रक्षारमक प्रतिवन्य न रखे गये हों।

दिसम्बरके इस आखिरी सप्ताहमें लाहौरमें वड़ी सर्दी थी। जो काफी कपड़ा नहीं लाये थे, वे ठिठुर रहे थे। इसिलये कांग्रेसने तय किया कि भविष्यके अधिवेशन फरवरी या मार्चमें हुआ करें। १८८५ में अपने जन्मसे ही कांग्रेसके अधिवेशन वड़े दिनकी छुट्टियोंमें हुआ करते थे। १९२९ का अन्तिम दिन था। आधी रातको जब साल खत्म हो रहा था सभी प्रतिनिधि बाहर निकले और पूर्ण स्वराज्यका झण्डा फहरा दिया। सरकारको दिया गया एक वर्षका समय समाप्त हो चुका था। नियतिकी घड़ी आ गयी थी।

वर्षके आरम्भमें कांग्रेसनों के विधानमण्डलोंसे इस्तोफा देनेके साथ ही संघर्षके वादल उमड़ उठे थे। कांग्रेसने २६ जनवरीको पूर्ण स्वतन्त्रता-दिवस मनाना तय किया। उस दिन रिववार था। कार्यसमितिने एक प्रस्ताव स्वीकार कर सभी मातहत समितियोंसे सार्वजिनक सभाओंमें इसी प्रस्तावको स्वीकार करनेको कहा था। यह प्रस्ताव एक प्रणके रूपमें, इस प्रकार था—"हमारा विश्वास है कि अन्य देशोंको भाँति भारतवासियोंका यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वे स्वतन्त्रता प्राप्त करें, अपने परिश्रमके फलका उपभोग करें और जीवनकी आवश्यकताएँ पूरी करें ताकि विकासकी सारी सुविधाएँ उन्हें मिल सकें। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई सरकार जनताके इन अधिकारोंको छीनकर उसका दमन करती है तो जनताका यह भी अधिकार होता है कि वह उस सरकारको खत्म कर दे या

वदल दे। भारतमें अंग्रेज सरकारने न सिर्फ भारतवासियोंकी स्वतन्त्रताका अपहरण किया है, विक उसने जनताका श्रोपण अपना आधार बना लिया है और आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मक दृष्टिसे देशको वरवाद कर दिया है। हमारा यह भी विद्यास है कि भारतको ब्रिटेनसे नाता तोड़कर पूर्ण स्वराज्यकी प्राप्ति करनी चाहिये। इस लम्बे प्रस्तावमें बताया गया था कि किस प्रकार ब्रिटिश मालके लिए देशी घरेल् धन्धे नए-भ्रष्ट किये गये, ब्रिटिश व्यापारकी सहायताके लिए तटकर और सुद्रा-विनिमय चलाया गया; भारतीयोंसे भाषण और संघटनकी स्वतन्त्रता छीन ली गयी, पूर्ण रूपसे शस्त्रविहीन बना दिये जानेके कारण भारतीय पुरुपत्वदीन हो गये हैं। अन्तमें प्रणक्ते रूपमें कहा गया था —"हमारा पक्का विश्वास है कि यदि हम कैवल अपना स्वेच्छापूर्ण सहयोग वापस ले लें और उत्ते जनामें भी हिंता किये विना, कर देना वन्द कर दें तो इस अमानवीय शासनका अन्त निह्न्तित है।"

गान्धीजी सिवनय अवज्ञा आन्दोलनकी तैयारी कर रहे थे, किन्तु ज्ञान्तिवादी और मुल्हमें विश्वास करनेवाले होनेके नाते उन्होंने वाइसरायको एक और मौका दिया। अपने साप्ताहिक 'शंग इण्डिया' के एक लेखमें उन्होंने वाइसरायको निम्नलिखित होतें वतायों और आदवासन दिया कि यदि सरकार उन्हें मान ले तो उसे सिवनय अवज्ञा आन्दोलनका नाम भी न सुन पहुंगा—

- १--पूर्ण नशावन्दी हो,
- २--- मुद्रा-विनियममें एक रुपया एक शिलिंग चार पेंसके वरावर माना जाय,
- २-मालगुजारी आधी कर दी जाय और उसे विधानमण्डलके नियन्त्रणमें रखा जाय,
- ४--नमकपर लगनेवाला कर वन्द हो,
- ५-फीजी खर्च कम हो, शुरूमें उसे आधा तो कर ही दिया जाय,
- ६—वड़े अफ़सरोंकी तनख्वाहें आधी या उससे कम कर दी जाबँ, ताकि कम आमदनीमें सरकार काम चला सके।
 - ७—विदेशी वस्त्रींपर तटकर लगाया जाय, ताकि देशी उद्योगका संरक्षण हो:
 - ८-तटीय व्यापार संरक्षण कानृत पारित किया जाय,
- ९—हत्या या हत्याकी चेष्टामें दिण्डत बन्दियोंको छोड़कर शेष सभी राजनीतिक बन्दी रिहा कर दिये जायँ, सभी मुकदमे वापस लिये जायँ, दक्ता १२४, ए और १८१८ का तीसरा विनियम रद किया जाय और भारतसे निर्वासित किये गये सभी लोगोंको भारत आने दिया जाय,
 - १० खुफिया पुढिस तोड़ दी जाय या इसे जन-नियन्त्रणमें रखा जाय,
 - ११—जननियन्त्रणमें आत्मरक्षाके लिए वन्दूक आदि हथियारोंके लैसंस दिये जावँ ।

सरकारकी ओरसे कोई उत्तर नहीं मिला; इतना ही नहीं आन्दोलन छिड़नेपर, उसे अधिक सफलता न मिले, इसलिए सरकारने राजनीतिक कार्यकत्तांओंकी गिरपतारियाँ जारी रखीं । नेतिओंमें सुभापचन्द्र वसु भी गिरपतार हुए और ११ अन्य व्यक्तियोंके साथ उन्हें एक वर्णकी कड़ी कैदकी सजा हुई । जिन साधारण कान्नोंकी शक्तिसे सरकारने अपने अधिकार बढ़ा लिये थे, उनमें किसीको भी, किसी भी भाषणके लिए दण्ड दे देना आसान था ।

कांग्रेस कार्य समितिने अव आन्दोल्नका कार्यक्रम तैयार करना गुरू किया।

आजादीके लिए लड़नेवालोंमें अनुशासन लानेके प्रस्तपर विचार हुआ। फरवरीकी वैठकमें कार्य-समितिने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया।

"कार्य-समितिके मतमें सिवनय अवशा आन्दोलन उन व्यक्तियों द्वारा प्रारम्भ और नियन्त्रित किया जाना चाहिये जो पूर्ण-स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए सिद्धान्त रूपमें अहिंसामें विश्वास करते हों, और चूँकि कांग्रेस संस्थामें ऐसे भी व्यक्ति हैं जो वर्तमान परिस्थितिमें अहिंसाको नीतिके रूपमें स्वीकार करते हैं, कार्यकारिणी इस सुझावका स्वागत करती है कि गान्धीजी और उनके वे सहयोगी जो अहिंसामें सिद्धान्त रूपमें (नीति रूपमें नहीं) विश्वास करते हों, जिस ढंगसे, जिस सीमातक, जब वे ठीक समझें सिवनय अवशा आन्दोलन चुक्त करें। कार्यसमितिका विश्वास है कि आन्दोलन छिड़ने पर सभी कांग्रेसजन व अन्य लोग इन विनयशील प्रतिरोधियोंको हर तरहसे सहयोग देंगे और हर परिस्थितिमें, उत्तेजनाक वावजृद् शान्त रहेंगे। कार्यसमितिको आशा है कि यदि आन्दोलन सार्वजिनक रूपमें छिड़ा तो सरकारसे स्वेच्छापूर्ण सहयोग करनेवाले सभी लोग—जैसे कि वकील और जो सरकारसे तथाकथित सुविधाएँ प्राप्त करते हैं—जैसे कि छात्र, सरकारसे अपना सहयोग वन्द कर देंगे तथा सुविधाएँ हेनेसे इनकार कर देंगे और आजादीकी आखिरी लड़ाईमें जुट जावँगे।

"कार्यसमितिका विश्वास है कि नेताओं के गिरपतार होने या सजा पाने पर जो छोग पीछे छूट जायँगे और जिनमें सेवा व त्यागर्की भावना है, वे कांग्रेसका संघटनं चलायेंगे और अपनी योग्यतानुसार आन्दोलन चलायँगे।"

कार्यसमितिका यह प्रस्ताव कांग्रेस महासमितिने स्वीकार कर लिया और गान्धीजी व उनके सैद्धान्तिक अनुयायियोंको सविनय प्रतिरोध आन्दोलन चलानेका अधिकार दे दिया।

यह गान्धीजीपर ही छोड़ दिया गया था कि किस अनुचित कान्तको सत्याग्रही तोड़ना ग्रुरू करें। गान्धीजीने नमक कान्न छाँटा क्योंकि इस कान्तका प्रभाव देशके हर गरीव अमीर इन्तानपर पड़ता था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारतमें नमकपर कर पहली वार अंग्रे जोंके राजमें ही लगा। अंग्रे जोंने एक तो अपनी आमदनी वढ़ानेके लिए और दूसरे भारतीय नमक महगा कर अंग्रे जी नमक भारतमें वेचनेके लिए यह कर लगाया था। जो अंग्रे जी जहाज भारतसे माल भरने आते थे वे नमक लाद लाते थे।

गान्धीजीने तय किया कि कुछ चुने हुए साथियोंके साथ किसी नमक गोदाम जाकर वे कानून तोड़ेंगे। उन्होंने वाइसरायको अपना यह निर्णय वताते हुए एक पत्र लिखा। २ मार्च १९३० के इस पत्रमें गान्धीजीने सावरमती आश्रमसे वाइसरायको वताया था कि वे कानून क्यों तोड़ रहे हैं। उन्होंने प्रस्न किया में ब्रिटिश शासनको अभिशाप क्यों मानता हैं और उसी पत्रमें उन्होंने उसका उत्तर इस प्रकार दिया—

"इसने मारतके करोड़ों मूक पाणियोंको वढ़ते हुए शोपण और ऐसे खर्चांले फौजी और नागरिक प्रशासनसे गरीव वनाया है जिसका खर्च यह देश वरदास्त नहीं कर सकता।

"इसने हमें राजनीतिक दृष्टिसे गुलाम रखा है। इसने हमारी संस्कृतिकी जड़ें काट दी हैं। निक्शस्त्रीकरण द्वारा इसने हमें आध्यात्मिक पतनकी ओर खींचा है। आन्तरिक शक्तिके अभावमें इस लगभग पूर्ण निक्शस्त्रीकरणके कारण हम भीक्तापूर्ण असहाय स्थितिमें हैं।"

"अनेक देशवासियोंकी तरह मैं भी इस आशाको गर्छे लगाये रहा कि प्रस्तावित गोलमेज सम्मेलनसे कोई हल निकलेगा। लेकिन, जब आपने साफ-साफ कह दिया कि आप या ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्यके संकल्पका आद्वासन नहीं दे सकते तब इस सम्मेलनसे वह इल निकलना सम्भव नहीं है जिसके लिए मुखर भारत चेतन मनसे और मूक भारत अचेतन मनसे लालायित है।

"यह विलक्ष्य रपष्ट है कि उत्तरदायी विधिश राजनीतिश अपनी नीतिमें ऐसा कोई परिवर्टन करनेको तैयार नहीं हैं, जिससे विधेनके भारतीय न्यापारपर आँच आये या भारतमें विधिश किया-कलापकी कड़ी जाँचकी सम्भावना पैदा हो। अगर यह शोएण वन्द न हुआ तो भारतका खुन और तेजीसे चूमा जायगा।

"फिर सिर्फ मालगुजारों ही कम करनेकी जलरत नहीं है, पूरी माल-व्यवस्था इस प्रकार वदलनी है कि रेयतकी मलाई उसका प्रथम कर्तन्य वन जाय । लेकिन ब्रिटिश प्रणाली-का उदेश्य तो रेयतकी जान ले लेना माल्स पड़ता है । जो नमक जीवन धारण करनेके लिए खाया जाता है, उसपर भी इस प्रकार कर लगता है कि उसका सारा वोझ उसी रेयतपर पड़े—बाहे वह गरीव अमीर सवपर निर्दय समानताके साथ लगता हो । यह कर गरीवोंपर और भी वड़ा अन्याय तव सावित होता है, जब यह देखा जाय कि गरीव अकेले और सामूर हिक रूपसे दोनों तरह अमीरोंसे ज्यादा नमक खाते हैं।

"ये अन्याय दुनियाका सबसे खर्चाला और मँहगा शासन कायम रखनेके लिए किये जाते हैं। आप अपनी ही तनख्वाह लीजिये। जो अप्रत्यक्ष रूपसे बहुत कुछ आपको मिलता है, उसे छोड़ भी दं तो भी आपको २१०००) महीना मिलता है। मुद्रा-विनिमयकी वर्तमान दरसे ब्रिटेनके प्रधान मन्त्रीको सिर्फ ५४००) महीना मिलता है। आपको ७००) प्रति दिन मिलता है जब कि भारतीयोंकी औसत आमदनी दो आने रोजसे भी कम है। ब्रिटेनके प्रधान मन्त्रीको १८०) रोज मिलते हैं जब कि वहाँके नागरिकोंकी ओसत आमदनी २) रोज है। इस प्रकार आप औसत भारतीयोंसे पाँच हजार गुना ज्यादा पाते हैं, जब कि ब्रिटिश प्रधान मन्त्री औसत ब्रिटिश नागरिकसे ९० गुना ज्यादा पाते हैं, जब कि ब्रिटिश प्रधान मन्त्री औसत ब्रिटिश नागरिकसे ९० गुना ज्यादा पाता है। में आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप इस आदचर्यजनक घटनापर विचार करें। एक कप्टदायक सत्यके लिए मेंने व्यक्तिगत उदाहरण लिया। लेकिन व्यक्तिगत रूपसे आपके लिए मेरे हृदयमें हतना आदर है कि मैं आपकी भावनाको टेस नहीं पहुँचाना चाहता। मैं जानता हूँ कि आपको इस वेतनकी आवश्यकता है। सम्भवतः आपका सारा वेतन दानमें चला जाता है। लेकिन जिस प्रणालीमें इस प्रकारकी व्यवस्था हो उसे तो फीरन ही खत्म करना चाहिये। जो वात वाहसरायके वेतनके सम्बन्धमें कही जा सकती है, वही पूरी नौकरशाहीके वारेमें।

"इसके लिए सरकारी प्रणालीमें ही परिवर्तन जरूरी है और यह स्वराज्यके विना असम्भव है। मेरी रायमें, २६ जनवरीके विराट आकस्मिक प्रदर्शनोंका जिनमें लाखों किसानों-ने भाग लिया, यही कारण है। उनके लिए स्वराज्यका अर्थ है इस जानलेवा बोझसे छुटकारा।

"फिर भी यदि भारतको एक राष्ट्रके रूपमें रहना है और यहाँकी जनताको भुखमरीसे धीरे-धीरे मरने नहीं देना है, तो स्थितिके तत्काल सुधारका कोई उपाय निकालना होगा। प्रस्तावित सम्मेलन वह उपाय नहीं है।"

आगे गान्धीजीने ब्रिटिश शासनकी बुराइयोंसे लड़नेके लिए सविनय अवशा आन्दो-लनकी अपनी योजना समझाते हुए लिखा—''लेकिन, यदि आपने इन बुराइयोंको दूर करनेका रास्ता न निकाला और मेरे अनुरोधका आपपर कोई प्रभाव न हुआ तो इस महीनेकी ११ तारीखको में आश्रमके ऐसे सहयोगियोंको लेकर नमक कान्नका उल्लंघन करने निकल्ँगा जो मेरे साथ चल सकेंगे। निर्धन लोगोंकी दृष्टिसे में इस नमक करको सबसे ज्यादा अन्यायपूर्ण मानता हूँ। चूँकि स्वतन्त्रता आन्दोलन अनिवार्य रूपसे देशके निर्धनोंके लिए है, इस बुराईको दूर करनेके प्रयत्नोंसे ही शुरुआत होगी। आक्चर्य तो यह है कि इस नृशंस इजारेदारीको हम अवतक वरदाक्त करते रहे। में जानता हूँ कि आप मुझे गिरफ्तार कर मेरी योजना ठप कर सकते हैं। मुझे आशा है कि मेरे बाद हजारों, लाखों व्यक्ति अनुशासित ढंगसे नमक कानृन तोड़कर उस दण्डके भागी होंगे जो ऐसे कानृनके अन्तर्गत मिलेगा जिसे कभी बनना ही नहीं चाहिये था।

"में जहाँतक हो सकता है आपको या किसी औरको अनावश्यक परेशानी या व्यग्रतामें नहीं डालना चाहता । अगर आप इस पत्रमें तथ्य पार्व और मसलोंपर मुझसे वात-चीत करना चाहें, इसलिये इस पत्रका प्रकाशन स्थिगत कराना चाहें तो आप इसे पाते ही मुझे तार दे दें, मैं खुशीसे प्रकाशन स्थिगत कर दूँगा। लेकिन मेरा आपसे यहो अनुरोध है कि जवतक आप मेरे पत्रमें लिखी वातोंके तथ्यसे सहमत न हों मुझे मेरे पथसे विचलित न करें।"

इस पत्रको एक अंग्रेज—रेजिनाल्ड रेनोल्ड्स, जो सावरमती आश्रममें कुछ दिनों रह चुके थे, लेकर वाइसरायके पास गये। उत्तरमें वाइसरायने सिर्फ इतना कहा कि "मुझे खेद है कि गान्धी वह रास्ता अिल्तयार कर रहे हैं जिसमें कानून और सार्वजनिक श्रांन्ति मंग होना अनिवार्य है"। गान्धीजीने इस जवावके बाद कहा—"मैंने घुटने टेककर रोटी माँगी थी, पर मुझे पत्थर मिला। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति पहचानता है और मुझे वाइसरायके पत्रसे आश्चर्य नहीं हुआ है। राष्ट्रको केवल एक ही सार्वजनिक श्रान्ति शत है, और वह है जेलकी शान्ति। भारत एक बहुत बड़ा जेल है। मैं इस कानूनको नहीं मानता और उद्गार प्रकट करनेमें असहाय राष्ट्र-हृदयको मसलनेवाली इस लादी गयी शान्तिकी शोकमय एक रसताको भंग करना अपना पुनीत कर्त्तव्य मानता हूँ।"

१२ मार्चको ७५ साथियोंके साथ गान्धीजी ढाँडीतटके लिए रवाना हुए । संवाददाताओं, फिल्म व फोटो खींचनेवालों और विभिन्न प्रान्तोंके कांग्रे सजनों व किसानोंके जत्ये
पीछे-पीछे चले । लेकिन फिल्मवालोंको निराश होना पड़ा, क्योंकि उन्हें फिल्म खींचनेमें
तो नहीं रोका गया, पर चर्खा-तकली लिये, सिर्फ धोती पहने गान्धीजीकी इस यात्राके
फिल्मके प्रदर्शनपर रोक लग गयी । सावरमतीसे डाँडीकी २०० मीलकी यात्रा २४ दिनमें
पूरी होनी थी । गान्धीजीने कहा था कि जबतक वे डाँडी न पहुँच जायँ और लोग सत्याग्रह
शुरू न करें । लेकिन यह समझकर कि शायद उन्हें गन्तव्य स्थानतक न पहुँचने दिया जाय,
विनयशील प्रतिरोधियोंके लिए कुछ बातें वता दी थीं । उन्होंने एक लेख लिखा था—"इस
वार मेरे गिरफ्तार होने पर निष्किय नहीं, सिक्षय अहिंसा होगी, जिससे इस प्रयत्नके अन्तमें,
भारतकी स्वाधीनताप्राप्तिके लिए अहिंसामें सिद्धान्त रूपमें विश्वास करनेवाला कोई भी
व्यक्ति जेलके वाहर जीवित रूपमें इस दासताको सहनेके लिए नहीं बचेगा । इसलिए सिवन्य
अवज्ञा या सिवनय प्रतिरोधमें—जैसा उसे मेरे उत्तराधिकारी या कांग्रेस चलाये, भाग लेना
हर एक व्यक्तिका कर्त्तव्य होगा । मैं स्वीकार करता हूँ कि इस समय मेरा कोई अखिल

भारतीय उत्तराधिकारी नहीं है.....प्रत्येक व्यक्तिको तवतक अपने कर्त्त व्यपर डटे रहना चाहिये जवतक प्रधान उसका आह्वान न करे । यदि स्वेच्छासे सार्वजनिक सहयोग हुआ— जैसी कि मुझे आशा है तो आन्दोलन अधिकांशतः स्वयं चालित ही होगा । लेकिन हर वह व्यक्ति जो अहिंसामें विश्वास रखता है—चाहे सिद्धान्त रूपमें चाहे नीति रूपमें, आन्दोलनमें सहायक होगा । सार्वजनिक आन्दोलनोंमें दुनिया भरमें नये नेता पैदा होते हैं । इसिलए, हालाँकि हिंसक शक्तियोंको रोकनेकी हर सम्भव कोशिश की जानी चाहिये, इस वार चलाया गया सिवनय अवशा आन्दोलन तवतक नहीं रुकना चाहिये और नहीं रुकेगा जवतक एक भी सत्याग्रही जिन्दा या जेलके वाहर है । सत्याग्रही या तो जेल या इसीचे मिलती-जुलती रिथितमें होगा, या अवशा आन्दोलनमें लगा होगा या आदेशानुसार स्वराज्य लोनेवाले चर्ला चलाने जैसे रचनात्मक कार्योंमें संलग्न होगा ।

गान्धीजीके दलके डाँडीके लिए खाना होनेके पहले वल्लमभाई पटेल गान्धीदलके अप्रदूतकी तरह चल चुके थे। वे गिरपतार कर लिये गये और आन्दोलनकी गति वढ़ गयी। सावरमतीके मैदानमें ७५००० व्यक्तियोंने इकट्ठे होकर प्रण किया कि जवतक भारत स्वाधीन नहीं हो जाता, न तो इम स्वयं चैन छंगे और न सरकारकी चैन छेने देंगे। गान्धीजीने उनके समक्ष भाषण करते हुए कहा—"अव पाँसा पड़ चुका है और लौटाया नहीं जा सकता: गान्धीने पहले सार्वजिनक अवना आन्दोलनके प्रयोगके लिए तुम्हारा तालुका छाँटा है, उसकी इस पसन्दको सही सावित करना तुम्हारा काम है ""में जानता हूँ कि तुममें से कुछ लोगोंको अपनी जमीनें छिन जानेका डर है। यह छिनना क्या है ! क्या वे जमीनोंको इंगलैण्ड उठा ले जायँगे ! तुम विश्वास रखो कि अगर तुम जमीन छिनवानेको तैयार हो तो पूरा गुजरात तुम्हारे साथ है।" गान्धीजी जब डाँडीकी यात्रामें थे, २१ मार्चको कांग्रेस महासमितिने जनताको सावधान किया कि जनतक हमारा नेता डाँडी पहुँचकर स्वयं नमक-कानृत भंग न कर ले कोई अन्य व्यक्ति तवतक आन्दोलन न करे । गान्धीजीकी सहमितिसे महासमितिने एक शपथ वनायी जिसपर हर सत्याग्रहीको हस्ताक्षर करने थे। इस शपथ द्वारा सत्याग्रही आन्दोलनमें जेल जाने तथा अन्य दण्ड स्वीकार करनेका वादा करता। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंसे, सरकारी वाधाओंके वावजूद, सार्वजनिक आन्दो-लनकी तैयारियाँ पूरी करनेको कहा गया।

गान्धीजी रास्तेमें सभाओंमें भाषण करते जाते थे। एक जगह उनका भाषण सुनकर २०० पटेलोंने सरकारी नौकरीसे इस्तीका दे दिया।

गान्धीजी ५ अप्रैलको डाँडी पहुँच गये। ६ अप्रैलको जालियाँवाला बाग नरमेथके अविरमरणीय दिन देशभरमें नमक सत्याग्रह शुरू होनेका निश्चय हुआ था। उस दिन प्रातः-कालीन प्रार्थनाके फौरन बाद गान्धीजी अपने अनुयायियोंके साथ कान्न मंग करने चले; उन्होंने समुद्रतटपर पड़े नमकको उटा लिया। कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। गान्धीजीने एक प्रेस-वक्तत्यमें कहा—"नमक कान्न जाव्ते या व्यवहार रूपमें मंग हो चुका है और अव हर वह व्यक्ति जो मुकदमेका खतरा उटानेको तैयार है, जहाँ और जब चाहे नमक बनानेको स्वतन्त्र है। मेरी सलाह यह है कि कार्यकर्त्तां हर जगह नमक बनावें और जहाँ साफ नमक बनाना सम्भव है वहाँ उसका प्रयोग भी करें; साथ ही ग्राम्यासियोंको खाद्य नमक बनानेकी विधि बतायें और साथ ही उन्हें बताते जावें कि वे इसके लिए दिण्ड पा सकते हैं ''''गाम-

वासियोंको यह साफ-साफ बता दिया जाय कि कानून मंग करना चोरी-छिपे नहीं, खुले आम होना है' नमक कानूनके विरुद्ध यह युद्ध राष्ट्रीय सप्ताहके अन्ततक अर्थात् १३ अप्रैल-तक चले।''

गान्धीजीकी यात्रामें प्रतिदिन बढ़ता जनताका संचित उत्साह ६ अप्रैलको प्रवाहित हो चला । सरकारको तैयारीका काफी समय मिला था; पुल्सि बन्दूक भरे, संगीन लगाये तैयार थी । उस दिन देश भरमें सार्वजिनिक समाएँ हुई, बड़े शहरोंमें इनमें लाखोंने माग लिया । एक तरफ गान्धीजीका सन्देश सुननेको आतुर निहत्थी जनता थी; दूसरी तरफ सशस्त्र धुड़सवार पुल्सि कान्त भंग किये विना भी भीड़पर गोली चलानेको उद्यत । सभाओंमें आये सभी लोग सत्याग्रही नहीं थे, उनमेंसे बहुतसे लोग गान्धीजी और उनके आन्दोलनमें श्रद्धा करते थे पर घरेल कारणोंसे कान्त भंग नहीं करना चाहते थे । उनका एकमात्र उद्देश्य सभाओंमें भाग लेकर घर लौट आना था । लेकिन सभा-खलोंपर पुल्सि आतंक जमानेके लिए एकत्र थी । पुल्सिकी आम चाल यह थी कि सभाके संयोजकोंसे सभा वरलास्त करनेके लिए कहकर विवाद करना; और संयोजकके शान्तिपूर्ण सभा करनेके अपने नागरिक अधिकारका हवाला देवर सभा भंग करनेसे इनकार करते ही; इससे गैर सत्याग्रही जनतामें भी आत्म-सम्मान उभरता; पुल्सि भीड़को तितर-वितर करनेके लिए गोली चला देती और जनता अहिंसाके अनुशासनमें निष्क्रिय रूपसे इसे स्वीकार करती; धीरे धीरे दोनों ओर भावावेश बढ़ता जाता; जनता अपने नागरिक अधिकारके प्रयोगके लिए इकट्ठी होती; पुल्सि और नृशांस होकर गोल्योंसे उसे भून देती और लाठियोंसे घायल कर देती ।

आन्दोलनके दिनोंमें भारतका दौरा करनेवाले अंग्रेज बेल्सफर्डने ब्रिटिश पत्र 'मेंचेस्टर गार्जियन' में १२ जनवरी १९३१ को लिखा—"यदि ऐसी सभाएँ हमेशा या आम तौरपर होने दी जातीं तो कोई अव्यवस्था नहीं होती। लेकिन जैसा हुआ—खास कर वम्बईमें, वह यह था कि भीड़ हटानेके इस भोंडे तरीकेने पूरे नगरमें रोष भर दिया; लाटी खाना आत्मसमानका प्रस्न वन गया और शहीद होनेकी भावनामें सैकड़ों स्वशंसेवक मरने और मिटने गये।"

६ अप्रैलको नमक कानून देशमें अनेक जगहोंपर तोड़ा गया। नमक ऐसी जगहोंपर भी बनाया गया जहाँ इस गैरकानूनी नमककी कीमत मामूली कीमतसे कहीं ज्यादा चैठी। कानून भंग करना हतों जारी रहा। पुलिस सत्याग्रहियोंको वेरहमीसे पीटती और यातनाएँ देती रही।

गिरपतारीके पहले वाइसरायको लिखे गये गान्धीजीके दूसरे पत्रसे इन अत्याचारोंका कुछ भास होता है। गान्धीजीने लिखा था—"मुझे आज्ञा थी कि सरकार सत्याग्रहियोंसे सम्य ढंगसे लड़ेगी। यदि सरकार सत्याग्रहियोंसे निपटनेके लिए न्याय और नियमोंके सामान्य पालनसे संतुष्ट हो जाती तो मुझे कुछ नहीं कहना था। लेकिन, जाने माने नेताओंके साथ तो थोड़ी वहुत न्यायव्यवस्था ठीक बरती गयी है, पर आम सत्याग्रहियोंपर जंगली और असम्य ढंगसे हमला किया गया है। यदि ऐसी घटनाएँ इक्की-दुक्की या छिटफुट होतीं तो इन्हें नजर-अन्दाज किया जा सकता था। लेकिन बंगाल, विहार, उत्कल, संयुक्त प्रान्त, दिल्ली और वम्बईसे मेरे पास विवरण आये हैं जो गुजरातके मेरे अनुभवोंकी पृष्टि करते हैं और जिनके मेरे पास काफी सबूत मौजूद हैं। कराची, पेशावर और मद्रासमें अनावस्यक रूपसे,

विना किसी उत्तेजनाके गोली चला दी गयी। सरकारके लिए व्यर्थ, पर स्वयंसेवकींका वहुमूल्य नमक छीन लेनेके लिए उनकी हिंडुयाँ तोड़ दी गयीं, उनके गुप्तांग दवाये गये। मधुरामें, वताया जाता है कि, एक सहकारी मजिस्ट्रेटने १० वर्षके एक वालकसे राष्ट्रीय झण्डा छीन लिया। एकत्र भीड़ने इस तरह गैरकान्नी ढंगसे छीने गये झण्डेको वापस माँगा पर उसे नशंसतापूर्वक लाठियोंसे खदेड़ा गया। वंगालमें नमकको लेकर कम ही हमले और गिरफ्तारियाँ हुई, पर स्वयंसेवकोंसे झण्डे छीननेमें ऐसी वेरहमी वरतनेकी रिपोर्टें मिली हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। घानके खेत जला डालने और जवरदस्ती अन छीन लेनेके समाचार मिले हैं। गुजरातमें एक सब्जी मण्डीपर सिर्फ इसलिये हमला वोल दिया गया कि वहाँ अफसरोंके हाथ तरकारी वेचनेसे इनकार किया गया था।

हालाँकि सत्यात्रहियोंको पीटने और यातनाएँ देनेके लिए सरकारने स्वयं न्यायके प्रशासनको तिलांजिल दे रखी थी पर कुछ मामलोंमें न्यायका एक ढोंग कायम रखना वाइसरायने आवस्यक समझा। उन्होंने वंगाल आर्डिनेंस जारी कर दिया और २७ अप्रैलको एक और आर्डिनेंस जारी कर सन् १९१० का प्रेस कान्न लागू कर दिया। गान्धीजीने प्रकाशकों और समाचारपत्रोंको "जमानत देनेसे इनकार करने और माँगे जाने पर या तो अखवार वन्द कर देने या फिर अधिकारियोंको जो चाहें उसे जन्त कर लेने देनेकी" सलाह दी। गान्धीजीने लिखा "जब स्वतन्त्रता हमारे दरवाजेपर थपकी दे रही हैं; उसके स्वागतमें सहसोंने यातनाएँ सही हैं, तब पत्र-प्रतिनिधियोंके सम्बन्धमें यह नहीं कहा जाना चाहिये कि उन्हें परखा गया पर वे खरे नहीं निकलें"। गान्धीजीके साताहिक 'यंग इण्डिया'के प्रकाशक नवजीवन प्रेससे जमानत माँगी गयी, पर गान्धीजीके आदेशपर जमानत देनेसे इनकार कर दिया गया। 'यंग इण्डिया' साइकलेस्टाइलसे निकलने लगा। मईके मध्यमें कांग्रेस कार्य-सितिकी वैठक इलाहावादमें हुई और कार्यसिमितिने जनतासे अपील की कि वह उन सभी "आंग्र भारतीय या भारतीय पत्रोंका बहिष्कार कर दे जो जमानत माँगे जानेके वाद भी प्रकाशन जारी रखते हैं।"

मईके पहले हफ्तेमें गान्धीजीने वाइसरायको एक और पत्र लिखा, (जिसका एक उदरण ऊपर दिया जा चुका है), जिसमें धरसानाके नमक कारखानेपर करना करनेके लिए दूसरे प्रयाणका अपना निश्चय प्रकट किया। इस पत्रमें गान्धीजीने फिर वाइसरायसे नमक कर हटानेके लिए कहा "जिसकी आपके देशके वहुतसे प्रतिभाशाली व्यक्तियोंने कड़े शब्दोंमें आलोचना की है और अवजा आन्दोलनमें परिलक्षित जिसका सार्वजिनक विरोध और निन्दा आपने भी देखी होगी।" इस बार धरसाना-यात्राकी इजाजत नहीं मिली और ५ मई सन् १९३० को गान्धीजी गिरफ्तार कर यरबदा जेल ले जाये गये।

उनकी गिरपतारीका समाचार देशभरमें दावानलकी तरह पैल गया। हर शहरमें वाजार-व्यापार सब फौरन बन्द कर दिये गये। बम्बईमें ५० हजारसे ज्यादा मजदूर अपना काम छोड़कर प्रदर्शनमें भाग लेने सड़कोंपर निकल आये। जी० आई० पी० और बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलचे कारखानोंके कर्मचारियोंने भी ऐसा ही किया। बम्बईके बद्ध-व्यवस्थियोंने ६ दिनतक बाजार बन्द रखकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। सभी प्रदर्शन शान्तिपूर्ण थे; पर शोलापुरमें एक भीड़ने पुल्सिकी छः चौकियाँ जला डाली। पुल्सिने भीड़-पर गोली चलाकर २५ को मार डाला और १०० को घायल कर दिया। हवड़ामें भी कुछ

अशान्ति हुई और पुलिसने भीड़पर गोली चलायी। पाँच व्यक्तियोंसे अधिकके एक जगह इकट्ठे होनेपर रोक लगा दी गयी। जनताका सरकारके विरुद्ध रोष बढ़ता जा रहा था और बहुत-से आत्मसम्मानवाले व्यक्तियोंने सरकारी नौकरियों व अवैतनिक पदोंसे इस्तीफा दे दिया।

गान्धीजीकी गिरफ्तारीके वाद कांग्रेस कार्य-सिमितिकी जो वैठक मईमें हुई उसमें आज्ञामंगकी सीमा वढ़ा दी गयी। उसमें कुछ प्रान्तोंमें करवन्दी आन्दोलन लगानवन्दीसे ग्रुक्त करनेको कहा गया। कार्यसमितिने मध्यप्रान्तमें अंगलात कानून और दूसरे प्रान्तोंमें भो ऐसे ही कानून तोड़नेकी अनुमित दे दी और पुलिस व फौजसे सरकारी आदेशोंका उल्लंबन करनेको कहा।

इस वीच आन्दोलन जारी था। नमक कान् नका तो इना और उसके लिए दण्ड पाना प्रतिदिनकी घटनाएँ हो गयी थीं। लेकिन सत्याप्रहका लक्ष्य घरसाना था जो गान्धीजीकी दूसरी यात्राका लक्ष्य था। सैकड़ों स्वयंसेवक प्रतिदिन वहाँ धावा वोलते। या तो उन्हें ठोंक पीटकर खदेड़ दिया जाता या वे गिरपतार कर लिये जाते। पहला जत्था अव्वास तैयवजीके नेतृत्वमें गया, दूसरा श्रीमती सरोजिनी नाय इके नेतृत्वमें। दो वड़े जत्थे २२० व ४४० स्वयंसेवकों के थे, जिन्हें गिरपतार कर लिया गया था। घरसानापर सबसे वड़ा धावा २१ मईको हुआ जव गुजरातके विभिन्न भागों से आये २५०० स्वयंसेवक वहाँ इकट्ठे हुए। मानों सबसे वड़े जत्थे के मुकावलेके लिए पुलिसने सबसे निर्मम हमला वोल दिया। २९० स्वयंसेवक घायल हुए, जिनमेंसे दोकी मृत्यु हो गयी। ३ जूनको २०० स्वयंसेवकोंके एक जत्थेकी भी यही हालत हुई।

'न्यू फीमैन'के संवाददाता वेत्र मिलरने पुलिसकी ज्यादितयोंका वर्णन करते हुए लिखा "२२ देशोंमें १८ वर्णतक संवादसंग्रहके काममें मैने असंख्य उपद्रव, संवर्ष, गली-कूचोंमें जमकर हुई लड़ाइयाँ और विद्रोह देखे हैं। लेकिन धरसाना जैसे रोंगटे खड़े कर देनेवाले मर्ममेदी दृश्य मैंने कभी नहीं देखे। कभी कभी इतनी पीड़ाके दृश्य होते कि मुझे थोड़ी देरके लिए ऑखें हटा लेनी पड़तीं। स्वयंसेवकोंका अनुशासन आश्चर्यजनक था। लगता था वे गान्धीकी अहिंसासे ओत-प्रोत हैं।" वडाला नमक डिपोपर भी स्वयंसेवक वार-वार धावा बोल रहे थे। लेकिन पहली जूनको सबसे बड़ा धावा हुआ। १५००० सत्याग्रहियों और अन्य व्यक्तियोंने भाग लिया। वडालामें भी पुलिसने लाठीचार्ज किया। "वर्ली नजरबन्दी कैम्पमें २ जूनको वडालापर धावा बोलनेवाले लगभग ४००० वन्दियों और पुलिसमें कहा-सुनी हो गयी जिससे गम्भीर स्थित पैदा हुई। पुलिसको दो बार लाठीचार्च करना पड़ा, फीज बुलायी गयी और ९० व्यक्ति घायल हुए जिनमें २५ के गम्भीर चोटें लगीं।"

मद्रासमें सरकारने लम्बे-लम्बे नुर्माने कर सत्याग्रहियोंको डंरानेकी कोशिश की, पर यह नीति सफल न होने पर उसने भी पुलिसके डण्डेकी शरण ली और जनताको धमकाना शुरू किया। वाजारोंमें खहर पहने या गांधी टोपी पहने लोगाँको बिना कारण पीटा जाता। आंश्रमें कई जगह फौजी पुलिस तैनात की गयी। उसका यह नित्यकर्म या कि वाजारोंमें घूमा जाय और हर रास्तेमें मिलनेवाले हर खहरधारीको ठोंका जाय। उसका यह रवैया

तभी खत्म हुआ जत एलोरमें उसका मुकावला कर लिया गया; पुलिसने गोली चला दी जिसमें दो-तीन व्यक्ति मारे गये और पाँच-छः घायल हुए।

४ जून, १९३० की बैठकमें कांग्रेस कार्यसमितिने जो प्रस्ताव स्वीकार किया उसके अनुसार घरसानामें पुल्सिक अत्याचारोंमें "और अत्याचारोंके अलावा, सत्याप्रहियोंको तव-तक लाठियोंसे मारते लाना जवतक वे अचेत होकर गिर न जाव और फिर उनके ग्रारीर व्होंसे कुचलवाना, सत्याप्रहियोंको नंगा कर उनके गुप्तांगोंमें हण्डे ठूँ सना, एक वालकके शरीरमें ववृत्वके काँटे चुमोना और उसके अण्डकोपपर प्रहार करना" भी ग्रामिल थे। प्रस्तावन्में कहा गया था—"लखनकमें अपने बरोंके छजों और गवाक्षोंमें खड़े लोगोंपर २६ मईको गोली चलायी गयी और उन्हें धायल किया गया। कुछ दूकानें भी पुल्सि द्वारा लूटी गयीं।"

मईके पहले सताहमें ही कांग्रेसके लगभग सभी वहें नेता पक दें जा चुके थे। कांग्रेसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू १४ अग्रैलको गिरफ्तार किये गये और उनकी जगह मोतीलारू नेहरू कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए। गान्धीजीकी गिरफ्तारीके वाद अध्यक्ष तैयवजी डिक्टेटर नियुक्त हुए, वे भी गिरफ्तार हो गये। २७ जूनको कांग्रेस कार्यस्मितिने सत्याग्रहका एक नया रूप वताया। उसने जनताको राय दी कि जहाँ भी सम्भव हो वह सरकारसे अपना पावना रूपये या नोटोंमें न ले और सोना माँगे। कार्यसमिति सरकारी मुद्राओंसे जनताका विश्वास डिगा देना चाहती थी। पर इस प्रस्तावके प्रति जनताने विशेष उत्साह नहीं दिखाया।

एक अन्य प्रस्ताय द्वारा कार्यसमितिने जनतासे अपील की कि वह "उन सरकारी अफसरों व अन्य व्यक्तियोंका समाजिक वहिष्कार करे जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलनको कुचलनेमें प्रस्यक्ष भाग लिया है। इस प्रस्तावका भी विद्योप असर नहीं हुआ।

२० जूनको कांग्रेस कार्यसमिति गैर-कान्ती संस्था घोषित कर दी गयी और अध्यक्ष मोतीलाल नेहरूको गिरफ्तार कर छः महीनेकी सजा दे दी गयी । कुछ प्रान्तीय व जिला कांग्रेस कमेटियाँ भी गैर-कान्ती संस्थाएँ घोषित कर दी गयाँ ।

उच्चिषिकारियों के आदेशोंका पालन करते हुए पुलिसने जो असंख्य अत्याचार किये, उनके वर्णनके लिए एक पूरी पुरतक भी काफी न होगी। यहाँ कुछ उदाहरण भर दे दिये जाते हैं। पुलिसकी वर्यरताका प्रत्यक्षदर्शी विवरण देते हुए एक फ्रांसीसी महिलाने लिखा है—''इसमें संशय नहीं कि अंग्रेज अफसरोंकी मातहतीमें भी पुलिस बहुधा सरकारके प्रति निष्ठाहीनताके लिए शारीरिक दण्ड देती है। कलक जे में विश्वविद्यालयके छज्जेमें खड़े कुछ छात्रोंने शान्तिपूर्ण जल्हमपर पुलिसका यर्वर प्रहार देखकर 'कायर' कहा। दो वण्टे याद, एक अंग्रेज अफसरके अधीन पुलिस विश्वविद्यालय वापस लोटी और कक्षामें बेटे छात्रोंको अन्धानुन्ध पीटना शुरू किया। कक्षाकी दीवालोंपर खन्के धन्वे पड़ गये। विश्वविद्यालयके अधिकारियोंने इसकी शिकायत की पर पुलिसको कोई दण्ड नहीं मिला एएसी ही यटना लाहौनमें हुई जहाँ एक अग्रेज अफसरके नेतृत्वमें पुलिसने एक कालेजपर छापा मारा और सिर्फ छात्रोंको ही नहीं यिक अन्यापकोंको भी पीटा। इस इमलेके लिए यह वहाना लिया गया या कि बुछ छात्र (मुझे विश्वास दिलाया गया कि वे एक दूसरे कालेजके थे) सड़कपर शान्तिपूर्ण धरना दे रहे थे। कोण्टइ (वंगाल) में एक निरीह शान्तिपूर्ण भीड़को तितर-वितर करनेके लिए पाँच शामीणोंको एक तालावमें ढकेल कर हुवा दिया

गया। मेरठमें मेरी एक प्रमुख वकीलसे मेंट हुई, जो एक सभाके प्रमुख वक्ता थे। गिरफ्तार करनेके वाद पुलिसने उन्हें ठोंकना शुरू किया और इसी हालतमें एक सिपाहीने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनका हाथ काटना पड़ा।"

गुजरातके सम्बन्धमें जहाँ किसानोंने मालगुजारी देनेसे इनकार किया था, उक्त महिलाने लिखा है—"गुजरातके गाँवोंमें पुलिसकी वर्वरताके मुझे अनेक प्रमाण मिले क्यों-कि मैं वहाँ चार दिन घूमी । कानृनी दमन स्वयं काफी कठोर था । कैरा और बारदोली जिलोंके लगभग सभी किसान गान्धी-भक्ति, स्वराज्यकी आकांक्षां,और भयानक मन्दीके कारण गिरी गरुहेकी कीमतों आदि कई कारणोंसे मालगुजारी देनेसे इनकार कर रहे थे। इसका जवाव यह था कि उनके खेत, गाय, भैंस सिंचाईके पम्प आदि जब्त कर लिये जाते और उन्हें नाममात्रकी कीमतपर वेच दिया जाता—यहाँतक कि ४० रुपयेकी कर-अदायगीमें किसानोंका सर्वस्य चला जाता। यही नहीं, वस्लीकी तिथि भी तीन महीने घटा दी गयी थी। जिन किसानोंने १९३० के दो लगान जमा कर दिये थे, उनसे १९३१ की जनवरी वाली किस्त अक्तृवरमें ही माँगी जाने लगी। यह सब कानूनी दृष्टिसे शायद ठीक रहा हो पर यह कड़ाईकी हद थी । इसके ऊपर मारपीटका आतंक आया । पुल्लिस राइफिलें और लाठियाँ लेकर आती और गाँव घेर लेतो । और फिर लाठियों तथा राइफिलोंके कुन्दोंसे किसानोंको अन्धाधुन्ध ठोंकना ग्रुरू करती । मेरे पास ४५ घायलोंके वयान हैं । इनमेंसे दो को छोड़कर (एक जवान लड़की लजावरा अपनी चोटें नहीं दिखा रही थी) रोष सभीकी चोटें और घाव मैंने देखे। इनमेंसे कुछ लोगोंको गम्भीर और गहरी चोटें आयी थी। एक व्यक्तिका हाथ टूट गया था, एकका अँगृठा ऐसे तोड़ दिया गया था कि हड्डी बाहर दिखाई पड़ती थी, दूसरोंके शरीरोंपर मारके निशान थे । वहुतसे ऐसे घायलोंको मैं नहीं देख सकी जो एक दूरके अस्प तालमें भरती थे। कभी इस अत्याचारका उद्देश्य लगान वसूली होता, कभी कभी मार्पीटके वाद या भैंस कन्जेमें ले लेनेके वाद कोई कोई व्यक्ति सरकारी देना अदा कर देते—हालाँ कि कानूनी तौरपर अदायगीकी तिथि अभी नहीं आयी थी। मेरे पास ऐसे भी कई लोगोंके वयान हैं ज़िन्हें ख़ुद लगान नहीं देना था पर मारपीट कर गैरहाजिर पड़ोसीका लगान उनसे वसूल कर लिया गया । एक गाँवमें पेड़ों व घरोंपर लगे राष्ट्रीय झण्डे उतारकर फाड़ डाले गये और आठ किसानोंको सिर्फ इमलिये पीटा गया कि उनके घर इन झण्डोंके पास थे। दो व्यक्तियोंको तयतक मारा जाता रहा जवतक उन्होंने गान्धी टोपी न उतार ली। एक व्यक्ति पर तवतक लाठीसे प्रहार किया जाता रहा जबतक उसने पुलिसको सात बार सलाम नहीं कर लिया । उसे कुल वारइ लाठियाँ लगीं । पुलिसका एक आम मजाक यह था कि वह किसीसे पूछती—'तुम स्वराज्य चाहते हो ? तो यह लो' और खटसे उसके सिर लाठी पड़ती सबसे खराव बात तो यह थी कि भारतीय सिविल व पुलिस अफसर 'जरायमपेशा' वरियोंकी पट्टीदारोंके खिलाफ मड़काते थे। वरियोंसे कहा जाता कि इनका उधार न चुकाओ, इनकी घरोंमें आग लगा दो । मेरे पास कई गाँवों के पाँच वरियों के वयान मौजूद हैं।

"में दो भारतीय अफसरोंसे मिली और मुझे उनका रंगढंग देखनेको मिला। एक अफसरने मेरे सामने एक वर्बर हमला कर दिया। अन्तमें मैंने वोरसदमें हवालातियों को रखनेका एक कटघरा देखा। ३०-३० फुट लम्बी चौड़ी चिड़ियाखाने जैसी इस खोहमें सीखचे लगे थे। इसमें १८ हवालाती दिन-रात वन्द रहते थे। उन्हें पढ़ने लिखने या

काम करनेकी इजाजत नहीं थी । एक व्यक्ति इस कटघरेमें छैं: इफ्तेंसे वन्द था । कटघरा दिन-में सिर्फ एक बार पीन घण्टेके लिये खुलता था, जब बन्दी शीचादिसे निवृत्त होते थे ।'''

१ अगस्त १९३० को कांग्रेस कार्यसमितिने निम्नलिखित कार्यक्रम वनाया—विदेशी वर्लीका वहिष्कार, नशावन्दी, प्रान्तीय व केन्द्रीय विधानमण्डलींका वहिष्कार, त्रिटिश सामानका वायकाट, डाकखानों व केश सर्टीफिकटोंमें जमा रुपया फौरन निकाल लेना, सरकारी गजटोंका वहिष्कार, सरकारी अफसरोंका वहिष्कार, फौज व पुलिससे सरकारी आदेशोंका उल्लंघन करनेकी अपीलवाला कार्यसमितिका प्रस्ताव छापकर उनमें बाँटा जाना, लगान व दूसरे कर अदा न करना, व्यापार सम्बन्धी विवादोंका पंच समझौता कर लेना, लात्रोंसे राष्ट्रीय आन्दोलनमें भाग लेनेकी अपील, अंग्रेजी जहाजी बीमा व वैंक कम्पनियोंसे सहयोग वापस लेना, स्वदेशिक प्रयोगका प्रचार।

गुजरातके वारदोली और वोरसद ताब्लुकोंमें पुल्सिका दमन और अत्याचार इतना ज्यादा था कि ८०००० लोग वहाँसे घर छोड़कर पासकी वड़ीदा रियासतमें चले गये। इस निर्वासनका वर्णन करते हुए बेल्सफर्डने लिखा है—"वहुतसे सवाल करने पर में एक इस्य अपने दिमागमें वना पाया । यह अफवा गाँवकी वात है, जो बीरान हो गया था । वहाँ कुछ भुमिर्द्यान लोग रह रहे थे और ऋछ किसान वड़ोदासे लौटकर खेत जीतने-बोने आ गये थे। २१ अक्तूबरको रातमें ३ वने दस सिपाहिबोंको एक मोटरमें लादे एक थानेदार उधरसे गुजरा। पुलिस उतर पड़ी और खेतींपर सी रहे इन लोगोंकी टींकना शुरू कर दिया। फिर ये लोग ् खींचकर थानेदारके पास लाये गये । थानेदारने खुद उन्हें वृटकी ठोकरों और हाथोंसे मारा । एक व्यक्ति तव मी लॅंगड़ाता था जब में वहाँ पहुँचा । एक और व्यक्तिके तब भी सूजन बनी हुई थी। थानेदारने दो माइयोंके सिर लड़ा दिये। फिर उन्हें लारीमें बन्द कर बारदोलीकी हवालातमें ले जाया गया। वहाँ थानेदारने न छापने योग्य भाषामें बताया कि किस प्रकार वह उन्हें 'उनकी पत्नियोंके अयोग्य'कर देगा । इस धमकीका यह असर हुआ कि छोटे भाई-पर कोई लगान बकाया न होने पर भी उसने वापके खेतका ही बकाया अदा कर दिया। एक दसरे मामलेमें थानेदारने एक राहगीरको पकड्वा बुलाया, उनके रुपये छीन लिये और एक दूसरे गाँवके किसानका वकाया लगान उन रकमसे पूरा कर रतीद काट दी और इस अजनवीको मार-पोटकर वह रसीद देकर कहा - जा कर उससे अपनी रकम वसल कर।" बोरसदमं पुलिसने "औरतोंको गिराकर अपने वृटोंसे उनके सीने कुचल कर" २१ जनवरी १९३१ को आखिरी नरकके दर्शन कराये।"

गुजरातके लगानवन्दी आन्दोलनकी 'काफी सफलता' सरकारी तौरपर भी स्वीकार की गयी। !

लगानवन्दी आन्दोलन दूसरे प्रान्तोंमें भी छोटे पैमानेपर चला। संयुक्तप्रान्तमें किसानों व जमींदारों-दोनोंसे लगान व मालगुजारी न देनेकी अपील की गयी थी और आन्दोलन "देशके वहे-बढ़े हलाकोंकी जनतापर प्रभाव डाल रहा था।" विदारमें चौकीदारी कर बहुत

९. पहाभि सीतारमैया, हारा उब्धत वही पुस्तक, पृष्ठ ४०७-९

२. पटाभि सीतारमैया द्वारा उद्धत, 'वही पुस्तक', पृष्ट ४२०

३. वही पुस्तक, पृष्ट ४२०

४. 'इण्डिया इन १९२०-३१' पृष्ट ८९

लोगोंने रोक लिया और इसके बदलें उनपर सामूहिक जुर्माने हुए और उनकी जायदादे जन्त हो गयीं । मध्यप्रान्तमें जंगलात कान्न भंग करनेका जवाब भारी जुर्मानों और पुलिसके अत्याचारोंसे दिया गया । इन इलाकोंमें कर्नाटक सबसे आगे था । वहाँका जिलेबार विवरण इस प्रकार है—कनारामें लगानवन्दीके लिए ८०० परिवारोंको परेशान किया गया; सिद्धापुर और अंकोलामें १०० स्त्रियों और ७०० पुरुषोंको कैदकी सजाएँ दी गयीं; यहाँ २००० एकड़ जमीन जन्त कर ली गयी, १६६ मकान छीन लिये गये और सम्पत्ति व पसलका १५ लाख रपयेका नुकसान हुआ; ३३० परिवार पीड़ित हुए । सिद्धपुरमें जन्त सम्पत्ति खरीदनेवालोंके घरोंपर ३७ महिला सत्याग्रहियोंने अनशन किया । मवीनागुण्डीमें एक महिलाने ३१ दिनतक अनशन किया । बहुतसे तालुकोंमें वड़ी संख्यामें ताड़ काट डाले गये।

चित्र पूरा करनेके लिए दूसरे प्रान्तोंके कुछ उदाहरण भी दे दिये जाउँ। वंगाल और आन्ध्रमें बहुतसे श्रान्तिप्रिय नागरिकोंको सिर्फ इसलिए जेलोंमें डाल दिया गया कि उन्होंने सड़कोंसे पुलिस अत्याचारोंके शिकार खूनसे लथपय सत्याग्रहियोंको उटाया, खानापानी या शरण दी। कोण्टईमें सत्याग्रहियोंके नमक बनानेकी तैयारी दूरले देखते हुए बहुतसे श्रान्तिपूर्ण नागरिकोंपर गोली चलायी गयी; छः मर गये और १८ घायल हुए। १९३०-३१ में हुए पुलिस-अत्याचारोंके विवरणोंसे पुस्तकों भर जावँगी। नेताओंके आदेशका पालन करते हुए जनता आम तौरपर शान्त और अहिंसक रही। इसके कुछ अपवाद भी थे और एक जगह रियति गम्भीर हो उठी। उन्होंने पुलिसवालोंको गिरपतार कर एक स्कूलमें वन्द कर दिया और इमारतमें आग लगा दी, पर कांग्रेसके दो स्वयंसेवकोंने अपना जीवन संकटमें डालकर स्कूलका दरवाजा तोड़कर पुलिसवालोंकी जानकी रक्षा की। मिदनापुरमें एक भीड़ने दो चौकीदारोंको मार डाला।

पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तमें घटनाओं ने दूसरा रूप धारण किया। वहाँके कांग्रेसी नेता खाँ अन्दुल गफ्पार खाँने लाल कुरतीवाले खुदाई खिदमतगारों का एक संघटन वनाया था। १९३० के ग्रुक्तमें इस संघटनमें भरती तेजीसे ग्रुक्त हुई। हालाँ कि देशके दूसरे भागों में मुसलमान कांग्रेसके आन्दोलनसे अलग रह रहे थे। अन्दुल गफ्पार खाँके प्रभावसे सीमाप्रान्तके मजनूत पठान वड़ी संख्यामें इसमें भरती हुए। गान्धीजीकी पिनत्रता, सादगी और संकल्प अन्दुल गफ्पार खाँमें भी था और लोग उन्हें सीमान्त गान्धी कहने लगे थे। वे अहिंसामें विश्वास करते थे और उन्होंने लड़ाकू पठानोंको भी अहिंसक बना लिया था। लेकिन लाल कुरतीवालोंकी वरदी, अनुशासन, फुरती देखकर लोगोंको लगता था कि जरा-सी उत्तेजनामें वे अपनी अहिंसा छोड़ देंगे। उनके त्यागका जनतापर बड़ा प्रभाव पड़ा था और वह उनने रनेह करने लगी थी। उनके नेताने उन्हें दो उद्देश्योंके लिए काम करना वताया था—एक मुहक्की आजादी और दूसरे भूखेको खाना और नंगेको कपड़ा देना।

सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें उन्हें इन दो उद्देशों के लिए संघर्षमें अपना परिचय देने का मौका मिला । सीमान्तमें आन्दोलन इस प्रकार ग्रुरू हुआ—२२ अप्रैल १९३० को कांग्रेस महासमितिका एक प्रतिनिधिमण्डल सीमान्त विनियमों के कार्यान्वित होने के ढंगका अध्ययन करने अटक पहुँचा; वहाँ उसे रोक लिया गया। खबर पेशावर पहुँची और पठानोंने एक जल्म निकाला व एक सभा इसके रोक के विरोध में की। अगले दिन सवेरे ही उनके ९ नेता गिरफ्तार कर लिये गये। ९ वजे दो और गिरफ्तार हुए।

लेकिन जिस मोटरमें वे हवालात ले जाये जा रहे थे, वह विगड़ गयी। इन दोनों नेताओंने आखासन दिया कि वे स्वयं थाने पहुँच जायँगे। पर जैसे ही वे थानेके लिये रवाना हुए, रास्तेमें एक वड़ी भीड़ इकट्टी हो गयी और उन्हें छेकर थानेकी तरफ चली। थाना ्वन्द था, पर फीरन दो तीन वख्तरवन्द गाड़ियाँ आयों और भीड़को चीरने लगीं; "१२-१४ व्यक्ति कुचल गये, जिनमेंसे ६-७ तो वहीं फौरन मर गये, वाकी बुरी तरह घायल हुए।" तमी एक अंग्रेज मोटर साइकिल्पर वेतहाशा भागता हुआ आया और वस्तरवन्द गाड़ीसे लड़कर कुचल गया । एक गाड़ीमें भी आग लग गयी । सरकारी वयान था कि इन दोनों घटनाओं के लिए भीड़ जिम्मेदार थी। पर उस वक्त तो सचाई जाननेकी फुरसत नहीं थी, दूसरी दो गाड़ियोंने फौरन भीड़पर गोली चलाना शुरू कर दिया। भीड़ चाहती थी कि मृतक और घायल उसे दे दिये जायँ और फौजी व गाड़ियाँ हुटं जायँ, तत्र वह हुटे। गोली चलने पर वह तितर वितर हुई पर गोली चलना वन्द होते ही वह फिर इकट्ठी हो गयी। फिर गोली चली और भीड़ फिर हटी, पर फिर इकट्ठी हो गयी। यह तीन घण्टेतक जारी रहा । सरकारी वयानके अनुसार ३० व्यक्ति मरे और ३३ धायल हुए । पर गैर-सरकारी अनुमानके अनुसार हताहतोंकी संख्या पाँच छः सौतक पहुँची थी। इस घटनासे और गम्भीर वटनाओंको प्रेरणा मिली और उसीमें रायल गढ़वाल राइफिल्सकी दो पलटनोंने निहत्थी भीडपर गोली चलानेसे इन्कार कर दिया । ये दो पलटनें तभी बुलायी गयी थीं जब पुलिस खितिपर कावू पानेमें असमर्थ हो चुकी थी। अधिकारियोंने ये लक्षण देखे तो पेशावर-से सभी पुलिस और फीज हटा ली और शहर खाली छोड़ दिया। गान्धीजीको फीजियोंकी हब्मउदली परनद नहीं आयी और बादमें एक विदेशी पत्रकारसे कहा—"जो सिपाही गोली चलानेसे इनकार करता है, वह कसम तोड़ता है।" २४ अप्रैलसे ४ मईतक पेशावरमें अंग्रेजी हुकुमत नहीं रही । अब्दुल गफ्फार खाँ २३ अप्रैलको ही गिरफ्तार कर लिये गये थे । वन्नु, कोहाट, मरदान व कुछ देहाती इलाकोंमें इसी तरहकी अशान्ति हुई। पेशावरकी घटनाओं के फीरन बाद अशान्तिके लक्षण पूरे सीमाप्रान्तमें हजारासे डेरा इस्माइल खाँतक दृष्टिगोचर होने लगे।

सीमाप्रान्तके कवीले ब्रिटिश सरकारसे ये इलाके छीन लेनेकी सीचने लगे। मईकें दूसरे हफ्तेमें चार हजार वजीरियोंने एक ब्रिटिश चौकोपर हमला बोल दिया। जवाबमें अंग्रेजोंने कवीलेवालोंके गावोंपर भीपण बमवारी की। रे जूनको ५००० अफरोदियोंका एक बड़ा लक्कर वाहा और बाजार घाटियोंमें उतर आया और गुफाओंमें जमा होने लगा। ४ जूनकी रातको २००० अफरोदियोंने पेशावर जिलेपर हमला वोल दिया। काफी लोग शहरतक जा पहुँचे। जून और जुलाई भर कवीलेवाले पेशावर जिलेके शहर व गाँवोंपर आक्रमण करते रहे। ७ अगस्तकी रातको अफरीदियोंने फिर एक जोरदार हमला किया, पर वह भी असफल रहा। मुख्ला लोग विभिन्न कवीलोंमें घूम-घूमकर विद्रोह करनेके लिए लोगोंको उभारते थे। अंग्रेज विद्रोहको शान्त करनेके लिए हवाई जहाजोंसे बमवारी कर रहे थे। स्थित इतनी गम्भीर थी कि साधारण प्रशासन कायम करना और चलाना असम्भव हो रहा था। अन्तमें अगस्तमें मार्शल लोगू कर दिया गया जो जनवरीतक लागू रहा। सरकारी रिपोर्टके अनुसार 'विशेप ध्यान देनेकी वात यह थी कि आवाद जिलेंमें घूमते हुए इस पूरे जमानेमें कवा-

१. 'इण्डिया इन १९३०-३१' पृष्ठ १७

यिलयोंने अपनी परम्पराके विरुद्ध गाँबोंको दो वार छोड़कर कभी नहीं लूटा और अधिका-रियोंसे समझौतेकी वात चलाते वक्त अफरीदियोंने गान्धीकी रिहाई और भारतमें जारी विशेष आर्डिनेंस वापस लेनेकी माँगें भी रखी, जिससे सावित होता है कि कांग्रेसी प्रचारक सीमाके उस पार भी सिक्रय थे।

मरदानमें २५ मईको एक भीड़ और पुलिसके बीच गम्भीर संवर्ष हो गया। पुलिसका सहकारी कप्तान मर्फी बुरी तरह मार डाला गया। सीमायान्तके जो चार जिले अशान्त हुए, उनमें बन्नूमें सबसे अधिक जोर रहा। ८ अप्रैलको रामसिंह नामक एक कांग्रेसी कार्यकर्त्ताकी गिरफ्तारीके विरोधमें एक कुद्ध भीड़ने शहर कोतवाली घेर ली, बाग उजाड़ दिया और पासमें गोल्फ खेलते हुए अंग्रे जोंपर पत्थर व कीचड़ फेंका। ११४ अप्रैलको शहर आनेवाले सभी रास्तोंपर फीज तैनात कर दी गयी ताकि गाँवोंसे लोग प्रदर्शनमें भाग लेने न आ सकें। इसके विरोधमें कांग्रेस कमेटीने आम इड़तालका संघटन किया, यह इड़ताल अनिश्चित कालके लिए थी, पर १९ को खत्म कर दी गयी। पर कवायलियोंके विद्रोहके कारण जुलाईमें फिर शहरके फाटक बन्द हुए और शराब व विदेशी कपड़ोंकी दूकानोंपर धरना देनेवाले ४४० स्वयंसेवक गिरफ्तार किये गये।

अगस्तमें फज्लेकादिर नामक एक मुल्लाने एक सशस्त्र जत्था इकट्ठा कर लिया और ६ वीं रायल बटालियनकी एक दुकडीपर हमला कर दिया। दुकड़ीके आठ सिपाही और कप्तान ऐशकापट मारे गये। जो संघर्ष हुआ उसमें बादमें मुल्लाके चालीस साथी खेत रहे (जिनमें मुल्ला भी था), तीस घायल हुए और ८० गिरपतार हुए।

सविनय अवजा आन्दोलन देश भरमें सफल रहा । खुद सरकारक अनुसार "कांग्रेस-को अपनी काररवाइयोंके लिए जनताका समर्थन जिस सीमातक मिला वह कांग्रेस और सरकार दोनों पक्षोंके योग्य लोगोंके अनुमानोंसे कहीं ज्यादा था। जुलाई गुरू होते-होते विटिश भारतका कोई प्रान्त आन्दोलनके प्रभावसे अछ्ता न रहा और आसाम व मध्यप्रान्त-को छोड़कर शेष सभी प्रान्तोंकी सरकारोंको उन घटनाओंका सामना करनेमें कभी न कभी बड़ी कठिनाई पड़ी जो इस आन्दोलनके फलस्वरूप घटों। आन्दोलनके पहले महीनेके बाद नमक कानून भंग करनेके देशके हर वड़े शहरमें हुए दिखावे व किसी हदतक बुद्धिहीन प्रदर्शनोंकी जगह कांग्रे सकी दूसरी काररवाइयोंने ले ली। बम्बईमें, जहाँ यह आन्दोलन सम्भवतः सबसे अधिक सफल हुआ, स्थानीय नेताओंने आस पासके नमक बनानेके तटों पर हमले संघटित करना शुरू कर दिया। पर यह काम मानसून शुरू होने पर खत्म हो गया। तव और प्रान्तोंकी तरह वहाँ भी विदेशी सामानके वहिष्कार और शराव व विदेशी वस्त्रोंकी दूकानोंपर धरना देनेका काम शुरू हुआ और इन दोनों दिशाओंमें विभिन्न प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंको काफी सफलता मिली। सरकारी कर्मचारियोंके सामाजिक बहि ष्कार और जनताको कर न देनेके लिए उभारनेका काम भी वड़े पैमानेपर हुआ जिससे अधिकारियोंको काफी परेशानीका सामना करना पड़ा । स्कूलों व विश्वविद्यालयोंमें कांग्रेसी काररवाइयोंसे भी कुछ दिक्कत हुई । पुल्सि और फौजमें निष्ठाहीनता पैदा करनेके प्रयास भी हुए पर ब्रे लगभग पूर्णतः असफल रहे।""

१. वही पुस्तक, पृष्ठ १७

२. 'इपिडया इन १९३०-३१' पृष्ठ ७२.

"जिस दूसरे स्त्रसे कांग्रेसको अप्रत्याद्यित सहायता मिली वह स्त्रियाँ थीं । इजारों रित्रयाँ, जिनमें काफी अच्छे घरोंकी और पढ़ी-लिखी थीं, एकाएक अपने घरोंके एकान्तरें बहुधा परदा-प्रथा तोड़कर, निकल पड़ीं और कांग्रेस-प्रदर्शनों व घरना देनेमें भाग लेने लगीं "—पहले तीन महीने खत्म होते न होते आन्दोलन कई दिशाओं में आश्चर्यजनक हंगसे सफल साबित होने लगा और सरकारके सारे साधन व शक्तियाँ आन्दोलन कुचलनेमें लग गयीं।"

मध्यप्रान्तमें, जहाँ आन्दोलन अपने प्रथम चरणमें कुछ ढीला रहा, जुलाई, अगस्त व सितम्बर्में जंगलात कानूनोंके विरुद्ध बहे और सार्वजनिक प्रदर्शन होते रहे; आदिवासी भी सरकारके खिलाफ उठ खहे हुए । २४ अगस्तको गोंड जातिकी एक भीड़ने पुलिसकी एक हुकड़ीपर बेन्लमें इमला कर दिया । गोंड बढ़े पैमानेपर जंगलात कानून मंग कर रहे थे । कांग्रेस आन्दोलनके दूसरे चरणके अस्थायी लक्षणोंमें विधानमण्डलोंके चुनावोंका विहिष्कार, लन्दनमें होनेवाले गोलमेल सम्मेलनके विरुद्ध १२ नवम्बरके प्रदर्शन और पुलिस व जनताके वीच कुछ मुठभेड़ें भी थीं । इनमें सबसे अधिक स्मरणीय कुछ स्थानोंपर समानान्तर ग्रासनतन्त्र स्थापित करने—स्वराज्य अदालतें वनानेके प्रयास थे । ब्रिटिश सामानका विह्प्कार कारगर हंगमे चल रहा था । नवम्बरमें आन्दोलन कुछ शियिल हुआ था, पर दिसम्बरमें उसमें फिर तेजी था गयी । कई जगह उपद्रव भी हुए । धरनेने जोर पकड़ा और सार्वजनिक समाऑकी संख्या वढ़ चली । २६ कांग्रेस कमेटियाँ जनमें कांग्रेस कार्य-समिति व अन्य कांग्रेस कमेटियाँ यां, उनसे समबद्ध आन्दोलन परिपदें व अन्य संघटन और पंजाव व संग्रक्तानिकी नीजवान भारत सभाएँ—ये सब गैरकान्नी करार दे दी गयीं ।

जुलाईमें जब कांग्रेसी आन्दोलन और सरकारी दमन दोनों अंपनी चरम सीमापर ये; दो नरमदलीय नेताओं - सर तेजबहादुर सप्रृव एम. आर. जयकरने वाइसरायको एक पत्र लिखा और "सामान्य परिस्थिति पैदा करनेके लिए" आन्दोलनके कुछ नेताओंसे वातकर रियति सुधारनेका प्रयास" करनेके लिए अपनी सेवाएँ प्रस्तुत की । वाइसरायने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और ये दोनों नेता २३ जुलाईको यरवदा नेलमें गान्धीजीसे और २७ जुलाईको नैनी जेलमें मोतीलाल नेहरू व जवाहरलाल नेहरूसे मिले। नेहरू पिता-पत्र व गान्धी जीके बीच सिंध प्रस्तावके सम्बन्धमें पत्रव्यवहार सफल होते न देख सरकारने इनको भी यरवदा जेल भेज दिया। वहाँ श्रीमती सरोजिनी नायहू, वल्लभ भाई पटेल, जयरामदास दौलतराम, डाक्टर सैयद महमूद, गान्धीजी व नेहरू आदि १५ नेताओंमें विचार विमर्श हुआ । इन लोगोंके संयुक्त इस्ताक्षरोंसे एक पत्र सप व जयकरको लिखा गया, हालाँ कि यह पत्र था वाइसरायके लिए । पत्रमें समझौतेके प्रस्तावोंका वर्णन था । उसमें लिखा था—"कोई समझौता तयतक सन्तोपजनक नहीं हो सकता जवतक (१) भारतका स्वेच्छासे ब्रिटिश सामाज्यसे पृथक होनेका अधिकार स्वीकार नहीं कर लिया जाता, (२) भारतमें पूर्ण रूपेण उत्तरदायी राष्ट्रीय सरकार नहीं वनती जिसके अधिकारक्षेत्रमें रक्षा व आर्थिक नियन्त्रण हो और वाइसरायको गान्धीजी द्वारा मेजा गया ११ सूत्री कार्यक्रम पूरा नहीं होता (३) भारत-को यह अधिकार नहीं मिलता कि जिन ब्रिटिश दावोंको वह राष्ट्रहितमें न समझे उन्हें किसी

१. वही पुस्तक, पृष्ट ७३.

निष्पक्ष ट्रिन्यूनलके सामने पेश कर सके।" इन नेताओंने ये शतें वाइसराय द्वारा मंजूर होने पर आन्दोलन वापस लेनेका आश्वासन दिया पर नमक बनाने व शराव और विदेशी वस्त्रोंकी दूकानोंपर घरना जारी रखनेका इरादा जाहिर किया। पत्रमें लिखा था कि नमक बनता रहेगा पर नमक गोदामोंपर धावे न होंगे। सपू व जयकर यह पत्र लेकर वाइसरायके पास गये। वाइसरायने २८ अगस्तको इन लोगोंको जवाब दिया कि इस पत्रमें लिखी शतोंके आधारपर समझौतेकी बात करना असम्भव है।

वाइसरायने मईमें घोषणा की थी कि अक्तूबरके अन्तमें लन्दनमें गोलमेज सम्मेलन होगा। देशमें भावना व्याप्त थी कि कांग्र सके प्रतिनिधियोंके विना गोलमेज सम्मेलन असम्मव है। केन्द्रीय विधायिका कोंसिलके जुलाई अधिवेशनमें वक्ताओंके बहुमतने अनुरोध किया कि ''देशको शान्त करने व सान्त्वना देनेके लिए '' और गोलमेज सम्मेलनको आरम्म करनेके लिए आवश्यक शान्तिपूर्ण वातावरण पैदा करनेके लिए सरकारको गान्धीजी व दूसरे कांग्र सजनोंको मुक्त कर देना चाहिये। सपू-जयकर प्रयास असफल होनेके बाद कांग्र सका गोलमेज सम्मेलन के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट था। अक्तूबरमें सम्मेलनके प्रतिनिधियोंके विरुद्ध प्रदर्शन संघटित किये गये। राष्ट्रीय समाचारपत्रोंसे कहा गया कि वे सम्मेलनकी खवरें न छापें। कुछ दिनों-तक अखबारोंने यह बात मानी भी पर १२ नवम्बरसे सम्मेलनकी काररवाई छुक होने पर उसकी खवरें महत्त्वपूर्ण होनेके कारण बहुत प्रमुख स्थान पाने लगीं। सम्मेलनमें ८६ प्रतिनिधि थे --५७ ब्रिटिश भारतके, १६ देशी रियासतोंके और इंगलैण्डके विभिन्न राजनीतिक दलोंके। सम्मेलनने विभिन्न विषयोंपर विचार करनेके लिए उपसमितियाँ बना दीं। रक्षा, मतदान, सीमा, अल्प-संख्यक, बर्मा, सरकारी नौकरियाँ, प्रान्तीय अधिकारक्षेत्र, संघीय, दाँचा आदि विषयोंपर बनी समितियोंकी रिपोटोंपर १९ जनवरी सन् १९३१ से सम्मेलनने फिर विचार शरू किया।

२१ जनवरीको कांग्रेस कार्यसमितिकी वैठकमें एक प्रस्तावमें कहा गया कि सम्मे-लनकी काररवाईको कांग्रेस कोई मान्यता नहीं देती; सम्मेलनमें भारतके प्रतिनिधित्वके लिए सरकारने अपने ही समर्थक नियुक्त कर दिये हैं।

सम्मेलनके खुले अधिवेशनमें ब्रिटिश प्रधान मन्नीने घोषणा की कि "ब्रिटिश सरकार चाहती है कि भारतमें शासन चलानेका उत्तरदायित्व केन्द्रीय व प्रान्तीय विधानमण्डलोंको ऐसे प्रतिवन्धोंके साथ दिया जाय जिससे संक्रमणकालमें कुछ विशिष्ट दायित्व निभ सके, विशेष परिस्थितयोंपर काबू पानेकी व्यवस्था हो और अल्पसंख्यकोंकी राजनीतिक स्वतन्त्रता और उनके अधिकारोंकी रक्षाका विधान हो सके।"

सम्मेलन वादमें होनेके लिए स्थगित हो गया। २१ जनवरीको राजेन्द्रप्रसादकी अध्यक्षतामें काफी नये सदस्योंसे बनी कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठक नयी परिस्थितिपर विचार करनेके लिए बैठी और एक प्रस्ताव द्वारा घोषणा की गयी कि "उस तथाकथित सम्मेलनकी काररवाईको मान्यता देनेके लिए कांग्रेस विलक्षल तैयार नहीं है, जिसमें ब्रिटिश पार्लमेण्टके कुछ सदस्य हों, देशी महराजे हों और सरकार-समर्थकों मेंसे नियुक्त—भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित नहीं—कुछ भारतीय हों।"

लेकिन स्वतन्त्रता दिवससे एक दिन पहले २५ जनवरीको वाइसरायने सरकारके इस निर्णयकी घोषणा की कि गान्धीजी और कांग्रेस कार्यसमितिके सभी सदस्य और वे लोग जो १ जनवरी १९२० के बाद कार्यसमितिके सदस्योंकी हैसियतसे कार्य करते रहे हों, विना शर्त रिहा कर दिये जायँ तथा कांग्रेस कार्यसमितिको वैधानिकता दे दी जाय। वाइसरायने कहा कि ब्रिटिश प्रधान मन्त्री द्वारा १९ जनवरीको की गयी घोषणापर विचार करनेका अवसर देनेके लिए यह किया जा रहा है।

२६ जनवरीको आधी रातके पहले कार्यसमितिके २६ स्थायी और अस्थायी सदस्य रिहा कर दिये गये। मोतीलाल नेहरू वीमारीके कारण पहले ही छोड़ दिये गये थे; उनकी यह बीमारी घातक सिद्ध हुई। जेलसे छूटते ही गान्धीजीने संवाददाताओंसे कहा कि में खुले दिमागसे मसलेपर गौर करने आया हूँ, "धरना देनेका अधिकार छोड़ा नहीं जा सकता और न करोड़ों, भुखमरीके शिकार लोगोंका नमक बनानेका अधिकार ही छोड़ा जा सकता है।" कांग्रेस कार्यसमितिकी बैटक २१ जनवरी व १ फरवरीको हुई और आन्दोलन वदस्त्र जारी रखनेका निश्चय किया गया। लेकिन चुपचाप आदेश जारी कर दिये गये कि आन्दोलन तो जारी रहे पर कोई नयी तहरीक शुरू न की जाय।

१४ फरवरीको गान्धीजीने वाइसरायसे मिलनेकी इच्छा प्रकट की और १७ फरवरीसे उन दोनोंके वीच लम्बी समझौता-वार्ता चली। कांग्रेस कार्यसमितिने गान्धीजीको समझौते-के पूरे अधिकार दे रखे थे। बीच बीचके थोड़े अवकाशको छोड़कर, १५ दिनतक गान्धीजी और वाइसराय व कुछ उच्च अफ़सरोंके बीच बातचीत चली और फलस्वरूप २१ सूत्री समझौता-जिसे आमतौरपर 'गान्धी इरविन पैक्ट' कहा जाता है, हो गया। ५ मार्चको इसपर दस्तखत हुए। समझीतेकी मुख्य वातें संक्षेत्रमें इस प्रकार हैं—(१) आन्दोलन वापस ले लिया जायगा; (२) भारतमें वैधानिक सरकार बनानेकी गोलमेज-सम्मेलन-योजनापर आगे और विचार होगा, (३) गोलमेज सम्मेलनमं कांग्रेसके प्रतिनिधि भाग लेंगे। (४) समझौता आन्दोलनसे प्रत्यक्ष रूपसे सम्बन्धित काररवाइयोंपर लाग् होगा; (५) कान्न भंग करनेकी हर काररवाई वन्द होगी; (६) ब्रिटिश सामानके वहिष्कारको राजनीतिक हथियारके रूपमें प्रयोग नहीं किया जायगा: (७) नशों और विदेशी वस्तुओंपर धरना जारी रह सदेगा पर उसमें दवाव डालनेकी वात न हो; (८) पुलिसके रवैयेकी खुली जाँच न होगी क्योंकि इनसे अनिवार्य रूपसे पारस्परिक दोपारोपण होगा; (९, १० व ११) आन्दोलनके सिलसिलेमं वने आर्डिनेंस, आदेश आदि वापस लिये जारँगे: (१२) जो मुकदमे चल रहे हैं, वे वापस लिये जायँगे: (१३) आन्दोलनसे सम्बन्धित कैदी छोड़े जायँगे: (१४) जो जमानतें और जुर्माने अभी वसूल नहीं हुए हैं उन्हें वसूल नहीं किया जायगा; (१५) अतिरिक्त पुलिस वापस ली जायगी, (१६) जो जन्त की हुई चल सम्पत्ति अवतक सरकारके कव्जेमें है, वह वापस की जायगी; (१७) अचल सम्पत्ति (अगर सरकारने वेच नहीं दी है तो) वापस की जायगी; (१८) जहाँ यह सावित हो जायगा कि वस्त्री न्यायपूर्ण नहीं हुई है, वहाँ सरकार क्षतिपूर्ति करेगी; (१९) जिन सरकारी नौकरोंने आन्दोलनके समय नौकरीसे इस्तीके दे दिये थे, उन्हें नौकरीमें वापस छेनेमें सरकार उदारनीति वरतेगी; (२०) नमक बनानेके सम्बन्धमें सरकार "कुछ गरीव वर्गोंको सुविधा देनेके लिए" कुछ जगहींपर प्रचलित प्रथाकी तरह ऐसी प्रशासकीय व्यवस्था कर देशी कि जहाँ नमक बनानेके केन्द्र हैं वहाँके आस-पासके गाँवोंवाले वहाँसे अपने प्रयोगके लिए नमक ले सकें, वेचने, व्यापार करने या उन क्षेत्रींके वाहर भेजनेके लिए नहीं; (२१) कांग्रेसके यह समझौता लागू न करने पर सरकार शान्ति व व्यवस्थाके लिए आवश्यक काररवाई कर सकेगी।

कांग्रे सकी सभी समितियों, उप-समितियोंको हिदायत दे दी गयी कि वे इस समझौते-की शतोंका पालन करें।

१९३० में कांग्रेसका कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ, एक तो इसलिए कि कांग्रेस स्वयं 'वनवास' में थी और दूसरे इसलिए कि लाहौर अधिवेशनमें तय हो गया था कि भविष्यमें अधिवेशन मार्च या अप्रैलमें हुआ करेंगे। १९३१ के मार्च के अन्तमें कांग्रेसका अधिवेशन वल्लभभाई पटेलकी अध्यक्षतामें कराचीमें हुआ। अपने भाषणमें पटेलने कहा—लाहौरके पूर्ण स्वतन्त्रताके प्रस्तावसे वापस लौटना या विमुख होना नहीं है। यह स्वतन्त्रता क्रिटेन या किसी अन्य देशसे सम्बन्ध न रखनेका अशिष्ट इरादा नहीं है। इसलिए इस स्वतन्त्रतासे यह सम्भावना अलग नहीं है कि पारस्परिक हित देखकर वरावरीके दर्जपर, किसी एक पक्षकी इच्छापर टूट सकनेवाली साझेदारी हो सके।"

कांग्रेसने तय किया कि अगर सरकार गोलमेज सम्मेलनमें भाग लेनेके लिए कांग्रेस को आमन्त्रित करें तो गान्धीजी उसका प्रतिनिधित्व करें और दूसरे प्रतिनिधियोंको कांग्रेस कार्यसमिति छाँटे। एक प्रस्ताव द्वारा विदेशों वस्त्रोंके विहिष्कार और शान्तिपूर्ण धरनेको और उग्र वनानेका निश्चय हुआ। दूसरे प्रस्तावमें वर्मा जनताका भारतसे अलग होनेका अधिकार स्वीकार किया गया। एक अन्य प्रस्ताव द्वारा भारतसे भावी विधानमें शामिल करनेके लिए मौलिक अधिकारों व कर्त्तव्योंकी सूची वनायी गयी।

आन्दोलन खत्म होने पर कांग्रेसका कार्य गान्धी इरविन पैक्टकी श्रतोंतक सीमित रह गया। धरना और ज्यादा व्यापक बनाया गया। बाइसरायका समझौता जिलोंके छोटे बाइस-रायोंके लिए आद्म्चर्यजनक था; कांग्रेसके जुल्ह्मों और धरना देनेवालोंपर लाटी-गोली वर्षा करनेके आदी पुल्सिवाले और मजिस्ट्रेट समझौतेके अनुसार धरना होते देखना कैसे वर-दादत करते ? उनके लिए तो गान्धी टोपी अब भी चुनौती थी, धरना उनको अब भी अख-रता था। समझौतेपर सबसे पहले इन्होंने चोट की। पूर्व गोदाबरी जिल्हेमें पुल्सिने एक छोटे जुल्ह्सपर गोली चलाकर चार व्यक्तियोंको मार डाला और कईको घायल कर दिया। जुल्ह्स शान्तिपूर्ण था; उसके संयोजकोंका एक मात्र अपराध यही था कि उन्होंने एक मोटरपर गांधी जीकी तस्वीर लगा रखी थी और पुल्सिके कहनेपर उसे हटाया नहीं था।

वहुत-से प्रान्तोंमें जिला अधिकारी अपने हाकिमों के इशारेपर नाचते और समझौतेको तो उकराते ही, कांग्रे सजनों ते पहले वदतर व्यवहार करने में भी न चूकते। यह कहा जा सकता है कि समझौता लागू करने के सम्बन्धमें उन्हें विस्तृत आदेश न मिले होंगे। संयुक्त प्रान्तमें सैकड़ों व्यक्ति गिरफतार किये गये और उनपर मुकदमे चलाये गये। कुछ जगहोंपर लोगोंसे गान्धी टोपी उतारनेको कहा गया। जो सरकारी नौकर आन्दोलनमें नौकरी छोड़ चुके थे समझौतेकी शर्तके अनुसार नौकरी वापस पाने किए अर्जियाँ और अपील मेजने पर उनकी कोई सुनवाई न होती। इसी तरह पूर्विश्वित लानेकी दूसरी शर्तें भी नहीं मानी जा रही थों। हाकिमों और अफसरोंके व्यवहारसे लगता था मानो कोई समझौता हुआ ही न हो और आन्दोलन वदस्तूर जारो हो। पुल्सवाले अव भी सभाएँ मंग करते, कांग्रेस कार्यकर्ताओं अर्थें स्रोंपर छापा मारते, स्त्रियोंके साथ दुर्व्यवहार

करते ओर राष्ट्रीय झण्डे जला डालते । वारदोलीमें लगानवन्दीर्का घोषणा हुई थी; २२ लाखकी मालगुजारीमें २१ लाख जमा हो चुकी थी; लेकिन अधिकारी फिर भी, जैसा कि गान्धीजीने वाइसरायको लिखा "दमन, जुर्माने, लोगोंके घर वेरकर पुलिस इ्यांकका परिचय" देते थे । सरकारने समझौतेके अनीसे अर्थ लगाकर अधिकारियोंके व्यवहारका समर्थन किया । इसपर गान्धीजीने सुझाव दिया कि एक स्थायी समझौता वोर्ड बना दिया जाय जी समझौतेकी व्याख्या सम्बन्धी विवाद तय किया करें । सरकारने समझौता भंग करनेके कुछ आरोप कांग्रेसपर भी लगाये थे; इसलिए गान्धीजीका सुझाव समस्याका एक इल था । लेकिन यह सुझाव माना नहीं गया । तय गान्धीजीने भारत सरकारके एइ-सचिवर्च अनुरोध किया कि वह प्रान्तीय सरकारोंको सरकार और कांग्रेसका एक एक प्रतिनिधि लेकर जाँच वोर्ड बनानेका आदेश दे दें, जो मामलोंकी सरसरी जाँच कर फैसला दे दिया करे। यह अनुरोध भी अस्वीकृत हो गया ।

इससे, गान्धीलो अपनी प्रस्तावित ल्न्दन-यात्रापर फिरसे विचार करनेको वाध्य हुए । उन्होंने वाइसरायको तार दिया कि 'संयुक्तप्रान्त, सीमाप्रान्त व दूसरे सुवोंमें जारी दमनसे लगता है कि गोलमेज सम्मेलनके विचारविमर्शमें भाग हेनेके लिए मुझे जाना नहीं चाहिये। गान्यीजीके निमन्त्रण अस्वीकार करनेका एक और भी कारण था। गान्धी-इर्विन समझौता वार्त्ताके समय इरविनने वादा किया था कि सम्मेलनमें शरीक होनेवाले कांग्रेसके प्रतिनिधि-मण्डलमें गान्वीजीके अलावा मदनमोहन मालवीय, डाक्टर अन्सारी और सरोजिनी नायह रहेंगी । पर नये वाहसराय विलिंगडनने डाक्टर अन्सारीका नाम काटकर यह दिखलानेकी कोशिश की कि कांग्रेस सिर्फ हिन्दुओं की संस्था है। लेकिन गान्धीजीने इस वातपर जोर दिया कि कांग्रेस गैरसम्प्रदायवादी संस्था है और वह मुसलमानीका भी प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा अन्सारी नेरानिलस्ट (राष्ट्रीय) मुसलमान पार्टीके भी प्रवक्ता थे। वाइ-सराय नहीं माने । वात-चीत कुछ समयतक रुकी रही । लेकिन पत्र-व्यवहार चलता रहा और फलस्वरूप दोनोंकी शिमलामें भेंट हुई। २७ अगस्त १९३१ को एक और छोटा सा समझौता हुआ जिसके फलस्वरूप गानधीजी लन्दन चल पहे । इस शिमला-समझौतेमें और वातोंके अलावा यह भी कहा गया था कि "५ मार्च १९३१ का समझौता लाग रहेगा, भारत व प्रान्तीय सरकारें समझौतेकी शर्तें उन मामलोंमें (यद ऐसे मामले हुए) भी लागू करेंगी जहाँ उनका न लागू होना सावित हो गया है और इस सम्बन्धमें की गयी शिकायताँ-की ध्यानपूर्वक जाँच करेंगी। कांग्रेस भी समझौतेकी शत मानेगी।" सरकारने वारदोली तालुकेके दमनकी जाँचका आश्वासन दिया। छेकिन सरकार कांग्रेसके प्रतिनिधिमण्डलमें डाक्टर अन्सारीके शामिल करनेके लिए राजी नहीं हुई । गान्धीजी अगरतके अन्तर्मे लन्दनके लिए रवाना हो गये।

अध्याय २२

लगानवन्दी आन्दोलन

१९३१ की विश्वव्यापी मन्दीके कारण भारतमें भी वस्तुओंकी कीमतें काफी गिर गयीं; यहाँतक कि कभी कभी किसान अपनी समस्त फसल वेचकर भी लगान चुकानेमें अस-मर्थ होते । परन्तु सरकारको फिर भी जमीन्दारोंके हितोंका ध्यान अधिक था। अपने सरकारी अफसरोंकी उस चेतावनीके वावजूद जो वे प्रायः दिया करते थे कि इस नीतिका परिणाम लाखों किसानोंकी कष्ट-वृद्धि और वरवादी होगा, सरकार जमीन्दारोंके हितोंकी रक्षामें ही तत्पर रहती थीं। जमीन्दार किसानोंपर मनमाने अत्याचार करते और अपनी इच्छानुसार उन्हें वेदखल कर देते थे। १९३० के आन्दोलनके पश्चात् जमीन्दारोंकी हिम्मत बढ़ गयी और वे और भी नृशंस होकर अत्याचार करने लगे। वेदखिलयों की संख्या वहुत वढ़ गयी और काश्तकार विनाशकी अन्तिम सीमातक पहुँच गये। वे जमीन्दार और सरकार रूपी चक्कीके दो पाटोंके बीच पिस रहे थे। हारकर उन्होंने कांग्रेससे प्रार्थना की। यह स्पष्ट था कि सरकारको किसानोंकी उंचित सहायता करनी चाहिये थी। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीने गोविन्दबल्लभ पंतको इस कार्यके लिए नियुक्त किया कि वे प्रान्तके किसानोंकी आर्थिक दुर्दशासे सरकारको परिचित कराशें। नेहरू एवं गोविन्दबब्लम पन्तने युक्तप्रान्तके चीफ सेकेंटरी व अन्य अफ्सरोंसे कई वार भेट की, पर व्यर्थ हुआ। जव गान्धीजी वाइसन्यसे शिमलेमें अगस्तमें मिले तो उन्होंने वाइसरायसे स्पष्ट कह दिया कि यदि सरकार संयुक्त प्रान्तके किसानोंकी उचित सहायता नहीं करती, तो कांग्रेस किसानों-की अपनी रक्षाके लिए आन्दोलन या सत्याग्रहकी सलाह देनेको वाध्य होगी।

संयुक्त-प्रान्तमें लगान-वन्दी आन्दोलनके लिए परिस्थित परिपक्ष हो रही थी। सर-कारने लगानमें कुछ छूट देनेकी घोषणा जरूर की—परन्त यह छूट आक्श्यकताको देखते. हुए इतनी कम थी कि इससे संकट घटनेंमें कोई सहायता नहीं मिली। इसी समय मानों इस संकटको और भी बढ़ानेके लिए ही एक और आजा जारी की गयी जिसके अनुसार अगर महीने भरके भीतर सब लगान जमा न किया गया तो लगानकी छूट सम्बन्धी रिया-यत वापस ले ली जायगी। इस आदेशके अनुसार अगर ज्यादा लगानके खिलाफ कोई प्रार्थना करनी होती तो वह भी पूरा लगान जमा करनेके वाद ही की जा सकती थी।

प्रान्तीय कांग्रेस द्वारा सरकारको किसानोंकी सहायता करने तथा इस संकटको टालने के प्रश्नपर सहमंत करानेके लिए फिर वार्ताएँ आरम्भ की गयीं परन्तु सरकारकी तरफते कोई उत्साह नहीं दिखलाया गया, इसलिए इलाहावादकी जिला कांग्रेस कमेटीने कांग्रेस कार्यसमितिसे सत्याग्रह आरम्भ करनेकी अनुमित देनेके लिए कहा और कार्यसमितिने अपनी अक्तूबरकी दिल्लीवाली वैठकमें अध्यक्षको लगानवन्दी सत्याग्रहके आरम्भके लिए आज्ञा देने न देनेके समस्त अधिकार दे दिये। समझौतेकी कोशिश और इन्त- जारमें कुछ वक्त गुजरा। फिर कांग्रेसके अध्यक्षने संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेसको लगानवन्दी

आन्दोलन चलानेकी अनुमित दे दी । दिसम्बर्मे कांग्रेसने किसानोंको लगान और कर देना अत्थायी रूपसे, समझौता वार्ता पूर्ण होनेतक रोक देनेकी सलाह दी । वार्ताके दौरानमें ही कांग्रेसको यह सलाह इसलिए देनी पड़ी कि सरकारी कर्मचारी जबरदस्ती और वेददांसे लगान वस्ल कर रहे थे । कांग्रेसने सरकारसे भी कहा कि अगर सरकार लगान वस्ली स्थितित कर देनेका वादा करे तो लगानवन्दी आन्दोलन वापस कर लिया जायगा । पर सरकार राजी नहीं हुई और कई जिलोंमें लगानवन्दी आन्दोलन आरम्भ हो गया । सरकारने स्थितिपर कांन् पानेके लिए संकटकालीन आर्डिनंस लागू कर दिया । रद दिसम्बरको जवाहरलाल नेहल, प्रान्तीय कांग्रेसके अध्यक्ष तसद्दुक अहमद खाँ शेरवानी, पुरपोत्तमदास टण्डन गिरफ्तार कर लिये गये। जमीन्दारोंने इस लगानवन्दीको अपने वर्ग-स्थार्थपर कुटाराधात माना जिसे दूर करनेके लिए कांग्रेस कांग्रेसको किसीके भी ऐसे न्याययुक्त अधिकारोंका अपहरण नहीं करना है जिनसे देश-हितमें वाधा न पड़े। कांग्रेस कांग्रेस समस्त धनी एवं जमीन्दार वर्गोंसे कांग्रेसके स्थान पढ़े। कांग्रेस कांग्रेसके समस्त धनी एवं जमीन्दार वर्गोंसे कांग्रेसके स्थानवान संग्रीममें सहायता करने की अपील करती है।"

सीमाप्रान्तमें लाल कुरतीवाले खुदाई खिद्मतगारींकी बढ़ती हुई संख्यासे सरकार घवरा रही थी । मार्च १९२१ में जेलते छुटनेके वाद खान अन्दुल गफ्फार खाँने अपना राजनीतिक कार्यक्रम उसी जोश और सरगर्मीसे गुरू कर दिया था जैसा कि आन्दोलन चलते समय था । अपने भाषणोंमें वे कहते कि दिल्ली ऐक्ट तो विरामसन्धिकी तरह है, इसका यह मतल्य नहीं है कि आजादीकी लड़ाई खत्म हो गयी। कान्त न तोहे जायँ पर देश अपनी शक्ति वढ़ाये। ''उन्होंने यह वात देहातींके अपने दीरेमें हर भाषणमें कही और लाल कुरती स्वदंसेवक सेनामें भरतीकी उनकी अपीलका उत्साहवर्धक रवागत हुआ।" जिन गाँचींमं जाते सड़कोंके दोनों ओर लाल कुरतीवाले स्वयंसेवक कतारें वाँचे खड़े होते, होल वजते और दो जगह तो बन्दूकोंकी बाढ़चे चलामी भी दी गयी। अगस्तमें लाल कुरती संघटन जान्तेसे कांब्रेसमें शामिल हो गया । संयुक्तपान्तकी तरह सीमाप्रान्तमें भी भीषण कृषि-संकट चल रहा था और उन्हीं कारणांवे किसान मालगुजारी अदा करनेमें असमर्थ थे। सान अब्दुल गक्फारं खाँ किसानोंसे कहते कि मालगुजारीका यह वोझ असहा है; किसानोंको उतनी रकम अदा कर देनी चाहिये जितनी उनके वृतेमें हैं। इस सुझावमें किसानोंको आशा-की चिनगारी दिखाई दी। और उन्होंने या तो विसात भर मालगुंबारी चुका दी या जहाँ न हो सको वहाँ विलक्कल ही न दी। पेशावर जिलेके एक इलाकेमें मालगुजारी विलक्कल ही वसूल न हुई । जुनके जुरूमें सरकारने मालगुजारीमें थोडी-श्री छुटकी घोषणा की, पर यह रियायत जरूरतचे बहुत कम थी। खान अब्दुल गक्फार खाँने माँग की कि तीन चौथाई लगान माफ कर दिया जाय और एक चौधाई फ़्सलकी उपजकी शक्लमें है हिया जाय । धरनेपर और अधिक जोर दिया गया । अकेले पेशावरके शहरमें लाल करतीवाले ९०० स्वदंसेवक थे। स्वयंसेवक पाली वाँधकर धरना देते और दूसरी पालीवाले पहली पालीको छुट्टी दिलाने ५०-५० के जत्थींमें मार्च करते हुए आते।

इन कार्योमें गैरकान्ती कुछ भी नहीं था, पर सरकार परेशान थी; उसे हर था कि कहीं १९३० की तरह लड़ाकू कवीली जातियाँ फिर न सिक्स हो जायँ। सरकारने सार्व- जितक सभाओं पर रोक लगाना और निहत्थी भीड़ों और जल्सों पर लाठी-गोली चलाकर तितर-वितर करना ग्रुक किया। वहुतसे लोग मारे गये। लोगों को पकड़कर विना मुकदमा चलाये जेलमें ठूँस देनेके लिए एक आर्डिनेंस जारी हुआ। २० दिसम्बरको सीमापान्तीय कांग्रेस कमेटीने तय किया कि अखिल भारतीय कांग्रेससे गान्धी-इरिवन पैक्ट खत्म करनेको कहा जाय और खान अन्दुल गपफार खाँको आन्दोलन चलानेकी अनुमित प्राप्त करनेके लिए वम्बई भेजा जाय। कमेटीने यह भी निक्चय किया कि नये साल पहली जनवरीको एक सार्वजितक सभा की जाय, जिसमें कांग्रेसका झण्डा फहराया जाय। "लालकुरती दलकी शिक्त व तैयारीका शानदार प्रदर्शन इस सभामें करनेका प्रवन्ध जल्दी-जल्दी किया जाने लगा।" सरकार संदेहमें थी। २४ दिसम्बरको कुछ आर्डिनेंस जारी हुए। उसी रात खान अन्दुल गपफार खाँ, उनके भाई डाक्टर खान साहव और खुदाई खिदमतगारोंके दूसरे नेता पकड़ लिये गये। छः सशस्त्र फीजी दस्तोंने पेशावर शहरका प्रवन्ध ले लिया। २६ दिसम्बरको कोहाटमें बड़ी-बड़ी भीड़ें इकट्ठी हो छावनीकी ओर चल पड़ी। पुलिसने उन्हें गोलियोंसे तितर-वितर किया। बहुतसे लोग मारे गये, सरकारी अनुमानके अनुसार १४ मरे व ३० घायल हुए।

वंगालमें, शायद आतंकवादी आन्दोलनमें मुद्ध होकर (आतंकवादी आन्दोलनका वर्णन अन्य एक अध्यायमें किया गया है) कुछ गैरसरकारी अंग्रे जों और हुल्लड़वाजोंकी एक भीड़ने एक रात एक छापेखानेमें शुसकर मशीनें तोड़ डालीं और मैनेजर व दूसरे कर्मचारियोंको मारा पीटा । दिल्ली व शिमला समझौतोंके आलोचक उनकी खिल्ली उड़ाते हुए कहते कि जब जेलोंमें इतने राजनीतिक वन्दी पड़े सड़ रहे हों और जेल अधिकारियोंके अत्याचार सह रहे हों, ये समझौते मजाक ही हैं। अगर बन्दी जेलमें वेहतर व्यवहारके लिए कहते तो लाठियोंसे चुप कर दिया जाता। हिजली नजरवन्दी कैम्पमें बन्दियोंपर गोली चलायी गयी जिससे दो मरे और २० घायल हए।

देशकी हालत यह थी जब २८ दिसम्बर १९३१ को गान्धीजी लन्दनसे वापस लौट-कर वम्बई पहुँचे। कांग्रेस कार्यकारिणीक सदस्य गान्धीजीका स्वागत करनेके लिए वम्बई आये थे। २९ दिसम्बरसे तीन-चार दिनतक कार्यसमितिकी वैठक चली। जो प्रस्ताव स्वीकार हुए उनमें एक यह भी था कि पिछले कुछ महीनोंकी घटनाओंने "यदि सरकारने अपना रवैया विलकुल ही न वदल दिया तो उसने कांग्रेसका सहयोग असम्भव वना दिया है"। मामूली कानूनोंकी जगह आर्डिनेंन्स जारी करनेकी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, इसकी खुली जाँच करनेकी माँग की गयी। कार्य-समितिने फैसला किया कि अगर सरकारसे सन्तोपजनक उत्तर नहीं मिला तो सविनय अवज्ञा आन्दोलन फिर ग्रुक्त कर दिया जायगा। सत्याग्रहमें लगान व दूसरे करोंकी अदायगी रोकने, विदेशी वस्त्रों व कम्पनियोंका विह्कार, शरावकी दूकानोंपर धरना, गैरकानूनी तौरपर नमक बनाना व इकट्ठा करना, आर्डिनेंसके अन्तर्गत जारो आदेशोंका उल्लंघन और ऐसे कानून भंग करना जो नैतिकतासे सम्बन्धित न हों और जनताके लिए अनिष्टकारी हों, आदि बातें शामिल की जानेवाली थीं।

कार्यसमितिकी वैठक चार दिन चली। इसी वीच गान्धीजी सरकारसे शान्तिपूर्ण समझौतेकी कोशिशमें वाइसरायसे तार द्वारा लिखापढ़ी कर रहे थे। २९ दिसम्बरके अपने पहले तारमें गान्धीजीने पूछा कि क्या संयुक्तप्रान्त, सीमाप्रान्त व बंगालमें जारी आर्डिनेंस इस वातका इंगित है कि सरकार व कांग्रेसके वीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध खत्म हो गये। गान्धीजीने पृद्धा था कि "क्या आप अव भी मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं आपसे मिल्ँ और कांग्रेसको स्या सलाह हूँ, इस सम्बन्धमें आपसे पय-निर्देशन लूँ १^३३ वाइसरायके प्राइवेट सेकेटरीने जवाव दिया-" सहयोग पारस्परिक होता है और संयुक्त व सीमा प्रान्तों में कांग्रे सी कार-रवाइयाँ उस मैत्रीपूर्ण सहयोगका परिचायक नहीं मानी जा सकतों जो सरकार माँगती है। प्राइवेट सेक्नेटरीने लिखा कि वाइसराय आपसे (गांधीजीसे) मिलनेके लिए तैयार हैं पर शर्त यह है कि राजनीतिक परिस्थितिपर कावृ पानेके लिए सरकारने जो काररवाई की है उसपर वातचीत न की जाय ! चूँ कि सिर्फ काररवाईपर वात करनेके लिए गान्धीजी वाइसरायसे मिलना चाहते थे और चूँ कि समझौतेकी वातचीतके लिए सरकारने इस प्रकार दरवाजा वन्द कर दिया था, कांग्रेस कार्यसमितिने आन्दोलन सम्बन्धी उपर्युक्त प्रस्ताव पास कर दिया । लेकिन गांधीजी अव भी सम्मानपूर्ण समझौतेकी आद्यामें थे और उन्होंने वाइसरायसे फिर पत्र-स्यवहार ग्रुरू किया । वाइसरायके प्राइवेट सेक्रेटरीने फिर सुखा जवाव दिया-"वाइसराय और उनकी सरकार विश्वास नहीं कर पाती कि आप या कांग्रेस कार्यसमिति यह सोच सकती है कि स्विनय अवज्ञा आन्दोलनकी धमकीके समय वाइसराय, किसी सुविधा-की आशामें आपने मिल सकते हैं।" गान्धीजीने ३ जनवरीके अपने अन्तिम तारमें धमकीका अस्तित्व अस्वीकार किया । टेकिन आन्दोलन फिरसे जारी करना अव अवस्यम्भावी था, इसलिए उस तारमें उन्होंने यह जोड़ दिया कि ''में सरकारको आस्वासन देना चाहता हूँ कि कांग्रेस अपनी ओरसे पूर्णरूपंण शान्तिमय व अहिंसक आन्दोलन चलाने और उसमें कटुता न आने देनेका प्रयत्न करेगी।"

परन्तु लार्ड विलिंगडनकी सरकारने इस आन्दोलनको चलनेके पहले ही समाप्त कर देनेकी पूरी तैयारी कर ली थी और अगले दिन ४ जनवरीको ही गान्धीजी व पटेल (जो कांग्रेसके अध्यक्ष ये) गुजरातके उन क्षेत्रोंके दौरेके पहले ही पकड़ लिये गये जिन्होंने १९३०-३१ के संवर्षोंका सबसे अधिक भार उठाया। उसी दिन चार नये आर्डिनेंस (काले कानून) जारी कर दिये गये। वे थे—

- (१) संकटकालीन-अधिकार आर्डिनेन्स,
- (२) गैरकानूनी-कार्योंको भड़कानेके विरुद्ध-आर्डिनेंस,
- (३) गैरकानूनी-या संघटन विरोधी-आर्डिनेंस,
- (४) दवाव और विहिन्दार विरोधी आर्डिनेन्स । सरकारके हाथमें इन आर्डिनेसों ते हतनी अधिक शक्ति आ गयी कि प्रायः सभी साधारण कान्न उनके सामने फीके पड़ गये और अधिकारियों का हर काम इनकी रक्षाके अन्तर्गत आ गया। २६ मार्चको ब्रिटिश पार्ल-मेण्टमें भापण करते हुए भारत सचिव ने कहा कि में स्वीकार करता हूँ कि ये आर्डिनेंस कटोर एवं व्यापक थे परन्तु उस समयकी स्थिति देखते हुए उन्हें इस वित्तृत रूपमें बनाना आवश्यक था। क्यों कि पूरी जानकारीके आधारपर सरकारको माल्म था कि उसका अस्तित्व ही खतरेमें था और भारतको अराजकतासे बचानेके लिए उन कानृनोंका बनना बहुत आवश्यक था।

महारमा गान्धीकी गिरपतारीके परचात् तमाम शहरों में कांग्रेची नेताओं की गिरपतारी की गयी । कांग्रेस एवं कांग्रेससे सम्बन्धित सब संस्थाएँ गैरकानृनी बोषित कर दी गर्यो । कांग्रेसके कार्यालयों व आश्रमीपर सरकारी कब्बा कर लिया गया। छापेलानों द्वारा कांग्रेसी-साहित्य प्रकाशित किये जानेपर रोक लगा दी गयी। डाक तथा तारकी सुविधाएँ भी कांग्रेसके लिए रोक दी गयीं—यहाँतक कि १९३२ के कांग्रेसके अधिवेशनके अध्यक्ष मदनमोहन मालवीयका एक तार इंगलैण्ड मेजनेसे रोक दिया गया। इन राज-कान्नोंके कारण कान्न भंग करनेकी एक नयी प्रधा शुरू हो गयो। कांग्रेसके कार्यालय गुप्त रूपसे छिपकर कार्य करने लगे। कांग्रेसने संवाद, पत्र तथा डाक मेजनेका अपना संघटन कर लिया। कभी-कभी स्ववंसेवक पहचान लिये जाते और डाक पकड़ ली जाती। कांग्रेसके समाचार एवं आदेश गुप्त रूपसे छापे तथा वाँटे जाते थे।

लेकिन विलिंगडनके सर्वश्राची आर्डिनेन्सोंमें भी कांग्रेसजनको मारने-पीटने और शारीरिक यातनाएँ देनेकी व्यवस्था न थी; और चूँकि भारतीय पुल्सि अपने पंजेमें आये लोगोंको मारे-पीटे विना रह ही नहीं सकती थी, १९३०-३१ की तरह इस वार भी पुल्सिन वहें पैमानेपर गैर-कानूनी ढंगसे मारपीट की। कांग्रेसके दफ्तरोंमें जो मिलते उनपर जबरदस्त मार पड़ती अगर वे यह न वताते थे या वतानेमें असमर्थ होते थे—स्वयंसेवक व दान-दाताओंकी स्चियाँ, रसीद वहियाँ व दूसरे कागजात कहाँ हैं। पुल्सिक यातनाएँ देनेके ढंगका एक उदाहरण यह है कि कि हाईकोर्टके एक वकीलने अपना नाम व पता वतानेसे इनकार कर दिया तो उनके सिरके वाल ही एक-एक करके नोच डाले गये।

१९३२ के सत्याग्रहने विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न रूप लिये। वंगाल व संयुक्तप्रान्तमें लगानवन्दी जारी रही, विहारमें चौकीदारी टैक्सवन्दी हुई। मद्रास, विहार, मध्यप्रान्त, कर्नाटक व संयुक्त प्रान्तके कुछ स्थानों में जंगलात कान्न तोड़े गये, बहुतसे अन्य स्थानों में गैर-कान्नी ढंगपर नमक बनाया व बेचा गया। शराव व विदेशी वस्त्रोंकी दूकानोंपर धरना हर प्रान्तमें व्यापक रूपसे दिया जाता रहा। "शान्तिपूर्ण विहिष्कार ही कांग्रेसकी सबसे सफल काररवाई थी। विदेशी सामानका विहिष्कार बहुत सफल रहा, पर, संस्थाओंका विहिष्कार उत्तना कामयाव नहीं हुआ।" आन्दोलनका दूसरा प्रमुख अंग विभिन्न 'दिवस' मनाना था। इनमें स्वतन्त्रता, गान्धी, मोतीलाल, सीमान्त, शहीद, झण्डा दिवस आदि प्रमुख थे।

यद्यपि १९३२ का आन्दोलन पिछले आन्दोलनकी छाया मात्र था, सरकारी रवैयेमें कोई अन्तर नहीं था। कांग्रेस खुल्स या किसीकी गिरफ्तारीकी सहानुभृतिमें इकड़ी भीड़ लाठीचार्ज या गोली चलाकर तितर-वितर कर दी जाती थी। बहुत वड़ी संख्यामें लोग घायल हुए व मारे गये। आन्दोलनके पहले तीन महीनोंमें ४०००० व्यक्ति गिरफ्तार हुए। अप्रैलके वाद हर महीने गिरफ्तारियोंकी संख्या कम होने लगी। लगान वस्ल करनेके लिए फिर गैरकान्ती हंग इस्तेमाल किये जाने लगे, और एक व्यक्तिसे वकाया वस्ल करनेके लिए पूरे संयुक्त परिवारोंकी सम्पत्ति कौड़ियोंके मोल नीलाम कर दी जाती। जेवर, जानवर, वरतन माँहे, खड़ी फसल सब करीव करीव मुपतमें ही निकल जाते, अगर वच जाते तो पुलिस उन्हें तोड़फोड़ डालती और वरवाद कर देती। कहीं कहीं सामूहिक खुमांने होते और पुलिस उसे अपने अनोखे हंगले वस्ल करती। कांग्रेसके कुछ दफ्तर और आश्रम पुलिसने अपने कल्लेमें लेकर व्यस्त कर डाले, या उनमें आग लगा दी। अखवारोंकी भी वही हालत हुई जो १९३०-३१ में हुई थी।

११ मार्च १९३२ को भारत सचिव सर सैमुअल होरको लिखे गये अपने पत्रमें गांधी•

जीने पुलिसके अत्याचारोंका वर्णन करते हुए लिखा—"मुझे लगता है कि दमन अपनी कान्नी सीमाओंको पार कर रहा है। देशमें सरकारी आतङ्कवादका जोर है। अंग्रेज व भारतीय दोनों अफसर पश्च वन रहे हैं। कँचे और नीचे दोनों तरहके भारतीय अफसर सरकार द्वारा जनताके प्रति निष्ठाहीनता और अपने ही खून मांसके वने लोगोंके साथ अमानवीय कृत्योंके क्लावनीय माने जानेके कारण अनैतिकताकी ओर छक रहे हैं। वे जबरदस्ती चुप किये जा रहे हैं। भाषणकी स्वतन्त्रता खत्म हो रही है। शान्ति व व्यवस्थाके क्लापर गुण्डागदीका वोल्वाला हो रहा है। जनताकी सेवाके लिए जो महिलाएँ आगे आ रही हैं उनके अपमानित होने और आवक् छिननेका डर है।" भारत सच्चिन वात टालकर शिकायत खारिज कर दी। उन्होंने लिखा—"भारत सरकार व प्रान्तीय सरकारें अपने व्यापक अधिकारोंका दुरुपयोग नहीं कर रहीं और किसी तरहकी ज्यादती या प्रतिशोधात्मक काररवाई रोकनेका हर सम्भव प्रयत्न कर रहीं हैं।

२४ अप्रैलको कांग्रेसका ४६ वाँ अधिवेशन दिल्लीमें होनेको था। यह पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच चतुरताकी लड़ाई सावित हुआ। पुलिसने अधिवेशन न होने देनेकी सब तैयारी कर ली थी। स्वागत समिति गैरकान्नी करार दे दी गयी थी और उसके दिल्लीवासी सदस्य पकड़ लिये गये थे। दिल्लीके लिए रवाना होनेवाले सैकड़ों प्रतिनिधि अपने स्टेशनोंपर ही पकड़ लिये गये थे। कार्यवाहक अध्यक्षा श्रीमती सरोजिनी नायट्ट वम्बईमें ही पकड़ ली गयी थीं। होटलों व धमेशालाओंको हुक्म जारी हो गये थे कि वे प्रतिनिधियोंको हरगिज न ठहरावें। अधिवेशनसे एक हपते पहले दिल्ली धेरेकी सी स्थितिमें थी और जिसपर भी कांग्रेस प्रतिनिधि होनेका शक होता था वह पकड़ लिया जाता था। श्रीमती सरोजिनी नायट्ट्ले बाद मदनमोहन मालवीय अध्यक्ष होनेको थे, पर वे दिल्लीमें उत्तरते ही पकड़ लिये गये। श्रीमती नायट्ट्ले ४० सदस्योंकी विषय समितिकी घोषणा की थी; उनमेंसे आधेसे ज्यादा पकड़ लिये गये। फिर भी, इस सबके बावजूद विषय समितिक शेप सदस्योंकी वैठक २३ अप्रैलको दिल्लीमें हुई और लाहीर अधिवेशनके पाँच प्रस्तावांके अलावा वम्बईमें हुई कार्यसमितिकी वैठक ने अप्रैलको दिल्लीमें हुई और लाहीर अधिवेशनके पाँच प्रस्तावांके अलावा वम्बईमें हुई कार्यसमितिकी वैठकमें स्वीकृत आन्दोलन सम्बन्धी प्रस्ताव पास हुए।

"२४ अप्रैलको चाँदनी चौकके एक छोरते दूसरेतक युड्सवार व सदास्त्र पुलिस गहत करने लगी। दाहरके हर हिस्सेमें भी पुलिस तैनात थी। वहाँ भी सभाएँ हो सकती थीं, वे सब जगहें पुलिसके कड़े पहरेमें थीं। सबेरे ठीक ९ बजे, देशके विभिन्न भागोंसे एकन्न सैकड़ों प्रतिनिधि चाँदनी चौकके घण्टाघरके नीचे खुले मेदानमें एकन्न हो गये। अधिवेदान लगभग १० मिनटतक चला जिसमें स्वागताध्यक्षका भाषण, कांग्रेसकी वार्षिक रिपोर्ट, कांग्रेसके प्रत्ताव आदि प्रतिनिधियोंको वाँटे गये और विषय समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव सर्वसम्मितिसे पास हुए। लेकिन श्रीन्न ही पुलिस आ गयी और उसने लगभग २०० प्रतिनिधियोंके आस-पास घेरा डालकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ऐसी ववरा गयी थी कि उसने गिरफ्तारीके पहले सभाको गैरकानृनी भी बोपित नहीं किया।

''इसके बाद छोटे छोटे जुद्ध चाँदनी चौक आने और गिरपतार होने लगे। प्रतिनिधि आधे आधे दर्जनके गुटोंमें आते और पकड़ लिये जाते। कुछ समय बाद पुलिसकी समझमें आया कि इस तरह तो गिरपतारियोंका ताँता ही लगा रहेगा। तीसरे पहर गिरपतार होनेके लिए घण्टाघर आये लोंगोंको लाठी-चार्ज द्वारा तितर-बितर करना शुरू हो गया।" दिल्ली कांग्रेसके अनुसार दिल्लीमें ६५०, मुरादाबादमें १६० और शेष भारतमें ५०० व्यक्ति गिरफ्तार हुए। नेताओंकी गिरफ्तारीके विरोधमें बहुतसे शहरोंमें हड़तालें हुई।

सितम्बर १९३२ में गान्धीजीने यरवदा जेलमें आमरण अनशन करनेकी घोषणा की । इस उपवाससे सम्बद्ध घटनाएँ इस प्रकार थीं पहले गोलमेज सम्मेलनमें दो प्रति-निधियों — अछूत नेता डाक्टर भीमराव अम्बेडकर व राववहादुर आर. श्रीनिवासनने प्रस्ताव रखा था कि दलित वर्गोंको अधिकार हो कि वे दस वर्पतक पृथक् निर्वाचन और वयस्क मताधिकारके आधारपर स्वयं अपने प्रतिनिधि चुनकर विधान मण्डलोंमें भेजें। दस वर्षके वाद विधान मंडलोंमें स्थान नियत कर दिये जायँ और उन स्थानोंके लिए संयुक्त निर्वाचन हो । दूसरे गोलमेज सम्मेलनमें भी यह प्रस्ताव जीरदार शब्दोंमें दोहराया गया और अछ्तोंके अधिकारका रूप देकर उसे खूब बढ़ाया-चढ़ाया गया । गान्धीजीने इसका विरोध करते हुए कहा कि दूसरे अल्पसंख्यकोंके दावे तो मेरी समझमें आते हैं, पर अछूतों का दावा तो बड़ा निर्मम है। इसका अर्थ तो यह है कि छूत-अछूतकी यह भयानक खाई हमेशा वनी रहेगी। हम नहीं चाहते कि हमारे समाजमें या मर्दुमशुमारीमें 'अछूत' कोई अलग वर्ग वनकर रहे। सिख हमेशा सिख रह सकते हैं, मुसलमान हमेशा मुसलमान रह सकते हैं, अंग्रेज भी रह सकते हैं पर क्या अछूत हमेशा अछूत रह सकते हैं ? अस्पृश्यता जिन्दा रहनेसे तो मैं हिन्दु त्वका मरना ही ज्यादा पसन्द करूँगा।" गान्धीजीने चेतावनी दी—''इसलिए, मैं अपना पूरा वल देकर कहना चाहता हूँ कि चाहे मैं अकेला ही इसका विरोध करनेके लिए रह जाऊँ, मैं अपनी जान देकर भी इसका विरोध करूँगा।" और उन्होंने विरोध किया।

गोलमेज सम्मेलनने सरकारो नौकरियों और विधान मण्डलोंमें प्रतिनिधित्वका प्रश्न सम्मेलनमें आये विभिन्न वर्गोंके कथित प्रतिनिधियोंपर छोड़ दिया था। प्रतिनिधि समझौतेके लिए वार-वार एकत्र होते और वार-वार असफल होते। अन्तमें उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और ब्रिटिश सरकारने घोषणा की कि वह स्वयं फैसला कर देगी। गान्धीजीने इस असफलतापर बोलते हुए सम्मेलनमें ही कहा था—"भारतीय प्रतिनिधिमण्डलके संघटनमें ही असफलताके कारण निहित हैं। लगभग हम सभी प्रतिनिधि बिना निर्वाचित हुए सरकार द्वारा नामजद होकर यहाँ आ गये हैं। जिस वर्ग या दलके प्रतिनिधि बनकर हम यहाँ वैठे हैं, उन्होंने हमें चुना नहीं है। समझौतेके लिए जिन लोगोंका यहाँ होना आवश्यक था, वे यहाँ दिखाई नहीं देते।"

ब्रिटिश सरकारने जो प्रतिनिधित्व सम्बन्धी साम्प्रदायिक निर्णय दिया उसमें दलित वर्गोंको प्रान्तीय विधान समाओं भें ७१ विशेष स्थान दिये गये; इन स्थानोंकी पूर्ति "विशेष निर्वाचन क्षेत्रोंमें केवल दिलत वर्गीय मतदाताओं के वोटों से चुने गये" लोगों से होनेको थी। लेकिन चूँकि ये स्थान दिलतोंकी जनसंख्याके अनुपातमें कम थे, उन्हें आम निर्वाचन क्षेत्रों में भी अपने उम्मीदवारोंको खड़ा करने और वोट देनेका अधिकार था। 'निर्णय' में घोपणा की गयी थी कि स्थान सुरक्षित रखनेकी व्यवस्था २० वर्षके लिये है, पर उसके पहले भी वह पारस्परिक समझौतेसे खत्म की जा सकती है। यह व्यवस्था हिन्दू समाजमें फूट डालकर

१. इण्डियन नेशनल कांग्रेस (आफिशियल एकाउण्ट) पृष्ट १४५-४६

भारतीय राजनीतिमें सिख, मुसलमान, ईसाई आदि वगों की तरह एक और दल खड़ा करनेके लिए की गयी थी। १८ अगस्तको गान्धांजीने यरवदा जेलसे एक पत्र ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीको लिखकर कहा कि में जान देकर भी इस निर्णयका विरोध करूँ गा। मेरे लिए जो एकमात्र रास्ता है वह यह कि में इर प्रकार खाना छोड़नेका जत लूँ और नमक सोडेके साथ या उसके बिना सिक पानी लूँ। यह उपवास तभी खत्म होगा जब ब्रिटिश सरकार खेच्छासे या जनमतके दवावमें अपना निर्णय वदले और दिलत वर्गके लिए पृथक निर्वाचनकी अपनी योजना वापस ले, दिलत वर्गका प्रतिनिधित्व आम संयुक्त निर्वाचनके हो, चाहे मतदान अधिकार कितना ही व्यापक क्यों न करना पड़े।" गान्धीजीने लिखा था कि उपवास २० सितम्बरसे गुरू होगा। ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीने अपने ८ सितम्बरके पत्रमें निर्णय बदलनेते इनकार किया और निर्णयके जिस अंशपर गान्धीजीको आपित्त थी उसके समर्थनमें लिखा— "दिलत वर्गके लिस अंशपर गान्धीजीको आपित्त थी उसके समर्थनमें लिखा— "दिलत वर्गके खेवरे हुए जिनसे दिलत वर्गोको छाप होरा बहुधा स्वीकृत उन सामाजिक अयोग्यताओंको देखते हुए जिनसे दिलत वर्गोको काफी प्रतिनिधित्व देकर उनकी रक्षा करना अपना कर्त्तव्य माना।"

नियत दिन २० वितम्बरको गान्धीजीने एक वक्तव्य देकर अपना उपवास शुरू किया। दिलत भाइयोंको सामाजिक अयोग्यताओंमें रखनेके लिए हिन्दू समाजकी आलोचना करते हुए गान्धीजीने वक्तव्यमें कहा —''यदि सार्वजनीन सामृहिक हिन्दू भावना अस्पृश्यताका म्लो- च्छेदन करनेको तैयार नहीं है तो उसे विना किसी झिकक मेरी कुर्वानी दे देनी चाहिये।" २१ सितम्बरसे ही तमाम भारतका ध्यान दल्ति वर्गोंकी समस्या और उसके हल्पर केन्द्रित हो गया । विभिन्न नेता इकट्टे होकर उस मसलेका इल दूँद्ने लगे जिसपर गान्धीजीने अपनी जानकी वाजी लगा दी थी। अंतमें पुनामें दलित वर्गों और रोप हिन्द समाजके जाने-माने नेताओंका एक बैठकमें सर्वमान्य समझीता हो गया। इस समझीते, पूना पैक्टके अनुसार दिलत वर्गोंके लिए ७१ नहीं १४८ स्यान सुरक्षित हुए । वे स्थान संयुक्त मतदानसे भरे जाने-बाले थे पर शर्त यह थी कि चुनावके पहले उस विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रके दलित वर्गीय मतदाता स्वयं प्रारम्भिक चुनाव द्वारा चार उम्मीदवारोंको चुन हं जो आम चुनावमें खड़े हों। इन प्रारम्भिक चनावोंको १० वर्ष या पारस्परिक समझीते द्वारा उसने पहले ही खरम हो जाना था। यद्यपि दल्ति वर्गोकी शावादी अधिक थी किन्तु उन्हें आम स्थानोंके लिए भी खहे हो सकतेकी छूट होनेके कारण आवादीके अनुपातम स्थान मुरक्षित रखनेपर जोर नहीं दिया गया । पूना पैक्ट गांधीजीके पास यरवदा जेळ मेला गया और उनकी त्वीकृति पर सर्वसम्मत समझौतेकी तरह उसे ब्रिटिश सरकारके पास भेजा गया । २६ सितम्बरको ब्रिटिश सरकारने साम्प्रदायिक निर्णयको पृना पैकटके आधारपर संद्योधित करनेकी अपनी रजामन्दीकी घोपणा की और शामको ५। वने गांधीनीने उपवास तोड़ दिया ।

लेकिन सवर्ण हिन्दुओं के अह्तों के प्रति व्यवहार में पैक्टने कोई अन्तर नहीं आया। यहाँ वहाँ कुछ मन्दिरों में उनके प्रवेशने रोक हट गर्या थी पर शताब्दियों की आदत एक दिनमें तो छूट नहीं सकती थी; अछूत सामाजिक बहिष्कार के शिकार बने रहे। स्वयं दिलत-वर्गीय होने के नाते हाक्टर अम्बेडकरको इसका बड़ा दुख था और उन्होंने गोलमेज सम्मेलन-में कहा था कि जो लोग अस्कुत्यताके आधारपर आचरण करते हैं उन्हें कड़ी कैंदकी सजा

मिलनी चाहिये। गान्धी जीके रचनात्मक कार्यक्रममें अस्पृश्यता निवारणका प्रमुख स्थान था और वह अनवरत रूपचे उसके लिए सचेष्ट रहते थे। इसका प्रभाव विशेष नहीं हुआ और सुधार लगभग सुधारकोंतक ही सीमित रहा। पूना पैक्टमें प्रमुख भाग लेनेवाले मदनमोहन मालवीयने स्वयं अक्त्वरमें एक वक्तव्यमें कहा कि "मन्दिर और कुँओं आदिका उपयोग दिलतोंके लिए खोल देना टीक है पर पूना-पैक्टका यह अर्थ नहीं कि खान-पान और रोटीक वेटीका सम्बन्ध अछूतों के किया ही जाय।"

अक्त्वरके अन्तमें ही कुछ छोगोंने अपनेको कट्टर हिन्दुओंका प्रतिनिधि वताते हुए वाइसरायको एक स्मृतिपत्र दिया और उसमें कहा कि अछूतोंके मन्दिर-प्रवेशके प्रस्तावसे हमारी रक्षा की जाय और हिन्दुओंके धार्मिक रीति-रिवाजोंमें वाहरी हस्तक्षेप न किया जाय । गान्धीजीको अपना अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलन जेलसे चलानेकी अनुमृति मिल गयी थी। हिन्दू सुधारक समझते थे कि सिद्यों पुरानी कुप्रथाएँ कान्तसे ही खत्म हो सकती हैं और इसके लिए दो विल मद्रास विधायका कौंसिल और विधान-सभामें लाये भी गये। विलोंमें व्यवस्था थी कि अस्पृश्यतापर आधारित किसी भी प्रथाको अदालतोंमें कोई मान्यता नहीं मिलेगी। सवर्ण हिन्दुओंके कई संघटनोंने इन विलोंका घोर विरोध किया और सम्भवतः इसीलिए विलोंपर विचार वार-वार स्थित होता रहा। डाक्टर अवेडकरने घोषणा की कि मन्दिर-प्रवेश खोखली चीज है और दिलत वर्ग उसके लिए अपने साधन नष्ट नहीं करेगे; वे तो सवर्ण हिन्दुओंके गर्वोन्मत्त व्यवहारके कारण अवतक वर्जित मन्दिरोंमें जानेकी जगह अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थित सुधारनेमें अधिक दिलचस्थी रखते हैं।

१९३३ में सत्याग्रहमें थकानके चिन्ह प्रकट होने लगे थे, यद्यपि संयुक्तप्रान्त, वंगाल, वन्वई, मद्रास, विहार व उड़ीसामें एक छोटे पैमानेपर वह अब भी जारी था । २६ जनवरीको स्वतन्त्रता-दिवस समारोहमें ज्यादा दिलचस्पी दिखायी गयी। लगानवन्दीका प्रचार व धरना संयुक्तप्रान्तमें जारो था, वम्बई, अहमदावाद, विहार व उड़ीसामें विहिष्कार, धरना व प्रचारकार्य चल रहा था।

कांग्रेसका ४० वाँ वार्षिक अधिवेशन कलकत्तेमें पहली अग्रैलको होना तय हुआ। कांग्रेस स्वयं गैरकान्नी संस्था करार नहीं दो गयी थी और वंगाल विधान सभामें जब गृह-मन्त्रीसे पूछा गया कि अधिवेशन करना गैरकान्नी होगा, उन्होंने वात टालते हुए उत्तर दिया था—यह अपनी अपनी रायका सवाल है। लेकिन अधिवेशन रोकनेकी तैयारी सरकार-कर चुकी थी। इस तैयारीके फलस्वरूप स्वागत समिति गैरकान्नी करार दे दी गयी और उसके अध्यक्ष व सेकटरी पकड़ लिये गये। पुलिसको अधिकार दे दिया गया कि जिसपर भी कांग्रेससे सम्वन्धित होनेका शक हो उसे गिरफ्तार कर लिया जाय। इलाहाबाद क्षेत्रके रेलवे सुपरिटेण्डेण्टको आदेश दे दिया गया था और वह सभी स्टेशन मास्टरोंतक पहुँचा दिया गया था कि जो लोग कांग्रेसके प्रतिनिधि माल्प्स पड़ें उन्हें कलकत्त्रेके टिकट न दिये जावँ। कलकत्त्रेकी जनताको सावधान कर दिया गया था कि वह कांग्रेसमें आये प्रतिनिधियोंको न ठहराये और स्वागत समितिके दफ्तरके लिये मकान न दे। इलाहाबादके जिला मजिस्ट्रेटने कलकत्ता अधिवेशनके लिये नियुक्त अध्यक्ष मदनमोहन मालवीयको सचना दी थी कि वे अधिवेशनमें भाग नहीं लेने पायेंगे। कलकत्त्रेके लगभग ५०० प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्त्ता पकड़ लिये गये। वाहरसे आनेवाले कांग्रेस नेता पकड़े जाने लगे। जिला मजिस्ट्रेटकी आशा भंग

कर कलकत्तेके लिये जाते हुए मदनमोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरूकी पत्नी श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू आसनसोलमें पकड़े गये । कलकत्तेके सभी ५९ पाकॉपर पुलिसका पहरा बैटा दिया गया । अधिवेशनके लिए देशके विभिन्न भागोंसे चले ढाई हजार प्रतिनिधियोंमेंसे एक हजार पकड़ लिये गये । तब भी लगभग १५०० प्रतिनिधि कलकत्ते पहुँच गये और प्रतिवन्ध होनेके वावज्द लोगोंने उन्हें ठहराया । इन प्रतिनिधियोंमें ८३ मुसलमान, ११७ महिलाएँ, २३ सिख, ७ पारसी व २ ईसाई थे । संयुक्त प्रान्तसे सबसे अधिक ६७३ प्रतिनिधि गये थे ।

कलकत्तेमें अजब दृश्य था। दो दिनतक प्रतिनिधियोंको पुलिस नहाँ पाती उन्हें मारती-पीटती और दूसरी तरहकी यातनाएँ देती। वादमें मदनमोहन मालवीयने पुलिस अत्याचारोंके सम्बन्धमें जो वक्तव्य दिया उससे खितिका कुछ पता लगता है। उन्होंने लिखा था--''३० मार्चको संयुक्त प्रान्तके ८९ प्रतिनिधियोंको छापा मारकर गिरफ्तार किया गया और लालवाजार यानेमें अंग्रेज व एंग्लो इण्डियन सार्जण्टोंने उनपर हमला कर दिया । यह हमला विना किसी उत्तेजनाके, पूर्वनिश्चित और पाश्चिक था। प्रतिनिधियोंको डण्डों और घूँसोंसे मारा गया। कुछ साजेंण्ट डण्डे मार रहे थे, वाकी अपने घूँसे इस्तेमाल कर रहे थे। मार पेट, सीने, चेहरे व सिरपर पड़ी । बहुतसे प्रतिनिधियोंके सिर व चेहरे जरूमी हो गये। जो प्रतिनिधि मारके कारण एक ओर गिर पड़ते, उन्हें फौरन दूसरी ओर मार पड़ने लगती। पेटकी चोट रोकनेके लिए कोई प्रतिनिधि अपने हाथ वहाँ ले जाता तो उसके मुँहपर मार पड़ने लगती । कोई अपना सिर हुका लेता तो उसकी दुई। पर घुँसा पड़ता । जो मारके कारण गिर पडते उन्हें वटोंकी टोकरं लगतीं। इटावेसे आये एक प्रतिनिधिने अपने हाथोंसे सिर वचानेकी कोशिश की तो कई साजेंग्ट उसपर टूट पड़े और उसका सिर दीवारसे लड़ा दिया और उसका गला पकड़कर दीवारने उसे सटाये रहे। उसका सिर जख्मी हो गया और वहुत खून वहा । हमला खत्म होनेके वहुत देर वादतक बहुतसे प्रतिनिधि बेहोरा या अर्द्ध-मूर्छित परे रहे। एक दर्जनसे अधिक प्रतिनिधियोंके सिर, मुँह, आँख या दाँतसे तृन वह रहा था। सार्जेण्ट जंगलियोंकी तरह मार रहे थे और साथ ही गन्दी गालियाँ देते जा रहे थे। हर प्रतिनिधिको सार्जेण्टोंकी दोहरी कतारके वीचरे निकलना पड़ा और कोई भी उनके हमलेसे नहीं बचा । कुछ प्रतिनिधि तो जन्म भरके लिए लँगई एले हो गये।"

कलकत्तेके दो अन्य यानोंमें भी प्रतिनिधियोंके साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ ।

लेकिन, तत्र भी, पुलिसकी खीझ और परेशानीके बीच, कलकत्तेके सबसे घने बसे इलाकों में एक, एरण्लेनडमें ठीक बक्तपर, शामके तीन बजेसे, श्रीमती नेलीसेन गुप्तकी अध्यक्षतामें कांग्रेसका अधिवेशन हुआ । ढाई सौ प्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे। श्रीमती सेनगुप्तके भाषणके बाद जल्दी-जल्दी सात प्रस्ताव पास किये गये। इसके बाद मालबीयजीके शब्दों में "पुलिसने अन्ततः लाठीचार्ज किया, वहाँ इकट्ठी अपार भीड़को तितर वितर किया और प्रतिनिधियोंको गिरफ्तार कर लिया। प्रतिनिधियोंने हमलेको शान्तिसे सहन किया। एकके बाद एक प्रतिनिधि प्रस्ताव पेश करनेके लिए खड़ा होता और सार्जण्ड प्रस्ताव पढ़ते रहे, उनका चश्मा हुट गया और एक आँखमें बुरी तरह चोट आयी। लाठीचार्जके साथ ठोकरें भी मारी जा रही थीं। जो अब भी जिन्दा हैं, उनके धार्वोके निशान अब भी मौजूद हैं,

और तव भी भारत-सचिवने ब्रिटिश पार्लमेण्टमें कहा कि मालवीयके वक्तत्यमें लगाये गये आरोप 'द्वेषपूर्ण' हैं।"

२० अप्रैलको जेलसे एक वक्तन्य जारी कर गान्धीजोने ८ मईसे २१ दिनके अपने 'अविखण्डनीय और विना शर्त' उपवासकी घोषणा की । यह उपवास हरिजनोंके मामलेमें अधिक सतर्क और सजग रहनेके उद्देश्यसे अपनी व साथियोंकी आत्मिक शुद्धिके लिए किया गया था । उपवास दोपहरको शुरू हुआ और वे शामको ही मुक्त कर दिये गये । भारत सरकारने उन्हें "उपवासके उद्देश्यके लिहाजसे और उसमें परिलक्षित मानसिक दृष्टिकोण"के कारण छोड़ा था ।

मुक्त होते ही गान्धीजीने एक वक्तव्यमें कहा कि मैं इस छुटकारेसे खुद्रा कैसे हो सकता हूँ । "मैं इस मुक्तिका लाम उठाकर आन्दोलन चलाने या उसके लिए सलाह देनेका काम कैसे कर सकता हूँ ?" उन्होंने छः सप्ताहके लिए आन्दोलन स्थगित कर दिया। उन्होंने सरकारसे अपील की कि "यदि वह देशमें सच्ची शान्ति चाहती है तो आन्दोलन,स्थगित होनेका फायदा उठाकर सभी सत्याग्रहियोंको विना शर्त रिहा कर दे।" लेकिन "जवतक सरदार वस्लभ माई, खानसाहव अव्दुलगफ्पार खाँ, पण्डित जवाहरलाल नेहरू व दूसरे लोग जिन्दा दफ्त हैं" उन्होंने आन्दोलन वापस लेनेसे इनकार कर दिया। इसकी सरकारी प्रतिक्रिया दूसरे ही दिन प्रकट हो गयी। एक सरकारी विश्वप्तिमें कहा गया कि सरकार कांग्रेससे समझौतेकी बात चलानेको तैयार नहीं है, क्योंकि राजनीतिक कैदियोंकी रिहाईके लिए आन्दोलन स्थगित करना भर काफी नहीं है।

१२ जुलाईको कांग्रेसजन गैररस्मी तौरपर पूनामें मिले और उन्होंने राजनीतिक परिस्थितिपर विचार किया । उन्होंने सरकारसे समझौतेकी बातचीत चलानेके लिए गान्धी-जीको सव अधिकार दे दिये । गान्धीजीने तार देकर वाइसरायसे भेंटके लिए समय माँगा । कई तार आये-गये । अन्तमें वाइसरायके प्राइवेट सेके टरीने गान्धीजीका अनुरोध उकराते हुए लिखा—सरकारका एक ऐसी संस्थाके प्रतिनिधिसे बातचीत करनेका सवाल ही नहीं उठता जिसने सविनय अवज्ञा आन्दोलन वापस नहीं लिया है ।

वाइसरायके उत्तरसे राजनीतिक नक्शा वदल गया और कांग्रेसके कार्यवाहक अध्यक्ष माध्य श्रीहरि अणेसे सलाह कर गान्वीजीने एक दूसरे रूपमें आन्दोलन चलानेका निश्चय किया। अणेने निम्नलिखित कार्यक्रमकी घोषणा की लगानवन्दी, करवन्दी व दूसरे सार्वजनिक आशा मंग कार्यक्रम समाप्त किये जायँ; कांग्रेसजन अपने व्यक्तिगत दायित्वपर निजीरूपसे सत्याग्रह करें; गुत् तरीके बन्द हों; कांग्रेस महासमिति व कांग्रेसके दूसरे संगठन कुछ समयके लिए खत्म कर दिये जायँ और उनकी जगह डिक्टेटर नियुक्त कर दिये जायँ।

गान्धीजी पहली अगस्तको रास नामक गाँव जाकर व्यक्तिगत सत्याग्रहका श्रीगणेश करनेवाले थे, पर वे २४ आश्रमवासियोंके साथ २१ जुलाईकी रातको ही गिरफ्तार कर लिये गये। उन्हें ४ अगस्तको छोड़ा गया और आदेश दिया गया कि यरवदा गाँव छोड़कर वे पूना जाकर रहें। गान्धीजोने आदेशका पालन नहीं किया और आधे घण्टेके भीतर उन्हें फिर गिरफ्तार कर एक सालकी कैदका दण्ड दे दिया गया।

इसके बाद सैकड़ों कांग्रेसजनोंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया और वे जेल गये। अणे

अपने १३ सहयोगियों के साथ १४ अगस्तको पकड़ लिये गये। वे अकोलाके लिए मार्च करनेवाले थे, जब वे पकड़े गये। उनके स्थानापन्न शार्दूलिंह कवीश्वर भी शीध ही पकड़ लिये गये। कवीश्वरने अपना स्थानापन्न नियुक्त नहीं किया था, ताकि आन्दोलन सचमुच व्यक्तिगत सत्याग्रह वन सके। अगस्त १९३३ से मार्च १९३४ तक सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी का तांता लगा रहा।

इस वार गान्धीजीको जेलसे अरहस्यता निवारण सम्बन्धी अपना कार्यकम चलानेकी सुविधा नहीं मिली और इसके विरोधमें उन्होंने गिरफ्तारीके कुछ ही दिन बाद फिर अनस्यन किया। रेडे अगस्ततक वे बहुत कमजोर हो गये और उनकी जानको खतरा पैदा हो गया। उसी दिन वे विना दार्त रिहा कर दिये गये। पर गान्धीजी अपनेको वन्दी मानते रहे और ३ अगस्त १९३४ तक वे मुख्यतः हरिजन आन्दोलनके संघटनमें ही व्यस्त रहे। उस दिन उनकी एक वर्षकी कैदकी अवधि समात होती थी। नवम्बरमें उन्होंने हरिजनोंकी समस्यापर प्रचार और धनसंग्रहके लिए देशच्यापी दौरा गुरू किया। १० महीनेमें उन्होंने लगभग हर प्रांतका दौरा किया। पूनामें किसीने, सम्भवतः किसी कहर सनातनी हिन्दूने, गान्धीजीयर वम फँका जो उन्हें तो नहीं लगा पर कई और लोग धायल हो गये। फरवरी १९३४ में जवाहरलाल नेहरूपर उनके कियत राजदोहात्मक भाषणोंके लिए कलकत्तेमें फिर मुकदमा चला और उन्हें दो महीनेको सजा हो गयी।

७ अप्रैल १९३४ को गान्धीजीने व्यक्तिगत सत्याग्रह भी लगभग समाप्त कर दिया। एक वक्तव्यमें उन्होंने कहा—"यहुत सीचने और दिल टटोलनेके बाद में इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि वर्तमान परिस्थितिमें कैयल एक व्यक्तिको अर्थात् मुझे कुछ समयके लिए सिवनय प्रतिरोधका उत्तरदायित्व लेना चाहिये—यदि प्रतिरोध पूर्ण स्वराज्यकी प्राप्तिके साधन रूपमें सफल होता है तो.....इसलिए वे सब लोग जो स्वराज्य-प्राप्तिके लिए मेरी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सलाइसे सिवनय प्रतिरोधके लिए प्रेरित हुए थे, अवसे प्रतिरोध न करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतकी आजादीकी लड़ाईके हितमें यही सबसे अच्छा रास्ता है।"

पिछले असहयोग आन्दोलनकी समाप्तिकी भाँति इस वार फिर स्वराज्य पार्टीका उदय हुआ। ३१ मार्च १९३४ को डाक्टर अंसारीकी अध्यक्षतामें दिल्लीमें कुछ कांग्रेस नेताओंका सम्मेलन 'गितरोध' समाप्त करनेके लिए विधान मण्डलीमें प्रवेशके कार्यक्रमपर विचार करनेके लिए हुआ और अखिल भारतीय स्वराज्य पार्टीको पुनरुजीवित करनेका निश्चय हुआ। सम्मेलनने विधान मण्डलीमें जाकर सभी दमनकारी कान्न रद करवाने और स्वेतपत्रके प्रस्तावोंको दुकराकर उनकी जगह राष्ट्रीय माँगें रखवानेका कार्यक्रम बनाया। सम्मेलनके निर्णयोंपर डाक्टर अंसारीने गान्धीजीकी सलाह माँगी। गान्धीजीने स्वराज्य पार्टीका स्वागत करते हुए लिखा—"आजकी स्थितिमें विधान-मण्डलीके उपयोग सम्बन्धी मेरी राय प्रकट है। विधान-मण्डल वैसे ही हैं जैसे १९२० में थे।"

फिर २ व ३ मई को राँचीमें कांग्रेसजनींका एक वृहत् सम्मेलन हुआ, जिसमें चुनाव लड़नेके लिए खराज्य पार्टीके पुनर्जीवनके निर्णयका समर्थन हुआ और गोलमेज सम्मेलन के निर्णयोंपर आधारित वैधानिक सुधारोंकी योजनाके विह्रिकार और राष्ट्रीय माँगोंकी पृतिके लिए संविधानपरिपद निर्माणकी माँगके आधारपर चुनाव लड़नेका फैसला हुआ। पटनामें १८ व १९ मईको हुई अखिल मारतीय कांग्रेस महासमितिकी वैठकमें राँची सम्मेलनके निर्णयोंको

स्वीकार कर लिया गया और चुनाव लड़ने व उम्मीदवार छाँटनेके लिए एक पार्लमेण्टरी वोर्डकी स्थापना की गयी।

१९३४ के मध्यतक अधिकतर कांग्रेसजन रिहा कर दिये गये थे यद्यपि सरकारकी प्रतिशोधात्मक नीति जारी थी। बहुतसे कांग्रेसी नेता विशेषकर गुजरातके कार्यकर्जा अब भी जेलोंमें बन्द थे; कई प्रान्तोंमें कांग्रेस कार्यालयोंकी इमारतें वापस नहीं की गयीं, जिन लोगोंने आन्दोलनमें भाग लिया था उनके विदेश जानेपर पावन्दी थी; जो लोग व्यापार या निजी कामसे जाना चाहते थे, उन्हें भी पासपोर्ट नहीं दिया जाता था। खुदाई खिदमतगार संघटन अब भी गैरकान्नी था।

१८ सितम्बर १९३४ को कांग्रेस छोड़नेके निर्णय सम्बन्धी गांधीजीका प्रेस वक्तव्य पढ़कर भारत अचम्भेमें आ गया । वक्तव्य इस प्रकार गुरू हुआथा—"कांग्रे ससे सभी भौतिक सम्बन्ध खत्म कर लेनेके मेरे विचारके सम्बन्धमें जो अफवाहें थीं, वे सही थीं।" यह कदम उठानेके कारण वताते हुए गान्धीजीने लिखा था-"(१) शिक्षित कांग्रेसजनोंका काफी वड़ा भाग मेरी रीति, नीति और कार्यक्रमको पसन्द नहीं करता, लोग उससे थक गये हैं; कांग्रेसके स्वाभाविक विकासमें सहायता देनेकी जगह मैं बाधा बनता जा रहा हूँ; जनतान्त्रिक और प्रतिनिधित्व पूर्ण संस्था रहनेकी जगह कांग्रेस मेरे व्यक्तित्वकी प्रमुखमें आ रही है, उसमें तर्क-की प्रतिष्ठा घट रही है। (२) मैंने चरखा और खादी सबसे आगे रखा था, लेकिन शिक्षित कांग्रेसजन चरला चलाना लगभग छोड चुके हैं, यदि विधानसे खादीकी शर्त हटा दी जाय तो कांग्रेस और उस करोड़ों जनताके वीचकी कड़ी हट जायगी, जिसका प्रतिनिधित्व करनेका प्रयस्न कांग्रेस अपने जन्मसे कर रही है, अगर यह शर्त विधानमें रहती है तो इसका कड़ाईके साथ पालन होना चाहिये, पर यह हो नहीं सकता यदि कांग्रेसके बहुमतका इसमें जीवित विश्वास न हो। (३) असहयोग आन्दोलनका शुरू करनेवाला होता हुआ भी मैं समझता हूँ कि देशकी वर्त्तमान परिस्थितिमें जब कि सविनय अवशका कोई कार्यक्रम नहीं है, कांग्रेस-के भीतर ही वैधानिक कार्यक्रमवाला एक दल कार्यक्रमके रूपमें आवश्यक है, पर इस सम्बन्धमें गहरे मतभेद हैं । पटनामें कांग्रेस महासमितिकी वैठकमें मैंने जिस जोरसे इस कार्यक्रमकी वकालत की थी, उससे मेरे कुछ सबसे अच्छे साथी परेशान थे, लेकिन वे अपने विश्वासके अनुसार करने या कहनेमें हिन्विकचाये। किसी संस्थाके स्वस्थ विकासके लिए यह आवश्यक भी है और मला भी लगता है कि एक सीमातक व्यक्ति अपने मतपर उस न्यक्तिके मतके आगे जोर न दे जो अनुभव या विवेकमें वड़ा माना जाता हो; पर यदि यही वात दिन प्रतिदिन दोहरायी जाती रहे तो वह ऋरता और अत्याचार वन जाती है। (४) सोशल्स्टोंकी पुस्तिकाओंमें छपे कार्यक्रमसे मेरे आधारमूत विरोध हैं। यदि कांग्रेसमें उनका उत्कर्ष हुआ, जो होगा ही, तो मैं कांग्रेसमें नहीं रह सकता, क्योंकि सिक्तय विरोधमें होनेकी वात सोची भी नहीं जा सकती। (५) अस्पृश्यताके प्रश्नपर भी, सम्भवतः मेरा दृष्टिकोण बहुतसे (यदि अधिकांश नहीं) कांग्रेसजनोंसे भिन्न है। (६) अन्तमें अहिंसाकी छें; १४ वर्षके व्यवहारके वाद आज भी कांग्रेसके बहुसंख्यक लोगोंके लिए वह केवल एक नीति है, जब कि मेरे लिए वह बुनियादी सिद्धान्त है।"

इन वातोंपर कांग्रेंसजनोंकी भावनाएँ परखनेके लिए गान्धीजीने कांग्रेस विधानमें कुछ संशोधन करनेका प्रस्ताव किया । पहला संशोधन यह होना था कि 'वैध और शान्तिपूर्ण साधनों' की जगह 'सत्य और अहिंसाके साधनों' कर दिया जाय । दूसरा संशोधन यह या कि कांग्रेसकी चार आना सदस्यताकी जगह यह कर दिया जाय कि हर सदस्य या सदस्या हर महीने अपने आप कातकर कमसे कम ८००० फुट १५ नम्बरी स्त जमा करे। तीसरा संशोधन यह था कि जो व्यक्ति खादी धारण करनेका आदी न हो और जो लगातार छः महीनेसे कांग्रेसका सदस्य न हो, उसे कांग्रेस संस्थाके चुनावोंमें माग न लेने दिया जाय। चौथा संशोधन यह था कि कांग्रेस प्रतिनिधियोंकी अधिकतम संख्या १००० निर्धारित कर दी जाय।

र६, २७ व २८ अक्टूबर १९३४ को वम्बईमें राजेन्द्रप्रसादकी अध्यक्षतामें हुए कांग्रेस-अधिवेशनने गान्धीजीका लगभग पूरा कर्यक्रम और संशोधन स्वीकार कर लिया; सिर्फ प्रतिनिधियोंकी संख्या १००० की जगह २००० नियत की गयी । लेकिन गान्धीज़ो व अन्य लोगोंके यीच जो मीलिक सैद्धान्तिक मतभेद था वह प्रस्तावोंसे दूर नहीं हो सकता था और गान्धीजी अपने निर्णयपर हद रहे। वम्बई अधिवेशनके बाद वे कांग्रेसे अलग हो गये। कांग्रेसने एक प्रस्ताव हारा गान्धीजीके नेतृत्वमें अपना विश्वास दोहराते हुए कांग्रेस छोड़नेके अपने निर्णयपर पुनर्विचार करनेकी अपील गान्धीजीसे की। इस प्रस्तावमें आगे कहा गया था—"किन्तु इस सम्बन्धमें उन्हें राजी कर सकनेमें असमर्थ होने पर कांग्रेस उनका निर्णय वेमनसे स्वीकार करती है और देशके प्रति उनकी विलक्षण सेवाओंके लिए कृतज्ञता ज्ञापन करती है। इस बातपर कांग्रेस सन्तोप प्रकट करती है कि जब भी आवश्यक होगा उनकी सलाह और नेतृत्व कांग्रेस को प्राप्त होता रहेगा।"

कांग्रें सने एक प्रस्ताव द्वारा कांग्रें स समितिकी सदस्यताके लिए यह अनिवार्य कर दिया कि छः महीनेकी शारीरिक मेहनत जरूर की जाय। शारीरिक मेहनतमें ५०० गज स्त कातना भी था।

अध्याय २३

फिर आतंकवाद

सात सालकी निष्कियताके बाद, जिस बीच क्रान्तिकारी पार्टियाँ गान्धीवादी आन्दो-लनोंके परिणामोंकी प्रतीक्षा करती रहीं, १९२४ में फिर आतंकवादी कार्य ग्रुक हो गये। उसी वर्ष जनवरीमें वंगाल पुलिस किमस्तर टैगर्टके धोखेमें, गोपीमोहन साहाने एक अन्य आदमी अनेंस्ट डेको गोली मार दी। अप्रैलमें एक दूसरे अंग्रेज ब्रुसको हरिसन रोड कलकत्तेमें गोली मार दी गयी। यहाँ भी धोखेमें ही ब्रुसपर गोली चलायी गयी। कलकत्तेमें ही मार्च के महीनेमें, बम बनानेका एक कारखाना पकड़ा गया। जुलाईमें कलकत्तेकी सड़कोंपर एक क्रान्तिकारी पार्टीका सदस्य पकड़ा गया। उसके पास भरी हुई पिस्तौल थी। अब कुछ कांग्रेसजन भी वम-राजनीतिसे इतने प्रभावित हो गये कि जूनमें चित्तरंजन दासकी अध्यक्षतामें वंगाल राजनीतिक सम्मेलनमें गोपीमोहन साहाके आत्म बल्दानकी प्रशंसा करते हुए एक प्रस्ताव पास किया।

१९२५ में अंग्रेजी पार्लमेण्टने, भारत सरकारको, बंगालमें पाँच सालसे लागू विशेष नियमोंको आगे भी लागू किये रहनेकी अनुमित दे दी जिसके परिणाम-स्वरूप वंगालमें आतंकवादी पार्टियोंके करीव डेढ़ सो नेता गिरफ्तार कर जेलोंमें वन्द कर दिये गये।

यू० पी० में, जहाँ १९२४ में क्रान्तिकारी संघटन हिन्दोस्तान रिपब्लिकन संघकी शाखा कायम हो गयी थी, लखनऊ जिलेंमें काकोरो रेलवे स्टेशनके पास एक हिश्यारवन्द डाका पड़ा। सुरादाबादसे लखनऊ आनेवाली एक मुसाफिर गाड़ीको रोक लिया गया और रिवालवर दिखाकर कुछ नौजवानोंने गार्डके डिव्वेसे रुपयेके वक्स उतार लिये। एक मुसाफिरने कुछ वाधा डालनेकी कोशिश की तो उसको गोली मार दी गयी। यू० पी० में ये शाखाएँ कायम करनेका विशेष श्रेय योगेशचन्द्र चटजींको है। वे १९२३ के अन्तमें कलकत्तेसे वनारस चले आये थे। इस काममें सचीन्द्रनाथ सान्यालने उनकी सहायता की। सचीन्द्रनाथ सान्यालको 'वनारस षड्यन्त्र केस' में १९१५ में सजा हुई थी और फिर १९२५ में 'क्रान्तिकारी' नामक परचा वाँटनेके अभियोगमें फिर उन्हें सजा हो गयी।

काकोरी रेल डकैतीके सम्बन्धमें अट्ठाइस आदिमयोंपर मुकदमा चलाया गया। चारको फाँसीकी सजा मिली, दोको कालेपानी और वाकीको पाँचसे चौदह वर्षकी कैदकी सजा दी गयी।

१९२८ में पंजाबमें भी आतंकवादी कार्य आरम्भ हो गये । लाहौरमें भगतसिंह और उनके साथियोंने एक जंगजू संस्था—नौजवान भारत सभा स्थापित कर ली । इस संघटनका काम, समाजवादी विचारधाराका प्रचार करना, अंग्रेजोंके विरुद्ध 'सीधी' काररवाई करनेकी आवश्यकता समझाना और आतंकवादी पार्टीके लिए सदस्य भरती करनेके केन्द्रके रूपमें काम करना था । यह भारत सभा आगे चलकर हिदोस्तान समाजवादी रिपव्लिकन संघमें परिणत हो गयी । इसकी प्रान्तीय और जिला शाखाएँ स्थापित हो गयीं । दिसम्बर १९२८ में लाहौरमें एक यूरोपीय नायव सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस साण्डर्स और एक हिंदुस्तानी पुलिस-

के िषपादीकी हत्या कर दी गर्या । लाजपतरायके नेतृत्वमें साहमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन पर पुल्सिने जो लाठीचार्ज किया या, जिसमें लाजपतरायको संवातिक चोठ लगी थी, उससे उत्ते जित होकर ये हत्याएँ हुई थीं । कुछ हफ्तों वाद लाजपतरायकी मृत्यु हो गयी । आतंकवादियोंने इसका वदला संडर्सकी हत्यासे लिया । लाठीचार्जका हुकम संडर्सने दिया था और उन्होंने अगुआई भी की थी । अप्रैल १९२९ में केन्द्रीय विधान सभामें औद्योगिक विवाद विधेयक (ट्रेड डिस्प्यूट्स विल) पास होने पर भगतसिंह और बी० के० दत्तने सरकारी सदस्योंपर वम फेंके । यह विधेयक मजदूर-आन्दोलनके विरुद्ध था । मजित्द्रेटके सामने उन्होंने अभियोग स्वीकार कर लिया और अपने वयानमें कहा कि उनका उद्देश प्रदर्शन मात्र था, किसीको चोठ पहुँचाना नहीं था । दोनोंको कालेपानीकी सजा मिली । ये दोनों संडर्स हत्याकाण्डमें भी अभियुक्त थे ।

कुछ ही दिन बाद लाहोरमें वम बनानेका कारखाना पकड़ा गया और इस सिल-सिलेमें न सिर्फ पंजाबमें बिल्क यू. पी. और विहारमें भी वहे पैमानेपर लोग गिरफ्तार किये गये। जुलाईमें लाहोर पड्यन्त्र कैसमें तेरह आदिमयों पर मुकदमा चलाया गया। इस कैसमें सांडर्म हत्याकाण्ड भी जोड़ दिया गया।

जेलके अन्दर कई मईनिंतिक अभियुक्तंपर अत्याचार होते रहे और उन्हें अमानुषिक यातनाएँ दी जाती रहीं। मैजिस्ट्रेटके सामने खुली अदालतकमें ये पीटे जाते थे। एक पुस्तिकामें एक अभियुक्तने लिखा है कि "वहीं (अदालतमें) वकीलों और दर्शकोंकी उपस्थितिमें डण्डों और लाठियोंसे लैस वीसियों पुलिसके सिपाही हमारे ऊपर टूट पड़े। हमने खालो हायोंसे इस हमलेको रोका मगर परिस्थितियाँ हमारे प्रतिकृल थीं, हमारे सर छाती, और वाँहोंपर लाठियोंकी वर्षा होती रही। जमीनपर गिराकर हमारे ऊपर टोकरों और लाठियोंकी वेशिर होने लगी। हम लोगोंकी चोटें इतनी गम्भीर थी कि कई साथी कई दिनोंतक हिल्डुल भी न सके। "एक मतवां जब सात लड़के लाहोर पट्यन्त्र केसके अभियुक्तोंकी रक्षाके लिए चन्दा जमा कर रहे थे तो पुलिसने उन्हें जिला मजिस्ट्रेटकी उपस्थितिमें पाटा, यहाँतक कि सब बुरी तरहसे जल्मी हो गये और कुछ बेहोरा होकर गिर पड़े।

अपने साथ किये गये दुर्घ्यवहारके विरोधमें और अपनी तकलीकोंको दूर करानेके लिए लाहाँर पड्यन्त्र केसके अभियुक्तोंने जेलमें भूख-हड़ताल शुरू कर दी । ६३ दिनतक लगातार भूख-हड़ताल करनेके बाद जतीन्द्रनाथ दासने अपना जीवन बलिदान कर दिया । उनकी मृख्यर सारे देशमें विरोधारमक प्रदर्शन हुए ।

सरकारने लाहीर पड्यन्त्रके अभियुक्तींका मुकदमा करनेके लिए एक आर्डिनेन्स द्वारा एक विशेष ट्रिन्यूनल कायम कर दिया । किसी वकीलको अभियुक्तींकी तरफले पैरवी करनेका अधिकार नहीं दिया गया । इस ट्रिन्यूनलने भगतसिंह, राजगुन और मुखदेवको फाँसीकी सजा दो और वाकी सातको कालेपानीकी सजा दो । वाइसरायके पास गान्धीजीके प्राथंना करनेके यावजूद और पूरे राष्ट्रकी माँग—'फाँसीके अभियुक्तींकी सजा वदलकर कालापानी कर दी जाय'—को उकराकर २२ मार्च १९३१ को भगतसिंह, राजगुर और मुखदेव फाँसीपर लटका दिये गये। इस फाँसीके खिलाफ लोगोंमें इस कदर गुस्मा या कि केन्द्रीय विधान-सभाके गैर-सरकारी सदस्वोंकी एक बहुत वड़ी संख्या विच विधेयक (फाइनेंस

अजय घोष, भगतसिंह एण्ड हिज कॉमरेट्स पृष्ट १४

विल) के ऊपर हो रहो वहसके दौरानमें फाँसीके विरोधस्वरूप २५ मार्चकी वैठक' छोड़, सभा-भवनसे वाहर चली आयी । कराची कांग्रेस अधिवेशन (१९३१) ने राजनीतिक हिंसाको उचित न मानते हुए और अपनेको उससे अलग करते हुए भगतसिंह और उनके साथियोंकी वहादुरी और बलिदानको प्रशंसा की।

२३ दिसम्बर १९२९ को दिल्लीके निकट वॉइसरायकी गाड़ीको नष्ट करनेका असफल प्रयत्न किया गया। इस वसके ठीक वक्तपर फटनेके लिए घड़ीकी तरहके यन्त्रका इस्तेमाल किया गया था।

अप्रैल १९३० में १५० बंगाली नौजवानों के एक दलने पूर्वी बंगालमें चटगाँवमें पुलिस शक्तशाला (आर्मरी) सहायक सेनाकी शक्तशाला (आग्जिलरी फोर्स आर्मरी) यूरोपीयन क्ल्व, तार और टेलीफोनके दफ्तरपर हमला किया और कुछ हथियार, गोली और वारूद लेकर भाग गये। ये नौजवान खाकी वरदी पहने हुए थे और इनके नेता अफसरों की वरदीमें थे। आक्रमणकारी चार दलों में विभक्त थे। सहायक सेनाकी शक्तशालापर हमला करनेवाली दुकड़ीने साजेंट मेजर फैरल और एक सिपाहीको मोली मार दी और इमारतमें पेट्रोलसे आग लगा दी। जब पि पुलिस शक्तशालापर हमला करनेवाली दुकड़ीने उस रास्तेसे गुजरनेवाली सब मोटर गाड़ियोंपर गोलियाँ चलायीं, उनकी गोलियोंसे एक रेलवे गार्ड, एक टैक्सीका ड्राइवर और सहायक ड्राइवर तथा मजिस्ट्रेटकी कारमें एक सिपाही मरा। इस दुकड़ीने सात आदिमयोंको मार डाला और दोको घायल किया। तार-घरपर हमला करनेवाली दुकड़ीने, जिसमें छः आदमी थे, वहाँके क्लर्कको पकड़ लिया, उसे क्लोरोफार्म सुँघाकर वेहोश कर दिया और टेलीफोन बोर्डको नष्ट कर दिया।

सफलता पानेके लिए आक्रमणकारियोंने हमला करनेसे पहले चटगाँवसे लेकर २७ मीलकी दूरीतकके तार काट दिये थे। आधी रातके करीव, जब कि आक्रमणकारी शहरके उत्तरकी तरफ पहाड़ियोंमें भागे तो उनमें और हथियारवन्द पुलिसमें छोटी-छोटी लड़ाइयाँ हुई। इन लड़ाइयोंमें १९ आक्रमणकारी मारे गये। कई पुलिसवाले भी घायल हुए और मारे गये।

पाँच दिन वाद फेनी रेलवे स्टेशनपर चटगाँव-आक्रमणसे सम्बन्ध रखनेके सन्देहमें ४ नौजवान गिरपतार कर लिये गये । नौजवानोंने रिवाल्वरसे गोलियाँ चलानी छक्त कर दीं और एक नायव इंस्पेक्टर व दो सिपाहियोंको घायल करके भाग गये ।

१९३० में वम्बई, हावड़ा, मद्रास, मुल्तान, कानपुर, लाहौर, लायलपुर, वारोसाल, अमृतसर, गुजरानवाला, रावलिपण्डी, शेलूपुरा, दिल्ली, कलकत्ते, पेशावर, झाँसी, ढाका, मैमनसिंह, वन्नू, राजशाही, वनारस, कराची, जैसोर, मुशिंदावाद, खुलना, खुरजा, इलाहावाद, खुधियाना, जैसोर, हैदरावाद (सिन्ध) चाँदपुर (वंगाल) और लाहौरमें वम फेंकने, गाड़ी रोकने, और अधिकारियोंकी हत्याके प्रयत्नोंकी अनेक घटनाएँ हुई।

८ दिसम्बर १९३० को यूरोपियन पोशाक पहने हुए तीन आतंकवादी जेलोंके इंस्पेक्टर जनरल, लेपिटनेण्ट कर्नल सिम्पसनके दफ्तर पहुँचे और उनको गोलीसे मार डाला व दो अन्य आदिमयोंको घायल कर दिया। हमला करनेवालोंमेंसे एकने जहर खाकर अपनी जान दे दी, वाकी दोनोंने अपनेको गोली मार ली। उनमेंसे एक विनय वसु मर गया और दूसरे दिनेश गुप्तपर मुकदमा चलाया गया और उसे फाँसी दे दी गयी।

विल) के ऊपर हो रही वहसके दौरानमें फाँसीके विरोधस्वरूप २५ मार्चकी वैठक' छोड़, सभा-भवनसे वाहर चली आयी । कराची कांग्रेस अधिवेशन (१९३१) ने राजनीतिक हिंसाको उचित न मानते हुए और अपनेको उससे अलग करते हुए भगतसिंह और उनके साथियोंकी बहादुरी और बलिदानकी प्रशंसा की।

२३ दिसम्बर १९२९ को दिल्लीके निकट वॉइसरायकी गाड़ीको नष्ट करनेका असफल प्रयत्न किया गया। इस वमके ठीक वक्तपर फटनेके लिए घड़ीकी तरहके यन्त्रका इस्तेमाल किया गया था।

अप्रैल १९३० में १५० बंगाली नौजवानोंके एक दलने पूर्वी वंगालमें चटगाँवमें पुलिस शस्त्रशाला (आमरी) सहायक सेनाकी शस्त्रशाला (आग्जिल्सी फोर्स आमरी) यूरोपीयन क्ल्व, तार और टेलीफोनके दप्तरपर हमला किया और कुछ हथियार, गोली और वारूद लेकर भाग गये। ये नौजवान खाकी वरदी पहने हुए थे और इनके नेता अफसरोंकी वरदीमें थे। आक्रमणकारी चार दलोंमें विभक्त थे। सहायक सेनाकी शस्त्रशालापर हमला करनेवाली टुकड़ीने साजेंट मेजर फैरल और एक सिपाहीको मोलो मार दी और इमारतमें पेट्रोलसे आग लगा दी। जब कि पुलिस शस्त्रशालापर हमला करनेवाली टुकड़ीने सानें गिर गाड़ियोंपर गोलियों चलायों, उनकी गोलियोंसे एक रेलवे गार्ड, एक टैक्सीका ड्राइवर और सहायक ड्राइवर तथा मजिस्ट्रेटकी कारमें एक सिपाही मरा। इस टुकड़ीने सात आदिमयोंको मार डाला और दोको घायल किया। तार-घरपर हमला करनेवाली टुकड़ीने, जिसमें छः आदमी थे, वहाँके क्लर्कको पकड़ लिया, उसे क्लोरोफार्म सुँघाकर वेहोश कर दिया और टेलीफोन बोर्डको नष्ट कर दिया।

सफलता पानेके लिए आक्रमणकारियोंने हमला करनेसे पहले चटगाँवसे लेकर २७ मीलकी दूरीतकके तार काट दिये थे। आधी रातके करीव, जब कि आक्रमणकारी शहरके उत्तरकी तरफ पहाड़ियोंमें भागे तो उनमें और हथियारवन्द पुलिसमें छोटी-छोटी लड़ाइयाँ हुईं। इन लड़ाइयोंमें १९ आक्रमणकारी मारे गये। कई पुलिसवाले भी घायल हुए और मारे गये।

पाँच दिन वाद फेनी रेलवे स्टेशनपर चटगाँव-आक्रमणसे सम्बन्ध रखनेके सन्देहमें ४ नौजवान गिरपंतार कर लिये गये। नौजवानोंने रिवाल्बरसे गोलियाँ चलानी शुरू कर दीं और एक नायव इंस्पेक्टर व दो सिपाहियोंको घायल करके भाग गये।

१९३० में वम्बई, हावड़ा, मद्रास, मुल्तान, कानपुर, लाहौर, लायलपुर, वारोसाल, अमृतसर, गुजरानवाला, रावलिएडी, शेखूपुरा, दिल्ली, कलकत्ते, पेशावर, झाँसी, ढाका, मैमनसिंह, वन्तू, राजशाही, वनारस, कराची, जैसोर, मुशिदावाद, खुलना, खुरजा, इलहावाद, खिल्याना, जैसोर, हैदरावाद (सिन्ध) चाँदपुर (वंगाल) और लाहौरमें वम फेंकने, गाड़ी रोकने, और अधिकारियोंकी हत्याके प्रयत्नोंकी अनेक घटनाएँ हुई ।

८ दिसम्बर १९३० को यूरोपियन पोशाक पहने हुए तीन आतंकवादी जेलोंके इंस्पेक्टर जनरल, लेपिटनेण्ट कर्नल सिम्पसनके दफ्तर पहुँचे और उनको गोलीसे मार डाला व दो अन्य आदिमयोंको घायल कर दिया। हमला करनेवालोंमेंसे एकने जहर खाकर अपनी जान दे दी, वाकी दोनोंने अपनेको गोली मार ली। उनमेंसे एक विनय वसु मर गया और दूसरे दिनेश गुप्तपर मुकदमा चलाया गया और उसे फाँसी दे दी गयी।

उसी महीनेमें पंजाव यूनिवर्षिटीके दक्षिांत समारोहके समय गवर्नर और उनके साथियोंपर गोलियाँ चलायो गर्या । गवर्नरको तो थोड़ी ही चौट आयी परन्तु पुलिसके एक अधिकारीको वातक चोट लगी। ३७५

१९३१ में भी बंगाल, पंजाब और यू॰ पी॰ में वम फंकनेको वाढ़-सी आ गयी थी। १९३१ के आरम्भमें मिदनापुरके जिला मजिस्ट्रेंटको गोलीसे मार डाला गया। अलीपुरका जिला जन भी इसी मकार मारा गया। मिदनापुरके कई जिला मजिस्ट्रेट एकके वाद एक इसी तरहसे मारे गये। २७ जनवरी १९३१ को इलाहाबादमें मसिद्ध परार

मान्तिकारी चन्द्रशेखर आजाद और पुलिसके वीच गोलियाँ चलाँ। आजाद मारे गये और कई पुलिस अधिकारी वायल हुए। १९३२ में आतंकवादियोंके हमलोंकी ९७ घटनाएँ हुई जब कि १९३२ में ८२, १९३० में ५३ और १९२९ में ८ हुई थीं। प्रन्तु १९३३ में में घटनाएँ घटकर ४३ रह गर्यो । १९३४ में और कमी हुई तथा १९३५ में आतंकवादी कार्य एकदमसे खत्म हो गरे। उस साल अक्रेले बंगालमें २७०० नजरवन्द केदी थे।

अध्याय २४

संगाजवादी व कम्यूनिस्ट पार्टियाँ

१९२४ में सरकारको सूचनाएँ मिलीं कि सीमाप्रान्तमें कम्यूनिस्ट प्रचार किया जा रहा है। सीमाप्रान्त हमेशासे ही अँग्रेजोंके लिए सरदर्द बना हुआ था। कम्यूनिस्ट प्रचार का मुख्य केन्द्र समरकन्द स्थित पुरानी 'कॉलोनी' थी जहाँसे एक समय बहाबी आन्दोलन संचालित होता था।

उस वर्ष सरकारने कानपुरमें एक कम्यूनिस्ट षड़यन्त्रका पता लगा लेनेका दावा किया। एम. एन. रायसे प्रेरणा पाकर कुछ नौजवानोंने 'भारतकी कम्यूनिस्ट पाटीं' संघटित .की । एम. एन. रॉय इन लोगोंसे वरिलनके एक पतेकी मार्फत पत्र-व्यवहार करते थे। ये नौजवान कम्यूनिस्ट-साहित्य वितरित कर रहे थे, जिसमें कहा गया था कि सरकारको हिंसा द्वारा उलट दो और वर्गरहित समाज स्थापित करो। इस अपराधके लिए कई लोगोंको गिरफ्तार करके, भिन्न-भिन्न सजाएँ दी गर्यी । कानपुर-षड़यन्त्रकारियोंको गिरफ्तारियोंके वावजूद कम्यूनिस्ट कार्य होते रहे । अत्यभक्त नामके एक व्यक्ति भारतमें कम्यूनिस्ट पार्टीके जन्मदाता और उसको संघटित करनेवाले थे। रायका प्रचार चाल था। "छपे हुए घोषणा-पत्रोंमेंसे एकमें (जो भारतमें बहुत बड़े पैमानेपर वाँटे गये थे) रायने कहा कि क्यों गोलियों और गुप्त समाज इत्यादिसे कान्ति नहीं हो सकती। व्यक्तिगत आतंक अंग्रेजी पार्लमेंटके कानूनोंकी भाँति निरर्थक हैं। केवल विद्रोही जनता ही भारतमें सामाजिक राजनीतिक उथल-पुथल पैदा कर सकतो है। कम्यूनिस्ट पार्टीका उद्देश्य । हर सम्भव तरीकेसे गरीवों और मजदूर वर्गकी दशामें सुधार करना था। किसान, दफ्तरके वावू, रेल और डाकके कर्मचारी, पुल्सिके सिपाही और विद्यार्थी सव 'मजदूर'की परिभाषामें रखे गये। कम्यूनिस्ट पार्टीका अन्तिम लक्ष्य 'वर्तमान सामाजिक संघटन और भारत सरकारको वदलना, उत्पत्ति और वितरण (जैसे जमीन, कारखाने, खानें, तार और व्यापारिक समुद्री वेंड़ा इत्यादि) के सब साधनींका नियन्त्रण साधारण जनताके हाथमें देना और उसे इन साधनोंका मालिक बनाना था। पार्टीका कहना था कि यह कार्य इस प्रकारसे पूरा किया जाय कि सर्वसाधारण अभीष्ट-सिद्धिके कार्यमें भाग छें और सब इससे लाभ उठाएँ।"

पार्टीने दिसम्बर १९२५ के अन्तमें, मद्रासके सिंगरावळ्की अध्यक्षतामें कानपुरमें अखिल भारतीय कम्यूनिस्ट सम्मेलनका आयोजन किया। सिंगरावळ् कानपुर षड्यन्त्र काण्डमें अभियुक्त थे, परन्तु उनपर सुकदमा नहीं चलाया गया। सम्मेलन उसी पंडालमें होनेवाला था जहाँ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, परन्तु इस पंडालके इस्तेमालको आज्ञा नहीं दी गयी। सम्मेलनमें पाँच सौ प्रतिनिधियोंने भाग लिया था। कानपुरमें सत्यभक्त द्वारा पार्टीके संघन

१. इव्डिया इन १९२४-२५ पृष्ठ १३

२, वही पुस्तक, पृष्ठ १३

३. इण्डिया इन १९२५-२६ से उद्धत पृष्ठ १९६

टनके तरीकों और प्रवन्धपर वड़ा असन्तोष व्यक्त किया गया। सत्यभक्तने, जो भारतीय कम्यूनिस्ट पाटोंको रूसी या और किसी विदेशी प्रभावसे मुक्त रखना चाहते थे, त्याग-पत्र दे दिया। पाटोंके प्रधान कार्यालयका स्थान कानपुरसे वदलकर वम्बई कर दिया गया और वादमें कलकत्तेमें प्रधान कार्यालय स्थापित किया गया।

दूसरी तरफ कम्यूनिस्ट १९२६ में मजदूरों और किसानोंकी पार्टियाँ संघटित कर रहे थे। १९२७ में ब्रिटिश पार्लमेण्टके सदस्य शापूरजी सकलातवाला तथा एक अन्य अंब्रोजी कम्यूनिस्ट जार्ज एलीसन उर्फ डोनाल्ड कैम्पवेल भारत आये । उन्होंने पूरे देशकी यात्रा कर मुख्य नगरोंमें बड़ी-बड़ी समाओं में भाषण किये और मजदूर तथा किसान पार्टियाँ संघ-टित करनेको प्रोत्साहित किया । महायुद्धके बाद, १९२८ का वर्ष मजदूर आन्दोलन और संघपोंकी सबसे बड़ी प्रगतिका वर्ष था। वंगाल मजदूर आन्दोलनोंका केन्द्र वन गया। साइ-मन कमीशन विरोधी राजनीतिक इड़तालों और प्रदर्शनींसे मजरूर आन्दोलनींको वहत प्रोत्साइन मिला । १९२८-२९ के सालमें देशमें २-३ हड्तालें हुई जिनमें एक साउथ इण्डियन रेलवेकी हड़ताल भी थी जिसमें ५०६,८५१ मजदूर शामिल थे। रेलवे हड़तालके सम्बन्धमें बहुतसे लोग गिरपतार किये गये और उनपर मुकदमा चलाया गया। उनमेंसे पन्द्रहको दस-दस सालकी कड़ी कैदकी सजा मिली। सरकार समझती थी कि सकलातवाला व कुछ अन्य यूरोपीय कम्यूनिस्ट भारतमें मजदूर संवर्षोंके लिए जिम्मेदार थे। इसलिए सरकारने १९२८ में केन्द्रीय विधान समामें जन सुरक्षा विधेयक पेश करके 'ऐसे लोगोंके जो ब्रिटिश भारतकी प्रजा हों और ध्वंसारमक उपायोंसे सरकारको उलटना चाहते हों' निष्कासनकी स्वीकृति चाही। विधान सभाने विधेयक अस्वीकृत कर दिया । जनवरी १९२९ में सरकारने इस विधेयक में कुछ संशोधन कर इसे फिर विधान सभामें स्वीकृतिके लिए पेश किया। यह विधेयक भी अमान्य कर दिया गया । लेकिन गवर्नमेंटने इस विषयका एक आर्डिनेंस जारी किया । मार्च १९२९ में सरकारने वत्तीस मजदूर नेताओंको जिनमें कुछ कांग्रेसजन, और तीन अंग्रेज भी थे गिरफ्तार किया और उनपर मेरठमें मुकदमा चलाया। उनपर भारत सरकारकी इस तरह शक्ति-प्रयोग द्वारा, जो अपराध माना जाता हो उलटनेके पड्यंत्र करनेका अभियोग लगाया गया। उनके ऊपर लगाये गये अन्य आरोप थे—मजदूरी और पूँजीपतियोंके बीच विरोध और वैमनस्य वढ़ाना, मजदूरों और किसानींकी पार्टियाँ व नौजवान संवीं (यूथ लीग) और यूनियनोंके जरिए इड़तालोंको प्रीत्माहन देना। पड़बंत्र सिद्ध नहीं किया जा सका, किर भी मुकदमा साढ़े तीन सालतक चलता रहा। जनवरी १९३३ में निर्णय सनाया गया । मुजनफर अहमदको कालेपानीकी चना दो गयी । एस. ए. डांगे, एस. वी. वाटे, के एन. जोगलेकर, आर. एस. निम्बालकर, फिलिप खेट, को १७-१७ सालकी सजाएँ दी गयी; और शौकत उत्मान व थी. एफ. बैडलेको दस दस सालकी । सबसे कम सजा तीन सालकी कड़ी कैंदकी थी। अपील करने पर ये सजाएँ घटा दी गर्या । अधिकतर सजाएँ तो १९३३ के अन्तके पहले ही समाप्त हो गयीं। छूटे हुए कम्यूनिस्ट फीरन ही अपने अपने कामींमें जुट गये। कांग्रेसके वाएँ वालुका मानसेवादकी तरफ अकाव था। १७ दिसम्बर १९३३ की जवाहरलाल नेहरूने कहा "आज संसारको कम्यूनिच्म और फासिच्ममेंसे एक चुनना है। में तो पूरे तौरपर कम्यूनिङमके साथ हूँ । कम्यूनिङमके मूळ सिद्धानत और इतिहासका वैज्ञानिक विख्लेपण दोनों तही हैं।" १९३३ के अन्तिम दिनों में कम्यूनिस्टाने जोरदार

प्रचार आन्दोलन ग्रुलं किया। हिन्दोस्तान समाजवादी रिपव्लिकन संघ द्वारा जारी हुए परचोंको दिव्लीमें चिपकाया गया। फरवरी १९३४ में, भारतके मुख्य औद्योगिक केन्द्रों, जैसे वम्बई, लाहौर, कलकत्ता, अहमदावाद वगैरहमें अकस्मात लम्बे-लम्बे लेख जिनमें कान्तिकारी कार्योंके सब पहलुओंकी व्याख्या और भारतमें भावी कार्यक्रमकी रूपरेला दी हुई थी, प्रकट हुए। उस गैरकान्नी पत्रिकाका नाम जिसमें ये सब लेख छपते थे 'कम्यूनिस्ट' था। अन्तरराष्ट्रीय कम्यूनिस्ट संघके अंग भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टाकी अस्थायी केन्द्रीय समिति (प्रॉविजिनल सेण्ट्रल कमेटी) का यह मुखपत्र था।

जनवरी १९३४ के अन्तिम सप्ताहमें बम्बईमें एक कम्यूनिस्ट सम्मेलनने आगामी तीन महीनोंके अन्दर कपड़ा-उद्योगके मजदूरोंको देशव्यापी हड़ताल संघटित करनेके लिए एक संघर्ष-समिति नियुक्त की। योजनाके अनुसार 'मई-दिवस' पर देशव्यापी आम हड़ताल आरम्भ होनेके लिए एक हफ्तेका समय देकर २३ अप्रैलको वम्बईमें हड़ताल ग्रुरू हो गयी। शोलापुरमें हड़ताल आरम्भ हो चुकी थी। दिल्ली और नागपुरमें भी मईमें हड़तालं हो गयीं।

२३ जुलाईको भारत सरकारने एक विज्ञित द्वारा भारतकी कम्यूनिस्ट पार्टा, पार्टाकी सिमितियों और इसकी शाखाओंको गैरकान्नी घोषित कर दिया, क्योंकि सरकारके अनुसार पार्टाका उद्देश शान्ति और व्यवस्था कायम रखनेमें बाधा डालना था जिसके कारण जनशान्तिको खतरा पैदा हो गया था। अगले महीने ग्रहमन्त्रीने इस कार्यकी सफाई पेश करते हुए विधान सभामें कहा कि मेरठ घडयन्त्र काण्डके मुकदमेंसे साफ तौरपर यह सिद्ध हो गया था कि भारतकी कम्यूनिस्ट पार्टी और कम्यूनिस्ट अन्तरराष्ट्रीय संघमें गहरा सम्बन्ध है और भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टीका उद्देश्य हिंसात्मक साधनों द्वारा समाजके वर्षामान ढाँचेको उलटना है तथा हथियारवन्द कान्तिके जरिये भारतको स्वतन्त्र करना है।

भारत सरकारका अनुसरण कर पंजाव, वस्वई और मद्रासकी प्रान्तीय सरकारोंने भी कई कम्यूनिस्ट संघटनोंके खिलाफ विज्ञितियाँ निकालकर उन्हें गैरकानूनी घोषित कर दिया। "एक दर्जनसे अधिक रिजस्ट्री ग्रुदा मजदूर यूनियनोंको गैरकानूनी करार दे दिया गया। नौजवान मजदूर संघ (बंग वर्कर्स लीग) भी अवैधानिक घोषित कर दी गयी। मजदूर वर्गके लड़ाकू और क्रान्तिकारी संघटनोंको कुचलनेके लिए गोलियोंका भी प्रयोग किया गया। विना मुकदमा चलाये मजदूर व कम्यूनिस्ट नेता जेलोंमें नजरवन्द कर दिये गये।"

मेरठ केसके वाद मजदूरों और किसानोंकी पार्टियाँ खत्म हो गयी थीं। कुछ वर्षों तक कम्यूनिस्ट-कार्य जो मजदूर-आन्दोलनतक ही अभी सीमित थे, करीय-करीय खत्मसे रहे।

१९२५ से १९३३ तक भारतमें कम्यूनिस्ट पार्टीकी प्रगति एक रूसी कम्यूनिस्टके रान्दों में यह थी, "देशमें विखरे हुए कम्यूनिस्टोंको एक संघटनमें लानेवाली १९२५ में वनी मजदूर और किसान पार्टी थी। परन्तु इस संघटनमें मन्यमवर्गीय बुद्धिजीवियोंके प्रतिनिधि भी घुस आये थे और वायें वाज्के समाज-सुधारक भी इसमें शामिल हो गये। समाज-सुधारक राष्ट्रीय पूँजीवादके दलालोंकी हैसियतसे मजदूर-वर्गके संघटनों में युस आये थे और प्रजातान्त्रिक तथा समाजवादी नारे लगाकर वे मजदूरवर्गको राष्ट्रीय पूँजीवादके प्रभावमें लाना चाहते थे। कम्यूनिस्टों द्वारा संघटित मजदूर यूनियनों में और कम्यूनिस्ट नेताओंकी नीतिमें इन दक्षिणपंथी-समाजवादी समाज-सुधारकोंका प्रभाव साफ दिखन

१. वहीं पुस्तक, (इण्डिया इन १९२५-२६ ?) पृष्ठ ३२

लाई पड़ता है। 'मजदूर और किसान पार्टा' (वर्क्स एण्ड पेजेण्ट्स पार्टा) में शामिल होनेवाले विभिन्न दलोंमें आपसी गुरवाजीके झगड़े होने लगे। १९२८ में भगोड़े रायको (एम.एन.
रायको) जो पार्टीमें गुरवाजी करा रहे थे, निकाल देनेसे परिस्थित सम्हल गयी। परन्तु
समाज-सुधारकोंका प्रभाव अभी वाकी था, जैसा कि आगे चलकर प्रत्यक्ष हुआ। १९२९ में
भारतीय मजदूर आन्दोलनमें फूट पड़ गयी और १९३१ तक देशमें भारतीय मजदूर आन्दोलनोंके तीन केन्द्र स्थापित हो गये—दि ऑल इण्डिया फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन,
जिसका नेतृत्व दक्षिणपन्थी सुधारक कर रहे थे, वामपक्षी नेतृत्वमें 'अखिल भारतीय ट्रेड
यूनियन कांग्रेस' और 'रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस' जिसमें सर्वहारा वर्गके कितकारी संघटन
एक हो गये थे। १९३३ के अन्तमें अभीतक विखरे हुए कम्यूनिस्ट दलोंका संघटनात्मक
एका हो गया और सब एक संघटनमें आ गये। '''

समाजवादी पार्टी

१९३०-२४ के सविनय अवजा आन्दोलनोंमें कांग्रेसके अन्दर गान्धीजीके अंग्रेजोंके खिलाफ लडनेवाले तरीकोंसे एक हिस्सेमें असन्तोप पैदा हो गया था। इन लोगोंका विस्वास था कि रचनारमक कार्योंके बजाय अंग्रेजी साम्राज्यवाद और भारतीय शोपण करनेवालोंके विरुद्ध संवर्ष करनेके लिए मजद्रों और किसानींके संघटन करनेपर अधिक जोर देना चाहिये। विहारमें मई १९३१ में इस विचारको ठोस रूप दिया गया और समाजवादी पार्टाकी स्थापना की गयी। समाजवादी पार्टी कांग्रे सके अन्दर ही बनी थी, और प्रोफेसर अन्दुलवारी उसके अध्यक्ष, राहुल सांकृत्यायन, फूलन० बी० वर्मा और गंगाशरण सिंह मन्त्री चुने गये। अभी पार्टीका कार्य गुरू ही हुआ था कि १९३२ में फिर सविनय अवजा आन्दोलन आरम्भ-हो गया। नासिक जेलमें जहाँ कांग्रेसके महामन्त्री ज्यप्रकाशनारायण, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, नरायन स्वामी, एन० जी० जे० गोरे और एस० एम० जोशी-बन्दें थे, एक मजबत और बड़ी समाजवादी पार्टी कायम करनेकी योजना बनायी गयी। उन्होंने कांग्रेसके अन्दर समाजवादी पाटीं कायम करनेका निश्चय किया। समाजवादी पाठांके विधानका मसविदा तैयार कर लिया गया और गुप्त रूपसे जेलसे वाहर भेज दिया गया । नेताओं के जेलसे छ्टनेके पूर्व ही १९३३ में वम्बई प्रेसीइंसी कांग्रेस समाजवादी पार्टी स्थापित हो गयी थी । इसकी स्थापना करनेमें पुरुषोत्तमदास त्रिकसदास, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, मीनू मसानी और यूसुफ मेहरअली मुख्य थे। पार्टीका संघटन करनेवालींके. सामने ये बुनियादी उद्देश थे-

(१) अगर मजदूरों और किसानोंको कांग्रेसके त्वाधीनता संग्रामकी तरफ आकृषित करना है तो उनके सामने समाजवादका चित्र सींचना पड़ेगा ताकि उन्हें माल्म हो सके कि स्वाधीन भारत किस प्रकार उनकी आर्थिक उन्नतिके लिए काम करेगा। (२) स्वतन्त्रता-संग्रामको वैधानिक स्तरपर जानेसे रोकना—यह संकेत स्वराज्य पार्टी मनोवृत्तिवालीकी और था।

मई १९२४ में पटनामें अखिल भारतीय कांग्रेस महासामितिकी बैठक हीनेवाली थी । समाजवादियोंने सोचा कि यह अवसर और स्थान जोर शोरसे पार्टीकी स्थापना करनेके

कॉलोनियल पीपुल्स स्ट्रग्ल फार लिबरेशन, पृष्ठ २२ (पीपुल्स पव्लिशिंग हाउस वम्बई)

लिए अत्युक्तम होगा । कांग्रेस महासमितिकी वैठकके एक दिन पहलेके लिए (१७ मई १९३४) एक वैठक समाजवादियोंने निश्चित की और इसका निमन्त्रण अखवारोंके जिए उन सब लोगोंको दिया गया जो समाजवादी विचारधारामें विश्वास रखते थे। पटना-समाजवादी सम्मेलनमें एक सौसे अधिक प्रतिनिधियोंने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता आचार्यनरेन्द्रदेवने की। स्वागत-समितिके अध्यक्ष अब्दुल्बारीने अपने भाषणमें भारतीय राजनीतिमें एक नया दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कहा कि "भारतकी जनता केवल राजनीतिक स्वतन्त्रतासे सन्तुष्ट नहीं हो सकती; जरूरत है राजनीतिक स्वतन्त्रताके साथ समाजकी आर्थिक नींवका पुनिनर्माण करनेकी—जिस पुनिनर्माणमें आदमी द्वारा आदमीका शोषण समात हो जायगा और जिसमें भौतिक, संसारिक उन्नतिके सब साधनोंका उपयोग सब लोग वरावरीसे कर सकेंगे।"

समाजवादियों के समने सबसे पहला काम कांग्रेसके विधानसभा-कार्यक्रमका विरोध करना था। इस विरोधका आरम्भ आचार्य नरेन्द्रदेवने अपने अध्यक्षपदके माषणसे किया। उन्होंने कहा कि "अवतक यह नीति रही है कि क्रान्तिकारी परिस्थितिमें सीधी राजनीतिक काररवाई की जाती है, परन्तु ज़व उसके बाद प्रतिक्रियाका काल आता है तो कांग्रेसजन अपने-अपने स्वभावानुसार या तो रचनात्मक काममें लग जाते हैं या विधायक कार्यक्रम अपना लेते हैं। यह अद्ला-वदली हमें पसन्द नहीं है।" सम्मेलनने आचार्य नरेन्द्रदेव, जयप्रकाशनारायण, सी. सो. वनजीं और फरीदुल हक असारीकी एक समिति पार्टीका विधान और कार्यक्रम बनानेके लिए नियुक्त कर दी। जयप्रकाशनारायण इस समितिके मन्त्री नियुक्त कर दिये गये।

फिर कांग्रेस अधिवेशनके अवसरपर ही समाजवादी पार्टीका पहला यथाविधि सम्मेलन अक्टूबरमें बम्बईमें हुआ। इसी वीच वीस प्रान्तोंमेंसे चौदहमें (कांग्रेस द्वारा निर्देशित माधाबार प्रान्तोंमें) पार्टीकी शाखाएँ स्थापित हो गयीं। वम्बईके सम्मेलनमें डेढ़ सौसे ऊपर प्रतिनिधियोंने भाग लिया और सम्पूर्णानन्दने इस सम्मेलनकी अध्यक्षता की। प्रतिनिधियोंमें उल्लेखनीय डा० राममनोहर लोहिया, जयप्रकाशनारायण, मोहनलाल गौतम, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, देशपाण्डे, श्रीमती कमला चट्टोपाध्याय और पुरुषोत्तमदास विकमदास थे।

पुरानी परम्परा तोड़कर सम्पूर्णानन्दने अध्यक्ष-पदसे कोई भाषण नहीं किया और सीधे सम्मेलनकी काररवाई आरम्भ कर दी। निम्निलिखित कार्यक्रम स्वीकृत हुआ। (१) मजदूरों और किसानोंको स्वतन्त्रता और समाजवादकी प्राप्तिके लिए शिक्तशाली जन-आन्दोलन चलानेके निमित्त संघटित करना। (२) सब साम्राज्यवादी युद्धोंका जोरदार विरोध करना। (३) वैधानिक प्रश्नोंपर अंग्रेजी सरकारसे कोई समझौता-वार्ता न करना (४) सत्ता हथियानेके वाद मारतका विधान बनानेके लिए संविधान सभा बुलाना। सम्मेलनने विधानके लिए कुछ मूल सिद्धान्त भी निश्चित कर दिये। ये थे (१) धनके वास्तिविक पैदा करने वालोंके हाथमें सत्ता रहे। (२) सरकार देशकी आर्थिक उन्नितकी योजनाएँ बनाये और उनका नियन्त्रण करे। (३) देशके मुख्य और प्रधान उद्योगों (लोहा, कपड़ा, जूट, रेलवे, खानें और जहाजी उद्योगों) वैंक, वीमा कम्पनियों, और जनहित सेवाओंका समाजीकरण कर दिया जाये। (४) वैदेशिक न्यापारके ऊपर सरकारका एकाधिकार रहे। (५)

लोगोंके आर्थिक जीवनके ऐसे क्षेत्रोंपर जिनका समाजीकरण न हुआ हो, सहकारी-संघोंका नियन्त्रण रहे। (६) विना मुआविजा दिये राजे महाराजे, जमींदारी प्रथा और दूसरे शोपण करनेवाले खत्म कर दिये जायँ, (७) किसानोंमें भूमिका फिरसे वितरण हो। (८) सहकारी व संयुक्त (कोआपरेटिव ऐण्ड कलेनिटव) कृषि समितियोंको प्रोत्साहन दिया जाय। (९) मजदूरों और किसानोंके सब कर्जे माफ कर दिये जायँ। (१०) प्रत्येकको नौकरीकी गारण्टी रहे। (११) 'प्रत्येकसे यथाशक्ति और प्रत्येककी आवश्यकतानुसार'का सिद्धान्त लाग् किया जाय। (१२) धर्म, जाति अथवा वर्गपर आधारित विशेषताको कोई मान्यता न दी जाय। (१४) लिंगके आधारपर कोई मेदभाव न किया जाय। (१५) मारतका सार्वजनिक ऋण अस्वीकार कर दिया जाय।

चूँकि कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी विलक विशेष राजनीतिक सिद्धान्तोंको माननेवालोंका एक मोचां थी इसलिए उसने फौरन ही उस कार्यक्रमके छठवें स्त्रसे अपनेको अलग कर लिया। १३ जून १९३४ को कार्यसमितिकी वर्धाकी वैठकमें निश्चय किया गया कि "कांग्रेस न तो सम्पत्ति जब्त करना चाहती है और न वर्गयुद्धका समर्थन करती है।" ये दोनों ही कार्यक्रम कांग्रेसकी अहिंसा नीतिक विपरीत हैं। फिर भी कार्यसमितिने इतना कहा कि "कांग्रेस व्यक्तिगत सम्पत्तिका उचित और अधिक बुद्धिमत्तासे उपयोग करनेका विचार रखती है तथा कांग्रेस, पूँजी और मजदूरोंके बीच ज्यादा अच्छे रिश्ते स्थापित करनेका भी विचार रखती है।

अव सोशलिस्टोंके सामने पहला काम कांग्रेस द्वारा भारत सरकारका १९१९ के ऐक्टके अन्तर्गत कार्यभार सम्हालनेका विरोध संघटित करना था। कार्यभार सम्हालनेके पक्षमें दक्षिण
पंथी अपनी शक्ति लगा रहे थे। सोशिलस्टोंने घोपणा की कि वीस सालके अनवरत आन्दोलनके
फलस्वरूप और साल-सालतक सरकारी गर्भमें रहनेके बाद भी यह ऐक्ट मांटफोर्ड-सुधारोंके
मुकावलेंमें अधिक उन्नतिशील नहीं है। इस ऐक्टके संघात्मक भागमें संघात्मक विधानसभामें राज्योंकी जनताके निर्वाचित प्रतिनिधियोंके स्थानपर भारतीय रियासतोंके राजाओंको
प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्य परिषद्में उनको (राजाओंको) कुल सीटोंका २/५ मिला
है और लोक-सभामें १/३ जब कि भारतीय रियासतोंकी आवादी भारतकी जन-संख्याकी
चौथाईसे भी कम है। फिर यह आवश्यक नहीं कि संबका विधान रियासतोंमें भी लागू हो।
रियासतोंका आन्तरिक शासन हमेशाकी भाँति प्रतिक्रियावादी ही रहेगा। संबक्ते मिन्त्रयोंके
अधीन शासनका एक सीमित क्षेत्र रहेगा, जब कि वास्तविक सत्ता वाँइसरायके हाथमें रहेगी
और वह विधान-सभाके फैसलोंको रह कर सकेगा।

संविधानके प्रान्तों संबंधी भागोंमें, यद्यपि वे प्रतिकियावादी केन्द्रकी अधीनतामें रहेंगे, वहाँकी विधान-सभाओंमें राजाओंके समान तत्व नहीं होंगे। विधान-सभा पूरे तौरपर निर्वाचित संस्था होगी यद्यपि मतदाता कुल जन-संख्याके केवल ११% होंगे। परन्तु कुल प्रान्तोंमें स्थापित राज्य परिषदें तो बहुत ही सीमित मताधिकारके आधारपर बनी थीं। प्रत्यव रूपमें लोक-प्रिय प्रतीत होने और पूरी तौरपर निर्वाचित होनेके बावजूद इन विधान-सभाओंको उत्तरदायी और अपने निर्णयोंको लागू करवानेमें समर्थ नहीं माना जा सकता था। प्रान्तोंके गवर्नर

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (हिन्दी) क्लेक्शन ऑफ सम स्पीचेन ऑफ जयप्रकाश-नारायण पृष्ठ १६-१७

सर्व-शक्तिमान थे और विधान सभाओंको प्रान्तीय धन-कोषका एक सीमित भाग ही खर्च करनेका अधिकार था। गवर्नर विधान-सभासे उच्च अधिकार रखता था। वह विधान-सभाओंके निर्णयोंको रद्द कर सकता था और स्वतन्त्र रूपसे कानून वना सकता था। इस ऐक्ट द्वारा उसे विशेषाधिकार मिले थे, जिनका इस्तेमाल वह मन्त्रि-मण्डलसे विना सलाह लिए ही कर सकता था। अगर गवर्नर "प्रान्तकी शान्ति अथवा व्यवस्था खतरेमें" समझता तो वह किसी भी दिशामें पूर्ण अधिकार अपने हाथमें ले सकता था।

इसलिए जवाहरलाल नेहरू, वहुतसे कांग्रेसजन और समाजवादी १९३५ के ऐक्टके लाग किये जानेके विरुद्ध थे।

अध्याय २५

कांग्रेस द्वारा पदग्रहण

कांग्रेसका ४९ वाँ अधिवेशन लखनऊमें अध्यक्षके पिताके नामपर वसायी गयी एक नयी वस्ती—मोतीनगर्में जवाहरलाल नेहरूकी अध्यक्षतामें हुआ। प्रान्तीय सरकारने जिला अधिकारियोंको आदेश दे रखा या कि 'लखनऊ अधिवेशनके रास्तेमें कोई अनावश्यक वाधाएँ न डाली जावँ।' अधिवेशनको शानदार सफलता मिली; ग्रामीण उद्योग-प्रदर्शनीने भी उसकी श्रीवृद्धि की।

हालाँ कि जवाहरलालका लिखित भाषण अंग्रेजीमें छपकर वॅट चुका था, वे दो घण्टेतक हिन्दीमें वोले । उनका भाषण कांग्रेस और भारतीय राजनीतिसे बढ़कर दुनियामें काम
करनेवाली आर्थिक और राजनीतिक शक्तियोंके विवेचनमें लग गया । उन्होंने कहा—
"दुनियामें दो प्रतिस्पर्धा राजनीतिक और आर्थिक ढाँचे तैयार हैं; ये दोनों व्यवस्थाएँ इस
समय एक दूसरेके प्रति सहनशील हैं, पर उनमें मोलिक विरोध है और वे दुनियापर आधिपत्य
जमानेके लिए लड़ रही हैं । एक व्यवस्था पूँजीवादको है जो अनिवार्य रूपसे उपनिवेशीकरण द्वारा साम्राज्यशाही शक्तियोंको जन्म देता है; ये साम्राज्यवादी शक्तियाँ एक दूसरेको
हड़प लेनेको उतावली रहती हैं … दूसरी व्यवस्था सोवियत यूनियनके नये समाजवादकी
है जो दिनोदिन उन्नति कर रहा है—यद्यपि बहुधा इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है;
यहाँ पूँजीवादकी समस्याएँ नहीं हैं।"

व्रिटिश साम्राज्यवादके सम्बन्धमें उन्होंने कहा—"यह देखकर ताज्ज्य होता है कि जो उनके कब्जेमें है उसपर कब्जा जमाये रखनेके लिए हमारे शासक नोचताकी किन गहरी खाइयोंमें उतर गये हैं और यह देखकर दुःख होता है कि हमारे कुछ देशवासी अंग्रेजोंसे ज्यादा अंग्रेजी साम्राज्यवादमें दिलचस्पी रखते हुए इस धृणित काममें अंग्रेजोंसे वाजी मार ले जानेकी कोशिशमें लगे हैं; शायद यह अनिवार्य होता हो । इन लोगोंने अपना मान-सिक सन्तुलन खो दिया है; कांग्रेस और राष्ट्रीय आन्दोलनका डर इनपर इस तरह छा गया है कि अपनी इच्छाको वे अपना विचार समझ बैठते हैं, विचारको निष्कर्प मान लेते हैं, निष्कर्पको तथ्य कहने लगते हैं और ये तथ्य गम्भीरतापूर्वक सरकारी विश्वतियोंमें प्रकाशित किये जाते हैं; जिटिश सरकारकी भारतमें गरिमा और प्रतिष्ठा इन्होंपर अधारित हैं; और जनता जेलें व नजरवन्दी हैं-पोंमें विना अभियोग या मुकदमेके हैंस दो जाती हैं।"

समाजवादी नेहरूने आगे कहा—"मुझे विस्वास है कि दुनिया और भारतकी समस्याओंका समाधान समाजवादमें हैं " में चाहता हूँ कि कांग्रेस एक से।शिलस्ट संघटन वनकर दुनियाकी उन शक्तियोंका हाथ बटाये, जो नवी सम्यता कायम करनेमें लगी हुई हैं। लेकिन में समझता हूँ कि आज कांग्रेसमें बहुमत सम्भवतः इतने आगे जानेकी तत्पर न होगा " यद्यपि में ग्रामीण उद्योग कार्यक्रममें भाग लेता हूँ, मेरा वीदिक दृष्टिकीण कांग्रेसके उन बहुतसे लोगोंसे भिन्न है जो औद्योगिकीकरण और समाजवादके विरोधी हैं।"

कांग्रेस मंचसे पहली वार संविधान परिषदकी माँग की गयी । नेहरूने कहा—"में समझता हूँ, नये प्रान्तीय विधान-मण्डलोंके चुनाव हमें लड़ने ही पड़ेंगे। हमें ठोस राजनीतिक और आर्थिक कार्य-क्रमके आधारपर चुनाव लड़ना चाहिये जिसमें संविधान परिपदकी माँग सबसे प्रमुख रहे। विधान निर्मात्री परिपद ही हमारा विधान ठीक और जनतान्त्रिक ढंगपर वनानेका उपाय है और परिपदके प्रतिनिधि ही ब्रिटिश सरकारसे संधिकी वात चलावें।"

वे १९३५ के विधानके अन्तर्गत मन्त्रिमण्डल बनानेके विरुद्ध थे। "यदि हम इस विधान व कान्तके विरुद्ध हैं और उन्हें अस्वीकार करते हैं, तो क्या इसीसे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि इन्हें लागू करनेमें हमारा हाथ नहीं होना चाहिये; इनके लागू होनेका हमें भरसक विरोध करना चाहिये? इस कान्तके अन्तर्गत मन्त्रिमण्डल बनाना, उसे अस्वीकार करनेका विरोध करना है और स्वयं ही अपनी निन्दा करना है।"

नागरिक स्वतन्त्रताके दमनके सम्बन्धमें अधिवेशनके मुख्य प्रस्तावसे उस समयकी स्थितिका पता लगता है। प्रस्तावमें कहा गया था—"राष्ट्रीय, मजदूर व किसान आन्दोलनों-को कुचलनेके लिए ब्रिटिश सरकारने भारतमें जिस व्यापक और तीव रूपसे नागरिक और बहुधा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका दमन किया है, उसकी ओर कांग्रेस ध्यान आकृष्ट करती है— विशेषकर सैकड़ों कांग्रेस, राष्ट्रीय, मजदूर व किसान और अन्य राजनीतिक संघटनोंको गैर-कानूनी कर देनेकी ओर; सरकारने बहुतसे आश्रमों और शिक्षा-संस्थओंको अपने कन्जेमें ले लिया है और उन्हें छोड़ नहीं रही; आर्डिनेंस राज जारी है "हालाँकि विधान समाने दो वार आर्डिनेंस व ऐसे ही दूसरे कान्नोंको अस्वीकार कर दिया है; कितावें और पत्रिकाएँ जन्त हो रही हैं: इधर कुछ वपोंमें कड़े प्रेस कानूनों व संसरके कारण ३४८ अखवार वन्द कर दिये गये हैं और अखवारों से माँगी गयी बड़ी बड़ी जमानतें जन्त कर ली गयी हैं, अभियोग व मुकदमा चलाये विना ही वड़ी संख्यामें लोग पकड़कर नजरवन्द कर दिये गये हैं; सीमाप्रान्तकी जनताको अन्य प्रकारकी असंख्य असुविधाओं व परेशानियोंका सामना करना पड़ रहा है, वंगालके कई हिस्सोंमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रतातक छिन गयी है; देशमें असंख्य लोगोंके आवागमन, प्रवेश, प्रस्थान आदिपर रोक लगाकर उन्हें अपना सामान्य काम करनेसे रोक दिया गया है; वहुधा साधारण मानवीय व सहायता कार्योंपर भी रोक लग जाती है; राजनीतिक कार्यकर्त्ताओंपर 'जरायमपेशा' या 'विदेशी' कानून लागू कर दिये जाते हैं; मकानोंकी व्यापक रूपसे तलाशियाँ ली जाती हैं: भारतीयोंके विदेश जानेमें वांधा डालीं जाती है। बहुतसे भारतीयोंको विदेशोंसे भारत नहीं लौटने दिया जाता और इस प्रकार उन्हें अपनी मातृभूमिसे निर्वासित रखा जाता है। १८५७ के महान् विद्रोहके बाद कभी भी इस प्रकार भारतीय जनताका दमन नहीं हुआ और कभी भी नागरिक व व्यक्तिगत आजादी ऐसे नहीं छीनी गयी जैसे कि आजकल; ब्रिटिश राजका आजकल यही साधारण रूप है

"कांग्रेसको इसका भी खेद है कि देशी रियासतों में। इसी प्रकारके दमन और स्वतन्त्रता अपहरणका चक्र चल रहा है; कई रियासतों में तो शेष भारतसे भी गयी वीती हालत है और किसी भी तरहकी आजादीका नामोनिशान नहीं है; कुछ रियासतों में कांग्रेस ग़ैरकानूनी करार दी गयी है।

"कांग्रेस भारतीय जनताका यह संकल्प प्रकट करती है कि राष्ट्रीय विकास और

क्रियाकलापको कुण्डित करनेके प्रयत्नोंके वावजूद वह साहस और धेर्यके साथ हिथितिका सामना करती रहेगी और स्वतन्त्रता प्राप्त होनेतक आजादीको लड़ाई लड़ती रहेगी।" लम्मे निर्वासनके बाद सुभापचन्द्र वसु भारत वापस लौट रहे थे, पर वे रास्तेम ही पकड़ लिये गये | खान अञ्चल गम्हार लाँ हेचारों अन्य लोगोंके साथ अत्र भी जेलमें बन्द थे। ध्याष्ट्रीय आकांक्षाओंकी किसी प्रकार भी पूर्ति ने करनेवाले और भारतीय जनताके दमन और शोपणको स्थायी व सुविधाजनक वनानेवाले १९३५ के भारत कान्न (गवर्नमण्ड आव हिडिया ऐस्ट) को कांत्रे सने अस्त्रीकार कर दिया। पर इस विधानको तोड़ देनेके लिए उसने पान्तीय विधान मण्डलोंके लिए चुनाव लड़नेका वैसला किया।

कांग्रेसने यह भी फैसला किया कि "जनता और कांग्रेस संघटनके यीच अधिक निकट-का सम्बन्ध रेथापित किया जाय ताकि वह कांग्रे सकी नीति निर्धारित करनेमें अधिक सिन्ध्र भाग हे सके।"

आसभ चुनावके कारण कांग्रेसका अगला अधिवेशन ८॥ महीने वाद ही दिसम्बर १९३६ में केनपुरमें कर लिया गया। सभी राजनीतिक दल चुनावमें ट्यस्त थे। सान अन्द्रल

गवकार खाँ छूट मंत्रे थे और केजपुरमें मीजूद थे | जवाहरलाल नेहरू किर अध्यक्ष सुने गये। नेहरूने साफ साफ यह घोषणा की— "ब्रिटिश साम्राज्यशाहीके शासन-यन्त्रसे सहयोग करनेके लिए हम विधान मण्डलों में नहीं जा रहे, बिहक उस अधिनियमका विरोध करने और उस तन्त्रका अन्त इर देनेके लिए जा रहे हैं। हम विधान मण्डलों में वैधानिकताका मार्ग पकड़ने या थोथे राजनीतिक सुधारांका अनुसरण करने नहीं जा रहे। अन्होंने विधान निर्मात्री परिपदकी माँग दोहरायी (जिसे कांग्रेस पहले ही जान्तेसे स्वीकार कर सुकी था) जीर कहा कि इसके बाद ⁽⁽⁾हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम (भारत) कान्तार कर उत्तर प्राचीय दाँचा तोड़ना होगा। पूरा कानून पूरी तरह तो रही है ही, पर उसमें संघसे बदतर कुछ भी नहीं है।"

चुनाव आन्दोलन जोरपर था और, जैसा कि नेहरूने कहा, कांग्रेसके विरुद्ध नीवर-शाहीका हरतक्षेप सिक्तय था धार्म पा जार, जाता कि भएड़ मतदाताओं के मतदानको गुन न राहाका ६त्तावन पामान ना देवका नापार पा का नक नव नापानाक नवस्वका था न रखनेकी कोशिशें जान-बुझकर हो रही थीं। संयुक्त मान्त हम कामके लिए लास वीरायर छाँडा मया है और दूसरे प्रान्तों में प्रयुक्त रंगीन वन्ते यहाँ इस्तेमाल नहीं ही रहे हैं।"

पेजपुर अधिवैश्वनमें तय हुआ था कि नया विधान लाग् होनेके दिन याने १ अप्रेल १९३७ को देशन्यापी हड़ताल की नाय। अधिवेशन खत्म होने पर मेहरू य उनको वार्थ-सिमितिने विभिन्न मान्तोंका दीरा शुरू किया । नेहल्ली १२-१२ और १४-१४ घण्डे संपर्द करते और सभाओं में भाषण करते । वे साधारणतः एक दिनमें आयी दर्वन बड़ी समाओं और एक दर्जन छोटी, सहक्रके किनारे हुई, समाओं में बोहते। हर हमते वे औसतन हेंद्र हजार मील चलते । अनुमान है कि अपने दीरेमें उन्होंने क्रमते क्रम एक करोड़ व्यक्तियाँ-को सम्त्रोधित किया । पूरा देश कांत्रे सके प्रचारसे भर गया ।

कांग्रेसके खिलाफ भड़कीले जनिय नाम लेल्ट्रेक्ट कुछ मीसभी पाटियाँ जुनाव हड़ रही थीं, जैसे कि प्रजापार्टी, बिह्रस (न्याय) पार्टी, केल्ह्रीरिसेवर (आतम-सम्भाव) पार्टी, राष्ट्रीय खेतिहर पार्टी, पीपुलर (जनियय) पार्टी, डेमेकिटिक (जनतिस्वक) पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टा आदि ।

लगभग हर प्रान्तमें कुछ न कुछ सिक्रय कांग्रेसी उम्मीदवार चुनाव लड़नेसे वंचित रह गये क्योंकि सत्याग्रह आन्दोलनमें वे जेल गये थे और कान्नन यह एक अयोग्यता थी। वम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रान्त, विहार, मध्यप्रान्त व उड़ीसामें कांग्रेसका इतना बहुमत चुना गया कि अन्य सब पार्टियोंके कुल सदस्योंकी संख्या भी उससे कम थी। वंगाल, आसाम व सीमा प्रान्तमें कांग्रेस सबसे बड़े दलके रूपमें विधान-मण्डलोंमें पहुँची। मुसलिम बहुमतके सिन्ध व पंजावके स्वोंमें कांग्रेस अल्पमतमें रही।

अव कांग्रेसके सामने सवाल यह था कि नहाँ उसका वहुमत है, वहाँ वह अपने मंत्रिमण्डल वनाये या न वनाये । यह सवाल पहले भी पेश हो चुका था, दक्षिणपंथी मन्त्रिमण्डल
वनानेके पक्षमें थे, सोशलिस्ट आदि वामपक्षी विरुद्ध और दोनोंके वीच वड़ी खाई थी। १७
व १८ मार्चको दिल्लीमें हुई कांग्रेस महासमितिकी वैठकमें गान्धीजीने समझौतेका रास्ता
निकाला और कुछ शतोंपर मन्त्रि मण्डल वनानेका फैसला हुआ। समझौतेके अनुसार मन्त्रिमण्डल तवतक नहीं वनने थे जवतक कि "कांग्रेस दलके नेता खुलेआस यह न कह सकें कि
मन्त्रि-मण्डलकी वैधानिक काररवाईके सम्बन्धमें गवर्नर हस्तक्षेपका अपना अधिकार इस्तेमाल
नहीं करेंगे।" इस समझौतेपर भी लोग एकमत नहीं थे और मत लेने पर मन्त्रि-मण्डल
वनानेका प्रस्ताव १२७ वोटोंसे (७० विरोधमें) स्वीकार हुआ।

महासमितिकी वैठकके वाद विधान-मण्डलोंके कांग्रेसी सदस्योंका सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस अध्यक्षने उन्हें शपथ दिलायी कि वे कांग्रेस अनुशासनमें काम करेंगे।

जिस प्रकारका आस्वासन दिल्ली-प्रस्तावमें माँगा गया था, "सहायता, सहानुभृति व सहयोग" की वातों के वावजूद गवर्नर वह आक्वासन देनेमें आनाकानी कर रहे थे। विलक्ष, वे अल्प-संख्यक दलोंके अन्तरिम मन्त्रि-मण्डल वनाने लगे । लेकिन यह स्थिति मली नहीं थी । विधान-मण्डलोंकी वैठकों. इस डरसे नहीं बुलायी गयीं कि कांग्रेसी वहमत मिनत-मण्डलोंके खिलाफ अविश्वासका प्रस्ताव पास कर देंगे। अन्ततः, वाइसरायने २७ जून १९३७ को 'भारतके नाम सन्देश' दिया जिसमें उन्होंने कहा कि विधान चलानेके लिए कांग्रेस द्वारा गवर्नरोंसे माँगे गये आश्वासन आवश्यक नहीं हैं। लेकिन उन्होंने खुद यह विश्वास दिलाया कि 'गवर्नर न सिर्फ मन्त्रि-मण्डलोंसे स्वयं झगड़े मोल न लेंगे, वित्क झगड़ा होनेपर उन्हें निपटानेमें वे कोई कसर न छोड़ेंगे--मिन्त्र-मण्डल चाहे जिस दलके हों।" कांग्रेस कार्य-समितिकी वैठक जुलाईमें वर्धामें हुई और वाइसरायके सन्देशपर विचारके वाद कहा गया कि यद्यपि यह दिल्ली माँगकी पूर्ति नहीं करता, फिर भी कांग्रेसकी माँग पूरी करनेकी इच्छा प्रकट करता ही है। कार्यसमितिने विभिन्न प्रान्तों में कांग्रेसको आमन्त्रण मिलनेपर मन्त्रि-मण्डल वनानेकी छूट दे दी । शीव ही छः प्रान्तोंमें कांग्रेस मन्त्रि-मण्डल वन गये। थोडे दिनों वाद ही सोमायान्तमें भी कांग्रेस मन्त्रि-मण्डल वन गया। वहाँ ५० में कुल १९ कांग्रे सी सदस्य चुने गये थे, पर, आठ दूसरे सदस्योंके कांग्रे समें शामिल हो जानेसे मन्त्रि-मण्डल वनना आसान हो गया। कांग्रेस मन्त्रि-मण्डल वननेके फौरन बाद कांग्रेसी प्रान्तोंकी विधान-सभाओंने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया-

"इस विधान-सभाकी रायमें १९३५ का 'भारत सरकार' कान्त राष्ट्रीय भावनाओंका विलक्षल प्रतिनिधित्व नहीं करता और भारतीय जनताकी दासता कायम रखनेके लिए ही बने होने के फलस्वरूप पूर्ण रूपेण असन्तोधजनक है। यह विधान-सभा माँग करती है कि यह कानून. रद कर दिया जाय और इसकी जगह वयस्क मताधिकारके आधारपर वनी विधान निर्मात्री परिपद् द्वारा बना वह विधान प्रतिष्ठापित हो, जिसमें भारतीय जनताको अपनी इच्छा और आवश्यकताके अनुरूप विकास करनेका पूरा अवसर मिले।"

कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डलोंने अपने कार्यकालमें सबसे पहला काम यह किया कि नहीं तक सम्भव था नागरिक स्वतन्त्रता पुनः स्थापित की गयी। वड़ी संख्यामें राजनीतिक यन्दी मुक्त किये गये, कहीं-कहीं गवर्नरोंके दकावट डालनेवाले रवैयेपर इस्तीफेकी धमकीसे काबू पाया गया। संयुक्त प्रान्तमें काकोरीकाण्ड और मद्रासमें मोपला-विद्रोहके बन्दी रिहा कर दिये गये। विहारमें केवल वे ही बन्दी बचे जो अण्डमानसे वापस आये थे। राजनीतिक कार्यकर्त्ताओंपर लगे प्रतिवन्ध हटा लिये गये। अखवारोंसे ली गयी जमानते वापस कर दी गयीं। "सन्देह-जनक" अखवारों व व्यक्तियोंकी खुफिया फिहरिस्तें खत्म कर दी गयीं। राजनीतिक संघटनों और पुस्तकोंपर लगी पावन्दियाँ हट गयीं। राजनीतिक फिरमोंके प्रदर्शनकी अनुमित मिल गयी।

किन्तु केन्द्रीय सरकार व गैरकांत्रें सी प्रान्तांव सरकारों और देशी महाराजाओं के शासन-क्षेत्रों में कोई विशेष अन्तर नहीं आया था। फजलुलहककी प्रजापार्टीके शासनमें वंगालमें—विशेषकर चटगाँव व मिदनापुर जैसी जगहों के शासनमें कोई अन्तर नहीं आया था। करवयू, नवसुवकोंवर परिचयपत्र रखनेकी वाय्यता (अकेले चटगाँवमें २५००० नव-सुवकोंको ये पत्र रखने पड़ते थे), मध्यमवर्गाय नवसुवकोंके साइकिल चढ़नेपर रोक, मिदनापुरके बहुतसे प्रमुख नागरिकोंके जिलेमें शुसनेपर रोक, मिदनापुर जिलेमें कांग्रेस व अन्य राष्ट्रीय संघटनोंके गैरकान्त्री होनेकी धोषणा और बहुतसे लोगोंकी नजरवन्दी अब भी वदस्त्र जारी थी। केन्द्रीय एसेम्बलीमें सरकार द्वारा दिये गये एक उत्तरके अनुसार अकेले चटगाँव जिलेमें २९००० नवसुवकों व नवसुवित्योंपर एक न एक प्रकारकी रोक लगी हुई थी; २०८ संबटन व संखाएँ गैरकान्त्री थीं; १२ अगस्ततक संशोधित जान्ता फीजदारी कान्त्रके अन्तर्गत वंगाल सरकार रे४७० प्रतिवन्धात्मक आदेश जारी कर चुकी थी। गान्धीजीके बीचमें पड़ने व वंगालके प्रधान मन्त्री व गवर्नरसे मिलनेपर १९३७ के अन्तर्ग १५०० नजरवन्द कुछ शतोंपर छोड़े गये। पर तत्र भी ४५० ऐसे वन्दी जेलमें वच्च गये थे जिनकी रिहाईके पहले उनके मामलोंपर विचार होना था।

पंजावकी यूनियनिस्ट पार्टीके मन्त्रिमण्डलके कार्यकालमें राजद्रोहके जितने मुक्दमें चले, उतने कहीं और नहीं चले थे। मुक्दमें, शहर-निकाला, तलाशियाँ, प्रतियन्धारमक आदेश नित्यप्रतिकी यटनाएँ थीं।

रिवासतों में राजनीतिक चेतनाका नृद्यांसतापूर्वक दमन होता था। मेंसूरमें, जहाँ सर-कार जनताकी आर्थिक मलाईके लिए आम तौरपर सचेष्ट रहती थी, कांग्रेसका अण्डा फ़ह-रानेपर रोक थी, इसे महाराजाकी सार्वभीम सत्ताके लिए अपमान-जनक माना जाता था। सभाओं, जुल्लों व सार्वजनिक भाषणोंपर रोक थी। अन्य रिवासतों—विद्येप कर जोधपुर व पटियालाका भी यही हाल था।

अण्डमानके कालेपानीमें सड़ रहे राजनीतिक बन्दिबोंपर भी दृष्टियात कर लिया जाय। २१ जुलाई १९३७ को भारत सरकारने बताया कि वहाँ २२५ राजनीतिक बन्दी २४ जुलाईसे भूख-इड़ताल कर रहे थे। बन्दियोंका जीवन घोर कृष्टमय या और उन्होंने यह कदम एक- दम निराश होकर ही उठाया था। वहाँ पहले भी अनशन हुए थे और तीन कैदी इनमें जानसे हाथ थो चुके थे। इस वार इतनी वड़ी संख्यामें लोग प्राणोंकी वाजी लगा चुके थे। भारतीय नेता परेशान थे, भारत सरकार उदासीन थी। कालेपानीके अनशनकारियोंकी सहानुभूतिमें भारतीय जेलों और नजरवन्दी कैम्पोंमें भी भूख-इड़तालें हुईं। ९ अगस्तको देशभरमें अण्डमान दिवस मनाया गया जिसमें राष्ट्रने कालेपानीकी हालतपर अपना क्रोध प्रकट किया। सरकारने इसे अपनी प्रतिष्ठाका प्रक्त वना लिया और अनशनकारियोंकी भूख इड़ताल खत्म हुए विना उनकी माँगोंपर विचार करनेते इनकार कर दिया। अन्ततः गान्धीजीका इस्तक्षेप कारगर हुआ। भारत सरकारा द्वारा गान्धीजीने अनशनकारियोंसे सम्पर्क स्थापित किया और उन्हें अनशन खत्म करनेपर राजी कर लिया। कालेपानीके कैदियोंने गान्धीजीको जो तार भेजा उसमें उन्होंने लिखा कि इममेंसे जो भी पहले आतंकवादमें विश्वास करते थे, वे भी अय उसमें निष्ठा नहीं रखते और उसकी राजनीतिक नीति या अस्त्रके रूपमें उपादेयतानमें विश्वास खो चुके हैं। उन्होंने घोषणा की कि आतंकवादसे देशहित आगे नहीं बढ़ता, विश्वास खो चुके हैं। उन्होंने घोषणा की कि आतंकवादसे देशहित आगे नहीं बढ़ता, विश्वास खो चुके हैं। इन्होंने घोषणा की कि आतंकवादसे देशहित आगे नहीं बढ़ता, विश्वास खो चुके के आरम्भतक सभी राजनीतिक कैदी अण्डमानसे अपने-अपने प्रान्तोंको वापस मेजे जा चुके थे।

लेकिन १९३७ के अन्तके निकट संयुक्त-प्रान्त व विहारके गवर्नरोंने अपना रख वदल दिया और हिंसाके अभियोगमें दिण्डत राजनीतिक विन्दयोंकी रिहाई रोक दी। संयुक्तप्रान्तके गवर्नरको हर था कि काकोरी-काण्डके विन्दयोंके सार्वजनिक स्वागतसे शान्तिमंगका खतरा है। कांग्रेसी मंत्रियोंने गवर्नरोंको समझानेकी कोशिश की कि अभीतक चलनेवाली नीतिमें वाधा डालना ठीक न होगा। पर गवर्नर अड़े रहे। इसपर कांग्रेसने दोनों प्रान्तोंके मिन्त्रिमण्डलोंको इस्तीफा देनेकी सलाह दी। पर तव गवर्नर झक गये और इस्तीफे वापस ले लिये गये। प्रान्तोंके आय-व्ययपर मिन्त्रमण्डलका नियन्त्रण नहीं था और वे जनताकी आर्थिक दशामें सुधार नहीं कर सके। जैसा कि पहािम सीतारमैयाने लिखा—"जनता आस्वयंसे पूछने लगी कि यह जमींदार किस तरह अब भी कायम हैं, पुल्सिके जल्म क्यों वदस्त्र जारी हैं; किसानोंके कप्ट और दुख अब भी क्यों दूर नहीं हो पाते, हिंसाके अभियोगोंमें दिण्डत लोग अब भी क्यों जेलोंमें सड़ रहे हैं।"

दूसरी ओर कांग्रेसके आम सदस्यों में उत्साह-पतनके लक्षण प्रकट हो रहे थे। पद्याभिके ही शब्दों में — "पता चला कि ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं, जहाँ कांग्रेस कमेटियाँ अफरसरों व सरकारी कमेचारियोंपर असर डालकर प्रशासनमें हस्तक्षेप करती हैं।" कांग्रेस महासमितिने एक प्रस्तावमें कहा—" नागरिक स्वतन्त्रताके नामपर लोग—कुछ कांग्रेसजन भी—कत्ल, आगजनी, लूटपाट और हिंसातमक वर्गयुद्ध का प्रचार करते पाये गये हैं, बहुतसे अखवार झूट और हिंसाका प्रचार कर रहे हैं, हिंसाके लिए उभार रहे हैं और प्रत्यक्ष झूटको चला रहे हैं। इसलिए नागरिक स्वतन्त्रताकी अपनी नीति कायम रखते हुए भी और अपनी परम्पराओंकी प्रतिष्ठा रखते हुए भी कांग्रेस अपनी सरकारोंके उन कामोंका समर्थन करेगी जो वे जान व मालकी रक्षाके लिए करें।" मध्य प्रान्तमें एक मन्त्रीने सरकारकी क्षमाशक्तिका प्रयोग कर एक धनिकको कारागारसे मुक्त करा दिया यद्यपि वह धनिक वलात्कारके अभियोग-

१. 'हिस्टरी आव कांग्रेस' लेखक पट्टामि सीतारमैया, भाग दो एए ९२

२, वही पुस्तक, भाग दो पृष्ठ ९२

में दिण्डत हुआ था। कांग्रेसके उच्चाधिकारियोंने इसको गम्भीर गलती माना और उस मन्त्रीको मिन्त्रिपदसे इस्तीफा देनेको बाध्य किया। मध्यप्रान्तमें ही एक और गम्भीर संकट आया। अपने मिन्त्रिमण्डलके सदस्य वदलनेके लिए वहाँके प्रधान मन्त्री एन. वी. खरेने अन्य मिन्त्रियों या कांग्रेस कार्यसमितिको बताये बिना, गवर्नरको मिन्त्रिमण्डलका इस्तीफा सौंप दिया। इस अनुशासनहीनताके लिए खरेको कांग्रेस दलका नेतृत्व छोड़ना पड़ा।

१९२८ में सुभाषचन्द्र वसुकी अध्यक्षतामें हरिपुरामें कांग्रेस अधिवेशन हुआ। यह अधिवेशन अधिकांशतः जान्तेका अधिवेशन ही था और इसमें रस्मी बातोंपर ही विचार हुआ।

मार्च १९३८ में कांग्रेसका त्रिपुरी अधिवेशन अध्यक्ष सुभापचन्द्र वसुके प्रति अविश्वासके प्रस्तायके एक नये वातावरणमें ग्रुरू हुआ। यद्यपि अविश्वासकी वात खुलकर नहीं आयी, वहाँकी घटनाएँ इसी ओर इंगित कर रही थीं। स्थितिकी विलक्षणताको अध्यक्षके तीत्र उचरके कारण अध्यक्षता न कर सकनेसे योग ही मिला। वसु गान्धीजीके नामजद उम्मीद्वार पष्टामि सीतारमैयाको ९५ वोटोंसे हराकर दूसरी वार कुछ असाधारण-सी परिस्थितिमें अध्यक्ष चुने गये थे। चुनावके निष्पक्ष न होनेके सम्यन्धमें भी कुछ अफवाहें फैल रही थीं। गान्धीजीने कहा—"प्रामिकी हार मेरी हार है।" और उनके इस वक्तव्यके ये अर्थ लगाये जाने लगे कि यह सत्य, अहिंसा और गान्धीजीके नेतृत्वकी हार है। "अध्यक्षके चुनावके पहले और वादके विवादोंने वातावरणको कटु और जनताको भ्रान्त कर दिया था। कांग्रेसजनोंमें मतभेद हो गया था। कांग्रेसकी मजबूती और एकताको छिन्न मिन्न कर देनेका खतरा परस्पर विरोधी दलोंमें परिलक्षित होने लगा।" त्रिपुरी अधिवेशनके ठीक पहले फरवरीमें कांग्रेस कार्यसमितिके १३ सदस्योंके इस्तिफेसे स्थित और भी जिटल हो गयी। कार्यसमितिमें अव अध्यक्ष और उनके भाई शरत्चन्द्र वसुके अलावा और कोई नहीं वचा था। इस काररवाई-का सीधा अर्थ अध्यक्षमें अविश्वास था। नये अधिवेशनके लिए पुरानी कार्यसमिति मस्ताव तैयार करती थी। पर अत्र कार्यसमितिके न रहनेसे गत्यवरोध पैदा हो गया।

बाहरसे त्रिपुरी अधिवेशनकी तड़क-भड़कमें कोई अन्तर नहीं आया था। अध्यक्षका जुल्स ५२ हाथियों द्वारा खीचे जानेवाले रथके साथ निकलनेवाला था, पर उनकी अस्वस्थ-ताके कारण उनके चित्रका जुल्स निकाला गया।

अन्य कारणोंके अलावा, कांग्रेसके जाने-माने नेताओं और सुभापचन्द्र वसुके वीच बड़ा मतभेद यह था कि वसु अंग्रेज सरकारको पूर्ण-स्वराज्यकी राष्ट्रीय माँग माननेके लिए छः महीनेका अव्टिमेटम देनेके पक्षमें थे और इस अवधिकी समाप्ति पर सार्वजिनक सिवनय आज्ञा भंग आन्दोलन ग्रुह्त करना चाहते थे। वसु चाहते थे कि अंग्रेज सरकार द्वारा भारतपर संघ व्यवस्था छादनेके पहले आन्दोलन छेड़ दिया जाय। गान्धीजीके अनुसार अभी आन्दोलनका समय नहीं आया था। वसु और गान्धीजीके अनुयायियोंके बीच गहरी सैद्वान्तिक खाई थी। यह मतभेद १६० प्रतिनिधियोंके हस्ताक्षरोंसे गोविन्दवल्लभ पन्त द्वारा अध्यक्षको दिये गये एक प्रस्तावमें प्रकट हुआ। वह प्रस्ताव कांग्रेस महासमितिकी बैटकमें पेश होनेको था, पर अध्यक्षने इसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन विषय-समितिकी बैटकमें उन्होंने इसे पेश करनेकी अनुमित दे दी। लम्बे विचार-विनिमयके वाद यह प्रस्ताव भारी वहुमतसे विषय समिति और बादमें खुले अधिवेशनमें स्वीकृत हो गया। वीमारीके कारण वसु खुले अधिवेशनमें

नहीं आ सके थे और अनुलक्लम आजादने कार्यसंचालन किया। अध्यक्षंपदके चुनावमें सोशिलस्टोंने पद्यामिके खिलाफ वसुका समर्थन किया था; पर पन्त प्रस्तावपर वे तटस्य रहे। प्रस्ताव इस प्रकार था—"पिछले वपोंमें महात्मा गान्धोंके नेतृत्वमें जिन मूल-भूत सिद्धान्तोंने कांग्रेस कार्यक्रम नियन्त्रित किया है, उनमें यह कांग्रेस अपना पक्का विश्वास प्रकट करती है और उसका श्रुच मत है कि इन नीति-सिद्धान्तोंमें कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं है, इन्हीं सिद्धान्तोंपर कांग्रेसका भविष्यका कार्यक्रम भी आधारित होना चाहिये।" गत वर्षकी कार्यसितिमें विश्वास प्रकट करते हुए प्रस्तावमें कहा गया था—"इस एक वर्षमें जो संकट उत्पन्न हो सकता है, उसे ध्यानमें रखकर और यह जानते हुए कि केवल महात्मा गान्धी ही देश व कांग्रेसको इस संकटमें विजयपथपर ले जा सकते हैं, कांग्रेस यह अनिवार्य मानती है कि उसकी कार्यसितित पूर्णक्षेण गान्धीजीकी विश्वासभाजन हो और इसलिए अध्यक्षसे अनुरोध करती है कि वे गान्धीजीके इच्छानुसार अपनी कार्यसितिका निर्माण करें।"

लेकिन गान्धोजीने कार्यसमितिके सदस्य छाँटनेसे यह कहकर इनकार कर दिया कि यह अध्यक्षपर दवाव डालनेके वरावर होगा। उन्होंने अध्यक्षको अपनी कार्यसमिति चुननेके लिए स्वतन्त्र कर दिया। वसुका कहना था कि वर्तमान परिस्थितिमें एक ही मतके सभी सदस्योंवाली कार्यसमितिसे काम न चलेगा। गान्धीजीके सुझावपर उन्होंने पुरानी कार्यसमितिके सदस्योंकी एक बैठक बुलायी। पटेल इस बैठकमें शामिल नहीं हुए और शेष सदस्योंसे वातचीतसे मसला इल नहीं हुआ। अब अध्यक्षके सामने दो ही रास्ते थे—या तो वे एकमत वाली कार्यसमिति बनायें या इस्तीफा दे दें। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस महासमितिने राजेन्द्रप्रसादको कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लिया।

मईके आरम्भमें सुभावचन्द्र वसुने कांग्रेसमें एक पारवर्ड ब्लाक (अग्रगामी दल) को स्थापना की। दलका कार्यक्रम त्रिस्त्री था—वामपक्षीय सदस्योंका संघटन, कांग्रेसका बहुमत अपने साथ करना और आजादीके लिए राष्ट्रीय आन्दोलनकी ग्रुस्थात करना। जूनमें वामपक्षी संघटन समिति बनी जिसमें पारवर्ड ब्लाकके अतिरिक्त सोशिलस्ट, कम्यूनिस्ट पार्टी (नेशनल फण्ट), रेडिकल डेमोके टिक पार्टी (एम. एन. रायका दल), मजदूर संघटन व किसान-सभाके लोग शामिल थे। सिमिति वसुके नेतृत्वमें काम करनेको थी। पहले अखिल भारतीय पारवर्ड ब्लाक सम्मेलनमें इन सभी दलोंके नेताओंने भाग लिया और पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता व स्वतन्त्र सोशिलस्ट सरकारकी स्थापनाका लक्ष्य स्वीकार किया। त्रिटिश भारत व देशी रियासतोंमें एक साथ साम्राज्यविरोधी देशव्यापी आन्दोलन छेड़नेकी तैयारीकानारा दिया गया।

जूनमें ही कांग्रेस महासमितिकी एक वैठक वम्बईमें हुई और उसमें एक प्रस्ताव द्वारा कांग्रेसजनोंको आदेश दिया गया कि वे प्रान्तीय कमेटियोंकी अनुमित विना किसी भी प्रकारके सत्याग्रहका संघटन न करें और न उसमें भाग छें। वसु व सोशिल्स्टोंने इस प्रस्तावका विरोध किया पर वह भारी वहुमतसे स्वीकृत हो गया। प्रस्ताव पास होनेके वाद भी वसुने इसकी खुलेआम आलोचना को और ९ जुलाईको इस प्रस्तावके विरुद्ध आन्दोलन ग्रुक करनेके लिए देशव्यापी दिवस मनानेकी अपील निकाली। उस दिन कुछ कांग्रेसजनों और वहुतसे गैरकांग्रेसी लोगोंके कहीं सफल और कहीं असफल प्रदर्शन हुए व सभाएँ हुई। वंगाल कांग्रेस कार्यकारिणीने स्वबं प्रदर्शनोंका संघटन किया। वसु वंगाल कांग्रेसके अध्यक्ष

थे। कांग्रेस कार्यसमितिकी अगली वैठक अगस्तमें वर्धामें हुई। उसने वसुको अनुशासन भंग करनेके अभियोगमें बंगाल कांग्रेसके अध्यक्षपदसे मुअत्तल कर दिया और तीन वर्षतक किसी निर्वाचनमें भाग न ले सकनेकी पावन्दी उनपर लगा दी।

रचनात्मक कार्योंके क्षेत्रमें बसुने राष्ट्रीय योजना समितिकी स्थापना जवाहरलाल नेहरूकी अध्यक्षतामें को थी। राष्ट्रीय साधनोंके अध्ययन और उनसे देशको समृद्धिशाली बनानेके उपायोंपर विचार करनेके लिए बनी इस समितिने राष्ट्रीय जीवनके विभिन्न पहलुओं- पर विचार करनेके लिए २७ उपसमितियाँ बनायों। ये उपसमितियाँ कृषि, उद्योग, यातायात, व्यवसाय व विच्त, जनहित, शिक्षा, सामाजिक स्थितिके विवेचन आदि विधर्योपर आँकड़े- और तथ्य-संग्रहमें लगीं।

सितम्बर १९३९ में यूरोपमें द्वितीय विश्व-च्यापी युद्धका सूत्रपात होनेसे भारतीय राजनीतिमें भी आमूल परिवर्तन होने लगे। युद्धकी घोषणाक कुछ घण्टों वाद ही रे सितम्बरको वाइसरायने जन-प्रतिनिधियोंकी राय लिये विना ही भारतके इस युद्धमें शामिल होनेकी घोषणा कर दी। ब्रिटिश पार्लमेण्टमें ११ मिनटके भीतर भारत सरकार कानून संशोधन विल पास कर दिया गया जिसके द्वारा वाइसरायको यह अधिकार मिल गया कि वे विधानको प्रान्तीय स्वराज्यकी धाराओंको भी खत्म कर सकते थे। उसी दिन दिनेंस आब इण्डिया (भारत रक्षा) आर्डिनेंस जारी कर दिया गया जिससे बहुतसे नागरिक अधिकारोंका अपइरण हो गया। वाइसरायने गान्धीजीको दिल्ली बुलाया और युद्ध छिड़नेके ४८ घण्टेके भीतर ही उन दोनोंका ग्रस परामर्श श्रुक हो गया। इस वातचीतकी प्रतिक्रिया वताते हुए गान्धीजीने कहा—'वाइसराय भवनसे में खाली हाथ लौटा हूँ और ग्रस या प्रकट किसी भी प्रकारका कोई समझौता नहीं हुआ है।'' गान्धीजीने एक वक्तव्य जारी कर यह भी कहा कि में वाइसरायसे निजी रूपसे मिला था और यदि कोई समझौता होगा तो वह सरकार और कांग्रेसके वीच होगा। लेकिन उन्होंने वाइसरायसे कहा—'भेरी व्यक्तिगत सहानुभूति मानवीय दृष्टिकोणसे इंगलैण्ड और फांसके साथ है।''

८ सितम्बरको कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठक वर्धामें हुई और उसमें "युद्ध और मारत" के प्रस्ति विचार हुआ । बसु भी इस बैठकमें आमित्रत थे। पाँच दिनतक विचार-विनिमयके बाद, कार्यसमितिने एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमें कहा गया था— "विटेन और फांसकी सरकारोंने घोषणा की है कि वे आक्रमणका अन्त करनेके लिए और जनतन्त्र व स्वतन्त्रताके लिए लड़ रही हैं। १९१४-१८ के युद्धमें भी युद्धके घोषित उद्देश जनतन्त्र, छोटे राष्ट्रोंकी स्वतन्त्रता और आत्म-निर्णयके अधिकार ही थे; किन्तु इन उद्देश्योंकी पवित्र घोषणा करनेवाली सरकारें ही साम्राज्य-विस्तारकी भावनाते उत्तमान (तुर्क) साम्राज्यके हिस्से-वाँटके लिए ग्रुप्त सन्धिमें लीन हुई। यदि यह युद्ध यथास्थित कायम रखनेके लिए—साम्राज्यवादी अधिकार, उपनिवेश, स्थिर स्वार्थ व सुविधाएँ आदि कायम रखनेके लिए—है, तो भारतीयोंको इससे कुछ भी लेना-देना नहीं है। किन्तु यदि जनतन्त्र और जनतन्त्रके आधारपर विश्व-व्यवस्था इस युद्धका उद्देश्य है, तो भारतको इसमें गहरी दिलचस्पी है।"

इसलिए कांग्रेस कार्यसमितिने बिटिश सरकारसे साफ और स्पष्ट शन्दोंमें घोपणा करने-को कहा कि उसके इस युद्धके उद्देश्य क्या हैं, वे उद्देश्य भारतमें किस प्रकार लागृ होंगे और 'अभी वर्तमानमें' किस प्रकार लागू होंगे । सिमितिने इस वातपर बोर दिया कि इन उद्देशोंन को भारतमें अधिकतम व्यापक रूपमें और फौरन लागू किया जाय, क्योंकि सिर्फ इसीसे भारतवासियोंको भरोसा हो सकेगा कि यह घोषणा कार्यान्तित होनेके लिए ही की जा रही है । भारतीय समस्याके पूर्ण व अन्तिम समाधानके लिए कांग्रेस कार्यसमितिने आत्मनिर्णयका अधिकार माँगा, जिसका आश्य हुआ कि भारतीयों द्वारा चुनी गयी विधान निर्मात्री परिपद् ही भारतका संविधान तैयार करे । केवल नरमदलवाले ही युद्धको तैयारीमें सरकारके साथ विना शर्त पूर्ण सहयोग करनेके पक्षमें थे ताकि "हमारे घर-द्वारकी रक्षा हो सके।"

ज्यादासे ज्यादा समय प्राप्त करने और कांग्रेस द्वारा उठाये गये सवालोंको टालनेके लिए वाइसरायने विभिन्न राजनीतिक दलों और अन्य हितोंके कथित प्रतिनिधियोंसे भेंट जुरू कर दी और ५२ प्रतिनिधियोंसे मिलनेके वाद (जिनमें गान्धीजी, पटेल, नेहरू, जिना, नरमदलीय नेता, सिख और परिगणित जातियोंके नेता भी थे) १८ अक्तृयरको घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार १९३५ के भारतसरकार कान्नमें वे सुधार कर देगी जो कि "वांछित हो"; अभी में विभिन्न वहे राजनीतिक दलोंके प्रतिनिधियों और देशी रियासतोंके शाहकोंकी एक सलाहकार समित वनाऊँगा जो युद्धकी तैयारियोंसे सम्यन्धित होगी। इस घोषणाके प्रतिक्रियास्वरूप गान्धीजीने कहा— 'कांग्रेसने रोटी माँगी थी पर उसे मिला पत्थर'। कांग्रेस कार्यसितिने कहा—हम "व्रिटेनको कोई सहायता नहीं दे सकते, क्योंकि इसका अर्थ ब्रिटेनकी उस साम्राज्यवादी नीतिका समर्थन होगा जिसे मिटानेके लिए कांग्रेस सदैव प्रयत्नशील रही है।" समितिने इस सहायता न देनेकी दिशामें पहला कदम कांग्रेस मिन्तमण्डलेंसे इस्तीफा देनेके लिए कहकर उठाया। दिसम्बर १९३९ तक सभी कांग्रेसी मिन्तमण्डल इस्तीफा दे चुके थे।

अध्याय २६

भारतीय रियासतोंमें आन्दोलन

ब्रिटिश भारतके अर्द्ध शताब्दी-व्याप्त राजनीतिक आन्दोलन और चेतनाका भारतीय रियासतोंपर कोई प्रभाव न पड़ा । पाँच सौ बासठ देशी रियासतोंपर राजा-महाराजाओं और सामन्तवादी जागीरदारोंका शासन था। ये रियासतें पूरे देशमें विखरी हुई थीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने अपना काम पूरे तरीकेसे ब्रिटिश भारततक ही सीमित रखा था और सावधानीसे रियासती जनताके सम्पर्कसे अपने आपको बचा रखा था । परन्त १९२१ के असहयोग आन्दोलनने कुछ रियासर्तोमें पहली राजनीतिक हिलोर पैदा कर दी; और वहाँके लोग कांग्रेसके समान उद्देश्योंपर अपने-आपको संघटित करनेकी सोचते रहे। रियासतींकी जनता चाहती थी कि उनके संघटन कांग्रेसमें शामिल हो जामूँ, परन्तु कांग्रेसके सामने ्यावहारिक कठिनाई थी। ब्रिटिश भारतमें तो केवल एक सरकारसे लडना था, परन्त भिन्न-भिन्न रियासतों के सैकडों राजशासकों के विरुद्ध लड़ाई लेना एक असम्भव-सा कार्य हो रहा था। सार्वभीम सत्ताके नाते अंग्रेजोंने भारतीय रियासतींको स्वतन्त्र मान लिया था और उन्हें शान्ति और रक्षाका विश्वास दिला दिया था। आन्तरिक आन्दोलनींसे रक्षा हो जाने-की गारण्टीके कारण बीसवीं शताब्दीमें भी रियासतों मध्यकालीन युगकी व्यवस्था कायम थी। रियासतों की जनता भयत्रस्त थी कि कहीं उसकी कुचलने के लिए अंग्रेजी शक्ति न बुला ली जाय । अंग्रेजोंकी नीति राजा और नवावोंकी रक्षा करना थी, वे चाहे जिस तरहका अत्याचारी शासन चलायें । कांग्रेसने इसलिए रियासतोंकी जनताकी सलाह दी कि वह अपनी रियासतोंके संबटनोंके जरिये अपनेको शक्तिशाली बनाये।

कुछ रियासतों में कांग्रेस कमेटियाँ वन गयीं और १९२१ में कांग्रेसने इन कमेटियों को इस शर्तंपर शामिल होने दिया कि विना कांग्रेस महासमितिकी स्वीकृतिके किसी भी रियासत-में कोई आन्दोलन शुरू नहीं किया जायगा। वड़ौदाके अन्दर वहाँकी जनताने राज-नीतिक अधिकारों के लिए लड़नेके उद्देश्यसे 'ग्रजा-मण्डल' नामका एक राजनीतिक संघटन कायम कर लिया था। मैसूर और काठियावाड़ में भी ऐसे संघटन वन गये थे। परन्तु दूसरी जगहों में शताब्दियों का अधीर अभी आधिपत्य जमाये हुए था।

१९२६ की गरमियोंमें रियासतोंकी समत्याओंमें दिख्यस्पी रखनेवाले कुछ लोग भारत सेवक समाजके कार्याख्यमें इकट्ठे हुए और प्रारम्भिक बातचीत करनेके पश्चात् उन्होंने रियासतोंका एक अखिल भारतीय राजनीतिक संबटन बनानेका निश्चय किया। वम्बईके फैसलोंको कार्यान्वित करनेके लिए एक अख्यायी समिति नियुक्त कर दी गयी थी। आठ महीनोंके बाद अखिल भारतीय रियासती जनता सम्मेखन (आल इण्डिया स्टेट्स पीपुल्स कानफरेन्स) की स्थापना की गयी और इसका प्रथम अधिवेशन, एलोरके उदारदलीय नेता दीवान वहादुर (वादमें सर) एम॰ रामचन्द्ररावकी अध्यक्षतामें १९२७ में वम्बईमें हुआ। आरम्भ वड़ी सावधानीते किया गया या और यही कारण था कि कांग्रेसजन नहीं वंदिक उपाधि-प्राप्त, उदारदलका आदमी अध्यक्षपदके लिए चुना गया। सम्मेलनमें, मैस्र,

ट्रावनकोर, हैदरावाद, कोचीन, वड़ौदा, दक्षिणी रियासतों और राजपूतानाके प्रतिनिधियोंने भाग लिया। इस सम्मेलनने अपना उद्देश स्वाधीन और संघात्मक भारतके अभिन्न अंगकी हैसियतसे रियासती जनता द्वारा शान्तिमय और वैधानिक उपायोंसे पूर्ण उत्तरदायी सरकार प्राप्त करना घोषित किया।

अस्यायी समितिके मन्त्री रंगदास कपाडियाने कुछ समय वाद एक लेखमें रियासतोंकी दशाके वारेमें लिखा था कि 'वहुतसे शासक तो यथार्थमें अत्याचारी हैं। वे अपने अधिकारोंका केवल एक प्रयोग जानते हैं—जनतापर अत्याचार करना और उनका धन चूसना। न्यायालय और पुलिस अष्ट है और स्वेच्छासे अत्याचारके साधन रूपमें काम करती है। करोंका भार असहा है। लोग प्रारम्भिक नागरिक स्वतन्त्रतासे भी वंचित हैं। राजाओं और नवावोंके खर्चकी सीमा नहीं है, उनका एक अपराधारमक रूप हो गया है। लोगोंमें बेहद गरीबी फैली हुई है।"

अखिल भारतीय रियासती जनताके सम्मेलनका अधिवेशन लगभग प्रत्येक वर्ष होता था और रियासतों में सुधारोंका एक नम्र आन्दोलन चलता रहा। कांग्रेसने इनको अपने प्रभावकी शक्ति भी प्रदान की और १९२९ से ब्रिटिश भारतकी भाँति रियासतों में भी जिम्मेदार शासन कायम करानेकी माँगकी घोषणा करनी शुरू कर दी। परन्तु इस माँगसे शासकों के कानपर जूँतक नहीं रेंगी। राजे अपनी सत्तामें से जरा भी शक्ति देनेके लिए तैयार नहीं थे। फिर भी लगभग तीस रियासतों में जनताकी राय लेनेकी परम्परा नियमित और आधुनिक बना दी गयी।

"केवल रस्मी तौरपर ही नहीं विधान द्वारा भी जनताकी आवाज कानून बनाने व शासकीय मामलोंमें अधिकाधिक सुनी जाने लगी थी। परन्तु यह केवल आवाज ही होती थी। आखिरी निर्णय राजाके ही हाथमें रहता था। आशय यह कि १९३७ तक ज्यादा प्रगतिशील रियासतोंमें भी उतनी ही प्रगति हुई जितनी साधारणतया ब्रिटिश भारतके प्रान्तोंने १९०९ और १९१९ के वीचमें हासिल कर ली थी।"

ट्रावनकोरमें १९२१ चे विधान परिषद कायम थी जिसमें निर्वाचित सदस्योंका बहुमत था। पुडुकोटाईमें १९२४ चे, कोचीनमें १९२५ चे और हैदरावादमें १९०० से विधान परिषदें काम कर रही थीं, हाळाँकि हैदरावाद विधान परिषदमें १९३७ तक उसके वीस सदस्योंमेंचे ११ सरकारी सदस्य होते थे।

रियासतों के नेताओंने कई बार कोशिश की कि कांग्रेस उन्हें अपने अन्दर शामिल कर ले परन्तु कांग्रेसको डर था कि यदि वह रियासतों की उल्झी हुई और पेचीदा समस्याओं में कसी तो अंग्रे जों के विरुद्ध चलनेवाले मुख्य संघर्ष में रुकावट पड़ जायगी। १९३८ में हरिपुरा कांग्रेस-अधिवेशन के समय यह मामला सरपर आ गया। उस समयतक रियासती जनताका सम्मेलन (स्टेट्स पीपुल्स कॉनफरेन्स) काफी लम्या रास्ता पार कर चुका था और कांग्रेसका अनुसरण कर रहा था। मैसूरमें १९३७ में एक जुल्सके ऊपर पुल्सिक गोली चला देने से, जिसमें दस मरे और वीस वायल हुए, राजनीतिक आन्दोलनने जोर पकड़ा। कुछ दूसरी रियासतों मी उपद्रव हुए। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में रियासती जनता के कुछ प्रतिनिधियोंने जोर दिया कि कांग्रेस उन्हें भी अपने महान नामका लाम उठानेकी अनुमति दे। कांग्रेस थोड़ा झकी और अधिवेशन में प्रस्ताव पास हुआ कि "फिल्हाल रियासतों में कांग्रेस कमेटियाँ

रीधे कांग्रेस कार्यसमितिके अन्तर्गत और निर्देशनपर काम करेंगी परन्तु कांग्रेसके नामसे अथवा तत्वावधानमें वैधानिक स्तर या सीधी काररवाईका कोई भी काम नहीं करेंगी। रिया- सर्तोंके आन्तरिक संघर्ष कांग्रेसके नामसे नहीं चलाये जा सकेंगे। इन शत्तोंपर, जहाँ कांग्रेस कमेटियाँ कायम हैं वहाँ संघटन शुरू कर देना चाहिये।" परन्तु रियासती जनताके नेताओंने इस प्रस्तावकी निन्दा की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव रियासती जनताकी आकांक्षाओंपर पानी डालता है।

कुछ मुख्य रियासतोंके अन्दर घटित राजनीतिक घटनाओंपर दृष्टि डालनेसे 'भारतीय भारत'के उद्दोलनका अच्छा चित्र मिलता है।

रियासतों में वास्तविक आन्दोलन तो १९३७ में प्रान्तों में कांग्रेसी सरकारें वन जाने के बाद ग्रुक हुआ। इस नये विकाससे रियासती जनताको प्रोत्साहन मिला और वहाँ के शासकों पर भी एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। यद्यपि कई रियासतों में प्रजा-मण्डल या रियासती जनताकी कांग्रेस १९३० या उससे पहले भी वन चुकी थीं परन्तु वे १९३८ के बाद ही वास्तवमें कियाशील हो पायीं जब कि उनके आन्दोलनों का नेतृत्व करने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं को अवकाश मिला।

द्रावनकोरमें रियासती कांग्रेसकी स्थापना १९३० में हो गयी थी परन्तु तबसे वह निष्किय ही वनी रही। १९३८ में फिर जिम्मेदार सरकारके लिए वहाँ जोरदार आन्दोलन ग्रुरू हुआ। आन्दोलन रोकनेके लिए राज्य सरकारने रियासती जनताकी कांग्रेसको गैर-कार्न्ती वोषित कर दिया और सार्वजनिक सभाओंपर रोक लगा दी। सरकारके इस कदमने कांग्रेसकन और रियासती जनताके सामने एक कार्यक्रम पेश कर दिया यानी सरकारी आजा (समाओंपर पावन्दी) को तोड़ना। कई स्थानोंपर आम-सभाएँ की गयीं जिनको पुलिसने लाठीचार्ज द्वारा अथवा गोली चलाकर मंग कर दिया। दमनसे सविनय प्रतिरोधको और वल मिला। दमनसे वाद और अधिक तीत्र तथा घोर दमन हुआ। खुलकर लाठीचार्ज हुए और गोलियाँ चलायी गयीं। लगभग ६६० आदिमयोंको जेलोंमें वन्द कर दिया गया। राज्य कांग्रेसके अध्यक्षकी गिरफ्तारी पर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गयी जो त्रिरोध प्रदर्शनके लिए एक जुल्समें परिणत हो गयी। कीज बुला ली गयी और गोलियों द्वारा जुल्सको तितर-वितर कर दिया गया। बहुतसे लोग मारे गये अथवा घायल हुए।

कुछ महीनों वाद, राजा साहबकी सालगिरहके उपलक्षमें गिरफ्तार किये गये लोग छोड़ दिये गये और वराय नाम नागरिक स्वतन्त्रता दे दी गयी।

कुछ दिनोंकी खामोशीके बाद १९३९ में फिर सिवनय प्रतिरोध आरम्म किया गया जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस कार्यकर्ताओंकी आम गिरपतारियाँ हुईं। जब ट्रावनकोरका संघर्ष अपनी पूरी तेजीपर था, गान्धीजीने उसे स्थगित करनेकी सलाह दी। उनका आदेश मान लिया गया। दीवान द्वारा परिस्थितिपर फिर गौर करनेके लिए गान्धीजीने आन्दोलनको स्थगित करनेका आदेश दिया था।

सुघारोंकी घोषणाके लिए दीवानने शर्त रखी कि घोषणाके पहले राज्य कांग्रेस जिम्मेदार सरकारकी माँगके लिए संघटित प्रयास समाप्त कर दे। परन्तु दीवानने सुघारोंका कोई आभास नहीं दिया। समझौता-वार्ता मंग हो गयी। कांग्रेसने आन्दोलन शुरू किया और दीवानने दमन। मैस्रमें भी लगभग इन्हीं परिस्थितियों में आन्दोलन आरम्भ हुओं। राज्य कांग्रेसने आन्दोलनकी योजना बनायी ही यी कि सरकारने निषेधात्मक आदेश जारी कर दिये। जनताने आदेश मंग किये और कोला जिलेके एक गाँव विदूर स्वाथम्में पुलिसने एक भीड़पर गोली चलायो। कई मारे गये और पचास धायल हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नियुक्त बरलभगई पटेल और जी. बी. कृपालानीके हस्तक्षेपसे मैस्र-सरकारके साथ एक समझौता हो गया। मैस्र सरकारने रियासतमें राज्य कांग्रेसको मान्यता दे दी, वैधानिक मामलोंपर गौर करनेवाली कमेटीमें तीन कांग्रेस-जन भी शामिल कर लिये गये, झण्डेके प्रश्नपर गान्वीजीका फॉरमूला मान लिया गया—अर्थात् सव उत्सवोंपर सरकारी झण्डेके साथसाथ कांग्रेसका झण्डा भी फहराया जायेगा, कांग्रेस-कार्य-कर्ताओंको रिहा कर देनेका और निषेधात्मक आदेश वापस लेनेका आश्वासन दे दिया गया। राज्य कांग्रेस इस समझौतेके पूरा किये जानेकी प्रतीक्षा करती रही परन्तु सरकारने अपने वादे पूरे नहीं किये। सितम्बरमें राज्य कांग्रेस और राज्य अधिकारियोंमें फिर संवर्ष गुरू हो गया परन्तु गान्धीजीके आदेश पर यह आन्दोलन रोक दिया गया।

काठियावाड़की एक छोटी-सी रियासत मनसाके किसानों में भी आम चेतनाके कारण हलचल आरम्भ हो गयो और उन्हें इस वातका एहसास हुआ कि अत्यधिक भूमि-करोंका भारी वोझ उन्हें नष्ट कर रहा है। जब भूमि-करमें कमीके लिए, दिये गये प्रार्थना-पत्र व्यर्थ सिद्ध हुए तो किसानोंने लगान देनेसे इनकार कर दिया और 'मनसा खेदूत समिति' नाम का एक संबटन कायम कर लिया। कुद्ध राज्य अधिकारियोंने यहाँ, भी दमनकी नीति अपनायी। इस मामलेमें भी पटेलके हस्तक्षेप करने पर सरकारने लगान समस्याको नयी जाँच और नये सिरेसे तय करनेकी आजा दे दी।

काठियावाड़की एक दूसरी रियासत लिम्बडीमें न सिर्फ भारी भूमिकर बिस्क स्वयं राजा द्वारा व्यापारकी हर वस्तुपर एकाधिकार कर लेनेके कारण आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । इस एकाधिकारके कारण कई व्यापारियों और दूकानदारोंकी जीविका छिन गयी थी । व्यापारी और किसानोंने राज्यके बुरे कान्तोंका विरोध करनेके लिए संयुक्त मोर्चा बनाया । राज्य-अधि-कारियोंने जनताकी जो अभीतक उनके सामने घुटने टेकती थी, इस चेतनाको चुनौती माना और उन्हें 'सबक सिखाने' के लिए दमनका आश्रय लिया । किसानोंको उनके घरोंसे वेदखल कर दिया गया । व्यापारियोंकी सम्पत्ति लूट ली गयी और उनके मकान जला दिये गये । इस नरकसे बचनेके लिए बहुतेरे तो रियासत छोड़कर भाग गये ।

उड़ीसाकी कुछ रियासतों में, उदाहरणार्थ धनकनल, रनपुर और तालचरमें दशा और खराव थी। गिरफ्तारियाँ, मारपीट, मध्यकालीन युगकी यन्त्रणाएँ, सम्पत्तिको नष्ट करना, खड़ो फसलोंको जन्त कर लेना, लाटीचार्ज, गोली चलाना, भीड़पर हाथी दौड़वा देना रोजमर्राकी घटनाएँ हो गयी थीं। हथियारवन्द पुलिस गाँवोंको घेर लेती और वहाँ अत्याचारका नंगा नाच होता। लोगों द्वारा रनपुर रियासतके एक अधिकारीका करल कर देनेके कारण शायद उड़ीसाकी रियासतोंमें वदलेकी भावनासे दमन इतना भवंकर रूपमें किया जा रहा था। अधिकारियोंने राज्य कांग्रेसको गैरकान्ती संस्था घोषित कर दिया। प्रमुख कांग्रेसजनोंको गिरफ्तार कर लिया और उनके घरोंमें ताला वन्द कर दिया। इस नये कदम (कांग्रेसको गैरकान्ती कर देनेसे) लोगोंको गुस्सा आया और उन लोगोंने एक

जगह इकट्ठा होकर अपने नैताओंकी रिहाईकी माँग की । मेजर वेजलगेटने भीड़पर पिस्तौल-से गोली चला दो, जिससे दो व्यक्ति मर गये और कई घायल हो गये। उत्तेजित भीड़ने मेजरको घेर लिया और उन्हें वहीं मार डाला । इस हत्याके प्रतिशोधमें अधिकारियोंने भवंकर दमन किया जो काफी समयतक चलता रहा । जब परिस्थित जरा शान्त हुई तो उड़ीसा जन-सम्मेलन (उड़ीसा पीपुल्स कानफरेन्स) ने उड़ीसाकी विभिन्न रियासर्तोकी दशाका अध्ययन करनेके लिए जाँच-समिति नियुक्त की । समितिकी रिपोर्टमें अधिकारियों द्वारा किये ग्ये दमनका कचा चिटठा है। अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिकामें रिपोर्टका संक्षेप दिया गया है कि "अधिकांश रियासतींके राजा शौकत और ऐशो-आरामकी जिन्दगी बसर करते हैं । उनकी प्रजाकी जिन्दगी, आजादी और सम्पत्ति उनकी निरंकुश स्वेच्छापर निर्मर करती है। एक-दोको छोडकर बाकी सब राजा मालगुजारीका कमसे कम पचास प्रतिशत, अपने ऊपर अपने कटम्ब व अपने प्रियपात्रोंपर खर्च करते हैं। शेष पचास प्रतिशतका अधिकांश टैक्स वसली व जबरदस्ती धन छीननेवाले कर्मचारियोंपर व्यय होता है । नागरिक स्वतन्त्रता अज्ञात वस्तु है। सार्वजनिक सभाएँ करनेकी अनुज्ञा नहीं मिलती और अखवार जब जी चाहे रोक दिये जाते हैं । बिना मुकदमा चलाये नजरवन्द करना, कष्टकारी प्रजाजनोंको नाममात्र-की काररवाई कर दण्ड दे देना, मनमाने तौरपर सम्पत्ति जन्त कर लेना, जुर्माने वसल करना, मारना और यन्त्रणाएँ देना आम घटनाएँ हो गयी हैं। विद्रोहको दवानेके लिए, राज्य अधिकारियोंने अँग्रेजी सेनाकी सहायता ली। धनकनल, गंगापुर और रनपुरमें कई आद-मियोंको गोलीसे मार डाला गया । २५ से ३० हजारके बीच लोगोंने भागकर उडीसा प्रान्तमें शरण ली।"

राजाओंने उड़ीसाकी सरकारसे माँग की और अंग्रेजोंने इस माँगका समर्थन किया कि निष्क्रमणके नेताओंको निष्कासित कर दिया जाय। उड़ीसा प्रान्तकी कांग्रेस सरकारने यह माँग स्वीकार नहीं की और मिन्त्रमण्डलमें संकट पैदा हो जानेके बावनूद गर्वन्रके इस्तक्षेपका विरोध किया।

१९३८ में हैदराबाद सरकारने एक आदेश द्वारा रियासतमें राज्य कोग्रेस बनानेपर रोक लगा दी। सिवनंय अवज्ञा आन्दोलन द्वारा इस आदेशका विरोध किया गया जिसमें कई आदमी गिरफतार कर लिये गये। कुछको नजरबन्द अथवा निष्कासित कर दिया गया। २३ अखवारोंके रियासतमें आनेपर रोक लगा दी गयी। राजनीतिक संघर्ष चल ही रहा था कि आर्यसमाजियोंने एक मुस्लिम शासक निजाम द्वारा धार्मिक स्वतन्त्रतापर प्रतिवन्ध लगानेके कारण, धार्मिक स्वतन्त्रता आन्दोलन शुरू कर दिया। आर्य-समाज आन्दोलनमें देश भरके लोगोंने भाग लिया। मुद्र अँग्रेज शासित भूमिमें भी आर्य-समाज नेता हैदराबाद-आन्दोलनके लिए स्वयंसेवक भरती कर रहे थे और उन्हें हैदराबाद रवाना कर रहे थे। आखिरकार निजाम-सरकार झकी और धार्मिक माँगको स्वीकार कर लिया। आर्यसमाजी सत्याग्रही छोड़ दिये गये। परन्त कांग्रेसने साम्प्रदायिकता पैदा होनेके भयसे अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया। साम्प्रदायिकताके कुछ लक्षण प्रकट भी होने लगे थे।

जयपुर रियासतमें गैरराजनीतिक प्रश्नके ऊपर उद्देखन बढ़कर राजनीतिक आन्दोखन-में परिणत हो गया । १९३८-३९ में जयपुरमें अकाख पड़ा और कांग्रेस महासमितिके कोपा- ध्यक्ष जमनालाल बजाज, जो जयपुरके रहनेवाले थे और अब ब्रिटिश भारतके नागरिक हो गये थे, अकाल-पीड़ित इलाकोंका निरीक्षण करने और जितनी सम्भव हो उतनी सहायता देनेके लिए जयपुर गये। उनका इरादा था कि इस अवसरपर राज्य जन-सिमितिकी मीटिंग-में भी सिमिलित हो जावँगे। अधिकारियोंने बजाजके राज्य प्रवेशपर रोक लगा दी। उन्होंने प्रार्थना की कि रोक हटा दी जाये अन्यथा वे आज्ञा मंग करनेपर मजबूर होंगे। अधिकारी अपनी हठ-धर्मीपर जमे रहे, और बजाजने आज्ञा-मंग की। वे कई दफा गिरपतार करके ब्रिटिश क्षेत्रमें छोड़ दिये गये और हर मतर्वा उन्होंने वापस आकर राज्य-सीमामें प्रवेश किया। इसी बीच जयपुर प्रजा-मण्डलने जिम्मेदार सरकारके लिए सविनय-प्रतिरोधका आन्दोलन छेड़ दिया। राज्य-सरकार किसी तरह भी यह माँग स्वीकार करनेको तैयार न थी। परन्तु बजाजने सरकार और प्रजामण्डलके बीच समझौता करवा दिया। समझौतेके अनुसार प्रजा-मण्डलको कुछ सुविधाएँ मिल गर्या जिनमेंसे एक यह थी कि अखवारोंके ऊपरसे प्रति-बन्ध हट गया।

राजकोट राज्य सत्याग्रहमें तो वादमें स्वयं गान्धीजीको भी उलझना पड़ा । दूसरी रियासतोंकी भाँति राजकोटमें भी जिम्मेदार सरकारकी माँग की गयी। राजकोटमें, संघटित तरीकेसे आन्दोलन चलाया गया और सरकारने लाठी-चार्ज, गिरपतारियों, सभाओं, जुल्स और अखवारोंपर रोक लगाकर आन्दोलनको कुचलनेकी कोशिश की। अंग्रेजी इलाकेसे भी कुछ औरतों और पुरुषोंने भाग हेकर अपनेको गिरपतार करवा दिया। वहाँके शासक ठाकुर साहबने पटेलके साथ एक समझौता कर लिया। समझौतेके अनुसार ठाकुर साहब 'जनताको ज्यादासे ज्यादा अधिकार देने'की गरजसे सुधारोंकी योजना प्रस्तुत करनेके लिए दस आदिमयोंकी एक सिमिति बनानेवाले थे। सिमितिमें सात सदस्य पटेल द्वारा चुने हुए गैर-सरकारी प्रजाके प्रतिनिधि होनेवाले थे। पटेलने नामोंकी सूची ठाकुर साहबको दे दी। .परन्तु ठाकुरने अंग्रेजी रेजीडेंटके परामर्शंसे तीन नाम इस आधारपर अखीकार कर दिये कि संमितिमें मुसलमानों व अन्य अल्पमत जातियोंके प्रतिनिधियोंको भी जगह मिलनी चाहिये। प्रजा मण्डल पटेलकी सूचीपर अड़ा हुआ था और शासक रेजीडेंटकी रायपर । फिर संघर्ष शुरू हुआ । गान्धीजी राजकोट पहुँचे और ठाकुरको समझाया कि वह अपना वादा पूरा करें । जब समझौता असफल रहा तो गान्धीजीने आमरण अनदान शुरू कर दिया । "चूँकि यह अनशन अनिदिचत कालके लिए था, इसलिए वॉइसरायसे हस्तक्षेप करनेकी प्रार्थना की गयी जिसके फलस्वरूप भारतके प्रधान न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायरको निर्णय करनेके लिए पंच वना दिया गया । उनका निर्णय ,गान्धीजीके पक्षमें था । परन्तु गान्धीजीके ख्यालमें 'अनरानसे द्वावका धव्वा' लग गया इसल्ए उन्होंने अपने पक्षमें पंचके फैसलेका लाम उठाना अस्वीकार कर दिया।"

अध्याय २७

मुसलिम लीगका अभियान

मुसलिम लीगके १९३० के अधिवेशनमें अध्यक्षपदसे जिनाने जो भाषण किया उसका हिन्दुओंने यद्यपि परिहास किया और वह मुसल्मानोंमें भी उत्साह भरनेमें नाकामयाव रहा मगर वह जिनाकी विभाजन-योजनाका आरम्भ था—उस योजनाका जिसका खाका जिनाने लाहीरमें सन् ४० में पेश किया था। उस वर्ष इलाहाबादमें लीगके वार्षिक अधिवानमें भाषण करते हुए उर्द्के प्रसिद्ध कवि डा० सर मुहम्मद इकवालने कहा कि "यूरोप इस नतीजेपर पहुँचा है कि धर्म मनुष्यका व्यक्तिगत मामला है और उसका सांसारिक कार्योंसे कोई सम्बन्ध नहीं है। इस्लाममें खुदा, और दुनिया, रूह और भौतिक पदार्थ, राज्य और धार्मिक संस्थाएँ एक दूसरेके अभिन्न अंग हैं।.....

"भारत एशियाका छोटा रूप है। भारतीयोंके एक हिस्सेके सांस्कृतिक सम्बन्ध एशियाके पूर्वा राष्ट्रींसे हैं तो दूसरेके एशियाके पश्चिमी और मध्यके राष्ट्रींसे। अगर भारतमें परस्पर सहयोगका कोई प्रभावशाली सिद्धान्त तय हो जाये तो उससे इस प्राचीन भूमिमें जिसमें अभीतक तवाही रही है शान्ति और परस्पर भाईचारेकी स्थापना हो जायगी।

''यह देखकर दुःख होता है कि आन्तरिक सौहार्द्रका कोई भी सिद्धान्त हूँ दनेमें हमें अभीतक असफलता ही मिली है और जैसा कि मैंने मुसलमानोंको समझा है, उससे मुझे यह कहनेमें कोई हिचिकिचाहट नहीं है कि अगर भारतीय मुसलमानोंके अपनी परम्पराओं और संस्कृतिके आधारपर पूरे विकासके अधिकारके सिद्धान्तको स्थायी साम्प्रदायिक समझौतेकी बुनियाद बना लिया जाय तो भारतीय मुसलमान भारतकी स्वतन्त्रताके लिए अपना सब कुछ होम देगा।

"भारत एक महाद्वीप है जिसमें विभिन्न जातियाँ वसती हैं जो अलग-अलग भाषाएँ बोलती हैं और जिनके धार्मिक मत भी पृथक्-पृथक् हैं। उनका व्यवहार समान जाति-चेतनाके वशीभृत निश्चित नहीं होता है। यहाँतक कि हिन्दू भी एकतत्व समुदाय नहीं हैं। इसलिए मुसलमानोंकी भारतके अन्दर एक मुस्लिम भारतकी माँग पूर्ण रूपसे न्यायपूर्ण है।

"मैं चाहता हूँ कि पंजाव, उत्तर-पश्चिमी-सीमायान्त, सिन्ध और वलेचिस्तानके सूत्रे मिलाकर एक राज्य बना दिया जाय। कमसे कम उत्तरी-पश्चिमी भारतीय मुसलमानोंके लिए अंग्रेजी साम्राज्यके अन्तर्गत या उसके वाहर, स्वराज्य दे देना ही उत्तरी-पश्चिमी भारतीय मुसलिम राज्यका निश्चित भविष्य मुझे माल्म पड़ता है।"

लीग अधिवेशनने अध्यक्षकी रायको कोई महत्त्व नहीं दिया और न कोई ऐसा प्रस्ताव ही वहाँ पास हुआ।

१९२० में साम्प्रदायिक समस्याका विवादस्थळ भारतसे हटकर लन्दन गोलमेज सम्मेलन हो गया। इस सम्मेलनके प्रतिनिधि वाइसरायने नियुक्त किये थे। भारतीय जनता-के प्रतिनिधि होनेके ब्जाय वे वाइसराय द्वारा ही नामजद किये गये थे और उनसे आशा की जाती थी कि वे विभिन्न साम्प्रदायिक हितोंका प्रतिनिधित्व करेंगे। इसिलए गोलमेज सम्मेलनमें महत्त्वपूर्ण विपयोंकी अपेक्षा साम्प्रदायिकतापर ही अधिक जोर दिया गया। वरत्तः हर प्रतिनिधि किन्हीं विशेष हितों या अपने सम्प्रदायका अपने मुँह नेता वना हुआ था। लन्दनमें रहनेवाले कुछ मुसलमानोंने भी भारतकी तरफसे बोलनेकी जिम्मेदारी अपने सरपर ले ली और 'पाकिस्तान' की माँग उटायी। उन्होंने मुस्लिम प्रतिनिधिमण्डलने प्रार्थना की कि वह इस आवाजको गोलमेज सम्मेलनमें उठाये। जब मुस्लिम प्रतिनिधिमण्डलने उनकी वातपर ध्यान नहीं दिया तव उन्होंने एक कमेटी बना ली और अपना एक कार्यालय लन्दनमें स्थापित किया; और सर इकवालके इलाहाबादवाले भाषणके आधारपर आन्दोलन करने लगे। सन् १९३२ में तीसरे गोलमेज सम्मेलनके अवसरपर इकवालने अपने विचारको ठीस तुझावके रूपमें पेश किया और कहा कि भारतमें कोई केन्द्रीय सरकार नहीं होनी चाहिये। प्रान्तोंको स्वशासन मिलना चाहिये और स्वतन्त्र उपनिवेशोंके रूपमें उनका सीधा रिश्ता लन्दन स्थित भारत-सचिवसे होना चाहिये।

लेकिन गोलमेज सम्मेलनमें मुसलमान प्रतिनिधियों द्वारा उठायी गयी माँगका सार था कि—(१) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान सभाओं और परिषदों में मुसलमानों के प्रतिनिधि पृथक निर्वाचन द्वारा चुने जावँ। (२) मुसलिम-अल्प-संख्यक प्रान्तों में, मुसलमानों को प्राप्त प्रतिनिधित्व कायम रखा जाय। इनके अतिरिक्त, पंजाव, सिन्ध, उत्तर-पिक्चमी सीमा प्रान्त और यंगाल जैसे मुस्लिम बहुसंख्यक स्वोंकी विधान सभाओं और परिपदों में उन्हें बहुसंख्या स्थानों की कानृतन गारण्टी दो जाय।

हिन्दू प्रतिनिधियोंने हिन्दू और मुसलमान दोनोंके लिए संख्याके अनुपातपर संयुक्त निर्वाचनकी माँग की । उन्होंने कान्न द्वारा सम्प्रदाय विशेषको कहीं भी 'बहुसंख्या'की मान्यता देनेपर घोर आपत्ति की ।

कुछ मुसलिम नेता कतिपय शतोंपर संयुक्त निर्वाचनके लिए राजी थे, पर उनकी शतें हिन्दू नेताओं को अमान्य थीं । उदाहरणके तौरपर मुहम्मदअलीने प्रथम गोलमेज सम्मेलनके अवसरपर (सम्मेलनके दौरानमें ही उनकी मृत्यु हो गयी) सुझाव दिया था कि "मारतीय राष्ट्रीयताके हितमें हमें संयुक्त निर्वाचनक्षेत्र स्वीकार कर लेने चाहिये।" इस सुझावके साथ कुछ शतें भी थीं; जैसे (१) विधान-सभाओं और परिपदोंमें हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिए स्थान सुरक्षित होना चाहिये। (२) किसी भी उम्मीदवारको निर्वाचित घोपित निक्या जाय, जवतक (अ) उसे अपने सम्प्रदायके कम-से-कम ४०% (चालीस प्रतिशत) बोट निमलें; और (व) जहाँ यह उम्मीदवार कुल आवादोकी दस प्रतिशत-अल्प-संख्यासे सम्बन्ध रखता हो वहाँ उसे कम-से-कम दूसरी जातियोंके पाँच प्रतिशत और यदि बहुसंख्यामें है तो कम-से-कम दस प्रतिशत बोट मिलना चाहिये। महम्मदअलीने कहा कि उनकी योजनाके तीन लाभ होंगे। प्रथम यह कि "बोटोंके लिए हर उम्मीदवारको दोनों समाजोंके लोगोंसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। दूसरे यह कि विना अपने समाजके बोटोंकी अच्छी खासी संख्या पाये हुए कोई भी निर्वाचित नहीं पायेगा। और तीसरे यह कि अगर किसी उम्मीद-

१. धीरेन्द्रनाथ सेन, दि प्रावलेम ऑफ माइनारिटील पृष्ट ४१७

२. वही पुस्तक, पृष्ठ ४१८

वारको अपने समाजके काफी वोट मिल भी जाबँ परन्तु यदि दूसरा समाज उसे अच्छा नहीं समझता तो वह चुना न जा सकेगा।

सर मुहम्मद शफीने प्रथम गोलमेज सम्मेलनकी अल्पमत-उपसमितिके सामने जो सुझाव पेश किये थे उनमें भी संयुक्त निर्वाचन स्वीकार कर लिया गया था। ह जनवरी १९३१ को उपसमितिकी वैठकमें बोलते हुए उन्होंने निम्नलिखित सुझाव पेश किये थे—

जो रातें में रख रहा हूँ उनपर हमें संयुक्त निर्वाचन मान्य है। पहली यह कि मुस्लिम अल्पमत प्रान्तोंमें मुसलमानोंको जो मुविधाएँ प्राप्त हैं वे कायम रहें। पंजाव और वंगालमें जनसंख्याके आधारपर प्रतिनिधित्व और संयुक्त निर्वाचन होना चाहिये। मौलाना मुहम्मद अली द्वारा पेश की गयी शतोंके साथ-साथ मुरक्षित स्थानोंका भी सिद्धान्त माना जाना चाहिये। र

उसी उपसमितिके सामने १४ जनवरी १९३१ को एक और मुझाव उन्होंने पेश किया- "आज मुझे ये वातें रखनेका अधिकार मिला है कि पंजावमें मुसलमानोंको साम्प्र-दायिक (पृथक्) निर्वाचन द्वारा कुल स्थानोंके ४९ प्रतिशत स्थान मिलना चाहिये और साथ ही उस प्रान्तमें प्रस्तावित विशेष निर्वाचन-क्षेत्रमं भी उन्हें चुनाव लड्नेका अधिकार प्राप्त हो। जहाँतक वंगालका सम्बन्ध है वहाँ मुसलमानोंको साम्प्रदायिक निर्वाचन द्वारा कुल सदस्यताके ४६ प्रतिशत स्थान मिलना चाहिये और साथ ही उस स्वेमें प्रस्तावित विशेष निर्वाचन-क्षेत्रमें भी उन्हें चुनाव छड्नेका अधिकार प्राप्त हो । जहाँ तक अल्पसंख्यक प्रान्तीं का सम्यन्य है वहाँ मुसलमानोंको पृथक निर्वाचन द्वारा जो अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है वह कायम रहे और सिंघमें इसी प्रकारका प्रतिनिधित्व-आधिक्य हमारे हिन्दू भाइयोंको, तथा हिन्दु और सिख भाइयोंको उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्तोंमें मिले। अगर किसी प्रान्तीय विधान सभा अथवा केन्द्रीय विधान सभामें किसी समाज विशेषके तीन चौथाई प्रतिनिधि प्रथक निर्वाचनको त्याग कर संयुक्त निर्वाचनको अपनाना चाहते हैं तो संयुक्त निर्वाचन प्रणाही लागू कर दी जायगी । पहले सुझावमें संयुक्त निर्वाचनके अन्तर्गत कानूनन बहुमतकी माँग की गयी थी; और दसरेमें पृथक निर्वाचनके साथ सुरक्षित स्थान रखनेकी माँग की गयी थी । परन्तु अंग्रेजोंने अपने फैसटेमें मुसलमानींकी दोनीं ही माँगें पूरी कर दीं—प्रथक निर्वाचन और कानूनन बहुमत दोनों ही वातें मान ली गयी थीं।

सिखोंने कानूनन बहुमत (स्टेड्टरी काम्यूनल मैजॉरिटी) और बहुसंख्यकंकि लिए स्थान सुरक्षित रखनेका विरोध किया। पंजावमें बहुत ही कम संख्यामें होनेके कारण सिखोंने माँग की कि साम्प्रदायिक सन्तुलन ठीक रखनेके लिए स्वेका पुनस्संघटन होना चाहिये। अगर यह माँग अमान्य हो तो केन्द्रीय सरकार पंजावका प्रशासन स्वयं अपने हाथमें हे ले जयतक कि सम्यन्धित सम्प्रदाय किसी समझौतेपर न पहुँच जावँ।

कांग्रेसने सुझाव रखे कि सिन्धमें हिन्दुओं के लिए, आसाममें मुसलमानों के लिए और पंजावमें सिखों के लिए, संयुक्त निर्वाचनके अन्तर्गत जन-संख्याके आधारपर सुरक्षित खान रखे जाव । लेकिन जिन स्वों में हिन्दू और मुसलमान कुल जन-संख्याके पचीस प्रतिशतसे कम हैं वहाँ उन्हें अतिरिक्त स्थानों के लिए भी चुनाव लड़नेका अधिकार प्राप्त होगा।

रिपोर्ट ऑफ दी माइनार्टींज सब कमेटी ऑफ दी फर्स्ट आर. टी. (इण्डियन ऐडिशन)
 प्रष्ठ ९६

गान्धीजीने, जिन्होंने गोलमेज सम्मेलनमें कांग्रेसका प्रतिनिधित्व किया था, सुझावोंकी व्याख्या करते हुए कहा कि जहाँ भी सम्भव हो, निर्वाचन क्षेत्रोंको इस प्रकार वनाना चाहिये कि हर सम्प्रदायको संख्याके उचित अनुपातमें प्रतिनिधित्व मिल जाय। अगर सिन्धवासी आर्थिक उत्तरदायित्व सम्हालनेको तैयार हों तो कांग्रेसको सिन्धके पृथक प्रान्त वनाये जानेमें कोई आपित्त नहीं।

मुसलमानोंमें आपसमें मतमेद पैदा हो गया।

"मुस्लिम राष्ट्रवादी सम्मेलन और सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन (मुस्लिम आल पार्टीज कानफरेन्स) में समझौता करानेकी कोशिश की गयी । २२ ज्न १९३१ को शिमलेमें विभिन्न प्रस्तावोंपर विचार करनेके लिए एक संयुक्त सम्मेलन बुलानेका प्रयत्न किया गया।" परन्तु सम्मेलन करनेका प्रयास असफल रहा। डा॰ अन्सारीने इस असफलताको समझाते हुए कहा कि "यहाँ आनेपर हमने देखा कि शिमलाका वातावरण किसी भी समझौतेके प्रतिकृल है। वदिकस्मतीसे हमारा डर सही निकला। शिमलाका वदिकस्मत वातावरण और असर, जिसको लोग इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि वतलानेकी जरूरत नहीं, एकता करानेवाली शिक्तयोंसे बहुत अधिक मजबूत साबित हुआ।"

जव विभिन्न सम्प्रदायोंके प्रतिनिधि आपसमें कोई समझौता न कर सके तो अंग्रेजी सरकारने साम्प्रदायिक मसलेपर फैसला देनेकी जिम्मेदारी ले ली। अगस्त १९३२ को अंग्रेजी प्रधान मन्त्रीने यह फैसला, जो साम्प्रदायिक निर्णयके नामसे मशहूर है, सुना दिया। यह निर्णय जिसका आशय मुसलमानोंको सन्तुष्ट करना था, किसीको भी सन्तुष्ट न कर सका, यहाँ तक कि मुसलमानोंको भी नहीं । अंग्रेजी नीतिकी परम्पराक्ते अनुसार इस निर्णयमें पृथक् निर्वाचन मान लिया गया था और संयुक्त निर्वाचनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया था, हालाँ कि मुसलमानोंने स्वयं कुछ शत्तोंके साथ संयुक्त निर्वाचनका प्रस्ताव रखा था। इस निर्णय (कम्यूनल अवार्ड) में हर सूत्रेमें मुसलमानोंके लिए स्थान सुरक्षित रखे गये, जिन प्रान्तोंमें मुसल्मान अल्पसंख्यामें थे वहाँ उनको प्रतिनिधित्व आधिक्य दिया गया, सिन्ध और उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्तमें हिन्दुर्थोको भी प्रतिनिधित्व-आधिक्य (वेटेज) दिया गया । परन्तु वंगाल और पंजाव सम्बन्धी निर्णयसे हिन्दू और मुसलमान दोनों ही असन्तुष्ट रहे। पंजायमें कुल जनसंख्यामें मुसलमान ५५% (पचपन प्रतिशत) थे परन्तु वहाँ उन्हें ४९% प्रतिनिधित्व मिला । इसपर भी हिन्दुओंका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें जितना मिलना चाहिये था उससे भी बहुत कम प्रतिनिधित्व मिला । उनकी जगहें कम करके सिलोंको प्रतिनिधित्व आधिक्य दिया गया । वंगालमें तो हालत और वुरी थी । मुसलमानोंकी संख्याका अनुपात ५४'८ फी सदी था और उन्हें कुछ ४७"५ फी सदी जगहें मिलीं । हिन्दुओं-की संख्याका अनुपात ४४ ८ प्रतिशत था, उन्हें केवल ३२ प्रतिशत स्थान मिले। फिर वंगालमें हिन्दुओं अथवा मुसलमानोंको मिलनेवाली जगहोंपर किसने कव्जा कर लिया? साम्प्रदायिक निर्णयमें यूरोपियनोंको बहुत अधिक प्रतिनिधित्व देनेकी व्यवस्या की गयी थी । वे जनसंख्याके सिर्फ '०१ फोर्सदी थे और उनको १० फी सदी जगहें दी गयीं । यानी अपनी जनसंख्याकी २५००० गुना जगहें उनको दी गयीं ! अखिल भारतीय मुसल्मि सम्मेलनने

९. राजेन्द्रपसाद, इण्डिया ढिवाइडेड पृष्ठ १२७

२. एनुअल रजिस्टर १९३१, पृष्ठ ३०५

(जो पहले सर्वदलीय मुसलिम सम्मेलन था) त्रिटिश प्रधान मन्त्रीके साम्प्रदायिक निर्णयपर निराशा जाहिर की और मुसलमानोंको पंजाब तथा बंगालमें कानूनन बहुमत न देने और कतिपय प्रान्तोंमें प्रतिनिधित्व-आधिक्य कम कर देनेकी निन्दा की । परन्तु इस निर्णयमें खुली छूट थी कि यदि सम्बन्धित सम्प्रदाय आपसमें कोई समझौता कर लेते हैं तो वह समझौता निर्णयका स्थान ले लेगा । चुनांचे समझौतेका रास्ता हूँढ्नेके लिए मौलाना शौकत अलीने गान्धीजीसे जेलमें मेंट करनेकी वाइसरायसे अनुमति चाही । शौकत अलीको अनुमति न मिली और उनसे कहा गया कि गान्धीजीसे मिलनेके पहले वे अपनी वातके लिए आम मुसलमानोंका समर्थन हासिल कर लें। तब तमाम मुसलिम पार्टियोंका एक सम्मेलन लखनकमें १५ अक्टूबर १९३५को बुलवाया गया । हिन्दुओंकी तरफसे मालवीयजी भी इसी प्रकारका प्रयास कर रहे थे, जिसका परिणाम इलाहावादमें हुआ एकता-सम्मेळन था जिसमें विभिन्न साम्प्रदायिक नेताओंने भाग लिया था—६३ हिन्दू, ३९ मुसलमान, ११ मिख और ८ भारतीय ईसाई। सम्मेलनमं, जो ३ नवम्बरसे १५ तक चलता रहा, आखिरमें परेशान करनेवाले पंजाव-वंगालके प्रस्तपर एक समझौता हो गया । हिन्दू मुसलमानींको ५१% प्रतिनिधित्व देनेपर राजी हो गये । संयुक्त निर्वाचन भी इस शर्तपर मान लिया गया कि किसी उम्मीदवारको जीतनेके लिए अपने समाजके कम से-कम २० फी सदी बोट मिलें। अगर किसीको भी २० फी सदी नहीं मिलते हैं तो जिसको सबसे अधिक भी सदी बोट मिले होगें वह निर्वाचित घोषित किया जायेगा । केन्द्रीय विधान सभामें मुसलमानोंके प्रतिनिधित्वके प्रश्नपर जिसपर अभी तक अंग्रेजी सरकारने कोई निर्णय नहीं दिया था-यइ निश्चय हुआ कि विधान सभाकी सदस्यतामें मुसलमानोंको ३२ की सदी स्थान दिये जाउँ । सम्मेलन इस शर्तंपर कि केन्द्रसे सहायता नहीं माँगी जायेगी, सिंधको पृथंक प्रान्त माननेपर तैयार हो गया । नये प्रान्तोंमें हिन्दुओंको भी कुछ नयी सुविधाएँ देना स्वीकार कर लिया गया।

वंगालपर हुआ हिन्दू-मुसिलम समझौता इसपर निर्मार करता था कि यूरोपीय लोग अपना अत्यधिक प्रतिनिधित्व कम करना स्वीकार कर लें। समझौतेके अनुसार मुसल-मानोंको ५१ प्रतिशत जगहें मिली थीं और हिन्दुओंको ४४ ८ फीसदी। इसका मतलब यह हुआ कि यूरोपीयनों व अन्य जातियोंके लिए सिर्फ ४२ फी सदी प्रतिनिधित्व शेप बचा था। इसिलए एकता-सम्मेलनकी एक समिति यूरोपीयोंके साथ इस प्रश्नपर बातचीत करनेके लिए कलकत्ता रवाना हो गयी।

१९१६ में लखनऊकी ही भाँति हिन्दू और मुसलमान फिर एक हो गये और अपनी समस्याओं को मुलझाने में उन्होंने व्यावहारिक बुद्धि दिखलायी। परन्तु अंग्रे जी सरकारने फिर चालाकी से भरा एक दाँव मारा। २४ दिसम्बर १९३२ को, जब कि एकता सम्मेलन चल ही रहा था, भारतसचिव सर सैमुअल होरने तीसरे गोलमेज सम्मेलनमें घोषणा की कि सरकारने केन्द्रीय विधान समामें मुसलमानों को २२ दे फी सदी प्रतिनिधित्व देनेका और सिधके नव-निर्मित प्रान्तको केन्द्रसे आर्थिक सहायता देनेका फैसला किया है। यह उससे कहीं ज्यादा था जो हिन्दुओंने देना और मुसलमानोंने लेना स्वीकार किया था। इस घोषणा-में हिन्दुओंको वे सुविधाएँ भी नहीं दी गर्वी जो मुसलमान उन्हें देनेको राजी हो। गर्व थे।

इस प्रकार यह एकता-सम्मेलन मुसलमानोंके लिए यकायक वेकार कर दिया गया - और यह खतम ही हो गया । अंग्रेज एक बार फिर परिस्थितिके स्वामी वनः गये।

जैसा कि एक वार पहले भी कहा जा चुका है, कांग्रेसके विधान सभा दलमें साम्प्रदायिक निर्णयपर मतमेद था। अणे और माल्वीयके नेतृत्वमें चलनेवाला दल इसका घोर विरोध कर रहा था और दूसरा तटस्य था, हालाँ कि निर्णयंके सिद्धान्तों और नियमोंके विरोधी वे भी थे। मालवीयजीकी राष्ट्रवादी पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों ही अपने-अपने पक्षमें लोकमत संघृटित करनेमें संलग्न हो गये—एक निर्णयके विरोधमें और दूसरा उसके पक्षमें । इसी अवसर पर लीगके अन्दर खुद १९३३ के अधिवेशनके अध्यक्ष पदके प्रस्त पर झगड़ा हो गया। अन्ततः लीगका अधिवेशन ३१ अक्टूबरको हावड़ामें पेशावरके वैरिस्टर अन्दुल अजीजकी अध्यक्षतामें हुआ । पुलिस वाहर चौकसी करती रही कि कहीं अन्दुल अजीजकी अध्यक्षताके विरोधी कोई गड़वड़ी और शान्तिमंग न करें। इस अधिवेशनने कुछ शर्तोंके साथ 'साम्प्रदायिक निर्णय'को स्वीकार कर लिया। मगर इस अधिवेशनकी उपेक्षा कर दी गयी और दिल्लीमें खान वहादुर हाफिज हिदायत हुसेनकी अध्यक्षतामें २५ नवम्बरको फिर लीगका अधिवेदान हुआ। इस अधिवेदानने साम्प्रदायिक निर्णयपर अपनी स्वीकृतिकी मोहर लगा दी तथा मन्त्रि-मण्डल और नौक्रियोंमें उचित भाग मिलनेकी माँग की । परन्तु लीगकी समस्या अभी सुलझी नहीं थी क्योंकि अब्दुल अजीज भी अध्यक्षपदपर कायम थे। इसिलए ४ मार्च १९३४ को लीगका एक और अघि-वेशन बुलाया गया और जिनाको जो दो साल इंगलैण्डमें रहनेके वाद हालमें ही भारत लौटे थे, दोनों पक्षोंने लीगका स्थायी अध्यक्ष मान लिया। २ अप्रैल १९३४ को लीगकी परिषद्ने एक प्रस्ताव पास करके साम्प्रदायिक निर्णयको 'जैसा है वैसा ही' स्वीकार करनेका फैसला किया हालाँकि इस निर्णयसे उनकी माँगं पूर्णतया पूरी नहीं होती थी। और लीग इसी आधारपर दूसरे सम्प्रदायों के साथ देशके लिए विधान, अगर वह सवको स्वीकार हो, वनानेके लिए सहयोगको तैयार थी । शायद दिल्लीके लीग-अधिवेशनमें उठायी गयी माँगके प्रतिक्रियास्वरूप ७ जुलाई १९३४ को भारत सचिवने घोषणा की कि नौकरियोंमें मुसलमानोंको २५% जगहें मिलेंगीं । नौकरियोंमें यह अनुपात जन-संख्याके आधारपर किया गया था। अखिल भारतीय मुसलिम सम्मेलनने भारतसचिवके इस फैसलेका विरोध किया और माँग की कि मुसलमानोंको नौकरियोंमें हिरसा उनके केन्द्रीय विधान सभामें प्रतिनिधित्वके बराबर यानी ३३३ फी सदी मिलना चाहिये, न कि जनसंख्याके आधारपर। उसी वर्षके आरम्भमें आगा खाँने मुस्लिम लीग और मुस्लिम सम्मेलन (मुस्लिम कान्फ्रेंस) को एक करनेकी कोशिश की थी और जिनाके स्थायी अध्यक्ष होनेके पूर्व आगा खाँकी इसी कोशिशके कारण लीगके अन्दर तीव मतभेद पैदा हो गये थे। लेकिन अगस्तमें, विधान सभाके चुनाव नजदीक आ जानेके कारण, चुनाव सम्बन्धी प्रचारके लिए किसी प्रकार एक होनेके उद्देश्यमे शिमलामें १३ अगस्तको दोनों संघटनोंकी कार्यसमितियोंकी एक संयुक्त वैठक बुलायी गयी। इस वैठकने एक संयुक्त चुनाव-घोपणा-पत्र जारी किया और मुसलमानोंसे पृथक् निर्वाचन सिद्धान्त और साम्प्रदायिक निर्णयोंके विरोधियोंके खिलाफ एक मोर्चा वनानेको कहा । चुनाव सिर्फ इसी प्रस्तपर लड़े जानेवाले थे ।

थोड़ा-सा जिन्न यहाँपर १९३५ के ऐक्टके प्रति मुसल्मि लीगके दृष्टिकोणका और

उसके अन्तर्गत पहले आम चुनावोंका कर देना चाहिये। अप्रैल १९३५ में वम्बईमें हुए लीगके अधिवेशनमें एक प्रस्ताव द्वारा १९३५ के ऐक्टका प्रान्तीय योजनाका भाग स्वीकार कर लिया गया और संघात्मक भाग अस्वीकार! प्रस्तावमें कहा गया था कि, "लीग यह समझती है कि देशकी दशा देखते हुए विधानको प्रान्तीय योजना, जैसी भी है, उसका उपयोग करना चाहिये, यद्यपि इस योजनामें बोर आपृत्तिजनक वातें हैं जो पूरे सरकारी ढाँचेके ऊपर वास्तविक नियन्त्रण, और मिन्त्र-मृष्ट्रलक्षी जिम्मेदारी तथा विधान-सभाओंको निर्यंक बना देती हैं।" विधानकी संघात्मक योजनाकी निन्दा करते हुए लीगने उसको प्रतिक्रियावादी, पिछड़ी हुई, भारतके हितोंके लिए हानिकारक और घातक कहा। प्रस्तावमें कहा गया था कि योजनाका मतलव भारतके पूर्ण उत्तरदायी शासनके ध्येयके हासिल करनेमें अनिश्चित कालके लिए विलम्ब लगाना और उसको रोकना है।

सर सैयद वजीर हसनने लीगके अध्यक्ष-पदसे भाषण करते हुए कहा कि न तो कांग्रेस ही देशको पूर्ण स्वराज्यके ध्येयकी तरफ अभी तक आगे बढ़ा सकी है और न लीग ही मुसलमानोंको उनके न्यायोचित अधिकार दिल्या सकी है। इसलिए उन्होंने देशकी आर्थिक और राजनीतिक समस्याओंको मुलझानेके लिए एक संयुक्त कार्य-कम बना-कर काम करनेके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियोंको निमन्त्रित किया। कुछ गैरमुसलिम-लीगी मुसलमानोंने भी बम्बई अधिवेशनमें भाग लिया और जमैयतिल उल्लेमके मीलाना अहमद सईदके प्रस्ताव पर जिनाको अधिकार दिया गया कि वे पार्लमेण्टरी बोर्ड नामजद करें।

बोर्डने जून १९३६ में चुनाव-घोषणा-पत्र तैयार कर लिया, जिसमें लीगकी नीतिका इस प्रकार स्पष्टीकरण किया गया था—"जिन मुख्य सिद्धान्तोंपर इमारे प्रतिनिधि विभिन्न विधान-सभाओं में काम करेंगे वे हैं (१) वर्तमान प्रान्तीय और प्रस्तावित केन्द्रीय विधानको रह् कर उनकी जगह फौरन ही प्रजातान्त्रिक स्वराज्य लागू कर दिया गया। (२) और इस बीचमें विभिन्न विधान-सभाओं में मुस्लिम लीगके प्रतिनिधि, राष्ट्रीय जीवनके विभिन्न क्षेत्रों में जनताके भले और उत्थानके लिए, विधानका अत्यधिक लाभ उठानेके लिए विधान-सभाओं का उपयोग करेंगे। जवतक पृथक निर्वाचन कायम है तवतक अनिवार्यतः मुस्लिम लीगको स्वतन्त्रं पार्टीकी हैसियतसे रहना जरूरी है, परन्तु लीग किसी भी दल अथवा पार्टीसे खुला सहयोग करेंगी जिसके सिद्धान्त लीगसे मिलते-जुलते हैं। लीग मुसलमानोंसे अपील करती है कि वे समाजकी एकता मंग करनेवाले किसी भी आर्थिक अथवा अन्य शोपणके शिकार न वने।"

१९३७ में लीगने भारतकी पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना अपना ध्येय वनाया । लीगके इस राजनीतिक निरुचयसे कांग्रेसको लाचार होकर लीगको समान उद्देश्यों और आदशोंपर कार्य करनेवाला मित्र संघटन मानना पड़ा । कांग्रेसने सिर्फ इतना ही नहीं किया कि लीगके उम्मीदवारोंके लिए मुसलिम सीटें (विधान-समाओंमें) छोड़ दीं विक्त अपत्यक्ष रूपसे कांग्रेसने लीगके उम्मीदवारोंको सहायता भी की । सरकारकी संरक्षता और छपा पाये हुए उम्मीदवारोंके लिलाफ कांग्रेस और लीगने संयुक्त रूपसे मोर्चा बनाया । दूसरे स्वोंकी उल्नामें कांग्रेस-लीग एका संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में अधिक उभरा । लेकिन चुनावके बाद कांग्रेसको माल्म हुआ कि मुसलमानोंमें लीगके अनुवादी नगण्य संख्यामें हैं।

हालाँकि १९३५ के ऐक्टके अन्तर्गत हुए चुनावींमें जनसंख्याके सिर्फ १०% मागको ही मताधिकार प्राप्त था मगर उनसे विभिन्न राजनीतिक पार्टियोंके अनुयायियोंका पता लग गया। प्रान्तीय विधान-सभाओंकी १५८५ सीटें १७ विभिन्न राजनीतिक, साम्प्र-दायिक, धार्मिक, व्यापारिक और विशेष हितोंमें वाँट दी गयी थीं । आम सीटें (अछूत सीटें मिलाकर) ८०८ थीं और मुसलिम सीटें ४८२ थीं । इन स्थानींके चुनावींके परिणाम . राजनीतिक पार्टियोंकी स्रक्तिके द्योतक थे। कांग्रेसने लगभग हर आम सीटपर अपना उम्मीदवार खड़ा किया था और ७१५ सीटोंपर विजयी हुई । कांग्रेसने केवल ५८ मुसलिम उम्मीदवार खड़े किये थे जिनमेंसे २६ जीत गये; अधिकांशतः सीमाप्रान्तमें । जहाँ चुनावोंके परिणामोंने कांग्रेसको देशकी राष्ट्रीय संस्था और सबसे अधिक लोकप्रिय सिद्ध कर दिया, वहीं यह भी साफ हो गया कि कांग्रेस मसलमानोंका प्रतिनिधित्व नहीं करती । परन्तु अगर कांग्रेस मुसलमानोंकी नुमाइन्दगी नहीं करती थी तो मुसलिम लीग भो नहीं करती थी । और इस तरीकेसे तो कोई भी एक संघटन पूरे तौरपर उनका प्रतिनि-धित्व नहीं करता था । ४८२ मुस्टिम सीटोंमेंसे छीगको केवल १०८ मिछी । वंगालमें मुस्टिम लीगकी सवसे भारी विजय हुई—११७ स्थानोंमेंसे ४० लीगने जीते—परन्तु दूसरे मुस्लिम वहुसंख्यक स्वोंमें लीग बुरी तरहसे हारी। पंजावमें ८४ सीटोंमेंसे लीग क्षेवल एक पर विजयी हुईँ। उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रान्त और सिन्धमें तो मुस्लिम लीगका कोई भी उम्मीदवार विजयी नहीं हुआ । किसी सूबेमें लीगका मित्रमण्डल वननेकी बात तो छोड़ दीजिये लीग कहीं महत्वपूर्ण शक्ति तक न वन सकी । यह निःसन्देह सावित हो चुका था कि सामन्तवादी वर्गके लोग जो अंग्रेजोंकी सुरक्षामें मुसलमानींके प्रवक्ता वने हुए थे, मुसलिम समाजके प्रति-निधि बिलकुल ही न थे। पंजावमें कांग्रेस (१८ स्थान) और लीग दोनोंको दवकर रहना पड़ा और इनकी जगह सामन्तवादियोंने हे ही जो यूनियनिस्ट पार्टीका नियन्त्रण करते थे। हिन्दू महासभाका तो चित्रमें कोई स्थान ही न था।

इस पृष्टभूमिमें हमें लीगके भावी कार्योपर एक दृष्टि डालनी चाहिये। नेहरूजीका चुनाचिवरलेपण, जैसा कि जिनाको लिखे गये उनके जनवरी १९३७ के पत्रसे ज्ञात होता है, इस तरहसे था। "अन्तिम विश्लेपणमें भारतमें दो ही इंक्तियाँ हैं—अंग्रेजी साम्राज्यवाद और भारतीय राष्ट्रीयताकी प्रतिनिधि कांग्रेस" मुसलिम लीग मुसलमानोंके एक छोटेसे हिस्से—इसमें शक नहीं कि वे लब्बप्रतिष्ट हैं— की प्रतिनिधि है। परन्तु मुसलिम लीग उच्च मन्यम वर्गके ऊँचे मुसलमानोंमें काम करती है। मुसलिम जनतासे इसका कोई सम्पर्क नहीं है और निम्न मन्यमवर्गसे इसका बहुत थोड़ा सम्पर्क है।"

उन स्त्रोंमं जहाँ कांग्रेसका बहुमत था, जब कांग्रेसने मन्त्रिमण्डल बनानेका भार उठानेका निश्चय किया तो मुसलमान मन्त्रियोंका हूँढ़ना इसके लिए एक समस्या वन गयी। सब विधान-सभाओंमें मिलाकर कांग्रेसके कुल २६ मुसलिम उम्मीदवार जीते थे और ऐसा सोचना व्यर्थ था कि वे सभी मन्त्रिपदके वोग्य हैं। कांग्रेस लीग पार्टांके सदस्योंको इस शर्तपर लेनेको तैयार थी कि वे कांग्रेसकी प्रतिज्ञापर इस्ताक्षर कर दें और कांग्रेसमें शामिल हो जायँ! लीगने, विशेषतया यू. पी. में, जहाँ कांग्रेस और लीगका चुनाव-एका ज्यादा मजबूत था, कांग्रेस मन्त्रिमण्डलमें अपने अधिकारके वलपर प्रतिनिधित्व माँगा और दावा किया कि वह मुसलिम समाजकी प्रतिनिधि है, इसलिए मुसलमान मन्त्रियोंको नामजद

कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो जाय, वहुसंख्यक हिन्दुओंकी विश्वासपात्र कांग्रेस कभी भी लीगके साथ सत्तामें वँटवारा करनेको तैयार न होगी।

आज सब तबाही हो जाने और एक ठोस सत्यके रूपमें पाकिस्तान वन जानेके बाद भी ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय कांग्रेस लीगके प्रति उदारता वरत सकती थी जो कि कांग्रेसको सन् १९१६ से चली आयी नीतिके अनुरूप ही होता।

जिना और लीगके अन्य नेता, विशेषतया यू पी. लीगके नेता, कांग्रेसके कट्टर दुष्मन वन गये । जिनाने पहला काम जो किया वह मुसल्मानोंको १९३५ के ऐक्टके खिलाफ प्रदर्शनके लिए कांग्रेस द्वारा आयोजित पहली अप्रैलकी हड़तालमें भाग लेनेसे मना कर दिया और कहा कि वे कांग्रेसको सहयोग न दें । मुसलमान आमतौर पर पहली अप्रैलकी हड़तालसे उदासीन रहे । इससे पहले भी जैसे सविनय अवज्ञा आन्दोलनोंमें भी ज्यादातर मुसलमान ऐसे प्रदर्शनोंमें कभी भी हिन्दुओंके साथ शामिल नहीं हुए थे । और जिनाकी सलाहने सिर्फ उनके हिंग्होणपर मुहर लगा दी ।

नेहरूजीके इस दावेको कि भारतमें सिर्फ दो पार्टियाँ हैं सरकार और कांग्रेस, मुसलमान नौजवानोंने अपने लिए चुनौती तथा ललकार माना। उन्होंने हढ़ निश्चय किया कि लीगको मुसलमानोंकी वास्तविक प्रतिनिधि संस्था वनाकर रहेंगे। कांग्रेसके खिलाफ कोंधके वातावरणमें लीगका अधिवेशन जिनाकी अध्यक्षतामें १५-१७ अक्टूबर १९३७ को लखनऊमें हुआ। अधिवेशनमें आये प्रतिनिधियोंमें एक आहत अहंकी भावना व्यास थी और वे समझते थे कि नेहरूजीके आरोपका एक ही जवाब है कि लीगको जनसंघटन वनाया जाय। एक प्रस्ताव द्वारा लीगका विधान बदल दिया गया और अल्पमतकी सुरक्षा और उचित प्रतिनिधित्व सहित पूर्ण स्वराज्य लीगका ध्येय निश्चित हुआ। एक व्यापक आर्थिक कार्यक्रम बनाया गया जो किसी प्रगतिशील पार्टीका चुनाव-धोषणावत्र-सा जान पड़ता था।

लखनऊ अधिवेदानके पूर्व जिना पंजाब और वंगालके गैर-मुसलिमलीगी मुख्यमिन्त्रयोंसे पत्र-व्यवहार कर रहे थे और जिनाकी कोशिद्य थी कि ये दोनों आदमी लीगको
मुसलमानोंकी संबिटत राजनीतिक पार्टी बनानेके लिए लीगमें सिमलित हो जायँ। पंजाबके
प्रधान मन्त्री सर सिकन्दर हयात खाँ—यूनियनिस्ट पार्टीके नेता (जो कई दलोंकी संयुक्त
पार्टी थी) लखनऊके लीग अधिवेदानमें शामिल हुए और वहाँ जिनाने घोषणा की कि
दोनोंके बीच एक समझौता हो गया है। जिना और सर सिकन्दरके बीच हुई वार्ताके फलस्वरूप यूनियनिस्ट पार्टीके मुसलिम सदस्य लीगमें शामिल हो जानेवाले थे और उनके ऊपर
प्रान्तीय लीग पार्लमेण्टरी वोर्डका अनुशासन लागू होता। जिना और सर सिकन्दर
दोनोंने एक समझौतेपर दस्तखत कर दिये। सिकन्दर-जिना समझौतेके नामसे मशहूर
इस समझौतेमें कहा गया था कि (१) लाहौर पहुँचनेपर सर सिकन्दर एक वैठक
बुलावंगे और अपनी पार्टीके मुसल्मान सदस्योंको लीगमें शामिल हो जानेकी सलाह देंगे।
(२) आगामी चुनावोंमें यूनियनिस्ट पार्टी दोनों दलोंके उम्मीदवारोंका लीगके साथ मिलकर
समर्थन करेगी (यूनियनिस्ट पार्टीमें हिन्दू सदस्य भी थे)। (३) विघान सभाके मुसल्मान
सदस्य मुस्लिम लीग पार्टी वनावंगे।

जिनाने यह भी कहा कि वंगालकी सत्तारूढ़ पार्टी वाने प्रजापार्टीके साथ भी पंजावकी तरह एक समझौता किया जायगा। प्रजा पार्टीमें भी हिन्दू और मुसलमान दोनों शामिल थे। परन्तु पंजाव और वंगालके मुख्य मन्त्री कभी भी लीगके अनुशासनमें कायदेसे नहीं चले। विधान-सभाओं में गये कांग्रेसके सदस्यों (यद्यपि वे अधिकांशतः हिन्दू थे) और

ही गर्के सदस्वों में प्रत्यक्ष अन्तर था। कांग्रेसी सदस्वों ने सरकार-विरोधी उम्मीदवारों की है सियतसे सुनाव जीता था, जब कि अधिकांशतः लीगी सदस्य या तो उपाधिप्राप्त लोग थे या बहे जमीदार घरानों के लोग जो अंग्रेज अधिकारियों के दोस्त या कृपापात्र रहे थे। इस विश्वासक साथ कि भविष्यमें मुसलमान लीग के झण्डेके नोचे जमा होंगे और कांग्रेसी सरकारकी लीग के उपर खास मेहरवानी रहेगी, वे लीग में शामिल हो गये हालां कि उन्होंने सुनावों में लीग का विरोध किया था और कई जगह लीगी उम्मीदवारों को हराया भी। विधान सभा के मुसलिम सदस्य इधर उधर विखरे हुए थे जिनको जिनाने एक सूत्रमें बाँधकर एक दल बना दिया। यह युक्ति इतिहासकी अभूतपूर्व घटना है। इस प्रकारसे लीग मुसलमान प्रतिनिधि संस्था बन गयी। यद्यि सुनावमें यह दावा झुटा सावित हो गया था। दूसरे मुसलिम बहुसंख्यक प्रातों में भी लीगने यही चाल चली जहाँ उसे अलग-अलग मात्रामें सफलता मिली।

जिसको भी पिछले पचास या उससे ज्यादा वर्षोंकी मुसलिम राजनीतिके विकासका इतिहास माल्म है, वह अच्छी तरहसे समझ सकता है कि सामान्यतः मुसलमान कभी भी अंग्रेजोंके विरुद्ध लड़ाईमें हिन्दुओंका साथ नहीं देनेवाले थे। इसके साथ-साथ २० सालके साम्प्रदायिक दंगोंसे जिनाको यह विश्वास हो गया था कि मुसलमान सिर्फ हिन्दू विरोधी नारोंपर ही जाग्रत किये जा सकते हैं। लखनऊ अधिवेशन (१९३७) में यह बात बहुत जोरोंसे कही गयी कि कांग्रेस हिन्दू फासिस्ट राज्य स्थापित करना चाहती है। हिन्दू फासिस्ट राज्य एक नारा वन गया और इस नारेने मुसलम जनताको अपने अल्पसंख्यक अधिकारोंके प्रति जागरूक बना दिया। मुसलमानोंको विश्वास हो गया था कि केवल लीग ही उनके अधिकार दिल्वा सकती है। लीगके साम्प्रदायिक प्रचारका असर मुसलमानोंपर पढ़ा और यू. पी. की विधान समाके उपचुनावोंमें लीगने अधिकांशतः मुसलिम सीट जीत लीं! लेकिन फिर भी कांग्रेसने विजनौरमें लीगी उम्मीदवारको बहुत बुरी तरहसे हराया। हाफिज ह्याहीमने अपने लीगी विरोधीको ७८ फी सदी वोटोंसे हरा दिया! आम चुनावोंमें हाफिज ह्याहीम लीगी उम्मीदवारकी हैसियतसे चुनावमें जीते थे मगर वादमें मन्त्रिपदके लिए वे कांग्रेसमें शामिल हो गये! लीगने उन्हें सदस्यतासे त्यागपत्र देकर कांग्रेसके नामसे दुवारा चुनाव लड़नेकी चुनौती दी! हाफिज इब्रहीमने चुनौती स्वीकार कर ली और लीगको हरा दिया।

कांग्रेसके मन्त्रिपद सम्हालनेक फौरन वादसे ही लीगने कांग्रेस और उसके मन्त्रियों की निन्दा करना और उनके खिलाफ गन्दा प्रचार करना आरम्भ कर दिया। सार्वजनिक भाषणों में मही और गन्दी भाषाका प्रयोग किया जाता और मुसलमानों को समझाया जाता कि उन्हें हिन्दू कांग्रेससे कोई सरोकार नहीं रखना चाहिये। लीगयोंने मुसलमानोंसे कहा कि "अगर तुम मुसलमान हो तो मुसलिम लीगमें आओ।" और मुसलमान लीगमें इस तरहसे आये जैसे यह उनका धार्मिक कर्तव्य हो। इसके पहले कभी भी लीगी मुसलिम जनतामें नहीं युसे थे। अगर उन्होंने ऐसा उचित समय पर किया होता तो आम चुनावके नतीजे दूसरे होते। और तब लीग अपने अधिकारके बलपर मन्त्रिमण्डलमें प्रतिनिधित्य माँग सकती! उसका यह नया उत्साह नेहरूजीके उस वयानके कारण था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देशमें केवल दो पार्टियाँ हैं—सरकार और कांग्रेस।

कांग्रेसी मिन्नमण्डलेंकी स्थित ऐसी नहीं थी कि कोई उससे ईन्ध्यों करता। लीगकी शिकायत थी, जैसा कि जिनाने १५ अक्टूबर १९३७ के अपने भाषणमें कहा था, कि मुसलमानेंको ''उनके (कांग्रेसके) हाथों किसी भी भलाई अथवा न्यायकी आशा नहीं करनी चाहिये।'' और दूसरी तरफ उसी दिन भाई परमानन्दने सिन्ध हिन्दू सम्मेलनके अध्यक्षपदसे भाषण करते हुए कहा कि ''छः हिन्दू प्रान्तोंमें कांग्रेसी मिन्त्रमण्डल हैं और बाकी चार या पाँच स्वोंमें मुसलमानोंने वजारतें बना ली हैं। जब कि मुस्लिम मिन्त्रमण्डल बिना हिन्दुओं और कांग्रेसका ख्याल किये हुए मुसलमानोंके हितोंका ध्यान खते हैं; कांग्रेस मिन्त्रमण्डल अभीतक अपने मुसलिम-हिताय कांग्रेसी प्रचारपर जमे हुए हैं और हमेशा मुसलमानोंकी कभी भी शान्त न होनेवाली साम्प्रदायिक क्षुधाको सन्तुष्ट करनेमें सचेष्ट रहते हैं।'' इसी प्रकार, बंगाल हिन्दू महासभाके सम्मेलनमें फरवरी १९३९ में सावरकरने अध्यक्ष-पदसे भाषण करते हुए कहा—''प्रान्तीय स्वराज्यके पहले हिन्दुओंकी जो हालत थी उसमें कांग्रेसी सरकारोंमें हिन्दुओंकी हालत बदतर हैं।'' आजादीकी लड़ाईमें कांग्रेसी सरकारोंके कुछ 'हिन्दू रंग लिये हुए' निर्णयोंकी शिकायत करते हुए एक प्रस्ताव स्वीकार किया। हालांकि, जमैयतने साथ ही कांग्रेससे मित्रताका अपना निर्णय एक बार फिर दोहराया।

लीगके उग्र साम्प्रदायिक प्रचारसे कांग्रेसको शान्ति-भंग होनेकी आशंका हो उठी थी। इसलिए नेहरूजीने संयुक्त प्रान्तकी मुसलिम लीगके प्रधान मुहम्मद इस्लाम खाँ और फिर जिनासे पत्र-व्यवहार कर उनका ध्यान लीगी वक्ताओं के खतरनाक रवैयेकी ओर दिलाया और उनसे अनुरोध किया कि कांग्रेस और लीगके बीच यदि कोई मतमेद है तो उसे विचार-विनिमय द्वारा दूर कर लिया जाय। यह असफल पत्र-व्यवहार नवम्बर १९३७ से मार्च १९३८ तक चला और वीचमें बड़ा कड़ हो गया। नेहरूजीने बार-बार अनुरोध किया कि मुसलमानोंकी शिकायतों और लीगकी माँगोंकी एक सूची दे दी जाय जो मतमेदोंको दूर करनेकी वातचीतका आधार वन सके, पर जिनाने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वादमें स्वबं गानधीजी और कांग्रेसके अध्यक्षने भी जिनासे पत्र-व्यवहार किया पर कोई नतीजा नहीं निकला।

पत्र-व्यवहारसे निम्नलिखित नयी मांगें प्रकट हुईं, जिनके सम्बन्धमें नेहरू जीने कांग्रेसका दृष्टिकीण रखा, पर कांग्रेस-लीग मनमुटाव चलता रहा—

- (१) वे १४ शर्तें जो मुसल्मि लीगने १९२९ में रखी थीं;
- (२) कांग्रेस साम्प्रदायिक निर्णयका विरोध करना और यह कहना छोड़ दे कि यह निर्णय राष्ट्रीयताकी भावनाके विरुद्ध है;
- (३) प्रान्तीय सरकारोंकी नौकरियोंमें मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व कान्त् वनाकर विधानमें सुरक्षित कर दिया जायः
 - (४) इस्टामी कानून और संस्कृतिकी गारण्टी कानूनके रूपमें हों;
- (५) शहीदगंज मसजिदका आन्दोलन कांग्रेस अपने हाथमें ले और नैतिक दबाव डालकर वह मसजिद मुसलमानोंको दिलवाये;
 - (६) अज्ञान देने और धार्मिक कृत्योंके मुसल्लिम अधिकारोंपर कोई पावन्दी न रहे;
 - (७) मुसलमानोंको गो-वध करनेकी आजादी हो:

- (८) जिन प्रान्तोंमें मुसल्मानोंका बहुमत है, वहाँ क्षेत्रके पुनः विभाजन द्वारा उस बहुमतको बदलनेका प्रयत्न न किया जाय;
 - (९) 'वन्देमातरम्' गाना वन्द कर दिया जाय;
- (१०) मुसलमान चाहते हैं कि उर्दू भारतकी राष्ट्रभाषा हो, और वे कान्नी गारण्टी चाहते हैं कि उर्दूके प्रयोगको सीमित या प्रति-वन्धित न किया जायगा;
- (११) स्वायत्त शासन संस्थाओं में मुसल्यानोंका प्रतिनिधित्व 'साम्प्रदायिक निर्णय' पर आधारित हो, अर्थात् उनकी आवादीके अनुपातमें हो और पृथक निर्वाचन पद्धित काममें लायी जाय;
- (१२) या तिरंगा झण्डा छोड़ दिया जाय, या फिर लीगके झण्डेको भी उतना ही आदर और महत्व दिया जाय;
- (१३) मुसलिम लीगको भारतीय मुसलमानोंकी एक मात्र प्रतिनिधि संस्था मान लिया जाय और सिर्फ लीगको ही मुसलमानोंकी ओरसे वोलनेका अधिकार हो और;
 - (१४) प्रान्तोंमें लीगके साथ संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाये जायें।

अगले वर्ष यह एक माँग और वढ़ गयी कि हर जगह, हर काममें मुसलमानींका आधा हिस्सा मान लिया जाय।

कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल अब सुधार-कार्योमें लग गये थे और विधानके सीमित क्षेत्रके भीतर ही जनहितके काम करनेकी चेष्टा कर रहे थे। नागरिक अधिकारोंकी स्थापनाका काम काफी हद तक पूरा हो चुका था। पुल्सिका सिपाही नये दृष्टिकीणको अपनाना सीख रहा था और उसका आतंक धीरे-धीरे खत्म हो रहा था। शासन गैरमजहवी लोकतांत्रिक ढंगपर चल रहा था और साम्प्रदायिक उपद्रवोंकी संख्या तेजीसे कम होती जा रही थी। इस नयी स्थितिमें लीगका तीत्र और कटु साम्प्रदायिक प्रचार अशान्तिका कारण वन रहा था। वहचा मुसलमानोंपर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलोंके काल्पनिक अत्याचारोंकी कहानियाँ पैला-कर मुसल्म जनताको धर्मके नामपर उभारा जाता था। पिछले ३० वर्षोंके सैकड़ों साम्प्र-दायिक उपद्रवोंके घाव और निशान वाकी थे और हिन्दू-मुसलिम मतभेद स्वाभाविक थे। ये मतभेद बढ़ा-चढ़ाकर दिखाये जाते और इस बातका ढिंढीरा पीटा जाता कि मुसल मानेंकि साथ हर तरहका अत्याचार, अन्याय और दुर्व्यवहार हो रहा है। २० मार्च, १९३८ को मुसल्म लीगकी कींसिलने एक विशेष समिति नियुक्त की जिसका काम इन अत्याचारांकी जाँच कर समय-समय पर कौंसिलको अपनी रिपोर्ट देना था। इस समितिने १५ नवम्बर, १९३८ को अपनी रिपोर्ट कोंसिलको दी। यह रिपोर्ट पीरपुर रिपोर्टके नामसे मशहूर है। ल्खनकके एक दैनिकके एक मुसलमान उपसंपादकने लखनकमें इंटकर ही रिपोर्टका अधिकांश भाग लिखा था । साम्प्रदायिक अत्याचारीं, वन्देमातरम्के गान, सार्वजनिक इमारतींपर कांग्रेसका झण्डा पहराना, हिन्दीका प्रचार आदिकी शिकायत करते हुए रिपोर्टमें कहा गया था कि कांग्रेसी सरवारें हिन्दूराजकी स्थापनामें सचेष्ट हैं, जिसमें भारतीय, मुसलमानींके धर्म, भाषा व संस्कृतिके दमन और उनके राजनीतिक व आर्थिक अधिकारोंके इननका ध्येय निहित है। यह भी आरोप लगाया गया था कि मुस्लमानोंक कदिस्तान वन्द किये जा रहे हैं और मुसल्मि छात्रोंके वजीफे रोक दिये गये हैं । इन आरोप लगानेवालों और शिकायत करनेवालोंको वार-वार कांग्रेसी नेताओं द्वारा चुनौती दी गयी कि साम्प्रदायिक अत्याचारोंकी

विशिष्ट घटनाएँ वतायी जायँ, पर इसका सीधा जवाव कभी नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्ल-मेण्टरी वोर्डके आदेश पर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलोंने लीगके आरोपोंकी जाँच करायी और उनके निराधार होनेकी पुष्टि करते हुए लम्बी लम्बी विज्ञासियोंमें आरोपोंके जवाब दिये। तब पार्ल-मेण्टरी वोर्डके अध्यक्ष चल्लभभाई पटेलने कांग्रेसी प्रधान मन्त्रियोंसे कहा कि वे अपने-अपने गवर्नरोंका ध्यान लीगके आरोपोंकी ओर आकृष्ट करायें। यह हुआ और गवर्नरोंने आरोपों-को निराधार माना।

कांग्रेसका जवाब उसके जनरल सेक्रेटरी जे. बी. कृपालानीकी वार्षिक रिपोर्टसे परिलक्षित हैं। रिपोर्टमें कहा गया था—''राष्ट्रीय झण्डा सन् १९२० से ही राष्ट्रीय एकता और विदेशी शासनके विरोधका प्रतीक रहा है। वह इस्लामके विरोधमें नहीं अपनाया गया था। वन्देमातरम् ऐतिहासिक लगावके कारण इस शताब्दिके प्रारम्भसे ही राष्ट्रीय गान बन गया था और वंग-भंगके समय प्रचलित हुआ था। इसके विरुद्ध मुसलिम आन्दोलन एक नयी वात है और कांग्रेसने इस गानेके केवल उसी अंशके गाये जानेको मान्यता दी है, जिसपर किसीकी आपित्तको सम्भावना नहीं है। जिस मिली-जुली भाषाका कांग्रेस प्रचार करती है, वह उत्तर भारतमें बोली जानेवाली हिन्दुस्तानी है, जो नागरी या उर्दू लिपिमें लिखी जाती है। ये सब वातें पुरानी हैं, पर लीग द्वारा उनका विरोध नया है। तब भी, जहाँ भी विरोध हुआ है, कांग्रेसी सरकारों और कांग्रेसजनोंने संघर्ष बचाया है।''

पर लीगने इन जवाबोंपर कोई ध्यान नहीं दिया और लीग कार्य-समितिने आरोपोंको दोहराते हुए कहा कि प्रान्तीय स्वराज्यका नतीजा यह हुआ है कि अल्पसंख्यक मुसलमानोंको हिन्दुओंने दबा लिया है और प्रतिदिन मुसलमानोंके जीवन, स्वतंत्रता, सम्पत्ति और मान मर्यादापर आक्रमण होता है।

कांग्रेस सरकारोंके विरुद्ध निराधार आरोपोंकी पुनरावृत्ति जारी रहनेपर कांग्रेस अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसादने जिनासे कहा कि लीगकी शिकायतोंकी निष्यक्ष जाँच भारतके चीफ जिस्टिस सर मौरिस ग्वायर या किसी अन्य व्यक्तिसे करा ली जाय। पर जिनाने यह प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए कहा-''अव इस मसलेपर हिज एविसलेंसी (वाइसराय) खुद गौरकर रहे है, और वही ऐसे उपयुक्त व्यक्ति हैं, जो हमारी माँगें पूरी करनेके लिए उचित कदम उठा सकते हैं और कांग्रेस मन्त्रिमण्डलवाले प्रान्तोंमें हममें पूर्ण सुरक्षाकी भावना फिर ला सकते हैं।" लेकिन न तो वाहसराय और न कोई गवर्नर ही जिनाकी शिकायतोंका समर्थन करते हुए कोई वक्त व्य देनेको आगे आया। बादमें जिनाने मांग की कि हमारे आरोपोंकी जाँचके लिए एक शाही कमीशन वैठाया जाय । ब्रिटिश सरकारने यह माँग अस्वीकार कर दी । कांग्रे एने अपनी ओरसे कांग्रेस मन्त्रिमण्डलवाले प्रान्तोंके अँग्रेज गवर्नरोंको दावत दी कि वे कांग्रेस सरकारोंका एक भी काम ऐसा वता दें जिससे अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसंलमानोंके किसी हितपर आँच आयी हो । इस सम्बन्धमें कांग्रेस मन्त्रिमण्डलोंके खिलाफ गवर्नरोंको कोई शिकायत नहीं थी । रिटायर होनेके वाद, संयुक्तप्रान्तके गवर्नर हेरी हेगने खुले आम कहा कि कांग्रेस सरकारका मुसलमानोंके साथ बहुत ही न्यायसंगत और उचित व्यवहार रहा। अत्याचारोंकी इन शिकायतोंकी जाँच करानेके हर सुझाव और चुनौतीको लीग चुपचाप पीती गयी और शिकायतोंका उपयोग मुसलमानोंको साम्प्रदायिक बनानेमें करती रही। कांप्रेस-

का हर काम, हर चीज—झण्डा, राष्ट्रीय गीत, बुनियादी तालीम, जनतासे सम्पर्क स्थापित करनेका कार्यक्रम—लीगको इस्लाम विरोधी लगता रहा ।

सितम्बर, १९३८ में मुसलिम लीगका जो वार्षिक जलसा पटनेमें हुआ, उसमें अध्यक्ष पदसे भाषण करते हुए जिनाने मुसलिम लीगके कार्यकलाप या कार्यक्रम, आदिका जिक न कर मुख्य रूपसे कांग्रेस सरकारोंके विरुद्ध शिकायतोंकी फेहरिस्त प्रस्तुत की थी। वास्तवर्मे लीगका कार्यक्रम ही नकारात्मक था। लीगकी कौंसिलने संयुक्त-प्रान्त, विहार व मध्यप्रान्तमें, 'मुसलमानोंके साथ होनेवाले अत्याचारोंके खिलाफ सीधी काररवाई' की तैयारी करनेको कहा। छीगके नेताओंकी इन उत्तेजक वातोंके बीच-बीच कांग्रेसके नेता जिनासे पत्र-व्यवहार करते और जिना हमेशा इस वातपर अडते कि दोनों संस्थाओं के बीच समझौतेकी पहली और वुनियादी शर्त है कि मुसलिम लीग मुसलमानोंकी एकमात्र प्रतिनिधि राजनीतिक संस्था हैं जो उनकी ओरसे वात कर सकती है और इसी तरह कांग्रेस हिन्दुओंकी संस्था है। वे कहते कि यह द्यर्त मान लेनेसे हिन्दू मुसलिम समस्या आसानीसे हल हो जायगी। कांग्रेस यह आधार ही माननेको तैयार नहीं थी। वह अपने इस जिन्दगी भरके दावेको केंसे भूल जाती कि वह पूरे भारतीय राष्ट्रका प्रतिनिधित्व करती है। फिर कांग्रेस लीगकी मुसलमानोंकी एकभात्र प्रतिनिधि संख्या मान भी कैसे सकती थी, जब कि जमेंअत, अहरार, खुदाई खिदमतगार, वंगालकी कृपक प्रजापाटीं, खाकसार आदि मुसलिम संस्थाएँ लीगसे विलक्कल भिन्न दृष्टिकोण रखती थीं और मुसलमानोंके विभिन्न वर्गोंका प्रतिनिधित्व करती थीं। इनमेंसे कुछ संस्थाओंने कांग्रेससे कन्धेसे कन्धा मिलाकर आजादीकी लड़ाई लड़ी थी। लीगका दावा मान हेनेसे कांग्रेसको इन संस्थाओंको प्रतिनिधित्वहीन मानना पहता। पर जिना अड़े रहे ।

अक्टूबर, १९३८ में ही सिन्ध-प्रान्तीय मुसिलम लीगने अपने वापिक अधिवेदानमें देशके वेंटवारेकी माँगका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस प्रकार विभाजनकी माँगमें वह भारतीय मुसिलम लीगसे १७ महीने आगं रही। इस अधिवेदानकी अध्यक्षता भी जिना ने की थी। प्रस्तावमें कहा गया था—''सिन्ध मुसिलम लीगका यह सम्मेलन इस विद्याल देशकी शान्ति, निर्वाध सांस्कृतिक विकास, हिन्दू व मुसलमानों दोनों राष्ट्रोंके राजनीतिक आस्मिणिय और आर्थिक व सामाजिक वेहतरीके लिए आवश्यक समझता है कि भारत दो संवोंमें विभाजित कर दिया जाय, एक संघमें मुस्लिम राज्य रहे, दूसरेमें हिन्दू राज्य।" कांग्रेसके मित्रमण्डल भंग होनेका पायदा उठाकर लीगने कांग्रेसको और भी बुरा-भला कहा और मित्रमण्डल संग होनेका पायदा उठाकर लीगने कांग्रेसको और भी बुरा-भला कहा और मित्रमण्डल खत्म होनेपर देश भरमें 'मुक्ति दिवस' मनाया। उस दिन भागणोंमें खुदाका शुक्तिया अटा किया गया कि कांग्रेसी सरकारोंका खारमा हुआ और मुसलमानोंको अन्याय, दमन तथा अत्याचारोंसे मुक्ति मिली। इस 'मुक्ति दिवस' की घोपणा जिनाने तय की जब साम्प्रदायिक झगड़ेके निवटारेके लिए वे और जवाहरलाल नेहरू मिलनेवाले थे। वह वातचीत पिर हुई नहीं।

लीगके कांग्रेस-विरोधी स्खकी पराकाष्टा तव हो गयी जब मार्च, १९४० में लीगके लाहौर अधिवेशनमें एक प्रस्ताव द्वारा भारतके विभाजनसे हिन्दुओं और मुसल-मानोंको दो अलग अलग 'मातृ-भूमि' बनानेकी माँग की गयी। हमेशाकी तरह जिना यहाँ भी अध्यक्ष थे और उन्होंने अपने भाषणसे देशको अचमभेमें डाल दिया। उन्होंने कहा—

''हमारे हिन्दू दोस्त क्यों हिन्दू-धर्म व इस्लामकी असिल्यत नहीं समझ पाते, यह समझना वड़ा मुश्किल है। हिन्दू व इस्लाम सही अर्थोंमें धर्म नहीं, दो मिन्न सामाजिक व्यवस्थाएँ हैं और यह सोचना कि वे मिलकर कभी एक राष्ट्र बना सकेंगी स्वप्नमात्र है। एक भारतीय राष्ट्रकी गलत कल्पना अपनी सीमा पार कर हमारे अधिकांश कछोंका कारण वन चुकी है, और यदि हम शीव्र ही इस कल्पनाको खत्म कर वस्तु-स्थित न समझ पाये तो देश वर्वाद हो जायगा। हिन्दू व मुसलमान दो मिन्न धार्मिक दर्शनों, सामाजिक रीतियों और साहित्योंके हैं। वे एक दूसरेसे शादी-विवाह नहीं करते, एक दूसरेके साथ खाते नहीं, वे दो मिन्न सम्यताओं हैं और ये सम्यताएँ परस्पर-विरोधी विचारों और धारणाओंपर आधारित हैं। उनके जीवनके और जीवनके सम्वन्धमें मिन्न दृष्टिकोण हैं। इतिहासके विरोधी तत्वोंसे उन्हें अपनी अपनी प्रेरणा मिलती है। उनके बीर मिन्न हैं, वीर गाथाएँ मिन्न हैं, उनकी कथाएँ मिन्न हैं। बहुधा ऐसा होता है कि एकका चीर दूसरेका शत्रु है और इतिहासके युदोंमें एककी पराजय दूसरेकी विजय होती है। ऐसे दो मिन्न राष्ट्रोंको एक ऐसे राज्यमें रख देनेसे, जिसमें एकका बहुमत हो और दूसरेका अल्पमत, असन्तोष हो बढ़ेगा और अन्ततः ऐसे राज्यकी सरकारका ताना-वाना टूट जायगा।"

यह वकालत घर कर गयी और एक प्रस्ताव पासकर लीगने इसपर अपनी मुहर लगा दी। इस ऐतिहासिक लाहौर प्रस्तावमें कहा गया था—"निश्चय किया गया कि अखिल-भारतीय मुसलिम लीगके इस अधिवेशनका यह निश्चित मत है कि कोई भी ऐसा वैधानिक सुधार न तो लागृ हो सकेगा और न मुसलमानोंको मान्य होगा जो निम्नलिखित मूल सिद्धान्त-पर आधारित न हो—िक, भौगोलिक क्षेत्रोंकी ऐसी इकाइयाँ बनायी जानी चाहिये और उनमें इस प्रकार आवश्यक परिवर्तन कर देने चाहिये कि सीमाप्रान्त और पूर्वी भारत आदिके मुसलिम बहुमतके क्षेत्र 'स्वतन्त्र राज्य' बनाये जा सके जिसमें शामिल होनेवाली इकाइयाँ स्वाधीन और स्वतन्त्र हों।"

लेकिन भारतमें दो राष्ट्रोंका सिद्धान्त जिनासे पहले सावरकरने चलाया था। १९३७ में, हिन्दू महासभाके अहमदाबाद अधिवेशनमें सावरकरने कहा—'वहुतसे वालकों जैसी बुद्धिवाले राजनीतिज्ञ यह माननेकी भारी भूल कर बैठते हैं कि भारत एक राष्ट्रके रूपमें संघिटत हो चुका है, या इच्छा मात्रसे हो सकता है। इस प्रकार हमारे सद्भावनापूर्ण किन्तु अविचारशील मित्र अपने स्वप्नोंको ही वस्तुस्थित समझ लेते हैं। और इसीलिए वे साम्प्रदायिक गुरिथयोंसे खीज उठते हैं और उनका दोष साम्प्रदायिक संघटनोंपर मढ़ देते हैं। लेकिन तथ्य यह है कि तथाकियत सम्प्रदायिक प्रकार हमें, हिन्दुओं और मुसलमानोंको शताब्दियोंके राष्ट्रीय, सांस्कृतिक व धार्मिक विरोधोंसे उत्तराधिकारमें मिले हैं। जब समय आयगा ये सवाल हल हो जायँगे; लेकिन इस वातके अस्तित्व मात्रसे ही इनकार कर उन्हें दवा देनेसे समस्या मुलझेगी नहीं। पुरानी वीमारीका निदान और उपचार उसके प्रति लापरवाह होनेसे ज्यादा अच्छा है। हमें साहसके साथ अरुचिकर तथ्योंका सामना करना चाहिये। भारत एक और एक स्त्रमें विधा राष्ट्र नहीं माना जा सकता, अपितु, यहाँ मुख्यतः दो—हिन्दू व मुसलमान राष्ट्र हैं।"

१९३९ में हिन्दू महासभाके कलकत्ता अधिवेशनमें सावरकरने फिर कहा—"हममें आपसमें चाहे जितने मतभेद हों, हम हिन्दू धर्म, संस्कृति, इतिहास, जाति, भाषा आदि अनेक एकताओं और समानताओं से इस प्रकार एक स्त्रमें वैंधे हैं कि किसी अन्य अहिन्दू जाति जापानी, अंग्रेज, या भारतीय मुसलमान किसी के समक्ष खड़े होते ही हम एक राष्ट्र प्रतीत होने लगते हैं। इसी कारण हम हिन्दुओं को कश्मीरसे मद्रास और मिन्धसे आसाम तक अपनेमें अलग एक हिन्दू राष्ट्र बनाना है।..."

लेकिन सावरकर हिन्दू भारत व मुसलमान भारतके रूपमें देशके दो दुकड़े नहीं करना चाहते थे। वे केवल हिन्दू बहुमतके लिए प्रमुख स्थान चाहते थे। वे कहते थे—"हिन्दू-महासभा 'एक व्यक्ति एक वोट' के सिद्धान्तमें विश्वास करती है, सरकारी नौकरियाँ योग्यताके आधारपर मिलती हैं, जाति या धर्मके भेद भूलकर सब नागरिकोंको एकसे मौलिक अधिकार और कर्त्तव्य मिलते हैं...जब ऐसी स्थिति हो तब अल्पसंख्यकोंके पृथक अधिकारोंकी वात सिद्धान्ततः अनावश्यक हो नहीं गलत भी होगी, क्योंकि इससे साम्प्रदायिक स्तरपर अल्पमत और बहुमतकी चेतना फिर शुरू होगी।"

अत्याचारोंकी कपोलकल्पित कहानियोंकी पृष्ठभूमिमं आये लाहीर प्रस्ताबने शिक्षित मुसलमानींका ध्यान खींच लिया और वे जिहादके उत्साहसे लीगके आन्दोलनमें भाग लेने लगे। इनमें भी कुछ लोग थे जो हिन्दू मुसलिम समस्याका कोई समाधान पाकिस्तानकी स्थापनामें नहीं पाते थे। वे कहते थे कि हिन्दू बहुमतवाले प्रान्तोंमें तो मुसलमान हिन्दुओंपर ही आश्रित रहेंगे और मुसलिम बहुमतवाले प्रान्तोंमें मुसलमानोंको उचितसे अधिक मुविधाएँ मिल जायँगी। इसके जवाबमें कहा जाता कि अपने बहुमतवाले प्रान्तोंमें अगर हिन्दू मुसलमानोंके साथ अत्याचार करेंगे तो वैसा ही व्यवहार मुसलिम बहुमतवाले प्रान्तोंमें हिन्दुओंके साथ होगा और यही डर दोनों जगहोंके बहुमतोंको सद्व्यवहारकी प्रेरणा देगा। व्यावहारिक जीवनमें झुठे आरोपोंकी गुंजाइश काफी होनेके कारण दोनों जगहोंके अल्पमत उन वित्योंकी स्थितिमें होनेकी आशंकामें होते जो अन्य स्थानोंके लोगोंके सद्व्यवहारकी गारण्टीके तौरपर पकड़े गये हों। बहुत सी नयी मुसलिम संस्थाएँ वन गयीं जो मुसलमानोंको तस्वीरका दूसरा रख दिखानेकी कोशिश करने लगीं। लेकिन ये सब संस्थाएँ मिलकर भी लीगका मुकावला नहीं कर सकती थीं। लीग अब मुसलमानोंकी सार्वजनिक संस्था हो रही थी।

वाइसरायने मुसलिम लीगको मुसलमानोंकी एकमात्र प्रतिनिधि-संस्था मान लिया और उन्होंने जब फिर गान्धीजी, जिना व कांग्रेस अध्यक्षको यह बतानेके लिए बुलाया कि में अपने पुराने वक्तन्यको संशोधित कर अपनी कार्यकारिणो कांसिलमें कुछ नेताओंको लेनेको तैयार हूँ, तब उन्होंने यह शर्त लगा दी कि कांग्रेस लीगसे सिर्फ केन्द्रीय कार्यकारिणी कांसिलके सम्बन्धमें ही नहीं, विल्क प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलोंके बारेमें भी समझीता कर ले। कांग्रेसके लिए मुख्य प्रश्न यह था कि वाइसराय सत्ताका इस्तांतरण करना चाहते हैं कि नहीं। लीग राजनीतिक माँगकी और उदासीन थो। लीग कोंसिलकी जो बैठक युद्धकी घोषणासे उत्पन्न परिस्थितिपर विचार करनेके लिए बुलायी गयी थी, वह कांग्रेस सरकारोंके खिलाफ आरोप लगाकर स्थिगत हो गयी। जिना ब्रिटिश सरकार या कांग्रेससे वात करनेमें पाकिस्तानकी शर्त सबसे पहले रखते थे। उनकी दूसरी शर्त यह होती थी कि वाइसरायकी कोंसिलमें यदि कांग्रेस शामिल होती है तो हिन्दू व मुसलमान सदस्योंकी संख्या वरावर हो, नहीं तो जितने नये सदस्य होनेवाले हों उनका बहुमत मुसलमान हो और मुसलिम प्रतिनिधियोंको लीग चुने।

वाइसरायने यह भी साफ कह दिया था कि राजनीतिक नेता मेरी कौंसिलमें आनेको स्वतन्त्र हैं, पर मेरे अधिकार पहलेकी तरह ही रहेंगे।

मुसलिम राजनीतिके नये दौरने जिनाको विलकुल वदल दिया। वे कभी भी सच्चा दोनो ईमानवाला, पाक और मुसलमान नहीं माने जाते थे। "विधान सभाके सदस्य होनेपर शपथके समय कुरान चूमनेके सिवा कभी कुरानमें क्या लिखा है और इसलाम क्या है, वह जाननेकी फिक्र करते किसीने उन्हें नहीं देखा। इसमें भी शक है कि वे जिज्ञासा या धर्मकी भावनासे प्रेरित रोकर कभी मसजिद गये हों। मुसलमानोंके धार्मिक या राजनितिक सार्वजनिक समारोहोंमें वे कभी नहीं देखे गये।" पर अब जिना मुसलिम जनताके थे—उसके कायदे आजम (बड़े नेता) थे। वे कुरान और इस्लाममें विश्वास ही नहीं करने लगे, उसके लिए मरनेको भी तैयार हो गये। वे मसजिदमें जाकर खुतवा सुनते और ईदकी नमाजमें शामिल होते! मुसलमानोंकी कोई सभा अला हो अकवर और 'कायदे-आजम जिन्दावाद' के विना शुरू या खत्म न होती।

जिनाने हिन्दू-विरोधी भावना कभी कम नहीं होने दी। अगस्त सन् १९४२ में जब उत्तेजित लोग ब्रिटिश सत्ता उखाड़ फेंकनेके लिए प्राणपणसे सचेष्ट थे, लीग कार्यसमितिकी १६ से २० अगस्त तक हुई बैठकमें कांग्रेस आन्दोलनको "हिन्दू अस्पजन समुदायको सत्ता सौंप देनेके लिए ब्रिटिश सरकारको बाध्य करने ही नहीं वरन् मुसलमानोंको भी कांग्रेसकी शत्तें माननेके लिए मजबूर करने" की संशा दी।

अव अंग्रेज गर्वनरोंकी सहायतासे लीग अपना प्रभाव गैरलीगी प्रान्तोंमें भी वढ़ानेमें सचेष्ट हुई । २८ मार्च १९४३ को वंगालके गवर्नर तर जीन हुर्वर्टने वहाँके प्रधान मन्त्री फजलुल हकको इस्तीफा देनेको वाध्य किया और वहाँ लीगी मन्त्रिमण्डल कायम कर दिया। फजलल इक ग्रुरूमें कांग्रेसी और राष्ट्रीय मुसलमान थे लेकिन परस्थितियोंके दास होनेके कारण उन्होंने वैगालके प्रधान मन्त्रीकी हैसियतमें कई बार अपनी राजनीति बदलो । विधान सभामें वे हिन्दुओं व मुसलमानोंकी संयुक्त प्रजा पार्टीके नेता थे; जिनाके आमन्त्रणपर वे लीगमें ज्ञामिल हो गये और ऐसे कहर लीगी वने कि १९४० में लाहौरमें पाकिस्तानकी स्थापनाकी माँगवाला प्रस्ताव पेश किया । फिर अपने भाषणमें उन्होंने हिन्दुओंको धमकाना गुरू किया कि "हममेंसे हर एक होर और चीता है।" दिसम्बर १९४१ में उन्होंने अपने मन्त्रिमण्डलका इस्तीफा दिया और एक दुसरा मन्त्रिमण्डल वनाया जिसमेंसे कुछ लीगो सदस्य निकाल दिये गर्चे थे । १९४२ के ग्ररूमें लाहौर प्रस्तावकी अपनी यह अनोखी व्याख्या कर कि वह वंगाल-पर लागू नहीं होगा, उन्होंने अपनेको लीगकी ओरसे अनुशासनकी काररवाईका शिकार वना लिया । पर शीव ही फिर उन्होंने लीगकी सदस्यताके लिए अर्जी दी, जो नामंजूर हो गयी । संयुक्त प्रान्तके वाद वंगाल ही ऐसा प्रान्त था जहाँ १९३६ के चुनावमें लीगको काफी स्थान ्रिमल गर्ये थे। तबसे बंगाल विधान समाके मुसल्मि लीगी दलमें और सदस्य भी शामिल हुए थे। कुछ यूरोपीय सदस्य भी इसमें शामिल हुए। लेकिन २५० सदस्योंमेंसे १५० अव भी फजलुल हकके साथ थे । पर गवर्नरको मन्त्रिमण्डल वरखास्त करनेका हमेशा अधिकार था। ३० मार्च, १९४२ को गवर्नरने हकको बुलाया और इस्तीफेके एक टाइप किये हुए कागज पर दस्तखत करनेको कहा। गवर्नरने कहा कि अगर आप इस्तीके पर दस्तखत नहीं करते तो में आपको वरखास्त कर दूँगा । हकने इस्तीफे पर दस्तखत कर दिये और

विधान सभामें छोटकर इसकी घोषणा कर दी । उनका अपराध यही था कि अगस्त १९४२ में ढाकामें हुए गोछीकाण्डकी जाँचके छिए एक समिति नियुक्त करनेका आस्वासन उन्होंने विधान सभामें दिया था । गवर्नरने अपदृष्ट्य कर उन्हें सजा दी और छीगी सर नाजिमुद्दीनको मन्त्रिमण्डळ बनानेका आमन्त्रण दिया । वे जानते थे कि विधान सभाके दुछमुळ सदस्योंकी सहायतासे छीगी मुख्य मन्त्री शीव ही अपना बहुमत कायम कर छैंगे।

ऐसा ही नाटक सिन्धमें खेला गया । वहाँ अल्लाह्बरूश प्रधान मन्त्री थे जो राष्ट्रीय मुसलमान थे । अंग्रेजोंकी दमन-नीतिके विरोधमें उन्होंने खानवहादुरीका खिताव छोड़ दिया । उन्हें बरखास्त कर गवर्नरने लीगी मन्त्रिमण्डल बना दिया । पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तमें विधान सभाके कांग्रेस दलकी शक्ति दस सदस्योंकी गिरफ्तारीके कारण घट गयो थो; वहाँ भी लीगका मन्त्रिमण्डल बन गया । इसी तरह आसाम भी मुसलिम लीगका प्रान्त हो गया ।

अंग्रेजोंकी मददसे पाँच प्रान्तोंमें लीगके मन्त्रिमण्डल वन गये और मुसलिम समाजके नेता होनेका जिनाका दावा सही सावित कर दिया गया । अप्रैल १९४४ में पंजाबके प्रधान मन्त्री खित्रहयात खाँ (जो १९४३ में सिकन्दर हयात खाँकी मौतके वाद प्रधान मन्त्री हुए थे) और जिनामें मतभेद हो गया क्योंकि जिना चाहते थे कि मन्त्रिमण्डल यूनियनिस्ट पाटोंका न कहकर मुसलिम लीग संयुक्त पाटींका कहा जाय और खिज्रहयात यह माननेको तैयार नहीं थे। वे कहते थे कि हम जिना-िकन्दर हयात समझौतेको लागु कर रहे हैं जब कि जिना अपने वादेके खिलाफ जा रहे हैं। उस समझौतेके अनुसार पंजानकी विधान सभामें मुसिल्मि लीग दल वननेपर यूनियनिस्ट पार्टीका मन्त्रिमण्डल रहनेकी वात थी। खिज्रहयातने एक वक्तन्यमें कहा—१९२५ के कान्नके अन्तर्गत हुए चुनावमें मुसलिम लीगका मन्त्रिमण्डल किसी भी प्रान्तमें नहीं वन सका जिससे लीग और उसके नेता मिस्टर जिनाको अखिल भार-तीय स्तरपर समझौतेकी कोई बात करनेमें बड़ी दिक्कत होने लगी। मिस्टर जिनाके मुसल-मानोंके मान्य नेता होनेमें जो संशय किया जाता था, उसे दूर करने और उन्हें पूरे मुसलिम समाजका प्रतिनिधि होनेका रुतवा देनेके लिए, ताकि वह अखिल भारतीय मामलोंमें दूसरे दलोंसे समझीता कर सकें या वातचीत कर सकें सिकन्दरह्यात खाँने अक्तूबर १९३७ में जिना-सिकन्दर समझौता किया । अय मिस्टर जिना प्रान्तीय मामलोंमें इस्तक्षेप करना चाहते हैं और मन्त्रिमण्डल वनानेवाली पार्टांके संचालनमें वाधा डालते हैं। इस रुखमें कोई ओचित्य नहीं है और इससे तानाशाही तरीकोंकी गन्य आती है। समझौतेमें यह साफ साफ कहा गया था कि विधान समामें मुसल्लिम लीग दल वननेसे यूनियनिस्ट पार्टीके 'वर्तमान' गुटपर कोई प्रभाव न पड़ेगा और 'वर्तमान' मिलाजुला संयुक्त गुट अपना यूनियनिस्ट पार्टीका नाम कायम रखेगा। अब मिस्टर जिना चाहते हैं कि यह नाम बदलकर 'मुसलिम लीग संयुक्त (फोलीशन) दल' रख दिया जाय । यह समझौतेका उल्लंघन है । में सच्चे मुसलमान और और इस्लामके पैगम्बरके अनुयायीकी हैसियतसे बादा तोड़नेका गुनाहगार नहीं वन्ँगा। "खिज्रह्यात असलमें यूनियनिस्ट पार्टांके हिन्दू व सिख सदस्योंको नाराज कर अपना मुख्य मन्त्रित्व खतरेमें नहीं डालना चाहते थे। लेकिन उन्होंने लीग और पाकिस्तान प्रस्तावमें अपना विक्षास प्रकट किया । लेकिन यह विक्ष्यास और निष्ठा व्यावहारिक राजनीतिमें कभी काम नहीं आयी। लीगी मुख्य मन्त्रियोंने (जिनमें खित्र भी शामिल थे) युदकी तैयारियोंमें पूरा सहयोग दिया और हर तरहका अपमान भी वरदायत किया । वे जानते थे कि गवर्नर और अफसर राजनीतिक आन्दोलनके दमनसे और राजनीतिक कैंदियोंके साथ व्यवहारसे सम्बन्धित मामलोंमें उनकी उपेक्षा करते हैं। कैंदियोंको हर तरहकी यातनाएँ दी जातों, और अगर वे इसमें इस्तक्षेप भी करना चाहते तो भी उनके आदेशोंका पालन न होता। वे कैंदियोंसे मिल नहीं सकते थे। कैंदी प्रधान मन्त्रीके पास जो शिकायतें भेजते, उन्हें अफसर बीचमें ही रोक लेते। लेकिन तब भी इससे जिनाको अखिल भारतीय मुसलिम नेताका महत्व तो प्राप्त हुआ ही और ब्रिटिश सरकारने भी उनका यह महत्व स्वीकार कर लिया।

अध्याय २८

युद्धविरोधी सत्याग्रह तथा क्रिप्स-प्रस्ताव

ं अंग्रे जों के एक ओर भारतको गुलाम वनाये रखने और दूसरी ओर जनतन्त्र और आत्मिनिर्णयके अधिकारके लिए लड़नेकी घोषणा करनेसे राष्ट्रीय भारतका कीध और खीझ वढ़ रही थी। जनता वेसब्रीसे कांग्रे सकी सार्वजिनक आन्दोलन छेड़नेकी घोषणाकी प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन सत्याग्रहके नेता-प्रणेता गान्धीजीको वेसब्री नहीं थी। संवर्ष छेड़नेके पहले समझौतेके सभी उपाय कर देखना ही उनकी अहिंसाकी नीति थी।

लेकिन कांग्रेस कैसे सोच रही थी, इसका संकेत मार्च १९४० में रामगढ़के वार्षिक अधिवेशनमें मिल गया। इजारीवाग (विहार) के इस गाँवमें हुआ कांग्रेसका यह सबसे संक्षित अधिवेशन था। एक तो देशकी परिस्थित कामकी वात झटपट कर डालनेकी माँग कर रही थी, दूसरे वर्षा वड़े जोर शोरसे हो रही थी और अधिवेशनका मैदान झील वन गया था। एम. एन. रायको १८३ के खिलाफ १८६४ वोटोंसे हराकर अध्यक्ष निर्वाचित हुए अबुलकलाम आजादने अधिवेशनके एक मात्र प्रस्तावकी भूमिका सी देते हुए अपने भाषणमें कहा—"भारत नात्सीवाद या फासिटीवादका भविष्य सहन नहीं कर सकता पर ब्रिटिश साम्राज्यवादसे वह और भी ऊव चुका है। यदि भारतको स्वतन्त्रताका अपना अधिकार नहीं मिलता, तो इसका अर्थ यही होगा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपनी तमाम परम्पराओं और विशेषताओं के साथ पनप रहा है। और ऐसी हालतमें भारत इसकी विजयमें मदद करनेके लिए किसी तरह भी तैयार न होगा।"

अध्यक्षके भाषणके बाद जवाहरलाल नेहरूने घोर वर्षाके बीच प्रस्ताव पेश किया जो लगभग एक मतसे स्वीकार हो गया—सिर्फ सात या आठ मत उसके विरोधमें आये। प्रस्ताव में कहा गया था कि ब्रिटिश सरकारकी ओरसे दिये गये सभी वक्तव्य यह बात स्पष्ट करते हैं कि युद्ध साम्राज्यको मजबूत बनाने और कायम रखनेके लिए ही लड़ा जा रहा है। ऐसी हालतमें कांग्रेसजन या कांग्रेस द्वारा प्रभावित लोग इस युद्ध में सहायता न देनेकी ओर पहला कदमके बाद "सविनय अवज्ञाका दूसरा कदम कांग्रेस विना हिचक तव उठायेगी जैसे ही कांग्रेस संघटन इस कामके लिए उपयुक्त मान लिया जायगा, वा परिस्थित ऐसी हो जायगी जिसमें संकटकी घड़ी आसन्न हो।"

कांग्रेसने यह आन्दोलन चलानेके लिए गान्धीजीको सेनापित बनाया और गान्धीजीने तरन्त ही अपने आन्दोलनका स्त्रपात भी कर दिया । अपने भाषणमें उन्होंने आदेश दिया कि "हर कांग्रेस समिति सत्याग्रह समिति वन जाय और ऐसे कांग्रेसजनोंकी फेहिरिस्त बनाये जो सबके प्रति सद्भावनासे प्रेरित हों, जिन्हें किसी भी प्रकारकी अस्पृश्यतामें विश्वास न हो, जो नियमित रूपसे कताई करते हों और जो दूसरे कपड़े छोड़कर केवल खादी पहननेके आदी हों।" जो इन शतोंको पूरा करते थे और जेल जानेको तैयार थे उन्हें गान्धीजीने सिक्षय सत्याग्रही माना। जो कताई न करते थे और जेल जानेको तैयार नहीं थे, पर जिन्हें सत्याग्रहके मृलभूत सिद्धान्तोंमें विश्वास था और जो सत्याग्रह आन्दोलनके ग्रुभिचन्तक थे, उन्हें गान्धीजीने निष्किय सत्याग्रही माना।

जुलाईमें, चक्रवर्ती राजगोपालाचारीके सुझावपर कांग्रेस कार्यकारिणीने अपनी माँगें कम कर दीं, ताकि वे ब्रिटिश सरकारको मान्य हो जायँ और आन्दोलन न चलाना पड़े। कांग्रेस महासमितिने भी अपनी पूनाकी वैठकमें माँगोंकी इस कमीको स्वीकार कर लिया। वादमें समझौतेकी यह इच्छा पूना प्रस्तावके नामसे जानी गयी। गतिरोधके अन्तके छिए दो शतें ये थीं एक तो ब्रिटिश सरकार भारतका पूर्ण स्वराज्यका अधिकार स्वीकार कर ले और दूसरे केन्द्रीय विधायिका सभाकी विस्वास-भाजन एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार वने । गान्धी-जी इसके विरुद्ध थे और कांग्रेस कार्यसमितिके कई सदस्य इसमें उनके साथ थे, क्योंकि सरकार द्वारा इस प्रस्तावकी स्वीकृतिके अर्थ थे कांग्रेस द्वारा अहिंसाकी तिलाञ्जलि। इस प्रस्तावसे अलग रहनेके लिए अब्दुल गफ्फार खाँने कार्यसमितिसे इस्तीफा दे दिया। नेहरू भी इतने उतरनेको तैयार न थे और उन्होंने इस प्रस्तावका विरोध किया। लेकिन, कार्य-सिमितिने एक बार फिर सहयोगके लिए अपना हाथ वढ़ाया और सरकारने फिर एक वार उसे झटक दिया । ८ अगस्त १९४० को वाइसरायने एक वक्तव्य दिया । (यह वक्तव्य वादमें अगस्त 'आफर' या अगस्त-प्रस्तावके नामसे जाना गया)। इस वक्तव्यमें उन्होंने कुछ भार-तीयोंको अपनी कार्यकारी कौंसिलमें लेकर एक युद्ध सलाहकार कौंसिल बनानेका सुझाव दिया । उन्होंने यह भी घोषणा की कि युद्ध के बाद भारतीयोंको अपना विधान स्वयं वनाने दिया जायगा ।

पूना-प्रस्तावके फौरन वाद कांग्रेसके अध्यक्ष अबुलकलाम आजादने मुह्गमद अली जिनाको तार दिया कि पूना-प्रस्तावमें माँगी गयी राष्ट्रीय सरकार किसी एक दलकी नहीं विक्क सभी दलोंकी संयुक्त सरकार होगी। किन्तु जिनाने अपने जवावमें कांग्रेस अध्यक्षका अपमान ही किया। उनका तार था—"मुझे आपका तार मिला। लेकिन में आपका विश्वास लीटा नहीं सकता(जैसा आपको विश्वास है, वैसा मुझे नहीं)। पत्र त्यवहार द्वारा या मिलकर में आपसे वात करनेको तैयार नहीं हूँ, क्योंकि आप मुसलिम भारतका विश्वास पूरी तरह खो चुके हैं। क्या आप यह समझ नहीं पाते कि आप जैसे खिलोने (मुसलमान) को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस यह दिखाना चाहती है कि वह राष्ट्रीय संस्था है और इस तरह विदेशोंको घोखा देना चाहती है। आप न हिन्दुओंका प्रतिनिधित्व करते हैं, न मुसलमानोंका। कांग्रेस हिन्दू संस्था है। आपने यदि आत्म-सम्मान है, तो फौरन उससे इस्तीफा दे दीजिये। अभीतक लीगका जितना नुकसान आप कर सकते थे, आपने किया है और आप यह भी जानते हैं कि आप असफल हुए हैं। यह खेल छोड़ दीजिये।"

लेकिन वास्तवमें पूना-प्रस्ताव तो ब्रिटिश सरकारको सम्बोधित था; और जब सरकारने कांग्रे ससे समझौतेका रास्ता भी वन्द कर दिया, हर व्यक्ति आन्दोलन करनेकी सोचने लगा।
१५ सितम्बरको कांग्रे स महासमितिकी एक बैठक वम्बईमें बुलायी गयी और गान्धीजीको मनचाहे ढंगसे आन्दोलन चलानेकी छूट दे दी गयी। गान्धीजीने आन्दोलनका एक विकल्प
निकाला। उन्होंने अपने भाषणमें कहा—''अगर हम सरकारसे ऐसी घोषणा प्राप्त कर सकें कि
कांग्रे स युद्धविरोधी तथा युद्धकी सरकारी तैयारियोंसे असहयोगका प्रचार कर सकेंगी तो हम
सविनय अवज्ञा आन्दोलन नहीं करेंगे।'' गान्धीजीने कहा कि मैं वाइसरायसे भेंट कलँगा

और उनसे कहूँ गा—"अव स्थित यह हो गयी है; हम झुककर इस स्थितिपर आ गये हैं; हम आपको परेशान नहीं करना चाहते और न हम आपको युद्धकी तैयारी ही विमुख करना चाहते हैं। हम अपने रास्ते जायँगे और आप अपने रास्ते जायँ; हमारे आपके मिलनेका आधार अहिंसा है। अगर जनता हमारे साथ हुई तो फिर यहाँ युद्धकी तैयारी नहीं होगी। और सिर्फ नैतिक द्वाबसे आप लड़ाईकी तैयारियोंमें जनताका सहयोग पा गये तो हमें भी शिकायतका मौका न रहेगा। अगर आपको राजाओं और नवानोंले, जमींदारोंसे, ऊँचनींच कहींसे सहयोग और सहायता मिले तो आप खुशिके साथ उसे लें; लेकिन हमारी आवाज भी सुनी जाने दें।" फिर आपने उस सत्याग्रहकी रूप-रेखा वतायी जो मजबूर होने पर ही शुरू किया जानेवाला था। "कोई भी सार्वजनिक सविनय अवशा आन्दोलन नहीं छेड़ा जायगा क्योंकि इस परिस्थितमें उसकी आवश्यकता नहीं होगी। स्वराज्यका असली आधार विचारों और लिखने-पढ़नेकी स्वतन्त्रता है। अगर इस नींवपर ही संकट आ जाय तो हमें सिर्फ नींवके इस परथरकी रक्षके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिये।"

गान्धीजी २७ सितम्बरको वाइसरायसे मिले । २० सितम्बरको फिर मिले । पर कोई नतीजा नहीं निकला । वाइसरायने कहा कि गान्धीजी द्वारा प्रस्तावित काररवाईसे भारतमें युद्धकी तैयारियों में बाधा पड़ेगी ।

लेकिन सुभापचन्द्र वसु युद्धकी तैयारियोंके विरोधमें काररवाई कर पहले ही जेल पहुँच चुके थे। रामगढ़में उन्होंने कांग्रेस अधिवेशनके समय ही युद्धविरोधी सम्मेलन बुलाया था जिसमें तय हुआ था कि—''राष्ट्रीय सप्ताहके पहले दिन ६ अप्रैल को देशभरमें युद्ध- विरोधी आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया जाय।'' लेकिन इस प्रस्तावमें फारवर्ड ब्लाक अकेला पड़ गया, क्योंकि सोश्लिस्टों व अन्य लोगोंने यह कदम गलत बताया। लेकिन वसु इसी कार्यक्रमपर अहे रहे और उनके साथियोंको राष्ट्रीय सप्ताहमें गिरफ्तारियाँ हुईं। जुलाईमें वसुने कलकत्ते के हालवेल स्मारकके विरुद्ध आन्दोलन किया। वसुका कहना था कि यह स्मारक राष्ट्रीय अपमान है, क्योंकि इससे सम्बद्ध कथा विलक्कल कपोलकित्वत है। इस आन्दोलनमें वसु गिरफ्तार कर भारतरक्षा नियमोंके अन्तर्गत नजरवन्द कर दिये गये। नवम्बरमें उन्होंने गैरकात्त्वी और अनावस्यक गिरफ्तारीके खिलाफ आमरण अनशन शुल कर दिया। अधिकारियोंसे उन्होंने कहा—''मुझे छोड़ दो, नहीं तो में जिन्दा रहनेका ही विरोध करूँगा।'' उन्होंने सरकारको एक पत्र लिखा जिसके साथ देशवासियोंके नाम एक अपील भी नत्थी कर दी। उन्होंने सरकारको एक पत्र लिखा जिसके साथ देशवासियोंके नाम एक अपील भी नत्थी कर दी। अन्दानके कारण वे वहुत कमजोर हो गये थे और उनकी जानका खतरा जान कर डाक्टरी रायपर सरकारने उन्हें दिसम्बरमें रिहा कर दिया।

कांग्रेसके मोचेंपर भारतरक्षा कान्तके नामपर सरकारने दमन ग्रुक कर दिया था, हालाँ कि सत्याग्रह अभी ग्रुक नहीं हुआ था। जयप्रकाश नारायण, लोहिया आदि मिलाकर दो हजारसे ज्यादा लोग पकड़े जा चुके थे। नवयुवकों और मजदूर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी सबसे ज्यादा जोर शोरसे हो रही थी। नागरिक अधिकार लोने जा रहे थे। चरों में लोगों को नजरबन्द कर देना लाम बात हो रही थी। बड़ी संख्यामें लोगों को बरावर थानों में जाकर हाजिरी देनेकी बाध्य किया गया। उन्हें युद्ध-विरोधी या सरकार-विरोधी प्रचार व काममें भाग लेनेसे रोका गया, स्कूलों व कालेजों के लाबों के मिलने या सम्पर्क स्थापित करनेपर रोक लगायी गयी। किसी भी प्रकारकी सभामें भाग लेनेपर पावन्दी लगा दी गयी। कहीं जानेके २४ वण्टे पहले उन्हें पुलिसको इत्तिला देनी पड़ती थी।

आखिरकार, १७ अक्तूबर १९४० को युद्धिवरोधी आन्दोलनका प्रतीक व्यक्तिगत सत्याग्रह गुरू हुआ। वर्धासे सात मील दूर पौनार विनोवाजीने गाँवमें युद्धिवरोधी भाषण कर सत्याग्रहका श्रीगणेश किया। देहाती जनताके सामने, उन्होंने सीधी-सादी भाषामें, भारतको जवरदस्ती युद्धमें शामिल कर देना, भाषणकी स्वतन्त्रताका अपहरण, राष्ट्रीय सरकार बनानेकी कांग्रेसकी माँगका ठुकराया जाना आदि प्रक्नोंपर प्रकाश डाला और इन वातोंसे भारतीय जनताका विरोध प्रकट किया।

गान्धीजीने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस वार केवल वे ही व्यक्ति सत्याग्रह कर सकेंगे, जिन्हें स्त्रीकृत स्वीपर रख लिया गया है। उस स्वीके व्यक्तियोंको एक एक कर गान्धीजी बुलाकर सत्याग्रह करनेका आदेश देनेको थे। सभी समझते थे कि नेहरू पहले सत्याग्रही होंगे। पर रचनात्मक कार्य-जगतके वाहर लगभग अज्ञात विनोवा भावेको चुनकर गान्धीजीने सारे संसारको आश्चर्यमें डाल दिया। विनोवाकी प्रशंसामें गान्धीजीने लिखा— "मेरे वाद विनोवा अहिंसाके सबसे अच्छे व्याख्याकार हैं, वे मूर्तिमान अहिंसा हैं; उन्होंने एक खास इलाकेमें रचनात्मक कार्य करनेमें अपनेको संलग्न कर रखा है; उनमें मुझसे अधिक एकाग्रचित्तता है। उनकी युद्ध होणा विशुद्ध अहिंसासे उपजी है।"

विनोवाके युद्ध-विरोधी भाषणका सारांश ही समाचारपत्रोंमें प्रकाशित हो सका; शेष संसरने काट दिया। बादमें यह भी बन्द हो गया। १८ अक्तूबरको देशभरमें जिला मिलस्ट्रेटोंने समाचार-पत्रोंको लिला कि दण्डसे बचनेके लिये यह आवश्यक है कि विनोवाका भाषण और उसके बादको घटनाओंका विवरण दिल्ली स्थित मुख्य प्रेस सलाहकारको दिखाये बिना न छापा जाय। विनोवा चार दिनतक युद्ध-विरोधी भाषण करते रहे। पाँचवें दिन, २१ अक्तूबरको उन्हें गिरफ्तार कर तीन महीनेकी कैदकी सजा दे दी गयी।

जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही होनेवाले थे और ६ नवम्बरको भाषण करनेवाले थे । पर ३१ अक्तूबरको ही वे गोरखपुरके जिला मजिस्ट्रेटके वारण्टपर गिरफ्तार कर लिये गये और वहाँ एक 'आपत्तिजनक' भाषण करनेके अभियोगमें उन्हें चार वर्षकी कैंदकी सजा दे दी गयी ।

इसपर, गान्धीजीने कांग्रेस कार्यसमितिकी रायसे निम्नलिखित आदेश सभी कांग्रेस कमेटियोंको भेज दिये— '

"कुछ समयतकके लिए, कांग्रेस कार्यसमिति, विधान मण्डलोंके कांग्रेसी सदस्यों और कांग्रेस महासमितिके सदस्योंमेंसे, में स्वयं सत्याग्रही चुनूँगा।

"सत्याग्रही केवल वे लोग हो सकेंगे, जो मेरी बतायी शतों के पावन्द होंगे। जो स्वयं सत्याग्रह करना चाहते होंगे और जो सत्याग्रह करनेके लिये स्वतन्त्र होंगे।

"कोई भी व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेटको सत्याग्रहके समय, स्थान और ढंगकी सूचना दिये विना सत्याग्रह नहीं करेगा।

"यह वेहतर होगा कि शहरों में सत्याग्रहके सम्बन्धमें सभाएँ न की जावँ। गाँवों में सभाएँ की जा सकती हैं। सत्याग्रहका सबसे मुन्दर ढंग यह होगा कि सत्याग्रही एक दिशामें प्रस्थान करे और तबतक नीचे लिखी बात हर राहगीरसे कहता चला जाय, जबतक वह गिरफ्तार न हो जाय—"युद्धकी तैयारीमें अंग्रेजोंको पैसे या व्यक्तियोंकी मदद देना गलत है, हर युद्धका अहिंसात्मक प्रतिरोध करना ही रलाधनीय और उचित प्रयास है। "में इस ढंगको इसलिए पसन्द करता हूँ कि यह निरंपराध, प्रभावकारी और किंपायतका ढंग है, इसमें तर्क करनेकी आवश्यकता नहीं, यह युद्धकी वातपर ही ध्यान केन्द्रित करता है। आशय यह है कि यह आन्दोलन सार्वजनिक आन्दोलनमें वदलने न पाये। सत्याग्रह एक-एक व्यक्ति करे। वहुतसे व्यक्तियोंका एक साथ सत्याग्रह करना आवश्यक नहीं है। सत्याग्रहका कार्यकम यदि हो सके तो एक महोनेमें पूरा हो जाय। सत्याग्रहके समय प्रदर्शन न होना चाहिये।"

१७ नवम्बरको वल्लममाई पटेलकी गिरफ्तारीसे नया दौर ग्रुक हुआ। उनपर मुकदमा नहीं चलाया गया बल्कि वे अनिश्चित कालके लिए नजरबन्द कर दिये गये। नवम्बरके अन्ततक मन्त्री, समासचिव, विधानमण्डलों व कांग्रेस महासमितिके लगभग सभी सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे। अशान्तिकी दो घटनाओं को छोड़कर श्रेप सभी स्थानों में पूर्ण शान्ति थी। विहारमें वहाँके प्रधान मन्त्रीकी गिरफ्तारीके समय एक भीड़ने प्रदर्शन किया और उसपर लाठीचार्ज हुआ। पंजाब कांग्रेसके अध्यक्ष मियाँ इफ्तिखारुदीनकी गिरफ्तारीपर लाहौरमें भी ऐसा ही हुआ। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकनेके लिए गान्धीजीने आदेश जारी किया कि सत्याग्रह करनेकी सूचना सिर्फ हाकिमोंको दी जाय, जनताको सूचना देनेकी कोई आवश्यकता नहीं।

कांग्रेसके अध्यक्ष अवुलकलाम आजाद २० दिसम्वरको पकड़ लिये गये और उन्हें खेढ़ वर्षकी कैदकी सजा मिली । पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तके प्रधान मन्त्री डाक्टर खान साहव एक वार गिरफ्तार होकर छूट चुके थे और सत्याग्रह करते रहनेके वावजूद फिर गिरफ्तार नहीं किये गये थे। वास्तवमें सीमाप्रान्तमें कोई सत्याग्रही गिरफ्तार ही नहीं हुआ था। सत्याग्रहियोंकी पहली नवम्बरवाली सूची खत्म होने पर नयी सूचियाँ वनीं और प्रान्तीय व दूसरी कांग्रेस समितियोंके सदस्योंको भी सत्याग्रह करनेकी अनुमित मिली। सरकारका रवैया कड़ा होता जा रहा था और मजिस्ट्रेट सत्याग्रहियोंपर लम्बे जुरमाने ठोंक कर उनकी सम्पत्ति नीलाम कर उन्हें वसूल करवा रहे थे। गान्धोजीने प्रकाशनके लिए दो वक्तव्य दिये, पर सेंसरने उन्हें रोक लिया।

जब यह व्यक्तिगत सत्याग्रह चल ही रहा था, तेजबहादुर सपृने नरमदलीय नेताओंका एक सम्मेलन, मार्च, १९४१ में बम्बईमें बुलाया जिसमें इस लम्बे गतिरोधको जत्म करनेके प्रस्तपर विचार हुआ। सपृके समापित्वमें हुए इस सम्मेलनमें नरमदलीय नेताओंके अलावा हिन्दू महासभाके नेता विनायक दामोदर सावरकर और व्यामाप्रसाद मुखजांने भी भाग लिया। सपूने अपने भाषणमें कहा—"भारतीय जनमत और विचारधारासे कोई भी सरकार इतनी दूर नहीं थी, जितनी कि वर्तमान भारत सरकार।" गतिरोध दूर करनेके लिए सम्मेलनने दो सुझाव दिये। एक तो यह कि वाइसरायकी कार्यकारी कांसिल (शासन परिपद) के सभी सदस्य गैरसरकारी भारतीय हों और दूसरा यह कि ब्रिटिश सरकार समय निश्चित कर दे कि युद्धकी समाप्तिपर इस विशिष्ट अवधिके भीतर भारतको पूर्ण औपनिचेशिक स्वराज्य दे दिया जायगा। बाइसरायकी इस प्रकार वनी कींसिल हो तो ब्रिटिश शासके प्रति उत्तरदायी, पर व्यवहारमें हर अन्तर्राष्ट्रीय मामलेमें उसे उसी स्तरपर माना जाय जिसपर अन्य औपनिवेशिक देशोंकी कींसिल मानी जाती हैं। भारत सचिव एमरीने

इन सुझानोंको अस्वीकार करते हुए कहा कि सुझानोंको लागू करनेके लिए आवश्यक वैधानिक परिवर्तन युद्धकी व्यस्तता और प्रयासोंमें नहीं किये जा सकते । हिन्दू-सुसलिम मतमेदोंकी ओर इशारा करते हुए एमरीने यह भी कहा कि वम्बई सम्मेलनके सुझाव गलत ओर मेंने गये हैं । उनका आश्य यह था कि हिन्दू और मुसलमान मिलकर पहले अपने मतभेद दूर कर लें और तब अंग्रेज सरकारसे मिलें। लेकिन तेजवहादुर सप्रू अपने काममें लगे रहे और अगले महीने वाइसरायसे मिलकर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस और लीग आपकी कोंसिलमें नहीं आतीं तो आप कोंसिलोंमें दूसरी विचारधाराओंके लोगोंको ले लें; कांग्रेस और लीगके कोंसिलमें आनेको तैयार होते ही ये लोग कोंसिलसे निकलनेको तैयार रहें।

जुलाईमें वाइसरायने अपनी कोंसिलकी सदस्य-संख्या वढ़ाकर उसमें सात नरमदलीय भारतीय रख लिये । सिर्फ माधव श्रीहरि अणे ही अकेले कांग्रेसी उसमें थे और वे भी कांग्रेस अन्दोलनोंसे अलग थे। युद्ध सलाहकार कोंसिलकी स्थापना भी हुई। अगस्त प्रस्ताव- के अनुसार यह स्थापना हुई थी; वह प्रस्ताव कांग्रेस और लीगके लिए था, पर दोनों संस्थाएँ ही इस कोंसिलके वाहर थीं।

अक्त्वरमें सरकारने रुख वदला और धीरे-धीरे सत्याग्रहियोंको छोड़ना ग्रुक किया। कम्यूनिस्ट वन्दियों—विशेषकर देवली जेलमें वन्द लोगोंके प्रति जेल अधिका-रियोंका व्यवहार बुरा था। कई वार इन लोगोंने जेलोंमें सार्वजनिक अनशन किये। एक बार तो १८० कैदियोंने अनशन किया। लेकिन जूनमें जर्मनीके रूसपर हमले और रूस व ब्रिटेन आदिके वीच मैत्री होनेसे युद्धके प्रति कम्यूनिस्टोंका रुख बदल गया। उन्होंने कहा कि अब यह लोक-युद्ध हो गया है और हम इसमें मदद करेंगे। सरकारने कम्यूनिस्टोंको धीरे-धीरे छोड़ना ग्रुक किया। पर कुछ कम्यूनिस्ट वन्दी आखीरतक नहीं छोड़े गये।

ग्रुरू दिसम्बरमं, सरकारने घोषणा को कि जिन सत्याग्रहियोंके अपराध सिर्फ प्रतोक रूपमें या जान्तेमें थे, वे छोड़ दिये जावँगे। कांग्रेस कार्य-समितिके सदस्य छूट गये, हाला कि सत्याग्रह जारी था। मुक्त सत्याग्रहियोंको फिर सत्याग्रह करनेको अनुमितं गान्धीजीने कुछ समयके लिए न दी।

इसी वीच राजगोपालाचारीने एक वैधानिक आपत्ति उठा दी थी, जिससे पूरे व्यक्तिगत सत्याग्रहका आधार ही खत्म हो गया । जिस वम्बई प्रस्तावमें गान्धीजीको सत्याग्रहका नेतृत्व करनेके लिए अधिकार दिया गया था, उसका अर्थ गान्धीजीने यह लगाया था कि अहँसामें विश्वासके कारण ही कांग्रेस इस युद्ध (हर युद्ध) में भाग लेनेका विरोध कर रही है। किसी अन्य व्याख्यासे गान्धीजी संघर्षका नेतृत्व ही नहीं करते । लेकिन २३ दिसम्बरकी वैठकमें कांग्रेस कार्यसमितिने कहा कि प्रस्तावके अर्थ वे नहीं थे जो गान्धीजीने लगाये थे। इसपर गान्धीजीने सत्याग्रहके नेतृत्वके उत्तरदायित्वसे मुक्ति चाही। कार्यसमितिने गान्धीजीकी इच्छा स्वीकार करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि वम्बई प्रस्ताव और अहिंसाकी नीति चाल्च रहेगी। कार्यसमितिके निर्णयपर विचार करनेके लिए बुलायी गयी कांग्रेस महासमितिकी वैठकमें गान्धीजीने कहा—अव जब कि आतंक और अफवाहोंको खत्म करनेके लिए लोगोंकी अधिक आवश्यकता है, मैं उन्हें जेल नहीं भेजना चाहता। उन्होंने सत्याग्रहियोंको रचनात्मक कार्मोमें लग जानेको कहा। इस प्रकार युद्ध-विरोधी आन्दोलन समाप्त हो गया और शान्ति छा गयी।

इसी वीच जापानने भी "मिन्न" राष्ट्रोंके विरुद्ध युद्धकी घोषणा कर दी थी। पूर्वमें युद्धका क्षेत्र भारतके विलकुल ही निकट आ गया था। जापानके युद्ध-प्रवेशके एक ही महीने वाद मार्च १९४२ में ब्रिटिश युद्ध-मन्त्रिमण्डलके सदस्य स्टेफर्ड किप्स, भारतीय राजनीतिक गत्यवरोध दूर करनेके लिए एक मुझाव लेकर भारत आये। भारत पहुँचते ही उन्होंने इस मुझावकी घोषणा की। मुझाव इस प्रकार था—

- (क) युद्धकी समाप्तिके फीरन वाद, भारतके लिए नया संविधान बनानेके निमित्त, नीचे लिखे ढंगसे एक निर्वाचित परिषद बनानेका प्रयास शुरू होगा।
- (ख) इस विधान निर्मात्री परिषद्में देशी रियासतींके प्रतिनिधित्वकी भी व्यवस्था होगी।
- (ग) ब्रिटिश सरकार इस परिपद द्वारा निर्मित विधानको स्वीकार कर लाग् करेगी, पर शर्त यह है कि—
- (१) यदि नये विधानको भारतका कोई प्रान्त स्वीकार न करे तो उसे वर्तमान स्वयस्था ही कायम रखनेकी छूट रहेगी और यदि वादमें वह प्रान्त नये विधानके अन्तर्गत आना चाहे तो आ सकेगा।

ऐसे प्रान्त यदि चाहेंगे तो उन्हें ब्रिटिश सरकार इसी प्रकार विधान वनाकर उसे स्वीकार करने और शेष भारतीय यूनियनके समान मान्यता देनेको तैयार रहेगी।

(२) विधान निर्मात्री परिपद और ब्रिटिश सरकारके वीच. एक सन्धि होगी। इस सिन्धमें वे सब वातं रहेंगी जो भारतीय शासनका पूर्ण उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकारसे हटा-कर भारतीय हाथोंमें सौंपनेके लिये आवश्यक होंगी। ब्रिटिश सरकार द्वारा किये गये वादोंके अनुसार धार्मिक व जातीय अल्पसंख्यक गुटोंकी रक्षाकी गारण्टी भी इस सन्धिपत्रमें रहेगी। ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलके अन्य सदस्य राष्ट्रोंसे किस प्रकारके सम्बन्ध रहें—यह निश्चित करनेका भारतीय यूनियनका अधिकार अक्षुण्ण रहेगा।

भारतीय रियासतें नये विधानको मानें, न मानें, नयी परिस्थितिमें इसके अनुसार सन्धिकी शतें बदलना आवश्यक होगा।

(घ) यदि भारतकी मुख्य जातियोंके नेताओंने युद्धकी समाप्तिके पहले कोई अन्य ढंग अपनाना सर्वसम्मतिसे स्वीकार न कर लिया तो विधान निर्मात्री परिपद इस प्रकार चुनी जायगी—

युद्धकी समाप्ति पर प्रान्तीय विधान गण्डलांके नये चुनाव हांगे । चुनावांके नतीजे घोषित होते ही प्रान्तीय विधान सभाएँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धतिसे विधान निर्मात्री परिपदके सदस्योंको चुनेंगी । परिपदके सदस्योंकी संख्या विधान समाओंके सदस्योंकी संख्याकी लगभग दस फीसदी होगी ।

देशी रियासतोंसे उनकी आवादीके अनुसार ही प्रतिनिधि नागजद हो कर आयँगे। आवादी और प्रतिनिधि-संख्याका वही अनुपात होगा जो शेप ब्रिटिश भारतमें। देशी रियासतोंके प्रतिनिधियोंके वही अधिकार होंगे जो ब्रिटिश भारतके प्रतिनिधियोंके।

(ङ) भारतके लिए जो संकटका समय है उसमें और जवतक नया विधान नहीं वनता, तवतक ब्रिटिश सरकार ही अनिवार्य रूपसे अपनी लड़ाईकी तैवारीके अन्तर्गत भारतकी रक्षाकी जिम्मेदारी ओहेगी, पर भारतके भौतिक, नैतिक और सैनिक साधनोंके पूर्ण संघटनकां काम भारतीय जनताके सहयोगसे भारत सरकार ही करेगी। ब्रिटिश सरकारकी यह इच्छा है और वह भारतीय जनताके प्रमुख वर्गोंके नेताओंको आमन्त्रित भी करती है कि वे अपने देश, राष्ट्रमण्डल और संयुक्त राष्ट्रसंघकी मन्त्रणाओं में फौरन हिस्सा लेना शुरू करें। इस प्रकार वे वह महत्वपूर्ण काम पूरा करनेमें सिक्षय और रचनात्मक सहायता देंगे जो भारतकी भावी स्वतन्त्रताके लिए महत्त्वपूर्ण और आवश्यक है।

इस सुझावकी म्मिकामें कहा गया था—''ध्येय यह है कि नये भारतीय यूनियनका ऐसा डोमिनियन (उपनिवेश) स्थापित किया जाय जो ब्रिटिश ताजके प्रति निष्ठा द्वारा ब्रिटेन व दूसरे राष्ट्रमण्डलीय राष्ट्रोंसे सम्बद्ध रहे लेकिन हर अर्थमें उन सबके समान और वरावर हो—आंतरिक या परराष्ट्र सम्बन्धी किसी मामलेमें किसीके अधीन न हो।"

प्रान्तोंको भारतीय यूनियनसे अलग रह सकनेकी छूट देनेवाला सुझाव कांग्रेस कार्य-सिमितिको स्वीकार न था। वह उसे भारतीय एकतापर आघात मानती थी। लेकिन कार्य-सिमितिने इसके अतिरिक्त भी, वर्तमानको भविष्यसे अधिक महत्त्वपूर्ण माना और कहा— "आजके गम्भीर संकटमें, आजका, वर्तमानका ही महत्त्व है और भविष्यके लिए आये सुझावोंका महत्त्व भी उतना ही है जितनेमें वें सुझाव वर्तमानपर प्रभाव डालते हैं।"

किप्सने जो व्याख्या और विवरण दिया, उससे कांग्रेस अध्यक्ष तथा कांग्रेसके अन्य नेता वर्तमानके लिए प्रस्तावित व्यवस्थासे संतुष्ट हुए । किप्स-सुझावको स्वीकार करनेके लिए कांग्रेसकी द्यार्त यह थी कि सुझावके अन्तिम भाग (ङ) में प्रस्तावित सरकारको पूर्ण अधिकार प्राप्त हों — वैसे ही अधिकार जैसे ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलको प्राप्त हें । यदि यह द्यार्त स्वीकार हो जाती तो कांग्रेस भविष्य सम्बन्धी सुझावोंकी विशेष चिन्ता करती; आश्रय यह था कि वर्तमान व्यवस्था संतोपजनक होने पर भविष्यकी वात भी स्वीकार हो सकती थी । कांग्रेसके अध्यक्षने कहा — "भविष्य महत्त्वपूर्ण तो हैं, पर वह अधिकांशतः इसपर निर्भर होगा कि आनेवाले कुछ महीनों या वर्षोमें क्या होता है । इसलिए हम इस अनिश्चित भविष्यके सम्बन्धमें आद्यासन लिये विना ही काम चला सकते थे; हमें आशा थी कि देशरक्षाके लिए की गयी कुरवानियोंके द्वारा हम स्वतन्त्र और स्वाधीन भारतकी स्थायी नींव डालेंगें।" संक्षेपमें, कांग्रेस केन्द्रमें एक सच्ची राष्ट्रीय सरकार चाहती थी, जिसे पूर्ण अधिकार प्राप्त हों और वाइसराय जिसके केवल वैधानिक अध्यक्ष हों।

किप्स कहते थे कि सुझावमें वह निहित है जो कांग्रेस माँगती है। वे कांग्रेस-अध्यक्ष-से वात-चीतमें 'मन्त्रिमण्डल' और 'राष्ट्रीय सरकार' जैसे शब्दोंका प्रयोग करते थे। उन्होंने यह भी कहा (जैसा कि कांग्रेस अध्यक्षने वादमें वताया) कि मन्त्रिमण्डलसे वाइसरायका वहीं सम्बन्ध होगा जो ब्रिटेनके शाहका होता है। कांग्रेस और किप्सके वीच मतभेद केवल एक वातपर था। किप्स कहते थे कि रक्षा-विभागका उत्तरदायित्व कमाण्डर इन-चीफ (सर्वोच्च सेनापित) के हाथमें ही रहे। कांग्रेस जायानी आक्रमणका मुकावला करनेका अधि-कार चाहती थी; आशंका यह थी कि जापान कभी भी भारतपर आक्रमण कर सकता है। इसलिए रक्षा-विभाग वहुत महत्त्वपूर्ण था। किप्स इस वातपर राजी नहीं थे। समझौतेके लिए आतुर कांग्रेस किप्सके निम्निलिखत सुझावको माननेके लिए एक कदम और आगे वढ़ी— "(अ) वाइसरायकी कार्यकारी कोंसिलमें कमाण्डर-इन-चीफ 'युद्ध सदस्य' की हैसि-यतसे रहे; भारतमें फौजी काररवाईका पूरा नियन्त्रण उसीके हार्योमें रहे। उसका यह अधिकार ब्रिटिश सरकार और युद्ध-मित्रमण्डलके अधीन रहे। युद्ध-मित्रमण्डलमें एक भारतीय प्रतिनिधि रहे जिसे भारत-रक्षाके सम्बन्धमें अन्य सदस्योंके समान अधिकार हों। प्रशान्त महासागर क्षेत्रकी कोंसिलमें भी एक भारतीय प्रतिनिधि रहे।

"(व) वाइसरायकी कौंसिलमें एक भारतीय प्रतिनिधि रहे जो कमाण्डर इन-चीफके युद्ध-विभागके उन उपविभागोंका भार ले ले जो रक्षा-विभागसे फौरन अलग किये जा सकते हों। इसके अतिरिक्त इस सदस्यको युद्ध-संयोजन-विभाग भी दे दिया जाय, जो अवतक किवल ब्राइसरायके अधीन ही है। और यह सदस्य भारत सरकारके उन कामोंको भी सम्हाल ले जो रक्षा-विभागसे सम्बन्धित हैं और अवतक किसी विभागके अन्तर्गत ८नहीं आते।"

कांग्रे सने यह सुझाव स्वीकार कर लिया। पर वादमें कहा जाता है कि किष्सने अपने उच्चिषिकारियों के आदेश पर सुझावके अन्तिम अंश (ङ) की व्याख्या वदल दी और कहा कि नयी सरकारमें वाइसरायके सभी पुराने अधिकार उन्हीं के पास रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रे सने जो समझा वह मेरा कभी भी मतलव नहीं था। राष्ट्रीय सरकार और मन्त्रिमंडलीय उत्तरदायित्वक विरोधमें किष्सने तर्क दिया कि ऐसी सरकार "बहुसंख्यक दलकी पूरी तानाशाही" हो जायगी और "अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए दिये गये ब्रिटिश सरकारके आश्वासनों के विरुद्ध होगी।

मुस्लिम लीगको 'वर्त्तमान' में अधिक दिल्चस्पी नहीं थी। यद्यपि किप्स-प्रस्तावमें मुस्लिम वहुमतके प्रान्तोंमें मुसलमानोंके आत्मनिर्णयका अधिकार निहित था और एक प्रकारसे पाकिस्तानको स्थापनाका आधासन भी उसमें था, पर मुस्लिम लीग इस सम्बन्धमें ब्रिटिश सरकारसे सीधा वादा चाहती थी। हिन्दू महासभाको किप्स-प्रस्ताव स्वीकार न था, क्योंकि उसमें भारत-विभाजनकी वात निहित थी।

गान्धीजीने किप्स-यात्राका उद्देश्य और फल पहले ही समझ लिया था और इसलिए उन्होंने समझौता-वार्तामें भाग लेनेसे इनकार कर दिया। पर किप्सके अनुरोध पर गान्धीजी दिल्ली गये और उनसे मिले। किप्स-प्रस्तावपर गान्धीजीकी कांग्रेसको राय थी—"यह तो ऐसी हुण्डी है जो भविष्यमें ही भुन सकती है, चाहे इसे स्वीकार करो चाहे न करो।" गान्धीजीने स्वयं यह हुण्डी स्वीकार नहीं की। किप्सने समाचार-पत्रोंके प्रतिनिधियोंसे एक भेंटमें कहा—विटिश सरकारके सुझावका मसविदा वापस ले लिया गया है और अब फिर वही स्थित आ गयी है, जो मेरे भारत आनेके पहले थी।

किप्सकी यात्रा असफल होनेसे भारतीय क्षितिजपर निराशा छा गयी। भारतीय जनता विटिश शासनकी तो और वड़ी शत्रु हो ही रही थी, भारत-रक्षाकी विटिश सरकारकी क्षमता-में भी उसका अविश्वास होता जा रहा था। सुदूर पूर्वके विटिश अधिकारके क्षेत्र जल्दी-जल्दी जापानी अधिकारमें जा रहे थे। वर्मा, मलाया और सिंगापुरके 'अभेश दुर्ग' पर जापानियोंके आश्चर्यजनक गतिसे कन्जा हो जानेसे विटिश प्रतिष्ठाको गहरा धक्का लगा। हांगकांग, मलाया, सिंगापुर व वर्मासे आनेवाले भारतीय और अंग्रेज शरणाथियोंकी यात्रा-व्यवस्थामें

विदिश शासकों द्वारा जातिमेद वरतनेसे भारतको सबसे वहे धक्के और अपमानका आभास हुआ । "भारतीय शरणार्थियोंको भूख और मृत्युका सामना करना पड़ा । बच्चे, बूढ़े, रित्रयाँ सड़कके किनारे गिरकर मर जाते; न उनको हटानेका प्रवन्ध था, न जलानेका । स्वस्थ नवयुवकों और नवयुवितयोंको दशा भी भारतीय सीमातक पहुँचते पहुँचते अत्यन्त दयनीय हो जाती थी; वे कंकाल मात्र रह जाते थे । लेकिन, दूसरी ओर अंग्रेज शरणार्थियोंकी खुशामदें होतीं, उनका जीवन सुखमय और आनन्दमय बनानेमें भारत सरकार कोई कोर-कसर न छोड़ती । व्यवहारमेदकी पराकाष्टा तव हो गयी जब गोरे व काले शरणार्थियोंके लिए सड़कें अलग कर दी गयीं । अंग्रेजोंवाली सड़क पक्की थी; उसपर कई कई मीलपर खाने, ठहरनेका प्रवन्ध था । इसके पूर्ण विरोधमें, हजारों, लाखों भारतीयोंके साथ जो अपमान-जनक और पाशविक व्यवहार हुआ वह समस्त भारतीयोंके हृदयमें काँटेकी तरह कसकता रहा । भारतके अपमानका प्याला लवालव भर चुका था।"

भारतमें अंग्रेज-विरोधी भावनाएँ बढ़ रही थीं। इसका प्रभाव यह हुआ कि जनता-में और पढ़े लिखे लोगोंमें भी जापानसे सहानुभूति होने लगी और लोगोंकी उत्कट इच्छा हो उठी कि जापान भारतपर आक्रमण करे और 'घृण्य' अंग्रेजोंको निकाल बाहर करे।

यह पृष्ठभूमि थी, जिसमें, अप्रैल १९४२ के अन्तमें कांग्रेस कार्यसमिति और महासमितिको बैठकें इलाहावादमें ग्रुल हुईं। गान्धीजीने इन वैठकोंमें भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने वर्धासे अपने विचार लिख भेजे। उन्होंने निम्नलिखित बातोंपर जोर दिया:-

- (१) किप्स-प्रस्तावने साम्राज्यवादका नग्नरूप सामने रख दिया है,
- (२) ब्रिटेन भारतकी रक्षामें असमर्थ है,
- (३) भारतीय और ब्रिटिश हितोंमें शास्वत विरोधामास है,
- (४) जापान भारतसे नहीं, ब्रिटिश साम्राज्यसे युद्ध कर रहा है,
- (५) युद्धमें भारतका शामिल होना विशुद्ध रूपमें ब्रिटिश निर्णय है,
- (६) अंग्रेजोंको भारत छोड़ देना चाहिये, ताकि भारतवासी अपने देशकी रक्षा कर सकें । देशी महाराजाओं और अल्पसंख्यकोंकी रक्षाके लिए भारतमें मौजूद रहनेका ब्रिटिश तर्क न्यायसंगत और टिकाऊ नहीं है । इन दोनों वर्गोंको अंग्रेजोंने ही जन्म दिया है,
- (७) भारतकी जापान या किसी अन्य देशसे कोई दुश्मनी नहीं है। पर यदि, तव भी, जापान भारतपर हमला करता है तो उसे पूर्ण रूपेण अहिंसात्मक असहयोगका सामना करना पड़ेगा। जापान भारतके लिए खतरा है क्योंकि भारत साम्राज्यवादी ब्रिटेनका गुलाम है और इससे जापानका लालच बढ़ता है।

इसलिए गान्धीजीका निष्कर्ष यह था कि ब्रिटेन मित्रभाव और शान्तिपूर्ण ढंगसे भारत छोड़ दे। कांग्रेस महासमितिने जो प्रस्ताव अन्ततः स्त्रीकार किया वह इन्हीं वातोंपर आधारित था।

मद्रासमें कांग्रेस राजनीतिने एक अलग मोड़ लिया। मद्रास विधान सभाके कांग्रेस दलके नेता राजगोपालाचारीने दलकी एक विशेष वैठकमें दो प्रस्ताव स्वीकार कराये। एक प्रस्तावमें प्रान्तोंमें मन्त्रिमण्डल बनानेपर जोर दिया गया था और दूसरेमें प्रथक होनेकी मुसलिम लीगकी माँग स्वीकार कर उससे समझौता कर लेनेकी माँग की गयी थीं। कांग्रेसकी

१. इण्डियन नेशनल कांग्रेस-रिपोर्ट ऑव दि जनरल सेकेटरीज। पृष्ठ ३६-७

नीतिके विरुद्ध होनेके कारण कांग्रेस अध्यक्षने इसपर आपित की। राजगोपालाचारीने खेद-प्रकाश किया, पर साथ ही, अपनी नीतिके प्रचारके लिए स्वतन्त्र रहनेके लिए कांग्रेस कार्य-समितिसे इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस महासमितिके इलाहाबाद अधिवेशनमें उन्होंने मुसलिम लीगकी माँगके सम्बन्धमें एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया और इसकी जगह भारतकी एकतापर जोर देनेवाला जगतनारायण लालका प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। लेकिन राजगोपालाचारी अपने मतपर हद रहे। अन्तमें गान्धीजीने उन्हें परामर्श दिया कि वे मद्रास विधान सभा और कांग्रेसकी सदस्यतासे इस्तीका दे हैं। राजगोपालाचारीने १५ जुलाईको कांग्रेससे इस्तीफा दे दिया।

अध्याय २९

अगस्त-विद्रोह

युद्ध के कारण भारतके कष्ट बढ़ रहे थे। सरकार भारतमें जापानसे लोहा लेनेके लिए जी-जानसे तैयारी कर रही थी। दुस्मनके हाथ कुछ न पड़ने देनेके लिए सब कुछ नष्टभ्रष्ट कर देनेकी नीति बरती जानेके कारण समुद्रतटों—विशेषकर बंगाल और उड़ीसाके लोगोंकी घबराहट बेहद बढ़ गयी। हजारों लोग अपने घरों और खेतोंसे निकाल दिये गये और जीविकाहीन हो गये। उन्हें पुलिस और फौज दोनों परेशान करती। युद्ध फण्डमें जबरन चन्दे लिये जाते। चोरवाजारीसे गरीब और ज्यादा गरीब हो रहे थे, अमीर और ज्यादा अमीर। उद्योग-व्यवसाय कारपोरेशन द्वारा अंग्रेज भारतीय-व्यापारसे भारी मुनाफा कमा रहे थे। उपभोक्ता सामग्रीको लड़ाईके काम लानेके लिए और जनतासे बचानेके लिए सरकार मुद्रास्फोतिकी नीति बरत रही थी। वह खाद्य व अन्य सामग्री कचे दामोंपर खरीदती और उसके लिए नये नोट छाप लेती। निम्न और मध्यम वर्ग, जिनकी आय बढ़ती हुई कीमतोंके अनुपातमें नहीं बढ़ी थी, अपने आभूपणादि बेचकर गुजारा कर रहे थे। गान्धीजीने कहा कि भारत एक शबके समान है जो मित्रराष्ट्रोंके कन्धोंपर भारी बोझकी तरह लदा हुआ है। भारतकी समस्याका केवल एक ही हल था, और वह यह कि अंग्रेजी राजका अन्त हो।

इसिलए इसी आधारपर गान्धीजीने १९४२ के आन्दोलनका संघटन किया और अंग्रेजोंसे भारत छोड़नेको कहा । १४ जुलाईको सेवाग्राम (वर्धा) में कांग्रेस कार्य-समितिकी वैठक हुई, गान्धीजीसे 'भारत छोड़ो' आन्दोलनके महत्त्व और आध्यके सम्बन्धमें परामर्श किया और उसीके अनुसार एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया। यह प्रस्ताव इंगलेण्डसे भारत-के साथ न्याय करनेकी अपीलके रूपमें था, जिसमें कहा गया था—''यदि यह अपील अस्त्री-कार हुई, तो कांग्रेस १९२० से संचित अपनी समस्त अहिंसक शक्तिके प्रयोगके लिए मजबूर हो जायगी। इतना व्यापक संघर्ष अनिवार्यतः गान्धीजीके नेतृत्वमें ही होगा।"

यह स्पष्ट था कि सार्वजिनिक आन्दोलन होनेवाला था; गान्धीजीने कहा भी था कि यह मेरे जीवनका सबसे बड़ा संवर्ष होगा । उन्होंने इंगलैण्डसे कहा था—"भारतको ईश्वरके भरोसे छोड़कर चले जाओ; अगर यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात हो तो उसे अराजकतामें छोड़ दो, पर चले जाओ।" लेकिन उन्होंने भारतवासियोंको सलाह दी कि वे "अंग्रेजी सत्तासे छुटकारा पानेके लिए जापानसे कोई आशा न लगाये।"

७ व ८ अगस्त, १९४२ को वम्बईमें कांग्रेस महासमितिका ऐतिहासिक अधिवैद्यंत हुआ । भारत छोड़ देनेकी ब्रिटिश सरकारसे अपनी माँग और अपील दोहराते हुए कांग्रेस महासमितिने अपने प्रस्तावोंमें कहा — "लेकिन महासमितिकी धारणा है कि अब मानवता तथा स्वयं अपने हितोंमें काम करनेसे रोकनेवाली साम्राज्यवादी और प्रभुत्वमत्त सरकारके विषद अपनी संकल्पशक्तिका प्रयोग करनेसे राष्ट्रको रोकना महासमितिके लिए उचित न होगा । इस लिये महासमिति निश्चय करती है कि स्वाधीनता और स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके अपने कभी

न छिन सकनेवाले अधिकारका प्रयोग करनेके लिए अधिकसे अधिक व्यापक सार्वजनिक अहिंसात्मक आन्दोलनकी अनुमित दी जाय, तािक, पिछले २२ वपोंके शान्तिमय संघर्षमें संचित अपनी सारी अहिंसात्मक शक्तिका देश प्रयोग कर सके। ऐसा संघर्ष अनिवार्यतः गान्धीजीके नेतृत्वमें होगा और महासमिति उनसे अनुरोध करती है कि वे नेतृत्व ग्रहण करें और जो कदम उठाने हों, उनका निर्देश दं।"

महासमितिने अधिकार दे दिया कि नेताओंकी गिरफ्तारीके वाद 'हर भारतवासी स्ववं अपना पथप्रदर्शन करेगा।'

प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरूने पेश किया था और वल्लभभाई पटेलने उसका समर्थन किया था। प्रस्तावका कैवल १३ सदस्योंने विरोध किया था; इनमेंसे १२ कम्यूनिस्ट थे। कम्यूनिस्टोंने जर्मनी द्वारा रूसपर आक्रमण होनेके वाद युद्धके सम्बन्धमें अपना मत बदल दिया था।

'मारत छोड़ो' प्रस्ताव स्वीकार हो जानेके 'बाद गान्धीजीने १४० मिनटतक महा-समितिके समक्ष भाषण किया। वे पहले हिन्दुस्तानीमें नोले, फिर अंग्रेजीमें। यह, सम्भवतः, उनके जीवनका सबसे लम्बा भाषण था। उन्होंने कहा—में फौरन आजादी चाहता हूँ, आज रातको ही, कल सबेरेसे पहले आजादी चाहता हूँ—अगर वह प्राप्त हो सके। अव आजादी साम्प्रदायिक एकताकी प्रतीक्षा नहीं कर सकती। यदि वह एकता अभी प्राप्त हुई, तो उसके लिए अव जितनी कुरवानी करनी पड़ेगी, पहले उससे कममें काम चल जाता। पर कांग्रेसको आजादी हासिल करनी है या उसे हासिल करनेकी कोश्यिमों मिट जाना है। और यह भी न भूलो कि जिस आजादीको पानेके लिए कांग्रेस जूझ रही है, वह सिर्फ कांग्रेस-जनोंके लिए ही न होगी, वरन भारतकी ४० करोड़ जनताके लिए होगी। कांग्रेस-जनोंको सदैव जनताके तुच्छ सेवक बने रहना है।'

मुस्लिम लीगकी पाकिस्तानकी माँगके सम्बन्धमें गान्धीजीने कहा—''देशके करोड़ों मुसलमान हिन्दू परिवारोंने आये हैं । हिन्दुस्तानके अलावा उनकी मातृभूमि और किस जगह होगी ? हिन्दुस्तान ही प्रायः सभी भारतीय मुसलमानोंकी मातृभूमि है । इसलिए हर मुसलमानको देशकी आजादीकी लड़ाईमें सहयोग देना चाहिये । कांग्रेस किसी एक वर्ग या समाजकी नहीं है; वह पूरे राष्ट्रकी है । कांग्रेसपर कन्जा कर लेनेके निमित्त मुसलमानोंके लिए दरवाजा खुला हुआ है ।"

लेकिन मुल्लिम लीगने घोषणा की कि कांग्रेसका सार्वजनिक आन्दोलन मुसलमानों और उनकी पाकिस्तानकी माँगके विरुद्ध है। इसलिए गान्धीजीने जनताको सायधान किया था कि "इस बार संघर्षमें बहुत ज्यादा बड़ी कुरवानी देनी होगी क्योंकि संघर्षका विरोध मुस्लिम लीग और अंग्रेज दोनों करेंगे।"

फिर उन्होंने अपने जीवनके सबसे महान् संघर्षके लिए जनताको प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा—"इसी क्षणसे तुममेंसे हर स्त्री-पुरुपको अपनेको स्वाधीन मानना चाहिये और इस तरह काम करना चाहिये मानों तुम आजाद हो और साम्राज्यवादके चंगुलमें जक है हुए नहीं हो। यह कोई कल्पनाकी बात नहीं है जो में तुमसे सच मान लेनेके लिए कह रहा हूँ। यही स्वतन्त्रताका सत्व है। गुलामीकी जंजीर उसी वक्त टूट जाती है जिस क्षण गुलाम अपनेको स्वतन्त्र मान लेता है।

"यह एक छोटा-सा मन्त्र है जो मैं तुम्हें देता हूँ । तुम इसे अपने हृदयपर लिख लो ताकि तुम्हारी हर साँसमें यह प्रकाशित हो । यह मन्त्र है—हम 'करेंगे या मरेंगे' । हम या तो भारतको आजाद करेंगे या उसकी कोशिशमें मर जावँगे । हम अपनी गुलामी कायम देखनेके लिए जिन्दा नहीं रहेंगे । कांग्रे सका हर सदस्य चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, संवर्षमें इस अठल संकल्पसे शामिल होगा कि उसे देशको गुलामीमें जकड़ा देखनेके लिए जिन्दा नहीं रहना है । यही तुम्हारी शपय है । जेल भरनेकी बात अपने दिमागोंसे निकाल दो । अगर सरकार मुझे स्वतन्त्र रहने देती है तो मैं तुम्हें जेलें भरनेका कप्ट नहीं दूँगा । जव सरकार कप्टमें है, में उसपर बड़ी संख्यामें कैदियोंके भरण-पोषणका बोझ नहीं डालूँगा।"

गान्धीजीने यह भी कहा कि "कोई भी काम छिपाकर नहीं किया जायगा। यह खुला विद्रोह है। इस संघर्षमें छिपाव पाप है। स्वाधीन व्यक्तिको छिपकर कोई काम नहीं करना चाहिये। "आजादी कल नहीं, आज आनी है। इसलिए मैंने कांग्रे ससे वादा किया है और कांग्रे सने मुझसे वादा किया है कि हम करेंगे या मरेंगे।"

गान्धीजीने कहा कि सार्वजनिक आन्दोलन फौरन शुरू नहीं होगा । मैं वाइसरायसे भेंट करूँगा और उनसे अपील और अनुरोध करूँगा। इसमें दो तीन सप्ताह लग जावँगे।-लेकिन ९ अगस्तको प्रातःकाल, समितिकी वैठक खत्म होनेके कुछ ही घण्टों वाद गान्धीजी और कांग्रेस कार्य-समितिके सदस्य गिरफ्तार कर किसी अज्ञात खानको है जाये गये। पूर्व-निश्चित योजनाके अनुसार प्रान्तोंमें कांग्रेस समितियाँ अवैध घोषित कर दी गयीं और ९ अगस्तकी शामतक देश भरके सभी प्रमुख कांग्रे एजन भारत रक्षा नियमोंके अधीन पकड लिये गये। जनता स्तम्भित रह गयी, विशेषकर अखवारोंमें यह पढ़कर कि गान्धीजी व कार्य-समितिके सदस्य किसी अज्ञात स्थानको छे जाये गये हैं। हर तरहकी अफवाहें फैलने लगीं और जो विश्वास कर पाये, उन्होंने अफवाहोंमें विश्वास भी किया । देशभरमें एक अभूतपूर्व तनाव और सनसनीका बातानरण हो गया और ऐसा लगने लगा कि जनता विद्रोह कर देगी और सरकारी व्यवस्थाको नष्ट कर देगी । ९ अगस्तकी गिरफ्तारियोंके कुछ दिन पहले ही, इस तरहकी अफवाहें फैलने लगी थीं कि ९ अगस्तको ट्रेनोंका चलना वन्द हो जायगा। कुछ लोग इन अफवाहोंपर हँसे, पर कुछने उनका विश्वास भी कर लिया। और हुआ भी यही, सैकड़ों मील लम्बी रेलवे लाइनें उखाड़ डाली गयीं और बहुतसे क्षेत्रोंमें रेलोंका चलना स्थगित हो गया । यह काम इतने चुपचाप ढंगसे संघटित हुआ और इस कुशलतासे कार्यान्वित हुआ कि सारे देशमें फैले खुफिया पुलिसके अपने संघटनके वादजूद भी सरकारको इसका पता न लगा और वह भी स्तम्भित रह गयी।

कुछ दिनोंतक जनताकी उत्तेजना सार्वजनिक प्रदर्शनोंमें परिलक्षित होती रही, जिन्हें रोकनेके लिए सरकारने मारपीट, लाठी व गोलीका सहारा लिया। फिर खुला विद्रोह ग्रुरू हो गया। विद्रोही स्वयं अपने नेता थे और कहाँ ब्रिटिश सरकारपर चोट की जाय, इसका निर्णय वे स्वयं करते थे। वड़ी-वड़ो भीड़ तत्काल निर्णय करतो कि सरकारी सत्ताके किस प्रतीकपर हमला किया जाय और हमला कर देती। थाने, स्टेशन व दूसरी सरकारी इमारते जला डाली गयीं या नष्ट कर दी गयीं, तारके खम्मे तोड़ डाले गये, तार काट डाले गये। यह कोई क्षणिक को घका उद्देक नहीं था। सरकारी सम्पत्ति व यातायातके साधनोंका विनाश महीनों तक जारी रहा। इसे सार्वजनिक आन्दोलनका कार्य-क्रम ही मान लिया गया।

जो किसी सत्याग्रह आन्दोलनमें एक वार भी जेल गये थे, वे सभी कांग्रेसजन गिरफ्तार किये जा चुके थे और आन्दोलन वे लोग चला रहे थे जो कभी कांग्रेसके सदस्य भी न थे। उनमें बहुत-से छात्र थे। वे अहिंसाके पुजारी नहीं थे और जो भी अस्त्र उनके हाथ आता उसीसे ब्रिटिश सत्तापर हमला कर बैठते। हर जगह बन्दूकों और पिस्तीलें आदि इकट्ठी की गयीं; वे या तो पुलिससे छीन ली गयीं या चुपचाप बना ली गयीं। गान्धीजीके करो या मरों मन्त्रसे उन्हें प्रेरणा मिल रही थी; आन्दोलनके दौरानमें करोड़ों व्यक्तियोंने यह मन्त्र दोहराया और गोलियोंकी बौछार भी उन्हें चुप न कर सकी। कई जगह भीड़ने पुलिसको वेकात्र कर यानोंपर कन्जा कर लिया। बिलया (संयुक्तप्रान्त) में जन-समूहोंने पूरे जिलेके शासन-तन्त्रपर कन्जा कर लिया और १९ अगस्तको स्वराज्य सरकारकी स्थापना की, जो कई दिनोंतक चली। इस स्वराज्य सरकारको मान्यता और सहायता देनेके लिए लोगोंने उदारतापूर्वक चन्दे दिये। सभी सरकारी कर्मचारी कैद कर लिये गये। चित्तृ पाण्डेय इस सरकारके अध्यक्ष थे।

रेर अगस्तको सरकारी दमन ग्रुरू हुआ । फीजने जिलेपर कव्जा कर लिया और जिनताको सबक सिखाना ग्रुरू किया । ''लगभग डेढ़ सौ कांग्रेस-जनोंके घर ल्टकर जला दिये गये; औरतें और बच्चे गाँवोंसे खदेड़ दिये गये । बहुत सी स्त्रियोंके वाल काट डाले गये, उनके जेवर कपड़े छीन लिये गये और वे चीथड़े पहननेको मजबूर की गयां। बहुत से परिवार विना खाना पानी २४ घण्टेतक घरोंमें बन्द कर दिये गये । कुछ लोगोंको पेड़ोंसे बाँघकर बुरी तरह पीटा गया । बहुत से लोग थुककर चाटनेके लिए बाध्य किये गये और गन्दी-भद्दी गालियाँ दी गयां। यह भी सूचना मिली कि कई थानोंमें पकड़े गये लोगोंके मुँहमें पेशाव डाल दिया गया । लाठी, डण्डों, बन्दूकोंके कुन्दों और घूसोंसे मारना आम बात थी। थप्पड़ मारना और कभी कभी संगीनोंसे घायल कर देना अनोली घटनाएँ नहीं थीं। लगभग १२ लाख रुपयेके सामूहिक जुर्माने किये गये। लेकिन कहा जाता है कि २९ लाखसे ज्यादा रकम वस्त्र की गया। ४६ से अधिक व्यक्ति गोलियोंके शिकार हो गये और इनसे बहुत ज्यादा व्यक्ति गोलियोंसे घायल हुए। कई सी मकान जला डाले गये और १०० से ज्यादा मकान गिरा दिये गये। '''र

भारत सरकारके गृहमन्त्रीने १५ सितम्बरको जो वक्तस्य दिया उसके अनुसार एक महीनेमें लगभग २५० रेलवे स्टेशन नष्ट कर दिये गये या उन्हें क्षति पहुँचाया गयी, जिसमेंसे १८० विलया तथा पूर्वी संयुक्त प्रान्तके अन्य जिलोंमें थे, २४ रेलवे ट्रेनें पटरियोंसे इतार दी गयीं, रेलके डन्बों व कई इंजनोंको भारी नुकसान पहुँचाया गया, ५५० डाकखानोंपर हमला किया गया, इनमेंसे ५० से अधिक विलक्कुल जला डाले गये और २०० को गहरी धित पहुँची। एक लाल क्ययेके डाकके टिकट नष्ट कर दिये गये। असंख्य लेटरवन्स चिट्टियों सिहत जला डाले गये। ३५०० स्थानोंपर टेलीफोन व टेलीप्राफ्के तार काट डाले गये। यहुत-सी जगहोंपर सड़कें खोद डाली गयीं, यातायातके साधन नष्ट कर डाले गये और पुल उड़ा दिये गये ताकि उन स्थानोंका नियन्त्रण जिलोंके सदर मुकामसे न हो सके। जिन लोगोंने सरकारी सत्तापर आक्रमण किया; उनकी भीड़ कभी-कभी वड़कर एक एक लाखतक की हो गयी।

१. गोविन्दस्हाय, '४२ रिवेलियन', पृष्ठ २२४-२२५

कुछ क्षेत्रोंमें गाँवोंको मुक्तकर प्राचीन भारतमें प्रचलित पंचायत शासन कायम किया गया जो कुछ दिनोंतक चला।

आन्दोलनमें छात्रोंने प्रमुख भाग लिया । वड़ी संख्यामें वे स्कूल और कालेजोंसे निकल आये या निकाल दिये गये । संयुक्त प्रान्तकी सिर्फ वनारस कमिश्नरोमें ही ३२००० छात्र शिक्षा-संस्थाओंसे निकाले गये । वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय विद्रोही छात्रोंकी सहाई-का मुख्य केन्द्र था और प्रान्तके पूर्वी जिलोंके विद्रोहमें यहाँके छात्रोंका काफी हाथ था । यहाँ और विहारमें आन्दोलनने जितना उम्र रूप धारण किया, उतना देशमें कहीं नहीं हुआ । अन्य प्रान्तोंकी परम्पराके विरुद्ध विहारमें हिन्दुओं और मुसलमान दोनोंने मिलकर आन्दोलनमें भाग लिया । अन्य जगहोंपर मुसलमान आन्दोलनकारियोंकी संख्या दालमें नमकके वरावर ही थी। लेकिन अधिकांश शहरी मुसलमान लीगके प्रभावमें आन्दोलनसे अलग रहे।

मजदूरोंने भी आन्दोलनमें भाग लिया । अहमदावाद व गुजरातके कुछ अन्य स्थानों-की १०० से अधिक मिल तीन महीनेसे ज्यादा वक्ततक वन्द रहीं । गुजरातकी हड़ताल और जगहोंतक फैली । मद्रास, वड़ौदा, इन्दौर, नागपुर, दिल्ली आदिमें कई-कई दिनोंकी हड़तालें हुई ।

विहारमें आन्दोलनने जेलेंपर हमलेका भी रूप लिया। भीड़ जेलेंपर हमले करती और विन्दियों को मुक्त कर देती। मधुवनीमें खुद कैदियोंने विद्रोह कर दिया। जेलके सुपिरटेंडेण्टको कैद कर लिया और राजनीतिक कैदियोंको छोड़ शेप सब वन्दी भाग निकले। लेकिन हाजीपुरमें, जहाँ २००० व्यक्तियोंकी भीड़ने जेलपर हमला किया था, सभी कैदी (जिनमें राजनीतिक केदी भी शामिल थे) भाग निकले, उनकी संख्या १००० थी। वादमें उनमेंसे कुछ फिर पकड़े गये और उन्हें नशंसतापूर्वक दण्ड दिया गया। उन्हें गर्धोपर वैठा कर शुमाया गया। सीतामदीमें १०००० व्यक्तियोंकी एक भीड़ने जेलपर आक्रमण किया। आरा और संयालपरगनेमें गोंडाकी जेलेंपर भी आक्रमण हुए।

संक्षेपमें, देशमें व्यापक रूपसे अस्तव्यस्तता छा गयी। कुछ जिलोंमें पूरा सरकारी शासन ठप हो गया। कई हफ्तों वाद ही सरकार स्थितिपर काबू पा सकी और अपने समस्त साधनोंका प्रयोग जनताके प्रतिरोधके दमनमें करने लगी। और तब जघन्य पाशविक अत्या-चारोंका अध्याय शुरू हुआ। तब भी, कुछ खानोंपर विद्रोहकी आग सुलगती ही रही और बड़े-से बड़े दमन भी उसे कुचल न सके।

१९४२ के विद्रोह और पुल्सि व फौजके अत्याचारोंके वर्णनसे पूरी एक पुस्तक भर जायगी । अत्याचारोंके कुछ उदाहरणोंसे पुल्सि व फौजके व्यवहारका चित्र पूरा हो जायगा ।

२४ सितम्बर, १९४२ को केन्द्रीय विधानसंभामें एक प्रस्ताव पेशे करते हुए के. सी. नियोगीने पुलिस और फौजके, ल्टके, जनताकी निजी सम्पत्तिकी निर्वाध बरवादी करने, विना किसी उत्ते जना गोली चलाने, अहिंसक भीड़ोंपर हमला करने और गोली चलानेकी घटनाओं के कुछ उदाहरण दिये। गाजीपुरके एक जमींदारने प्रान्तीय सरकारको जो एक नोटिस दी थी, आपने उसके कुछ उद्धरण सुनाये। नोटिस इस प्रकार थी—"२६ अगस्त, १९४२ को मेरे मैनेजर (कारिन्दे) ने मुझे सन्देश मेजा कि २४ अगस्तको दोपहरमें चार अंग्रेज फौजी लगभग डेढ़ सौ फौजी सिपाहियों और नन्दगंजके थानेदारके साथ मेरे गाँव पहुँचे और गाँवके सभी मदों (जिसमें मेरे मैनेजर और नौकर भी थे) और वचोंको गोली मार

देनेकी धमकी देकर गाँवकी कची सड़कपर कतार वनाकर खड़े होनेको कहा। सब लोग सड़कपर आ गये। तब चारों अंग्रेज फीजी कुछ अन्य फीजियोंको लेकर गाँवमें धुस गये और शेपको सड़कपर पुरुषोंपर निगाह रखनेके लिए छोड़ गये। गाँवमें धुसकर फीजियोंने औरतोंसे धरोंके बाहर निकलनेको कहा और धमकी दी कि न निकलनेपर गोली मार दी जायगी। जब औरतें बाहर निकल आयीं तब सिपाहियोंने उनके जेवर उतार लिये वादमें घरोंमें धुसकर रुपया-पैसा, जेबर, आभूपण, घड़ियाँ जो कुछ मिला, लूटने लगे।

"इसके वाद फौजियोंने घरोंसे कपड़े लत्ते निकालकर उनमें आग लगा दी, गाँवके बहुतसे छप्पर जला दिये और मेरे २० असामियोंके घर जला दिये।

"गाँव ऌटने और घरोंमें आग लगा देनेके बाद फौजियोंने सड़कपर इकट्ठे १२ वर्षसे छोटे बचोंको हटा दिया । इसके बाद वहाँ मौजूद लोगोंको कपड़े उतारकर मेंढककी तरह सड़कपर बैठनेको कहा गया । यह हुक्म राइफिलोंके कुन्दोंसे मनवाया गया ।

"इसके बाद बाँस काट-काटकर छड़ियाँ बनायी गर्या और गाँववालोंकी नंगी पीट-पर पाँच-पाँच छड़ियाँ जोर-जोरसे मारी गर्या । मेरे एक नोकरने इसका विरोध किया तो उसे एक पेड़ंसे बाँधकर बुरी तरह मारा गया और उसपर रे॰ बेंत पड़े। बादमें उस नौकरके साथ तीन अन्य गाँववालोंको गिरफ्तार कर ले जाया गया। 138

के. सी. नियोगीने दूसरी घटना यह सुनाथी—"कुछ छात्र गाँवोंमें सत्याग्रहका प्रचार करने गये थे। प्रचारके बाद वे कैरा जिलेमें किसी स्टेशनसे रेलगाड़ी पकड़ने गये। उसी रेलगाड़ीसे कुछ पुलिसके सिपाहियोंकी एक दुकड़ी उतर आयी और छात्रोंकी ओर बढ़ी। छात्र शान्तिपूर्वक गिरफ्तार होनेको तैयार थे, पर पुलिसने उनपर गोली चला दी। तीन छात्र मारे गये और बहुतसे घायल हो गये। गोली चलानेके बाद पुलिसने उन लोगोंको रोक दिया जो घायलोंको पानी पिलाने आये। घायलोंको प्यास लग रही थी। पर रेलवे कर्मचारियों और गाँव वालोंको उन्हें पानी नहीं देने दिया गया।"

वम्बई प्रान्तमें पूर्वी नन्दुवारमें एक थानेदार कुछ लड़के-लड़िकयोंका पीछा कर रहा था,जिन्होंने एक ज़ल्समें भाग लिया था।एक लड़केने थानेदारको रोककर कहा—मेरे हाथमें राष्ट्रीय झण्डा है, मेरे सीनेमें गोली मार दो। थानेदारने गोली मार दी, पर वह निज्ञाना चृक गया। लड़केने फिर गोली मारनेकी चुनौती दी। इस बार थानेदारने सिपाहियोंसे लड़केको पकड़ लेनेको कहा। जब लड़का जकड़कर खड़ा कर लिया गया तब थानेदारने उसपर गोली चलायी और उसे मार गिराया। इसके बाद फिर गोली चली और वहीं पाँच लड़के मरकर हैर हो गये।

इसी तरह पटनाके सरकारी सिचवालयपर राष्ट्रीय झण्डा लगाते हुए ११ छात्रोंने पास खड़े एक अंग्रेज पुलिस अफसरसे कहा—अगर हमें रोक सकते हो तो रोक लो। उनपर गोली चलायी गयो। छः वहीं मर गये। सतवाँ अस्पतालमें मर गया। अस्पतालमें जब उसे होश आया, उसने नर्ससे पूछा—गोली मेरे सीनेमें लगी है या पीठ में ?

१, 'जे, एम, देव' 'ब्लंड एण्ड टीअर्स' में पृष्ट ६०-६१ पर उद्धत

२. वही पुस्तक, पृष्ठ ६२

नर्सके यह वताने पर कि गोली सीनेमें लगी है उस लड़केने सन्तोषकी साँस लेते हुए कहां— 'में जब मर जाऊँगा तव लोग यह नहीं कहेंगे कि में भाग रहा था तब गोली लगी।'

विहारमें "१८ महीनेके एक वच्चेको पंकड़कर इसलिए जेलमें डाल दिया गया कि उसका वाप फरार था। चार दिनतक वह बचा अपनी माँसे अलग जेलमें रखा गया।" हाकिमोंका ख्याल था कि इस तरह माँ अपने पतिके छिपनेकी जगहका पता बता देगी। लेकिन वेचारी माँको खुद पता नहीं था कि पित कहाँ हैं। पूर्णिया (विहार) में १३ अगस्तको आठ व्यक्ति गोलीसे मार डाले गये। उनमें श्रुव नामक एक वालक भी था। उसके पिता डाक्टर कुण्डू जब उसके शवकी अन्त्येष्टि करके लौट रहे थे तभी पुल्सिने उन्हें गिरफ्तार कर नजरबन्द कर दिया।

देशके कई भागों में — विशेषकर वंगाल और मध्यप्रान्तके (आहती और चिमूर गाँवों में) तथा अन्य गाँवों में सिपाहियों ने लगभग २०० स्त्रियों के साथ वलात्कार किया। कई जगह स्त्रियाँ घरों से घसीट लायी गयीं और खुली सड़कों और चौराहों पर उनके साथ वलात्कार किया गया। लोगों में आतंक छा गया। चिमूरकाण्डके विरोध में गान्धी जीके सेवाग्राम (वर्धा) के प्रोपेसर भंसाली ने ६३ दिन तक अनशन किया। वह काण्डकी जाँचकी माँग कर रहे थे, पर वाहसरायकी कोंसिलके सदस्य माधव श्रीहरि अणेतकने उनकी सहायता करने से इनकार कर दिया।

'समाज' में प्रकाशित एक लेखमें वल्जीत सिंहने पुल्सिक अत्याचारोंका वर्णन करते हुए लिखा—''तपती धूपमें खड़ा कर लोगोंपर गोली चला देना, उन्हें नंगाकर पेड़ोंसे उल्टा टाँग देना और तव कोड़े मारना, औरतोंको नंगाकर मारना, उनके गुप्तांगोंमें मिर्चे पीसकर मार देना, लोगोंको ऐसे कमरोंमें वन्द कर देना जहाँ मिर्चोंकी धूनी दी जा रही हो, लोगोंको नंगा कर पेटके वल वसिटनेको वाध्य करना और ऐसे ही दूसरे तरीके पुल्सिने जनतामें आतंक जमानेके लिए इस्तेमाल किये। पिताकी मौजूदगीमें पुत्रियोंके साथ वलात्कार किया गया। आम सड़कों और खुले स्थानोंमें औरतोंको नंगा करके घसीटा गया और दूसरी तरहसे अपमानित किया गया। पुल्सिन यन्त्रणा देनेका एक नया ढंग निकाला। लोगोंको पैर पसार कर बैटाया जाता, दो आदमी उनके हाथ पकड़ लेते, तीसरा आदमी अपना सिर उनके पेटमें दवाता, जिससे उन लोगोंके गुप्तांगोंसे खूनका फव्चारा छूट पड़ता, वे या तो वहीं मर जाते या जीवन भरके लिए वेकार हो जाते।"

पंजावके प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता शार्तू छ सिंह कवीश्वरने एक पुस्तिका में लाहीरके किलेमें राजनीतिक वन्दियोंपर पुल्सिके अत्याचारोंका वर्णन किया है। इस पुस्तिकामें उन कैदियोंके वयान हैं, जिनके साथ वर्वर व्यवहार किये गये। ये वयान अन्य जेलेंमें भी हुए अत्याचारोंके प्रतीक हैं। वास्तवमें कहीं-कहीं तो अत्याचार यहाँसे भी अधिक वृशंस हुए। इन वयानोंमेंसे कुछ यहाँ उदाहरणके लिए दे देना अनुपयुक्त न होगा।

सुभापचन्द्र वसुके भतीजे हिजेन्द्रनाथ वसुका वयान—"खुफिया पुल्सिके डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरल मिस्टर वेस मईके अन्तिम सप्ताह, एक दिन मुझसे तफतीशके वक्त वोले कि 'अगर तुमने सब कुछ न बता दिया तो तुम्हें गोली मार दी जायगी।' इसके बाद

१. गोविन्दसहाय, वही पुस्तक, पृष्ट १६१

२. दि लाहौर फोर्ट टार्चर कैम्प

मुझे तनहाई मेलमें ले जाया गया । मैं फिर सरदार वहादुर सम्पूरन सिंहके सामने पेश किया गया, जिन्होंने मुझसे कहा कि डी. आई. जी. ने मेरे और पीटे जाने तथा मेरे सेलमें कचा कोयला जलानेका हुक्म दिया है। वे मुझे जूतों और घूँसोंसे पीटने लगे और रातमें देरतक मुझे जबरदस्ती जगाये रहे। फिर में सेलमें ले जाया गया जहाँ कच्चा कोयला जल रहा था, में आध घण्टे वाद वेहोश हो गया। डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्टने मुझे फिर बुलाकर धमकी दी कि "तुम्हें नंगा कर एक वाँस तुम्हारे गुप्तांगमें ठूँस दिया जायगा या सरदार निरंजन सिंह तालिबकी तरह यातना दी जायगी।"

सुभाप वसुके साथी सरदार निरंजनसिंह तालिवका वयान—"एक सव इंस्पेक्टरने मुझे जमीनपर गिरा दिया, मेरा मुँह जमीनसे लड़ गया। मेरे कपड़े उतारकर उसने मुझे जूलोंसे बुरी तरह मारा। फिर वह मेरी जाँचोंपर बैठ गया और मेरे सीनेपर इतनी चोटं की कि मैं वेहोश हो गया। इसके वाद प्रतिदिन मुझे इसी तरह मारा जाता। दिन रात मुझे जगाये रखा जाता। मुझे बैठने नहीं दिया जाता। अगर में ऊँघने लगता तो मेरी दादी नोची जाती। मैंने आत्मचात करनेका फैसला कर लिया और एक दिन दपतरकी सबसे ऊँची सीढ़ीसे कूढ़ पड़ा। पर मैं मरनेसे वच गया।"

प्रोफेसर हेरल्ड लास्कीको सोशिलस्ट नेता राममनोहर लोहियाने एक पत्रमें लिखा— "चार महीनेतक मुझे एक न एक यातना दी जाती रही। मुझे दिन रात जगाये रखा जाता—एक बार तो इस दिनतक बराबर जगाये रखा गया। पुलिस मुझे बराबर खड़ा रखती और जब-जब मैंने इसका विरोध किया तब-तब पुलिसने मुझे हथकड़ोमें जकड़े हाथोंके बल फर्शवर घसीटा।"

सोशल्स्ट नेता जयप्रकाशनारायण—"मुझे परेशान करनेकी यन्त्रणा सीमातक जा पहुँची जब मुझे बराबर जगाये रखा जाता। सबेरेसे आधी राततक मुझे बराबर दफ्तरमें रखा जाता, उसके बाद घण्टे भरके लिए सेलमें भेज दिया जाता, फिर घण्टे दो घण्टेके लिए दफ्तरमें रखा जाता, फिर घण्टे भरके लिए सेलमें भेज दिया जाता, फिर घुला लिया जाता, ऐसे ही सबेरा हो जाता।"

रामानन्द मिश्र—"मुझे २० बार मार पड़ी । मुझे थप्पड़, घूँसे, ठोकर, तमाचे गारे जाते, मेरे बाल नोचे जाते । ११ मार्च १९४२ को मुझे इतना मारा गया कि में अचेत हो गया और कह नहीं सकता कि उसके बाद भी मार पड़ती रही कि नहीं।"

वम्बईमें—"पुलिसने लोगोंको वेरहमीसे टोंका और स्चना मिली कि दो व्यक्ति मारके बाद खूनकी के करने लगे और मर गये। दो दिनकी नृशंस ठुकाईके बाद एक व्यक्ति जब तीसरे दिन छूटा तो उसने आत्महत्या कर ली। नाखुनोंमें पिनें चुमोने, कई कई दिन लगातार वेरहमीसे मारपीट करने, पैरोंसे उलटा लटकाकर छलाने और किर शिरके वल ही पटक देने, वर्षकी सिलींगर लिटाने और इसी तरहकी और निर्दय घटनाओंकी भी यूचनाएँ मिलीं।" एक अध्यापकको मोटर वससे घसीट लिया गया और मार-मारकर नोला कर दिया गया क्योंकि उसने कांग्रेसके नारे लगाये थे। वेदकी हालमें एक लड़केके चार दाँत तोड़ डाले गये क्योंकि 'उसने फरार लोगोंका पता नहीं वताया।"

कांग्रेसके अनुमानके अनुसार "पुल्सिका गोली, वम और गारसे '१५००० से कम व्यक्ति नहीं' मारे गये । जो धायल हुए वे असंख्य थे।" लेकिन भारत सरकारके अनुसार ९४० मारे गये; १६३० घायल हुए; ५३८ वार गोली चलायी गयी; ६०२२९ व्यक्ति गिरफ्तार हुए; ६० वार फीज बुलायी गयी; पटना, भागलपुर, निदया, मुँगेर, तालचेरा और तमलुकमें ६ वार हवाई जहाजोंसे वम वरसाये गये; ३१८ रेलचे स्टेशन जलाये गये; १२००० जगहोंपर टेलीफीन व टेलीग्राफके तार काटे गये; ९४५ डाकखाने लूटे या जलाये गये; ५९ रेलगाड़ियाँ पटरीसे उतारी गयीं; १८ लाख रुपयेके रेलगाड़ियोंके डब्बों व इंजनोंकी क्षित हुई; ९ लाख रुपयोंकी ट्रकोंको क्षित पहुँचायी गयी, रेलवे स्टेशनोंके नष्ट होनेसे ८॥ लाख रुपयेकी क्षित हुई, २ लाख रुपयेकी नगदी या कीमती चीजोंका नुकसान हुआ और ६॥ लाख रुपयेके दूसरे सामानोंका नुकसान हुआ।

पुलिस और फौजके हमलों और अत्याचारोंसे जनताका कितना नुकसान हुआ उसका अनुमान कभी किसीने नहीं लगाया।

यह ग़ुरूके हपतों में हुआ । उसके वाद आन्दोलनने गुप्त रूप घारण कर लिया और गुप्त उपायों से उसे जीवित रखा गया । राजनीतिक कार्यकर्त्ता छिप,गये और पुलिसको चकमा देने लगे । वे नाम और वेशमृषा वदलकर फिर विद्रोहकी तैयारी करने लगे । कांग्रेसके मध्यम दर्जे के नेता अधिकांशतः सोशिलस्ट और वे जिन्हें अहिंसामें विश्वास नहीं था, हिश्यार इकट्टा करने और वमवारूदका उपयोग सीखने लगे । एक बार यह योजना वनायी गयी कि रेलके इंजनोंके कोयलेमें वारूद रख दी जाय जिससे इंजनोंमें विस्फोट हो जायगा । अगस्त विद्रोहमें सरकारको मँहगी खुफिया पुलिस सोती रह गयी । उसे पता ही न चलसका कि ९ अगस्तको नेताओंकी गिरफ्तारीके वाद आन्दोलन जगह-जगह संबदित कैसे हुआ । लेकिन दूसरे विद्रोहकी तैयारीके समय खुफिया पुलिस सचेत हो चुकी थी और यहुतसे नये लोग उसमें भरती हो चुके थे । बहुतसे भेदिये गुप्त आन्दोलनकारियोंके गुप्त अड्डोंमें घुस आये और उनमेंसे एकने गुप्त वारूद गोदामकी स्चना देकर सरकारका वहुत मला किया । गोदामपर पुलिसने छापा मारा और इंजनोंके कोयलेमें वारूद मिलानेकी योजना नाकामयाव हो गयी । यह एक उदाहरणमात्र है ।

अक्सर, फरार लोगोंका पता लग जाने पर भी पुल्स उन्हें गिरपतार न करती। इससे पुल्सिको उन लोगोंको भी गिरफ्तार करनेका मौका मिल जाता जो इन फरार लोगोंको शरण देते थे। जब ये लोग गिरफ्तार होते तो दो-दो महीनेतक जाँच, तफतीश और सवाल पूछनेके लिए पुल्सि थानोंकी हवालातोंमें रखे जाते जहाँ हवा और रोशनीका भी इन्तजाम न होता था। ये हवालातें यन्त्रणाग्रह होती थीं जहाँ राजनीतिक कार्यकर्ताओंको मारपीट कर और भूखे रखकर उनसे उनके साथियोंका पता और उनके खुदके कामोंका क्योरा पूछा जाता था। इस पुस्तकका लेखक स्वयं हवालातको यन्त्रणाका शिकार हुआ। एक महीनेतक उसे तीन आने रोज खानेके लिए मिलते रहे जो मजदूरोंके खानेकी दूकानसे एक वक्तके भोजनके लिए भी काफी न होते थे। वह इस तरह भूखा हो नहीं रखा गया; उसे एक हवालातसे दूसरी हवालातमें भेजा जाता रहा। जिस आखिरी हवालातमें उसने दो हफते गुजारे उसमें पेशावकी तीव दुर्गन्ध आती थी। हवालातें कभी साफ नहीं की जातीं। वहाँ वे लोग अधिकसे अधिक २४ घण्टेके लिए रखे जाते हैं जिनपर मुकदमें चलते होते हैं। ये लोग वहीं फर्शवर पेशाव कर देते और उसकी सफाई कभी नहीं होती। यहीं लेखकको खुफिया पुल्सिके एक अफसरने इतने जोरसे तमाचा मारा कि कई मिनटतक उसकी आँखोंके सामने अंधेरा

छाया रहा । लेखकके एक साथी कार्यकर्त्ताको हवालातमें ही इतना मारा गया कि जब लेखक उनसे मिलने गया तो उनका अंग अंग दर्द कर रहा था । यह हवालातमें होनेवाले पुलिस व्यवहारका एक उदाहरण है ।

कुछ मामलोंमें, फरार लोगोंके वृहे पिता और सम्बन्धी गिरफ्तार कर लिये गये या परेशान!किये गये ताकि पुलिसको फरार लोगोंका पता लग जाय ।

लेकिन विद्रोहकी दूसरी चिनगारी भड़कानेवालोंको जनतामें पहले जैसा उत्साह पेदा करनेमें सफलता नहीं मिली। इसका एक कारण उनके गोपनीय ढंग थे और दूसरा था पुलिसका सजग रहना। लेकिन तो भी, इधर उधर छिटफुट घटनाएँ होती रहीं, जिनके कारण अधिकारियोंको चैन नहीं मिला। विद्रोहके इस दूसरे दीरका एक रूप अहिंसात्मक भी था। कांग्रेसके पुराने ढंगके जुल्स निकाले जाते और प्रदर्शन किये जाते, जिन्हें पुलिस लाटी गोलींसे तितर वितर करती। लेकिन अब जनतामें पुलिसका पुराना आतंक नहीं रहा और जुल्सोंमें जो दिलेर होते वे उन्हें खुले आम गालियाँ देते थे। लगता था कि कांग्रेसका पूर्ण दमन हो चुका था; कांग्रेस दप्तरों और कागजपत्रोंपर पुलिसका कव्ना था; तिरंगा कहीं दिखाई भी नहीं पड़ता था—स्वतन्त्रता दिवसको भी नहीं। गान्धीजीके आर्थिक दर्शनके प्रतीक खहर भण्डार या तो खुद गान्धीजीके आदेशानुसार वन्द कर दिये गये थे या पुलिसने उनपर कव्ना जमा लिया था। इसी तरहसे, गान्धीजीके कहनेपर, संसरके गलाघोंह आदेशोंका पालन करनेकी जगह ९६ राष्ट्रीय समाचारपत्रोंका प्रकाशन वन्द कर दिया गया था। लेकिन कुछ समय बाद उनमेंसे अधिकांश फिर प्रकाशित होने लगे। गान्धीजीने कहा था कि अगर अखवारोंपर सची खवरें छापनेपर पावन्दी लगायी जाय तो हर व्यक्तिको खवरें देनेवाला चलता फिरता अखवार वन जाना चाहिये।

कांग्रेसका अनुमान था कि "कमसे कम एक लाख व्यक्ति कैंद किये गये। उनमेंसे कुछ नजरबन्दीको थोड़ी-सी अवधिके बाद छोड़ दिये गये, लेकिन शेप अनिश्चित कालके लिए बन्द रहे। गिरपतारियाँ पुलिसके लिए रुपया कमानेका ढंग बन गर्यो। निरीह व्यक्ति पकड़ लाये जाते और बड़ी रकमें बसूल करनेके बाद ही रिहा किये जाते।"

जिस तरह विद्रोहके विस्फोटने हिंसात्मक रूप ले लिया, वह गान्धोजीके अहिंसा सिद्धान्तके विलकुल विपरीत था। अपनी गिरफ्तारीके पाँच दिन वाद १४ अगस्त १९४२ को गान्धीजीने वाइसरायको लिखा कि जो हिंसा हो रही है, उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने लिखा—"हिंसाकी वात तो किसी मंजिलपर सोचीतक नहीं गयी। अहिंसात्मक कार-वाईमें क्या-क्या शामिल हो सकता है—उसकी परिभाषाकी ऐसी चालाकी और कुटिलतासे व्याख्या की गयी है कि उसका यह अर्थ ले लिया जाय कि कांग्रेस हिंसात्मक काररवाईकी-तैयारी कर रही थी।" भारत सरकारके यहसचिवको २३ सितम्बर को लिखे गये पत्रमें गान्धीधीने फिर कहा—"इसके विपरीत जो कुछ भी कहा गया है, उसके बावजुद मेरा दावा है कि कांग्रेसकी नीति अहिंसाकी है और इस वातमें कोई संशय नहीं है। कांग्रेस नेताओंकी अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियोंसे जनता इतनी कोधित हो गयी लगती है कि वह अपना आत्मसन्तुलन खो बैठी। मेरी धारणा है कि जो विनाश हुआ है उसके लिए कांग्रेस नहीं, सरकार जिम्मेदार है।" जब १९४३ में ये पत्र प्रकाशित हुए, लोग सोचने लगे कि सरकारने इन्हें समयसे प्रकाशित क्यों नहीं किया।

३१ दिसम्बर १९४२ को :गान्धीजीने वाइसरायको एक पत्र और लिखा जिसमें उन्होंने १० फरवरी १९४३ से २१ दिनका उपवास करनेकी अपनी इंच्छा प्रकट की ! गान्धीजीने लिखा कि सरकारने कांग्रेस नेताओंकी अनावस्यक गिरफ्तारियोंसे लेकर निरन्तर दमनकी जो वाढ़-सी ला दी उससे उसने जनताका वहुत वड़ा अहित किया। गान्घीजीने कहा कि परीक्षाके ऐसे समयके लिए सत्याग्रहके नियमके अनुसार एक उपचार है और वह है 'उपवास द्वारा दारीरको स्लीपर चढ़ा देना।' गान्धीजीने अन्तर्मे लिखा कि लेकिन यदि सरकार मुझे मेरी गलती या गलतियाँ समझा दे और मुझे विस्वास दिला दे कि गलती मेरी ही थी तो मैं उपवास नहीं कहूँगा और गलती दूर करनेका उपयुक्त प्रवास कहूँगा। अपने जवावमें वाइसरायने देशमें जो कुछ हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेसपर, और उसका काफी वडा भाग स्वयं गान्धीजीपर डाला । उन्होंने गान्धीजीसे उपवास न करनेके लिए कहा और लिखा कि अन्य कारणोंके अलावा उपवास एक तरहकी राजनीतिक धमकी और जवर-दस्ती है। लेकिन गान्धीजीने कहा कि "मुझे जो वाइंसरायसे नहीं मिला उस न्यायके लिए मेरा उपवास सर्वोच न्यायालयमें एक अपील है।" उत्तेजित भीडकी हिंसाका जो उत्तरदायित वाइसरायने कांग्रेस और गान्धीजी पर डाला था, उसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा— ''आपने विना मुकदमा चलावे और विना उनका पक्ष चुने लोगोंको दण्ड दिया है। मेरे यह पूछनेमें क्या गलती है कि जिस अपराधमें आपने दण्ड दिया उसका सवृत सुझे दिखा-इये । आपने अपने पत्रमें जो लिखा है उससे दिलजमई नहीं होती । जो सवृत आपको देना है वह अंग्रेजी न्याय-शास्त्रके अनुकूल होना चाहिये। आप कहते हैं कि कांग्रेसके विरुद्ध अभियोग प्रकाशित करनेका समय अभी नहीं आया है। पर क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि किसी निष्पक्ष अदालतमें पेश होने पर आपके सवृत निराधार भी सावित हो सकते हैं।"

वाइसरायसे हुए पत्र-व्यवहारसे, उपवास करनेका गान्धीजीका निश्चय नहीं बदला और नियत दिन १० फरवरी सन् १९४३ को सवेरे ९ वजेसे वम्बईमें आगा खाँके महलमें गान्धीजीने उपवास आरम्भ कर दिया । वह यहीं नजरवन्द थे । उनकी गिरफ्तारीके बाद उनके उपवासकी खबर उनके वारेमें पहली खबर थी जो जनताको मिली ।

१३ फरवरीको, जब गान्धीजीका उपवास चल रहा था, कांग्रेंसके अध्यक्षने कार्यसिमितिके सदस्योंकी रायके आधारपर अहमदनगर किलेसे जहाँ वे सब एक साथ नजरबन्व
थे, वाइसरायको एक पत्र लिखा जिसमें इस आरोपका खण्डन किया गया था कि कांग्रेसने
हिंसात्मक आन्दोलनका संघटन किया था। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस महासमितिने कभी
ऐसे आन्दोलनके वारेमें सोचा भी नहीं। गान्धीजीके उपवासके जल होते ही सरकारने
एक पुस्तिका— उपद्रवोंके लिए कांग्रेसका उत्तरदायित्व' नामसे प्रकाशित की और उसका
त्यापक वितरण किया। गान्धीजीके लेखोंसे गलत सन्दर्भमें उद्धरण छापकर यह समझानेकी
कोशिश की गयी कि वे पस्तिहम्मत और जापानके समर्थक हैं; उन्होंने और कांग्रेसने
हिंसक कार्योंकी योजना बनायी या उन्हें नजरअन्दाज किया; गान्धीजी '४२ के उपद्रवोंके लिए उत्तरदायी हैं। कुछ और भी छोटे-मोटे दोपारोप थे। गान्धीजीने इन आरोपोंका उत्तर विस्तृत रूपमें दिया। उन्होंने अपने साप्ताहिक 'हरिजन' से लम्बे-लम्बे अंश उद्धृत
कर साबित किया कि सरकार जो साबित करनेकी कोशिश कर रही है, तथ्य उसके विल्

कुल उलटे हैं । गान्धीजीने कहा कि मेरे और मेरे सहयोगियोंके खिलाफ जो अभियोग लगाये गये हैं, वे या तो वापस लिये जायँ या उन्हें किसी निष्पक्ष अदालतके सामने पेश कर दिया जाय ।

जय विद्रोहकी यक्ति क्षीण हो गयी और भारत अंग्रेजों द्वारा पददलित हो असहाय पड़ गया, तव गान्धीजी फिर एक वार देशके ध्यानके केन्द्र वन गये। गान्धीजीके स्वास्थ्यके सम्बन्धमें जाननेके लिए सैकड़ों लोग रेडियोके आसपास इकट्ठे हो जाते। २० फरवरीको डाक्टरोंने गान्धीजीके सम्बन्धमें विज्ञित प्रकाशित की कि उनकी हालत अत्यधिक चिन्ताजनक हो गयी है। दूसरे दिन तीसरे पहर उनकी हालत और विगड़ गयी और नाड़ी लगभग वन्दि सी हो गयी। उत्तेजित भीड़ सड़कोंपर टहल रही थी। पुलिसके जरासे उकसानेसे फिर एक बार अगसके हश्य दिखाई पड़ने लगते। लेकिन सरकारने देशभरमें पूरी तैयारी कर रखी थी; वह जानती थी कि गान्धीजी किसी क्षण भी मर सकते हैं। एक अजन खामोशी चारों तरफ छायी हुई थी, जिससे लगता था कि यह दुःखद घटना अनिवार्य है। वाइसरायकी कींसिलके तीन भारतीय सदस्यों—सर होभी मोदी, निल्नीरंजन सरकार और माधव श्रीहरि अणेने वाइसरायसे गान्धीजीकी रिहाईकी असफल प्रार्थनाके बाद कींसिलसे इस्तीफा दे दिया था। चर्चिल इङ्गलैण्डके प्रधान मन्त्री थे; वे, चाहे जो हो जाय, गान्धीजीको रिहा करनेको तैयार नहीं थे। लेकिन, उपवासके १५ वे दिन गान्धीजीका शरीर उपवासके अनुकृल प्रतिकिया करने लगा और उनके संकट पार कर जानेकी घोषणा कर दी गयी। ३ मार्चको नारंगीका रस पीकर गान्धीजीने उपवास तोडा।

वहे-वहे डाक्टरोंने उपवास घातक वताया था। उपवास खत्म होने पर डाक्टर विधानचन्द्र रायने डाक्टरी दृष्टिकोणके सम्बन्धमें निम्नलिखित वक्तव्य दिया—

"हमारी भविष्यवाणी (कि गान्धीजीको वचाया नहीं जा सकता) गलत सावित हुई। हमें औसतपर निर्भर रहना था और हम सिर्फ यह राय दे सकते थे कि इस हालतमें औसत व्यक्तिको क्या होगा। लेकिन गान्धीजी एक चमस्कार हैं; कभी-कभी वे औपिध और शरीर विज्ञानको चिकित और स्तिभित कर देते हैं। शरीरपर मस्तिष्कका पूर्ण नियन्त्रण और जीवित रहनेका हद संकल्य—जिसके लिए उन्होंने हर क्षण संघर्ष किया — इन दो वातोंसे ही वे संकट पार कर गये। उपवासके वीच एक बार यह संकट दुर्निवार माल्स्म पढ़ता था।"

उपवासके कारण देशमें जो उत्तेजना दिखाई पड़ती थी, उपवासके सफल अन्तने वह खत्म हो गयी। अगले १२ महीनोंमें देशमें लगभग कोई भी राजनीतिक काररवाई नहीं हुई। ५ मई १९४४ की शामको वम्बई पुल्सिके इंस्पेक्टर-जनरल आगा खाँ पैलेसके नजरवन्दी कैम्पमें पहुँचे और गान्धीजीसे (जिनका स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं था) कहा कि कल सबेरे आप अपने दलके साथ मुक्त कर दिये जाक्यों। "क्या आप मजाक कर रहे हैं ?" गान्धीजीने पूछा। "नहीं, में गम्भीर वात कह रहा हूँ।" इंस्पेक्टर जनरलने जवाब दिया और कहा—"आप यदि चाहें तो स्वास्थ्य सुधारके लिए यहाँ कुछ दिन और रह सकते हैं। कल सबेरे ८ वजे पहरा उठा लिया जायगा और तब आपके मित्र आपसे मिलने आ सकेंगे या आप अपने मित्रोंके यहाँ पूना या वस्बई कहीं भी जा सकेंगे। निजी तीरपर

में आपको यहाँ रहनेकी सलाह नहीं दूँगा । यह फौजी क्षेत्र है और जब आपके दर्शन आदि-के लिए भीड़ इकट्ठी होने लगेगी तव कोई झगड़ा भी हो सकता है, जिसे आप पसन्द नहीं करेंगे।" रिहाईसे पहले गान्धीजीको छोड़कर उनके दलके हर सदस्यको नोटिस दी गयी कि नजरवन्दीकी अविधमें आगा खाँ महल्में जो कुछ हथा उसे आप किसीको नहीं वतायंगे। दलके लोग ऐसा वादा करनेमें हिचकिचाये, पर गान्धीजीके कहने पर वे मान गये और वादा कर दिया। गान्धीजीका दल नजरवन्दीसे लौट आया। पर गान्धीजीके दो प्रिय संगी नहीं लौटे। वे थे उनके सेकेंटरी महादेव देसाई जिनकी मृत्यु १५ अगस्त १९४२ को हृदयकी गति वन्द हो जानेसे हो गयी थी और गान्धीजीकी पत्नी कस्तूर वा जिनकी मृत्यु २४ फरवरी १९४४ को हुई थी। गान्धीजीको मलेरियाने जकड़ लिया था और वादमें पता चला कि वे कृमिरोगसे भी काफी दिनोंसे पीड़ित थे। जब सरकारके डाक्टरी सलाहकारने वताया कि गान्धीजीको नजरवन्द रखना खतरेसे खाली नहीं है, तब उन्हें छोड दिया गया। इसीलिए गान्धीजी रिहाईसे खुदा नहीं थे। उन्होंने कहा-"मैं लिजत हूँ। मुझे वीमार नहीं पड़ना चाहिये था। मैंने स्वस्य रहनेको कोशिश भी की, पर अन्तमें हार गया।'' यह प्रस्त उटा कि क्या गान्धीजी फिर सार्वजनिक आन्दोलन शुरू करेंगे। पर उनकी अचानक फिर गिरफ्तारीके कारण यह सवाल ऐसे ही रह गया। गान्धीजीने कहा कि मुझे आन्दोलनका नेतृत्व करनेका जो अधिकार मिला था, वह मेरी गिरफ्तारीके कारण खत्म हो गया । अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति बदल गयी थी और १९४२ की कांग्रेसकी माँग उसी तरह दोहरायी नहीं जा सकती थी । गान्धीजीने कहा-" आजकी परिस्थितिमें में गैरफौजी मामलें -पर पूर्ण नियंत्रणका अधिकार-प्राप्त राष्ट्रीय सरकारसे ही संतुष्ट हो जाऊँगा। सरकार वनानेवाले व्यक्ति केन्द्रीय विधानसभाके निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जार्ये । आजकी परिस्थितिमें ऐसी सरकारका निर्माण स्वतन्त्रताकी घोषणाके समान ही होगा । इ गरुँण्डके शाहकी तरह वाइस-राय उत्तरदायी मन्त्रिमण्डलके अध्यक्ष रहेंगे । हर प्रान्तमें जनप्रिय सरकार वनेगी । रक्षा विभाग रहेगा तो राष्ट्रीय सरकारके अधीन, पर वाइसराय और कमाण्डर-इन-चीफ सारे फौजी काम-काजकी देखभाल करेंगे। वाइसरायने यह सुझाव अस्वीकार कर दिया।

१७ जूनको गान्धीजीने कांग्रेस कार्य-सिमिति और आवश्यकता हुई तो स्वयं वाइस-रायसे मिलनेकी अनुमित माँगी, जो नहीं मिली । एक वर्ष और गुजरा, पर जून १९४५ तक देशके राजनीतिक गत्यवरोधका कोई हल नहीं निकला ।

इसी वीच, वंगालमें ऐसा भवंकर अकाल पड़ा जैसा लोंगोंकी याददाखमें कभी नहीं पड़ा था। हजारों व्यक्ति प्रतिदिन भूखसे मरते और सड़कोंपर लाग्नें इकट्ठी होतीं। सरकारके अनुसार अकालमें १५ लाख व्यक्ति मरे, पर कलकत्ता विश्वविद्यालयके प्राच्य मानविज्ञान विभागने अकालग्रस्त गाँवोंमें जाँच करके जो अनुमान लगाया उसके अनुसार ३४ लाख व्यक्ति अकालके कारण मर गये। कुछ अन्य अनुमानोंके अनुसार मृत व्यक्तियोंकी संख्या और भी ज्यादा थी। लड़ाईके क्षेत्रोंमें वड़ी मात्रामें चावल भेजा गया था और मुनाफाखोरोंने इस जबन्य पापमें १५० करोड़ रुपयेका मुनाफा कमाया।

अध्याय ३०

आजाद हिन्द फौज

पहले महायुद्धकी तरह दूसरे महायुद्धके भी आरम्भसे ही सुदूर पूर्वके विभिन्न देशों में वसे भारतीयोंने ब्रिटिश-विरोधी कार्यों लिए संघटन ग्रुरू किया। ऐसे प्रमुख भारतीयों का एक सम्मेलन टोकियोमें हुआ। यह तय हुआ कि भारतको आजादीका जोरदार प्रचार थाइलिए, मलाया और वर्मामें किया जाय। वर्मा और मलाया स्थित भारतीय फीजियों में ब्रिटिश-विरोधी-साहित्य गुप्त रूपसे भेजा गया और उनसे विद्रोह कर देनेकी अपील की गयी। ऐसे कामों प्रवीण लोग वहाँ स्थित फीजों में जुपचाप भरती भी करा दिये गये; उनमेंसे कुछ पकड़े गये और उनहें लम्बी लम्बी कैदकी सजाएँ मिलीं। शंघाईमें उस्मान खाँने एक गदर पाटीं स्थापित की और थोड़े समयमें सुदूर पूर्वमें काम करनेवाली ऐसी सभी संस्थाओं आपसी सम्पर्क स्थापित हो गया। मलाया, वर्मा व थाइलैण्डके भारतीय राजनीतिक कार्य-कर्चाओं अधिकांशतः सिख थे और उनमें सबसे अधिक उत्साही कार्यकर्त्ता थे ज्ञानी प्रीतम सिंह।

सुदूर पूर्वके इन कान्तिकारियों सं सबसे प्रमुख रासिवहारी बसु थे जो सन् १९१५ में जापान निकल भागे और शादी कर वहीं वस गये थे। युद्धने उन्हें पूर्वके देशों में भारतीयों को अंग्रेजोंपर आक्रमणके लिए संघटित करनेका एक बिंद्या अवसर प्रदान किया। जिस दिन जापानने ब्रिटेन और अमेरिकाके विरुद्ध युद्धकी घोषणा की, उसी दिन टोकियों में रहने-वाले भारतीयोंने एक सभा कर बसुकी अध्यक्षतामें एक सिमित बनायी, जिसका काम भारतकी स्वाधीनताके लिए काम करना था। भारतीय जेलों ने २२ वर्षकी केंद्र काटनेवाले पुराने कान्तिकारी अमरिसहने दिसम्बर १९४१ में वंकाकमें स्वाधीनता लीगकी स्थापना की। स्वामी सत्यानन्द पुरीने थाइलैण्डमें जो याइ-भारत संस्कृति लीग बनायी थी, वह भारतीय राष्ट्रीय कोंसिलमें परिवर्तित हो गयी। ये भारतीय भारतकी आजादीके लिए जापानके सहयोगसे लड़नेवाले थे, जिसने उन्हें आक्ष्वासन दिया था कि भारतमें अपना राज्य कायम करनेका उसका कोई इरादा नहीं है। जब जापानी सेना मलायामें बढ़ रही थी प्रीतमित उसके साथ गये। उनका एक उद्देश्य यह था कि भारतीय सिपाहियोंसे अंग्रेजोंकी ओरसे न लड़नेकी अपील करें, और उनका दूसरा उद्देश्य था कि घायल भारतीयोंकी चिकित्साका प्रवन्ध किया जाय।

मलायामें जापानी सेना बड़ी तेजीसे आगे बड़ी और सिंगापुरके पतनने अंग्रे जोंका साहस मंग कर दिया। अंग्रे जी व भारतीय फीजोंके सिंगापुर स्थित सेनापित लेपिटनेण्ट कर्नल हण्टने जैसे ही अपनी फीजों जापानी प्रतिनिधि मेजर फूजीवाराको सोंपीं, उन्होंने भारतिय फीजको भाषणमें वताया कि जापानने ब्रिटेनके खिलाफ युद्धकी घोषणा की है, भारतके खिलाफ नहीं और यहाँ मौजूद भारतीय फीजी युद्ध-चन्दी नहीं हैं। १४ वीं पंजाब रेजिमेण्टके कतान मोहनसिंह भारतीय फीजियोंके सबसे पुराने अफसर थे और उस वक्त जीटरामें स्थित थे। प्रीतमिसह उनसे मिले और वे भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमें शामिल होनेको तैयार हो गये।

मोहनसिंहने भारतीय फौजके समक्ष भाषण करते हुए कहा—'पूर्वमें अंग्रेजी अत्याचार अव अधिक समय नहीं चलनेवाला और उनका बदनाम राज शीघ ही खत्म होगा । जापानी फौजने उन्हें मलाया और सिंगापुरसे खदेड़ दिया है और वे वर्मासे भी भाग रहे हैं। हिन्दु- . स्तान आजादीके दरवाजेपर खड़ा है और यह हर भारतीयका कर्त्तव्य है कि वह इन राक्षसीं-को मार भगानेमें मदद दे, जो इतने दर्जनों सालोंसे हमारा खून चूस रहे हैं। आजादीके हमारे सपने पूरे करनेमें जापानियोंने हमें पूरी मददका भरोसा दिलाया है और अव यह हमारे अपर निर्भर है कि हम ४० करोड़ देशवासी नरनारियोंकी स्वतन्त्रताके लिए संघटित हों।"

इसके शीव बाद मलाया स्थित गैरफौजी भारतीयोंके प्रतिनिधियोंने सिंगापुरमें एक वैठक कर भारतीय स्वाधीनता लीग वनायो । लीगने आजाद हिन्द फौजकी स्थापना करनेका निर्णय किया और इसके लिए जून १९४२ में वंकाकमें सुदूरपूर्वके सभी भारतीयोंका एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलनकै अध्यक्ष रासविहारी वसु हुए और इसमें ११० प्रति-निधियोंने भाग लिया। "यह सम्मेलन कैवल भारतीयोंका था और इसमें जापानियोंका कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ नहीं था। सभी वक्ताओंने जापानके संशयात्मक उद्देश्योंका खलकर जिक्र किया। उनमेंसे कईने जापानी साम्राज्यवादकी कद्भतम आलोचना की।" भारतीय स्वाधीनता लीगकी संघर्ष समितिकै नियन्त्रणमें डेढ् लाख सैनिकोंकी फौज बनानेका निरचय इस सम्मेलनमें हुआ । यह फौज भारतमें विदेशियों के खिलाफ संवर्ध करने के लिए वनी । मोहनसिंह इस फौजके जनरल अफसर कमाण्डिंग वने और उन्होंने अपना सदर दफ्तर माउण्ट प्लेजेण्ट (सिंगापुर) में बनाया । माउण्ट प्लेजेण्टमें अंग्रेजोंने कभी किसी भारतीय या एशियाईको टहलने भी नहीं दिया था । आजाद हिन्द फौजमें लगभग २००० लोग भरती हुए । सुद्र पूर्वके भारतीय समाजमें आजादीकी लड़ाईमें योग देनेके लिए उत्साह भर गया था। लेकिन जब आजाद हिन्द फौजने ब्रिटिश भारतपर हमलेकी तैयारी शुरू की, जापानियोंने उसमें हस्तक्षेप कर उसका प्रवन्ध अपने हाथमें लेनेकी कोशिश की, जिसके लिए भारतीय राजी नहीं थे। आजाद हिन्द फौजके अफसरोंने यह स्पष्ट कर दिया था कि जापानी फौजियोंकी किसी भी मददके विना आजाद हिन्द फौज भारत भूमिमें बुसेगी। इन अफसरोंको आर्याका हो उठी कि जापान भारतीयोंका, अपने साम्राज्यवादी उहेर्यको पुरा करनेके लिए, उपयोग करना चाहता है। जब मोहनसिंहने जापानी अधिकारियोंसे कहा कि जो भारतीय एण्टी एयर क्रेफ्ट कम्पनियोंके उपयोगमें आ रही हैं, वे मेरे सिपुर्द की जावँ, तव जापानियोंने साफ इनकार कर दिया। संवर्ष समितिको सूचनाएँ मिल रही थीं कि जापानी भारतीयोंके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आजाद हिन्द फौज तथा जापानी अफसरोंके बीच विचार-विमर्शके लिए एक वैठक बुलायी गयी जिसमें एक जापानी मेजर-जनरलने वहे घमण्ड और क्रोधसे भारतीय प्रतिनिधियोंसे वात की । इसपर मोहनसिंहने आजाद हिन्द फीज भंग कर देनेका फैसला किया, पर रासविहारी वसुने इस फैसलेका विरोध करते हुए कहा कि मोहनसिंहको ऐसा करनेका अधिकार ही नहीं है। मतभेद इस सीमातक बढ़ा कि भारतीय स्वाधीनता लीगके अध्यक्षकी हैिसयतसे रासिवहारी वसुने मोहनसिंहको गिरफ्तार करनेका हुक्म दे दिया । गिरफ्तारी हो भी गयी । वसु जापानसे छड़ छेनेके पक्षमें नहीं थे । उनका तर्क था-" हमारे पास न घन है, न अस्त्र है, न सिपाही हैं, पर हम आजादीके लिए लड़ना चाहते हैं। हमें जापानियों से मदद लेनी है; पर साथ ही में यह भी नहीं चाहता कि सिर्फ हमारे मालिक बदल जावें और ब्रिटेनकी जगह जापानका राज हो जाय। में नहीं चाहता कि जापानी भारत भूमिपर पैर भी रखें। लेकिन यहाँ हजारों मील दूर वसे ३० लाख भारतीयोंको जापानी मददके बिना संघटित करना असम्भव है; जापानी सहायता बिना हम इन भारतीयोंतक पहुँच भी नहीं सकते और न उन्हें एक स्त्रमें बाँघकर एक उद्देश्यके लिए खड़ा ही कर सकते हैं। जापान अपने युद्धमें व्यस्त है। हमें जापानसे जितनी मदद मिल सके, मैत्री भावसे लेनी चाहिये, लड़कर नहीं।"

वसु और मोहनसिंहके मतभेदके वाद आजाद हिन्द फीज भंग सी ही थी। पर लेफ्टिनेण्ट कर्नल भींसले, लेफ्टिनेण्ट कर्नल शाहनवाज व मेजर प्रेम सहगलने उसका पुनस्संघटन किया। भारतीय स्वाधीनता लीगके १२ विभाग संविटत किये गये; इनमें सबसे प्रमुख फीजी भरती करनेवाला विभाग था।

मई १९४३ के आरम्भमें सुभाषचन्द्र वसु एक जर्मन पनडुव्यीमें पेनांग आये और वहाँसे जापान सरकारसे भारतीय राजनीतिक मसलोंपर वात करने विमान द्वारा टोकियो गये। सुदूर पूर्वके भारतीयोंके प्रतिनिधियोंका एक संग्मेलन लगभग उसी समय सिंगापुरमें हुआ जिसमें रासिबहारी वसुने घोषणा की कि अवसे मेरी जगह भारतीय आन्दोलनका नेतृत्व सुभापचन्द्र वसु करेंगे। सुभापचन्द्र वसुने टोकियो रेडियोसे अपना सबसे पहला भापण २६ जून, १९४३ को किया जिसमें उन्होंने पूर्वके भारतीयोंके सन्देह मिटाकर अपनेमें निष्ठा रखनेको कहा। "उन्होंने कहा कि अगर आप मुझमें विक्वास रखें तो में आपको स्वाधीनताके लक्ष्यतक पहुँचाऊँगा" उनके अनुयायियोंने उन्हें 'नेताजी' कहना गुरू किया और सुभाप वसुने आजाद हिन्द फौजके सर्वोच्च सेनापितकी हैसियतसे अपना सदर दपतर सिंगापुरमें कायम किया। वहीं नेताजीको सलामी देनेके लिए २०००० भारतीयोंकी परेड हुई, जिसमें जापानी प्रधान मन्त्री तोजो भी अतिथिक रूपमें आमन्त्रित थे।

आजाद हिन्द फीजको नेताजीने सन्देश दिया—साथियो ! मेरे सिपाहियो ! आपका नारा है—'दिल्ली चलो'। आजादीकी लड़ाईमें, आपमेंसे कितने वचेंगे, यह में नहीं जानता । लेकिन में यह जानता हूँ कि अन्तमें विजय हमारी होगी, हमारा काम तवतक खत्म नहीं होगा, जवतक हमारे जवान दिल्लीके ऐतिहासिक लाल किलेमें विजय परेड नहीं करते। अभी मैं भूख, प्यास, कष्ट, लम्बी कठिन यात्रा और मृत्युके सिवा और किसी चीज का आख्वासन नहीं दे सकता।

"आजाद हिन्द फौज भारतकी राष्ट्रीय फौज है और यह पूरी तरह भारतीयोंके नियन्त्रणमें रहेगी। हम उसमें जापानियोंको नहीं आने देगे। अगर हमारी इच्छाके विरुद्ध जापानी भारत जाते हैं तो हम उन्हें अपना दुस्मन मानेंगे।"

वसु कलकत्तेके अपने सकानसे मौलवीके वेदामें चुपचाप निकल आये थे और भगत-राम नामक एक व्यक्तिके साथ पेद्यावरसे काबुल आ गये थे। वहाँ एक सरायमं वह जिया-उद्दीनके नामसे रहे और उसके बाद उत्तमचन्द नामक एक भारतीय व्यापारीके साथ रहे। वसु मास्को जाना चाहते थे पर वहाँके रूसी राजदूतसे कोई सहायता न पाने पर इटलीके राजदूतसे उन्होंने मदद माँगी, जिसने उन्हें रोम भेज दिया। रोमसे वे बरिलन गये। साल- भर वाद वसुके भगानेमें उत्तमचन्दकी मददका पता सरकारको लगा और अफगानिस्तानकी सरकारने उन्हें पकड़कर ब्रिटिश अधिकारियोंको दे दिया और वे रावलिपण्डी जेलमें रखे गये।

सुदूरपूर्व पहुँचनेके शीघ वाद वसुने व्यापक प्रचार शुरू किया । उन्होंने लगभग एक दर्जन सार्वजिनक भाषणोंमें वहाँके भारतीयोंसे आजादीकी इस लड़ाईमें भाग लेनेकी अपील की । सिंगापुरकी एक सार्वजिनक सभामें स्वतन्त्र भारतकी अस्थायी सरकारकी खापनाकी घोषणा की गयी और वसु व अन्य मन्त्रियोंने इस सरकारके प्रति निष्ठाकी शपथ ली । इस सभामें ७००० भारतीय मौजूद थे ।

दूसरे दिन ५०००० नागरिकोंका प्रदर्शन हुआ, जिसमें इस सरकारने इंगलैण्ड और अमेरिकाके खिलाफ युद्धकी घोषणा की। १९४४ के आरम्भमें भारतपर आक्रमणके लिए आजाद हिन्द फौजने अपने प्रवन्ध पूरे कर लिये। फौजके समक्ष भाषण करते हुए वसुने कहा— "भारतके सिपाहियो! वहाँ दूरपर, निदयों और जंगलों और पहाड़ोंके पार इमारा देश है— जहाँकी मिडीसे हम सब वने हैं, जहाँ हम अब जा रहे हैं। सुनो! हिन्दुस्तान पुकार रहा है! हिन्दुस्तानकी राजधानी, दिल्ली तुम्हें पुकार रही है! हमारे ३८ करोड़ देशवासी पुकार रहे हैं। खून खूनको पुकार रहा है! उठो! अब खोनेके लिए समय नहीं है! हथियार उठाओं! दिल्लीका रास्ता आजादीका रास्ता है। दिल्ली चलो!"

जनवरीके अन्ततक, आजाद हिन्द फौजकी कुछ टुकड़ियाँ लेपिटनेण्ट कर्नल लक्ष्मण स्वरूप मिश्रकी कमानमें आराकान मोर्चेकी ओर वढ़ चुकी थीं और अंग्रेजोंकी अधिक सज्ञक्त फौजसे जूझ रही थीं । दोनों ओरके सिपाहियोंमें कई टक्करें हुई और घमासान युद्धके बाद आजाद हिन्द फौजको ग्रुक्तमें कई सफलताएँ भी मिलीं। अंग्रेजोंसे छीने गये स्थानों में म्याम्यो भी था जहाँ स्वतन्त्र भारत सरकारकी राजधानी बनायी गयी। लेकिन जब युद्धकी स्थिति आजाद हिन्द फौजके पक्षमें थी, तभी घनघोर मानसून ग्रुक्त हो गया। युद्ध स्थितिन सहा हो गया और इसी बीच अंग्रेजी फौजकी कुमक पहुँच गयी। अंग्रेजोंने विभिन्न पहाड़ियोंपर १२ वड़ी-वड़ी तोपें लगा दीं। आजाद हिन्द फौजके पास सिर्फ एक ही तोप थी। इस दूसरे मोर्चेमें आजाद हिन्द फौज हारी। वाढ़वाली निदयों और जंगलोंमें बहुत से भारतीय खेत रहे।

१८ अगस्त, १९४५ को विमान-दुर्घटनामें सुभाप वसुकी मृत्यु हो गयी। वे सिंगापुरसे टोकियो जा रहे थे। ताइ होकू (ताइवान) हवाई अड्डेसे हवाई जहाज उड़ा ही था कि मशीन विगड़ गयी। दो मिनटमें जहाज जमीन पर आ गिरा। पेट्रोलकी टंकियोंमें आग लग गयी। वसु लड़खड़ाते हुए जहाजसे निकले। उनके कपड़े जल रहे थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बुरी तरह जल जानेके कारण सात घण्टे वाद, रातके ९ वजे उनकी मृत्यु हो गयी।

युद्धमें जापानकी पराजयके बाद आजाद हिन्द फीजके वे लगभग १०००० सिपाही जो पहले भारतीय फीजमें थे, भारत लाये गये और दिल्लीके लाल किले व अन्य जेलों में बन्द कर दिये गये। भारतीय समाचारपत्रोंने पहली बार अगस्त, १९४५ में आजाद हिन्द फीजका नाम छापा। २० अगस्तको जवाहरलाल नेहरूने भारत सरकारको सावधान किया कि आजाद हिन्द फीजके कैदियोंके साथ बुरे या प्रतिशोध भरे व्यवहारसे भारतके

करोड़ों नागरिकोंको गहरी चोट पहुँचेगी। देशभरमें असन्तोष था और स्थिति गम्भीर हो रही थी। २७ अगस्तको भारत सरकारने एक वक्तव्यमें कहा—"दुश्मनका साथ देना और अपने पुराने साथियोंके खिलाफ लड़ना सिपाहीके लिए सबसे बढ़ा अपराध है। हर देशमें इसकी सजा मौत है… लेकिन भारत सरकारकी घारणा है कि जिस परिस्थितिमें भारतीय सैनिक पकड़े गये और वहाँ जिस स्थितिमें पढ़ गये, उसका खयाल किया जाना चाहिये। उनके साथ दयाका व्यवहार होगा लेकिन ऐसे लोगोंको भी एक संख्या है जिनपर अभियोग है कि उन्होंने अपने पुराने साथियोंको हत्या की, जिन्होंने मित्र राष्ट्रोंके सिपाहियोंको पकड़ा और लगता है कि जिनके नेताओंने जान बूझकर जापान व जर्मनीका साथ दिया इन लोगोंका फीजी अदालतमें मुकदमा होगा।"

आजाद हिन्द फीजके तीन नेताओं—शाहनवाज खाँ, प्रेमकुमार सहगल व गुरवस्था-सिंह दिल्लनको ५ नवम्बर, १९४५ को लाल किलेमें एक विशेष फीजी अदालतके सामने पेश किया गया। कांग्रेस कार्यसमितिने उनकी सफाई और बचावका प्रवन्ध किया। इन लोगोंके खिलाफ भारतके सम्राट्के विरुद्ध युद्ध छेड़नेका अभियोग था। दिल्लनपर हत्या और शेष दोनोंपर हत्यामें मदद देनेके अभियोग भी थे। इस मुकदमेमें देश भरकी दिलचरपी हो गयी। इसके समाचार देशभरके अखबारोंमें मोटे-माटे अक्षरोंमें छपने लगे। जैसे-जैसे मुकदमेकी मुनवाई आगे बढ़ी, जनताकी सहानुभूति इस बातसे और बढ़ती गयी कि इन लोगोंने हजारों अन्य लोगोंके साथ देश-प्रेममें यह युद्ध किया था। आजाद हिन्द बन्दियोंकी सहानुभूतिमें बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए।

कांग्रेस कार्यसमितिने जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, तेजबहादुर सम्, कैलाइन्नाथ काटज्, बख्दा टेकचन्द्र, बद्रीनस, दिलीपसिंह, आसफअली आदिकी एक समिति सुकदमेकी तैयारी और पैरवीके लिए बनायी। भूलाभाई देसाईने मुकदमेको अन्तरराष्ट्रीय स्तरपर पहुँचा दिया और सब्त पक्षके तर्क तोड़ दिये। लेकिन विशेष अदालतने तीनों अभियुक्तोंको सम्राटके विरुद्ध युद्ध घोषित करनेके अभियोगमें दोषी पाया। शाहनवाज खाँके खिलाफ हत्यामें सहायताका अभियोग भी सिद्ध पाया गया। अदालतने इन लोगोंके वेतन आदिका बकाया जन्त कर लेने और इन्हें आजीवन काले पानीकी सजा दी। कमाण्डर-इन-चीफने दण्डको ठीक माना पर तत्कालीन परिख्यितिको ध्यानमें रखकर काले पानीकी सजा माफ कर दी। तीनों व्यक्ति छूट गये और देशमें तनावका जो वातावरण छा गया था, वह बहुत हदतक खत्म हो गया।

अध्याय ३१

कैविनेट मिशन

(ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलका प्रतिनिधिद्ल)

८ अप्रैल, १९४४ को राजगोपालाचारीने जिनाके सामने भारतके विभाजनकी एक स्पष्ट योजना रखी। वास्तवमें वह योजना जिनाकी हो थी, पर राजगोपालाचारीके पेश करने पर जिनाने उसे अस्वीकार कर दिया। अगस्त, १९४२ में हिन्दू महासभाने एक विशेष सिमिति नियुक्त की थी, जिसका काम "राष्ट्रीय माँगके लिए देशकी विभिन्न प्रमुख राजनीतिक पार्टियोंसे जनमत वनानेके लिए वात करना" था। महासभाके जनरल सेकेटरी महेदवरदयाल सेठने एक मित्रके द्वारा जिनासे सम्पर्क स्थापित किया और उनसे निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त किया—

"भारतीय हिन्दू महासभाको कार्यसमितिक २० अगस्त, १९४२ के प्रस्तावमें वर्णित भारतीय स्वतन्त्रताकी राष्ट्रीय माँगका मुस्लिम लीगके नेता समर्थन करते हैं और दूसरे राजनीतिक दलोंके साथ फौरन आजादी हासिल करनेके लिए संवर्षमें हिस्सा लेनेको तैयार हैं, वसतें कि कुछ आम विद्वान्तोंपर मुस्लिम लीगसे समझौता हो जाय। ऐसा समझौता हो जाने पर लीग प्रान्तोंमें संयुक्त मिन्त्रमण्डल बनानेमें सहयोग देगी। जिन सिद्धान्तोंपर समझौता होना है वे हैं—(क) देशके उत्तर पूर्व व उत्तर पिरचममें उन क्षेत्रोंकी सीमा निर्धारित करनेके लिए, जहाँ मुसलमानोंका बहुमत है, एक कमीशन नियुक्त किया जायगा। (ख) इन दोनों क्षेत्रोंमें सार्वजनिक मतगणना होगी और यदि आवादी बहुमतसे एक पृथक स्वाधीन राज्य स्थापित करनेके पक्षमें मत दे तो उनका पृथक् राज्य बना दिया जायगा, (ग) यदि पृथक राज्य स्थापित हुआ तो हिन्दुस्तानके मुसलमान अस्पमत होनेके नाते किसी विशेष मुविधाकी माँग नहीं करेंगे। दो हिन्दुस्तानोंके धार्मिक अल्पसंख्यकोंकी मुरक्षाकी व्यवस्था दोनों सरकार कर सकेंगी, (घ) पिरचमोत्तर और पूर्वोत्तरके दोनों क्षेत्रोंको मिलानेके लिए कोई गलियारा नहीं होगा पर दोनों क्षेत्रोंका मिलकर एक स्वतन्त्र मुस्लिम राज बनेगा, (ङ) जो आवादी पूर्ण स्वेन्छासे दूसरे राज्यमें जाना चाहेगी, उसे मुविधाएँ प्रदान करनेकी सरकारी व्यवस्था होगी।

हिन्दू महासभाके सेकेटरीने दिसम्बर १९४२ में तेजवहादुर सप्रूके घरपर हुए सम्मेलन में यह प्रस्ताव पढ़कर सुनाया। इसकी एक प्रति राजगोपालाचारीको भी दो गयी जो वहाँ मौजूद थे। २१ दिनके उपवासके समय आगा खाँके महलमें राजगोपालाचारीने इस प्रस्ताव पर गान्धीजीकी स्वीकृति ले ली। ८ अप्रैल १९४७ को राजागोपाचारीने इन्हीं मूल सिद्धान्तों पर आधारित, पर थोड़े-से वदले हुए रूपमें एक प्रस्ताव जिनाको दिया। प्रस्ताव इस प्रकार था—

(१) स्वतन्त्र भारतके विधानके सम्बन्धमें ये शतें पूरी होने पर मुस्लिम लीग भारतकी स्वाधीनताकी माँगको मानती है और अन्तरिम कालकी अस्थायी सरकार बनानेमें कांग्रेसको सहयोग देगी; (२) युद्धकी समाप्ति पर भारतके उत्तरपूर्व व उत्तरपश्चिमके उन जिलोंकी सीमा तय करनेके लिए एक कमीशन नियुक्त किया जायगा जहाँ मुसलमानोंका पूर्ण बहुमत है। इस तरह छाँटे गये मुसलिम बहुमतके जिलोंमें वयस्क मताधिकार या अन्य किसी व्यावहारिक पद्धतिसे मतगणना होगी जिसके द्वारा हिन्दुस्तानसे पृथक् होनेके प्रश्नपर निर्णय होगा। यह निर्णय विना भेदभाव लागू किया जायगा और जो जिले सीमापर होंगे उन्हें किसी भी तरफ जानेकी छूट होगी; (३) जनमतगणनाके पहले सभी दलोंको अपना-अपना दृष्टिकोण समझानेकी स्वतन्त्रता होगी; (४) यदि पूर्वोत्तर व पश्चिमोत्तरके क्षेत्र भारतसे पृथक हुए, तो इन क्षेत्रों और शेप भारतके बीच रक्षा, व्यवसाय व यातायात आदिके प्रश्नोंपर आपसी समझोता होगा; (५) आबादीका जो भी तवादला होगा वह पूर्ण स्वेच्छाके आधारपर; (६) ये शतें तभी लागू होंगी जब ब्रिटेन भारत सरकारको पूर्ण सत्ता और उत्तरदायित्व सींप दे।"

जिनाने अब इस योजनाको अस्वीकार करते हुए कहा कि यह तो पाकिस्तानको छिन्न-भिन्न करना है। पर भारतके विभाजनका आधार अन्ततः यही योजना हुई।

मुसलमानोंकी एकमात्र प्रतिनिधि संस्था वननेकी दिशामें मुसलिम लीग तेजीसे बढ़ रही थी। २४ से २६ अप्रैल १९४३ में दिल्लीमें लीगके वार्षिक अधिवेशनमें एक लाख व्यक्तियोंने भाग लिया। देशी रियासतोंमें भी मुसलमान जाग रहे थे और शीव अखिल भारतीय देशी रियासती मुसलिम लीगकी स्थापना हुई, जिसके अधिवेशन शेप भारतकी मुसलिम लीगके अधिवेशनके साथ ही होते थे। दिसम्बर, १९४४ में कराचीमें लीगका जो वार्षिक अधिवेशन हुआ, उपस्थितिकी दृष्टिसे वह भी बहुत सफल रहा। जिना १९३७ से लगातार हर वर्ष लीगके अध्यक्ष चुने जाते थे; उन्होंने कराचीमें कहा कि अप्रेज भारतको दो भाइयोंके वीच वाँट दें और भारत छोड़ दें। उनका नारा था — विभाजित करो और छोड़ों।

१९४४ में ही सरकारने कांग्रेसजनोंको एक-एक दो दो करके छोड़नेकी नीति अपना ली थी। केन्द्रीय विधान सभाके लगभग सभी कांग्रेसी सदस्य छूट गये थे और वे विधान-सभाकी बैटकोंमें भाग लेने लगे थे। कांग्रेस दलके नेता भूलाभाई देसाईने फिर एक वार लीगके उपनेता लियाकतअली खाँसे केन्द्रमें अन्तरिम सरकार वनानेके लिए समझौतेकी वात चलायी। गान्धीजी और जिनाकी स्वीकृतिके लिए निम्नलिखित सुझाव वना—

"कांग्रेस और लीग इस बातपर राजी हैं कि केन्द्रमें एक अन्तरिम सरकार बने जिसमें दोनों शामिल हों। यह सरकार इस प्रकार बनेगी कि (क) उसमें लीग और कांग्रेसके प्रतिनिधियोंकी संख्या बराबर होगी; अनुपात इस प्रकार होगा—कांग्रेस ४० फीसदी, लीग ४० फीसदी, अन्य २० फीसदी; जो प्रतिनिधि कांग्रेस या लीग तय करे, यह जरूरी नहीं कि वे पहलेसे ही केन्द्रीय विधान-सभाके सदस्य हों; (ख) अहप संख्यकोंके (विशेषकर परिगणित जातियों और सिखोंके) प्रतिनिधि होंगे; (ग) कमाण्डर-इन-चीफ (सर्वोच्च सेनापित) होंगे।" यह सरकार १९३५ के भारत सरकार कान्तकें अन्तर्गत यननेको थी पर आशा यह की गर्या थी कि केन्द्रीय विधान-सभाओंके निर्णयोंके विकद्य सरकार वाइसरायके विशेष सुरक्षित अधिकारोंका प्रयोग नहीं करेगी।

देसाई-लियाकतअली वातचीत लम्बी चली। फिर १५ जून १९४५ को गान्धोजीने यह सुझाव स्वीकार करते हुए एक वक्तव्यमें कहा कि मैं कांग्रेस कार्य-समितिसे इसे स्वीकार करनेके लिए कहूँगा। पर इस वीच हुई घटनाओंके कारण यह सुझाव पुराना पड गया।

१४ ज्नको वाइसराय लार्ड वैवलने रेडियोसे घोषणा की कि कांग्रेस कार्य-समितिके सभी सदस्योंकी रिहाईके आदेश जारी हो गये हैं। यूरोपमें युद्धका अन्त हो चुका था और ब्रिटिश सरकार भारतीय स्थितिकी वास्तिविकताकी ओर ध्यान देनेमें समर्थ हो गयी थी। वाइसरायने प्रस्ताव किया कि मेरी कोंसिलमें मुझे और कमाण्डर-इन-चीफको छोड़कर शेष सभी सदस्य भारतीय हों, इसके लिए मैं नेताओंको बातचीतके लिए आमन्त्रित करता हूँ। परराष्ट्र विभाग भी भारतीय सदस्यको सोंप देनेके लिए वाइसराय तैयार थे। वैवलने कहा कि कोंसिलके समक्ष मुख्य काम होंगे—(१) जापानके विरुद्ध युद्ध चलाना, (२) नया स्थायी विधान वननेतक भारतका शासन चलाना, और (३) सभीको मान्य समझौतेके लिए प्रयास करना। यह कोंसिल भी १९३५ के कानूनके अन्तर्गत बननेको थी पर वाइसराय भारतीय हितोंके विरुद्ध और तर्कहोन ढंगसे अपने विशेष अधिकारोंका प्रयोग नहीं करनेवाले थे।

उसी दिन ब्रिटिश सरकारके भारत सचिवने ब्रिटिश लोक सभामें पुराना प्रस्ताव दोहराते हुए कहा—"इस प्रस्तावकी बुनियादमें दो सिद्धान्त हैं। एक तो यह कि भारतको कितनी आजादी मिले, इसपर कोई प्रतिवन्ध नहीं हैं। वह चाहे तो स्वतन्त्र सदस्यकी हैंसियतसे ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलमें रहे और राष्ट्रमण्डलमें न भी रहे। दूसरा यह कि यह भारतके अपने ऐसे विधान या विधानों द्वारा ही सम्भव है जिसे या जिन्हें मुख्य दल स्वीकार करते हों।"

लगभग तीन सालके वाद २१ व २२ जूनको कांग्रेस कार्यसमितिको वैठक वम्बईमें फिर हुई और वाइसराय द्वारा बुलाये गये २५ जूनके नेता-सम्मेलनमें भाग लेनेका निश्चय हुआ । इस सम्मेलनमें कांग्रेसके प्रतिनिधि उसके अध्यक्ष अबुलकलाम आजाद थे जिन्होंने कांग्रेसका दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा कि जो व्यवस्था होनेका प्रस्ताव है उसे हम अस्थायी और अन्तरिम मानते हैं; हम ऐसी कोई वात स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें कांग्रेसके राष्ट्रीय संस्था होनेके गुणको आँच आये; कांग्रेस कार्यसमिति जो भी फैसले किये हैं वे कांग्रेस महासमिति द्वारा स्वीकार होते हैं, और महासमिति अव भी अवैध है।

२५ जूनके नेता सम्मेलनमें कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ और प्रस्तावित कार्य-कारी कोंसिलके सदस्योंकी नामावलीके सम्बन्धमें अपनी-अपनी संस्थाकी कार्यसमितिकी सलाह लेनेके लिए यह १५ दिनके लिए स्थागत कर दिया गया। इस बीच वाइसरायने अपनी फेहरिस्त तैयार कर ली और कांग्रेसने पूरी कोंसिलके लिए सदस्योंकी एक फेहरिस्त दे दी जिसके सभी मुसलिम सदस्य मुसलिम लीगके सदस्य नहीं थे। पर मुलिलम लीगने कोई फेहरिस्त नहीं दी। जब जिना वैवलसे मिले, वैवलने उन्हें अपनी फेहरिस्त दिखायी जिसके एक मुसलिम सदस्य लीगके सदस्य नहीं थे। जिनाने इसपर आपित्त की और कहा-कि सभी मुसलिम सदस्य लीगो होने चाहिये क्योंकि लीग ही मुसलमानोंकी एकमात्र प्रति-निधि संस्था है। अनोखी बात यह है कि वैवलने अपनी सूची कांग्रेसके नेताओंको नहीं दिखायी। लेकिन समझौतेकी बातचीत जिनाकी जिदकी वजहसे मंग हो गयी।

१४ जुलाईको जब फिर सम्मेलन हुआ, वाइसरायने घोषणा कर दी कि समझौता

वार्ता असफल हो गयी है। भारत सरकारने केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान मण्डलेंके नये चुनाव करानेका फैसला कर लिया।

इस वीच सरकारी घोपणा हो जानेके कारण कांग्रेस महासमित भी अवेध नहीं रह गयों और उसके सदस्य मुक्त हो गये थे। महासमितिकी वैटक सितम्बरमें वम्बईमें हुई। महासमितिकी आगत, १९४२ के उद्देश्य और ध्येय दोहराते हुए यह निश्चय प्रकट किया कि विश्वशान्तिके लिए भारतकी स्वाधीनता आवश्यक है। "१९४२ के स्वाधीनता संप्रामपर राष्ट्रको गर्व है यद्यपि अहिंसाकी कसौटीपर उसकी आलोचना की जा सकती है।" राष्ट्रको वधाई देते हुए महासमितिने कहा—"जिस साहस और सिहण्णुतासे ब्रिटिश सरकारके भयानक हिंसापूर्ण हमलेका उसने सामना किया उसके लिए वह बधाईकी पात्र है।" महासमितिने "तीन सालके पुलिस, फीज व आर्डिनेंस राजमें जिन्हें कए हुआ" उनसे गहरी सहानुभूति प्रकट की।

मुसलमानोंकी एकमात्र प्रतिनिधि संस्था होनेके' मुस्लिम लीगके दावेका प्रतिवाद राष्ट्रीय मुस्लिम कानफरेन्स, भोमीन कानफरेन्स, अहरार पार्टा, शीया कानफरेन्स, जमेयत- उल-उलेमा आदि मुस्लिम संस्थाओंने भी किया। जमेयतने अपने प्रधान हुसैन अहमद मदनीको कांग्रेस और सरकारसे कोंसिलमें अपने (जमेयतके) प्रतिनिधित्वकी वात करनेके लिए तैनात भी किया। पंजावके प्रधान मन्त्री खिज्रह्यात खाँने भी वाइसरायको अपनी एक फेहरिस्त मेजी, जिससे स्पष्ट ही जिनाका विरोध होता था। अहरार पार्टाका थोड़ा-सा जिक्र यहाँ असंगत न होगा।

अहरार पार्टी १९२९ में पंजायमें बनी थी और कांग्रेसके साथ चल रही थी। यह गरीव मुसलमानों-मजदूरों और किसानोंका प्रतिनिधित्व करती थी और इसकी वैठकोंमें वे दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह हजारकी संख्यामें आते थे। इनके लिए अहरार पार्टीने कई लड़ाइयाँ भी लड़ीं जिनमें १९३१ में तीन महीनेमें ही कपूरथला, कश्मीर और सियालकोटमें ५० हजार व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे। १९३७ में जब लीगने कांग्रेस विरोधी रवेया अख्तियार किया, अहरारोंने लीगसे सम्बन्ध विच्छेदका निश्चय कर लिया। इन्होंने कांग्रेससे पहले ही युदका विरोध किया था और उसकी भरतीका विरोधकर बड़ी संख्यामें जेल भी गये थे।

जुलाईमें जब युद्ध-समाप्तिके आसार प्रकट हो रहे थे, पर जापानसे लड़ाई चल ही रही थी, इंगलैंण्डमें जुनाव हुए, जिनमें चर्चिलकी कंजरबेटिव (अनुदार) पार्टा हार गयी और लेबर (मजदूर) दलके नेता क्लीमेण्ट एटलीने १० जुलाईको प्रधान-मन्त्रित्व ले लिया। एटलीने वैवलको २५ अगस्तको लन्दन बुलाया, जनसे बातचीत की और वैवलने हिन्दुस्तान लौटकर १८ सितम्बरको (जब कांग्रेस महासमितिकी बैठक वम्बईमें चल रही थी) एक नया वक्तव्य दिया। उसमें कहा गया था—"ब्रिटिश सरकार जल्दी-से-जल्दी संविधान परिपदका निर्माण करना चाहती है और इसके लिए मुझे अधिकार मिला है कि प्रान्तोंमें विधान-सभाओंके जुनाव खत्म होते ही में उनके प्रतिनिधियोंसे बात कर पता लगाऊँ कि १९४२ का प्रस्ताव उन्हें मान्य है, या उसकी जगह कोई नयी योजना अधिक परान्द होगी।

"ब्रिटिश सरकार उस सन्थिपर विचार कर रही है जो भारत और ग्रेट ब्रिटेनके बोच होगी।

"इस वीच भारत सरकारको शासन चलाना ही है और वड़ी बड़ी आर्थिक व सामा-

जिक समस्याओंको हल करना है। नयी विद्य-व्यवस्था वनानेमें भी भारतको योग देना है। विद्या सरकारने इसलिए मुझे यह भी अधिकार दिया है कि प्रान्तीय चुनाव पूरे होते ही में प्रमुख भारतीय राजनीतिक दर्लोकी सहायतासे केन्द्रोय कार्यकारी कोंसिल वनाऊँ।"

अगले दिन एटलीने लन्दनमें ऐसा ही एक वक्तव्य दिया। इन वक्तव्योंके अनुसार केन्द्रीय कोंसिलकी स्थापना प्रान्तीय चुनावोंके वादतकके लिए स्थगित हो गयी, जिसका अर्थ यह था कि उसमें विभिन्न दलोंके प्रतिनिधित्वकी कसौटी चुनाव ही होने थे।

कांग्रेस कार्यसमिति और महासमितिने इन वक्तव्योंको "अरपष्ट, अनुपयुक्त और असन्तोप-जनक" वताया क्योंकि इनमें भारतकी स्वाधीनताकी स्पष्ट घोषणा नहीं थी। लेकिन कांग्रेसने चुनाव लड़नेका फैसला किया। इन वक्तव्योंका स्पष्टीकरण करते हुए नये भारत सचिव लार्ड पेथिक लारेंसने एक सभामें कहा—"व्रिटिश राष्ट्रमण्डलमें स्वशासनके साथ कोई वाध्यता नहीं है; राष्ट्रमण्डलका कोई सदस्य राष्ट्र अपनी इच्छाके विरुद्ध वहाँ नहीं रखा जा सकता; यही वात भारतपर भी लागू होती है; लेकिन हमें आशा और विश्वास है कि भारतको स्वाधीनता मिलनेपर वह अपनी इच्छासे और अपने हितमें ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलमें शामिल रहेगा।"

४ दिसम्बरको ब्रिटिश लार्डसमामें पेथिक लारेंस पुराने वक्तव्योंको स्पष्ट करते हुए, एक कदम और आगे वहे और घोषणा की कि ब्रिटिश पार्लमेण्टका एक प्रतिनिधिमण्डल भारत जायगा। उन्होंने कहा—

"भारतमें कुछ इस तरहकी तर्कहीन भावना पैदा हो गयी है कि वातचीत हीमें काफी समय निकाल देनेका इरादा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि संविधान निर्मात्री परिपद और उससे सम्बन्धित अन्य वातोंको ब्रिटिश सरकार जल्दीसे जल्दी कर डाल्ना चाहती है।

"इस भ्रमके कारण ब्रिटिश सरकारने इस प्रश्नपर भी विचार किया है कि इधर कई वर्षोमें ब्रिटेन व भारतके जो व्यक्तिगत पारस्परिक सम्बन्ध कट-से गये थे, उन्हें फिर क्यों न शुरू किया जाय। इसिलए एम्पायर पार्लमेण्टरी (साम्राज्य संसदीय) एसोसियेशनकी ओरसे एक प्रतिनिधिमण्डल भारत भेजनेका प्रवन्ध किया जा रहा है।"

यह प्रतिनिधिमण्डल देश भरमें घूमा, लोगोंसे मिला और परवरी १९४६ में इंगलेण्ड वापस चला गया। मण्डलने यह स्वीकार किया कि देशके मतभेद आजादीकी माँगमें
मिट जाते हैं। एक अनुदार दलीय प्रतिनिधितकको कहना पड़ा कि भारत राजनीतिक
वयस्कताको सीमापर पहुँच चुका है" (वह राजनीतिक दृष्टिसे वालिग हो गया है)। मण्डलकी राय थी कि भारतकी आजादी अब ज्यादा दिन रोकी नहीं जानी चाहिये। मण्डलमें
निम्निल्खित लोग थे—रिचर्इ (नेता), निकल्सन, व्याट, सोरेनसन, बॉटमले, हॉपिकन
मॉरिस, लार्ड कॉलें, लार्ड मंस्टर व श्रीमती निकोल।

१९ फरवरी, १९४६ को पेथिक लारेंसने भारतीय राजनीतिका एक नया अध्याय गुरू किया और १५ मार्चको एटलीने मानों आजादीका द्वार खोल दिया। पेथिक लारेंसने ब्रिटिश लोकसभामें घोषणा की कि ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलका एक प्रतिनिधिमण्डल (कैविनेट मिशन) भारत जायगा और स्वाधीन भारतके विधान और राष्ट्रीय अन्तरिम सरकार वनाने- के सम्यन्धमें वहाँ क्या कदम उठाये जावँ, इसपर भारतके प्रतिनिधियोंसे बात करेगा ।
 मण्डलमें एलेक्जेण्डर, किप्स और मैं रहूँ गा ।

प्रधान मन्त्री एटलीने वहीं लोकसभामें भाषण करते हुए कहा—"मेरे सहयोगी भारत इस इरादेसे जा रहे हैं कि भारतको जल्दीसे जल्दी और पूरी स्वाधीनता देनेमें अपनी पूरी सहायता दे सकें। वर्तमान सरकारकी जगह वहाँ कैसी सरकार वने, यह तय करना भारतीयोंके हाथमें है, हमारा प्रयास यही है कि यह निर्णय करनेके लिए वे जल्दी व्यवस्था कर लें। यह भारतको ही तय करना है कि दुनियामें उसकी स्थिति मविष्यमें क्या होगी।

"में आशा करता हूँ कि भारत ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डलमें ही रहेगा। मुझे विश्वास है कि इसमें उसका वड़ा लाभ होगा। लेकिन अगर भारत राष्ट्र-मण्डलमें रहनेका निर्णय करता है, तो भी वह यह निर्णय स्वेच्छासे ही करेगा क्योंकि मण्डलके देश वाहरी द्यावके सूत्रसे नहीं वँधे हैं। मण्डल तो स्वतन्त्र देशोंका स्वतन्त्र संघ है।

"िकन्तु यदि भारत मण्डलसे स्वतन्त्र रहना चाहे, और हमारी रायमें ऐसा करनेका उसे अधिकार है, तब भी यह हमारा कर्चन्य है कि हम उसकी वह स्थिति बनानेका काम जितना सरल हो सके, करें।"

अस्पसंख्यकों के सम्बन्धमें उन्होंने कहा—"अस्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति हम जागरूक हैं और उन्हें निर्भय रहना चाहिये। लेकिन हम किसी अस्पसंख्यक वर्गको बहुमतः की प्रगतिपर रोक भी नहीं लगाने दे सकते।"

अंग्रेजोंके भारतसे जानेके परिणामोंके सम्यन्धमें उन्होंने कहा—''जो सरकार पुरानी सरकारका पावना लेगी वही देना भी देगी । पर यह प्रश्न वादमें उठेगा, इसके लिए अभी व्यवस्था करना आवश्यक नहीं हैं। जहाँतक सन्धिका सवाल है, हम अपने हितमें ऐसा कुछ भी करनेको अड़ेंगे नहीं, जो भारतके हितोंके विरुद्ध हो।''

एटलीने अन्तमें कहा—"एशियाके देशोंमें, युद्ध ते वरवाद हुए एशियामें, भारत एक देश है जो जनतन्त्रके सिद्धान्त लागू करनेमें सचेष्ट है। मेरी यह हमेशाकी धारणा है कि राज-, नीतिक भारत एशियाका पथप्रदर्शक हो सकता है। मेरे सहयोगी वहाँ इस संकल्पते जा रहे हैं कि वे सफल होकर ही रहेंगे। मुझे विश्वास है कि सभी उनकी सफलता चाहेंगे।"

ब्रिटिश राजके इतिहासमें पहली वार ब्रिटिश सरकारके इस वक्तव्यका भारतमें स्वागत किया गया कि अंग्रेज सचमुच भारत छोड़कर जाना चाहते हैं। लेकिन जिना खुश नहीं थे, क्योंकि एटलीके वक्तव्यमें पाकिस्तान बनानेकी बात नहीं थी। वक्तव्यको अत्यन्त शोचनीय बताते हुए उन्होंने पंजाब विधान सभाके मुसलिम लीग दलसे कहा—"पाकिस्तानको स्थापनामें आपका तलवारवाला हाथ शानदार काम करे।"

सिखोंको जब पता लगा कि पंजाब पाकिस्तानमें शामिल हो जायगा, तब उन्होंने 'सिखोंके लिए मातृभूमि, सिखोंका राष्ट्रीय घर' माँगकर जिनाके सिक्केमें ही उन्हें जवाब दे डाला । लेकिन जिनाने मह माँग फौरन स्वीकार कर सिख आन्दोलन रोक दिया । २१ मार्च १९४६ को जिनाने लाहौरमें कहा—"एक राष्ट्र होनेके नाते सिखोंका अपना एक राज्य होना आवश्यक है और सिद्धान्ततः मुझे उनकी माँगपर आपत्ति नहीं है।" पर सिख नेता वह क्षेत्र तो बतायें जहाँ उनका राज्य बन सकता है ?

ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलके तीन सदस्योंका प्रतिनिधिमण्डल २३ मार्चको कराची पहुँचा। २९-क

एक सप्ताहतक मण्डल वाइसराय, उनकी काँसिलके सदस्यों, और प्राग्तीय गर्वनरोंसे परामद्ये करता रहा, फिर विभिन्न राजनीतिक दलोंके नेताओंसे मिला और फिर देशी रियासतोंके राजाओंसे । ये मेटें २६ अप्रैलतक चलती रहीं पर कांग्रेस-लीग गुत्थी सुलझानेमें सफलता नहीं हुई । मण्डल चाहता था कि लीग और कांग्रेसमें कोई समझौता हो जाय जो उसकी सिफारिशोंका आधार हो । कांग्रेसका कहना था कि समस्याका हल लीग-कांग्रेसके समझौतेमें नहीं, कांग्रेस, लीग या किसी अन्य दलको सत्ता सौंपकर चले जानेमें है । जिस दलको भी सत्ता मिलेगी वह अन्य दलोंका सहयोग पानेके लिए प्रयत्नशील होगा । यह सुझाव मण्डल या वाइसरायको स्वीकार नहीं-था ।

२७ मईको मण्डलने लीग, कांग्रेस व अपना एक त्रिदलीय सम्मेलन करनेको कहा— कांग्रेसने अनुलक्तलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, अन्दुल गफ्तार खाँ वहलम भाई पटेल को प्रतिनिधि बनाया; लीगने जिना, लियाकत अली खाँ, नुहम्मद इस्माइल खाँ व अन्दुर्रव निस्तरको । इस सम्मेलनमें विचारका आधार था, भारत सचिवका कांग्रेस व लीगको निमन्त्रण कि "ब्रिटिश भारतका मिन्ध्यका वैधानिक ढाँचा ऐसा हो—एक यूनियन सरकार बने जो निम्नलिखित विभागोंको चलाये—परराष्ट्र, रक्षा व यातायातः प्रान्तोंके दो समृह हों— एक हिन्दू बहुमतवाला और दूसरा मुस्लिम बहुमतवाला । ये दो समृह उन विभागोंको सम्हालें जो उस समृहके प्रान्त आपसमें तय कर लें । प्रान्तीय सरकारें शेष विभागोंको सम्हालें ।''

आजाद और जिना दोनोंने विचार-विनिमयके इस आधारका विरोध किया, यद्यपि उनके विरोध करनेके कारण भिन्न थे। कांग्रेस धर्मके आधारपर प्रान्त-समूह वनानेके विरुद्ध थी और जिना लाहौर-प्रस्तावकी माँग दोहरा रहे थे। पर तब भी दोनों पक्षोंने निमन्त्रण स्वीकार कर बिदलोय सम्मेलनमें भाग लिया।

सम्मेलन ५ मईको शिमलामें ग्रुरु हुआ और कई दिनतक विचार-विनिमय होता रहा | जैसी कि सम्भावना थी, समझौता नहीं हो सका | लीगने सम्मेलनमें एक स्मृतिपत्र पेश किया जिसमें उसकी निम्नतम माँगें थीं:—

- (१) छः मुस्लिम प्रान्तों—पंजाव, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, सिन्ध, वंगाल, आसाम व वल्निस्तानका एक समृह वने । यह समृह सभी शासकीय विषय और विभाग सम्हालेगा, सिर्फ परराष्ट्र, रक्षा और रक्षासे सम्बन्धित यातायातके विभागोंको छोड़कर; और इन तीन विभागोंको हिन्दू प्रान्तों व पाकिस्तान समृहकी संविधान निर्माण परिषदें सम्हाल हैं।
 - (२) छः मुस्लिम प्रान्तोंके लिए एक पृथक संविधान परिषद वने ।
- (३) यदि केन्द्रमें कोई विधान-सभा या कार्यसमिति वने तो उसमें दोनों प्रान्त सम्होंके प्रतिनिधियोंकी संख्या वरावर हो ।
- (४) यदि कोई प्रान्त अपने समृह्से अलग निकलना चाहे तो उसे इसकी स्वतन्त्रता हो पर शर्त यह रहे कि उस प्रान्तकी यह इच्छा जनमतगणना द्वारा जानी जाय।
- (५) दोनों संविधान निर्मात्री परिषदें तय करें कि एक केन्द्रीय विधान सभाकी आवश्यकता है या नहीं; वे यह भी तय करें कि केन्द्र (यूनियन) की आयके साधन क्या हों; पर ये साधन कर वैठाना कदापि न होंगे।
- (६) साम्प्रदायिक समस्यासे सम्विष्यत कोई प्रश्न तवतक हल न किया जाय ज्ञवतक दोनों विधान परिपर्दे इस हलके पक्षमें अलग-अलग, बहुमतसे अपना फेसला न दे दें।

- (७) कोई भी महत्त्वपूर्ण वैधानिक, प्रशासकीय या कार्यकारी प्रश्न केन्द्रमें तीन चौथाई बहुमतके विना तब न हो।
- (८) प्रान्त व प्रान्त-समृहके विधानींमें विभिन्न जातियोंके धर्म, संस्कृति आदिकी सुरक्षाकी गारण्टी हो ।
- (९) प्रारम्मिक दस वर्षोंके बाद किसी भी प्रान्तको यूनियनसे अलग हो जानेका अधिकार हो।

कांग्रेसने निम्नलिखित सुझाव दिये -

- (१) विधान निर्मात्री परिपदके सदस्य प्रान्तीय विधान-सभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुने जावँ।
- (२) विधान परिपद् यूनियनका संबीय विधान वनाये । इस विधानमें संब सरकार और केन्द्रीय विधान-सभाके निर्माणकी व्यवस्था हो, जो परराष्ट्र, रक्षा, यातायात, मोलिक अधिकार, मुद्रा, नियोजन व तटकर तथा ऐसे विपयों व विभागोंका काम चलाये जो बादमें इन विषयोंसे सम्वन्धित साबित हों। इस कामके लिए जो धन चाहता हो उसे प्राप्त करनेका अधिकार केन्द्रको हो।
 - (३) श्रेप सभी विषय व विभाग प्रान्तीय सरकारोंमें निहित हों।
 - (४) यदि कुछ प्रान्त चाहें तो वे प्रान्त-समूह बना सकें।
- (५) साम्प्रदायिक समस्याओंसे सम्वन्धित प्रश्न उस सम्प्रदायके प्रतिनिधियोंके बहुमतसे तय हों जिसपर उस प्रश्नका प्रभाव पड़ता हो।
 - (६) सविधानमें परिवर्तन करनेकी व्यवस्था हो।
- (७) जिन विवादोंका निर्णय न हो सके, उन्हें पंच निर्णायकको सैंपनेकी व्यवस्था हो।

स्पष्ट है कि इन दोनों दृष्टिकोणोंमें ही बहुत बड़ा अन्तर था। लीग और कांग्रेसमें समझौता नहीं हो सका । १६ मईको मण्डलने अपने सुझाओंकी घोपणा की जिनमं भारतके विभाजनका विरोध किया गया था, लीगकी माँगका विरोध किया गया था, और फिर भी पाकिस्तानको माँग प्रच्छन्न रूपसे मान ली गयी थी। मण्डलने कहा-"हमने मुस्लिम लीग द्वारा वेश पूर्ण स्वतन्त्र और स्वाधीन पाकिस्तान राज्यकी स्थापनाके प्रश्नपर विचार किया। यह राज्य दो क्षेत्रोंका-व्रिटिश वल्चिस्तान, पंजाव, सिन्ध व सीमाप्रान्तके पश्चिमोत्तरके क्षेत्र और बंगाल व आसामके पूर्वोत्तरके क्षेत्रका होगा।" मण्डलने हिसाब लगाया कि परिच-मोत्तर क्षेत्रमें ६२'०७ प्रतिशत मुसलमान हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्रमें ५१'६९ प्रतिशत, शेप भारत-में उनकी संख्या लगभग दो करोड़ है जो १८'८ करोड़की आवादीमें विखरे हुए हैं। मण्टल-का तर्क था—"इन आकडोंसे स्पष्ट है कि मुस्लिम लीगका दावा स्वीकार कर एक पृथक स्वाधीन पाकिस्तान राज्य वना देनेसे साम्प्रदायिक अल्पसंख्यकोंकी समस्या दल नहीं होगी। पाकिस्तानमें पंजाव, वंगाल व आसामके उन जिलोंको शामिल कर देनेका औचित्य भी नहीं समझमें आता जहाँकी आवादीका भारी बहुमत गैर-मुसल्या है। पाकिस्तानकी न्थापनाके पक्षमें जो तर्क दिये जाते हैं, वे हमारी समझमें, उतने ही ओचित्यके साथ पाकिस्तानसे गैर-मुसलिम आवादीवाले इलाकोंको अलग कर देनेमें लागू होते हैं। यह वात सिखोंकी स्थितिके सम्बन्धमें खास तौरपर लागू होती है: "पंजायका विभावन किसी भी ढंगसे क्यों न किया जाय, सिख जातिके वहे-वहे भाग सीमाके दोनों ओर रहेंगे।" आर्थिक, भौगोलिक, सैनिक, रक्षात्मक आदि अन्य प्रश्नोंपर विचार कर मण्डलने कहा—"इसलिए हम ब्रिटिश सरकारको यह राय देनेमें लाचार हैं कि आज जो सत्ता अंग्रेजोंके पास है वह दो विलकुल स्वतन्त्र और अलग-अलग राज्योंको सौंपी जाय।"

मुसलिम लीगके दृष्टिकोणसे समस्याको देखते हुए मण्डलने कहा—''लेकिन इस निर्णयके कारण हम मुसलमानोंकी इस विलकुल सञ्ची आशंकासे आँखें नहीं चुरा रहे कि विशाल हिन्दू बहुमतवाले भारतके विरुद्ध एकात्मक केन्द्रीय शासनमें मुसलमानोंके सांस्कृतिक, सामाजिक व राजनीतिक जीवनके डूव जानेकी सम्मावना है। इसके लिए कांग्रेसने सुझाव रखा है कि प्रान्तोंको लगभग पूर्णतः स्वाधीन बना दिया जाय, सिर्फ वैदेशिक सम्बन्ध, रक्षा व यातायात जैसे निम्नतम विषयोंको केन्द्रके अधीन रखा जाय।'' इस प्रकार ब्रिटिश सरकारके मन्त्रिमण्डलके प्रतिनिधियोंने सिद्धान्ततः कांग्रेसकी योजना स्वीकार कर ली थी।

मण्डलने विधानके बुनियादी ढाँचेके सम्बन्धमें सुझाव दिया—"(१) भारतका एक यूनियन हो जिसमें देशी रियासतें व ब्रिटिश भारत शामिल हों; यह यूनियन वैदेशिक सम्बन्धों, रक्षा व यातायातके विषय अपने अधीन रखे, और अपने कामके लिए आवश्यक धन इकट्ठा करनेका उसका अधिकार हो।

- (२) यूनियनकी एक कार्यसमिति और एक विधान परिषद् हो, जिनमें ब्रिटिश भारत व देशी रियासतों के प्रतिनिधि हों। किसी बड़े साम्प्रदायिक प्रश्नके केन्द्रीय विधान-सभामें पेश होने पर निर्णय दोनों मुख्य जातियों के प्रतिनिधियों के अलग-अलग बहुमत और सभी उपस्थित प्रतिनिधियों के बहुमत से हो।
- (३) यूनियन अधिकारक्षेत्रके विषयोंको छोड़कर रोष सभी विषय और अधिकार प्रान्तोंमें निहित हों।
- (४) अन्य प्रान्तोंकी भाँति देशी रियासतोंके भी वे सभी अधिकार रहें जो यूनियनके नहीं हैं।
- (५) प्रान्तोंको अपने समृह वनाने और समृहको सामान्य प्रान्तीय विषय निश्चित करनेका अधिकार रहे।
- (६) यूनियन व प्रान्त-समूहोंके विधानमें यह व्यवस्था रहे कि कोई भी प्रान्त शुरूके दस सालके वाद विधानकी व्यवस्थाओंपर पुनर्विचारकी माँग अपनी विधान-सभाके बहुमत द्वारा कर सके। पुनर्विचारकी माँग दस-दस सालके अन्तरपर ही की जा सके।

ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधि-मण्डलने विधान निर्मात्री परिषद्के सम्वन्धमें सिफा-रिश की कि—

- "(क) हर प्रान्तके लिए उसकी आवादीके अनुपातमें (मोटे तौरपर हर १० लाखकी आवादीपर एक) विधान परिपदके सदस्योंकी संख्या तय कर दी जाय। इसे वयस्क मताधिकारका सबसे निकट पर्याय माना जाय।
- (ख) प्रान्तोंके लिए इस प्रकार निर्धारित संख्याओंको वहाँ वसी मुख्य जातियों (सम्प्रदायों) की आवादीके अनुपातमें विभिन्न जातियोंमें वाँट दिया जाय ।

(ग) प्रत्येक सम्प्रदायके लिए निर्धारित प्रतिनिधियोंको उसी सम्प्रदायके विधान समाओंके सदस्य चुनें ।

मण्डलने भारतीय प्रान्तोंको तीन श्रेणियोंमें वाँट दिया और सिफारिश की कि विधान निर्मात्री परिपद इन्हीं तीन भागोंमें वाँट दी जाय । ये भाग अपने अपने प्रान्तोंके विधान वनायें और यह भी तय करें कि प्रान्त-समृह वनते हैं या नहीं और यदि वनते हैं तो प्रान्तीय विपयोंमें से कौनसे विपय समृहके अधिकार क्षेत्रमें जायें । प्रान्तोंको यह भी अधिकार रहे कि नये संविधानके अनुसार चुनी गयी पहली विधान सभाएँ अगर चाहें तो वहुमतसे प्रस्ताव कर प्रान्त-समृहसे पृथक हो जायें।

प्रान्तोंकी तीन श्रेणियाँ और उनके लिए संविधान निर्मात्री परिपदमें निर्धारित स्थानोंकी संख्या इस प्रकार थी---

	भाग क				
		आम	मुस्लिम		बु,ल
मद्रास		४५	X		४९
. वम्बई		१९	२		२१
संयुक्तप्रान्त		४७	6		५५
विहार		38	Ų		३६
मध्यप्रान्त		१६	१		१७
उड़ीसा		9	•		9
	जोड़	१६७	२०		१८७
			भाग ख सिख		
पिवमोत्तर सीमापान्त		٥	३	0	3.
पंजाव		૮ ફ	१६	8	२८
सिंघ		\$	ą	0	8
	नोड़	9	रर	8	३५
			भाग ग		
वंगाल		२७	३३		६०
आसाम		9	३		१०
	जोड़	કુંજ	३६		60

श्रेणी 'क' में दिल्ली, कुर्ग और अजमेर-मेरवाड़ाका एक एक प्रतिनिधि नुड़ना था। देशी रियासतोंको ९२ से अधिक स्थान नहीं मिलने थे। इनका श्रेणी और विभाजन परामर्शसे तय होना था।

प्रान्तीय और प्रान्त समृहीं सम्बन्धी विधानींके वन जाने पर देशी रियासतीं और भागोंके प्रतिनिधि इकट्ठे होकर केन्द्रीय यूनियनका विधान वनानेवाले थे।

यह भी सिफारिश की गयी थी वड़े साम्प्रदायिक प्रश्नोंके फैसलेके लिए परिपदके उपस्थित सदस्योंका बहुमत और दोनों मुख्य सम्प्रदायोंके उपस्थित प्रतिनिधियोंका अलग-अलग बहुमत आवश्यक होगा। मण्डलने यह भी घोषणा की कि प्रमुख राजनीतिक दलोंके प्रतिनिधियोंकी अन्तिरम केन्द्रीय सरकार फौरन बना दी जायगी।

मण्डलके इन सुझानोंके प्रकाशनके फौरन वाद मण्डल, कांग्रेस, लीग, देशी-राजाओं, िसखों आदिमें लम्बा पत्र-व्यवहार ग्रुक हुआ जिसमें या तो कुछ सुझानोंका विरोध किया गया या अन्य कुछ सुझानोंका स्पष्टीकरण माँगा गया। िसख नेता मास्टर तारासिंहने सुझानोंको अस्त्रीकार करते हुए कहा कि इनमें सिखोंको मुसलमानोंकी दयापर आश्रित कर दिया गया है।

१६ जूनको मण्डल व वाइसरायने उन व्यक्तियों के नामों की घोषणा की जो उन्होंने अन्तिरम सरकारके मन्त्रिमण्डलके लिए छाँटे थे। इस स्चीपर कांग्रेसको आश्चर्य हुआ क्यों कि कांग्रेसकी नामावलां में से डाक्टर जाकिर हुसेन और शरत्चन्द्र वसुके नाम काटकर हरेकृष्ण महताव और सर एन. पी. इंजीनियर (गैर-कांग्रेसी) के नाम रख दिये गये थे। कांग्रेसको महतावके नामपर इतनी आपित्त नहीं थी पर डाक्टर जाकिर हुसेनको हटानेको वह तैयार नहीं थी क्योंकि कांग्रेस अपनेको साम्प्रदायिक संस्था नहीं विक राष्ट्रीय संस्था होनेकी वातपर जोर देना चाहती थी। कांग्रेसने लीगकी नामावलीमें अन्दुर्श्व निस्तरके नामपर भी इसलिए आपित्त की कि उन्हें हालमें ही हुए चुनावमें एक कांग्रेसी मुस्लिम उम्मीद वारने हरा दिया था।

वाइसरायने कांग्रेसकी आपित इस आधारपर स्वीकार नहीं की कि यदि कांग्रेसको एक मुस्लिम प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार दिया गया तो मुस्लिम लीग राजो न होगी क्योंकि उसका दावा है कि वही भारतीय मुस्लमानोंकी एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। समझौतेकी कोशिश एक वार फिर असफल हो गयी और वाइसरायने मानों प्रतिशोधकी भावनामें, अधिकांशतः अंग्रेज सदस्योंकी एक अस्थायी सरकार बना दी।

अवतक मण्डल और अन्य लोगोंके वीच पत्रव्यवहार समाप्त हो चुका था और कांग्रेस व लीग दोनोंने मण्डलके १६ मईके मुझावोंको स्वीकार कर लिया था। लेकिन जुलाईमें लीगने अपनी स्वीकृति वापस लेते हुए कहा कि हमने तो दीर्घ व अल्पकालीन दोनों योजनाएँ एक साथ स्वीकार की थीं, पर कांग्रेसने अल्पकालीन योजना अस्वीकार कर दी। २६ जूनके कांग्रेस कार्य-समितिके प्रस्तावमें कहा गया—

"जिस प्रकारकी स्वाधीनता प्राप्त करना कांग्रे सका लक्ष्य है, उसमें संयुक्त जनतान्त्रिक भारतीय संवकी स्थापना होनी चाहिये; एक केन्द्रीय सत्ता होनी चाहिये जो विश्वके राष्ट्रों को प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके; अधिकतम प्रान्तीय स्वाधीनता होनी चाहिये, देशके हर नर-नारी समान अधिकार होने चाहिये। सण्डलके सुझावोंमें विशेषकर प्रान्त-समृह वनानेकी प्रणाली में निहित केन्द्रीय सत्तापर लगनेवाली सीमासे पूरा ढाँचा निर्वल होता है और पिश्चमोत्तर, सीमाप्तान्त व आसाम जैसे प्रान्तोंके लिए सुझाव सन्तोपजनक हैं, वे कुछ अल्पसंख्यकों, विशेषकर सिखोंके लिए असन्तोपजनक हैं। कार्यसमिति इस स्थितिको स्वीकार नहीं करती। लेकिन कार्यसमितिका मत है, सुझावोंको उनके पूर्णत्वमें एक साथे लेकर विचार करनेसे लगता है कि केन्द्रीय सत्ताको व्यापक व सशक्त वनाने तथा समूह वनानेके सम्बन्धमें प्रान्तोंके स्वेच्छासे निर्णय करनेके अधिकारकी रक्षा करने और ऐसे अल्पसंख्यक वगोंको सरक्षा देनेकी उसमें काफो गुंजाइश है जो अन्यथा अहितकर स्थितिमें हैं।"

कार्यसमितिने यह भी निश्चय किया कि ''स्वतन्त्र, संयुक्त, जनतान्त्रिक भारतका संविधान वनानेकी दृष्टिसे'' कांग्रेसको प्रस्तावित संविधान परिषद्में भाग छेना चाहिये। कार्यसमितिने माँग की कि केन्द्रमें शीव्रातिशीव्र एक उत्तरदायी, प्रतिनिधित्वपूर्ण राष्ट्रीय अस्यायी सरकार स्थापित की जाय। ७ जुलाईकी अपनी वैठकमें कांग्रेस महासमितिने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

२७ जुलाईको वम्बईमें मुसलिम लीगकी बैठक हुई और इसमें लीगने दावा किया कि दो प्रमुख दलोंमेंसे सिर्फ इमने ही मण्डलके वक्तव्योंको पूरा-पूरा (अन्तरिम सरकार वनानेके मुझावको मिलाकर) स्वीकार किया है। संविधान परिषदके निर्माणसे सम्बन्धित मुझावोंकी अप्रत्याशित व्याख्या करनेका आरोप कांग्रेसपर लगाते हुए लीगने अपने प्रस्तावमें कहा-"विटिश सरकारके प्रतिनिधिमण्डल और वाइसरायने अलग-अलग और संयुक्त रूपसे कई वार कहा था कि बुनियादी सिद्धान्त सिर्फ इसलिए तय कर दिये गये हैं कि संविधान परिषदमें दोनों प्रमुख पक्ष भाग ले सकों; उन्होंने यह भी कहा था कि यह योजना तवतक नहीं चल सकती, जवतक उसे सहयोगकी मावनासे न लागू किया जाय । कांग्रेसके रवैयेसे यह स्पष्ट है कि संविधान परिपदके सफल संचालनकी इस पूर्व-परिस्थितका अस्तित्व भी नहीं है। यह वात और इसके साथ मुसलिम राष्ट्र व भारतीय जनताके कुछ अन्य कमजोर वर्गोंके हितोंकी, कांग्रेसको खुरा रखनेके लिए, कुरवानी करनेका ब्रिटिश सरकारका रवैया और उसका मसलमानोंको बार-वार दिये गये लिखित और मौखिक वचनों व आखासनोंके उल्लंघनका रवैया इस बातमें कोई संशय नहीं छोड़ते कि इस स्थितिमें मुसलमानोंके लिए प्रस्तावित संविधान निर्मात्री परिपदमें शामिल हो जानेमें खतरा है, इसलिए लीगकी यह कौंसिल मण्डलके सुझावोंको दी गयी अपनी वह स्वीकृति वापस लेती है जो लीगके अध्यक्षने ६ जुन १९४६ को ब्रिटिश सरकारके भारत सचिवको दी थी।"

लीग एक कदमें आगे बढ़ो। उसने 'सीधी काररवाई'का फैसला किया, और बंगाल-को रक्तरनान करा दिया । सीधी काररवाई सम्बन्धी प्रस्तावका उद्देश्य वताया गया था ''पाकिस्तान प्राप्त करना, मुसलमानीके न्यायसंगत अधिकारीका दावा करना और वर्तमान अंग्रेजोंकी गुलामी और भविष्यमें कल्पित सवर्ण हिन्दुओंकी गुलामीसे छुटकारा हेकर अपना राष्ट्रीय आरमसम्मान प्राप्त करना ।" लोगने अपनी कार्य-समितिसे 'सीधी काररवाई'का कार्य-कम बनाने और मुसलमानोंसे 'विदेशी सरकार द्वारा दिये गये खिताबोंको छोड़ देने'को कहा। खितावींके वहिष्कारकी लीगकी अपीलको विशेष सफलता नहीं मिली । जिन्हें उपाधियाँ मिली हुई थीं, उन्हें विश्वास नहीं होता था कि अंग्रेज सचमुच जा रहे हैं, वे लीगमें शामिल हो कर वह भी नहीं खोना चाहते थे, जो उन्हें मिला हुआ था। लेकिन हिंसा और रक्तपातका खेळ रचना ज्यादा आसान था। 'सीधी काररवाई'के लिए १६ अगस्तका दिन नियत किया गया । वंगालके लीग मिन्त्रमण्डलने उस दिन सार्वजनिक छुटीकी घोषणा कर दी । कल-कत्तेके लीगी नेता "हिन्दुओंको सबक सिखाने"के लिए हिंसाका प्रचार करने लगे । जिना खुद हिंसा नहीं चाहते थे और उन्होंने एक वक्तव्यमें लीगके प्रस्तावकी व्याख्या करते हुए कहा कि लोगकी माँगके समर्थनमें जनमत बनानेके लिए उस दिन सभाएँ की जारें; 'सीधी-काररवाई'का किसी अन्य अर्थमें सीधी काररवाई करनेका आशय नहीं था। उन्होंने मुसल-मानोंसे उनके आदेशका पालन कर शान्त और अनुशासित ढंगसे व्यवहार करनेकी अपील की और 'दुइमनके हाथमें खेल जाने'से सावधान किया। लेकिन लीगके कुछ नेताओंने वहे पैमाने पर हिंसात्मक काररवाई करनेका पूरा प्रवन्ध पहले ही कर लिया था, जिनाकी चेतावनी जनतातक देरमें पहुँची। नियत समयपर कलकत्ता और सिल्हर्टमें कत्ल ग्रुक्त हो गये, शीघ ही सड़कोंपर खून वहने लगा। लगभग ७००० व्यक्ति मारे गये, इससे कहीं ज्यादा जख्मी हुए। कलकत्तेकी सड़कोंपर शव सड़ने लगे। मुसलमानोंकी रक्तिपपासा शान्त होनेके वाद हिन्दुओंका प्रतिशोध ग्रुक्त हुआ, और इससे नोआखाली और टिप्परा जिलोंके वहु-संख्यक मुसलमान उत्तेजित हुए। इन दो जिलोंमें जो हुआ वह कलकत्तेकी घटनाओंसे भी ज्यादा लोमहर्षक और भयानक था। पहले हत्या, अग्निकाण्ड और सम्पत्तिकी लूटपाटकी बाढ़-सी आयी। फिर हिन्दुओंकी स्त्रियोंको भगाकर उनकी मुसलमानोंसे वलपूर्वक शादी करना ग्रुक्त हुआ। वलात्कार और वलात् धर्मपरिवर्तन इन उपद्रवोंकी विशेषता थी।

कुछ समयतक सम्पूर्ण देशका ध्यान तो नोआखालीमें केन्द्रित रहा। सार्वजनिक पैमानेपर हिंसासे गान्धीजी विचलित हो गये और उन्होंने शान्तिस्थापनार्थ नोआखालीमें ही रहनेका निश्चय किया। वे अपने उद्देश्यमें सफल हुए। वरवाद और उजड़े नोआखालीमें सद्भावनापूर्ण मुसलमानोंने उनका अपने वीच स्वागत किया, उन्होंने गान्धीजीको अपना मेहमान वनाया और शान्ति व व्यवस्था स्थापित करनेमें हर तरहसे मदद देनेका आश्वासन दिया। वंगालकी लीग सरकारने गान्धीजीकी मुरक्षाकी व्यवस्था कर दी हालाँ कि गान्धीजी यह नहीं चाहते थे। किन्तु रवीन्द्र वाव्के 'एकला चलो रे!' ध्वनिके साथ मुसलमानोंकी घनी वस्तियोंमें अकेले जाते और कहते कि मुझपर कोई आँच नहीं आयगी। और उनपर कोई आँच नहीं आयो। अनेक परिवारोंमें वे फिर प्रसन्नता ला सके, मुसलमानोंने उन्हें वचन दिया कि हम अपने हिन्दू भाइयोंकी रक्षा करेंगे। जादूसे, चमत्कारसे, गान्धीजीन उनका हृदय वदल दिया। वहुत-सी भगायी हुई हिन्दू स्त्रियाँ अपने-अपने परिवारोंको वापस मेज दी गयीं। जो शान्ति हिंसासे असम्भव थी वह प्रेमसे स्थापित हो गयी।

पर जो दुष्टता गान्धीजीके प्रयाससे नोआखालीमें समाप्त हो गयी, दुष्टोंने दूनरे स्थानों-पर उसे उभारा । आखिरकार हिन्दू, मुसलमान एक दूसरेके सिर पचासों वणेंसे फोड़ते आ रहे थे । इस वार विहारमें हिन्दुओंने मुसलमानोंपर भीषण हमला वोल दिया और बहुतसे मुसलमानोंको मार डाला । एक वार तो स्थिति इतनी गम्भीर हो गयी कि जवाहरलाल नेहरूने (जो अन्तरिम मन्त्रिमण्डलमें आ चुके थे) अशान्त क्षेत्रमें हवाई जहाजोंसे वमवारी करनेका हुक्म दे दिया ।

२५ अगरतको वाइसरायने एक वक्तव्य जारी किया जिसमें अन्तरिम सरकारके लिए निम्नलिखित व्यवस्था थी—कांग्रेस छः सदस्य (जिनमें एक परिगणित जातिका हो) नाम-जद करे, पाँच लीग नामजद करे और अन्य अल्पसंख्यकोंके तीन प्रतिनिधि (एक सिखोंका हो) वाइसराय खुद नियुक्त करें । अन्तरिम सरकारका उतना ही मान और उसकी सलाहका उतना ही महत्त्व होगा जितना किसी औपनिवेशिक सरकारका। लीगने इस मन्ति-मण्डलमें शामिल होनेसे इनकार कर दिया, वह कांग्रेसको अपने प्रतिनिधियोंमें भी एक मुसलमान नियुक्त नहीं करने देना चाहती थी, चाहे कांग्रेस हिन्दुओंके लिए नियत संख्यामें हो एक राष्ट्रीय मुसलमान मले ही नियुक्त करना चाहे। वाइसरायने लीगके विना ही सरकार १. पट्टामि सीतारमेया, हिस्टरी आव नैशनल कांग्रेस, प्रष्ठ ८०५

वना दी और निम्नलिखित मिन्त्रयोंकी घोषणा कर दी— जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, राजेन्द्रप्रसाद, आसफअली, राजगोपालाचारी, शरत्चन्द्र वसु, जान मयाई, वलदेव सिंह, शफात अहमद खाँ, जगजीवन राम, अलो जहीर, क्वरजी होरमुसजी भाभा। दो मुसलिम प्रतिनिधि वादमें नियुक्त होनेवाले थे।

जवाहरलाल नेहरू २ सितम्बरको मन्त्रिमण्डलमें शामिल हुए थे। उसके फीरन वाद उन्होंने लीगको अन्तरिम मन्त्रिमण्डलमें शामिल होनेके लिए राजी करनेके इरादेसे जिनासे पत्र-व्यवहार शुरू किया । ६ अक्तूवरके अपने पत्रमें नेहरूने लिखा-"चुनावके नतीजींपर मुसलिम लीगको भारतीय मुसलमानोंके भारी वहमतका प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था और इसलिए जनतान्त्रिक सिद्धान्तोंके अनुसार भारतीय मुसलमानीका प्रतिनिधित्व करनेका अधिकार मैं स्वीकार करता हूँ "वशत्तें कि लीग इन्हीं तकोंसे कांग्रे सकी सभी गैरमसलमानों और ऐसे मुसलमानोंका प्रतिनिधि मान ले जिन्होंने अपना भाग्य कांग्रेसके साथ मिला दिया है।" अपने दावेकी इस रिवीकृतिपर सन्तोष प्रकट करते हुए जिनाने सरकारमें शामिल होनेकी अपनी शर्च दोहरा दी और हरिजनोंका प्रतिनिधित्व करनेके कांग्रेसके अधिकारका विरोध किया । लेकिन १५ अक्तूबरको वे झुके और अन्तरिम सरकारमें शामिल होनेके लिए लीगकी ओरसे लियाकतथली खाँ, आइ. आइ. चुन्दरीगर, अब्दुर्रव निस्तर, गजनफरअली खाँ तथा जोगेन्द्रनाथ मण्डलके नाम दिये। जोगेन्द्रनाथ मण्डल परिगणित जातिके थे। मन्त्रिमण्डलमें दो स्थान पहलेसे ही खाली थे, तीन स्थान और खाली करनेके लिए शफात अहमद खाँ, अली जहीर और शरत्चन्द्र वसुने इस्तीफे दे दिये। लेकिन लीग अपनी शत्तें लेकर मन्त्रिमण्डलमें आयी थी। पाकिस्तानी क्षेत्रोंकी अलग संविधान परिपदकी माँग करते हुए उसने संविधान परिपदमें भाग लेनेसे इनकार कर दिया।

कांग्रेस लीगका संयुक्त मिन्त्रमण्डल सन्तोपजनक ढंगसे नहीं चला, चल भी नहीं सकता था। मुसलमान जनताका पाकिस्तानके लिए जो उत्साह था, उसपर अप्रत्यक्ष रूपसे भी प्रभाव डालनेवाला कोई काम लीगी मन्त्री करनेको तैयार नहीं थे। विधान सभामें ही किस तर्ह लीगी व कांग्रेसी मन्त्री एक दूसरेका बिरोध करते थे, उसका एक उदाहरण यह है कि राज्यपरिषदमें अन्दुर्शव निस्तरने कहा कि विहारमें उपद्रवोंके कारण दसों लाख व्यक्ति मारे गये। यह हास्यपद अतिरंजना थी और राजेन्द्रप्रसादंको उटकर कहना पड़ा कि मेरे सहयोगीका अनुमान मूर्खतापूर्ण है।

'सीधी काररवाई दिवस'को कलकत्तेमें जिस हिंसात्मक प्रवृत्तिने सिर उठाया था, वह भारतके विभिन्न स्थानों में अपना भहा रूप दिखाती रही । २३ व २४ नवम्बरको मेरठमें कांग्रेसका ५४वाँ अधिवेशन ६॥ वर्षके अन्तरसे हो रहा था । वड़ी संख्यामें लोगोंके आने की सम्भावना थी पर अधिवेशनके कुछ दिन पहले वहाँ साम्प्रदायिक उपद्रव हो जानेके कारण, अधिवेशन केवल कामकी संक्षिप्त वातों और अति आवश्यक उपस्थितितक ही सीमित रह गया । जे. वी. कृपालानीकी अध्यक्षतामें हुए इस अधिवेशनमें यह निश्चय दोहराया गया कि "विश्वमें शान्ति, स्वतन्त्रता और प्रगतिकी स्थापनामें अन्य राष्ट्रांसे समानताके स्तरपर सहयोग करनेके लिए कांग्रेस भारतको पूर्ण स्वाधीन वनानेके संवर्षमें लगी रहेगी"।

लीगके नेता चुनचाप नर-संहार देखते रहे—शायद इस डरसे कि हिंसाके विरोधसे

मुसलमानोंका पाकिस्तानके लिए उत्साह ठण्डा न पड़ जाय । संविधान परिषदकी पहली वैठक ९ दिसम्बरको होनेवाली थी। लीग उसका वहिष्कार करनेका संकल्प कर चुकी थी। दिसम्बरके आरम्भमें ही नेहरू, जिना, लियाकतअली खाँ और वलदेव सिंह इस उद्देश्यसे लन्दन-आमिन्तित किये गये कि सभी दलोंका सहयोग संविधान परिपदको मिल सके, इसका एक और प्रयास किया जाय। प्रयास असफल हुआ और नेहरू ९ दिसम्बरको संविधान परिपदकी पहली वैठकमें शामिल होनेके लिए लोट आये। परिपद नियत दिन शुरू हुई और लीगको छोड़ शेप सभी दलोंने उसमें सहयोग दिया।

लेकिन लन्दन-वार्तांचे लीगको अपने पक्षके समर्थनमें एक वात मिल गयी । वार्तांके अन्तमें ब्रिटिश सरकारने ब्रिटिश सन्त्रिमण्डलके प्रतिनिधिमण्डलके १६ मईके वक्तव्यकी व्याख्याके रूपमें जो वक्तव्य दिया, उसका अन्तिम अंश इस प्रकार था—''जो विधि निश्चित की गयी थी, उसके पालन न होने पर संविधान परिपदकी सफलताकी कोई आशा कभी भी नहीं थी । यदि ऐसी संविधान परिपद कोई संविधान वनाये जिसमें भारतीय जनताका काफी बड़े भागका प्रतिनिधित्व न हो तो उस संविधानको भारतके ऐसे भागोंपर लागू करनेकी वात सोची भी नहीं जा सकती (जैसा कि कांग्रेसने भी कहा है) जो रजामन्द न हों।'' इस वक्तव्यसे जिनाके अनुवायियोंके हृदयमें आशाका फिर संचार हो गया और पृथक् संविधान परिपदकी सम्भावना उन्हें फिर स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। लीगकी कार्यसमितिने ब्रिटिश सरकारसे यह घोषणा करनेको कहा कि उसके ''प्रतिनिधिमन्डलने जो वैधानिक योजना वनायी थी वह असफल हो गयी है'' और ''परिपदके चुनाव व उसका बुलाना ग्रुक्ते ही अवैध, गैरकानृती और अर्थहीन है, उसका जारी रहना व उसकी वैटकोंकी काररवाई अवैध है और वह भंग कर दी जाय।'' अब इतने समयके वाद, ब्रिटिश सरकारके लिए भी यह करना आसान न था। संविधान परिपद अपना काम करती रही।

१९४६-४७ में भारतीय राष्ट्रीयताको घेरणा देनेवाली बहुत-सी घटनाएँ हुई और ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीको स्वीकार करना पड़ा कि भारतीय जनता आजादीके लिए वेचन है। फरवरी १९४६ में भारतीय नौतेनाके सिपाहियोंने हड़ताड़ कर बिद्रोह कर दिया। "बहुत-सी शिकायतें काफी समयतक दूर न होनेके कारण १८ फरवरीको 'तलवार' ट्रेनिंग स्कूलमें यह शुरू हुआ। १९ फरवरीके सवेरेतक वह वस्वई और उसके आस-पासके १२ नौसैनिक शिविरों व वन्दरगाहमें लंगर डाले २० जहाजोंके २०००० कर्मचारियोंमें फैल गया। जहाजोंके मत्त्रलेंसे ब्रिटिश यूनियन जैक (झण्डा) उतार दिया गया और उसकी जगह लीग और कांग्रेसके झण्डे फहराने लगे। कम्यूनिस्ट, लीग और कांग्रेस झण्डोंके नीचे शहरमें नाविकोंके प्रदर्शन शुरू हो गये, जिनके नारे थे—जयहिन्द, इनिक्लाव जिन्दाबाद, हिन्दू मुसलिम एक हों, अंग्रेजी साम्राज्यशाहीका नाश हो, हमारी माँगें पूरी हों, आजाद हिन्द फोजके राजनीतिक केंदी छोड़े जाक, इण्डोनेशियासे भारतीय फोजें वापस बुलायी जाकँ। यह बिद्रोह उसी समय हुआ जब ब्रिटिश सरकारने अपना प्रतिनिधिमण्डल भेजनेके निश्चयकी घोषणा की थी। कांग्रेस और लीग दोनीने विद्रोहका समर्थन नहीं किया।

आजाद हिन्द फीजकी कहानी हर एककी जुवानपर थी। उसके नेताओंके (जो अंग्रेजी सेनामं उच पदोंपर थे) सुकदमेमें दुनियाभरमें दिलचरपी ली गयी। इस लम्बे सुकदमेसे जनताकी वेचैनी बढ़ रही थी। कलकत्ता और वम्बईमें कई वार दस-दस लाख जनताकी सभाएँ हुईं, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। दूसरे राहरोंमें भी प्रदर्शन हुए जो इतने वहें नहीं थे। आन्दोलन नागरिकोंतक ही सीमित न रहा और फौजियोंमें भी घर कर गया। जिनाने वार-वार सिर्फ देशके ही नहीं, विक्क पुलिस, फौज हर चीजके वँटवारेकी माँग की थी। पाकिस्तानकी भावना फौजियोंमें भी घर करने लगी और मुसलमान सिपाही नये मुसलिम राज्यको स्थापनाके प्रति उत्साह दिखाने लगे। १८५७-५८ के महान् विद्रोहके बाद कई वार भारतीय फौजी टुकड़ियोंमें विद्रोह हुआ था, पर कभी भी इस पैगाने-पर उनमें जोश नहीं आया था जितना कि जिनाके नारेने पैदा कर दिया था। नियति अंग्रेजोंसे प्रतिशोध ले रही थी; "फूट डालो और राज करो" को नीति आज उलटकर उन्हीं-पर चोट कर रही थी। इस नीतिके फल पक रहे थे। सरकारका कोई ऐसा विभाग नहीं था जहाँ भारतमें रहने या पाकिस्तानमें जानेके प्रश्नपर कर्मचारी उद्देलित न हो रहे हों। मुसलमान पाकिस्तानको अपनी कल्पनाका देश मान रहे थे। एक समय अंग्रेज मुसलमानोंको अपनी सत्ताका मजबूत स्तम्भ मानते थे; अब उन्हीं मुसलमानोंकी निष्ठा पाकिस्तानके प्रति थी और जिना उनके आदर्श थे। अपने विशिध नाटकीय ढंगसे जिनाने मुसलमानोंको भावावेशके इस स्तरपर ला दिया था। उन्होंने मुसलमानोंको मुस्लाओंके फतवोंके असरसे निकालकर राजनीतिके पथपर ला खड़ा किया था।

मजदूरों में भी आजादी के लिए वही लगन और उमंग थी। १९४६ में १९६१००० मजदूरों ने हड़ताल की जिससे कामके १,२७,१७,००० घण्टों का नुकसान हुआ। जन कि पिछले सालों में यही संख्याएँ कमशः केवल ७,४७,००० व ४०,५४,००० तक ही पहुँची थीं। १९४७ के पहले आठ महीनों में इन संख्याओं में और वृद्धि हुई। १९४७ के शुरूमें सरकारने मजदूरों के प्रति कड़ाईका रुख अख्तियार कर लिया और वहुत-से कम्यूनिस्ट गिरफ्तार कर लिये गये। २१ फरवरी, १९४७ को केन्द्रीय विधान-सभामें ग्रहमन्त्री व्हिमभाई पटेलने वताया कि कुल १९५० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

देशी रियासतों में असन्तोप उवला पड़ रहा था। कश्मीर, हैदराबाद व त्रावनकोर में यह असन्तोप सबसे ज्यादा था। कश्मीरमें शेल अब्दुलाक नेतृत्वमें नेशनल (राष्ट्रीय) कानफरेन्सने 'कश्मीर छोड़ो' आन्दोलन चलाया था जिसका उद्देश कश्मीरके महाराजसे गद्दी छुड़वाकर शासन-संत्रा जनताक हाथमें देना था। महाराजाकी स्थिति केवल वैधानिक अध्यक्षकी कर देनेकी माँग थी। महाराजाक प्रधान-मन्त्री रामचन्द्र काकने जवाहरलाल नेहल तकको कश्मीरमें नहीं बुसने दिया। वे दमनके अंग्रेजी ढंगको काममें ला रहे थे। भारतके आजाद होनेके कई महीने बाद महाराजाने अपना ढंग वदला और वह भी तव जव पाकिस्तानकी शहपर कुछ मुस्लिम कवीलोंने कश्मीरपर हमला बोल दिया। शेख अब्दुल्हा प्रधान मन्त्री बना दिये गये।

आसाममें आन्दोलनने दूसरा रूप धारण किया। सिलहटको छोड़कर आसामके शेष सभी जिलोंमें हिन्दुओंका बहुमत था, पर लीग उसको पाकिस्तानमें शामिल करना चाहती थी और ब्रिटिश सरकारी प्रतिनिधि-मण्डलने भी उसे बंगालके साथ जोड़ दिया था। पूर्वा बंगालमें मुस्लिम लीगने यह आन्दोलन चलाया कि बड़ी संख्यामें मुसलमान जाकर आसाममें यस जाय, ताकि आसाममें हिन्दू बहुमतकी जगह अल्पमत हो जाय। पूर्वा बंगालके गरीब मुस्लिम किसानोंको आसाममें खेतीके लिए बड़ी-बड़ी जमीनें देनेका लालच दिया गया और वड़ी संख्यामें मुसलमान आसाम जाने लगे। उनका यह आगमन इस तरह अकस्मात और अचानक हुआ कि आसामके कांग्रेस मन्त्रि-मण्डलको चिन्ता होने लगी और उसने वंगा- लियोंके आसाम-प्रवेशपर रोक लगा दी।

इन सब बातोंसे ब्रिटिश सरकारको विश्वास होने छगा कि भारतीयोंको ज्यादा दिन दास नहीं बनाये रखा जा सकता और उसने शासन-सत्ता हस्तान्तिहत करनेको तिथि निश्चित कर दी। २० फरवरी १९४७ को ब्रिटिश, प्रधान मन्त्रीने छोकसभामें घोषणा की कि—

"व्रिटिश सरकार चाहती थी कि शासन-च्यवस्था उस सत्ताको सोंपी जाय जो सभी भारतीय दखें द्वारा स्वीकृत हो, विधानके अनुसार स्थापित की गयी हो । यही मिनत्रमण्डलके प्रितिनिधिदलकी योजना थी। पर दुर्भाग्यवश अभी ऐसी कोई आशा नहीं है कि इस तरहका संविधान वनेगा और इस तरहकी व्यवस्था स्थापित होगी। वर्त्तमान अनिश्चित परिस्थितिमें संकट निहित है और यह स्थिति कायम नहीं रखी जा सकती। ब्रिटिश सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि उसका यह निश्चित इरादा है कि जून १९४८ से पहले ही शासन-सत्ता उत्तरदायी भारतीयोंके हाथोंमें सोंप दी जाय।……

"विटिश सरकारको यही सोचना है कि विटिश भारतकी केन्द्रीय सरकारके अधिकार निश्चित तिथिपर किसे सौंपे जायँ भारतकी किसी केन्द्रीय सरकारको सौंपे जायँ या कुछ इलाकोंमें वर्त्तमान प्रान्तीय सरकारोंको सौंपे जायँ जिसमें भारतीय जनताका सबसे अधिक हित साधन हो और जो सबसे अधिक न्यायसंगत प्रतीत हो। सत्ताका अन्तिम हस्तान्तरण चाहे जून १९४८ के पहले न हो, लेकिन उसकी तैयारी पहलेसे करनी होगी।"

ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीने यैवलकी जगह 'सत्ता हस्तान्तरणका कार्य पूरा करनेके लिए' एडिमरल वाइकाउण्ट माउण्ट्येटनको भारतका नया वाइसराय नियुक्त किया।

१५ दिन वाद ५ मार्चको त्रिटिश लोकसभामें वादिववादके समय ब्रिटिश सरकारके भारत छोड़नेके कारण वताते हुए स्टेफर्ड क्रिप्सने कहा —

"सरकारके सामने दो बुनियादी रास्ते थे। एक रास्ता यह था कि भारतपर ब्रिटिश नियन्त्रणको और मजतूत किया जाय, भारत-सचिवके कर्मचार्रियोंकी संख्या और बढ़ायी जाय, भारतमें ब्रिटिश फौजोंकी संख्यामें वृद्धि की जाय तथा प्रशासकीय उत्तरदायित्व तव-तक निभाते रहा जाय जनतक भारतीय जातियोंमें कोई समझौता न हो जाय। इस नीतिके लिए यह निर्णय आवश्यक था कि अगले १५-२० वर्पोतक भारतमें रहना ही है, क्योंकि इससे कम समयमें वहाँ शासन व्यवस्थाको मजतूत और स्थायी नींवपर खड़ा नहीं किया जा सकता।

"दूसरा रास्ता यह था कि हम यह स्वीकार कर लें कि पहले रास्तेपर चलना सम्भव नहीं है… यह निर्णय करना असम्भव था कि हम अनिश्चित कालतकके लिए उत्तर-दायित्व ओढ़ लें—उस समयतकके लिए यह दायित्व ले लें जवतक निभानेकी शक्ति हममें नहीं है।"

इस समयतकको लीगकी स्थितिपर एक दृष्टि डाल लें। लीग अब भी भारतीय मुस-लमानोंकी एकमात्र प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। उसके मन्त्रिमण्डल वंगाल व सिन्धमें काम कर रहे थे। अत्यधिक मुसलिम बहुमतवाले पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तमें कांग्रेसका मन्त्रि-मण्डल था; पंजाब विधान सभामें लीग दल सबसे बड़ा था, पर यूनियनिस्ट दल शासन कर रहा था क्योंकि हिन्दू, सिख, मुसलमानोंकी सहायतासे यूनियनिस्ट दलका विधान सभामें वहुमत था, आसाममें विशुद्ध कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल काम कर रहा था। जिना और उनके अनुयायियोंको सबसे बढ़ी फिक यह थी कि शासन-सत्ता तो मिल रही है, पर वह पंजाब व सीमायान्तमें लीगको नहीं मिलेगी।

इसिलए लीगने आसाम, सीमाप्रान्त व पंजावमें अपना जोर वढ़ानेके लिए कोशिंगें गुरू की । आसाममें उसने जो ढंग अपनाया वह ऊपर लिखा जा चुका है। सीमाप्रान्तमें कांग्रेस और खुदाई खिदमतगारोंके खिलाफ गाली गलीजका प्रचार गुरू हुआ। वहुत-से सरकारी नौकर लीगमें शामिल हो गये। लूट-मार, आगजनी व करलकी घटनाएँ होने लगीं। हिन्दू व सिख वहाँसे भागने लगे। वे अपनेको असहाय पाते थे क्योंकि मुसलमान पुलिस चाले उनकी रक्षा नहीं करते थे। वहाँ अव्यवस्था व अराजकता फैल गयी।

पंजावमें सरकारी कर्मचारियोंकी निष्ठा सरकारके प्रति कम थी, लीगके प्रति ज्यादा । शान्ति व व्यवस्था कायम रखनेके आदेशोंका या तो पालन ही न होता और होता भी तो अनमने ढंग से । मुस्लिम लीगके प्रचारक खुलेआम हिंसाका प्रचार करते घूमते, हाकिम या तो उनकी काररवाईको नजरअन्दाज कर देते या उन्हें और शह देते । कई सो व्यक्ति गिरफ्तार तो हुए पर अराजकता बढ़ती गयी । शासन व्यवस्था डगमगाने लगी और यूनियिन्ट प्रधान मन्त्री खिज्रहयात खाँने अपने मन्त्रिमण्डलका इस्तीफा दे दिया । इस्तीफेके कारण एक शून्य-सा पैदा हो गया । विधान-सभामें लीग दलका बहुमत नहीं था । उसने हिन्दुओं व सिखोंसे मिलकर बहुमत बनानेकी कोशिश भी की पर हिन्दुओं और सिखोंका लीगसे विश्वास उठ चुका था । इस गितरोधकी परिस्थितिमें ही बड़े पैमानेपर लूट-मार, हत्या व आगजनी होने लगी । मार्चके शुरूमें कांग्रेस पंजावके काण्डसे इतनी वेचैन हो उठी कि उसकी कार्यसमितिने इस स्थितिका एक ही हल यह पाया कि पंजावके दो हिस्से—हिन्दू पंजाव व मुस्लिम पंजाव कर दिये जायाँ।

इस रक्तपात, नरसंहार, लूर्ट व अग्निकाण्डोंके बीच हिन्दू जो कुछ भी सम्पत्ति ले जा पाते, उसे लेक्र पूर्वकी ओर आ रहे थे, मुसलमान पश्चिमकी ओर भाग रहे थे। आवादीका तबादला चल रहा था। पाकिस्तानकी स्थापना और लीगका शासन निश्चित माने जा रहे थे। लेकिन निर्धन लोग अपने-अपने घरोंपर जमे हुए थे। सुरक्षित स्थानोंको ले जानेके लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। शान्ति और व्यवस्था काल्पनिक हो गयी थी क्योंकि व्यवस्था रखनेवाले स्वयं संवर्धमें पक्षपात कर रहे थे। इस स्थितिसे वचनेका एक ही रास्ता दृष्टिगोचर होता था—भारतका विभाजन।

अध्याय ३२

भारत स्वतन्त्र

"फूट डालो और राज करो" की नीतिने ही (जिसने अंग्रेजी राजको प्रायः दो सौ वपोंतक कायम रखा था) उसका अन्त भी निकट ला दिया । अंग्रेजी सरकारने त्वीकार किया कि वह जून १९४८ तक भी राज चलानेमें असमर्थ है और भारतको विभाजित करनेके आधारपर उसने जल्दी ही शासन-सत्ता भारतीयोंको सौंप देनेकी इच्छा प्रकट की ।

३ जून १९४७ को भारतके नये वाइसराय माउण्टवैटनने अंग्रेजी सरकारके अन्तिम वक्तव्यकी घोषणा की जिसमें भारतके विभाजन तथा भारत तथा पाकिस्तानको उपनिवेशीय स्वराज्य देनेकी योजनाका वर्णन था।

इस वक्तव्यमें मुसलिम लीग द्वारा संविधान परिपद्के विहिष्कारके कारण उत्पन्न हुए गित रोधको सुलझानेका सुझाव दिया गया था। इसमें वताया गया कि "यह स्पष्ट है कि इस संविधान परिपद् द्वारा निर्मित कोई भी विधान देशके उन भागोंपर लागू न हो सकेगा जो इसे माननेके लिए तैयार नहीं हैं।" इसलिए इन भागोंकी जनताके सही विचार जाननेके लिए कि वह अपना संविधान (१) वर्त्तमान संविधानपरिपद् द्वारा ही तैयार कराना चाहती है, या (२) एक नयी और पृथक् संविधान परिपद् द्वारा तैयार कराना चाहती है जिसमें उन क्षेत्रोंके प्रतिनिधि होंगे जो वर्त्तमान संविधान परिषद्में भाग लेना नहीं चाहते, निम्निलिखत तरीका वताया गया—

"वंगाल और पंजावकी विधान सभाएँ (यूरोपीय सदस्योंको छोड़कर) दो भागोंमें अपनी वैठकें करें। एक भागमें मुसलिम वहुमत जिलोंके प्रतिनिधि बैठें और दूसरेमें प्रान्तके होप भागकें। ठीक जनसंख्या जाननेके लिए १९४१ की जनगणना अधिकृत मानी जायगी।

"प्रत्येक विधान सभाके दोनों भागोंके सदस्य, उक्त नीतिसे अलग-अलग वैठकर बोट द्वारा निश्चय करेंगे कि प्रान्तका विमाजन हो या न हो। यदि किसी भी एक भागके सदस्य साधारण बहुमतसे विभाजनके पक्षमें निर्णय लेंगे तो विभाजन किया जायगा और तदनुसार विभाजनका प्रवन्ध किया जायगा।

"विभाजन विपयक प्रश्नका निर्णय करनेसे पहले यह वांछनीय है कि प्रत्येक भागकें प्रतिनिधियोंको पता रहे कि यदि अन्ततः प्रान्तने एक साथ संयुक्त रहनेका ही निश्चय किया तो वह कौन-सी संविधान परिपदमें शामिल होना चाहेगा। इसलिए यदि कोई भी सदस्य ऐसी इच्छा प्रकट करेगा तो पांतीय विधान सभाका संयुक्त अधिवेशन (यूरोपीय सदस्योंको छोड़कर) किया जायगा जिसमें पूरी विधान सभा यह निश्चय करेगी कि प्रान्तको किस संविधान परिपदमें शामिल होना है।

"यदि विभाजनका निर्णय हुआ तो हर भाग अलग अलग निश्चय करेगा कि उसे किस संविधान परिपदमें शामिल होना चाहिये।

"सिंधकी विधान सभा (यूरोपीय सदस्योंको छोड़कर) भी ऐसा ही निर्णय करेगी!

परन्तु सिंधमें कोई हिन्दू वहुमतका जिला नहीं है, इसलिए वह दो भागोंमें नहीं वैठेगी।"

उत्तर-पिश्चमी सीमान्त प्रान्तके विषयमें ब्रिटिश सरकारके वक्तव्यमें कहा गया कि यह निश्चय करनेके लिए कि वहाँके लोग वर्तमान संविधान पिश्पदमें रहना चाहते हैं या नयी पृथक पिश्पदमें, जनमत-गणना करायी जाय। ऐसी जनमत-गणनाका प्रवन्ध सिल्हट जिलेके सम्बन्धमें भी किया गया जो हिन्दू वहुमत प्रान्त आसाममें केवल एक मुसलिम बहुमत जिला था।

भारत और पाकिस्तानकी सीमाएँ निर्धारित करनेके लिए वंगाल, पंजाव और सिल-हटके लिए अलग-अलग सीमा-कमीशनोंकी स्थापनाका प्रवन्ध किया गया।

सन् १९४१ की जनगणनाके अनुसार पंजावमें मुसिलम बहुमतवाले जिले ये थे:— लाहोर डिवीजन—गुजरानवाला, गुरदास पुर, लाहोर, शेलूपुरा, स्वालकोट; रावल-पिण्डी डिवीजन—अटक, गुजरात, शेलम, मियाँवाली, रावलिण्डी, शाहपुर; मुस्तान डिवीजन—डेरा गाजी खाँ, झाँग, लायलपुर, माँटगोमरी, मुलतान, मुजफ्पर गढ़।

वंगालके मुसलिम बहुमतके जिले ये थे -

चटगाँव डिवीजन—चटगाँव, नोआखाली, टिपरा; ढाका डिवीजन—वाकर-गंज, ढाका, फरीदपुर, मैमनिसंह; प्रेसिडेंसी डिवीजन—जैसोर, मुरशिदाबाद, निदया; राजशाही डिवीजन—बोगरा, दीनाजपुर, मालदा, पवना, राजशाही, रंगपुर।

विटिश सरकारका यह वक्तव्य जो माउण्टवैटन योजनाके नामसे प्रसिद्ध हुआ, वास्तवमें राजगोपालाचारी-फारम्लाका व्यावहारिक रूप था। जनसाधारणके सामने इसकी घोषणा करनेसे पहले माउण्टवैटनने इस वक्तव्यकी प्रतियाँ राजनीतिक नेताओंको अध्ययन करनेके लिए भेज दी थीं जिससे वे र जूनकी आधी रातर्तक उसपर अपने विचार प्रकट कर सकें। जिनाने कहा कि मैं अकेले कोई निर्णय नहीं कर सकता और न लीगकी कार्यसमिति ही कर सकती है—''इस निर्णयके लिए'' उन्होंने कहा, "हमें मुसलिम जनताके सामने जाना होगा। मैं तो केवल इतना ही कर सकता हूँ कि वैधानिक ढंगसे उसको प्रभावित करनेकी भरसक कोशिश करूँ जिससे वह इसे स्वीकार कर ले। मेरी कार्यसमिति इस मामलेमें मेरा समर्थन करेगी।''

तव माउण्ट्येटनने जिनासे साफ-साफ कहा कि आपकी इस चालके वारेमें कांग्रेस दलको बहुत सन्देह है क्योंकि आप हमेशा यही तरीका इस्तेमाल कर अपना निर्णय कांग्रेस द्वारा परिपक्व निर्णय हो जानेके कई दिन बाद करते हैं, और इस प्रकार आप लीगको स्वेच्छानुसार निर्णय करनेका अवसर प्राप्त कर लेते हैं। माउण्ट्येटनने जिनाको यह भी चेतावनी दे दी कि इस बार नेहरू, कुपालानी और पटेल इस बातपर अड़ गये हैं कि यदि मुसलिम लीग कांग्रेसके साथ इस योजनाको अन्तिम रूपसे स्वीकार नहीं करती तो वे भी इसे अस्वीकार कर देंगे।

कांग्रेसी नेतागण बहुत सदांक थे क्योंकि कुछ ही सप्ताह पहले जिनाने वंगालसे पंजाव-तक, दोनों पाकिस्तानी क्षेत्रोंको भौगोलिक रूपसे जोड़नेके लिए ८०० मील लम्बा एक "गिलि-यारा" माँगा था, और लीगके मुखपत्र "डान"ने उसके लिए खूब प्रचार आन्दोलन करना आरम्भ कर दिया था। और जब जिनाने लीग कोंसिलका अधिवेशन शीग्र बुलानेमें अस- मर्थता प्रकट की तो कांग्रेस दलका सन्देह और भी पुष्ट हो गया। इसिलए माउण्टेनेटनने जिनासे इदतापूर्वक कह दिया—"अगर आपका यह रुख है तो कांग्रेस और सिख दोनों ही कल प्रातःकाल इस योजनाको अस्वीकार कर देंगे, खलवली मच जायगी, और आप अपना पाकिस्तान खो बैठेंगे, शायद सदैवके लिए।" जिनाने कन्धे सिकोड़ते हुए उत्तर दिया—"जो होना है, होगा।" तब माउण्टेनेटनने कहा—"मिस्टर जिना, जो सारी मेहनत इस समझौतेके बनानेमें व्यय हुई आप उसे वर्बाद नहीं कर सकते। क्योंकि आप मुसलिम लीगकी ओरसे स्वीकृति नहीं देंगे, में स्वयं उसकी ओरसे बोलूँगा। में यह कहूँगा कि आपने जो आदवासन मुझे दिया है उससे में सन्तुष्ट हूँ और यदि लीग कोंसिल स्वीकृति न दे, तो आप सारा दोष मेरे ऊपर रख सकते हैं। में सिर्फ एक शर्त रखता हूँ, और वह यह है कि जब में प्रातः की बैठकमें कहूँ कि 'मिस्टर जिनाने मुझे आदवासन दिया है, उसको मैंने स्वीकार कर लिया है और उससे में सन्तुष्ट हूँ" तब आप किसी भी दशामें उसका खण्डन नहीं करेंगे, और जब में आपकी ओर देखूँ, तो आप स्वीकृति सूचक सिर हिला दीजियेगा। '"

योजनाके विषयमें जिनाका जवाव केवल सम्मतिस्चक सिर ।हिलाना था । उन्होंने मौिखक स्वीकृतितक नहीं दी । परन्तु कांग्रेसने निश्चयात्मक रूपसे अपनी स्वीकृति प्रकट कर दी, यद्यपि गान्धीजीने इससे सम्बन्धित होनेसे इनकार कर दिया था । प्रातःकाल बैठक हुई, सब नेतागण अपनी-अपनी स्वीकृति देकर बिदा हो गये । सिखोंकी ओरसे बलदेवसिंहने स्वीकृति दी । जिस स्थानपर यह बैठक हुई थी उसके प्रवेश-द्वारके हालमें "क्लाइवका तैल चित्र ब्रिटिश राजकी इहलीला समाप्तिके इस दृश्यको घृणासे देख रहा था।"

घोषणा होनेके दो-चार दिनके अन्दर ही कांग्रेस और लीगकी कार्यसमितियोंने इस स्वीकृतिको पुष्टि प्रदान कर दी।

६ जूनको अपनी प्रार्थना सभामें गान्धीजीने वाइसरायसे मेंट करनेके वाद घोषणा कर दी कि अंग्रेज अधिकारी १५ अगस्तके दिन भारतको सत्ता हस्तान्तरित करनेको तैयारी कर रहे हैं।

वड़ी तत्परता और तेजीसे सरकार योजनाके उपवन्धोंको कार्यान्वित करने लगी। पंजाव और वंगालकी विधान समाएँ बुलायी गर्यी और सीमा प्रान्त तथा सिलहरमें जनमत गणनाका आदेश जारी कर दिया गया। विधान समाएँ क्या निर्णय करेंगी इसमें तो किसीको सन्देह था ही नहीं—सुसलिम बहुमत जिलोंके प्रतिनिधियोंने एक पृथक् संविधान परिषदके लिए वोट दिया। उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्तमें, जहाँकी जनताने १९४६ में कांग्रे सको बहुमतमें वोट दिया था, लीगको सफलताका भरोसा न था। इसलिए उसने अपने अनुयायियों और समर्थकोंको हिन्दू व गैरलीगी मुसलमानोंपर हिंसात्मक आक्रमण करनेकी योजना वनायी। अनेक सरकारी अफसर पाकिस्तानके पक्षमें थे। उन्होंने या तो चुपकेसे लीगके विद्रोहकी सहायता की या नृश्चंसताओंकी ओरसे निगाह वचाकर अप्रत्यक्ष रूपसे उन्हें बढ़ावा दिया। पहले लीगयों द्वारा हिन्दुओं और गैरलीगी मुसलमानोंके खिलाफ घर-घर पृणित प्रचार किया गया। फिर हिंसाका नग्न नृत्य होने लगा। ऐसी स्थितिमें शान्तिप्रय लाल कुर्तीवालोंने अपनेको असहाय अवस्थामें पाया। उनके नेताने सोचा कि ऐसे वातावरणमें निध्यक्ष जन-

१. ऐसेन कैम्बेस —जानसन, "मिशन विद माउण्टवैंटन, ए० १०३

मतगणना असम्भव है और उन्होंने गणनाका वहिष्कार करनेका फैसला कर लिया। २५ जूनको उन्होंने एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमें कहा—

"पिछले कुछ महीनोंमें मुसलिम लीगियोंने संघटित रूपसे आतंकका प्रचार किया, जिसके फलस्वरूप सैकड़ों पुरुप, स्त्री और वच्चे मौतके घाट उतार दिये गये। करोड़ों रुपयेकी सम्पत्ति नष्ट कर दी गयी। पूरा वातावरण साम्प्रदायिक वौखलाहट और विपसे भरा हुआ है।

"अव भी मुसलिम लीगके प्रमुख सदस्य वहें जोर-शोरका प्रचार करके लोगोंको भयभीत कर रहे हैं कि वे लीगके खिलाफ वोट नहीं दे सकेंगे। प्रकट है कि वे उन हजारों शरणार्थियोंको जो प्रान्तके वाहर भाग गये हैं, वोट देनेसे रोकना चाहते हैं। सीधे सादे पठानोंका भी धार्मिक जोश जागरित किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि जनमत-गणनाका मामला 'काफिर' और 'इसलाम' के वीचका झगड़ा तय करनेके लिए उठा है।"

अन्दुलगफार खाँने कहा कि यदि लीगको एक पृथक राज्य मिलता है, तो पठानों-को भी एक पृथक मातृभूमि, पख्तृनिस्तान, मिलनी चाहिये। उन्होंने दावा किया कि पख्तृनों-का भारी बहुमत एक आजाद पठान राज्यके पक्षमें है। उन्होंने खुदाई खिदमतगारों तथा अन्य लोगोंसे जो आजाद पठान राज्यमें विश्वास रखते थे, अपील की कि वे जनमतगणनामें भाग न लें। गान्धीजीने सीमान्त नेताकी इस उक्तिका समर्थन किया। जनमतगणना निश्चित दिन हुई, अन्दुलगफार खाँके अनुयायियोंने उसका बाइकाट किया। हिन्दू जो अधिकांश शरणार्थीकी हालतमें सीमान्त प्रान्तके वाहर थे, इस गणनामें भाग न ले सके। लीगने कुल जनसंख्याके ५० प्रतिशतसे कुल अधिक वोट प्राप्त कर लिये।

सिल्हटकी मतगणनामें भी लीगने इन्हीं तरीकोंसे सफलता प्राप्त कर ली।

जुलाईमें ब्रिटिश पार्लमेण्टने भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित कर दिया जिसमें भारत और पाकिस्तानके दो नये स्वतन्त्र राज्योंको जन्म दिया गया। इस अधिनियमसे दोनों औपनिवेशिक स्वतन्त्र राज्योंकी विधायिकाओंको पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया कि वे अपने-अपने देशोंके आन्तरिक तथा वाह्य मामलोंके लिए कोई भी कान्त् वना सकती हैं और यह भी उपवन्ध कर दिया गया कि ऐसे कान्त् चाहे वे ब्रिटिश कान्त् के विपरीत ही क्यों न हों, अवैध नहीं ठहराये जा सकेंगे। इस अधिनियमने ब्रिटिश पार्लमेण्टको उसकी भारतपर नियन्त्रणकी शक्तिसे वंचित कर दिया और भारत और पाकिस्तानको अपने-अपने भाग्यका विधाता वना दिया।

आधी रातके समय जव १५ अगस्त भारतीय स्वाधीनताको लाने ही वाला था, भारतीय संविधान परिपदने एक प्रस्ताव पारित करके भारतको स्वतन्त्र घोषित कर दिया और माउण्टवैटनको उसका प्रथम वैधानिक गवर्नर-जनरल वननेके लिए आमन्त्रित किया। उस रातकी संविधान परिषदकी काररवाई अति गम्भीर और प्रभावशाली थी। अपने हृदय-ग्राही भाषणमें नेहरूने कहा "वर्षों पूर्व हमने भाग्यके साथ जो गुप्त समझौता किया था, आज उसके पूरा करनेका समय आया है, पूर्णतया नहीं, फिर भी वड़ी मात्रामें। ठीक आधी रातके घण्टेकी आवाजके साथ, जब सम्पूर्ण संसार सोता होगा, भारत स्वतन्त्रता और जीवनमय स्कृतिसे जाग उटेगा।"

रातके १२ बजे माउण्टवैटन अपनी मेजपर चुपचाप वैठे थे— गम्भोरता और कुछ

कुछ अलगावके वातावरणमें ।' उन्होंने अपना पढ़नेका चक्ष्मा उतार लिया और कागज-पत्रोंके वक्षों में ताले लगा दिये, फिर अपने प्रेस सेकेंटरीको बुलाया ताकि "वह कमरा साफ कर सके और 'वाइसरायी' कायों के वाहरी और दृष्टिगोचर चिन्हों को हटा दे।" लगभग १२ वजकर ४५ मिनटपर प्रधान मन्त्री नेहरू और विधान परिपदके अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद रस्मी तौरपर माउण्टवैटनको निमन्त्रण देने आये। जो कहना था, उसे राजेन्द्रप्रसाद वुदाना शुरू किया, लेकिन "वे पाठ भूल गये और नेहरूको पिछसे उन्हें पाठ वतानेकी भूमिकामें आना पड़ा।" माउण्टवैटनने मुसकराते हुए कहा—"मुझे इस सम्मानपर गर्व है, और आपकी सलाहको वैधानिक ढंगसे लागू करनेके लिए में सतत प्रयत्नशील रहूँ गा।" इसपर नेहरूने एक लिफाफा उन्हें देते हुए आदर और सौजन्यसे कहा—"क्या में नये मन्त्रिन मण्डलके सदस्योंके नाम पेश कर सकता हूँ ?" पूरा समारोह लगभग १० मिनटमें समाप्त हो गया। अपनी उत्सुकता शान्त करने और नये मन्त्रियोंके नाम याद करनेके लिए माउण्ट वैटनने लिफाफा खोला पर खाली निकला—विशिष्ट असावधानी वश।

सबेरे ८॥ वजे वही तुरही और तूली व सुनहरी सजधजमें स्वतन्त्र भारतके पहले गव-र्नर-जनरल निष्ठाकी शपथ लेने आये, जिसमें पहले गुलाम भारतके २० वाइसराय आये थे। भवनके वाहर ढाई लाखसे अधिक उत्साहित भीड़ इकट्टी थी और 'जयहिन्द'के नारोंके साथ भवनमें शुस पड़नेकी चेष्टा कर रही थी। भीड़को शान्त करनेके लिए नेहरू आदि नेताओंको वाहर आना पड़ा।

सव ओर उमंग और उत्साह था। भवनके भीतर दुनिया भरसे आये वधाईके सन्देश पढ़ना ग्रुक किया गया "किन्तु, भ्रमवश अमेरिकाके राष्ट्रपति ट्र्मनका सन्देश न पढ़ा गया और अमरीकी राजदूतके जोरसे फुसफुसा कर प्रवोधन करने पर ही उस ओर ध्यान गया और गलती सुधार ली गयी।" इसके उपरान्त राजेन्द्रप्रसादने पहले हिन्दी और फिर अंग्रेजीमें लम्बा भाषण किया—"जो हमने प्राप्त किया है वह बहुत सीमातक हमारे त्याग और विल्दानके कारण तो प्राप्त हुआ ही है, साथ ही अन्तरराष्ट्रीय घटनाओं और शक्तियोंने भी इसमें योग दिया, ब्रिटिश जातिकी ऐतिहासिक परम्परा और जनतान्त्रिक आदशोंका पूर्णत्व भी इसमें हैं " भारतपर ब्रिटेनका प्रभुत्व आज समाप्त हुआ और ब्रिटेनसे अव हमारे सम्बन्ध समता, सद्भावना और पारस्परिक लाभपर आधारित हैं।"

उत्सवके उपरान्त माउण्टवैटनके वाइसराय भवन वापस छोटते समय भीड़ने 'जय-हिन्द', 'माउण्टवैटनकी जय', 'पण्डित माउण्टवैटनकी जय' आदि नारोंसे उनका स्वागत किया । उत्साह और उमंगके ऐसे ही हक्य उस दिन देशभरमें दिखाई दिये ।

अध्याय ३३

उपसंहार

जब देश स्वतन्त्रता-दिवसकी खुशियाँ मना रहा था, गान्धीजी दूर नोआखालीतक आन्तिका सन्देश पहुँचाने कलकत्ते गये थे। लेकिन स्वयं कलकत्तेमं साम्प्रदायिक उत्पातोंकी तैयारीका समाचार पाकर वे वहीं रक गये। उनकी मौजूदगोका जाद जैसा असर हुआ और कलकत्तेमें १४ व १५ अगरतको उपद्रवकी जगह हिन्दू-मुसिलम सद्भावनाक वे दृश्य देखें गये जो खिलाफत आन्दोलनके समय देखनेको मिलते थे। गिलयों और सड़कोंपर हिन्दू और मुसलमान गले मिल रहे थे। सितम्बरमें फिर एक वार स्थिति विगड़नेको हुई, पर गान्धीजीन फिर उसे सम्हाल लिया—इस वार उपवास करके।

,लेकिन पंजाय और पाकिस्तानके कुछ अन्य क्षेत्रों में पूरे गृहयुद्धके दृश्य दिखाई देते थे। सभ्य समाजकी नींव ढह गयी थी। लगता था कि पूरे मुसलिम समाजने पूरे हिन्दू समाजके खिलाफ युद्धकी घोषणा कर दी है और यह युद्ध पाश्चिकताकी पराकाष्ट्रा पार कर गया है। आक्रमणकी सबसे बड़ी शिकार खियाँ थीं, उन्हें इस निर्देयतापूर्वक मारा जा रहा था कि उसके वर्णनसे नृशंस सितमगरका दिल भी दहल जाय। नययुवितयाँ व बालिकाएँ बलात् मुसलमान बनाकर गुण्डों हारा रखेलियोंकी तरह रखी जा रही थीं। पंजायके हिन्दू भागमें मुसलमानोंके साथ भी ऐसा ही ब्यवहार हो रहा था।

व्यवस्था और कान्त्नका अस्तित्व मिट गया या, लूट-पाट, आगजनी, हत्या, बलात्कार, सार्वजनिक करल, ये नित्यप्रतिकी घटनाएँ थीं । इस अप्रिपक्षिक बीच लाखों व्यक्ति अपनी जमा-पूँजी लिये एक पंजायसे दूसरे पंजाय जा रहे थे । यहुत-से वालक, दृद्ध, स्त्री-पुरुष इस यात्रामें ही मर गये । जय भारत व पाकिस्तानकी सरकारोंने देखा कि साम्य-दायिक ढंगपर आवादीका तबादला ही इस नरकसे छुटकारेका एकमात्र रास्ता है तो उन्होंने अल्पसंख्यकोंके निष्क्रमणमें सहायता देनेका निर्णय किया । लेकिन जहाँ पाकिस्तानके हर कोनेसे हिन्दू खदेडे जा रहे थे, पंजाय छोड़ शेष भारतमें मुसलमान सुरक्षित थे और उन्हें पाकिस्तान खदेड़ देनेकी हवा नहीं वह रही थी । तव भी कहीं-कहीं भारतमें भी हिन्दुओंने मुसलमानोंके साथ वैसा ही पैशाचिक व्यवहार किया जैसा हिन्दुओंके साथ सारे पाकिस्तानमें हो रहा था ।

पिश्वमी पंजाव और पिश्वमोत्तर सीमाप्रान्तसे हिन्दुओं और सिखोंके पूरी तरह हट जाने पर ही वहाँ सामान्य जीवन प्रारम्भ हुआ । लेकिन लाखों शरणार्थी अपना घरवार छोड़ भारतमें रोटी और शरणके लिए भटक रहे थे और उनकी दुःखगाथा सहानुभृतिपूर्ण हिन्दुओं को उकसा देती थी । शरणार्थियों में प्रतिशोधकी आग थी और कई जगह उन्होंने उदिग्न हिन्दुओं के साथ मिलकर मुसलमानोंकी सार्वजनिक हत्या कर दी । मुसलमान डरे हुए थे । गान्धीजीतक की अपीलें उपद्रवकारियोंको शान्त न कर पार्या । उल्टे साम्प्रदायिक हिन्दू यह समझने लगे कि गान्धीजी उन्हें उनका 'धार्मिक कर्त्त व्या पूरा करनेसे रोक रहे हैं । कुछ

समयतक रेडियो और समाचारपत्रोंमें प्रसारित गान्धीजीके प्रार्थना-समाओं के भाषणोंने लोगोंको संयत रखा, पर सम्प्रदायवादी वीच-वीचमें लोगोंको भड़का देते और नयी दुखान्त घटनाएँ हो जाती । स्वयं दिस्लीमें जहाँ गान्धीजी उस समय रह रहे थे, करल होते थे और गान्धीजीकी उपस्थितिका उपद्रवियोंपर प्रभाव नहीं पड़ता था । मुसलमान सतत भयके वाता-वरणमें रह रहे थे । गान्धीजीका क्लेश और मानसिक वेदना उनके आमरण अनशनमें प्रकट हुई । १३ जनवरीको उन्होंने उपवास शुरू किया जो दिस्लीमें शान्ति-स्थापनातक चलनेवाला या—जैसा कि हमेशा होता था, उनके उपवाससे सभी वर्ग चिन्ताकुल हो उठे और विभिन्न वर्गों व राजनीतिक दलोंके सैकड़ों नेताओंने लिखकर आश्वासन दिया कि वे शान्ति-स्थापनाके लिए प्रयत्नशील रहेंगे । १८ जनवरीको उपवास भंग-हुआ । दिल्लीमें पुनः शान्ति स्थापित हो गयी । कुछ दिनोंतक देशभरमें पूर्ण शान्ति रही; लेकिन किर इक्को दुक्की छिटफुट घटनाएँ होने लगीं।

गान्धीजी भारत और पाकिस्तानकी सद्भावनापूर्ण हार्दिक एकताके लिए प्रयत्नशील थे, ताकि दोनों ओरके शरणार्थी फिरसे अपने-अपने घरोंमें बसाये जा सकते । इस सद्भावना-पूर्ण वातावरणके लिए यह आवश्यक था कि भारतमें मुसलमान पूर्णरूपसे सुरक्षित रहें । इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए वे कोई भी कीमत चुकानेके लिए तैयार थे । लेकिन कुछ हिन्दू ऐसे भी थे जिनकी प्यास सिर्फ मुसलमानोंके खूनसे ही बुझती; वे गान्धीजीके कामको मुसलमानों-को खुश करना भर मानते थे ।

उपवास भंग होनेके दो दिन वाद २० जनवरीको गान्धीजीको डरानेके इरादेसे उनकी प्रार्थना-सभामें एक वम फेंका गया। लेकिन ऐसी असंख्य घटनाएँ भी गान्धीजीको उनके निश्चयसे नहीं डिगा सकती थीं; वे हर शाम प्रार्थना-सभामें साम्प्रदायिक सद्भावनाकी अपील करते।

अन्तमें असन्तुलित बुद्धिके एक सम्प्रदायवादी हिन्दूने गान्धीजीको मार डालनेका निश्चय किया। शुक्रवार, ३० जनवरीको, शामको ५ वजकर १२ मिनटपर जव गान्धीजी प्रार्थना-सभामें मंचकी सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, एक ३५ वर्षाय युवकने उनके सामने आकर कहा—"आज आपको देर हो गयी।" गान्धीजी मुस्कराये और वोले—"हाँ, मुझे देर हो गयी।" उसी समय उस युवकने रिवाल्वर निकाल कर गान्धीजीके कुश तनपर दृदयके नीचे तीन गोलियाँ वेध दीं। गांधीजी गिर पड़े। उनका अन्तिम कुत्य था, प्रार्थना-सभाके लिए एकत्र भीड़की दिशामें हाथ जोड़ना। उनके अन्तिम शब्द थे—'हे राम!' वे फौरन विड़ला भवन ले जाये गये। ५ वजकर ४० मिनटपर उन्होंने अन्तिम साँस ली।

कुछ मिनटोंमें ही सारे देशने सुना कि गान्धीजी नहीं रहे। लोगोंको विश्वास नहीं हुआ, हर एक दो-दो तीन-तीन वार यही पूछता कि खबर गलत है। कुछ लोगोंको इस समाचारसे ऐसी सांघातिक चोट लगी कि खबर सुनते ही उनके हृदयकी गति वन्द हो गयी।

इस ऐतिहासिक दुःखद घटनाकी घोषणा करते हुए प्रधान मन्त्री नेहरूने काँपती वाणीमें रेडियोसे कहा-

"साथियो और भाइयो ! हमारे जीवनकी रोशनी चली गयी है और हर तरफ अँधेरा है । हमारा प्यारा नेता, राष्ट्रिपता, जिसे हम वापू कहकर पुकारते थे, नहीं रहा "''रोशनी चली गयी है, जैसा मैने कहा; पर मैं गलत था । क्योंकि जो रोशनी इस देशको रौशन करने आयी वह कोई साधारण रोशनी नहीं थी। जो रोशनी इधर वपाँतक देशकी जिन्दगीको प्रकाशमान करती रही, वह आनेवाले सालों में भी चमकती रहेगी; हजार साल बाद भी वह रोशनी इस देशमें रहेगी और दुनिया उसे देखेगी और वह असंख्य लोगोंके हृदयको आलोकत करेगी।"

देर राततक भीड़ विड्ला भवनके आसपास रही। भीड़ गान्धीजीके दर्शनके लिए बढ़ती गयी। खेत खादीमें सजाकर शरीर एक साधारण अर्थापर रखकर छतपर हाका कर रख दिया गया। वहाँ वहुत तेज रोशनी कर दी गयी। ९ वजे रातसे भीड़ वहाँ दर्शन करने आती रही। भागतमा गान्धीकी जय'के नारोंसे आकाश काँपता रहा।

दूसरे दिन देशभरमें सब काम बन्द रहा और शामको हर शहर व कस्त्रेमें लोग महात्माकी मृत्युपर शोक प्रकट करनेके लिए एकत्र हुए । १३ दिनतक सरकारने शोक मनाया । सारे संसारसे समवेदनाके सन्देश आये । सारे संसारके समाचारपत्रोंने, सारे संसारके सर्वजनिक नेताओंने उन्हें श्रदांजलि श्रपित की । ऐसे व्यक्तिके लिए पहली बार—जो संबक्त सदस्य न हो या किसी देशकी सरकारका नेता न हो—संयुक्त राष्ट्र संघका झण्डा तीन दिनतक झका रहा ।

गान्धीके बिल्दानने साम्प्रदायिक आगको जादूकी तरह बुझा दिया। उनकी मृत्युके बाद कोई साम्प्रदायिक उपद्रव नहीं हुआ।

३१ जनवरीको सबेरे ११ वजकर ४३ मिनटपर शबका जुल्ल विङ्ला भवनसे चला । १० लाख व्यक्ति राजवाटतकका ५॥ मीलका सफर पाँच घण्टेमें पूरा कर यसुनाके किनारे पहुँचे । स्थल सेनाके ४ हजार, नम सेनाके १ हजार और जल सेनाके १०० जवान व पुलिसके हजार सिपाही जुल्लके आगे थे।

शामके ४ वजे ही राजवाटके मैदानमें विशाल जनसमूह एकत्र था। जुल्स पहुँचने पर अन्तिम दर्शनके लिए पागल भीड़ने पुलिसका घेरा तोड़ दिया। दर्जनों व्यक्ति वेहोश हो गये और उन्हें अस्पतालकी गाड़ियोंपर ले जाया गया।

४ वजकर २० मिनटपर शव वितापर रखा गया। ४ वजकर ४५ मिनटपर गान्धी जीके तीसरे पुत्र रामदासने चितामें अग्नि दी। उस समय सूर्व अस्त हो रहा था और जैसा नेहरूने कहा—''जिस सूर्यने हमें प्रकाश दिया, ऊप्मा दी, वह अस्त हो गया है और हम अन्धकार व शीतमें काँप रहे हैं।"

·			
	•		